

एरीया का आधुनिक इतिहास

प्रथम भाग

, जापान, कोरिया, इन्होचायना, फिलिब्पीन, इन्होनीसिया, बाईलेण्ड, मलाया और बरमा)

"अल्ब्स

सत्यकेतु विद्यालंकार, डी० लिट् (पेरिस)

(मंगलाप्रसाद गारितोषिक विजेता)

प्रवागक

सरस्वती सदन, मसूरी

करण]

मार्च, १९५२

[सूल्य ९॥)

प्रकाशक सरस्वती सदन, मसुरी (उत्तर-प्रदेश)

मृदय--युनाइटेड कमसिंयल प्रें लिए
३२, सर हरिराम गोयना र निक

प्रकाशक का निवेदन

रवतन्त्र भारत के शासन विधान में यह बातें स्वीकृत कर ली गई है, कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है, और अधिक से अधिक पन्द्रहें वक्षों में भारत की संघ सरकार अपने प्रायः सभी कार्य हिन्दी में करने लगेगी। भारतिय संघ के अन्तर्गत अनेक राज्य हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाने लगी हैं।

इस दशा में हिन्दी के लेखकों व प्रकाशकों पर विशेष उत्तरदायित्व आ गया है। अब यह आवश्यक हो गया है, कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, रसायन, ,ीतिकविशान आदि सभी आधुनिक विषयों पर उच्च से उच्च जान हिन्दी में अध हो। हिन्दी का साहित्य भण्डार विविध वैज्ञानिक व आधुनिक विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों से इतना अधिक परिपूर्ण हो जाय, कि किसी को यह जन का अवसर न रहे, कि पुस्तकों की कमी के कारण हिन्दी को उच्च शिक्षा का पम बनाने व सरकारी कार्यों के लिये प्रयुक्त करने में स्कावट होती है। हमारा न यह है, कि विविध विषयों पर उच्चकोटि की पुस्तकों हिन्दी में तैयार कराके ह प्रकाशित करें।

इसी उद्देश्य से, दो साल हुए, हमने डा॰ सत्यकेतु विद्यालंकार द्वारा लिखित 'यूरोप का आधुनिक इतिहास' दो भागों में प्रकाशित किया था। हिन्दी संसार में इस पुस्तक का अच्छा आदर हुआ। इसका प्रथम संसकरण दो साल से भी कम रामय में विक कर रामाप्त हो गया। अनेक विश्वविद्यालयों व कालिजों के अध्यापकों ने इस पुस्तक को बी॰ ए॰ के विद्यार्थियों के लिये प्रयुक्त किया। समाचारपत्रों और विविध विद्यानों ने भी इस पुस्तक का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इससे उत्साहित होकर हमने गत वर्ष राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्तों पर भी एक उच्च कोटि का ग्रन्थ प्रकाशित किया था। हमें सन्तोष है, कि इस पुस्तक का भी जिन्दी संसार ने स्वागत किया और अनेक विश्वविद्यालयों ने इसे बी॰ ए॰ की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कर हमारे उत्साह को बढ़ाया।

अब हम 'एशिया का आधुनिक इतिहास' लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं । हमें आशा है, हिन्दी के विज्ञ पाठक हमारी अन्य पुस्तकों के समान इसका भी स्वागत करेंगे । एशिया के आधुनिक इतिहास पर सम्भवतः हिन्दी में यह प्रथम पुस्तक है। इसमें चीन, जापान, कोरिया, फिलिप्पीन, इन्डोचायना, इन्डोनीसिया, याईलेण्ड, मलाया और वरमा के आधुनिक इतिहास पर विश्व रूप से प्रकाश डाला गया है। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में ये देश किस प्रकार पाश्चात्य साम्राज्य-वाद के शिकार हुए, किस प्रकार इनमें राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन प्रवल हुआ और किस प्रकार ये देश बीसवीं सदी के मध्य भाग में साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त होकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के मार्ग पर अग्रसर हुए, इस महत्त्वपूर्ण प्रकापर इस पुस्तक में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। 'एशिया का आधुनिक इतिहास' का दितीय भाग भी हम शीव्र प्रकाशित कर रहे है। इसमें साइबीरिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, अरव और टर्की का आधुनिक इतिहास दिया जायगा।

सम्भवतः पाठक यह स्वीकार करेंगे, कि हम अपने ग्रंथों की छपाई व कागज आदि की उत्कृष्टता पर विशेष ध्यान देते हैं। साधारणतया इस साइज की हिन्दी पुस्तकों में प्रति पृष्ठ २६ लाइने दी जाती है। हम जहां प्रति पृष्ठ ३२ लाइन देते हैं, वहां प्रत्येक लाइन की चौड़ाई भी अधिक रखते हें। इसीलिये हमारी पुस्तकों के एक पृष्ठ में जितना मैटर आता है, उतना साधारण छपाई की पुस्तकों के १॥ पृष्ठों में भी कठिनता से आता है। अतः हम विश्व पाठकों से अनुरोध करेंगे, कि हमारी पुस्तकों के मूल्य पर दृष्टिपात करते हुए हमारी पुस्तकों की छपाई, कागज, व पाठ्य सामग्री को भी ध्यान में रखने की कृपा करें। यूरोप और एशिया के इतिहास पर इसी ढंग की जो पुस्तकों अग्रेजी में हैं, उनका मूल्य हमारी पुस्तकों की मुकावले में तिगुने से भी अधिक होता है। उपन्यास आदि लोकप्रिय पुस्तकों की नुलना में इस ढंग की पुस्तकों का मूल्य अधिक होना स्वाभाविक है।

आशा है, हमारी अन्य पुस्तकों के समान 'एशिया का आधुनिक इतिहास' का भी हिन्दी संसार में अच्छा आदर होगा।

सरस्वती सदन, मसूरी

विषय-सूची

विषय	पुरुष
प्रकाशक का निवेदन	३
विषय सूची	4
प्रारम्भिक शब्द	११
समर्पण	१५
पहला अच्यायविषय प्रवेश	80
(१) प्रस्तावना	१७
(२) एशिया महाद्वीप	
े(३) एशिया के आधुनिक इति	हास का विषय विभाग
(४) चीन का प्राचीन इतिहास	
दूसरा अध्याय-उन्नीसवीं सदी के पूर्वाई में	चीन की दशा. ३७
(१) मञ्चू साम्राज्य	
(२) चीन ने निवासी	
(३) राजनीतिक संगठन	4
(४) चीन की संस्कृति	
तीसरा अध्याय-यूरोप और चीन का सम्प	र्क ५३
(१) चीन और यूरोपियन राज्	न्यों का न्यापार सम्बन्ध
(२) इङ्गलैण्ड और चीन का य	रुद
(३) पाश्चात्य राज्यों से चीन	का दूसरा युद्ध
(४) ईसाई मिशन और उनक	। विरोध
(५) विदेशियों के साथ सम्ब	न्ध
(६) मञ्जू सम्राटों का निर्बल	शासन
(७) चीन में नवयुग का प्रारम	भ
(८) चीन के सम्बन्ध में विदेषि	तयों की नीति
चौथा अध्याय-जापान के उत्कर्ष का प्रार	भ . ८३
(१) पुरातन इतिहास	i i
(२) पाश्चात्य देशों से प्रथम	सम्पर्क

	एजिया का आधुनिक इतिहास	
(૪)	उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जापान की दशा पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध की पुनःस्थापना सम्राट् की शक्ति का पुनश्द्वार	
, ,	जापान का कायाकरप	808
	नया शासन	
, ,	पाञ्चात्य देशों से की गई सन्धियों में संशोधन	
) सामाजिक व आर्थिक उन्नति	
	चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार	११९
(?)) जापान और चीन का युद्ध	
(२)) चीन में रूस की शक्ति का विस्तार	
) जर्मनी की शक्ति का विस्तार	
(8)) चीन में अन्य राज्यों की शक्ति का विस्तार	
(4)) सुघार के प्रयत्न	
) बोक्सर विद्रोह	
(७)) रूस और जापान का युद्ध	
(6)) चीन में विदेशी राज्यों का आधिक साम्राज्यवाद	
सातवाँ अध्याय-	वीन में राज्यकान्ति) राजसना में सधार का प्रथल	१५३
()	1 4444 4 3444	
(२)) चीन की राज्यकान्ति	
(३)) रिपब्लिक की स्थापना	
` ') रिपब्लिक की समस्याएँ	
	वीन में रिपब्लिक का शासन	909
	प्रथम रिप् बिलकान सरकार	¥.
	यु आन शी काई का स्वेच्छाचारी शासन	
) रिपब्लिक का पुनः संगठन	
) प्रथम महायुद्ध और चीन	
	चीन में अराजकता का काल	
	तिब्बत, मंगोलिया और सिन्किआंग	868
	भौगोलिक परिचय	
(7)	तिब्बत •	
(३)	सि न्नि जांग	
1(8)	मंगो <i>लिया</i>	

(६) मलाया

(७) बरमा	
(८) दक्षिण-पूर्वी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति	
पन्द्रहवा अध्याय-जापान का वशवर्ती सञ्चूकुओ राज्य	३७६
(१) जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति	
(२) मञ्जूरिया की स्थिति	
(३) मञ्जूरिया की स्थापना	
(४) राष्ट्रसंघ और मञ्चूकुओ	
(५) मञ्जूकुओ पर जापान का प्रमुत्त्व	
(६) मञ्चकओ राज्य की प्रगति	
सोलहवां अध्याय—चीन में जापान के आधिपत्य का विस्तार	808
(१) मंगोलिया और जापान	
(२) उत्तरी चीन और जापान	,
सतरहवाँ अध्याय—चीन और जापान का पुढ	268
(१) १९३७ में चीन की दशा	
(२) युद्ध का सूत्रपात	
(३) युद्ध का इतिवृत्त	
(४) स्वतन्त्र चीन	
(५) जापान द्वारा अधिकृत चीन	
अठारहवी अध्यायमहायुद्ध और जापान	ጸጳጳ
(१) महायुद्ध से पूर्व जापान की अन्तराष्ट्रीय गीति	
(२) चीन में पाश्चात्य देशों के प्रभावक्षेत्र और जापान	
(३) अमेरिका और जापान	
(४) महायुद्ध और जापान	
(५) जापान की आन्तरिक नीति	
उन्नीसर्वा अध्यायविभण-पूर्वी एशिया में महायुद्ध का प्रसार	850
(१) जापान द्वारा पाश्चात्य देशों के साम्राज्यों का अन्त	
(२) दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रति जापान की नीति	
(३) जापान की पराजय	
बीसवाँ अध्यायचीन में कम्युनिस्ट ज्ञासन की स्थापना	४९६
(१) महायुद्ध और चीन	
(२) अमेरिका द्वारा चीन में एकता की स्थापना का उद्योग	
(३) लोकतन्त्र शासन की स्थापना का प्रयस्त	

	सम्युनिस्ट दल का उत्कर्ष	
युषकीसर्वां अध्यायः	—-दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष	484
	इन्डोचायना	
(२)	थाईलैण्ड	
(3)	मलाया	
(8)	बरमा	
(4)	इन्डोनीसिया	
बाईसवां अध्याय-	—जापान को नई व्यवस्था 🥙	५४६
(१)	परास्त जापान के सम्बन्ध में मित्र राज्यों की नीति	
(7)	जापान की नई सरकार	
(₹)	जापानी नेताओं पर मुकदमे	
	जापान के सम्बन्ध में नई नीति	
तेईसवां अध्याय-	-कोरिया की समस्या <i>।</i>	५६१
(१)	कोरिया की नई व्यवस्था	
(२)	दक्षिणी कोरिया में रिपब्लिक की स्थापना	
(\$)	उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार	
(8)	कोरिया का गृहयुद्ध	
चौबीसवां अध्याय-	पूर्वी व वक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्स का विस्तार	408
	चीन में कम्युनिस्ट शासन	
	फार्मूसा की कुओमिन्तांग सरकार	
	दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का विस्तार	
, ,	भविष्य	
(५)	उपसंहार	
यानचित्र		५९३
, ,	दक्षिण-पूर्वी एशिया	486
(२)	पूर्वी एशिया	
	चीन का मध्यदेश (अठारह प्रान्त)	
	तिब्बत, सिन्कियांग और मंगोलिया	

सहायक पुस्तकों की सूची

Latourette K. S,: The Chinese: Their History and Calture.

Latourette K. S.: A Short History of the Far East.

Vinacke H. M.: A History of the Far East in Modern Times.

Gubbins J. H.: The Making of Modern Japan.

Holcombe A, N,: The Chinese Revolution.

Mclaren W. W.: A Political History of Japan during the Meiji Era.

Wells H. G.: Outline of History.

Bisson T. A.: Japan in China.

Borton H.: Japan since 1931.

Mills L. A.: The New World of South-east Asia.

Wehl D.: The Birth of Indonesia.

Van Mook H. J.: The Stakes of Democracy in South-east Asia.

Mills L. A. & Emerson R.: Government and Nationalism in

South-east Asia.

Hammer E.: The Emergence of Viet Nam.

Chou Hsiang-Kuang: Modern History of China.

Keetan G. W.: China, The Far East and the Future.

Reischauer E. O.: Japan, Past and Present.

Takekoshi Y.: Self portrayal of Japan.

Yanaga C.: Japan since Perry.

Cambridge Modern History, Vols. XI & XII.

Payne R.: The Revolt of Asia.

Pannikar K. M.: The Future of South east Asia,

Furnivall J. S.: Netherlands India.

Thompson: Thailand, the New Siam.

Pankratova A. M.: A History of the U.S. S. R. (3 Vols).

Astafyev G.: China, from a Semi-colony to a People's Democracy.

Mao Tse-Tung: China's New Democracy.

Vasilieva V. Y.: Viet-Nam & Malaya fight for Freedom.

Shabshina F. I.: Korea after the Second World War.

Ohatterji B. R.: The last Hundred Years in the Far East: Japan.

राहल सांक्ल्यायन : बौद्ध संस्कृति

राहल सांकृत्यायन : तिब्बत में बौद्ध धर्म

इन पुस्तकों के अतिरिक्त इस ग्रन्थ के लिखने के लिये निम्नलिखित पत्रिकाओं के

विविध लेखों से सहायता ली गई है-

People's China. 🗸

Foreign Affairs Quarterly.

World Today.

विषय दर्शन 🗸

Pacific Affairs ~

प्रारम्भिक शब्द

हमारे देश के लिये एशिया का आधुनिक इतिहास बहुत अधिक महत्व रखता है। अठारहवीं सदी में यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने एशिया में अपने आधिपत्य का विस्तार शुरू किया। उन्नीसवी सदी के अन्त तक एशिया के प्राय: सव देशों में किसी न किसी रूप में यूरोप का प्रमुत्व व प्रभाव स्थापित हो गया। अनेक ऐतिहासिक यह प्रतिपादित करने लगे, कि पाश्चात्य जगत के गौराङ्ग लोग एशियन लोगों की तुलना में नसल व जाति की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट हैं, और यह सर्वथा स्वामाविक है, कि पाश्चात्य लोग संसार की अन्य जातियों पर शासन करें और उन्हें सभ्यता व संस्कृति का पाठ पढ़ावें। पर एशिया पर यूरोप का यह प्रभुत्व देर तथा कायम नहीं रहा। वीसवी सदी में एशिया के प्राय: सभी देशों में राष्ट्रीय स्वाधीनता और लोकतंत्रवाद के आन्दोलन विकसित होने शुरू हो गये, और अदितक यह दशा आ चुकी है, कि एशिया पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से प्राय: मुक्त हो गया है।

एशिया में जो यह भारी परिवर्तन आया है, उसी का इतिहास मैंने इस प्रत्थ म संक्षिप्त रूप से लिखने का प्रयत्न किया है। एशिया के विविध देशों की उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भकाल में क्या दशा थी, उन्नित की दौड़ में वे किस प्रकार यूरोण के मुकाबले में पीछे रह गये थे, पाश्चात्य देशों ने उन्हें किस प्रकार अपने साम्राज्यवाय का शिकार बनाया, पाश्चात्य देशों की आधुनिक वैज्ञानिय उन्नित के सम्पर्क में आकर किस प्रकार एशिया में नवजीवन का प्रारम्भ हुआ, किस प्रकार इन देशों में राष्ट्रीय स्वाधीनता और लोकतन्त्रवाद के आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, और किस प्रकार ये देश स्वतन्त्र होकर राष्ट्रीय उन्नित के मार्ग पर अग्रसर हुण्— इसी को प्रविश्व करना इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। क्योंकि भारत भी एशिया का अन्यतम देश है, और प्राचीन समय में धर्म, ज्ञान और सम्यता के क्षेत्र में एशिया का नेतृत्व करता रहा है, अतः भारतीय पाठकों के लिये एशिया के इस आधुनिक इतिहास का महत्व बहुत अधिक वढ़ जाता है।

महाभारत के अनुसार इतिहास एक ऐसे प्रदीप के समान है, जो मोह (प्रज्यु-डिस) रूपी अन्वकार का विनाश कर सब बातों व घटनाओं को उनके यथार्थ रूप

गें प्रकट गरता है। इसमें सन्देह नहीं, कि इतिहासकार को यही लक्ष्य अपने सम्मख रखना चाहिये। ऐतिहासिक का कार्य यही है, कि वह सब घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करे, अपने विचारों और सम्मतियों को वह इतिहास लिखते हुए सामने न लावे। घटनाओं के यथार्थ हुए में निरूपण द्वारा वह पाठकों को यह अवसर दे, कि वे स्वयं अपनी सम्मति बना सकें। ऐतिहासिक के लिये यह आवर्श निस्सन्देह अत्यन्त उच्च है, पर इसे क्रिया में परिणत कर सकना सूगम नहीं है। विशेषतया आधुनिक इतिहास को लिखते हुए किसी भी ऐतिहासिक के लिये यह सुगम नहीं होता, कि वह अपने विचारों व मत को भछाकर घटनाओं के यथार्थ रूप को पाठकों के सम्मुख रख सके। वर्तमान युग विचारधाराओं के संघर्ष का युग है। वैथिनितक सम्पत्ति पर आश्रित लोकतन्त्रबाद और समाजवाद के पारस्परिक संघर्ष के कारण इतिहासलेखक के लिये निष्पक्ष रहकर घटनाओं का यथार्थरूप से निरूपण कर सकना और भी अधिक कठिन हो गया है। दक्षिण-पूर्वी एशिया पर बुद्ध समय के लिये जापान ने अपना प्रभुद्ध स्थापित कर लिया, इस घटना का बुतान्त यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के ऐतिहासिक इस ढंग से लिखते हैं, जैसे कि जापान इस क्षेत्र के लोगों के स्वाधीन जीवन का अन्त कर उन्हें अपना गुलाम व वशवर्ती बनाने के लिये प्रयत्नशील था। जिन लोगों को जापान के उत्कर्ष के कारण पाइचात्य साम्राज्यवाद से छटवारा पाने का अवसर मिला, वे इस घटना के सम्बन्ध में दूसरा ही दिष्टिकोण रखते हैं। आधुनिक इतिहास पर लिखे हुए विविध ग्रन्थों की पढ़िये, उनमें आपको भारी मतभेद दृष्टिगोचर होगा। रूस व चीन के कम्यनिस्ट लेखक एक घटना की किस ढंग से लिखते हैं, अमेरिका व ब्रिटेन के ऐतिहासिक उसे सर्वथा भिन्नकृप से प्रतिपादित करते हैं। इस दशा में निष्पक्ष ऐतिहासिक का कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। मैंने इस वात का प्रयत्न किया है, कि इस पुस्तक में प्रत्येक घटना को निष्पक्ष रूप से प्रतिपादित करूँ, अपने विचारों को कहीं प्रकट न होने दूं। एशिया के आधुनिक इतिहास के सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार रखता हुँ, समाजवाद और लोकतन्त्रवाद जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर मेरे कोई अपने विचार न हों, यह बात नहीं है। पर मैंने उन विचारों को इस इतिहास से पृथक् रखने का प्रयत्न किया है। मुझे अपने प्रयत्न में कहां तक सफलता हुई है, इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकते हैं।

भारत में अभी एशिया के इतिहास के अध्ययन को अधिक महत्त्व नहीं विया जाता । यूरोप का इतिहास हमारे विश्वविद्यालयों के पाठ्यकम के अन्तर्गत हैं,और शिक्षित लोग शीक से जसका अध्ययन करते हैं । पर संसार की राजनीति में अब एशिया का महत्त्व निरन्तर बढ़ता रहा है । चीन, भारत, इन्डोनीसिया आदि विविध एशियन देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त होकर जिस तेजी के साथ उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, उसके कारण अब एशिया संसार में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने लगा है। इस दशा में हमारे लिये एशिया के इतिहारा का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है। यह प्रसन्नता व सन्तोय की बात है, कि गति पय विश्वविद्यालयों ने एशिया के आधुनिक इतिहास को भी वैकल्पिक रूप से अपने पाठ्य विषय में स्थान दिया है। इसरो हमारे देश के नवयुक्कों में एशियन इतिहास के प्रति रिच बढ़ेगी। चीन, इन्डोनीसिया, इन्डोचायना, थाईलैण्ड आदि एशियन देश सम्यता और संस्कृति की दृष्टि से हमारे बहुत समीप हैं। उनके सहयोग से भारत संसार की राजनीति में अपने उन उच्च आदर्शों व विचारों को समाविष्ट कर सकता है, जिन पर मानव समाज का हित व कल्याण निर्भर है। मुझे आशा है, कि इस पुस्तक द्वारा हिन्दी पाठकों को एशिया के आधुनिक इतिहास को समझने में सहायता मिलेगी और वे अपने पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में अनेक जातव्य वाने जान सकेंगे।

--सत्यकेतु विद्यालंकार

जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ज्ञान के उपार्जन और सरस्वती की सेवा में व्यतीत किया, और जिनकी यह हार्दिक इच्छा थी, कि मैं भी उन्हीं के पदिच हों का अनुसरण करूं, अपने उन धर्मपिता (श्वसुर) स्वर्गीय श्री पण्डित मनानीप्रसादजी की पुण्य स्मृति में

पहला अध्याय

विषय प्रवेश

(१) प्रस्तावना

संसार के इतिहास में एशिया का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। मानव सभ्यता का उदय सबसे पूर्व एशिया में ही हुआ था। सिन्ध और गंगा, युफ्रेटिस और टिग्निस, ह्वांग-हो और यांग-त्से-कियांग निदयों की घाटियों में अत्यन्त प्राचीन समय में जिन सभ्यताओं का विकास हुआ था, उन्होंने भनुष्य जाति के इतिहास की बहत अभावित किया है। संसार के सभी प्रमुख घर्मी का अभ्युदय एशिया में हुआ। बुद्ध, ईसा और मुहम्मद एशिया के ही निवासी थे। बीद्ध धर्म के प्रचारकों ने मनुष्यं जाति के बहुत बड़े भाग को अपने विचारों द्वारा प्रभावित किया । इस्लाग के अनु-यायियों ने उत्तरी अफ़ीका और युरोप में भी अपने धर्म का विस्तार किया । किसी समय स्पेत, सिसली और बाल्कन प्रायहीय में भी इस्लाम की सत्ता थी। पिक्सिंग एकिया में प्रादुर्भूत हुए ईसाई धर्म ने तो न केवल यूरोप में अपित अमेरिका में भी फरोड़ों नर-नारियों को अपना अनुयायी बनाया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी एकिया संसार का अगुआ रह चुका है। गणित, ज्योतिप आदि विज्ञानों का विकास सबसे पूर्व एशिया में ही हुआ था । विग्दर्शक यन्त्र, छापाखाना और बारूद भी पहले पहल एशिया में ही आविष्कृत हुए थे। राजनीतिक दृष्टि से भी किसी रायम एकिया नंतार का नेतल्य कर चुका है। यदि गुरोप से सिकन्दर ने एशिया पर जानमाण किया था, तो प्रतिक मंगोल विजेता चंगेज खां और बातू खां भी उराल पर्वतमाला को पारकर सम्पूर्ण हस को अपने आधिपत्य में छाने में समर्थ हुए थे। गंभील और तुर्व आवादााओं ने मुरोप में बीएना तक पर वाक्रमण किये थे । अरब क्षीम तो मन्यूणं भीत को अपनी वायोगना में छाकर क्षांत के दिशाण में पिरेनीज की गर्धनभाला तम जमनी चन्ति का विरतार करने में समर्थ हुए थे। यदि पिछली दी श्रुवियों के इतिहास को जांनों से जोश्रह कर दिया जाय, तो यह समझ संगने में जरा भी रुडिनाई नहीं होती, कि धर्म, सर्यता, नंस्कृति, विकान और राजक्षित के धेयों में एशिया पा महत्त्व बुरोप ने बहत अधिक रहा है और एशिया इन सब विषयों से मानव समाज या वेतस्य करता रहा है ।

पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में गूरोप के आधुनिक उत्कर्ष का सूत्रपात हुआ । जब पश्चिमी एशिया से अरव लोगों के प्रभूत्व का अन्त होकर तुर्क लोगों की शक्ति स्थापित हुई,तोयूरोपके व्यापारियों और मल्लाहोंने एशियाके देशों के साथ सम्पर्क रखने के लिये नये मार्गों की खोज शुरू की । इसी प्रयत्न के कारण उन्हें अमेरिका का पता लगा और वे अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत आदि प्राच्य देशों में आने जाने लगे । ,सोलहबीं और सतरहबीं सदियों में यरोपियन लोगों ने एशिया के विविध देशों के साथ त्यापारिक सम्बन्धों का विकास किया । पर इस काल में एशिया की राजनीतिक शक्ति निर्वल नहीं थी। भारत के मुगल सम्राट् और चीन के मिगवंशी सम्राट् राज्यशक्ति की दृष्टि से यूरोप के किसी राजा या सम्राट् के म्काबले में ्रीन नहीं थे। दिल्ली और पेकिंग के राजदरबार वैभव, कला, समृद्धि क सैन्यशक्ति की बृष्टि से पेरिस, वीएना व मैड्डि के राजदरबारों के मुकाबले में कहीं बढ़े चढ़े हुए थे। अठारहवीं सदी में यूरीम के लोगों ने एशिया के विविध प्रदेशों में अपने ्प्रभुत्व को स्थापित करना शुरू किया। भारत में मुगल वादशाहन इस समथ ्रिक्षिल होने लग गई थी। दिल्ली के सम्प्राटों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वै सुदूरवर्ती प्रान्तों पर अपने प्रभुत्व को कायम रख सकें। परिणाम यह हुआ, कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता से लाभ उठाकर फेञ्च और अंग्रेज लोगों ने एस देश में अपने राजनीतिक प्रमुक्त की नींव डालनी प्रारम्भ कर दी। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक अंग्रेज लोग भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गये। पर इस समय तक चीन, जापान, अरब, ईरान आदि एशियन देश यूरोप के राजनीतिक प्रभुत्व में नहीं आये थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्घ में विविध धारचात्य देशों ने पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया। वीसवीं सदी के शुरू तक यह दशा आ गई थी, कि जापान के अतिरिक्त अन्य सब एशियन देश किसी न किसी रूप में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व में आ गये थे । एक तरफ जहां भारत, वरमा, लंका, फिलिप्पीन, इण्डोनीसिया, इण्डोचायना आदि विविध देश राजनीतिक दृष्टि से किसी न किसी पाश्चात्य देश के अधीन थे. वहां नीन. तिब्बत, पर्शिया, अरब आदि देशों पर पाश्चात्य देशों का आर्थिक व अन्य प्रकार का प्रभुत्त्व स्थापित हो गया था। लेकिन एशिया पर युरोप व अमेरिका का यह प्रभत्त्व देर तक स्थिर नहीं रह सका। बीसवीं सदी के मध्य भागतक भारत, रुंका, बरमा, अरव, इण्डोनीसिया आदि सब देश पारुचात्य साम्राज्यवाद के शिकेंजे से मुक्त हो 🚅 गरें ! जो चीन पारचात्य देशों के आर्थिक साम्राज्यवाद का बुरी तरह से शिकार था, बह् न केवल पूर्व रूप रे स्वतन्त्र हो गया, अपित संसार की सर्वप्रभाग राजनीतिक शिवता में गिना जाने लगा । एशियन देशों की पराशीनता का काल बहुत देए

तक नहीं रहा । भारत सवा सवी के लगभग तक अंग्रेजों की अधीनता में रहा, और अन्य एशियन देशों की पराधीनता का काल आधी सदी से लेकर एक व सवा सदी तक रहा । मानव जाति का इतिहास हजारों साल पुराना है । यदि संसार के इतिहास की दृष्टि से एशिया के राजनीतिक अपकर्ष के काल को देखा जाय, तो वह बहुत ही छोटा प्रतीत होगा । इससे कहीं अधिक समय तक उत्तरी व पूर्वी यूरोप एशियन देशों की अधीनता में रहा था । आज एशिया स्वतन्त्र हो चुका है । उसके कुछ प्रदेशों पर पाच्चात्य देशों का जो प्रभाव व प्रमुत्त्व अब तक भी कायम है, उसे नष्ट होने में भी अधिक रामय नहीं लगेगा, यह बात सर्वथा निश्चित है । अब वह समय दूर नहीं है, जब एशिया संसार के इतिहास में फिर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका प्रमुख स्थान होगा।

इस पुस्तक में एशिया का आधुनिक इतिहास हमें लिखना है। एशिया के विविध देश किस प्रकार पारचात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए, उनमें किस प्रकार राष्ट्रीय नेतना उत्पन्न हुई, किस प्रकार उन्होंने अपनी आन्तरिक निर्बलताओं को दूर कर उन्नित के मार्ग पर कदम बढ़ाया और किस प्रकार वे विदेशी प्रभुत्व को नष्ट कर अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करने में सफल हुए—इसी का वृत्तान्त संक्षिप्त रूप से लिखना इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। अठारहवीं सदी में यूरोप में वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रारम्भ हुआ था। व्यावसायिक क्रान्ति में पहल करने के कारण पाश्चात्य देशों को यह अवसर मिल गया था, कि वे एशिया पर अपना प्रभुत्व कायम कर लें। किसी समय बारूद आदि के आविष्कार में पहल करने के कारण एशियन देश भी इसी प्रकार अपना उत्कर्ष करने में समर्थ हुए थे। पर एशिया पर पाश्चात्य संसार का यह आधिपत्य केवल सामयिक था। यूरोप के लोगों में कोई ऐसी स्वाभाविक उत्कृष्टता नहीं थी, कि वे एशियन देशों को सदा के लिये अपनी अधीनता में रख सकते। लगभग सवा सदी के समय में पाश्चात्य लेगों के उत्कर्ष का अन्त हो गया और स्वाधीन एशिया फिर से अपने उत्कर्ष में प्रवत्त हो गया। इस ग्रन्थ में हमें एशिया के इसी संघर्ष का वृत्तान्त लिखना है।

(२) एशिया महाद्वीप

एशिया की विशालता—पृथिवी के सब महाद्वीपों में एशिया सबसे अधिक विशाल है। इसका क्षेत्रफल १,७०,००,००० वर्णमील के लगभग है। उत्तरी धृष के हिममय समुद्र से शुरू होकर दक्षिण में यह भूमध्यरेखा के भी नीचे तक फैला हुना है। एशिया के लग्भीत अपेक शिप भूमध्यरेखा के दक्षिण में भी स्थित हैं। सम्पूर्ण नृमण्डल का एक किश्वरे स्थल भाग एशिया में है। इस विशाल

महाद्वीप की जनसंख्या १,२०,००,००,००० के लगभग है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से पृथिवी का अन्य कोई महाद्वीप एशिया का मुकाबला नहीं कर सकता।

एशिया में सब प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियां, जलवाय और भीगोलिक दगाएं विद्यमान हैं। जहां एक तरफ इसमें ऐसे प्रदेश हैं, जो प्रायः वारहों महीने हिम से आच्छादित रहते हैं, वहां ऐसे भी प्रदेश हैं, जहां ग्रीष्म की प्रचण्डता मनुष्य और जीव-जन्तुओं को व्याकुल कर देती है। कुछ स्थान रेगिस्तान हैं, कुछ ऊंचे पथार हैं, कुछ शस्यस्यामल उपजाऊ मैदान हैं और कुछ सघन जंगलों से आवृत हैं। पृथिवी की कोई भी ऐसी प्राकृतिक दशा नहीं है, जो एशिया में न पाई जाती हो। यहीं कारण है, कि इस महाद्वीप में बहुत सी विभिन्न जातियों का निवास है, जो सभ्यता की दृष्टि से एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इसके कुछ प्रदेशों में अब तक ऐसी जातियां बसती हैं, जो इस बीसवीं सदी में भी प्रस्तर युग से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। दूसरी तरफ इसमें ऐसे लोग भी विद्यमान हैं, जो सभ्यता के क्षेत्र में यूरोप और अमे-रिका के अत्यन्त उन्नत व सभ्य लोगों के समकक्ष हैं। पहाड़ों की गुफाओं, खाल के डेरों और फूंस के झोंपड़ों में निवास करनेवाले लोगों के साथ-साथ एशिया में ऐसे भी लोग निवास करते हैं, जो लोहे और सीमेन्ट की बनी विशाल इमारतों में रहते हैं, और जो उपरली मंजिलों तक पहुंचने के लिये बिजली के लिपटों का उपयोग करते हैं। तेल अवीव, जमशेदपुर, कोम्सोमोल्स्क सद्श एशियन नगर व्यावसायिक क्षेत्र में यूरोप व अमेरिका के प्रसिद्ध व्यावसायिक केन्द्रों का सुगमता से मुकाबला कर सकते हैं।

एतिया की एकता—एशिया में अनेक भाषाओं, अनेक जातियों, अनेक धर्मों व अनेक संस्कृतियों की सत्ता है। इस महाद्वीप के ठीक मध्य में हिमालय तथा उससे सम्बद्ध पर्वतों की एक ऐसी प्रृंखला है, जो ५००० मील के लगभग लम्बी है। इसकी अधिकतम चौड़ाई भी २००० मील के लगभग हैं। पर्वतों, निदयों, रेगिस्तानों और समुद्रों ने एशिया को अनेक ऐसे विभागों में विभक्त कर दिया है, जहां न केवल पृथक् राज्यों का अपितु पृथक् सम्यताओं का भी विकास हुआ है। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एशिया को एक नहीं समझा जा सकता। यही कारण है, कि विविध एशियन देशों का समग्र रूप से एक साथ इतिहास लिख सकना सुगम कार्य नहीं है। एशिया की विशालता और विविधता ऐतिहासिक के समगुख एक विकट समस्या उपस्थित करती है, और उसके कार्य को अत्यन्त कठिन बना देती है।

धर्म, नसल, जाति, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, भौगोलिक दशा और ऐतिहासिक परस्परा की विभिन्नता के जावजूद भी विविद्य एशियन देशों ने कुछ ऐसी समानताएँ

हैं, जो उसके निवासियों को यूरोग, अफीका व अमेरिका के लोगों से पृथक् करती हैं। अरब, भारत और चीन अत्यन्त प्राचीन समय से उन्नत सम्यताओं के केन्द्र रहे हैं। इन प्राचीन सभ्यताओं में परस्पर सम्बन्ध भी विद्यमान था। मैसोपोटामिया की प्राचीन सुमेरियन, असीरियन और वैविलोनियन सभ्यताओं का भारत की सिन्ध नदी की घाटी की सभ्यता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। प्राचीन भारतीय आर्य चीन से परिचय रखते थे और इन दोनों देशों का व्यापारिक सम्बन्ध था। ईरान, भारत, अफगानिस्तान, एशिया माइनर और मध्य एशिया में कभी एक ही आर्य जाति का विस्तार हुआ था, और इन सब देशों के धर्म व संस्कृति में बहुत कुछ समता थी । बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारत में, अपित मध्य एशिया, अफगा-निस्तान, चीन, जापान, लंका, बरमा, मलाया, स्याम, तिब्बत आदि सर्वत्र हुआ और उसके कारण एक समय में एशिया के वहत वड़े भाग में धार्मिक व सांस्कृतिक एकता की स्थापना हुई । इस्लाम के धर्म प्रचारक दक्षिणी एशिया के प्रायः सभी देशों में धर्म प्रचार के लिये गये, और उनके प्रयत्नों से एशिया के अच्छे वहे भाग में धार्मिक एकता का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और इस्लाम के कारण एशिया के निवासियों का जीयन के सम्बन्ध में एक ऐसा विशिष्ट दृष्टिकोण है, जो यूरोप व अमेरिका में कहीं भी दुष्टिगोचर नहीं होता। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भारत में हुआ था और उसके धार्मिक सिद्धान्त भारत के प्राचीन आर्य धर्म से घनिष्ठ सामीप्य रखते हैं, अतः एशिया की संस्कृति के आधारभूत सिद्धान्त इस प्रकार के हैं, जो इस महाद्वीप के वड़े भाग में समान रूप से मान्य हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत से एशियन देश एक शासन में रह नुके हैं। चंगेज खां द्वारा स्थापित मंगील साम्राज्य पूर्व में प्रशान्त महासागर से शरू कर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक विस्तत था। जराका विस्तार उत्तर में साइबीरिया तक और दक्षिण में ईरान की खाड़ी तक था। भारत का उत्तर पश्चिमी भाग भी कुछ समय के लिये मंगोल साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। चीन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक एशियन देश मंगील साम्राज्य के अधीन थे। आधुनिक समय में एशिया के बहुसंख्यक देश सूरोप और अमेरिका के ता प्राज्यवाद के समान हव ने जिकार हुए । विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप के लोगों ने जो एशिया की अपेक्षा पहले उन्नति की, उसके कारण विवित यूरोपियन देश एशिया के बड़े भाग की अपनी अधीनता व प्रभाव में छा राहने में नगर्य हुए । बीसवीं रहीं "में एशिया में सर्वत्र राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियां प्रबल होनी युक्त हुई, और पिछने उस सालों में प्रायः सनी एशियन देश युरोप व अमेरिका के सा साज्यवाद ते कृत्यारा पाने में समर्थ हुए । इस प्रकार गह स्पष्ट है कि, एशिया के इतिहास को समग्र ७५ से एक साथ छिदा मनने के लिये पर्याप्त करण विश्वमान

हैं। विशेषतया, एशिया के आधुनिक इतिहास को लिखते हुए ऐतिहासिक को जिन घटनाओं व प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना है, वे प्रायः सभी एशियन देशों के लिये एक समान हैं। एशिया अठारहवीं सदी में यूरोपियन लोगों के चंगुल में फंसना शुरू हुआ। उन्नीसवीं सदी तक प्रायः सब एशियन देश स्वेता क्ल साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में सर्वत्र जागृति प्रारम्भ हुई, और वीसवीं सदी के मध्य तक प्रायः सम्पूर्ण एशिया राष्ट्रीय स्वाधीनता स्थापित करने में समर्थ हुआ। इस इतिहास में हमें एशिया के इसी इतिवृत्त को संक्षंप के साथ उपस्थित करना है।

एशिया के विविध विभाग—भौगोलिक दृष्टि से एशिया को छः भागों में विभक्त किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इन छः विभागों का उपयोग है। ये विभाग निम्निलिखित हैं:—

(१) पूर्वी एशिया-इसमें चीन, कोरिया, मंचूरिया, जापान और प्रशान्त

महासागर के तटवर्ती विविध द्वीप अन्तर्गत हैं।

(२) दक्षिणी-पूर्वी एशिया—बरमा, इण्डो-चायना, सियाम, मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, फिलिप्पीन द्वीप समूह और प्रशान्त महासागर में स्थित हजारों छोटे बड़े द्वीप इसके अन्तर्गत हैं।

(३) उत्तरी एशिया—एशिया के जो उत्तरी प्रदेश इस समय सोवियत रूस

के अधीन हैं, उन्हें उत्तरी एशिया कह सकते हैं।

(४) एशिया का विशाल पथार या ऊर्ध्व एशिया—इसमें तिब्बत, सिंगिलियांग और बाह्य मंगोलिया के प्रदेश अन्तर्गत हैं। यह प्रदेश न केवल पर्वत प्रधान है, गर इसके भैदान भी समुद्रतट से बहुत अधिक ऊंचाई पर होने के कारण एक पथार के रूप में हैं।

(५) भारतवर्ष—भारत, पाकिस्तान, लंका और अफगानिस्तान इसके अन्तर्गत हैं। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से इस सगय ये चारों राज्य एक दूसरे से पृथक् हैं, पर भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से इनकी एकता में कोई सन्देह नहीं हो सकता।

(६) दक्षिण पश्चिमी एशिया—टर्की, अरब और ईरान इसके अन्तर्गत हैं। ये गुसलिम सभ्यता के केन्द्र हैं, और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका परस्पर घनिष्ठ

सम्बन्ध रहा है।

एशिया के इस आधुनिक इतिहास को लिखते हुए हम इन्हीं विभागों ना उपयोग करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये एक दूसरे से पृथक रहे हैं, और इनके इतिवृत्त का पृथक् रूप से निरूपण विषय को स्पष्ट करने के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

विविध विभागों का क्षेत्रफल और जनसंख्या—एशिया के इन विविध विभागों का कितना कितना क्षेत्रफल हैं, और उनमें कितने मनुष्य निवास करते हैं, इसका उल्लेख भी आवश्यक हैं। इससे यह भी भलीमांति स्पष्ट हो सकेगा, कि किस विभाग में कितने मनुष्य प्रति वर्गमील में निवास करते हैं।

LES 1141	क्षेत्रफल	जनसंख्या प्रति वर्गमील	गावादी
पूर्वी एशिया दक्षिण-पूर्वी एशिया उत्तरी एशिया पथार का प्रदेश भारतवर्षे दक्षिण-पश्चिमी एशिया	१७,००,००० १७,००,००० ६३,००,००० २८,००,००० १७,००,०००	५२,३०,००,००० १५,१०,००,००० ४,१०,००,००० १,७०,००,००० ३६,४०,००,०००	* 0 0 0 W RY RY RY RY
सम्पूर्ण एशिया सम्पूर्ण पृथिनी (स्थल)	8,89,00,000 4,00,00,000	१,१८,१०,००,००० २,१५,५०,००,०००	86

इस तालिका से स्पष्ट है, कि एशिया के कतिपय प्रदेशों में जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात से बहुत अधिक है। चीन और जापान में ३०८ गनुष्य प्रति वर्गमील में रहते हैं, इसी तरह भारतवर्ष की आबादी प्रति वर्गमील में २३२ है। इसके विपरीत सोवियत रूस द्वारा अधिकृत उत्तरी एशिया में आबादी बहुत कम है । वहां एक वर्गमील में केवल सात मनुष्यों का निवास है। इसी प्रकार तिब्बत, सिंग-मियांग और बाह्य मंगालया के पथार में एक वर्गमील में केवल छः मनुष्यों की आवादी है। अरब के दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में भी क्षेत्रफल के अनुपात से वहत कम मनुष्यों का निवास है। अब तक इतिहास में प्राकृतिक परिस्थितियां जनसंख्या पर बहुत प्रभाव डालती थीं। शस्य स्यामल उपजाऊ प्रदेशों में अधिक मनुष्य बसते थे, और रेगिस्तान, पयार व झाड़ियों से आच्छादित प्रदेशों में मनुष्य को अपने लिये भोजन व अन्य सामग्री इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थीं, कि वहां जनसंख्या अधिक बढ़ सके। यही कारण है, कि उत्तरी एशिया व एशिया के विशाल पथार में अधिक जनसंख्या नहीं हो सकी । पर आधुनिक युग में जो वैज्ञानिक उन्नति हुई है, उनके कारण इस दशा में बहुत परिवर्तन हो गया है। भनुष्य विज्ञान की सहायगा से छजाए प्रदेशों की खेली के लिये उपगुरूत बना सकता हैं, जोर वह रेकिस्तान, प्रभार शांदि में भी ऐसे पदार्थों की आपत कर सकते की आसा रखना है, जो मानव के हित और करवाण के जिये अत्यन सहायके हों। इसी- लिये एशियामें सोवियत इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ६३ लाख वर्गमील का जो विशाल भूखण्ड उसके संघराज्य के अन्तर्गत है, वह भविष्य में उसकी रामृद्धि में बहुत सहायक हो सकता है। यही कारण है, कि तिब्बत, सिंगिकयांग और बाह्य मंगोलिया के प्रदेशों पर विविध उन्नत देश अपना आधिपत्य व प्रभाव स्थापित करने के लिये उत्सुक हैं। भारत, चीन और जापान में जो एक अरब के लगभग लोग निवास करते हैं, वे भी विश्व की राजनीति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण अस्व-शस्त्रों का चाहे युद्ध के लिये कितना ही महत्त्व बढ़ गया हो, पर वर्तमान समय में भी अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के लिये कनसंख्या का यहुत महत्त्व हैं। एशिया के विविध प्रदेशों में जनसंख्या का जो अन्तर हैं, वह भी आधुनिक इतिहास पर बहुत प्रभाव डालता है। जापान जो साम्राज्य विस्तार के लिये विशेष इप से तत्पर हुआ, उनमें उसकी अत्यधिक जनसंख्या भी एक महत्त्वपूर्ण कारण थी। भारत के लोग जो बहुत बड़ी संख्या में अन्य देशों में मजदूरी आदि की तलाश में गये, उसमें भी इस देश की सघन आवादी एक बड़ा कारण थी। इसमें सन्देह नहीं, कि भविष्य में एशिया की जनसंख्या की यह विभिन्नता एशिया महादीप के इतिहास पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगी।

(३) एशिया के आधुनिक इतिहास का विषय विभाग

एशिया अत्यन्त विशाल महाद्वीप है, और भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से इसे अनेक विभागों में विभवत किया जा सकता है। यह सम्भव नहीं है, कि सम्पूर्ण एशिया के इतिहास को एक देश के इतिहास के रूप में लिखा जा सके। एशिया के आधुनिक इतिहास की जिन बातों पर हमें विशेष रूप से प्रकाश डालना है, थे निम्निक्लिखत हैं:—(१) एशिया के विविध देश किस प्रकार पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए। (२) साम्राज्यवाद के शिकार होने के समय इन देशों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आधिक दशा किस प्रकार की थी। इन देशों में वे कौन सी निवंलतायें थीं, जिनके कारण ये इतनी सुगमता से साम्राज्यवाद के शिकार हो गये। (३) इन देशों में किस प्रकार राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई और ये किस प्रकार उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुए। (४) किस प्रकार इन देशों ने पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकां से छुटकारा पाकर स्वतन्त्रता प्राप्त की और अब इन देशों की क्या दशा है ?

इन बातों पर विचार करने के लिये हम एशिया के आधुनिक इतिहास का विपय विभाग इस प्रकार कर सकते हैं—

(१) चीन और जापान—इन्हीं को हमने पहले पूर्वी एशिया के नाम से

कहा है। उधीसवीं सदी के मध्यभाग में पाश्चात्य देशों ने इनमें अपने प्रभुत्य की स्थापना शुक्त की। जापान शीन्न ही विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ हुआ और पाश्चात्य देशों के समान स्वयं भी साम्राज्यवाद के प्रसार के लिये तत्पर हुआ। जापान के साम्राज्यवाद का क्षेत्र प्रधानतया चीन था, अतः इन दोनों देशों का इतिहास एक दूसरे से सम्बद्ध है। इनके इतिहास को हमने इस ग्रथ्य में हमने एक साथ लिखा है। तिब्बत और सिगिकियांग के प्रदेश चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत हैं, और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका चीन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। अतः इनका इतिहास भी चीन और जापान के साथ घलिष्ट सम्बन्ध रहा है। अतः इनका इतिहास भी चीन और जापान के साथ लिखना ही उचित और क्रियात्मक है। राजनीतिक दृष्टि से मंगोलिया वो भागों में विभक्त हैं, बाह्य मंगोलिया और आभ्यन्तर मंगोलिया। इस समय बाह्य मंगोलिया में सोवियत रिपब्लिक विद्यमान है और आभ्यन्तर मंगोलिया चीन का एक भाग है। अतः आभ्यन्तर मंगोलिया का इतिहास की कुछ घटनाएं जहां चीन के साथ अवेंगी वहां उसका मुख्य इतिहास कस के साथ दिया जायगा।

(२) विक्षण-पूर्वी एशिया—इस क्षेत्र में जो अनेक देश व द्वीप सम्मिलित हैं, वे उन्नीसवीं सदी में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्त्व में आये। त्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, फेंच और अमेरिकन लोग इनमें अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। इनका

इतिहास हम पृथक् रूप से लिखेंगे।

- (३) उत्तरी एजिया—इस सुविस्तृत प्रदेश में इस ने अपने आधिपत्य का विस्तार किया। यह अब भी इस के अधीन है। इस में इस समय समाजवादी व्यवस्था के अनुसार शासनसूत्र का पुनः संगठन हो चुका है और उत्तरी एशिया के प्रदेश को विविध सोवियत रिपब्लिकों के इप में संगठित कर विया गया है, और ये रिपब्लिकों इसी सोवियत संघ के अन्तर्गत हैं। इस क्षेत्र में इस के प्रभुत्त्व का किस प्रकार विकास हुआ और फिर किस प्रकार इसमें स्वतन्त्र समाजवादी रिपब्लिकों की स्थापना हुई, इसका वृत्तान्त पृथक् इप से ही विया जाना उचित है। बाह्य मंगोलिया और मध्यएशिया के प्रदेशों में भी इस समय सोवियत रिपब्लिकों स्थापन हैं। गढ़िन्हें ने ज्यो साप्राज्यवाद के शिकार हुए और फिर इस में समाजवादी व्यवस्था के स्थापत होने पर उन्हें पृथक् व स्वतन्त्र रिपब्लिकों के इप में परिणत किया गया। अतः उनका वृतान्त भी उत्तरी एशिया के साथ देना ही अधिक कियात्मक होगा।
- (४) दक्षिण-विश्वम एशिया --- इसमें टकीं, अरव और ईसन सम्मिलित हैं। ये सब मुसलिम राज्य हैं, और इनका इतिहास प्रायः अन्य एशियन देशों से पृथक रहा

है। अरव पहले तुर्की सामाज्य के अन्तर्गत था। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में वह टर्की की अधीनता से मुक्त हुआ, पर यूरोपियन देशों के प्रभाव में आ गया। वाद में उसने पाश्चात्य प्रभाव से रवतन्त्रता प्राप्त की। ईरान ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यवाद का शिकार हुआ और अब तक भी वह इन देशों के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सका हैं। ऐतिहासिक वृष्टि से अफगानिस्तान का सम्बन्ध भारत से अधिक रहा है। पर क्योंकि इस ग्रन्थ में हम भारत का इतिहास विश्वद रूप से नहीं लिखेंगे, अत: अफगानिस्तान की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य मुसल्मि देशों के साथ करना ही क्रियात्मक होगा।

(५) भारतवर्ष एशिया के आधुनिक इतिहास में भारतका बहुत अधिक महत्त्व हैं। पर क्योंकि इस ग्रन्थ के पाठक भारत के इतिहास से भलीभांति परिचित्त होंगे, अतः हमारे लिये यह उचित नहीं होगा, कि उस पर हम संक्षेप के साथ भी प्रकाश डालें। यदि एशिया का आधुनिक इतिहास भारतीयों के अतिरिक्त अध्य देशों के पाठकों के लिये लिखा जायगा, तो उसमें भारत के इतिहास थो चीन और जापान के वृत्तान्त के समान ही प्रमुख स्थान दिया जायगा। पर हम भारत के इतिहास की केवल उन घटनाओं का ही उल्लेख करेंगे, जो अन्य एशियन देशों के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्ब ध रखती हैं।

इस प्रन्थ में एशिया के आधुनिक इतिहास को लिखते हुए हम इसी विषय विभाग का उपयोग करेंगे।

(४) वीन का प्राचीन इतिहास

एशिया के आधिन इतिहास को मलीभांति समझने के लिये यह आवश्यक हं, कि हम उसके प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास का भी संक्षेप के साथ उल्लेख करें। पर विध्य के प्रतिपादन की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी होगा, कि हम एस प्रकरण में पहले केवल पूर्वी एशिया और विशेषतया चीन के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश हालें। अन्य एशियन देशों के प्राचीन इतिहास का निदर्शन तभी अधिक उन्युक्त होगा, जब हम इन देशों के आधुनिक इतिहास को शुरू करेंगे।

प्राचीन चीन जनरी चीन में अनेक स्थानों पर पुरातन प्रस्तर गुग के अवशेष मिले हैं। इससे सूचित होता है, कि प्राचीन काल में भी इस देश में मनुष्य जाति का निवास था, और चीन के ये प्राचीनतम निवासी सभ्यता के मार्ग पर अप्रसर होना शुरू कर चुके थे। चीन में कई स्थानों पर नूसन प्रस्तर गुग के भी अवशेष मिले हैं। ये लोग पत्थर के वने हुए सुन्दर उपकरणों का प्रयोग करते

थे, बरतन बनाते थे और खेती द्वारा अनाज उत्पन्न करना भी प्रारम्भ कर चुके थे।

पर चीन में सबसे पहली उन्नत सभ्यता का विकास ह्वांग हो और यांग— हसे कियांग निवयों की घाटियों में हुआ। ये दोनों निवयां तिब्बतकी उत्तरी पर्वतमाला में निकलती हैं, और हजारों मील की यात्रा कर प्रशान्त महासागर में मिल जाती हैं। इन निवयों के तत्व्वर्ती प्रदेश बहुत उपजाऊ हैं। बहुत प्राचीन काल में मनुष्यों ने इनमें बस कर खेतीऔर पशुपालन करके अपना निर्वाह प्रारम्भ किया था। धीरे धीरे उनकी बहुत सी बस्तियां इस प्रदेश में बस गईं। शुरू में ये बस्तियां नगर— राज्यों के रूप में थीं। प्रत्येक बस्ती एक स्वतन्त्र और पृथक राज्य थी, और अपना शासन स्वयं करती थी।

सामन्त पद्धति-इन बस्तियों के पड़ोंस में बहुत सी ऐसी जातियों का निवास था, जो अभी पशुपालक दशा में थीं। समय-समय पर वे इन सभ्य बस्तियों पर हमले करती रहती थीं। उनसे अपनी रक्षा करने के लिये प्राचीन चीन के नगर-राज्यों में अनेक ऐसे वीर व्यक्ति उत्पन्न हुए, जिन्होंने बाकायदा सेनाओं का संगठन कर आकान्ताओं का मुकाबला किया। उनकी सूसंगठित सेनाओं के कारण पश्यालक जातियों के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वे चीन के नगर-राज्यों पर हमले कर सकें। पर जिन वीर पुरुषों ने विदेशियों के आक्रमणों से अपने देश की रक्षा की थी, शीघ्र ही उन्होंने अपने राज्यों में भी अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। अपनी सेनाओं द्वारा उन्होंने विविध नगर-राज्यों के शासन को अपने हाथों में ले लिया, और उनमें वे स्वतन्त्र राजाओं के समान शासन करने लगे। चीन के इन प्राचीन राजाओं की संख्या हजारों में थी। बाद में वे अपनी शक्ति का विस्तार करने में प्रवत्त हए, और धीरे-धीरे कुछ प्रतापी राजाओं ने अन्य राजाओं को जीतकर अपने विस्तत साम्राज्य स्थापित किये। इस प्रकार स्वतन्त्र राजाओं की संख्या कम होने लगी, और कुछ समय बाद ऐसे विक्तवाली सम्राटों का विकास हुआ, जिन्होंने ह्यांगही और यांग-त्से-कियांग नदियों की घाटियों के सब राजाओं को जीतकार अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार के पहले चीनी चकवर्ती सम्राट शांग वंश के थे। इस वंश ने १६५० से ११२५ ई० पू० तक शासन किया। शांग वंश के बाद चाऊ वंश का शासन ११२५ से २५० ई० पूर तक रहा। पर इन दोनों राजवंशों के शासन काल में विविध राजाओं का अन्त नहीं हो गया था, सम्राट की अधीनता में सामन्त रूप से उनकी तत्ता कागण थी। ये सामन्त राजा समाह की निर्वेकता से लाम उठाकर विम्रोह कर देने और स्वच्छन्द रूप संभारत करने के दिये गया नत्पर पहते थे। यही कारण है, कि इस काल में चीन

में शान्ति और व्यवस्था नहीं थी। चौथी सदी ई० पू० तक यह दशा हो गई थीं, कि विविध सामन्त राजा सम्राट की सत्ता की सर्वथा उपेक्षा कर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लग गये थे।

सम्राट तिश्वन शी—इस दशा में तीसरी सदी ई० पू० में चीन में एक शिवतशाली सम्राट का उदय हुआ, जिनका नाम तिशन-शी था। इसने चीन के विविध राजाओं और सामन्तों को जीतकर अपने अधीन किया और देश में एक व्यवस्थित शासन की स्थापना की। इस समय चीन पर हुण लोगों के आक्रमण बड़ी तीक्रता के साथ जारी थे। हुण लोग असम्य और जंगली थे। वे चीन के उत्तरी प्रदेश में निवास करते थे। उनका मुकाबला करने के लिये सम्राट त्थान थी ने तीन लाख सैनिकों की एक शिवतशाली सेना का संगठन किया। इस सेना के सम्मुख हुण लोग नहीं टिक सके। उनके हमले बन्द हो गये। भविष्य में हुण लोग फिर हमले न करें, इसके लिये सम्राट त्थान शी ने एक विशाल दीवार का निर्माण किया, जो लम्बाई में १८०० मील है। इस दीवार के बन जाने से असम्य व जंगली जातियों से चीन की रक्षा कर सकना सुगम हो गया। इसके कारण चीन एक विशाल दुर्ग के रूप में परिवित्तत हो गया, जिसमें स्थान-स्थान पर सेनाएं रखकर बाहरी आक्रमणों के भय को बहुत कुछ दूर किया जा सकता था। १८०० मील लम्बी दीवार को बनवा सकता सुगम बात नहीं थी। सम्राट त्थान शी का शासन कितना समृद्ध व उन्नत था, चीन की दीवार इसका प्रमाण है।

हूगों के आक्रमण से निश्चिन्त होकर चीनी लोगों ने मंचूरिया, मंगोलिया, चुिक्स्तान और तिब्बत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्शिन शी के समय में चीन में जो उन्नित शुरू हुई थी, वह उसके बाद भी जारी रही। तिब्बत से मंचूरिया तक एकछत्र साम्राज्य स्थापित हो जाने से चीन की शक्ति व समृद्धि बहुत बढ़ गई। वह संसार के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा।

प्राचीन धर्म—चीन के लोग प्राचीन समय में विविध देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रत्येक वस्ती के अपने अपने पृथक देवता थे। कुछ देवता ऐसे भी थे, जिन्हें चीन के सब निवासी मानते थे। इनको सन्तुष्ट रखने के लिये वे विविध प्रकार के विधि विधानों और पूजा पाठ का अनुष्ठान करते थे। राजा जहां अपने राज्य का शासक होता था, वहां साथ ही वह उसके देवताओं का प्रधान पुजारी व धर्माचार्य भी होता था। इसी कारण जनता उसे देवतुल्य मानती थी। इस दृष्टि से संगार की जायः सभी पाचीन सभ्यताओं में समता है।

पर छठी सदी ईस्वी पूर्व में चीन में एक विचारक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम कन्फ्यूसियस था। वह लू नामक एक छोटे से राज्य का निवासी था। उसने धर्म के सम्बन्ध में एक नई कल्पना अपने देशवासियों के सम्मुख पेश की। वह कहता था, विविध देवी देवताओं की पूजा की अपेक्षा सदाचारमय और पवित्र जीवन मनुष्य के लिये अधिक हितकारी है। मनुष्य का यह ध्येय होना चाहिये, कि वह अपने जीवन को पवित्र व परोपकारी बनावे। संसार में हमें सब ओर कच्ट नजर आता है। इस कच्ट को दूर करने का उपाय यही है, कि संसार के सब मनुष्य एक दूसरे की सहायता करें। मनुष्य केवल अपने लिये ही न जिये, अपितु सबकी सुख-समृद्धि में ही अपना हित समझे। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब कि मनुष्यों का जीवन अधिक ऊंचा और मर्यादित हो। मानव समाज के कच्टों का तभी अन्त हो सकता है, जब कि प्रस्येक मन्ष्य अपने जीवन को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करे। अपने विचारों के प्रचार के लिये कन्पयुसियस ने एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की, और गुरु बिड्य परम्परा द्वारा उसके विचार धीरे-धीरे सारे उत्तरी चीन में फैल गये। लगभग इसी समय में भारत में महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने भी इसी प्रकार के विचार अपने देशवासियों के सम्मुख रखे थे । इसमें संदेह नहीं, कि कन्पयुसियस और महातमा वृद्ध जैसे महापुरुषों द्वारा संसार में एक नये प्रकार के धार्मिक आन्दोलन का मुत्रपात हुआ, जो पुराने समय के विधि विधानों और अनुष्ठानों से पूर्ण धर्म से बहुत भिन्न था।

इसी समय के लगभग चीन में एक अन्य विचारक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम लाओ तसे था। यह कहना था, मनुष्य को भोग विलास के जीवन से बचकर पिवत्र और सावा जीवन विताना चाहिये। कन्प्यूसियस जीवन के नियन्त्रण और विनय पर बहुत जोर देता था। लाओ तसे की शिक्षाओं का सार यह था, कि मनुष्य त्याग की ओर जाय और तपस्या का जीवन विताये। उसकी शिक्षाओं का भी बहुत प्रचार हुआ। विशेषतया, दक्षिणी चीन में बहुत से लोग लाओ तसे के अनुयायी हो गये। इस समय भी चीन में कन्प्यूसियस और लाओ तसे की शिक्षाओं का बड़ा प्रचार है। यद्यपि वहां के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, पर के इन वो पुराने आचारों को भी बड़ें आदर की दृष्टि से देखते हैं, और इनके विचारों का उन पर बड़ा प्रभाव है।

सभ्यता—चीन के प्राचीन निवासियों ने सम्मता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति की थी। बहुत पुराने समय में हा उन्होंने किन्ने ना आनिप्तार कर किया था। ईजिएट के समान उन्नी लिपि भी एक प्रकार की चित्रलिप थी। कला में भी वे बड़े प्रवीण थे। गड़ी के नमकील बरान बनाने में वे अस्पन्त कुशल थे। रेशम के कीड़ी को पालकर उनसे रेशम तैयार करना और फिर उसके सुन्दर बस्क बनाना उनका प्रमुख व्यवसाय था। आजकल भी चीन का रेशम संसार भर में प्रसिद्ध है। बहुत पुराने समय में भी चीनी रेशम दूर-दूर तक विदेशों में किकने के लिये जाता था।

खेती के लिये पुराने चीनी लोगों ने बहुत सी नहरों का निर्माण किया था। ह्वांगहों और यांग-स्से-कियांग निर्द्यों से अनेक छोटी छोटी नहरें निकाल कर उन छोगों ने अपने खेतों की सिंचाई करने का बड़ा उत्तम प्रवन्ध कर रखा था। यहां कारण है, कि प्राचीन चीन में भोजन की प्रचुरता रहती थी और उसकी सुख-समृद्धि से आकृष्ट होकर विविध जंगली और पशुपालक जातियां उस पर हमलें करती रहती थीं।

चिन वंश—सम्राट त्शिन शी चिनवंश का था, उसी के वगरण इस देश का नाम चीन पड़ा।

सम्राट िरशन शी ने जहां एक तरफ हुणों से अपने देश की रक्षा करने के लिये १८०० मील लम्बी विशाल दीवार का निर्माण शुक् किया, वहां साथ ही उसने यह भी अनुभव किया, कि देश की उन्नति के लिये ऐसा उपाय करना नाहिये, जिससे चीन के विविध राज्य अपनी पृथक् सत्ता को एकदम भूल जावें। उसने सोचा, इसका सर्वोत्तम उपाय यह है, कि चीन के लोगों को अपने पुराने इतिहास का ज्ञान न रहे। पुराने समय में जिन नगरों व राज्यों ने अच्छी उन्नति की थी, जिन विद्वानों के ग्रन्थों का उन्हें अभिमान था, उन सबको वे विस्मृत कर दें। इस उद्देश्य से त्यान शी ने यह आज्ञा जारी की, कि पुराने समय की सब पुस्तकों को अग्न के रखा ज्ञाय! चीन के विद्वानों को अपनी पुरानो पुस्तकों से बहुत प्रेम था। उन्होंने इन्हें छिपाकर बचाने का यत्न किया। परिणाम यह हुआ, कि सैकड़ों चीनी विद्वानों को जीते जी जमीन में गाड़ दिया गया। सम्बाट त्यान शी तीसरी सदी ई० पू० में हुआ था। भारत में इसी समय के लगभग सम्बाट अशोक का जासन था। चीन और भारत के इन सम्बाटों की नीति में कितना अन्तर था।

हान वंश—२०९ ई० पू० में त्यान शी की मृत्यु हुई। उसके बाद विशाल चीनी साम्राज्य की राजगद्दी के लिये झगड़े शुरू हो गये। इस स्थिति से लाभ उठाकर हान वंश के एक साहसी व्यक्ति ने चिन वंश का अन्त कर एक नये वंश का प्रारम्भ किया। यह हान वंश २०६ ई० पू० से शुरू होकर २२० ई० प० तक कायम रहा। त्यान शी के प्रयत्न से चीन में जो राजनीतिक एकता कायम हुई थी, हान सम्राटों के शासन में वह स्थिर रही। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट वून्ती था। उसके समय में चीनी साम्राज्य अपने विस्तार की चरम सीमा तक

पहुंच गया था। पूर्व में प्रशान्त महासागर से पश्चिम में कैस्गियन सागर तक जसका एकछत्र शासन था। मध्य एशिया की सब जातियां उसकी अधीनता स्वीकृत करती थीं। हान वंश के इस चीनी साम्राज्य का विस्तार शिकन्दर के मैसिडोनियन साम्राज्य व ट्राजन के रोमन साम्राज्य की अपेक्षा वहुत अधिक था।

हान वंश के शासन काल में बौद्ध धर्म का चीन में प्रवेश हुआ। अशोक के समय में बौद्ध भिक्षुओं ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये बिदेशों में जाना प्रारम्भ किया था। धीरे धीरे सम्पूर्ण चीन वौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। बौद्ध भिक्षु केवल चीन में ही मगवान बुद्ध के सन्देश को पहुंचा कर संतुष्ट नहीं हो गये, वे और आगे बढ़े और कोरिया तथा जापान में भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण चीन और भारत का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया। भारत से बहुत से व्यापारी समुद्ध के मार्ग से व्यापार के लिये चीन जाने लगे। चीन का व्यापारिक सम्बन्ध रोम के साथ भी स्थापित हुआ। पहली सदी ई० पू० में रोम का साम्राज्य पूर्व में कैस्पियन सागर और टिग्निस नदी तक विस्तृत हो गया था। उधर चीनी साम्नाज्य की पश्चिमी सीमा कैस्पियन सागर को छूती थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि इन दोनों साम्नाज्यों में परस्पर व्यापार की उन्नति हो।

हान बंश के शासन काल में चीन में छापेखाने का आविष्कार हुआ। लक्ष्मी के ब्लाक बनाकर चीनी लोग उन्हें पुस्तकें छापने के लिये प्रयुक्त करने लगे। इस रामय तक परिचमी संसार में कहीं भी छापेखाने का प्रवेश नहीं हुआ था। सिकन्दरिया आदि के विविध पुस्तकालयों में पुस्तकों की नकल करने का ही रिवाज था।

हानवंश के शासन में ही चीन में उस परीक्षा पद्धति का सूत्रपात हुआ, जो वहां दो हजार वर्ष तक कायम रही। इस समय अन्य देशों में राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिये किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। राजकुल अ उच्च कुल के अमीर उमराओं को विविध पदों पर नियत कर दिया जाता था। किस पद पर कौन व्यक्ति नियत किया जाय, यह बात राजा की इच्छा व कृपा पर आश्रित थी। पर हान सम्राटों ने चीन में विविध राजकीय पदों पर नियुक्ति के लिये परीक्षापद्धति को शुरू किया। जो व्यक्ति चीन के पुरातन ग्रन्थों और विद्याओं में निष्णात हों, और राज्य द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जावें, वे ही विविध राजकीय पदों पर नियत किये जाते थे। जन्म, कुल आदि का कोई भेव इसमें नहीं किया जाता था। जो भी व्यक्ति इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जावें, राजकीय पदों को वह प्राप्त कर सकता था।

तीन राज्य हान वंश के शिन्तशाली राजाओं का वैभवपूर्ण व विशाल साम्राज्य तीसरी सदी ई० प० में समाप्त हो गया। अनेक सिदयों के सुदृढ़ शासन ने भी चीन में भलीभांति एकता उत्पन्न नहीं की थी। परिणाम यह हुआ, कि २२० ई० प० के लगभग चीन तीन भागों में विभक्त हो गया। यह दशा सातवीं सदी के शुरू तक रही। इस बीच में भारत के बौद्ध भिक्षु वड़ी संख्या में चीन गये, और वहां उन्होंने न केवल अपने धर्म का, अपितु अपने ज्ञान, विज्ञान और कला का भी प्रसार किया। चीन के लोग इस समय भारत को अपनी धर्मभूमि समझते थे। इसी कारण बहुत से चीनी यात्री इस समय भारत आये, और उन्होंने यहां आकर विविध विद्यापीठों में धर्म और वर्शन का अध्ययन किया। इन चीनी यात्रियों में फाइयान और हचुन्त्सांग सबसे प्रसिद्ध हैं। फाइयान चौथी सदी ए० पू० में भारत आया था, और सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में उसने भारत का भ्रमण किया था। हचुन्त्सांग सातवीं सदी के शुरू में भारत आया था। उस समय देश का सबसे शिन्तशाली राजा हर्षवर्धन था। हचुन्त्सांग में नालन्दा विद्यापीठ में रहकर बौद्ध धर्म का विशद रूप से अनुशीलन किया।

तांग वंश—६१८ ई० प० में चीन में तांग वंश का शासन शुरू हुआ। इस वंश का पहला राजा काओ त्सु था। वह बड़ा बीर और महत्वाकांशी था। उसने सम्पूर्ण चीन को जीतकर फिर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। अनाम और कम्बोडिया के राज्य भी उसने विजय कर लिये। उसने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कैस्पियन सागर तक विस्तृत थी। तांग वंश का शासन ९०७ ई० प० तक कायम रहा।

तांग सम्राटों के जासन काल में चीन ने बहुत उन्नति की थी। तांग सम्राट बड़े उदार और वैभवपूर्ण थे। उन्होंने विदेशी व्यापार को उन्नत करने के लिये अनेक यत्न किये। वे विदेशियों का आदर करते थे, और उनसे नई-नई बातें सीखने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। यही कारण था, कि ईसाई और मुसलिम धर्म के प्रचारक भी बड़ी संख्या में इस समय चीन गये। चीन के लोग इस धर्म प्रचारकों का आदर करते थे, और रोमन सम्राटों के समान तांग वंशी सम्राट धर्म के मामले में संकीण हृदय व असहिष्णु नहीं थे।

व्यवस्था और शक्ति का अभाव था। यही दशा यूरोप में भी थी। रोमन साम्राज्य इस समय खण्ड-वण्ड हो चुका था। पश्चिमी एशिया में कुछ समय के लिये अरबों ने एक व्यवस्थित साम्राज्य कायम किया था, पर वह भी देर तक स्थिर नहीं रह मना था। गंगार के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में इन सिदयों में चीन का साम्राज्य बहुत व्यवस्थित और शान्तिमय था। यही कारण है, कि इस युग में चीन संसार का शिरोमणि था। छापेखाने के विकास क साथ-साथ चीनी लोगों ने ही पहले पहल बाहद और बादूक का आविष्कार किया। इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय चीन संसार में गबसे अधिक उन्नत देश था।

हास का काल—पर सुङ्ग वंश का शासन देर तक स्थिर नहीं रहा । बारहवीं सदी के शुरू में चीन में फिर अनेक राज्य स्थापित हो गये । इनमें तीन प्रमुख थे—(१) उत्तर में किन राज्य, (२) दक्षिण में सुङ्ग राज्य और (३) उत्तर-पश्चिम में हिंसया राज्य।

इस प्रकार जब चीन में कोई एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रहा था, चीन के उत्तरी प्रदेशों में एक नई जाति का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ, जिसने कुछ ही समय में न केवल सम्पूर्ण चीन को, अपित् पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप को भी विजय कर एक अत्यन्त विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह शक्ति मंगोल लोगों की थीं, और इनका प्रधान नेता चंगेज खां था।

भंगोल जाति—वारहवीं सदी में जीन के उत्तरी प्रदेशों में एक पशुपालक जाति का निवास था, जिसे मंगोल कहते थे। शिकार और पशुपालन इसके मुख्य व्यवसाय थे। मंगील लोग प्रधानतया घोड़ों को पालते थे, और डेरों में निवास करते थे। उनकी कोई स्थिर बस्तियां व नगरियां नहीं थीं। बारहवीं सदी के अन्तिम भाग में इस जाति में एक ऐसे वीर नेता का प्रावुर्भाव हुआ, जिसने इसे एक प्रवल राजनीतिक शिवत बना दिया। इस नेता का नाम चंगेज खां था। उस समय मंगोल लोग देवी-देवताओं की पूजा करते थे, और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये विधिव विधि-विधानों का अनुष्ठान करते थे। चंगेज खां के नाम से यह भ्रम नहीं होना चाहिये, कि वह मुगलमान था। मंगोल लोगों के सरदारों की उपाधि खां या खान होती थी।

खंगेज को का साम्राज्य जिन दिनों उत्तरी चीन में किन वंश के चीनी गुआरों का शायान था। मंगीयों ने किन गायाज्य के विकत विद्रीह कर अपने की हरका श्रीपेट कर दिया। अन उन्होंने किन गायाज्य कर हरका लिया, वह प्रवास हो गात और उराजी राजधानी पेकिंग चंगेज को के हाथ में आ गई। पेकिंग की मह विजय १२१४ है हों की गई थी। उत्तरी चीन के प्रिक्त में उद्दर्श है हों की गई थी। उत्तरी चीन के प्रिक्त में उद्दर्श है हों की गई थी। उत्तरी चीन के प्रिक्त में उद्दर्श है हों की गई थी।

समय तुर्क जाति का एक शक्तिशाली साम्राज्य विद्यमान था, जिसकी राजधानी खीवा थी। खीवा का तुर्क राज्य बहुत प्रवल था। धीरे-धीरे उसके सम्राटों ने पड़ोस के अन्य राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति का बहुत विस्तार कर लिया था। युफेटस और टिग्निस निदयों से शुरू कर पूर्व में तिब्बत की सीमा तक खीवा का तुर्क साम्राज्य विस्तृत था। चंगेज खां की सेनाओं ने इस तुर्क साम्राज्य पर हमला किया। मंगोल सेना के सम्मुख तुर्क लोग नहीं टिक सके। खीवा का सम्मूण साम्राज्य चंगेज खां के हाथ में आ गया।

पर चंगेज लां की साम्राज्य की भूल लीवा के तुर्कों का विनाश करके ही शान्त नहीं हो गई। वह पश्चिम और उत्तर में निरन्तर आगे बढ़ता गया। कैल्पियन सागर के उत्तर में रूस पर उसने हमला किया। रूसी लोग उसका मुकाबला नहीं कर सके। काला सागर (ब्लैक सी) के उत्तर में कीफ में रूसी सेना गंगील लोगों द्वारा बुरी तरह परास्त हुई। रूस का राजा मंगोलों के हाथ कैद हो गया। इंसी समय एक अन्य मंगोल सेना ने भारत पर आक्रमण किया। उत्तरी भारत में इस समय अफगान सूलतानों का शासन था। तर्क विजेता महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर कन्नौज के शक्तिशाली राजा व अन्य विविध राजाओं को परास्त कर इस देश में भी तुर्क शासन स्थापित किया था। तुर्की का शासन उत्तरी भारत में देर तक कायम नहीं रहा । गजनी के पड़ोस में एक छोटा सा अदेशथा, जिसे गोर कहतेथे। जब गजनी व तुर्क सुलतानों की शक्ति कमजोर पड़ी, ज़ो गोर स्वतन्त्र हो गया, और उसके अफगान सरदार अलाउदीन ने गजनी को भी जीतकर अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, और बारहवीं सदी के अन्त में उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया । चंगेज खां के समय में भारत के उत्तरी प्रदेशों में अफगानों का ही शासन था। मंगोल सेनाओं ने भारत पर हमला किया और लाहौर तक के प्रदेश को जीतकर अपने अधीन कर लिया। इस समय अफगान सल्तनत मा स्वामी अल्तमश (१२११-३६ ई०) था। वह चंगेज खां के राम्मृख असहाय था।

१२२७ ई० में चंगेज लां की मृत्यु हुई। उसका साम्राज्य प्रशान्त महासागर से शुरू होकर काला सागर तक विस्तृत था। सिकन्दर जैसे विजेताओं के साम्राज्य चंगेज लां के साम्राज्य की तुलना में तुच्छ थे। इस विशाल मंगोल की साम्राज्य की राजधानी उत्तरी चीन में कराकुरम थी। यह मंगोलों की सबसे बड़ी बस्ती थी। इस प्रदेश को अब तक भी मंगोलिया कहते हैं, उसका कारण ये मंगोल लोग ही हैं।

जगदई खां- १२२७ ई० में विशाल मंगील साम्राज्य का अधिपति उगदह सां बना । वह चंगेज सां का लड़का था, और अपने पिता के समान ही वीर और साहसी था। उगदई खां ने मंगोल साम्राज्य को और अधिक विस्तत किया। काला सागर से आगे बढ़वार उसके भाई बातु खां ने सम्पूर्ण इस की अपने अधीन निया, और पोलैण्ड पर आक्रमण कर उस देश को भी जीत लिया । इसके हमलों के कारण युरोप में खलबली मच गई। उस समय पितृत्र रोमन सम्राट के पद पर फोडरिक द्वितीय विराजमान था। उसने अपनी जर्मन सेनाओं के साथ उगदर्ड खां का मुकाबला करने की कोशिश की । पर उत्तर-पूर्वी जर्मनी में १२४१ ई० में जर्मन सेनाएं मंगोलों द्वारा परास्त कर दी गईं। बातू खां शायद यूरोप में और भी आगे बढ़ता, पर इसी समय (१२४२ ई०) उगदई खां की मृत्यु हो गई। विशाल मंगोल साम्राज्य का स्वामी कौन हो, इस बात को लेकर झगड़े शुरू हो गये और पश्चिमी यूरोप मंगोल लोगों के आक्रमणों से बच गया। उगदई खां के समयमें ही एक अन्य मंगोल सेना ने दक्षिणी चीन पर हमला किया। इस प्रदेश में उस समय सुंग वंश का राज्य था। सुंग सम्राट् मंगोलों का मुकावला नहीं कर सके। धीरे-धीरे उनका सब राज्य भी मंगोलों के हाथ में आ गया, और सम्पूर्ण चीन मंगोल साम्राज्य में शामिल हो गया।

मंगू लां—जगदई सां का उत्तराधिकारी कीन हो, इस बात को लेकर कुछ समय तक झगड़ें चलते रहें। अन्त में मंगू ला १२५१ ई० में विशाल मंगोल साम्राज्य मा अधिपति बना। उसके समय में मंगोल साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। चीन पहले ही मंगोलों के अधीन था। अब तिब्बत पर हमला किया गया और इसे भी जीतकर मंगोल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। एक अन्य मंगोल सेना ने बगदाद पर आक्रमण किया। यहां अब तक भी अरब खलीफाओं का शासन या। मंगोलों ने बगदाद को जीत लिया। मुसलिम धर्म और अरब सभ्यता के इस प्रसिद्ध केन्द्र का मंगोलों के हाथ से बुरी तरह विनाश हुआ। बगदाद से आगे बढ़कर मंगू खां ने सीरिया और एशिया माइनर को भी अपने अधीन कर लिया। कान्स्टेन्टिनोपल के पूर्वी रोमन सम्नाट् उसके भय से थर थर कांपने लगे। १२५९ ई० में मंगू खां की मृत्यु हो गई।

मंगोल साम्राज्य के विभाग मंगू खां की मृत्यु के वाद विशाल मंगोल साम्राज्य चार भागों में विभवत ही गया। (१) चीन इसका शासक कुवले खां था। मंगू खां के समय में वह चीन का शासक वियत हुआ था। उसने अपनी राजधानी कराजुरम की जगह पैकिंग को बना लिया था। मंगोलिया, चीन, तिब्बत और तुकिंस्तान कुवले सां के भीन थे। (१) पशिया राज्या शासक

हुल्गू खां था । अफगानिस्तान, पाँशया मैसोपोटासिया और सीरिया के प्रदेश हुल्गू खां के अवीन थे। एशिया माइनर के तुर्क सरदार भी हुलगू खां को अपना अधिपति मानते थे। (३) रूस—कैस्पियन सागर और काला सागर के उत्तर में रूस और पोलैण्ड के प्रदेश इस तीसरे मंगोल राज्य के अन्तर्गत थे। उसे 'किपचल' कहा जाता था। (४) साइवीरिया—किपचनः और चीन के मंगोल राज्यों के बीच में एक अन्य मंगोल राज्य था, जिसे साइबीरिया कहते थे।

शुरू में ये चारों मंगोल राज्य कुबले खां का आधिपत्य स्वीकार करते थे। पर जब १२९४ ई० में कुबले खां की मृत्यु हो गई, तो ये चारों मंगील राज्य एक इसरे से पथक व स्वतन्त्र हो गये।

स्रोत में मंगोल शासन—कुबले खां के उत्तराधिकारी चीन में राज्य करते रहे। चीन के इतिहास में कुबले खां से एक नये राजवंश का प्रारम्भ हुआ, जिसे युआन वंश कहते हैं। यह वंश १२५९ से १३६८ ई० तक चीन का शासन फरता रहा। युआन वंश के शासन काल में चीन ने अच्छी उन्नति की। कुबले खां के समय में मार्को पोलो नाम के एक यूरोपियन ने चीन की यात्रा की थी। कुछ समय तक वह कुबले खां के दरबार में भी रहा था। मार्को पोलो इटली के वेनिस नगर का निवासी था। उसने कुबले खां के राज-दरबार का भी वृतांत लिखा है, जिससे इस मंगोल सम्बाट के वैभव, शक्ति और विद्याप्रेम का अच्छा परिचय मिलता है।

भिंग बैश — कुवले खां के वंशज १३६८ ई० तक चीन का शासन करते रहे। एक सदी के काल में मंगोल राजा निर्वेल हो गये थे। परिणाम यह हुआ, कि १३६८ ई० में उनके विरुद्ध विद्रोह हो गया और मिंग वंश के शासन का चीन में शारम्भ हुआ। मिंग वंश का शांसन १३६८ से १६४४ ई० तक स्थिर रहा। १६४४ ई० में मञ्चू वंश के अतापी राजाओं ने चीन पर अपना अधिकार कर लिया। मञ्चू लोग उत्तरी चीन के निवासी थे। इन्हीं के पूर्वज पहले उत्तरी चीन के शासक थे। चंगेज खां ने इन्हीं (किन वंश) को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था। मञ्चू वंश का शासन चीन में १६४४ से १९१२ ई० तक कायम रहा। १९१२ में वहां रिपब्लिक की स्थापना हो गई।

दूसरा अध्याय

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में चीन की दशा

(१) मञ्जू साम्राज्य

मञ्जू शासन की स्थापना—१६४४ ई० में चीन में मिग वंश (१३६८—१६४४) के शासन का अन्त हुआ। चीन के उत्तरी प्रदेशों में, जिसे आजकल मञ्जूरिया कहते हैं, एक जाति का निवास था, जो मञ्जू कहलाती थी। सतरहवीं सदी के शुरू में मंजू लोगों ने अपनी शिक्त को बढ़ाकर विशाल चीनी दीवार के दक्षिण की ओर आक्रमण प्रारम्भ किये। १६४४ में उन्होंने पेकिंग को विजय कर लिया। चीनी सम्राट् मञ्जू आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहे। अन्तिम मिंग सम्राट ने पराजय के अपमान को न सह सकने के कारण आत्महत्या द्वारा अपने जीवन का अन्त किया और चीन में मञ्जू राजयंश का प्रारम्भ हुआ। मञ्जू लोग सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से चीनियों में अधिक भिन्न नहीं थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी ये और कन्त्यमूसियस सदृश आचार्यों ने चीन में जिस मर्यादा व परम्परा का प्रारम्भ किया था, उसवा आदर करते थे। इसीलिये चीनी लोग उन्हें विदेशी नहीं समझते थे और वे चीनी जनसमाज के ही अंग हो गये थे।

मञ्जू बंश के सम्राटों में लंग-ह्सी और चिएन लुंग सबसे प्रसिद्ध हैं। लांग-ह्सी का शासनवाल १६६१ से १७२२ तक है। वह फांस के लुई चौदहवें, रूस के पीटर द ग्रेट और भारतवर्ष के और ज़्जें के समकालीन था। वह इन सम्राटों के समान ही महत्त्वालंकी और शक्तिशाली था। विशाल चीनी साम्राज्य पर उसने बड़ी योग्यता और शक्ति के साथ शासन किया। चिएन-लुंग का शासनवाल १७३९ से १७९६ तक था। इसके शासन के समय में मञ्जू साधाज्य अपनी अर्थात की चरम सीमा पर पहुंच गया था। भारत में इस समय मुगल साम्राज्य वा पतन शुरू हो चुका था। न केवल विविध सूवेदार मुगल साम्राज्य की अधीनता से स्वतन्त्र होने शुरू हो गये थे, अपितु इङ्गलिश और फोंच जोग भी शासन में जानी अनित व अधिपत्त की स्वागना में तत्तर थे। पर उस यूग में नीन का विशाल साम्राज्य नवीं था। विरंशी लोगों न भी वहां अभी अपने प्रमाव का विस्तार शुरू नहीं किया था। चिएन-लुंग के

बाद मञ्ज्यू सम्राटों की शिवत क्षीण होने लगी। साम्राज्य के अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश सम्राट् के शासन की उपेक्षा करने लगे। चिएन-लुंग के साम्राज्य में वास्तविका चीन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रदेश अन्तर्गत थे। उत्तर में उसकी सीगा आमूर नदी तक विस्तृत थी, सम्पूर्ण मञ्ज्यूरिया उसके अधीन था। सिगिनियांग और तिब्बत उसके आधिपत्य में थे। नेपाल और बरमा उसे बानायवा वार देते थे। अनाम, कोरिया, फार्मूसा और प्रशान्त महासागर के तटवर्ती अनेक द्वीप मञ्जू सम्राट की अधीनता को स्वीकार करते थे। चिएन-लुंग (१७३६-१७९६) के बाद चीनी साम्राज्य में शिथिलता आने लगी, और अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश ब राज्य मञ्जू सम्राटों की उपेक्षा करने लगे।

उन्नीसर्वी सदी के पूर्वार्द्ध में चीनी साम्राज्य—१८४२ के लगभग यूरोपियन लोग चीन में अपनी शक्ति व प्रभाव का विस्तार करने के लिये प्रवृत्त हुए। उस समय मञ्चू सम्राटों की अधीनता में निम्नलिखित प्रदेश थे—

- (१) वास्तविक चीन-जिसें चीन के लोग मध्यदेश के नाम से बाहते थे। इसमें कुछ अठारह प्रान्त थे।
 - (२) मञ्चूरिया-यह चीनी मध्यदेश के उत्तर में हैं। यह मञ्चू साम्राज्य के अन्तर्गत था।
- (३) अधीनस्थ राज्य-तिब्बत, मंगोलिया और सिंगिकियांग मञ्जू सम्राटों की अधीनता स्वीकृत करते थे, और पेकिंग की केन्द्रीय सरकार उनके शासन पर निरीक्षण रखती थी।
- (४) करद राज्य-कोरिया, अनाम और फोर्मूसा चीन से पृथक थे, पर वे मञ्चू सम्राटों को कर प्रदान करते थे। बरमा पर इस समय अंग्रेजों का आधिपत्य स्यापित हो चुका था और नेपाल चीन के प्रभाव से मुक्त हो गया था।

करद राज्यों को न गिनकर मञ्चू साम्राज्य का क्षेत्रफल इस समय ४२,७७,१७० वर्गमील था और इसकी जनसंख्या ३७ करोड़ के लगराग थी। इस विशाल साम्राज्य के सब निवासी जातीय दृष्टि से एक नहीं थे। पर धर्म, संस्कृति और आचार विचार की दृष्टि से उनमें एक इस प्रकार की एकता अवस्य विद्यमान थी, जो उन्हें अन्य सब देशों के लोगों से पृथक करती थी।

(२) चीन के निवासी

चीन ने सैतीस करोड़ के लगभग निवासी अपने कार्य व पेशे की दृष्टि से पांच भागों में विभक्त थे। ये पांच विभाग पण्डित, कृषक, शिल्पी, व्यापारी और सेवक इन नामों से प्रकट किये जा सकते हैं।

(१) पण्डित वर्ग-चीन के जन समाज में पण्डित वर्ग प्रतिष्ठा की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्व रखता था । जिस प्रकार भारत में ब्राह्मणों को अत्यन्त आदर की दुष्टि से देखा जाता है, वैसे ही चीन में पण्डित वर्ग का स्थान बहुत सम्मानित है। पर चीन का पण्डित वर्ग कोई पृथक जाति नहीं है और नहीं कोई मनष्य किसी कुल विशेष में उत्पन्न होने के कारण पण्डित माना जाता है। चीन में पंडित पद को पाने के लिये विद्याभ्यास की आवश्यकता होती है, और इस पद को प्राप्त करने के इच्छ्क मनुष्य वर्षी तक कठिन तपस्या करते हैं। सात साल की आय में वालक अपने गांव की पाठशाला में शिक्षा को शुरू करता था। यदि बालक के माता-पिता गरीब हो और बालक होनहार हो, तो ग्राम पंचायत उसकी पढाई के बोझ को अपने ऊपर ले लेती थी। पाठ्य विषय में प्राचीन ग्रंथों और धर्म प्रतकों का प्रमुख स्थान होता था। भारत के पुरातन परिपाटी के पण्डितों के समान चीन के पंडित भी व्याकरण, कोश और धर्मग्रन्थों को शिक्षा में प्रमुख स्थान देते थे। जिले में जितने निद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते थे, पहले उनकी परीक्षा ली जाती थी। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सबसे उत्तम स्थान प्राप्त करें, उन्हें प्रदेश की परीक्षा में बिठाया जाता था। प्रदेश की परीक्षा में बैठनेवाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में होती थी। इसमें जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते थे, उन्हें हि सड-रसेई (स्नातक) की उपाधि प्रदान की जाती थी। प्रदेश की परीक्षा उत्तीर्ण भरवे विद्यार्थी प्रान्त की परीक्षा में बैठते थे। इसे उत्तीर्ण कर लेने पर चू-जेन की उपाधि दी जाती थी। चु-जोन (वाचस्पति) की उपाधि प्राप्त कर लेने पर विद्यार्थी को इस योग्य समझा जाता था, कि वह राजकीय पद को प्राप्त कर सबो या अन्यत्र कार्य कर सके। चु-जोन की उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद चीनी पण्डितों में जो सबसे अधिक योग्य होते थे, वे पेकिंग की सर्वोच्च परीक्षा चिन-शिह (आचार्य) के लिये बैठ सकते थे। चिन-शिह परीक्षा जतीर्ण कर लेने पर राज्य के किसी भी उच्च पद पर नियुक्ति की जा सकती थी। जो विद्यार्थी उच्च परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे, वे साधारण पाठशालाओं में अध्यापन का कार्य करते थे, या मुंशी आदि की ऐसी नीकरी प्राप्त कर लेते थे, जिसके लिये शिक्षित होना आवश्यक समक्षा जाता था। आर्थिक दृष्टि से चीन का यह पण्डित वर्ग बहुत समृद्ध नहीं होता था, पर इसमें संदेह नहीं कि समाज में इसका भान बहुत अधिक था। चीन के शिक्षणालयों में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का प्रवेश अभी नहीं हुआ था। अठारहवीं सदी में यूरोप में जो वैज्ञानिक उन्नति प्रारम्भ हुई थी, चीन के लोग उससे प्राय: अपरिचित थे। वे पुराने समय के बास्त्रों और ताहित्यिक ग्रन्थों से ही सन्तुष्ट थे और इन्हीं का भेलीगांति अध्ययन कर वे पण्डित पद को प्राप्त कर लेते थे। अठारहवीं सदी के मध्य तक यूरोप में भी शिक्षा की प्रायः यही दशा थी। वहां भी प्रायान लैटिन-प्रन्थों के अध्ययन को ही विद्वत्ता के लिये आवश्यक माना जाता था। पर इंसमें सन्देह नहीं, कि शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से चीन यूरोप की अपेक्षा एक संदी के लगभग पीछे रह गया था।

- (२) कृषक वर्ग—चीन की आबादी का अस्सी फी सदी कृषक वर्ग था। कृषक लोग गांवों में निवास करते थे। गांव के बाहर खेती की भूमि होती थी, जिस पर ये कृषक खेती किया करते थे। कृषि के उपकरण पुराने ढंग के थे और खेतों का आकार छोटा होता था। पिता के बाद उसकी जमीन उसके लड़कों में बंट जाती थी और इस कारण खेतों का आकार निरन्तर अधिक छोटा होता जाता था। किसानों के लिये यह सुगम नहीं होता था, कि वे अपने खेत में पर्याप्त अन्न उत्पन्न कर सकें और अपने परिवार का भलीमांति पालन-पोषण कर सकें। बहु-संख्यक किसान गरीव थे और मट्टी के बने हुए झोंपड़ों में निवास करते थे। गांचों का प्रवन्ध करने के लिये ग्राम पंचायतें संगठित थीं। इनके सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे। प्रत्येक परिवार का मुखिया अपने अधिकार से ग्रामपंचायत का सदस्य होता था। परिवार में मुखिया का बहुत महत्त्व होता था। शादी-विवाह की व्यवस्था वही करता था। तलाक की प्रथा चीन में विद्यमान थी। सन्तान न होने की दशा में पति को यह अधिकार था, कि वह दूसरा विवाह कर सके। पर दूसरी पत्नी की परिवार में वह स्थित नहीं मानी जाती थी, जो कि पहली पत्नी को प्राप्त थी।
- (३) शिल्पी वर्ग-कारीगर या शिल्पी लोग अपने घर पर रहकर कार्य करते थे। कल-कारखानों का विकास अभी चीन में नहीं हुआ था। व्यावसायिक काल्ति के अभाव में पूंजीपित और मजदूर ये दो प्रधा श्रेणियां अभी चीन में विकसित नहीं हुई थीं। जुलाहे, मोची, तेली, रंगसाज आदि सब प्रकार के शिल्पी पुराने ढंग के मोटे व भद्दे औजारों से आर्थिक उत्पत्ति का कार्य किया करते थे। शिल्पी लोग आर्थिक श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित थे। प्रत्येक शिल्प की अपनी पृथक श्रेणी होती थी। प्रत्येक कारीगर के पास अनेक अन्तेवासी (शागिर्द) काम सीखा करते थे, और सात-आठ साल तक आचार्य (उस्ताद) के घर रह कर शिल्प में प्रवीणता प्राप्त करते थे। अन्तेवासी का काल समाप्त कर चुकने पर या तो कारीगर अपना स्वतन्त्र कार्य प्रारम्भ करता था, और या अपने आचार्य के साथ रहकर काम करता रहता था, जिसके लिये उसे निश्चित वेतन दिया जाता था। प्रत्येक शिल्प के लिये बाकायदा नियम बने होते थे, जिनका निर्माण उस शिल्प की श्रेण (गिल्ड) द्वारा

किया जाता था। तैयार माल को क्या कीमत हो, कारीगरों को कितना वेतन दिया जाय, किस ढंग का माल तैयार किया जाय—ये सब वातें श्रेण द्वारा ही निव्नित की जाती थीं। प्रत्येक श्रेणि का एक प्रधान होता था, जिसे सब शिल्पी (केवल आचार्य, अ तेवासी नहीं) मिलकर चुनते थे। प्रधान को अपने कार्य में प्रामशं देने के लिये एक कार्यकारिणी समिति भी होती थी, जिसके सदस्यों की नियुक्ति भी निर्वाचन द्वारा की जाती थी। शिल्प सम्बन्धी सब विवादों का निर्णय श्रेण द्वारा किया जाता था। इस बात की आव्ययकता बहुत कम होती थी, कि शिल्प के अगड़े राजकीय न्यायालय के सम्मुख उपस्थित हों। चीन में प्रायः सर्वत्र शिल्पी लोग इसी प्रकार की श्रेणियों में संगठित थे। प्रत्येक नगर में विविध शिल्पों की पृथक-पृथक श्रेणियों विद्यमान थीं, और उनके द्वारा चीन का व्यावसायिक जीवन बहुत सुन्दर रूप से संचालित होता था। कल-कारखानों के अभाव के कारण उन व्यायसायिक समस्याओं का चीन में सर्वथा अभाव था, जो इस युग में यूरोप के देशों में उत्पन्न हो गई थीं।

(४) व्यापारी वर्ग-व्यापारी वर्ग के लोग संख्या में अधिक नहीं थे, कारण यह कि शिल्पी लोग प्रायः स्वयं ही अपने माल का ऋय-विकय किया करते थे। शिल्पी ें लोगों का निवास स्थान ही उनका कारखाना होता था, जहां वे अपने माल का उत्पादन करते थे। यही उनकी दकान भी होती थी, जहां से उनका गाल सुगमता से बिक जाता था। पर कुछ नगर ऐसे भी घे, जहां किसी खास किसम का माल बहुत अधिक परिणाम में तेयार होता था, और उस सब की खपत उस नगर में नहीं हो सकती थी। यह माल व्यापारी लोग खरीद लेते ये और उसे अन्यत्र जाकर बेचा करते थे। इस प्रकार एक प्रथक व्यापारी वर्ग का विकास हो गया था, जिसका कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाना व वहां उसे बेचना होता था। बंड़े नगरों में बाकायदा बाजार होते थे, जहां व्यापारी लोग दूर-दूर से माल की लाकर उसका विक्रय करते थे। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रापना यहन मुगभ नहीं था । उस युग में चीन में न अच्छी सड़कें थीं, और न ही अच्छे यानों की सत्ता थी। सड़कें प्रायः कच्ची और खराब हालत में थीं। पश् या उनसे खींची जानेवाली गारियां भाग होने के काम में लाई जाती थीं। समुद्र ूनट पर स्थित नगरों में ज्यापार की अधिक सविधा थी, ऋगींकि उनके माल की नीकाओं द्वारा अन्यन भगाता से पहुंचाया जा सकता था। नीकाएँ व छोटे जहाज केवल समुद्रसट के साथ-राप ही नहीं आते जाते थे, अपितुं नदियों में भी उनको प्रयुक्त किया जाता था। नौकाओं हारा नदियों में हजारों मील तम कामारी लोग माल को एक स्थान र वृसरे स्थान पर ले

जा सकते थे और जल मार्गी द्वारा चीन के आन्तरिक व्यापार ने अच्छी उशित को हुई थी।

शिल्पी वर्ग के समान ज्यापारी लोग भी अपने संगठनों (निगमों) में संगठित थे। ये निगम ज्यापार सम्बन्धी नियमों का निर्माण करते थे, ज्यापारियों पर निरीक्षण रखते थे और आपस के झगड़ों का निबटारा करते थे। निगमों के प्रधान व अन्य अधिकारियों की नियक्ति भी निर्वाचन द्वारा की जाती थी।

(५) सेवक वर्ग-इस वर्ग में वे लोग सम्मिलित थे, जो नौकरी द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। मजदूर श्रेणी का उस समय तक चीन में विकास नहीं हुआ था, अतः ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, जो वेतन या भृति प्राप्त करके अपना निर्वाह करते हों। पर समृद्ध व धनी लोग इस स्थिति में थे, कि अन्य लोगों को अपनी नौकरी में रख सकें। साथ ही राज्य की ओर से बहुत से लोग सेना की नौकरी में रखे जाते थे। सैनिक वर्ग को चीन में विशेष सम्मानास्पद स्थान प्राप्त नहीं था। समाज में उसकी स्थिति हीन समझी जाती थी, और उनकी गणना सेवक वर्ग में ही की जाती थी।

(३) राजनीतिक संगठन

चीन के विविध विभाग-शासन के लिये वास्तिवक चीन (मध्य देश) की अठारह प्रान्तों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रान्त के अनेक उपविभाग (प्रदेश) होते थे, जिन्हें 'फू' कहते थे। चीन के अठारह प्रान्तों में कुल मिलाकर १८४ प्रदेश या फू थे। प्रत्येक फू अनेक जिलों (हि सअन) में विभक्त होता था। चीन में इस प्रकार के कुल १४७० जिले थे। जिले में बहुत से नगर व ग्राम होते थे, जिनमें अपनी-अपनी ग्रामपंचायतें विद्यमान थीं। पर शासन की वृष्टि से जिले या हि सअन को इकाई माना जाता था, और चीन की राजधानी पेकिंग से इन जिलों के शासनों द्वारा ही देश के शासन की संचालन किया जाता था।

सम्राट् की स्थिति—चीन में शासन का केन्द्र सम्राट् होता था। उसकी शक्ति असीम थी। यह समझा जाता था, कि वह न केवल अपनी इच्छा से कानूनों का निर्माण कर सकता है, पर राज्य के सब अधिकारी उसी की इच्छा और आदेश के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में शासन का कार्य करते हैं। सम्राट् अपने शासन कार्य के लिये किसी पालियामेंट या विधान सभा के प्रति उत्तरवायी नहीं था और नहीं चीन में इस प्रकार की किसी सभा की सत्ता ही थी। सम्राट् देवी अधिकार से शासन करता है, ईश्वर ने उसे राज्य के शासन का कार्य सुपूर्व किया है और इसलिये जनता को यह अधिकार नहीं है, कि वह उसके कार्य में हस्तक्षेव बार सके, ये

विचार इस युग में चीन में सर्वसम्मत रूप से स्वीकृत किये जाते थे। राजा स्वयं अपने पदाधिकारियों को नियुक्त करता था, और ये अधिकारी अपने कार्यों के लिये उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पर यह सब कुछ होते हुए भी चीन के सम्नाट् अठारहवीं सदी के यूरोपियन राजाओं के समान निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं थे। फांस का लुई चौदहवां, स्पेन का फिलिप दितीय, रूस का अलेक्जेण्डर प्रथम व इंगलेण्ड का जेम्स प्रथम जिन अर्थों में निरंकुश राजा थे, उन अर्थों में चीन के कांग-ह् सी या चिएन-लुंग को निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं कहा जा सकता। इसके कारणों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

- (१) चीन में प्रचलित राजनीतिक विचारों के अनुसार ईश्वर जब राजा की शासन का अधिकार प्रदान करता है, तो उसे यह कर्तव्य भी सुपूर्व करता है, कि वह देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखे, जनता सुखी और समृद्ध हो और प्रजा के लोग किसी प्रकार से पीड़ित न हों। ईश्वर ने जहां राजा को अपरिमित अधिकार व शक्ति प्रदान की है, वहां साथ ही उसके कतिएय कर्तव्य भी निश्चित कर दिये हैं। इस दशा में यदि किसी राजा के शासन काल में दुर्भिक्ष पड़ता है, प्रजा अन्न के अभाव में दुख उठाती है, तो इसका कारण केवल यही हो सकता है, कि राजा . अपने कर्तव्यों के पालन में विमुख है। इस अवस्था में जनता को अधिकार है, कि वह राजा के विरुद्ध विद्रोह कर सके। विद्रोह के कारण यदि राजा अपने पद पर स्थिर न रह सके, तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यह होगा, कि अब ईरवर की यह इच्छा नहीं है, कि वह राजा राजपद पर रहे । ईश्वर ने जनता पर शासन करने का जो अधिकार राजा को प्रदान किया था, अब वह उसने वापस ले लिया है। इसीलिये चीन के प्राचीन ग्रन्थों में ये विचार प्रतिपादित किये गये थे, कि "जो जनता सुनती" है, वही ईश्वर सुनता है। जो जनता देखती है, वही ईश्वर देखता है।" और '''राज्य में जनता का स्थान सर्वोच्च है, राजा का स्थान सबसे हीन है।'' इस प्रकार के विचार चीनी जनता में बद्धमूल थे, और इसी कारण वह समझती यी कि राजा उसी समय तक अबाधित रूप से शासन कार्य का संचालन कर सकता है, जब तक उसके शासन में प्रजा सुखी रहे। इस सिद्धान्त का यह परिणाम था, कि चीन में राजा के विरुद्ध विद्रोह के अधिकार को न्याय्य व उचित माना जाता था।
- (२) यद्यपि राजा को अपनी इच्छान्सार कानून बनाने का अधिकार या, पैर चीन के लोग यह मानते थे, कि परभारागत रूप से जो निवस व कानून देश में चले आ रहे हैं, पुराने समय के राजत्यों ने जिन कानूनों को जारी विधा था और जो नियम प्राचीन शास्त्रों व ग्रन्थों में बिहित हैं, राजा को उनका उल्लंबन नहीं करना चाहिये। चीन के कानून में चरित्र, हमें और परम्परा का बहुत महरूब

था। अतः चीन के सम्राट् उनके विरुद्ध आज्ञाएँ प्रचारित नहीं करते थे। वे पुरानी परिपाटी का आदर करते थे और इसी कारण वे किन्हीं ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं करते थे, जो चीन के परम्परागत कानून व चरित्र कें विपरीत हों।

(३) चीन में ऐसी संस्थाओं व सभाओं की भी सत्ता थी, जो राजा को उसके कार्य में परामर्श देती थी और जिनके परामर्श को राजा अत्यन्त महत्त्व देता था। इस प्रकार की एक संस्था 'राजसभा' थी, जिसके छः सदस्य होते थे। वे छः सदस्य राज्य के प्रधान विभागों के मुख्य अधिकारी होते थे । ये विभाग निम्न-लिखित थे-राजकीय पदों पर नियुक्ति का विभाग, राजकीय आमदनी का विभाग, राजंकीय अनुष्ठान सम्बन्धी विभाग, युद्ध विभाग, दण्ड विभाग और सार्वजनिक इमारत व सडक आदि का विभाग । केन्द्रीय शासन के विविध राजकीय विभागों (अधिकरणों) में इन छः का सबसे अधिक महत्त्व था, और इन छः विभागों के प्रधान अधिकारी राजसभा के सदस्य होते थे। यह राजसभा राजा की राज्य-कार्य के सम्बन्ध में परामर्श देती थी, और राजा उसकी सम्मत्ति के अनुसार कार्य करता था। राजसभा के अतिरिक्त एक अन्य संस्था थी, जिसे 'निरीक्षण सभा' कहते थे। निरीक्षण सभा के इन सदस्यों (निरीक्षकों) का यह कार्य था, वि विविध राजकर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करें, उनकी आलोचना करें. और उनके कार्यों के विषय में राजा को परामर्श देते रहें । पेकिंग की केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार के चौबीस निरीक्षक थे. और प्रान्तों की सरकारों में निरीक्षकों की संख्या छप्पन थी। केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन से सम्बद्ध ये निरीक्षक गुरुसार के विविध कार्यों की स्वतन्त्र व निर्भीक आलोचना करना अपना कर्तव्य समझते थे। जो राजकर्मचारी अपना कार्य सुचारु रूप से कर रहे हैं, ये उन्हें पुरस्कृत करने की सिफारिया करते थे। जो अपने कर्तव्यों से विमुख हों, उन्हें से दण्ड देने के लिये अपनी रिपोर्ट भेजते थे। ये निरीक्षक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राजा व उसके कृत्यों की आलोचना करना भी आवश्यक समझते थे। इसी का यह परिणाम था, कि चीन के राजा भी आलोचना से ऊपर नहीं माने जाते थे, और वे भी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे।

प्रान्तों का शासन-चीन की राजधानी पेकिंग थी। साम्राज्य के शासन का संचालन वहीं से होता था। पर प्रान्तीय शासन के लिये सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। उस समय चीन में आवागमन के साधन अधिक उसत नहीं थे। इस कारण प्रान्तीय शासकों पर नियन्त्रण रख सकना बहुत सुगम नहीं था। सूबेदार लोग अपने अपने प्रान्त में स्वतन्त्र शासक के रूप में शासन करते थे और

प्राप्तों की स्थिति अर्द्धस्वतन्य राज्यों के समान थी। पर प्रान्तों के सूबेदार भी अपने क्षेत्र में स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते थे। इसका कारण यह था कि (१) मूबेदार के समान अध्य अनेक प्रान्तीय राजकर्मचारियों की नियुक्ति भी सीबी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती थी। ये कर्मचारी सूबेदार की शक्ति को नियन्त्रित रखने में बहुत सहायक होते थे। (२) प्रान्तों के शामन में भी परम्परागत कानून, व्यवहार और चरित्र का बहुत महत्त्व होता था। सूबेदार लोग इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। (३) प्रान्तों के जो अन्य उपविभाग थे, उनके शासकों को भी शासन सम्बन्धी बहुत से अधिकार प्राप्त थे। यदि कोई सूबेदार देश की परम्परा का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारी होने का प्रयत्न करे, तो ये उसका विरोध कर सकते थे। (४) सूबेदार लोग अपने क्षेत्र में शक्ति को बढ़ाकर कहीं स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करें, इसिल्ये सगय समय पर उनकी बदली कर दी जाती थी। कोई सूबेदार सुदीर्घ समय तक किसी एक प्रांत में नहीं रहने पाता था। इस व्यवस्थाओं का यह परिणाम था, कि चीन के विशाल साम्राज्य में अकेन्द्रीभाव (डिसिण्डलाइजेशन) की प्रवित्यां बहुत प्रवल नहीं हो सकती थीं।

सूबेदार के अतिरिक्त प्रान्तीय शासन के अन्य प्रमुख राजवर्मचारी निम्तिलिखत होते थे—(१) बोबाध्यक्ष—इसकी स्थित सृबेदार के समकक्ष मानी जाती थी। राजकीय करों को एक करना व राजकीय व्यय की व्यवस्था करना इसी का कार्य था। साथ ही यह केन्द्रीय सरकार की और से सूबेदार पर निरीक्षण भी रखता था। (२) विकास के निर्माण के न्याय विभाग का प्रधान अविकारी होता था। (३) विकास के स्थान के न्याय विभाग का प्रधान अविकारी होता था। (३) विकास इस विभाग का संचालन करता था। (४) समाहती—इसका कार्य टैक्स के रूप में प्राप्त अन्न को एक विभाग वा उसकी व्यवस्था करना था। चीन में कुषकों से टैक्स अन्न के रूप में लिया जाता था। अतः इस विभाग का चीन में बहत महत्व था।

प्राप्त के उप विभाग-हम पहले लिख चुके हैं, कि चीन में प्राप्त अनेक प्रदेशों (फू) में विभक्त होते थे, फू के प्रवान अधिकारी को ताओ-तेई कहा जाता था। गू जिस जिलों में (डिए-अन) में विभक्त होना था, उनके प्रधान अधिकारियों में हान में अनता हा वारतिक वातन निहित था। एपीलिये चीन की प्रचित्र सापा में उने 'मा बार' बहते में । बहु क के एक सरकारी ईपरों को एक व करता था, अपिन बीनाको बार फोजदारी थे। नामके की जगीकी अवक्त में ऐसे होते थे। बिल के को बार को बार भी उगी के सुपूर्व था। यह सावारण अवता का सीधा सम्बन्ध उसी के साथ होता था, और इसीलिये जनता वार के हित स

कत्याण का उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने के लिये भी उसी को उत्तरदायी समझा जाता था। यही कारण् है, कि जिले के प्रधान अधिकारी की योग्यता और कार्य कुशलता पर देश के शासन की क्षमता प्रधान रूप से निर्भर करती थी।

कर्मचारियों की नियुक्ति-इस युग में चीन में लोकतन्त्र शासन का सर्वधा अभाव था। जनता को अपने मामलों का स्वयं संचालन करने का अवसर यदि कहीं मिलता था. तो केवल ग्राम पंचायतों,शिल्पियों की श्रेणियों और व्यापारियों के निगमों में ही मिलता था। देशके शासनका संवालन राजकर्मचारी लोग करते थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट्व उसके सहकारियों द्वारा की जाती थी। पर सरकारी कर्मचारियों को अपने पदों पर नियक्त करते हुए उनकी शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया जाता था। हम ऊपर उन परीक्षाओं का उल्लेख कर चुके हैं, जिन्हें चीन के पण्डितवर्ग के लोग उत्तीर्ण किया करते थे। जो व्यक्ति जितनी उच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था. उसे उतने ही उच्च राजकीय पद के लिये योग्य समझा जाता था। इस व्यवस्था का यह परिणाम था, कि चीन के शासक व राजकर्मचारी वर्ग में केवल गुयोग्य व्यक्ति ही नियक्त हो सकते थे। परीक्षा पद्धति के कारण राजकर्मचारियों की नियुक्ति में सिफारिश बहुत काम नहीं देती थी। जिस प्रकार अठारहवीं सदी में यूरोप के विविध देशों में राजकीय पदों की नियुक्ति के समय दरबारियों और राजा के कृपापात्रों की सिफारिशों का महत्त्व था, वैसा चीन में नहीं था। यूरोप में कुलीन श्रेणी के लोग उच्च राजकीय पदों को बहुत सुगमता के साथ प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि दरबार में रहते हुए वे राजा को अपनी मटठी में रखते थे। पर चीन में उच्च परीक्षाओं को उत्तीर्ण किये बिना कोई व्यक्ति राजकीय पद को प्राप्त करने की आशा नहीं रख सकता था। विविध पदों पर नियुक्ति पहले तीन साल के लिये की जाती थी। कोई व्यक्ति साधारणतया तीन साल से अधिक समय तक एक स्थान पर व एक पद पर नहीं रह सकता था। मञ्जू राजवंश के अन्तिम काल में इस स्थिति में परिवर्तन आने लगा। मञ्जू सम्राट् भोग विलास में फंसकर अपने कर्तव्यों की जपेक्षा करने लगे। राजकीय पदों पर नियुक्ति करते हुए व राजकर्मचारी को तरक्की देते हुए वे अपने अनुचरों व पार्खंचरों की सिफारिशों को महत्त्व देने लगे । परिणाम यह हुआ, कि परीक्षा पद्धति की उपेक्षा होने लगी और चीन का शासनसूत्र शिथिल पड़ने लगा। 🦠 मञ्जू शासन के विरुद्ध कान्ति होकर जो राजसत्ता का अन्त हुआ और रिपव्लिक की स्थापना हुई, उसमें यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

चीनी साम्राज्य की सार्वभीम सत्ता-चीनी लोग समझते थे कि, उनका

सम्राट् सार्वभीम शासक है। जिस प्रकार संसार में एक ही सूर्य होता है, वैसे ही मनुष्य जाति का एक ही राजा हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं, कि चीनी लोगों ंकी दिष्टि में जो सभ्य मानव समाज था, वह सब चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत था। चीन का मध्य देश वस्तुतः एक विशाल देश था। उसके चारों और के विविध राज्य भी चीनी सम्राट् की अधीनता की स्वीकृत करते थे। जिन देशों का चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध था, वे सब चीन के सम्राट को अपना अधिपति स्वीकृत करते थे। इसी युग में यूरोप में अनेक छोटे बड़े राज्य थे। ये सब राज्य प्रभुत्व शावितसम्पन्न और अपने आपमें पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थे। उनमें परस्पर सम्बन्ध रखने के लिये शक्ति-समुत्तुलन (वेलेन्स आफ पावर) के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता था। यूरोप के विविध राज्य व उनके शासक आपस में किस प्रकार का सम्बन्ध रखें, इसके लिये कूटनय (डिप्लोमेसी) का विकास हुआ था, और यूरोप के विविध राजनीतिज्ञ इस नृटनय में अत्यन्त दक्ष थे। पर चीन में न शक्तिसम्-त्तुलन की आवश्यकता थी और न कूटनय की। चीन का अपना विस्तार यूरोप से अधिक था। उसके समीपवर्ती सब राज्य चीनी सम्राट् की अधीनता स्वीकृत करते थे । इस दशा में यदि चीन में अपने सम्राट्व साम्राज्य की सार्वभौमता का विचार विकसित हुआ हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। इसीलिये जब यूरोप के विविध देशों से चीन का सम्पर्क स्थापित हुआ, तो चीनी राजनीतिज्ञ यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कि संसार में कोई ऐसे भी देश हैं. जो उनके अपने देश के समान ही पूर्णतया स्वतन्त्र व प्रभुत्त्वशक्तिसम्पन्न हैं। चीन की इस मनीवृत्ति पर हम आगे चलकर अधिक विशव रूप से प्रकाश डालेंगे।

(४) चीन की संस्कृति

नसल व जीत की दृष्टि से विशाल चीनी साम्राज्य के सब निवासी एक नहीं थे। पर उनमें एक प्रवार की एकानुभूति विद्यमान थी, जिसका आधार सांस्कृतिक एकता थी। इस चीनी संस्कृति का विकास कन्म्यूसियस (५५१-४७९ ई० पू०) के समय से शुरू हुआथा। इस प्रसिद्ध विचारक के सम्बन्ध में हमपहले लिख चुके हैं। कन्म्यूसियस ने जिस विचारधारा का प्रारम्भ किया था, वह ढाई हजार साल बीत जाने पर भी अब तक चीन के सांस्कृतिक जीवन का आधार थी। चीन में कितने ही अन्य विचारक उत्पन्न हुए, कितनी ही नई विचारधाराएं चलीं, कितने ही मये धर्मी का प्रवेश हुआ, गौट धर्म ने बहुसंस्थक चीनी जाता को अपना अनुगायी चना लिया, इस्लाभ और विविचएनिटी का भी चीन में प्रवेश हुआ, गर कन्म्यूसियस द्वारा प्रतिपित विचारों का प्रभाव इन सवरों मिटा नहीं। विद्याल चीन के सब

निवासी कन्पयसियस द्वारा प्रारम्भ की गई विचारधारा और संस्कृति का आदर करते थे और यह बात चीन की सांस्कृतिक एकता की आधार शिला थी। जो कोई जाति चीन की इस प्राचीन संस्कृति को अपना ले, वह चीनी जनसमाज की अंग ६न जाती थी । मञ्च लोग चीन के लिये विदेशी थे, उन्होंने आक्षमण हारा चीन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था । पर क्योंकि उन्होंने चीन की प्राचीन संस्कृति को अपना लिया था. अतः चीनी लोग उन्हें विदेशी नहीं समझते थे। अपने शासन कार्य में भी मञ्चू सम्राट् चीन की पुरानी परम्परा का अनुसरण करते थे, और इसका यह परिणाम था, कि चीनी लोग उनके जासन की सर्वधा उचित व स्थाभाविक समझते थे। इसी प्रकार जो विविध जातियां समय समय पर चीन में प्रविष्ठ हुईं, या जो बाह्य प्रदेश चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत होते गये. वे सब भी चीन के अंगरूप होते गये। यही कारण है, कि चीन में उस प्रकार की जातीय समस्याओं का प्रादर्भाव नहीं हुआ, जैसा कि इस यग में यरोग में हो रहा था । आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य में चेक, पोल आदि विविध जातियों का निवास था । ये सब अपने को आस्ट्रियन (जर्मन) लोगों से भिन्न समझती थीं और अपनी राप्टीय स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थीं। पर विशाल चीनी साम्राज्य में निवास करनेवाली विभिन्न जातियों में अपने पृथकृत्व की भावना का अभाव था, क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि से वे परस्पर एकानुभृति रखती थीं।

भाषा— भाषा की दृष्टि से चीन में एकता नहीं है, वहां अनेक भाषाएं बीछी जाती हैं। जो व्यक्ति केवल कैन्टन की भाषा जानता है, वह फूजों या तीन्तिसन की भाषा को नहीं समझ सकता। भाषा के इस भेद के रहते हुए भी बहुनंक्क चीनी लोग एक सर्व सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जो 'मन्दारिन' नाम से प्रसिद्ध हैं। मन्दारिन के भी अनेक मेद हैं, पर उतरी चीन में जो गन्दारिन भाषा प्रयुक्त होती है, वह यांगत्से नदी की घाटी के प्रदेश में भी समझी जा सकती हैं। चीन की विविध भाषाओं में चाहे कितना भी भेद क्यों न हो, पर सारे देश की लिपि एक समान हैं। कैन्टन का निवासी उत्तरी चीन के निवासी से चाहे बातचीत न कर सकता हो, पर वह उसके साथ पत्रव्यवहार कर सकता है। इसका कारण चीन की लिपि की विशेषता है। चीन की लिपि में उस प्रणार के अक्षर नहीं हैं, जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि में हैं। हिन्दी का 'क' या 'प' एक ध्वित विशेष को सूचित करते हैं, किसी भाव था अर्थ विशेष को नहीं। पर चीन की लिपि में जो विविध चिह्न हैं (हम उन्हें अक्षर नहीं कह सकते), वे किसी विशेष्ट भाव या अर्थ के सूचक हैं। अतः उन चिह्नों को देखकर चीन के किसी विशेष का निवासी उस भाव को समझ सकता है। मान लीजिये, 'क्ष' यह चिह्न

गरम इस भाव को सूचित करता है। उर्दू भाषा में जिसे गरम कहेंगे, संस्कृत या हिन्दी में उसे ही उष्ण और अंग्रेजी में उसे ही हाट कहेंगे। यदि हम भी चीन की लिपि के समान एक ऐसी लिपि को विकसित कर लें, जो 'क्ष' इस चिह्न से उष्णता के भाव को प्रकट करे, तो उसे देख कर उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी आदि विविध भाषाओं को जाननेवाले पाठक उस चिह्न से ग्रीष्मता के अभिप्राय को भर्जीभांति समझ सकेंगे। चीनी लिपि के विविध चिह्न, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, भाव व वस्तु सूचक हैं। इसीलिये उसमें लिखी हुई पुस्तक को चीन के विविध भाषाभाषी लोग समान रूप से समझ सकते हैं। पर इसके लिये लिखित पुस्तक को आंखों से देखना व पढ़ना आवश्यक होता है। यदि उसे पढ़कर सुनाया जाय, तो सब लोग उसे सुगमता से नहीं समझ सकेंगे। लिखित चीनी भाषा जिस रूप में विद्वान लोग पढ़ते हैं, वह सबके लिये सुबोध नहीं होती। पर उसकी लिपि में इस प्रकार की विशेषता है, जो चीन के विविध भाषा भाषी लोगों को एक सूत्र में बांधे रख सकने में समर्थ होती है।

साहित्य-सम्भवतः कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था ह यह बात तो निर्विवाद है, कि मुद्रण कला सबसे पहले चीन में ही आविष्कृत हुई थी। जिस समय यूरोप में छापेखाने का प्रवेश हुआ, उससे अनेक सदी पहले चीन में पुस्तकों छपने लग गई थीं। इसका यह परिणाम हुआ, कि चीन में साहित्य के विकास में बहुत सहायता मिली। उन्नीसवीं सदी के शुरू में चीन में जितना साहित्य था, उतना संसार के अन्य किसी देश में नहीं था । ये पुस्तकें प्रधानतयाः इतिहास, धर्म, वर्शन, काव्य और गद्य साहित्य के सम्बन्ध में थीं। इतिहास पर चीनी लोगों ने बहत ग्रन्थ लिखे। इनमें चीन के विविध राजवंशों का इतिवत्त कमित्र रूप से उल्लिखित है। यद्यपि शुरू के राजवंशों का इतिहास वहत कुछ कल्पनात्मक है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि इन इतिहास ग्रन्थों में चीन की ऐतिहा-सिक अनश्रति बहुत कुछ अविकल रूप में सुरक्षित है। कन्पयसियस आदि जो बहत से विचारक व तत्त्ववेता प्राचीन चीनमें उत्पन्न हुए, उनके ग्रन्थोंका चीनमें बहुत आदर है। इन आचार्यों ने जो विचारधाराएं प्रारम्भ कीं, उनकी शिष्य परम्परा ने उन्हें बहत विकसित किया और उनकी पृष्टि व प्रतिपादन में अनेक ग्रन्थों की रचना की। बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद चीनी विद्वानों ने न केवल भारतीय न्द्रौद्ध ग्रन्थों का अपनी भाषा में अनुवाद किया, पर उन पर अनेक नई पुस्तकों भी लिखीं। चीनी पण्डितों ने विश्वकोग के एन में भी बहुत सी पुस्तकों का संकलन किया । गृंदा और पद्माग काव्यों के निर्माण पर भी जन्होंने बहुत ध्यान दिया । विज्ञान के देव में उन्होंने विविद्धासास्य, हुए। विज्ञान और ज्योदिय पर अनेक ग्रन्थ

लिखे । उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक चीनी लोग इसी साहित्य का अध्ययन करते थे । आधुनिक युग में पाश्चात्य देशों ने परीक्षण द्वारा जिस नये ज्ञान विज्ञान का विकास किया, उसका उन्हें कोई परिचय नहीं था । उनमें स्वयं भी यह प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई थी, कि प्राचीन प्रमाणवाद का परित्याग कर निरीक्षण और परीक्षण द्वाराप्रकृतिके विविध तत्त्वों का परिज्ञान प्राप्त करें और इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में उन्नीतिक विविध तत्त्वों का परिज्ञान प्राप्त करें और इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में उन्नीतिक रोग भारत, ईरान, तिब्बत और अरव आदि अन्यप्राच्य देशों में भी उन्नीसवीं सदी के शुरू तक वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई थी । इस अंश में यूरोप ने संसार का नेतृत्व किया और इसी कारण वह भूखण्ड के बड़े भाग पर अपना प्रभुक्व स्थापित करने में समर्थ हुआ ।

· धर्म-धर्म के विषय में चीनी लोग समन्वयवादी थे । जिस प्रकार इस्लाम या किश्चिएनिटी के अनुयायी अपने की केवल मुसलिम या ईसाई समझते हैं, अन्य किसी धार्मिक सिद्धान्त को न मान कर केवल अपने विशिष्ट धर्म का अनुसरण करते हैं, वैसी बात चीनी लोगों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती । चीनी लोगों के धार्मिक विधिविधानों व अनुष्ठानों का आधार वे रीति रिवाज थे, जो उनमें बहुत प्राचीन काल से चले आते थे। यद्यपि बहसंख्यक चीनी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पर वे कनाय्सि-यस और लाओ-रसे के सिद्धान्तों का भी समानरूपसे आदर करते थे। जिसप्रकार भारत के बहसंख्यक हिन्दू लोग परम्परागत सनातन धर्म को मानते हैं, शिव, विष्णु आदि विविध देवताओं की समान रूप से पूजा करते हैं, बौद्ध, जैन, सिक्ख, वैष्णव व शैव सन्तों व आचार्यों को आदर की दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही चीन में भी था। चीन के बौद्ध लोग जहां बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों को मानते थे, वहां साथ ही कन्पयूसियरा और लाओ-त्से जैसे प्राचीन आचार्यों के उपदेशों व मन्तव्यों का भी अनुसरण करतेथे। धार्मिक क्षेत्र में वे वहुत सिहुष्णुथे। इस्लाम व किश्चिएनिटी जैसे पिदेशी धर्मी से भी उन्हें विरोध व विद्वेष नहीं था, बशर्ते कि ये धर्म चीन की परम्परागत संस्कृति के विरोध में आवाज न उठावें। चीन में वौद्ध धर्म, सन्प्यूसियस और लाओ रसे के अनुयायियों के मन्दिर विद्यमान है। बौद्ध मन्दिरों में बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणियों का निवास है, और कन्पयुसियस व लाओ-त्से के मन्दिरों में इन धार्मिक सम्प्रदायों के पुजारियों की सत्ता है। पण्डित, मिध् और पुजारी चाहे अपने विशिष्ट सिढान्तों का प्रतिपादन करते रहें और विविध मन्दिरों में चाहे विशेष प्रवार की पूजा व अन्ष्टानों का अनुसरण होता रहे, पर सर्वसाधारण चीनी जनसाः इन सबको आदर की दृष्टि से देखती है। वह कन्पयूसियस द्वारा प्रतिपादिल नैतिक जीवन के आदशों को स्वीकार करती है, लाओ-त्से के गल्वव्यों का आदर भरती है और बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है। इन विविध सम्प्रदायों के पण्डित

लोग चाहे सैद्धान्तिक दृष्टि से एक दूसरे का विरोध भी करें, पर जनता का उससे विशेष सम्बन्ध नहीं होता । धर्म के मामले में चीनी लोग समन्वयवादी हैं, वे विविध धर्मों के सामञ्जस्य पर विश्वास रखते हैं। चीन की जनता के धार्मिक विश्वासों में पितरों की पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पितरों के अतिरिक्त वे बहुत से देवी देवताओं में भी विश्वास रखते हैं, और उनकी पूजा के लिये अनेक विधि विधानों का प्रयोग करते हैं।

परम्परागत प्राचीन धर्म के अतिरिक्त चीन में इस्लाम और किश्चिएनिटी का भी प्रवेश हुआ है। विविध ईसाई मिशन किस प्रकार इस विशाल देश में कार्य करते रहे, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पश्चिमी चीन में इस्लाम का भी पर्याप्त प्रचार है। पर ये धार्मिक विभिन्नताएं चीन के निवासियों में विशेष भेद उत्पन्न नहीं करतीं। धार्मिक वृष्टि से भिन्न होते हुए भी चीनी लोग सांस्कृतिक वृष्टि से एक हैं।

सेना-मञ्जू सम्राटों की सेना का संगठन प्रायः उसी प्रकार का था, जैसा कि भारत में मुगल सम्राटों या युरोप में फिलिप द्वितीय व लुई चौदहवें की सेनाओं काथा। चीन की राजधानी पेकिंग में सम्राट की अंगरक्षक सेना रहती थी, जो सैन्य नीति में विशेष कुशल थी। इस सेना के सैनिकों की संख्या चार हजार थी। राजधानी की यह सेना जहां सम्राट् की रक्षा करती थी, वहां राजधानी में भी शन्ति और व्यवस्था कायम रखने का काम करती थी। चीन के उत्तरी प्रदेश मंच्रिया में एक बड़ी सेना रखी जाती थी, जिसमें दो लाख के लगभग सैनिक होते थे । चीनी मध्य देश के अठारहों प्रान्तों में प्रान्तीय सेनाएं थीं, जिनके सैनिकों की कुल संख्या पांच लाख के लगभग थी। ये प्रान्तीय सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये उपयोगी थीं। किसी बाह्य शत्रु के आक्रमण का चीन में विशेष भय नहीं था, क्योंकि चीन का साम्राज्य अत्यन्त विशाल था। अतः सेना का मुख्य पयोजन आन्तरिक बिडोहोंको जान्तकरना और देशमें व्यवस्था स्थापित करना ही था । नारुव का आविष्कार सबने पहले योन में हा हुआ था । थाता हो। इत ता है। उने ता पान्नाचा जपने विज्ञाल साध्याच्या की तथातवा में समर्थ हु हु के। इन्ने १० व 🔊 🖒 🚉 राज्य को भंगोल आक्रांताओं द्वारा रुगण्या से परास्त न र किरोब का उनका जाना कराव ही भी । पर छन्नी नहीं सकी है पूर्व ही में जब ब्रोपिंट लोग वैजातिक आकि राजिने कारण पनेक मंत्रकारक काम करनीका अपणीन करते हमें थे, बील के पान्ह पराव इंतरी बन्दूनी कर जातेला ही प्रयोग भारते थे । भही कारण हैं, कि व्यक्तिका समाजांका के भूग व न वहीं कर सके । कला और व्यवसाय उर्जानमां सदी के पूर्वा है में बीट व नरामशादिक कान्ति

का प्रारम्भ नहीं हुआ था। कारीगर लोग अपनी आर्थि 🔏 में में मालको तैयार करते थे। पर इस युग में चीन इस प्रकार की अनेक वस्तुओं का उत्पादन करता था, जिनकी दुनिया के बाजारों में वहत अधिक मांग थी। यूरोप और अमेरिका में जिस चाय की बहत अधिक मांग थी, उसका बड़ा भाग चीन में ही पैदा होता था। चीन का रेशम संसार में सर्वोत्कृप्ट माना जाता था। वहां के वने हए मिटटी के बरतन कलाके उत्कृष्ट नमने होते थे। चाय, रंशम और मिट्टी के बरतन इस प्रकार के पदार्थ थे, जिन्हें चीन बहुत बड़े परिमाण में अन्य देशों की बेचता था। युरोप के व्यापारी इस माल को खरीदकर अपने देश में ले जाने के लिये बहुत उत्सूक रहते थे। पर चीन अपनी सब आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण कर लेता था, उसे विदेशी माल की कोई गरूरत महसूस नहीं होती थी। यही कारण है, कि जब यूरोपियन व्यापारियों ने चीन में व्यापार के विस्तार के लिये अपनी कोठियां कायम कीं, तो वे चीन के माल की कीमत सोना चांदी में अदा करते थे। उनके पास कोई ऐसा माल नहीं था, जिसे वे चीनी लोगों को बेच सकें। इसी कारण अंग्रेजों ने चीन में अफीम के व्यापार का प्रारम्भ किया। उन्होंने जान बुझकर यह कोशिश की, कि चीनी लोगों में अफीम खाने की आदत पैदा करें और इस अफीम को चीन में वेचकर बदले में वहां से चाय आदि अन्य माल प्राप्त करें।

मञ्जू शासन की निर्बलता-सम्राट् चिएन-लुंग (१७३६-१७९६) के समय तक मञ्जू सम्राटों की शक्ति अक्षुण्ण रही। पर उसके बाद विशाल चीनी साम्राज्य के शासन में निवंलता आने लगी। राज्य के विविध कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये चीन में जिस परीक्षा पद्धति का आश्रय लिया जाता था, वह अठारहवीं सदी तक अवस्य उपयोगी थी। पर इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिये उन्नीसवीं सदी में भी प्राचीन शास्त्रों का पण्डित होना आवश्यक था। जो व्यक्ति जितना बड़ा विद्वान हो, जितना शास्त्र पारंगत हो, उतना ही वह इन परीक्षाओं के लिये योग्य होता था। पर शास्त्र पारंगत होना एक बात है, और सुयोग्य शासक होना दूसरी बात है । उन्नीसवीं सदी में जो विविध नये ज्ञान विज्ञान विकसित हो रहे थे, चीन की इन परीक्षाओं में उन्हें कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था । इसका परिणाम यह था, कि चीन का शासन समय के अनुसार उन्नति करने में असमर्थ था। साथ ही इस युग में चीन के शासन में अन्य प्रकार से भी विकार आना गुरू हो गया था। राजकीय पदों की प्राप्ति के लिये रिश्वत और सिफारिका का महत्त्व वढ़ने लगा था, और अनेक उच्च राजकीय पदों का कथ विकय प्रारम्भ हो गया था। यही कारण है, कि जब उन्नीसवीं सदी के भध्य भाग में चीन और विविध यूरोपियन राज्यों का सम्पर्क हुआ, तो चीन उनका मुकाबला नहीं कर सका 1

तीसरा अध्याय

यूरोप और चीन का सम्पर्क

(१) चीन और यूरोपियन राज्यों का व्यापार-सम्बन्ध

पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया का बहुत कम परिचय था। उस समय यूरोप और एशिया का न्यापारिक मार्ग लाल सागर से ईिजिप्ट होता हुआ भूमध्य सागर पहुंचता था। एक दूसरा मार्ग पश्चिया की खाड़ी से बसरा बगदाद होता हुआ एशिया माइनर के बन्दरगाहों पर जाता था। पहले इन ज्यापारिक मार्गों पर अरबों का अधिकार था। अरब लोग सम्य थे और ज्यापार के महत्व को भलीभांति समझते थे। पर पन्द्रहवीं सदी में तुर्क लोग इन प्रदेशों के स्वामी हो गये और एशिया व यूरोप के ज्यापारिक मार्ग रुद्ध होने लगे। १४५३ में जब तुर्क विजेता महम्मद द्वितीय ने कोन्स्टेन्टिनोपल को भी जीत लिया, तब तो यूरोप के लोगों के लिये इन पुराने मार्गों से ज्यापार कर सकना किन हो गया।

अब यूरोपियन लोगों को नये मार्ग ढूंढ़ निकालने की चिन्ता हुई। उस समय यूरोप का भारत आदि प्राच्य देशों से चिनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था। विशेषतया मसाले बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वी देशों से यूरोप में आते थे। इस व्यापार से लाभ उठाने के लिये अब नये मार्गों की खोज प्रारम्भ हुई। इस कार्य में पोर्तुगाल और स्पेन के लोगों ने विशेष तत्परता प्रविश्तत की। इस समय तक यूरोप में दिग्दर्शक यन्त्र का प्रवेश हो चुका था। जहांजों का आकार भी पहले की अपेक्षा बड़ा होने लगा था, और इन्हें चलाने के लिये पाल का प्रयोग शुरू हो गया था। पाल से चलनेवाले और दिग्दर्शक यन्त्र से युक्त जहांजों के लिये यह सम्भव था, कि महासमुद्रों में दूर दूर तक आ जा सकें। पोर्तुगीज लोगों के मन में पहले पहल यह कल्पना उत्पन्न हुई, कि अफीका का चक्कर काटकर पूर्व में पहुंचा जा सकता है। इसी दृष्टि से अनेक पोर्तुगीज मल्लाहों ने अफीका के समुद्रतट के साथ साथ यात्रा प्रारम्भ की। आखिर १४९८ में नाम्कोडिनामा नागक पोर्तुगीज मल्लाह अफीका का चक्कर काटकर मार्ग पहुंचा में सफूल हुआ।

एशिया आने जाने के छिये पोर्तुगीज छोगों को जो नया सामृद्रिक मार्ग जात हो गया था, उससे वेदूर दूर तक पूर्व में आने जाने छगे । १५११ में उन्होंने मलक्का पर अपना अधिकार कर लिया । मलक्का को आचार बनाकर वे पूर्वी एशिया में दूर दूर तक जाने लगे, और १५१४ में वे चीन पहुंच गये। पीर्तुगीज लोगों का एशियन लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था । वे उन्हें अपने से हीन समझते थे और उनमें ईसाई मत का जबर्दस्ती प्रचार करने का उद्योग करते थे। भारत, मलाया आदि में जब पोर्तुगीज लोग शुरू शुरू में गये, तव उन्होंने इन देशों के निवा-सियों के साथ बहुत बुरा बरताव किया । उनका खयाल था, कि जैसे स्पेनिश लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों (मय और अजटक सभ्यताओं) को नष्ट कर वहां अपनी स्थिर बस्तियां बसा ली हैं, वैसे ही एशिया में भी किया जा सकता है । पोर्त-गीज लोगों का उद्देश्य एशिया के विविध प्रदेशों में व्यापार करना ही नहीं था, वे इनके वास्तविक निवासियों को सर्वथा नष्ट कर या अपना गुलाम बनाकर इन्हें अपने उपनिवेश के रूप में विकसित करने के लिये भी प्रयत्नशील थे। पोर्तगीज लोगों के इस व्यवहार के समाचार चीन में पहुंच चुके थे। सोलहवीं सदी में चीन में मिंग वंश के सम्राटों का शासन था। उन्होंने यह निश्चय किया, कि पोर्त्गीज लोगों को चीन में प्रविष्ट न होने दिया जाय। अतः पोर्तुगीज लोग चीन में कहीं अपनी बस्ती नहीं बसा सके और नहीं वे व्यापार के लिये कहीं कोठी ही कायम कर सके। पर कैन्टन के समीप एक द्वीप को उन्होंने अपना केन्द्र बनाया और यहां रहकर वे चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हुए । १७५७ में पोर्त्गीज लोगों ने मकाओ में अपनी एक बस्ती कायम की, जो अब तक उनके अधीन है। इसी बीच में स्पेनिश लोग फिलिप्पीन द्वीप समृह को अपनी अधीनता में ला चुके थे। १५५७ में वे फिलिप्पीन से चीन आये और वहां के व्यापार में हाथ बटाने लगे। डच और इज़ुलिश लोगों ने पोर्तुगीज व स्पेनिश लोगों का अनुसरण किया । १६३७ में डच लोग चीन आये और १६३७ में अंग्रेजीं ने वहां भाना शुरू किया । सोलहवीं सदी में रूसी लोग बड़ी तेजी के साथ उत्तरी एशिया में आगे वढ़ रहे थे। साइबीरिया उनके प्रभुत्त्व में आ गया था। सत्तरहवीं सदी के अन्त (१६८९) तक रूस की सीमा चीन के साथ आ मिली थी और रूसी लोग भी इस बात के लिये प्रयत्नशील थे, कि चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध को स्थापित करें। इस प्रकार सोलहवीं और सतरहवीं सदियों में विविध युरोपियन राज्यों के व्यापारियों ने जीन में आना जाना प्रारम्भ कर दिया था और चीन के शासकों के सम्मान यह समस्या थीं, कि इन विदेशियों से किस प्रकार का सम्बन्ध रखा जाय ।

चीनी लोग स्वाप से ही अतिथिसेवी होते हैं। विदेशियों का वे स्वापत करते हैं। स्थलमार्ग से जो यूरोपियन लोग पिछली सदियों में चीन आते जाते थे, उनके साथ चीनी लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। पर समुद्र मार्ग से आते

जाने वाले ये यूरोपियन लोग केवल व्यापार से ही संतुब्द नहीं थे । अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये वे कटिवद्ध थे। उनका यह यत्न था, कि एशिया के विविध प्रदेशों पर अपने आधिपत्य की स्थापना करें। यही कारण है, कि इस समय चीनी लोग यूरोप के व्यापारियों का स्वागत करने के लिये इच्छुक नहीं थे। १६४४ में चीन में मिगवंश का अन्त होकर मञ्चू वंश के शासन की स्थापना हो गई थी। १६८५ में सम्राट् कांग-ह्सी ने एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसके अनुसार यूरी-पियन लोगोंको चीन के तटवर्ती सब बन्दरगाहों में व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। पर युरोपियन व्यापारियों ने इस सुविधा का दुरुपयोग किया और वे चीन के आन्त-रिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। परिणाम यह हुआ, कि १७५७ में सम्राट् चिएन-लंग ने यह आजा प्रकाशित की, कि विदेशी यूरोपियन लोग केवल कैन्टन में ही व्यापार कर सकें, अन्यत्र नहीं । कैन्टन चीन का सबसे दक्षिणी बन्दरगाह था । १७५७ के बाद यूरोपियन व्यापारियों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे कैन्ट्रन के अतिरिक्त किसी अन्य बन्दरगाह में व्यापार के लिये आ जा सकें। चीन ने जो यह व्यवस्था की थी, उसका कारण यह नहीं था, कि चीनी लोग विदेशी व्यापार के विरोधी थे या उन्हें युरोपियन लोगों से कोई घृणा थी। ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिये चीनी सरकार ने अनुमति दे ही दी थी, पर साम्राज्यवादी यूरोपियन लोग चीन में जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, छसी से विवश होकर चीन के सम्राट ने उनके व्यापार के क्षेत्र को केवल कैन्टन तक सीमित कर दिया था।

कैन्टन के साथ ज्यापार कैन्टन में भी यूरोपियन ज्यापारियों को यह अनुमति नहीं थी, कि वे साल भर वहां रह सकें। ग्रीष्म ऋतु में उन्हें वहां रहने की अनुमति नहीं थी। वे केवल ज्यापार के दिनों में ही कैन्टन आकर रह सकते थे। अन्य गमय में उन्हें मकाओ चले जाना पड़ता था। ज्यापार के दिनों में भी यूरोपियन ज्यापारी अपने परिवारों को कैन्टन में नहीं ला सकते थे। चीनी सरकार इस बात के लिये उत्सुक थी, कि यूरोपियन लोग कैन्टन में अपनी स्थिर वस्तियां न बसा सकें।

सूरोपियन व्यापारियों को यह अनुमति नहीं थी, कि वे जिस किसी चीती व्यापारी से भार भरीद सकें दा जिस तिनी चीनी व्यापारी को अपना भार बेच सिकें। १००० में मझाट झारा एक व्यापारी को नियुत्त करने की व्यवस्था की मई थी, और पृथोपियर व्यापारियों को यह आदेश दिया गया था. कि वे केवल इस एक महाह के अनिनिधि आपारी से हो माल का अब विक्य कर सकें। सूरोपियन लोगोनो चीनरें जो गाउकारीयनाहोताथा,नेइस एक व्यापारी से उसे स्परीयसकते थे और इसी को वे अपना माल बेच सकते थे। पचास साल बाद १७५२में इस एक व्यापारी के स्थान पर व्यापारियों के एक संघ (को-होंग) का निर्माण किया, गया और यूरोपियन व्यापारियों को यह सुविधा दी गई, कि वे एक चीनी व्यापारी के स्थान पर इस व्यापारी संघ से माल का कय-विकय कर सकें। इस समय चीन के सब बन्दरगाह यूरोपियन लोगों के लिये खोल दिये गये थे, और इन विविध बन्दरगाहों में यूरोपियन देशों के व्यापारी को-होंग से माल का क्रय-विकय करता थे। १७५७ में कैन्टन के अतिरिक्त अन्य सब बन्दरगाह यूरोपियन लोगों के लिये बन्द कर दिये गये। को-होंग के व्यापारी कैन्टन में आ गये और वहीं पर चीन के साथ यूरोप के लोगों का सब व्यापार केन्द्रित हो गया। को-होंग में सम्मिलित व्यापारियों की संख्या तेरह थी। यूरोपियन व्यापारियों को यह अवसर नहीं था, कि वे अन्य किसी चीनी व्यापारी के साथ व्यापार कर सकें। इसी प्रकार यदि अन्य किसी चीनी व्यापारी को स्राप्त लोगों के साथ माल का क्रय विकय करना होता था, तो वह भी यह को-होंग की मार्फत ही कर सकता था।

यूरोपियन लोग कैन्टन शहर के बाहर निवास करते थे। वहां उनकी व्यापारिक कोठियां कायम थीं। यूरोपियन लोग चीनी भाषा सीखने का कष्ट नहीं उठाते थे। वातचीत व पत्र-व्यवहार के लिये उन्होंने चीनी लोगों को दुभाषिये के रूप में नौकरी में रखा हुआ था। कैन्टन के इन विदेशी व्यापारियों में इज्जलिश लोग सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थे। १७१५ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से कैन्टन में कोठी की स्थापना हुई थी। कम्पनी की ओर से वहां अनेक सुपरिन्टेन्डेन्ट निवास करते थे। स्वतन्त्र अंग्रेज व्यापारियों को यह अधिकार नहीं था, कि वे वाम्पनी से पृथक् अपना व्यापारकर सकें। १७८९ में अमेरिकन लोगोंने भी कैन्टन में अपनी कोठियां कायम की और इस प्रकार इज्जलिश, पोर्तुगीज, स्पेनिश, डच और फेञ्च लोगों के समान अमेरिकन लोग भी चीन के साथ अपने व्यापार का विकास करने में तत्वर हुए।

शुरू में विदेशी लोग चीन से केवल माल ही खरीदते थे। उनके पास कोई ऐसा माल नहीं था, जिसे वे चीन में बेच सकें। इसके विपरीत चीन की नाय, रेशम व मिट्टी के बरतन आदि की यूरोप में बहुत मांग थी। इन्हें खरीदकर यूरोपियन व अमेरिकन व्यापारी खूब ऊंची कीमत पर अन्य देशों में बेचते थे। चीन के माल की कीमत सोने चांदी में अदा की जाती थी। पर धीरे-धीरे इन कि विदेशी व्यापारियों ने चीन में भी बाहर से माल लाना शुरू किया। इङ्गलैण्ड में इस सगय तक व्यावरायिक चान्ति का प्रारम्भ हो चुका था। वहां कपड़े के बड़े बड़े कारदाने स्थापित होने शुक्त हो नये थे, जिनमें तैयार किये गये वस्त्र संसार के विविध

बाजारों में सस्ते मुल्य पर बिक सकते थे । इसी तरह कनाडा और संयुक्त राज्य ू अमेरिका के जंगलों से जो फर एकत्र की जाती थी, दुनिया के धनी लोग उन्हें वड़े शौक से खरीदन लगे थे। इङ्गलैण्ड के कपड़ों और अमेरिकाकी फरों की चीन में भी मांग बढ़ने लगी और इस प्रकार विदेशी माल का विकय भी चीन में शुरू हुआ। पर ब्रिटिश लोग केवल इतने से सन्तुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे, कि चीन में किसी ऐसे पदार्थ की खपत को बढ़ाया जाय, जिससे चीन में निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मात्रा अधिक हो जाय और उन्हें चीन के माल के लिये सोना चांदी के रूप में कीमत न अदा करनी पड़े। इस समय (अठारहवीं सदी) तक भारत के अनेक प्रदेश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रभत्त्व में आ चके थे। कम्पनी के व्यापारी वहां अफीम की खेती बड़े परिमाण में करा रहे थे और उनका यह प्रयत्न था, कि चीन में इस अफीम के लिये बाजार तैयार किया जाय। चीनी लोग अफीम के आदी नहीं थे। पर ब्रिटिश लोगों ने उन्हें अफीम का सेवन करना सिखाया। उन्होंने पहले तम्बाकू में अफीम मिलाकर चीनी लोगों को इसकी आदत डाली। एक बार अफीम के आदी होकर चीनी लोगों ने तम्बाकू के बिना शुद्ध रूपसे भी अफीम खाना व उसका हुक्का पीना शुरू किया। सन् १८०० तक चीन में अफीम का इतना अधिक प्रचार हो गया था, और इतनी अधिक अफीम यूरोपियन व्यापारियों द्वारा चीन में विकनी प्रारम्भ हो गई थी, कि उसकी कीमत उस माल की कीमत से अधिक बढ़ गई थी, जो विदेशी व्यापारी चीन से खरीदते थे। चीन की सरकार इस स्थिति से बहत चिन्तित थी। अफीम के प्रचार को वह अत्यन्त आपत्तिजनक समझती थी । स्वास्थ्य और नैतिकता दोनों की दृष्टि से अफीम का सेवन अत्यन्त हानिकारक था। अतः १८०० में चीन के सम्राट् ने यह आज्ञा प्रकाशित की, कि कोई विदेशी व्यापारी चीन में अफीम न ला सके। अफीम का ऋय विऋय गैर-कानुनी घोषित कर दिया गया, पर इससे भी उसका प्रचार रुका नहीं। यूरोपियन व्यापारी छिपकर अफीम को चीन में लाते थे, और चीनी लोग उसके इतने अधिक आदी हो चुके थे, कि उसे छिपकर खरीदते थे। सरकारी अफसर भी इस व्यापार में सहायक थे, वयोंकि इससे उन्हें बहुत आमदनी थी। यूरोपियंन व्यापारियों से रिक्वत लेकर वे उन्ह अफीम बेचने से नहीं रोकते थे और इस प्रकार अफीम का ूर्यापार निरन्तर उन्नति करता जाता था । पर चीन की सरकार इस ओर से विमुख नहीं थी। वह अनुभव करती थी, कि अफीम से देश को भारी नुकसान पहुंचता है, अतः वह इस बात ने लिये प्रयत्नवील भी कि जिम प्रकार भी सम्भव हो, अफीम के व्यापार को रोका जाय । १८३८ में चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार के विकड़ सक्त कार्रवाई शुरू की । परिणाम यह दुआ, कि अंग्रेज व्यापारियों की नुससार

होने लगा। आर्थिक दृष्टि से अफीम का व्यापार अंग्रेजों के लिये अमदनी का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन था। उसे नष्ट होता देखकर उनके रोष की सीमा नहीं रही। इसी का यह परिणाम हुआ, कि अंग्रेजों की चीन के साथ लड़ाई का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश लोग अपने स्वार्थ के कारण इस बात की जरा भी चिन्ता नहीं करते थे, कि अफीम से चीन के लोगों को कितना अधिक नुकराान पहुंच रहा है। वे समझते थे, कि उन्हें इस बात का पूरा अधिकार है, कि जिस माल को चाहें चीन में वेच सकें। अपने व्यापार पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण उन्हें सहा नहीं था। चीनी सरकार जो अफीम के व्यापार पर स्कावट डाल रही थी, उसका कारण भी केवल नैतिक नहीं था। अफीम की मांग के अत्यधिक बढ़ जाने से चीन में एक प्रकार का आर्थिक संकट उपस्थित हो रहा था। निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मांत्रा अधिक बढ़ गई थी और इस माल की कीमत चीन के लोगों को सोना चांदी के रूप में अदा करनी पड़ती थी। इससे देश का धन निरन्तर विदेशों में पहुंच रहा था, और यह स्थिति चीन के लिये अत्यन्त चिन्ताजनक थी।

(२) इंगलैण्ड और चीन का युद्ध

युद्ध के कारण—अफीम के ज्यापार को बन्द कर देने के कारण मिटिश ज्यापा-रियों को बहुत अधिक नुकसान था। इसलिये वे इस बात के लिये उत्सुक थे, कि चीन के साथ युद्ध को शुरू कर ज्यापार सम्बन्धी अधिक सुविधाएँ प्राप्त करें। पर निटेन और चीन के युद्ध का एकमात्र कारण अफीम की समस्या ही नहीं थी। इस युद्ध के कारणों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है—

- (१) ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि चीन में अपना प्रभुत्य स्थापित करें। उन्नीसवीं सदी के शुरू तक भारत के अनेक प्रदेश ब्रिटेन के प्रभुत्य में आ चुके थे। भारत में ब्रिटेन का आधिपत्य निरन्तर बढ़ता जा रहा था। पूर्वी एशिया के अन्य भी अनेक प्रदेशों व द्वीपों पर ब्रिटिश लोग अपना शासन स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे। वे समझते थे, कि चीन की निर्वलता से लाभ उठाकर वहां भी अपना प्रभाव कायम किया जा सकता है।
- (२) इस युग में यूरोपियन लोगों में अपनी उत्कृष्टता की भावना मलीभाति विकसित हो चुकी थी। व्यावसायिक क्रान्ति और वैज्ञानिक उन्नति के कारण यूरोप के देश एशिया के लोगों के मुकावले में उन्नति की दौड़ में बहुत आगे निकल गये थे। इसलिये उनमें यह विचार बढ़मूल हो गया था, कि हम एशिया व अफीका के निवासियों की अपेक्षा बहुत उत्कृष्ट है। प्रभुत्त्व शक्ति (सोविरेनिटी) राज्यों की एक अनिवार्य विशेषता होती है, चीन भी एक प्रभुत्त्वशक्ति सम्पन्न राज्य है और

उसे यह अधिकार है, कि व्यापार आदि के सम्बन्ध में अपनी इच्छानुसार व्यवस्था . कर सके, यह बात उनकी समझ में नहीं आती थी । चीनी सरकार ने यह व्यवस्था की थी, कि विदेशी व्यापारी केवल को-होंग द्वारा व्यापार कर सकें, जनता व सरकार के साथ उनका सीवा सम्पर्क न हो । पर ब्रिटिश लोग कहते थे, कि कैन्टन में स्थित उनके सुपरिन्टेन्डेन्ट ब्रिटेन के प्रतिनिधि हैं। चीनी सरकार को चाहिये, कि उनके साथ वैसा व्यवहार न करे, जैसा कि साधारण व्यापारियों के साथ किया जाता है । उन्हें ब्रिटेन का प्रतिनिधि माना जाना चाहिये। १८३४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार का अन्त कर दिया गया था। ब्रिटिश व्यापारियों को यह अधिकार दे दिया गया था, कि वे कैन्टन में स्वतन्त्र रूप से व्यापार कर सकें। इस दशा में ब्रिटिश सरकार ने वहां एक सुपरिन्टेन्डेन्ट की नियक्ति कर दी थी, जो विविध ब्रिटिश व्यापारियों के कार्यों पर निगाह रखता था। १८३४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एकाधिकार का अन्त होने के बाद सुपरिन्टेन्डेन्ट के इस पद पर लाई नेपियर की नियुक्ति की गई। कैन्टन में लार्ड नेपियर का कार्य राजनीतिक नहीं था, उसकी नियक्ति केवल व्यापार के लिये हुई थी। इस दशा में चीन की सरकार को यह अधिकार था, कि वह उसके साथ कोई सम्बन्ध न रखे । चीनी सरकार का कहना था, कि सरकार का व्यापार के गामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका कार्य केवल यह ह, कि वह जनता का शासन करे और अपराधियों को दण्ड दे। व्यापार सदश विषय ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध व्यापारियों से हैं, राज्य से नहीं है। इसलिये यदि चीनी सरकार लार्ड नेपियर से कोई सम्बन्ध नहीं रखना नाहती थी, तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं था। पर ब्रिटिश लोग समझते थे, कि चीनी सरकार उन्हें नीची निगाह से देखती है, इसीलिये ब्रिटेन के प्रतिनिधि से वह कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहती । पर वास्तविक बात इससे ठीक उलटी थी । कैन्टन में विद्यमान ब्रिटिश व्यापारी अपने को केवल व्यापारी ही नहीं समझते थे। वे चीन में ब्रिटिश प्रभाव को स्थापित करने के लिये उत्स्व थे और इसी कारण यह समझते थे, कि जनका सुपरिन्टेन्डेन्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होने के कारण यह अधिकार रखता है, कि व्यापार विषयक मांमलों पर सम्राट्या उसके उच्च अधिकारियों से ब्रिटिश राजदूत के रूप में विचार विनिमय कर सके। चीन की सरकार ब्रिटिश ृमुपरिन्टेन्डेन्ट की इस स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थी। ब्रिटेन और चीन में जी विरोध बढ़ रहा था, उसमें यह भी एक प्रधान कारण था।

(३) कैन्टन में निवास करनेवाले बिटिश लोग कानून की दृष्टि से चीन के अधीन हैं या नहीं, इस प्रश्न पर भी बिटेन और चीन में मतभेद था। १७८४ में एक अंग्रेज की बन्दूक से एक चीनी नागरिक की हत्या हो नई थी। चीन की सरकार

का कहना था, कि इस अंग्रेज को चीनी पुलीस के सुपुर्व किया जाय और चीनी अवालत में उसके अपराध का निर्णय हो । ब्रिटिश लोग कहते थे, यह सम्भव नहीं है कि कोई अंग्रेज चीन की अदालत के सम्मुख पेश हो और वहां उसके अपराध का निर्णय किया जाय । १७८४ के इस मामले में उस अंग्रेज को गिरणतार करके चीनी अदालत द्वारा प्राणदण्ड दिया गया । अंग्रेज लोग इससे बहुत असंतुष्ट हुए । १७९३ में मैकार्टने नामक अंग्रेज के नेतृत्त्व में एक ब्रिटिश मिशन ने यह प्रयत्न किया, कि केन्टन की अंग्रेज वस्ती में अंग्रेजों को स्वशासन का अधिकार मिले और अंग्रेज अभियुक्तों का निर्णय अंग्रेजी अदालत द्वारा ही हो । पर इस प्रयत्न में मैकार्टने मिशन को सफलता नहीं हुई । १७९३ के बाद भी अनेक ऐसे मामले पेश आये, जिनमें िटिश अभियुक्तों पर चीनी अदालतों में मुकदमे दायर किये गये और वहां उन्हें दण्ड दिया गया । ब्रिटिश लोग इस बात से बहुत असन्तुष्ट थे । उन्हें यह अत्यन्त अपमान-जनक प्रतीत होता था, कि चीन का न्यायाधीश किसी अंग्रेज के मामले का निर्णय करें।

(४) अफीम की समस्या ब्रिटेन और चीन के इस युद्ध का प्रमुख व तात्कालिक कारण थी। १८३९ में चीन की सरकार ने कैन्टन में एक विशेष राजकमंचारी की नियुक्त की, जिसे अफीम के व्यापार का अन्त करने का कार्य सुपुर्द किया गया। उसने ब्रिटिश व अन्य यूरोपियन व्यापारियों को इस बात के लिये विवश किया, कि उनके पास अफीम की जो पेटियां हों, उन सबको वे सरकार को दे तें, ताकि उन्हें नष्ट कर दिया जाय। इस राजकर्मचारी ने यह भी कहा, कि यूरोपियन व्यापारियों को यह भी आश्वासन देना होगा कि वे भविष्य में फिर कभी अफीम कैन्टन में नहीं लावेंगे। ब्रिटिश व अन्य यूरोपियन व्यापारियों ने अपने पास विद्यमान अफीम को तो चीनी राजकर्मचारी के सुपुर्द कर दिया, पर वे भविष्य के लिये किसी प्रकार का आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हुए। उनका खयाल था, कि वे शक्ति का उपयोग कर चीनी सरकार के आदेश की उपेक्षा कर सकते हैं। इस दशा में युद्ध का प्रारम्भ हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था।

चीन और ब्रिटेन का मुब्ब — १८३९ से १८४२तक चीन और त्रिटेन का युद्ध जारी रहा। ब्रिटिश जलसेना ने कैन्टन का घेरा डाल दिया। समुद्र में ब्रिटेन की शिवत का मुकाबला कर सकना चीन के लिये कठिन था। प्रशान्त महासागर के तटवर्ती अनेक नगर और द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में आ गये। ब्रिटिश सेना ने चिक्कि यांग को भी जीत लिया और नानिका पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। इस दशा में चीनी सरकार ने यही उचित समझा, कि ब्रिटेन के साथ समझीते की बात प्रारम्भ की जाय। अस्त्र-शस्त्र और सैन्य की दृष्टि से इस समय चीनी लीग

ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। २९ अगस्त, १८४२ के दिन चीन और ब्रिटेन में समझीता हो गया। यह समझौता नानिकंग की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है।

नानिकंग की सन्धि—इस सिन्ध की मुख्य शर्ते निम्नलिखित थीं:—(१) बिटिश लोगों को न केवल केन्टन में, अपितु अमाँय, फूचो, निगपो और शंघाई में भी बसने और ज्यापार करने का अधिकार हो। (२) हांगकांग का द्वीप ब्रिटेन को मिले। (३) चीन और ब्रिटेन के राजकर्मचारी परस्पर समानता के आधार पर रहें। (४) चीन के निर्यात और आयात माल पर किस हिसाब से कर लगाया जाय, इसकी दरें निश्चित कर ली जावें और इन दरों को प्रकाशित कर दिया जाय, ताकि उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न रहे। (५) को-हांग को तोड़ दिया जाय और बिटिश ज्यापारी चीनी ज्यापारियों के साथ स्वतन्त्ररूप से माल का कय विकय कर सकें। (६) चीनी सरकार ब्रिटेन को दस करोड़ रुपया हरजाना दे। इसमें से तीन करोड़ रुपया उस अफीम की कीमत थी, जो चीनी सरकार के विशेष कर्मचारी ने ब्रिटिश लोगों से छीनकर नष्ट कर दी थी। छः करोड़ रुपया लड़ाई के खर्च के लिये चीनी सरकार को हरजाना देना पड़ा था, और शेष रकम वह थी, जो कि को-होंग के ज्यापारियों को ब्रिटिश ज्यापारियों को प्रदान करनी थी।

अन्य राज्यों से सन्धियां—नानिकंग की सन्धि के बाद अन्य पादचात्य देशों ने भी चीन से इसी ढंग की सन्धियां करने का प्रयत्न किया । संयक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री. टाइलर ने श्री. कांशग को चीन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और श्री. किंवा को यह कार्य सुपूर्व किया गया था, कि वह चीन जाकर सम्राट् से मिले। यदि सम्राट्से भेंट कर सकता सम्भवनहो, तो वहकिसी अन्य उच्च राज्य पदाधिकारी से मिलकर अमेरिका के साथ सन्वि स्थापित करने का प्रयत्न करे। २४ फरवरी, १८४४ को श्री. कशिंग मकाओ पहुंचे । वे पेकिंग जाकर सम्राट् से तो नहीं मिल सके, पर चीन के साथ सन्धि करने में सफल हुए। इस अमेरिकन सन्धि की शर्तें प्रायः वही थीं, जो नानिकंग की सन्धि की थीं। पर इनमें एक शर्त नई व अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। इस वर्त के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी, कि यदि चीन के किसी नागरिक के खिलाफ यह अभियोग हो, कि उसने किसी अमे-रिकन नागरिक के साथ किसी प्रकार की फौजदारी की है, तो उसपर चीनी अदालत ूमें मुकदमा चले और उसे चीनी कातृत के अवसार वण्ड दिया जाय । इसी प्रकार यदि ैंकिसी अमेरिकन नागरिक पर फॉलटारी का कोई अभियोग हो, तो उसका फैसला अमेरिकन अदालत में अमेरिकन कानन के अनसार किया जाय । ऊपर से देखने पर यह शर्त बहुत उचित और त्याच्य प्रतीत होती है । पर इससे चीन में उस पद्धति का प्रारम्भ हुआ, जिस अंग्रेजी में 'एनन्ट्रा-टैरिटोरिएल्लिटी' कहते हूं । यह तो उचित

ही था, कि चीन के नागरिकों के मुनदमों का फैसला चीनी अदालत में हो । पर प्रमुख शिवतसम्पन्न चीनी राज्य को अमेरिकन अभियुक्तों के अपराधों का फैसला करने का अधिकार न हो, यह बात चीन की प्रभुत्वशितसम्पन्नता और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सर्वथा विपरीत थी । कुछ समय बाद दीवानी मामलों में भी अमेरिकन नागरिकों के मुकदमों का फैसला अमेरिकन अदालतें ही करें, यह बात भी चीन की सरकार ने स्वीकार कर ली । इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ, कि चीन में निवास करनेवाल अमेरिकन लोग चीनी सरकार के शासन में नहीं रह गये । चीनी सरकार न उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी और न उन्हें किसी प्रकार का दण्ड दे सकती थी । इस व्यवस्था के कारण चीन में विदेशी लोगों के एक इस प्रकार के प्रभुत्य का स्त्रपात हुआ, जिसने चीन की प्रभुता और स्वतन्त्र सत्ता को भारी आघात पहुंचाया । अमेरिका के बाद ब्रिटेन व अन्य यूरोपियन राज्यों ने भी 'एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी' के इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त किये ।

अमेरिका और ब्रिटेन के अनुकरण में कुछ समय बाद फांस ने भी चीनी सरकार के साथ सिन्ध की । इस सिन्ध में एक विशेष बात यह थी, कि फांस के रोमन कैथो- िलक भिश्तनिरयों को यह अधिकार दिया गया, कि वे कैन्टन व अन्य वन्दरगाहों में (जो कि अब यूरोपियन व्यापारियों के लिये खोल दिये गये थे) अपने गिरजाघरों का निर्माण कर सकें, और अपने धर्म का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार कर सकें । बाद में अन्य पाश्चात्य देशों के ईसाई पादियों को भी यह अधिकार दिया गया और रोमन कैथोलिक व प्रोटेस्टेन्ट पादरी गिरजाघरों के निर्माण व धर्म-प्रचार के कार्य में सर्वथा स्वतन्त्र हो गये।

सिन्धियों का परिणाम—बिटेन, अमेरिका और फांस के साथ जो संधियां उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में हुई, उनका मुख्य परिणाम यह हुआ, कि जीन के विशाल प्रवेश पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के विस्तार के लिये खुल गये। इन सिन्धियों का प्रयोजन केवल यह नहीं था, कि पाश्चात्य लेगे चीन के साथ न्यापार कर सकने की उचित सुविधायें प्राप्त कर सकें। पाश्चात्य देशों के लोग इन सिन्धियों हारा चीन में ऐसे अधिकारों को प्राप्त कर रहे थे, जो आगे चलकर उनकी प्रभुता व शिक्त की स्थापना में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुए। कैन्टन आदि बन्दरगाहों में अब पाश्चात्य देशों की न्यापारिक कोठियां के साथ साथ उनकी बस्तियां भी विकासित होनी शुन्त हुई। इन बस्तियों में ये देश अपनी सेना रखते थे और अपने देशवासियों का शासन भी स्वयं करते थे। ज्यावसायिक और वैज्ञानिक वृष्टि से चीनी लोग पाश्चात्य लोगों के मुकाबले में पिछड़े हुए थे। सैनिक वृष्टि से उनकी शिक्त पाश्चात्य देशों की अपेक्षा कम थी। इस स्थिति से लाभ उठाकर पाश्चात्य

देश इस जात के लिये प्रयत्नशील थे, कि चीन की सरकार पर सब प्रकार मे दबाव डालकर उसे विदेशियों को सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करने के लिये विवश करें।

(३) पाञ्चात्य राज्यों से चीन का दूसरा युद्ध

१८४२ में ब्रिटेन और चीन में जो सन्धि हुई थी, ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि अब उसे दोहराया जाय। अमेरिका और फांस के साथ की गई सन्धियों में तो इस बात की व्यवस्था भी की गई थी, कि दस साल बीत जाने पर इन सन्धियों को दोहराया जायगा। ब्रिटेन, अमेरिका और फांस अनुभव कर रहे थे, कि चीन पर दबाव डालकर उसे सन्धियों को दोहराने के लिये विवश किया जा सकता है।

युद्ध के कारण--(१) पाश्चात्य लोग समझते थे, कि चीन में अपने प्रभाव की बढ़ाने का एक ही उपाय है, वह यह कि उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जाय ! व्यापार की सुविधायें प्राप्त करने की आड़ में वे अपने साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्नशील थे। (२) कैन्टन आदि बन्दरगाहों में अनेक ऐसे मामले पेश आते रहते थे, जिन पर चीनी व पाश्चात्य लोगों में मतभेद व विवाद बहुत सुगम था । कैन्टन के समीप एक जहाज लंगर डाले हुए पड़ा था, जिसका मालिक एक चीनी व्यापारी था । पर यह जहाज हांगकांग में रिजस्टर्ड था और हांगकांग पर ब्रिटेन का अधि-. कार स्वीकृत किया जाता था। चीन के एक राजपदाधिकारी की आज्ञा से इस जहाज के मल्लाहों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश लोगों ने दावा किया, कि इन मल्लाहों को गिरफ्तार कर सकने का अधिकार चीन की पुलिस को नहीं है । चीनी पदाधिकारी समझते थे, कि क्योंकि जहाज का मालिक चीन का एक नागरिक है, अतः उनको पूरा अधिकार है, कि वे उसके मल्लाहों को गिरफ्तार कर सकें। इस मामले ने बहुत गम्भीर रूप घारण किया । इसी प्रकार की अन्य भी समस्यायें जल्पन होती रहती थीं, जिनका मूल कारण यह था, कि कैन्टन आदि बन्दर-गाहों में पारचात्य लोग भी अपने विशेष अधिकार समझते थे। (३) १८५६ में फ्रांस का एक रोमन कैथोलिक पादरी चीनी पूलीस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह पादरी अपने धर्म प्रचारके सिलसिलेमें चीन में बहुत दूर तक चला गया था और वहां कतिपय ऐसे कार्यों में लगाहुआथा,जिन्हें चीनीसरकार आगत्तिजनक समझती थीं । इस पादरी पर चीनी अदालत में मुकदमा चलायां गया और इसे प्राणदण्ड ्दिया गया।

्रियुद्ध की प्रगति—१८५६ में एक विकित सेना ने कैनल पर करवायण किया और उसे जीतकर अपने अभीन कर रिश्त । केन्द्रन को दी कर को दिया है से सेना ने उसेर की तरफ प्रदर्शन किया । केन्द्र कीन इत बुद्ध में ब्रिटेन के प्रहारक थे । जिटेन की इन्छ। भी, कि अमेरिका और इस भी इस मुद्ध में असकी सहारता गरे, पर अमेरिका और रूस ने उदासीन रहना ही उचित समझा । कैन्टन से उत्तर की ओर आगे बढ़ती हुई ब्रिटिश और फ्रेंच सेनायें तीनित्सन तक पहुंच गईं। अब चीन की सरकार के सम्मुख एक ही उपाय था, वह यह कि पाश्चात्य देशों की मांग को स्वीकृत कर ले और इन देशों के साथ जो सन्धियां पहले स्थापित हुई थीं, उन पर

पुनर्विचार करे।

तीन्त्सन में सन्धि के लिये बातचीत शुरू हुई। पर नई सन्धियां की अन्तिम स्वीकृति पेकिंग की केन्द्रीय सरकार द्वाराही दीजा सकतीथी। यथिप तीन्त्सन में सन्धि की शतों के सम्बन्ध में समझौता हो गया था (१८५८), पर पेकिंग में वे स्वीकृत नहीं हो सकीं। इस दशा में ब्रिटेन और फांस ने एक बार फिर चीन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इस बार वे आक्रमण करते हुए पेकिंग तक पहुंच गये। चीनी सेनायें उनका मुकाबला कर सकने में असमर्थ रहीं। पेकिंग पर ब्रिटिश और फेंच सेनाओं का कब्जा हो गया, और मञ्चू सम्राट् पेकिंग छोड़कर बाहर चले जाने के लिये विवश हुआ। ब्रिटिश और फेंड्च सेनाओं ने चीन के सम्राट् की राजसत्ता की जरा भी परवाह नहीं की। उन्होंने उसके एक प्रासाद को भस्म कर दिया। अब चीनी सरकार के सम्मुख इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था, कि इन विदेशी राज्यों के साथ इनकी इच्छानुसार सन्धि कर ले।

१८६० की सन्धि-१८५६-६० के यद्ध के बाद विदेशी राज्यों के साथ चीन की जो नई सन्धि हुई, उसकी मुख्य शर्ते निम्नलिखित थीं--(१) ग्यारह नये बन्दरगाह पाश्चात्य देशों के न्यापार व निवास के लिये खोल दिये गये । ये बन्दर-गाह उत्तर में न्यच्यांग (मंच्रिया में) से शुरू कर दक्षिण में स्वातो तक फैले हुए थे। कैन्टन आदि पांच बन्दरगाहों में पाश्चात्य लोगों को पहले ही व्यापार और निवास का अधिकार प्राप्त था। अब इस प्रकार के बन्दरगाहों की संख्या सोलह हो गई। प्रशान्त महासागर के तट पर स्थित प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण वन्वरगाहों में अपनी बस्तियां बसाने व स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने का अधिकार इस सन्धि द्वारा पाश्चात्य देशों ने प्राप्त कर लिया । (२) पाश्चात्य देशों के जहाजों को यह अन-मति दी गई, कि वे यांग-त्से नदी में आ जा सकें। (३) पाश्चात्य देश अपने राज-दूत पेकिंग में रहने के लिये भेज सकें, यह स्वीकृत किया गया। (४) जिन विदे-शियों के पास बाकायदा पासपोर्ट हों, वे चीन में जहां चाहें स्वतन्त्रता के साथ आ जा सकें। (५) ईसाई घर्म प्रचारकों को यह अधिकार हो, कि वे चीन में अपने ... धर्म का प्रचार कर सकें और जो चीनी नागरिक ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें, उन्हें अपने धर्म के पालन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। (६) फांस के रीमन कैयोलिक पादरियों को अधिकार हो, कि वे ऊपर लिखे सोलह बन्दरगाहों के अति-

रिक्त भी चीन में जहां चाहें, जभीन को खरीद सकें या किराये पर ले राकें और उस पर गिरिजाघर व अन्य इमारतें बना सके। (७) एक्स्ट्रा-टेरिट्रेरिएएलिटी की नीति को ओर अधिक विशद किया गया और उन नियमों को बहुत स्पष्ट और विशद रूप से बनाया गया, जिनके अनुसार पाइचात्य लोगों को चीन में रहना है। (८) चीन की गरकार युद्ध के लिये ब्रिटेन और फ्रांस को हरजाना प्रदान करे. यह ब्यवस्था की गई। (९) अफीम के ब्यापार के लिये पाइचात्य देशों को अनुमित देना चीनी सरकार ने स्वीकृत किया।

१८५६-६० के युद्ध में रूस चीन का भित्र रहा था। पर वह उतर की तरफ से चीन की सीमा की ओर निरन्तर आगे तढ़ रहा था। १८५८ में चीन की सरकार ने स्वीकृत किया, कि आगूर नदी के उत्तर का चीनी प्रदेश रूस को दिया जाता है। इसी प्रकार १८६० में उसूरी पूर्व के प्रदेश पर रूम के अविकार को स्वीकृत किया गया। ये प्रदेश पहले चीन के अन्तर्गत थे। पर रूस पूर्वी एशिया में अपने आधिपत्य का विस्तार करने में तत्पर था। इन प्रदेशों को यह पहले ही हस्तगत कर चुका था। १८५८ और १८६० में चीन की सरकार ने इन प्रदेशों पर रूस के प्रभुत्त्व को स्वीकृत कर लिया।

इन सन्धियों की विवेचना---१८४२ मे १८६० तक चीन ने पारचात्य देशों के साथ अनेक सन्वियां कीं। पर चीन ने ये सन्वियां स्वेच्छापूर्वक नहीं की थीं। पाश्चात्य देशों ने अपनी सैन्यशक्ति का प्रयोग कर चीन को इन सन्धियों के लिये विवश किया था । चीनी लोगों को इन सन्धियों के खिलाफ मुख्य शिकायतें निम्न-लिखित थीं--(१) चीनी लोग समझते थे, कि ये सन्वियां वैसी नहीं हैं, जैसी कि समान स्थिति के राज्यों में की जाती हैं। इनके कारण जो बिशेष अधिकार पाक्चात्य लोगों ने चीन में प्राप्त किये, उसी तरह के अधिकार चीनी लोगों को इन यरोपियन देशों व अमेरिका में नहीं दिये गये थे। (३) चीनी सरकार का यह स्वयंसिद्ध अविकार था, कि वह इस बात का निश्चय कर सके कि उसके निर्यात व आयात माल पर कितना कर लगाया जाय । राज्य की प्रभुता की दृष्टि से इन करों का निर्णय करते हुए किसी भी विदेशी राज्य से बातचीत व समझौते की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। पर इन सन्धियों द्वारा यह भी निश्चित किया गया था, कि ्यायान और नियान माल पर दैनम की दर नमा हो । चीनी सन्कार के लिये यह र्मभाष नहीं था, कि पारचारम देजों से समर्दाति के दिना देवत की इन दरों में परिकर्तन क्षण सके । यह बात जाद्दीय स्थलस्वता और गौरक की दृष्टि ने अस्यत अने जिल्लाकी से (६) एनसम्। इंग्लिसिएकिटी के स्पानि जो विशेष अधिकार चीत में पावसास्य देशों में अपन फिले थे, ये हो किसी भी अकार उनिहान नवाजगंगन नहीं अगले जा सकते

थे। ये विशेषाधिकार चीन के लोगों की दृष्टि में बहुत ही अनुचित थें, क्योंकि भिटेन, फांस, अमेरिका आदि किसी भी देश में इस प्रकार के अधिकार चीनी लोगों को नहीं दिये गये थे। पाश्चात्य लोग इनका दुरुपयोग करने में भी संकोच नहीं करते थे। उन्हें इस वात का जरा भी भय नहीं था, कि चीनी पुलीस उन्हें गिरफ्तार कर सकेगी या चीनी अदालतों द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का दण्ड मिल सकेगा। इस कारण वे चीनी नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और बहुधा ऐसा उद्दण्डतापूर्ण व्यवहार करते थे, मानो वे किसी अधीनस्थ देश में निवास कर रहे हों।

आश्राज्यवाद—१८४२ और १८६० की इन सिन्धयों द्वारा चीन का पाइचात्य देशों के साथ जिस ढंग का सम्बन्ध स्थापित हुआ था, उसे समान रूप से स्वतंत्र व प्रभुत्त्वशिक्तसम्पन्न देशों का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। यह पाइचात्य साम्राज्यवाद का एक नया रूप था और सैन्यशिक्त का उपयोग कर इसे स्थापित किया गया था। इस नये प्रकार के साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में निम्निलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं—

- (१) १८४२ की सन्धि द्वारा हांगकांग का प्रदेश ब्रिटेन की प्राप्त हुआ था। इसकी स्थिति एक काउन कोलोनी के समान थी। चीनी सरकार का इसके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा था। ब्रिटिश लोगों ने यहां एक संमृद्ध नगर का विकास किया और कुछ समय बाद यह प्रशान्त महासागर के चीनी तट के समीप का सबसे अहस्वपूर्ण बन्दरगाह बन गया। इसके बहुसंख्यक निवासी चीनी लोग थे, पर राजनीतिक दृष्टि से यह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत था।
- (२) कैन्टन आदि सोलह नगर जिन्हें इतिहास में ट्रीटी पोर्ट (सिन्ध के अधीन बन्दरगाह) कहा जाता है, विदेशी राज्यों के प्रभुत्त्व में थे। धीरे धीरे इन नगरों में ऐसी बस्तियों का विकास हुआ, जिस पर चीनी सरकार का कोई भी अधिकार नहीं था। एक्स्ट्रा-टेरिटोरिएलिटी की पद्धित के कारण ये बस्तियां पूर्ण रूप से विदेशी लोगों के कब्जे में थीं और इनका शासन भी उन्हों के द्वारा होता था। उदा-हरण के लिये शंघाई को लीजिये। शंघोई के पुराने नगर के बाहर ब्रिटिश, अमेरिकन और फेंच लोगों की पृथक् पृथक् बस्तियां थीं, जिनका शासन इन बिदेशी लोगों के हाथ में था। बाद में अमेरिकन और बिटिश बस्तियां मिलकर एक हो गईं, और उन्हें एक अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती का रूप प्राप्त हुआ। शंघाई की इस अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती का शासन करने के लिये एक म्युनिसिपल कौंसिल का निर्माण किया गया, जिसकें लिये सदस्य चुनने का अधिकार केवल विदेशी लोगों को प्राप्त था। यद्यपि शंघाई की इस अन्तर्राष्ट्रीय नगरी (या बस्ती) की बहुसंख्यक जनता चीनी थीं, पर चीनी लोगों को इस कौंसिल के चुनाव के लिये वोट तक देने का अधिकार नहीं

था। चीन के ये सोलह नगर सामुद्रिक व्यापार के लिये अत्यधिक महत्त्व रखते थे। चीन के विदेशी व्यापार के ये ही केन्द्र थे। पर इन पर विदेशी लोगों का इस प्रकार का अधिकार चीन की स्वतन्त्रता के लिये विघातक था।

- (३) चीन के निर्यात और आयात माल पर चीनी सरकार जो टैक्स लेती थी, पहले उसे बसूल करने के लिये चीनी कर्मचारी नियुक्त होते थे। पर बाद में (१८६०) यह कार्य भी विदेशी लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। इसके लिये एक इम्पीरियल मेरीटाइम कस्टम्स सर्विस संगठित की गई, जिसका पहला अध्यक्ष (इन्स्पेक्टर जनरल) रोवर्ट हार्ट नाम का एक आयरिश था। इस सर्विस के लोग चीनी सरकार की नौकरी में समझे जाते थे, पर इसके बहुसंख्यक कर्मचारी यूरोपियन व अमेरिकन थे। तटकर चीनी सरकार की राजकीय आमदनी का अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण साधन था। इसे बसूल करनेवाली सर्विस जब विदेशी लोगों के हाथ में चली गई, तो चीन की सरकार पर विदेशी लोगों का प्रमुक्त और अधिक दृढ़ हो गया।
- (४) चीन का सब विदेशी व्यापार मुख्यतया विदेशी लोगों के हाथ में था। समुद्र के मार्ग से जो भी माल चीन से जाता था या चीन में आता था, उस सबकी सुलाई विदेशी जहाज करते थे। व्यापार के लिये इस समय चीन में अनेक वैंकों की स्थापता हुई, जिनमें सबसे मुख्य हांगकांग एण्ड शंघाई वैंकिंग कारपोरेशन था।
- (५) चीन के बन्दरगाहों में विदेशी लोग वड़ी संख्या में तिवास करते थे। चीनी जनता से इनका सम्पर्क नाममात्र की था। ये शहर से बाहर अपनी पृथक् बस्तियों में बड़ी शान शौकत और समृद्धि के साथ रहते थे और चीनी लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। चीनी भाषा को सीखने तक की ये विदेशी लोग आवश्यकता अनुभव नहीं करते थे। ये अपने को चीनियों से उत्कृष्ट समझते थे और उनकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं करते थे।

इस प्रकार चीन में पारचात्य देशों द्वारा एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था, और चीन की सरकार उसके सम्मुख अपने को असहाय अनुभव करती थी।

(४) ईसाई मिशन और उनका विरोध

ईसाई मिशन—चीन के सुविस्तृत प्रदेशों को पाश्चात्य देशों के प्रभाव में लान में पाश्चात्य व्यापारी जितने सहायक हुए, उसके कहीं अधिक ईसाई मिश-नियों ने इस पाश्चा में आर्य किया। १८५८ और १८६० की सन्धियों द्वारा ईसाई मिशनरियों को यह अधिकार प्राप्त हो गया था, कि वे चीन में जहां चाहें आ जा नजें और अपने पर्म का प्रनार कर सकें। फांम के रोमन कैथोलिक पाटरियों को यह अधिकार भी कि अपने को स्त्रीतकर या किराये पर लेकर

गिरजाधरों व अन्य इमारतों का निर्माण कर सके । इन मन्वियों का लाग उठाकर ईसाई मिक्नरियों ने चीन में दूर-दूर तक आना जाना स्कृतिया। ये पादरी न केवल अपने धर्म का प्रचार करते थे, अपित चीनीलोगों के धार्मिकविक्यासों, विधि विधानों और पूजा के नरीकों पर आक्षेप भी करते थे। चीन की सर्व माधारण जनता इसमें बहुत उद्देग अनुभव करती थी।

विरोध के कारण — ईसाई पादिरयों के खिलाफ चीन में जो भावना उत्पन्न हो रही थी, उसके कारण निम्नलिखित थे—

- (१) पाक्चात्य देशों के ईसाई मिशनरी चीन मे दूर दूर तक फैले हुए थ। उनकी जान व माल को कोई क्षित न पहुंचे, इसकी उत्तरदायिता चीनी सरकार पर थी। पर यदि किसी पादरी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंच जावे, तो पादरी लोग चीन के राजकर्मचारी से अपनी रक्षा व क्षितपूर्ति के लिये आवेदन करना अपने लिये अपमानजनक समझते थे। वे अपने देश के राजदूत व कैन्टन आदि वन्दरगाहों में निवास करने वाले व्यापारियों व अन्य कर्मचारियों से सहायता की अपील करते थे। विदेशी लोग तो सदा इस बात की प्रतीक्षा में ही रहते थे, कि उन्हें कोई वहाना मिले और वे चीन की प्रभुता व स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करें और इसके लिये सैन्यशक्ति का उपयोग करें। मुदूरवर्ती किसी प्रदेश में किसी ईसाई पादरी पर आक्रमण हो गया, या उसके साथ किसी प्रकार का झगड़ा हो गया, तो उसके देशवामी उसके मामले को लेकर चीन के विरुद्ध शस्त्र प्रयोग करने में जरा भी संकोचनहीं करते थे। यह बात चीनी लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुमती थी।
- (२) जो चीनी नागरिक ईसाई धर्म को स्वीकृत कर लेते थे, पाश्चात्य देशों के विदेशी पादरी उचित अनुचित सब उपायों से उनका पक्ष लेते थे। यदि इन चीनी ईसाइयों ने अपने देश के किसी कानून का उल्लंघन किया हो, या कोई अपराध किया हो, तो भी ईसाई पादरी यह चाहते थे, कि चीन के सरकारी कर्मचारी उन्हें दण्ड न दे सकें। वे चीनी ईसाई को अपनी प्रजा समझते थे, और यह बात चीन के लोगों को बहुत बुरी लगती थी।
- (३) केवल कानून का उल्लंघन करने व अपराध करने के मामलों में ही ईसाई पादरी हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे चीनी अदालतों के साधारण मामलों में भी ईसाईयों का अनुचित रूप से पक्ष लिया करते थे। मान लीजिये, एक आदमी ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, उसका अपने बन्धु बान्धवों से जायदाद या विरासत के सम्बन्ध में कोई मुकदमा चल रहा है। इस दशा में विदेशी पादरी उस चीनी ईसाई का पक्ष लेकर न्यायाधीश पर चीनी ईसाई के पक्ष में फैसला करने के लिये जोर देते थे। यदि न्यायाधीश का फैसला ईसाई के खिलाफ हो,

तो ये पादरी समझते थे, कि उसके साथ अन्याय हआ है । न्याय के क्षेत्र में ईमाई पादरियों का इस ढंग का हस्तक्षेप चीन की जनता को बहुत आपत्तिजनक प्रतीत होता था ।

- (४) चीनी लोगों में अपने पितरों की पूजा का बड़ा महत्त्व था। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति असाधारण रूप से आदर का भाव रखता था और उन्हें तृष्त रखने के लिये अने का प्रकार के विधि-विधानों का अनुष्ठान करता था। ईसाई पादरी इस पितृपूजा के भी विरुद्ध प्रचार करते थे। परिवार का जो व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था, वह पितृत्र्पणको बन्दकर देता था। परिवार के अन्य लोग इसे बहुत अनुचित समझते थे और उस ईसाई व्यक्ति का अपने परिवार के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रह जाता था।
- (५) ईसाई मिशनों में केवल पुरुष पादरी ही नहीं होते थे, यूरोप और अमेरिका से बहुत सी नवयुवितयां भी चीन में धर्म प्रचार के उद्देश्य से इस युग में आ रही थीं। ये युवितयां प्रायः अविवाहित होती थीं और पुरुष पादरियों के साथ स्वतन्त्रता से घूमती फिरती थीं। चीनी लोग यह समझ नहीं सकते थे, कि कोई अविवाहित नवयुवती इस प्रकार स्वतन्त्रता के साथ पुरुषों के साथ घूम फिर सकती हैं। उनका खयाल था, कि ईसाई पादरी नैतिक दृष्टि से बहुत पतित हैं, और उनके द्वारा चीन में जिस धर्म का प्रचार किया जा रहा है, वह यहां भी इसी ढंग की अनैतिकता का प्रवेश करा देगा।
- (६) रोमन कैथोलिक पादिरयों के अनेक विधिविधान व अनुष्ठान चीनी लोगों को बहुत अद्भुत प्रतीत होते थे। उनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की ऐसी अफबाहें चीन में फैल रही थीं, जो चीनी जनता के हृदय में विदेशी पादिरयों के प्रति तीन विरोध को उत्पन्न करती थीं। चीनी लोग कहते थे, पादरी लोग अपने अस्पतालों में चीनी रोगियों की आंखें व अन्य अंग निकाल लेते हैं। उनका प्रयोग ववाइयों के निर्माण में किया जाता है। ये अफवाहें चाहे कितनी ही निराधार क्यों न हों, पर गर्व में मस्त हुए विदेशी पादिरयों ने कभी इस बात की आवश्यकता अनुभव नहीं की, कि चीनी जनता के मिथ्या भ्रम को दूर करने का प्रयत्न करें।

मिशनों के कार्य का विस्तार-१८६० के बाद ईसाई मिशनरियों के प्रचार कार्य में बहुत बृद्धि हुई। विशेतया रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक सम्प्रदाय इस समय दीन के विविध प्रदेशों में अपने कार्य में उत्पर थे। इन सम्प्रदायों में जेसुइट, फ्रांसिलान, ऐतिम की विदेशी गिशन गोनागड़ी और लजारिस्ट के नाम विशेष रूप में उल्लेगनीय है। उद्योगनी रायों क उत्तराई में प्रोटेस्टेन्ट पादियों ने चीन में अधिक जोर से प्रचार कार्य को शुरू किया। पहला प्रोटेस्टेन्ट जो चीन में प्रचार

के लिये गया था, उसका नाम रावर्ट मोरिसन था। वह १८०७ में चीन पहुंचा था। पर उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रोटेस्टेन्ट लोगों ने चीन में अपने कार्य का अधिक विस्तार नहीं किया था। पर १८९५ तक यह स्थिति आ गई थी, कि चीन में प्रोटेस्टेन्ट पादिरयों की संख्या रोमन कैथोलिक पादिरयों की अपेक्षा अधिक बढ़ गई थी। इन पादिरयों ने चीनी भाषा में बाइवल का अनुवाद किया और व्याख्यान तथा पुस्तिकाओं द्वारा ईसा के सन्देश को चीनी लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। प्रोटेस्टेन्ट लोगों ने धर्म प्रचार के लिये अनेक शिक्षणालय और अस्पताल भी स्थापित किये। उन्नीसवीं सदी के अन्त तथ चीन में ढाई हजार से अधिक ईसाई पादरी अपने धर्म के प्रचार में व्याप्त थे और उन्हों ने आठ लाख के लगभग चीनी नागरिकों को अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था।

ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह-चीन में ईसाई धर्म का प्रचार जिस प्रकार तेजी के साथ वढ़ रहा था और विदेशी पादरी जिस ढंग से चीन के नागरिकों के साथ वरतान कर रहे थे, उसका यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि चीन का जनता उनके प्रति अपनी विरोध भावना को प्रकट करे । इस समय चीन में अनेक स्थानों पर ईसाई मिशनों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया गया। तीनृत्सिन में चीनी लोगों ने ईसाई गिरजे पर हमला करके उसे ज़ला दिया और इस बगड़े में बहुत से आदमी मारे भी गये। इस झगड़ेका कारण यह था कि ईसाई पादिरयों ने तीनृत्तिन में एक अनायालय खोल रखा था। अनायालय में ईसाई बच्चे अधिक संख्या में नहीं थे, अतः इसाई पादरियों ने यह पद्धति शुरू की थी, कि जो आदमी अनाथालय में बच्चे लायगा, उसे प्रति बालक कुछ रकम इनाम के तौर पर दी जायगी। ईसाई पादरी यह भी कहते थे, कि जब कोई बच्चा बहत बीमार हो, उसके इलाज की कोई सम्भावना न रहे, तो उसे अनाथालय में ले आया जाय, ताकि मरने से पहले उसका वपतिस्मा कर दिया जा सके। चीनी जनता इस व्यवस्था के बहत विरुद्ध थी। उसका खयाल था, कि पादरी लोग रुपया देकर बच्चों को खरीदते हैं, और मृत्यु से पहले उनकी आंख आदि को निकाल लेते हैं। तीन्त्सिन के लोगों में यह विचार इसलिये भी उत्पन्न हो गया था, कि इस साल (१८७०) वहाँ के ईसाई अनाघालय में चालीस के लगभग बच्चे किसी संकामक रोग के कारण कुछ ही दिनों में मर गये थे । तीन्तिसन में चीनी छोगों ने जिस ढंग से ईसाई पादिरयों पर हमला निया, वह किसी षड्यन्त्र का परिणाम नहीं था। चीन की जनता में जिदेशी पादिरियों के निरुद्ध जो घृणा व विद्वेष की भावना थी, वह इस आक्रमण के रूप में अकस्मात् ही फूट पड़ी थीं। इसी ढंग के अन्य भी अनेक आक्रमण इस समय चीन में अन्यव विदेशी पादिरियों के ऊपर किये गये। धर्म प्रचार करते हुए भी विदेशी पादिरियों

में जो अपने की उत्झुष्ट और चीनी लोगों को हीन समझने की भावना थी, उसी ने चीनी लोगों में इन धर्म प्रचारकों के विरुद्ध विद्वेष का भाव उत्पन्न कर दिया था।

(५) विदेशियों के साथ सम्बन्ध

मार्गरी हत्या काण्ड — ईसाई पादिरयों और विदेशी व्यापारियों के रख के कारण लोग सब विदेशियों के प्रति विद्वेष का भाव रखने लगे थे। विदेशियों के प्रति वीनी लोगों की इस समय क्या मनोवृत्ति थी, वह एक घटना द्वारा भलीभांति स्पष्ट की जा सकती है। ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि बरमा के रास्ते से दिलणी चीन के साथ व्यापार की सुविधा प्राप्त करें। १८७६ में उन्होंने इस विपय में अनुसन्धान करने के लिये एक मिशन चीन भेजा। दिक्षणी चीन के यूनान प्रदेश का अवगाहन करने के लिये उन्होंने मिशन के सदस्यों के लिये चीनी सरकार से पासपोर्ट भी प्राप्त कर लिये। जब यह मिशन यूनान पहुंचा, तो उसे सूचना मिली कि चीनी लोग उसपर आक्रमण करने के लिये उचत हैं। मिशन का एक सदस्य श्री मार्गरी अपने कुछ साथियों को साथ में लेकर इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिये आगे बढ़ा। वहां उस पर आक्रमण किया गया और उसके पांच साथियों के साथ चीनी लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। परिणाम यह हुआ, कि ब्रिटिश मिशन दक्षणी चीन में अपना कार्य नहीं कर सका।

पर पाश्चात्य लोग इस प्रकार की घटनाओं को अपने लिये बहुत उत्तम अवसर सगझते थे। इस समय पेंकिंग में स्थित बिटिश राजदूत के पद पर सर थामस वेड विद्यमान थे। जब उन्हें श्री मार्गरी की हत्या का हाल मालूम हुआ, तो उन्होंने चीनी सरकार से मांग की, कि श्री मार्गरी की हत्या का अनुसन्धान करने के लिये एक कमीशन की नियुक्त की जाय, जिसमें ब्रिटेन के भी प्रतिनिधि हों। साथ ही इस हत्याकाण्ड वा प्रतिशोध करने के लिये चीन की सरकार ब्रिटेन को हरजाना प्रदान करें और इस बात का आक्वासन दे, कि भविष्य में फिर कभी ऐसी घटना नहीं होगी। सर थामस वेड ने इस समय यह सवाल भी उठाया, कि ब्रिटेन के प्रतिनिधियों को यह भी अधिकार होना चाहिये, कि ने सम्राट्से समानता के आधार पर मिल सथा करें और चीन व ब्रिटेन की सरकार में जिन अन्य प्रश्नों पर मतभेव हैं, उन पर भी विचार करके उनका समाधान किया जाना चाहिये। चीन की सरकार ने इस बात को तो स्वीकृत कर लिया, कि श्री मार्गरी ही हणा की जांच परने के लिये कमीशन की नियुक्त की जाग और इस कमीशन में ब्रिटेन का भी प्रतिनिधि रहे। यह बात यद्यपि चीन की प्रभुत्व-घित और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का विरुद्ध थी, यह बात यद्यपि चीन की प्रभुत्व-घित और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का विरुद्ध थी,

तथापि ब्रिटेन की यह मांग स्वीकृत कर ली गई। पर अन्य वातों को मंजूर करने के लिये चीन की सरकार ने इन्कार कर दिया। परिणाम यह हुआ, कि सर थामम वेड ने पेकिंग से प्रस्थान कर दिया और ब्रिटिश सेनाएं एक बार फिर चीन के साथ युद्ध करने के लिये तैयारी करने लगीं। इस स्थित में चीन की मरकार ने यही उचित समझा, कि ब्रिटेन से सुलह कर ली जाय। १३ सितम्बर, १८७६ के दिन ब्रिटेन और चीन में नई संधि हुई, जिसके अनुसार अनेक नये बन्दरगाह ब्रिटेन के ब्यापार के लिये खोल दिये गये और ब्रिटेन की अन्य मागें भी स्वीकार वार ली गई। १८७६ की यह संधि चेफू के समझौते के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह संधि चेफू के समझौते के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह साम्ध

भागरी हत्याकाण्ड का ऍतिहासिक दृष्टि से यह महत्त्व है, कि जहां यह एक ओर चीन की जनता की विदेशियों के प्रति भावना को सूचित करता है, वहां इससे यह भी स्पष्ट होता है, कि ऐसी घटनाओं का प्रयोग पारचात्य देश किस ढंग से करसे थे। इस युग में अन्य भी इस प्रकार की अनेक घटनायें हुई, और दिवेशी

लोगों ने उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया ।

विदेशों में चीन के राजदूत-१८६० में पाश्चात्य देशों के राजदूत चीन में निवास करने लग गये थे। अब यह आवश्यकता अनुभव हुई, कि चीन की भी अपने राजदूत अन्य देशों में भेजने चाहियें। सब से पहले १८७७ में चीन की ओर से एक राजदूत की ब्रिटेन में नियुक्ति की गई। १८७७ के बाद अन्य देशों में भी चीन के राजदूत नियुक्त किये गये।

पर १८७७ से पहले भी चीन की सरकार ने पाश्चात्य देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयत्न किया था। इम्पीरियल मेरीटाइम वास्टम्स सिवस का अध्यक्ष सर राबर्ट हार्ट जब १८६६ में चीन से इङ्गलैंड गया, तब उसके साथ एक चीनी प्रतिनिधि इस उद्देश्य से भेजा गया था, कि वह दङ्गलैंण्ड य अन्य प्रोपियन राज्यों की दशा का अध्ययन कर उसके विषय में चीनी सरकार को रिपोर्ट दे। पर इस प्रतिनिधि ने यूरोप के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी, वह अच्छी नहीं थी और इस कारण चीन की सरकार को यह उत्साह नहीं हुआ, कि वह यूरोप के साथ अपने सम्बन्ध को अधिक विस्तृत व वनिष्ट करने का प्रयत्न करे।

१८६७ में चीन की सरकार ने एक अन्य मिशन अमेरिका और यूरोग में इस उद्देश्य से मेजा, कि वह इन पारचात्य देशों का अध्ययन करे। इस मिशन का अध्यक्ष श्री आन्सन बिल्ङ्गम को बनाया गया। श्री बिल्ङ्गम पेकिंग में अमेरिकान राजदूत के पद पर रह चुके थे और चीन की दशा से भलीभांति परिचित थे। इस मिशन ने अमेरिका, इङ्गलैण्ड, फांस, इस आदि की यात्रा की और वहां के राजनी- तिजों से परिचय प्राप्त किया । थी बिलिङ्गम चीन के लोगों की मनोवृत्ति को भली मानि मानते थे। उन्होंने पाक्चात्य लोगों को बनाया, कि चीन के लोग पाक्चात्य संसार के जान विज्ञान को सीखने के लिये तैयार है, वे विदेशों के साथ व्यापार को विक्रिमन करने के लिये भी उचन है, वे ईसाई मिशनिर्यों का भी स्वागत करते हैं, और इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं, कि पाक्चात्य सम्यता को अपनाकर अपने देश की उन्नति करें। थी बिलिङ्गम ने चीन की मनोवृत्ति को सही क्य में पाक्चात्य देशों के सम्मुख पेश किया। उनके भाषणों के कारण पाक्चात्य लोगों को यह अवसर मिला, कि वे चीन के सम्बन्ध में सही बातें मालूम कर सकें। चीनी लोगों को अपने से हीन समझने की जो प्रवृत्ति पाक्चात्य लोगों में विद्यमान थी, उमे दूर होने में इस चीनी मिशन से बहुत सहायता मिली।

चीनी लोगों का अमेरिका में प्रवेश-श्री विलिङ्गम के प्रयत्न मे १८६८ में चीन और अमेरिका में एक नई सिन्व हुई, जिसके अनुसार (१) अमेरिका ने चीन की स्वतन्त्रता को स्वीकृत किया, (२) चीनी मजदूर अमेरिका में आकर मजदूरी कर सके, यह स्वीकृत किया गया, (३) धर्म प्रचार के सम्बन्ध में दोनों देशों को पूरी पूरी स्वतन्त्रता दी गई, और (४) दोनों देशों के लोगों को दूसरे देश में यात्रा व निवास का अधिकार प्रदान किया गया।

इस सन्धि में सबसे महत्त्व की बात यह थी, कि इसमें चीन के मजदूरों की अमेरिका में आकर मजदरी करने का अवसर दिया गया था। १८६८ से पहले भी चीन के लोग नौकरी व मजदूरी की तलाश में अमेरिका जाना शुरू कर चुके थे। चीन की जनसंख्या वहत अधिक थी और सर्वसाधारण लोगोंको वहां आजीविका प्राप्त करने की सम्चित सुविधा नहीं थी। इसके विपरीत परिचमी अमेरिका में मजदूरों की बहुत कमी थी और वहां के खेतों, खानों व कारखानों में मजदूरों की सदा आवश्यकता रहती थी। १८६७ तक ५०,००० के लगंभग चीनी मजदूर अमेरिका पहुंच चुके थे। शुरू में अमेरिकन लोग चीनी मजदूरों का स्वागत करते थे। चीनी मजदूरों की मजदूरी की दर बहुत सस्ती थी और वे खूब परिश्रम करते थे । साथ ही चीनी लोग भी अमेरिका जाकर सुगमता से मजदूरी प्राप्त कर सकते थे । १८६८ के बाद चीनी लोग बड़ी संख्या में अमेरिका जाने लगे । १८८२ में अमेरिका में विद्यमान चीनी मजदूरों की संख्या १, ३२, ००० हो गई । अमेरिकन लोग अपने देश में इस प्रकार बढ़ती हुई चीनी आबादी से बहुत चिन्तित थे। विशेषतया अमेरिकन मजदूर चीनियों के अमेरिका प्रवेश के बहुत विरुद्ध थे। कैलिफोनिया व अनेक राज्यों में चीनी लोगों के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए। अमेरिकन लोगों ने वैयक्तिक व सामृहिक रूप से चीनियों पर हमले शुरू कर दिये।

परिणाम यह हुआ, कि अमेरिका की कांग्रेस (पार्लियामेन्ट) में चीनी लोगों के अमेरिका प्रवेश के विरुद्ध कानून पास किया गया (१८७८)। पर यह कानून १८६८ की चीन-अमेरिकन सिंध के विरुद्ध था। अतः राष्ट्रपति हेम्स ने इसे वीटो कर दिया। साथ ही उसने एक अमेरिकन कमीशन इस उद्देश से चीन भेजा, कि १८६८ की सिंध को दोहराया जाय और उसमें इस प्रकार के परिवर्तन किये जावें, जिनसे अमेरिकन सरकार चीनियों के अमेरिकन प्रवेश को नियन्त्रित कर सकें। चीनी सरकार अमेरिकन किशे मांग को अस्वीगृत नहीं कर सकी। १८८० में चीन और अमेरिका की संधि में संशोधन किया गया और १८८२ में अमेरिकन कांग्रेस ने एक कानून हारा यह व्यवस्था की, कि दस साल तक चीनी लोग अमेरिका में न आ सकें और जो चीनी लोग अमेरिका में विद्यमान हैं, उन्हें अमेरिकन नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हो सकें। १८९२ और १९०२ में अमेरिकन कांग्रेस ने फिर इसी प्रकार के कानून स्वीगृत किथे और १९०४ के एक कानून के अनुसार चीनी लोगों का अमेरिका में आकर वसना सदा के लिये बन्द कर दिया गया। इन कानूनों से चीन में बहुत असन्तोप था, पर अमेरिका की शक्त के सम्मुख चीन की सरकार सर्वथा असहाय थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के समान मध्य और दक्षिणी अमेरिका के पेरू, क्यूबा आदि अन्य प्रदेशों में भी चीनी लोग इस यग में बड़ी संख्या में जाकर वसने छगे थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तराई में अमेरिकन महाद्वीप में भी दास प्रथा का अन्त हो गया था। उसके अनेक प्रदेशों में मजदरों की कमी अनुभव की जा रही थी और इस कारण चीन में अनेक ऐसी एजिन्सयां कायम हुई थीं, जो गरीब चीनियों की बहुकाकर अमेरिका में कूली का काम करने के लिये भरती करने में तल्पर थीं। जिस प्रकार दक्षिणी अफ़ीका, फिजी आदि के लिये कुलियों की भरती फरने के निमित्त भारत में प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा का प्रारम्भ हुआ था, वैसे ही दक्षिणी अमेरिका के लिये कुलियों को प्राप्त करने के निमित्त चीन में इस प्रथा की शुरू किया गया। हजारों की संख्या में गरीव चीनियों को बहका फसला कर दक्षिणी अमेरिका ले जाया जाने लगा । छोटे-छोटे जहाजों में पशुओं की तरह चीनी कृलियों को भरकर अमेरिका ले जाया जाता था और वहां उनसे ग्लामों के समान व्यवहार किया जाता था । चीन की सरकार ने इस प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा के विरुद्ध कानृत जारी किया, पर मकाओ (पूर्तगाल के आधीन) की केन्द्र बनाकर पाश्वास्थ लोगों ने इस प्रथा को जारी रखा। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक संसार का लोकमत इस प्रथा के इतना विरुद्ध हो गया, कि धीरे-धीरे चीन से प्रतिजायढ कुलियों को भरती कर सकता सम्भव नहीं रहा । साथ ही अभेरिका

में कार्य करनेवाले चीनी कुलियों की दशा में सुधार करने का भी प्रयत्न किया। गया।

(६) मञ्चू सम्राटों का निर्बल शासन

सम्राट ताओ कुआंग—सन १७९६ में चीन के शिक्तशाली मञ्जू सम्राट् चिएन-लुंग की मृत्यु हुई थी। उसके उत्तराधिकारी निबंल थे, और उनके समय में मञ्जू शासन में ह्रास की प्रिक्रया का प्रारम्भ हो गया था। यहां इम बात की आवश्यकता नहीं हैं, कि इन सम्राटों के वृत्तांत का उत्लेख किया जाय। १८२० में चीन की राजगद्दी पर सम्राट् ताओ कुआंग आरूढ़ हुआ। उसके शासन काल में चीन के दुविन शुरू हो गये। यूरोप के व्यापारी उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जिस ढंग से प्रशान्त महासागर के तट पर अपने प्रभुत्व व प्रभाव की स्थापना में तत्पर थे, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका हैं। १८३२ में चीन में भारी दुर्भिक्ष पड़ा। चीनी लोग समझते थे, कि दुर्भिक्ष आदि के रूप में देश को जिस दैनी प्रकोप का सामना करना पड़ता है, उसकी उत्तरदायिता राजा पर होती हैं। दुर्भिक्ष आदि वैवी विपत्तियां इस बात का प्रमाण हैं, कि ईश्वर राजा से संतुष्ट नही हैं। परिणाम यह हुआ, कि इस समय चीन में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को शान्त करने के लिये चीनी सरकार को अनेक प्रकार के कठोर उपायों का आश्रय लेना पड़ा।

सम्प्राट् हि्सएन फंग-१८५० में ताओ कुआंग के वाद उसका लड़का हि्सएन फंग चीन का सम्राट् बना। इसी के शासन काल में इङ्गलैण्ड और फांस की सेनाओं ने पेकिंग पर आक्रमण किया था और सम्राट् को अपनी राजधानी को छोड़ देने के लिये विवश किया था। १८६० की संधि, जिसके द्वारा पाश्चात्य देशों को चीन में अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व को विस्तृत करने का अपरिमित अवसर प्राप्त हो गया था, इसी सम्राट् के समय में हुई थी। १८६० में राजधानी से निर्वासित दशा में ही सम्राट् हि्सएन फंग की मृत्यु हो गई थी।

साम्राज्ञी त्सू ह् सी- ित् सएग फंग की मृत्यू के समय उसका एक पात्र पत्र अभी बालक ही था। अनः उसकी रानी त्सू ह् नी ने बासन सूत्र की अपने हाय में ित्या। उसका पुत्र तुंग चिह्न देर तक जीवित नहीं रहा। १८०५ में उसकी मृत्यू हो गई। इस दशा में एक अन्य बालक को गोद लेकर साम्राज्ञी त्सू ह् सी ने शासन कार्य का गंनालन जारी रखा। चीन के इस नये वालक सम्राट् का नाम कुआंग ह सू था। १८८७ में वह नयरक हुआ। एन प्रकार १८६० से १८८७ तक चीन की राजगही

पर नावालिंग सम्राट् विराजमान रहे और उनके नामपर साम्राज्ञी त्सू हु सी शासन का संचालन करती रही । चीन के आधुनिक इतिहास में यह बात ध्यान देने सीस्पृत् हैं, क्योंकि इस काल में चीन का शासन सूत्र किसी योग्य व शिक्तशाली व्यक्ति के हाथ में नहीं था । साम्राज्ञी न्सू हु मी निःसंदेह एक सुसंस्कृत व दक्ष महिला थी । पर मञ्चू शासन के सूत्र को संभाल मकना उनकी शक्ति के बाहर था । उसके समय में अन्तःपुर में और राज-प्रासाद के विविध कर्मचारियों की शक्ति बढ़ने लगी और वे देश के शासन में मनमानी करने लगे । राजकीय पदों पर नियुक्ति करते हुए सिफारिशों और रिश्वतों वा महत्त्व बढ़ने लगा और साम्राज्य के शासन में शिथिलता आने लगी । यदि इस समय चीन की सरकार का संचालन किसी जबर्दस्त व्यक्ति के हाथ में होता, तो सम्भवतः चीन की इतनी दुर्दशा न हो पती ।

इस समय चीन को जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा था, उनमें से कितिप्य का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पाश्चात्य व्यापारी समुद्र तट के प्रदेशों में अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे और विदेशी पादरी चीन में दूर दूर तक धर्म प्रचार के नाम पर स्वेच्छाचार में सलग्न थे। पर चीन की सरकार को केवल विदेशियों से ही अपने देश की रक्षा नहीं करनी थी। इस समय उसे अनेक आन्तरिक समस्याओं का भी मुकावला करना पड़ा। चीन में अनेक स्थानों पर विद्रोष्ट हुए और इन विद्रोहों ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया, कि कुछ समय ने लिये चीनी साम्राज्य जड़ में हिल गया। इस प्रकार के कुछ विद्रोहों का यहां उल्लेख करना उपयोगी है।

ताइ पिग विद्रोह-इस विद्रोह का नेता हुंग हि सउ-शुआन था। वह एक ग्राम में अध्यापक का कार्य करता था। चीन की परीक्षा पद्धित के अनुसार विद्या का अध्ययन कर उसने अनेक उच्च परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थीं, और इस बात के लिये प्रयत्न किया था, कि किसी उच्च सरकारी पद को प्राप्त करें। पर इसमें उसे सफलता नहीं हुई और उसे अध्यापक का कार्य स्वीकारकरने के लिये विवश होना पड़ा। इन दिनों चीन के देहातों में ईसाई पादरी धर्मप्रचार का कार्य बड़ी तत्परता के साथ कर रहे थे। हुंग हिं सउ-शुआन कितपय पादि यों के सम्पर्क में आया और उसने बाइबल के उपदेशों का अनुशीलन किया। पिछले दिनों हुंग सुदीर्घ सग्प कर वीमार रहा था और रोगशय्या पर पड़े हुए वह अनेक प्रकार के स्वप्न देखाई करता था। उसने अनुभव किया, कि बीमारी के दिनों के स्वप्न ईसाई धर्म की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते हैं। प्रोटेस्टेन्ट पादि यों के सम्पर्क में आकर हुंग ने निश्चय किया, कि उसे अपने विचारों का प्रचार करना चाहिये। क्वांगसी के

प्रदेश में बहुत में चीनी लोग हुंग के अनुयायी हो गये और १८५० तक उसके अनया-.Suuों की संख्या हजारों में पहुंच गर्ड । हुंग-हि ्सउ-श्आन के अनुयायी बाइबल 🖏 आदर करते थे, अनेक किरिचयन सिद्धान्तों को मानते थे और अनेक ईसाई विधि विधानों का अनुसरण करते थे। यद्यपि उन्होंने ईसाई धर्मकी दीक्षा नहीं छी थी, पर हंग द्वारा एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ था, जिसके सिद्धान्त व विधि-विधान ईसाई धर्म से बहन मिलने जलते थे। चीनी संस्कार ने हंग के बढते हुए प्रभाव को आपत्तिजनक समझा, और इस नयं सम्प्रदाय के प्रचार को राजाजा हारा निविद्ध कर दिया। हंग के अनेक किष्य गिरफ्तार भी किये गये। इस दशा में हंग ने निश्चय किया, कि मञ्च शासन का अन्त कर चीन में एक नये राजवंश का प्रारम्भ किया जाय। उसने चीन की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हंग ने अपने को सम्राट् घोषित कर दिया और अपने राजवंश का नाम ताइ-पिंग रखा। हंग द्वारा जो नया धार्मिक सम्प्रदाय स्थापित हुआ था, उसने अब राजनीतिक रूप धारण कर लिया । बाकायदा रोनाओं का संगठन किया गया और १८५४ में हंग की सेना ने नानिकंग को विजय कर लिया। नानिकंग को राजधानी बनाकर हुंगकी सेनाओं ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया और कुछ ही समय में वे तीन्त्सिन द्विक पहुंच गई । इस समय चीनी सरकार के सम्मुख यह विकट समस्या उपस्थित हुई, कि वह इस ताइ-पिंग विद्रोह का मुकाबला करे। ईसाई पादिरयों का विचार था, कि पाश्चात्य देशों को ताइ-पिंग की सहायता करनी चाहिये और उसे ही चीन का असली राजवंश स्वीकृत कर लेना चाहिये । ब्रिटेन के चीन स्थित प्रतिनिधि इस विचार से सहमत थे। पर अमेरिका की नीति इसके अनुकुल नहीं थी। अमेरिका की प्रेरणा पर पारचात्य देशों ने निरुचय किया, कि ताइ-पिंग के मुकाबले में मञ्चू शासन का पक्षपोषण करना चाहिये। फेडरिक वार्ड नामक अमेरिकन ने नेतृत्व में एक सेना का संगठन इस उद्देश्य से किया गया, कि ताइ-पिंग विद्रोह को शान्त करने के कार्य में चीनी सरकार की सहायता की जाय। विदेशी लोगों की सहायता से मञ्च शासक ताइ-पिग विद्रोह को शान्त करने में समर्थ हुए और १८६४ के अन्त ार है जान निवद किने गये सब प्रदेश फिर से चीनी सरकार की अधीनता में ा १८ । भिंदो लोग ने जो इस समय ताइ-पिंग के विरुद्ध मञ्चु शासन की सहायता भने थी, उसका प्रधान कारण यह था, कि मध्य जारान बहत विक्रत व निर्वल दमा में चा। उसको कावम रखवार। बिदेशी कोशों को वह मुगस प्रतीत होता था, कि ये नीन में अनुने प्रभाव व प्रभता को अधिक सुगमता है स्थानिक कर सकेंगे।

अन्य विद्रोह-ताइ-पिंग विद्रोह के अतिरिक्त इस समय चीन में दो अन्य विद्रोह

हुए । ये दोनों विद्रोह चीन के मुसलमानों द्वारा किये गये थे । उत्तर-पश्चिमी चीन और यूनान के प्रदेशों में बहुत से चीनी लोग इस्लाम को स्वीकृत कर चुके थे इनका आचार विचार चीनी जनता से बहुत मिन्न था। इसी कारण चीनी राजकर्म- चारी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मुसलमानों में इससे बहुत असंतोष था। ताइपिंग विद्रोह में उत्साहित होकर इन प्रदेशों के मुसलमानों ने भी विद्रोहकर दिया। पर उनको यश में लाने में चीनी सरकार को विशेष कठिनता नहीं हुई।

विद्रोहों का परिणाम—यद्यपि चीनी सरकार इस समय के विविध विद्रोहों को शान्त करने में सफल हुई, पर इनके अनेक दुष्परिणाम हुए। चीन की सेना पर पाश्चात्य लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और चीनी सरकार आर्थिक दृष्टि से बहुत हीन दशा को प्राप्त हो गई। इस विद्रोहों का सामना करने में सरकार को बहुत हमन दशा को प्राप्त हो गई। इस विद्रोहों का सामना करने में सरकार को बहुत हमना लगाये जावें। नये टैक्सों के कारण जनता में बहुत असन्तोप हुआ। १८७६ में चीन को अनेक प्राकृतिक विपत्तियों का भी सामना करना पड़ा। विद्रोहों के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे खेती को बहुत नुक्तसान पहुंचा था। इस पर १८७६ में जब टिड्डी दल ने भी चीन के बड़े भाग पर हमला किया, तब जो थोड़ी बहुत फसल बोई जा सकी थी, वह भी नष्ट हो गई। १८७६—७८० में चीन की जनता को घोर दुक्ति का सामना करना पड़ा। इस दुक्ति में लाखों आदमी मौत के शिकार हुए। फसल के विनाश और करों की अधिकता से चीन के लोग बहुत ही परेशानी अनुभव करने लगे। इस वशा में यह स्वाभाविक था, कि मञ्जू शासन अत्यन्त निर्वल हो जाय और जनता में उसके प्रति असन्तोष की भावना बढ़ने लगे।

साम्राज्य का ह्रास-विदेशी राज्य न केवल चीन के शासन में हस्तक्षेप कर उसके शासकों से ऐसे विशेष अधिकारों को प्राप्त करने में लगे थे, जो चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और प्रभुत्वशिक्तसम्पन्नता के विरोधी थे, अपितु उनका यह भी प्रयत्न था, कि चीनी साम्राज्य के विविध प्रदेशों को अपतने अधिपत्य में ले आवें। किस प्रकार ब्रिटेन ने हांग कांग को और इस ने आमूर नदी के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। १८८५ में ब्रिटेन ने बरमा पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। बरमा चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था और उसे कर प्रवान करता था। जब बरमा ब्रिटेन के अधीन हो गया, तो उसकी ब्रिटिश शासकों ने चीन को कर देंना वन्द कर दिया। बरमा के समान अनीम और तोन्किंग के राज्य भी चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत माने जाते थे। १८८४-८५ में फारा से इन्हें अपने अचीन कर लिया और इन प्रदेशों से चीन के प्रभुत्य का अन्तर

हो गया । बरमा, अनाम और तोन्किंग किस प्रकार चीन के साम्राज्य से पृथक हो , कर पारचात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए, इस पर हम यथास्थान विशद रैक्ष्प से प्रकाश डालेंगे ।

(७) चीन में नवयुग का प्रारम्भ

उन्नीसवीं रादी के मध्य भाग तक चीन की राजशिक्त बहुत क्षीण हो गई थी। ईसाई मिशनरी और विदेशी व्यापारी वहां धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे। क्रिटेन, अमेरिका, फांस आदि से जो सिन्धयां चीन ने की थीं, उनसे उसकी प्रभुत्त्वशिक्त व स्वतन्त्रता बहुत कुछ मर्यादित हो गई थी। वह विदेशी राज्यों की सहमित के विना अपने आयात और निर्यात माल पर टेक्स की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता था, और एक्स्ट्रा-टेरिटोरिएलिटी की पढ़ित के कारण चीन में निवास करते हुए विदेशी लोग चीनी कानून व चीन के शासन से स्वतन्त्र थे। आन्तरिक विद्रोहों और प्राकृतिक विपत्तियों ने चीन की दशा को और भी अधिक खराब कर दिया था। इस अवस्था में यह स्वाभाविक था, कि विचारशील चीनी लोग अपने देश की दुर्वशा को अनुभव करें और उसके सुधार के लिये प्रयत्नशील हों। परिणाम यह हुआ, कि घीरे घीरे चीन में नवयुग के चिह्न प्रकट होने लगे और विविध देशभक्तों ने अपने देश की उन्नित के लिये प्रयत्न का प्रारम्भ किया। जो कारण चीन में नवयुग का सूत्रपात कर रहे थे, उनका यहां संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना आवश्यक है—

(१) ईसाई पादिरयों ने चीन में जो अनेक शिक्षणालय स्थापित किये थें, उनमें प्रश्नानतया ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इन शिक्षणालयों में सबसे प्रधान पेकिंग का स्कूल था। १८६५ में पेकिंग के इस किश्चियन स्कूल की कालिज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम तुंगवन कालिज रखा गया। तुंगवन कालिज में विज्ञान की शिक्षा के लिये भी एक विभाग खोला गया और उसके द्वारा चीनी विद्यार्थियों को यह अवसर मिला, कि वे पाश्चात्य देशों के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकें। तुंगवन कालिज के बाद चीन के अन्य भी अनेक ईसाई शिक्षणालयों में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन प्रारम्भ किया गया।

(२) प्रोटेस्टेन्ट मिशन द्वारा स्थापित एक रकूल में युंग विश्व नागल एक नीती विद्यार्थी ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस स्कूट का जन्मतन अव्यापक जब अपने देश अमेरिका को बापस गया, तो गुंग विभ को भी अपने साथ प्रमेरिका के भया। युँग विग को ग्रेक युगिवस्टिटो में उच्न शिक्षा के छिये प्रतिष्ट कराय। गया और वहां

उसने आध्निक शिक्षा प्राप्त की । युँग विग पहला चीनी विद्यार्थी था, जो अमेरिका की एक उच्च शिक्षा संस्था का स्नातक बना था। अमेरिका में अध्ययन करते हुए यँग विग का यह विज्वास दृढ़ हो गया था, कि चीन की उन्नति तभी सम्भव है, जब कि वह पारचात्य देशों के ज्ञान विज्ञान को सीखे और समार की नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को परिवर्तित करें । अमेरिका में शिक्षा समाप्त करके गुग विग चीन वापसे आ गया, और वहां उसने यह उद्योग किया कि चीनी विद्यार्थियों की एक मण्डली को उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका भंजा जाय । यग विंग के उद्योग से १२० चीनी विद्यार्थी १८७० में अमेरिका भेजे गये । चीनी लोग युंग विग की इस गोजना को अच्छा नहीं ममझने थे। उनका खयाल था, कि विदेश में शिक्षा प्राप्त करके चीन के नव्युवक अपने धर्म और संस्कृति से विम्ख हो जावेंगे। जनता के विरंध का यह परिणाम हुआ, कि सब चीनी विद्यार्थी अमेरिका में अपनी विक्षा को पूर्ण नहीं कर सके, उन्हें अपनी शिक्षा को अध्रा छोड़कर चीन वापस लौटना पड़ा । पर उन्होंने अमेरिका में रहते हुए अपनी आंखों से जो कुछ देखा था और जो शिक्षा प्राप्त की थी, अपने देश लीटकर उन्होंने उसका उपयोग किया और अपने देश-वासियों को इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे पारचात्य देशों से मशीनें खरीदकर व्यावसायिक उन्नति में तत्पर हों। १८७० के बाद अन्य चीनी विद्यार्थी भी अमेरिका गये और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किये हुए ये युवक अपने देश की उन्नति में बहत् अधिक सहायक सिद्ध हुए।

- (३) पारचात्य देशों के साथ सम्पर्क का यह परिणाम हुआ, कि चीन की जनता और सरकार ने अपनी सेना के पृनः संगठन और व्यावसाधिक उन्नति पर ध्यान देना शुरू किया। ताई-पिंग विद्रोह को शान्त करने के लिये अगेरिकन लोगों के नेतृत्व में एक चीनी सेना को संगठित किया गया था। यह सेना अन्य चीनी सेनाओं की अपेक्षा बहुत अधिक दक्ष थी। चीन के नेताओं ने अनुभव किया, कि सैन्य संगठन और युद्ध के संचालन में वे पारचात्य देशों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। उन्होंने प्रयत्न किया, कि पारचात्य ढंग पर चीन की सेना को संगठित किया जाय और उसे नथे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया जाय।
- (४) व्यावसायिक क्षेत्र में चीन में किस प्रकार नवयुग का प्रारम्भ हुआ, इस सम्बन्ध में कतिपय बातों का उल्लेख करना उपयोगी हैं। १८७६ में चीन में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। यह लाइन शंघाई से वृसंग तक कि बनाई गई थी। पर चीन की जनता और पण्डित मण्डली रेलवे के उनने जिन्हें थी, कि १८७७ में रेलवे लाइन को उलाइ दिया गया और लोहे की पर्टार्यों को फार्म्सा द्वीप में ले जाकर डाल दिया गया, ताकि चीन में उन्हें फिर न लाया जा

संके । पर यह सम्भव नहीं था, कि चीन समय की प्रगति से पृथक रह सके । १८८१ ्में चीन में फिर रेलवेका निर्माण शुरू हुआ और उसके बाद रेलवे लाइनोंका निर्माण निरन्तर जारी रहा । इस समय चीन के अनेक उच्च राजपदाधिकारी इस प्रकार के थें, जो समय के अनुसार परिवर्तित होने के पक्ष में थे। चिहली प्रान्त का गवर्नर ली हंगचांग एक इसी प्रकारका अधिकारी था। उसीकी कोशिश से इस समयचीन में रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा था। १८८५ में चीन में पहले पहल टेलीग्राफ का प्रारम्भ किया गया । शंघाई से तीन्त्सिन तक तार लगाई गई और धीरे धीरे अन्यत्र भी तार का विस्तार किया गया । इसी समय के लगभग "चाइना मर्चेन्टस स्टीम नेविगेशन कम्पनी" का संगठन हुआ, जिसका उद्देश्य चीन की नदियों में और समृद्र तट पर जहाजों द्वारा यातायात का प्रारम्भ करना था। इस कम्पनी का संगठन कतिपय ऐसे चीनी नागरिकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण की थी । १८७८ में चीन में पहली कोयले की खान का प्रारम्भ किया गया और १८९० में हनयांग आयर्न वर्म्स की स्थापना हुई। आगे चलकर लोहे का यह कारखाना बहुत विकसित हुआ । चीन में व्यावसायिक उन्नति का यह प्रारम्भ मात्र था । सर्व साधारण जनता और पण्डित मण्डली इसके खिलाफ थी । - इंसी कारण ली हंग चांग जैसे शिक्षित व्यक्ति इस समय अपनी इच्छा के अनुसार चीन की उन्नति कर सकने में असमर्थ थे। पर इसमें सन्देह नहीं कि इस समय चीन में नवयग का सूत्रपात हो गया था।

(८) चीन के सम्बन्ध में विदेशियों की नीति

(१) चीन का साध्यक्त अत्यना निवाल था। उसमें पैतीस करोड़ से अधिक भनुष्यों का निवास था। चीनी लोगों में अपनी संस्कृति के लिये त्रेम था और वे अपने वेस की रक्षा के लिये जुर्जानी करने की तैयार थे। भारत में जब अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया. तो दिल्ली के मुगल वादशाहों की शिवत कीण हो गई थी और यहां अनेक छोटे बड़े राजा अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगे थे। ब्रिटिश लोग इन राजाओं के पारस्परिक झगड़ों से लाभ उठा सकते थे। इसके विपरीत उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में चीन एक शासन के अधीन था। उसके विविध प्रदेशों में विभिन्न राजा अपनी अपनी राजगद्दी के लिये संघर्ष करने में तत्पर नहीं थे। पाश्चात्य देशों को भय था, कि विशाल चीन की सामूहिक शक्ति को परास्त कर सकता उनके लिये सुगम नहीं होगा।

- (२) विविध पारचात्य देशों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि चीन की विजय के लिये वे परस्पर एकमत हो सकें। यदि चीन को जीतकर उसे विभवत करने का प्रयत्न किया जाता, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि के हित आपस में टकरा सकते थे। इस दशा में पारचात्य देशों के लिये उचित नीति यही थी, कि चीन पर अपने राजनीतिक प्रमुत्त्व को स्थापित करने का यत्न न करें। यदि कोई एक पारचात्य देश चीन को जीतने का प्रयत्न करता, तो अन्य देश उसके उत्कर्ष को सहन न कर सकते।
- (३) व्यापार के क्षेत्र में अपना प्रभुत्त्व स्थापित करके पाइचात्य देशों को प्राय: वही लामे प्राप्त हो रहा था, जो वे राजनीतिक प्रभुत्त्व की स्थापना से प्राप्त कर सकते थे।

पर पाइचात्य देशों की चीन के सम्बन्ध में जिस नीति का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वह देर तक स्थिर नहीं रही। उनीसवीं सदीका अन्त होने से पूर्व ही उन्होंने यह भलीभांति समझ लिया, कि चीन की निर्वलता से लाग उठाकर उसे पूर्णतया अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का शिकार बनाया जा सकता है। अपनी नीति में परिवर्तन कर उन्होंने किस प्रकार चीन को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया, इस पर हम अगले एक अध्याय में विचार करेंगे। पर यहां यह निर्देश कर देना आवश्यक है, कि चीन पर अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व की स्थापना का उद्योग सबसे पहले जापान ने किया था। उनीसवीं सदी के मध्य तक जापान भी चीन व अन्य एशियाई देशों के समान उन्नति की दौड़ में बहुत पिछड़ा हुआ था। पर पाइचात्य देशों के सम्पर्क में आकर जब जापान ने एक बार इस बात को समझ लिया, कि अन्य देश उसकी अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत हो गये हैं, तो उसने बड़ी शी द्वाता से पाइचात्य ज्ञान विज्ञान को अपनाना शुरू किया। इसी का यह परिणाम हुआ, कि वह भी पाइचात्य देशों के समान उन्नत और शक्तिशाली हो गया। जापान की इस आक्वर्य जनक उन्नति पर हम अगले अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

चौथा अध्याय

जापान के उत्कर्ष का प्रारम्भ

(१) पुरातन इतिहास

संसार के अन्य देशों के समान जापान का प्राचीन इतिहास भी प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं होता । जापानी लोग यह मानते हैं, कि प्रारम्भ में इजानगी नामक एक देवता और इजानभी नामक एक देवी के संयोग से जापान का प्रादुर्भाव हुआ। संसार में चेतन व अचेतन जितनी भी सत्ताएँ हैं, सबका प्रादुर्भाव देवताओं द्वारा हुआ हैं। जापानी दन्तकथाओं के अनुसार जब इजानगी देवता अपनी बाईँ आंख धो रहा था, तो अमतेरसू-ओमीकमी (सूर्य देवता) की उत्पत्ति हुई। सूर्य देवता के पौत्र का नाम निनिगी-नो-मिकोतो था। उसे पृथ्वी का शासन करने के लिये नियुक्त थिया गया। पृथ्वी का राजा बनकर वह पहले पहल क्यूशू द्वीप पर प्रकट हुआ। उस समय उसने रत्न, खड़ा और दर्पण इन तीन राजचिल्लों को धारण किया हुआ था। निनिगो नो-मिकोतो का प्रपौत्र जिम्मू तेनो हुआ, जो कि जापान का प्रथम सम्राट् माना जाता है।

जापानी इतिहास के सम्बन्ध में इसी प्रकार की अन्य भी बहुत सी कथाएँ विद्यमान हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें कहां तक सचाई हैं, यह कह सकना कठिन हैं। शिव, गणेश, इन्द्र आदि भारतीय देवताओं के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं। भारतीय पुराविदों के समान अनेक जापानी विद्यान भी इन कथाओं की इस हंग से व्यास्था करते हैं, जो यूक्तिसंगत व गत्य प्रतीत होती हैं। जापान का सम्राह् येथी हैं, यह विज्ञास अब तक जापानी छोगों में विद्यमान हैं। जिगिगी-नो-भिकाता के समान जापान के सब मधाट् राम, सब्द और दर्पण को राजित हो किए में बारण करते हैं। और अवतक भी जनको भारण करते हैं। युक्त में जापानी छोग छिखना नहीं जानते थे। छिन्दों की कला सम्भवतः जन्होंने चीन से सीमा अब भी जापान थीं छिप का जापान में प्रवेश हुआ। इसी कारण उससे पहले के समय की कोई छिदित पुस्तक व अन्य छंश जापान में उपलब्ध नहीं

होते और इसीिलये ईसवी सन् से पूर्व का जापानी इतिहास केवल दन्तकथाओं व परम्परागन गाथाओं पर आश्रित हैं।

ईसवी सन् के शुरू होने से पूर्व जापान में सभ्यता के दो प्रमुख केन्द्र थे, इज्मो और यमतो। क्यश द्वीप में सूर्य देवताका पौत्र निनिगी-नो-मिकोतो प्रकट हुआ था। उसके प्रपौत्र जिम्म तेनो ने ही यमतो का विजय कर वहां सभ्यता का विकास किया था । इसमें सन्देह नहीं, कि यमतो के निवासी लोहे का उपयोग जानते थे, और प्रस्तर युग से आगे बढ़कर सभ्यता के क्षेत्र में उन्नति करने के लिये प्रयत्नशील थे। जिम्मू नेनो के समय से जापान का बड़ा भाग एक शासन की अधीनता में आ गया था। पर यमतो के राजा व सम्राट्की शक्ति के विकास ने अन्य राज्यों की सत्ता को नष्ट नहीं कर दिया था। इस युग में जापान में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। प्राचीन ग्रीस व भारत के समान प्राचीन जापान भी बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज्य के निवासी यह मानते थे, कि वे किसी एक पूर्वज की सन्तान हैं, वे सब एक देवी देवताओं की पूजा करते थे और एक राजा की अधीनता में रहते थे। यमतो का राज्य इन सबमें प्रधान व शक्तिशाली था और उसके राजा को अन्य सब राजा अपना अधिपति स्वीकार करते थे। इसीलिये उसे सम्राट् की पदवी प्राप्त थी। यमतो के सम्राट् जिम्मू तेनी ने जिस राजवंश का प्रारम्भ किया, वही अब तक जापान में विद्यमान है। सम्भवतः इतिहास में अन्य किसी राजवंश ने इतने सुदीर्घ समय तक राजशक्ति का उपभोग नहीं किया है। भीरे धीरे यमतो के राजवंश की शक्ति बढ़ती गई, अन्य राज्यों के राजा उसकी अधीनता में आते गये और जिम्मू तेनो के वंशजों के सम्मुख उनकी स्थिति स्वतन्त्र राजाओं की अपेक्षा सामन्तों के सद्ध होती गई। राजशक्ति के एक केन्द्र में केन्द्रित होने के साथ-साथ पुराने छोटे-छोटे राज्यों के राजा सम्राट्के सामन्त व जागीरदार की स्थिति प्राप्त करते गये और इसप्रकार जापान में एक कुलीन जागीरदार श्रीण का विकास हुआ, जो कुल कमानुगत रूप से अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा को प्राप्त करती थी । ईसवी सन् के प्रारम्भिक काल तक यह अवस्था आ गई थी, कि प्रायः सम्पूर्ण जापान जिम्मू तेनो के वंशज सम्राटों के अधीन या और प्राने छोटे छोटे राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता का ह्वास हो गया था। वे पूर्णतया यमतो के सम्राट् के वशवतीं हो गये थे।

प्राचीन जापान की जनता को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, कुलीन जागीरदार श्रेणि, व्यवसाय व व्यापार में लगे हुए लोगों की श्रेणि और दास वर्ग । कुलीन जागीरदारों का विकास किस प्रकार हुआ, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। भूमि पर इन जागीरदारों का स्वामित्व था और

उसको जोतने बोने वाले किसानों की स्थित दासों के समान थी। व्यवसायी और व्यापारी आर्थिक श्रेणियों (गिल्ड) में संगठित थे। कीन मनुष्य क्या काम करे, यह उसके जन्म के अनुसार निश्चित होता था। जुलाहे की सन्तान जुलाहा होती थी और वैद्य का लड़का वैद्य होता था। जापीन में यह सम्भव नहीं था, कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को कर सके, जो उसके पूर्वज न करते हों। जिस प्रकार भारत में अनेक पेशे जातियों का रूप धारण किये हुए हैं, वैसी ही दशा जापान में भी थी। शिल्पियों और व्यापारियों की स्थित कुलीन जागीरदारों के मुकाबले में हीन समझी जाती थी। बहु-संख्यक जनता दास थी, और वह जागीरदारों की जमीन पर खेती का कार्य किया करती थी।

जापान के प्राचीन धर्म में देवी देवताओं का बड़ा महत्त्व था। जापानी लोग समझते थे, कि प्रकृति की विविध शक्तियां व विविध पदार्थ जीवित जागृत सत्तायें हैं। वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु आदि सबमें वे अधिष्ठातृ देवताओं की करणना करते थे। इन देवताओं को सन्तुष्ट व तृप्त करने के लिये वे अनेक प्रकार के विधि विधानों का अनुष्ठान किया करते थे। वे यह भी मानते थे, कि कतिपय देवता अधिक शक्तिशाली हैं, और वे अन्य देवताओं पर शासन करते हैं। इन शक्तिशाली देवताओं की पूजा पर जापानी लोग अधिक ध्यान देते थे।

बीत के साथ सम्पर्क जापान के पड़ोस में चीन का शक्तिशाली साम्राज्य विद्यमान था। चिन और हान (२०६ ई० पू० से २२० ई० प० तक) राजवंशों के समय में चीन ने किस प्रकार अपनी शक्ति का विस्तार किया, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। कोरिया के कुछ प्रदेश हान साम्राज्य के अन्तर्गत थे, और चीनी लोग अच्छी बड़ी संख्या में वहां निवास करते थे। चीनी सभ्यता कोरिया में भलीभांति प्रवेश पा गई थी। इस दशा में यह स्वामाविक था, कि कोरिया द्वारा जापानी लोग भी चीन के सम्पर्क में आवें। हान राजवंश के पतन के बाद चीन की राजशिक्त निर्वल हो गई थी और चीन में अनेक राज्य स्थापित हो गये थे। इस युग (२२० ई० प० से ६१८ ई० प० तक) में जापान और चीन का अधिक सम्बन्ध नहीं रहा। पर इस काल में भी जापान के राजदूत चीन के विविध राज्यों के राज दरवारों में आते जाते थे और बहुत से चीनी लोग भी जापान की यात्रा करते थे। राजशिक्त की दृष्टि से चीन इश गम्य अनेक राज्यों में विभक्त था, और उनमें प्रायः युद्ध होते रहते थे। यह स्वागिधिक था, कि

चीन के राजा आपस के युद्धों में यमतो के जापानी राज्य की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते। हान राजवंश के बाद बौद्ध धर्म का चीन में बहुत प्रचार हुआ। बौद्ध प्रचारक चीन से कोरिया भी गये और यहां भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। यह स्वाभाविक था, कि बौद्ध भिक्षु कोरिया से जापान भी जावें। ऐतिहासिक लोग यह मानते हैं, कि जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश छटीं सदी में हुआ और धीरे धीरे सम्पूर्ण जापान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया।

बौद्ध धर्म के साथ साथ चीनी भाषा, लिपि और साहित्य का भी जापान में प्रवेश हुआ। जापान के कूलीन व समृद्ध लोग बड़े शौक से चीनी पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। चीन के सम्पर्क ने जापान में तये जीवन का संचार किया। जापानी लोगों में यह विशेषता है, कि वे अंपने से उन्नत सभ्यता और नये ज्ञान विज्ञान को बड़ी तेजी के साथ अपना लेते हैं। उन्नीसवीं सदी के उत्तराई में जब पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में आकर उन्होंने अपनी हीन दशा का अनुभव किया, तो उन्होंने बड़ी शी घता के साथ नये ज्ञान विज्ञान को ग्रहण किया और आधी सदी से भी कम समय में वे अमे-रिका और यूरोप के समकक्ष हो गये। सातवीं और आठवीं सिवयों में पहले भी ठीक यही प्रक्रिया जापान के इतिहास में हो चकी है। जब जापानी लोग अपने से अधिक उन्नत चीनी लोगों के सम्पर्क में आये, तो अपनी उन्नति के लिये भी उनमें उत्साह का संचार हुआ और बड़ी तेजी के साथ वे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हए। चीनी लिपि को अपनाकर जापानी लोगों ने अपनी भाषा में साहित्य का निर्माण शुरू किया । काव्य, इतिहास, धर्म, चिकित्सा आदि पर बहुत से ग्रन्थ लिखे गये और मृतिनिर्माण, चित्रकला, संगीत आदि के क्षेत्र में भी जापानी लोगों ने बहत उन्नति की।

सामन्त पढ़ित — इस इतिहास में हमारे लिये यह सम्भव नहीं हैं, कि जापान के प्राचीन राजनीतिक इतिहास का संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकें। पर जापानी इतिहास की. कुछ वातों का निर्देश करना आवश्यक है। इसमें प्रथम सामन्तपढ़ित का विकास है। सातवीं सदी तक जापान बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और ये सब राज्य एक जापानी सम्राट् की अधीनता को स्वीकृत करते थे। प्रमुख राजकर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्रीक सरकार द्वारा की जाती थी। पर धीरेश्वीरे राजकर्मचारी के पद वंश-कमानुगत होने लगे और कित्पय कुलीन परिवार राजशक्ति का उपभोग करने के कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये। जापान में राजकर्मचारियों की

अपना निर्वाह करने के लिये जागीर देने की प्रथा थी। जागीर की आम-द्रनी से वे अपना गुजारा करते थे। जब राजकीय पद पिता के वाद पुत्र की मिलने लगे, तब जागीरें भी एक कुल में स्थिर हो गईं। न केवल विविध राजकीय पदों पर अपितु जागीरों पर भी विशिष्ट कुलों का वंश-क्रमानुगत रूप से अधिकार स्थापित हो गया। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि जापान में सामन्त पद्धित का विकास हुआ और जिन राजकर्मचारियों की नियुक्ति पहले सम्राट् की केन्द्रीय सरकार द्वारा होती थी, वे अब बड़े बड़े जागीरदार बन गये और अपने अपने क्षेत्र में वे स्वतन्त्र सामन्तों के समान शासन करने लगे। पुराने राज्यों की शासक श्रेणियों के लोग अब शासक के हाथ साथ जागीरदार भी हो गये और उनका यह प्रयत्न होने लगा कि वे शित का प्रयोग कर जहां अपनी जागीरों में वृद्धि करें वहां साथ ही राज्य में भी उनका प्रभाव वृद्धि को प्राप्त हो।

सैनिक श्रीण — सामन्त पढ़ित के विकास का यह परिणाम हुआ, कि जापान में एक ऐसी श्रीण का निर्माण शुरू हुआ, जिसका कार्य ही सैनिक सेवा था। प्रत्येक सामन्त या जागीरदार इस वात के लिये प्रयत्नजील था, कि वह अपनी जागीर पर अपने आधिपत्य को कायम रखे, और यदि सम्भव हो तो अपनी जागीर की वृद्धि भी करे। इसलिये उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाना शुरू किया और बहुत से मनुष्य शक्ति और आर्थिक आमदनी के लोग से आकृष्ट होकर उनकी सेनाओं में भरती होने प्रारम्भ हुए। प्रत्येक सामन्त की यह कोशिश रहती थी, कि उसकी सेना अधिक से अधिक प्रवल् हो। बारहवीं सदी तक जापान में यह दशा आ गई थी, कि विविध सामन्त लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र राजाओं के समान शासन करने लगे थे। सम्राट्व केन्द्रीय सरकार का उन पर आधिपत्य नामभात्र का रहे गया था और ये सामन्त एक दूसरे के साथ युद्ध में भी निरन्तर व्यापृत रहते थे। सम्राट् इन सामन्त राजाओं के सम्मुख अपने को असहाय अनुभव करता था।

शीपूनों का शासन—जापानी सम्राट् की अवीनता की स्वीकृत करने वाले सामन्त राजा, जिन्हें जापान में दैम्यों कहते थें, जहां अपनी जागीरों के विस्तार में तत्पर थे, वहां साथ ही अपने अतिरिक्त अन्य सामन्तों को अपना बरावतीं करके केन्द्रीय सरकार पर भी अपना प्रभाय स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। सम्राट् के प्रति इनके हृद्य में भनित का भाव था, उसे ये दैवी मानते थे। अतः इन्होंने यह बत्न नहीं किया, कि सराद को राज्यच्युत कर स्वयं उस पद को प्राप्त कर छें। पर जिरा प्रकार भारत में पेशवा लोगों ने छत्रपति राजा को नाममात्र के लिये राजा के पद पर अधिष्ठित रखकर स्वयं शासनसूत्र का संचालन किया, या जिस प्रकार नैपाल में राना लोगों ने महाराजाधिराज की सत्ता को स्वीकृत करते हुए नैपाल के वास्त-विक शासन को अपने हाथ में कर लिया, वैसे ही जापान में अनेक वैम्यो लोगों ने सम्राट्की मत्ता को कायम रखते हुए शासन शक्ति अपने अधीन कर ली। इस प्रकार के सामन्त राजाओं में योरीतोमो का नाम विशेष रूप से उल्लेख-नीय है। वह बड़ा प्रतापी और महत्त्वाकांक्षी मनुष्य था। बारहवीं सदी के अन्त में उसने अन्य सब सामन्तों को परास्त कर केन्द्रीय शासन में अपने प्रभाव को स्थापित किया और सम्राट को अपने हाथों में कठपुतली बना लिया । वह जापान का प्रथम शोगुन (सर्व-विजयी सेनानी) बना । योरीतोमो ने यह यत्न नहीं किया, कि अन्य सामन्तों को सर्वधा नष्ट कर दे। जसने सामन्तपद्धति को जारी रखा, पर सेना की सहायता से अपनी शक्ति को इतना अधिक बढ़ा लिया, कि कोई अन्य सामन्त उसके सम्मुख सिर नहीं उठा सकता था। वह सच्चे अर्थों में 'प्रणत-सामन्त' था। उसने जापान की केन्द्रीय सरकार का नये सिरे से संगठन किया और इस समय रा जापान में सैनिक लोगों का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया। पर शोगून का पद योरीतोमो के वंश में सदा के लिये स्थिर नहीं रह सका। योरीतोमो के उत्तराधिकारी उसके समान प्रतापी नहीं थे। परिणाम यह हुआ, कि अन्य सामन्त राजा प्रबल हो गये। पर योरीतोमी शोगन द्वारा जापान के शासन की जिस पढ़ित का प्रारम्भ किया गया था, वह बाद में भी कायम रही। शोगून का पद योरीतोमो के कुल से निकलकर अन्य कुलों में चला गया, पर जापान की केन्द्रीय सरकार पर किसी न किसी शोगून का आधिपत्य कायम रहा, और सम्राट् की शक्ति इन शोगूनों के सम्मुख सर्वदा अगण्य रही।

तोकुगावा शोगून—शोगून का पद प्राप्त करने के लिये जापान के विविध सामन्त कुलों में किस प्रकार संघर्ष होता रहा, इसका वृत्तान्त यहां लिख सकता असम्भव है। यहां इतना निर्देश कर देना पर्याप्त होगा, कि १६०३ में शोगून का पद तोकुगावा कुल में चला गया और १८६७ तक (१६०३ से १८६७ तक) यह पद इसी कुल में स्थिर रहा। जिस प्रतापी के तोकुगावा नेता ने अन्य सब सामन्तकुलों को परास्त कर शोगून के गौरवमय पद की सबसे पूर्व प्राप्त किया था, उराका नाग प्रमास था। ढाई सदी से अधिक समय तक कोई अन्य सामन्तकुलों नहीं हुआ, कि तोकुगावा कुल का मकावला

कर सके। इसका परिणाम यह हुआ, कि २६५ वर्षों तक जापान सामन्तों के पारस्परिक युद्धों से बचा रहा। देश में शान्ति कायम रही और जापान को यह अवसर मिला, कि वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। तोकुगावा कुल के शोगूनों के शासनकाल में ही यूरोपियन लोगों के दुव्यंवहार से परेशान होकर तोकुगावा शोगूनों ने उनका जापान में आना निषिद्ध कर दिया और जब १८५३ में कोमोडोर पेरी द्वारा पाश्चात्य लोगों ने जापान के साथ अपने सम्पर्क को पुनः स्थापित किया, तब भी वहां का शासन-सूत्र तोकुगावा कुल के शोगूनों के ही हाथों में था।

(२) पारुचात्य देशों से प्रथम सम्पर्क

मंगील साम्राज्य के समय में यूरोप के लोग चीन में आते जाते थे। मार्को पोली आदि अनेक यात्रियों ने इस काल में चीन की यात्रा की थी और मंगोल सम्राटों के राजवरबार में निवास भी किया था। पर तेरहवीं चौदहवीं सदियों में कोई यूरो-पियन यात्री जापान भी आया हो, इसका पता नहीं है। मार्को पोलो ने चीन में निवास करते हुए जापान के विषय में भी सुना था और इस देश के सम्बन्ध में अनेक - बातें भी उसने अपने यात्रादिवरण में उल्लिखित की थीं। यही कारण है, कि जब अफ़ीका का चक्कर काटकर पोर्तुगीज व अन्य यूरोपियन लोगों ने एशिया के पूर्वी देशों में आना जाना शुरू किया, तो वे जापान भी गये। सबसे पहले १५४२ में यूरोपियन जातियों का जापान के साथ सम्पर्क हुआ । भारत, चीन, आदि के समान जापान में भी समुद्रमार्ग से जाने वाले पहले यूरोपियन यात्री पोर्तु-गीज लोग थे। सोलहवीं सदी के अन्त तक स्पेनिश लोग भी जापान गये और सत-रहवीं सदी के शुरू में (तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में) डच और इङ्गलिश लोग भी जापान आने जाने लगे । ये यूरोपियन यात्री हिन्द महासागर, मलक्का अन्तरीय और फिलिप्पीन के समीप से होते हुए जापान की तरफ जाते थे, अतः स्वाभाविक रूप से शुरू में ये क्यूज़ गये और नागासाकी में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कायम की । क्यूशू के सामन्तों ने इन विदेशी व्यापारिशों का स्वागत निया और व्यापार कार्य में इनकी सहायता की।

यूरोपियन ज्यापारियों के साथ साथ ईसाई मिशनरी भी जापान पहुंचने रहते । जेसुएट भन्य क्षय का नेता क्षांसिस बहेनियर पूर्ती एचिया में ईसाई धर्म का प्रभार करता हुआ जापान भी गया । १५४९ में उसने आपान में अपना प्रचार कार्य प्रारम्भ किया और उत्तर में क्योती तक की गाया की । फ्रांसिस बनेजियर देर तक जापान में नहीं रहा, पर उसके साथी बहा गर कार्य करते रहे । जेगुएट लोगों के बाद फांसिस्कन, डोमिनिकन आदि अन्य ईसाई सम्प्रदायों के प्रचारक भी जापानगये और इन मिशनरियों ने हजारों जापानी नागरिकों को किविचयन धर्म का अनुयायी बनाया। जापानी लोग नये विचारों का स्वागत करने के लिये सदा उद्यत रहते थे, अतः उन्होंने ईसाई धर्म में भी बहुत दिलचस्पी प्रदिश्त की। रामन्त लोगों का खयाल था, नियूरोपियन लोगों के व्यापार से उनका अपना भी बहुत लाभ है। अतः वे जहां विदेशी व्यापारियों का स्वागत करते थे, वहां साथ ही विदेशी धर्म प्रचारकों का भी आदर करते थे।

यूरोपियन लोगों को जापान से सम्पर्क रखने का निषेध—यूरोपियन लोग जापान में व्यापार और धर्म के विस्तार में तत्पर थे, पर वे देर तक अपने कार्य को जारी नहीं रख सके । जुछ समय बाद ही जापान की सरकार ने एक आजा प्रकाशित की, जिससे यूरोपियन लोगों के जापान में आवागमन को रोक दिया गया । जापान ने इस नीति का अनुसरण किन कारणों से किया, इस पर प्रकाश टालने की आव-ध्यकता है—

- (१) यूरोपियन व्यापारियों में परस्पर एकता नहीं थी, वे एक दूसरे की निन्दा करने में तत्पर थे। डच लोग जापानियों से कहते थे, कि अंग्रेजों से व्यापार करना अनुनित है, और इससे उनके देश का नुकसान होगा। स्पेनिश और इझ लिया लोग इसी तरह की बात डच लोगों के विषय में कहते थे। यूरोपियन लोगों से एक दूसरे की निन्दा सुनकर जापानी लोग सोचते थे, कि सभी पाश्चात्य लोग बुफे हैं और उनके साथ सम्पर्क रखना उनित नहीं है।
- (२) भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच लोग, फिल्प्पीन में स्पेनिश लोग, चीन के समुद्रतट पर पोर्तुगीज लोग और दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों में डच लोग इन प्रदेशों के निवासियों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे थे, उससे जापानी लोग परिचित थे। इस दुर्व्यवहार का वृत्तान्त जापानियों में इस विचार की दिल-सित कर रहा था, कि सूरोपियन लोगों के साथ सम्पर्क रखना सर्वथा अनुचित है।
- (३) जापान के समुद्र तट के समीप भी डच और इंगलिश लोगों में अनेक बार लड़ाइयां हुई। इन लड़ाइयों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर जापानी लोग यह भलीगांति अनुभव करने लगे थे, कि यूरोपियन व्यापारी जिन देशों से आ रहे हैं, वे लड़ाक् हैं, और उनका उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यापार करना ही नहीं है।
- (४) जापान में धर्म प्रचार कार्य में व्यापृत ईसाई मिशनरी अपने को जापान समाद की प्रजा नहीं समझते थे। उनमें यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जाती। थी, कि अपने को जापान की सरकार के अधीन न समझें और अपनी रक्षा के लिये अपने देश की सरकारों पर निर्भर रहें। जापान के जो नागरिक ईसाई धर्म की

स्वीकार कर लेते थे, विदेशी मिशनरी उनके प्रति पक्षपात का भाव रखते थे और प्रहु प्रयत्न करते थे, कि सरकारी कर्मचारियों व न्यायाधीशों पर अनुचित रूप से जोर देकर इन जापानी ईसाइयों को लाभ पहुंचावें। जापान में यह विचार निरन्तर जोर पकड़ता जाता था, कि विदेशी मिशनरी केवल धर्म प्रचारक ही नहीं हैं, अपितु अपने देश के गुप्तचर भी हैं और वे जापान में विदेशी सत्ता को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

इसीलिये तोकुगावा कुल के शोगूनों से पूर्व ही १५८७ में जापानी सरकार की ओर से यह आज्ञा प्रकाशित की गई थी, कि जापान देवताओं का देश है और उसमें एक ऐसे धर्म का प्रचार उचित नहीं है, जो देवपूजा का विरोधी है। ईसाई मिश-नरियों को आदेश दिया गया, कि वे जापान को छोड़कर चले जावें। कुछ मिशनरी गिरफ्तार भी किये गये, पर इसी बीच में १६०३ तीकुगावा कुल के नेता इयासू ने अन्य सब सामन्तों को परास्त कर शोगून पद को प्राप्त कर लिया । इयासू पाइचात्य लोगों के प्रति मैत्री भावना रखता था, वह विदेशी व्यापार का प्रबल पक्षपाती था और उससे अपने देश का लाभ मानता था। यही कारण है, कि उसने १५८७ की सरकारी आजा को शिथिल कर दिया और ईसाई मिशनरी पहले के सदश अपने ैজার্য में तत्पर हो गये। इयासु की सहिब्ज्ता की नीति से लाभ उठाकर विदेशी पादरी इतने उद्दण्ड हो गये, कि अन्त में इयासू ने भी अनुभव किया कि इन धर्म प्रचारकों का उद्देश केवल धर्म प्रचार ही नहीं है, वे धर्म की आड़ में अपने देशों के प्रभुत्त्व को जापान में स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इसीलिये १६१२ में इयासू ने अनेक ऐसी आज्ञायें प्रकाशित की, जिनका उद्देश्य विदेशी पादरियों के कार्य को नियन्त्रित व मर्यादित करना था। पर ईसाई पावरी इन आजाओं की उपेक्षा करते थे। परिणाम यह हुआ, कि अनेक पादरी गिरफ्तार किये गये और कतिपय को प्राणदण्ड भी दिया गया। पर इससे भी ईसाइयों ने अपने कार्य की बन्द नहीं किया। १६३७-३८ में उन्होंने राजनीति में खुले तौर पर हस्तक्षेप गुरू किया और यह प्रयत्न किया कि शोगन के शासन के निरुद्ध जनता को निष्रोह करने के लिये प्रेरित करें । परिणाम यह हुआ, कि जापानकी सरकार विदेशी मिशनरियों के बहुत िलाफ हो गई और इनके विक्रम्न संस्त कार्रवाई की गई । कानून द्वारा ुंपारं धर्म के पचार को रोक दिया गया और बहुत से पादरी जापान को छोड़कर कोहर चले जाने के लिये वियन हुए। इहर ने पादिरयों को राज्य की ओर से कठोर दण्ड भी दिये गये।

जापान की सरकार ने केवल ईसाई धर्म के प्रचार की ही बन्द नहीं किया, फ़िन्तु यह भी व्यवस्थाकी, कि यूरोपियन व्यापारी जापान में व्यापार न कर सकें। स्पेन, पोर्त्गाल और इङ्गलैण्ड के व्यापारियों को आज्ञा दी गई, कि वे जापान में न आवें। इसी प्रकार जापानी लोगों के लिये भी फिलिप्पीन आदि ऐन् प्रदेशों में व्यापार के लिये जाना निपिद्ध कर दिया गया, जहां यूरोपियन लोग अपने पैर जमा चुके थे। यूरोपियन लोगों में केवल डच लोगों को यह अनुमित दी गई, कि वे जापान के साथ व्यापार को जारी रख सकें। पर उनके लिये भी यह व्यवस्था की गई, कि वे केवल नागासाकी बन्दरगाह में ही आजा सकें। इस प्रकार सतरहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जापान यूरोपियन लोगों के सम्पर्क से पृथक् हो गया और इन पाइचात्य लोगों को यह अवसर नहीं रहा, कि वे चीन के समान जापान में भी धर्म प्रचार व व्यापार की आड़ में अपने साम्राज्यवाद का प्रसार कर सकें।

(३) उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जापान की दशा

राज्य का शासन—तोकुगावा शोगूनों ने जापान में जिस ढंग से शासनसूत्र का संचालन किया, जस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। शासन का अधिपति सम्राट्था, पर वास्तविक शिक्त उसके हाथ में नहीं थी। सम्पूर्ण शासन उसके नाम पर होता था, पर वह शासन-नीति का निर्माण नहीं करता था। सम्राट्धा उसके परिवार को खर्च के लिये राजकीय आमदनी का इतना भाग दे दिया जाता था, कि वह बड़ी शान के साथ अपने राजप्रासाद में जीवन बिता सके। जापानी लोग समझते थे, कि सम्राट्देवी है, देवताओं का वंशज है, वे उसे साक्षात् देवता मानते थे। उनके हृदय में अपने सम्राट्के प्रति असीम आदर का भाव था। किसी स्यक्ति के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह सम्राट् से मिल सके या शोगून के विरुद्ध उसके कान भर सके। सम्राट्का राजप्रासाद क्योतो में विद्यमान था और वहां वह जनता से किसी भी प्रकार का सम्पर्क न रखता हुआ आराम के साथ जीवन क्यतीत करता था।

शोगून का निवासस्थान येदो में था। जापान के शासन का सञ्चालन इसी नगर से होता था। वास्तिवक राजशिक्त शोगून के हाथों में थी। अन्य सब सामन्तों को तोकुगावा कुल के शोगूनों ने अपना वशवर्ती वना रखा था। सामन्तों के लिये यह आवश्यक था, कि वे साल में कुछ समय येदो में शोगून के दरवाण परिचे । जब वे येदो से अनुपस्थित हों, तब उनकी पत्नी व सन्तान को वहां रहिं। पड़ता था। शोगून समझते थे, कि यदि कोई सामन्त विद्रोह करने का यत्न करेगा, तो उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार करके उसे अपने वश में लाया जा सकेगा। सामन्त लोग क्या सोचते हैं, क्या योजनायें बनाते हैं, यह आगने के लिये उस गर

गुप्तचर रखे जाते थे। इन गुप्तचरों के कारण सामन्त लोग शोगन के खिलाफः षड्यन्त्र करने में सर्वथा असमर्थ थे। प्रत्येक सामन्त के लिये आवश्यक था, कि वह शोगून के प्रति लिखित रूप में राजभित्त की शपथ ले। जिन सामन्तों पर शोगून को विश्वास होता था, उन्हें शासन के महत्त्वपूर्ण कार्य मुपुर्द किये जाते थे। शोगून की तरफ से यह भी व्यवस्था की गई थी, कि कोई सामन्त सरकारी आज्ञा के बिना अपने दुर्ग की गरम्मत भी न करा सके। इन सब उपायों का यह परिणाम था, कि सामन्त लोग शोगूनों के पूर्णतया वशवर्ती हो गये थे और उनमें विद्रोह और षड़यन्त्र की प्रवृत्ति सर्वथा नष्ट हो गई थी।

किस प्रकार जापान में एक सैनिक श्रीण का विकास हुआ, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस सैनिक वर्ग के लोग समूराई कहाते थे। तोकुगावा शोगूनों के समय में जापान में आन्तरिक युद्धों का प्राय: अन्त हो गया था और देश में पूर्णतया शान्ति और व्यवस्था स्थापित थी। किसी वाह्य देश के आक्रमण का भी जापान को भय नहीं था। इसल्यि इस काल में समूराई को अपनी सैनिक क्षमता प्रविश्ति करने का कोई महत्त्वपूर्ण अवसर उपस्थित नहीं हुआ। यही कारण है, कि ये समूराई लोग शारीरिक शक्ति और सैनिक क्षमता प्रदी कारण है, कि ये समूराई लोग शारीरिक शक्ति और सैनिक क्षमता के साथ साथ विद्याध्ययन और शिक्षा प्राप्ति के लिये भी तत्पर हुए । सतरहवीं सदी से पूर्व तक जापान में बौद्ध विहार ही विद्या के केन्द्र थे और बौद्ध भिक्ष ही शिक्षा की ओर ध्यान देते थे। पर तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में समूराई वर्ग ने भी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। प्रत्येक जापानी सैनिक के लिये जिस प्रकार खद्भ संचालन में कुशल होना आवश्यक था, वैसे ही पाण्डित्य में प्रवीण्यता प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया। सैन्यशिक्त और शिक्षा में कुशलता प्राप्त कर लेने के कारण समूराई लोगों का प्रभाव जापान के जनसमाज में बहुत अधिक वह गया।

धर्म जापान के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देश में सर्वत्र बौद्ध बिहार और मन्दिर विद्यमान थे और इनमें हजारों बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पर महात्मा बुद्ध ने भारत में जिस अब्दांगिक आर्यमार्ग का उपदेश किया था, वह अपने अविकल रूप में जापान में विद्यमान नहीं था। यह अवंथा स्वागाविक था, कि जापान में जो विधिविधान अनुष्ठान व विद्यास पर पराचात रूप से चल आते थे, जायम रहें और उनके कारण जापानी वौद्ध धर्म एक ऐसा रूप घारण कर ले, जो लंका, भारत, बरमा न चीन के बौद्ध पर्म से बहुत कुछ भिन्न हो। जापान के प्राचीन पर्म वी 'शिक्तों धर्म के अवेक विश्वांस अक्षण रूप से जायम रहें। चीन के साथ जापान में शिक्तों धर्म के अवेक विश्वांस अक्षण रूप से जायम रहें। चीन के साथ

सम्पर्क स्थापित होने पर जापानी लोगों ने कन्फ्यूसियस आदि प्राचीन चीनी विचारकों के ग्रन्थों का अनुशीलन भी प्रारम्भ कर दिया था। तोकुगावा शोगून कन्फ्यूसियस के विचारों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे और उनकी संरक्षा के कारण प्राचीन चीनी ग्रन्थों का जापान में बहुत अध्ययन होता था। इस कारण चीन के समान जापान में भी इस आचार्य के विचारों का बहुत प्रभाव था।

नगरों के बिकास—तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में जापान में अनेक नगरों ने बहुत उन्निति की । इस काल में जापान के शासन का केन्द्र येदो था । सब सामन्तों के लिये यह आवश्यक था, कि वे स्वयं या उनके परिवार वहां पर निवास करें । इसका परिणाम यह हुआ, कि येदो में बहुत ही सुन्दर इमारतें बनीं और वह जापान का सबसे बड़ा व समृद्ध नगर बन गया । सम्राई लोग भी वहां बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे । इस दशा में यह स्वागाविक था, कि देश के सबसे धनी व समृद्ध वर्ग की विविध प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये बहुत से शिल्पी, ज्यापारी व नौकरी पेशा लोग वहां आकर बसने लगें । उन्नीसवीं सदी के शुरू में येदो की जनसंख्या दस लाख से भी ऊपर पहुंच गई थी । इस यूग में लण्डन, पेरिस आदि की जनसंख्या भी इससे अधिक नहीं थी और येदो को संसार के सबसे बड़े नगरों में गिना जा सकताथा । येदो के समान क्योतो, नागासाकी आदि अन्य अनेक नगरों ने भी इस यूग में बहुत उन्निति की।

क्यापार की उन्नति—तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में जापान में पूर्णतया शान्ति और व्यवस्था कायम थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि आधिक पृष्टि से देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। इस युग में जापान में कला और शिन्त्य में बहुत उन्नति की। सामन्त और समूराई लोग आधिक दृष्टि से सर्वथा निश्चिन्त और समृद्ध थे। वे शित्य और कला की वस्तुओं पर दिल खोलकर खर्च कर सकते थे। अतः बहुत से लोग शित्य और कला द्वारा अपनी आजीविका कमाने छगे और एक ऐसे वर्ग का विकास हुआ, जिसका काम शित्यियों द्वारा तैयार किये गये माल को जापान के विविध प्रदेशों में विक्रय करना था। यह क्यापारी वर्ग पेदो, क्योतों आदि समृद्ध नगरों में व्यापार द्वारा धन कमाने में प्रयत्नशील था, और इसकी आमदनी निरन्तर बढ़ती जानी थी। यही कारण है, कि सामन्त कुलों के अनेक लोग भी इस सगाव व्यापार के अन्त में आये और उन्होंने अपनी जागीर में राजशनित के उपयोग की प्रोक्षा व्यापार हात्र घन गमाना अधिक हितकर समझा। उन्नीतनों और भीगवीं सिदयों में मित्रुई कुल के लोग आधिक दृष्टि से बहुत समृद्ध हो गये। इन्होंने व्यापार द्वारा हो अपार धन का उपार्जन किया था।

में लोग वस्तुतः सामन्त वर्ग के थे, पर व्यापार में लाम देखकर इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट हुए थे।

विदेशों के साथ सम्पर्क-जापान की सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार और यरोपियन व्यापार को जिस प्रकार निषिद्ध कर दिया था, उससे यह समझा जाता है, कि इस युग में जापान का विदेशों के साथ कोई भी सम्पर्क नहीं रहा था। पर यह बात पूर्णरूप से सत्य नहीं हैं । डच लोगों को जापान के एक बन्दरगाह में व्यापार बारने की अनुमति मिली हुई थी। वहां जापानी लोग उनके सम्पर्क में आते थे। इस यग में यूरोप के विविध देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति कर रहे थे, डच लोगों द्वारा जापानी उससे भी परिचित थे। अठारहवीं सदी में चिकित्साशास्त्र, सैन्यशक्ति, भूगोल आदि अनेक विषयों की युरोपियन पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया । इन पुस्तकों द्वारा जापानी लोग पारुवात्य देशों के ज्ञान विज्ञान से परिचय प्राप्त करते थे। यही कारण है, कि १८५२ में जब कोमोडोर पेरी ने पाक्चात्य देशों के जापान के साथ सम्पर्क को अधिक चनिष्ठ रूप से स्थापित किया, तो जापान पाश्चात्य विज्ञान को ग्रहण करने के लिये बिलकुल तैयार था । सतरहवीं सदी में जापान की सरकार ने यूरोपियन व्यापारियों और मिशनरियों पर जो प्रतिबन्ध लगाया था, उसके कारण येपारचात्य लोग उस देश में उस ढंग से अपना प्रभुत्य नहीं स्थापित कर सके, जैसे कि उन्होंने भारत, चीन, आदि में स्थापित किया था।

(४) पाइचात्य देशों के साथ सम्बन्ध की पुनः स्थापना

जिशीसबीं सदी में पाक्चात्य देशों ने जापान के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध को स्थापित करने के लिये एक बार फिर प्रयत्न किया । वैज्ञानिक उन्नति के कारण इस समय पाक्चात्य देशों के जहाज भाप की सिक्त से चलते थे और पृथिवी के सव देशों में आते जाते थे । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार असाधारण रूप से उन्नति कर रहा था । एशिया और अफीका के पिछड़े हुए प्रदेश बड़ी तेजीं से पाक्चात्य देशों के प्रभाव व प्रभुत्त्व में आते जाते थे । इस दशा में यह सम्भव नहीं था, कि जापान समय की छहर से अछूता बचा रह सके । भौगोलिक वृष्टि से जापान रूप के बहुत सभीप था । सखालिन द्वीप पर रूस और जापान का संयुवत अविकार था । पुरोल दीप था । सखालिन द्वीप पर क्स और जापान का संयुवत अविकार था । पुरोल दीप जापान से अपने सम्बन्ध को अनिक पनिष्ठ ननावे । इस उद्देश्य से रूस का एक प्रतिनिधि मण्डल १७९२ में जापान आया । जहाज के दूट जाने से कतिपय जापानी मल्लात प्रभावत हो सबे थे । रूस के एक जहाज ने इन्हें सहामता थी घी, और

इन्हें जापान पहुंचाने के नाम पर ये रूसी लोग वहां आये थे। पर जापान आने का उनका असली प्रयोजन जापान से सम्पर्क स्थापित करना था । १८०४ में रूस ने एक अन्य मिशन जापान भेजा। पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हुई है जापान रूस के साथ व्यापारिक व अन्य सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार नहीं हुआ । रूस के समान ब्रिटेन ने भी इस यग में जपान के साथ सम्पर्क में आने का प्रयत्न किया। १८०८ में एक अंग्रेजी जंगी जहाज नागासाकी आया। होल मछली पकड़ने के बहाने से अन्य यूरोपियन देशों के जहाज भी जापान के समुद्रतट के आस-पास चक्कर काटने लगे। पारचात्य देशों के जहाजों ने कई बार इस नाम पर जापान के बन्दरगाहों तक पहुंचने की कोशिश की, कि उनके पास पीने का पानी समाप्त हो गया है, या कोयले की कमी होगई है, या खाद्य सामग्री कम पड़ गई है। पर जापानी लोग अपनी नीति पर दृढ़ थे। उन्होंने इन विदेशियों को अपने देश में प्रविष्ट नहीं होने दिया । जापान के कुछ मिछयारे मछली पकड़ते हुए अमेरिका के समद्रतट तक पहुंच गये थे। जहाज टट जाने के कारण उन्होंने अमेरिका का आश्रय लिया था। अमेरिका ने सोचा, जापान के साथ सम्पर्क स्थापित करने का यह अत्यन्त उत्तम मौका है । इन जापानी मछियारों को पहले इङ्गलैण्ड लाया गया । फिर ये चीन के मकाओ बन्दरगाह पर पहुंचाये गये और फिर इन्हें मोरिसन नामक अमेरिकन जहाज पर जापान ले जाया गया । १८३७ में जब मोरिसन जहाज जापान पहुंचा, तो जापानियों ने उस पर गोलाबारी की और उसे वापस लौटा आना पडा।

१८४० के बाद अमेरिकन लोगों की जापान के सम्बन्ध में दिलचस्पी बहुत बढ़ गई थी। इस समय तक संयुक्तराज्य अमेरिका प्रशान्त महासागर के तट तक अपना विस्तार कर चुका था। कैलीफोर्निया भलीभांति आबाद हो गया था और अमेरिकन लोग जहाजों हारा प्रशान्त महासागर में भलीभांति आने जाने लगे थे। १८४० में दो अमेरिकन जहाज इस उद्देश्य से येदो की खाड़ी में भेजे गये, कि जापानी सरकार से मिलकर उसके साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करें। पर इस अमेरिकन मिशन को सफलता नहीं हुई। जापान की सरकार ने अमेरिका से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने से इनकार कर दिया। १८४२ से १८६० तक विविध पश्चात्य देशों ने चीन में किस प्रकार अपने व्यापारका विस्तार कियाथा, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस काल में चीन के बहुत से बन्दरपाह, पश्चात्य देशों के व्यापार के लिये खुल गये थे और चीन पर विवेशी प्रभाद निरंति स्थाप कहना जा रहा था। इस दशा में यह सम्मन नहीं था, भि जापान पश्चात्य लोगों के सम्पर्क से इस प्रकार बना रह सके। जापानी लोग भी एशिशम में पश्चात्य देशों के

बढ़ते हुए प्रभाव से परिचित थे। डच लोगों द्वारा उन्हें फिलिप्पीन, चीन आदि के सुद्ध समाचार मिलते रहते थे। पर प्रश्न यह था, कि पश्चात्य देश किस प्रकार जापान को अपने साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये विवदा करें।

कमोडोर पेरी का आगमन-जापान के साथ अपना सम्पर्क स्थापित करने में सबसे अधिक तत्परता अमेरिका ने प्रविशत की । अमेरिका के राष्ट्रपति ने कमोडोग पेरी के नेतृत्त्व में एक मिशन इस उद्देश्य से जापान भेजा, कि वह वहां जाकर अमेरि-कन सरकार का सन्देश जापान की सरकार तक पहुंचावे। पेरी के इस मिशन के जहेश्य निम्नलिखित थे—(१) यदि कोई अमेरिकन जहाज जापान के समुद्रतट पर टट जाय, तो उसके मल्लाहों व यात्रियों को जापान में आश्रय दिया जाय। (२) अमेरिकन जहाजों को यह अनुमति हो, कि वे जापानके बन्दरगाहों से कोयला, जल या ख़ाद्य सामग्री आदि ले सकें। (३) जापान के बन्दरगाह अमेरिकन व्यापार के लिये खोल दिये जावें । २४ नवम्बर, १८५२ को पेरी ने नार्फोक के बन्दरगाह से प्रस्थान किया । उसके साथ में चार जहाज थे । ३ जुलाई, १८५३ को पेरी के शहाज योकोहामा की खाड़ी में पहुंच गये। जापानी सरकार की ओर से उन्हें बादेश दिया गया, कि वे समुद्रतट के समीप न आवें। पर पेरी ने इस आदेश की कोई: भ्षरबाह नहीं की । वह जापान के समुद्र तट पर पहुंच गया और अमेरिकन राष्ट्रपति के पत्र को जापानी कर्मनारियों के मुपूर्व कर यह कहकर लौट गया, कि मैं एक साल बाद फिर आऊँगा । इस बीच में जापानी सरकार अमेरिका की मांग पर भलीमांति विचार कर ले और अपने उत्तर को तैयार कर ले। पेरी द्वारा लागा गया अमेरिकन राष्ट्रपति का पत्र जोगृन के पास पहुंचा दिया गया। जोगृन और उसके साथियों ने उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया। जापानी सरकार भलीभांति अनुभव भारती थी, कि इस समय की परिस्थिति ऐसी है, कि पाक्चात्य देशों की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है । केवल अमेरिका ही नहीं, रूस भी इस रापग जागान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये जोर दे रहा था । उनकी और ने भी एक मिशन इस रागय नानानाकी पहुंच नया या । फांस के जहाज भी जापान के समुद्रतट के आसपास करतर लगा यह थे और विदेन भी इस किस्ता में था, कि शीझ से सीझ जातात के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की स्थापना की जाय । इस दशा में कमोडोर पेरी ुन्ने पूरं एक साल तक प्रतीका करना नए वित समझा । फरवरी, १८५४ में वह अपने . रेन्हाजों को रेट्यार जापान पहुंच गता। इस जहाजों ने अमेरिकन सैनिक बड़ी संख्या में विद्यमान ये और पेरीको यह आयेरा था, कि जिल्लाकी सरकार अमेरिकाकी मांगी पर ज्यान न दे, व वेरी को जायान-प्रवेश हो रोहो, तं। वह सैन्य धरिन का प्रयोग वार सके । चर क्षणोटोट पेरी को अमेरिकन सैन्यशनित का प्रयोग करने की आवस्यकता

नहीं हुई । जापानी सरकार भलीभांति अनुभव करती थीं, कि युद्ध में पारचात्य देशों का मुकावला कर सकता सम्भव नहीं है । भाप की शक्ति से चलनेवालें विशालकाय अमेरिकन जहाजों ने जापान के सैनिक नेताओं को यह सुचारु रूप से बोध करा दिया था, कि वे उन्नति की दौड़ में पारचात्य संसार के मुकावले में वहुत पीछे रह गये हैं।

अमेरिका के साथ प्रथम सन्धि—पेरी का प्रयत्न सफल हुआ और १८५४ में जापान और अमेरिका की सन्धि हो गई। इस सन्धि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं—(१) विदेशी जहाजों को यह अधिकार रहेगा, कि वे नागासाकी और दो अन्य जापानी वन्दरगाहों में कोयला भरने, रसद प्राप्त करने, ताजा पानी लेने व अपनी मशीन आदि की भरम्मत करने के उद्देय से आ जा सकें। (२) अमेरिका का एक प्रतिनिधि जापान में रह सके। (३) यदि कोई अमेरिकन जहाज जापान के समुद्रतट के सभीप टूट जाय या डूव जाय, तो उसके मल्लाहों व यात्रियों को यह अनुमित हो, कि वे जापान में आश्रय पा सकें। कमोडोर पेरी के प्रयत्न से अब जापान विदेशी राज्यों के साथ सम्पर्क से पृथक् नहीं रहा। वह पाश्चात्य देशों के लिये अब 'खुलना' प्रारम्भ हो गया।

अमेरिका के बाद अन्य पाश्चात्य देशों ने भी जापान के साथ इसी प्रकार की स्मित्यां की । १८५४ में इङ्गलैण्ड को, १८५५ में रूस को और १८५५-५७ में हालैण्ड को इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए।

अमेरिका के साथ दितीय सन्धि—१८५४ की सन्धि के अनुसार श्री टाउन शैण्ड हैरिस को जापान में अमेरिका का प्रथम प्रतिनिधि व राजदूत नियत किया गया। श्री हैरिस अत्यन्त कुशल व चाणाक्ष राजनीतिक था। उसने जापान के राजनीतिक नेताओं से मैत्री स्थापित की और उन्हें यह समझाया कि उन्नीसवीं सदी के इस उत्तराई में जापान के लिये पाक्चात्य देशों के सम्पर्क से पृथक् रह सकना असम्भव है। विविध यूरोपियन राज्य इस समय (१८४२-६०) चीन में जिस प्रकार अपने प्रभाव का प्रसार कर रहे थे, हैरिस ने उसकी ओर जापानी, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उसने जापानी नेताओं को यह भी कहा, कि इस और इङ्गल्खेण्ड चीन के समान जापान के विरुद्ध भी सैन्यशक्ति के उपयोग में संकोच नहीं करेंगे और इस स्थित में जापान का हित इसी बात में है, कि वह पाक्चात्य देशों, के साथ सम्पर्क को बढ़ावे और उन्हें व्यापार आदि की वे सब सुविधाएँ प्रदान करें, आए उन्हें चीन व पूर्वी एशिया के अन्य देशों में प्राप्त हो चुकी हैं। हैरिस के प्रयत्न से १८५८ में जापान और अमेरिका की नई सन्धि हुई, जिसकी मुख्य शर्ते निम्नलिखित थीं—(१) चार नये जापानी वन्दरगाह अमेरिका के लिये सील दिये गये। तीन

बन्दरगाह १८५४ की सिन्ध द्वारा खोल जा चुके थे। (२) इन सातों जापानी जुन्दरगाहों में अमेरिका को व्यापार करने की अनुमित दी गई। (३) अमेरिका ने इस बात का आक्वासन दिया, कि यदि जापान को पाक्चात्य देशों के कारण किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो वह उसकी सहायता करेगा। (४) जापान अपने निर्यात व आयात माल पर अमेरिका से केवल पांच प्रतिशत कर ले सके। अमेरिका की सहमित के बिना इस कर की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाय। (५) व्यापार आदि के निमित्त जो अमेरिकन लोग जापान में रहें, उन पर अमेरिकन कानून लागू हों और उनके अभियोगों का फैसला अमेरिकन अदालतों के अधीन न समझे जायें।

श्री हैरिस के प्रयत्न से १८५८ में जापान और अमेरिका के बीच जो सन्धि हुई, उसमें दो बातें जापान की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये विधातक थीं। प्रभुत्व-शिक्तसम्पन्न जापानी सरकार को अब यह अधिकार नहीं रहा था, कि अपने आयात और निर्यात माल पर अपनी इच्छानुसार कर लगा सके। इसी प्रकार 'एक्स्ट्रा टैरिटोरिएलिटी' की जिस पद्धित का प्रारम्भ चीन में हुआ था, बह जापान में भी काम हो गई थी।

१८५८ की सन्धि का विरोध-कमोडोर पेरी और श्री हैरिस द्वारा जो सन्धियां जापान के साथ की गई थीं, उनपर जापान की ओर से शोगून की सरकार ने हस्ताक्षर निये थे। पर इस समय तोकृगावा शोगुनों की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो चुकी थी । २५० साल के लगभग उन्होंने अप्रतिहत व अवाध रूप से जापान का धासन किया था । यह स्वाभाविक था, कि इतने सुदीर्घ समय तक शासन कर चुकने पर उनके कुल में निर्वलता आने लगे। इस दशा में जापान के अन्य अनेक बड़े सामन्तों ने तोकुगावा कुल का विरोध प्रारम्भ कर दिया था । अमेरिका के साथ कोगून द्वारा जो सन्धि की गई थी, उससे इन सामन्तों को एक सुवर्णीय अवसर हाथ स्मा गया । जापान में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो विदेशी राज्यों के बढ़ते हुए प्रभाव को विन्ता की दृष्टि से वेसते थे । त्रिनेपतया, १८५८ की सन्धि द्वारा क्षमेषिक्षण लागों को एक्स्पूर् टैरिटोरिएलिटी के जो अधिकार मिले थे, बहुत से लोग ्रकुकि सध्य जिलामा थे। अय संक्रिमात्रा कुछ के विरोधी सामन्ती ने जामानी रुम्राट् को इस बाग के लिये बेरित करना आरम्भ किया. कि वह १८५८ की सन्धि की लिक्कत करने से इनकार कर दें। हैरिस के सम्मूख जब एक विकट समस्या उपरिपत हुई। येदी की शोगन अस्तार से यह सन्धि भर नुका था, पर सम्राट् इस सन्धि को स्वीफल नहीं करता था । पर इसी समय ब्रिटिश जीर फेल्च रोनाओं

ने चीन में तीन्स्तन पर कब्जा कर लिया था, और चीन की सरकार को इस बात के लिये विवश किया था, कि वह उनको व्यापार, धर्मप्रचार आदि की गुविधाएँ प्रदाक्त करें। चीन में पाश्चात्य देशों की बढ़ती हुई शक्ति का उदाहरण जापान के सम्मुख था। श्री हैरिस ने इसका उपयोग किया और जापान के सम्राट् को भी १८५८ की सन्धि को स्वीकृत कर लेने के लिये प्रेरित किया।

हालैण्ड, ब्रिटेन, रूस और फांस ने भी अमेरिका का अनुकरण कर जापान की सरकार से नई सन्धियां कीं, और इन सन्धियों द्वारा प्रायः वे सब अधिकार प्राप्त किये, जो श्री हैरिस के प्रयत्न से १८५८ में अमेरिका को प्राप्त हुए थे। पर यहां यह ध्यान में रखना चाहिये, कि अभी पाश्चात्य देश जापान में वे सब अधिकार प्राप्त नहीं कर सके थे, जो उन्होंने चीन में प्राप्त कर लिये थे। उदाहरणार्थ, जापान में पाश्चात्य देशों को यह अधिकार नहीं था, कि उनके नागरिक सात बन्दरगाहों के अतिरिवत अन्यत्र आ जा सकें। उन्हें अभी यह अधिकार भी नहीं मिला था, कि वे किश्चिएनिटी का जापान में प्रचार कर सकें और वहां जमीन खरीदकर या किराये पर लेकर गिरजाघरों व अन्य इमारतों का निर्माण कर सकें।

पाश्चात्य देशों से सन्धियों के परिणाम—१८५८ और उसके बाद जापानी सरकार जिस प्रकार विविध पाश्चात्य देशों को व्यापार सम्बन्धी सुविधाएँ देखें, नट-कर को निश्चित करने में अपनी स्वतन्त्रता का परित्याग करने और एक्स्ट्रा-टैरिटारिएलिटी को स्वीकृत करने के लिये विवश हुई, उसके अनेग महत्त्वपूर्ण करिणाम हुए—

हैं, या तो प्राणी मृत्यु का ग्रास वन जाय या उसमें नई शक्ति का संवार हो। पास्चात्य देशों का सम्पर्क जापान के लिये बिजली के साथ सम्पर्क के समान था, किससे उसमें नई शर्यित और नवजीवन का संचार हुआ।

(२) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क ने तोकुगावा कुल के शोगूनों के आधिपत्य का अन्त करने में बहुत सहायता दी । शोगूनों के शासन का अन्त होकर किस प्रकार जापान में फिर से सम्राट् द्वारा शासन का प्रारम्भ हुआ, इस पर हम अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे। यहां इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि तोकुगावा कुल के शोगूनों के विश्द्ध जो भावना जापान में उत्पन्न हुई, उसमें विदेशों के साथ सम्पर्क एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

(५) सम्राट्की शक्ति का पुनरुद्धार

१८६८ में तोकुगावा शोगूनों की शक्ति का अन्त हुआ और जापानी सम्राट् ने राजशक्ति के प्रयोग को फिर से अपने हाथों में लिया। जापान के जिस सम्राट् के शासनकाल में यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, उसका नाम मृत्सुहितो था और वह १८६७ में जापान के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। सम्राट् बनने पर उसने मेइजी की उपाधि धारण की थी, और वह इसी नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। सम्राट् मेइजी द्वारा राजशक्ति के संचालन को अपने हाथों में लेना जापान के आधु- निक इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है, और उसपर अधिक विशद रूप सम्बाश डालने की आवश्यकता है।

१८५८ में तोकुगावा कुल के शोगून शासन ने अमेरिका के साथ जो सन्धि की थी, उससे जापान के बहुत से प्रभावशाली व्यक्ति अत्यन्त असन्तुष्ट थे। उनका विवार था, कि जिस प्रकार अब तक जापान अपने को पश्चात्य लोगों के सम्पर्क से पृथक रखता रहा है, उसमें परिवर्तन लाना देश के लिये हानिकारक है। इन्होंने शोगून सरकार का विरोध करना शुरू किया। तोकुगावा कुल की प्रभुता के खिलाफ अन्य सामन्त कुलों में जो विरोध भावना थी, उसने इस समय उप रूप धारण किया। तोकुगावा कुल के इन विरोधियों में सत्सुमा और चोशू कुल प्रधान ये समूराई लोग भी विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव के विरोधी ये और उनके खिलाफ शम्य उठाने को उत्सुक थे। १८५८की सन्धिक खिलाफ आन्दोलन अनेक रूपों में प्रकट हुआ। लोगों का कहना था, कि विदेशियों को जागान से निकाल बाहर करना प्रकट हुआ। लोगों का कहना था, कि विदेशियों को जागान से निकाल बाहर करना प्रकट हुआ। लोगों का कहना था, कि विदेशियों को जागान से निकाल बाहर करना प्रकट हुआ। लोगों का कहना था, कि विदेशियों को जागान से निकाल बाहर करना प्रकट हुआ। लोगों का कहना था, कि विदेशियों को जागान से कि लागून संक्रार करना राजवित्र को उत्तर को बीहिये। स्वाहिये। व्यक्ति को खीन कर स्वाह को कि स्वाह के स्वाह को स्वाह से प्रवाह के स्वाह से स्वाह से प्रवाह के स्वाह से स्वाह से स्वाह से से स्वाह से से से स्वाह से साम से दिस समय यह प्रवृत्ति शोगून शासन के विद्व आन्दोलन के अतिरिक्त जागान में इस समय यह प्रवृत्ति

भी जोर पकड़ रही थी, कि विदेशियों पर आक्रमण किये जावें। १८५९ और १८६५ के बीच में ब्रिटिश लोगों पर दो बार हमले हुए । सत्सुमा कुल का सामन्त एक दिन जुलूस के साथ येदो से बाहर जा रहा था । जापान में यह रिवाज था, कि 📑 जब इतनी ऊंची स्थिति का कोई व्यक्ति राजमार्ग से जा रहा हो, तो अन्य सब छोग भाग से हट जावें। बिटिश लोगों ने इस रिवाज की परवाह नहीं की। रिचर्डसन नामक एक अंग्रेज इस समय इसी रास्ते से अपने कुछ साथियों के साथ घोड़े पर जा रहा था। सत्सूमा के सामन्त राजा के सम्मुख उसने मार्ग नहीं छीड़ा, इस पर जापानी लोगोंने उस पर हमला किया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा ! जब इस घटना का समाचार ब्रिटिश सरकार को मिला, तो उसने रिचर्डसन की हत्या का प्रतिशोध करने के लिये सत्सुमा के प्रदेश की राजधानी कागोशिमा पर गोलाबारी की । इस घटना (१८६३) से जापांनी लोगों में पाश्चात्य देशों के प्रांत विद्वेप की भावना और भी अधिक प्रबल हो गई। विदेशियों के विरुद्ध भावना से प्रभावित होकर १८६३ में सम्राट् की ओर से आज्ञा प्रकाशित की गई, कि पाश्चात्य देशों का कोई जहाज जापान में न आ सके। शोगुन का विचार था, कि इस राजाशा को किया में परिणत कर सकना क्रियात्मक नहीं है। इसिलये चोशु के सामन्त राजा ने सम्राट् के आदेश को किया में परिणत करने का कार्य अपने हाथों में लिया । चोश् के सामन्त का प्रदेश शिमोनोसेकी के जलडमरू मध्य के समीप स्थित था। इस स्थान से पारचात्य देशों के जहाज बड़ी संख्या में आते जाते थे। चीशू के सामन्त ने आज्ञा दी, कि जो कोई विदेशी जहाज शिमोनोसेकी के जलडमरूमध्य से गुजरे, उस पर गोलावारी की जाय । सबसे पहले एक अमेरिकन जहाज पर हमला हुआ । इस पर अमेरिका ने अपने एक जंगी जहाज को शिमोनोसेकी पर गोलाबारी करने के लिये भेज दिया । ब्रिटेन, फांस, और हालैण्ड ने अमेरिका का साथ दिया और १८६४ में इन चारों राज्यों की सम्मिलित शक्ति ने जापान पर आक्रमण किया । जापान की जलसेना पाश्चात्य देशों का मुकाबला करने में असमर्थ रही। इस स्थिति में चोशू और सत्सुमा के सामन्त राजाओं ने भी अनुभव किया, कि पाश्चात्य देशों का मुकाबला कर सकना असम्भव है, और उनके साथ सन्धि करके ही रहना अधिक उत्तम है। पर पाश्चात्य देशों के प्रति जिस व्यवहार का सूत्रपात तोकृगावा के शागूनों द्वारा हुआ था, उसके प्रति जापानी लोगों में इतना अधिक विरोध था, कि कोगून सरकार का प्रभाव कम होने लगा और सम्राट् के दरबार में चोशू और 🔭 सत्सुमा के सामन्तों का प्रभाव बढ़ने लग गया । इन सामन्तों ने यह तो अनुभव कर्र लिया था, कि पारचात्य देशों का मुकावला युद्धक्षेत्र में नहीं किया जा सकता, पर इनके हृदय में उनके प्रति बिरोध भावना में कमी नहीं आई थी।

१८६७ में जापान के राजिंसहासन पर सम्राट् मेइजी के नाम से मुत्सृहितो आरूढ़ हुआ। सम्राट् पद को ग्रहण करते समय इसकी आयु केवल चौदह साल की 🕍 । पर उसकी शिक्षा ऐसे वातावरण में हुई थी, कि वह किशोरावस्था में ही जापान की राजनीतिक समस्याओं को भलीभाति समझता था। १८६७ के अन्त से पूर्व ही सत्सुमा, चोशू, तोसा और हीजन के सामन्तों ने शोगून की सेवा में एक आवेदन पत्र भेजा, जिसमें यह अनुरोध किया गया, कि नये सम्राट् को राजशक्ति का स्वयं उपयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिये और शोगन सरकार का अन्त होना चाहिये। इस रामय तोकुगावा कुल के पुराने शोगून की मृत्यु हो चकी थी और १८६६ में एक नया व्यक्ति इस गौरवपूर्ण पद पर नियुक्त हुआ था। नया शोगन जापानी जनता की भावनाओं को भलीभांति अनुभव करता था। उसने स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार तोकृगावा शोगनों का अन्त हुआ। शोगून सरकार का अन्त और सम्राट् द्वारा शासनसूत्र को संभाल लेना जापानी इतिहास की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इस घटना से जापान में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ । विदेशी राज्यों के प्रति विरोध व विद्वेप की भावना जापान में भलीभांति विद्यमानथी, पर साथही वहां के लोग यह भी अनुभव करते थे, कि इन विदेशियों से अपने देश की रक्षा करने का एकमात्र उपाय यह है, कि जापान में भी उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान, व्यवसाय व सैन्यशक्ति की उन्नति की जाय, जैसे कि पारचात्य देशों में हुई है।

सम्राट् द्वारा राजशिक्त को अपने हाथ में ले लेने से जापान में जो महान् परिवर्तन हुआ, उसके विरोधियों की भी कमी नहीं थी। यद्यपि शोगून ने अपने पद
से स्वयं त्यागपत्र दे दिया था, पर तोकुगावा कुल के अन्य अनेक व्यक्ति अपने कुल की
शिक्त के ह्वारा को सहन नहीं कर सके। उन्होंने क्योतो पर आक्रमण किया और
इस बात का प्रयत्न किया, कि सम्राट् को अपने विरोधियों के प्रभाव से मुक्त करें।
पर उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई। एक साल के लगभग तक तोकुगावा
कुल के लोग अपनी शिवत की पुनः स्थापना का उद्योग करते रहे, पर अन्त में उन्होंने
नई परिस्थित को स्वीकार कर लिया। तोकुगावा कुल का अन्तिम शोगून के इकी
था। १८६६ में ही उसने शोगून के पद को प्राप्त जिला था। वह पहल गृशिकित
व्यक्ति था। इतिहास का अराने गर्मांग्या ने गर्मां अनुनीलन किया था श्रीति अनुभव करता था। कि जागान की नेन्द्रोव अनुनीलन किया था श्रीति अनुभव करता था। कि जागान की नेन्द्रोव अनुनीलन स्वाप्त हो नामती
ही, जब कि उसका संनालन एक के प्राप्त की निज्ञाव अपने स्वाप्त अपने स्वाप्त अपने पद वा त्याग कर दिया था।

प्रोत्य गरकार या अन्य होने पर जापान की बेन्द्रीय सरकार में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुए, उन पर हुन समन्द्र अन्याय में विचार करेंगे ।

पांचवां अध्याय

जापान का कायाकल्प

(१) नया शासन

सामन्त पद्धित का अन्त —सम्राट् मेइजी ने किस प्रकार शोगून सरकार का अन्त कर जापान के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया, इसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब सम्राट् के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह था, कि देश में एक व्यवस्थित व शिक्तशाली सरकार की स्थापना की जावे और सम्पूर्ण जापान अपने आन्तरिक भेदों को भूलकर एक सुदृढ़ केन्द्रीय शासन के अधीन हो जावे। यह बात तभी सम्भव हो सकती थी, जब कि सामन्त पद्धित का पूर्ण रूप सं अन्त हो जाय और सम्राट् अपनी सब प्रजा पर समान रूप से शासन करे। इसमें सन्देह नहीं, कि तोकुगावा शोगूनों के शासनकाल में जापान के विविध सामन्त राजा शोगून के वशवर्ती थे, पर जनता पर उनका अपरिमित अधिकार था और वे अपने-अपने प्रदेशों में पर्याप्त रूप से स्वतन्त्र राजाओं के समान सत्ता रखते थे। अब सम्राट् मेडजीने यह प्रयत्न किया, कि धीरे-धीरे जापान से सामन्त पद्धित का अन्त कर दिया जाय। इसके लिये उसने निम्नलिखित उपायों का बाश्रय लिया—

- (१) १८६८ में सम्राट् मेइजी ने यह व्यवस्था की, कि प्रत्येक सामन्त की जागीर में एक राजकर्मचारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की ओर से भी की जाय। जागीरों पर से सामन्तों के शासन का अन्त नहीं किया गया, पर केन्द्रीय सरकार की ओर से एक उच्च राजकर्मचारी की नियुक्ति के कारण सामन्त राजाओं और जनता को यह अनुभव होने लगा, कि जागीरों में निवास करनेवाली प्रजा पर सम्राट् का भी प्रत्यक्ष शासन है।
- (२) १८६९ में किदो, सागो आदि विविध नेताओं ने अनेक सामन्तों को इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे अपनी अपनी जागीरों गर को उनका विकास है, उसे स्वेच्छापूर्वक सम्राद् की अर्पण कर दें। सत्युगा, चोजू, होजज, तांका आदि के अनेक सामन्तों ने इस समय अपनी जागीरों को स्वयमेव सम्राट् को छोटा दिया। सम्राट् ने बुद्धिमत्तापूर्वक इन सामन्तों को ही अपनी अपनी जागीरों में सुवेदार

के पद पर नियत कर दिया । पुराने युग के ये सामन्त अब अपनी जागीरों के राजा न रहकर उनके सूबेदार बन गये।

- (३) कुछ मास पश्चात् सम्राट् ने एक आज्ञा प्रकाशित की, जिसमें अन्य सामन्त राजाओं को भी यह आदेश दिया गया, कि वे सब भी सत्सुमा आदि के सामन्तों का अनुसरण कर अपनी अपनी जागीरों को सम्राट् के सुपूर्व कर दें। इस समय तक जापान में राष्ट्रीय भावना और देशप्रेम का विचार इतना प्रवल हो चुका था, और पाश्चात्य लोगों के सम्पर्क में आने के कारण जापानी लोग अपनी राष्ट्रीय उन्नति के लिये इतने अधिक उत्सुक हो चुके थे, कि किसी सामन्त राजा ने सम्राट् की खाजा का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया और सबने अपनी नई स्थिति को असमतापूर्वक स्वीकार कर लिया।
- (४) १८७१ में सम्राट् की आजा द्वारा सामन्त पढ़ित का बाकायदा अन्त कर दिया गया। यह व्यवस्था की गई, कि सामन्त छोगों को जन्म भर पेंशिन मिलती रहे और उनकी नौकरी में जो समूराई सैनिक थे, उन्हें भी राज्य की ओर से वृत्ति गिलती रहे। सामन्तों और समूराई लोगों को पेंशिन देने की व्यवस्था के कारण राज्यकोष पर खर्च का बोझ बहुत बढ़ गया। अतः १८७३ में यह आज्ञा जारी की गई, कि मासिक पेंशिन के स्थान पर एक रकम सामन्तों व समूराइयों को दे दी जाय।

जो सामन्त और समूराई लोग सदियों से अपने विशेषाधिकारों का जपभोग कर रहे थे, जनकी स्थिति में अकस्मात् इस प्रकार का परिवर्तन आ जाना सुगम बात नहीं थी। पर देशभिक्त की भावना से प्रेरित होकर ही बहुत से सामन्तों ने इस समय स्वेच्छापूर्वक अपने विशेषाधिकारों का परित्याग किया। केन्द्रीय सरकार ने भी उन्हें इतनी रक्तम मुआवजे के तौर पर प्रदान कर दी, जिससे वे जागिर को संभालने की झंझट से मुक्त होकर अपना निर्वाह भलीभांति कर सकते थे। समूराई लोगों को भी नई स्थिति में विशेष संकट का सामना नहीं करना पड़ा। हम पहले लिख चुके हैं, कि इस समय जापान में समूराई लोगों में शिक्षा का विशेष रूप से प्रचार था। सम्पूर्ण जापान के एक केन्द्रीय शासन के अधीन हो जाने के कारण उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार उच्च राजकीय पद प्राप्त करने का अवसर मिला। पर यह नहीं समझना चाहियें, कि सामरा पड़ा पर पर इसने सन्देह नहीं, कि जन्त में केन्द्रीय सरकार परिस्थित की पंजाल नकने में गमर्य हुई।

नई सेना—सामन यहित का अन्त करते ही जामान की सरकार में नई सेना का संगठन कया। अब तक जामान की सेना का निर्माण समृताई लोगों हारा होता या, और में समूराई विकिम सामन्त्रों की सेवा में रहकर सैनिक सेवा करते थे। सर्वसाधारण जनता को यह अवसर नहीं था, कि सेना में भरती हो सके। पर अव सब लोगों को यह अवसर दिया गया, कि वे सेना में भरती हो सकें और अपनी योग्यता के अनुसार सैनिक क्षेत्र में उन्नति कर सकें। १८७२ में जापान में बाधित मैं सैनिक सेवा की पद्धति को प्रारम्भ किया गया। सब लोगों के लिये यह आवश्यक कर दिया गया, कि वे सैनिक शिक्षा प्राप्त करें और निश्चित समग तक सैनिक जीवन व्यतीत करें। नि:सन्देह जापान के जीवन में यह भारी क्रान्ति थी। अब तक सेना का संचालन सामन्त राजाओं द्वारा होता था, अब जनता में प्रत्येक प्रकार की स्थिति के लोगों को यह अवसर मिला, कि वे सेना में उच्च पदों को प्राप्त कर सकें।

नये शासन के सिद्धान्त—सम्राट् मेइजी ने शोगून सरकार का अन्त करके शासनसूत्र को अपने हाथ में लेते हुए १८६८ में एक घोषणा प्रकाशित की थी, जिसमें शासन के नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था। सम्राट् ने अपनी प्रजा को यह बतलाया था, कि अब जापान में एक विचारसभा की स्थापना की जायगी और राज्य सम्बन्धी नीति का निर्धारण उसकी सम्मति व परामशं के अनुसार ही हुआ करेगा। विचारसभा में लोकमत पर भी घ्यान दिया जायगा। न्याय करते हुए सब मनुष्यों के साथ एक सद्श बर्ताव होगा और राज्य के शासन में जिम किसी देश से भी कोई बुद्धिमत्ता की बात ली जा सकेगी, उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं किया जायगा। निःसन्देह, सम्राट् मेईजी द्वारा प्रारम्भ किये गयें नये शासन के ये आधारभूत सिद्धान्त थे, और उसने उन्हें बड़ी योग्यता के साथ फिया में परिणत किया।

वासन सुधार के लिये आम्बोलन इस समय जापान में अनेक ऐसे विचारशील नेता उत्पन्न हुए, जिन्होंने देश के शासन में सुधार के लिये आन्दोलन ना प्रारम्भ किया। इनमें इतागाकी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १८७४ में उसने एक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजनीतिशास्त्र का अध्ययन करना था। कुछ समय बाद १८७४ में ही इतागाकी और उसके सहकारियों न सम्राट् की सेवा में एक आवेदन पत्र भेजा, जिसमें यह प्रार्थना की गई, कि १८६८ की उद्घोषणा के अनुसार जापान में एक विचारसभा की स्थापना की जाय और यह विचारसभा लोकमत का प्रतिनिधित्त्व करनेवाली हो। पर सरकार के अन्य महत्त्वपूर्ण लोग शासन सुधार के मार्ग पर इतना अधिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। फिर भी इस समय जापान के शासन में कितपय सुधार किये गये और इनके अनुसार जापान में पहली बार एक सीनेट और एक प्रधान केन्द्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस समय तक अनेव जापानी नागरिक यूरोप की यात्रा कर चुके थे और वहां की राजनीतिय संस्थाओं से बहुत प्रभावित थे। किस प्रकार विविध जापानी लोग

यूरोप में जाने शुरू हुए, इस पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे। विदेश में शिक्षा प्राप्त कर या अमण करके लौटे हुए ये जापानी निगरिक शारान-सुधार के लिये प्रवल आन्दोलन में तत्पर थे। इनके आन्दोलन का यह परिणाम हुआ, कि १८७८ में जापान में स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात किया गया। जापान के विविध प्रान्तीय सूवेदार अपने शासन-कार्य में इन स्थानीय सभाओं में परामर्श लें, यह भी व्यवस्था की गई। पर शासनसुधार के लिये जो आन्दोलन इस समय जापान में जारी था, वह इन सुधारों से संतुष्ट नहीं हुआ। १८७४ में इतागाकी द्वारा राजनीतिक प्रक्तों का अध्ययन करने के लिये जिस संस्था की स्थापना की गई थी, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अब इसी प्रकार की अन्य भी अनेक संस्थाएँ स्थापित हुईं। धीरे धीरे ये सब संस्थाएँ एक संगठन में संगठित हो गई, और एक राजनीतिक दल का निर्माण हुआ, जिसका प्रधान नेता इतागाकी था। इतागाकी के इस राजनीतिक दल को हम लिबरल या उदार दल कह सकते हैं। यह दल जापान में पालियामेन्ट की स्थापना करने के पक्ष में था और पाक्चात्य देशों के अनुसरण में लोकासत्तावाद का विकास करने का पक्षपाती था।

१८८१ में काउण्ट ओकुमा ने एक नये दल का संगठन किया। पहले वह जापाल के अर्थमन्त्री के पद पर अधिष्ठित था, पर सरकार के अन्य सदस्यों से मतभेद होने के कारण उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। वह भी जापान में वैध राजसत्ता स्थापित करने के पक्ष में था। पर उसके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह इतागाकी के दल में शामिल होकर कार्य करे। उसने अपने दल का पृथक् रूप से संगठन किया। यह दल प्रगतिशील (प्रोग्नेसिव) दल के नाम से प्रसिद्ध है।

इस दशा में सम्राट् ने अनुभव किया, कि देश में शासन सुधार करना आवश्यक है। १८८१ में उसकी ओर से एक घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें यह वायदा किया गया, कि १८९० तक जापान में पालियामेन्ट की स्थापना कर दी जायगी। साथ ही जनता से यह भी अनुरोध किया गया, कि अब वह राजनीतिक आन्दोलन को बन्द कर दे। एक कानून द्वारा समाचार पत्रों में सरकार की आलोचना करने और सुधार के लिये आन्दोलन करने को बन्द किया गया और १८८३ में सम्राट् की ओर से यह आजा प्रकाशित हुई, कि विविध राजनीतिक दलों को भंग कर दिया जाय। १८८४ में इतागाकी का उदार दल भग हो गया और लगान दनी समय में जिल्हा को प्रोत्ता की प्रोत्तेशिय पार्टी की सामित हो गई।

मध्ये शासन विधान का सिर्माण—शासन मृथार सम्पन्नी राजाजा को जिया में परिणय भारते के विश्वे १८८२ में श्री इसी की इन उद्देव से यूरीण गेणा गया, कि वे वहां के विभिन्न देशों की शासन पद्धति या अनुशीलन करें और सरकार की परा-

मर्श दें कि किस प्रकार के शासन सुघार जापान के लिये सबसे अधिक उपयुक्त हैं। श्री इतो जापान के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे और शोगून की सरकार का अन्त कर सम्राट् की सत्ता को पूनः स्थापित करने में उनका प्रमुख हाथ था । जापान के नय शासन के सम्बन्ध में उनके विचार निम्नलिखित थे--(१) नये शासन विधान का ं निर्माण जनता द्वारा नहीं होना चाहिये। वह सम्राट्या उसकी सरकार की कृति होनी चाहिये और उसमें सम्राट् की स्थिति को सर्वथा मुरक्षित रखना चाहिये। (२) सामन्त पद्धति का अन्त करने में जिन जापानी नेताओं का प्रधान कर्ष त्य था, ं उनकी स्थिति व शक्ति भी अक्षुण्ण रखनी चाहिये। (३) जनता में प्रतिनिधि-सत्तात्मक जासन स्थापित करने की जो मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है, नये शासन विधान में उसे भी स्थान मिलना चाहिये। यह स्पष्ट है, वि फांस व अमेरिका के रिपब्लिकन शासन श्री इतो के लिये कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते थे, जापान के शासन विधान का निर्माण करते हुएं उन्हें आदर्श नहीं वनाया जा सकता था। इङ्गलैण्ड का शासनविधान भी उनके लिये विशेष उपयोगी नहीं था, क्योंकि उसमें भी राजा की स्थिति 'ध्वजमात्र' (नाममात्र) थी। युरोप के विविध देशों में ं इतो ने प्रशिया के शासन को इस ढंग का पाया, जिसका जापान में सुगमता से अनु-सरण किया जा सकता था। प्रशिया में होहन्ट्सीलर्न राजवंश का शासन था, ं मन्त्रिमण्डल राजा के प्रति उत्तरदायी था और पालियामेन्ट में कुलीन जागीरदारों और धनिक वर्ग का प्रभुत्त्व था। इतो की सम्मति में इस प्रकार का गासन ही ं जापान के लिये सबसे अधिक उपयुक्त हो सकता था ।

१८८३ में इतो यूरोप की यात्रा समाप्त करके जापान वापस लौट आया। उसी समय सरकार ने एक नया विभाग स्थापित कर दिया, जिसे देश के लिये शासन-विधान तैयार करने का कार्य सुपुर्द किया गया। इस विभाग का अध्यक्ष श्री इतो को नियत किया गया। १८८९ में सम्राट् की ओर से नये शासन विधान की घोपणा कर दी गई, यद्यपि उसके कुछ अंश पहले ही किया में परिणत कर दिये गये थे। उदाहरणार्थ, १८८५ में जापान में बाकायदा मन्त्रिमण्डल का संगठन हो गया था और उससे एक साल पहले १८८४ में प्रिवाय के नमूने पर जापान में भी एक नई कुलीन श्रीण का निर्माण किया गया था, जिसमें पांच प्रकार के लार्ड रखे गये थे। ये लार्ड प्रिस, मान्विस, काउन्ट, विस्काउन्ट और वैरन कहाते थे। ये पांचों प्रकार के लार्ड सम्राट की कृति थे और उसी द्वारा कोई व्यक्ति इन पदों को प्राप्त करता थे। अंश उसी हारा कोई व्यक्ति इन पदों को प्राप्त करता थे। अंश कुछ क्राक्तियों को लार्ड के ये विविध पद वंशक्रमानुगत रूप से दिये जाते थे, और कुछ को केवल वैयन्तिक रूप से।

१८८९ का शासन विधान-सम्राट् द्वारा १८८९ में जिस नये शासन

विक्षान की घोषणा की गई, उसकी क्यरेखा पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है।

श्रामन का अधिपति व मुखिया सम्राट् को बनाया गया। उसकी स्थित 'पिवन व अनुल्लंघनीय' रखी गई। विविध राजपदाधिकारियों को नियुक्त करना, उन्हें अपने पद से बर्खास्त करना व उनके वेतन को निश्चित करना उसी के हाथों में रखा गया। युद्ध की घोषणा नरने व सन्धि विग्रह के सब अधिकार भी उसी को दिये गयं। विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश (आर्डिनेन्स) जारी करने का अधिकार भी सम्राट् को प्रदान किया गया। सम्राट् को शासनकार्य में सहायता करने के लिये एक मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था की गई। मन्त्रियों को सम्राट् ही नियुक्त करता था और वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पालियामेन्ट के प्रति उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाया गया था और वे तब तक अपने पद पर रह सकते थे, जब तक सम्राट् वा विश्वास उन्हें प्राप्त हो।

१८८९ के शासन विधान द्वारा जापान में एक पार्कियामेन्ट की भी स्थापना की गई। इसमें दो सभाएं होती थीं, लार्डी की सभा और लोकसभा। लार्डी की सभा में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते थे-(१) राजघराने के पुरुष, (२) प्रिस और मानिवस वर्ग के लार्ड लोग, (३) काउन्ट, विस्काउन्ट और बैरन वर्ग कें लार्डों के प्रतिनिधि, (४) सम्राट् द्वारा मनोनीत सदस्य और (५) सबसे अधिक राजकीय कर देनेवाले लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि । पहले तीन प्रकार के सदस्य जीवन भर के लिये लाहों की सभा में रहते थे और पिछले वो प्रकार के मदस्यों की सदस्यता का काल सात साल होता था। इस प्रकार लाडों की सभा के सब सबस्य उच्च व कुलीन वर्ग के होते थे। लोकसभा के सब सबस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, पर १८८९ में वोट का अधिकार बहुत कम छोगों को दिया गया था । वोटर होने के लिये सम्पत्ति की शर्त रखी गई थी । ज्यों ज्यों समम बीतता गया, जापान में बोट का अधिकार भी अधिक अधिक विस्तृत होता गया । यह आवश्यक था, कि साल में एक बार पालियामेन्ट का अधिवेशन बुलाया जाय । कोई नया टंक्स लगाया जा सकता था । यह भी आवश्यक था, कि राजकीय वजट िक्षी स्थीकृति पालियामेन्ट से ली जाय । पर यदि कभी पालियामेन्ट नये वजट को स्थीकार गरने से इनकार कर है, तो पिछले साल के नजर के अनुसार आय व व्यय निरिचन किया जाला था । सम्राट की यह जिबकार था कि दह पार्किटामेन्ट में र रिक्षत हुए किसी भी फानून को वीठों कर गई। गालियानंग्ट के सदस्य मन्त्रियों से प्रकृत पुरु सबते थे और उनके विकट प्रस्ताव भी न्वीकार कर सकते थे। एर मन्तियो

को वर्खास्त करने का अधिकार केवल सम्राट् को था। पार्लियामेन्ट के सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी और अपने भाषण के लिये उन्हें गिरपतार नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि १८८९ के शासन विधान में पार्लियामेन्ट को पर्याप्त अधिकार दिये गये थे और समय के साथ साथ वह अपनी शिक्त को भी बढ़ा सकती थी।

१८८९ के शासन विधान में नागरिकों के अधिकारों का भी विशद रूप से प्रतिपादन किया गया था । कानून के सम्मुख सब जापानी एक समान स्थित रखते थे। राजकीय पद व नौकरी प्राप्त करने का सबको अधिकार दिया गया था। भाषण, लेखन व अन्य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करने, सभाएं करने, संगठन बनाने और अपने विश्वास व विचार के अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करने की सबको स्वतन्त्रता दी गई थी। राजकर्मचारियों को यह अधिकार नहीं था, कि वे किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक गिरफ्तार कर सकें। यह व्यवस्था की गई थी, कि अभियुक्तों पर न्यायालयों में बाकायदा मुकदमा चलाया जाय और न्यायालय से दण्ड पाये विना किसी व्यक्ति को जेल में न रखा जा सके। सम्पत्ति के अधिकार को अनुल्लंघनीय घोषित किया गया था और सब नागरिकों को यह अवसर दिया गया था, कि वे सरकार के पास अपनी शिकायतों व आवेदन पत्रों को भेज सके ग जापान के शासन विधान के ये 'नागरिकों के अधिकार' ठीक उसी प्रकार के थे, जैसे कि इस समय पाश्चात्य देशों के लोकतन्त्र शासन विधानों में प्रतिपादित थे।

१८८९ के शासन विधान द्वारा जापान सरकार व शासन की दृष्टि से इस युग के पारचात्य देशों के समकक्ष हो गया था। इसमें सन्देह नहीं, कि फांस, अमेरिका और क्रिटेन लोकतन्त्रवाद के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके थे। पर इसी समय जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, स्पेन आदि अनेक राज्यों के शासन लोकतन्त्रवाद की दृष्टि से जापान से अधिक उन्नत नहीं थे। रूस, टकीं आदि की सरकारें तो जापानी सरकार की अपेक्षा निश्चित रूप से अधिक निरंकुश व स्वेच्छाचारी थीं। यूरोप के विविध देशों में सामन्त पद्धित और एकतन्त्र शासन का अन्त होकर लोकतन्त्र शासन की स्थापना में एक सदी से भी अधिक समय लगा था। पर जापान इस युग में इतनी शीझता से उन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ा रहा था, कि उसने चौथाई सदी से भी कम समय में सामन्त पद्धित और निरंकुश शासन का अन्त कर ऐसे शासन थियान की स्थापना कर ली थी, जो उन्नीसवीं सदी की प्रवृत्तियों के सर्वथा अनुकुल था।

(२) पारचात्य देशों से की गई सन्धियों में संशोधन १८५८ में अमेरिका से और उसके बाद ब्रिटेन, हालैण्ड आदि पारचात्य देशों के

साथ जो सन्धियां जापान ने की थीं, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। ्ये सन्धियां जापान की स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतिकूल थीं। आयात और निर्यात मारू पर जापानी सरकार अपनी इच्छानुसार टैक्स नहीं लगा सकती थी । जापान में निवास करनेवाले पाश्चात्य व्यापारी व अन्य लोग जापानी कानन व जापानी अदालतों के अधीन नहीं थे। साथ ही जापान की मद्रापद्धति पर भी इन पारचात्य देशों का नियन्त्रण था । इस समय जापान में सोना और चांदी दोनों के सिक्के प्रचलित थे। सिन्ध्यों द्वारा पाश्चात्य देशों ने इन सोना चांदी के सिक्कों में एक और चार के अनुपात को स्वीकार किया था। एक तोला वजन के सोने के सिक्के के बदले में चार तोले वजन के चांदी के सिक्के प्राप्त किये जाते थें। दूसरे शब्दों में इसी बात को इस ढंग से कह सकते हैं, कि यदि सोने का मृल्य १०० येन (जापान का सिक्का) प्रति तोला हो, तो चांदी का मृल्य २५ येन प्रति तोला था । इसी समय यूरोप में सोना और चांदी के मूल्य में एक और सोलह का अनुपात था । पाक्चात्य व्यापारी अपने देशों से चांदी के सिक्के भारी परिमाण में लाते थे, पहले उनका विनिमय जापान के चांदी के सिक्कों से करते थे और फिर जापानी चांदी के सिक्कों के बदले में चार और एक के अनुपात से जापान के सोने के - सिक्कों को प्राप्त कर लेते थे। इस विनिमय में उन्हें ४०० फी सदी का मुनाफा हो जाता था । रान्धि की शतों में इस विनिमय दर का उल्लेख था, अतः जापानी सरकार पाइचात्य व्यापारियों के इस अनुचित व्यापार को रोक नहीं सकती थी। इस दशा का परिणाम यह था, कि सोना बहुत बड़ी मात्रा में जापान से यूरोप और अमेरिका पहुंच रहा था और जापान प्रायः सोने से बिलकुल खाली होने लग गया था।

स्वाभाविक रूप से जापानी सरकार इस वात के लिये उत्सुक थी, कि इन सिन्धयों में संगोधन किया जाय। इसीलिये जब १८६८ में शोगून गासन का अन्त होकर सम्राट् की शक्ति की पुनः स्थापना हुई, तो इन सिन्धयों के संशोधन के प्रश्न पर भी ध्यान दिया गया। १८७१ में श्री इवाकुरा के नेतृत्त्व में एक मिशन इस उद्देश्य से यूरोप और अमेरिका भेजा गया, कि वह वहां की सरकारों से बातचीत कर इन सिन्धयों में परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। श्री इवाकुरा ने विविध देशों की यात्रा कर उनकी रारकारों के साथ भग्यतं आगित किया, पर उसे अपने श्रीवर्तन में सफलता नहीं है। सकी। जायान वापन की कर में इवाकुरा ने अपनी सरकार को सुचना दी, कि सिन्धगा में संशोधन तभी सम्भव होता. जब कि पहले जापान में न्याय व्यवस्था को सुचाइ रूप से संगठित कर लिया जाया। जापानी सरकार के लिये यह आवश्यक है। कि पहले अपने कानूनों को, दण्ड विधान को और न्यायविभाग को इस प्रकार से संशोधित कर लिया जाय, जिससे कि वह आधुनिक

युग के विचारों के अनुकूल बन जाय। इसी प्रकार आयात और निर्यात माल पर अपनी इच्छानुसार टैक्स लगा सकने का अधिकार जापानी सरकार को तब प्राप्त हो सकेगा, जब कि विदेशी व्यापारियों को जापान में व्यापार कर सकने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी। उन्नीसवीं मदी के उनराई में संसार बहुत उन्नित कर गया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वत्र विकास हो रहा है, और पारचात्य देशों में विदेशी व्यापार को हानिकारक न मानकर देश के लिये हितकर समझा जाता है। श्री इवाकुरा की रिपोर्ट पर जापानी सरकार ने भलीभांति विचार किया और कानृन व न्यायपद्धित में उन सुधारों को प्रारम्भ किया, जिनके कारण इस क्षेत्र में भी जापान पारचात्य देशों का समकक्ष हो गया।

जापानी सरकार ने अपने देश के दीवानी और फौजदारी कानूनों का नये सिरे से निर्माण किया। इस कार्य में फौस और प्रशिया के विशेषकों का सहयोग प्राप्त किया गया। ज्याय विभाग का भी नये सिरे से संगठन किया गया। छोटी व बड़ी अदालतों का निर्माण करते हुए फौस की न्यायपद्धित को सम्मुख रखा गया। १८८९ तक कानून और न्यायालय सम्बन्धी यह नई व्यवस्था पूर्ण रूप से बनकर नैयार हो गई थी और १८९० में सम्राट् ने इस पर अपनी अन्तिम स्वीकृति भी दे दी थी। १८९४ तक ये नये कानून अविकल रूप से सम्पूर्ण जापान में प्रयुक्त होने लग गये श्रे और अब पाश्चात्य देशों को यह कहने का कोई अवसर नहीं रहा था, कि एक्स्ट्रा- टैरिटोरिएलिटी की पद्धित की इस कारण आवश्चकता है, क्योंकि जापान के कानून व न्यायालय आधुनिक युग के अनुकूल नहीं हैं।

क्रिया में परिणत नहीं हो सका । १८८८ में काउण्ट ओकामा ने इस सम्बन्ध में ्मिचयों में संशोधन के लिये बातचीत करने के उद्देश्य से पाञ्चात्य देशों की आया की। अमेरिका को वह एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति को नष्ट कर देने के लिये तैयार करने में सफल हुआ । पर अमेरिका ने यह शर्त लगाई, कि इस बात को तभी किया में परिणत किया जाय, जब अन्य देश भी इसी प्रकार के संशोधन की स्वीकृत करने के लिये तैयार हो जावें। १८९४ तक जापान में तये दीवानी व फीजदारी कानन अधिकल रूप से प्रयोग में आने लगे थे, अदालतों का संगठन भी नये ढंग से हो गया था । इस दशा में १८९४ में इङ्गलैण्ड ने इस बात को स्वीकार कर लिया, कि १८९९ से इङ्गलिश नागरिकों के मुकदमे जापानी अदालतों में पेश होने लगें। उसका विचार था, कि पांच साल में यह बात भलीभांति स्पव्ट हो जावगी, कि जापानी अदालतें भी पादनात्य देशों की अदालतों के समान न्याय सम्बन्धी नये आदर्शों के अनसार न्याय कार्य का सम्पादन करती हैं या नहीं। १८९४-९७ के तीन सालों में अन्य पारुचात्य देशों ने भी इङ्गिलिश सन्धि के ढंग पर जापान के साथ हुई अपनी सन्धियों में संशोधन किये और इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के अन्त से पूर्व ही एक्सटा-टैरिटोरिएलिटी की पढ़ति का जापान से अन्त हुआ । इसी समय १८५८ व उसके र बाद की विदेशी सन्धियों में जो अन्य अनेक दोष थे, उन सबको भी दूर किया गया। पाच्चात्य ज्ञान विज्ञान को अपना लेने के कारण जापान इस रामय जिस तेजी के साथ राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति कर रहा था, उसके कारण वह पारचात्य देशों का पूर्णतमा सगकक्ष वन गया था, और अब यह सम्भव नहीं रहा था फि उराके साथ वह व्यवहार किया जा सके, जो कि चीन आदि अन्य एशियाई देशों के साथ किया जाता था।

(३) सामाजिक व आर्थिक उन्नति

शिक्षा का विस्तार—जीयून सरकार के शासनकाल में ही अनेक जापानी विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के दिये पाल्चात्य देशों में जाना प्रारम्भ कर दिया था। उस समय जापानी लोगों के लिये विदेश गाना गिपाया थी। फिर भी कानून का उन्लंधन कर अनेक जापानी यूनक अपनी जान गिपाया को शान्त करने के लिये दिशों में जान दान हो गये थे। दोगून सरकार के पत्त और सजाद अरत का राज-विद्यार्थ में जान दान हो गये थे। दोगून सरकार के पत्त और सजाद अरत पाल-विद्यार्थ के अर्थ हो गये हैं हो तो नह उद्देश था, कि पाज्यात्य देशों ने जान विद्यान के लिये में जाने शुद्ध हो यो गुन्ह भी उन्नि गिहाशी एक पत्ती के काल में की है, उस सबको सीक्षार अपने देश में उस जा गारणन करें। अमेरिका और युरोग के उच्च शिक्ष-

णालयों में हजारों जापानी विद्यार्थी प्रविष्ट हुए और उन्होंने अपने देश में लीटकर शिक्षा के क्षेत्र में कान्ति का प्रारम्भ किया। अब तक जापान में प्रधानतया प्राचीन साहित्य और धर्मग्रन्थों की शिक्षा दी जाती थी। अब उनके साथ साथ नये ज्ञान विज्ञान का भी प्रवेश हुआ। जापानी स्कूलों में पाश्चात्य भाषाओं, विशेषतया इज्जिलिश की भी पढ़ाई शुरू की गई और कुछ ही समय में जापान के शिक्षणालय पढ़ाई के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों के स्कूलों, कालिजों व यूनिवर्सिटियों के समकक्ष हो गये।

१८७२ में जापान में बाधित शिक्षा की पद्धित को जारी किया गया। इसके लिये प्रत्येक नगर व विविध ग्रामों में प्रारम्भिक शिक्षणालयों की स्थापना की गई। प्रत्येक वालक व बालिका के लिये यह आवश्यक कर दिया गया कि वह कम से कम चार साल तक स्कूल में वाकायदा शिक्षा ग्रहण करे। बाद में इस काल को बढ़ाकर चार साल के स्थान पर छः साल कर दिया गया। जापान के स्कूलों में केवल पढ़ाई ही नहीं होती थी, अपितु चरित्र निर्माण पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। देश के प्रति प्रेम और सम्राट् के प्रति भिक्त की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को दी जाती थी। उन्हें सिखाया जाता था, कि प्रत्येक जापानी का जीवन देश और सम्राट् के लिये हैं। लड़कियों की शिक्षा में गृहकार्य को प्रमुख स्थान दिया जाता था। जापानी लोग समझते थे, कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर है, अतः उन्हें गृहकार्य में विशेष रूप से निपुणता प्राप्त करनी चाहिये। इसीलिये उन्होंने १९०२ तक लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं की थी। बाद में स्त्रियों के लिये पृथक् कालिकों की स्थापना की गई और उन्हें यूनिविसिटियों में शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर दिया गया।

प्रारम्भिक शिक्षणालयों के लिये जापानियों ने अमेरिका की शिक्षापद्धित को आदर्शस्य से स्वीकृत किया । उच्च शिक्षा के लिये उन्होंने फांस की यूनिवर्शिटियों का अनुकरण किया और शिल्प विषयक शिक्षा के लिये जर्मनी को अपना आदर्श बनाया। इसका परिणाम यह हुआ, कि शीझ ही जापान में सब प्रकार के शिक्ष-णालयों की स्थापना हुई, और जापानी विद्यार्थियों के लिये अपने ही देश में सब प्रकार की शिक्षा को प्राप्त कर सकना सुरुभ हो गया।

आर्थिक उन्नति—जापान की नई सरकार देश की आर्थिक उन्नति के लिये विशेषक्ष से प्रयत्नशील थी। जब एक बार जापानी लोगों ने अनुभव कर लिया हैं कि वे व्यावसायिक क्षेत्र में पाइचात्य देशों के मुकाबले में बहुत पीछे रह गये हैं, ती उन्होंने बड़ी तेजी से यूरोग और अमेरिका के नैज़ानिक आयित्या में और मक्षीन री को अपनाना शुरू कर दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने बहुत से गये कारखान रेगांगा

किये, इनके लिये मशीनरी पाश्चात्य देशों से मंगवाई गई। सरकार ने स्वयं अपने खर्च से विदेशों से मशीनरी मंगवानी शुरू की और नये कारखानों की स्थापना कर उन्हें धनपतियों को बेचना प्रारम्भ किया। सरकार का यत्न यह था, कि लोग कारखाने खोलने के लिये उत्साहित हों। इसीलिये वह स्वयं कारखानों की इमारतों को बनवाती थी, स्वयं मशीनरी मंगाती थी और कारखानों को चालू हालत में लाकर उन्हें प्जीपतियों को बेच देती थी। जापान के अनेक सम्पन्न परिवार जहां सरकार से इन कारखानों का कय करने के लिये उत्साहित हुए, वहां साथ ही बहुत से लोगों ने स्वयं भी आधुनिक ढंग के कारखानों की स्थापना प्रारम्भ की। परिणाम यह हुआ, कि कुछ ही समय में जापान में व्यावसायिक कान्ति हो गई और वहां के विशालकाय कारलानों में कपड़ा, रेशम, लोहे का सामान आदि प्रवृरं मात्रा में तैयार होने लगा। जापानी सरकार की यह नीति थी, कि ऐसे व्यवसायों के विकास पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाय, जो सैनिक शक्ति के लिये सहायक हों। इसीलिये जापान में बहुत सी खानें खोदी गईं, लीह व्यवसाय को विशेष रूप से उन्नत किया गया, और बारूद व विविध प्रकार के अस्व शस्त्रों को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया । १८९० तक जापान में यह दशा हो गई थी, कि २५० से अधिक ऐसे कारखाने वहां कायम हो गये थे, जिनमें भापकी शक्तिसे सब कार्य होता था। १८९० के बाद तो जापान ने व्यावसायिक क्षेत्र में और भी अधिक उन्नति की और बीसबीं सदी के प्रारम्भ तक वह आर्थिक उत्पत्ति में ब्रिटेन जैसे उसत देशों का सफलता के साथ मकाबला करने लगा।

१८७२ में जापान में पहली रेलवे का निर्माण हुआ। यह पहली जापानी रेलवे लाइन तोक्यों से योकोहामा तक बनाई गई थी। १८९४ तक २११८ मील लम्बी रेलवे लाइन ने जापान के विविध प्रदेशों में रेल का एक जाल सा विद्या दिया था। ये रेलवे लाइने जहां देश के आन्तरिक व्यापार व व्यावसायिक उन्नति के लिये अत्यन्त सहायक थीं, वहां साथ ही राष्ट्रीयता के विकास में भी इनसे बहुत सहायता मिल रही थी। अब जापान के विविध प्रदेशों व द्वीपों में निवास करनेवाले लोगों के लिये यह बहुत सुगम हो गया था, कि वे अपने देश में सर्वत्र यात्रा कर सम्बें और एक दूसरे के साथ परिचय प्राप्त कर सर्वे। जापान एक राष्ट्र है, और उसके सब नियासी एक हैं, उस भावना को निक्तित करने में जानाममन के साधमों की उन्नति में इस अधिक सहायक सिंह हुई। जापानी सरकार ने इसी समय टाकवाने के विभाग को भी विद्योग रूप ने उन्नत किया। १८६८ में वहा हैलीवाक का पहले पहले एवेल एवेल हो। कुछ हो समय ने जापान में सर्वत्र पीटड आफिरों की स्थापना हो। गई। रेलवे और पोस्ट आफिरों के प्रिम्ता है। साथ साथ जागानी सरकार ने

जहाजों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया । उन्नीसवीं सदी के मध्य तक जापान को किसी ऐसे जहाज का परिचय भी नहीं था, जो भाप की शक्ति से चलता हो । उसके अपने जहाज छोटे छोटे होने थे और वं तट के साथ साथ समृद्ध में आया जाया करते थे । पर अब जापान ने भाप से चलनेवाले विशाल जहाजों को अधिगत करता शुरू किया । शुरू में इन जहाजों को पाञ्चात्य देशों से खरीदा गया, पर बाद में जापान में ही ऐसे यार्डों की स्थापना की गई, जहां सब प्रकार के जहाज बड़ी संख्या में बनने शुरू हुए । उन्नीसवीं सदी के अन्त तक यह दशा आ गई थी; कि सामृद्धिक क्षेत्र में जापान संसार के अच्छे उन्नत देशों में गिना जाने लगा था । उसके जंगी जहाज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आतंक की चीज समझे जाने लगे थे ।

व्यावसायिक उन्नति के कारण जापान में पूजीपति वर्ग का भी विकास हुआ। मित्मुई, मित्मुबिजी, सुमितोमो, यासुदा आदि अनेक परिवार व्यवसाय, महाजनी और व्यापार द्वारा अत्यन्त अधिक समृद्ध हो गये और इनका प्रभाव जापान की राजनीति में भी बहुत अधिक बढ़ गया। १८६८ में जापान में सामन्तपद्धति का अन्त किया गया था। उन्नीसनी सदी के अन्त तक वहां एक ऐसा समृद्ध व घनी वर्ग विक-सित हो गया था, जिसकी आर्थिक उन्नति का कारण व्यवसाय व व्यापार थे। पुराने सामन्तों का स्थान अब इस पूंजीपति वर्ग ने ले लिया था।

१८७३ में जापान में पहले नेशनल बैंक की स्थापना हुई। १८७९ तक केवल छ: साल के काल में जापान में इस प्रकार के बैंकों की संख्या १५१ हो गई, और थे बैंक करोड़ों का लेन देन करने लगे। १८८५ में जापान में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की गई, जो 'जापान का बैंक' कहाता है। बैंक के कारोबार का सुचार रूप से संचालन करने के लिये पालियामेन्ट ने अनेक कानन भी स्वीकृत किये।

व्यावसायिक उन्नति, बैंकिंग का विकास और रेलेंवे आदि के निर्माण से जापान की आधिक दशा आमूल चूल रूप से परिवर्तित हो गई थी। अब उसे पाश्चात्य देशों के व्यापारियों से कोई भय नहीं रहा था। आधिक क्षेत्र में वह उनका खुले तौर पर मुकाबला कर सकता था। अब जापान स्वयं इस चिन्ता में था, कि अपने माल को और देशों में बेचे और इस विदेशी व्यापार से अपने को समृद्ध करे। पाश्चात्य देशों ने विविध सन्धियों द्वारा जापान में व्यापार सम्बन्धी जो विशेष अधिकार प्राप्त किये थे, वे सब अब निर्यंक होते जाते थे और यही कारण है, कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में इन सन्धियों को संशोधित व परिवर्तित कराने में जापान को कोई विशेष असुविधा नहीं हुई।

१८६८ के बाद सम्राट् की गरकार ने किसानों की रूपा को भी उन्नत गरने के लिये ध्यान दिया । सागराण्डात का अन्त हो आने के कारण अब किसानों की

स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छी हो गई थी । किसानों का यह अधिकार ्रिटिया गया, कि वे जिस भूमि को जोनते वोते हैं, उसपर अपना स्वामित्त्व स्थापित कर सकों और खेल पर अपने स्वत्व का विकय भी कर सकों। १८७२ में किसानों का अपने खेतों पर स्वन्व स्थापित कर दिया गया । पूराने समय में सामन्त लोग अपनी जागीरों की भिम को जीतनेवाले किसानों से उपज का एक निश्चित भाग लगान के रूप में लिया करते थे। पर अब सरकार ने उपज का भाग लेने के स्थान पर सिक्के के रूप में मालगुजारी लेनी प्रारम्भ की । किस खेत में कितनी फसल होती है, इसका हिसाब करके उसकी मालगुजारी की मात्रा नियत की गई। इस व्यवस्था से किसानों को जहां अनेक लाभ हुए, वहां एक नुकसान भी हुआ। अब किसान इस बात के लिये विवश हुए, कि वे मालगुजारी की रकम को अदा करने के लिये अपनी फसल को गण्डी में जाकर वेचें। फसल तैयार होने पर सब किसानों की यह कोशिश होती थी, कि वे जल्दी से जल्दी मालगजारी अदा करने के लिये अपनी उपज को बाजार में ले जावें। इससे चावल व अन्य अनाज की कीमतें गिरने लगीं और बहुत से छोटे छोटे किसानों के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि ये मालगजारी दे चुकने के बाद अगने निर्वाह के लिये गर्याप्त अन्न बचा सकें। इस कारण बहुत से किसान अपने खेतों को बेचने के लिये विवश हुए। इस अवसर का लाभ उठाकर बहुत से धनी लोगों ने गरीब किसानों की जमीनों को खरीदना शुरू किया और जमींदारों की एक नई श्रेणि का विकास प्रारम्भ हुआ, जो अपने धन के ओर पर देहातों में अपने प्रभुत्तव का प्रसार कर रही थीं। इस समय जापान में व्यावसायिक फान्ति का प्रारम्भ हो चुका था। बहुत से नये कल कारखानों का प्रादुर्भाव हो रहा था और इनमें कार्य करने के लिये मजदूरों की मांग निरन्तर बढ़ रही थी। बहत से गरीय निसान इस समय अपने कुलकमानुगत घरों को छोड़कर शहरों में आये और मजदूरी प्राप्त करके अपना निर्वाह करने लगे। पाश्चात्य देशों के समान जापान में भी अब मजदूर वर्ग का विकास प्रारम्भ हुआ और व्यावसायिक कान्ति के कारण पूंजीपतियों और मजदूरों की जो समस्या यूरोप में उत्पन्न हुई थी, वह जापान में भी प्रादर्भत होने लगी।

धार्मिक दशा—वीद्ध धर्म का जापान में किस प्रकार प्रवेश हुआ, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। सम्राट् की शक्ति की पुनः स्थापना (१८६८) के बाद जापान के प्राचीन परम्परागत धर्म (शिन्तो) में नवजीवन का संचार हुआ। पर इसके कारण बौद्ध धर्म का हास नहीं हुआ। शिन्तो धर्म के जो तत्त्व इस समय प्रबल हुए, वे जापान की बौद्ध जनता में पाचीन विधिविधानों के प्रति निष्ठा और सम्राट् को देवता रूप में भागने की भावना में युद्ध कर रहे थे। शिन्तो सिद्धान्तों

के कारण जापान का बौद्ध धर्म अन्य देशों के बौद्ध धर्म से भिन्न रूप धारण कर रहा था। जन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जापान में किश्चिएनिटी के प्रचार को भी वल किला। फांस के रोमन कैथोलिक और अमेरिका के प्रोटेस्टेन्ट पादियों ने वहां अनेक निश्नों की स्थापना की और इनके कारण अनेक जापानी लोग इस पाश्यात्य धर्म के प्रति आकृष्ट होने लगे।

साम्राज्यवाद के मार्ग पर—व्यावसायिक उन्नति और सैनिक शिक्त की दृष्टि में जापान अब पश्चात्य देशों का समकक्ष हो गयां था। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वह भी यूरोप और अमेरिका का अनुकरण कर साम्राज्यवाद के मार्ग पर अग्रसर हो। उक्षीसवीं सदी की समाप्ति से पूर्व ही जापान ने कोरिया और चीन में अनेक युद्ध किये और वीसवीं सदी में तो कुछ समय के लिये वह पूर्वी एशिया में अपने विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में भी समर्थ हुआ। जापान के इस साम्राज्य विस्तार पर हम आगे चलकर यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

तोषयो नगर—शोगूनों के शासनकाल में जापान का सम्राट् क्योतो में रहता था, और शोगून शासकों की राजधानी येदो नगरी थी। जब शोगूनों के शासन का अन्त होने पर सम्राट् ने राजशक्ति को अपने हाथों में लिया, तो वह भी अपने दरवार के साथ येदो चला आया। इस समय ये ो का नाम बदल कर तोक्यो— रखा गया, और धीरे-धीरे यह न केवल जापान का, अपितु एशिया का सबसे बड़ा नगर बन गया।

चीन में विदेशी साम्राज्यवाद का प्रसार

(१) जापान और चीन का युद्ध

जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां-- उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में विविध पारचात्य देश चीन में अपने प्रभाव व प्रभुत्वका विस्तार करने के लिये किस प्रकार प्रयत्नशील थे, इसका उल्लेख पहले एक अध्याय में किया जा चुका है। रूस उत्तरी एशिया में अपना विस्तार कर चुका था और उसकी दक्षिण-पूर्वी सीमा चीन के साथ आ मिली थी । युरोप के विविध देश प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीपों को अपने अधिकार में ला चुके थे और चीन के अनेक वन्दरगाहों पर उनका प्रभृत्व स्थापित हो गया था । जब जापान भी व्यावसायिक उन्नति और सैन्यशक्ति में वृद्धि के कारण े पारचात्य देशों का समकक्ष हो गया तब उसका ध्यान भी साम्राज्य विस्तार की ओर आकृष्ट हुआ। जापान के उत्तर में सवालिन द्वीप और कुरील द्वीपसमृह विद्यमान हैं। सलालिन पर रूस और जापान का संयुक्त अधिकार माना जाता था। करील द्वीप समह पर जापान और रूस दोनों अपने अधिकार का दावा करते थे। १८७५ में जापान ने रूस के साथ एक समझौता किया. जिसके अनसार सलालिन द्वीप से जापान ने अपने अधिकार का परित्याग कर दिया और उसके बदले में कस ने कुरील हीप-समूह को जापान के सुपुर्द कर देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार १८७५ में कुरील द्वीपसगृह पर जापान का अबाधित आधिपत्य स्थापित हुआ । १८७८ में बोनीन द्वीपसमूह पर भी जापान ने अधिकार कर लिया । ये द्वीप प्रशान्त महासागर में स्थित हैं, और सैनिक दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व है । इन पर अधिकार हो जाने से प्रशान्त महागागर में जापान की शक्ति बहुत सुदृढ़ हो गई।

प्रशास्त महातानर मं एम अन्य द्वीपसमूह है, जिसे र्यूक्यू द्वीपसमूह कहते हैं। इसमें जापानी कोयों का ही निवास है। एक इन दीपों का शासक अनेक सदियों से जीन के सप्राट् को अर्थाननानुक्य भट उनहार भेजा करना था और इन दीपों को जीन के सप्राट् को अर्थाननानुक्य भट उनहार भेजा करना था और इन दीपों को जीन के साधाक्य का एक अंग माना जाता था। १८७२ में र्यूक्ष्यू का एक जहाज फार्मूसा के तट के समीप हुव मना। इनके मल्लाहों और याधियों ने अपनी जान नवाने के लिये कार्युशा में आश्रय लिया। पर कार्युशा के लोगों ने इन्हें जान ने मार

दिया । इस समय फार्म्सा चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था । जापान की सरकार ने कहा, र्यूक्यू के लोग जापानी हैं और उनकी हत्या का प्रतिशोध चीन को करना । चाहिय । चीनी सरकार का कहना था, कि र्यूक्यू द्वीपों के साथ जापान का कोई सम्बन्ध नहीं है और चीनी सरकार के लिये यह भी सम्भव नहीं है, कि वह फार्म्सा के लोगों के किसी कार्य के लिये उतरदायिता ले सके । इस पर जापान की एक सेना ने फार्म्सा पर आक्रमण किया और उसके कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिया । अब चीन इस बात के लिये विवश हुआ, कि जापान को हरजाने की रकम देकर र्यूक्यू के लोगों की हत्या का प्रतिशोध करे । हरजाने की रकम प्राप्त करके जापान की सेना फार्म्सा से वापस लौट आई । पर इस घटना का यह महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ, कि र्यूक्यू द्वीपसमूह पर जापान का आधिपत्य निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया । कुरील और र्यूक्यू द्वीपसमूहों की उपलब्धि जापानी साम्राज्यवाद की पहली सफलता थी।

कोरिया की समस्या-भौगोलिक दृष्टि से कोरिया का बहुत महत्त्व है। वह जापान और चीन के बीच में स्थित है, और कोरिया व जापान के बीच का समद्र बहुत अधिक चौड़ा नहीं है। अत्यन्त प्राचीन काल से जापान का चीन के साथ सम्बन्ध कोरिया द्वारा ही रहा है। जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश भी कोरिया द्वारा ही हुआ था। उन्नीसवीं सदी में कोरिया का भौगोलिक महत्त्व और भी अधिक बढ गया था. क्योंकि इसके उत्तर के प्रदेश रूस के आधिपत्य में आ गये थे। साइवीरिया के रूस के अधीन हो जाने के कारण अब कोरिया की स्थिति तीन शक्तिशाली राज्यों के बीच में हो गई थी। ये तीन राज्य थे, रूस, जापान और चीन। राजनीतिक दृष्टि से कोरिया चीन के सम्राट् की अधीनता को स्वीकृत करता था। यद्यपि उसका अपना पृथक् राजा था, जो कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र राजा के समान अपने देश का शासन करता था, पर इसमें सन्देह नहीं कि कोरिया के ये स्वतन्त्र राजा चीन के सम्राट् को अपना अधिपति स्वीकार करते थे। जब कोई तया राजा कोरिया के राजसिंहासन पर आरूढ़ होता था, तो वह चीनी सम्राट की अनुमति प्राप्त करता था। कोरिया की ओर से चीनी सम्राट् की सेवा में प्रति वर्ष भेंट व जपहार भेजे जाते ये और विशिष्ट अवसरों पर कोरिया का राजा या उसका कोई प्रतिनिधि पेकिंग के राजदरबार में उपस्थित भी हुआ करता था। चीनी साम्राज्य में कोरिया की प्रायः वही स्थिति थी, जो बरमा या तिब्बत की थी।

एशिया के विविध देशों में अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व को स्थापित करते हुए पाश्चात्य देशों का ध्यान कोरिया की ओर भी आकृष्ट हुआ । अनेक रोमन कैथोलिक पादरियों वे धर्म प्रचार के नाम पर वहां प्रवेश किया । ये पादरी मुख्यतया फेञ्च थे । १८६६ भे कुछ फेञ्च पादरी कोरिया में मारे गये। इस अवसर से लाभ उठाकर फास के एक जहाजी बेड़े ने कोरिया के बन्दरगाहों में प्रवेश किया। फेञ्च लोग चाहते थे, कि कोरिया की सरकार को पादरियों की हत्या के लिये हरजाना देने को विवश करें और अपने देश के लिये ज्यापार सम्बन्धी सुविधाएं भी प्राप्त करें। पर उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी। इस समय फेञ्च लोगों की शक्ति कोचीनचायना पर अपना अधिकार स्थापिन करने में ज्यापृत थी और वे कोरिया की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे सके। इसी समय के लगभग अमेरिकन लोगों ने भी कोरिया में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, पर उन्हें भी अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी। १८७१ में अमेरिका का जहाजी बेड़ा भी निराश होकर कोरिया से वापस लौट आया।

१८७५ में जापान का एक जहाज कोरिया के समद्र तट पर पहुंचा। इस समय कोरियन सरकार की यह नीति थी, कि वह किसी भी विदेशी राज्य के सम्पर्क को पसन्द नहीं करती थी। इस जापानी जहाज पर गोलाबारी की गई। परिणाम यह हुआ, कि जापान में इससे बहुत बेचैनी हुई और वहां के बहुत से लोग कोरिया के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर देने के लिये आन्दोलन करने लगे। पर जापान की सरकार ने इस समय बद्धिमता से काम लिया । कोरिया के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देने के बजाय उसने यह निरुचय किया, कि अपनी ओर से एक दूतमण्डल कोरिया भेजे, जो वहां की सरकार को जापान के साथ बाकायदा व्यापारिक सन्धि करने के लिये प्रेरित करे। जिस प्रकार १८५३ में कमोडोर पेरी चार जहाजों और बहत से सैनिकों को साथ लेकर जापान आया था, वैसे ही अब १८७६ में एक जापानी दूतमण्डल सैनिक शक्ति को साथ लेकर कोरिया गया। यह द्वमण्डल कोरिया के साथ सन्धि करने में समर्थ हुआ। १८७६ में कोरिया के साथ जापान की जो सन्धि हुई, उसमें कोरिया की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया गया। कोरिया ने जापान को यह अधिकार दिया, कि वह सेऊल आदि कोरियन बन्दरगाहों में व्यापार कर सके और जो जापानी नागरिक व्यापार आदि के लिये कोरिया के बन्दरगाहों में रहें, वे कोरियन कानून थीर कोरियन अदालतों के अधीन नहीं। एनसटा-दैरिटोरिएलिटी की जिस पढ़ति के विख्य जापान स्टपं पारनार पहेंगी के साथ भंधी में तत्पर था, उसे उसने स्वयं कोरिया में प्रारम्भ किया । १८८२ में इसी प्रकार की मन्ति अमेरिका ने कोरिया के साथ की और उसके बाद बिटेन, जर्मनी, हम, इटली और प्रांस ने भी कोरिया के साथ व्यापारिक साचन्य स्थापित करने के छिदे गुथक पथक सन्धियां भी । अब कोरिया के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह अन्य देशों के समार्क से निन्तित रह राहे । विदेशियों के व्यापार हे लिये जसके द्वार अब पूरी तरह से खुळ गये थे ।

इसी अध्याय में हमने पहले लिखा है, कि कोरिया चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत था। यहां स्वाभाविक रूप से यह प्रक्न उत्पन्न होता है, कि चीन के अधीन होने पर कोरिया ने किस प्रकार एक स्वतन्त्र राज्य के समान विदेशों के साथ ये सिष्धयां की थी। इस प्रक्न का उत्तर यहीं है, कि चीन का सम्राट कोरिया के आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। वह केवल इतने से संतृष्ट था, कि कोरिया उसकी अधीनता को स्वीकार करता है, और उसे वार्षिक रूप से भेंट उपहार भेजता है। कोरिया की विदेशी नीति से उसे कोई ताल्लुक नहीं था और उसके इन मामलों में किसी प्रकार का दखल देना वह अपनी प्रतिष्ठा के विदेश समझता था।

विदेशी लोगों के साथ कोरिया का जिस ढंग से सम्पर्क बढ़ रहा था, उसे सब कोरियन लोग पसन्द नहीं करते थे। वहां एक ऐसे दल की सत्ता थी, जो विदेशी प्रभाव का सख़्त विरोधी था। कोरिया का राजा विदेशों से सम्पर्क का पक्षपाती था, अतः यह दल उसके भी खिलाफ था। परिणाम यह हुआ, कि १८८२ में कुछ कोरियन लोगों ने सिऊल (कोरियाकी राजधानी) में विद्यमान जापानी डेलीगेशन पर आक्रमण किया। राजप्रासाद पर भी इन लोगों ने हमले किये। अनेक जापानी इस आक्रमण में मारे गये। इस दशा में जापानी सरकार को अवसर मिला, कि वह कोरिया को इस हत्याकाण्ड का प्रतिशोध करने के लिये विवश करे। जापान की शाक्ति के सम्मुख कोरिया को सिर झुकाना पड़ा। कोरिया की सरकार ने हरजाने के रूप में एक भारी रकम जापान को देनी स्वीकार की, व्यापार के लिये जापान को कुछ और अधिक अधिकार प्रदान किये और यह भी मंजूर किया। कि एक जापानी सेना सिऊल में रहा करे।

जापान व अन्य विदेशी राज्य इस समय कोरिया में जिस ढंग से अपने प्रभाय व प्रभुत्व का विस्तार कर रहे थे, आखिर चीनी सरकार का घ्यान उसकी तरफ आहण्ट हुआ। चीन की ओर से युआन शिकाई को कोरिया में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। यह युआन शिकाई वही है, जो आगे चलकर मञ्चू वंश के पतन के बाद (१९१२) चीन का प्रथम राष्ट्रपति बना था। चीन की ओर से एक सेना भी कोरिया में शान्ति और व्यवस्था को स्थापित रखने के उद्देश से भेज दी गई। जापान की भी एक सेना इस समय कोरिया में विद्यमान थी। यह स्वाभाविक था, कि इन दोनों सेनाओं में परस्पर संघर्ष हो। इस समय कोरिया में दो दल थे। एक दल विदेशियों के सम्पर्क का विरोधी था। यह दल चीन की सहायता पर भरोसा रखता था। दूसरा दल विदेशियों के सम्पर्क का पक्षपाती था और आधुनिक ज्ञान विज्ञान को सीखकर कोरिया की उद्यति के लिये प्रयत्नशील था। इस दल को जापान की सहायता का सहारा था। १८८४ में नोरिया में रिधत

चीनी और जापानी सेनाओं में मुठभेड़ हो गई। पर इस समय स्थिति ने अधिक अभीर रूप धारण नहीं किया। १८८५ में कोरिया के प्रश्नपर चीन और जापान में परस्पर समझौता हो गया, और दोनों देशों ने कोरिया से अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया।

यद्यपि १८८५ में चीन और जापान में समझीता हो गया था, पर इन दो देशों में विरोध की भावना कम नहीं हुई थी। इस समय जापान इतनी अधिक उन्नति कर चुका था, कि वह भी ब्रिटेन, फांस, रूस आदि पाश्चात्य देशों के समान अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये उत्मुक था। जापान के लिये साम्राज्य विस्तार का सबसे उपयुक्त क्षेत्र चीन था। वह भलीभांति जानता था, कि चीन का विशाल साम्राज्य अन्दर से बहुत निर्वल है। चीन पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने का जापान की द प्टि में एक ही मार्ग था, और यह मार्ग कोरिया होकर जाता था। कोरिया में एक ऐसा दल भी विद्यमान था, जो चीन के प्रभाव में रहने की अपेक्षा जापान जैसे शक्तिशाली और प्रगतिशील देश को अपना नेता और सरक्षक मानने को तैयार था। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि कोरिया के प्रकार पर चीन और जापान में संघर्ष का सूत्रपात हो। कोरिया चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था, पर जापान उसे अपने प्रभाव और प्रभुत्त्व में लाना चाहता था। इसी कारण १८९४-९५ में चीन और जापान के यद्ध का प्रारम्भ हुआ।

चीन और जापान के युद्ध का कारण—(१) कोरिया की आन्तरिक दशा अच्छी नहीं थी। उसका शासन विकृत और निर्बेछ था। वहां दछवन्दी का भी जोर था और ये विविध दल आपस में लड़ाई के लिये तत्पर रहते थे। जापान समझता था, कि कोरिया की दुरवस्था और अव्यवस्था हमारे लिये हानिकारक है, क्योंकि कोरिया जापान का पड़ोसी है, और पड़ोसी के घर में होनेवाली घटनाओं की उपेक्षा कर सकना हमारे लिये सम्भव नहीं है।

(२) इस उत्तरी एशिया में अपने आधिपत्य की स्थापित कर चुका था और अब वह दक्षिण की और अपना प्रसार कर रहा था। इस की दक्षिण-पूर्वी सीमा कोरिया से आ मिली थी और यह शिक्तशाली देश कोरिया में अपने प्रभाव को विस्तृत करने के लिये उत्सुक था। कोरियन सेना का पुनः संगठन करने के लिये इसी अफसर नियुक्त किये गये थे और रून की इस गहायता के उत्रेरे में कोरिया ने देलरफ का बन्यरमाह इस के मुपुर्ट कर दिया दा, जहां उनके सब प्रमार के बहाज स्वतन्त्रना के साथ था जा तकते थे। इस जैसे शिक्तशाली राज्य का प्रमाय जिस हंग से कोरिया में बढ़ रहा था, जापान उसे अत्यन्त निता की पृष्टि से देखता था। वह सबसे कोरिया को अपने प्रभाव में रखना नाहता था। इस कही कोरिया पर

अपना प्रभत्त्व स्थापित न कर ले, इस भय से जापान उसे पहले अपने आधिपत्य में ले आना चाहता था।

(३) आर्थिक दिष्ट से भी जापान की कोरिया पर आंख थी। व्यावसायिक क्षेत्र में असाधारण उन्नति कर लेने के कारण जापान को भी अब यह फिक थी, बि कोई ऐसे प्रदेश अधिगत किये जावें, जहां वह अपने तैयार माल को निश्चिन्तता के साथ वेच सके और जहां से कन्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकता हो । जापान की दिल्ट में चीन और कीरिया ही ऐसे प्रदेश थे जहां अपने आधिपत्य की स्थापना कर वह अपनी आर्थिक समस्या को हल कर सकता था। जापान के लिथे

चीन का मार्ग कोरिया होकर ही जाता था।

(४) १८८५ में चीन और जापान में जो समझौता हुआ था, चीन के अनेक ्राजनीतिज्ञ उससे असंतुष्ट थे। इस समझौते के अनुसार चीन और जापान दोनों ने ही कोरिया से अपनी सेनाओं को वापस वुला लेने की बात स्वीकृत की थी। इस प्रकार कोरिया में जापान और चीन की स्थिति एक समान हो गई थी। चीन के नेता कहते थे, कोरिया चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत है और वहां उसे अपनी सेनाएं रखने का अधिकार है। कोरिया में यदि अव्यवस्था हो, तो उसे दूर गरने की अन्तिम उत्तरदायिता भी चीन पर ही है। अतः १८८५ के समझौते के विष्कु

भावना चीन में निरन्तर प्रवल होती जा रही थी।

(५) १८५९ में कोरिया में एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ था, जिसे ्तोंग-हाक कहते थे। यह एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसका निर्माण बौद्ध धर्म, कन्प्यसियस और लाओन्से की शिक्षाओं को मिलाकर किया गया था। तोंग-हाक लोग कोरिया में विदेशी प्रभाव को नापसन्द करते थे और अपने विचारों के प्रचार में तत्पर थे। कोरिया की सरकार इस सम्प्रदाय के विरोध में थी और एक राजाज्ञा द्वारा इसके प्रचार कार्य को रोक दिया गया था । १८८३ में तोंग-हाक सम्प्रदाय के बहुत से नेताओं ने सरकार की सेवा में एक प्रार्थनापत्र भेजा, जिसमें यह आवेदन ं किया गया था, कि उनके सम्प्रदाय के विरुद्ध जो आज्ञा पहले प्रकाशित की जा चकी . है, उसे रह कर दिया जाय । कोरिया की सरकार ने इस प्रार्थनापत्र को स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ, कि कोरिया में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए। सरकार के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह इस विद्रोह को शान्त कर सके। ईसाई मिशनरियों और विदेशी व्यापारियों के खिलाफ जो भावना कोरिया में विद्यमान येक्क उसने तोंग-होक लोगों की सहायता की और इस विद्रोह ने गम्भीर रूप धारण कर े लिया । इस दशा में कोरिया की सरकार के सम्मुख एक ही उपाय था, वह यह कि चीन से सहायता की याचना की जाय। चीन की एक सेना कोरिया पहुंच गई, जिसमें

कुल मिलाकर १५०० सैनिक थे। १८८५ के समझौते के अनुसार चीनी सेना के कीरिया भेजने के सम्बन्ध में जापान को भी सूचना दे दी गई। जब यह समाचार जापान को मिला, तो उसने भी अपनी एक अच्छी बड़ी सेना सिऊल भेज दी। चीन और जापान दोनों की सेनाएं अब कोरिया पहुंच गई थीं। तोंग-हाक विद्रोह को शान्त हुए पर्याप्त समय हो चुका था। अब इस बात का कोई कारण नहीं था, कि चीनी सेना कोरिया में रहे। चीन की सरकार ने कहा, हमारी सेनाएं तभी कोरिया में बापस लौटोंगी, जब जापान भी अपनी सेनाओं को वहां से वापस बुला लेगा। सेनाओं को लौटान के सम्बन्ध में चीन और जापान में समझौता नहीं हो सका। इस दशा में मामले को निबटाने का एक ही उपाय था, वह यह कि दोनों देश युद्धक्षेत्र में अपनी शक्ति को आजमावें।

जिन कारणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनसे जापान कोरिया को अपने प्रभाव में लाना चाहता था। चीन समझता था, कि कोरिया उसके साम्राज्य के अन्तर्गत है और वहां किसी अन्य देश को अपने प्रभाव का विस्तार करने का अधि-कार नहीं है। यही बात इन दोनों देशों के युद्ध का कारण हुई।

१८९४-९५ का युद्ध-जापान की स्थल व जलसेनाएं भलीभांति संगठित े थीं। उनके पास नये ढंग के सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। यद्यपि जापान एक छोटा सा देश है और उसकी सेना में सैनिकों की संख्या भी अधिक नहीं थी, पर आधृनिक ज्ञान विज्ञान को पूर्णतया अपना लेने के कारण जापान की सैन्यशिक्त चीन के मकाबले में बहुत अधिक उत्कृष्ट थी। विशालकाय चीन और उसकी विशाल सेना जापान का मुकाबला कर सकने में असमर्थ थी। सबसे पहले जापान की जलसेना नं चीन के सम्द्रतट पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित किया। याल नदी के मुहाने पर चीन का जहाजी बेड़ा जापान द्वारा बुरी तरह से परास्त हुआ । अब चीन के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह जापानी सेनाओं को चीन में उतरने देने में किसी प्रकार बाधा डाल सके । चीन की जलसेना को परास्त कर जापानी सेनाएं कोरिया में प्रविष्ट हुईं। कोरिया के लिने नह गम्भय नहीं था, कि वह जायान का मुका-बला कर सके। उस पर जापान का जिल्हार हो गया। कीरिया में जापानी सेनाओं ने मञ्जूरिया की लोर प्रस्थान किया । नहां भी नीनी संकार्य धुरी नरह से परास्त हुई । अब चीन के मध्यदेश पर आकारण करने के लिये गार्ग खुल एका था । मञ्जू सरकार ने अनुभव किया, कि जालान के साथ युद्ध को जारी रखना निर्धिक है। उसने सन्धि का प्रस्ताव किया।

शिमोनोसेकी की सन्धि जापान से सन्धि करने का कार्य लिन्हुंग-जांग के सुपूर्व किया गया। यह चीन का प्रगुरा राजनीतिज्ञ या और उत्तरी चीन में नायस-

राय के पद पर विराजमान था । कोरिया के विषय में पिछले सालों में जिस नीति का निर्धारण चीनी सरकार ने किया था, उसका निर्चय लि-हुंग-चांग द्वारा ही गिया गया था। लि-हुंग-चांग के प्रयत्न से जापान के साथ जो सिन्ध इस समय हुई, वह शिमोनोसंकी की सिन्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य शर्त निम्नलिखित थीं—(१) लिखाओ नदी के पूर्व का मर्जरचूया का प्रदेश (लिखाओ तुंग) जापान को दे दिया जाय। (२) फार्म्सा का विशाल द्वीप जापान को मिले। (३) पेस्का-दोरस द्वीपसमूह पर जापान के अधिकार को स्वीकृत किया जाय। (४) चीन हरजाने के रूप में भारी रकम जापान को दे, जब तक यह रकम बसूल न हो जाय विईहाईवेई के बन्दरगाह पर जापान का कब्जा रहे। (५) कोरिया को स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत किया जाय और चीन का उसपर किसी भी प्रकार का प्रभुत्व न रहे। (६) चार नये बन्दरगाहों को जापान के ब्यापार के लिये खोल दिया जाय। पारचात्य देशों के साथ जो सिन्ध्यां पहले हो चुकी थीं, उन सबमें यह ब्यवस्था रखी गई थी, कि उन्हें वे सब सुविधाएं रहेंगी, जोकिसी भी अन्य राज्य को प्राप्त होंगी। इसके कारण ये चार नये बन्दरगाह अन्य राज्यों के लिये भी खुल गये।

यूरोपियन राज्यों का विरोध-शिमोनोसेकी की सन्धि द्वारा लिआओ त्य १ का प्रदेश जापान को दिया गया था। यह बात रूस को अत्यन्त आपत्तिजनक प्रतीत हुई। रूस की सीमा मञ्चिरिया से मिलती थीं और वह स्वयं इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिये उत्सुक था। जापान जैसे शक्तिशाली राज्य के लिआओ तुंग पर कब्जा कर लेने से अब उसके लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह मञ्चिरिया व कोरिया की दिशा में अपने प्रभुत्व का विस्तार कर सके। रूस ने लिआओ तुंग पर जापानी प्रभुत्त्व का विरोध शरू किया। इस विरोध में फांस ने रूस का साथ दिया । १८९३ में रूस और फांस में एक सन्धि हो गई थीं, जो इतिहास में 'डयूएल एलायन्स' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कारण यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस और फांस के सम्बन्ध बहुत अधिक घनिण्ठ हो गये थे। जर्मनी भी इस समय तक साम्राज्यवाद के क्षेत्र में आगे वहने लग गया था। प्रिस बिस्मार्क के नेतृत्व में जब विविध जर्मन राज्य एक साम्राज्य के रूप में संगठित हो गये थे,तो उसके लिये यह सर्वथा स्वामाविक था, कि वह भी अपनी राष्ट्रीय शक्ति के विस्तार के लिये तत्पर हो । जर्मनी ने भी इस अवसर पर जापान के खिलाफ रूस और फांस का समर्थन किया । इन तीन शक्तिशाली राज्यों के विरोध के कारण जापान ने लिआओतुंग पर से अपने अधिकार का परित्याग कर विया और उसके बदले में चीन से हरजाने की एक अतिरिक्त रकम प्राप्त की।

चीन-जापान के युद्ध का परिणाम—१८९४-९५ के युद्ध ने इस वान को स्पट्ट कर दिया, कि विशालकाय चीनी साम्राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यन्त निर्वल हैं। अब तक पाश्चात्य देशों को यह साहस नहीं होता था, कि वे चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्त्व स्थापित करने का उद्योग करें। चीन की शविन के सम्बन्ध में उनकी जो धारणा इस युद्ध से पहले थी, वह अब नष्ट हो गई। उनमें अब यह प्रवृत्ति हुई, कि जापान का अनुसरण कर वे भी चीन को अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का शिकार बनावें। इसी का यह परिणाम हुआ, कि जापान, ब्रिटेन, फांस, जर्मनी आदि सब यूरोपियन देश चीन पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये तत्वर हुए।

(२) चीन में रूस की शक्ति का विस्तार

यूरोप के जो राज्य इस समय चीन में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिये प्रवृत्त हुए, उनमें रूस का स्थान सबसे प्रमुख है। लिआओ तुंग से जापान ने अपना कब्जा हटा लिया था। इस दशा में रूस के लिये यह सर्वथा सुगम था, कि वह मञ्चुरिया की दिशा में अपने प्रभाव का प्रसार करे। लिआओत्ंग को जापान के कब्जे से मुक्त कराने में रूस ने प्रमुख रूप से कर्तृत्व को प्रदर्शित किया - था। इस कारण पेकिंग की चीनी सरकार में उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था । अब तक पेकिंग में ग्रेट ब्रिटेन का प्रभाव सबसे अधिक था । पारचात्य देशों ने विविध सन्धियों द्वारा चीन में जो अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त किये थे, उनका श्रीगणेश ब्रिटेन द्वारा ही हुआ था। चीन के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का प्रमुख स्थान था। पर १८९५ के बाद चीन की सरकार पर रूस का प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया । लिआओ तंग के प्रदेश की फिर से चीन की दिलवाकर रूस ने यह प्रविशत करना शुरू किया, कि वह वस्तुत: चीन का मित्र है, और चीन सदा उसकी सहायता व पक्षसमर्थन पर निर्भर रह सकता है। यदि भविष्य में किसी भी विदेशी राज्य ने चीन के स्विस्त्त प्रदेशों में से किसी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, तो उसका म्काबला करने में वह चीन की सहायता करने में संकोच नहीं करेगा। इस प्रकार शिमोनोसेकी की सन्धि के बाद रूस और चीन के सम्बन्ध बहुत मित्रतापूर्ण हो गये थे।

१८९४ में रूस के राजसिंहासन पर जार निकोलस द्वितीय आरूढ़ हुआ। मई, १८९६ में रूस की राजधानी सेण्ट पीटसेंबुर्ग में निकोलस द्वितीय का राज्याभिषेक होना था। इसमें सम्मिलित होने के लिये चीन के प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया गया। चीनी सरकार की ओर से इस कार्य के लिये लि हुंग चंग को चुना गया। रूस के प्रसिद्ध राजनीदिन काउण्ट वीड़े ने लि हुंग चंग से चीनी साम्राज्य के सम्बन्ध में विशद रूप से वातचीत की । काउण्ट वीटे ने चीन के प्रतिनिधियों को समझाया, कि विदेशी राज्यों से अपने देश की रक्षा करने का सबसे उत्तम जपाय यही हैं, कि चीन रूस को अपना मित्र समझे और उसकी सहायता पर निर्भर करें। लि हंग चंग और काउण्ट वीटे ने बातचीत द्वारा एक नई मन्धि की, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं-(१) यदि जापान पूर्वी एशिया में अपनी शिवत की बढ़ाने का यत्न करते हुए चीन या रूस के साथ लड़ाई शुरू करे, तो ये दोनों राज्य एक दूसरे की सहायता करें। (२) जापान के साथ युद्ध की दशा में रूस की यह अधि-कार हो, कि वह चीन के बन्दरगाहों का पूर्णरूप से उपयोग कर सके व युद्ध की आव-ध्यकताओं को दिष्ट में रखकर चीन में अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सके। (३) रूस को यह अनुमति दी जाय, कि वह उत्तरी मञ्जूरिया में एक रेलवे लाइन का निर्माण कर सके । उनरी एशिया में रूस इस ममय ट्रांस-साइबीरियन रेलवे के निर्माण में तत्पर था । इस सुदीर्घ रेलवे लाइन का निर्माण १८९१ में प्रारम्भ हुआ। था। रूस की यह इच्छा थी, कि यह लाइन पूर्व में ब्लादीबोस्तॉक के वन्दरगाह तक पहंच जावे। रूस के अपने प्रदेशों में से जो रेलवे लाइन ब्लादीबोस्तॉक तक जा. सकती थी, उसमें बहत चक्कर पड़ता था। अतः रूस ने चीन से इस बात की अन-मित ली, कि हार्बिन से ब्लादीबोस्तॉक तक रेलवे लाइन का वह निर्माण कर सके 🍁 यह लाइन एक हजार मील तक चीन के साम्राज्य में से होकर गुजरती थी। साथ ही इस को चीन ने यह भी अनमति दी, कि इस रेलवे की एक बाञ्च दक्षिण में पोर्ट आर्थर (लिआओ तंग प्रायद्वीप में) तक वनाई जा सके। (४) १८९४-९५ के युद्ध के बाद शिमोनोसेकी की सन्धि के अनुसार हरजाने की जो भारी रकम चीन ने जापान को देनी थी, उसे अदा करने में कस चीन की सहायता करे। इस चर्त के अनुसार इस समय रूस ने चीन को एक अच्छी वडी धनराचि कर्ज के रूप में प्रदान की।

मञ्चूरिया में रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिये जिस धनराशि की आव-श्यकता थी, उसकी व्यवस्था करने के लिये रूसो-चाइनीज वैंक का संगठन किया गया। इसी वैंक की मदद से मञ्चिरिया में टैलीग्राफ की लाइनों का भी विस्तार किया गया। रेलवे लाइन का निर्माण करने और उस पर रेलगाड़ियों को चलाने के लिये एक पृथक् कम्पनी की स्थापना की गई, जिसमें रूसी सरकार और रूसी धनपतियों ने बहुत उदारता के साथ रुपया लगाया। रेलवे लाइन के समीपवर्ली प्रदेशों में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने का कार्य भी इस कम्पनी के सुपुर्द किया गया। यह भी व्यवस्था की गई, कि इस चाइनीज ईस्टर्न रेलवे पर कम्पनी का अधिकार ४० साल तक कायम रहे, और उसके बाद इसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति पर चीनी सरकार का प्रभुत्त्व कायम हो जाय और इसके लिये चीन को कोई मुआवजा देने की आवश्यकता न हो।

हार्बिन-ब्लादीबोस्तांक रेलवे के निर्माण के कारण उत्तरी मञ्चूरिया का आर्थिक दृष्टि से बहुन विकास हुआ। पर साथ ही इससे मञ्चूरिया में रूस के प्रभाव व प्रभुत्त्व की भी स्थापना हो गई। जिस प्रकार अठारहवीं और उत्तीसवीं सदियों में रूस ने साइबीरिया के मुविस्तृत प्रदेशों पर अपना प्रभाव स्थापित किया था, वैसे ही अब उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में उसने मञ्चूरिया में भी अपने प्रभाव को विस्तृत करना शुरू किया। इस प्रदेश में आवागमन का जो सबस अधिक सुविधा-जनक साधन था, वह क्स के कब्जे में था, अतः यहां अपना आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्त्व स्थापित कर सकना भी उसके लिये अत्यन्त सुगम हो गया। रूस ने इस अवसार का पूरी तरह से उपयोग किया।

(३) जर्मनी की शक्ति का विस्तार

शिमोनोसेकी की सन्धि में संशोधन कर लिआओ-तंग के प्रदेश को जापान के फब्जे से मुक्त कराने में जर्मनी ने भी चीन की सहायता की थी। अतः उसकी भी ्यह इच्छा थी, कि चीन के इरा पक्षसमर्थन से लाभ उठाकर अपने लिये कुछ विशेष मुविधाएं प्राप्त करे । १८९७ में जर्मनी ने अन्य राज्यों की सूचना दी, कि वह चीक में एक ऐसे स्थान को प्राप्त करने के प्रयत्न में है, जहां उसके जहाज अपने अख्डा वना सकों और जहां उन्हें मरम्मत व रसद आदि की पूर्ण सुविधा हो । इसी बीच में दो जर्मन पादरियों की चीन में हत्या हो गई । अब क्या था, जर्मनी को अपनी इच्छा पूर्ण करने का सूबर्णीय अवसर हाथ लग गया। जर्मन सरकार की ओर से पेकिंग की सरकार के सम्मख निम्नलिखित मांगें पेश की गई-(१) दिसंग ताओ (उत्तरी चीन में) के बन्दरगाह को ९९ साल के पट्टे पर जर्मनी को दिया जाय। साथ ही कियाऊ-वाऊ की लाड़ी पर भी जर्मनी के अधिकारको स्वीकृत किया जाय। (२) बात्ंग के प्रदेश में जर्मनी को रेलवे लाइन बनाने का अधिकार मिले और इस प्रदेश में जो कोई भी खानें हों, उन्हें विकसित करने का अधिकार केवल जर्मनी की रहे । (२) जर्गन पादिर्यों की हत्या के लिये चीन जर्गनी की हरजाता दे । साथ हीं, इस शांनों को पेड़ करते ने पूर्व तिमन ताओं के परवरगाह पर करना न उने के लिये जीं कुछ खर्म जर्मन चलनेना को करना गड़ा था, वह सब भी चीन की सरकार उसे प्रदान करे।

जर्मनी की इन मांगों को अस्वीकृत कर सकने की शक्ति चीन में नहीं थी। इ मार्च, १८९८ को चीन और जर्मनी में सन्ति की गई, जिनके अनुवार जिल्लाकों चाओं की खाड़ी, तिसग ताओ बन्दरगाह और उसके समीपवर्ती प्रदेश जर्मनी को ९९ साल के पट्टे पर प्राप्त हुए। नाम को ये प्रदेश अब भी चीन के सम्राट् के अधीन रहे, पर सन्धि में इस बात को भलीभांति स्पष्ट कर दिया गया, कि चीनी सरकार इन प्रदेशों में शासन सम्बन्धी किसी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। साथ ही शांतुंग प्रदेश में रेलवे लाइन का निर्माण करने और वहां खानों की खुदाई के सम्बन्ध में अनेक विशेषाधिकार जर्मनी को दिये गये। इस प्रकार १८९८ में जर्मनी ने चीन के कतिपय प्रदेशों में अपने राजनीतिक प्रभृत्व को स्थापित किया।

(४) चीन में अन्य राज्यों की शक्तिका विस्तार

ग्रेंट ब्रिटेन हस और जर्मनी ने जिस प्रकार चीन के विविध प्रदेशों में अपने विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे, उसके कारण अन्य राज्यों में भी यह प्रवृत्ति हुई, कि चीन की निर्वलता से लाभ उठाकर अपने लिये इसी ढंग के विशेषाधिकारों को प्राप्त करें। ब्रिटेन ने चीन से यह मांग की, कि (१) वेई हाई वेई का बन्दरगाह उसे पट्टे पर दिया जाय। (२) चीन यह घोषणा करे, कि यांगत्से नदी के समीप-वर्ती प्रदेशों में किसी अन्य राज्य को विशेषाधिकार नहीं दिये जावेंगे। (३) विदेशी व्यापार के आयात व निर्यात माल पर कर एकत्रित करने के लिये जो चाइनीज मैरीटाइम कस्टम्स सर्विस स्थापित हैं, उसका अध्यक्ष सदा कोई अङ्गरेज ही रहे। (४) हांगकांग पर इस समय ब्रिटेन का आधिपत्य था, उसके सामने का चीनी प्रदेश भी ब्रिटेन को पट्टे पर दिया जाय। चीनी सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि ब्रिटेन की इन मांगों का विरोध कर सके। उसने उन्हें स्वीकृत कर लिया।

फान्स—ब्रिटेन के बाद फांस ने चीनी सरकार से अनेक नई सुविधाएं प्राप्त की। ये सुविधाएं निम्निलिखित थीं—(१) चीन की सरकार ने स्वीकृत किया, कि हैनान दीप किसी अन्य राज्य को नहीं दिया जायगा। (२) यूनान, क्वांगसी और ववांगत्तुंग के प्रदेशों में खानें खोदने तथा अन्य प्रकार आर्थिक साधनों को विकसित करने का अधिकार केवल फांस को रहे। (३) फांस ने अनाम में जिस रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया था, उसे दक्षिणी चीन में भी विस्तृत करने का उसे अधिकार हो। (४) क्वांग-चोऊ की खाड़ी व उसका समीपवर्ती प्रदेश फांस को ९९ सम्लि के पट्टें पर दिया जाय।

जापान-विटेन और फांस का अनुसरण कर अब जापान ने भी चीन में अनेक विशेषाधिकार प्राप्त किये। इनमें सबसे मुख्य यह था, किफार्मूसाके सामने चीनका जो फूकिएन प्रदेश हैं, वहां जापान के अतिरिक्त किसी अन्य देश को आधिक विकास कर सकने का अधिकार न दिया जाय।

इटली — इटली भी इस समय इस बात के लिये प्रयत्नशील था, कि चीन में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करे। इटली के विविध राज्यों को एक सूत्र में संगठित कर शिवतशाली इटालियन राष्ट्र के विकास की जो प्रिक्रिया नैपोलियन के युद्धों के बाद प्रारम्भ हुई थी, वह १८७० में पूरी हो गई थी। अब इटली भी अपने साम्राज्य का निर्माण करने के लिये तत्पर था। उसने भी चीन की निर्वलता से लाभ उठाकर अपनी कुछ मांगें पेश कीं, पर चीनी सरकार ने उन्हें स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। १९०० के बाद इटली को चीन में अपने प्रभाव को विस्तृत करने के लिये फिर अवसर मिला। इस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

सुविधाओं का स्वरूप--- ब्रिटेन, रूस, जापान आदि देश चीन में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे, उनके कारण इन देशों का वहां एक विशेष प्रकार का प्रभावक्षेत्र विकसित होता जाता था। इन प्रभावक्षेत्रों में ब्रिटेन, रूस आदि देश आर्थिक हित तो अविकल रूप से प्राप्त कर लेते थे, पर राजनीतिक दिष्ट से चीन का प्रभुत्व कायग रहता था। क्योंकि चीन की राजशक्ति इस समय बहुत निर्वल थी, अतः शासन के सम्बन्ध में भी वह विदेशियों के इन प्रभावक्षेत्रों में अपने अधिकारों के उपयोग में असमर्थ रहती थी। विशेषतया जो प्रदेश विदेशी राज्यों ने ९९ साल के पड़े पर प्राप्त कर लिये थे, वहां तो कियात्मक दृष्टि से चीन के प्रभुत्त्व का अन्त ही हो जाता था । विदेशी राज्यों के लिये यह सर्वथा सुगम था, कि वे इन प्रदेशों पर अपने राजनीतिक स्वत्व की स्थापना कर लें। इस प्रकार चीन में एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था, जिसका स्वरूप आर्थिक था। १८४२ और १८६० में विविध विदेशी राज्यों ने चीन के साथ जो सन्धियां की थीं, उनके कारण चीन के बहुत से बन्दरगाह विदेशियों के प्रभाव में आ गये थे। अब उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में तो इन विदेशी राज्यों के प्रभत्त व प्रभाव का चीन में और भी अधिक विस्तार हो गया था। ये विदेशी राज्य जहां एक तरफ चीन की सरकार से अपने लिये विशेष सुविधाओं को प्राप्त कर लेने के लिये प्रयत्नशील थे. वहां साथ ही जापस में भी इनमें प्रतिस्पर्धा जारी थी । इस प्रकार चीन विविध विदेशी राज्यों के साम्राज्य विस्तार सम्बन्धी संघर्ष का क्षेत्र बनता जाता या ।

जमेरिका की नीति—उजीसवी सदी के मध्य भाग तक संयुक्तराज्य अमेरिका में व्यावसायिक क्रान्ति ने बहुत अधिक प्रभान उत्पन्न नहीं किया था। पर इस समय (उजीसवीं सदी के अन्त) तक अमेरिका संसार के सर्व प्रमान व्यावसायिक देशों में भिना जाने लगा था। जिन कारणों ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि को साम्राज्य-

विस्तार के लिये प्रेरित किया था, वे अमेरिका में भी विद्यमान थे। १८९८ में स्पेन और अमेरिका में युद्ध हुआ। इसमें स्पेन की बुरी तरह से पराजय हुई और 🚶 अनेक प्रदेश उसकी अधीनता में निकलकर अमेरिका के हाथ में आ गये। फिलि-प्पीन द्वीप समृह भी इनमें से एक था। फिलिप्पीन के अधिगत कर लेने के बाद अमेरिका का साम्राज्य प्रशान्त महासागर में भी विस्तृत हो गया था और अब उसके लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह चीन की राजनीतिक घटनाओं को उपेक्षा की दिट से देख सके । विविध विदेशी राज्य जिस ढंग से चीन में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे. अमेरिका उमे अपनी आंखों में ओझल नहीं कर सकता था । अतः १८९९ में अमेरिका की ओर से इन्डलैण्ड, फांस, इटली, जर्मनी, कस और जापान की सरकारों के पास एक विज्ञाप्ति भेजी गई, जिसमें निम्नलिखित बातों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया था--(१) चीन के विविध बन्दरगाहों में व्यापार आदि के सम्बन्ध में जो अधिकार विदेशी राज्यों को प्राप्त हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया जाय, चाहे अब ये बन्दरगाह किसी एक विदेशी राज्य के प्रभावक्षेत्र में आ चुके हों। (२) चीन के साथ हुई सिन्धयों द्वारा आयात व निर्यात माळ पर टैक्सों की जो दर पहले निश्चित हो चुकी है, उनका कोई राज्य उल्लंघन न करे। यदि कोई बन्दरगाह किसी विदेशी राज्य के प्रभावक्षेत्र में हो, तब भी वह अन्य सबके साय-नटकर के मामले में एक सदश व्यवहार करे और अन्य राज्यों के जहाजों के आवा-गमन के सम्बन्ध में कोई रुकावट न डाले। (४) किसी राज्य के प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत बन्दरगाहों में जब अन्य राज्यों के जहाज आवें, तो उनसे बन्दरगाह का खर्च अपनी अपेक्षा अधिक न लिया जाय।

इस समय अमेरिका इस नीति का प्रतिपादन कर रहा था, कि चीन के बन्दरगाहों में ज्यापार की जो सुविधाएं व विशेषाधिकार विदेशी राज्यों ने पहले प्राप्त
किये हुए थे, प्रभावक्षेत्रों के कायम हो जाने से उनमें किसी प्रकार का अन्तर न पड़े।
विटेन भी इस समय इसी नीति का समर्थक था। यद्यपि उसने स्वयं चीन के अनेक
प्रदेशों में अपने प्रभावक्षेत्र को कायम कर लिया था, तो भी उसका हित इस बात में
था, कि चीन के विविध बन्दरगाह सब विदेशी राज्यों के लिये समान रूप से खुले रहें।
इसका कारण यह था, कि बिटेन का चीन में ज्यापार अन्य सब राज्यों की अपेक्षा बहुत
अधिक था। रूस, फांस, जापान आदि ने इस समय चीन में अपने अपने प्रभावक्षेत्र
कायम कर लिये थे। यदि ये देश अपने इन प्रभावक्षेत्रों में अन्य राज्यों के ज्यापार
में रुकावट डालने का प्रयत्न करते, तो इससे सबसे अधिक नुकसान ब्रिटेन को
पहुंचता। यही कारण है, कि इस समय ब्रिटेन और अमेरिका की चीन के सम्बन्ध
में एक ही नीति थी और ये दोनों इपितजाली राज्य है। बात के लिये प्रयत्नशील थे,

कि विविध विदेशी राज्यों ने चीन में जो प्रभावक्षेत्र कायम किये हैं, उनका रूप आधिक ही रहे और वे इन राज्यों के राजनीतिक आधिपत्य में न आ जावें। अमेरिका और ब्रिटेन की इस नीति के कारण उन्नीमवी सदी के इस अन्तिम भाग में विदेशी राज्य चीन में अपनी प्रभुता का और अधिक विस्तार नहीं कर सके।

(५) सुधार के प्रयत्न

१८९४-९५ के युद्ध में जापान ने परास्त होकर चीन के लोगों ने अपनी दुईशा को अच्छी तरह से अन्भव कर लिया था । विविध विदेशी राज्य जिस प्रकार चीन में अपने प्रभावक्षेत्र कायम करने में तत्पर थे, चीन के लोग इससे भी बहुत चिन्तित थे। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि चीन में ऐसे दलों का प्रादुभवि हो, जिनका उद्देश्य देश की राजनीतिक दुर्बलना को दूर कर शक्ति का संचार करना हो । पारुचात्य देशों के आयुनिक ज्ञान विज्ञान से अब चीनी लोग भी अपरिचित नहीं रहे थे । अनेक चीनी युवक विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करके बापस आये थे और इनका यह प्रयत्न था कि अपने देश की दशा का सुधार करें। सुधार के पक्षपाती इन दलों में डा॰ सन यात मेन के दल का विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। डा० सन यात सेन के पिता ने किश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया था और अपने पुत्र को हवाई और हांगकांग के विदेशी शिक्षणालयों में पढ़ाया था। पारचात्य विचारों के सम्पर्क में आकर डा० सन यात सेन के हृदय में यह आकांक्षा प्रवलरूप से उत्पन्न हो गई थी, कि चीन को भी फांस, ब्रिटेन आदि के समान उन्नत और समृद्ध होना चाहिये। जापान का उदाहरण उसके सम्मृद्ध था। १८९५ में उसने कैन्टन में एक विद्रोह का नेतृत्त्व किया। पर इसमें उसे सफलता नहीं हो सकी। उसे चीन छोडकर विदेशों में आश्रय लेना पड़ा। उसे गिरपतार करते के लिये चीनी सरकार ने एक इनाम की घोषणा की थी।

सुधार के पक्षपाती चीनी लोगों में कांग यू वेई का उल्लेख करना भी आवश्यक हैं। वह डा॰ सन यात सेन के समान कान्तिकारी नहीं था। उसका विचार था, कि कान्ति के मार्ग का आश्रय लेकर चीन का उद्धार नहीं किया जा सकता। चीन को सुधार के मार्ग का अनुसरण करना चाहिये और देश के शासन में सुधार कर वैध राजसत्ता की स्थापना करनी चाहिये। इसी प्रकार चीन के दो प्रमुख राज-पदाधिकारी चांग चिह-तुंग और लियु कुन-यी भी सुधारवादी दल के साथ सम्बन्ध रखते थे। चांग-चिह-तुंग ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम धा 'जिया लो'। इसमें उसने प्रतिपातित किया था, कि चीन को पश्चिमी रेशों से जान विज्ञान की शिक्षा लेकर अपनी उसति करनी चाहिये, अन्यया उसकी भी वही गर्त होर्गा,

जो कि भारत, अनाम, ईजिप्ट आदि की हुई है । चांग चिह-तुंग की पुस्तक का बहुत प्रचार हुआ और उसके कारण चीन में सुधार के आन्दोलन को बहुत बल मिला।

यद्यपि डा० सन यात सेन को कान्ति के प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी थीं, पर सुधारवादी लोगों की शिवत निरन्तर बढ़ती जाती थी। सम्राट् कुआंग ह् सू की इन सुधारवादियों के साथ सहानुभूति थी। १८८७ में कुआंग ह सू वयस्क हो गया था और साम्राज्ञी त्सू ह सी के प्रभाव व संरक्षा से विमुक्त होकर स्वयं राज्य-कार्य की देखरेल करने लगा था। १८९८ में प्रसिद्ध सुधारवादी नेता कांग यू-वेई के साथ उसका सम्पर्क स्थापित हुआ और उसने यह निश्चय किया, कि चीन की सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा। इसीलिये जून १८९८ से सितम्बर १८९८ तक सम्राट् कुआंग ह सू की तरफ से अनेक नई आजाएँ प्रकाशित की गईं, जिनका उद्देय चीन के शासन में सुधार करना था। इन राजा-ज्ञाओं में केवल शासन सम्बन्धी सुधारों का ही आदेश नहीं दिया गया था, अपितु यह भी ध्यवस्था की गई थी, कि चीन में शिक्षाका विस्तार किया जाय, और बड़े सब प्रकार के शिक्षणालयों की स्थापना की जाय, और उच्च शिक्षा के लिये एक विश्व-विद्यालयकी भी स्थापना हो। चीन में रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाय और जहाजों के निर्माण का भी उद्योग हो। सम्राट् कुआंग हसू द्वारा आदिष्ट सब सुधार यदि क्रिया में परिणत हो सकते, तो नि:सन्देह चीन में असाधारण उन्नति हो जाती।

पर अभी चीन में मुधार के निरोधियों की कमी नहीं थी। निशेषतया सरकारी पर्वाधिकारी और राजकर्मचारी सम्राह् द्वारा प्रकाशित आज्ञाओं के सख्त खिलाफ थे। शासन सुधार के लिये जो व्यवस्थाएँ सम्राह्ने की थीं, उनसे इस नर्ग की सता में बहुत अन्तर आता था। साम्राज्ञी त्सू ह्सी ने सुधार के निरोधियों का साथ दिया। सत्ताईस साल तक वह चीन के शासन का संचालन कर चुकी थीं। ब्रिटेन, फांस आदि पाश्चात्य देशों के प्रति उसके हृदय में उत्कट घृणा थी। १८५८ और १८६० की घटनाओं का उसे भलीभांति स्मरण था। उसका विचार था, कि पाश्चात्य देशों का अनुसरण करने से चीन की हानि हैं। चीन का हित इसी बात में हैं, कि इन निदेशी राज्यों को अपने से दूर रखे और पाश्चात्य विचारों के सम्पर्क में न आकर अपनी प्राचीन मर्यादा का पालन करे। साम्राज्ञी त्सू ह्सी ने सुधारों का निरोध करना शुरू किया और पेकिंग की सरकार ने यह अनुभव किया, कि तसू ह्सी को गिरफ्तार किये बिना सुधारसम्बन्धी आज्ञायें किया में परिणतर नहीं की जा सकेंगी। यह कार्य युआन शी काई के सुपुर्द किया गया। सुधारवादी लोग समझते थे, कि युआन शी काई की सहान भूति सुधारों के पक्ष में हैं। उसे चिहली प्रान्त का सूबेदार नियत किया गया और यह आदेश दिया गया कि तीन्तिसन

पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वहां के राजप्रासाद पर आक्रमण करे और साम्राज्ञी को गिरफ्तार कर छे। पर तीन्तिम जाकर युआन शी काई साम्राज्ञी के साथ मिल गया। अब साम्राज्ञी त्सू ह्सी की सेनाओं ने सम्राट् पर आक्रमण किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। सम्राट् कुआंग ह्सू का शेप जीवन कैदी के रूप में व्यतीत हुआ।

अब सारी शासन शिवत एकबार फिर साम्राज्ञी त्मू ह्सी के हाथों में आ गई। सम्राट् कुआंग ह् सू को इस बात के लिये विवश किया गया, कि वह एक नई आजा प्रकाशित करे, जिसमें यह लिखा हो, कि देश के हित को दृष्टि में रखकर मैंने साम्राज्ञी त्सी ह् सू से प्रार्थना की है, कि वह राज्य कार्य को फिर से सभाल लें और उन्होंने अत्यन्त कुपापूर्वक मेरी इस प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया है। इस प्रकार शासन-सूत्र को फिर से अपने हाथों में लेकर साम्राज्ञी ने उन सब राजाज्ञाओं को रह किया, जो १८९८ में प्रकाशित की गई थीं। इस समय बहुत से सुधारवादी चीनी नेता गिरफ्तार किये गये और बहुतों ने चीन से भागकर अपनी जान बचाई। कांग यू वेई पेकिंग से भागकर जापान पहुंचने में सगर्थ हुआ और उसने वहां जाकर सुधार के पक्ष में अपने आन्दोलन को जारी रखा। सुधारवादी नेताओं में से कुछ को इस समय प्राणदण्ड भी दिया गया।

सुघारों का आश्रय लेकर चीन में नवजीवन का संचार करने का जो प्रयत्न सम्राट् कुआंग ह् सू की संरक्षा में प्रारम्भ हुआ था, उसका इस प्रकार बुरी तरह से अन्त हुआ। इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय मञ्जू शासन इतना विकृत हो चुका था और चीन के विविध राज्यपदाधिकारी अपने कर्तव्यों से इतने अधिक विमुख हो गये थे, कि कान्ति के विना चीन के विकृत शासन का अन्त सम्भव नहीं था। यही कारण है, कि १९११ में राज्यकान्ति द्वारा मञ्जू शासन का अन्त हुआ और उसके साथ ही नवीन चीन के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ।

(६) बोक्सर विद्रोह

चीन में विदेशी लोगों का प्रभाव जिस हंग से बढ़ रहा था, उसी के कारण विविध चीनी देशभक्तों में अपने देश के सुधार की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हुई थी। सुधार के पक्षपातियों के प्रयत्नों को सफलता नहीं भिल सकी। पर इससे विदेशी लेंगों के प्रति विरोध व विदेश की मावना कम नहीं हुई। चीन के सभी लोग, चाहे ये मुधारों के पक्षपाती हों या विरोधी हों. विदेशियों से विदेश रखने थे। ईसाई पाद-रियों के पिरजा घर, विदेशियों द्वारा वनाई गई रेलवे लाइनें और पादचात्य लोगों द्वारा स्थापिस वेंक य कम्यनियां चीनी लोगों की लांहों में कांटे की तरह से चुभती

शीं। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि विदेशियों के प्रति विद्वेश की भावना एक बिद्रोह के रूप में प्रकट हो । १८९४-९५ के युद्ध के बाद विविध बिदेशी राज्ये। ने चीन के विभिन्न प्रदेशों में जिस प्रकार अपने प्रभाव क्षेत्र कायम कर छिये थे, उसने चीन की जनता में गहरे असन्तोप को उत्पन्न कर दिया था। इस स्थिति में चीन में एक समिति व दल का संगठन हुआ, जिसे अंग्रेजी में 'बोक्सर' कहते है । इस दल में सम्मिलित चीनी लोग अपनी बन्द मटठी या कसे हए मक्के की शिवत में विश्वास रखते थे और इसी का प्रयोग कर विदेशियों को चीन से बहिष्कृत कर देने के लिये कटिवद्ध थे। १८९९ का अन्त होने से पूर्व ही बोक्सर दल ने चीन के विविध प्रदेशों में चिदेशियों पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। बहत से ईसाई पादरी बोक्सर लोगों के कोध के शिकार हुए। पेकिंग के दक्षिण में अनेक विदेशी इञ्जीतियर रेलवे लाइन के निर्माण में तत्पर थे। इन पर आक्रमण किये गये और इन्हें गीत के घाट उतार दिया गया। उन घटनाओं के समाचार से पेकिंग में स्थित विदेशी राजदूतों में खलबली मच गई। उन्हें डर लगा, कि कहीं हम पर भी बोक्सर लोग हमला न कर दें। चीन के समुद्र तट के समीप जो बहुत से बिदेशी र्जगी जहाज विद्यमान थे, उनसे सेनाओं को पेकिंग वुलाया गया। बोक्सर लोगों ने कहा, विदेशी राज्यों ने चीन पर वाकायदा चढाई कर दी है। इन सेनाओं से अपनी व रक्षा करने के लिये नोक्सर लोगों ने पेकिंग और तीन्तिसन के बीच की रेलने लाइन को कई स्थानों से उखाड़ दिया । अब विदेशी लोगों को और भी अधिक चिन्ता हुई। तीन्त्सिन मं दो हजार विदेशी सैनिकों की एक सुव्यवस्थित सेना का संगठन किया गया और इस सेना ने पेकिंग की तरफ प्रस्थान किया। इसी बीच में विदेशी षंगी जहाजों ने चीन के समुद्र तट पर आकृतमण शुरू कर दिये और अनेक महत्त्वपूर्ण नगरीं और किलों पर कब्जा कर लिया। अब बोक्सर लोगों और विदेशी राज्यों की सेनाओं में बाकायदा युद्ध शुरू हो गया और चीनी सरकार ने पेकिंग में विद्यमान विदेशी लोगों को आज्ञा दी, कि वे चौबीस घण्टे के अन्दर अन्दर पेकिंग को छोडकर बाहर चले जावें। इसी बीच में पेकिंग में स्थित जर्मन राजदूत की हत्या हो गई। अब विदेशियों के सम्मुख आत्मरक्षा का केवल एक ही उपाय था। वे सब पेकिंग के विदेशी दूतावासों में एक व हो गये और वहां रहकर अपनी सेनाओं के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। यदि वे पेकिंग छोड़कर समुद्रतट की ओर जाने का उद्योग करते, तो उन्हें भय था, कि मार्ग में वोक्सर लोग कहीं उन पर आक्रमण न कर दें में बहुत से चीनीं ईसाइयों ने भी इस समय आत्मरक्षा के लिये विदेशी दूतावासों में गरण ग्रहण की। बोक्सर लोगों ने पेकिंग के वृतावासों को घेर लिया। पर इन वृता-वासों का निर्माण किले के रूप में हुआ था और वहां पर विदेशी लोग कई महीने

तक बोक्सर लोगों के हमलों से अपनी रक्षा करते रहे। १९०० के मध्यतक विदेशियों की एक मुख्यवस्थित सेना पेकिंग पहुंच गई और वहां उसने बोक्सर लोगों से अपने दूतावासों की रक्षा की।

इसमें सन्देह नहीं कि १८९९-१९०० में बोक्सर विद्रोह ने बहुत गम्भीर कप धारण कर लिया था। साम्राज्ञी त्सू-ह् सी की सहानुभूति बोक्सर लोगों के पक्ष में थी। पर चीनी सरकार के बहुत से उच्च कमंचारी विदेशियों के विरुद्ध बोक्सर लोगों के युद्ध को देश के लिये हानिकारक समझते थे। चीन के विविध प्रान्तों में उनके सूबेदारों ने बोक्सर लोगों को काबू में रखने की भरसक कोशिश की। यदि सम्पूर्ण चीनी सरकार इस समय बोक्सर लोगों के साथ सहानुभूति रखती, तो विदे-शियों के लिये चीन में रह सकना असम्भव हो जाता। पर विविध प्रान्तीय सूबे-दारों ने बोक्सर लोगों को काबू में रखने में असाधारण कर्न्य प्रदर्शित किया। पेकिंग की केन्द्रीय सरकार ने भी एक आज्ञा द्वारा प्रान्तीय कमंचारियों का यह आदेश विया, कि वे बोक्सर लोगों के आक्रमणों से विदेशियों की रक्षा करने का प्रयत्न करें।

बोक्सर विद्रोह का समाचार जब पारचात्य देशों में पहुंचा, तो उन्होंने चीन में अपने आधिक व राजनीतिक हितों की रक्षा के लिये अपनी सेनाओं को चीन भेजा। ब्रिटेन, फांस, जर्मनी आदि की सेनाएं शीघ्र ही चीन पहुंच गई। चीन में जहां कहीं बोक्सर लोगों ने विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, वहां इन पारचात्य सेनाओं ने भयंकर अत्याचार किये। चीनी लोगों से बुरी तरह से बदला लिया गया। अनेक प्रामों व नगरों को भूमिसात् कर दिया गया। विदेशी सेनाओं ने चीन में एक प्रकार के आतंक के राज्य की स्थापना कर दी। बोक्सर विद्रोह का प्रयोग पारचात्य देशों ने चीन में अपने प्रभुत्व को विस्तृत करने के लिये किया और इसको निमित्त बनाकर उन्होंने वहां अपनी सेनाओं का जाल सा विछा दिया।

बोक्सर बिद्रोह का परिणाम—विदेशी प्रभुत्त्व के विरुद्ध चीनी लोगों ने जो विद्रोह किया था, वह सफल नहीं हो सका । पाश्चात्य देशों की सेनाएं चीन में अपने विशेषाधिकारों व प्रभाव को कायम रखने में सफल हुई । इस समय यदि विदेशी राज्य आपरा में एफागन होदार कार्य करने, तो उनके लिये चीन पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर सकता कठित नहीं था। जाजनीतिय वृष्टि में पीन की लग्धार अत्यन्त विश्वन द्या में भी, और गैनिय विदेश चीन के लिये पाश्चात्य देशों का मुकाबला कर सकता असलाव था। पर पाञ्चात्य राज्यों में आदल का जिये हैं। वहुत अधिक था। उत्ती नाएण वे चीन के सम्बन्ध में किसी एक नीनि का निर्धारण नहीं कर सके। बोक्सर बिद्रोह की समाप्ति पर ७ सितम्बर, १९०१ की जीन के

साथ विदेशी राज्योंका जो समझौता हुआ, उसमें मुख्य बातें निम्नलिखित थीं---(१) पेकिंग में जर्मनी का जो राजदूत मारा गया था, उसके छिये चीनी सरकार जर्मनी से क्षमा प्रार्थना करे । जिस स्थान पर जर्मन राजदूत की हत्या हुई थी, वहां चीनी सरकार एक स्मारक का निर्माण करे। (२) विदेशियों के साथ दुव्यवहार के लिये जिन चीनी राजकर्मचारियों को जिम्मेवार पाया जाय, उन्हें चीनी सरकार कठोर दण्ड दे । (३) जिन नगरों में विदेशी लोगों का कतल हुआ था, वहां पांच साल तक कोई सरकारी परीक्षा न हो सके, ताकि इन नगरों के निवासी सरकारी परीक्षा को उत्तीर्ण कर राजकीय पद न प्राप्त कर सकें। (४) जापान के दुतावास के अध्यक्ष की हत्या के लिये चीनी सरकार जापान से क्षमा याचना करे। (५) दो साल तक चीन न कोई अस्त्र-शस्त्र बना सके और न कोई अन्य ऐसा माल तैयार कर सके, जो युद्ध सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता हो। (६) हरजाने के तौर पर चीन १५०,००,००,००० रुपया विदेशी राज्यों की प्रदान करे। हरजाने की यह रकम ३९ वार्षिक किश्तों में अदा की जाय। (७) पेकिंग में विदेशी दुताबासों का निर्माण इस ढंग से किया जाय, कि आवश्यकता पड़ने पर वे सूगमता से अपनी रक्षा कर सकें। पेकिंग के जिस प्रदेश में ये विदेशी दूतावास हों, यहां चीनी लोग न रह सकें। चीनी पुलिस को भी वहां आने जाने का अधिकार न हो। इन् दूतावासों को यह भी अधिकार हो, कि वे अपनी रक्षा के लिये अपनी सेनाएं वहां रख सकों। (८) तीन्तिमन के समीप जो अनेक चीनी किले हैं, उन्हें भूभिसात कर दिया जावे, ताकि पेकिंग और समुद्रतट के बीच का मार्ग विदेशी लोगों के लिये सर्वथा सुरक्षित हो जाय। (९) तीन्त्सिन पर विदेशियों का अधिकार स्थापित किया जाय। (१०) चीन की सरकार की ओर से यह आजा प्रकाशित की जावे, वि प्रान्तीय सुबेदार अपने अपने क्षेत्र में विदेशियों के विरुद्ध सब प्रकार के आन्दोलनों को काबु में लावें। (११) विदेशी राज्यों और चीती सरकार के बीच में जो सन्धियां विद्यमान हैं, उनमें संशोधन किये जावें।

१९०१ का यह समझौता चीन के लिये बहुत हानिकारक व अपमानजनक था। इसके कारण चीन में विदेशी राज्यों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। पेकिंग में विदेशी सैनिक अच्छी बड़ी संख्या में निवास करने लगे। अब चीन में स्थित विदेशी राजदूतों की स्थित ऐसी नहीं रह गई, कि वे चीनी सरकार के साथ एक स्वतन्त्र राज्य की सरकार के समान व्यवहार करें। वे समझते थे, कि चीन उनके सम्मुख्य असहाय है और वे अपनी इच्छाओं को सैनिक शक्ति की सहायता से चीनी सरकार से मनवा सकते हैं। उनकी दृष्टि में चीन एक स्वतन्त्र राज्य न रहकर अधीनस्थ राज्य के सदृश हो गया, जिसे वश में रखने के लिये राजधानी में उनकी सेनाए विद्य-

मान थीं ! डेढ़ अरब रुपया चीन को हरजाने के रूप में विदेशी राज्यों को प्रदान करना था । यह रक्षम इतनी बड़ी थी, कि इसे अदा कर सकना चीन के लिये सुगम नहीं था । इसके बोझ से चीनी सरकार इतनी बुरी तरह से दब गई थी, कि आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर सकना उसके लिये कठिन हो गया था । तीन्त्सिन सदृश नगरों पर विदेशियों का कब्जा चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये अत्यन्त विद्यातक था । इस समय चीन के प्रायः सम्पूर्ण समुद्रतट पर विदेशी राज्यों का प्रभुत्त्व कायम हो गया था, और इन विदेशी लोगों को यह भी भलीभांति ज्ञात हो गया था, कि चीन उनकी सैन्यशक्ति के सम्मुख सर्वथा असहाय है ।

(७) रूस और जापान का युद्ध

मञ्जूरिया और कोरिया के क्षेत्र में रूस और जापान के हित परस्पर टकराते थे। इसी कारण १९०५ में इन दोनों देशों में एक भयंकर लड़ाई हुई। यह लड़ाई विशाल चीनी साम्राज्य में विविध विदेशी राज्यों के साम्राज्य-विस्तार सम्बन्धी प्रयत्नों का ही परिणाम थी। अतः इसी अध्याय में इस पर प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

भञ्चरिया-चीन के मध्यदेश के उत्तर के प्रदेश की मञ्च्रिया कहते हैं। चीन की प्राचीन विशाल दीवार इसे मध्यदेश से पृथक करती है। मञ्चिरिया का क्षेत्रफल ३,६५,००० वर्गमील के लगभग है। चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत यह विशाल प्रदेश तीन प्रान्तों में विभक्त था-क्वान्तुंग, किरिन और हाइलुंग कियांग । इनमें क्वान्तुंग प्रान्त सबसे अधिक आबाद और समृद्ध था । लिआओ-तुंग प्रायद्वीप इसी के अन्तर्गत था। क्वान्तुंग में चीनी लोग बहुत वड़ी संख्या में आबाद थे और खेती आदि द्वारा अपना निवहि करते थे। किरिन की जनसंख्या अधिक नहीं थी, और हाइलुंग कियांग का प्रान्त तो प्रायः गैरआबाद ही था। उसकी दशा प्रायः वैसी ही थी, जैसी कि उत्तरी एशिया के साइबीरिया की थी। मञ्चूरिया में सोया बीन प्रचुर परिमाण में उत्पन्न की जाती थी और गेहूं आदि अन्य अन्न भी पर्याप्त मात्रा में पैदा होते थे। खानों की दृष्टि से भी यह प्रदेश अच्छा समृद्ध था। कोयले, लोहे और सोने की इस प्रदेश में प्रचुर परिमाण में सत्ता है, यह बात चीन व अन्य देशों के लोगों को ज्ञात थी । यद्यपि मञ्जूरिया चीन के मध्य-देश के अन्तर्गत नहीं था ; पर चीनी साम्राज्य में उसकी स्थिति कोरिया, तिब्बत आदि अधीनस्थ प्रदेशों से भिन्न थी। कोरिया, निब्बत आदि शासन के सम्बन्ध में स्वतन्त्र स्थिति रखते थे, वे चीनी सम्राट की अधीननामात्र स्वीकृत करते थे ए

पर मञ्चूरिया का ज्ञासन मीधा पेकिंग की केन्द्रीय सरकार के अधीन था और उसके शासकों की निय्क्ति पेकिंग सरकार द्वारा ही की जाती थी ।

सञ्चरिया में रूस की स्थिति -- रूस उत्तर की ओर से किस प्रकार मञ्चूरिया में अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व का प्रसार करने में तत्पर था, इसका उल्लेख पहले किया जा चका है । १९०० में जब बोक्सर विद्रोह हुआ, तो रूस इस प्रदेश में अपने प्रभूत्व की किस हद तक स्थापित कर चुका था, इसका स्पप्ट रूप से उल्लेख कर द्रेना अगली घटनाओं को समझने के लिये बहुत उपयोगी होगा। १८९४-९५ के युद्ध के बाद रूस ने जापान के विरुद्ध चीन का जो पक्ष लिया था, उसके कारण लिआओ-तुंग प्रायद्वीप पर जापान का अधिकार नहीं रह गया था। कुछ समय बाद रूस ने चीन के साथ जो सन्धि की, उसकी प्रमुख शर्तों को हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं। इस सन्धि द्वारा रूस ने मञ्चूरिया में ब्लादीवीस्तॉक तक एक हजार मील लम्बी रेलवे लाइन के निर्माण का अधिकार प्राप्त कर लिया था और साथ ही इस रेलवे की एक ब्राञ्च लाइन को दक्षिण में पोर्ट आर्थर (लिआओ-तुंग प्रायद्वीप का बन्दरगाह) तक बना देने की अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। पोर्ट-आर्थर और उसके समीय का प्रदेश पच्चीस साल के लिये रूम को पट्टे पर दे दिया गया था और यहां रूसी सरकार ने ऐसी किलाबन्दी शुरू कर दी थी, जिससे रूसी जंगी जहाज वहां पर मुरक्षित रूप से रह सकें। पोर्ट आर्थर प्रशान्त महासागर में रूस का सबसे बड़ा नाविक अड्डा बन गया था और इसके कारण इस क्षेत्र में रूस की शक्ति बहुत दढ़ हो गई थी । मञ्चरिया में रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिये चाइनीज ईस्टर्न रेलवे कम्पनी और मञ्चरियन रेलवे कम्पनी नामक दो कम्पनियों का संगठन किया गया था, जिनका नियन्त्रण रूसी सरकार के हाथ में था। ये कम्पनियां प्रधानतया रूसी लोगों की ही थीं। इनके लिये रूपये का प्रवन्य करने के लिये रूसी-चाइनीज वैंक का निर्माण किया गया था । इस बैंक में चीनी सरकार की पूंजी बहुत कम थी। पुंजी का बड़ा भाग रूसी सरकार ने लगाया था, जिसे उसने फ्रांस में ऋण के रूप में प्राप्त किया था। यूरोप की राजनीति में इस समय रूस और फांस में घनिष्ठ मित्रता थी। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति के भय ने फेड़च रिपब्लिक और रूसी जारसाही में मैत्री सम्बन्ध को स्थापित कर दिया था। इन रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये रूसी लोग वहुत बड़ी संख्या में मञ्चूरिया में आ गर्ये थे और इन ठाइनों की रक्षा के छिये रूस की एक शक्तिशाली सेना भी इसे प्रदेश में रहने लग गई थी।

बोक्सर विद्रोह के अवसर पर रूस को मञ्जूरिया में अपनी शक्ति के विस्तार का सुवर्णावसर हाथ लगा । चीन के अन्य प्रदेशों के समान मञ्जूरिया में भी बोक्सर

लोग अपना कार्य कर रहे थे । उनके आक्रमणों से रूसी रेलवे लाइनों की रक्षा का बहाना बनाकर रूसी सेनाएं मञ्चूरिया पहुंचने लगीं । कुछ समय के लिये मञ्चू-रिया में रूस का फौजी शासन स्थापित हो गया । रूसी सरकार का कहना था, कि मञ्चरिया पर यह कब्जा केवल सामयिक रूप से किया गया है। ज्योंही बोक्सर बिद्रोह शान्त हो जायगा और चीन में शान्ति व व्यवस्था स्थापित हो जायगी. रूसी सेना को मञ्चिरिया से हटा लिया जायगा । पर बोक्सर विद्रोह की समाप्ति के बाद भी रूस ने अपनी सेनाओं को मञ्चिरिया से नहीं हटाया। उसका कहना था, कि अभी इस प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, कि रूस अपनी सेनाओं को वहां से हटा सके । अगेरिका, जागान, इङ्गलैण्ड आदि अन्य देश रूस के इस रुख को अत्यन्त चिन्ता की दृष्टि से देख रहे थे। पर वे स्वयं भी पेकिंग में अपनी सेनाओं को स्थापित कर चुके थे और उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे मिलकर रूस का विरोध कर सकें। साथ ही रूस का यह भी कहना ा, कि मञ्चरिया के प्रधन पर अन्य किसी राज्य को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। यह कस और चीन का अपना मामला है, और इसका फैसला ये दोनों राज्य ही कर सकते हैं। परिणाम यह हुआ, कि रूस ने मञ्चिरिया में अपने सैनिक कब्जे को जारी रखा। 🤏 बोक्सर विद्रोह से पहले मञ्चरिया में रूस का प्रभावक्षेत्र केवल आर्थिक था, अब वह सैनिक और राजनीतिक भी हो गया। रूस की इस आकांक्षा में अब कोई सन्देह नहीं रह गया, कि वह साइबीरिया के समान मञ्च्रिया को भी अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लेने के लिये कटिबढ़ है।

मञ्जूरिया और जापान मञ्जूरिया में रूस की इस प्रकार बढ़ती हुई बिला जापान को सहा नहीं थी। जापान यह नहीं सह सकता था, कि उसके पड़ोस में इतने समीप रूस जैसा बिक्तवाली व विशाल राज्य आ जाय। पोर्टआर्थर में रूस जिस प्रकार अपना नाविक अड्डा बना रहा था, उसमें जापान को सरन एनराज था। वह अनुभव करता था, कि प्रशान्त महासागर में रून की जिला उसकी अपनी स्वतन्त्रता के लिये विधातक हो सकती है। इस प्रकार मञ्जूरिया में रूस के बढ़ते हुए प्रभुत्व से जापान को बहुत बेचैनी अनुभव हो रही थी। साथ ही जापान स्वयं भी मञ्जूरिया में अपने प्रभुत्व की न्यापान करना चाहता था। व्यावसायिक वृद्धि अपनात्र देशों का समनक हो नाने के कारण जापान भी अपने नाम्याच्य के विस्तार के लिये उत्सुक्त था और उनके लिये उन्हें स्वयं अधिक उन्हां केन जीन ही नजर आता था। जीनी गाम्याव्य में भी मञ्जूरिया ही ऐसा प्रदेश था, जो जहां जापान के बहुत समीप था, वहा गाय ही गह भी नम्भव था, कि जापान के बहुत समीप था, वहा गाय ही गह भी नम्भव था, कि जापान के बहुत समीप था, वहा गाय ही गह भी नम्भव था, कि जापान के बहुत समीप था, वहा गाय ही गह भी नम्भव था, कि जापानी वहा कम भी

और इनमें जापानी बस्तियों के विकास के लिये मैदान खाली पड़ा था। मञ्चूरिया की खानें और उपजाऊ जमीन जापान के लिये आकर्षण का कारण बनी हुई थी के इसीलिये १८९४-९५ के चीन-जापान के युद्ध के बाद जापान ने लिआओ-तुंग के प्रदेश को अधिगत किया था। रूस के विरोध के कारण ही यह प्रदेश जापान की अधीनता में नहीं रह सका था और अब वहां पर रूस का कब्जा हो जाना जापान को असहा था।

कोरिया की समस्या-रूस और जापान के संघर्ष का दूसरा क्षेत्र कोरिया था। '१८९४-९५ के चीन-जापान यद्ध के अवसर पर जापान ने कोरिया पर अधिकार कर लिया था। जापानी लोगों ने इस समय कोरिया में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं कीं, जिनके कारण जापानी पुंजीपतियों को वहां अपना रुपया लगाने व विविध प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला। चीन-जापान के युद्ध की समाप्ति पर कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकृत कर ली गई, पर जापान ने वहां के आर्थिक जीवन पर जो प्रभृत्य स्थापित कर लिया था, उसका अन्त नहीं हुआ। यही नहीं, जापानी लोग कोरिया के राजघराने व सरकार के मामलों में भी हस्तक्षेप करते रहे । कोरिया की महारानी अपने देश में जापानियों के बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत चिन्तित थी । कोरिया में जापान के विरोधी जो लोग थे, महारानी की संरक्षा उन्हें प्राप्त थी। इसल्बिन् एक दिन आधी रात के समय कुछ जापानियों ने राजप्रासाद पर हमला कर दिया और महारानी को कतल कर दिया। कुछ दिन बाद कोरिया के महाराजा ने जापा-नियों से बचने के लिये रूस के दूतावास में शरण ली। इस समय रूस की भी एक सेना सिऊल में विद्यमान थी और उसी के कारण कोरिया का महाराजा अपने प्राणों की रक्षा कर सकने में समर्थ हुआ था। जापानी लोगों को यह बात सहा नहीं थी. कि रूस उनके मार्ग में बाघक हो। परिणाम यह हुआ, कि कोरिया के प्रश्न पर जापान और रूस के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये। पर १८९६ में कोरिया के प्रकृत पर इन दोनों देशों में समझौता हो गया, जिसकी मुख्य शतें निम्नलिखित थीं--(१) जापान और रूस दोनों अपनी सेनाओं को कोरिया से वापस बुला लें। कोरिया में चान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने की उत्तरदायिता कोरियन सरकार पर ही रहे । (२) रूस और जापान दोनों का यह प्रयत्न हो, कि आर्थिक दिन्द से कोरिया का उत्कर्ष हो। इसके लिये यदि कोरिया को पूंजी की आवश्यकता हो, तो दोनों देश मिलकर इस विषय में उसकी सहायता करें। इस प्रकार १८९६ के समझीते द्वारा कोरिया में रूस और जापान की स्थिति एक समान हो गई। यदि ये दोनों देश ईमानदारी से समझौते पर दृढ़ रहते, तो उनमें विरोध की कोई भी सम्भावना न होती । पर कठिनता यह थी, कि दोनों ही देश कोरिया को

अपने प्रभाव में लाने के लिये उत्सुक थे। रूस ने इस सम्वन्ध में विशेष ुतत्परता प्रदर्शित की। लिआओ-तुंग प्रायद्वीप को अपने प्रभाव में लाकर जब पोर्ट आर्थर और उसके समीप के प्रदेश को रूस ने पट्टे पर प्राप्त कर लिया. तो उसके लिये कोरिया में अपने प्रभाव को विस्तृत कर सकना और भी अधिक सुगम हो गया । रूस और जापान में कोरिया के सम्बन्ध में कोई भी समझौता इस ढंग से नहीं हो सकता था, जिससे दोनों देशों को पूर्ण रूप से सन्तोष हो, क्योंकि इस देश में उन दोनों के हितों में बहुत अधिक विरोध था। फिर भी बीसवीं सदी के शरू में जापान और रूस के राजनीतिज्ञों ने परस्पर समझौते के लिये अनेक प्रयत्न किये। १९०३ में सेण्ट पीटर्सबर्ग में स्थित जापानी राजदूत ने रूसी सरकार के सम्मुख निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किये-(१) रूस और जापान दोनों कोरिया और चीन की स्वतन्त्रता को स्वीकृत करें, और यह वचन दें कि इन देशों की स्वतन्त्रता को अक्षणण रखेंगे । (२) रूस इस बात को स्वीकार करे, कि कोरिया में जापान का विशेष प्रभावक्षेत्र है और इस कारण उसे अधिकार है, कि वह कोरिया में अपने आर्थिक हितों को विकसित कर सके और साथ ही कोरियन सरकार को सुव्यवस्थित करने के लिये परामर्श दे सके। (३) जापान मञ्चिरिया में रूस के विशेष प्रभावक्षेत्र 🕨 को स्वीकृत करे और वहां उसे वही सब कुछ करने दे, जो वह स्वयं कोरिया में करना चाहता है।

रूसी सरकार जापानी राजदूत के इन प्रस्ताओं को स्वीकृत करने के लिये सैयार नहीं हुई। रूसी सरकार चाहती थी, कि (१) कोरिया की स्वतन्त्रता को रूस और जापान दोनों स्वीकृत करें। (२) कोरिया में जापान का विशेष प्रभाव- क्षेत्र है, इस बात को मान लिया जाय। (३) जापान जिस प्रकार कोरिया में व्यापारिक और व्यावसायिक विकास करना चाहता है, उसमें रूस बाधा न डाले। (४) रूस और जापान दोनों इस बात को स्वीकार करें, कि वे कोरिया में कहीं किलाबन्दी नहीं करेंगे और कोरियन समुद्रतट का प्रयोग युद्ध के प्रयोजन के लिये नहीं करेंगे। (४) मञ्चूरिया में रूस का विशेष प्रभावक्षेत्र है, इस बात को जापान स्वीकार करें। रूस और जापान के प्रस्तावों में मुख्य भेद यह था, कि रूस कोरिया में अलाव के प्रयोजन के लिये वहीं अलाव के प्रयोजन के लिये नहीं का का का का जापान स्वीकार करें। रूस और जापान के प्रस्तावों में मुख्य भेद यह था, कि रूस कोरिया किलाव की स्वाव हो। इस की विशेष की किलाव की प्रमान की वहीं अलाव की स्वाव हो। इस की किलाव की प्रमान हो। की वहीं की वहीं प्रमान की वहीं प्रकार की प्रमान हो। इसके विश्वरीत जापान यह चाहता था, कि मञ्चूरिया में जो विश्वरीत करान वहीं उसे कोरिया में प्राप्त हों। वहीं उसे कोरिया में प्राप्त हों।

इस दशा में कोरिया के प्रश्न पर रूस और जापान में जो मतभेद व हित विरोध था, उसका निबटारा युद्ध के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से मम्भव नहीं था। इसी कारण रूस और जापान के युद्ध का प्रारम्भ हुआ।

इ.इ.क.ण्ड और जापान की सन्धि-इससे पूर्व कि हम रूम और जापान के युद्ध का उल्लेख करें, उस महत्त्वपूर्ण सन्धिका विवरण देना आवध्यक है, जो कि १९०२ में जापान और इङ्गलैण्ड के बीच में हुई थी। १८९४-९५ के चीन-जापान के यद्ध के बाद जापान के राजनीतिज्ञों में दो प्रकार के विचार कार्य कर रहे थे। एक पक्ष कहता था, कि रूस और जापान में मैत्री की स्थापना कर सकनः असम्भव नहीं है और ये दोनों देश परस्पर मिलकर उन सब प्रवनी का निवटारा कः सकते है, जो उनके पारस्परिक हित-विरोध के कारण उत्पन्न होते हैं । इस पक्ष १ अपने प्रयत्न में किस प्रकार असफलता हुई, इसका उल्लेख हम अभी कर चुके हैं: दूसरे पक्ष का कहना था, कि रूस और जापान में समझीता हो सकता सम्भव नहीं हैं, अतः जापान को कस का मकावला करने के लिये ब्रिटेन के माथ सन्धि करनी चाहिये। अन्य बिदेशी राज्यों के मुकाबले में ब्रिटेन का चीन में सबसे अधिक प्रभाव था, अतः जापान का ध्यान उसी के साथ सन्धि करने के लिये आकृष्ट हुआ। इस समय साम्राज्यबाद के क्षेत्र में रूस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वन्दी थे। तुर्व माम्राज्य और बालकन प्रायद्वीप के क्षेत्र में उनके हित-विरोध के कारण ही की मियन यद्ध (१८५४-५६) का प्राद्भीव हुआ था । रूस बालकन प्रायद्वीप में अपने प्रमाव का जिस प्रकार से विस्तार कर रहा था, उसके कारण ब्रिटेन यह अनभक्ष करता था, कि भारत आदि प्राच्य देशों में आने जाने का उसका मार्ग सुरक्षित नहीं रह सकेगा । मध्य एशिया और तुकिस्तान पर रूस अवना अधिपत्य स्थावित कर चुका या और इसके कारण रूस भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के बहुत समीप आ गया था। ईरान में भी रूस अपने प्रभाव की बढ़ा रहा था। मञ्चूरिया में रूस ने जिस प्रकार अपने प्रभुत्त्व का प्रसार श्रूक किया था, उसे भी ब्रिटेन चीन में अपने आर्थिक हितों के लिये हानिकारक समझता था। इस कारण वह भी इस बात के लिये उत्सुक था, कि जापान के साथ सन्चि करके एशिया में अपनी श्वित को मुरक्षित कर ले।

ब्रिटेन और जापान में यह सन्चि १९०२ में हुई। इसकी मुख्य बातें निम्न-लिखित थीं—(१) ब्रिटेन यह स्वीकार करता है, कि कोरिया में जापान के विशेष हैं हित हैं, और चीन में भी उसके आधिक हितों की सत्ता है। (२) जापान चीन में ब्रिटेन के हितों को स्वीकृत करता है। (३) दोनों देश यह मानते हैं, कि दोनों को अपने अपने हितों की रक्षा के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। (४) यदि इन हितों की रक्षा करने के लिये ब्रिटेन और जापान का किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध की आवश्यकता हो, तो दूसरा राज्य इस युद्ध में उदासीन रहेगा। (५) यदि ऐसे युद्ध की दशा में कोई अन्य राज्य ब्रिटेन या जापान के शत्रु की सहायता के लिये लड़ाई के मैदान में उतर आये, तो ब्रिटेन और जापान दोनों मिलकर उसका मुकावला करेंगे।

१९०२ की यह सन्धि शुरू में पांच मालों के लिये की गई थी। पर बाद में इसे फिर से दोहराया गया। इसमें सन्देह नहीं, कि इस सन्धि के कारण पूर्वी एशिया में जापान की स्थिति बहुत सुदृढ़ और सुरक्षित हो गई थी, और बहु शेरिया में अपने प्रभूत्व की स्थापना का प्रयत्न अधिक निविचन्तता के साथ करू कता था।

क्स और जापान का युद्ध--यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि क्स और जापान के युद्ध (१९०४-५) की घटनाओं का संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकें। लड़ाई गुरू होते ही जापान के जहाजी बेड़े ने पोर्टआर्थर पर आक्रमण किया । कसी वेडा उसका मुकावला नहीं कर सका । यह परास्त हो गया और भयंकर लडाई के बाद जापानी सेनाओं ने पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लिया । अब जापानी सेनाओं ने लिआओ-तंग प्रायद्वीप में बढ़ना ग्रह किया । ट्रांस-साइवीरियन रेलवे इस समय तक बनकर तैयार हो चकी थी। पांच हजार मील के लगभग दूर से इस रेल मार्ग द्वारा रूसी सेनाएं व युद्ध-सागग्री मञ्चूरिया में पहुंचाई जा रही थी। पर रूस के लिये यह मुगम नहीं था, कि इतनी दूरी पर अपनी सेनाओं व युद्ध सामग्री को पर्याप्त परिमाण में पहुंचा सके । साइबीरिया का विशाल भूखण्ड अभी आर्थिक दृष्टि से भलीमांति विकसित नहीं हो पाया था। नं वैहां कारखाने बने थे और न ही खेती आदि का भलीभांति विकास हुआ था । अतः मञ्चूरिया में स्थित रूसी सेनाओं को रसद व यह सामग्री के लिये उराल पार के यूरोपियन रूस पर ही निर्भर रहना होता था। साथ ही रूम की राजशिक्त भी इस समय अत्यन्त विकृत दशा में थी । वहां एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता का शासन था और शासन कार्य में जनता को कुछ भी अधि-कार प्राप्त नहीं थे। जनता में जारशाही के खिलाफ उग्र असन्तोष था और अनेक कान्तिकारी दल रूस में जार के एकतन्त्र शासन के विरुद्ध षड्यन्त्रों में तत्पर थे। ुडूसुके विवरीत जापान में जहां राष्ट्रीय भावना तीव रूप में विद्यमान थी, वहां साथ नी लोकतन्त्र शारान का भी सूत्रपात हो चुका था। जापान का सम्राट्व सरकार अनता की उसने के दिखे करिवड़ थे और समूर्य जागानी दोग अपनी सरकार। के प्रति अनुश्वन थे : कान्तिकारी अवृक्तियों का वहां सर्वथा अभाव धा । स्वीः जहाजी बेहें ने परास्त हो जाने के कारण जापान के लिये यह बहत सुगम हो गया।

या, कि वह अपनी सेनाओं और युद्ध सामग्री को मञ्चूरिया पहुंचा सके । किय ने यत्न किया, कि अपने एक अन्य जहाजी वेड़े को चीन के समुद्ध में भेजे, तार्वितान की सेनाओं के मंचूरिया पहुंचने में बाधा डाल सके। पूर्वि एशिया में कि कि लिये छोटा रास्ता स्वेज की नहर होकर आता था। पर इस मार्ग पर ब्रिटे प्रभुत्त्व था। जापान और ब्रिटेन की १९०२ में सिच्च हो चुकी थी और रूस के था, कि कही ब्रिटेन रूसी वेड़े को स्वेज नहर से गुजरने में बाधा न डाले। अत किस का जहाजी बेड़ा स्वेज के मार्ग का उपयोग नहीं कर सका। विशाल अफ्रीकन द्वीप का चक्कर काटकर मई, १९०५ में रूस की नौसेना ने जापान के समीप स्समुद्ध में प्रवेश किया। पर इस बार फिर रूस के जहाजी बेड़े की जापान द्वारा बुरी तरह पराजय हुई। २८ मई, १९०५ को जापान की नौसेना ने रूसी बेड़े को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। इस दशा में रूस के लिये लड़ाई जारी रख सकता सम्भव नहीं रहा। वह सन्धि कर लेने के लिये विवश हुआ।

पोर्ट्समाउथ की सन्धि-रूस और जापान के युद्ध की समाप्ति कर उनमें 'सन्धि कराने के कार्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री थिओडोर रूज-वेल्ट ने विशेष कर्त् त्व प्रदर्शित किया । युद्ध के समय ब्रिटेन के समान अमेरिका की भी सहानुभूति जापान के पक्ष में थी। सन्धि की बातचीत अमेरिका में ही शुरू हैं और उसी के अन्यतम नगर पोर्ट्समाउथ में सन्वि पर हस्ताक्षर किये गये। सन्धि के लिये जापान ने निम्नलिखित शर्तें पेश की थीं--(१) कोरिया पर जापान के प्रभत्त्व को स्वीकृत किया जाय । यह ध्यान में रखना चाहिये, कि रूरा जापान के यद की समाप्ति से पूर्व ही ब्रिटेन कोरिया पर जापान के प्रभुत्त्व को स्वीका कर चुका था। अब जापान चाहता था, कि रूस भी इस बात को स्वीकार कर ले 🖟 '(२) मञ्चरिया में रूस को जो भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वे सब जापान के 'दे दिये जावें। पोर्ट आर्थर और उसके समीप के प्रदेश का पट्टा भी जापान की मिल जावे। (३) पूर्वी एशिया के समुद्र में रूस के जो भी जहाज हैं, वे राव जापान के दे दिये जातें। (४) लड़ाई में जापान को जो कुछ खर्च करना पड़ा है, उसक हरजाना रूस प्रदान करे। (५) साइबीरिया के समुद्रतट पर जापानियों को मछ 🛷 पकड़ सकने का अधिकार दिया जाय । (६) राम्पूर्ण सखालिन द्वीप जापान क दे दिया जाय।

• स्स इन सब शर्तों को मानने के लिये तैयार नहीं था। पर अन्त में जिन प्राह्म पर ५ सितम्बर, १९०५ को रूस और जापान में सन्वि हुई, उसकी मुख्य बातें निम्ह्म िलिखित थीं—(१) रूस और जापान दोनों मञ्चूरिया से अपनी अपनी सेना को वापस बुला लें। (२) लिआओ-तुंग प्रायद्वीप के जिन प्रदेशों को (पोर्टअपूर्ण ब उत्का समीप का प्रदेश) रूम ने पट्टे पर लिया था, वे अब जापान को पट्टे पर िक्ष लोवें। (३) मञ्चूरियन रेलवे का दक्षिणी माग रूस जापान को प्रदान कर कान्यां विन और मुकदन के बीच में जो मञ्चूरियन रेलवे रूस ने वनाई थी, उसका अभाग इस शर्त द्वारा जापान को प्राप्त हुआ। (४) रूस और जापान मञ्चून भी अपनी अपनी रेलवे लाइनों का उपयोग केवल व्यावसाधिक और व्यापारिक प्रयोग नो के लिये करें, सैनिक प्रयोजन के लिये नहीं। (५) लिआओ-तुंग प्रायद्वीय अपना को जो विशेषाधिकार दिये गये हैं, और मञ्चूरियन रेलवे पर रूस और जापान को जो विशेषाधिकार हैं, उनके अतिरिक्त अन्य सब विषयों में मञ्चूरिया पर चीन का प्रभूत्व कायम रहे। (६) कोरिया में जापान के राजनैतिक, सैनिक और आधिक हितों व विशेषाधिकारों को स्वीकृत किया जाय। (७) सखालित द्वीप का दक्षिणी आधा भाग जापान को प्राप्त हो। (८) साइबीरिया के समुद्र-सट पर मछली पकड़ने के व्यवसाय को विकसित करने का जापान को अधिकार हो।

जापान सम्पूर्ण सलालिन द्वीप को प्राप्त करना चाहता था, पर पोट्संमाउय की सिन्ध द्वारा उसे केवल आधा सलालिन प्राप्त हुआ। युद्ध के लिये हरजाने की भी कोई रक्तम उसे प्राप्त नहीं हुई। मंन्दिया में भी जितने विशेषाधिकार वह प्राप्त क्रूरना चाहता था, वे उसे नहीं मिल सके। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस सिन्ध क्रिया वह सम्पूर्ण कोरिया पर अपना प्रमुत्त्व स्थापित करने में समर्थ हुआ, और पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लेने के कारण मञ्जूरिया में अपने प्रमुत्त्व को विस्तृत कर रूप ने का द्वार उसके लिये खुल गया।

क्स-जापान युद्ध के परिणाम—(१) पोर्स्माउय की सिंघ द्वारा पूर्वी गणाया में जापान की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। कीरिया पर उसके राजनीतिक, सैनिक और आधिक विशेषांधिकारों के स्वीकृत हो जाने के कारण यह देश पूर्णतया जापान का वशवर्ती हो गया। चीनी साम्राज्य के अन्यतम प्रदेश मञ्जूरिया जिसने अनेक विशेषांधिकार प्राप्त किये। जापान की सबसे बड़ी महत्त्वाकांक्षा जिसने अनेक विशेषांधिकार प्राप्त किये। जापान की सबसे बड़ी महत्त्वाकांक्षा जिसने अने वह चीन की निर्वलता से लाभ उठाकर अपने साम्राज्य का विस्तार जिस कीरिया नीन की अनीनता से मृन्त ट्रीचर जापान की अभीनता में आ जापान की साम्राज्य का विस्तार जापान की मान्य वाद के गुर्वा अविक वृद्धि हो। जाने के कारण अन जापान के प्रभाव व शिवारों बहुत अविक वृद्धि हो। (२) क्स की पराजय जार जापान की विजय के कारण एशिया के लोगों कि उत्साह का रांचार हुआ। उत्तीनवीं सदी में एशिया ने प्रायः सभी देशों जारण राज में में साम्राज्यवाद का शिकार होना वहा था। यूरोप भीर

अमेरिका के गौराङ्ग लोग ऐसा मानने लगे थे, कि नसल की दृष्टि से वे सर्वोत्कृष्ट हैं, और एशिया के लोग उनकी अपेक्षा हीन हैं । पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आकर एशिया के भी बहुत से लोग अपने को पाश्चात्य लोगों की अपेक्षा हीन समझने लगैं थं। जापान की विजय ने इस भावना को जड़ से हिला दिया। एशिया के निवा-मियों ने अनुभव किया, कि उन्नति की दौड़ में पारचात्य लोग जो उनकी अपेक्षा आगे निकल गये हैं, उसका एकमात्र कारण यह है, कि ज्ञान विज्ञान की आधुनिक उन्नति यरोप में कुछ समय पहले हुई। यदि जापान यरोप के ज्ञान विज्ञान को अपनाकर रूस जैसे शक्तिशाली व विशाल देश को परास्त कर सकता है, तो एशिया के अन्य लोगों के लिये भी यह सम्भव है, कि वे पाच्चात्य देशों की अधीनता से मनत होकर स्वतन्त्रता को प्राप्त कर सकें। भारत आदि सभी एशियन देशों पर जापान की इस विजय का असर हुआ और सर्वत्र जनता में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन को बल मिला। (३) रूम का जासन कितना निर्वल और विश्वत है, यह बात इस युद्ध में परास्त हो जाने के कारण रूसी लोगों के सम्मुख सर्वथा प्रत्यक्ष हो गई। इसमे सम के क्रान्तिकारियों को वहत बल मिला। अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह किये । २२ जनवरी, १९०५ को सेण्ट पीटर्सव्रो के मजदूरों ने एक विशाल जुल्म निकाला । इन पर गोली चलाई गई । मैकड़ों निहत्ये मजदूर एसी पुरिक्ष की गोलियों के शिकार हुए । २२ जनवरी का यह हत्याकाण्ड रूस के कान्तिकारियों के लिये वहत उपयोगी सिद्ध हुआ। सर्वत्र कान्ति प्रारम्भ हो गई। वारमा में पोल लोगों ने विद्रोह किया। फिनलैण्ड ने अपनी स्वतन्त्रना की घोषणा कर दी। वाल्टिक मागर के तट पर विद्यमान लिय्एनिया, लेटविया आदि देशों ने भी विद्रोह का अण्डा खड़ा कर दिया। आर्मीनियन और ज्योजियन लोग भी विद्रोह के लिये तैयार हो गये। मजदूर लोगों ने सर्वत्र हड़ताल की तैयारी शरू कर दी। इस दशा में जार निकोलस द्वितीय शासनस्थार के लिये विवश हुआ। रूम में पहली बार वैध राजसत्ता की स्थापना का उद्योग हुआ। (४) मञ्चुरिया में पोर्समाउथ की सन्धि द्वारा तीन राज्यों का प्रवेश हो गया था। चीनी सम्राट का वहां शासन था और इस व जापान ने वहां अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे। एक म्यान में तीन तलवारों का रह सकना असम्भव था। यही कारण है, कि पोट्सं-माउथ की सन्धि द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था देर तक मञ्चूरिया में कायम नहीं. रह सकी । शीघ्र ही वहां नये युद्धों का सूत्रपात हुआ और पोर्टआर्थर पर किला कर लेने के कारण जापान ने मञ्चूरिया में जो अपना पैर जमा लिया था, उसकी उपयोग कर उसने न केवल मञ्च्रिया अपितु सम्पूर्ण उत्तरी चीन पर अपने प्रभूत्व की स्थापना का उद्योग प्रारम्भ किया।

(८) चीन में विदेशी राज्यों का आर्थिक साम्राज्यवाद

💆 चीन को विजय करने का नया ढंग---इतिहास में अनेक बार पहले भी चीन पर विदेशी आकान्ताओं ने आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया था । पर वे सब विजेता चीन में आकर चीनी सभ्यता, संस्कृति आर धर्म को अपना लेने के कारण चीनी जनता के ही अंग बन गये थे । जिस प्रकार जो भी यवन, शक, हण आदि आकानता भारत पर आक्रमण कर यहा अपने विविध राज्य स्थापित करने में समर्थ हए, वे कुछ ही समय में पूर्णनया भारतीय बन गये, वैसे ही चीन के विदेशी आकान्ता चीन में आकर उसी की सभ्यता के रंग में रंग गये। इसका कारण यह था, कि चीन की सभ्यता अधिक उत्कृष्ट थी और उसके लिये इन विदेशियों को अपने में मिला लेना व सभ्यता के क्षेत्र में परास्त कर देना वहत सूगम था। पर उन्नीसवीं सदी में जो विदेशी राज्य चीन में अपने प्रभुत्त्व की स्थापना में तत्पर थे, वे सभ्यता, ज्ञान, राजनीतिवा मंगठन, व्यावसायिक उन्नति आदि की दृष्टि से चीनी लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत थे । इसीलिये चीनी लोग सभ्यता वे क्षेत्र में उन्हें परास्त कर सकते में असमर्थ रहे। साथ ही चीन पर इनकी विजय का एक नया ढंग था। कर्होंने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी, कि सिकन्दर, चंगेर्ज का या समुद्रगुप्त की बौली का अनुसरण कर एक विशाल मेना को साथ लेवार चीन पर आक्रमण करें. और उसको विजय कर लें। न ही इन्होंने चीन की सरकार को हटाकर उसके स्थान पर अपनी सरकार की स्थापना का उद्योग किया। मञ्च वंश के सम्राट चीन के राजसिंहासन पर पहले के समान विद्यमान रहे, बासन का कार्य चीनी कर्मचारियों के ही हाथ में रहा, पर इन विदेशी राज्यों का चीन पर शिकंजा उतना ही मजबूत था, जितना कि राजनीतिक दिष्ट से अधीन भारत, वरैमा आदि देशों पर था । विदेशियो के इस साम्राज्यवाद का चीन में स्वरूप आर्थिक था। चीन को अपनी अधीनता में रखने के लिये विदेशी सेनाओं को वहां स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चीन की निर्वल सरकार आर्थिक द्विट से विविध विदेशी राज्यों की इतनी अधिक वशवर्ती हो गई थी, कि पह भाग्य या वरमा आदि के मुकाबले में किसी भी प्रकार अधिका प्रताहत नहीं एक गई थी।

आधिक साधाज्यकार का स्वरूप—विकेशी राज्यों का यह आधिक साधाज्य-वार्ट निम्नलिखित रूपों में चीन को अपने वश में रखे हुए था—(१) बोक्सर विद्रोह कै बाद चीन ने जो भारी रण्याना विदेशी राज्यों को देना स्वीकार किया था, उसको वसूल करने के लिय चीन के आयात और निर्यात माल पण वसूस किया जानेवाला तट नाण अमानत के का में एक लिया नया था। विदेशी लोग इस कर को वसूल करते थे और इसे हरजाने की रकम में मुजरा कर लेते थे। चीन की सरकार की इसकी एक पाई भी प्राप्त नहीं हो पाती थी। (२) चीन की सरकार ने विविध प्रयोजनों के लिये विदेशी राज्यों से भारी रकमें कर्ज ली थीं। उनको अदा करने के लिये चीन के अन्य अनेक टैक्स अमानत के रूप में रख लिये गये थे। चीनी सरकार अपने देश में स्वयं इन करों को वसूर नहीं कर पाती थी। (३) चीन में रेलवे लाइनों का निर्माण-कार्य प्रायः ऐसी कम्पनियों के सपर्द किया गया था, जिनमें विदेशी पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में लगी हुई थी। ये रेलवे लाइनें विदेशियों के कब्जे में थीं, और इनके समीपवर्ती प्रदेशों पर भी विदेशियों का प्रभुत्व था। (४) चीन के अनेक प्रदेशों में खानों को खोदने व अन्य प्रकार से आर्थिक विकास करने का कार्य भी विदेशी राज्यों के सुपूर्व था। इस आर्थिक विशेषाधिकार के नाम पर इन विदेशी राज्यों को चीन में मनमानी करने की छुट्टी मिली हुई थी। (५) चीन के बहत में बन्दरगाहों में विदेशी राज्यों को व्यापार आदि की विशेष मुविधाएं प्राप्त थीं। इनमें जो विदेशी लोग बसते थे, वे चीन के कानूनों व अदालतों के अधीन नहीं थे । चीनी सरकार को यह भी अधिकार नहीं था, कि वह तटकर की मात्रा व दर का स्वयं निश्चय कर सके । (६) चीन के अनेक प्रदेश, विशेषतया समुदतट के प्रदेश विदेशी राज्यों ने पट्टे पर लिये हुए थे और इन पर इन विदेशी राज्यों अक्ष पूर्ण रूप से आधिपत्य विद्यमान था।

इन सब बातों का परिणाम यह था, कि राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होता हुआ भी चीन वस्तुतः विदेशी राज्यों के साम्रीज्यवाद का शिकार हो गया था। सञ्चू सरकार में यह शक्ति नहीं थी, कि विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव व प्रभुत्त्व से अपने देश की रक्षा कर सके।

आधिक साम्राज्यवाद के कारण—विदेशी राज्यों के लिये चीन में इस प्रकार अपना आधिक प्रभुन्व स्थापित कर सकना क्योंकर सम्भव हुआ, इस बात पर भी विचार करने की आवस्यकता है—(१) चीन के गास रुपये की कभी नहीं थी, वहां अनेक ऐसे कुल विद्यमान थे, जो अत्यन्त सम्पन्न व धनी थे। पर चीन में बैंक आदि ऐसी संस्थाओं का विकास नहीं हो पाया था, जिनमें लोग अपने रुपये को निश्चिन्तता और विश्वास के साथ जमा कर सकें और यह रुपया चीन के व्यावसायिक विकास, रेलवे निर्माण व इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिये प्रयुक्त हो सके। जॉयन्ट स्टाक कम्पनी की पद्धति से भी अभी चीनी लोग अपरिचित थे। इसलिये भीनी लोगों के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि वे रेलवे निर्माण व खानों की खुदाई आदि के कार्य में अपनी पूंजी का प्रयोग कर सकें। यह सब कार्य विदेशियों ने अपने हाथों में ले लिया। (२) चीन-जापान युद्ध (१८९४-९५) और बोक्सर विद्रोह के बाद

चीन ने विदेशी राज्यों को जो भारी रकम अदा करनी थी, उसका प्रवन्य करने का यही उपाय था कि या तो चीनी सरकार जनता से कर्ज छ सके या टैक्सों में वृद्धि करके अपनी आमदनी वढ़ा सके। वैंकों के अभाव में राष्ट्रीय ऋण प्राप्त कर सकता मुगम नहीं था और टैक्सों में वृद्धि करने से जनता में घोर असंतोष उत्पन्न हो जाने का भय था। चीन में सरकारी टैक्सों की दर परम्परागत रिवाज पर आश्रित थी। वहां किसी पाल्यामेन्ट की सत्ता नहीं थी, जो राष्ट्र की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर टैक्सों की दर में परिवर्तन करती रहे या नये टैक्सों को लगाने की व्यवस्था करे। आधुनिक युग में तटकर राजकीय आमदनी का महत्त्वपूर्ण साधन होता है। पर चीन में तटकर की दर विदेशियों के साथ की गई सन्धियों द्वारा निर्धारित थीं और उनकी सहमति के बिना इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकना सम्भव नहीं था। (३) चीन की नौकरशाही अत्यन्त विकृत थी। जो कर वभूल होते थे, वे सब भी सरकारी खजाने में नहीं पहुंच पाते थे। इस कारण चीनी सरकार को राय्ये की सदा कमी रहती थी और इसका यही परिणाम हो सकता था, कि वह निरन्तर विदेशी राज्यों के आर्थिक शिकंज में जकहती जावे।

आधिक प्रभुत्त का विकास-विदेशी राज्य चीन में अपने आर्थिक प्रभुत्त्व को स्थापित करने में किस प्रकार सफल हुए, इस विषय में भी कुछ घटनाओं का उल्लेख करना उपयोगी है। १८९४-९५ के चीन-जापान युद्ध से पूर्व तक चीन पर कर्ज का बोझ अधिक नहीं था। इस यद्ध की समाप्ति पर चीनी सरकार इस बात के लिये विवश हुई, कि २३,००,००,००० ताअल (एक ताअल=२॥ तोला चांदी) हरजाने के रूप में जापान को प्रदान करे। चीन को इस भारी रकम को तीन किस्तों में अदा करना था। पहली किश्त रूसी सरकार ने उसे कर्ज के रूप में प्रदान कर दी, और उसे बसूल करने के लिये चीन के तट-कर को जमानत के रूप में प्राप्त कर लिया। हरजाने की रकम की अगली दो किश्तें ब्रिटेन और जर्मनी ने कर्ज के रूप में चीन को प्रदान की । इस कर्ज के बंदले में उन्होंने किसी टैवस को जमानत के रूप में नहीं रखाया, क्योंकि टैक्स की जमानत के तौर पर रखकर तो रूस भी चीन की यह रकम देने को तैयार था। रूस के मुकाबले में ब्रिटेन और जर्मनी इसीलिये यह कर्ज देने में सफल हए, क्योंकि उन्होंने जमानत रखने पर जोर नहीं दिया था। पुर चीनी सरकार को अपना कर्जदार बनाकर १८९८ में ब्रिटेंन और जर्मनी उससे अनेक नई आर्थिक सुविधाओं को प्राप्त करने में समर्थ हुए । इन आर्थिक विशेषा-धिकारों का उल्लेख इसी जच्याय में पहले दिया जा चुका है।

बोबगर बिद्रोह के बाद चीनी सरधार को १,५०,००,००,००० हपया विदेशी राज्यों को हरजाने के रूप में देना था। इस रजम की भी कर्ज ठेकर ही प्राप्त किया जा सकता था। इस नये कर्ज के लिये चीनी सरकार ने निम्नलिखित टैन्थों को अमानत के तौर पर विदेशी राज्यों को दे दिया—(१) जो चीनी बन्दरगाह विदेशियों के न्यापार के लिये नहीं खुले थे, उनसे प्राप्त होने नाला तट कर, और (२) नमक में समूल होने नाली आमदनी। नमक के न्यानसाय पर चीनी सरकार का एकाधि-पत्य था और वह उमकी आमदनी का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन था। अब विनश होकर चीनी सरकार ने इस आमदनी ो भी अपने उत्तमणों के पास जमानत के रूप में रख दिया। बीसवीं सदी में आगे चलकर भी चीन विदेशों में कर्ज लेने के लिये विनश हुआ। इन कर्जों का हम यथाम्थान उल्लेख करेंगे। यहां इतना लिख देना पर्याप्त है, कि ज्यों-ज्यों चीनी सरकार विदेशों से ऋण लेती जाती थी, वह उनके आधिक शिकंज में जकड़ती जाती थी। अपने कर्ज को वसूल करने के नाम पर ये विदेशी राज्य चीन की राजनीतिक स्वतन्त्रता में भी हस्तक्षेय करते थे और इन विदेशी शक्तियों के सम्मुख चीनी सरकार अपने को सर्वथा असहाय अनुभव करती थी।

रेलवे लाइनों के निर्माण, खानों की खुदाई और अन्य प्रकार से आर्थिक विकास के जो विशेषाधिकार विदेशी राज्यों ने चीन में प्राप्त कर लिये थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन सबने चीन में विदेशी प्रमुत्त्व के स्थापित होने में बहुत अधिक सहायता दी। इनके कारण चीन का आधिक जीवन विदेशी राज्यों के हाथों में आ गया था, और चीनी लोगों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे स्वतन्त्रता के साथ अपने देश का विकास कर मकें।

सानवां अध्याय

चीन में राज्यक्रान्ति

(१) राजसत्ता में सुधार का प्रयत्न

शासन की विकृत दशा—उन्नीसवीं सदी के मच्य भाग में चीन के मञ्चू शासन की क्या दशा थी, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। पेकिंग की केन्द्रीय सरकार बहुत निर्वेल थी। आवागमन के साधनों की उन्नित के अभाव में उसके लिये यह सुगम नहीं था. कि वह विशाल चीनी साम्राज्य के विविध प्रान्तों व अधीनस्थ राज्यों पर अपने नियन्त्रण को भलीभांनि कायम रख सके। प्रान्तों के सूबेदार इस अवस्था से लाभ उठाकर सम्राट् की सरकार के आदेशों की उपेक्षा करने में संकोच नहीं करते थे। चीनी सरकार के पाम आमदनी की भी सदा कभी रहती थी। राजकीय करों की दर में वृद्धि कर सकना मुगम नहीं था और तट-कर की दर में परिवर्तन तो तभी सम्भव था, जब कि बिदेशी राज्य उससे सहमत हों। धन की कभी के कारण चीन के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह अपना आधिक विकास करने के लिये नये यन्त्रों च रेलवे आदि को प्राप्त कर सके और अपनी सेना को नये ढंग के अस्त्र-शस्त्रों से मुसज्जित कर सके। यहीं कारण हैं, कि विदेशी राज्यों का मुकाबला कर सकना चीनी सरकार के लिये मम्भव नहीं था और चीन-जापान युद्ध व बोक्सर विद्रोह के अवसरों पर उसे विदेशी राज्यों के सम्मुख नीचा देखना पड़ा था। मञ्चू सम्राट् इतने निर्वल थे, कि उनके लिये इस समय चीन को संभाल सकना सुगम नहीं रहा था।

सुधारों के लिये आन्दोलन—पर चीन में ऐसे विचारशील लोगों की कमी नहीं थीं, जो अपने देश की इस बुदंशा को अनुभव करते थे। किस प्रकार क्रान्तिकारी आन्दोलन चीन में शुरू हुए और किस प्रकार अनेक लोगों ने मञ्चू सरकार में सुधार का प्रयत्न किया, इसका उल्लेख गिछले अप्याण में किया जा चुका है। सुधारवादी लोगों के प्रभाव में अपने प्रभाद कुआंग-हूम ने १८९८ में अनेक ऐसी आजाएं कियां की थीं, जिनका उद्देश्य चीन के शासन में सुधार करना था। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हो सकी। साम्राज्ञी (राजमाता) त्सू हु सी का आश्रम पाकर सुधार-विरोधी लोग प्रवल हो गये और गम्राट् कुआंग हु सू को कैंद कर त्यु- हु सी ने शासनसूत्र को अपने हाथों में ले लिया। गुधार का अग्नोलन समाण हा

गया, और त्मू ह् सी के नेतृत्व में चीन का पुराने ढंग का एकतन्त्र व विकृत शासन

वथापूर्व जारी रहा।

वोक्सर विद्रोह के बाद चीन को विदेशी राज्यों के सम्मृत जिस प्रकार नीचा के स्वा पड़ा था, उसके कारण साम्राज्ञी त्यू ह्सी ने भी अनुभव किया, कि शासन-सुघार किये विना चीन की उन्नित सम्भव नहीं है। साम्राज्ञी त्यू ह्सी यह मानने की तैयार नहीं थीं, कि १८९८ के सुघारों का विरोध कर उसने कोई गल्ती की थीं। उसका कहना था, कि १८९८ में सुघारवादियों का यत्न यह था, कि मञ्जू शासन का सर्वथा अन्त कर एक नई कान्तिकारी सरकार की स्थापना की जाय। पर वह यह स्वीकार करती थीं, कि अब समय की गति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है, कि मञ्जू राजवंश की सत्ता और चीन की प्राचीन मयींदा की कायम रखते हुए शासन में ऐसे परिवर्तन होने चाहियें, जो चीन को उन्नित के भाग पर आगे बढ़ाने में समर्थ हों। त्यू ह्सी की इस नीति में उसका प्रधान सहायक युआन शी काई था, जो १८९८ के बाद में निरन्तर उसका साथ दे रहा था।

सुधारों का सूत्रपात — पुआन शी काई की सहायता से साम्राज्ञी त्सू ह्सी ने शासन सुधार के कार्य को प्रारम्भ किया। सबसे पूर्व सेना के पुनः संगठन पर ध्यान दिया गया। १९०१ में एक राजाज्ञा प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार सेना का नये ढंग से संगठन करने की व्यवस्था की गई। प्रान्तों के विविध सूबेदार अपनी अपनी जो सेनाएं रखते थे, उनके स्थान पर अब चीन की एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया और यह निश्चय किया गया, कि चीन की राष्ट्रीय सेना में १९१२ तक छत्तीस डिविजनों का संगठन कर लिया जाय। इस आंर जापान के युद्ध के समय पर इस प्रकार की सुसंगठित सेना की आवश्यकता को अत्यन्त उग्र इप से अनुभव किया गया।

की गई। इस परीक्षा पद्धित के स्वरूप को हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। चीन में विविध राजकीय पदों पर जिन व्यक्तियों को नियत किया जाता था, उनके लिये इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता था। इन परीक्षाओं के पाठ्य-विषय में आयुनिक युग के ज्ञान विज्ञान को कोई स्थान नहीं था। प्राचीन प्रत्यों और धर्मशास्त्रों में प्रवीण होना ही इन परीक्षाओं के लिये आवश्यक होता था। इसी कारण चीन के सरकारी कर्मचारी नये ज्ञान-विज्ञान से सर्वथा अपरिचित होते अस् और उनके लिये समय के अनुसार अपने को परिवृत्तित कर सकना सम्भव नहीं होता

१९०५ में चीन की प्रानी परीक्षा पद्धति का अन्त कर देने के लिये आज्ञा जारी

था। विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके जो लोग इस समय चीन में वापस आ रहें थे, वे सरकारी कर्मचारियों की संकीर्ण मनीवृत्ति को अनुभव करते थे और इसी कारण १९०५ में सिंदयों पुरानी परीक्षापढ़ित का अन्त किया गया और अब उन लोगों के लिये चीन में सरकारी पद प्राप्त करना सम्भव हो गया, जो प्राचीन ग्रन्थों में अपरि-चित होते हुए भी नये ज्ञान-विज्ञान से भलीभांति परिचित थे। बीसवीं सदी के गुरू में चीन के नवयुवकों में यह प्रवृत्ति बहुत प्रवल हो गई, कि वे अमेरिका आदि विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करें।

रूस-जापान के युद्ध में जापान के विजयी होने पर चीन में सुघारवादी आन्दो-लन को बहुत बल मिला। यदि जापान नये ज्ञान विज्ञान को अपनाकर और अपने देश के शासन को आधुनिक ढंग पर संगठित करके इतना शिवतशाली हो सकता है, कि रूस जैसे विशाल और यूरोपियन देश को परास्त कर सके, तो क्या कारण है, कि चीन भी उसी के मार्ग का अनुसरण कर अपने को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त नहीं कर सकता—यह विचार चीन के लोगों में बहुत प्रबल हो गया। साम्राज्ञी त्सू ह्सी और उसके पार्श्वचर भी इस विचार से प्रभावित हुए और इसी कारण उन्होंने शासन के प्रकार में सुधारों का प्रारम्भ किया। १९०५ में एक मिशन इस उद्देश्य से पाश्चात्य देशों में भेजा गया, कि वह वहां के विविध देशों की शासन पद्धतियों का अनुशीलन कर यह प्रस्तावित करे, कि चीन की दशा और परिस्थित के अनुसार कौन से सुधार उसके लिये उपयोगी हैं।

शासन सम्बन्धी सुधार-१९०८ में पेकिंग की मञ्चू सरकार ने एक घोषणा हारा उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार वह चीन में शासन सुधार करने के लिये तैयार है। ये सिद्धान्त निम्नलिखित थे--(१) मञ्चू राजवंश की सत्ता और शक्ति की अक्षुण्ण रखा जावे। शासन में जो भी सुवार किये जावें, वे सम्राट् की इच्छानुसार व उसी की आज्ञा से हों। मञ्चू राजवंश का शासन चीन में सदा स्थिर रहेगा और उसके आधिपत्य व अधिकारों में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने पावेगी । (२) सुधार धीरे-धीरे किये जावें । पहले प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो, पुलिस का पुनः संगठन किया जाय, देश के कानूनों को व्यवस्थित किया जाय, बाकायदा जनगणना की पद्धति जारी की जाय, और शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न हो। चीनी सरकार के लिये वाकायदा बजट तैयार करने की व्यवस्था हो और सरकारी आय-बाद को निविधन रूप ने प्राटिट किया जामा करे। (३) जब इन सुधारों द्वारा चीन की सरकार का नंगठन गुच्यवन्यित हो जाय, ये। बाद में एक पालियानेन्ट की स्थापना की जात । ताथ ही चीप में एक मन्त्रिपरिषद् बनाई जाय, जिसके हाथ में देश के काबुनों को किया में परिणत करने का कार्य हो ! (४) प्रत्येक प्रान्त में विधान समायें स्थापिन की आवें, जिनके नवस्य जनता द्वारा निर्वाचित हुआ करें । पाकियामैन्ट की स्थापना ने पूर्व प्रान्तों में विधाप समाओं

का संगठन कर लिया जावे और सब शासनसुधार इतने समय में पूर्ण कर लिये जावें, कि नौ साल (१९१७) तक पेकिंग में पालियामेन्ट की स्थापना सम्भन हो सके।

साम्राज्ञी त्सु र मी द्वारा कासन सुवार की जिस नीति का प्रतिपादन किया गया था, उसके अनुसार कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १९०९ मे चीन में पहली बार प्रान्तों की विधानसभाओं की रचना की गई। इन सभाओं के सदस्य चनने के लिये बोट का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था। विधान समाओं की शक्ति को भी बहुत मर्यादित रखा गया था। उन्हें यह अधिकार नहीं था, कि सरकार के कार्यों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण एवं मकें। उनका कार्य केवल यह था, कि प्रान्त के सूबेदार की ओर से जो विषय विचार के लिये पेश किये जावें, उन पर बहस करें और अपने विचारों से सूचित करें। मञ्चू सरकार की दृष्टि में उनका प्रयोजन केवल यह था, कि उन द्वारा जनता की सम्मति और विचारी का शासकवर्ग को परिचय मिलता रहे । पर चीन की जनता में इस समय इतनी अधिक जागृति हो चकी थीं, और लोकतन्त्र की भावना उनमें इतनी प्रवल हो गई थी, कि प्रान्तों की विधानसभाओं के सदस्यों ने सरकार की आलोचना प्रारम्भ कर दी और इस बान का प्रयत्न किया. कि पाश्चात्य देशों की विधानसभाओं के समाग चीन की ये विधान सभाएं भी सरकार की शासननीति और कार्यों पर नियन्त्रण रखें। यही कारण है, कि जब तीन साल बाद चीन में राज्यकान्ति हुई, तो विविध विधान-सभाओं के बहसंख्यक सदस्यों ने उसका स्वागत किया।

ें साम्राझी त्सू ह्सी की मृत्यु — प्रान्तों में विवानसभाओं की स्थापना से पूर्व ही सम्राट् कुआंग ह सू की मृत्यु हो गई थी। हम पहले लिख चुके हैं, कि यह सम्राट् साम्राझी (राजमाता) त्सू ह सी हारा कैंद में डाल दिया गया था, और राजप्रासाद में ही एक कैंदी के समान जीवन व्यतीत कर रहा था। असली शासन शांकत त्सू ह सी के हाथों में थी। कुआंग ह सू की मृत्यु के कुछ देर बाद ही त्सू ह सी की भी मृत्यु हो गई। मरने मे पूर्व साम्राज्ञी ने इस बात की व्यवस्था कर दी थी, कि मञ्चू राजसिंहासन पर अब कीन व्यक्ति आखड़ हो। नया सम्राट् ह सूआन तुंग अभी बालक ही था, अतः शासन कार्य का संचालन प्रिस चुन के हाथों में आया, जो कि प्रतिभू (रीजेन्ट) के तौर पर चीन का शासन करने के लिये प्रवृत्त हुआ। मृत्यु से पूर्व सम्राट् कुआंग ह सूने यह इच्छा प्रकट की थी, कि युआन शी कार्द को प्राणवण्ड दिया जाय। १८९८ में युआन शी कार्द ने साम्राजी त्सू ह सी का पक्ष लेकर कुआंग ह सू के साथ जो विश्वासघात किया था, उसके कारण उसके हृदय में युआन शी कार्द की प्रति उग्र विदेश की मावना विद्यमान थी। प्रिस चुन ने दिवंगत सम्राट् की

इच्छा को पूर्ण करने के लिये युआन शी काई को प्राणदण्ड तो नही दिया, पर उसे पदच्युत अवश्य कर दिया ।

राष्ट्रीय महासभा साम्राजी त्यु ह सी ने जिन शासनसुधारों का सूत्रपात किया था, प्रिस चन ने उनको जारी रखा। १९०९ में उसी के आदेश के अनुसार प्रान्तों में विधानसभाओं की स्थापना हुई थी। अक्टूबर, १९१० में सम्पूर्ण चीन के लिये प्रथम बार राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की गई। इसके आधे सदस्य केन्द्रीय सरकार हारा मनोनीत किये गये थे और लेन आधे सदस्य प्रान्तीय विधानसभाओं हारा निर्वाचित हुए थे। सरकार को आशा थी, कि महासभा के सदस्य उप्र विचारों के न होकर मञ्चू राजसत्ता के समर्थक होंगे। पर नये विचार चीन में इतने अधिक प्रवल हो चुके थे, कि राष्ट्रीय महासभा ने शासनसुधारों के लिये बड़ी प्रवलता के साथ भाग शुरू कर दी। उसने मांग की, कि चीन में जन्दी से जल्दी नये शासन - विधान का निर्माण किया जाना चाहिये और वहां ऐसी पालियामेन्ट की स्थापना होनी चाहिये, जो सरकार पर अपना नियन्त्रण रख सके। मन्त्रिमण्डल पालिया-मैन्ट के प्रति उत्तरदायी हो और बह तभी तक अपने पद पर रह मके, जब तक कि पालियामेन्ट के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास उन प्राप्त रहे। राष्ट्रीय महासभा ने सरकार के कार्यों और नीति की आलोचना करने में भी गंकोच नहीं किया।

यदि इस समय चीन की मञ्चू सरकार बुद्धिमता से कार्य करती, तो वहां राज्यकान्ति की आवश्यकता न होती। यूरोप के विविध राज्यों और जापान के समान वहां भी वैध राजसत्ता का विकाम होता और मञ्चू राजवंग देर तक चीन के राजसिंहासन पर आरूढ़ रह मकता। पर पेकिंग की सरकार को राष्ट्रीय महा-सभा का रख जरा भी पसन्द नहीं था। उसने जनना की भावनाओं की उपेक्षा की। इसी का यह परिणाम हुआ कि चीन में वैध राजसत्ता का विकास न होकर रिपब्लिक की स्थापना हुई।

(२) चीन की राज्यकान्ति

राज्यकान्ति के कारण—१९११ में चीन में राज्यकान्ति हो गई। मञ्चू राजवंदा का अन्त हुआ और रिपब्लिक की स्थापना की गई। इस राज्यकान्ति के प्रथा गारण थे. एम पर प्रकार तालने की आवश्यकाना है।

(१) आधिक युष्टि से चीन की जनका में घोर अधानि भी। वहां की आबादी गड़ी तेजी के साथ नई पड़ो घी। देख में यो लाख सामग्री उत्पन्न होती थी, वह जनता के लिये पर्याप्त नहीं थी। १८८५ में कीन की कुछ झावादी ३७,७०,००,००० थी। १९११ में वह बढ़कर ४३,००,००,००० हो मई थी। पनीस साल के समग्री

में चीन में छः वरोड़ मनुष्य बढ़ गये थे। इतने मनुष्यों के लिये खाद्य सामग्री क्या, ज्टा मकना तभी सम्भव था, जब कि पैदाबार में भी इसी अनुपात से बृद्धि हो । पर चीन में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज उत्पन्न करने का कोई प्रवन्य नहीं किया गया था। बढ़ती हुई आबादी को अपना निर्वाह कर सकना कठिन प्रतीत होता था है। इसके साथ ही दुभिक्ष और बाड़ों की प्रचुरता के कारण चीन में खेती को नुकमान भी क बहुत अधिक पहुंचा करता था। १९१०-११ में चीन की अनेक निदयों में भयंकर बाहें आई। इनसे न केवल खेती नष्ट हुई, अपित हजारों गांव भी वह गये । लाखों नर-नारी वे घर-बार हो गये और उनकी आजीविका का कोई भी साधन नहीं रह गया । अनुमान किया गया है, कि १९१०-११ ाहों के कारण तीस लाल के लगभग मन्ष्यों ने भूख के कारण तड़प तड़पकर जान दी। जब आर्थिक दृष्टि से जनता की इतनी दुर्दशा हो, तो यह स्वाभाविक है, कि उसमें विद्रोह की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। जनसंख्या की वृद्धि और सरकार की निर्वलता के कारण इस समय चीन में प्रायः हर साल ही दुर्भिक्ष पड़ते थे और बहुत से लोगों को पर्याप्त अम न मिलने के कारण मृत्य का शिकार बनना पड़ता था। इससे उनमें विद्रोह की प्रवृत्ति प्रवल होती जाती थी। १९१०-११ की बाढ़ों और दुर्भिक्ष ने इस प्रवृत्ति को और भी अधिक उग्र बना दिया था।

(२) अपने देश में आर्थिक दुर्दशा से परेशान होकर बहुत से चीनी लोगों ने इस समय आजीविका की तलाश में विदेशों में जाकर बसना प्रारम्भ कर दिया था । इारू में चीनी लोग संयुक्तराज्य अमेरिका में जाया करते थे। पर १८९० में वहां की सरकार ने चीनी लोगों के खिलाफ अनेक कानून स्वीकृत किये, और उनके लिये अमेरिका में जाकर वस सकने का मार्ग वन्द हो गया। पर फिर भी १९११ में संयुक्तराज्य अमेरिका में बसे हुए चीनी लोगों की संख्या तीन लाख के लगभग थी। अमेरिका में बस सकते का मार्ग जब चीनी लोगों के लिये बन्द हो गया, तो उन्होंने हवाई, फिलिप्पीन, मलाया आदि में जाकर बसना शुरू किया। हवाई और फिलि-प्पीन में भी उनके खिलाफ कानन स्वीकृत किये गये । मलाया में चीनी लोग ननी अधिक संख्या में आजीविका की तलाश में गये, कि १९११ में वहां उनकी ? ३,००,००० तक पहुंच गई । दक्षिणी अमेरिका के विविध देशों में भी चीनी छोग कुली का पेशा करने के लिये जाने लगे और प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा के अनुसार लाखें। चीनियों को वहां कुली या गुलाम के रूप में कार्य करने के लिये ले जाया गया 🗟 इतनी वड़ी संख्या में चीनियों का विदेशों में जाना इस बात को भलीभांति सचित करता है, कि इस समय चीनी लोगों की आधिक दृष्टि से कितनी दुर्दशा थी। पर चीनियों के इस प्रकार विदेश जाने का एक परिणाम यह भी हुआ, कि विदेशों में

बारा करनेवाले चीनी लोगों को नये विचारों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला है। यह वान चीन में कान्ति की भावना को विकसित करने में बहुत सहायक हुई। (३) क्रान्तिकारी दल चीन में पहले से विद्यमान था। पाश्चात्य देशों से उच्च क्षा प्राप्त कर जो लोग अपने देश को नापस आ रहे थे, ने यूरोप के जान विज्ञान साथ साथ वहां की क्रान्तिमयी भावनाओं को भी अपने साथ ला रहे थे। डा॰ सन यात सेन के नेतृत्व में जिस क्रान्तिकारी दल का संगठन चीन में हुआ था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुना है। १८९८ में इन क्रान्तिकारी लोगों को चीन छोडवर वाहर भागना पड़ा और डा॰ सन यात सेन ने जापान जाकर आश्रय लिया । को रहते हुए इस प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता ने अपने दल का पुनः संगठन किया और तुंभ मेंग हुई नाम से एक नये क्रान्तिकारी दल का निर्माण हुआ। इस दल के लोग भञ्च राजवंश का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना के पक्षपाती थे। शुरू में इस दल में वे चीनी लोग सम्मिलित हुए, जो विदेशों में बसे हुए थे। पर धीरे-बीरे चीन में भी इसकी शाखाएँ स्थापित हुई। सेना के सिपाहियों में भी यह दल अगना कार्य कर रहा था, और इसके प्रयत्नों से १९०६-१९०७ और १९१० में अनेक स्थानों पर विद्रोह भी हुए थे।

(४) १९०५ में चीन की प्राचीन परीक्षा पद्धति का अन्त कर दिया गया था। अब सरकारी पदों के लिये नियुक्ति करते हुए प्राचीन ग्रन्थों में नियुणता की अपेक्षा आधिनक शिक्षा की अधिक महत्त्व दिया जाने लगा था। चीन में अभी ऐसे उच्च शिक्षणालय पर्याप्त संख्या में नहीं स्थापित हुए थे, जिनमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की मुविधा हो । इसलिये १९०५ के बाद बहुत अधिक चीनी विद्यार्थियों ने यूरोप और अमेरिका जाना शुरू किया । जो लोग इतनी दूर उच्च शिक्षा के लिये जा सकते में असमर्थ थे, वे अपने पड़ोसी जापान के कालिओं में प्रविष्ट होने लगे। इस रामय तक जापान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों का समकक्ष हो गया था। १९०५ के बाद इतने अधिक चीनी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये जापान गये, कि वह[्] उनके लिये प्रवेश पा सकना कठिन हो गया । परिणाम यह हुआ, कि बहुत से ाट कालिज जापान में स्थापित हुए, जिनका उद्देश्य चीनी विद्यार्थियों की भरती कर राजा कमाना था। इनमें अधायन का संमृत्ति प्रबन्ध नहीं था, पर ्रात्रमें पढ़नेता है चीनी विधार्थी जहां नवे अन्त विज्ञान से शोड़ा। बहुत, परिचय प्राप्त कर ठेरी थे. वहां मध्य ही उन्हें कालियारी चीनी देए से नामके में आने का भी नुवर्णीय अवसर िङ जाता था । १८५८ में जो जीती कास्तिकारी नेता जापात में आधार ग्रहण करने के लिये विवश हुए थे, वे इन चीची विशाधियों में बड़े उत्साह से अपने निचारों का प्रधार कर रहे थे 🕒 🧢 🥏

- (५) छापेखाने का आविष्कार सबसे पूर्व चीन में ही हुआ था। पर चीन के ये पुराने प्रेम पहले केवल प्राचीन पुस्तकों के मुद्रण का ही कार्य किया करते थे कि उन्नीमवीं सदी के अन्तिम भाग में चीन में समाचार पत्रों का प्रकाशन भी शुरू हो गया था। ये समाचारपत्र जनता में नई भावनाओं को विकसिन करने और लोकतन्त्र शासन की स्थापना के लिये आन्दोलन करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे थे।
- (६) १९१२ की राज्यकान्ति के प्राद्रभवि में जहा ये सब आधारभूत कारण थे, वहा एक सामधिक समस्या ऐसी भी उत्पन्न हो गई थी, जिसने पैकिंग की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रान्तीय शासकों में विरोध भावना को विकसित कर दिया था । इस समय चीन मे रेलवे लाइनों का वडी तेजी के साथ निर्माण हो रहा था । पेकिंग मरकार में अनुमति लेकर अनेक विदेशी राज्य चीन के विविध प्रदेगों े रेलवे का निर्माण करने में तत्पर थे। इस दशा में चीन के अनेक प्रान्तों के सुब्बारों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि क्यों न वे अपने प्रदेशों में स्वयं रेलवे का निर्माण करें और इसके लिये आंबश्यक पूंजी अपने प्रान्त की राजकीय आगदर्ग हारा प्राप्त कर लें। पर इस सम्बन्ध में पेकिंग की केन्द्रीय सरकार की नीति यह थी, वि: रेल लाइनों का निर्माण केन्द्रीय शासन के नियन्त्रण में ही रहे । पेकिंग सरकार के पर पूंजी का अभाव था पर वह विदेशी राज्यों से कर्ज लेकर पूजी प्राप्त कर सकर 🦠 थीं । विदेशी लोग चीन में जिस प्रकार अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर के लिये उत्मुक थे, उसके कारण पेकिंग सरकार को पंजी का प्रवन्ध करने में किसी। विशेष कठिनाई का सामना करने की आवश्यकता नहीं थी। पर अनेक प्रान्तीयः मुखेदार चीन में निदेशियों के बढ़ते हुए प्रभूत्व को चिन्ता की दृष्टि से देख रहे थे और वे इस बात पर जोर दे रहे थे, कि उनके अपने प्रदेशों में रेलवे निर्माण का कार्य उन्हों ने मुपूर्व कर दिया जाय । इस विजय में केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में बहुत विरोध हुआ और यही कारण है कि १९११ की राज्यकान्ति के समय अनेक प्रान्तों ने कान्तिकारियों का साथ दिया। १९११ में आवागमन के विभाग का प्रधान अधिकारी क्षेंग हु सुअन-हआई को नियत किया गया । यह रेलवे लाइनों को केन्द्रीय सरकार के प्रमुत्त्व में रखने का प्रबल पक्षपाती था और इसने रेलये विस्तार के लिये पूंजी प्राप्त करने के लिये विदेशी राज्यों से कर्ज लेने की योजना की किया में परिणत किया । ब्रिटेन आदि विदेशी राज्यों से भारी रकम कर्ज ली गई 🗟 प्रान्तों में इससे बहुत अधिक असन्तोष हुआ और अनेक स्थानों पर विद्रोह प्रारम्भ हो गये।
- (७) जिस समय पेकिंग सरकार की नीति के दिश्क अनेक त्यानों पर विद्रोह शुरू हो गये थे, १० अक्टूबर, १९११ को हंको में एक योग्य फुट गया । अनुसन्धान

के बाद मालूम हुआ, कि जिस मकान में बॉम्ब फूटा था, वहां चीन के क्रान्तिकारी दल का बड़ा अड्डा था और वहां बॉम्ब आदि अस्त्र वड़ी माना में तैयार किये जाते ये। पुलिस ने हैंको के क्रान्तिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया और उनमें में बहुतों को प्राणदण्ड दिया। इस प्रदेश की सेना के भी अनेक अफसर व सैनिक क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित होने के सन्देह में गिरफ्तार किये गये। इससे सेना में बहुत असन्तोष हुआ। अन्य सैनिकों को भी यह सन्देह हुआ, कि कहीं उन्हें भी क्रान्तिकारी दल से सहानुभूति रखने के कारण गिरफ्तार न कर लिया जाय। परिणाम यह हुआ, कि यांगत्से नदी के पार ब्चांग प्रदेश की सेना ने विद्रोह कर दिया। अपने सेनानायक कर्नल ली युआन-हुंग को विद्रोही सैनिकों ने इस बात के लिये विवश किया, ि यह उनका नेतृत्व करे। आगे चलकर यह ली युआन हुंग क्रान्तिकारी चीन का का ५५ प्रधान नेता बन गया और अन्त में चीनी रिपब्लिक के राष्ट्रपित पद पर भी अधिष्ठित हआ।

अब चीन में राज्यकान्ति का प्रारम्भ हो गया था ।

राज्यकान्तिकी प्रगति-वृचांगकी सेना द्वारा सन् १९११ के अन्तिम सप्ताहीं 🤲 जो विद्रोह प्रारम्भ किया गया था, वह ची घ ही यांगत्से व उसके दक्षिणवर्ती घदेशों 🤊 फैल गया। कांतुंग और चिहली के प्रान्तों की सेनाओं ने भी पेकिंग ंरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । उत्तरी चीन की सेनायें मञ्चू सरकार के प्रति अनुरक्त रहीं, और विद्रोह में शामिल नहीं हुई । इन सेनाओं का संगठन युआन की काई द्वारा किया गया था और ये आध्निक ढंग पर संगठित थीं। यांगल्से के दक्षिणी प्रदेश कान्तिकारियों के साथ थे और उत्तरी चीन में मञ्चू शासन सूब्य-वस्थित रूप से स्थापित था । विद्रोही प्रदेशों में एक सुसंगठित क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना का भी उद्योग किया गया । इसी बीच में कान्ति की ज्वालाएं शंघाई तक पहुंच गई और वहां एक रचनना रिपटिलकन संस्कार का संगठन किया गया। इस सरकार में बिदेश मन्त्री का पर की वृतिक फांग ने शहल किया। ये सज्जन पहले संयुक्तराज्य अमेरिका में चीनी राजदूत के पद पर रह चुके थे और पाइचात्य राज्यों की शासन पद्धति से मलीमांति परिचित थे। इन्होंने एक उद्योषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें कान्तिकारी सरकार के उद्देश्यों अप्रेर कार्यक्रम का भलीभांति निरूपण किया गया और विदेशी राज्यों से शह अनुरोग किया कि वे पेकिन शास्त्रार हो किसी भी पंचार की सहायका म । हैं और चीन के इस अन्यक्ती अन्त पर सर्वया उदासीन पीति का अनुत्तरण गरें । इस उदघीनणापत्र में यह बात भी स्थप्ट कर दी गई थी, कि यदि इस समय विदेशी राज्यों ने पेविस सरकार की आधिक सहायसा

करने के उद्देश्य से उसे कोई ऋण दिया, तो चीन की रिपब्लिकन सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी।

जब चीन के बिविध प्रान्तों में विद्रोह की अग्नि भड़क रही थी, पेकिंग में राष्ट्रीय महासभा शासन सुधार के लिये नई नई मांगें पेश करने में तत्पर थी। २२ अक्टबर. १९११ को राष्ट्रीय महासभा का नया अधिवेशन शरू हुआ। इसने मांग की कि शोंग ह सुअन हआई को अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाय। आवागमन विभाग के प्रधान अधिकारी की स्थिति में इन सज्जन ने विदेशी पंजी को प्राप्त कर केन्द्रीय सरकार की ओर से रेलवे विस्तार की जिस नीति का अनसरण किया था, उससे जीन के विविध प्रान्तों में घोर असन्तोष विद्यमान था। शेंग ह सुअन हुआई को अपने पद से पृथक् कर दिया गया। नि:सन्देह, यह लोकमत की भारी विजय थीं। अब राष्ट्रीय महासभा ने मांग की, कि चीन में मन्त्रिमण्डल की बाकायदा स्थापना होनी चाहिये। इस मन्त्रिमण्डल को निर्माण करने का कार्य किसी ऐसे सुयोग्य नेता को सूपूर्व करना चाहिये, जिस पर जनता को विश्वास हो। राज परि-द्वार का कोई भी व्यक्ति मन्त्रिमण्डल में नहीं होना चाहिये और शीघ्र ही चीन में नये शासनविधान का निर्माण किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय महासभा की एक भाग यह भी थी, कि जिन लोगों को किसी राजनीतिक अपराध के कारण गिरफ्तार 🗇 किया गया है, व जिन्हें देश से बहिष्कृत किया गया है, उन सबकी क्षमा प्रदान की जाय । पेकिंग की मञ्जू सरकार राष्ट्रीय महासभा की इन सब मांगों को स्वीकृत करने के लिये विवश हुई। सेना में सर्वत्र जिस प्रकार विद्रोह हो रहे थे, उसकी उपेक्षा कर सकना अव सम्भव नहीं रहा था। नवम्बर, १९११ के शुरू में मञ्चू 'सम्राट की ओर से इन सब मांगों को स्वीकृत कर लिया गया।

पर चीन के विविध प्रान्तों में कान्तिकारी लोगों के विद्रोह जो गम्भीर रूप धारण कर रहे थे, उनको उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था। इस समय चीन की सबसे बड़ी आवश्यकता यह थी, कि शासनसूत्र का संचालन किसी ऐसे सुयोग्य व शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में दिया जाय, जो अव्यवस्था और विद्रोह का शमन कर शान्ति स्थापित करने में समर्थ हो। अब यह कार्य युआन शी काई के सुपुर्द किया गया और उससे यह प्रार्थना की गई, कि वह पेकिंग सरकार के संचालन का कार्य अपने हाथों में ले ले। ८ नवम्बर, १९११ को राष्ट्रीय महासभा ने युआन शी वाई को प्रधान गन्त्री निर्याचित किया और स्थल व जलसेना के प्रधान सनापति का कार्य भी उसी के सुपूर्व कर दिया गया।

विध राजसत्ता की स्थापना का उद्योग—युआन की काई मञ्जू राजवंश की सत्ता की पक्षपाती था। असव की गति की रेखणर उसने निक्तय जिया, कि चीन में वैध राजसत्ता की स्वापना द्वारा ही मञ्चू राजवंश की सता को कायम रक्षा जा सकता है। पर मञ्चू राजवंश को इस बात के लिये तैयार कर सकना सुगम नहीं था, कि बहु अपनी शिवत और अधिकारों का परित्याग कर उस स्थिति को स्वीकार कर ले, जो इङ्गलैण्ड में राजा की थी। अतः युआन शी काई ने अनुभव किया, कि विशेष्टियों को अपने प्रयत्न में सफल होने देना देश के लिये हितकर है। यदि क्रान्तिकारी लोग निरन्तर प्रवल होते जावेंगे, तभी मञ्चू राजवंश के लोग यह समझ सकेंगे, कि उन्हें भी समय के साथ साथ वदलना चाहिये और चीन में वैध राजसत्ता की स्थापना की जानी चाहिये। पर साथ ही युआन शी काई यह भी अनुभव करता था, कि यदि क्रान्तिकारी लोग अधिक प्रवल हो जावेंगे, तो उनको मञ्चू राजवंश की सत्ता के स्थीकृत करने के लिये मनवा सकना असम्भव हो जायगा। इस प्रकार युआन शी काई एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में इस बात का प्रयत्न कर रहा था, कि न क्रान्तिकारी लोग अधिक प्रवल होने पावें और न ही मञ्चू राजवंश यह अनुभव कर सके, कि उसकी शिवत बहुत प्रवल है। उसकी सेनाओं ने अनेक स्थानों पर क्रान्तिकारी सेनाओं का डटकर मुकाबला किया और क्रान्तिकारी ने ताओं को इस बात के लिये विवश किया, कि वे उसके साथ समशौतम करने का उद्योग करें।

(३) रिपब्लिक की स्थापना

सामयिक रिपब्लिकन सरकार की स्थापना—युआन शी काई की इसी नीति के कारण जहां पेकिंग की सरकार एक तरफ क्रान्तिकारियों के विरुद्ध सैन्यशिक्त का प्रयोग कर रही थी, वहां साथ ही वह कर्नल ली युआन हुंग के साथ समझौते की बातचीत में भी तस्पर थी। ली युआन हुंग सिन्ध की बातचीत के लिये तैयार था, पर शंघाई में स्थित क्रान्तिकारी सरकार ने इस बात पर जोर दिया, कि समझौते की बातचीत उसी के साथ की जाय। कर्नल ली युआन हुंग ने भी इस बात को स्वीकार किया, कि क्रान्तिकारी लोगों से सुलह करने के लिये शंघाई की सरकार से बातचीत करना ही अधिक उपयुक्त है। युआन शी काई ने अपनी ओर से ताग-शाओ-यी को समझौते की शर्ते तय करने के लिये नियत किया। शंघाई की सरकार की ओर से बात वृतिग फांग को अपना प्रतिनिध्व बनागा गया। ये दोनों सज्जन कैन्टन के तियानं शे और उन शानों की उच्च शिक्षा अमेरिया में हुई थी। जिस सम्य गांकिंग की गज्ज गरकार और रांगाई की क्रान्तिकारों सरकार में परस्थर समझौते की बातचीत जारी थी, विविध कान्तिकारी नेताओं ने यह निश्चप विगात कि परस्थर मिलतर रिपब्लिकन सरकार का याकायदा संगठन कर छैं। कर्नल की परस्थर मिलतर रिपब्लिकन सरकार का याकायदा संगठन कर छैं। कर्नल की युआन हुंग की प्रेरणा से विविध क्रान्तिकारी नेता नार्निका में एकत्र हुए। इन

नेताओं का चुनाव या तो क्रान्तिकारी सेनाओं द्वारा किया गया था और या प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा । चीन के जिन प्रान्तों ने पेकिंग की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके क्रान्तिकारियों का साथ दिया था, उनकी प्रान्तीय विधानसभाएँ पूर्ण उत्साह से क्रान्तिकारी रिपब्लिकन सरकार की स्थापना में सहयोग दे रही थीं। नानकिंग में जिस सामयिक रिपब्लिकन सरकार का संगठन हुआ, उसमें राष्ट्रपति पद के लिये डा॰ सन यात सेन को निर्वाचित किया गया । १८९८ में डा॰ सन यात सेन चीन छोड़कर जापान चले जाने के लिये विवश हुए ये और इस समय में अमेरिका में निवास करते हुए वहां के प्रवासी चीनी लोगों में कान्ति की भावना को विकसित करने में तत्पर थे। १९११ की क्रान्ति को उन्होंने अपने स्वप्नों की चरितार्थ कर सकते का उपयक्त अवसर समझा और वे चीन वापस लौट आये। २९ दिसम्बर, १९११ के दिन उन्हें सामयिक रूप से चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और १ जनवरी, १९१२ को उन्होंने अपने पद के कार्यभार को संभाल लिया । नानिकंग की इस सामयिक रिपब्लिकन सरकार के संगठित हो जाने के कारण क्रान्तिकारियों की शक्ति बहुत बढ़ गई। इस क्रान्तिकारी सरकार में नव-जीवन और शक्ति थी । इसके विपरीत मध्य सरकार की दशा अत्यन्त विकृत और निर्वल थी।

समझौते की बातचीत--डा० वु तिंग फांग और तांग-शाओ-यी में समझौते की जो बातचीत चल रही थी, वह तभी सफल हो सकती थी, जब पहले इस बात का फैसला हो जाय कि चीन में शासन का प्रकार क्या हो । इसके लिये यह प्रस्ताव पेश किया गया, कि शासन के प्रकार का निर्णय करने का कार्य एक संविधान परिषद् के सुपूर्व कर दिया जाय, जिसके सदस्य जनता के वोटों द्वारा निर्वाचित हों। पर लोकमत द्वारा संविधान परिषद् के निर्माण के प्रश्न पर दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। कान्तिकारी सरकार के प्रतिनिधि डा० वृ तिग-फांग ने इस बात पर जोर दिया, कि मुञ्चू राजवंश के नेतृत्व में चीनी राष्ट्र को उन्नत कर सकना असम्भव है। मञ्चू दरबार इतना अधिक विकृत हो चुका है, कि उसमें नवजीवन का संचार कर सकना सुगम बात नहीं है। श्री तांग शाओ-यी ने भी इस बात को स्वीकार किया । दोनों पक्ष इस समय समझौते के लिये उत्सुक थे, कारण यह कि किसी के पास भी युद्ध को जारी रखने के लिये इस समय पर्याप्त घन नहीं था। विदेशी राज्यों ने परस्पर मिलकर यह फैसला कर लिया था, कि वे किसी भी पक्ष की आर्थिक सहायता नहीं करेंगे। मञ्चू सरकार का खजाना खाली हो चका था और युआन शी काई ने मञ्चू सम्राट् के घरेल् कोष से भी घन प्राप्त करने में संकोच नहीं किया था। नानिकंग की रिपब्लिकन सरकार के पास जो कुछ भी धन था, वह या तो जनता से चन्दा एकत्र कर और या प्रान्तों की राजकीय आमदनी दूरा प्राप्त किया गया था। यह धन इतना नहीं था, कि युद्ध को देर तक चलाया जा सके। इस अवस्था में दोनों पक्षों ने इसी बात में अपना हिन समझा, कि युद्ध को बन्द कर आपस में सुलह कर ली जाय।

समझौते की शर्ते—१२ फरवरी, १९१२ को युआन शी काई और डा० सन यात सेन की सरकारों ने परस्पर समझौता कर लिया। इसकी मुख्य शर्ते निम्न-लिखित थीं—(१) मञ्चू राजवंशका अन्तकर दिया जाय। सम्राट् ह् सुआन तुंग (उसकी आयु इस समय केवल छः साल की थी) जीवन पर्यन्त सम्राट् की पदवी का प्रयोग कर सके, राजप्रासाद पर उसका बच्जा रहे और जीवन भर उसे एक अच्छी बड़ी धनराशि वाषिक रूप से राज्यकोष मे प्राप्त होती रहे। मञ्चू राजकुल की जो समाधियां हैं, उनकी रक्षा का भार राज्य पर रहे। (२) मञ्चू वंश की राजरात्ता की समाप्ति पर चीन में नई सरकार की स्थापना का कार्य युआन शी काई के सुपूर्व किया जाय।

चीन के लोगों ने इस समझौते को स्वीकार कर बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य किया। ,भञ्चु राजवंश ने स्वयं अपने राजसिंहासन के परित्याग की बात स्वीकार कर अपने गौरव और प्रतिष्ठा को कायम रखा । यदि मंचू लोग समय की लहर के विषद्ध कान्ति की प्रवृत्तियों का मुकाबला करने का प्रयत्न करते, तो उनकी भी वही गति होती, जो कि फांस के बूर्वी राजवंश की हुई थी। सम्राट् की ओर से ही एक घोषणा १२ फरवरी, १९१२ के दिन प्रकाशित की गई, जिसमें यह कहा गया था-"युआन शी काई को हम यह अधिकार देते हैं, कि वह सामयिक रिपब्लिकन सरकार का संगठन करे और देश में एकता की स्थापना के लिये रिपब्लिक की सेना का सहयोग है। यही एक ढंग है, जिससे फिर से जनता में शान्ति और साम्राज्य में व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। जिस प्रकार अब तक मञ्चु, चीनी, मंगोल, मुसलिंग और तिब्बतन लोग एक साम्राज्य में शान्ति के साथ रहते रहे हैं, वैसे ही भविष्य में भी वे परस्पर मिलकर एक विशाल चीनी रिपब्लिक में निवास करें।" डा॰ सन यात सेन ने शुरू में सम्राट् की इस घोषणा का विरोध किया। उसका कहना था, कि सम्राट् की आजा द्वारा जो रिपब्लिक स्थापित होगी, वह जनता को किसी भी किंगा में स्वीकार्य नहीं होगी। पर युआन शी काई ने उसे विख्यास दिलाया, कि इस घोषणा द्वारा उसे जो विशेषाधिकार आप्त हुए हैं, उनका वह दुरायीग नेहीं फरेमा और यह चीन में जनता हारा रिपव्लिक की स्थापना में पूर्णसप से सहयोग देगा ।

युआन भी काई के साथ समजीता करने के लिये डा॰ पन बात रीन ने राष्ट्रपति

पद से त्यागपत्र दे दिया और नानिका में एकत्रित कान्तिकारी नेताओं ने युआन की काई को सामयिक चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपति निर्याचित कर लिया। इस्क प्रकार पेकिंग और नानिका की सरकारों में परस्पर समझौता हुआ। पर यहां यह ध्यान में रखना चाहिये, कि कान्तिकारी चीनी नेता युआन की काई को दिल से नहीं चाहते थे। उनका बिचार था, कि वह वस्तुतः रिपब्लिकन शासन का पक्षपाती नहीं है। पर युआन शी काई से समझौता करने का केवल यही उपाय था, कि उसे चीनी रिपब्लिक का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाय। अन्यथा वह उत्तरी चीन की सैन्यशक्ति का उपयोग कर कान्तिकारी लोगों से युद्ध को जारी रखने के लिये तैयार था। पर नानिका की रिपब्लिकन सरकार के पास धन की शक्ति का सर्वथा अभाव था और उसके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह उत्तरी सेनाओं के साथ संघर्ष को जारी रख सके।

इस प्रकार चीन से मञ्चू वंश के शासन का अना हुआ। सतरहवीं सवी के मध्य भाग में मञ्चू विजेताओं ने जिस शासन का चीन में प्रारम्भ किया था, अब उसकी समाप्ति हो गई और चीन में रिपब्लिक सरकार की स्थापना हो गई। एशिया के विशाल महाबीप में यह पहली रिपब्लिक थी, जो बीसवीं सदी के शुक्त में चीन में स्थापित हुई थी। जापान ने अपना उत्कर्ष करते हुए राजसत्ता की कायम रखा था। इसी कारण उसके शासन विधान का विकास प्रशिया, ब्रिटेन आदि उन देशों के ढंग पर हुआ, जिनमें राजा की सत्ता को कायम रखा गया था। पर चीन ने कान्तिकारी फांस का अनुसरण किया और राजसत्ता का सदा के लिये अन्त कर लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना की। निःसन्देह, न केवल चीन के अपितु सम्पूर्ण एशिया के इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी।

विविध विदेशी राज्यों ने युआन शी कोई के नेतृत्व में स्थापित रिपब्लिकन सरकार को स्वीकार कर लिया और चीन की राज्यकान्ति सफल हो गई।

(४) रिपब्लिक की समस्याएं

चीन में मञ्चू राजवंश का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी, पर इससे चीन की समस्याओं का अन्त नहीं हो गया था। इस समय चीन को अनेक विकट समस्याओं का मुकाबला करना पड़ रहा था। इनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख अगले चीनी इतिहास को समझने के लिये अत्यन्त उपयोगी है—

(१) अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्ति—चीन बहुत विशाल देश हैं। मञ्ज्यू राजवंश सम्पूर्ण चीन में शासन करने में समर्थ था। इसका कारण यह था, कि पेकिंग की केन्द्रीय सरकार प्रान्तों के शासन पर नियन्त्रण रखने के लिये निग्नलिखा उपायों का प्रयोग करती थी—(१) प्रान्तों में उच्च अधिकारियों की नियुवित के समय इस बात का ध्यान रखा जाता था, कि वे उस प्रान्त के निवासी न हों। (२) कितने बाल के लिये वे प्रान्त में रहेंगे, इसकी अविध नियत होती थी। (३) केन्द्रीय सर्कार विविध राजपदाधिकारियों को समय के साथ साथ अधिकाधिक उच्चे पदों पर नियुक्त करती जाती थी। इसका परिणाम यह होता था, कि विधिध अधिकारी अपनी तरक्की के लिये केन्द्रीय सरकार के आदेशों का पालन करने के लिये उत्सुक रहते थे। (४) प्रान्तों में जो सेनाएँ केन्द्रीय सरकार की अधीनता में रखी जाती थीं, उनके सेनानी भी केन्द्र द्वारा ही नियुक्त होते थे। प्रान्तीय सेनाओं के ये सेनानी सुवैदार की शक्ति को मर्यादित करने में बहुत सहायक होते थे।

पर बीसवीं सवी के प्रारम्भिक भाग में जब चीन के अनेक प्रदेशों में विद्रोह और अव्यवस्था की प्रवृत्ति प्रवर्ण हो गई थी, तब समय की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर अनेक प्रान्तीय सूबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रों में नई सेनाओं का संगठन कर लिया था। शुरू में इन सेनाओं का यह प्रयोजन था, कि वे शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के कार्य में प्रान्त की पुलीस को सहायता दें। इन सेनाओं की प्रान्तीय कामदनी में से वेतन दिया जाता था और ये प्रान्त के सुवेदार को ही अपना स्वामी ैसमझती थीं। १८९८ में जब चीन में सुधारवादी और कान्तिकारी नेताओं के आन्दोलनों के कारण अनेक प्रदेशों में विद्रोह और अञ्चान्ति की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, तो अनेक प्रान्तीय सुबेदार अपनी इन सेनाओं में बृद्धि करने के लिये विवश हुए। १९११ के क्रान्तिमय साल तक प्रान्तीय सेनाएँ निरन्तर बढती गई और रिपब्लिक की स्थापना के समय तक यह दशा आ गई थी, कि अनेक प्रान्तों में इस प्रकार की विशाल सेनाएँ विद्यमान थीं, जिनकी सहायता से प्रान्तीय सुवेदार केन्द्रीय सरकार की बहुत सुगमता से उगेक्षा कर सकते थे। राष्ट्रपति युआन शी काई ने १९१२ में रिपब्लिक के शासनसूत्र को हाथों में लेकर इसी बात में श्रेय समझा, कि इन शक्ति-शाली सुबेदारों को अपने अपने पद पर कायभ रखा जाय। राजसत्ता के अन्त के वाद उसके सम्मुख इतनी विकट समस्याएँ उपस्थित थीं, कि प्रान्तों में व्यवस्था स्थापित रखने का उसे यही उतान नगर व कियात्मक प्रतीन होता था, कि जो सुबेदार जिस प्रदेश में अवना प्रभुत्य स्थापित तिये हुए हैं, उसे नहीं पर रहने दिया ्रेनाय, ताकि यह अपने प्रदेश में जातित आर व्यवस्था को कायर एके रहे । पर इस बात का यह परिणाम अवस्थानमादी था, कि विविध सुप्रेतार अपने अपने भेन में स्वतन्त्र आचरण दार्ग अमें और केन्द्रीय सरकार भी जोजा करें । प्रान्तों में इस प्रकार की शक्ति। गार्टा रोनाएँ विद्यमान भी, जो प्रान्तीय वृवेदार से बेतन प्राप्ता करती थीं, और उसी को जन्म स्वामी मानवी थीं । जतः स्वामाविक रूप से उस सूबेदारों में यह प्रवृत्ति विकसित हुई, कि वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण करने छों और केन्द्रीय सरकार की निर्वछता से छाम उठाकरू, अपनी शक्ति के विस्तार में प्रवृत्त हों।

- (२) रिपब्लिक के पक्षपातियों और युआन शी काई में विरोध—डा० सन यात सेन और उसके साथी क्रान्तिकारियों ने युआन शी काई को रिपब्लिक का राष्ट्रपति बनाना समझौते के तौर पर स्वीकार किया था। वे भलीभांति जानते थे, कि युआन शी काई वस्तुतः क्रान्ति और रिपब्लिक का पक्षपाती नहीं है। इसीलिये वे हृदय से उसकी सरकार के समर्थंक नहीं थे। नानिका की राष्ट्रीय महासभा के बहुसंख्यक सदस्य युआन शी काई के विरोधी थे और बाद में जब चीन में पालियामेन्ट की स्थापना हुई, तो उसकें भी राष्ट्रपति का विरोधी दल बड़ा प्रबल था। राष्ट्रपति और पालियामेन्ट के इस विरोध के कारण चीन में रिपब्लिक के शासन को सफलता नहीं हो सकी। शीघ ही वहां विविध राजनीतिक नेताओं और सुवेदारों में परस्पर संघर्ष का प्रारम्भ हो गया।
- (३) जनता में जागृति का अभाय-चीन में राज्यकान्ति सफल हो चुकी थी और मञ्जू राजवंश के शासन का अन्त हो गया था। पर रिपब्लिकन शासन तभी सफल हो सकता था, जब जनता में जागृति हो, उसमें राष्ट्रीयता की भावनी भलीमांति विकसित हो चुकी हो और लोग अपना शासन स्वयं करने के लिये कटिनद्ध हों। पर चीन की बहुसंख्यक जनता अभी सर्वथा निरक्षर थी। शिक्षित लोगों की बहुसंख्या भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपरिचित थी। प्राचीन ग्रन्थों और धर्मशास्त्रों में निष्णात होते हुए भी वह नवयुग की भावनाओं को विशेष महत्त्व नहीं देती थी। यूरोप के विविध देशों में भी जब एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता का अन्त होकर लोकतन्त्र शासनों की स्थापना हुई, तो उन्हें सफल होने में बहुत समय लगा। फांस में वर्वो राजवंश का अन्त होकर जब पहली बार रिपब्लिक की स्थापना हुई, तो वह शीघ्र ही नैपोलियन के आधिपत्य के रूप में परिणत हो गई। नैपोलियन के पतन के बाद (१८१४) फिर बुर्बो वंश के एकतन्त्र राजा को फांस की राजगही पर विठाया गया । १८३० और १८४८ में फिर फेञ्च कान्तिकारियों ने रिप्रिक्लिक की स्थापना के लिये प्रयत्न किये। पर दोनों बार लुई फिलिप्प (१८३०) और नैपोलियन तृतीय (१८५२) राजसत्ता की स्थापना में समर्थ हुए। फ्रांस में रिप्क विलक्त शासन १८७० में सफल हो सका । तीन चौथाई सवी के लगभग तक फांस में नई और पुरानी प्रवृत्तियों में संघर्ष हुआ। इसी प्रकार की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जर्मनी आदि में भी हुई। इस दशा में यह कैसे आशा की जा सकती थीं, कि चीन में कान्तिकारी प्रवृत्तियां एकदम सफल हो जातीं । जनता में राष्ट्रीय भावना का अभाव

और लोकतन्त्र शासन के प्रति उत्साह की कमी के कारण चीन की नई रिपब्लिक को बहुत सी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा। चीन में नई और पुरानी प्रवृत्तियों का यह विरोध निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुआ—(१) यूआन शी काई ने रिपब्लिक का अन्त कर स्वयं सम्राट् बनने का प्रयत्न किया। उसका यह प्रयत्न ठीक उस प्रकार का था, जैसे कि फांस में नेपोलियन ने रिपब्लिक का अन्त कर अपने का सम्राट् बना लिया था। (२) कुछ लोगों ने मञ्चू राजवंश की सत्ता का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। कुछ दिनों के लिये इस प्रयत्न में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। (३) प्रान्तीय सूबेवार अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होने की कोशिश करने लगे। केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सूबेदारों के इस संघर्ष के कारण कुछ समय के लिये चीन की शासनशक्ति बहुत अधिक निर्बल हो गई।

(४) आधिक दुर्दशा--जिन आधिक कारणों ने चीन में ग्राज्यकान्ति का सत्रपात किया था, रिपब्लिक की स्थापना से वे एकदम दूर नहीं हो गये थे। अब भी चीन की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। व्यावसायिक उन्नतिका वहां अभाव था। खेती द्वारा इतनी खाद्य सामग्री उत्पन्न नहीं हो सकती थी, कि जनता अपना ्रनिवहि भलीभांति कर सके । बाढ़ और दुर्भिक्ष आदि के कारण देहातों में निवास करनेवाली सर्वसाघारण जनता पहले के समान ही परेशान रहा करती थी। चीन के विदेशी व्यापार पर विदेशी लोगोंने जिस प्रकार अपना प्रमुख स्थापित कर रखा था, उसमें अब भी किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया था। चीन की राजकीय आमदनी के अनेक साधनं विदेशी राज्यों के पास जमानत के रूप में रखे हुए थे। सरकार को इतनी आमदनी नहीं थी, कि वह अपने साधारण खर्च को भी सुचार रूप से चला सके । इस दशा में यह आशा कैसे की जा सकती थी, कि वह देश की आर्थिक उन्नति के लिये धन का प्रवन्ध कर सके। आर्थिक द्रवंशा के कारण चीनकी जनता में जो वेचैनी और अशान्ति कान्ति से पहले थी, वह अब भी वैसे ही विद्यमान थीं। जनता में असन्तोष की भावना इसलिये और भी अधिक विद्यमान थी, क्योंकि मञ्च शासन के विरुद्ध कान्ति के समय क्रान्तिकारी नेताओं ने जनता की सहा-नुभृति प्राप्त करने के लिये उमे अनेक प्रकार के आख्वासन दिये थे। सर्वसाधारण लोगों का खयाल था, कि गजन गानन का अन्त हो जाने के बाद दैक्सों की मात्रा चिंहत कम हो जायगी और जनता पर सरकारी नियन्त्रण भी बहुत कम हो जायगा। अब जब कि रिपब्लिक की स्थापना हो जाने के बाद भी पहले के समान ही दैक्स लगते थे, पहले की तरह ही सरकारी कर्मचारी अपराधियों को गिरफ्तार करते थे और शासनसूत्र पहले से भी अधिक सुदढ़ करने का प्रयत्न किया जाता था, तो जनता में असन्तोष का नदना सर्नथा स्यामायिक था। यदि चीन की नई

मरकार इस समय ऐसी स्थित में होती, कि जनता की आधिक रामृढि के लिये नई योजनाओं को किया में परिणत कर सकती, तो चीन में ऐसे समझदार लोगों की कमी नहीं थी, जो नई सरकार से संतुष्ट होते । पर सरकार के पास रुपये की बहुत कमी थी । टैक्सों हारा राजकीय आमदनी को बढ़ा सकना सम्भव नहीं था । विदेशी राज्यों से कर्ज लेकर ही सरकार अपनी आधिक कठिनाइयों को हल कर सकती थी । पर विदेशों से कर्ज लेने का एक ही परिणाम हो सकता था, वह यह कि चीन पर विदेशों प्रभुत्व में और अधिक वृद्धि हो जाय। पर यह बात भी रिपब्लिक के नेताओं को स्वीकार्य नहीं थी । युआन शी काई ने जब विदेशों से कर्ज लेने का प्रयत्न किया, तो उसका बहुत विरोध हुआ । जनता की आर्थिक दुर्दशा में सुधार कर सकना चीन की नई सरकार के सम्मुख एक बहुत ही विकट समस्या थी और इसे हल कर सकने का कोई गुगम उपाय उसको समझ नहीं आता था ।

आठवां अध्याय

चोन में रिपब्लिक का शासन

(१) प्रथम रिपब्लिकन सरकार

मञ्जू राजवंश का अन्त होने के बाद श्री. युआन शी काई के राष्ट्रपितित्व में चीन की प्रथम रिपब्लिकन सरकार का संगठन हुआ। पर नानिकण की जिस सामियक रिपब्लिकन सरकार ने समझौते द्वारा युआन शी काई को चीन का राष्ट्रपित स्वीकार किया था, वह देश में वास्तिविक लोकतन्त्र शासन की स्थापना करना चाहती थी। उसकी यह योजना थी, कि चीन के लिये वाकायदा संविधान का निर्माण किया जाय, जिसमें नागरिकों के जन्मसिद्ध अधिकारों का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन हो। कानून बनाने और शासन विभाग पर नियन्त्रण रखने के लिये वालियामेन्ट की रचना की जाय और मन्त्रिमण्डल पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी हो। राष्ट्रपत्ति की चीन में वही स्थित हो, जो फांस में होती है। राष्ट्रपत्ति के नाम से जिन राजकीय आजाओं को प्रकाशित किया जाय, उन पर साथ में उस विभाग के मन्त्री के हस्ताक्षर भी आवश्यक हों। सरकार विदेशी राज्यों से जो सन्ध्यां करे, जो कर्ज ले व देश के शासन के लिये जो व्यवस्था करे, उन सबके लिये पालियामेन्ट की स्वीकृति ली जाया करे। चीन के कान्तिकारी गेताओं के सम्मुख फेल्च रिपब्लिक आदर्श रूप से विद्यमान थी और वे उसी ढंग पर अपने देश में रिपब्लिक का संगठन करना चाहते थे।

पर युआन शी काई नाममात्र का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता था। उसने राष्ट्रपति पद को इसीलिये स्वीकार किया था, क्योंकि वह इस पद द्वारा चीनं के शासनसूत्र की अपने हाथों में रखने के लिये उत्सुक था। पर चीन की जनता ने उसे जिन कारणों से राष्ट्रपति स्वीकार किया था, वे सर्वथा भिन्न थे। कात्तिकारी कैनेता जग्यने थे, कि वास्तिवक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में न रहकर पार्कियामेन्ट के प्रति उत्तरदाशी पत्तिमण्डल के हाथों में रहेगी। उनके हक्यों में जुआन भी काई के प्रति अधिकार की भावता शिवमान भी। पर उन्होंने उने राष्ट्रपति स्थीकार भर लिया था। तथोंकि वे आनते थे कि उत्तर्र प्रदेशों की नेना उनकी आना में हैं ऑर उसमे समसाता किये विना आनतिक युग्न का नन्त कर सकता सम्भव नहीं है।

पर युआन शी काई के प्रति अविश्वास रखने के कारण ही उन्होंने समझौते में एक यह शर्त भी रखी थी, कि चीन की राजधानी पेकिंग के स्थान पर नानकिंग रहेगी... पेकिंग व उसके समीपवर्ती प्रदेशों में कान्तिकारी दल का जोर नहीं था। इसके विपरीत नानिकंग क्रान्तिकारी दल का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। डा॰ सन यात सेन व उसके अनुयायी चीनी रिपब्लिक की सरकार को इसी कारण नानकिंग में रखना चाहते थे, ताकि उनका प्रभाव सरकार पर रह सके। पर युआन शी काई पेकिंग छोड़कर नानकिंग आने में संकोच करता था । उसके सौभाग्य से मार्च, १९१२ में पेकिंग की सेना ने विद्रोह कर दिया। अब युआन शी काई को इस सैनिक विद्रोह को शांत करने के लिये पेकिंग रहने का बहाना मिल गया। उसने नानिकंग की राष्ट्रीय महासभा को भी पेकिंग चले आंने के लिये विवश किया । यह बात युआन की काई के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। पेकिंग के वातावरण में रिपब्लिकन नेताओं के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे राष्ट्रपति की स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों का सफलता के साथ मुकाबला कर सकें। पेकिंग में विदेशी राज्यों के दूतावास भी विद्यमान थे। यहाँ इनकी शक्तिशाली सेनाएँ भी अच्छी बड़ी संख्या में निवास करती थीं। विदेशी राजदूत युआन शी काई के पक्षपोषक थे। उनका सहारा पाकर वह चीन के क्रान्तिकारी नेताओं का मुकावला करने में समर्थ हुआ। चीन के उत्तरी प्रदेशों में कान्ति का विशेष प्रभाव नहीं हुआ था । वहां के लोग व सरकारी कर्मचारी रिपव्लिक के प्रति विशेष अनुराग नहीं रखते थे। युआन शी काई की इनकी सहायता व सहयोग का भी पूरा भरोसा था।

नई चीनी रिपब्लिक के पद पर युआन शी काई रहेगा, यह तो तय हो चुका था। अब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, कि प्रधान मन्त्री कौन बने और मन्त्रिमण्डल में किन किन व्यक्तियों को रखा जाय। तांग शाओ-यी को चीन का प्रथम प्रधानमन्त्री नियत किया गया। मञ्चू शासन के युग में यह युआन शी काई के अधीन कार्य कर चुका था और अब डा॰ सन यात सेन के जान्तिकारी दल का सदस्य था। अतः दोनों पक्षों ने इसे प्रधानमन्त्री के रूप में स्वीकृत कर लिया। युद्धमन्त्री के पद पर तुआन ची जुई को नियत किया गया। यह भी युआन शी काई का समर्थंक था। अन्य मन्त्री भी दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त किये गये। नानकिंग में जिस राष्ट्रीय महासमा का संगठन हुआ था, वह अब नानिकंग चली आई थी। यह निर्णय किया गया, कि जब तक पालियामेन्ट के चुनाव के सम्बन्ध में सब व्यवस्था पूर्ण न हो जाय, तब तक यह महासभा ही चीनी रिपब्लिक की विधानसभा का कार्य करती रहे। इस बीच में वोटरों की सूची तैयार की गई और पालियामेन्ट के चुनाव की व्यवस्था की गई। पालियामेन्ट में दो सभाएं रखी गई, सीनेट और प्रतिनिधि

मभा । १९१३ में नई पार्लियामेन्ट का निर्वाचन हो गया । इसमें जो सदस्य निर्वाचित होकर आये थे, वे अनेक दलों के थे । इनमें मुख्य दल निम्निलिवित थे—हिंगे । राष्ट्रपति का पक्षपाती दल—इसमें मुख्यतया उत्तरी चीन के प्रतिनिधि थे । इन्हें युआन शी काई की नीति पर पूर्ण विश्वास था और ये सब प्रकार से उसका समर्थन करने को उदात थे । (२) कान्तिकारी दल—ये मुख्यतया दक्षिणी चीन का प्रतिनिधित्त्व करते थे और डा० सन यात सेन के अनुयायी थे । पार्लियामेन्ट में इस दल के सदस्यों की संख्या अन्य दलों की अपेक्षा अधिक थी । (३) मध्यमार्गी दल—यह न युआन शी काई का पक्षपाती था और न सन यात सेन का । इसके कोई निश्चित राजनीतिक विचार भी नहीं थे । युआन शी काई के लिये यह सुगम था, कि इस दल के लोगों को अपने पक्ष में कर सके । राजनीतिक नैतिकता अभी चीन में भलीमांति विकसित नहीं हुई थी । पद के लोभ व रुपये के लालच से लोग अपना मत बदल लेने में संकोच नहीं करते थे। युआन शी काईने मध्यमार्गी दल के लोगों को अपने पक्ष में करते थे। युआन शी काईने मध्यमार्गी दल के लोगों को अपने पक्ष में करते थे। युआन शी काईने मध्यमार्गी दल के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिये सब प्रकार के उपायों का प्रयोग किया । कान्तिकारी दल की पार्लियामेन्ट में बहुसंख्या नहीं थी, यद्यपि उसके सदस्य अन्य किसी भी दल की अपेक्षा अधिक संख्या में निर्वाचित हुए थे।

भ इस प्रकार चीन में नई सरकार का संगठन हो गया था। राष्ट्रपति पद पर युआन शी काई विराजमान था। नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हो गया था और पालियामेन्ट का भी चुनाव किया जा चुका था। पर चीन की राजनीतिक समस्या अभी पूर्ण रूप से हल नहीं हुई थी। देश के शासनसूत्र का संचालन राष्ट्रपति के हाथ में हो या मन्त्रिमण्डल के यह प्रश्न बहुत विकट था। डा० सन यात सेन का कान्तिकारी दल वास्तविक शासनशिक्त मन्त्रिमण्डल के हाथों में रखना चाहता था। पर मध्यमार्गी दल के सदस्यों को अपने वश्में करके युआन शी काईने पालियामैन्ट हारा यह स्वीकृत करा लिया, कि राष्ट्रपति ही चीन की सरकार का संचालन करे। परिणाम यह हुआ, कि कान्तिकारी दल के लोगों के निक्ति कर के स्वर्ण के कान्तिकारी वल के लोगों के निक्ति कर के स्वर्ण के स्वर्

चीत की नई सरपार के संस्कृत गत्नी अधिक गम्भीर प्रश्न आर्थिक था। कर्मां की गुज्यवासा और देश की उत्ति के लिये रुपये की आवश्यकता थीं कर्मिंग राजकीय करों हारा प्राप्त नहीं विधा जा कारण था। राज्यकीय खाली पहा भा। युकान दी कार्ड इस बान के लिये उत्सुक था, कि प्राप्तीय सुनेवार अपनी सेनाओं को संग कर में। पर बहुत सी प्राप्तीय ग्रेनाएं ऐसी थी, जिनके सैनिकों को देर में वेतन नहीं मिला था। इन्हें तभी नीकारी से बर्जास्त किया जा सकता था, जब

इनके वेतनों को चुकता कर दिया जाय । सैनिकों को वेतन न मिलने के कारण कई स्थानों पर सैनिक अफसर स्वयं जनता से कर वसूल करने लग गये थे और प्रान्तीय सरकारों को भी केवल उतना ही कर प्राप्त हो पाता था, जो सैनिक अफसर उन्हें खशी से प्रदान कर देते थे। इस स्थिति को संभाल सकने का यही उपाय था, कि सैनिकों को वेतन देकर बर्जास्त कर दिया जाय और प्रान्तीय शासन का पूनः संगठन किया जाय । पर इस काम के लिये रुपये की जरूरत थी और केन्द्रीय रिपब्लिकन सरकार के पास रुपये का सर्वथा अभाव था। इस रुपये को कर्ज लेकर ही प्राप्त किया जा सकता था, अतः युआन शी काई ने विदेशी राज्यों से कर्ज की यातचीत शुरू की । इस समय ब्रिटेन, फांस, रूस, जर्मनी, जापान और अमेरिका--इन छः राज्यों ने मिलकर अपना एक गुट बना रखा था और यह निश्चय किया हुआ था, कि वेचीन को कोई कर्ज तभी देंगे, जब कि परस्पर मिलकर उसकी शती को तय कर छेंगे। विदेशी राज्यों की इस वैंकिंग सिण्डीकेट ने चीनी सरकार के सम्मख क्षर्ज के लिये यह शर्त पेश की, कि नमक के व्यवसाय पर विदेशी राज्यों का पूरी तरह से नियन्त्रण रहे, ताकि उससे होनेवाली आमदनी से कर्ज के मूलघन व सुद की प्राप्त किया जा सके । नमक की आमदनी पूरी तरह से विदेशी राज्यों के पास जमानत... के रूप में रहे । साथ ही विदेशी राज्यों को यह भी अधिकार हो, कि वे चीनी सरकार के व्यय पर भी नियन्त्रण रख सकों। सरकारी व्यय पर नियन्त्रण रखने का यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि चीन की स्वतन्त्रता बहुत हद्द तक सीमित हो जाती। यही कारण है, कि १९१३ में अमेरिका बैंकिंग सिण्डीकेट से अलग हो गया और अब इस गुट में केवल पांच राज्य रह गये। अमेरिकन सरकार को यह बात पसन्द नहीं थी, कि चीन की राजनीतिक स्वतन्त्रता में इस ढंग से हस्तक्षेप किया जाय। डा० सन यात सेन की कान्तिकारी पार्टी भी इस कर्ज के विरोध में थी। इसके कारण चीन की स्वतन्त्रता में जो बाधा उपस्थित होती थी, उसे फ्रान्तिकारी वल के लोग किसी भी दशा में सहन करने को तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ, कि उन्होंने पालियामेन्ट में विदेशी कर्ज की शतों का घोर विरोध किया। पर युआन शी काई ने मध्यमार्गी दल को अपने पक्ष में करके कर्ज को पालियामेन्द में स्वीकृत करा लिया। पांच विदेशी राज्यों की बैंकिंग सिण्डीकेट से युआन शी काई की सरकार कर्ज लेने में समर्थ हुई और इस रकम का प्रयोग कर उसने देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने का उद्योग किया।

कुओमिन्तांग बल-डा० सन यात सेन के प्रयत्न से चीन में जिल कान्तिकारी दल का संगठन हुआ था, पहले उसे तुंग मेंग हुई कहते थे। बाद में उसी का कुओ-मिन्तांग बल के नाम से पुनः संगठन हुआ। यह बल राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवार को बहुत महत्त्व देता था और इसका उद्देश्य यह था, कि जहां चीन राष्ट्रीय दृष्टि से मुसंगठित व सुव्यवस्थित राज्य हो, वहां साथ ही उसमें लोकतन्त्रवाद का भी विकास है। कुओभिन्तांग दल के लोग चीन को उन्नति के उसी मार्ग पर ले जाना चाहते थे, जिस पर कि फांस, अमेरिका आदि पाश्चात्य देश चल रहे थे।

युआन शी काई का उत्कर्ष—कुओिमन्तांग दल का इस समय सबसे वड़ा विरोधी युआन शी काई था। यह दल उसके खिलाफ कोई कार्य न कर सके, अतः सबसे पहले उसने पालियामेन्ट द्वारा नये शासन विधान के उस भाग को स्वीकृत कराया, जिसमें राष्ट्रपति के अधिकार आदि की व्यवस्था की गई थी। पालियामेन्ट की दोनों सभाएँ—सीनेट और प्रतिनिधि सभा—जब कि एक साथ मिलकर अपना अधिवेशन करती थीं, तो उन्हें संविधान परिषद् कहतं थे और नये शासन विधान को अन्तिम रूप से निर्मित व स्वीकृत करने का कार्य इसे ही सुपुर्द था। राष्ट्रपति सम्बन्धी सब बातों का अपने पक्ष में निर्णय कराके युआन शी काई ने स्वयं अपने को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करा लिया। इसके लिये उसने मध्यमार्गी दल को अपने पक्ष में करने के लिये रूपये को पानी की तरह से बहाया। विदेशी राज्यों से कर्ज की जो भारी रक्म देश की उन्नित के उद्देश्य से प्राप्त की गई थी, उसका कुछ अंश युआन शी काई ने पालियामेन्ट के सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिये भी व्यय किया। अब युआन शी काई की स्थित सर्वथा सुरक्षित हो गई थी और न केवल पालियामेन्ट अपितु मन्त्रिमण्डल भी पूर्णतया उसके वशवतीं हो गये थे।

पर युआन शी काई इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। वह अपने विरोधियों का विनाश करने के लिये कटिबद्ध था। ४ नवम्बर, १९१३ की उसने कुओमिन्ताग दल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। इस दल के बहुत से सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये, वहुतों ने विदेश भागकर अपने को कैंद्र होने से बचाया। कुओमिन्तांग दल के सदस्यों के चले जाने के कारण पालियामेन्ट के अधिवेशनों में कोरम हो सकना किंत हो गया और पालियामेन्ट का स्वयमेव अन्त हो गया। यद्यपि नाम को अब भी पालियामेन्ट की सत्ता थी; उसे बर्खास्त नहीं किया गया था, पर कोरम के अभाव के कारण उसका अधिवेशन हो सकना सम्भव नहीं रहा था और युआन शी काई के लिये मनमानी तरीके से देश का शासन कर सकना सुगम हो गया था। डा० सन यात सेन

(२) युआन शी काई का स्वेच्छाचारी शासन

नया शासन विधान—अंड राजा की सम्पूर्ण शक्ति ब्यान शी काई के हायों में केन्द्रित हो गई थी। पालिसामेन्ट, मन्दिमण्डल व लोकमत—संबकी उपेका

कर उसने स्वेच्छापूर्वक शासनसूत्र का संचालन करना प्रारम्भ किया। नानिकग की राष्ट्रीय महासभा द्वारा देश के लिये जिस शासन विधान का खाका तैयार किया गया । और जिनके अनुसार पेकिंग की संविधान परिषद् (सीनेट 🛣 प्रतिनिधि सभा) नई शासन व्यवस्था का निर्माण करने में तत्पर थी, उसे आंखों से ओझल कर युआन भी काई ने अपने विचारों के अनुसार चीन के लिये नये शासन-विधान का निर्माण कराया । इस कार्य के लिये एक नई संविधान सभा का संगठन किया गया। इस सभा में केवल वे सदस्य नियत किये गये, जो यशान शी काई के समर्थक थे और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने को तैयार थे। संविधान सभा ने चीन की रिपब्लिक के लिये जो नया गासन विधान बनाया, उसकी मस्य बातें निम्नलिखित थीं--(१) राज्य की सब शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो। (२) राष्ट्रपति का निर्वाचन दस साल के लिये किया जाय। यदि राष्ट्रपति की सम्मति में दस साल समाप्त हो जाने के बाद देश की ऐसी परिस्थिति हो, जिसमें कि उसका अपने पद पर कायम रहना आवश्यक हो, तो उसे अधिकार हो कि वह अपने पद के काल को और बढ़ा सके, या यह निर्णय कर सके कि उसका उत्तराधि-कारी कीन हो। (३) राज्य के विविध विभागों के अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हों। प्रधानमन्त्री का स्थान एक राजमन्त्री (सेक्रेटरी आफ स्टेट) को दिया गया और यह व्यवस्था की गई, कि इसकी नियक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाय और यह उसी के प्रति उनरदायी हो। (४) पालियामेन्ट के स्थान पर एक राज-सभा (कौंसिल आफ स्टेट) का निर्माण किया जाय और इस सभा का कार्य राष्ट्रपति को परामर्श देना मात्र हो । मार्च, १९१४ में युआन शी काई ने इस सिद्धान्तों के अनुसार देश की शासन व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। वह स्वयं दस साल के लिये राष्ट्रपति नियुक्त हुआ और स्वेच्छाचारी रूप से देश का शासन करने के लिये प्रवृत्त हुआ । राज्यकान्ति से पूर्व मञ्चू सम्राटों के शासनकाल में चीन की सरकार की जो दशा थी, वही अब पुनः स्थापित हो गई। जिन लोगों नें भी युआन शी काई का विरोध करने का साहस किया, उनको कठोर दण्ड दिये गये। सर्वत्र गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गयो । गुप्तचरों के कारण किसी आदमी के लिये यह सम्मव नहीं रहा, कि वह स्वतन्त्रता के साथ अपनी सम्मति को प्रकट कर सके। समाचारपत्रों पर कठोर निरीक्षण रखा गया, और अपने विरोधियों का अन्त करने के लिये राजनीतिक हत्याओं का आश्रय लिया गया । इस काल में कितने ही चीनी नेताओं की हत्याएँ हुईं। युआन शी काई अपने विरोधियों का जह से उन्मलन कर देने के लिये यूणित से घूणित उपायों का अवलम्बन करने के लिये कटियद्ध था। **प्रयम महायुद्ध (१९१४-१८)—जिस रागय वृजान की काई नीत में लोकताल.**

रिपब्लिक का अन्त कर अपने स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना में तत्पर था, तभी ु दूरोप में एक महायुद्ध की अग्नि भड़क उठी । इस युद्ध में आस्ट्या-हंगरी, जर्मनी और टर्की के खिलाफ फांस, ब्रिटेन और रूस लड़ाई के मैदान में उतर आये थे। जापान और ब्रिटेन परस्पर सन्धि के सूत्र में बंधे हुए थे, यह पहले लिखा जा चका है। इस महायुद्ध को जापान ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिये उपयुक्त अवसर समझा और वह जिटेन व फांस के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। अन्य पारचात्य देशों के समान जर्मनी ने भी चीन में अनेक आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे और कियाऊ चाऊ का प्रदेश उसने पट्टे पर भी प्राप्त किया था। जापान की आंख इस प्रदेश पर थी। वह चाहता था, कि जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होकर इस प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर छे। पर चीन यूरोप के इस महायुद्ध में उदासीन था। उसने यत्न किया, कि चीन के प्रदेश में कहीं भी लड़ाई न होने पावे और कोई राज्य उसकी उदासीन सत्ता कर व्याचात न करे। पर जापान ने इसकी कोई परवाह नहीं की। एक जापानीः सेना ने कियाऊ चाऊ के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया । ब्रिटेन ने भी इस आक्रमण में जापान की सहायता की । यूरोप में बेल्जियम की उदासीन सत्ता का जर्मनी द्वारा व्याधात होने पर ब्रिटेन ने बहुत अधिक एतराज किया था और वह इसी नाम पर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुआ था। पर चीन की उदासीन सत्ता की उसने जरा भी परवाह नहीं की और ब्रिटेन व जापान की सम्मिलित सेनाओं ने कियाऊ चाऊ को जीत लिया । उसके बन्दरगाह स्सिगताओ पर जापानी सेनाओं का कब्जा हो गया।

जापान की मांगें — जनवरी, १९१५ में जापानी सरकार ने चीन के सम्मुख २१ मांगें पेश कीं। इनमें मुख्य निम्नलिखित थीं — (१) शांतुंग के प्रदेश (जिसमें कियाऊ वाऊ स्थित था) में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें जर्मनी से प्राप्त करने के लिये जापान जो कुछ भी उद्योग करे, चीन उसमें बाधक न हो। (२) शांतुंग के प्रदेश में रेलवे लाइन बनाने का जापान को अधिकार दिया जाय और उराके समुद्रतट के सब बन्दरगाहों में उसे व्यापार आदि के विशेष अधिकार दिये जावें। (३) लिआओ तुंग प्रायद्वीप और पोर्ट आर्थर के पट्टे के काल की प्राप्त से बढ़ाकर ९९ साल कर दिया जाय। इसी प्रकार मञ्चूरिया में रेलवे लाइनों पर जापान को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनका कुछ भी नढ़ाकर ९९ साल कर दिया जाय। इसी प्रकार मञ्चूरिया में रेलवे लाइनों पर जापान को जो अधिकार प्राप्त हैं, उनका कुछ भी नढ़ाकर ९९ साल कर विशा चाय। यक्षिणी मञ्चूरिया के विशा प्रदेशों पर जापान को रेलने आदि के निर्माण के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्रान्त थे, उनमें आपान होगों को यह अधिकार भी दिया जाय, कि वे वहां जायथार के राके, गकान बना हमें और

स्वतन्त्रता के साथ यात्रा कर सकें। जापान की सहमित के बिना चीन इन प्रदेशों में किसी अन्य देश के लोगों को राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक मामलों में सलाहकार के रूप में नियुक्त न कर सके और न ही इन प्रदेशों में किसी अन्य राज्य को कोई विशेषाधिकार दिये जा सकें। (४) मध्य चीन में लोहे का जो विशाल कारखाना उन्नीसवीं सदी के उतराई में स्थापित किया गया था, उसपर जापान और चीन का सम्मिलित रूप से आधिपत्य हो । (५) जापान की अनुमति के विना चीन किसी अन्य देश को अपने समुद्रतट पर स्थित किसी बन्दरगाह को पट्टे पर न दे सके और न ही वहां व्यापार आदि के कोई नये विशेषाधिकार दिये जा सकें। (६) चीन को अपनी सरकार की सुव्यवस्था के लिये जिन किन्हीं राजनीतिक, सैनिक अ आर्थिक सलाहकारों ी आवश्यकता हो, वे सव जापानी ही नियुक्त किये जावें। (७) जापान के बौद्ध धर्म के प्रचारकों को यह अधिकार हो कि, वे चीन में जहां चाहें धर्म प्रचार कर सकें व अपने विहारों व मन्दिरों की स्थापना कर सकें। (८) चीन की जी भी अस्त्र-शस्त्र विदेशों से खरीदने हों, उनका कम से कम ५० प्रतिशत भाग वह जापान से क्या किया करे। यदि चीन अस्व शस्त्रों के निर्माण के लिये कोई कारखाना खोले, तो उसका प्रवन्ध भी चीन और जापान दोनों के सम्मिलित नियन्त्रण में रहे।

यदि जापान की इन मांगों को स्वीकृत कर लिया जाता, तो इसका यही परिणाम होता, कि चीन पूर्ण रूप से जापान का संरक्षित राज्य बन जाता और उसकी स्वतन्त्र सत्ता बहुत कुछ नष्ट हो जाती । अन्य यूरोपियन देश इस समय यरोप के महायुद्ध में इतने अधिक व्यस्त थे, कि वे जापान की मांगों का विरोध नहीं कर सके । इसके विपरीत जर्मनी की शक्ति का मुकाबला करने के लिये फांस और ब्रिटेन जापान की सहायता प्राप्त करने के लिये अत्यधिक उत्सुक थे । जापान के राजनीतिज्ञों ने इस स्थिति से लाभ उठाया और चीन में अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाना शुरू किया । जापान की इन मांगों के कारण चीन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय पर हम आगे अधिक विस्तार से विचार करेंगे । यहां इतना निर्देश कर देना, पर्याप्त है, कि युआन सी काई जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इस समय जापान का विरोध कर सकने का साहस नहीं कर सकता था।

राजसत्ता की स्थापना का प्रयतन—राष्ट्रपति युआन शी काई ने किस प्रकार लोकतन्त्र शासन का अन्त कर सम्पूर्ण राजशिक्त को अपने हाथों में ले लिया था, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब फ्रांस के नैपोलियन प्रथम का अनु-सरण कर उसने यह प्रयत्न किया, कि चीन से रिपब्लिक का अन्त कर राजसत्ता का पुनरुद्धार करें और वह स्वयं सम्राट् पद को प्राप्त करे। पर इस परिवर्तन के लिये

वह ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहता था, जिससे संसार यह समझे कि उसने - अतिता के आग्रह के कारण ही मम्राट् पद को स्वीकार किया है। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिये युआन भी काई ने जिस राजसभा की स्थापना की थी, उसके प्राय: सब सदस्य' उसकी हां में हां मिलाने वाले थे। उन्होंने प्रस्ताव किया, कि चीन में रिपब्लिक का अन्त करके युआन शी काई से प्रार्थना की जाय कि वह सम्राट पद को स्वीकार कर ले। राजसभा ने तीन वार इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पर युआन शी काई इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि यदि जनता के प्रति-निधियों की एक महासभा उससे यह अनुरोध करेगी, तभी वह इसे स्वीकार कर सकेगा । नैपोलियन के समान युआन शी काई भी यह प्रदक्षित करना चाहता था. कि वह जनता के अनुरोध व इच्छा के कारण ही सम्राट् पद को स्वीकार कर रहा है। पर 'जनता के प्रतिनिधियों की महासभा' का आयोजन कोई कठिन कार्य ओमिन्तांग के लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इस दशा में जनता से ऐसे प्रतिनिधियों को निर्वाचित करा मकना जरा भी कठिन नहीं था, जो युआन शी काई के सम्राट् पद की ग्रहण कर लेने के पक्षपाती हों। महासभा ने भी अबें आग्रह के साथ युआन शी काई से अनुरोध किया, कि वह देश के हित को दृष्टि में रखकर चीन में राजसत्ता का पुनरुद्धार करे और स्वयं सम्राट् पद को स्वीकार कार ले।

जनता का विरोध — युआन शी काई ने जनता के प्रतिनिधियों की महासभा के 'अनुरोध' को स्वीकार कर लिया और नये सम्राट् के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। पर वस्तुतः चीन की जनता रिपब्लिक के अन्त और राजसत्ता की पुनः स्थापना के विरुद्ध थी। दक्षिणी चीन के यूनान प्रान्त के लोगों ने पेकिंग सरकार की सेवा में एक आनेदन पत्र भेजा, जिसमें राजसत्ता के पुनरुद्धार का घोर विरोध किया गया। जब युआन शी काई ने इस आवेदन पर कोई घ्यान नहीं दिया, तो यूनान के लोगों ने विद्रोह कर दिया। पेकिंग सरकार ने विद्रोह को शान्त करने के लिये कठोर उपायों का प्रयोग किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। विद्रोह की अग्नि केवल यूनान तक ही सीमित नहीं रही। शीघ्र ही वह दक्षिणी चीन के अन्य प्रान्तों में भी फैल गई। इन विद्रोही प्रान्तों ने घोषणा की, कि वे अब केन्द्रीय सरकार के किसन में नहीं रहेंगें। युआन शी काई के विरोधी कान्तिकारियों की इस समय मुख्य मांगें निम्मिलिखित थीं— (१) राजसका की पुनः रथापना के निर्णय को रह कर दिया जाय। (२) जानिका की रान्तीय गहारामा द्वारा देख के बासन विधान का जो खाका तैयार किया गया था, उसके अनुसार शासन ब्यवस्था का निर्णण किया जाय। (३) पालियामेन्द की पुनः स्थापना की जाय।

युआन शी काई के लिये यह सम्भव नहीं था, कि कान्तिकारी लोगों की इन मांगों का बिरोध कर सके। अब उसने घोषित किया, कि 'जनता के प्रतिनिधियुं की महासभा' ने उससे सम्राट् पद को ग्रहण करने का जो अनुरोध किया था, वह वस्तुतः लोकमत के प्रतिकृत था, अतः राजसत्ता के पुनरुद्धार का परित्याग किया जाता है। युआन शी काई की इस घोषणा से कान्तिकारियों की हिम्मत और अधिक बढ़ गई। अब उन्होंने मांग पेश की, कि युआन शी काई अपने पद का त्याग कर दे। पर इसे स्वीकृत कर सकना युआन शी काई के लिये सम्भव नहीं था। उसने यत्न किया, कि कान्तिकारियों के साथ समझौता कर ले। वह इस समय निम्निलिखित बातों के लिये तैयार था—(१) मन्तिमण्डल का निर्माण किया जाय और सरकार का संचालन मन्त्रियों के सुपुर्व कर दिया जाय। (२) सेना का नियन्त्रण भी युद्धमन्त्री के अधीन रहे। (३) पालियामेन्ट का पुनः संगठन हो। एक बार फिर युआन शी काई कान्तिकारियों के साथ समझौता कर रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में शासन का संचालन करने के लिये उद्यत हो गया।

युआन शी काई की मृत्यु—अभी कान्तिकारी नेताओं के साथ अन्तिम रूप से समझौता नहीं हो पाया था, कि ६ जून, १९१६ को अकस्मात् ही युआन शी काई की मृत्यु हो गई। अब राजसत्ता के पक्षपातियों में कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति नहीं रहा था, जो लोकतन्त्र रिपब्लिक का विरोध कर सके। रिपब्लिक के पुनरुद्धार का मार्ग अब पूर्ण रूप से साफ हो गया था।

चीन के आधुनिक इतिहास में युआन शी काई का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसमें सन्देह नहीं, कि वह अत्यन्त योग्य शासक था, उसकी वैयिक्तक शिंक्त और समता से कोई भी ऐतिहासिक इनकार नहीं कर सकता। आधुनिक युग के नवीन विचारों से भी वह भलीभांति परिचित था। पर उसने अपनी योग्यता, शिंक्त और प्रतिभा का प्रयोग चीन में नवयुग लाने के लिये नहीं किया। यदि वह चाहता, तो चीन में एक मुसंगठित और सुव्यवस्थित लोकतन्त्र शासन की स्थापना में अपनी शिंक्त का सबुपयोग कर सकता था। पर उसने प्रगति की प्रवृत्तियों का साथ न देकर प्रतिकियावादी प्रवृत्तियों का पक्ष लिया। यदि वह नैपोलियन के समाम सम्राट् पद पर आरूढ़ होकर चीन को विदेशी प्रभुत्त्व से मुक्त करने में समर्थ हो सकता, तो भी वह अपने देश के लिये उपयोगी कार्य कर जाता। पर जिस सामूछ वह चीन का एकाधिपति बना हुआ था, तो भी उसने विदेशी राज्यों से भारी मार्मा में कर्ज लेकर अपने देश पर विदेशी प्रभुत्त्व में वृद्धि की। यही कारण है, कि चीन के इतिहास में युआन शो काई का स्थान बहुत उज्जवल व गीरवपूर्ण नहीं समझा जा सकता।

(३) रिपब्लिक का पुनः संगठन

नई सरकार—युआन शी काई की मृत्यु के बाव रिपब्लिकन शासन का चीन में पुनः संगठन किया गया। उप राष्ट्रपति के पद पर कर्नल ली युआन हुंग विद्यमान या। अब वह राष्ट्रपति बन गया। तुआन ची जुई को प्रधानमन्त्री के पद पर नियत किया गया और उसने नये मन्त्रिमण्डल का संगठन किया। पालियामेन्ट का पुनरुद्धार किया गया। राष्ट्रपति ली युआन हुंग ने शासन के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया, कि चीन की रिपब्लिक में पालियामेन्ट का स्थान सर्वोच्च है। ली युआन हुंग ने नानिका की राष्ट्रीय महासभा द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त को भी स्वीकृत किया, कि देश के शासनसूत्र का संचालन राष्ट्रपति के हाथों में न रहकर मन्त्रिमण्डल के हाथों में रहेगा। इसका यह परिणाम हुआ, कि इस ममय चीन की सरकार में तुआन ची जुई की स्थित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गई। हम पहले लिख चुके हैं, कि तुआन ची जुई पहले युआन शी काई का अधीनस्थ कर्गचारी रह चुका था और उसका पक्षसमर्थक था। उसके विचारों पर युआन शी काई का बहुत प्रभाव था। यही कारण हैं, कि उसने भी स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों का अप्रवर्शन किया और पालियामेन्ट की शक्ति व प्रभृत्त्व की उपेक्षा की। शीघ्र ही पालियामेन्ट के साथ उसका विरोध प्रारम्भ हो गया।

पालियामेन्ट का अन्त- युआन शी काई की मृत्यु के बाद पेकिंग में पालियामेन्ट की पुनः स्थापना हो गई थी। इस समय पालियामैन्ट ने न केवल देश के लिये कानूनों का निर्माण और सरकार की नीति को नियन्त्रित करना था, अपितु देश के लिये शासन विधान को भी तैयार करना था। हम पहले लिख चुके हैं, कि पालियामेन्ट की दोनों सभाओं—सीनेट और प्रतिनिधि सभा—के सदस्य मिलकर संविधान परिषद् के रूप में एकत्र होते थे और यह परिपद् देश के लिये नये संविधान का निर्माण करने का कार्य करती थी। पर प्रधानमन्त्री तुआन ची जुई और पालियामेन्ट में शीघ्र ही विरोध हो गया और इस विरोध ने इतना प्रचण्ड रूप धारण किया कि कुछ ही समय में पालियामेन्ट का और उसके साथ ही लोकतन्त्र शासन का भी चीन से अन्त हो गया। प्रधान मंत्री और पालियामेन्ट के सुस विरोध के निम्नलिखित कारण थे—(१) चीन की सरकार ने अपने आधिक तिकट को दूर करने के लिये निश्चय किया, कि विदेशी रोज्यों से नया कर्ज लिया। जाय। तुआन ची जुई ने कर्ज की राज शर्त विदेशी रोजियों से नया कर्ज लिया। जाय। तुआन ची जुई ने कर्ज की राज शर्त विदेशी रोजियों से नया कर्ज लिया। जाय। तुआन ची जुई ने कर्ज की राज शर्त विदेशी रोजियों से नया कर्ज लिया। जाय। तुआन ची जुई ने कर्ज की राज शर्त विदेशी रोजियों से नया कर्ज लिया। उसका घोर विरोध हुआ। (२) पालियामेन्ट के रायमुद्ध पेश किया राया, तो नहां उसका घोर विरोध हुआ।। (२) पालियामेन्ट के रायम्य समहातेथ, कि मिन्तमण्डल

उनके प्रति उत्तरदायी है । वे उसके प्रत्येक कार्य की कड़ी आलोचना करते थे । पर नुआन ची जुई इतना जबर्दस्त आदमी था, कि पालियामेन्ट की जरा भी परवाह नहीं करता था। (३) प्रधान मन्त्री तुआन ची जुई चाहता था, कि यूरोपियन महायुद्ध में चीन मित्रराष्ट्रों (फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि) का पक्ष लेकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। बोक्सर युद्ध में हरजाने की जो भारी रकम चीन ने विदेशी राज्यों को प्रदान करनी थी, और जिसकी बहुत सी किस्तें अभी अदा करनी केष थीं, उसके वारे में कुछ रियायत चीन को प्राप्त हो जायगी, यदि वह यूरोपियन महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों की सहायता करेगा-ं इस बात का तुआन ची जई को परा भरोसा था, पर मित्रराष्ट्र इस विषय में पहले से ही कोई पक्का समझौता करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, कि यदि चीन महायद में मित्रराष्ट्रों की पूरी पूरी सहायता करेगा, तो वे इस प्रश्न पर सहानुभृति पूर्वक विचार करेंगे। पर चीन की पालियामेन्ट महायुद्ध में शामिल होने की सहमति इसी शर्त पर देने को तैयार थी, कि पहले मित्रराष्ट्रों के साथ हरजाने की रकम के बारे में पक्का समझौता कर लिया जाय । तुआन ची जुई को इस बात में सफलता नहीं हो सकी। परिणाम यह हुआ, कि पालियामेन्ट ने युद्ध में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। इस दशा में राष्ट्रपति ली युआन हुंग ने तुआन-ची जुई को प्रधानमन्त्री के पद से पृथक् कर देने की आज्ञा जारी की । राष्ट्रपति का यह कार्य वैधानिक दृष्टि से बिलकुल ठीक था। क्योंकि तुआन ची जई को पालि-यामेन्ट के बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं था, अतः वह अपने पद पर नहीं रह सकता था । पर तुआन ची जुई ने प्रधानमन्त्री के पद से पृथक् होने से इनकार कर दिया। उत्तरी चीन के अनेक प्रान्तीय सुबेदार उसकी पीठ पर थे। उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ पेकिंग की ओर प्रस्थान कर दिया। पेकिंग की सरकार उनका मुकाबला नहीं कर सकी। पेकिंग पर उत्तरी प्रान्तों के सूबेदारों की सेनाओं का कब्जा ही गया। उन्होंने राष्ट्रपति ली युआन हंग को इस बात के लिये विवश किया, कि वह पार्लियामेन्ट को बर्खास्त कर दे और तुआन ची जुई को प्रधानमन्त्री के पद से न हटाचे ।

युआन शी काई की मृत्यु के बाद चीन में जिस लोकतन्त्र सरकार की स्थापना की गई थी, वह देर तक कायम नहीं रह सकी। जुलाई, १९१६ तक उसका अन्त् 'हो गया। अनेक सुबेदार सेनापितयों (इन्हें हम अब से सिपहसालार कहेंगे, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतनकाल में भारत में भी अनेक सुबेदार जहां प्रान्तीय शासन के मुख्य अधिकारी होते थे, वहां प्रान्तीय सेना के सिपहसालार भी होते थे) ने इस समय यह यत्न भी किया, कि मञ्चू राजवंश का पुनरुद्धार किया जाय। सिपह-

सालार चांग ह् मुन ने रिपब्लिक का पूर्ण रूप से अन्त कर नावालिंग मञ्चू सम्राट् को फिर से पेकिंग की राजगद्दी पर विठाया । पर बहुसंख्यक सिपहसालार इस वात की विरोध में थे । परिणाम यह हुआ, कि चांग ह् मुन को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई और मञ्चू राजवंश की पुन: स्थापना नहीं हो सकी । रिपब्लिक कायम रही, पर उसमें न पालियामेन्ट की सत्ता थी और न ही शासन पर जनता का किसी प्रकार का प्रभाव था । प्रधानगन्त्री तुआन ची जुई का सरकार पर उसी प्रकार से आधिपत्य था, जैसे कि पहले युआन शी काई का था । इस दशा में राष्ट्रपति ली युआन होंग ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया ।

तुआन ची जुई का एकाधिपत्य--ली युआन हंग के राष्ट्रपति पद से पृथक् हो जाने के बाद तुआन ची जुई के लिये अपने उत्कर्ष का मार्ग खुरु गया। अब राष्ट्रपति के पद पर फेंग कुओ-चंग को नियत किया गया। यह हुकुआंग प्रान्त का सिपहसालार था और युआन शी काई की मृत्यु के बाद जब ली युआन हंग उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गया था, तो उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुआ था । ली युआन हुंग के त्यागपत्र दे देने पर यह स्वयं अपने अधिकार से राष्ट्रपति बन गया था। ली युआन हुंग के समान फेंग कुओ-चंग को भी तुआन ची जुई की ैप्रभुता पसन्द नहीं थी । वह स्वयं एक शक्तिशाली सिपहसालार या और एक बड़ी सना उसके आधिपत्य को स्वीकार करती थी। उसने प्रधानमन्त्री तुआन ची जुई का विरोध करना शुरू किया। इस दशा में प्रधान मन्त्री के पास एक ही उपाय था, वह यह कि पालियामेन्ट के अधिवेशन को फिर से बुलाकर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन करावे । अक्टूबर, १९१८ में फेंग कुओ-चंग का राष्ट्रपति पद का काल समाप्त होता था। इससे लाभ उठाकर तुआन ची जुई ने पार्लियामेन्ट का अधिवेशन ब्लाया, उसके बहुसंख्यक सदस्यों को पद व रुपये के लोभ से अपने पक्ष में किया और अपने समर्थक हु सू शिह-चंग को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करा दिया । तुआन ची जुई इतने से ही सन्तुट्ट नहीं हुआ, उसने अपने समर्थकों का एक नया दल बनाया, जिसे अन्फू बलव कहते थे। इस क्लब के सदस्यों ने परस्पर मिलकर एक गुटबन्दी बनाई थी और ये राजकीय पदों को प्राप्त करने में एक दूसरे की सहायता करते थे। तुआन ची जुई ने विदेशों से अनेक बार कर्ज लिये। यद्यपि यूरोप के विविध कुष इस समय महायुद्ध में तत्पर थे, पर जापानी सरकार बड़ी उदारता के साथ वीन को कर्ज देने के लिये उद्यत थीं। जागानी लोग भलीभांनि समझने थे, कि से कर्ज चीन पर अपना आधिक व राजनीतियः प्रभत्त स्थापित करने के सर्वोत्तम साधन हैं। विदेशों से कर्ज लेने की शर्तों का पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत कराना आवश्यक था। पर अन्फू कलब के सदस्यों की सहायता से तुआन ची जुई के लिये यह कठिन

नहीं था, कि इन कर्जी को पालियामेन्ट से स्वीकार करा ले। कर्ज की रक्षम का हिस्सा अन्क कलव के सदस्यों की जेवों में भी पहुंचा दिया जाता था। इस प्रकार पद व रुपये के लोभ से नुआन ची जुई ने पालियामेन्ट को अपने हाथों में कठपुतहीं के बना लिया और स्वेच्छाचारी ढंग से चीन का शासन करना प्रारम्भ किया।

केन्द्रन की पृथक रिपब्लिकन सरकार—पर यहां यह घ्यान में रखना चाहिये, कि तुआन ची जुई की पेकिंग सरकार का आविपत्य सारे चीन पर विस्तृत नहीं था। विविध सिपहसालारों की शक्ति के बढ़ जाने के कारण अब पेकिंग में स्थित चीनी सरकार के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह सारे चीन पर अपना शासन स्थापित रख सके। इस स्थिति से लाभ उठाकर डा॰ सन यात सेन के अनुयायी राष्ट्रीय कान्तिकारी दल के लोगों ने कैन्टन में अपनी पृथक् सरकार का संगठन किया। युआन शी काई द्वारा कुओमिन्तांग दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। पर तुआन ची जुई और ली युआन हुंग के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर इस दल ने किर शक्ति प्राप्त करनी शुरू कर दी थी, और दक्षिणी चीन के विविध प्रदेशों ने उसका साथ दिया था। कैन्टन की सरकार का दावा था, कि वही चीन की असली सरकार है यद्यपि उसका आधिपत्य केवल दक्षिणी चीन पर ही स्थापित था। १९२१ में डा॰ सन यात सेन को कैन्टन सरकार का राष्ट्रपर्ति निर्वाचित किया गया।

अराजकता का सूत्रपात—कैन्टनमें डा० सन यात सेन की सरकार का शासन या और पेकिंग में तुआन ची जुई स्वेच्छाचारी रूप से सरकार का सञ्चालन कर रहा था। पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि इस समय चीन में इन दो सरकारों का व्यवस्थित शासन था। उत्तरी चीन के विविध प्रदेशों में विभिन्न सिपहसालार अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र राजाओं के समान शासन करने में तत्पर थे। वे जहां आपस में लड़ते रहते थे, वहां साथ ही पेकिंग सरकार पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। इन विभिन्न सिपहसालारों के कारण तुआन ची जुई का आधिपत्य बहुधा पेकिंग की चहारदीवारी तक ही सीमित रह जाता था। पर क्योंकि विदेशी दूतावास पेकिंग में विद्यमान थे, अतः अन्तर्राष्ट्रीय वृष्टि से तुआन ची जुई की सरकार को ही चीन की कानूनी सरकार माना जाता था। जिस प्रकार मृगल साम्राज्य के हास के युग में दिल्ली के सम्राटों का शासन वहन थोड़े से प्रदेश तक सीमित रह गया था और मराठा, अफगान आदि विविध सरवाई दिल्ली को अपने प्रभुत्व में लाने में तत्पर रहते थे, कुल वैसी ही दशा इस समय पेकिंग सरकार की हो गई थी। तुआन ची जुई का पेकिंग पर कब्जा था, पर अन्य सिपहसालार तिरन्तर उसे अपने आधिपत्य में लाने में प्रयत्नशील थे। कैन्टन की

कुओमिन्तांग सरकार की दशा भी प्रायः इसी प्रकार की थी। कैन्ट्रन व उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर उसका आधिपत्य विद्यमान था, पर दक्षिणी चीन के अन्य कैं प्रदेश उसी अंश में कैन्ट्रन सरकार के अधीन थे, जिस अंश तक वहां के विविध सिगहसालार उसकी अधीनता को स्वीकृत करने के लिये उद्यन हों।

१९१६ से १९२६ तक चीन में इसी प्रकार की अराजकता विद्यमान रही। इस काल की कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख हम अगले एक प्रकरण में करेंगे। १९२६ के बाद चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिन्तांग दल की शक्ति बहुत बढ़ गई और यह चीन के बड़े भाग में एक सुव्यवस्थित व शक्तिशाली शासन की स्थापना करने में समर्थ हुआ।

(४) प्रथम महायुद्ध और चीन

चीन की उदासीनता--१९१४ में जब यूरोप में प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) का प्रारम्भ हुआ, तो जापान ब्रिटेन, फांस और रूस के पक्ष में लड़ाई में शामिल हो गया । पर चीन ने उदासीन वृत्ति को अपनाया और युद्ध में किसी पक्ष में शामिल न होने का निरुचय किया। इससे लाभ उठाकर जापान ने किस प्रकार कियाऊ ं बाऊ के प्रदेश पर, जो पहले जर्मनी के अधीन था, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । शांतुंग के प्रान्त में जो विशेषाधिकार जर्मनी को प्राप्त थे, वे सब जापान ने प्राप्त कर लिये। यदि चीन शुरू में ही जर्मनी के खिलाफ महायुद्ध में शामिल हो जाता, तो वह शांतुंग को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर सकता था। जर्मनी के विशेषाधिकारों को नष्ट करने के कार्य में ब्रिटेन, फांस आदि मित्रराष्ट्रों की सहानुभृति चीन के साथ में होती। पर युआन शी काई ने उदासीन नीति का अनुसरण करने में ही अपने देश का लाभ समझा था। चीन में युद्ध के लिये न पर्याप्त अस्त्र-शस्त्र ये और न ही इतना धन था, कि वह विदेशों से युद्ध सामग्री को क्रय कर सकता। सरकारी खर्च को चलाने के लिये भी युआन शी काई विदेशों से कर्ज लेने के लिये विवश हुआ था । साथ ही, चीन के लिये यह निश्चय कर सकना भी सुगम नहीं था, कि महायुद्ध में किस पक्ष में शामिल हुआ जाय। विदेशी राज्य उसे समान रूप से लूटने में तत्पर थे। जर्मनी ने खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का चीन के लिये कोई विशेष कारण नहीं था।

पर इसमें सन्देह नहीं. कि चीन की उक्तनीत नीति का जापान ने बहुत दुरुपयोग किया । उसने न केवल जानुंच पान्त में अमेनी के विसंधाधिकारों को नष्ट कर अपने आधिपत्य की स्थापना की, अपितु पीनी मरदार के नस्मुल २१ मार्गे भी पेश की । इस मांगों का उल्लेख हम दुर्श अध्याय में पहले कर चुके हैं। ये मांगें १९१५ के शुक्र में पेश की गई थीं। उस समय चीन पर युआन शी काई का आधिपत्य था। उसकी इतनी शक्ति नहीं थी, कि वह जापान की मांगों की पूर्णत्या उपेक्षा
कर सके। शांतुंग प्रान्त के सम्बन्ध में जापान की मांगों को उसने पूर्णरूप से "
स्वीकार कर लिया। लिआओ तुंग प्रायद्वीप, पोर्ट आर्थर और मञ्चूरियन रेलवे
के सम्बन्ध में भी युआन शी काई ने जापान के सम्मुख िमर झुकी दिया। चीन के
सबसे बड़े लोहे के कारखाने पर भी जापान के संयुक्त नियन्त्रण को स्वीकार किया
गया। जापान की इस मांग के विषय में, कि चीन अपने समृद्रतट पर स्थित
कोई नगर व बन्दरगाह किसी अन्य राज्य को पट्टे आदि पर न दे, युआन शी काई ने
यह कहा कि वह इस बात के लिये तैयार है, कि चीनी समुद्रतट का कोई भी प्रदेश
किमी बिदेशी राज्य (जिनमें जापान भी शामिल हो) को नहीं दिया जायगा।
जापान ने भी इस विषय में मामले को अधिक नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसके कारण
उसे फांस, ब्रिटेन आदि के विरोध का भय था। अस्त्र-शस्त्र आदि को जापान से
खरीदने की मांग के सम्बन्ध में युआन शी काई ने यह कहा, बिः इस मामले का
विचार भविष्य के लिये स्थिति रखा जाय।

जापान की २१ मांगों के विषय में चीन की जिस प्रकार झुकना पड़ा, उससे यह स्पष्ट है, कि महायुद्ध में उदासीन रहकर चीन ने बहुत बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिक्षर् था । इसके कारण जापान को पूर्वी एशिया में मनमानी करने का अवसर मिल गया था। जिटेन, फांस आदि यूरोप में युद्ध-कार्य में इतने अधिक व्यप्र थे, कि उन्हें सुदूर पूर्व के मामलों पर ध्यान देने का अवकाश नहीं था। साथ ही उनके लिये यह भी सम्भव नहीं था, कि वे जापान को नाराज कर सकते । पूर्वी एशिया में जापान ने ही जर्मनी की शक्ति का अन्त किया था, और जापानी जहाजी बेड़े को यह कार्य सुपुर्द था, कि वह प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जर्मनी के लिलाफ पहरा रलने का काम करे। जब यूरोप में महायुद्ध ने अधिक उग्र रूप धारण किया, तो मित्रराष्ट्री ने जापान से अनुरोध किया, कि वह अपने कुछ जंगी जहाजों को भूमध्यसागरमें भी भेजे । जापान मित्रराष्ट्रों में सम्मिलित था और ब्रिटेन, फांस आदि उसकी सहायता को बहुत महत्त्व देते थे । इसके विपरीत चीन महायुद्ध में उदासीन था । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ, कि जापानको चीन में अपने प्रभ्रत्व को विस्तृत करने का सुवर्णीय अवसर हाथ लग गया । शांतुंग और मञ्चूरिया में जिस ढंग से इस समय जापान ने अपनी शक्ति का विकास किया, उसके कारण भविष्य में उसके लियें चीन में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिये मार्ग बहुत कुछ साफ हो गया।

चीन का महायुद्ध में प्रवेश--१९१७ के प्रारम्भ में संयुक्तराज्य अमेरिका ने मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका ने

अन्य उदासीन राज्यों से भी अपील की, कि वे जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। पेकिंग में स्थित अमेरिकन राजदून के अन्रोध को स्वीकार कर प्रधान मन्त्री ्रैंआन ची जुई ने चीन के लिये महायुद्ध में सम्मिलित हो जाने को हितकर समझा । चीनी सरकार की ओर से पहले जर्मनी को नोटिस दिया गया, कि उदासीन राज्यों के जहाजों पर पनड्ब्यियों द्वारा आक्रमण करना अन्तर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के विरुद्ध है, अतः इस प्रकार के हमलों को त्रन्त बन्द कर दिया जाय । जर्मन सरकार ने चीन के नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसपर चीनी सरकार ने जर्मनी के साथ अपने सम्बन्ध का विच्छेद कर लिया। पर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने से पूर्व तुआन ची जुई यह चाहता था, कि मित्रराष्ट्रों से (जिनमें अव अमेरिका भी सम्मिलित हो चुका था) एक ऐसा समझौता कर ले, जो चीन के लिये लाभदायक हो । इस समझौते के लिये वह निम्नलिखित शतें पेश करता था--(१) बोक्सर युद्ध के वाद चीन को जो हरजाना विदेशी राज्यों को देना था, उसमें से उस अंश को रह कर दिया जाय, जो जर्मनी को दिया जाना था। (२) मित्र-राष्ट्रों को हरजाने की जो रकम दी जाती थी, उसकी अदायगी को अभी स्थगित रखा जाय । (३) चीन के आयात और निर्यात माल पर तट कर की जो दरें सन्धियों क्वारा निर्णीत थीं, उन्हें दोहराया जाय और चीन को तट करमें वृद्धि करने की अन्मति दी जाय । (४) बोक्सर युद्ध की समाप्ति पर विविध सन्धियों द्वारा जो विदेशी सेनायें पेकिंग व अन्य चीनी नगरों में स्थापित की गई थीं, उन्हें अब चीन से हटा लिया जाय । इन शर्तों को स्वीकार कर लेने पर मित्रराष्ट्रों को यह लाभ या, कि चीन महायुद्ध में जर्मनी के खिलाफ शामिल हो जाता। सैनिक दृष्टि से चीन मित्रराष्ट्रों के लिये बहुत अधिक उपयोगी नहीं हो सकता, पर उसके लिये यह सुगम था, कि चीनी मजदूरों को वड़ी संख्या में युरोप में कार्य करने के लिये भेज दे। चीनी मजदूर फ़ेंडच और ब्रिटिश मजदूरों का स्थान ले लें, और यूरोपियन मजदूर मेना में भरती होकर लड़ाई के मैदान में जा सकें। इसके अतिरिक्त चीन अनेक प्रकार का कच्चा माल व भोजन-सामग्री भी मित्रराष्ट्रों को दे सकता था। इस दिष्ट से मित्रराष्ट्र भी चीन के युद्ध में सम्मिलित होने को पर्याप्त महत्त्व देते थे।

पर मिशराष्ट्र इस बात के लिये तैयार नहीं हुए, कि वे पहले तुआन ची जुई हुएर पेश की गई शतों को स्वीकार कर लें। उनका कहना था, कि पहले चीन सिंशराष्ट्रों के पक्ष में लड़ाई में शामिल हो जावे और बाद में वे उसकी शतों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने भी तैयार होंगे। पर चीन की पालियामेन्ट बिगा किसी शर्त के युद्ध में गामिल होने को तैयार नहीं भी। इस प्रका पर नुआन भी जुई और पालियामेन्ट में जो संघप हुआ, उसका उन्लेख हम इस अध्याय में पालें कर

चुके है। तुआन ची जुई ने पालियामेन्ट को वर्षास्त करके मम्पूर्ण राजशिवत को अपने हाथों में ले लिया, और मित्रराष्ट्रों के पक्ष में होकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। १४ अगस्त, १९१७ को चीन बाकायदा महायुद्ध में शामिलें हो गया।

महायद्ध में भाग लेने के परिणाम--(१) जब चीन मित्रराष्ट्रों का पक्ष लेकर लड़ाई में शामिल हो गया, तो उन्होंने तुआन ची जुई की शर्ती पर सहान्भृतिपूर्वक विचार किया । इन शतों में से उन्होंने तटकर में वृद्धि करने की बात को स्वीकार किया। तटकर में इस समय जो वृद्धि हुई, उसके कारण चीनी सरकार को यह अवसर मिला, कि वह पांच फी सदी अतिरिक्त तटकर वसूल कर सके। चीन की राजकीय आमदनी की विद्ध में इससे बहुत सहायता मिली। (२) जर्मनी और आस्ट्रिया की जो कुछ भी सम्पत्ति चीन में थी, उस सब पर चीनी सरकार ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अन्य पाश्चात्य राज्यों के समान जर्मनी ने भी चीन के बन्दरगाहों में बहत से विशेषाधिकार प्राप्त किये हए थे। उसकी बडी-बड़ी व्यापारिक कोठियां वहां बनी हुई थीं। इन सब पर चीन ने कब्जा कर लिया। (३) मित्रराष्ट्रों ने इस बात को स्वीकार किया, कि बोक्सर यद्ध के बाद हरजाने की जो रकम चीन द्वारा जर्मनी को प्रदान करनी थी, उसे रह कर दिया गया। अन्द्रः देशों को हरजाने की रकम अदा करने की बात को पांच साल के लिये स्थगित कर दिया गया। (५) युद्ध की समाप्ति पर जब सन्धि परिषद् के अधिवेशन हों, तो चीन को भी उसमें अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो, यह बात भी स्वीकृत कर ली गई।

महायुद्ध में शामिल होने के कारण जहां चीन को ये लाम हुए, वहां मित्रराष्ट्रों को भी उससे अनेक लाभ हुए। ये लाभ निम्नलिखित थे—(१) इस समय मित्र राष्ट्रों ने हजारों मजदूर चीन से भरती किये। इन्हें फांस व यूरोप के अन्य रणक्षेत्रों में काम करने के लिये भेजा गया। चीनी मजदूरों के कीरण यूरोपियन मजदूरों के लिये सेना में भरती हो सकना सम्भव हो गया। (२) चीन से मित्रराष्ट्रों को कच्चा माल व भोजन प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुआ। महायुद्ध के कारण यूरोप में इन पदार्थों की बहुत कमी थी। चीन के सुविस्तृत प्रदेशों से अनेक प्रकार का माल इस समय मित्रराष्ट्रों के लिये सुलभ हो गया। (३) महायुद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी के जो जंगी व व्यापारी जहाज पूर्वी एशिया में विद्यमान थे, उन्होंने चीन की समुद्र तट पर आश्रय लिया हुआ था। जापान के कारण इन जहाजों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि जर्मनी वापस जा सकें। क्योंकि चीन युद्ध में उदासीन था, अत: उसके समुद्र तट पर विद्यमान इन जर्मन जहाजों पर जापान व अव्य मित्रराष्ट्र

कब्जा नहीं कर सकते थे। जब चीन युद्ध में शामिल हो गया, तो ये सब जर्मन जहाज दुम्बराप्ट्रों के हाथ में आ गये। इस समय मित्रराष्ट्रों के पास जहाजों की बहुत कमी थी, जर्मन पनडुब्बियों ने मित्रराष्ट्र पक्ष के बहुत से जहाजों को डुबो दिया था। जर्मन जहाजों के हाथ आ जाने से मित्रराष्ट्रों की नाविक शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई।

वेरिस की सन्धि परिषद् और चीन--१९१४-१८ के महायद्ध की समाप्ति के बाद परास्त देशों के साथ सन्धि करने के लिये पेरिस में सन्धि परिपद का आयो-जन किया गया । इसमें चीन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए । इस समय चीन में दो सरकारें थीं, पेकिंग की सरकार जिसका नेता तुआन ची जुई था और कैन्टन की सरकार, जिसका नेता डा॰ सन यात सेन था। सन्धि परिषद् में सम्मिलित चीनी प्रतिनिधि दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पेरिस की सन्धि-परिषद में नीनी प्रतिनिधियों की मुख्य मांग यह थी, कि गांतुंग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे और युद्ध के दौरान में जिन्हें जापान ने प्राप्त कर लिया था, वे अब चीन को प्राप्त हों। युद्ध के अवसर पर जापान ने २१ मांगों को पेश कर चीन को जिस ढंग से एक ऐसी सन्चि करने को विवश किया था, जिसके कारण ्यातुंग और मञ्चिरिया में जापान का प्रभाव व प्रभुत्त्व स्थापित हो गया था, उस सन्धिको रह किया जाय। पर जापान चीन की इस मांग को किसी भी प्रकार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अन्य मित्रराष्ट्र भी जापान के मुकाबले में चीन को कोई महत्त्व नहीं देना चाहते थे। वे स्वयं इस बात के लिये उत्स्क थे, कि जर्मनी की पराजय के कारण शांतुंग के प्रदेश में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का जो अवसर प्राप्त हो गया है, उसका प्रयोग किया जाय । चीन के प्रतिनिधियों के बहत जोर देने पर जापान ने इस बात को स्वीकार किया, कि वह शांतुंग में अपना राजनीतिक प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये इच्छुक नहीं है। वह केवल यह चाहता है, कि इस प्रदेश में जर्मनी को जो आधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, केवल उन्हीं को अब वह प्राप्त कर ले।

वर्साय की सन्धि और वीन पेरिस की सन्धि परिषद् के परिणाम स्वरूप की वर्साय की सन्धि तैयार हुई, उसमें चीन के साथ सम्बन्ध रखनेवाली महत्वपूर्ण शर्ते निम्नलिखित थीं—(१) बोक्सर युद्ध के परिणामस्वरूप हरजाने की जो रकम बीन द्वारा जर्मनी को देनी थी, उसे रद्द किया जाय। (२) तीन्त्सिन और हैंको में जो विशेषाधिकार जर्मनी ने चीन से १८९८ में प्राप्त किये थे, उन्हें रद्द समझा जाय। (३) महायुद्ध के समय में जर्मनी और बास्ट्रिया की जिस सम्पत्ति पर चीनी सरकार ने बाधकार कर लियाथा, वे तब चीन के पायही नहीं, विनाय उसराप्ति के जिसका जम्बन्ध दुनावानों के साथ था। (४) दात्तुन प्रान्ता में जर्मनी को जो विशेषाधिकार

प्राप्त थे, वे जापान को मिलें। शांनुंग प्रान्त में कियाऊ नाऊ के प्रदेश का जो पट्टा जर्मनी के पास था, वह भी जापान को प्राप्त हो। अगेरिका के राष्ट्रपति विल्स्त् , ने इस बात को स्वीकार किया था, कि शांनुंग प्रान्त के सम्बन्ध में चीन की मांग ज्याय पर आश्रित है। पर जापान व अन्य मित्रराष्ट्रों के सम्मुख वे अपने को असहाय अनुभव करते थे। उन्होंने इस बात से सन्तोष कर लिया था, कि वर्साय की सिष्ध के कारण जिस राष्ट्रसंघ की स्थापना की जा रही है, चीन भी उसमें सम्मिलित होगा और उसे यह अवसर होगा कि वहां वह अपनी शिकायतों को दूर करा सके। जापान ने भी मौखिक रूप से इस बात का आश्वासन दिया था, कि वह शांतुंग प्रान्त में केवल आर्थिक विशेषाधिकारों का ही उपभोग करेगा, राजनीतिक प्रमुक्त की स्थापना का उद्योग नहीं करेगा। जापान के इस आश्वासन के कारण मित्रराष्ट्रों ने अपने को यह समझा लिया था, कि वे चीन के साथ कोई विशेष अन्याय नहीं कर रहे हैं।

वर्साय की सन्धि से चीन के प्रतिनिधियों को बहुत निराशा हुई। यद्यपि इस समय चीनी सरकार की दशा बहुत अव्यवस्थित थी और वहां विविध सिपहसालार घरस्पर संघप में व्यापृत थे, पर पेरिस की सन्धि-परिपद् में चीन के साथ धोर अन्याय हुआ है, इस बात को सब लोग उम्र रूप से अनुभव करते थे। यही कारण है, कि चीन के प्रतिनिधियों ने बर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन के हस्ताक्षरों के विना ही वर्सीय की सन्धि पूर्ण कर ली गई और चीन ने जर्मनी के साथ पृथक रूप से सन्धि की।

जर्मनी और चीन की सिम्ध—क्यों कि चीन ने वर्साय की सिम्ध पर हस्ताक्षर कर देने से इनकार कर दिया था, अतः इस बात की आवश्यकता थी, कि चीन और जर्मनी पृथक् रूप से सिम्ध करें। यह सिम्ध २० मई, १९२१ को हुई और इसकी युख्य वर्ते निम्निलिखित थीं—(१) शांतुंग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनका वह परित्याग कर दे। कियाऊ चाऊ से जर्मनी के पट्टे का भी अन्त हो जाय। (२) विविध सिम्बयों द्वारा जर्मनी ने चीन के विविध वन्दरगाहों में व्यापार करने के सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार प्राप्त किये थे, उन सवका अन्त हो जाय। जर्मनी और चीन, दोनों देशों के लोगों को यह अधिकार और अवसर हो, कि वे एक दूसरे देश में व्यापार, यात्रा आदि के लिये स्वतन्त्रता से आ जर्म सकों। व्यापार और यात्रा के सम्बन्ध में चीन और जर्मनी के लोगों को समान रूप से अधिकार हो। (३) विविध सिम्धयों के कारण जर्मन लोगों को चीन में 'एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी' विषयक जो अधिकार प्राप्त थे, उनका अन्त किया जाय। सविध्य में जो जर्मन लोग व्यापार आदि के लिये चीन में रहें, उन पर चीनी

कानून लागृ हों, और उनके अभियोगों का निर्णय नीनी अदालतों द्वारा ही

ुकिया जाय।

जर्मनी और चीन की यह सन्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके कारण कम से कम एक पाश्चात्य राज्य ऐसा हो गया, जो चीन को अन्तर्रोष्ट्रीय दृष्टि से अपना समकक्ष मानता था और जिसे वहां किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। इसमें चीनी लोगों को यह आशा करने का अवकाश हो गया था, कि वे भविष्य में अन्य विदेशी राज्यों से भी इसी प्रकार की सम्मानास्पद स्थिति प्राप्त कर सकेंगे।

पर जर्मनी और चीन की सन्धि हारा शांतुंग प्रान्तमें जापानी प्रभुत्त्व की समस्या का हल नहीं हो सका था । इसके लिये चीन ने भविष्य में जो उद्योग किया, उसपर हम ययास्थान प्रकाश डालेंगे।

(५). चीन में अराजकता का काल

इसी अध्याय में पहले हम इस बात पर प्रकाश डाल चुके हैं, कि किस प्रकार पेकिंग और कैंन्टन में दो पृथक चीनी सरकारों की स्थापना हुई। उत्तरी चीन पेकिंग सरकार के अधीन था और दक्षिणी चीन कैंन्टन सरकार के। पर पेकिंग मरकार का उत्तरी चीन पर आधिपत्य नाममात्र का था,क्योंकि विविध सिपहसालार विभिन्न प्रदेशों में स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण कर रहे थे और इस बात के लिये भी प्रयत्नशील थे, कि अपनी सैन्यशक्ति का उपयोग कर पेकिंग पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लें। अनेक अंशों में यही बात कैंन्टन सरकार के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। दक्षिणी चीन के विविध प्रदेशों में उसका प्रभुत्त्व उसी अंश तक विद्यमान था, जहां तक कि विविध सिपहसालार उसकी सत्ता को स्वीकृत करने के लिये उद्यत थे। हम यह भी लिख चुके हैं, कि १९१७ में पेकिंग सरकार का शासनसूत्र तुआन ची जुई के हाथों में था।

उत्तरी चीन की पेकिंग सरकार—१९२० तक पेकिंग में तुआन ची जुई का आधिपत्य कायम रहा । अन्फू क्लब के सदस्यों को पद व रुपये का लोभ दिखाकर उसने पालियामेन्ट के बहुमत को अपने पक्ष में किया हुआ था । इसी उपाय का अश्रय लेकर उसने अपने प्रमुख विरोधी फेंग कुओ चंग के स्थान पर अपने समर्थक स्थान को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करा लिया था । हम पहले लिख चुके हैं, कि ली बुआन हुंग में स्थानगढ़ दे देने पर फेंग कुओ चंग चीन का राष्ट्रपति बन गया था । पर पन सब उपायों हारा भी उत्तरी चीन में तुआन ची जुई की स्थिति सुरक्षित नहीं हो गई थी । इसका कारण यह भा, कि उत्तरी चीन के अनेक सिपह-रालार इस समय जपनी जिन्त के निरनार में तत्तर थे और वे पेकिंग पर भी अपना

प्रभुत्त्व स्थापित कर लेने के लिये प्रयत्नशील थे। १९२० में मञ्चूरिया के सिपह-सालार चांग त्सो-लिन ने पेकिंग पर आक्रमण किया । इस आक्रमण में त्साओ कृत् उसका प्रधान सहायक था । यह हुकुआंग का सिपहसालार था । पहले इसी पद पर फेंग कुओ चंग विराजमान था । पर राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेने के बाद उसका नायब त्माओ कुन हुकुआंग का निपहसालार बन गया था । क्योंकि तुआन ची जुई ने फेंग कुओ चंगके स्थान पर ह् सू शिह चंगको राष्ट्रपति निर्वाचित कराया था, अनः त्साओ कुन उसका प्रबल विरोधी हो गयाथा। मञ्चुरिया के सिपहसालार चांग त्सो लिन और हक्यांग के सिपहसालार त्साओकून की सम्मिलित सेनाओं ने पेकिंग पर आक्रमण किया। तुआन ची जुई उनका मुकाबला नहीं कर सका। वह परास्त हो गया और पेकिंग की सरकार पर चांग त्सो-लिन का आधिपत्य स्थापित हो गया । १९२० से १९२२ तक चांग त्सो-लिन पेविंग सरकार का अधिपति रहा। पर उसकी सत्ता भी देर तक कायम नहीं रह सकी। त्साओ कुन इस बात को नहीं सह सका, कि अकेला चांग त्यां लिन पेकिंग का शासन करे। एक अन्य सिपहसालार वृ पेई-फू के सहयोग से त्साओ कुन ने चांग तसी लिन की पेकिंग छोड़कर सङ्बरिया वापस चले जाने के लिये विवश किया। सङ्ब्रिया लीटकर चांग त्सी लिन ने घोषणा की, कि मञ्जूरिया का पेकिंग सरकार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, और अब से मञ्च्रिया को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

वू पेई फू का शासन—चांग तसी लिन के चल जाने के बाद पेकिंग पर वू पेई फू का शासन कायम हो गया। पर उसकी सत्ता केवल पेकिंग नगरी तक ही सीमित थी। मञ्चूरिया पर चांग तसी लिन का आधिपत्य था। उत्तरी चीन के अन्य प्रदेशों पर विभिन्न सिपहसालार स्वतन्त्र शासकों के समान शासन करने लग गये थे। वू पेई फू की दशा कितनी शोचनीय थी, इसका अनुमान इसी घटना से किया जा सकता है, कि १९२४ में जब चांग तसी लिन ने अपनी मञ्चूरियन सेनाओं को साय लेकर पेकिंग पर आक्रमण करना शुरू किया, तो स्वाभाविक रूप से वू पेई फू उसका मुकाबला करने के लिये आगे बढ़ा, पर इस अवसर से लाभ उठाकर उसके सहायक सेनापित फेंग यू-हि सआंग ने पेकिंग पर अपना कब्जा कायम कर लिया। वू पेई फू को १९२४ में पेकिंग का परित्याग करने के लिये विवश होना पड़ा। एउ फेंग-यू-हि सआंग की स्थित भी सुरक्षित नहीं थी। अन्य सिपहसालार उसके विश्व लड़ाई करने को उद्यत थे। इस समय चीन में अराजकता विद्यमान थी। पेकिंग मरकार की सत्ता नाममात्र को थी और विविध सिपहसालार आपस में संघर्ष में तत्तर थे। यहां हगारे लिये यह गम्भव गहीं है, कि इन सिपहसालारों के पारस्परिक्ष

संघर्ष के वृत्तान्त को उल्लिखित कर सकें। वू पेई फू के खिलाफ विद्रोह कर फेंग यु हि सआंग ने पेकिंग में जो सरकार स्थापित की थी, उसमें उसे मञ्चूरिया के श्मिपहसालार चांग त्सो-िलन का सहयोग प्राप्त हो गया था । पर इन दोनों सनानियों में भी देर तक सहयोग कायम नहीं रह सका। फेंग यु हि संशान ने चांग त्सो लिन के बिलाफ लड़ाई शुरू कर दी । १९२५ में चाग त्सो लिन को एक बार फिर पेकिंग छोडकर मञ्जूरिया जापस लौट जाने के लिये विवश होना पड़ा । अब उसने अपने पुराने प्रतिद्वन्ही सेनापति वू पेई फू के साथ मुल्ह कर ली और १९२६ के गुरू में चांग त्सो लिन और वृ पेई फू की सम्मिलित सेनाओं ने फेंग यू हि सआंग के साथ मोरचा लेने के लिये पेकिंग की ओर प्रस्थान किया । पर उन्हें इस लड़ाई की आव-व्यकता नहीं हुई, वयोंकि इस बीच में कैन्टन की कुओमिन्तांग सरकार की वानित भलीभाति व्यवस्थित और सदृढ़ हो गई थी तथा कैन्टन सरकार अब इस प्रयत्न में थी, कि उत्तरी चीन के विविध सिपहसालारों को परास्त कर चीन की राप्ट्रीय एकता को फिर से स्थापित करे । इस उद्देश्य से कुओमिन्तांग सरकार की सेनाओं ने १९२६ में पेकिंग की ओर प्रस्थान किया। वूपेई फूको उनका मुकाबला करने के लिये दक्षिण की ओर जाना पड़ा। कुओमिन्तांग सरकार विविध चीनी सिपह- मालारों को परास्त कर चीन की राष्ट्रीय एकता की स्थापना के उद्देश्य में किस प्रकार सफल हुई, इस पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

तुन्तुन—इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह लिख देना आवश्यक है, कि चीन के जिन सूबेदार सेनानियों को हम अवतक सिपहसालार नाम से लिखते रहे हैं चीन में उन्हें तुचुन कहा जाता था। १९१७ से १९२६ तक का काल चीन में विविध शक्तिशाली तुचुनों के पारस्परिक संघर्ष का युग था। इस काल में चीन में कोई व्यवस्थित सरकार विद्यमान नहीं थी। रिपब्लिक का ढांचा कुछ अंशों में पेकिंग में इस काल में भी मौजूद था। तुआन ची जुई और वू पेई फू जैसे तुचुन अपने को प्रधानमन्त्री कहते थे, पर वस्तुत: वे अपनी सेनाओं की सहायता से अपना

काविपत्य स्थापित करने में तत्पर थे।

नवां अध्याय

तिन्वत, मंगोलिया और सिन्किआंग

(१) भौगोलिक परिचय

तिब्बत, मंगोलिया और सिन्किंंगा—ये तीन देश एशिया महाद्वीप के उस क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, जिसे हम ऊर्घ्य एशिया कह सकते हैं। इन तीनों देशों का कुल क्षेत्रफल २५,६९,१११ वर्गमील हैं, और इसकी जनसंख्या १,७९,६६,००० के लगमग हैं। यह स्पष्ट हैं, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इन प्रदेशों की आवादी बहुत कम हैं, और एक वर्गमील में औमतन सात व्यक्तियों का निवास है। राजनीतिक दृष्टि से ये तीनों देश विशाल चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत हैं। मञ्चू राववंश के शासनकाल में तिब्बत और सिन्किंआंग चीन के अधीनस्य देश थे, और मंगोलिया में निवास करनेवाली विविध जातियां भी मञ्चू सम्राटों को अपना अधिपति मानती थीं वर्तमान समय में तिब्बत पर समाजवादी (कम्युनिस्ट) चीनी सरकार का आधिपत्य हैं, सिन्किंआंग चीन का एक अंग हैं, और मंगोलिया दो भागों में विभक्त हैं, आभ्यन्तर मंगोलिया और वाह्य मंगोलिया। इनमें से,आभ्यन्तर मंगोलिया चीन की समाजवादी रिपब्लिक का एक भाग हैं, और बाह्य मंगोलिया में एक पृथक् समाजवादी रिपब्लिक (मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक) स्थापित हैं, जो रूसी सोवियत संघ के साथ सम्बद्ध हैं।

क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इन तीनों (व चारों) देशों की क्या स्थिति हैं, यह निम्नलिखित तालिका द्वारा भलीभांति स्पष्ट हो जायगा—

G.S.	. क्षेत्रफल	वानुगानिक जनसंख्या	मित्रिक्मील आबादी
आभ्यन्तर मंगोलिया	३,२६,२८५	86,82,000	१४.८
बाह्य मंगोलिया तिब्बत	६,२५,७८३ ९,११,२७४	२०,७८,००० ६७,९१,०००	9.9
सिन्किआंग	७,०५,७६९	80,44,000	٤٠.٠٥
ऊर्घ्व एशिया	२५,६९,१११	१,७९,६६,०००	ف

इस तालिका में विविध देशों की जो आबादी दी गई है, उसमें सिन्किआंग की अाबादी १९४८ की मनुष्यगणना के आधार पर दी गई है, इसीलिये ऊर्ध्व एशिया की जनसंख्या इस तालिका में १९४० के मुकावले में अधिक प्रदर्शित की गई है। पर इस तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है, कि एशिया भर में अन्य कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां प्रति वर्गमील मनुष्यों की आबादी इतनी कम हो। ऊर्घ्व एशिया में जनसंख्या की इस कमी के कारण निम्निलिखित हैं-(१) यह प्रदेश वहुत अधिक ठण्डा है। तिब्बत समुद्रतल से १६,००० फीट के लगभग ऊंचाई पर स्थित है. अतः स्वाभाविक रूप से वहां बहुत अधिक ठण्ड पड़ती है। मंगोलिया की ऊंचाई भी प्रायः ३००० से ५००० फीट तक है। (२) सिन्किंआंग और मंगोलिया में बड़े बड़े मरुस्थल है, जिनके कारण वहां मनच्यों के लिये अपनी आजीविका प्राप्त करने के साधन जुटा सकना सुगम नहीं है। जहां महस्थल नहीं हैं, वहां की भी प्राकृतिक दशा ऐसी नहीं है, कि अन्न प्रचर परिमाण में उत्पन्न किया जा सके । वहुत से प्रदेश पूली घास व छोटी छोटी झाड़ियों से आच्छादित हैं, जिनमें भेड़ बकरियों को तो पाला जा सकता है, पर खेती भलीभांति नहीं की जा सकती । ऊर्घ्व एशिया के सुविस्तृत प्रदेशों में ऐसे स्थान बहुत कम हैं, जो खेती के मानव सभ्यता के विकास के लिये उपयुक्त हैं। यही कारण है, कि अब तक इन प्रदेशों में समृद्ध ग्रामों व नगरों का सुचार रूप से विकास नहीं हो सका है । पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि आर्थिक दृष्टि से इन प्रदेशों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। वर्तमान समय की वैज्ञानिक उन्नति द्वारा यह सम्भव हो गया है, कि सिचाई आदि द्वारा इस क्षेत्र के अनेक स्थानों को उपजाऊ खेतों के रूप में परिवर्तित किया जा सके। रूस और चीन इसके शिये प्रयत्नशील भी हैं। कोई आश्चर्य नहीं, कि निकट भविष्य में मंगोलिया और सिन्किआंग प्रचुर परिमाण में अनाज व अन्य पदार्थों को उत्पन्न करने लगें। साथ ही, ऊर्ध्व एशिया के इन प्रदेशों में कोयला. लोहा, पेटोलियम आदि भी प्रभुत मात्रा में विद्यमान हैं। वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से ज्यों ज्यों इन प्रदेशों में यातायात और आवागमन के साधनों का विकास होता जायगा, त्यों त्यों इनके खनिज द्रव्यों की उपलब्धि सम्भव होती जायगी और इस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति में असाधारण सहायता 'सिलिमी'।

ें ऊर्ध्व एशिया के इस सुविस्तृत क्षेत्र के दक्षिण में हिमालय की पर्वतर्श्वला है। इसके उत्तर में भी अनेक पर्वतमालाएं हैं, जिनमें तिएन यान, तर्वागताई, अन्ताई और माथान की पर्वामालाएं नुरूष हैं। इसके पश्चिम में पाभीर पर्वत हैं, और पूर्व

में चीन के विविध मैवान है।

तिब्बत-- ऊर्घ्य एशिया का सबसे दक्षिणी प्रदेश तिब्बत है। यह देश पूर्व से पश्चिम तक प्रायः उतना ही लम्बा है, जितना कि भारतवर्ष है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई ६०० से ७०० मील तक है। इसके दक्षिण में हिमालय है, और उत्तर में कुनलन पर्वतमाला । पश्चिम में इसे कराकुरम और हिमालय की विवध पर्वत शृंखलाओं ने घेरा हुआ है, और इसके पूर्व में दक्षिणी चीन के विशाल मैदान हैं। निट्यत स्वयं एक विशास पथार के समान है, जिसकी औसतन ऊंचाई १६००० फीट है। राजनीतिक दिन्द से तिब्बत दो भागों में विभक्त हैं, पूर्वी या आभ्यन्तर तिब्बत (इनर तिब्बत) और तिब्बत । चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया की अनेक बड़ी निदयों का उद्गम स्थान पूर्वी तिब्बत में है । इनमें ह्वांगहो, यांगत्से, मेगोज़ और माल्यीन नदियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पूर्वी तिब्बत के भी दो भाग है, सिकांग और चिन्हाई। सिकांग पूर्वी तिब्बत का दक्षिणी प्रदेश है, इसके अनेक स्थल उपजाऊ हैं, और खेती के लिये उपयुक्त हैं। यही कारण है, कि इसमें बहुत सी चीनी बस्तियां विकसित हो गई हैं और चीनी लोग यहां खेती आदि के लिये आबाद होने छगे हैं। सिकांग का कुछ क्षेत्रफल १,७२,८६३ वर्गमील है और उसकी आवादी १७,५६,००० है। जनसंख्या का अनुपात वहां १० मन्ष्य प्रति वर्गमील है। सिकांग के कुछ स्थानों पर सधन जंगल भी विद्यमान हैं। इसके विपरीत चिन्धाई (जो पूर्वी तिव्वत का उत्तरी प्रदेश है) सुखी वास और छोटी छोटी झाड़ियों से आच्छादित है, और खेती के लिये उपयुक्त स्थानों का प्रायः वहां अभाव है । उसकी कंचाई भी औसतन १२,००० फीट है। भेड बकरी आदि के पालन के लिये यह प्रदेश उपयुक्त है। इसका क्षेत्रफल २,६९,११७ वर्गमील है, और इसमें १५,१३, ००० मनुष्यों का निवास है। एक वर्गमील में ६ के लगभग मन्ष्य वहां वसते हैं। इसका कारण यही है, कि वहां खेती के बजाय लोग पश्पालन द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। पूर्वी तिब्बत में कोई खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं या नहीं, इसका भी अभी अनुसन्धान नहीं हुआ है। पर कतिपय छोटे-छोटे कसबे वहां अवध्य विकसित हो गये हैं, जिनमें चामदो, बतांग और ताचिएनलू प्रमुख हैं। पूर्वी तिब्बत के खेतों व चरागाहों में जो कतिपय अनाज, ऊन आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं, वे इन कसबों में बिकी के लिये आते हैं, और धीरे धीरे ये कसबे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। पूर्वी तिब्बत चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत है, और अन्तर्राष्ट्रीय दिष्ट से उस पर चीत का आधिपत्य स्वीकृत किया जाता रहा है। १९०४ में शिमला में ब्रिटेनी, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों की जो कान्फरेन्स हुई थी, किन पूर्वी तिब्बत और तिब्बत की सीमा को निश्चित करने का प्रयत्न किया गया था। पर इस सीमा के सम्बन्ध में चीन और ब्रिटेन में विवाद रहा है, यश्रपि अब इस विवाद की

आवश्यकता नहीं रहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण तिब्बत ही इस समय चीन के आधिपत्य में आ गया है।

पश्चिमी तिब्बत को भी प्राकृतिक दृष्टि से दो भागों में विभनत किया जा सकता है, चड्. थड्. और दक्षिणी तिब्बत । चड थड्. अत्यधिक जीतप्रवान पथार है, जो तहासा के उत्तर में कुनल्न पर्वतमाला तक फैला हुआ है । यह प्राय: १६,००० फीट ऊंचा है, और इसके अनेक पर्वत शिखर २०,००० फीट से भी अधिक ऊँचे हैं। इस प्रदेश में कोई भी फसल पैदा नहीं की जा सकती। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी तिब्बत का तीन चौथाई भाग चड्. थड्. के पथार के अन्तर्गत है। इतने विस्तृत भ्खण्ड में जो थोड़े बहुत मनुष्य निवास करते हैं, उनकी आजीविका का प्रधान साधन पश्पालन है। वे यान और भेड़ बकरी पालकर अपना निर्वाह करते है। दक्षिणी तिब्बत में अनेक ऐसे प्रदेश हैं, जो खेती व मनुष्यों के निवास के छिये अधिक उपयुक्त हैं। इसकी ऊंचाई ६००० फीट से १५००० फीट तक की है। ऊंची जमीन पर भी यहां जो घास व वनस्पति उत्पन्न होती हैं, वे पगुओं के लिये अधिक अनुकूल हैं, और यही कारण है, कि इस प्रदेश में भेड़, बकरी, याक आदि को पाछ सकना अधिक सुगम हैं। साथ ही कम ऊंचाई की घाटियों में ऐसी जमीन भी पर्याप्त हैं, जिसे खेती के काम में लाया जा सकता है। इसीलिये इस प्रदेश के अनेक स्थानों पर आलु, जौ, गेहँ व शाक सब्जी की खेती की जाती है, और इसमें अनेक ऐसे ग्रामां व नगरों का भी विकास हो गया है, जिनमें गनुष्य अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। यही कारण है, कि इस दक्षिणी तिब्बत में एक वर्गमील में १५ मनुष्यों का निवास है। इस प्रदेश की मुख्य नदी कोड्.-पो है, जिसकी एक बाखानदी के तट पर तिब्बत की राजधानी ल्हासा स्थित है। ल्हासा तिब्बत का मुख्य नगर है और उसकी स्थिर आबादी २०,००० के लगभग है। तिब्बत के अन्य बड़े नगर प्यांची और चिगातमे हैं। दक्षिणी तिव्वत का भारत के साथ व्यापार आदि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत आने जाने का मुख्य मार्ग ल्हासा से दक्षिण की ओर कालिम्पोंग आता है।

सिन्तिआंग—तिब्बत के उत्तर में कुनलुन पर्वतमाला के पार सिन्तिआंग का सुविस्तृत प्रदेश हैं। इसके ठीक बीच में तबला एकान का विकास तरायल हैं, जिसके उत्तर और दक्षिण दोनों गानों में अने महिंग निवास काते हैं। चीन से इस अंगे जाने वाले मार्ग प्रदी तस्त्यल के दक्षिण व उत्तर में होनार जाते हैं। सिन्ति-आंग का उत्तरी मार्ग कान्सू (चीन में) से हामी और वर्तुल होता हुआ चुंगुचक पहुंच जाता है। चुंगुचक नगर सिन्तिआंग और इस की सीमा पर स्थित है। तिह्वा रिन्थिंग की राजनानी है, और १९४८ में ट्राकी जानादी ६९, २०५ थी। हामी,

वर्कुल और तिह् वा तकला मकान सब्स्थल के उत्तरी भाग में हरे भरे स्थान हैं, और इसी कारण इनमें इन नामों के नगर विकसित हो गये हैं। सिन्वाआंग का उत्तरी मार्ग तकालमकान महस्थल के उत्तर में स्थित तिएन शान पर्वतमाला के उत्तर को ओर से होता हुआ तिह् वा और चुंगुचक तक जाता है। पर इस उत्तरी मार्ग के अति-रिक्त एक अन्य मार्ग है, जो हामी से उत्तर-पश्चिम की ओर न मुडकर सीधा पश्चिम की ओर जाता है, और नूर्फान, कूच तथा आक्सू होता हुआ काशगर पहुंच जाता है। इसे सिन्किआंग के उत्तरी मार्ग की ही दक्षिणी शाखा कह सकते हैं। पर इन दो उत्तरी मार्गों के अतिरिक्त एक तीसरा अन्य मार्ग है, जो तकलामकान महस्थल के दक्षिण में कान्सू से चर्चन, खोतान और यारकन्द होता हुआ काशगर पहुंचता है। सिन्किआंग में खोतान, यारकन्द और काशगर व्यापार के बड़े केन्द्र हैं, और अच्छे समृद्ध नगर हैं। इससे अनेक मार्ग इस, अफगानिस्तान और काश्मीर को जाते हैं। मारत के प्राचीन बौद्ध पण्डितों ने इन्हीं मार्गों द्वारा मध्य एशिया में बौद्धधर्म का प्रचार किया था। मंगोल विजेताओं ने जो चीन से इस तक अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके लिये भी उन्होंने सिन्किआंग के इन्हीं विविध मार्गों का उपयोग किया था।

सिन्किआंग का कुल क्षेत्रफल ७,०५,७६९ वर्गमील है, और १९४८ में उसकीं जनसंख्या ४०,५५,००० थी। तकलामकान के विशाल महस्थल के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या का अनुपात एक वर्गमील में केवल ५.७ पड़ता है। इस आवादी के ७७ प्रतिशत लोग इस्लाम के अनुयायी हैं, और कृषि व व्यापार द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। इन मुसलमानों को तुर्की व उर्दशर कहा जाता है। काशगर आदि नगर जिन हरे भरे स्थानों पर स्थित हैं, वे खेती के लिये बहुत उपयुक्त हैं। इसीलिये ये नगर अच्छे समृद्ध हैं। १९३० में इन नगरों की जनसंख्या इस प्रकार थी—काशगर ३५,०००, यारकत्व ६०,००० और खोतान २६,०००। सिन्किआंग के नगरों की बहुसंख्यक जनता मुसलमान है, यद्यपि उनके अल्पसंख्यक लोग धर्म से वौद्ध हैं। यही बात उन विविध जातियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती हैं, जो पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह करती हैं।

यद्यपि सिन्कियांग राजनीतिक दृष्टि से चीन के अन्तर्गत है, पर रूस की समाज-वादी सरकार का उस पर बहुत प्रभाव है। चीन में समाजवादी व्यवस्थां के स्थापित होने से पूर्व ही रूस ने इस प्रदेश को अपने प्रभाव में लाना शुरू कर दिया था। रूसी रेलवे का स्टेशन आल्मा आता सिन्कियांग की उत्तर पश्चिमी सीमा से अधिक दूर नहीं है। सिन्कियांग की राजधानी तिह् वा और आल्मा आता के बीच में केवल ६०० मील का अन्तर है, बब कि चीन का समीपतम रेलवे स्टेशन पाओकी तिह् वा

में १५०० मील दूर है। रूस के प्रयत्न से तिह वा और आल्मा आता के वीच में . भेसी सड़कों का निर्माण हो गया है, जिनमें मोटरें चल सकती है। इसीलिये उत्तरी सिन्किआंग का रूस के साथ व्यापारिक सम्बन्य भलीभांति विकसित हो गृहा है। दक्षिणी सिन्किआंग का व्यापार भारत, अफगानिस्तान और चीन के साथ होता है, यद्यपि इस व्यापार के लिये अब तक भी खच्चरों व घोडों का ही प्रयोग किया जाता है। चीन और सिन्किआंग के बीच में अब ऐसी सड़कें भी बन गई हैं, जिन पर मोटरें आ जा सकती हैं। सिन्किआंग और रूस के बीच में हवाई जहाजों की सदिस भी विद्यमान है। इसके लिये हामी, तिह्वा और इली में हवाई जहाजों के उतरने के लिये अड्डों का निर्माण किया गया है। चुंगिकिंग से आल्मा आता तक बाकायदा हवाई जहाज चलते हैं, जो मार्ग में सिन्किआंग में हामी, तिह वा और इलीमें उतरते है। हवाई जहाजों की इस सर्विस के कारण अब ऐसी स्थिति आ गई है, कि सिन्कि-आंग को सभ्य संसार से सर्वथा पृथक् नहीं समझा जा सकता । खनिज पदार्थों की दिष्ट से भी सिन्किआंग पर्याप्त समृद्ध है। वहां पेट्रोलियम भी उपलब्ध हुआ है। आध्निक वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से जब इस प्रदेश का भलीमांति अवगाहन क्षिया जायगा, तो इंसमें सन्देह नहीं, कि इसके आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहायता भिलेगी।

मंगोलिया--सिन्धिआंग के पूर्व, चीन की दीवार के उत्तर और साइबीरिया के दक्षिण में विद्यमान सुविस्तृत प्रदेश को मंगोलिया कहते हैं। इस प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भाग ऐसे हैं, जो उपजाऊ हैं, और जहां मानव सभ्यता का विकास सम्भव है। इनके बीच का प्रदेश एक विशाल मरुस्थल है, जिसे गोवी का रेगिस्तान कहते हैं। गोबी मरुस्थल का दक्षिणी भाग व उसके नीचे का निवास योग्य प्रदेश इनर (आभ्यन्तर) मंगोलिया कहाता है। यह चीन के अन्तर्गत है, और वर्तमान समय में तीन प्रान्तों में विभवत है। इन प्रान्तों के नाम हैं, चहर, सुइयुआन और निगृहि सञ्जा। गोबी महस्थल का बड़ा भाग और उसके उत्तर का प्रदेश आउटर (बाह्म) मंगोलिया कहलाता है। मञ्चू सम्राट् इसपर भी अपना आधिपत्य समझते थे और उनके समय में यह प्रदेश चीन की अधीनता में था । पर चीन की अधीनता के काल में भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस प्रदेश का अधिक सम्बन्ध हैंसे के साथ था । १९२१ से बाह्य मंगोलिया चीन से पृथक है, और वहां मंगोलियन पीपएस रिपब्लिक स्थापित है. जिसका संगठन समाजवादी व्यवस्था के अनुसार किया गया है। एस के मोवियत युनियन के साथ इस मंगोलियन रिपल्लिय का धनिष्ठ सम्बन्ध है । इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से इस मगय बाह्य और आभ्यन्तर मंगोलिया एक दूसरे से पृथक् हैं।

अभ्यन्तर मंगोलिया का क्षेत्रफल ३,२६,२८५ वर्गमील है और उसकी जनसंख्या ४८,४२,००० है। ऊर्घ्व एशिया का यह प्रदेश आवादी की दृष्टि से अस्ति सब प्रदेशों के मुकावले में बढ़कर है। यहां प्रति वर्गमील में १४.८ मनुष्यों का निवास है। गोबी महस्थल के दक्षिण भाग में जो मंगोलिया का प्रदेश है, वह चौड़ाई में अधिक से अधिक २५० मील है, यद्यपि उसका अधिकांश ४० मील से भी कम चौड़ा है। इम प्रदेश में जहां पशुपालन के लिये अनुकूल परिस्थितियां हैं, वहां साथ ही कृषि के योग्य भूमि भी पर्याप्त मात्रा में है। इन स्थानों पर चीनी लोगों ने अपनी बहुत सी वस्तियां कायम की हैं, और वे ज्वार, जौ, गेहूं, सरसों, अलसी, आलू आदि की खेती करके अपना निर्वाह करते हैं। इनर मंगोलिया के मुख्य नगर कल्गान, क्वेईह वा और पाओती हैं।

गोबी महस्थल के उत्तर में बाह्य मंगोलिया स्थित है। यह क्षेत्रफल में ६,२५, ७८३ वर्गमील है, और १९४४ में इसकी जनसंख्या २०,७८,००० थी । रेगिस्तान की अधिकता के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या वहत कम है। एक वर्गमील में केवल ३.३ मन्त्यों का निवास है। इस प्रदेश के बहुसंख्यक निवासी पशुपालन द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। पर कुछ स्थल ऐसे भी हैं, जो खेती के लिये उपयुक्त है, र इनमें प्रधानतया जौ, वाजरा और ज्वार की खेती की जाती है । रूस की समाजवादी व्यवस्था के कारण मंगीलियन पीपल्स रिपव्लिक उन्नति के मार्ग पर बडी तेजी के साथ अग्रसर हो रही है। सिंचाई की ओर वहां की सरकार का विशेष ध्यान है। इसीलिये अब वहां न केवल चरागाह अधिक उन्नति कर रहे हैं, पर खेती के योग्य जमीन भी लगातार वढ़ रही है। सरकार इस बात का भी यत्न कर रही है, कि इस प्रदेश के खनिज द्रव्यों का पता किया जाय और खानों का विकास हो । छोहे, तांबे, सोने, चांदी और सीसे की सत्ता का वहां पता भी लग चुका है, और सरकार इन धातुओं की निकासी के लिये प्रयत्नशील है। अनेक कल कारखानों के विकास का भी वहां प्रयत्न किया जा रहा है। मंगोलियन रिपब्लिक की राजधानी जलान वातोर है, जो रेलवे व सड़क द्वारा रूस के साथ सम्बद्ध है। हवाई जहाजों की सर्विस भी मंगोलिया में स्थापित की जा चुकी है।

अर्घ्य एशिया के विविध देशों का यह परिचय उनके इतिहास को समझने में अवस्य सहायक होगा । अभी तक इन देशों का भौगोलि परिज्ञान भी संसार के अन्य सभ्य व उन्नत देशों के समान पूर्ण नहीं है । न इनकी सीमाएं भलीभांति निर्धारित हैं, और न ही इनकी प्राकृतिक दशाओं के विषय में पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया जा सका है। इस दशा में इनके प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास के सम्बन्ध में परिचय दे सकना सुगम नहीं है। फिर भी हम इस अध्याय

के अगले प्रकरणों में इनके इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त रूप से *जल्लेख करेंगे।

(२) तिब्बत

प्राचीन इतिहास--संसार के अन्य देशों के समान प्राचीन समय में तिब्बत में भी अनेक छोटे बड़े राज्य थे। सातवीं सदी में इस देश में खोड़-गचन-गस्म-पौ नाम का शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने अन्य बहुत से राजाओं को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। अपने समकालीन भारतीय राजा हर्ववर्धन के समान वह भी अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी और प्रवल सम्राट् था, और उसने पश्चिम में शिल्गित. उत्तर में चीनी तुर्किस्तान, दक्षिण में नेपाल और पूर्व में पश्चिमी चीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, । व्हासा नगरी को उसने अपने विशाल साम्राज्य की राजवानी बनाया। इस सम्राट् की दो रानियां थीं, प्रथम नेपाल के राजा अंशुवर्मा की कत्या खि-चुन और दूसरी चीन के राजा की कन्या कोइ.-जों। ये दोनों रानियां बौद्ध धर्म को मानतेवाली थीं और सम्राट् खोड्-गचन-गस्म-पो ने उनके पुजा पाठ के लिये दो विशाल बौद्ध मन्दिरों का निर्माण कराया था । यद्यपि बौद्ध धर्म का प्रवेश इस समय से पहले भी तिब्बत में हो चुका था, पर सम्राट का आश्रय पाकर सातवीं सदी में इस धर्म का तिब्बत में बड़ी तेजी के साथ प्रचार हुआ ! इसी समय तिब्बत की भाषा को लेखबढ़ करने के लिये लिपि बनाई गई. और तिब्बत में साहित्य के निर्माण के साथ साथ कला, सभ्यता, संस्कृति आदि के क्षेत्र में भी उन्नति शक हई।

सम्नाद् स्रोड्-गचन-गस्म्-पो के समय में तिब्बत का जो उत्कर्ष शुरू हुआ था, वह उसके उत्तराधिकारियों के सगय में जारी रहा। तिब्बत के इन शिंक्तशाली सम्नाटों में खि-स्रोड्-ल्दे-ब्च्न (८०२-८४५ ई० प०) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तिब्बत के इतिहास में उसका वही स्थान है, जो भारत में सम्नाट् अशोक का है। उसने अपने देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये विशेष रूप से उद्योग किया। तिब्बत में बौद्ध धर्म की सुचार रूप से स्थापना के लिये उसने आवश्यक रामझा, कि भारत से किसी ऐसे प्रसिद्ध विद्वान को तिब्बत आने के लिये निमन्त्रित करें हैं के किये उसने अपने रामझा, कि भारत से किसी ऐसे प्रसिद्ध विद्वान को तिब्बत आने के लिये उसने अपने रामझां कि सारत से किसी ऐसे प्रसिद्ध विद्वान को तिब्बत आने के लिये उसने अपने रामझां शान्तरिक्षत को तिब्बत प्रधारने के लिये निमन्त्रित किया। आचार्य शान्तरिक्षत को तिब्बत आंकर बहां बीद्ध धर्म की विश्व हुप में स्थापित किया। अपने स्थारित के अवशेष आज नक भी तिब्बत के एक चैन्य में विद्यान हैं, और बौद्ध लोग सरीर के अवशेष आज नक भी तिब्बत के एक चैन्य में विद्यान हैं, और बौद्ध लोग

उन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। आचार्य शान्त रिक्षत के बाद पद्मसम्भव, कमलशील, ज्ञानेन्द्र, विमलिम आदि कितने ही भारतीय विद्वान् तिब्बत गये कि इन विद्वानों ने सैकड़ों बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। नवीं और दसवीं सिदयों में भारतीय आचार्यों के प्रयत्न में निब्बत में बौद्ध धर्म ने अच्छी उन्नति की। पर ग्यारहवी सदी के प्रारम्भिक भाग में तिब्बत के बौद्ध धर्म में शिथिलता आने लगी थी। इस दशा में विक्रमशिला महाविहार के प्रधान आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान (अतिशा) ने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म में नवजीवन का मंचार किया। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के भारतीय आचार्यों और उनके तिब्बती शिष्यों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से लिख सकें। इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि भारतीय आचार्यों के प्रयत्न से तिब्बत में धर्म और ज्ञान की बहुत अधिक उन्नतिहुई, और वहां बहुत से बौद्ध चैत्यों और मठोंकी स्थापना हुई। ये मठ व विहार न केवल बौद्ध धर्म के केन्द्र थे, अपितु साथ ही ज्ञान विज्ञान के भी केन्द्र थे।

तेरहवीं सदी के शुरू में प्रसिद्ध मंगोल सम्राट् चंगेज लां की मंगोल सेनाओं ने तिब्बत पर भी आक्रमण किया और प्रायः सारे तिब्बत को मंगोल साम्राज्य 🦫 अन्तर्गत कर लिया। पर मंगोल साम्राज्य के विस्तार से तिब्बत के बौद्ध पण्डित निराश नहीं हुए। मंगोल साम्राज्य के साथ तिब्बत का जो सम्बन्ध इस समय स्थापित हुआ था, उसका उपयोग कर उन्होंने मंगोलिया में भी बौद्ध प्रचारकों को भेजा। आगे चलकर ये बौद्ध भिक्षुक न केवल मंगोल लोगों को अपितु चीन के मंगोल सम्राट्को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित करने में सफल हए । १२४८ में चीन के मंगोल सम्राट् ने तिब्बत के द्व्स् और ग्चड. (जिसे हमने ऊपर दक्षिणी तिब्बत लिखा है) प्रदेश अपने गुरु को प्रदान कर दिये। तिब्बत में लामाओं या घमिचार्यों के शासन का सूत्रपात इसी समय से हुआ । तिब्बत के इन लामाओं में आचार्य फर्स-प का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १२५१ में इन्होंने चीन के मंगोल राजकुमार कुव्ले खान को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तेरहवीं सदी के अन्तिम भाग में ही तिब्बत में यह प्रथा शुरू हुई, कि लामा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को नियत करने के लिये यह निश्चय किया जाने लगा, कि दिवंगत लामा की आत्मा किस बालक में अवतरित हुई है। इस समय तिब्बत में न केवल ल्हासा के दलाई लामा अपित अन्य विविध मठों के लामाओं की नियक्ति भी इसी आधार पर होती है, कि कतिपय विशिष्ट चिह्नों द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया जाता है, कि मृत छाना की चात्का ने किन बालक ने रूप में अवतार लिया है । तिब्बत में इस प्रथा का प्रारम्भ तेरहवीं सदी के जन्तिम मान (१२८४) में हुआ था ।

तेरहवीं सदी का तिब्बत के इतिहास में वहुत अधिक महत्त्व है। मंगोल आफ्रमणों के कारण इससमय तिब्बतके विविय प्राचीन राजवंशोंका अन्तहआऔर मंगोलसम्राट् द्वारा वहांका शासन बौद्ध धर्माचार्यों के सुपूर्व किया गया। १२४८ में तिब्बत के कितपय प्रदेश मंगील सम्राट् हारा बाँद्ध गुरु को प्रदान किये गये थे। पर यह धर्मगुरु केवल अपने प्रदेशों से ही संतुष्ट नहीं रहा । उसने तिब्बत के अन्य प्रदेशों को अपनी अधीनता में लाना ग्रूक किया और १२५२ तक निब्बत के तेरह प्रान्तों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । अब तिब्बत में किसी राजवंश का शासन नहीं रहा था । बौद्धों के विविध मठ जहां धर्म के केन्द्र थे, वहां देश में व्यवस्था रखना भी उन्हीं का काम था। प्रत्येक बड़े मठ की अपनी सेना होती थी। और इस सेना की सहायता से जहां एक तरफ विविध मठाधीश अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक शासन और व्यवस्था कायम रखते थे, वहां साथ ही परस्पर संघर्ष में भी तत्पर रहते थे। तिब्बत काबौद्ध धर्म अनेक सम्प्रदायों में विभक्त था और प्रत्येक मठ किसी सम्प्रदाय विशेष के साथ सम्बद्ध होता था। मठाधीशों की स्थित सामन्त राजाओं के रामान थी। सब मठाधीश चीन के मंगील सम्राट को अपना अधिपति स्वीकृत करते थे और आपस में संघर्ष करते हुए अपने प्रभुत्त्व को विस्तृत करने के लिये तत्पर रहते थे । पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदियों में तिब्बत में यही अवस्था रही । सतरहवीं सदी में मंगोलिया के मंगोल सरदार की सैनिक सहायता से तिब्बत के अन्यतम मठाधीश दलाई लामा ब्ली-ब्सड्-ग्य-म्छोने अन्य मठाधीशों की परास्त कर अपनी सत्ता स्थापित की । जिस मंगोल सरदार ने दलाई लामा के इस उत्कर्ष को कायम किया था, उसका नाम ग्-श्री-लान था । वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और दलाई लामा को अपना गुरु मानता था। १६४२ में दलाई लामा सम्पूर्ण तिब्बत का अधिपति बना । तब से अब तक उसी की अवतार परम्परा में तिब्बत का शासन चला आता है। दलाई लामा न केवल तिब्बत के सबसे बड़े मठाधीश होते हैं, अपित साथ ही वहां के प्रमुख शासनाधिकारी भी होते हैं।

इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि तेरहवीं सदी में चीन में जो मंगोल साम्राज्य स्थापित हुआ था, चौदहवीं सदी के उत्तराई (१३६८) में चीन में उसका शासन समाप्त हो गया था। मंगोलों की शक्ति के हास होने पर चीन में स्थि वंश (१३६८-१६४४) का शासन प्रारम्भ हुआ था। पर इस मिंग वंश का शासन सिन्किंशंग और मंगोलिया में विद्यमान नहीं था। ये प्रदेश अब भी विविध मंगोल सरदारों की अधीनता में थे। यही कारण है, कि गंगोल सम्राटों के समय तिब्बत पर चीन भा जो अधिपत्न प्रायभ हुआ था, यह भिग वंश के शासनकाल में जारी नहीं रहा। पर शिन्किंशंग और गंगोलिया के विविध मंगोल सरदार तिब्बत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहे । १६४२ में मंगील सरदार गुश्रीखान के साहास्य द्वारा है। तिब्बन पर दलाई लामा का शासन स्थापित हुआ था । 💃

चीन में मिश वंश का शासन देर तक कायम नहीं रह सका । १६४४ में मञ्चे लोगों ने चीन पर आक्रमण किया और उसे जीतकर एक नये राजवंश की स्थापना की । इस इतिहास में चीन के इस नये राजवंश को हम मञ्जू राजवंश लिखते रहे हैं। इसी को चिगवंग भी कहा जाता है। मञ्च या चिक्न वंग के अनेक सम्राट अत्यन्त शक्तिशाली थे। इनमें सम्राट कांग हुसी (१६६१-१७२२) का तिब्बत के इतिहास के साथ विशेष सम्बन्ध है। दलाई लामा के पद पर कौन व्यक्ति आरूढ़ हो, इस प्रकृत पर एक विवाद का लाभ उठाकर सम्राट् कांग-ह् सी ने तिव्वत पर आक-मण किया। १७२० में चीन की सेनाओं ने ल्हासा पर कब्जा कर लिया, और नये दलाई लामा के पद पर उस उम्मीदवार की नियक्ति हुई, जिसे सम्राट् कांग .ह सी का समर्थन प्राप्त था। इस समय से तिब्बत पर फिर से चीन का आधिपत्य स्थापित हो गया। मञ्जू सम्राटों के शासनकाल (१६४४-१९११) में तिब्बत की स्थिति चीन के साम्राज्य में एक अधीनस्थ व करद राज्य के समान थी। जब चीन में रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब भी तिब्बत पर चीन की रिपब्लिकन सरकार अपना प्रभुत्त्व समझती थी। इस समय भी तिब्बत पर चीन कि प्रभुत्त्व स्थापित है, और वहां की समाजवादी सरकार तिब्बत को चीन का एक अंग मानती है।

पाश्चात्य वेशों से सम्पर्क मंगोल साम्राज्य के उत्कर्षकाल में जब मार्को पोलो आवि यूरोपियन यात्री चीन में आने जाने लगे, तब तिब्बत के साथ किसी पाश्चात्य यात्री ने सम्पर्क स्थापित नहीं किया। सबसे पूर्व १६२६ में जेमुइट सम्प्रदाय का पोर्तुगीज पादरी अन्द्रेदा ने तिब्बत में प्रवेश किया, और वहां ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया। पर अन्द्रेदा लहासा तक नहीं पहुंच पाया था। सतरहवीं सदी में रोमन कैथोलिक धर्म के एक अन्य सम्प्रदाय के कैपुचिन फादर्स लहासा में गये और १७०८ तक वहां अपने धर्म के प्रचार में लगे रहे। पर अपने कार्य में उन्हें विशेष सफलता नहीं हुई और वे चीन व' जापान के समान तिब्बत में ईसाई धर्म की नींय डालने में समर्थ नहीं हए।

त्रिटेन के साथ सम्पर्क अठारहवीं सदी के उत्तराई में जब बिटिश खेम भारत के अच्छे बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे, उनका ध्यान तिब्बत की ओर भी आकृष्ट हुआ। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित इस देश की उपेक्षा कर सकना बिटिश लोगों के लिये सम्भव नहीं था। इसीलिये जब लाई हिस्टम्स भारत के गवर्नर जनरल थे, ज्यार्ज बोगल की बिटिश प्रतिनिधि के रूप में

तिव्यत भेजा गया । उसके बाद १७८३ में कैप्टन टरनर की तिव्यत में ब्रिटेन का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया । पर अठारहवीं सदी के ये ब्रिटिश प्रतिनिधि तिट्वत के साथ व्यापारिक व राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ रहे । उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में जब वरमा पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया था, भारत की ब्रिटिश सरकार ने यह प्रयन्त किया, कि निब्बत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया जाय । तिब्बत चीन की अधीनता में था, अनः पैकिंग की मञ्च सरकार से ल्हासा में अपना व्यापारिक मिशन भेजने की अतमति ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त कर ली। पर तिब्बत की सरकार यह नहीं चाहती थी, कि चीन के समान तिब्बत में भी पाक्चात्य लोगों का प्रवेश हो और वे व्यापार की आह भें वहां अपने राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना का उद्योग करें। तिब्बती सरकार ने ब्रिटिश सिशन को अपने देश में प्रविष्ट होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया । ब्रिटिश लोग कही बल का प्रयोग कर तिब्बत में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें, इसलिये तिब्बत की एक सेना ने सिविकस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन के मियन को सिविकम होकर तिब्बत में आना था। १८८८ में ब्रिटिश लोग तिब्बती सेना को सिविकम से वाहर निकालने में समर्थ हए, पर तिब्बत की सरकार के विरोध के कारण उनका व्यापारिक मिशन इस समय तिब्बत नहीं जा सका। तिब्बत और सिक्किम की सीमा के सम्बन्ध में विवादग्रस्त बातों का निर्णय करने के लिये एक संयुक्त कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसमें चीन और ब्रिटेन के प्रतिनिधि नियत फिये गये। इस कमीशन ने इस बात की भी योजना की, कि यातुंग (तिब्बत-सिक्किम की सीमा पर) में एक ऐसा व्यापारिक केन्द्र कायम किया जाय, जहां तिब्बत और भारत का व्यापार विकसित किया जा सके । पर यह योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि तिब्बत के लोग पाश्चात्य देशों के साथ अपना सम्बन्ध हानिकारक समझते थे। वीसवीं सदी के शुरू में जब लार्ड कर्जन भारत का वायसराय था, भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान से अलग थी। इस समय विश्व की अन्तरिष्ट्रीय राजनीति में रूस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। ईरान, भारत आदि सर्वेत्र रूस और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां एक दूसरे के साथ टकरा रही थीं। इस दशा में यह स्वामाविक था, कि तिब्बत को भी रूस और ब्रिटेन दोनों ही अपने प्रभाव में ्रिकों का प्रयत्न करते । इस समय तिब्बत के दलाई लामा का प्रधान सलाहकार दाजिप नाम का व्यक्ति था, जो जाति से मंगोल था, पर रूस की प्रजा था। १९०० में उत्तरे म्हम दी याता की और जार की सरकार ने उनका वड़ी धुनवाम के साम स्वागन किया । ब्रिटेन की इसमें बहुत जिल्ही हुई । अग्रेजी ने अपदार कि एस लिंद्यक्ष में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिये प्रयक्तकीय है । यदि भारत के

पड़ोसी राज्य तिब्बत में रूस का प्रभाव कायम हो जायगा, तो यह बात त्रिटेन के लिये बहुत हानिकारक होगी।

तिब्बत पर प्रभुत्त्व के लिये संघर्ष—लार्ड कर्जन कट्टर साम्राज्यवादी याँ 🖟 वह चाहता था, कि जिस प्रकार विविध पाश्चात्य देश चीन, सिआम, ईरान आदि एशियन देशों में अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर रहे हैं, वैसे ही तिब्बत में भी जिटिश आधिपत्य को कायम किया जाय । इसीलिये उसने इङ्गलैण्ड की सरकार पर इस बात के लिये जोर देना शुरू किया, कि एक ब्रिटिश मिशन तिब्बत भेजा जाय। यह मिशन तिब्बत की सरकार के सम्मुख उन समस्याओं को उपस्थित करे, जो सिक्किम और तिब्बत की सीमा पर उत्पन्न हो रही हैं। यह मिशन तिब्बत की सरकार को यह जताये, कि जिस ढंग से तिब्बत पाश्चात्य देशों के सम्पर्क से पृथक रहने का प्रयत्न कर रहा है, वह वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है। १८८८ में चीन और ब्रिटेन की सरकारों ने तिब्बत के सम्बन्ध में जो योजना स्वीकृत की थी. उसे किया में परिणत करना तिब्बत की सरकार का कर्तव्य है, और अंग्रेजों को विब्बत में व्यापार आदि की सुविधाएं मिलनी आवश्यक हैं। वस्तुतः लार्ड कर्जन षिटिश मिशन की तिब्बत भेजकर उस देश के साथ उसी ढङ्ग की सन्धि करना चाहता था, जैसी सन्धियां उन्नीसवीं सदी के मध्य गाग में चीन की पेकिंग सरकार्य से की गई थीं। उसे इस बात की बहुत चिन्ता थी, कि कहीं तिब्बत रूस के प्रभाव में न आ जाय, क्योंकि उस दशा में रूस का प्रभावक्षेत्र भारत की सीमा तक विस्तत हो जायगा। पर ब्रिटेन की सरकार तिब्बत के सम्बन्ध में इस उग्र नीति का अवलम्बन करने के विरोध में थी। यूरोप की राजनीति में उस समय ब्रिटेन जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिन्तित था। इसीलिये वह रूस और फांस के साथ मैत्री करने के लिये तत्पर था। इसका परिणाम यह हुआ, कि तिब्बत के सम्बन्ध में एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न हो गई। लार्ड कर्जन इस देश को ब्रिटिश प्रभाव में लाना चाहता था, ब्रिटेन की सरकार तिब्बत के मामले में रूस को नाराज नहीं करना चाहती थी। रूस का कहना था, कि वह तिब्बत में अपने प्रभत्त्व को स्थापित करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है और चीनी सरकार पर ब्रिटिश राजदूत इस बात के लिये जोर दे रहा था, कि वह १८८८ की योजना को किया में परिणत करने के लिये तिब्बत को विवश करे, पर चीनी सरकार तिब्बत को विवश करने की स्थिति में नहीं थी। आखिर, लार्ड कर्जन की प्रेरणा से इङ्गलैण्ड की सरकार ने तिब्बत 🕷 अपना मिशन भेजने की अनुमति दे दी। कर्नल यंगहरूबैण्ड को इस मिशन का नेता नियत किया गया और तिब्बती व चीनी सरकारों को यह सूचना दे दी गई, कि भारत-तिब्बत सीमा के पार तिब्बत के खम्बाजोग नामक स्थान

पर उनके प्रतिनिधि ब्रिटिश मिशन से भेंट करें। तिब्बत की सरकार का कहना था, कि उसके प्रतिनिधि भारत-तिब्वत सीमा के किसी स्थान पर ब्रिटिश र्जियान से भेंट कर सकेंगे, लम्बा जोंग में नहीं। परिणाम यह हआ, कि चीनी सरकार के प्रतिनिधि तो खम्बा जोंग में पहुंच गये, पर तिब्बत के प्रतिनिधि वहां नहीं आये। अब कर्नल यंग हस्बैण्ड ने ग्यांची की तरफ प्रस्थान कर दिया और मार्च, १९०४ में उसका मिशन तिब्बत के इस नगर में पहुंच गया। तिब्बत की सरकार इस बात को नहीं सह सकी। उसकी सेना ने ब्रिटिश मिशन का मुकाबला किया। यहां यह ध्यान में रखना चाहिये, कि कर्नल यंग हस्बैण्ड के मिशन के साथ एक अच्छी वडी अंग्रेजी सेना भी थी, जो सब प्रकार के आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। तिब्बत की सेना इसके मुकाबले में नहीं ठहर सकी। ३१ मार्च, १९०४ के युद्ध में ७०० के लगभग तिब्बती सैनिक लड़ाई में काम आये । ११ एप्रिल को अंग्रेजी मिशन ग्यांची पहुंच गया। पर दलाई लामा के प्रतिनिधि अपने राष्ट्रीय अपमान को सहने के लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने कर्नल यंग हस्बैण्ड के साथ भेंट करने से इनकार कर दिया । अब ब्रिटिश मिशन ने ल्हासा की तरफ प्रस्थान किया । ३ अगस्त, १९०४ को अंग्रेजी सेनाएं ल्हासा पहुंच गईं। दलाई लामा को ल्हासा छोड़कर बाहर चले ्जाने के लिये विवश होना पड़ा।

अब तिब्बती सरकार को विवश होकर बिटिश मिशन के साथ सिन्ध की बात करनी पड़ी। ७ सितम्बर, १९०४ को दोनों देशों में जो सिन्ध हुई, उसकी मुख्य शतें निम्निलिखत थीं—(१) यातुंग, ग्यांची और गर्तोंक में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की अनुमित दी जाय। (२) ग्यांची में बिटेन का एक व्यापारिक एजेण्ट रह सके, जो आवश्यकता पड़ने पर ल्हासा भी जा सके। (३) तिब्बत ब्रिटिश सरकार को ७५,००,००० रुपया हरजाने के रूप में दे। इस रक्तम को ७५ वार्षिक किस्तों में अदा किया जाय। (४) चुम्बी घाटी के प्रदेश (भूटान और सिक्किम का मध्यवतीं प्रदेश) में अंग्रेजी सेनाएं तब तक रहें, जब तक कि हरजाने की पूरी रकम वसूल न हो जाय। (५) तिब्बत की सरकार को यह अधिकार न हो, कि वह अपने किसी प्रदेश को किसी अन्य राज्य को पट्टे आदि पर दे सके, या अपने प्रदेश में किसी अन्य राज्य को खान खोदने, रेलवे या सड़क बनाने, तार आदि का निर्माण करने व इसी प्रकार के अन्य कार्य की स्थिमति दे सके।

धर्नल यग हस्बैण्ड द्वारा की गई इस सन्धि का समाचार जब इङ्गलैण्ड में पहुंचा, तो वहां की सरकार को इससे बहुत चिन्ता हुई, कारण यह कि इससे रूस के भाराजहोने की बहुत अधिक सम्भावना थी। रूसकी सरकार यह कभी भी सहन नहीं कर सकती थी, कि तिब्बत पर ब्रिटेन का प्रभाव व प्रभुत्त्व स्थापित हो। इस समय ब्रिटेन रूस के साथ बिगाड़ नहीं करना चाहना था। जर्मनी की बढ़ती हुई शिवत के कारण बह रूस से मित्रता का सम्बन्ध कायम रखने के लिये उत्सुक था। परिण्युक्त यह हुआ, कि तिब्बत के साथ की गई इस सिंध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। विहास सिंध की रक्ष ७५ लाख के दी गई, और ग्यांची में स्थित ब्रिटिश एजेन्ट का ल्हासा जाने का अविकार रद्द किया गया। साथ ही यह भी तथ हुआ, वि जब निब्बत हरजाने की रक्ष की तीन किस्तें ब्रिटेन को दे चुके. तो अंग्रेजी सेनाएं चुम्बी में न रहें, बशर्ते कि तिब्बत की सरकार सिंध की अन्य सब शर्तों को मुचार रूप से पूरा कर रही हो।

तिब्बत और ब्रिटेन में सन्धि हो चकी थी, पर यह आवश्यक था कि इस सन्धि को चीनी सरकार द्वारा भी स्वीकृत करा लिया जाय, न्योंकि निब्बत चीन का अधीनस्य राज्य था । एप्रिल, १९०६ में पेकिंग सरकार के साथ ब्रिटेन ने सन्धि की, जिसके द्वारा जहां रहासा की सन्धिकी सब शतीं को स्वीकार किया गया, वहां साथ ही दो नई शतें भी बढ़ाई गईं। ये शतें निम्नलिखित थीं--(१) ब्रिटेन विद्वत को अपने अधीन करने या उसके आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करेगा । (२) चीन इस बात का जिम्मा लेगा, कि अन्य कोई विदेशी राज्य भी निव्यत को अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व में लाने का उद्योग नहीं करेगा। इस प्रकार १९०६ की सन्धि द्वारा ब्रिटेन ने इस बात का पूरा प्रबन्ध कर लिया, कि रूस तिन्यत को अपने प्रभावक्षेत्र में न ला सके । पर साथ ही उसे स्वयं भी अनेक अंशों में तिब्बत पर अपने प्रभुत्व व प्रभावका परित्याग करना पड़ा । उसने यह बात स्वीकृत की, कि वह स्वयं भी तिब्बत को अपनी अधीनता में लाने का उद्योग नहीं करेगा । तिब्बन ने २५,००,००० रुपये की जो रकम ब्रिटेन को देनी थी, उसे अदा करने की जिस्से-दारी भी चीनी सरकार ने अपने ऊपर ले ली। यह रकम १९०८ तक अदा कर दी गई और अब चीन ने यह मांग की, कि चुम्बी घाटी में जो अंग्रेजी सेना कायम है, उसे वापस वुला लिया जाय । भारत की ब्रिटिश सरकार इसके विरुद्ध थी । वह किसी न किसी बहाने चुम्बी में अपनी सेना रखने को उधार खाये हुए थी। पर इङ्गलैण्ड की सरकार ने यही तय किया, कि चुम्बी से सेनाएं हटा ली जावें। रूस के साथ मैत्री सम्बन्य की कायम रखने के लिए इङ्गलैण्ड की सरकार इस समय यह आवश्यक समझती थी, कि तिब्बत के 'ठे में दोनों देशों में किसी प्रकार के संघर्ष की राम्भावना न हो । फरवरी, १९०८ में चुम्बी से अंग्रेजी सेनाएं सामग पुछा ग्री गर्द ।

इसी श्रीज में एस और विटेनने आपसमें समझौता कर लिया था। एशिया के

विविध क्षेत्रों में इन दो देशों के हित जहां कही टकराते थे, उन सब पर १९०७ में समझौता कर लिया गया था। इस समझौते में तिब्बत के विषय में निम्नलिखित बीतें तय की गई थीं—(१) तिब्बत की स्वतन्त्रता और पृथक् सता को दोनों देश स्वीकार करते हैं, और वे इस बात पर एकमत हैं, कि तिब्बत के शासन में किसी प्रकार से भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। (२) यदि उन्हें तिब्बत की सरकार से किसी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी, तो यह सम्पर्क चीनी सरकार की मार्फत ही स्थापित किया जायगा। (३) इस व ब्रिटेन लहासा में अपना कोई एजेन्ट व प्रतिनिधि नहीं रखेगा। १९०७ के इस समझौते के कारण ब्रिटेन और इसदोनों ने ही इस बात को स्थीकार किया, कि वे तिब्बत में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वह सम्पर्क विशेष अपने प्रभुत्त्व व प्रभाव में लाने का उद्योग नहीं करेंगे।

पर रूस और ब्रिटेन की तिब्बत सम्बन्धी नीति का यह परिणाम हुआ, कि तिब्बत पर चीन का आधिपत्य और अधिक दृढ़ हो गया । इसमें मन्देह नहीं, कि तिब्बत चीन का अवीनस्थ राज्य था। दलाई लामा मञ्जू सम्राट् को अपना अधिपति स्वीकृत करता था । चीन का एक प्रतिनिधि (रेजिडेन्ट) भी ल्हासा में रहता था और वह तिब्बत की सरकार पर चीन का नियन्त्रण रखता था। पर टेरें ०७ के बाद चीनी सरकार ने तिब्बत पर अपने नियन्त्रण को और अधिक दढ़ करना शुरू किया । जुलाई, १९०८ में दलाई लामा को पेकिंग बुलाया गया । वहां जाकर उसने अनुभव किया, कि पेकिंग राजदरवार के सम्मुख उसकी स्थिति बहुत हीन है, और वह पूर्णतया मञ्चू सम्राट् का वशवर्ती है। इसी समय चीन की सेनाएं भी व्हासा पहुंच गई और उन्होंने तिब्बत को अपने अधिकार में कर लिया । इसीलिये जब १९१० के जरू में दलाई लामा चीन से तिब्बत वापस आया, तो उसने ब्रिटिश सरकार से सहायता के लिये अपील की । चीन के आधिपत्य से अपनी रक्षा करने के लिये वह फरवरी, १९१० में ल्हासा से भारत की ओर चल पड़ा और भारत की सीमा को पार कर दार्जिलिंग पहुंच गया । दार्जिलिंग से वह कलकत्ता गया और वहां उसने भारत के वायसराय लार्ड मिन्टो से भेंट की । इस बीच में चीनी सरकार ने एक नये व्यक्ति को दलाई लामा के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। पुराने दलाई लामा ने भारत की ब्रिटिश सरकार से चीनी सरकार के विषेक्ष सहायता की प्रार्थना की, पर उसे सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार इस ममग इस मिश्नि में नहीं थी, कि वह तिब्बत और चीन के आन्तरिक मामले में र र र । साथ ही, ब्रिटेन के तिब्बत में हस्तक्षेप का यह परिणाम अवश्यमभावी था, कि इस निय्यत में यिदिया हस्ताक्षेप को गासह मकता । तियनत के प्रश्न पर ब्रिटेन और रूस में फिर मनमुटाव हो, यह बात ब्रिटिश सरकार को

पसन्द नहीं थी । इस प्रकार १९१० में तिब्बत का शासन पूर्णतया चीन की अधीनता में आ गया । नया दलाई लामा पूर्णतया चीन का बशवर्ती था ।

चीन के विरुद्ध विद्रोह--१९११ में चीन में राज्यकान्ति हो गई और मङ्की सम्राट को पदच्यत कर रिपव्लिक की स्थापना की गई। चीन की इस राज्यकान्ति का वृत्तान्त हम पहले एक अध्याय में लिख चुके हैं। राज्यकान्ति के कारण चीन में जो अब्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उसमें चीनकी सरकार के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह ल्हासा में स्थित चीनी सेना की नियमित रूप से वेतन दे सके। परिणाम यह हुआ, कि ल्हासा की इस चीनी सेना ने विद्रोह कर दिया। उसने ल्हासा में लंटमार मचादी और तिब्बत के राज्यकीष को लंटना शुरू कर दिया । इस दशा में 'तिब्बती लोगों ने भी चीनी सेना का डट कर मुकाबला किया और उसे ल्हासा छोड़कर चीन वापस लौट जाने के लिये विवश किया । तिब्बत का पदच्यत दलाई लामा, जी इस समय भारत में था, इस अवसर पर शान्त नहीं बैठ सकता था । वह तूरन्त तिब्बत वापस गया और वहां जाकर उसने देश के शासन को फिर अपने हाथों में ले लिया । ल्हासा में विद्यमान चीनी रेजिडेन्ट के साथ उसने यह समझौता किया, कि वह अपने हाथ में केवल उतनी सेना रख सके, जो चीन की रेजिडेन्सी की रक्षा के लिये आवश्यक हो, पर उसे यह अधिकार न हो, कि वह तिब्बत के आहती रिक शासन में हस्तक्षेप कर सके। चीन की नई रिपब्लिकन सरकार ने भी इस समय यही उचित समझा, कि तिब्बत के दलाई लामा के साथ समझौता कर लिया जाय । चीन की सरकार इस स्थिति में नहीं थी, कि वह तिब्बत पर पहले के समान अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिये सेनाएं भेज सके । उसने दलाई लामा के शासन सम्बन्धी अधिकारों को स्वीकार कर लिया।

१९१४ का समझौता—पर कुछ समय बाद जब चीन की रिपब्लिकन सरकार की स्थिति सुदृह हो गई, तो उसने प्रयत्न किया, कि तिब्बत पर अपने प्रभुत्त्व की पुनः स्थापना करें। पर बिटिश लोग इसके विरुद्ध थे। भारत की बिटिश सरकार यह समझती थी, कि तिब्बत पर चीन का प्रभुत्त्व बिटिश हितों के लिये विधातक है। चीन एक अत्यंत विशाल राज्य था, मंचू शासन का अंत होने के बाद वहां जो नई रिपब्लिकन सरकार कायम हुई थी, वह अपने सम्पूर्ण राज्य को सुसंगठित व शक्तिशाली बनाने के लिये प्रयत्नशील थी। यदि भारत की उत्तरी सीमा पर चीन जैसे शिवतशाली राज्य का प्रभुत्त्व हो जाता, तो यह बात बिटिश सरकार की दृष्टि में अनुचित थी। अतः उसने यह घोषणा की, कि यद्यपि तिब्बत पर चीन का आधिपत्य है, पर यह उचित नहीं है, कि चीन तिब्बत को अपना एक प्रान्त बना ले और तिब्बत की सरकार की स्थिति एक प्रान्तीय सरकार के समान हो जाय। ब्रिटिश सरकार इस बात का

पूर्ण रूप से विरोध करेगी। तिब्बत की समस्या को हल करने के लिये १९१३ और फिर १९१४ में शिमला में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसमें चीन और तिब्बत के प्रतिनिधि निमन्त्रित किये गये। भारत की विटिश सरकार का परराष्ट्र सचिव इस कान्फरेन्स का सभापित बना। इस कान्फरेन्स में तिब्बत को दो भागों में विभक्त किया गया, पूर्वी तिब्बत और पश्चिमी तिब्बत। पश्चिमी तिब्बत पर दलाई लामा के शासन को स्वीकृत किया गया, और उसे देश के शासन के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार दिये गये, यद्यपि यह स्वीकार किया गया कि उसका शासित प्रदेश भी चीन का एक अधीनस्य राज्य है। पूर्वी तिब्बत में चीन का आधिपत्य अधिक सुदृढ़ व कियात्मक रूप से स्थापित किया गया। इस पूर्वी तिब्बत के दो विभागों—सिकांग और चिधाई—का उल्लेख हम इसी अध्याय में पहले कर चुके हैं। पूर्वी और पश्चिमी तिब्बत की सीमा भी इस कान्फरेन्स ढ़ारा निर्धारित की गई, यद्यि इस सीमा के सम्बन्ध में ब्रिटेन और चीन में मतभेद बाद में भी कायम रहा।

१९१४ की शिमला कान्फरेन्स द्वारा तिब्बत की राजनीतिक स्थिति सर्वथा स्पष्ट हो गई। ब्रिटेन ने उस पर चीन के आधिपत्य को स्वीकृत किया और चीन ने यह स्वीकार किया कि पश्चिमी तिब्बत के शासन में उसकी तरफ से कोई हुस्तक्षेप नहीं किया जायगा। इस समय से पूर्वी तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व निरन्तर बढ़ता गया। उसके उपजाऊ प्रदेशों में बहुत से चीनी लोग निरन्तर आबाद होते गये और धीरे-धीरे उसके दोनों विभागों की स्थित चीन के अन्य प्रान्तों के समान होती गई। इसके विपरीत पश्चिमी तिब्बत पर दलाई लामा का शासन कायम रहा और क्योंकि १९१४ के बाद चीन की आन्तरिक राजनीतिक दशा निरंतर अध्यवस्थित होती गई, अतः चीनी सरकार उसके शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकी। तिब्बत और चीन के व्यापारिक मार्ग इस काल में सुरक्षित दशा में नहीं रहें, इस कारण तिब्बत और भारत का व्यापार निरन्तर बढ़ता गया। जब चीन में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुई, तो उसकी नई सरकार ने तिब्बत की ओर भी ध्यान दिया। इस समय तिब्बत पूर्ण रूप से चीन का एक अंग है, और धीरे-धीरे उसमें भी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जा रही है।

तिब्बत की दशा—आधुनिक युग की प्रवृत्तियों का अभी तिब्बत पर प्रभाव विशेष रूप से पड़ना शुरू नहीं हुआ है। नये ज्ञान विज्ञानों का प्रवेश भी अभी वहां के शिक्षणालयों में भलीभांति नहीं हो पाया है। तिब्बत में अभी मध्यकालीन परिस्थितियों की सत्ता है। वहां भी २० प्रतिशत के लगभग जनता भिक्ष जीवन व्यतीत करती है। देशमें बहुतसे छोटे गड़े वीड गठ विद्यमान हैं, जिनमें लाखों भिक्ष

निवास करते हैं। इल मठों के स्वामित्व में बहुत सी जागीरें है, अतः इनकी आमवनी भी पर्याप्त है। ये मठ जहां बौद्ध धर्म के केन्द्र हैं, वहां साथ ही विद्या और शिक्षा कर् प्रसार करने का कार्य भी करते हैं। सभी मठ शिक्षणालय के काम आते हैं, पर तिब्बत में चार ऐसे महाविहार भी हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। ये महाविहार गन्दन्, डे. पुड्, से-रा और ठ शि-ल्हुन-पो के हैं। तिब्बत के इन शिक्षाकेन्द्रों की स्थापना पन्द्रहवीं सदी में हुई थी। इनमें डे. पुड्, विश्वविद्यालय सबसे बड़ा है, और उसमें ७,७०० के लगभग विद्यार्थीं शिक्षा पाते हैं। से-रा में विद्यार्थियों की संख्या ५,५०० से ऊपर है। इन विश्वविद्यालयों व विद्यापीठों का रूप प्रायः वैसा ही है, जैसा कि भारत के नालन्दा और विक्रमशिला का था। इनमें भाषा, ब्याकरण, दर्शन, धर्म आदि की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाता है। इन विद्यापीठों के साथ बड़े बड़े पुस्तकालय भी हैं, जिनमें हजारों प्राचीन पुस्तकें संगृहीत हैं। न के वल तिब्बत अपिनु सिन्किआंग, मंगोलिया और पश्चिमी-दक्षिणी चीन से भी वहुत से बौद्ध विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये इन में आते हैं।

अव तक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से तिब्बत का विशेष महत्त्व नहीं था। प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण यह सम्भव नहीं था, कि तिब्बत का अन्य देशों के साथ व्यापार अधिक परिमाण में विकसित हो सके। ऊन, चमड़ा आदि अनेक वस्तु वहां से भारत व चीन के बाजारों में बिकी के लिये जाती थीं, और उनके बदले में तिब्बत सूती कपड़ा व कितपय तैयार माल इन देशों से क्रय करता था। पर यह निश्चित है, कि भविष्य में तिब्बत के विदेशी व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि होगी। आधृतिक वैज्ञानिक उन्नति के कारण अब यह बहुत कठिन नहीं रहा है, कि तिब्बत में अच्छी सड़कों का निर्माण हो सके। साथ ही हवाई जहाजों द्वारा तिब्बत का विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकना भी अब असम्भव नहीं रह गया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार तिब्बत में नया युग लाने के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील है। तिब्बत की मुविस्तृत भूमि में अनेक बहुमूल्य खनिज-पदार्थों की भी सत्ता है। इनके कारण उसका न केवल आर्थिक विकास होगा, अपितु उसके अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व में भी अवश्य वृद्धि होगी।

(३) सिन्किआंग

भौगोलिक दृष्टि से सिन्तिआंग का परिचय हम इसी अध्याय में पहले दे मुक्कि हैं। अब यह आवश्यक है, कि इसके इतिहास के सम्बन्ध में भी संक्षेप के साथ लिखा जाय, क्योंकि तिब्बत के समान सिन्किआंग भी चीग का एक अंग है, और चीन की राजनीतिक प्रगति का उसपर बहुत असर पहला है।

प्राचीन इतिहास-सिन्किआंग प्रदेश के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में अभी भली-भांति परिचय नहीं दिया जा सकता । पर इस देश से आर्यावर्ती सभ्यता के इतने अधिक अवशेष मिल्ने हैं , कि अनेक विद्वानों ने इस देश का नाम ही उपरला हिन्द (Serindia) एख दिया है। जिस प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक प्रदेशों के प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ भारतीय उपनिवेशों से होता है, वैसे ही सिन्किआंग के दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश का इतिहास भी भारतीय उपनिवेशों के साथ होता है । इस प्रदेश में न केवल भारतीय लोग जाकर आवाद हुए थे, अपितू उन्होंने वहां की विविध जातियों को भी अपनी सभ्यता के रंग में रंग दिया था। भारतीय लोग इस प्रदेश को उत्तर कुरु कहते थे। उत्तर कुरु के दक्षिण में नाभक देश था, जिसका वर्तमान नाम खोतान है। इस नाभक देश में अशोक का अन्यतम पुत्र कुस्तन जाकर आबाद हुआ था, और तिब्बत की एक प्राचीन अनुश्रृति के अनुसार इस कुस्तन ने ही वहां उस उपनिवेश की स्थापना की थी, जो आगे चलकर उसी के नाम से खोतान प्रसिद्ध हुआ । खोतान के उत्तर में पामीर की पर्वतमाला और तकला मकान गरुस्थल के मध्य भाग में अन्य अनेक भारतीय उपनिवेशों की सत्ता थी। इनके और अधिक उत्तर में तकला मकान मरुस्थल के उत्तर व तिएन शान पर्वत के दक्षिण में युइशि जाति का निवास था, जिसे पुराणों में ऋषिक कहा गया है। आगे चलकर इसी युइशि जाति ने अपनी शक्ति का बहुत अधिक विस्तार किया, और इसी जाति के अन्यतम राजा कुशाण ने पहली सदी ई० प० में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें गध्यएशिया, अफगानिस्तान आदि के बहुत से प्रदेश अन्तर्गत थे। राजा क्शाण के वंशज सम्राट कनिष्क के विशास साम्राज्य का भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है । यहिश जाति के उत्कर्ष पर हमें इस ग्रन्थ में प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। यहां इतना निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त है, कि इस शक्तिशाली युइशि जाति का मल अभिजन सिन्किआंग प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही था । कनिष्क के विशाल साम्राज्य में जहां प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत शामिल था, वहां साथ ही दक्षिण-पश्चिमी सिन्किआंग भी उसके अन्तर्गत था। यहिंश लोगों ने भारत में आकर इस देश के धर्म, सभ्यता व संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया था। इससे उनके विशाल साम्राज्य में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रमार में बहुत अधिक सहायता मिली । व्यरी शताब्दी ई० प० में दक्षिण-पश्चिमी िनिक्सिंग के सम्पूर्ण क्षेत्र में गान्यार देश की प्राकृतिक भाषा का प्रचार था, और इस भाषा को अरोद्धी लिए में लिखा जाता था। उत्तर-पश्चिमी भारत में उपलब्ध हुए महाद् अदोल के शिलालेच इस धरोएफी भाषा में ही लिये हुए हैं । एसरी सदी से जीशी सदी ई० प० नक दक्षिण यदिनमी किन्किआंग की यही दशा रही । इस

प्रदेश की पुरानी बस्तियों से लकड़ी की तिस्तियों पर लिखे हुए प्राकृत भाषा के बहत से लेख उपलब्ध हुए हैं। ये सब भारत की ही अन्यतम प्राकृत भाषा के लेख हैं। खोतान के समीप गोश्रृङ्ग विहार के खण्डहरों में इसी प्राकृत 'धम्म पद' 🕏 एक प्रतिमिली है, जो भोजपत्रों पर लिखी गई है। सिन्कियांग के तुर्फान नगर का जल्लेख हम इस अध्याय में पहले कर चुके हैं। इस शहर के पुराने भग्नावशेषों मे महाकवि अश्वधोष के नाटक 'शारिपुत्र प्रकरण' के कुछ अंश मिले हैं, जो दूसरी सदी ई० प० के लिखे हुए हैं। भारतीय पुस्तकों की सबसे प्राचीन हस्त-लिखित प्रतियां ये ही हैं। इस प्रदेश में खुदाई द्वारा बौद्ध मृतियों, स्तूपों तथा मठों के बहत से अवशेष मिले हैं, जिनसे यह भलीभांति सूचित होता है, कि प्राचीन काल में उत्तर-पश्चिमी सिन्किआंग बृहत्तर भारत का ही एक अंश था। पांचवीं सदी में चीनी यात्री फाहियान और सातवीं सदी में हयएन्ट्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी । उनके वर्णनों से सूचित होता है, कि इस प्राचीन युग में यह सम्पूर्ण प्रदेश बौद्ध धर्म का अन्यायी था और सर्वत्र बौद्ध विद्वान् विद्यमान थे । इस प्रदेश के अनेक नगर बौद्ध शिक्षा और सभ्यता के प्रसिद्ध केन्द्र थे। इसमें रान्देह नहीं, कि इस प्रदेश के इतिहास में यह सुवर्णीय युग था । इस प्रदेश से अनेक बौद्ध विद्वान चीन में अपने धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे।

वीन का प्रभएव--चीन और पश्चिमी संसार को परस्पर मिलानेवाले स्थल-मार्ग सिन्किआंग से होकर ही गुजरते हैं। इसीलिये इस प्रदेश का चीन के लिये बहुत अधिक महत्त्व रहा है। यही कारण है, कि अनेक शक्तिशाली चीनी सम्राटों ने सिन्किमांग को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया। तांग वंश (६१८-९०७ ई० प०) के सम्राटों के साम्राज्य में सम्पूर्ण सिन्किआंग शामिल था। इस काल में उपरले हिन्द का भारत के साथ सम्बन्ध बहुत कम हो गया था और इस प्रदेश के प्रधान व्यापारिक नगर-काशगर, यारकन्द और खोतान-उस व्यापार के समृद्ध केन्द्र हो गये थे, जो चीन का पश्चिमी देशों के साथ होता था। तांग वंश के काल में ही अरब में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और सिन्किआंग में मुसलिग धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ । तांग वंश के पतन के बाद चीन में जो अनेक राजवंश स्थापित हुए, वे इतने शक्तिशाली नहीं थे, कि सिन्किआंग जैसे सुदुरवर्ती प्रदेशों को अपनी अधीनता में रख सनते । पर तेरहवीं सदी में जब चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल लोगों ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और चीन को जीता रू वहां एक नये युआन राजवंश (१२७९-१३६८) का प्ररम्भ किया, तो सिन्कियाँग भी उस मंगोल साम्राज्य के अन्तर्गत था। मंगोल साम्राज्य पूर्व में प्रशान्त महा-सागर ने जुरू कर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक विस्तृत था । बाद में वह अनेक

टुकड़ों में विभक्त हो गया और सिन्किआंग में अनेक मंगोल सरदार चीन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगे । बाद में मञ्चू सम्राटों ने सिन्किआंग वर अपना प्रभृत्व स्थापित किया । मञ्चू सम्राट् कांग ह् सी (१६६१-१७२२) ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पश्चिम में तकला मकान महस्थल के परे तारिम नदीं की घाटी के प्रदेश पर भी आक्रमण किया, और उसे अपने अधिकार में कर लिया । उसने सिन्किआंग को अपने विशाल साम्राज्य का एक प्रान्त बना लिया । सम्राट् कांग ह् सी के समय से अब तक सिन्किआंग चीन के अन्तर्गत है ।

यह हम पहले लिख चुके हैं, कि वर्तमान समय में सिन्किआंग के ७७ प्रतिशत निवासी इस्लाम के अनुयायी हैं। जिस प्रकार प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के प्रचारक मृदूरवर्ती प्रदेशों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे, वैसे ही मध्यकाल में मुस-लिम प्रचारकों ने अपने धर्म प्रचार कार्य में असाधारण तत्परता प्रदिश्तित की थी। सिन्किआंग के बौद्धों को भी वे अपने धर्म में वीक्षित करने में समर्थ हुए थे। सिन्किआंग के इन मुसलमानों को बौद्ध मञ्चू सम्राटों का आधिपत्य पसन्द नहीं था। अतः अठारहवीं और उन्नीसवीं सिदयों में अनेक बार उन्होंने चीनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। पर उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हुई। मञ्चू सम्राट्सिन्किआंग को अपनी अधीनता में रखने में समर्थ रहे।

१९११ में राज्यक्रान्ति द्वारा जब चीन में मञ्चू राजवंश का अन्त होक स्रिपिंडिल की स्थापना हुई, तब भी सिन्किआंग के मुसलमानों ने विद्रोह किया। १९३० में उनके विद्रोह ने भयंकर रूप घारण कर लिया, और यह विद्रोह १९३४ तक जारी रहा। इस अवसर पर चीन की सरकार सोवियत रूस की सहायता से ही इस विद्रोह को शान्त कर सकी। सिन्किआंग के लोगों को यह आव्यासन दिया गया, कि उन्हें स्थानीय स्वशासन के अधिकार दिये जायंगे और अपने आन्तरिक शासन में उन्हें स्वतन्त्रता रहेगी। इस व्यवस्था द्वारा ही १९३०-३४ के विद्रोह को शान्त करनेमें चीनी सरकार सफल हई।

पर १९३४ के मुधारों से सिन्तिआंग की जनता को सन्तोष नहीं था । इसी-लिये १९३७ में जब जापान उत्तरी चीन पर आक्रमण कर रहा था, उसने फिर विद्रोह कर दिया । एशिया के आधुनिक इतिहास में इस विद्रोह का बहुत महत्त्व है। इस उन पर स्थार्थान प्रकार उन्होंगे।

क्तमान स्था--ितिस्थाम के नहुनस्यक निवासी तुर्की या उईगूर लोग हैं, जो इस्लाम के अनुगायी हैं। इनमें दिक्षा का प्रायः अज्ञाव हैं। मुल्ला लोग जो कुछ शिक्षा पात हैं, वह घामिक होती है। सामुनिक ज्ञान विज्ञान से इस प्रदेश के लोग अपरिचित हैं। १९४७ तक सन्दर्भ गिन्छियांग में १५ ऐसे स्कूल थे, जिनमें वर्तमान हों से शिक्षा दी जाती थी। इनमें पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या भी कुछ सी तक ही सीमित थी। शिक्षा की इस पिछडी हुई दशा में सिन्किआंग यदि वर्तमान समयू में उन्नति की दौड़ में पीछं रह गया हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं हैं। इस प्रदेश में निवास करनेवाले चीनी लोगों में शिक्षा का पर्याप्त प्रचार है। यही कारण है, कि चीनी लोगों के लिये उसे अपनी अधीनता में रख सकता सम्भव रहा है।

सिन्तिआंग से जो माल विकय के लिये बाहर जाता है, उसमें ऊत, चमड़ा, रेशम और कपास प्रमुख हैं। पर मोवियत रूस के सहयोग से चीन की सरकार इस प्रदेश के आधिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, और कोई आश्चर्य नहीं, कि निकट भविष्य में यह प्रदेश आधिक दृष्टि से अच्छा उन्नत हो जाय।

(४) मंगोलिया

चीन की प्राचीन विशाल दीवार के उत्तर और साइबीरिया के विक्षण में मंगोलिया का जो मुविस्तृत प्रदेश है, उसका भौगोलिक परिचय हम इसी अध्याय में पहले दे चुके हैं। यह प्रदेश प्रधानतया रेगिस्तान के रूप में है, और इसीलिये इसमें किसी उन्नत सभ्यता का विकास नहीं हुआ । पर ऐतिहासिक दृष्टि से इसक्री महत्त्व कम नहीं है। बहुत प्राचीन समय से इसमें अनेक इस प्रकार की पशुपालक जातियां बसती रही हैं, जो समय-समय पर पड़ोस के उन्नत व सभ्य राज्यों पर आक-मण कर उन्हें अपने अधीन करने में तत्पर रही हैं। प्राचीन समय में इस प्रदेश में एक जाति का निवास था, जिसे चीनी लोग हियंग-नू कहते थे। संस्कृत में इसी जाति को हण कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी सम्राट् शी-हुआंग-ती (२४६-२१० ई० पू०) ने इन्हीं हियंग-न लोगों के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये उस विशाल चीनी दीवार का निर्माण कराया था, जो पूर्व में समुद्र तट से शुरू होकर पश्चिम में कान्सू तक विस्तृत थी । इस दीवार के कारण हियंग-नू या हुण लोगों के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वे चीन पर आक्रमण कर सकें। अब उन्होंने पश्चिम की ओर घुमकर सिन्किआंग पर हमले श्रूक किये, और युइशि व ताहिया आदि जातियों को अपने स्थान से धकेलना प्रारम्भ किया। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि मंगोलिया के इन प्राचीन निवासी हण लोगों के सम्बन्ध में अधिक लिख सकें। इतना लिख देना पर्याप्त है, कि यह प्रदेश ऐ अनेक जातियों का निवास स्थान रहा है, जो समय-समय पर वहां से निकलकरें टिड्डी दल के समान पड़ोस के सभ्य राज्यों पर आक्रमण करती रही हैं।

इन जातियों में सबसे मुख्य मंगील जाति थी । बारहवीं सदी में मंगील लोगों

के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ। मंगोल एक पशुपालक जाति थी, जो किसी एक स्थान पर वसी हुई नहीं थी। वे डेरों में निवास करती थी और दूघ व मांस से अपना निर्वाह करती थी। चंगेज खां ने मंगोल लोगों को संगठित किया और उन्हें एक जबर्दस्त शिवत के रूप में परिणत कर दिया। चंगेज खां के साम्राज्य का हम इसी पुस्तक में पहले उल्लेख कर चुके हैं। तेरहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में मंगोल लोगों ने प्रशान्त महासागर से कैंस्पियन सागर तक अपने विकाल साम्राज्य का विकास किया। १२९७ तक चंगेज खां के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कैंस्पियन सागर से भी आगे ब्लैक सी (काला सागर) तक विस्तृत हो गई थी। इस विशाल मंगोल साम्राज्य की राजधानी कराकुरम नगरी थी, जो गोबी के महस्थल के उत्तर में मंगोलिया में स्थित थी। चंगेज खां के बाद मंगोल साम्राज्य अनेक भागों में विभक्त हो गया और पश्चिमी मंगोल राज्य ने रूस पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया। मंगोल लोगों के इतिहास के सम्बन्ध में यहां अधिक लिख सकना सम्भव नहीं है। यह स्पष्ट है, कि तेरहवीं सदी मंगोलिया के लिये अत्यन्त समृद्धि और शक्ति की सदी थी।

चीन में जो मंगोल लोग गये, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया और धीरे धीरे वे चीनी सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंग गये। उनमें और अन्य चीनी जनता में कोई विशेष अन्तर नहीं रहा। चीनी ऐतिहासिकों ने कुबले खां (चंगेजखां का पौत्र) को एक चीनी सम्राट्माना है, और उससे चीन के युआन वंश का प्रारम्भ किया है। इसी प्रकार ईरान और मध्य एशिया के मंगोल लोग इस्लाम के सम्पर्क में आकर मुसलिम बन गये। पर मंगोलिया में जो विविध मंगोल सरदार अपने कवीलों के साथ निवास करते थे, वे अपनी पुरानी दशा में ही रहे। यदि चंगेज खां का विशाल साम्राज्य अखण्डित व सुविस्तृत दशा में रह पाता, तो शायद इन मंगोल कबीलों की दशा में परिवर्तन आ सकता। पर तेरहवीं और चौदहवीं सदियों में जब मानवृसमाज के पास घोड़े की अपेक्षा तेज चल सकनेवाली कोई सवारी नहीं थी, इतने विशाल साम्राज्य का एक केन्द्रीय संगठन के अधीन रह सकना सम्भव नहीं था। चीन के सम्राटों के लिथे यह सम्भव नहीं था, कि वे मंगोलिया प्रदेश के विविध सरदार इस युग (चौदहवीं सदी के अन्त) में स्वतन्त्र हो गये और उनका चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहा।

यहां यह लिख देना भी आवश्यक है, कि तिब्बत के बौद्ध प्रचारक इस समय अपने धर्म का प्रचार करते हुए मंगोलिया भी जान लगे थे ! सिन्किआंग में अपने धर्म प्रचार का कार्य करते हुए तिब्बत के भिधु गंगालिया गये थे, और वहां उन्होंने विविध मंगोल सरदारों व जनता को अपने धर्म में दीक्षित किया था। विकम शिला के प्रसिद्ध आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान ने तिब्बत के बौद्ध धर्म में नवजीवन का, संचार किया था। नई धार्मिक स्फूर्ति से अनुप्राणित होकर तिब्बत के बौद्ध भिर्स्ट्रैं सुदूर मंगोलिया में अपने धर्म के प्रचार में तत्पर थे। हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं, कि अन्यतम मंगोल सरदार गृथीखान हारा ही तिब्बन में दलाई लामा के शासन का मूत्रपात हुआ था।

चौदहवीं सदी के अन्त से सनरहवीं सदी के मध्य भाग तक मंगोलिया का चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध नहीं रहा। १६४४ में जब मंच्रिया के निवासी मञ्च लोगों ने चीन पर आक्रमण कर उमे अपने अधीन किया, तो मंगील लोगों का साहाय्य भी उन्हें प्राप्त था। अनेक मंगोलियन सरदार गञ्च आकान्ताओं के साथ थे। यही कारण है, कि सम्राट् कांग हुसी (१६६१-१७२२) ने जब सम्पूर्ण चीन पर अपने आधिपत्य को स्थापित कर अपने विशाल साम्राज्य को मंगठित किया, तो मंगोलिया का प्रदेश भी उसके अन्तर्गत था। बाह्य और आभ्यन्तर दोनों मंगोलिया मञ्च सम्राटों की अधीनता में थे। मञ्च शासन में चीनी लोगों ने मंगोलिया में अपनी बहुत सी नई बस्तियां बसाई । आभ्यन्तर मंगोलिया के अनेक प्रदेश कृषि के लिये उपयक्त हैं। चीनी लोगों ने इनमें आवाद होकर खेती प्रारम्भ की। बाह्य मंगोलिया में बहत से चीनी लोग व्यापार के लिये जाने लगे। इस प्रदेश में ऊन: खाल, फर आदि प्रचुर परिमाण में मिलती थीं। चीनी व्यापारी इनको खरीद कर मुनाफा उठाने के लिये तत्पर हुए । चीनी सरकार ने यह भी यत्न किया, कि मंगी-लिया के विविध कबीलों पर अपने शासन को सुदृढ़ रूप से स्थापित करे और मंगोल लोगों को अपनी सेना में भरती करे। बहुत से चीनी महाजन भी इस काल में बाह्य मंगोलिया गये और मंगोलियन लोगों की सरलता से अनुचित लाभ उठाने लगे । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि मंगोलियन लोगों में चौनी शासन के प्रति असन्तोष उत्पन्न हो ।

१९११ में जब चीत में राज्यकात्ति हुई, तो बाह्य मंगोलिया ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। इस उसकी पीठ पर था। भौगोलिक दृष्टि से इस बाह्य मंगोलिया के अधिक समीप था और उसके इस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध भी विद्यमान थे। इस दशा में १९१२ में इस ने बाह्य मंगोलिया को एक स्वतन्त्र राज्य के इप में स्वीकृत कर लिया। १९१३ में चीन की नई रिपब्लिकन सरकार ने इस के साथ समझौता किया, जिसमें इस ने चीन की नई सरकार को स्वीकृत किया और बदले में चीन ने बाह्य मंगोलिया की स्वतन्त्र स्थिति को मान लिया। बाह्य मंगोलिया का यह नया स्वतन्त्र राज्य स्वाभाविक इप से इस के प्रभाव में था

और इसकी स्वतन्त्र स्थिति रूसकी कृपा पर भी निर्भर थी। १९१७ में रूपमें राज्य-क्रान्ति हई और जार के एकतन्त्र शासन का अन्त होकर समाजवादी रिपव्लिक की स्यापना हुई । यह स्वाभाविक था, कि रूस की इन घटनाओं का असर मंगोरित्या पर भी पड़े । १९२१ में बाह्य मंगोलिया में भी समाजवादी क्रान्ति हो गई और रूस की सहायता से वहां समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार नई सरकार का संगठन हुआ । चीन के लिये यह बात बहुत चिन्ताजनक थी । यद्यपि १९१३ की सन्धि बारा चीन की रिपब्लिकन सरकार ने बाह्य मंगोलिया की स्वतन्त्र स्थिति को स्वीकार कर लिया था, पर अब तक भी यह देश चीन का ही एक अंग माना जाता था । इसकी स्थिति चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र राज्य के समान थी । इस दशा में बाह्य मंगोलिया में समाजवादी सरकार की स्थापना होना चीन के लिये अत्यन्त चिन्ताजनक था । १९२४ में रूस और चीन में एक नई सन्धि हुई, जिसमें चीन ने बाह्य मंगोलिया की कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकृत किया और बदले में क्स ने यह मान लिया कि यह प्रदेश चीन का ही एक अंग है, पर कियात्मक दृष्टि से बाह्य मंगोलिया का सम्बन्ध इस समय चीन की अपेक्षा रूस के साथ अधिक था। १९२४ में बाह्य मंगोलिया के शासन और सामाजिक व्यवस्था का समाजवादी ं सिद्धान्तों के अन्सार पूनः संगठन किया गया । इस प्रदेश में अब तक बौद्ध संघ का प्रभाव बहुत अधिक था। बहुत सी भूसम्पत्ति बौद्ध मठों के स्वामित्व में थी। नई स्थापित हुई मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक ने सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित कर लिया । इससे बौद्ध मठों के प्रभाव में बहुत कमी आ गई। मंगो-लियन रिपब्लिक के आर्थिक जीवन का निर्माण समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार होने से इस देश की अवस्था में बहुत परिवर्तन आ गया । जब चीन में कुओमिन्तांग वल का जोर बढ़ा और १९२७ में कम्युनिस्टों और कुओमिन्तांग सरकार में विरोध श्रूक हुआ, तो यह स्वाभाविक था कि चीन और रूस के सम्बन्ध कटु हो जावें। इस दशा में मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गई और चीन के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया।

आभ्यन्तर गंगोलिया पर चीन का आविषत्य कायम रहा । १९११ में मञ्चू शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना होनेपर इसे तीन प्रान्तों में विभवत किया गया, जिनके नाम चहर, सुईयुआन और निग्हि सआ हैं। इन प्रदेशों में चीनी लोग मञ्चू शासन के युग में ही बड़ी संख्या में बसने शुरू हो चुके थे। १९११ के बाद इस प्रवृत्ति में और अविका वृद्धि हुई। भंगोल लोग मुख्यत्या पशुपालन हारा अपना निर्वाह करते थे। चीनो किसानों का आधिक क्षेत्र में मुकावला कर समना जनके लिये सुगम नहीं था। इस दशा का गरिणान यह हुआ, कि धीरे धोरे आभ्यन्तर

मंगोलिया की सब भूमि चीनी लोगों के हाथों में आती गई। १९३१ तक यह दशा आ गई थी, कि मंगोल लोग दो तिहाई के लगभग भूमि पर अपना स्वामित्व को चुके थे। मंगोलों और चीनियों में विरोध निरन्तर बढ़ना जाता था। इस दशा किंगी जापान ने चीन में अपने उत्कर्ष के लिये किस प्रकार उपयोग किया, इस पर हम अगले एक अध्याय में यथास्थान प्रकाश डालेंगे। यहां इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि १९३१ में जापान ने मञ्च्रिया में अपना प्रभृत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था और यह स्वामाविक था, कि मञ्च्रिया के बाद जापान मंगोलिया को अपने प्रभृत्व में लाने का उद्योग करे।

दसवां अध्याय

कुओमिन्तांग दल का चीन में उत्कर्ष

(१) कुओमिन्तांग दल

मञ्च शासन का अन्त कर लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना करने के उद्देश्य से डा॰ सन यात सेन ने तुंग मेंग हुई नाम की जिस कान्तिकारी संस्था का निर्माण किया था, उसका उल्लेख पहले किया जा जुका है। १९११ की राज्यकान्ति से पूर्व यह संस्था एक गुप्त सिमिति के रूप में थी। रिपब्लिक की स्थापना के बाद इसे गप्त रूप के कार्य करने की आवश्यकता नहीं रही । पर जब १९१३ में युआन शी काई ने पेकिंग सरकार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, तो डा॰ सनयात रसेन केदल के लिये अपना कार्य करना कठिन हो गया। रिपब्लिक की स्थापना के बाद १९१२ में डा० सन यात सेन ने अपने अनुयायियों को कूओमिन्तांग दल के रूप में संगठित कर लिया था। हिन्दी में हम इस दल को 'राप्ट्रीय जनता दल' कह सकते हैं। युआन शी काई ने कुओमिन्तांग दरु को गैर कान्नी घोषित कर दिया था। इसके अनेक नेता गिरफ्तार कर लिये गये थे और अनेक लोगों को चीन से भागकर विदेशों में आश्रय लेने की आवश्यकता हुई थी। युआन शी काई का चीन पर एकाधिपत्य देर तक कायम नहीं रहा । १९१६ में उसकी मृत्य के बाद चीन के विविध प्रदेशों में अञ्यवस्था शुरू हो गई। विभिन्न सिपहसालार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण करने लगे। इस स्थिति से लाभ उठाकर डा॰ सन यात सेन ने दक्षिणी चीन में अपनी शक्ति की पूनः स्थापना की और कैन्टन को राजधानी बनाकर कुओमिन्तांग दल की सरकार का संगठन किया गया। १९२६ रो कैन्टन की इस कुओमिन्तांग सरकार के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ और कुछ वर्षों में प्रायः सम्पूर्ण चीन कुओमिन्तांग दल के शासन में आ गया।

संगठन-तारू में कुत्रोमिन्तांग दल का संगठन सुव्यवस्थित नहीं था । जो लोग दा० यन यात रोन को अपना गेना मानके थे, उसके प्रति भिक्त रखते थे, वे ही इस दल में सम्मिछित थे, सर्वसादारण जनता में इसके सिद्धान्तों का अधिक प्रचार नहीं था। यही कारण है, कि कैन्टन सरकार का प्रभत्व सम्पूर्ण दक्षिणी चीन में भी स्वीकृत नहीं किया जाता था । दक्षिणी चीन के विविध प्रदेशों के सिपहसालार जिस अंश तक उचित समझें, उसी अंश तक वे कैन्टन सरकार के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे । इस दशा में डा॰ सन यात सेन ने कुओमिन्तांग दल के पूनः संगठन पर ध्यान दिया । इस कार्य में रूस के कम्युनिस्ट दल का सहयोग लिया गया । १९१७ में रूस में कान्ति द्वारा बोल्शेविक व कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हो गई थी और रूस की नई सरकार समाज संगठन के कतिपय नवीन सिद्धान्तों के अनुसार अपने देश का शासन सूत्र संचालित करने में तत्पर थी । १९२३ में डा० सन यात सेन ने रूस की सरकार से सहयोग प्राप्त किया और माइकेल बोरोडिन नामक रूसी कम्युनिस्ट कुओमिन्तांग सरकार का सलाहकार बनकर कैन्टन पहुंच गया। उसने कुओमिन्तांग दल के पुनः संगठन पर विशेष रूप से ध्यान दिया । इसके लिये रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को आदर्श के रूप में रखा गया। यह व्यवस्था की गई, कि चीन में सर्वत्र कुओमिन्तांग दल की शाखाएं स्थापित की जावें, इन स्थानीय कमे-टियों के बाकायदा सदस्य हों, जो एक निश्चित प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करें। स्थानीय कमेटियां अपने पदाधिकारियों को स्वयं निर्वाचित करें। दो सप्ताह में एक .. बार स्थानीय कमेटी की नियमित रूप से बैठक की जाय। कमेटियों के आय व्यय को नियम पूर्वक रखा जाय और उसके ऑडिट की भी व्यवस्था की जाय । स्थानीय कमेटियों का यह प्रधान कर्त्तव्य हो, कि वे अपने अपने क्षेत्र में कुओमिन्तांग दल के सिद्धान्तों का प्रचार करें। स्थानीय कमेटियों के ऊपर तहसील, जिला और फिर प्रान्त की कमेटियों का संगठन किया गया। सबसे ऊपर अखिल चीन कुओगिन्तांग कमेटी बनाई गई, जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय कमेटियां करती थीं। यह भी व्यवस्था की गई, कि कुओमिन्तांग दल की राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य किया जाय। १९२४ में कूओमिन्तांग दल की महासभा का पहला अधिवेशन बड़े समारोह के साथ किया गया, जिसमें सब स्थानों से प्रतिनिधि एकत्र हुए । चीन की आन्तरिक राजनीतिक अव्यवस्था के कारण १९२५ में कोई अधिवेशन होना सम्भव नहीं हुआ । दूसरा अधिवेशन १९२६ में हुआ और तीसरा १९२९ में।

कुओमिन्तांग महासभा का अध्यक्ष डा० सन यात सेन को चुना गया। यह न् व्यवस्था की गई, कि वह आजीवन दल का प्रधान बना रहे। डा० सन यात सेन ने चीन में लोन नन्त्र रिपब्लिन की स्थाएना के लिये जो असाधारण कर्तुं त्व प्रविधित किया था और नुओगिन्तांग दल में उसकी जो विधिष्ट स्थिति थी, उसे दृष्टिमें रखकर यह व्यवस्था की गई, कि दल को महाराभा में स्वीकृत किसी भी प्रस्ताव को बीटो करने का उसे अधिकार हो और केन्द्रीय कार्यकारिणी संमिति के सदस्यों की जियक्ति उसकी सहमति द्वारा ही की जाय।

कुओ सिन्तांग दल के सिद्धान्त-१९२४ में जब कुओ मिन्तांग दल की पहली महा-सभा हुई, तो उसमें दल के सिद्धान्तों व आदशों को स्वीकृत किया गया। इसका आधार डा० सन यात सेन के विचार थे, जिन्हें उसने समय समय पर अपने व्याख्यानों व पुस्तिकाओं में प्रतिपादित किया था। कुओ मिन्तांग दल के सिद्धान्तों को इस प्रकार संक्षेप में लिखा जा सकता है—

- (१) राष्ट्रीयता इस दल का प्रथम व मुख्य सिद्धान्त था।, डा॰ सन यात सेन का यह विश्वास था, कि जब तक चीन के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का भलीभांति विकास नहीं होगा, तब तक न तो देश के शासन को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा और न ही चीन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा। वह बहुधा कहा करता था, कि चीनी जनता की दशा रेत के एक ऐसे ढेर के समान है, जिसके प्रत्येक कण एक दूसरे से पूरी तरह मिलते हैं, पर उन्हें एक दूसरे से मिलाकर एक शक्ति वना देने के लिये सीमेन्ट का अभाव है। सांस्कृतिक दिष्ट से चीन में एकता ुहै, इसका यह परिणाम अवस्य हुआ है, कि चीन के विविध निवासी रेत के कर्णों के समान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं । पर राष्ट्रीयता ही एक ऐसा तत्त्व है, जो सीमेन्ट के समान उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ कर एक जबर्दस्त ताकत बना सकती है। डा॰ सन यात सेन यह भी अनुभव करता था, कि चीन में राष्ट्रीयता की विकसित करने के लिये यह बहुत आवश्यक है, कि उनमें विदेशी राज्यों के प्रभुत्त्व के विरुद्ध भावना को उत्पन्न किया जाय । डा॰ सन यात सेन विदेशी राज्यों का विरोधी नहीं था, पर वह विदेशी साम्राज्यवाद की सहन करने के लिये तैयार नहीं था। वह कहा करता था, कि विदेशी राज्य चीन की ऐसी स्थिति में लाते जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी दशा औपनिवेशिक राज्यों से भी हीन होती जाती है। पर चीन को विदेशी साम्राज्यवाद का शिकार बनने से तभी बनाया जा सकता है, जब कि चीन के लोग अपने देश के प्रति प्रेम करने लगें, अपने कुल व गांव के प्रति जो भिनत की भावना उनके हृदयों में विद्यमान है, वह चीनी राष्ट्र के प्रति हो जाय। निःसन्देह चीन में पांच विभिन्न प्रकार के कींगों का निवास है, पर यदि चीनी राष्ट्र में इन पांची जातियों की एक सदश स्थान प्राप्त हो, तो चीन के सब निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना की विकसित कर सकना जरा भी कठिन नहीं है।
- (२) लोकतन्त्र शासन कुओमिन्तांग दल का दूसरा सिद्धान्त था। मञ्चू शासन का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना करने में डा॰ सन यात सेन का विशेष

कर्त त्व था । पर वह यह भलीभांति अनुभव करता था, कि चीन की विशेष परि-स्थितियोंको दिष्ट में रखते हुएयह आवश्यक है, कि चीनकी सरकारबहुत मजबूत हो । जनता का उस पर नियन्त्रण अवश्य हो, पर सरकार के पास इतनी शक्ति होनी चाहिये, कि वह देश में शान्ति और व्यवस्था को भलीभांति कायम रख सके। इस लिये डा० सन यात सेन का यह विचार था, कि पूर्ण लोकतन्त्र शासन की स्थापना होने से पूर्व चीन को तीन दशाओं में से गुजरना होगा । सबसे पहले केन्द्रीय चीनी सरकार की सैन्य शक्ति को इतना प्रवल बनाना होगा, कि वह विविध प्रान्तीय सिपह-मालारों के साथ लोहा लेकर उन्हें अपना वशवर्ती बना सके । सैन्य शक्ति के प्रयोग द्वारा जब चीन एक केन्द्रीय सरकार के अधिपत्य में आ जायगा, तो धीरे धीरे जनता को लोकतन्त्र ग्रासन की शिक्षा देनी होगी। केन्द्रीय सरकार में लोकतन्त्र संस्थाओं की स्थापना से पूर्व प्रान्तों व जिलों में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना होगा । प्रान्तीय सिपहसालारों की सत्ता का अन्त हो कर जो जो प्रदेश केन्द्रीय सरकार की अधीनता में आते जावेंगे, उनमें लोकतन्त्र जासन का प्रारम्भ किया जायगा और इस शासन में कुओमिन्तांग दल की प्रधानता रहेगी। यही दल चीन में इतना सृब्यवस्थित और संगठित था, कि देश के शासन को संभाल सकता था। जबग्रान्तों में लोकतन्त्र शासन भलीभांति विकसित हो जायगा, तब बेन्द्रीय सरकार को भी लोकतन्त्र सिद्धान्तों के अनुसार संगठित कर सकना सम्भव होगा।

(३) जनता की आर्थिक उन्नति कुओमिन्तांग दल का तीसरा सिद्धान्त था। बीन की बहुसंख्यक जनता वेहातों में निवास करती थी और खेती द्वारा अपना निर्वाह करती थी। अतः डा० सन यात सेन का यह विचार था, कि कालं मार्क्स के समाजवादी सिद्धान्त चीन के लिये विशेष हितकर नहीं हो सकते। समाजवादी कान्ति के लिये यह आवश्यक है, कि व्यावसायिक उन्नति भलीभांति हो चृकी हो और देश में पूंजीपतियों और मजदूरों की दो श्रेणियों का स्पष्टतया विकास हो गया हो। यह दशा अभी चीन में नहीं आई थी, अतः डा० सन यात सेन का यह विचार था, कि कुओमिन्तांग दल को देहातों की किसान जनता की आर्थिक उन्नति पर विशेष घ्यान देना चाहिये, और इसीसे चीन की आर्थिक समस्या को हल किया जा सकता है। डा० सन यात सेन कम्युनिस्ट नहीं था, यद्यपि उसने अपने दल का संगठन करते हुए रूस के कम्युनिस्ट नेताओंका सहयोग प्राप्त किया था। शुरू में इस दल में चीनी कम्युनिस्ट भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। पर शीघ्र ही ऐसी स्थित उत्पन्न हो गई, कि कम्युनिस्ट लोगों के लिये कुओमिन्तांग दल में रह सकना सम्भव नहीं रहा।

डा ० सन यात सेन और कुओमिन्तांग दल-१९२० में कुओमिन्तांग दल ने

कैन्टन में अपनी सरकार को सुदृढ रूप से स्थापित कर लिया था। १९२३ नव माइ-केल बोरोडिन के सहयोग से इस दल का मंगठन भी बहुत दृढ़ हो गया था। रूस और चीन के कम्युनिस्ट लोगों का सहयोग कुओमिन्ताग दल को प्राप्त था। इसके कारण कुओमिन्तांग दल में दो प्रकार की प्रवृत्तियां विद्यमान थीं। कुछ लोग कि-सानों और मजदूरों को संगठित करने के लिये प्रयत्नशील थे। डा० सन यात सेन की इनके साथ सहानुभूति थी। पर कैन्टन के धनिक व्यापारी कुओमिन्तांग में सम्मिलित होते हुए भी किसानों और मजदूरों की शक्ति को चिन्ता की दृष्टि से देखते थे। परिणाम यह हुआ, कि उन्हों ने अपनी पृथक स्वयंसेवक सेना का संगठन किया और इस सेना को सुसज्जित करने के लिये विदेशी राज्यों से अस्य शस्त्र मंगाये। पर डा० सन यात सेन का मुकावला करने में ये धनिक व्यापारी लोग सफल नहीं हो सके। इनके अस्य शस्त्रों को जव्त कर लिया गया और डा॰ सन यात सेन कैन्टन सरकार में अपने प्रभुत्त्वं को स्थापित रखने में समर्थ हुआ।

अब डा॰ सन यात सेन नेयह प्रयत्न िक्या, िकपेकिंग सरकार से समझौता करं चीन में राष्ट्रीय एकता को स्थापित िकया जाय। उसका विचार था, िक वू पेई फू के खिलाफ तुआन ची जुई, चांग त्सो िलन और फेंग य हि सआंग के साथ समझौता करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जा सकती है, जिससे पेकिंग और कैन्टन की सरकार संयुक्त हो जावें। इसी उद्देश्य से उसने कैन्टन से उत्तर की ओर प्रस्थान किया। १९२५ के शुरू में वह पेकिंग पहुंच गया, पर वहां जाकर उसे घोर निरा-जा का सामना करना पड़ा। उत्तरी चीन के महत्त्वाकांकी व प्रवल सिपहसा-लारों के साथ उसका समझौता नहीं हो सका। १२ मार्च १९२५ को पेकिंग में ही उसकी मृत्यु हो गई।

डा० सन यात सेन की मृत्यु के कारण कुओमिन्तांग दल की शक्ति घटी नहीं, उसमें और भी अधिक वृद्धि हुई। लोगों ने समझा, डा० सन यात सेन एक महा- पुरुष था, जिसने अपना सारा जीवन ही देशकी उन्नति में स्वाहा कर दिया था। देश का कल्याण इसी में हैं, कि उसके दरसाये हुए मार्ग का अनुसरण करे। उसके जीवन काल में अनेक लोग कुओमिन्तांग दल में ऐसे भी थे, जो उसके विरोधी थे। परअव लोगों ने उसके सिद्धान्तों को आदर्श रूप से स्वीकार किया। जिस प्रकार भारत में महात्मा गांधी को और रूस में लेनिन को अत्यधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, वैसे ही चीन की जनता ने सन यात सेन के प्रति सम्मान और श्रद्धा के भाव प्र- दिश्वों की नशापना की गई और अनेक श्रद्धालू लोग गुण आदि की मेंट द्वारा इन कियों की नशापना की गई और अनेक श्रद्धालू लोग गुण आदि की मेंट द्वारा इन कियों की गुण करने में भी करार हुए। अन यात सेन की पुस्तकों का छोग

धर्मप्रन्थों के समान आदर करने लगे और उसके नाम व आदशी के कारण कुओ-मिन्तांग दल में नई स्फूर्ति और नवजीवन का संचार हुआ।

(२) राष्ट्रीय एकता की स्थापना

कैन्टन में अपनी सरकार की सृव्यवस्थित रूप से स्थापित करने के बाद कुओ-मिन्तांग दल के सम्मुख मुख्य कार्य यह था, कि सम्पूर्ण चीन को एक शासन की अधीनता में लाने का प्रयत्न किया जाय। समझौते द्वारा यह बात सम्भय नहीं ! थी। इसके लिये डा॰ सन यात सेन ने जो प्रयत्न किया था, वह असफल हो चुका था। अव कुओमिन्तांग सरकार के सम्मुख केवल यही मार्ग शेष था, कि वह धैन्यशक्ति का प्रयोग कर चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना का उद्योग करे। १९२६ में कैन्टन सरकार की सेनाओं ने उत्तर की ओर अपनी विजय यात्रा प्रारम्भ की। इन सेनाओं का प्रधान सेनापति चियांग काई शेक था। उसका जन्म १८८७ में चेकिआंग प्रान्त में हुआ था। वचपन में ही वह क्रान्तिकारी विचारों के सम्पर्क में आ गया था। उसकी शिक्षा सैनिक ढंग पर हुई थी। चीन में सैनिक र शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर वह उच्च सैनिक शिक्षा के लिये जापान गया था। डा० सन यात सेन के सम्पर्क में आकर वह उसका कट्टर अनुयायी बन गया था 🔄 १९१७ की बोल्शेविक कान्ति के बाद उसने रूस की भी यात्रा की थी और वहां रहकर उसने समाजवादी व्यवस्था का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया था। समाजवाद के प्रति उसके हृदय में आदर का भाव था, पर वह स्वयं कम्युनिस्ट रहीं बना था। डा० सन यान सेन की प्रेरणा से उसने व्हाम्पोआ नामक स्थान पर एक मिलिटरी एकेडमी की स्थापना की थी। इस एकेडमी में क्रओमिन्तांग दल के नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उन्हें सैनिक अफसर का पद ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता था। चियांग काई रोक केवल सैनिक द्ष्टि से ही सुशिक्षित नहीं था, साथ ही वह आधुनिक युग की प्रवत्तियों से भी भलीभांति परिचित था। चीन के प्राचीन ग्रन्थों के साथ साथ उसने कानून और आधनिक प्रन्थों का भी भलीभांति अन्शीलन किया था।

उत्तरी चीन पर कैन्टन सरकार की सेनाओं के आक्रमण की योजना रूसी सैनिक सलाहकार जनरल ब्लूचर द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना के अनुसार पहले हैं को पर आक्रमण किया गया। है को पर कब्जा करने में चिआंग काई शेक की सेन्ह्रें ओं को कोई कठिनाई नहीं हुई। इसके बाद नानिकंग और शंघाई पर आक्रमण किया गया, और इन दोनों नगरों को भी विजय कर लिया गया। इस प्रसंग में यह बात भी घ्यान में रखनी चाहिए, कि कैन्टन सरकार की सेनाओं के अतिरिक्त कुओमिन्तांग दल के प्रचारक भी इस समय चीन में बहुत प्रयत्नशील थे। सेनाओं से आगे आगे ये प्रचारक चलते थे, और जनता को अपने दल के मन्तव्यों का भली-गांति बोध कराते जाते थे। राष्ट्रीय एकता की बात चीन की मर्वसाधारण जनता को बहुत आकर्षक प्रतीत होती थी और वह कैन्टन सरकार की सेनाओं का विरोध नहीं करना चाहती थी।

पर इसी समय कुओमिन्तांग दल के आन्तरिक विरोधों ने गम्भीर रूप धारण करना शुरू कर दिया था । कम्युनिस्ट लोग कुओंमितांग दल में सम्मिलित थे और वे इस समय सर्वसाधारण चीनी जनता में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने में तत्पर थे। बोल्शेविक कान्ति के बाद मोस्को में सन यात सेन यनिवर्सिटी के नाम से एक नई संस्था की स्थापना हुई थी, जिसमें चीनी विद्यार्थी बहुत वड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ये विद्यार्थी जब रूस से उच्च शिक्षा प्राप्त करके चीन वापस आते थे, तो स्वाभाविक रूप से कम्यनिस्ट सिद्धान्तों के प्रचार का उद्योग करते थे। हैंको की विजय के बाद वहां कूओमिन्तांग दल का जो शासन स्थापित हुआ. था, उसमें कम्युनिस्टों का वहत जोर था। कम्युनिज्म के विरोधी कुओमिन्तांग दल के सदस्य इस बात से बहत विन्तित थे। चियांग काई शेक की इन लोगों के साथ सहानुभूति थी। कम्यूनि-जम के साथ सहातुम्ति रखने वाले चीनी युवक जहां एक तरफ अपने देश में समाज-वादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, वहां साथ ही विदेशी राज्यों का प्रभत्व भी उन्हें किसी प्रकार भी सहा नहीं था। इस समय यूरोप के प्रमुख राज्य रूस की कम्युनिस्ट सरकार के प्रवल विरोधी थे। उनमें परस्पर संघर्ष भी जारी था। इस दशा में चीन के कम्युनिस्ट भी यदि पाश्चात्य देशोंके प्रति विद्वेष का भाव रखते हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था । इसीलिये जब मार्च, १९२७ में कुओमिन्तांग चल की सेनाओं ने नानिका पर कब्जा किया, तो चीनी नवयुवकों ने विदेशी लोगों पर भी आक्रमण किये। बहुत से पारचात्य लोग इस हुमले में मारे गये। यदि पाश्चात्य जहाज इस समय हस्तक्षेप न करते, तो शायद विदेशी लोगों के लिये नान-किंग से अपनी जान वचाकर निकल सकना भी कठिन हो जाता । नानिका पर कुओमिन्तांग सेनाओं का कब्जा हो जाने के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जापान बादि विदेशी राज्यों ने यह मांग की, कि जिन रोनापितयों व सैनिकों के कारण विदेशी छोगों पर हमले हुए हैं, उन्हें दण्ड दिया जाय और निदेशी राज्यों को इन हमलों से जो क्षति हुई है, उसके लिये उपयुक्त हरजाना दिया जाय । विदेशी राज्यों की इन मांगों के कारण कुओमिन्तांग सरकार को एक विकट समस्या का सामना करना पडा। चिमांग काई शेल व उसके अनुयायी स्वयं नम्युनिस्ट लोगोंसे परेशान थे। उन्होंने

इस वात का आश्वासन दिया, कि वे कम्युनिस्ट लोगों को वश में रखने के लिये सब उचित कार्यवाई करेंगे। इस समय से कम्युनिस्टो और चिआंग काई शेक के अनु-यायियों में विरोध निरन्तर बढ़ता गया। कुओिमन्तांग दल के दक्षिण और वाँमें पक्षों में इस समय जो संघर्ष शुरू हुआ, चीन के इतिहास में उसका बहुत अधिक महत्त्व है। इस संघर्ष के कारण चियांग काई शेक कम्युनिज्म का प्रवल विरोधी वन गया और इस सिद्धान्त को विनष्ट करना उसने अपना मुख्य कार्य बना लिया।

नानिकंग पर कब्जा हो जाने के बाद उसे ही कुओमिन्तांग सरकार की राजधानी बनाया गया । कम्युनिस्ट लोग हैको व उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बहुत प्रबल थे। चियांग काई शेक ने उनके खिलाफ सब्त कार्रवाई की। बहुत से कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया । इनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी। सैकड़ों कम्युनिस्ट विद्यार्थियों को प्राणदण्ड दिया गया । रूस के जो कम्युनिस्ट चीन में कार्य कर रहे थे , उन्हें अपने देश वापस लीट जाने के लिये विवश होना पड़ा। अपने विरोधियों को विनष्ट कर १९२८ में चियांग काई शेक ने उत्तर में पैकिंग की और प्रस्थान किया। इस समय पैकिंग पर मञ्चिरिया के सिपहसालार चांगत्रो लिन का अधिपत्य था। वह चियांग काई शेंक की सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सका । जून, १९२८ में पेकिंग पर कुओमिन्तांग दल का कब्जा हो गया । चांग त्सी लिन ने अपनी सेनाओं को साथ लेकर मञ्चूरिया की तरफ प्रस्थान किया, पर अभी वह अपनी (मञ्जूरिया की) राजधानी मुकदन नहीं पहुंच पाया था, कि मार्ग में एक बॉम्ब द्वारा उसकी मृत्य हो गई। चियांग काई शेक का विचार था, कि इस समय मञ्जूरिया पर भी आक्रमण किया जाय और उसे भी जीत कर कुओमिन्तांग सरकार के शासन में ले आया जाय। पर दक्षिणी मञ्चिरिया जापान के प्रभाव में था। जापानी लोगं नहीं चाहते थे, कि चियांग काई शेक की सेनाएं इस प्रदेश पर आक्रमण करें। उनके विरोध के कारण कुओमिन्तांग सरकार की सेनाओं ने निक्चय किया, कि अभी मञ्जूरिया पर आक्रमण करने का यत्न न किया जावे । चांग त्सी लिन की मृत्यु के बाद उसका लड़का चांग हु सुएहु -लिआंग मंचुरिया का सिपह-सालार बना । वह कुओमिन्तांग सरकार के साथ समझौता करने के लियें तैयार था । परिणाम यह हुआ, कि युद्ध के बिना ही मञ्चूरिया पर कुओमिन्तांग सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया।

पेकिंग की विजय और मञ्चुरिया पर आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद ची में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई। पर यह नहीं समझना चाहिये, कि इस समय (१९२८) में सारे चीन पर एक सुव्यवस्थित सरकार का शासन कायम हो गया था। चीन के विविध प्रदेशों में अभी तक भी अनेक ऐसे सिपहसालारों की सत्ता

विद्यमान थी, जो कुओमिन्तांग सरकार की उपेक्षा कर स्वतन्त्र शासकों के समान कुषाचरण करने के लिये उद्यत रहते थे। चियांग काई शेक को अनेक बार इन सिपहमालारों के साथ भयंकर युद्ध लड़ने पड़े। इनके अतिरिक्त कम्युनिस्ट लोग भी अनेक प्रदेशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे। किआंगसी, आन्हुई और फ्किएन प्रान्तों के अनेक प्रदेशों पर १९३० में १९३३ तक कम्युनिस्ट लोगों का प्रभुत्व रहा। १९३० में कुछ समय के लिये कम्युनिस्टों ने हनान प्रान्त की राजधानी पर भी अपना कब्जा कायम कर लिया था। चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रचण्ड रूप से सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। पूर्वी चीन के धनपित लोग इस कार्य में उसकी दिल खोलकर सहायता कर रहे थे। अनेक सिपहसालारों और कम्युनिस्ट लोगों की सत्ता के कारण यह कह सकना कठिन है, कि १९२८ के बाद चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई थी। पर इसमें सन्देह नहीं कि कुओमिन्तांग दल के कर्तृत्व के कारण चीन राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो रहा था।

(३) नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकार

सरकार का संगठन—पेकिंग की विजय के बाद चीन में राष्ट्रीय एकता बहुत अंशों में स्थापित हो गई थी। डा० सन यात सेन द्वारा चीन की उन्नित के लिये जो प्रोग्राम बनाया गया था, उसका पहला भाग पूर्ण हो गया था। अब कुओमिन्तांग दल के सम्मुख अगला कार्य यह था, कि सरकार का व्यवस्थित रूप से संगठन किया खाय और लोकतन्त्र के मार्ग पर आगे बढ़ा जावे। अब चीन की राजवानी नानिकंग निश्चित की गई। कुओमिन्तांग दल का उत्तरी चीन पर अधिक प्रभाव नहीं था। पेकिंग में उन लोगों की बहुसंख्या थी, जो नई प्रवृत्तियों के विरोधी थे। इसीलिये १९११ में भी सुधारवादी व कान्तिकारी लोगों ने यह प्रयत्न किया था, कि चीन की राजधानी पेकिंग के बजाय नानिकंग को बनाया जाय। पर युआन शी काई के कारण चीनी जनता की यह इच्छा किया में परिणत नहीं हो सकी थी। अब कुओमिन्तांग दल नानिकंग को चीन की राजधानी बनाने में सफल हुआ। धीरे-धीरे विदेशी राजदूत भी पेकिंग को छोड़कर नानिकंग चले आये।

अगस्त, १९२८ में कुओमिन्तांग पार्टी की सेन्द्रल एम्जीक्यृदिव कमेदी की बैठक इस उद्देश्य से हुई फि नई चीनी सम्बागकी जागन व्यवस्था व संगठत के सम्बन्ध में निर्णय किया जाय । इस समय चीन के बाधन व्यासंगठन जिस रंग ने किया गता, उसकी मृश्य बातें निध्नार्जित थी- (१) सम्बार पर मुओमिन्तांच पार्टी का प्रभुत्व रहे। (२) सरकार पर नियन्त्रण रखने और पाज्य की नीनि का निर्णा-

रण करने के लिये एक सेन्ट्ल पोलिटिकल कौसिल का संगठन किया जाय। इस कौंसिल के सदस्य निम्न लिखित प्रकार से रहें-क. कुओमिन्तांग दल की सेन्द्रल्य एग्जीक्यूटिव कमेटी के सब सदस्य, और ख. सेन्ट्रल स्टेट कौंसिल के सब सदस्य । सेन्ट्रल स्टेट कौंसिल के सदस्यों की संख्या ३५ थी और इन्हें व कुओमिन्तांग दल की केन्द्रीय कमेटी के सदस्यों को मिलाकर राज्य की केन्द्रीय राजनीतिक सभा (सेन्ट्रल पोलिटिकल कौसिल) के निर्माण की व्यवस्था की गई थी । इस प्रकार राज्य की केन्द्रीय सभा में कुओमिन्तांग दल का स्थान बहत महत्त्वपूर्ण था। (३) राज्य की केन्द्रीय सरकार में पांच विभाग (युआन) हों, शासन युआन, व्यवस्थापक युआन, न्याय युआन, परीक्षा युआन और नियन्त्रण युआन । पाइचात्य राज्यों की सरकार में शासन, व्यवस्थापन और न्याय-ये तीन विभाग बनाये जाते हैं, पर चीन में इन तीन विभागों के अतिरिक्त परीक्षा और नियन्त्रण के दो अन्य विभाग भी कायम किये गये। ये दोनों नये विभाग चीन की प्राचीन परम्परा को दिष्ट में रखकर स्थापित किये गये थे, क्योंकि मञ्च शासन के काल में परीक्षा पद्धति और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर नियन्त्रण को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता था। केन्द्रीय सरकार के समान प्रान्तों की सरकार का भी इस समय पुनः संगठन किया गया और प्रान्तीय सरकारों के ऊपर नियन्त्रण रखने के लिये सेंट्रल पोलिटिकल कौंसिल के ढंग पर प्रान्तीय कौंसिलों की स्थापना की गई।

मई, १९३१ में चीन के लिये नया शासन विधान तैयार हुआ। १९३४ में इसको संशोधित किया गया। १९३१ और १९३४ के शासन विधानों के अनुसार चीन की राज्यशिकत सर्वसाधारण जनता में निहित थी और संविधान में जनता के जन्मसिद्ध अधिकारों का विश्रद रूप से प्रतिपादन किया गया था। "प्रत्येक मनुष्य कानून की दृष्टि में समान हैं, धर्म, नसल, लिङ्ग, जाति आदि के कारण नागरिकों की स्थिति और अधिकारों में कोई भेद नहीं किया जायगा, सब को निर्वाचन में समान रूप से वोट देने का अधिकार होगा; सम्पत्ति पर वैयक्तिक अधिकार को स्वीकृत किया जायगा, बशतें कि यह अधिकार सर्वजिक हित का विरोधी न हो," इस प्रकार के जन्मसिद्ध अधिकार संविधान द्वारा स्वीकृत किये गये। राज्य के शासन में कुओमिन्तांग दल के प्रभुत्व को स्थापित किया गया, पर्प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार भी दिया गया, कि वह इस दल का सदस्य वन सके। चीन के इस नये संविधान पर अधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालने का इस कारण विशेष लाभ नहीं हैं, वयोंकि कुओमिन्तांग सरकार को एस समय इतना अवकाश नहीं था, कि वह चीन में लोकतन्त्र शासन के विकास गर अधिक ध्यान दे थके।

उसके सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था, कि देश में अकेन्द्री भावकी प्रवृत्तियों को क्षा में लाकर किस प्रकार राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाय । नई सरकार का अधिपति चियांग काई शेक था और उसकी सब शक्ति अपने विरोधियों के साथ मंघर्ष में लगी हुई थी ।

चियांग काई शेक के विरोधी—नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकार के अधि-पति चियांग काई शेक को जिन विरोधी शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था, उन्हें निम्न लिखित विभागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) विभिन्न प्रदेशों के सिपहसालार लोग, जो अवसर पाते ही स्वतन्त्र होने के लिये उद्यत रहते थे, (२) कुओमिन्तांग दल के अन्तर्गत वाग पक्ष के लोग, और (३) कम्युनिस्ट दल। इन तीनों विरोधी तत्त्वों का संक्षेप के साथ उल्लेख करना इसयुग (१९२९—३३) के चीनी इतिहास को समझने के लिये बहुत उपयोगी है।

१९२९ में चियांग काई शेक ने उद्योग किया, कि विभिन्न सिपहसालारों से बातचीत करके एक ऐसा समझीता किया जाय, जिससे वे नानकिंग सरकार की अधीनता में रहते हुए उसके साथ सहयोग करने को उद्यत हों। पर इस प्रयत्न में ुं उसे सफलता नहीं हो सकी। उसका मुख्य प्रतिस्वर्धी फेंग यू हि ्सआंग था। इस शक्तिशाली सिपहलासार का उल्लेख इस इतिहास में कई बार पहले किया जा चुका है। चियांग काई शेक और फेंग यू हि सआंग दोनों इस बात के लिये उत्सुक थे, कि मञ्जूरिया के सिपहसालार चांग ह् सुएह लिआंग और शान्सी प्रान्त के सिपहसालार येन हुसी ज्ञान का सहयोग प्राप्त करें। फेंग यु हि संजांग अपने प्रयत्न में आशिक रूप से सफल हुआ और येन ह् सी शान का सहयोग उसे प्राप्त हो गया। पर चांग ह सुएह लिआंग इस संघर्ष में उदासीन रहा। चियांग काई शेक इन दो शक्तिशाली सिपहसालारों को तभी परास्त कर सकता था, जब कि चांग हु सू-एह लिआंग जैसे किसी प्रबल सिपहसालार की सहायता उसे प्राप्त हो। अन्त में उसने मंचूरिया के सिपहसालार को यह आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया, कि फैंग यु हि सआंग और येन हुशी शान की परास्त कर उनके प्रदेशों पर उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया जायगा। चांग हु सुएह लिआंग की सहायता प्राप्त कर चियांग काई शेक ने अपने प्रतिद्वन्द्वी सिपहसालारों से परास्त किया। 🔫 इस पराजय के बाद मंचरिया के सिपहसालार की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। यद्यपि वह नामको नानिका सरकारको अधीनतास्वीकृतकरताया, पर कियात्मक द्षिट से वह उत्तरी चीन के विकार प्रदेश का स्वनन्त्र गासक था। चियांग काई श्रोक को इसी ढंग से अन्य भी अनेक सिमहसालारों के साथ संघर्ष करना पड़ा और इन संघर्षी को दृष्टि में रखते हुए यह स्वीकार करना पहेगा, कि वस्तुत: नानिका

सरकार की शक्ति सम्पूर्ण चीन में स्थापित नहीं थी । पेकिंग सरकार की पृथक् सत्ता का अन्त हो जाने के बाद भी अभी चीन एक नहीं हुआ था । उसमें पहले के , समान ही आन्तरिक युद्ध जारी थे ।

केवल उत्तरी चीन में ही नहीं, अपितु दक्षिणी चीन में भी चियांग काई शेक के विरोधी विद्यमान थे। कुओमिन्तांग दल में जो वामपक्षी लोग थे, उनके प्रधान नेता बाग चिंग वेई और चेन कूंग-पो थे । इन्होंने यतन किया, कि चियांग काई शेक के विलाफ फेंग यू हि संआंग और येन हुसी जान की महायता करें। जब ये दोनों सिपहसालार परास्त हो गये, तो वामपक्षी नेताओं ने कैन्टन को राजधानी बनाकर अपनी पृथक सरकार का संगठन कर लिया । क्वांगमी प्रान्त की सेनाएं इस प्रयत्न में उनकी पीठ पर थीं । कैन्टन में एक नई सरकार का संगठन हो जाने के कारण चियांग काई शेक की स्थिति वहत जटिल हो गई। यह सरकार भी अपने को कुओमिन्तांग दल का कहती थी और यह दावा करती थी, कि डा० सन यात सेन ने चीन में जिम क्रान्ति का प्रारम्भ किया था, उसे यही सरकार पूरा कर सकती है। १९३१ के प्रारम्भ में कैन्टन सरकार की सेनाओं ने नानकिंग पर आक्रमण किया। इस समय जापान चीन में अपने प्रभ्त्व के विस्तार में विशेष रूप से तत्पर था । विदेशी शत्र का मुकाबला करने के लिये कुओमिन्तांग दल के लिये वाम और दंक्षिण पक्षी नेताओं ने यह उचित समझा, कि वे परस्पर मिलकर समझौता कर लें । इस लिये नानकिंग सरकार का पून: संगठन किया गया और शासन शक्ति का प्रयोग तीन व्यक्तियों के मुपूर्व कर दिया गया। तीन व्यक्तियों की इस कमेटी के सदस्य चियांग काई शेक, वांग चिंग वेई और हू हान मिन थे। इस कमेटी में चियांग काई शेक की शक्ति वहुत कम थी। पर वाम और दक्षिण पक्षों का यह सहयोग देर तक कायम नहीं रह सका । शीघ्र ही उनमें फुट पड़ गई और कुओमिन्तांग दल के वामपक्षी लोगों ने कैन्टन में अपनी पथक सरकार का फिर से संगठन कर लिया ।

चियांग काई रोक के विरोधियों में सबसे महत्त्वपूर्ण कम्युनिस्ट लोग थे। १९२७ में इन्हें नष्ट करने के लिये जो प्रयत्न किये गये थे, वे सामियक रूप से अवश्य संफल हो गये थे, पर उनके कारण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अन्त नहीं हो गया था। जिस समय कुओमिन्तांग दल की सेनाएं पेकिंग पर अपना आधिपत्य स्थाणित करने के लिये प्रयत्नशील थीं, कम्युनिस्टों को अपने उत्कर्ष का अवसर हाथ लग गया और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित कर लिया। कियांगसी प्रान्त के पर्वतों में आश्रय लेकर कम्युनिस्ट लोग उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। १९३३ के प्रारम्भ तक कम्युनिस्ट दल ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया

था और कियांगसी, आन्हर्द और फूकिएन प्रान्तों के अनेक प्रदेशों पर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था । इन प्रदेशों में कम्युनिस्ट आदर्शों के अनुसार गई श्रीमाजिक व्यवस्था भी कायम कर ली गई थी। बड़ी जमींदारियों का अन्त कर जमीन को किसानों में बांट दिया गया था और सहोद्योग प्रणानी के अनुसार बैकों की स्थापना कर ली गई थी, ताकि कृषकों और व्यावसायिक उत्पादकों को अपने कार्यों के लिये रुपये की प्राप्ति सुगम हो जाय। अफीम की खंती के लिये जो भूमि पहले प्रयोग में लाई जाती थी, वहां अब अनाज की खेती श्रूक कर दी गई थी और अफीम की खेती को गैरकानुनी घोषित कर दिया गया था। कम्यनिस्ट लोगों ने देश की आर्थिक उन्नति पर भी बहुत ध्यान दिया । सिचाई के लिये अनेक योजनाओं को किया में परिणत किया गया और नदियों की बाढ़ों से खेतों की रक्षा करने के लिये अनेक व्यवस्थाएं की गईं। दैवस की वसूली का ऐसा ढंग जारी किया गया, जिससे अमीरों पर टैक्स का बोझ अधिक हो और गरीवों को कम टैक्स देना पड़े। शहरों में व्यावसायिक उन्नति पर भी कम्युनिस्ट लोगों ने विशेष ध्यान दिया। इन सब वातों का प्रिणाम यह हुआ, कि जनता की सहानुभृति कम्युनिस्टों के पक्ष में हो गई और इस दल की स्थिति उन प्रदेशों में बहुत अधिक सुरक्षित व सुदृढ़ हो गई, जो उसके कब्जे में थे।

कम्युनिस्टों को काबू में ला सकना चियांग काई शेक व उसकी सरकार के लिये सुगम कार्य नहीं था। यद्यपि उसकी सैन्यशक्ति कम्युनिस्ट लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक थी, पर अपने अधिकृत प्रदेशों में कम्युनिस्टों ने अपनी जड़ को इतनी वृढ़ता के साथ जमा लिया था, कि उन्हें परास्त करना बहुत कठिन था।

आग्तरिक सुधार-चियांग काई शेक का नानिका सरकार के सम्मुख प्रधान कार्य यह था, कि देश के अन्दर विद्यमान विरोधी शक्तियों को अपने वश में लाकर चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित करें। इसीलिये उसे निरन्तर युद्धों में च्याप्त रहना पड़ा। पर फिर भी उसने देश के आन्तरिक सुधारों की उपेक्षा नहीं की। विविध सिपहसालारों और कम्युनिस्टों के साथ संधर्ष करते हुए भी उसने चीन में जिन अने सुधारों का सूत्रपात किया, उनका संक्षेप के साथ उन्लेख करना आवश्यक की। ये सुधार निम्नलिखित थे-(१) श्री टी० वीं० सु ग के नेतृत्व में अर्थ विभाग के। सुचार कप से संगठन किया गया। चीन की आधिक समस्या अन्यन्त विकट थी। विदेशी कर्जों का उस पर गारी बोट था। राजकीय आमरनी के अनेक महत्त्वपूर्ण साधन विदेशी राज्यों के पास जमानत के रूप ये रने हुए थे। उन दशक में श्री तुंग ने जहां अनेक प्रकार से राजकीय आमदनी को बढ़ाने का उद्योग किया,

वहां साथ ही सरकारी खर्चों में भी बहुत कमी की । इस युग में चीन की कुओ-मिन्तांग सरकार ने यह भी प्रयत्न किया , कि आर्थिक क्षेत्र में विदेशी राज्यों का जो प्रभुत्व चीन में विद्यमान है, उसे दूर किया जाय । श्री सुंग के प्रयत्न से चीन की आधिक व्यवस्था में पर्याप्त उन्नति हुई। (२) रेलवे का प्रबन्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार के अधीन एक पृथक विभाग की स्थापना की गई। अब तक चीन की जो रेलवे लाइनें केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के अधीन थीं, उन सब का प्रवत्थ इस विभाग के सुपूर्व कर दिया गया। साथ ही इस विभाग ने यह भी प्रयत्न किया, कि नई रेलवे लाइनों का भी निर्माण किया जाय, ताकि चीन में एक व्यवस्थित जासन की स्थापना सुगम हो सके । इस विभाग की ओर से नई सडकों के निर्माण का भी उद्योग किया गया। (३) चीन की मुद्रापद्धति में मुधार के लिये एक कमीशन की नियक्ति की गई, और उसकी विदेशी विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त कराया गया। (४) चीन के लिये नये कानुनों को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिये उद्योग किया गया । फौजदारी और दीवानी के जो कानुन अब तक चीन में विद्यमान थे, वे प्रायः परम्परागत थे। पर अब यह कोशिश की गई, कि कानुन के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति पाश्चात्य देशों में हुई है, उसका उनयोग कर चीन के सब कानूनों का नये सिरे से निर्माण किया जाय, (५) न्या यालयों का भी नये ढंग से पून: संगठन किया गया। (६) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति, अफीम के सेवन का निर्पेष, कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों के हित व कल्याण की व्यवस्था और शिक्षा प्रसार आदि के लिये भी नई व्यवस्थाएं की गई। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद जिस राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, चीन भी उसका सदस्य था। राष्ट्रसंघ के सहयोग को प्राप्त कर नानकिंग की कुओमिन्तांग सरकार ने इस बात का उद्योग किया, कि चीन आन्तरिक सुधारों के क्षेत्र में उन्नति करे।

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि चीन की बहुसंख्यक जनता चियांग काई शेक और उसकी सरकार के सुधार सम्बन्धी कार्यों से सन्तोष अनुभव नहीं करती थी। इसका प्रधान कारण यह था, कि सर्वसाधारण जनता की आधिक समस्या अभी हल नहीं हुई थी। बहुसंख्यक चीनी लोग अत्यधिक गरीब थे, उनके लिये अपना पेट भर सकना भी कठिन था। इसी का यह परिणाम था कि जहां कम्युनिस्ट लोग निरन्तर शक्तिशाली होते जाते थे, वहां साथ ही कुओमि नतांग दल का नामपक्षी भाग चियांगकाई शेक के शासन से अत्यन्त असंतुष्ट था। इसी कारण वामपक्ष के लोगों ने कैन्टन में अपनी पृथक सरकार की स्थापना कर ली थी। चीनी लोग समझते थे, कि चियांग काई शेक की सरकार पूंजीपति

लोगों के हाथों में कठपुतली मात्र है, और उसे सर्वसाधारण जनता के हित का कोई भ्रीकृष्यान नहीं है ।

(४) विदेशी प्रभुत्व के अन्त का प्रयत्न

नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकार के सम्मुख एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य यह था, कि चीन में विदेशी राज्यों के जो अनेक प्रकार के प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित है, उन्हें नष्ट किया जाय। इसके लिये उद्योग कुओमिन्तांग दल के उत्कर्ष से पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। १९१४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति पर जर्मनी के विशेषाधिकारों का चीन से अन्त हो गया था। चीन ने जर्मनी के साथ पथक रूप से जो सन्धि की थी, उसमें जर्मन सरकार ने अपने सब विशेपाधिकारों को छोड़ देने की बात को स्वीकृत कर लिया था। १९१७ में रूस में बोलशेविक क्रान्ति हो गई थी। इस क्रान्ति के कारण रूस के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह सञ्चरिया और मंगोलिया में अपने विशेषाधिकारों व आधिपत्य को कायम रख सके। बोल्शेविक कान्ति के कारण १९१९-२१ के सालों में रूस में जो शुन्यवस्था फैल गई थी, उसका लाभ उठाकर चीन ने वाह्य मंगोलिया के प्रदेश पर . जो पहले रूस के आधिपत्य में था, अपना कव्जा कर लिया । चीनी सरकार बोक्सर युद्ध के परिणाम स्वरूप हरजाने की रकम का जो भाग रूस को देती थी, उसकी किस्त का देना १९२० में बन्द कर दिया गया था। इस दशा में रूस की कम्युनिस्ट सरकार ने यह उचित समझा, कि चीन के साथ एक नई सन्धि कर ली जाय । इस सन्धि के लिये ये शर्त तय हुई-(१) रूस के नागरिकों को एक्स्ट्रा-टैरिटोरियेलिटी की पद्धति द्वारा जो विशेषाधिकार चीन में प्राप्त हैं, उनका अन्त कर दिया जाय । चीन में निवास करनेवाले रूसी लोग चीनी कानन और चीनी अदालतों की अधीनता में आ जावें। (२) बोक्सर युद्ध के कारण जो हरजाना चीन ने रूस को देना था, उसका अन्त कर दिया जाय। (३) चाईनीज ईस्टर्न-रेलवे, जिस पर पहले रूस का अधिकार था, अब चीन के सुपूर्व कर दी जाय। चीन के लिये ये शर्ते बहुत अच्छी थीं। जिस प्रकार जर्मनी के विशेपाधिकारों का महायद्ध के कारण अन्त हो गया था, वैसे ही अब रूसी विशेषाधिकारों के का भी समय उपस्थित हो गया था। रूस की कम्युनिस्ट सरकार साम्राज्यबाद के विरुद्ध थी। वह यह तो चाहती थी, कि संसार में सर्वत्र समाज-वादी व्यवस्था की स्थापना हो. पर प्ंजीवादी देशों के समान वह अन्य देशों पर अपना अधिपत्य स्थापित करने की नीति को नहीं अपनाना चाहती थी। इसके साथ ही दूरा समय रूस की कम्य्निस्ट सरकार इस स्थिति में नहीं थी, कि अन्य

देशों पर अपने प्रभुत्व को कायम रख मके। उसके लिये रूस के विस्तृत प्रदे-शों में भी व्यवस्था को स्थापित कर सकता कठिन हो रहा था। चीन को क्रूड़ की इस दशा में बहुत लाभ हुआ और वह रूसी आधिपत्य से बहुत कुछ छुटकारो प्राप्त करने में समर्थ हुआ।

बाजिंगटन कान्फरेन्स-अब चीन के सम्मुख प्रधान समस्या यह थी, कि ब्रिटेन, फांस, जापान, इटली, आदि अन्य विदेशी राज्यों ने जो विशेपाधिकार वहां स्थापित किये हए हैं, उनसे किस प्रकार छटकारा पाया जाय । पेरिस-सिन्य परिषद में चीन के प्रतिनिधि ने इस सम्बन्ध में जो यत्न किया था, वह सफल नहीं हो सका था। अब इसके लिये अगला अवसर वाशिंगटन कान्फ्रेन्स द्वारा उपस्थित हुआ । इस कान्फ्रेन्स का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था और इसका प्रधान प्रयोजन पूर्वी एशिया के साथ सम्बन्ध रखने वाली विविध समन्याओं पर विचार करना था। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद जापान पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील था और इसके कारण अमेरिका के साथ उसका विरोध निरन्तर वढ़ता जाता था। वाशिंगटन कान्फ्रेन्स का उद^{्रा}र यही था, कि पूर्वी एशिया के साथ सम्बन्ध रखनेवाली विविध समस्याओं पैरें विचार कर शान्ति पूर्वक उनका समाधान किया जाय । ११ नवस्वर, १९२१ को इस कान्फ्रेन्स का अधिवेशन वाशिंगटन में शुरू हुआ। इसमें मुख्यतया ब्रिटेन, अमेरिका, फांस, इटली और जापान के प्रतिनिधि एकत्र हुए। इस पांच प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त चीन, बेल्जियम, हालैण्ड और पोर्तुगाल के प्रति-निधियों को भी पूर्वी एशिया के विषय में विचार करने के लिये निमन्त्रित किया गया। वाशिगटन कान्फरेन्स के सम्बन्ध में हम अगले एक अध्याय में विगद रूप से प्रकाश डालेंगे। यहां केवल उन निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा, जिसका सम्बन्ध चीन के साथ था । चीन के सम्बन्ध में जो निर्णय इस कान्फ रेन्स में हुए, वे 'नौ राज्यों की सन्धि' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये निर्णय निम्न लिखित थे-(१) सब राज्य इस बात को स्वीकार करते हैं, कि चीन एक सर्वप्रभृत्वसम्पन्न और स्वतन्त्र राज्य है, और उसे अवने सम्पूर्ण प्रदेशों पर शासन करने का अधिकार है। (२) सब राज्यों को चीन में व्यापार कर सकने का 🕬 समान अवसर होना चाहिये। (३) कोई राज्य चीन के किसी विशिष्ट प्रदेश भी अपने प्रभावक्षेत्र कायम करने का प्रयत्न न करे। (४) पूर्वी एशिया व प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में यदि भविष्य में कोई युद्ध हो और चीन उसमें उदासीन रहना चाहे, तो उसकी उदासीन सत्ता को सब राज्य स्वीकार करें। नौ राज्यों

की सन्धि में चीन के सम्बन्ध में इन चार सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया था और इनके कारण चीन को इस बात का भरोसा हो गया था, कि भविष्य में अवित-कैली राज्य उसके प्रदेशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करेंगे।

पर चीनी सरकार के सम्मुख अधिक गम्भीर समस्या उन विशेषाधिकारों की थी, जो अब तक वहां विदेशी राज्यों द्वारा स्थापित किये जा चुके थे। इन समस्याओं के सम्बन्ध में जो निर्णय वाजिंगटन कान्फरेन्स में किये गये, वे निम्निलिन थे—

(१) चीन के प्रतिनिधि चाहते थे, कि शांत्ंग प्रान्त में जापान के विशेषा-धिकारों पर वाशिगटन कान्फरेन्स में विचार किया जाय। महायद्ध के समय में जापान ने इस प्रान्त में किस प्रकार अपने प्रभाव व प्रभत्व की स्थापना कर ली थी. इस पर हम पहले प्रकाश डाल चके हैं। इसी समस्या का सन्तोषजनक रूप से समाधान न हो सकने के कारण चीन ने वसीय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। जापान के प्रतिनिधियों ने वाशिगटन कान्फरेन्स में भी घातुंग के प्रश्न पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस पर अमेरिका ने 🅍 जीन और जापान दोनों के प्रतिनिधियों को इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वे पुथक रूप मे आपस में भिलकर इस प्रश्न पर विचार करें। बहुत बहुम के बाद चीन और जापान के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह फैसला किया कि (क) जर्मनी के पास किआऊ चाऊ आदि के जो प्रदेश पट्टे पर थे, और जिन्हें अब जापान ने हस्तगत कर लिया था, वे चीन को वापस कर दिये जावें। (ख) इन प्रदेशों में जर्मन सरकार की जो सम्पत्ति थीं, वह भी चीन को प्राप्त हो जाय, पर इस सम्पत्ति में जो वृद्धि जापान ने पिछले दिनों में कर ली थी, उसके लिये जापान को मुआवजा दिया जाय। (ग) कियाऊ चाऊ प्रदेश के बंदरगाह त्सिगताओं में जापान को अपने दूतावास के लिये जो इमारतें चाहिये, उन्हें जापान अपने पास रख सके। साथ ही इस प्रदेश में स्कूल, मन्दिर आदि के लिये जो इमारतें जापान अपने पास रखना चाहें, उन्हें भी रख सकते का उसे अधिकार हो। (घ) शांतुंग में जापानकी जो भी सेनायें हैं, उन्हें छः महीने के अन्दर अन्दर वापस बुला लिया जाय और इस बीच में चीनी सरकार इस बात की समुचित व्यवस्था कर ले, कि उसकी अपनी हानायें इस प्रान्त में जापानी नागरिकों और रेलवे जादि की भलीभांनि रक्षा करने में समर्थ हो जावें। (ड.) गांतून प्रान्त में जापान की दो रेजने रिनंगताओं ने त्सिनान तक मीजूद है, वह चीन दो निल जाय, पर इसकी कीमत चीन जापान : की अदा कर दे। जब तक यह कीमत अदा ग हो जाय, तब तक इस रेलवे

का ट्रेफिक मैनेजर जापान द्वारा नियुक्त हो और इस रेलवे के हिसाब को रखने के कार्य में भी जापान सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति का हाथ रहे। इसमें संदेह नहीं, कि शांतुंग प्रान्त के सम्बन्ध में जो यह समझौता इस समय हुआ, उसके कार्रिण इस प्रान्त में चीन का प्रभुत्व पुनःस्थापित हुआ। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस समझौते को किया में परिणत करने में समय लगा, और १९२९ तक इसकी सब बातें किया में परिणत नहीं हो सकीं।

- (२) नौ राज्यकी सन्धिमें जो सिद्धान्त तय किये गये थे, उसके अनुसार अन्य प्रकारसे भी चीन में विदेशी राज्यों के अनेक विशेषाधिकारों का अन्त किया गया। बोक्सर यद्ध के बाद विविध विदेशी राज्यों की सेनायें पेकिंग में रहने लगी थीं। पेकिंग आने जानेवाले रेलमार्गों की रक्षा भी विदेशी सेनाओं द्वारा की जाती थी. ताकि वहां आने जाने में विदेशी लोगों को किसी प्रकार का भय न हो । पेकिंग के अतिरिक्त जिन अन्य नगरों व प्रदेशों में विदेशी लोग पर्याप्त संख्या में निवास करते थे. वहां भी विदेशी सेनायें स्थापित की गई थीं। बन्दरगाहों और चीनी समुद्रतट पर भी विदेशी जंगी जहाज पर्याप्त संख्या में विद्यमान थे। वाशिगटन कान्फरेन्स में एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकृत किया गया, कि इस बात का अनुसन्धान किया जाय, कि इन सेनाओं की चीन में सत्ता किस अंशा 🕵 पूरानी सन्धियों के अनुकुछ है। साथ ही जिन स्थानों पर चीनी सरकार इस बात का प्रवन्य कर सकती है, कि विदेशी लोगों की जान व माल सुरक्षित रहे, वहां से विदेशी सेनाओं को घीरे घीरे हटा लिया जाय । इस प्रस्ताव को किया में परि-णत करने में भी पर्याप्त समय लगा, पर इसमें सन्देह नहीं कि वाशिगटन कान्फ-रेन्स द्वारा विदेशी सेनाओं को चीन से हटा लेने के कार्य को शुरू करने का सूत्र-पात अवश्य हो गया।
- (३) चीन में अनेक विदेशी राज्य पोस्ट आफिसों का अपनी ओर से सञ्चा-लन कर रहे थे। पर इस समय तक चीनी सरकार ने अपनी पोस्टल सर्विस को सुव्यवस्थित रूप से संगठित कर लिया था। अतः वाशिगटन कान्फरेन्स में यह भी निश्चय किया गया, कि धीरे-धीरे विदेशी पोस्टल सर्विस को बन्द कर दिया जाय।
- (४) चीन के जो अनैक प्रदेश विदेशी राज्यों ने लम्बे समय के लिये पहरे पर प्राप्त किये हुए थे, वाशिगटन कान्फरेन्स में उन पर भी विचार किया गर्यों कियाऊ चाऊ के प्रदेश पर से जापानी पट्टे के अन्त कर देने के सम्बन्ध में समझौता हो चुका था। अब फांस ने इस वात को स्वीकार किया, कि क्वांगचाऊ की खाड़ी पर से वह अपने पट्टे के अधिकार का परित्याग कर देने को उद्यत है।

इसी प्रकार ब्रिटेन ने वेई हाई वेई पर से अपने पट्टे का अन्त कर देने के लिये इच्छा प्रकट की । पर जब इन निर्णयों को किया में परिणत करने का प्रकन उपस्थित क्रिया, तो इन देशों ने कहा कि जब तक अन्य सब राज्य भी अपने अपने पट्टों का अन्त नहीं कर देते, तब तक उनके लिये भी यह सम्भव नहीं है, कि वे अपने विशे-पाधिकारों को छोड़ सकें । इसीलिये १९३० व उसके बाद तक भी चीन के विविध प्रदेशों पर विदेशी राज्यों का प्रभुत्व कायम रहा ।

- (५) एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धित से चीनी लोगों में बहुत असन्तोष था। वाशिंगटन कान्फरेन्स में यह निर्णय हुआ, िक एक कमीचन नियत किया जाय, जो चीन में विद्यमान न्याय पद्धित का अनुशीलन करके यह वतावे, िक विदेशी राज्यों के नागरिकों को चीनी कानून व चीनी अदालतों के अधीन कर सकना किस हद तक सम्भव है। यह कमीचन १९२५ से पहले अपने कार्य को प्रारम्भ नहीं कर सका, क्यों कि इस समय आन्तरिक कलह के कारण चीन में बहुत अव्यस्था फैली हुई थी। कमीचन ने आवश्यक अनुसन्धान के बाद यह प्रस्तावित किया, िक पहले चीन में कानूनों का आधुनिक ढंग पर निर्माण किया जाना चाहिये, तभी एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धित का अन्त कर सकना सम्भव किर क्योंकि कानून और अदालतों के सम्बन्ध में चीन कुछ अंशों में उन्नित कर च्का है, अतः धीरे धीरे इस पद्धित का अन्त किया जा सकता है।
- (६) तट-करों के सम्बन्ध में चीनी सरकार की यह मांग थी, कि उनको पूर्ण रूप से चीन के अधीन कर दिया जाय और चीनी सरकार इन करों का निर्धारण करने की पूरी स्वतन्त्रता रखे। वाशिंगटन कान्फरेन्स में यह बात तो स्वीकृत नहीं की गई, पर इस सम्बन्ध में निम्निलिखित नीति का निर्धारण किया गया—क—तट कर की दर में परिवर्तन किया जाय। क—तट कर के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था की जाय, कि सब विदेशी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार हो। किसी राज्य से अधिक व किसी से कम कर न लिये जावें। ग—चीन के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में माल ले जाने पर या एक ही प्रान्त में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को माल जाने पर जो कई प्रकार के टैक्स लगते हैं (इनको लिकिन टैक्स कहते थे), उनको नष्ट कर दिया जाय और उनके स्थान पर तट कर की मात्रा में २॥ फी सदी की वृद्धि कुर दी जाय। घ—इन सब बातों के सम्बन्ध में विश्वद रूप से विचार करने के लिये एक कान्फरेन्स की बायोजना की जाय। पर अनेक नाण्य प्रयन्त करने पर भी तट कर के विषय में विदेशी राज्यों के साथ ऐसे सम्बन्ध में निन को स्वनन्थता प्राप्त हो चीन की राज्यार को सन्तोप हो। इस सम्बन्ध में नीन को स्वनन्थता प्राप्त हो जाने का परिणाम धरी हो सकता था, कि विदेशी राज्यों को मनमानी तरीके से जाने का परिणाम धरी हो सकता था, कि विदेशी राज्यों को मनमानी तरीके से

चीन में व्यापार के विकास में रुकावट पड़े। इस बात को वे किसी भी दशा में महने के लिये नैयार नहीं थे और पुरानी सन्धियों के नाम पर वे तट कर पर अपना नियन्त्रण रखने के लिये कटिवद्ध थे। इस मामले में चीनी सरकार और विदेशी राज्यों में समझौता हो सकना बहुत कठिन था।

तट बरों की दर में परिवर्तन करने के मामले में सब विदेशी राज्य परस्पर मिलकार कार्य कर रहे थे, क्योंकि इस विषय में उन सबके हित एक थे। पर अब चीन की मरकार ने विविध राज्यों में सम्मिलित रूप में वात न कर अलग अलग ममझौता करने की नीति का अनुसरण किया। १६ एप्रिल, १९२६ को चीन की ओर से बेन्जियम के राजदूत को यह नोटिस दिया गया, कि चीन और बेल्जियम की व्यापार सम्बन्धी सन्धि अंक्ट्बर में समाप्त हो जायगी और चींन इम अवधि के बाद जो नई सन्धि करेगा, उसमें उसे अधिकार होगा, कि वह सन्धि की शर्तों में परिवर्तन कर सके । बेल्जियम इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं था. कि चीन को स्वेच्छापूर्वक सन्यि की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। बेल्जियम की सरकार ने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (राष्ट्रसंघ के अधीन स्थापित किये गये पर्मनन्ट कोर्ट आफ इन्टरनेशनल जस्टिस) के सम्मान ंनिर्णय के लिये उपस्थित करना चाहा। पर चीन का कहना था, कि यह माम🐠 ऐसा नहीं है, जो अन्तरिष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख न्याय के लिये पेश किया जा संकें। चीनं और बेल्जियम की संन्यि की अवधि जब समाप्त हो जायगी, तो उस सन्धि की अवधि को बढाने न बढाने का या परिवर्तित शर्तों पर नई सन्धि करने का चीन को पूरा अधिकार है। अभी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मामलेपर विचार शरू नहीं हुआ था, नि बेल्जियम और चीन ने आपस में समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार (१) तीन्तिसन में बेल्जियम का जो अधिकृत प्रदेश था, वह चीन को वापस दे दिया गया, (२) बेल्जियम के चीन में निवास करनेवाले नाग-रिकों का न्याय चीनी अदालतों द्वारा हो, यह बात तय की गई, और (३) व्यापार के सम्बन्ध में दोनों देशों में जो मतभेद थे, उन सबका फैसला किया गया। चीन के इतिहास में यह समझौता वहंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कारण कम से कम एक विदेशी राज्य ने चीन के इस दावे की स्वीकृत किया, कि वह अंपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र व प्रभ्त्वसम्पन्न है, और उसे अपने क्षेत्र में विदेशी लोगों के साथ समान स्थिति में वरताव करने का अधिकार है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है और उसका प्रभुत्व भी ब्रिटेन, फांस व जापान के समान चीन में अधिक नहीं था। इसीलिये संबसे पूर्व चीन को उसे इस प्रकीर का समझौता करने के लिये विवश कर सकने में सफलता प्राप्त हो गई थी।

ज्यां-ज्यां अन्य विदेशी राज्यों के साथ की गई सन्धियां की अर्वाध समान्त द्वीती गई, चीनी सरकार ने इस बात के लिये जोर दिया. कि अब जो भी नई सन्धिया उसके साथ की जावें, वे इस ढंग की हों, जेसी कि दो स्वतन्त्र व समक्ष्य राज्योंके बीच में की जाती है। १९२७ में फ्रांस, जापान और स्पेन के साथ की गई पुरानी संधियों की अवधि समाप्त हुई और चीनी सरकार ने उन पर इस बात के लिये जोर दिया, कि नई सन्धियों में चीन के साथ स्वतन्त्र व समक्ष्य राज्य के सद्धा व्यवहार किया जाय। इस समय तक चीन में कुओमिन्तांग दल की शक्ति वहुत बढ़ गई थी और उग्र राष्ट्रीय विचार रचनेवाले इस दल ने नानकिंग में अपनी सरकार की स्थापना कर ली थी। इस राष्ट्रीय दल ने इन सन्धियों के सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया, उस पर विशेद हप के प्रकाश डालना आवश्यक है।

कुओिसिन्तांग सरकार का कर्तृ त्व—डा० सन यान सेन दारा चीन में जो फान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था, उसकाप्रधान उद्देश चीन की राष्ट्रीय एकता और पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इसिल्ये जब कुओिसिन्तांग दल ने नानिका में अपनी मुस्कार स्थापित की और पेकिंग को भी अपने अधीन कर लिया, तो उसने चीन को बिदेशी प्रभाव और प्रभुत्व से मुक्त करने के प्रक्रन पर विशेष व्यान दिया। चीनी जनता में ब्रिटिश लोगों के प्रति विरोध की भावना अत्यन्त उप थी, विशेषत्रया नवयुवक विद्यार्थी अपने देश में ब्रिटिन की सना व शक्ति को अन्यन्त अनुनित्त समझते थे। इसील्यि चीनी जनता की ब्रिटिश अधिकारियों के नाथ अनक बार मुठभेंड हुई। विद्यार्थियों के नेतृत्व में चीनी जनता ने ब्रिटिश माल के बहित्कार का भी प्रारम्भ किया। इस दशा में ब्रिटेन की सरकार ने यह अनुभव किया, कि चीन के सम्बन्ध में अधिक उदार नीति का अवलम्बन करना आवश्यक है। वार्शिगटन कान्फरेन्स में जो निर्णय हुए थे, न केवल उन्हें पूर्ण रूप से किया में परिणत किया जाना चाहिये, अपितु उनसे भी आगे बढ़कर चीन की जनता को संतुष्ट करना चाहिये।

१९२८ और १९२९ में ब्रिटेन, इटली आदि विविध विदेशी राज्यों ने यह स्वीकार किया, कि तट कर के सम्बन्ध में चीनी सरकार की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी। हाहिये। १९३० में जापान और हाउँण्ड ने भी इस बात को न्दीकार पर किया। फांस और स्पेन १९२७ में ही इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चहे थे। १९३० के अन्त तक यह अवस्था आ गई थी. कि चीनो सरकार को तटकर की दर को स्विच्छा- पूर्वक निश्चित कर सुकते का अदिकार पूर्ण क्य से प्राप्त ही पात था। १९२९ में ही चीन ने तट कर के सम्बन्ध में अपनी वीति का निर्धारण कर किया था और

भविष्य में आयात और निर्यात माल पर किस दर से कर लिया जायगा, इसकी घोषणा कर दी थी। जापान और हालैण्ड के विरोध के कारण ये नई दरें सुरन्त किया में प्रयुक्त नहीं हो सकी थीं। पर जब १९३० में इन देशों ने भीं तटकर के सम्बन्ध में चीन के अधिकार को स्वीकृत कर लिया, तो नई दरों के प्रयोग में लाने में कोई भी वाधा शेप नहीं रह गई। इस समयसे तटकर व व्यापारिक नीति के विषय में चीन पूर्णत्या स्वतन्त्र हो गया।

तट कर सम्बन्धी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ साथ कुओमिन्तांग सरकार इस बात के लिये भी प्रयत्नशील थी, कि एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का अन्त किया जाय । २८ दिसम्बर, १९२९ को नानिकंग सरकार ने निश्चय किया, कि विदेशी लोगों को अपने मुकदमों का अपने देश की अदालतों द्वारा फैसला कराने का जो अधिकार है, उसका अन्त कर दिया जाय । इस निर्णय की सुचना विदेशी राज्यों के राजदूतों को भेज दी गई। एक्स्टा -टैरिटोरिएलिटी के अन्त के लिये १ जनवरी, १९३० का दिन नियत किया गया । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के राजदूतों ने चीनी सरकार की सूचना का यह उत्तर दिया, कि वे सिद्धान्त रूप से एक्स्टा-टैरिरोरिएलिटी का अन्त कर देने के लिये सहमत है, पर इसके लिये अधिक समय की अपेक्षा होगी। यदि कुओमिन्तांग सरकार इस समय अपनी विरोधी शक्तियों के साथ संघर्ष में बुरी तरह से न फंसी होती, तो वह विदेशी राज्यों को अपने निर्णय को तुरन्त स्वीकार करने के लिये विवश कर सकती थी । पर १९३० का सारा साल विदेशी राजदूतों के साथ बातचीत में ही निकल गया। अन्त में उनके साथ यह समझौता हुआ, कि १ जनवरी, १९३२ से एक्स्टा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का अन्त कर दिया जायगा और इस बीच में चीन की सरकार को यह चाहिये, कि वह अपने सब कानुनों का नये हुंग से निर्माण कर ले और अपनी अदालतों का भी आधुनिक शैली पर पूनः संगठन कर ले। पर १९३१ में चीन की कुओमिन्तांग सरकार जापान के साथ संघर्ष में वरी तरह से उलझनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस समय जापान मञ्चरिया में अपने प्रभत्व को विस्तृत करने के लिये प्रयत्नशील हो गया था। इस स्थिति में १ जनवरी, १९३२ को भी एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति का अन्त नहीं किया जा सका। आगे चलकर इस पद्धति का किस प्रकार अन्त हुआ, इस पर हम, धयास्यान प्रकाश डालेंगे ।

चीन के जो प्रदेश विदेशी राज्यों को लम्बे पट्टे पर प्राप्त हुए थे, या जिन चीनी नगरों में विदेशियों के निवास के लिये पृथक क्षेत्र बने हुए थे और उन क्षेत्रों पर विदेशी राज्य अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी समझते थे, उनका अन्त कर देने

के लिये भी कुओमिन्तांग सरकार प्रयत्नशील थी । १९२९ में चिगकियांग और अमोय पर से ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र का अन्त किया गया और १९३० में वेई-ै_{हाँ}ई वेई पर चीन का प्रभुत्व फिर से स्थापित हुआ । १९३१ तक सम्पूर्ण चीन में केवल तेरह प्रदेश ऐसे रह गये थे, जो विदेशी राज्यों के प्रभूत्व व प्रभाव क्षेत्र में थे। इनमें सबसे अधिक महत्त्व का प्रदेश शंघाई का वह हिस्सा था, जिसे अन्त-राष्ट्रीय बस्ती (इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट) कहते थे। इस अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में ४०,००० के लगभग विदेशी लोग वसते थे और इसके चीनी निवासियों की संख्या दस लाख से भी ऊपर थी। इस विशाल नगर का प्रबन्ध एक म्यनिसिपल कौंसिल के हाथों में था, जिसके सदस्यों को निर्वाचित करने का अधि-कार केवल विदेशी लोगों को प्राप्त था। शंघाई चीन के समुद्र तट पर व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र था। अनः स्वाभाविक रूप से चीनी सरकार इस बात के लिये उत्सक थी, कि इस क्षेत्र को भी अपने प्रभाव व प्रभुत्व में लाया जाय। १९२८ में कुंओमिन्तांग सरकार के प्रयत्न से यह बात तय हई, कि शंघाई की म्यनिसिपल कौंसिल में ३ चीनी सदस्य भी रहें। १९३० में इन चीनी सदस्यों की संख्या ३ से ५ कर दी गई। इस समय यह भी कोशिश की गई, कि चीनी सरकार द्वारा *गजदूरों के हित के लिये जो अनेक कानून बनाये गये हैं, उन्हें शंघाई की अन्तर्राष्ट्रीय बंस्ती में भी लागु किया जाय । विदेशी लोग इसके लिये मुगमता से तैयार नहीं हए, पर उन्होंने इस सिद्धान्त को अवश्य स्वीकार कर लिया, कि सम्पूर्ण चीन में एक ही प्रकार के व्यावसायिक कानून का प्रयोग में आना उपयोगी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया, कि इस सिद्धान्त को किया में परिणत करने के लिये आंवश्यक कदम उठाने का प्रयत्न किया जाय।

इस प्रकार कुओमिन्तांग सरकार के प्रयत्न से चीन विदेशी राज्यों के प्रभाव व प्रभुत्व से छुटकारा पाने में बहुत अंश में सफल हुआ। पर अभी चीन के दुर्विनों का अन्त नहीं हुआ था। कुओमिन्तांग सरकार को चीन में जिन विरोधी शक्तियों के साथ निरन्तर संघर्ष करना पड़ रहा था, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। १९३१ में जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से मञ्चूरिया में अपनी शक्ति को बहाना गरू किया और इसी कारण चीन को उन युद्धों में क्यापृत होना पर्मा जिनके कारण चल अपनी आन्तरिक उन्नति पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। इन युद्धों का हम अगले एक अध्याय में विश्वद रूप से उल्लेख करेंगे।

ग्यारहवां अध्याय

चीन की सर्वतोमुखी उन्नति

(१) आर्थिक उन्नति

अब तक हमने चीन के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला है। विदेशी राज्यों के सम्पर्क में आने के बाद चीन की राजनीति में किस प्रकार परिवर्तन हए, मञ्च शासन का अन्त होकर किस प्रकार रिपव्लिक की स्थापना हुई, कुओ-भिन्तांग दल ने किस प्रकार चीन में राष्ट्रीय एकता और लोकतन्त्र शासन की स्थापना का उद्योग किया और किस प्रकार चीन विदेशी राज्यों के प्रभाव व प्रभत्व में मुक्त होने के मार्ग पर अग्रसर हुआ, इन बातों पर हमने पिछले अध्यायों में विचार किया है। पर इस वीच में चीन केवल राजनीतिक संघर्षे में ही व्यापन नहीं था, वह आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में सर्वतीम्खी उन्नति के लिये भी प्रयत्नशील था। चीन में यह उन्नति उतनी तेजी के साथ नहीं हुई, जितनी कि जापान में हुई थी। जापान के शासक वर्ग ने पायचात्य देशों के साथ सम्पर्क में आने ही इस बात को भलीभांति अनुभव कर लिया था, कि वह उन्नति की दौड में वहत पीछे रह गया है, और वह इन देशों का समकक्ष तभी बन सकता है, जब कि वह भी पारचात्य ज्ञान विज्ञान को अविकल रूप से अपना ले। इसी कारण वहां की सम्पूर्ण राजशक्ति अपने देश का कायाकल्प करने के लिये प्रयत्नशील हो गई थी। इसके विपरीत चीन में उन्नति की जो प्रक्रिया हुई, उसका श्रेय वहां की राजशनित को नहीं दिया जा सकता। चीन के मञ्चू शासक देश की उन्नति के प्रति उपेक्षा भाव रखते थे। वहां की सरकार में इतनी अधिक विकृति आ चुकी थी, कि वह देश की उन्नति पर ध्यान दे सकने के लिये सर्वथा असमर्थ ही गई थी। चीन ने विविध क्षेत्रों में जो उन्नति आधुनिक युग में की, उसका प्रधान श्रेय वहां की, जनता को है। जब राजसत्ता का अन्त होकर चीन में कुओमिन्तांग दल का प्रभुत्व स्थापित हो गया, तव भी उसकी शक्ति मुख्य रूप से आन्तरिक अव्यवस्था को दूर करने में ही लगी रही । पर इसमें सन्देह नहीं, कि कुओमिन्तांग सरकार ने देश की उसति पर भी पर्याप्त ध्यान दिया।

त्रिदेशी व्यापार-उनीमवीं मदी के मध्य भाग में चीन का पाठ्यात्य देशों ुके साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ था । १८४२ में चीन के पांच बन्दरसाह विदेशी व्यापार के लिये 'सोल' दिये गये थे। इसके बाद निरन्तर और और बन्दरगाह पाञ्चात्य व्यापारियों के लिये खुलने गये। इन्हें 'ट्रीटी पोर्ट' कहा जाता था. क्योंकि सन्वियों द्वारा इन बन्दरगाहों में विदेशी लोग व्यापार की विशेष सुविधाएं व अधिकार प्राप्त करने जाते थे । १९३१ तक इन ट्रीटी पोर्टी की संस्था बढते बढ़ने ६९ तक पहुँच गई थी । इनके अतिरिक्त चीन में ११ बन्दरगाह और थे, जो विदेशियों के व्यापार के लिये लुले हुए थे, यद्यपि उनमें विदेशियों को किसी सन्धि के कारण कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे। इतने अधिक बन्दरगाहों में विदेशी व्यापार की सत्ता का यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि चीन के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि होती जाय । १९०० में विदेशों से जो माल चीन में आता था, उसकी कीमत केवल २१,१०,००,०००नायल थी, १९१० में केवल १० साल बाद आयात माल की कीमत बढ़कर ४६, ३०,००,००० तायल तक पहुंच गई थी। इसी प्रकार १९०० से १९१० तक दस सालों में चीन के निर्यात ,माल का मृत्य १५,९०,००,००० से बढ़कर ३८,१०,००,०००तक पहुंच गया र्था। १९१० के बाद चीन के विदेशी व्यापार में और भी अधिक वृद्धि हुई। १९३० में चीन के आयात माल का मूल्य १,३०,९७,५५,७४२ तायल था और नियति माल का मृत्य ८९, ४८,४३,५९४ तायल था। इस प्रकार केवल तीस साल के समय में (१९०० से १९३० तक) चीन के विदेशी व्यापार में ३५० गुना की वृद्धि हुई थी।

शुरू में चीन के आयात माल में अफीम की मात्रा सबसे अधिक होती थी। १८८२ में चीन के कुल आयात माल की ३४ प्रतिशत अफीम होती थी। इसके बाद अन्य प्रकार का माल इतना अधिक चीन में विकी के लिये आने लगा था, कि अफीम उसका केवल ११ प्रतिशत (१९०२ में) रह गई थी। बाद में अफीम के आयात में और भी कभी हुई। इसका एक कारण यह था, कि चीन में भी अफीम की खेती शुरू हो गई थी। साथ ही सरकार का भी यह प्रयत्न था, कि लोग अफीम के उपयोग में कभी करें। १९०२ में चीन के कुल आयात माल का ७२ भी सदी स्ती कपड़े थे। इसके अतिरिक्त मिट्टी का तेल व घानुएं भी अच्छी वड़ी गात्रा में चीन आने लगी थीं। १९३० में सूती कपड़ों की मात्रा कुल आयात माल का ११ फी सदी के लगभग रह गई थी। उसका कारण यह था, कि चीन में भी कपड़े की मिलें खुल गई थीं और चीन विदेतों में बिन्य किस्मकी रूई को कपड़ा तैयार करने के लिये मंगने लगा था। इस गुग में चीन में व्यानमायिक उपित

इतनी तेजी के साथ हो रही थी, कि १९३० में ७,८०,००,००० तायल की मशीनरी विदेशों से चीन आई थी। इस साल में कुल आयात का ६ फी सदी के लगभग्रु मशीनरी थी। इतनी कीमन की मशीनरी का चीन में आना इस वात का स्पष्ट प्रमाण है, कि अब वहां व्यावसायिक कान्ति का सूत्रपात हो गया था। मट्टी का नेल, दियासलाई आदि भी इस समय प्रचुर परिमाण में चीन आने लगे थे। पहले चीन में रोशनी के लिये वानस्पितक तेल का प्रयोग होता था। मट्टी के नेल के कारण जहां चीन के मकानों में अधिक तेज रोशनी उपलब्ध हो गई, वहां साथ ही वानस्पितिक तेल को प्रचुर परिणाम में विदेशों में भेजा जाने लगा। १९३० तक मोटर कार, फोटोग्राफी का सामान, नये किस्म की प्रिटिंग प्रेस की मशीनें, टेलीफोन व टेलीग्राफ का सामान व इसी प्रकार की अन्य आधुनिक वस्तुएं भी विदेशों से चीन में आने लगी थीं और इनके कारण चीन के समृद्ध लोगों के रहन सहन में भारी परिवर्तन आने लग गया था।

१८८२ में चीन के नियति माल में चाय की मात्रा सबसे अधिक थी। कूल निर्यात का ४८ प्रतिशत चाय होती थी। पर १९३० में चाय का निर्यात कुल निर्यान माल का केवल ३ प्रतिशत रह गया था । इसका मुख्य कारण यह है, कि इस समय भारत और लंका में चाय बड़े परिमाण में तैयार होने लगी थी और इसकी मांग विदेशों में बहुत वढ़ गई थी। इसी प्रकार चीनी रेशम के मुकाबले में फ्रांस और इटली का रेशम विदेशी बाजारों में अधिक पसंद किया जाता था और उसके कारण चीनी रेशम के निर्यात में कमी हो गई थी। पर यदि चाय और रेशम के निर्यात में कमी हुई थी, तो सोयावीन और अन्य तिलहन के निर्यात में वृद्धि भी बहुत अधिक हुई थी। १९३० में इन पदार्थों के निर्यात की मात्रा १८,५०,००,००० तायल थी । चीन से जो माल बाहर जाता था, उसका बड़ा भाग कच्चे माल का होता था। तैयार माल में केवल रेशम, गलीचे व अन्य कला की वस्तुएं ही ऐसी थीं, जिनकी विदेशों बाजारों में मांग थी । यद्यपि व्यावसायिक कान्ति का चीन में प्रारम्भ हो गया था, पर उसके कारखानों में जो माल तैयार होता था, वह देश की अपनी आवश्यकताओं के लिये भी पर्याप्त नहीं होता था। शुरू में जब चीन का विदेशों के साथ व्यापार प्रारम्भ हुआ, तो उसका आयात माल नियति माल की अपेक्षा कम होता था। पर बीसवीं सदी में निर्यात माल की अपेक्षाः आयात माल की मात्रा व कीमत बहुत अधिक बढ़ गई थी। निर्यात की अपेक्षाँ आयात की अधिकता का यह स्वाभाविक परिणाम था, कि चीन आर्थिक दृष्टि से अधिक दुर्दशाग्रस्त होता जाता था। तट-कर को वह इस ढंग से लगा सकता था, जिससे आयात माल की मात्रा में कमी हो, पर इस विषय में उसे स्वतन्त्रता प्राप्त

नहीं थी। तट कर की दर विदेशी सिन्धयों द्वारा निश्चित की हुई थी, और इनमें ूचीनी सरकार स्वेच्छापूर्वक परिवर्तन नहीं कर सकती थी। यही कारण है, कि 'चीन के राष्ट्रवादी देशभक्त तट कर के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये इतने अधिक उत्मुक थे।

कृषि की बशा-चीन की बहसंस्थक जनता अपने निर्वाह के लिये कृषि पर आश्रित थीं। ९० फी सदी से भी अधिक चीनी लोग खेती द्वारा अपनी आर्जाविका चलाते थे। चीन की यह विशाल क्रयक जनता देहातों में निवास करती थी और आधुनिक युग की प्रवित्तयों में सर्वथा अपरिचित थी। खेती के लिये जो उनकरण मदियों से चीन में प्रयक्त होते चले आये थे, अब बीसवीं सदी में भी उन्हीं को प्रयक्त किया जाता था। पूराने ढंग के हलों को बैलों ढारा चलाया जाता था और फावड़ा, खरपी व दरांती किसान के सर्वोत्तम उपकरण थे। यह बात नहीं. कि चीनी लोगों को पारचात्य देशों के कृषि सम्बन्धी उपकरणों का कोई परिज्ञान नहीं था । पर चीन की विशेष परिस्थितियां ऐसी थीं, कि अमेरिका में प्रयक्त होनेवाले दैक्टर व विशाल हल वहां उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते थे। चीन ,में जनसंख्या बहुत अधिक थी, और खेतों के आकार बहुत छोटे छोटे थे । इसके विपरीत अमेरिका में खेती के लिये बिशाल मैदान खाली पडे थे, और इस परती पड़ी हुई जमीन को कृषि के योग्य बनाने के कार्य में ट्रैक्टर आदि का बहुत उपयोग था। अमेरिका में जनसंख्या बहुत कम थी और मीलों लम्बे खेतों में मशीनरी की सहायता के बिना खेती कर सकना असम्भव था। चीन के लोगों ने अमेरिका की कृषि सम्बन्धी मशीनरी को जो नहीं अपनाया, उसका प्रधान कारण यहां की विशेष परिस्थितियां ही थीं।

पर यह नहीं समझना चाहिये, कि आयुनिक उन्नति का चीन के किसानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। रेलवे और सड़कों के निर्माण के कारण चीन में आवागमन और यातायात के साधनों में बहुत अधिक उन्नति हो गई थी। उन्नीसवीं सदी में जब चीन में न रेलवे थी और न पक्की सड़कों, तो किसान का यह प्रयत्न होता था, कि वह अपनी आवश्यकता की सब चीजों को स्वयमेव उत्पन्न कर ले। वह जहां अपने खेत में अनाज पैदा करता था, वहां साथ ही कपास भी खोता था, ताकि अपनी आवश्यकता का कपड़ा गांव के जुलाहे द्वारा तैयार करा सके। पर अब रेलवे जाति की उन्नति के कारण चीन के जिलान के लिये यह सम्भव हो गया था, कि वह केवल उप चीज को पैदा कर, जिलके लिये उत्तवी जमीन सनसे अधिक उपयुक्त है, और अपनी पैदावार के कुछ जंश की वाजार में पंच कर उन चीजों को खरीब ले, जी उनके अपने सेतो में उत्तव नहीं होती। इसी का यह उन चीजों को खरीब ले, जी उनके अपने सेतो में उत्तव नहीं होती। इसी का यह

पिन्गाम हुआ, कि चीन के विभिन्न प्रदेशों में कपाम, चावल, चायआदि की पैदाबार विदाय कप से प्रारम्भ हुई। जो प्रदेश जिम फसल के लिये अधिक उपयुक्त था वहां उसी की खेती की जाने लगी। मच्िया में सोयाबीन, चिहली और कियांगं सूने कथान और युनान में चावल की पैदाबार पर विशेष घ्यान दिया गया। चीन में कगाम उननी अधिक मात्रा में पैदा होने लगी, कि उमें विदेशों में भी भेजा जाने लगा। मरकार ने इस बान पर भी घ्यान दिया, कि किसान लोग अपने खेतों में अच्छी खादों का प्रयोग करें और उत्कृष्ट किस्म के बीज को बोवें। विदेशों वाजारों में चीन की चाय के मुकावले में भारत और लंका की चाय को अधिक पमन्द किया जाता था, अतः चीन की सरकार ने अपने यहां चाय की किस्म में उन्नति पर विशेष घ्यान दिया। इसी प्रकार रेशम के की हों की नसल में तरक्की की गई और कपास के चढ़िया बीज अमेरिका से मंगाकर उन्हें बुआने का प्रवस्थ किया गया। चीन में कृषि की शिक्षा के लिये अनेक स्कृत और कालिज भो स्थापित किये गये। खेती की उन्नति पर सरकार का इतना अधिक ध्यान था, कि १९२३ में ४,००,००,००० तायल की खाद विदेशों से चीन में मंगायी गई थी।

चीन की सरकार खंती की उन्नति पर ध्यान अवश्य दे रही थी, पर इससे कृष्यी जनता की दशा में वहुत अधिक सुधार नहीं हो पाया था। यह ठीक है, कि अब चीन का किसान अने एसी वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने लग गया था, जिनका वह पहले नाम भी नहीं जानता था। अब वह मिल के बने कपड़े खरीदने लगा था, तमाख़ का सेवन करता था और मट्टी के तेल की लालटेन से अपनी झोंपड़ी को प्रकाशित करता था। पर इन नवीनताओं के होते हुए भी चीन या किसान बहुत गरीब था। जमीदार के लगान और महाजन के कर्जे से यह इतना अधिक दबा हुआ था, कि अपने परिवार के योग्य भोजन प्राप्त कर सकना भी उनके लिये कठिन था। यही कारण है, कि चीन में कम्यनिज्य का प्रचार बहुत स्ममता के साथ हो सका।

व्यावसायिक उन्नति—उन्नीमवीं सदी तक चीन में व्यवसायों की उन्नति बहुत कम हुई थी । कारीगर लोग अपने घर पर वैठकर काम करते थे और पुराने ढंग के मोटे नहें औजारों से आधिक उत्पत्ति किया करते थे। पर चीसवीं सदी में चीन में व्यावसायिक कान्ति के चिह्न प्रकटहोने लगगये थे। विदेशी राज्यों के सम्पर्क में आने के कारण चीनी लोगों ने भी यह अनुभव करना शुरू कर दिया था, कि पारचात्य संसार के वैज्ञानिक आविष्कारों को अपनाये विना उनके देश की उन्नति सम्भव नहीं है। रेलवे और सड़कों के निर्माण के कारण चीनी लोगों को आधिनक

युग की अवित्तियों से परिचित होने का सुवर्णीय अवसर मिला था । इसका परिणाम खहुहुआ, कि अनेक भनी व सम्पन्न चीनी नागरिक कल कारवानों की स्थापना के लिये प्रवृत हुए । चीन में ऐसे धनिक लोगों की कभी नहीं थी, जो अकेले या परम्पर मिलकर इतनी पूंजी जुटा सकें. जिसमें नये हंग के कारवानों की स्थापना मम्भव हो । कतिपय मुशिक्षित लोगों ने जायन्ट स्टाक कम्पनियों के संगठन पर भी ध्यान दिया। शुरू में इन्हें विशेष सफलता नहीं हुई, क्योंकि सर्वसाधारण लोगों को इस पर विश्वास नहीं था । मध्य श्रेणी के लोग अपने रुपये को अपरिचित कम्पनियों में लगाने के लिये उत्साह अनुभव नहीं करते थे। पर वैकों के विकास के कारण लोगों में अपने रुपये की बैंकों व कम्पनियों द्वारा रोजगार में लगाने की प्रवित्त बढने लगी और इससे बड़े वह कारखानों का विकास सम्भव हुआ। महा-जनी का कारोवार चीन में पहले भी विद्यमान था। पर वीसवीं सदी में वहां नये हंग के भी अनेक बैकों की स्थापना हुई । जनता द्वारा स्थापित किये गये वैकों के साथ साथ सरकार के तत्त्वावधान में 'बैंक आफ चाइना' का भी संगठन हुआ और इस राष्ट्रीय वेंक के कारण चीन में भी आधुनिक ढंग की महाजनी का शलीभांति क्रिकास प्रारम्भ हुआ। जायन्ट स्टाक कम्पनियों और वैकों के विकास के कारण ^थीन में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उन्नति सम्भव हो सकी। सबसे पहले सूती कवड़े को तैयार करने के लिये मिलें खोली गईं। चीन में कवास पर्याप्त मात्रा में पैदा होती थी, मजदूर भी वहां बहुत सस्ते रेट पर मिल सकते थे। अतः अनेक विदेशी पंजीपतियों का ध्यान भी इस बात पर आकृष्ट हुआ, कि चीन में मिलें खोलकर रुपया पैदा करें। १९२८ तक चीन में वस्त्र व्यवसाय इतना अधिक उन्नत हो गया था, कि कपड़े की मिलों में ढाई लाख से अधिक मजदूर काम करते थे। आधी के लगभग कपड़े की मिलें शंघाई में स्थित थीं और इनमें विदेशी पंजीपतियों ने बड़ी उदारता के साथ अपनी पूंजी लगाई हुई थी। वस्त्र व्यवसाय में कुल मिलाकर जितनी पंजी चीन में लगी हुई थी, उसका एक तिहाई भाग विदेशियों द्वारा लगाया गया था। वस्त्र व्यवसाय के अतिरिक्त रेशमी वस्त्र दियासलाई, चीनी, लोहा, शराब आदि को तैयार करने के लिये भी बहुत से नये प्रकार के कारखाने इस समय चीन में स्थापित हए। कागज का व्यवसाय ्रीत में बहुत देर से चला आ रहा था। शुरू में कागज छोटे छोटे कारखानों म तैयार होता था, जिनमें छः सात मजदूर काम करते थे। पर अब नये ढंग की पेपर मिलें स्थापित होती शह हुई. और तीन इस व्यवसाय में भी बच्छी उन्नित कर गया । पर १९३१ तक चीन में व्यावसायिक उन्नति का श्रीनणेन मात्र ही हुआ था। चीन में कामले अंद बोहे की प्रयुक्ता है। भजदूर भी बहां बहन

बड़ी संस्था में और सस्ते दर पर उपलब्ध है। निदयों और स्रोतों के बाहुल्य के कारण वहां विजली की उत्पत्ति भी कितन नहीं है। कच्चा माल भी बहु प्रचुर परिमाण में प्राप्त हो सकता है। इस दशा में यदि जापान की सरकार के समान चीनी मरकार भी अपने देश की व्यावसायिक उन्नति पर ध्यान देती, तो चीन आधिक क्षेत्र में बहुत उन्नति कर जाता। पर १९३१ तक चीन की सरकार को अपनी आन्तरिक समस्याओं में ही फुरसत नहीं थी और इसीलिये बह देश की व्यावसायिक उन्नति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकी। पर यह स्पष्ट है, कि मरकार के उपेक्षा के बावजूद भी चीन में व्यावसायिक उन्नति का प्रारम्भ हो गया था और पाश्चात्य देशों के समान वहां भी श्रम सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न होने लग गई थीं। पर चीन के लिये इन समस्याओं को हल कर सकता सुगम नहीं था, क्योंकि अनेक कारखाने विदेशियों के स्वामित्त्व में थे और अनेक कारखाने ऐसे प्रदेशों में स्थित थे, जो विदेशी राज्यों के प्रभाव क्षेत्रों के अन्त-र्गत थे। चीनी सरकार इन पर अपने कानूनों को लागू नहीं कर सकती थी।

श्रीमयों की समस्या—कल कारखानों के विकास के कारण चीन में भी मजदूरों की समस्या विकसित होनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले १९१९ में 'चीनी मजदूरों की उन्नति के लिये संघ' की शंघाई में स्थापना हुई। इस संघ का उद्देश यह था, कि मजदूरों के हितों की रक्षा की जाय। इसकी शाखाएं चीन के विविध व्यावसायिक केन्द्रों में स्थापित की गईं। मजदूरों के इस संघ ने मजदूरी की दर में वृद्धि करने और कार्य करने के घण्टों में कभी करने के लिये आन्दोलन शुरू किया। आन्दोलन से अपने प्रयत्न में सफलता होती न देखकर चीन के मजदूरों ने हड़तालों का आश्रय लिया। पेकिंग के एक समाचार पत्र के अनुसार सितम्बर, १९२२ से दिसम्बर, १९२२ तक चार महीनों में चीन में ४१ हड़तालों हुई। इस स यह भलीभांति समझा जा सकता है, कि चीन के मजदूरों में इस समय कितनी अधिक अशान्ति थी। कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों में वहुत कम बेतन मिलता था। अपने वेतन से उनके लिये यह असम्भव था, कि वे अपना व अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें। इसी कारण मजदूर लोगों में इस समय घोर अशान्ति थी और वे अपनी दशा के सुधार के लिये घोर संघर्ष में तत्पर थे।

मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये तीन ही उपाय थे—(१) सरकार की ओर से ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाय, जिनसे मजदूरों के कार्य करने की दशा में उन्नति हो, उनकी न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाय और वे अधिक से अधिक कितने घंटे प्रतिदित काम कर सकें, यह भी कानून द्वारा तय कर

दिया जाय । (२) कारखानों के मालिक स्वयमेव मजदूरों की दशा के मुवार पर्ध्यान दें। (३) कारखानों में ऐसी पंचायतें स्थापित की जावें, जिनमें मजदुरों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। मजदूरों और मालिकों में झगड़ा होने पर ये पञ्चायतें उनका फैसला करें। चीन के अनेक मिल मालिको ने मजदूरीं की दशा के सुधार पर ध्यान देने का प्रयत्न किया । कई कारखानों में मजदूरों के निवास के लिये साफ मुथरे मकान बनाये गये, उनके इलाज के लिये अस्पताल खोले गये और बच्चों की शिक्षा व मनोरंजन के लिये स्कल व पाकों की स्थापना की गई। पर मजदूर इनसे संत्रष्ट नहीं थे। ऐसे कारखानों में उन्हें वेतन वहत कम दिया जाता था और पर्याप्त आमदनी के अभाव में मजदूरों की दशा में सुधार असम्भव था । कुछ कारखानों में ऐसी पञ्चायतें भी स्थापित की गईं, जिनमें मजदूरों की अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था। पर राजकीय शक्ति के साथ न होने के कारण इस प्रकार की पञ्चायतों के लिये सफलता प्राप्त कर सकता मुगम नहीं था। मजदूरों की समस्या को हल करने का सीधा और सरल उपाय यह था, कि चीन में भी सरकार की ओर से उसी ढंग के कानून बनाये जावें, ज़ैसे कि कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों के लिये पाञ्चात्य देशों में बनाये जा रहे थे। १९२९ में चीन में 'ट्रेड युनियन एक्ट' स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार मजदूरों को यह अधिकार दिया गया, कि वे अपने संघ बना सकें और सामृहिक रूप से अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न कर सकें। चीन की सरकार चाहती थी, कि मजदूरों के हित के लिये अन्य कानुनों का भी निर्माण करे। पर उसके सम्मुख सबसे बड़ी कठिनता यह थी, कि बहुत से कारखाने ऐसे प्रदेशों में स्थित थे, जो विदेशी राज्यों के प्रभावक्षेत्रों के अन्तर्गत थे। चीनी सरकार के कान्त इनमें लाग् नहीं होते थे। यदि चीनी सरकार के आधिपत्य में विद्यमान प्रदेशों में स्थित कारखानों के लिये कानून बनाये जाते, उनमें काम करनेवाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी व अधिकतम कार्यकाल को निश्चित करने का प्रयत्न किया जाता, तो स्वाभाविक रूप से इन में जो माल तैयार होता, उसकी लागत उन कारखानों के माल के मुकाबले में अधिक पड़ती, जो विदेशी प्रभाव-क्षेत्रों में विद्यमान थे। इससे चीनी लोगों के अपने कारखानों के लिये विदेशी क्रिरखानों का मकाबला कर सकना सम्भव न रहता। अतः चीन की सरकार के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण यही था, कि पहले विदेशी लोगों के प्रभाव व प्रभत्व का चीन से अन्त किया जाय। तभी वह मजदूरों की दशा की सुधारने के लिये आवश्यक कानुनों के निर्माण पर भी ध्यान दे सकती थी। मुद्रापद्धति-पदार्थों के विनिमय और व्यापार के लिये चीन में जो मुद्राएं

प्रचलित थीं, वे दो प्रकार की थीं, तायल और तांबे के सिक्के । तायल २॥ नोका चांदी के बराबर होता था और नगरों में वस्तुओं के विनिमय और व्यापुर के लिया इसी का उपयोग होता था । देहातों में प्रायः तांवे के सिक्के चलते थे और थेंगी को मन की आदायगी के लिये गहरों में भी ये प्रयुक्त होते थे। विदेशी राज्यों के महार्क के कारण चीन में अनेक विदेशी सिक्कों का भी चलन शुरू हुआ, जिनमें अमेरिका का डालर सर्वप्रधान था। १८९४ में चीनी सरकार की आर में गुरु तथ सिनके को जारी किया गया, जिसे युआन कहते थे। यह अमेरिकन डालर में मिलना जलता था। जब चीन में बैंक खुलने शुरू हुए, तो पत्र मुद्राओं का भी चलन गुरु हुआ। येपत्र मुद्राएं न केवल वैकों द्वारा जारी की जाती थी, अपित अनेक प्रान्तीय सरकारें भी इन्हें जारी करती थी। इसका परिणाम यह था, कि चीन को राजनीति के समान उसकी मुद्रापद्धति भी सर्वथा अन्यवस्थित थी। मद माधारण लोगों के लिये यह समझ सकता सुगम नहीं था, कि वे किन मुद्राओं पर भरोसा कर सकते हैं। पत्र मुद्राओं में वृद्धि के कारण चीन में कीमतें भी निरन्तर बढ़ रही थीं। १९१४-१८ के गहायद के बाद जब संसार के सभी देशों में कीमतें बढ़ने लगीं, तो उसका असर चीन पर भी पड़ा । किसी मुख्यवस्थित मुद्राल पद्धति के अभाव में वहां की दशा और भी अधिक गोचनीय हो गई। इस दशा में नुओं मिन्तांग सरकार के सम्मुख यह भी एक प्रधान समस्या थी, कि वह मुद्रा-पद्धित को व्यवस्थित कर किस प्रकार देश की आर्थिक दशा का सुधार करे। जानान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों और आन्तरिक विरोधी शवितयों के साथ निरन्तर संवर्ष करते रहने के कारण कुओमिन्तांग सरकार की इस विषय में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । अगले एक अध्याय में हम इस यात पर विशव रूप से प्रकाश डालेंगे, कि किस प्रकार चीन में मुद्रापद्धति में निरन्तर हान होता गया और एक समय ऐसा आ गया, जब कि चीन की पत्रमुद्रा की कीमन न के बराबर रह गई।

(२) विद्या का पुनः जागरण

पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क में आने के कारण चीन में विद्या और ज्ञान का पुन: जागरण प्रारम्भ हुआ। किश्चियन मिश्रनिर्यों द्वारा स्थापित शिक्षणाद्वा में चीनी विद्यार्थी जहां ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे, वहां साथ ही ने ज्ञान विज्ञान से परिचित होने का भी उन्हें अवसर मिलता था। विदेशों से शिक्षा पाकर जो नवयुवक चीन लौटते थे, वे अपने देश में नवयुग की स्थापना के लिये तीन अभिलाषा साथ लेकर वापस आते थे। १९०५ में जब प्राचीन परीक्षा-

पद्धति का अन्त किया गया, तो शिक्षा की पद्धति में सुधार कर मकता बहुत सृगम हो गया । इस परीक्षा पद्धित के कारण चीन के विद्यार्थी प्राचीन ग्रन्थों और धर्म- अल्हेंबों के अध्ययन को बहुत अधिक महत्त्व देते थे, क्योंकि इनमें निष्णात होने पर ही उनके लिये सरकार में उच्च पदों को प्राप्त कर सकता मम्भव होता था । परीक्षा पद्धति का अन्त हो जाने पर चीन के नवयूदक नवीन जान-विज्ञान पर ध्यान देने लगे और प्राचीन ग्रन्थों की अपेक्षा आधुनिक विज्ञान का महत्त्व अधिक बढ़ गया । १९१२ में जब राज्यकान्ति द्वारा मञ्च जामन का अन्त हुआ, तब नये जान विज्ञान के प्रति अभिक्षिच में और भी अधिक वृद्धि हुई, और चीन में नये जागरण का प्रारम्भ हुआ।

शिक्षा का प्रसार-उन्नीसवीं नदी में आध्निक शिक्षा देने के लिये जो भी संस्थायं चीन में विद्यमान थी, वे ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापिन की गई थीं। चीनी लाग शिक्षा को बहुत महत्त्व देते थे । चीन के समाज में पण्डिन वर्ग का जो असाधारण रूप से सम्मान था, उसका उल्लेख पहले किया जा चका है। अतः ईसाई मिशनरियों ने यह प्रयत्न किया, कि जो चीनी नागरिक ईसाई धमं को स्वीकार कर प्रचारक का कार्य प्रारम्भ करें, वे भी गशिक्षित और विहान हों। किंगनरी लोगों द्वारा स्थापित स्कलों में जहां ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी. वहां साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच आदि पारचात्य भाषाओं और उनके साहित्य को भी पढाया जाता था । ईसाई धर्म के प्रचार के लिये मिशनरी लोगों ने बहुत से चिकि-त्सालयों की भी स्थापना की थी। अतः ईसाई स्कुलों में चिकित्साशास्त्र की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाता था, ताकि चीनी डाक्टर व नसे चिकित्माल्यों में कार्य करके ईसाई धर्म के प्रचार में सहायक हो सकें। किश्चियन प्रचारक यह भी भलीभांति अनुभव करते थे, कि चीनी भाषा, साहित्य व धमंग्रन्थों का अध्ययन भी उनके धर्म प्रचार कार्य के लिये उपयोगी है। अतः उन्होंने चीनी भाषा के शब्दकीय तैयार करने और अनेक चीती ग्रन्थों के अनुवाद कार्य पर भी ध्यान दिया । इन अन्वादों के कारण पाश्चात्य देशों की युनिवर्सिटियों में विद्वानों का ध्यान चीनी भाषा और साहित्य के प्रति आकृष्ट हुआ। पाश्चात्य देशों के मिशनरियों ने बाइपल का अनवाद तीनी भाषा में किया और धर्म प्रचार के उद्देश से बहुत सी छोटी वड़ो पुनतके भी जीनी नागा में प्रकालित की । ईसाई मिशनरियों हो रा जो स्कुल व कालिज चीन में न्यापित किये गये थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चका है । इसमें सन्देह नहीं, कि किश्चियन स्कुलों द्वारा ही पहले पहल चीनी लोग पार्कात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान के सम्पर्क में आये।

पर चीन की सरकार भी गई। शिक्षा का देश में प्रचार करने के लिये तस्पर

थी । १८६५ में तुंगवन कालिज की स्थापना हुई थी और यह कालिज किविचयन मिशनों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखता था। चीन में यह आधुनिक ढंग का पहला कालिज था। १८९५ में ली हंग चांग द्वारा तीन्त्सिन में एक युनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, इसे पेइयांग युनिवर्सिटी कहते थे। इसके वाद १९०० में चिआओ-तंग-पुनत्यांग और पेकिंग विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । इन यूनि-वसिटियों में चीन के प्राचीन साहित्य के अतिरिक्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की भी व्यवस्था थी । साथ ही सैनिक शिक्षा के लिये भी अनेक शिक्षणालय इस काल में सरकार द्वारा स्थापित किये गये थे। उच्च शिक्षणालयों के अति-रिक्त स्कली शिक्षा की ओर भी सरकार का ध्यान गया था और इसी का यह परिणास था. कि उन्नीसवीं सदी की समाप्ति से पूर्व ही चीन में विविध प्रकार के बहुत मे शिक्षणालय खुलने प्रारम्भ हो गये थे। पर क्योंकि अभी प्राचीन शिक्षा-पद्धति चीन में विद्यमान थी, अतः इन शिक्षणालयों में प्राचीन साहित्य के अध्ययन को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिये जिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक था, उनमें कन्फ्युसियस आदि प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों का स्थान बहुत महत्त्व का था, अतः चीन के सब शिक्षणालयों में उनके अध्ययन अध्यापन पर बहुत जोर दिया जाता था। १९०५ में परीक्षा-पद्धति कां अन्त किया गया और इससे चीन के शिक्षणालयों की पाठिविधि व पाठ्य विषयों में बहुत अन्तर आया। १९०५ के बाद चीन के विक्षणालयों में प्राचीन साहित्य की अपेक्षा नये ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। बहुत से नये स्कूल खोले गये। अनेक पूराने मन्दिरों और मठों को स्कुलों के रूप में परिवर्तित किया गया। राज्यकान्ति के बाद जब १९१२ में चीन में रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब शिक्षा प्रसार पर और अधिक ध्यान दिया गया। चीन के नेता यह बात भलीभांति अनुभव करते थे, कि लोकतन्त्र शासन तभी सफल हो सकता है, जब कि सर्व साधारण जनता शिक्षित हो और वह आधु-निक युग की प्रवृत्तियों से परिचय रखती हो। शिक्षा प्रसार के कार्य पर सरकार का इतना अधिक ध्यान था, कि १९३१ में चीन में विविध प्रकार के छोटे बडे शिक्षणालयों की संख्या १,३१,०००तक पहुंच गई थी। इनमें पढ़ने वाले विद्या-थियों की संख्या भी इस समय में ४३ लाख के लगभग थी। सरकारी नियंत्रण के बाहर निज् रूप से जो शिक्षणालय धार्मिक सम्प्रदायों व पुराने ढंग के पण्डि वर्ग द्वारा संचालित थे, वे इनसे अलग थे। सरकार शिक्षा के प्रसार के लिये इतनी तेजी के साथ स्कूलों व कालिजों की स्थापना में तत्पर थी, कि उनके लिये उपयुक्त अध्यापकों का मिल सकना सुगम नहीं था । विशेषतया नये ज्ञान विज्ञान

को पढ़ाने के लिये अध्यापकों का मिल सकता तो बहत ही कठिन था। इसी कारण बहुत से चीनी युवक इस समय विदेशों में विद्या के अध्ययन के लिये गये। संयवत र उंग अमेरिका, ब्रिटेन, फांस, जापान आदि कोई भी ऐसा उन्नत देश नही था, जिसमें इस समय चीनी नवयुवक हजारों की मंख्या में उच्च शिक्षा के लिये न गये हों। जो लोग अधिक सम्पन्न थे, वे युरोप और अमेरिका जाते थे और जिनके पास धन की कमी होती थी, वे जापान जाकर ज्ञान की पिपासा को जान्त करते थे । उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये विद्यार्थी जब विदेशों से चीन लीटने थे, तो वहां के शिक्षणालयों में कार्य करके न केवल शिक्षा के प्रसार में महायक होते थे. अपित् साथ ही नये विचारों का भी अपने देश में प्रचार करते थे। इन विद्यार्थियों द्वारा पाश्चात्य सभ्यता के चीन में प्रवृष्ट होने में बहुत अधिक सहायता मिली । इसमें सन्देह नहीं, कि विदेशों में शिक्षा पाये हुए इन चीनी नवयुवकों को अपने देश के प्राचीन साहित्य की अपेक्षा पाश्चात्य साहित्य का अधिक परिचय होता था। पर विदेशों में निवास करने और नवीन विचार धाराओं के सम्पर्क में आने के कारण इनमें राष्ट्रीयता का भावना बड़े उग्र रूप में विकसित हो जाती थी। विदेशी रहन सहन को अपना लेने पर भी इनमें स्वदेश के प्रति भिक्त क्त भावना कम नहीं हो पाती थी। यही कारण है, कि चीन की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये ये विद्यार्थी बहुत सहायक सिद्ध हुए।

१९१४-१८ के महायुद्ध के समय श्री० येन द्वारा सर्वसाधारण जनता में शिक्षा का प्रसार करने के लिये एक नये आन्दोलन का प्रारम्भ किया गया। श्री० येन धर्म से ईसाई थे और चीन की ईसाई संस्था वाई० एम० सी० ए० (यंग मेन्स किश्चियन एसोसिएशन) के प्रमुख कार्यकर्ता थे। महायुद्ध के अवसर पर जो हजारों चीनी मजदूर फांस आदि यूरोपियन देशों में मजदूरी के लिये गये थे, श्री येन ने उन्हें साक्षर बनाने के कार्य में बिशेष तत्परता प्रविश्वत की। चीनी कुलियों व मजदूरों को शिक्षित करने में श्री० येन को जो सफलता हुई, उससे उत्साहित होकर उन्होंने महायुद्ध की समाप्ति पर चीन में कार्य करना शुरू किया। देहातों के किसानों और शहरों के मजदूरों में शिक्षा का प्रसार करने के लिये श्री० येन ने बड़ा भारी आयोजन किया। अब इस आन्दोलन का सम्बन्ध केवल वाई० एम० सी० ए० के साथ ही नहीं रह गया, यह चीन की सर्वसाधारण जनता का आन्दोलन की गया और इसके कारण चीनी जनता को साक्षर बनने में बहुत अधिक सहा-यता मिली।

विद्यार्थी आन्दोलन-शिक्षा के प्रसार के कारण चीन में विद्यार्थियों की एक ऐसी अंभी का विकास प्रारम्भ हो नया था, जो राष्ट्रीयता, देशअंग बार नय-

जीवन से ओनप्रोन थी। देश की उशनि और विदेशियों के प्रभृत्व की नष्ट करने की भावना उस श्रेणि में अत्यन्त उग्र हुए से विद्यमान थी। यही कारण है, कि चीन के राजनीतिक आन्दोलनो में विद्यार्थियों का बड़ा हाथ होता था । १९१४ - र्रेक्ट के सहायुद्ध की समाप्ति के अनन्तर पेरिस की सन्धि परिषद ने शांतग पर जापान के प्रभूत्व को जारी रखने का जो फैसला किया था, उसका समाचार जब पेकिंग पहचा, तो वहा के विद्यार्थियों में बेचैनी फैल गई । जलस बनाकर वे पेकिंग के उस प्रदेश में जा पहुंचे, जहां विदेशी राज्यों के दूतावास थे। विदेशों की सनाओं ने उन्हें इताबासों के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं होने दिया। इसपर उन्होंने पैकिंग सरकार के अर्थमन्त्री श्री त्याओं ज्लिन के निवास स्थान को घर लिया । उनका खयाल था. कि त्माओं जुलिन जापान के साथ सहान्भृति रखता है। त्साओं जुलिन को अपनी जान बचाने के लिये जापानी दुताबास की शरण लेनी पड़ी। अब विद्या-थियों ते चीन के मन्त्रिमण्डल पर इस बात के लिये जोर दिया, कि वह पेरिस स्थित अपने प्रतिनिधि को यह आदेश दे, कि अह वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर न करे। पेकिंग सरकार ने विद्यार्थियों के इस आन्दोलन को कुचलने के लिये भरसक कोशिश की। पेकिंग व अन्य नगरों में हजारों विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये, चीन की जेलें विद्यार्थियों से भर गईं। पर दमन नीति द्वारा विद्यार्थी आन्त्रे लन दबा नहीं। ज्यों ज्यों गिरफ्तारियां होती थीं, विद्यार्थी और अधिक संख्या में संघर्ष के मैदान में आते जाते थे। उन्होंने मजदरों के संघों को अपने साथ आन्दोलन में शामिल कर लिया । चीन में सर्वत्र इस समय हड़तालों का आयो-जन किया गया । बहुत से कारखाने मजदूरों की हड़तालों के कारण बन्द हो गये। विद्यार्थियों ने जापानी माल के बहिष्कार के लिये भी आन्दोलन शुरू कया। व्यापारियों को इस वात के लिये विवश किया गया, कि वे जापानी माल को न बेचें। विद्यार्थियों के इस आन्दोलन ने इतना उग्र रूप धारण किया, कि अन्त में विवश होकर चीन की सरकार ने यह फैसला किया, कि वसीय की सन्धि पर हस्ताक्षर न किये जावें और गिरफ्तार किये गये विद्यार्थियों व मजदूरों को जेल से भवत कर दिया जाय।

चीन के आधुनिक इतिहास में विद्याधियों का यह आन्दोलन अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण स्थान रखता है। इस समय चीन के नवयुवक विद्यार्थी देश में जागृति उत्पक्ष करने में तत्पर थे। विदेशियों ने चीन में जो अनेक प्रकार से अपना प्रभुत्व कार्यों किया हुआ था, उसके विश्व विद्यार्थी लोग जलूस निकालते थे, सभाय करते थे, विदेशी माल को वहिष्कृत करने के लिये जनता को उकसाते थे और सब प्रकार के उपायों का अनुसरण कर जनता में विदेशियों के विश्व भावना को उत्पन्न करते

थे। रूस के कम्युनिस्टों की चीन के विद्यार्थी आन्दोलन के साथ सहानुभृति थी। गृही कारण है, कि ब्रिटेन, अमेरिका, जापान आदि की सरकार चीन के विद्यार्थी आन्दोलन को कम्युनिस्ट लोगों द्वारा प्रारम्भ किया हुआ उसे बदनाम करने की कोशिश करनी थीं और पेकिंग सरकार को प्रेरित करती थीं, कि उग्र उपायों का अवलम्बन कर उसे कुचल दें। कुओमिन्तांग दल के उत्कर्ष में विद्यार्थियों का बड़ा कर्तृत्व था। उन्हीं के महयोग के कारण डा० सन यात सेन और उसके अनुयायी अपनी शक्ति का विस्तार करने में सफल हए थे। १९२५ में शंघाई में विद्यार्थियों ने मजदूरों को हड़ताल करने के लिये प्रेरित किया । शंघाई की अनेक मिलें जापानी लोगों द्वारा स्थापित थी । विद्या-थियों के प्रयत्न से इन जापानी मिलों में हडताल हो गई और विद्याधियों ने एक बहुत बड़ा जलूस मजदूरों के साथ सहानुभृति प्रदर्शित करने के लिये निकाला । शंघाई की विदेशी पुलिस ने इस जलूस पर गोली चलाई और अनेक विद्यार्थी गोली के शिकार बने । इस हत्याकांड के खिलाफ एक और भी अधिक वड़े जल्स का आयोजन किया गया । विदेशी पुलिस ने इस जलुस पर भी गोली चलाई और ्बंहत से विद्यार्थी इस बार पुलिस की गोलियों द्वारा मारे गये। शंघाई की इस विदेशी पुलिस में अंग्रेज लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। उनका अफसर भी अंग्रेज था । परिणाम यह हुआ, कि चीन में अंग्रेजों के खिलाफ भावना बहुत प्रबल हो गई। एक बार फिर विदेशी माल के बहिष्कार का आन्दोलन शुरू हुआ। इस समय चीन की जनता में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ बहुत तीव्र आन्दोलन चल रहा था। १९२६ में कुछ चीनी सिपाहियों ने एक ब्रिटिश जहाज पर गोली चला दी । इसका प्रतिशोध करने के लिये अंग्रेजों ने एक चीनी नगर पर गोलाबारी की और वहां के निरपराध निवासियों के साथ भयंकर रूप से बदला लिया। विद्यार्थी इससे और अधिक भड़क गये और उन्होंने विदेशियों, विशेषतया अंग्रेजों के खिलाफ अपने आन्दोलन को जारी रखा। इसी समय विद्यार्थी आन्दोलन की सहायता से कुओमिन्तांग दल ने पेकिंग की निर्वल सरकार का अन्त कर नानिकंग में अपनी सरकार की स्थापना की। चीन में जो अब राष्ट्रीय चेतना विकसित हो गई थी, उसमें विद्यार्थियों का कर्तृत्व बहुत महत्त्वपूर्ण था।

समाचार पत्र और नया साहित्य-जिस प्रकार शिक्षा के प्रसार और विद्यार्थी शान्तीलन द्वारा चीन में पुनः जागरण हो रहा था, वैसे ही समाचार-पत्र और नया माहित्य भी इस नवजीवन में बहुत सहायता पहुंचा रहे थे। शुरू में जो समाचार पत्र चीन में इकाजिन हुए, वे विदेशी भाषाओं के थे। समुद्रतट पर स्थित बन्दर-गाहों में व्यापार आदि के छिये बहुत ने विदेशी लोग आवाद थे। इन पत्रों का

प्रचार इन विदेशियों में था और इनमें प्रायः इसी प्रकार के समाचार व लेख प्रका-जित होते थे, जिनमें विदेशी लोगों को दिलचस्पी होती थी। चीनी भापा 🎉 पहला ममाचार पत्र १८७० में प्रकाशित होना शुरू हुआ। चीन-जापान यद्ध (१८९४-९५) के समय में अन्य अनेक पत्र चीनी भाषा में निकलने लगे। इस समय चीन में जागित का प्रारम्भ हो गया था, जनता राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी लेने लगी थी और वह चीन जापान यद्ध, बोक्सर विद्रोह, स्थार-वादियों व कान्तिकारियों के आन्दोलन, मञ्चू जासन के विरुद्ध विद्रोह आदि के समाचारों को बड़े उत्साह व दिलचम्पी के साथ पढ़ा करती थी । १९११ की राज्य-'कान्ति के बाद समाचार पत्रों की संख्या में और अधिक वृद्धि हुई। १९३६ तक · चीन में यह दशा आ गई थी, कि प्राय: सभी बड़े नगरों से कोई न कोई पत्र अवस्य प्रकाशित होने लगा था। आवागमन के साधनों की उन्नति और टैलीग्राफ व ैटैलीकोन के प्रारम्भ के कारण इन समाचार पत्रों का प्रचार बहुत बढ़ गया था और अनेक पत्र न केवल चीन की आन्तरिक राजनीति अपित विदेशी राजनीति धर भी समाचार व लेख प्रकाशित करने लग गये थे। दैनिक व साप्ताहिक पत्रों के साथ साथ मासिक व त्रैमासिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन शुरू हो गया था 🚜 और कतिपय पत्रिकायें वैज्ञानिक विषयों पर भी निकलने लगी थीं। इस बात की अनुमान सहज में किया जा सकता है, कि चीनी भाषा में प्रकाशित ये पत्र पत्रिकायें देश में नवजीवन का मंत्रार करने और जागृति को उत्पन्न करने में कितनी अधिक सहायक थीं।

नीन में पहले जो कुछ भी राहित्य तैयार होता था, वह वहां की प्राचीन भाषा में होता था। पण्डित वर्ग प्राचीन भाषा में लिखने पढ़ने में ही गौरव अनुभव करना था। जिस प्रकार भारत की पण्डित मण्डिली संस्कृत प्रत्थों का अध्ययन करनी थी, संस्कृत में ही पुस्तकें लिखती थी और हिन्दी आदि लाकिक व प्राकृतिक भाषाओं में पुस्तकें लिखना हीन बात समझती थी, वैसी ही दशा चीन में भी थी। १९१७ में डा० हू सुह ने घोषणा की, कि भविष्य में वे अपनी पुस्तकें उस भाषा में लिखेंगे, जिसे सर्वसावारण जनता प्रयुक्त करती है। डा० हू सुह की शिक्षा अमेरिका में हुई थी और वे पिकन यूनिविसिटी में अध्यापक थे। जब तक चीन में पुरानी परीक्षा पद्धति विद्यमान थी, यह सम्भव नहीं था, कि इस प्राचीन भाषा की उसे की जा तकती। पर अत्र परीक्षा पद्धति का अन्त हुए बारह साल व्यतीत हो चुक थे। अब डा० हू सुह जैसे विद्यानों के लिये यह सम्भव था, कि वे जन साधारणकी भाषा में साहित्य का निर्माण करने में प्रवृत्त हों। १९२० में सरकार की ओर से आज्ञा प्रकाशित की गई, कि स्कूलों की प्रारम्भिक कक्षाओं में प्राचीन भाषा को

न पढ़ा कर केवल प्रचलित चीनी भाषा की पढ़ाई हो। इस प्रकार चीन में एक ऐसे नवीन साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जिसे सर्व सावारण जनता भली-भांति समझ सकती थी और जिसे पढ़ कर उसके लिये नये ज्ञान विज्ञान से परिचित हो सकना अधिक सुगम था। इस नये माहित्य पर प्राचीन ग्रन्थों व ज्ञाम्बों की अपेक्षा पाश्चात्य विचारधाराओं का प्रभाव अधिक था और इसके विकान में चीन के पुनः जागरण में बहुन अधिक महायता मिली।

पत्र पत्रिकाओं और नवीन साहित्य द्वारा चीन के नवयुवकों में यह प्रवित्त बढ़ रही थी, कि वे प्रमाणवाद का परित्याग कर वृद्धि और तर्क द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिये प्रवृत्त हों। चीनी लोग जहां प्राचीन समय के परम्परागत बन्धनों को तोड़ कर स्वतन्त्र होने के लिये उत्सूक थे, वहां साथ ही वे पारचात्य लोगों के विचारों व विश्वासों को भी आंख मीच कर स्वीकार कर लेने के लिये उद्यत नहीं थे। पाञ्चात्य सभ्यता को उत्कृष्ट मान लेने की प्रवृत्ति जनमें नही थी। १९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर ब्रिटेन, फांस आदि देशों की ओर से चीन में जर्मनी और आस्ट्रिया के विरुद्ध बहुत प्रचार किया ्र गया। जर्मन लोग मनुष्य के रूप में राक्षस हैं और उनकी सभ्यता व संस्कृति जंगली व बर्वर लोगों से किसी भी प्रकार उत्कृष्ट नहीं है, यह विचार मित्रराष्ट्रों की ओर से डंके की चोट के साथ प्रचारित किया गया । पर चीनी लोगों की दृष्टि में जैसे जर्मन थे, वैसे ही ब्रिटिश व फ्रेंच थे। विविध पारचात्य देशों के साम्राज्यवाद के कारण चीनी लोगों ने एक समान कष्ट उठाया था। अतः मित्रराष्ट्रों के जर्मन विरोधी प्रचार के कारण चीनी लोगों ने यह विचारना गुरू किया, कि पाश्चात्य देशों द्वारा जो नये आदर्श व विचार उनके सम्मुख पेश किये जा रहे हैं, क्या वस्तुतः वे सत्य है। चीन में इस समय जो पूनः जागरण हो रहा था, वह उनमें स्वतन्त्रता की भावना को उत्पन्न कर रहा था। उसके कारण जहां चीन की पुरानी जंजीरें टट रही थीं, वहां साथ ही चीनी जनता अपने को पाश्चात्य लोगों का अन्धानुयायी बना लेने के लिये भी तैयार नहीं थी।

(३) सामाजिक जीवन

पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क और व्यावसायिक उन्नति के कारण चीन में जिस नवयुग का प्रारम्भ हो रहा था, उन का प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ना भी आवश्यक था। चीनकी जनता पड़ले प्रभवमें देशतों व नगरों में रहती थी, एक परिवार व कुल के लोग एक स्थान पर निवास करने थे। सितरों की पूजा दीनी धर्म व सामाजिक संगठन का महत्त्वपूर्ण अंग थी। प्रत्येक स्पित का यह पुनीत

कर्तव्य समझा जाता था, कि वह अपने पितरों की पूजा करे और उनकी समाधि-यों के प्रति अपने सम्मान की प्रदर्शित करे। पर बीसवी सदी के प्रारम्भ होझे से पूर्व ही चीन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लग गईं थीं, जिनके कारण एक कुल व परिवार के सब लोगों के लिये एक स्थान पर निवास करते रहना सम्भव नहीं रहा था। रेलों और सड़कों के निर्माण के कारण यात्रा करना बहुत सगम हो गया था, और आजीविका की खोज में बहुत से चीनी लोग अपने कुल कमा-नुगन घरों को छोड़कर मुदुरवर्ती प्रदेशों में व्यापार, मजदूरी व नौकरी के लिये जाने लग गये थे। अपने पितरों की समाधियों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करने के लिये अपने घर जाते रहना इनके लिये सुगम नहीं था। कल कारखानों के विकास के कारण लाखों की संख्या में देहाती किसान मजंदूर बन कर शंघाई जैसे विभाल नगरों में एकत्र हो गये थे। ये लोग छोटी छोटी कोटरियों में निवास करते थे। इनकी आमदनी इतनी कम थी, कि ये अपने कुल के लोगों के साथ घनिष्ट सम्पर्क नहीं रख सकते थे। परिणाम यह हुआ, कि कूल के प्रति निष्ठा की भावना जनता में मन्द पड़ने लगी और जिस प्रकार पहले एक परिवार के सब व्यक्ति अपने क्लवृद्ध के शासन में रहते थे, वह बात अब सम्भव नहीं रही । कुल व विरादरी के शासन से मुक्त हो कर चीन के लोग अपने छोटे छोटे परिवारों का निर्माण करने में प्रवत्त हुए और शहरों व परदेश में निवास करने वाले पति-पत्नी परम्परागत कूल मर्यादा की उपेक्षा कर स्वच्छन्दता के साथ जीवन बिताने लगे । कुल मर्यादा का स्थान वैयक्तिक स्वतन्त्रता ने ले लिया । ईसाई मिशनरियों के प्रचार और पश्चिमी देशों के सम्पर्क द्वारा इस प्रवृत्ति में सहायता भिली। अब चीन के सर्वसाधारण लोगों में यह प्रवृत्ति प्रवल होने लगी, कि वे सब पुरानी बातों पर बुखिपूर्वक विचार करें। यदि उन्हें वे बातें युक्तियुक्त प्रतीत हों, तो उन्हें माने, अन्यया उनका परित्याग कर दें। विरादरी के प्रभाव में रहने के कारण लोग जो पहले पुरानी परिपाटी को कायम रखने के लिये विवश होते थे, अब उसकी ओई आवश्यकता नहीं रह गई।

चीन में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ स्त्री शिक्षा का प्रचार भी बढ़ रहा था। उत्तीसनीं सदी तक चीन में स्त्री शिक्षा नाम मात्र को थी। क्योंकि स्त्रियों को विविध राजकीय पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, अतः उन्हें शिक्षित कर्ति की भी। कोई आवश्यकता नहीं समझी जानी थी। जब पाश्चात्य मिशनिरयों ने चीन में अपने स्कूल स्पाध्या किये, तो उन्होंने गर्थ आदि के कार्य के लिये चीनी स्त्रियों को तैयार करने के लिये उन्हें भी शिक्षा देना शुरू किया। १९११ में जब चीन में राज्यकाल्ति हुई, तो उसका असर स्त्री शिक्षा पर भी पड़ा। सरकार

की ओर से अनेक कन्या पाठशालायें स्थापित हुई, और बहुत सी चीनी लड़कियां इन पाठशालाओं व कालिजों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रवृत्त हुई। जिस श्रुकार नवयुवक चीनी विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये गये. वैसे ही चीनी नवयुवितयों ने भी अमेरिका, ब्रिटेन, फांस, जापान आदि में जाना शुरू किया। स्त्रियों के उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने का यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि वे अब केवल वैवाहिक जीवन व्यतीत करना ही अपना एकमात्र कार्य न समझें। उन्होंने चिकित्सा, अव्यापन आदि अनेक पेशों का भी अनसरण शक किया और धीरे धीरे चीन में स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग विकसित होना प्रारम्भ हुआ, जो अविवाहित रहकर चिकित्सक, पत्रकार, अध्यापिका आदि के रूप में आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र रह कर अपना जीवन व्यतीत करता था। जो शिक्षित स्त्रियां विवाह करती थीं, वे भी घर को ही अपना एकमात्र कार्यक्षेत्र नहीं समझती थी। वे देश के सामाजिक व राजनीतिक जीवन में भी हाथ बटाती थीं। जिस विद्यार्थी आन्दोलन का हमने इसी अध्याय में ऊपर उल्लेख किया है, उसमें लड़कियों ने भी सिकय रूप से भाग लिया था। इस समय चीन में अनेक ऐसे विक्षणालय भी स्थापित हुए थे, जिनमें लड़कों और लड़िक्यों की सहिशक्षा की पद्धित को अवनाया गया था। इनमें शिक्षा प्राप्त की हुई स्त्रियां स्वभाविक रूप से अपने को पुरुषों के बराबर व समकक्ष समझती थीं और अपनी सामाजिक स्थिति को पूरुषों के मुकाबले में किसी भी प्रकार हीन समझने के लिये उद्यत नहीं थीं।

चीन में नवयुग के सूत्रपात का एक परिणाम यह हुआ, कि विवाह के मामले में नवयुवक और नवयुवितयां, अधिक स्वतन्त्रता का आचरण करने लगे। पहले चीन में यह प्रथा थी, कि माता-पिता व कुल के बुजुर्ग लोग विवाह-सम्बन्ध का निश्चय किया करते थे। अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों से शिक्षा प्राप्त करके जो लोग इस समय चीन वापस आ रहे थे, वे अपने विवाह के विश्य में बुजुर्गों की बात मानने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे, कि स्वयं अपनी सह्धामणी का चुनाव करें। धीरे-धीरे सब शिक्षत लोगों में यह प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ, कि चीन के वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भारी परिवर्तन आना शुक्त हुआ। पर चह नहीं नगाना पाहिस्म, कि चीन की सर्वसाधारण जनता अपनी कुल मर्यादा का परित्याग कर इस समय नये विचारों के अनुसार वैवाहिक व पारिवारिक सम्बन्धों में स्वतन्त्र होने लग गई थी। यह जो परिवर्तन हो रहा था. वह प्रधाननया उच्च शिक्षत लोगों तक ही सीमित था, यद्यपि जनता भी उसके गमान से सर्वशा विच्नत नहीं थी।

मञ्चू यासन के अन्त हो जाने के बाद चीन के लोगों के रहत सहन में एक

महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ, कि पुरुषों ने चोटी रखना बन्द कर दिया। इस प्रथा का प्रारम्भ तब हुआ था, जब मञ्चू आक्रान्ताओं ने चीन को विजय करके अपने अधीन कर लिया था। भञ्चू सम्राट समझते थे, कि सिर पर लम्बी चोटी रखना इस बात का चिह्न है, कि चीनी लोग उनकी अधीनता को स्वीकार करने हैं। रिपब्लिक की स्थापना होने पर चीनी लोगों ने चोटी कटवा कर पाश्चात्य लोगों के समान छोटे वाल रखना गुरू किया। पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में आने के कारण चीन के बहुत से शिक्षित लोगों ने यूरोपियन पोशाक को भी अपना लिया था, पर कुओमिन्तांग दल के शिक्षत प्राप्त करने के बाद जनता में यह भावना विकसित हई, कि विदेशी पोशाक राष्ट्रीय दृष्टि से अनुचित है।

(४) धार्मिक विचारों में परिवर्त्तन

पाटचान्य देशों के सम्पर्क में आने के कारण चीनी जनता के धार्मिक विचारों में भी बहुत परिवर्तन आया । ईसाई धर्म के प्रायः सभी सम्प्रदाय चीन में अपने मिद्धान्तों का प्रचार करने में तत्पर थे। रूस का ओथेडिंक्स चर्च (जिसे पहले ग्रीक कैथोलिक चर्च भी कहते थे, और ग्रीम के तर्क साम्राज्य के अन्तर्गत हो जाने के बाद जिसका प्रधान केन्द्र ऋस बन गया था) मञ्चरिया और चीन में अपना ? प्रचार कार्य कर रहा था। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट पादरी मध्य और दक्षिणी चीन में अपने मत के प्रचार में तत्पर थे। १९२९ में ३४०० विदेशी पादरी रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन चीन में कार्य कर रहे थे। इसी समय में चीन में काम करनेवाले विदेशी प्रोटेस्टेन्ट पादरियों की संख्या ८००० से भी अधिक थी। इन प्रचारकों के प्रयंत्नों का यह परिणाम था, कि १९२९ में २५ लाख के लगभग चीनी लोग रोमन कैथोलिक धर्म के और ५ लाख के लगभग चीनी लोग प्राटेस्टेन्ट धर्म को स्वीकार कर चुके थे। संख्या की दिष्ट से ईसाई प्रचारकों को चीन में बहुत अधिक सफलता नहीं हुई थी, पर वहां के समाज पर ईसाईयों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जाता था । ईसाई पादिरयों द्वारा स्थापित स्कूलों और चिकित्मालयों के सम्पर्क में लाखों चीनी नागरिक प्रति वर्ष आते थे और इस धर्म के सिद्धान्तों का उन पर प्रभाव पडना सर्वथा स्वाभाविक था। पादिरयों द्वारा ही आधुनिक शिक्षा का पहले पहल चीन में प्रारम्भ हुआ था, और अनेक चीनी ईसाई राज्यकान्ति के प्रमुख नेता थे। डा० सन यात सेन धर्म से ईसाई ये। चियांग काई शेक ने भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। कुओमिन्तांग सरकार का सुयोग्य अर्थ मन्त्री श्री सुंग भी ईसाई था। उसकी दो वहनें श्रीमती सन यात सेन और श्रीमती चियांग काई शेक चीन के आधनिक

इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। चीनी सरकार के अन्य भी अनेक उच्च राजकीय पदों पर इस प्रकार के चीनी नेता आरूढ़ थे, जिल्होंने पाइचात्य अहें जो में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और जो ईसाई धर्म में दीक्षित हो चुके थे। चीन की रिपब्लिक के प्रथम राष्ट्रपति श्री युआन की काई भी वर्म से ईसाई थे। इन बातों से यह भलीभांति समझा जा सकता है, कि चीन में ईमाई लोगों का स्थान बहुन महत्त्वपूर्ण था और उनका वहा की जनता पर बहुन प्रभाव था। यदि विदेशी राज्यों का साम्राज्यवाद चीन की जनता में अत्यविक असन्तोष और उद्देग उत्पन्न न करता, तो वहां ईसाई धर्म का प्रचार और भी अधिक हो सकता। पर चीन की जनता में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि के साम्राज्यवादियों के प्रति जो विरोध व विद्वेष की भावना थी, उसके कारण लोग ईसाई धर्म को भी अच्छी। निगाह से नहीं देखते थे । कुओमिन्तांग दल के उत्कर्ष के साथ जब चीन में राष्ट्रीय प्रवित्यों ने जोर पकड़ा, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि लोगों में ईसाई धर्म के मकावले में अपने प्राचीन धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। इस प्रमंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि धीरे घीरे चीन का ईसाई चर्च भी गप्ट्रीय होता जाता था। जो चीनी लोग ईसाई धर्म को स्त्रीकृत कर लेते थे, उनमें से भी बहुत से अपादरी का पेगा ग्रहण करते थे। धीरे धीरे चीन के ईसाई चर्च के उच्च पदों पर भी चीनी पादरी नियत किये जाने लगे। पर १९३१ तक ईसाई चर्च का प्रबन्ध व संचालन मख्यतया विदेशियों के ही हाथों में था, यद्यपि चीनी ईसाईयों का उस पर प्रभाव निरन्तर बढता जाना था। १९३१ के बाद इस दिशा में और अधिक प्रगति हुई।

ईसाई धर्म के प्रचार के कारण बौढ़ धर्म में भी नवजीवन का संचार हुआ। जापानी लोग बौढ़ धर्म के अनुयायी हैं। पाञ्चात्य देशों के अनुसरण में जापानियों ने भी चीन में अपने स्कूल और चिकित्सालय स्थापिन किये। ये स्कूल और चिकित्सालय न्थापिन किये। ये स्कूल और चिकित्सालय जापान के बौढ़ मिशन द्वारा स्थापित किये गये थे। जापानी लोगों ने भी इस वात को अनुभव किया, कि धर्म प्रचार साम्राज्यदाद की नफलना जा एक अत्यन्त उत्तम साधन है। पाश्चात्य देश जो चीन में अने प्रधाय भी प्रभूल के विस्तार में सकल हो रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ईसाई मिशन हैं। इसी बात को दृष्टि में रखकर जापानियों ने भी बौढ़ धर्म के प्रचार पर विशेष ध्यान विद्या। चीन के जो प्रदेश जापान के प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत थे, वहां बौढ़ चर्च के तत्वावधान में स्कूलों और चिकित्सालयों की स्थापना की गई। चीन के चौढ़ों में भी इससे नये उत्साह का संचार हुआ। वहां भी अनेक ऐने धार्मिक नेना उत्पत्र हुए, जिन्होंने ईसाई धर्म के यहने हुए प्रचार को रोकन थे लिने दौड़ धर्म का प्रचार

आरम्भ किया। इसी का यह परिणाम हुआ, कि चीन में एक नये धार्मिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे पाश्चात्य इतिहास को दृष्टि में रखकर 'धार्मिक सूथारणा' के नाम से कहा जा सकता है।

जिस समय विविध वार्मिक नेता चीन में अपने-अपने धर्म के प्रचार में तत्पर थे, चीन की मुशिक्षिन जनता में धर्म के प्रति सन्देह और अविश्वास की भावना में भी निरन्नर बृद्धि हो रही थीं। आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले चीनी नवयुवक धर्ममात्र को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे थे। उन्हें जिस प्रकार चीन के प्राचीन धार्मिक विश्वास व विधि विधान अनावश्यक प्रतीत होने थे, वैसे ही ईसाई धर्म के मन्तव्यों में भी उन्हें कोई सार नजर नहीं आता था। इसका परिणाम यह हुआ, कि चीन में नास्तिकता की प्रवृत्तियां निरन्तर प्रबल होने लगीं, और बहुन से लोग धर्म से सर्वथा विमुख हो गये।

(५) कला और आमोद-प्रमोद

कला की दृष्टि में चीनी लोग बहुत उन्नत थे। चित्रकला और स्थापत्य— दोनों में चीन की अपनी पृथक शैली थी, जिसमें बाह्य आकृति की अपेक्षा भावना को अधिक महत्त्व दिया जाता था। चीनी लोग समझते थे, कि चित्र एक काव्य के समान होते हैं, जिनमें भावों की अभिव्यक्ति के लिये शब्दों का प्रयोग न कर आकृति को प्रयोग में लाया जाता है। पाश्चात्य कला के सम्पर्क में आने से चीनी कलाकारों ने चित्र की आकृति की उत्कृष्टता को भी महत्त्व देना शुरू किया। पर पाश्च त्य सम्पर्क के बावजूद भी चीन की कला की मौलिकता कायम रही। यही कारण है, कि चीन के चित्रों और प्रतिमाओं को पाश्चात्य देशों में आदर की दृष्टि से देखा जाता था और वहां के कला प्रेमी लोग उनके संग्रह में विशेष उत्साह प्रदिश्तत करते थे।

वीन में अमीद प्रमोद के प्रधान साधन नाटक होते थे, जिन्हें देखने के लिये चीनी लोग बड़े उत्साह के साथ एकत्र होते थे। पारचात्य देशों द्वारा वहां चल-चित्रों (सिनेमा) का प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ। शुरू में सिनेमा घर उन बन्दरगाहों में खोले गये, जहां विदेशी लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे। धीरे धीरे पेकिंग आदि अन्य नगरों में भी सिनेमा का प्रचार हुआ। शुरू में इन सिनेमा घरों में अमेरिका आदि में तैयार किये गये विदेशी भाषाओं के चित्र ही प्रदिश्तत किये जाते के भेरिका आदि में तैयार करने के लिये चीनी कम्पनियां भी स्थापित हुई और चीनी भाषा में भी चलचित्रों का निर्माण होने लगा। सिनेमा के प्रचार के कारण नाटकों की लोकप्रियता कम हो गई, पर इनसे यह लाभ

अवश्य हुआ कि जनता को कम मूल्य में मनोरंजन का एक अत्यन्त उत्कृष्ट नाधन हाथ लग गया।

पाश्चात्य लोगों के सम्पर्क से चीन के शिक्षणालयों में विविध प्रकार की खेल कूद का भी प्रवेश हुआ। पुराने ढंग के चीनी पण्डित शिक्षा में खेलों को जोई महत्त्व नहीं देते थे। पर बीसवीं सदी में चीन में जो नये शिक्षणालय खुल रहे थे, उनमें कसरत, ड़िल, जिमनास्टिक, टैनिस आदि को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता था।

पूर्वी एशिया में जापान के साम्राज्य का विकास

(१) जापान के उत्कर्ष का प्रारम्भ

उन्नीमवीं नदी के मध्य भाग में जापान का पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क न्यापित हुआ था । उस समय जापानी लोगों ने अनुभव किया, कि वे उन्नति की दौड़ में यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में बहुत पीछे रह गये हैं। इस अनुभृति के कारण जापान के लोग अपने देश का कायाकल्प करने के लिये किस प्रकार प्रवृत्त हुए, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है । १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद यह स्थित आ गई थी, कि जापान संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में से एक गिता जाने लगा था और उसकी जल सेना संसार में तीसरा स्थान रखती थी। केवल ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका ही ऐसे देश थे, जे जलसेना की दिष्ट में उससे आगे थे। राष्ट्रसंघ की कौंसिल में जापान को स्थिर सदस्य के रूप में अम्मिलित किया गया था और विश्व की राजनीति में जापान की अन्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जापान की स्थिति सबसे अधिक शक्तिशाली थी। इस दशा में यह सर्वथा स्थाभाविक था, कि जापान भी पाश्चात्य राज्यों के अनुसरण में साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रयत्नशील हो । संसार के आधुनिक इतिहास में राजशक्ति की अति शयता का यही परिणाम होता था, कि शक्तिशाली राज्य निर्वेल देशों को अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाने का प्रयतन करते थे। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली आदि सभी राज्य अपने अपने साम्राज्यों का विस्तार करने में नत्पर थे। इस दगा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि व्यावसायिक उन्नति और सैनिक शक्ति में पारचात्य देशों का समकक्ष बनकर जापान भी साम्राज्य विस्तार के मार्ग पर अग्रसर हो । जापान के साम्राज्य के लिये सबसे उपयुक्त क्षेत्र चीन और प्रशान्त महासागर में स्थित विविध द्वीप थे। इन्हें अपनी अधीनी में लाने के लिये जो प्रयत्न जापान ने किये, उन्हीं पर हम इस अव्याय में प्रकार डालेंगे । जापान का साम्राज्य प्रसार सम्बन्धी प्रयत्न १९३१ के बाद विशेष रूप से सफल होना गुरू हुआ । १९४२ तकु वह पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया

में अपने विशाल साम्राज्य के निर्माण में सफल हो गया। पर १९३९--४५ के महा्युड में मित्रराष्ट्रों की विजय के कारण जापान को अपने विस्तृत साम्राज्य के जत्थान और पतन का यह वृत्तान्त एशिया के आधुनिक इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। हम इस अध्याय में, १९३१ तक जापान ने जिस ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया. इस थियय पर प्रकाश डालेंगे।

साम्नाज्य विस्तार के हेतु—पाञ्चात्य देशों के समान जापान भी साम्राज्य प्रसार के कार्य में वयों तत्पर हुआ, इसके कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये कारण निम्नलिखित थे—

(१) जापान की आवादी में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी। १८७२ में जापान की कुल जनसंख्या ३,५०,००,००० थी। १८९४ में वह बढ़कर ४,१०, ००,००० हो गई थी। १९३० में जापान की जनसंख्या ६,९०,००,००० तक पहुंच गई थी। १८७२ से १९३० तक आधी सदी के काल में जापान की आबादी में शत प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जापान के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह इतनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी का भलीभांति पालन पोषण कर सके। इसके 🏂 उमें भी उसी ढंग से उपनिवेशों की आवश्यकता अनुभव होती थी, जैसे कि इस काल में पाश्चात्य देश अनुभव करते थे। ब्रिटेन का कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, न्युजीलैण्ड आदि पर आधिपत्य विद्यमान था। इन विशाल प्रदेशों की खाली पड़ी हुई जमीन पर ब्रिटिश लोग यथेष्ट रूप से अपनी वस्तियों का विकास कर सकते थे। भारत, बरमा, लंका आदि अधीनस्थ देशों में ब्रिटेन के सुशिक्षित लोगों के लिये उच्च राजकीय व सैनिक पद प्राप्त कर सकता बहुत सुगम था। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल भारत की अपेक्षा दुगुना था, पर उसकी जनसंख्या भारत के मुकाबले में एक तिहाई मे भी कम थी। इस दशा में अमेरिकन लोगों के छिये यह अत्यन्त सुगम था, कि वे प्रशान्त महासागर की ओर पश्चिम दिशा में अपना विस्तार कर सकें। रूस उत्तरी एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था, साइबीरिया का मुवितुस्त प्रदेश उसकी वस्तियों के लिये खुला पड़ा था । फांस उत्तरी अफीका पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित सह चुका था, वहां उसके लिये अपना विस्तार कर सकना वहुत सुगम था। पॉकैंबात्य संसार के प्रायः सभी प्रगतिशील देश अपनी बढ़ती हुई जनसंस्था के हित और कल्याण के लिये उपयुक्त क्षेत्र प्राप्त कर चुके थे। इस दशा गे जाणान नी अपनी जनसंख्या की वृद्धि से विवस होकर साम्राज्य-विस्तार के निवे उत्सुक था। (२) गृह में जापान के छोग संयुक्त राज्य अमेरिका में भाकर वन समते

थे। १९१० में ७२,००० के लगभग जापानी नागरिक अमेरिका में आबाद हो चुके थे। १९२० में अमेरिका प्रवासी जापानियों की संख्या ७२,००० से बढ़कर १,१०,००० हो गई थी। पर अमेरिकन लोग एशिया के लोगों रेंके अपने देश में नहीं बसने देना चाहते थे। वहां इस बात के लिये प्रवल आन्दोलन चल रहा था, कि एशियन लोगों के अमेरिका प्रवेश को कानून द्वारा रोका जाय। अमेरिका के खेनाग लोग एशिया के लोगों को अपने से हीन व निकृष्ट समझते थे। १९०६ में कैलिफोर्निया में एक कान्न बनाया गया, जिसके अनुसार जापानी विद्यार्थियों को अमेरिकन स्कुलों मे पढ़ने से रोक लिया गया । १९०७ में अमेरिकन सरकार ने यह व्यवस्था की, कि जापानी पुरुषों को अमेरिका में आने से रोका जाय । केवल उन विवाहित स्त्रियों को ही भविष्य में अमेरिका आने दिया जाय, जिनके पति पहले से वहां मौजूद है। १९१३ में कैलिफोर्निया की सरकार ने एक कानून बनाया, जिसके अनुसार तीन साल से अधिक काल के लिये किसी जमीन को जापानी लोग किराये व पट्टे पर न ले सकें, यह व्यवस्था की गई। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक कानुन अमेरिका के विविध राज्यों व संघ सरकार द्वारा वनाये गये । इसका परिणाम यह हुआ, कि जापान की वढ़ती हुई आबादी के लिये अमेरिका में आकर बस सकना असम्भव हो गया । इस दशा में जापाई के लिये यही मार्ग ज्ञेष रह गया, कि वह भी पाश्चात्य देशों का अनुसरण कर अपना ऐसा साम्राज्य बनावे, जहां उसकी बढती हुई आवादी के लिये बस सकना व आजीविका कमाना सम्भव हो जाय।

(३) पाश्चात्य देशों के ज्ञान विज्ञान को अविकल रूप से अपना लेने के कारण जापान में ज्यावसायिक उन्नित बड़ी तेजी के साथ हो रही थी। जापान की ज्यावसायिक कान्ति पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। वहां के कल कारखाने बहुत बड़ी मात्रा में सब प्रकार का तैयार माल उत्पन्न कर रहे थे। पाश्चात्य देशों के समान जापान भी इस बात के लिये उत्सुक था, कि उसका अपना साम्राज्य हो, जहां वह अपने तैयार माल को निश्चित्तता के साथ बेच सकने के लिये सुरक्षित बाजारों को प्राप्त कर सके और जहां से कच्चा माल सस्ती कीमत पर खरीद सकने की उसे पूर्ण रूप से सुविधा हो। साम्राज्य के अभाव में जापान के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह अपने कल कारखानों में तैयार हुए माल को विदेशों में निश्चित रूप से बेच सके। भारत, बरमा बादि के रूप में ब्रिटेन के ज्यावसाहित पतियों के पास जिस ढंग के बाजार थे, जापान भी अपने लिये उसी प्रकार के बाजारों को प्राप्त करना चाहता था। जापान की ज्यावसायिक पैदावार केवल अपने देश में नहीं खप सकती थी।

(४) जिस प्रकार जापान ने पाश्चात्य देशों से व्यावसायिक उत्पत्ति के बद्ध तरीकों को सीखा था, वैसे ही उसने इन देशों से राष्ट्रीयता का भी पाठ पढ़ा था । जापान एक राष्ट्र है, और उसकी सभ्यता व संस्कृति अन्य सवकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है, यह विचार उसमें निरन्तर प्रवल होता जाता था। जिन लोगों की जाति, भाषा, धर्म व परम्परा एक हो, वे अपना पृथक व स्वतन्त्र राज्य बनाकर रहें, वस्तुतः राष्ट्रीयता की भावना का यही अभिप्राय है। पर कठिनता यह है. कि मनुष्यों की अन्य भावनाओं के समान राष्ट्रीय भावना भी मर्यादा में नहीं रहने पाती । राष्ट्रीय गौरव विविध देशों को इस बात के लिये प्रेरित करता है, कि वे अन्य देशों को अपने अधीन कर अपनी राष्ट्रीय उन्नति में तत्पर हों। ब्रिटिश, फ्रेंडच. अमेरिकन-सभी पारुचात्य लोगों में यह विकृत रार्प्ट्रायता विद्यमान थी। जापानी लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। अपनी जातीय उल्क्रप्टता की अनुभृति जापानी लोगों में पहले भी मौजूद थी। वे अपने राजा को ईश्वर का वंशज मानते थे और यह समझते थे, कि जापान की संस्कृति संसार में सर्वोत्कृप्ट है। अब पारचात्य देशों के सम्पर्क में आकर उनमें यह भावना और भी अधिक प्रवल हो गई। 🌋 (५) विविध पाश्चात्य देश चीन और प्रशान्त महासागर के द्वीपों में अपने प्रभूत्व की स्थापना में तत्पर थे। रूस, ब्रिटेन, फांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, हालैण्ड आदि देश चीन में अपने प्रभावक्षेत्र कायम कर चुके थे। फ्रांस ने इण्डो-चायना में अपने उत्कर्ष का प्रारम्भ कर दिया था। रूस साइवीरिया को जीतकर उत्तरी चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये तत्पर था। हवाई द्वीपों पर १८९८ में अमेरिका का शासन स्थापित हो गया था, यद्यपि उनकी आबादी में जापानियों की संख्या सबसे अधिक थी। फिलीप्पीन द्वीप समृह पहले स्पेन के प्रभूत्व में था, पर उन्नीसवीं सदी के अन्त से पूर्व ही वह अमेरिका के प्रभूत्व में आ गया था। जब विविध पाश्चात्य देश जापान के पड़ोस के प्रदेशों में अपने आधिपत्य की स्थापना में तत्पर थे, तो जापान के लिये यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वह भी साम्राज्यवाद के क्षेत्र में उनका मुकाबला करने के लिये मैदान में उतर आये।

साम्राज्य विस्तार के लिये जो अनेक उद्योग जापान ने किये, उनमें से कितिपय कि उत्लेख इस पुस्तक में पहले किया जा चुका है। जिन प्रदेशों में जापान अपना अधिपत्य स्थापित करने के लिये तत्पर था, वे निम्नलिखित हैं—-(१) फार्म्सा, (२) कोरिया और (३) मञ्चूरिया। १९३१ तक जापान प्रधानतया इन्हीं को अपने प्रभुत्व में ला सका था। इनके सम्बन्ध में उत्लेख करना जापान के साम्राज्य विस्तार को समझने के लिये बहुत उपयोगी होगा।

(२) फार्म्सा पर प्रभुत्त्व

प्रारम्भिक विजय-सामन्त पद्धति और शैगून शासन का अन्त होने के बाद जब जापान में सम्राट की सत्ता का पुनरुद्धार हुआ, और जापान ने अपने साम्राज्य विस्तार का प्रारम्भ किया, तो सबसे पहले १८७५ में कुरील द्वीप समृह को वह अधीनता में लाया। ये द्वीप येजो से शुरू होकर उत्तर में कामचात्का तक विस्तृत हैं। इनकी प्राकृतिक दशा ऐसी नहीं है, कि इनमें मनुष्य अधिक संख्या में निवास कर सके। पर सैनिक दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व है। इन पर जिस किसी राज्य का प्रभुत्व होगा, वह साइवीरिया के समुद्रतट पर सुगमता से अपना आधिपत्य स्थापित कर सकेगा। उत्तरी प्रशान्त महासागर पर अपना कब्जा रखने के लिये इन द्वीपों का बहुत उपयोग है। १८७८ में बोनिन द्वीप समृह पर जापान ने अपना प्रभृत्व स्थापित किया । आर्थिक व व्यापारिक दृष्टि से ये द्वीप भी विशेष महत्त्व के नहीं है, पर यदि इन पर जापान के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य का कब्जा हो, तो वह इन्हें अपनी जलसेना का अब्डा बनाकर जापान के पूर्वी समुद्रतट पर सुगमता के साथ आक्रमण कर सकता है। कुरील और बोन्निक द्वीप समूहों का महत्त्व सैनिक दृष्टि से है, और इन्हें अपनी अधीनता में लाकेरें जापान ने अपनी स्थिति को बहुत सुरक्षित कर लिया था। १८८० के बाद जापान ने कोरिया में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया और १८९४-९५ में चीन के साथ उसका जो युद्ध प्रारम्भ हुआ, उसमें कोरिया को हस्तगत करने का प्रयत्न एक महत्त्वपूर्ण कारण था, यह हम पहले बता चुके हैं।

फार्म्सा पर आधिपत्य—१८९४-९५ के चीन जापान युद्ध के परिणाम स्वरूप फार्म्सा पर जापान का आधिपत्य स्थापित हुआ। चीनी और जापानी लोग इस द्वीप को तैवान कहते हैं। जापान के लिये फार्म्सा का अनेक दृष्टियों से महत्त्व या। वह यहां अपनी वस्तियों को बसा सकता था और इसे अपनी सैन्यशिक्त का आवार बनाकर उसके लिये यह भी सम्भव था, कि वह दक्षिणी चीन के फूक्लिएन प्रदेश पर अपने प्रभुत्व का विस्तार कर सके। जापान ने दोनों प्रकार से फार्म्सा का उपयोग किया। जापानी लोग अच्छी बड़ी संख्या में वहां जाकर आबाद हुए और उन्होंने फार्म्सा का आधिक विकास करने के लिये कोई क्यार उठा नहीं रावी। १९३० में फार्म्सा की कुल आवादी ४५ लाख के लगभग थी। इनमें से ३,००,००० व्यक्ति जापानी थे। ये वहां व्यवसायों का विकास करने व रेलवे आदि का निर्माण करने में तत्पर थे। फार्म्सा के बहुमंख्यक निरागी चीनी लोग थे, जो जापान की अधीनता में रहने हुए मुख्यत्या कृषि द्वारा अपना

निर्वाह बरते थे। जापानी छोगों ने फार्मूसा में जहां व्यवसायों का विकास किया, खुट्टां साथ ही सड़कें बनान, रेळवे छाइनों का निर्माण करने और बन्दरगाहों को विकसित करने गर भी ध्यान दिया। जापानी सरकार का यह भी प्रयत्न था, कि फार्मूसा के निवासियों को पूर्णतया जापानी रंग में रंग दिया जाय। इसके लिये उन्होंने शिक्षणालयों में जापानी भाषा की पढ़ाई को अनिर्वाय किया और सारा शासन कार्य जापानी भाषा में करने की व्यवस्था की । फार्मूसा के छोग जापान के शासन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अनेक बार विद्रोह किये, गर जापानी सरकार को इन विद्रोहों का दमन करने में विशेष कठिनता नहीं हुई।

(३) कोरिया

जापान ने किस प्रकार कोरिया में अपने प्रभूत्व को स्थापित किया, इसका वृत्तान्त पहले लिखा जा चुका है। १८९५ तक कोरिया चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था। १८९४-९५ के चीन-जापान युद्ध के बाद कोरिया से चीन के प्रभुत्व का अन्त हुआ और रूस और जापान उसे अपनी अधीनता में लाने के ्ख्यि संघर्ष में तत्पर हुए। १९०५ में रूस और जापान के युद्ध की समाप्ति पर कोरिया जापान का संरक्षित राज्य बन गया । वहां के शासन पर निरीक्षण रखने के लिये जापान की ओर से एक रेजिडेण्ट-जनरल की नियक्ति की गई। जिस प्रकार ब्रिटिश युग में भारत की देशी रियासतों में शासन का निरीक्षण व नियन्त्रण करने के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा 'रेजिडेन्टों' की नियक्ति की जाती थी, वैसे ही जापान ने कोरिया में अपने रेजिडेन्ट-जनरल की निय्वित की । कोरिया में प्रथम रेजिडेन्ट प्रिस इतों को नियक्त किया गया। इस समय से कोरिया में जापान का प्रभुत्व निरन्तर बढ़ने लगा । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आय व्यय आदि के महक्षमों में कोरियन अधिकारियों को 'परामर्श देने के लिये जापानी सलाहकार नियत किये गये। पोस्ट आफिस, टैलीग्राफ और टैलीफोन के विभाग का संचालन जापानी कर्मचारियों ने सीधा अपने हाथों में ले लिया । कोरिया के समुद्र तट पर मछली पकड़ने के व्यवसाय पर जापानियों ने अपने एकाधिकार को स्थापित किया । वहत सी उपजाऊ जमीनों को भी जापानी लोगों ने अपने अधिकार में अंग लिया और वहां अफीय की खेती जह की, क्योंकि इसकी मांग गीन और कं।रिया में बहत अधिक थी। कंरिया की उपनी मनकर दर्गनी निर्वेक और विकत थी, कि उसने किये यह सम्तर नहीं था. कि वह जापान के बढ़ते हुए प्रभाव व प्रधान का विरोध कर सके । ब्रिटेन और जागान इस समय परस्पर संनिध कर चुके थे। जांनी और रंस की बदती हुई शक्ति का मुकावला करने वे लिये

ब्रिटेन यह आवश्यक समझता था, कि जापान के साथ मैत्री सम्बन्ध की स्थापना करे। इसीलिये वह कोरिया के विषय में जापान की नीति का विरोध नहीं कूर सकता था । अमेरिका की सरकार जापान की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिन्तित थीं। उसे अनभव होता था, कि यदि जापान इसी प्रकार पूर्वी एशिया में प्रबल होता जायगा, तो फिलीप्पीन पर अमेरिका का प्रभूत्व निरापद नहीं रह सकेगा। इस दशा में अमेरिकन लोग चाहते थे, कि कोरिया में निरन्तर बढ़ते हुए जापानी प्रभुत्व का विरोध करें। १९०५ में कोरिया के सम्राट् ने अमेरिका के राष्ट्रपति की सेवा में एक आवेदनपत्र भेजा, जिसमें जापान से कोरिया की रक्षा करने की प्रार्थना की गई। १९०७ में कोरिया की सरकार ने हेग में होने वाल अन्तरिष्टीय सम्मेलन में अपने देश की समस्या को उपस्थित करने का प्रयत्न किया। इसका परिणाम यह हुआ, कि जापान ने कोरियन सम्राट को राजगद्दी का परित्याग कर देने के लिये विवश किया। यवराज को राजगही पर बिठाकर जापान के रैजि-डेन्ट जनरल प्रिस इतो ने कोरिया के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया । जागान के अनेक सैनिक नेता इस समय अपनी सरकार पर इस बात के लिये जोर दे रहे थे, कि कोरियन सरकार का अन्त कर इस देश पर पूर्ण रूप से जापानी। शासन की स्थापना कर दी जाय । पर जापानी सरकार सावधानी से चलने की नीति को पसन्द करती थी। इसी समय कोरिया के अनेक देशभक्त अमेरिका आदि विदेशी राज्यों की सहायता से निराश होकर आतंकवादी उपायों का अव-लम्बन कर रहे थे। कोरिया में अनेक ऐसी गुप्त समितियां कायम हो गई थीं, जिनके सदस्य जापानी अफसरीं पर आक्रमण करने में तत्पर थे। १९०९ में प्रिस इतो की हत्या हो गई। उसके समान अन्य भी अनेक उच्च जापानी कर्मचारी कोरियन कान्तिकारियों द्वारा कतल किये गये। इस दशा में जापानी सरकार ने कोरिया के राजवंश का अन्त कर इस देश को सीधे अपने शासन में ले लिया।

कोरिया पर जापान का शासन—कोरिया को पूर्ण रूप से अपनी अधीनता में ले आने के बाद जापान ने उसके शासन को सुज्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया। कोरियन लोगों की इतनी शिक्त नहीं थी, कि वे जापानी शासन के विरुद्ध विश्रोह का झंडा खड़ा कर सकते। पुलीस और सेना की सहायता से जापान ने कोरिया पर अपने प्रभुत्व को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। सब उच्च राज्यश्रिष्ठ पदों पर जापानी अफसर नियत किये गये और कोरिया में जापान ने प्रायः उसी हंग की सरकार का संगठन किया, जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में किया था। जापान के साथ सम्पर्क स्थापित होने के कारण कोरिया को आधुनिक रूप से उन्नत होने में सहायता मिली। वहां बहुत सी नई सड़कें बनाई गई, नई रेलवे

लाइनें निकाली गई, वन्दरगाहों को नये ढंग से बनाया गया और नये नये का कारखानों की स्थापना की गई। सिऊल आदि बड़े कोरियन नगरों में दिउनी की रोशनी का मुत्रपात जापान द्वारा ही हुआ। नये दंग के बेकी का जापानी सर-कार के संरक्षण में संगठन हुआ और व्यापार की जन्नति पर विशेष हुए में १६३ न दिया गया । कोरिया का विदेशी व्यापार प्रधान रूप में जापान के साथ होता था। १९२९ में तीस करोड़ येन (१ येन==१ शिलिंग व १२ आने के लगभर) का माल कोरिया से जापान गया था और लगभग इतने मृत्य का ही माल जापान से कोरिया आया था। इसी काल में कोरिया से तीन बरोड यंन का गाल चीन गया था और वहां से सात करोड़ येन का माल कोरिया आया था। अमेरिवा आदि अन्य राज्यों के साथ कोरिया के विदेशी व्यापार की सात्रा इससे भी कर थी। कोरिया के कुल विदेशी व्यापार का ९० प्रतिशत के लगभग भाग जापान के साथ था। विदेशी व्यापार के समान ही कोरिया के आन्तरिक व्यापार में भी जापान का प्रमुख स्थान था। बहुत से जापानी व्यापारी इस समय कोरिया में आकर बस गये थे, और उन्होंने वहां के न्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित अपर लिया था। कोरिया के व्यवसायों पर भी जापानियों का प्रभृत्व था। 'जापानी पुंजीपतियों ने कोरिया में अनेक वड़े बड़े कारखानों की स्थापना की थी। इनके मुख्य कर्मचारी जहां जापानी होते थे, वहां इनका मुनाफा भी जापान पहं-चता था । कोरिया के लोग निरन्तर अधिक अधिक दरित्र होने जाते थे । उनके लिये अपने देश में आजीविका कमा सकता कठिन होता जाना था। कोरिया की जनसंख्या भी इस समय निरन्तर बढ़ रही थी। १९११ में कोरिया की कुछ आबादी १,३०,००,००० थी। १९३५ में वह बढ़कर २,३०,००,००० हो गई थीं । इस स्थिति में यह स्वाभाविक था, कि बहुत से कोरियन लोग अन्य देशों में जा कर मजदूरी प्राप्त करने का यत्न करें; । यही कारण है, कि इस समय बहुत से कोरियन लोग मजदूरी की तलाश में जापान गये और वहां जापानी मजदूरों के मुकाबले में बहुत थोड़ी मजदूरी स्वीकार कर अपना निर्वाह करने को प्रवृत्त हए। जापानी सरकार ने कोरिया में कृषि और व्यवसाय का विकास इस हंग ' से नहीं किया था, कि कोरियन लोग वहां अच्छी आगदनी प्राप्त कर सकते। ्यापानी लोगों का उद्देश्य केवल यह था, कि जिस प्रकार में भी सम्भव हो, कोरियन लेगों का शोषण करें और उनकी दरबस्था से लाभ उठाकर स्वयं धन का उपार्जन वारें।

जापानी शासकों ने कोरिया में यह भी उद्योग किया, कि कोरियन लोगों को जापानी सम्यता और संस्कृतिके रंग में रंग लें। स्कूलों में जापानी भाषा का अध्ययन अनिवायं कर दिया गया। उच्च शिक्षा का माध्यम जापानी भाषा तो बनाया गया। कोरियन साहित्य के विकास में बाधाएं उपस्थित की गई कोरियन समाचार पत्नों पर कड़ा नियन्त्रण रखा गया। जागानी लोग नहीं चाहते थे, कि कोरिया में जिथा का प्रसार हो। इसीलियं जापानी जासन में केवल ४०० स्कूल वहां ऐसे खोले गये, जिनमें कोरियन विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इनके मुकावले में जापानी विद्यार्थियों के लिये स्थापित किये गये स्कूलों की संख्या ३८० थी। कोरिया की कुल आवादी में जापानियों की संख्या केवल हो भी सदी थी, पर इस दो भी, मदी जनता के लिये जहां ३८० स्कूल स्थापित किये गये थे, वहां शेष ९८ भी सदी कोरियन जनता के लिये केवल ४०० स्कूल खोले गये थे। इन स्कूलों में शिक्षा का ढंग इस प्रकार का रखा गया था, कि कोरियन विद्यार्थी जापान की उत्कृत्यता को मलीभांति ह्वयंगम कर लें, ताकि वे शिक्षा अपन कर चुकने पर जापान की भक्त प्रजा बन सकें।

यद्यपि कोरिया पर जापान का शासन अत्यन्त सुदृढ़ और कठोर था, पर वहां की जनता में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना का सर्वथा छोप नहीं हो गया था । अनेक कोरियन नवयुवकों ने पाश्चात्य देशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इनमें अपने देश को जापानी शासन से मुक्त कराने की इच्छा यहेतीय रूप से विद्यमान थी। कोरिया के निवासी अपने देश की दुर्दशा को अन्भव करते थे. और इस अवसर की प्रतीक्षा में थे, कि जापान के विरुद्ध विद्रोह करके राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना करें। १९१४-१८ के महायुद्ध क अवसर पर संसार के प्रायः सभी देशों में राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र शासन की प्रवित्तयों को बल मिला। १९१९ में जापानी शासन के विरुद्ध कोरिया में आन्दोलन बहुत प्रवल हो गया। जनता ने वहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का अवलम्बन कर जापान का विरोध करना शुरू किया। शंघाई में कृतिपय कोरियन देशभक्तों ने "स्वतन्त्र कोरियन सरकार" का संगठन किया और पेरिस सन्धि परिषद में एकत्रित राजनीतिज्ञों से अन्रोध किया, कि वे कोरियन देशभक्तों की मांग को स्वीकृत करें। पर १९१९-२० का यह कोरियन स्वातन्त्र्य आन्दोलन सफल नहीं हो सका। सन्धि परिषद ने 'स्वतन्त्र कोरियन सरकार' की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शंघाई की फेञ्च बस्ती भे इस कोरियन सरकार का प्रधान कार्यालय स्थापित था। फेञ्च अधिकारिया ने इस सरकार के खिलाफ कार्यवाही की और इसे भंग होने के लिये विवश होना पडा। राष्ट्रपति विल्सन (अमेरिका) और मित्र राष्ट्रोंके अन्य राजनीतिक नेता इस ममय संसारके सब देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र शासनकी स्थापना के

लिये प्रयत्न करने का दावा कर रहे थे, पर कोरिया की स्वतन्त्रता का उनकी दृष्टि में कोई भी मूल्य नहीं था। वे जापान को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर कित थे। कोरिया में जापानी सरकार ने देशभक्तों के साथ बहुत वृरा वर्ताव किया। स्वातन्त्र्य आन्दोलन को वृरी तरह में कुचला गया। बहुत में कोरियन देशभक्त गिरफ्तार किये गये, बहुतों को प्राणदण्ड दिया गया। इस स्थिति में बहुत में देशभक्त इस समय कोरिया छोड़कर अन्य देशों में चले गये और वहां जाकर उन्होंने अपने देश की स्वाधीनता के लिये प्रयत्न जारी रखा। जापानी शासन से मुक्ति पाने के लिये कोरियन लोगों ने जो प्रयत्न किया था, बहु असफल रहा। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस क्रान्तिकारी आन्दोलन के कारण जापानी सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिये विवश हुई। जापान ने यह यात स्वीकृत की. कि धीरे धीरे कोरिया में स्वराज्य की स्थापना की जायगी। इसी नीति को दिख्ट में रखकर इस समय कोरिया में स्थानीय स्वशासन का प्रारम्भ किया गया।

(४) मञ्चूरिया

क्स जापान युद्ध की समाप्ति पर जापान ने किस प्रकार मञ्जूरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस को पराजित करने के बाद जापान के लिये यह सम्भव हो गया था, कि वह मञ्जूरिया में अपने प्रभाव क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि करता जाय। १९०५ के बाद इस क्षेत्र में जापान की शक्ति का किस प्रकार उत्कर्ष हुआ, इसी वात पर अब हमें इस प्रकरण में प्रकाश डालना है।

कस जापान युद्ध के बाद १९०५ में पोर्ट् समाउथ की सिन्ध द्वारा मञ्चूरिया के सम्बन्ध में निम्निलिखित व्यवस्था की गई थी-(१) लिआओतुंग प्रायद्वीप में जो विशेषाधिकार पहले कस की प्राप्त थे, वे अब जापान को हस्तौन्तरित कर दिये जावें। (२) मञ्चूरियन रेलवे के दिक्षणी भाग पर जापान का अधिकार हो जाय। (३) सखालिन द्वीप का दिक्षणी भाग जापान को प्राप्त हो। (४) कस और जापान दोनों मञ्चूरिया से अपनी सेनाओं को हटालें, पर रेलवे के क्षेत्र की सुरक्षित रखने के लिये जिन सेनाओं को मञ्चूरिया में रखना आवश्यक ही, उन्हें वे वहां रख सकें। (५) कस और जापान मञ्चूरिया में अपनी रेलवे लाइनों का उपयोग केवल आधिक व क्यापारिक प्रयोजनों के लिये करें, राजनीतिक प्रयोजन के लिये नहीं। पर लिआओतुंग प्रायद्वीप में अपना राजनीतिक व सैनिक प्रभूत्व कायम रखने गा जापान को अधिकार हो।

पोट ममाउथ की मन्त्रि द्वारा जापान को यह अवसर मिल गया था, कि वह वहां अपने प्रभाव व प्रभाव का विस्तार कर सके। जापान द्वारा मञ्जूरियनु रेलवे का प्रवत्व करने के लिये 'दक्षिणी मञ्चिरियन रेलवे कम्पनी' का संगठने किया गया। पर यह कम्पनी केवल रेलवे की ही व्यवस्था नहीं करती थी। जिम प्रदेश में में रेलवे लाइन गुजरती थी, उसका शामन प्रवन्ध भी इस कम्पनी के अधीन था। उस प्रदेश में इस कम्पनी की तरफ से अस्पताल और स्कूल स्था-पित किये गये थे और खोज आदि के उद्देश्य में कतिपय संसथाएं भी कायम की गई थीं। इस प्रदेश के अनेक नगरों में विजलीका उत्पादन भी इसी कम्पनीके हाथ में था। इसकी और में अनेक होटल भी चलते थे और अनेक बन्दरगाहों का भी प्रवन्ध होता था । इतना ही नहीं, इस प्रदेश में खाने खोदने व उनका विकास करने का अधिकार भी इस कम्पनी को ही प्राप्त था। मञ्चूरिया के समृद्रतट पर जशज चलाने का काम भी यह रेलवे कम्पनी ही करती थी। यह दक्षिणी मञ्चरियन रेलवे कम्पनी जापानी नरकार की अधीनता व नियन्त्रण में थी, क्योंकि उसके सबसे अधिक हिस्से जापानी सरकार के पास थे। इस कम्पनी की स्थापना बीस करोड येन की पुजी से की गई थी, इनमें से दस करोड़ येन जापानी सरकार ने लगाये थे। बाद में इस कम्पनी की पूंजी बीस करोड़ से बढ़ा कर ैं चालीस करोड़ येन कर दी गई। प्जी के बढ़ जाने पर भी कम्पनी के आधे हिस्से जापानी सरकार के हाथ में रहे । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि दक्षिणी मञ्चिरियन रेलवे कम्पनी के रूप में वस्तृत: जापानी सरकार ही मञ्च्रिया के क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर शी।

इसमें मन्देह नहीं, कि मञ्च्रियन रेलवे कम्पनी द्वारा मञ्च्रिया के आधिक विकास में बहुन अधिक सहायता मिली। १८९८ में मञ्च्रिया के विदेशी व्यापार की मात्रा केवल ४,००,००,००० ताअल थी। १९०८ में यह बढ़कर १०,००,००,००० ताअल तक पहुंच गई थी। इसके बाद मञ्च्रिया के विदेशी व्यापार में और भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई। १९२० में उसके विदेशी व्यापार की मात्रा ५४,००,००,००० तक पहुंच गई थी। इससे स्पष्ट है, कि मञ्च्रिया पर जापानी प्रभाव स्थापित हो जाने के बाद उसके विदेशी व्यापार में बारह गुना में भी अधिक वृद्धि हुई थी। यह विदेशी व्यापार मुख्यतया जापान के साथ होता में भी अधिक वृद्धि हुई थी। यह विदेशी व्यापार मुख्यतया जापान के साथ होता मात्रा में मच्च्रिया से जापान जाते थे और जापान का तैयार व्यावसायिक माल वहां वहें परिमाण में विकी के लिये आता था। रेलवे लाइन के निर्माण के कारण अब यह वात बहुन सुगम हो गई थी, कि मञ्च्रिया में व्यापार का विकास हो सके।

बहत से चीनी किसान इस समय मञ्जूरिया में आकर आबाद हुए और उन्होंने पर्रती पड़ी हुई जमीनों को लहलहाते खेतों के रूप में परिवर्तित किया। जापान के बहुत में व्यापारी इस समय मञ्चूरिया गये । जिस समय अभी व्य-गापान के यद्भ का पूरी नरह से अन्त नहीं हुआ था, तभी जापानी व्यापारियों ने मञ्चिरिया में प्रवेश करना शृष कर दिया था। यद्यपि पोर्ट्ममाउथ की मन्धि हारा यह व्यवस्था की गई थी, कि सब देशों को मञ्चूरिया में व्यापार के मस्बन्ध में समात अधिकार प्राप्त रहे, पर रेलवे लाइन पर जापानी लोगों का कव्जा होने के कारण उनके लिये यह बहुत सुगम था, कि वे इस प्रदेश में व्यापार विश्वयक अनेक एंमी स्विधाएं प्राप्त कर सके, जो कि अन्य देशों के व्यापारियों को प्राप्त नहीं थीं। जापानी लोग मञ्चूरिया में केवल आर्थिक प्रभुत्व की स्थापना में ही तत्पर नहीं थे, वे अपने आधिक विशेपाधिकारों का प्रयोग कर यहा अपना राजनीतिक व सैनिक आधिपत्य कायम करने के लिये भी प्रयत्नशील थे। लिआऑतंग प्रायद्वीप में उनका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित था, उसे अपना आधार बनाकर जापानी लोगों के लिये यह अत्यन्त मूगम था, कि वे मञ्चुरिया के अन्य प्रदेशों को भी अपने राजनीतिक प्रभाव में लाते जावें। दक्षिणी मञ्चरियन रेलवे के क्षेत्र में जिपानी लोग अपनी सेनाओं को रख सकते थे। ये सेनाएं रेल्वे के क्षेत्र के बाहर भी जापानी शक्ति के विस्तार में सहायक हो सकती थीं।

व्यापार आदि के उद्देश्य से जो जापानी लोग बहुत बड़ी मंख्या में इस समय मञ्जूरिया के विविध प्रदेशों में बस रहे थे, वे अपने को चीनी कानून व चीनी अदालतों के अधीन नहीं समझते थे। वे दावा करते थे, कि 'ट्रीटी पोटों ' में निवास करनेवाले विदेशी नागरिकों के समान उन्हें भी 'एक्स्ट्रा-टैरिटोरियोलिटी के सब अधिकार प्राप्त हैं। जापानी सरकार भी यह समझती थी, कि अपने इन नागरिकों के जान और माल की रक्षा की उत्तरदायिता उसके ऊपर हैं। चीनी सरकार की निर्वलता से लाभ उठाकर जापान ने मञ्जूरिया के अनेक प्रदेशों में (जो कि रेलवे क्षेत्र के बाहर थे) अपनी पुलीस कायम कर दी थी। इस विदेशी पुलीस की सत्ता मञ्जूरिया की राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये अत्यन्त विधातक थी। पर चीनी सरकार जापान की इस बढ़ती हुई शक्ति के सम्मुख अपने को भूवैया असहाय अनुभव करती थी। १९१४ में प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ समय तक मञ्जूरिया पर जागान का प्रभाव व प्रभन्व 'प्रलीभानि स्थापिन हो गया था। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि हो सञ्जूरिया जब भी चीनी साम्राप्त के अनर्वन भा अधीर उसके शक्तियाली स्थिहसालार अपनी सैन्यादित की गहायना से पेकिंग सरकार पर अपना एनाव स्थापित करने में प्रयन्तिल की गहायना से पेकिंग सरकार पर अपना एनाव स्थापित करने में प्रयन्तिल की गहायना से पेकिंग सरकार पर अपना एनाव स्थापित करने में प्रयन्तिल की गहायना से पेकिंग सरकार पर अपना एनाव स्थापित करने में प्रयन्तिल की एनावन से पेकिंग

कि धीरे बीरे दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी मञ्चूरियापर जापान का प्रभाव बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था।

(५) महायुद्ध और जापान

शांतंग पर आधिपत्य--१९१४-१८ के महायुद्ध ने जापान की उन्नति व माम्राज्य विस्तार के लिये एक मूवर्णीय अवसर उपस्थित किया । इस महायद्ध के कारण पारचात्य देशों को पूर्वी एशिया के मामलों पर ध्यान देने की जरा भी फरसत नहीं थी। वे यरोप के घनघोर युद्ध में इतने अधिक व्यापत थे, कि चीन और जापान के मामले पर जरा भी ध्यान नहीं दे सकते थे। १९०२ में ब्रिटेन और जापान में जो सन्धि हुई थी, उसके कारण महायद्ध में जापान ने मित्र-राष्ट्रों का साथ दिया । १५ अगस्त, १९१४ को जापानी सरकार की ओर से एक नोटिस जर्मनी को दिया गया, जिसमें यह मांग की गई, कि शांत्ंग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे सब जापान को हस्तान्तरित कर बिये जावें, ताकि वह उन्हें चीनी सरकार को वापस कर देने की व्यवस्था कर सके। इस नोटिस का उत्तर देने के लिये एक सप्ताह की अवधि नियत की गई। जब २२ अ अगस्त तक जर्मन सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तो २३ अगस्त १९१४ को जापान ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। जापान की एक सेना ने जर्मनी के अधिकृत बन्दरंगाह दिसग ताओं पर आक्रमण किया। जापानी मेनाएं मीबा भी तिसग ताओ पर हमला कर मकती थीं, पर उन्होंने उससे १०० मील उत्तर की ओर एक स्थान पर पहले अपना कब्जा किया और वहां से स्थल मार्ग द्वारा दिसग ताओ की तरफ प्रस्थान किया । जर्मन सेनाएं जिस स्थान पर उतरी थीं, वह चीन के अधीन था और जिस मार्ग से वे त्सिंग ताओं की तरफ आगे बढ़ रही थीं, वह भी चीन के अन्तर्गत था। इस प्रदेश पर किसी भी विदेशी राज्य का प्रभाव-अत्र नहीं था। अतः जापाती सेनाओं की यह कार्रवाई अन्तर्राप्टीय. कानून के खिलाफ थी, क्योंकि चीन महायुद्ध में उदासीन नीति का अनुसरण कर रहा था। इस स्थिति में चीनी सरकार के सम्मख केवल एक ही मार्ग था, वह यह कि जापानी सेना के इस अभियान मार्ग ो 'यद का क्षेत्र' घोषित कर दे और दोनों पक्षों से यह आशा रखे, कि इस युद्धक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किली प्रदेश को वे सैनिक कार्रवाई के लिये इस्तेमाल न करें। पर जापानी सेनाओं ने चीन की इस घोषणा की कोई परवाह नहीं की । सैनिक आवश्यकता के नाम पर उन्होंने शांत्ंग प्रान्त की अन्दरूनी रेलवे पर भी अपना कब्जा कर लिया। यह रेलवे लाइन जर्मनी और चीन के संयुक्त कब्जे में थी, यद्यपि इस पर त्सिंग ताओ

की जर्मन सरकार का नियन्त्रण विद्यमान था । ७ नवम्बर, १९१४ को स्मिग नाओ पर जापानी सेनाओं का प्रभत्व स्थापित हो गया । ब्रिटिश सेनाओं की सहायता दैत आक्रमण में जापान को प्राप्त थी। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दिष्ट में जापान और ब्रिटेन को यह अधिकार नहीं था, कि वे चीन की उदासीन सना की उपेक्षा कर दिसग ताओ पर आक्रमण करें। पर उन्होंने चीन की उदासीन स्थिति की जरा भी परवाह नहीं की । वे केवल दिसग ताओ पर कब्जा करके ही मन्तृष्ट नहीं हए । कुछ ही समय बाद जापानी सेनाओं ने दिसग ताओं में आगे बढ़कर जातन में प्रवेश किया और इस प्रान्त में जर्मनी के जो भी विशेषाधिकार थे, उन सबको हस्तगत कर लिया। तिसग ताओ मे त्यिनान (शांत्ंग की राजधानी) तक जो रेलवे लाइन जाती थी, उस पर जापान ने अपना कटजा कर लिटा और रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा के नाम पर इस क्षेत्र में अपनी सेनाएं स्थापित कर दीं। यहां यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस रेलवे की रक्षा के लिये जर्मनी की कोई सेना इस क्षेत्र में नहीं रहती थी और रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा की उत्तरवायिता चीन की सरकार के ऊपर ही थी। शांतुंग में अपना सैनिक प्रभुत्व ्रस्थापित करके जापान ने इस प्रान्त में अपने राजनीतिक प्रभृत्व का भी विस्तार ಶ शुरू किया । १५ अगस्त, १९१४ के नोटिस में जापान ने इस बात को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया था, कि जर्मनी से इस प्रदेश के विशेषाधिकारों को लेकर वह उन्हें चीनी सरकार को वापस कर देने की व्यवस्था करेगा। पर अब जापानी सरकार का कहना था, कि जर्मनी ने अपने विशेषाधिकारों को स्वेच्छापूर्वक जापान को नहीं दे दिया है, उसके लिये जापान को अपने नागरिकों का खुन और प्रचुर युद्ध-सामग्री व्यय करनी पड़ी है। अतः उसका प्रतिशोध तभी सम्भव है, जब कि जर्मनी द्वारा अधिकृत इन प्रदेशों को जापान अपने हाथ में ले ले। इस प्रकार १९१४-१८ के महायुद्ध का सबसे प्रथम लाग जापान को यह प्राप्त हुआ, कि शांतुंग प्रान्त में उसका प्रभाव व प्रभुत्व स्थापित हो गया । कोरिया और मंचूरिया पर पहले ही उसका प्रभूत्व था, अब शांतुंग भी उसके साम्राज्यवाद का शिकार हो गया।

प्रशान्त महासागर के द्वीप-प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीपों पर जर्मनी क्षा प्रभुत्व था। इनमें से जो द्वीप भूमध्यसागर के उतर में स्थित थे, उन्हें जापान नि अपने कब्जे में कर लिया। इनमें मार्शल, कैरोलिन और मारिआना द्वीप-समूहों का उल्लेख विशेष रूप से महत्त्व का है। इन द्वीपों में जनसंख्या अधिक नहीं थी और नहीं आधिक दृष्टि से इनका विशेष उपयोग था। पर सैनिक दृष्टि से इनका महत्त्व बहुत अधिक था। यदि किसी अन्य राज्य का जंगी जहाजी

बहु दक्षिण की ओर से जापान पर आक्रमण करना चाहे, तो इन द्वीपों को दुल्ल के कप में प्रयुक्त किया जा सकता था। यदि जापान इन द्वीपों की किला करने कर ले, तो वह उनमें स्थित अपनी जलसेना द्वारा विदेशी आक्रमण का सुगमता मिनकावला कर संकता था। साथ ही जापान के लिये यह भी सम्भव था, कि वह इन द्वीपों को आधार बनाकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के विजय का उपक्रम कर सके। १९४० में जापान ने इन द्वीपों को इस उद्देश्य से प्रयोग किया भी था। इन द्वीपों को अधिकत कर लेने से प्रथानन महासागर में जापान की सैनिक स्थित बहुत सुदृढ़ हो गई थी। इसी प्रमंग में यह भी लिख देना उपयोगी है, कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में जर्मनी के अधीन जो द्वीप थे, उन पर इस समय ब्रिटेन ने अपना आधिपत्य न्यापित कर लिया था।

जापान की इक्कीस मांगें-शांत्ंग प्रान्त पर जापानी मेनाओं की स्थापना मे चीन की सरकार बहुत अधिक चिन्तित थी। ७ जनवरी, १९१५ को चीन के राष्ट्रपति श्री युआन शी काई ने जापानी सरकार को मूचना दी, कि क्योंकि महायुद्ध में चीन उदामीन है, अनः शांतुंग में भी उदासीन नीति को यरता जावेगा ्रीर केवल किआऊ चाऊ के प्रदेश का ही (जो कि जर्मनी के पास पट्टे पर था) ज्यान सैनिक दृष्टि से उपयोग कर सकेगा । इस बात से जापान बहुत ऋद्ध हुआ. 🏋 ांग उसने चीनी सरकार की सूचना दी, कि उसका यह कार्य जापान कं प्रति विरोध भावना को प्रकट करता है। अतः यह उचित है, कि चीन और जापान आपस में समझीता कर लें, और यह समझीता किन शर्ती पर हो, इसके न्यि जापान ने चीनी सरकार के सम्मुख २१ मांगें पेश की । इन मांगों का उन्लेख हम इस इतिहास के एक पहले अध्याय में कर चुके हैं। उन्हें यहां फिर से जिलने की आवष्यकता नहीं है । जापान की इन इक्कीस मांगों के परिणामस्वरूप २५ मई, १९१५ को चीन और जापान में एक नया समझौता हुआ, जिसकी म्ख्य दर्ने निम्नलिखित थीं-(१) मञ्चूरिया में लिआओ तुंग प्रायद्वीप पर जापान के पट्टे की अवधि को बढ़ाकर ९९ वर्ष कर दिया जाय। (२) दक्षिणी मञ्जूरियन रेजवे के पट्टे का काल भी बढ़ाकर ९९ वर्ष कर दिया जाय। (३) जापानी नागरिकों को अधिकार हो, कि वे दक्षिणी मञ्चूरिया में जहां चाहें यात्राकर सकें, वस सकें व्यापार व व्यवसाय का सञ्चालन कर सकें और निवास, व्यापार, व्यवसाय व्या गृती के लिये अमीन पट्टे पर ले सकें। (४) मङचूरिया में निवास करनेवालें ∰ जापानी लोगों के मामलों का फैसला जापानी अवालतों द्वारा किया जाय। (५) पूर्वी आभ्यन्तर मंगोलिया में भी जापानी लोगों को व्यापार के विस्तार का अवसर हो। (६) यदि चीनी सरकार को मञ्चिरया में सैनिक, आर्थिक व

पुलीन के मामलों के लिये किन्हीं विदेशी सलाहकारों के महयोग की आवश्यकता हो, तो ये मलाहकार जापानी ही नियत किये जावें। (७) शांतुंग में जापानी सैन्कार जर्मनी के साथ भविष्य में जो भी फैसला करे, वह चीनी मरकार को मान्य हो। (८) शांतुंग प्रान्त में किआऊ चाऊ के अतिरिक्त अन्यत्र भी जापानी लोगों को निवास और व्यापार का अधिकार दिया जाय।

१९१५ के इस समझौते द्वारा जापान के लिये चीन में अपने अधिकार व प्रभाव को विस्तृत कर सकना और अधिक सुगम हो गया। युआन भी काई ने विवश होकर ही जापान को अपने देश में ये सब सुविवाएं व विशेषाधिकार प्रदान किये थे। जापान ने उसे स्पष्ट रूप से यह बात सूचित कर दी थी, कि यदि चीन ने उसकी २१ मांगों के सम्बन्ध में समझौता न किया, तो वह शक्ति का प्रयोग करने में संकीच नहीं करेगा। यूरोप के महायुद्ध के कारण पाश्चात्य देशों को उस बात का अवकाश नहीं था, कि वे जापान की इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध कर सकते। चीन की शक्ति इतनी नहीं थी, कि वह अपने भरोसे पर जापान को नागाज कर सकता। परिणाम यह हुआ, कि १९१५ के बाद जापान चीन में अपनी शक्ति का निरन्तर विस्तार करता रहा।

१९१७ की गुप्त सन्धियाँ-पूरोपियन महायुद्ध में ब्रिटेन और फांस को बहुत मसीबत का सामना करना पड़ रहा था । जर्मनी की पनड्बियों के कारण मित्र-राज्दों के जहाज बड़ी तेजी के साथ समुद्र के गर्भ में पहुंचाये जा रहे थे। इस दशा में ब्रिटेन और फांस इस बात की आवश्यकता की अनुभव करते थे, कि जहाजों के सम्बन्ध में अपनी कमी को जापान की सहायता से पूरा किया जाय । १९१७ में इस में राज्यकान्ति हो गई थी। जार का पतन होने के बाद कस की नई सरकार यद्ध में शामिल रहने की अनावश्यक समझती थी। रूस के युद्ध से पृथक् हो जाने के कारण जर्मनी की सब सेनायें पश्चिमी रणक्षेत्र में चली आई थीं। इस कारण मित्रराष्ट्रों की स्थिति और भी अधिक डांबांडोल हो गई थी। इस स्थिति में फांस और ब्रिटेन ने जापान को इस बात के लिये प्रेरित किया, कि वह अपने जहाजी वेड़े को मित्रराष्ट्रों की सहायता के लिये भूमध्यसागर में भेज दे। पर इस सहा-यता के बदले में जापान ने पूरी कीमत वसूल की । उसने फांस और ब्रिटेन से एक गुप्त सन्धि (१९१७) की, जिसके अनुसार इन राज्यों ने यह स्वीकार किया कि युद्ध की समाप्ति पर जब सन्वि परिषद् होगी. नो उसमें ये राज्य आंतुंग प्रान्त में जापान के विशेषाविकारों का मार्थित करेंग । जापान के बहादी बेहे की सहायता के बदने में फिरसाप्ट्रों ने शांतुग प्रान्त की बिल चढ़ा दिया था। इन्ली ने भी कुछ रागन बाद जापान से एक गप्त रागझौता कर लिया था, जिसमें उसने शांतुंग प्रान्त पर जापान के विशेषाधिकारों के समर्थन का वचन दिया था। इन गुप्त संधियों द्वारा यूरोप के राज्यों ने इस बान को स्वीकार कर लिया था, कि चीन जापान के साम्राज्य विस्तार का उपयुक्त और न्याय्य क्षेत्र है।

लासिग-इन्नी समझौता-फांस, ब्रिटेन और इटली के साथ जापान की सिन्धि हो चुकी थी। अब केवल संयुक्तराज्य अमेरिका एक ऐसा देश रह गया था, जो चीन में जापान के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद का विरोध कर सकता था। १९१७ में अमेरिका भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया था। अतः अमेरिकत राजनीतिज्ञों ने भी यह आवश्यक समझा, कि वे जापान के साथ समझौता कर लें। नवम्बर १९१७ में यह समझौता हो गया, जिसपर अमेरिका की शोर जापान की ओरसे श्री लांसिंग ने और जापान की ओरसे श्री हशीने हस्ताक्षर किये थे। इसके अनुसार अमेरिकाने इसबात को स्वीकार कर लिया, कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जापान का चीन के साथ सिन्नकट सम्बन्ध है, और इसलिये चीन के मामले में जापान की विशेष दिलचस्पी सर्वथा उचित है। इस विशेष दिलचस्पी के कारण जापान को वहां कितपय विशेषाधिकार भी प्राप्त होने ही चाहियें। पर लांसिंग-इशी समझौते में यह बात स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की गई, कि चीन में जापान के ये विशेषाधिकार क्या रूप धारण करेंगे, और किस हद तक अमेरिका इन्हें स्वीकार में पर इसमें सन्देह नही, कि लांसिंग-इशी समझौते के कारण जापान के साम्राज्य विस्तार में अमेरिका भी बाथक नहीं रह गया।

साम्राज्य प्रसार के विफल प्रयत्न-महायुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर जापान ने चीन के शांतुंग प्रान्त और मञ्चूरिया में अपने प्रभुत्व व प्रभाव का किस प्रकार प्रसार किया, यह हमने ऊपर लिखा है। १९१७ में जब रूस में राज्यकान्ति हो गई, तो रूसी साम्राज्य के मुविस्तृत प्रदेशों में अव्यवस्था फैल गई। बोल्शेविक कान्तिकारियों और जारशाही के पक्षपातियों में घोर संघर्ष का प्रारम्भ हुआ। साइबीरिया और उत्तर-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में इस संघर्ष का प्रभाव अवश्यम्भावी था। जुलाई, १९१८ में एक श्वेत रूसी (बोल्शेविक कान्ति के विरोधी) सेनापति ने अपनी सेनाओं के साथ उत्तरी मञ्चूरिया में प्रवेश किया। इस प्रदेश पर रूस को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। जापान ने समझा, कि उत्तरी मञ्चूरिया को अपने कन्जे में ले आते ज्य यह सुवर्णीय अवसर है। इस आशंका से कि इस श्वेत रूसी सेनापित का पीकि करती हुई बोल्शेविक सेनाएं भी इस प्रदेश में घुस आवेंगी, जापानी सरकार ने अपनी एक शक्तिशाली सेना वहां भेज वी। अमेरिका की सरकार इस बात को नहीं सह सकी। अमेरिकन सरकार जापान की बढ़ती हुई शक्ति से अत्यधिक

चिन्तित थी । अमेरिका के हस्तक्षेप का यह परिणाम हुआ, कि जापान उत्तरी कुंच्चरिया को अपने कब्जे व प्रभाव में नहीं ला सका ।

रूस की अव्यवस्था के कारण पूर्वी साइबीरिया को भी अपने प्रभटव में लाने का उद्योग जापानी सरकार ने किया। आस्ट्रिया की सेना के बहुत से कैदी कर्मा सरकार के पास नजरबन्द थे। इन्हें साइबीरिया में रखा गया था। इन आस्ट्रियन सैनिकों में एक अच्छी बड़ी संख्या चेको-स्लोवाक लोगों की थी, जो आस्ट्रियन शासन के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये उत्सुक थे। चेकां-स्लोबाकिया का प्रदेश उस समय आस्ट्रियन साम्राज्य के अन्तर्गत था और उसके राष्ट्रवादी नेता महाय्द्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर अपने देश की स्वाधी-नता के लिये प्रयत्नशील थे। आस्ट्रियन सेना के चेकोस्लोवाक सैनिकों की सहा-नभति स्वाभाविक रूप से अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के पक्ष में थी । जब रूस में वोल्शेविक क्रान्ति के कारण अव्यवस्था और अराजकता फैल गई, तो इन चेकोस्लोवाक सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और जुन, १९१८ में ब्लादीबोस्तोक पर कब्जा कर लिया। इस स्थिति में मित्रराष्ट्रों ने यह आवश्यक समझा, कि इंग्रदीबोस्तोक को अपने अधिकार में ले आवें, ताकि जर्मन व बोल्शेविक सेनाएं विकोस्लोवाक सैनिकों से इस बन्दरगाह को न छीन सके। अमेरिका, ब्रिटेन और फांस की सेनाएं क्लादीबोस्तोक पहुंच गईं। जब यह समाचार जापान को मिला, तो उसने भी अपनी एक अच्छी बड़ी सेना वहां भंज दी। इस जापानी सेना के मैनिकों की संख्या ७२००० थी। इतनी बड़ी सेना को ब्लादीबोस्तोक भेजने का यही प्रयोजन था, कि जापान पूर्वी साइबीरिया पर अपने प्रभुत्व की स्थापना कर ले। पर इस प्रयत्न में भी अमेरिका ने उसका विरोध किया। पर साइबीरिया के क्षेत्र में जापान और अमेरिका को परस्पर संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि शीघ्र ही बोल्शेविक सेनाओं ने इस प्रदेश पर अपने आधिपत्य को स्थापित कर लिया और रूसी सोवियत संघ के अन्तर्गत साइवीरियन रिपब्लिक का संगठन कर लिया गया। उत्तरी मञ्जूरिया और पूर्वी साइबीरिया में जापान अपना प्रभूत्व नहीं स्थापित कर सका, पर महायुद्ध की परिस्थितियों से लाभ इठाकर वह अपने साम्राज्य विस्तार के लिये कितना अधिक प्रयत्नशील था, दैह इन दो घटनाओं से भलीभाति स्प्रष्ट हो जाता है।

पेरिस की शान्ति परिषद महायुद्ध की समाप्ति पर सन्धि की शर्ते तय करने के लिये पेरिस में शान्ति परिषद् का आयोजन किया गया। इस परिषद् में चीन के प्रतिनिधि ने मांग की, कि शांतुंग प्रान्त में जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त ये और जिन्हें युद्ध के समय जापान ने हस्तगत कर लिया था, वे अब चीन को

बारम मिल जावें। पर जापान के प्रतिनिधि का यह दावा था, कि पूर्वी एशिय से जमंन प्रभुत्व का अन्त करने के लिये जापान ने जो कुर्वीनियां की है, उनिष्टु प्रतिकल उमें यह मिलना चाहिये, कि शांतुंग प्रान्त में जापान के विशेपाधिकारों के स्वीकृत कर लिया जावे। साथ ही भूमध्यभागर के उत्तर में जो दीप जर्मन के कठजे में थे, उन पर भी जापान का प्रभुत्व स्वीकृत होना चाहिये। अमेरिक के राष्ट्रपति विल्मन जापान की इन दोनों मांगों के विरोध में थे। पर अन्य मित्र राष्ट्र जापान के पक्षपानी थे। इसके कारण को स्पष्ट करने की आवश्यकत नहीं है। फास, ब्रिटेन और इटली १९१७ में जापान के साथ गुष्त संनिध्यां कर चुके थे और उन्होंने जापान के दावे का समर्थन करने का बचन दिया हुआ था परिणाम यह हुआ, कि चीन के प्रतिनिधि को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं है नहीं। बर्मीय की सन्धि में गांतुंग प्रान्त पर जापान के विशेपाधिकार के स्विकृत किया गया और प्रणान्त महासागर के विविध दीप (जो पहले जर्मनी वे अर्थन के प्रतिनिधि ने वर्भीय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन के प्रतिनिधि ने वर्भीय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

वाशिगटन कान्फरेन्स—संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयत्न से १९२१—२२ में वाशिगटन में एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसके मृत्य विचारणीय प्रवन निम्नलिखित थे——(१) सैन्यशक्ति और विशेषतया जल मेना में कमी करना, ताकि विविध राज्य जिस ढंग से अपनी मैन्यशक्ति पर अमयोदिन कप से व्यर्च करने में तत्पर थे, उसमें कमी की जा सके। (२) पूर्वी एशिया के मम्बन्ध में विविध राज्यों और विशेषतया अमेरिका तथा जापान में जो विरोध था, उसे दूर करना।

वाणिगटन कान्फरेन्स के सम्बन्ध में हम पहले एक अध्याय में भी। विचार कर चुके हैं। उसके जिन निर्णयों का जापान के साथ सम्बन्ध था, वे निम्निलिखित है—

(१) जलनेना के सम्बन्ध में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फांस और इटली ने परस्पर मिलकर यह समझौता किया, कि इन राज्यों के जहाजों में ५, ५, ३, १७५ और १.७५ का अनुपात हो। इसका अभिप्राय यह है, कि यदि अमेरिका की जल सेना के जहाजों की मात्रा ५ हो, तो ब्रिटेन के जहाज ५, जापान के जल सेना के जहाजों की मात्रा ५ हो, तो ब्रिटेन के जहाज ५, जापान के लिखें कुल जहाजों के बोझ (टनेज) को आधार माना गया। संस्था के स्थान पर टनेज को अनुपात का आधार मानने के कारण यह व्यवस्था की गई, कि यदि अमेरिका को नेनी के जहाजों का जुल बोझ ५०,००,००० लाख टन हो, तो ब्रिटेन के कुल

जहाजों का टनेज भी ५०,००,००० टन हो । उस दशा में जापान के जहाज लोझ में ३०,००,००० टन हों और फांस व इटली के १७,५०,००० टन । नेदी के भैम्बन्ध में निश्चित किया गया यह अनुपात जापान के लिये अत्यन्त लाभदायक था। इसके कारण जापान के लिये यह तो सम्भव नहीं था, कि वह अमेरिका या त्रिटेन पर आक्रमण कर सके। इसकी उसे कोई उच्छा भी नहीं थीं। पर यदि अमेरिका और ब्रिटेन पूर्वी एशिया में जापान के बढ़ते हुए प्रभाव का मकाबला करने के लिये उस पर हमला करने का प्रयत्न करने, तो उनकी मिमलित शक्ति भी जापान को परास्त करने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती थी। जापान पर हमला करने के लिये अमेरिकन जलमेना हवाई द्वीप को आधार के नोर पर प्रयुक्त कर सकती थी और ब्रिटेन की जलसेना सिंगापुर को । पर हवाई और सिगापूर जापान से इतनो अधिक दूरी पर थे, कि उनकी विशाल नेवी भी उसे सुगगता से परास्त नहीं कर सकती थी । ५,५ और ३ के अनुपान को स्वीकार करते हए जापान ने इस बात पर जोर दिया, कि वह प्रशास महासागर में स्थित विविध द्वीपों (जो उसकी अधीनता में थे) में किलाबन्दी कर सके । हम पहले लिख चके हैं, कि क्रील, बोनिन, मरिआना, मार्झल आदि विविध द्वीप समुहों - अ जापान का प्रभुत्व था। ये विविध द्वीप समूह जापान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में इस हंग से फैले हए हैं, कि यदि इन्हें सैनिक दिष्ट से दुर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, तो इनमें स्थित जापानी जल सेना स्गमता के साथ शत्र राज्यों की जलसना का मुकाबला कर सकती है। अमेरिका और ब्रिटेन ने जापान की इस मांग को स्वीकृत नहीं किया । इस पर जापान ने यह मांग की, कि अमेरिका और ब्रिटेन भी अपने उन प्रदेशों व द्वीपों में किलावन्दी न कर सकें. जी प्रशान्त महासागर में स्थित हैं। जापान की यह मांग स्वीकृत कर ली गई और यह निश्चय किया गया कि अमेरिका फिलीप्पीन, गुआम और अल्युनियन द्वीपों में किलाबन्दी न कर सके । हवाई द्वीप में उसे किलाबन्दी करने का अधिकार दिया गया । बिटेन के हाथ में हांगकांग आदि जो विविध प्रदेश व द्वीप प्रशास्त-महासागर में थे, उनमें उसे किलाबन्दी करते का अधिकार नहीं मिला। सिगापूर में वह अपनी जलसेना का अड्डा बना सकता था । इस प्रकार हवाई और सिंगापूर ये दो ही ऐसे स्थान थे, जहां अमेरिका और ब्रिटेन अपनी जलशक्ति को केन्द्रित कर्ने सकते थे। पर ये स्थान जापान से इतनी अधिक दूरी पर है, कि इनको आधार बनाकर जापान को विजय कर सकता सम्भव नहीं था। रंग रियनि में ब्रिटेन और अमेरिका की निमालिय जलगनित (१०) के मुकाबल में आपान की जलश्वित (३) बहुत पर्याप्त थी। प्रशान्त महानागर के चिविय डीपो की किलाबन्दी करने का अधिकार जापान को नहीं दिया गया था, इस कारण जापान के लिये भी यह मुगम नहीं था, कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत आस्ट्रे-लिया, न्यूजीठण्ड आदि उपनिवेशों पर आक्रमण कर उन्हें अपनी अधीनता का सके।

- (२) जलसेना की मर्थादित करने के सम्बन्ध में जो समझौता अमेरिका, बिटन, जापान, फांस, और इटली के बीच में हुआ, उसकी अविध ३१ दिसम्बर, १९३६ नक नियत की गई। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई, कि इस तिथि से दो साल पूर्व यदि कोई एक राज्य भी इस समझौते का अन्त करने का नोटिस दे दे, तो यह समझौता ३१ दिसम्बर, १९३६ के बाद जारी नहीं रहेगा। २९ दिसम्बर १९३४ को जापान ने इस व्यवस्था का उपयोग कर वाश्चिगटन कान्फरेन्स के इस महत्त्वपूर्ण समझौते का अन्त कर देने का बाकायदा नोटिस दे दिया था और इसके परिणामस्वरूप १ जनवरी, १९३७ को इस समझौते का अन्त हो गया। १९३७ से जापान ने अपनी जलसेना की वृद्धि के लिये असाधारण रूप से उपकम प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटेन और अमेरिका भी इस क्षेत्र में जापान से पीछे नहीं रहे। वे भी अपनी जलसेना की वृद्धि के लिये तत्पर हो गये। १९३९ में वीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध के सूत्रपात में इन राज्यों की प्रतिस्पर्धा एक महत्त्व के कारण थी।
- (३) वाशिंगटन कान्फरेन्स ने चीन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की थी, उसका उल्लेख हम पहले एक अध्याय में विश्वद रूप से कर चुके हैं। उसे यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं हैं। यहां इतना लिख देना पर्याप्त होगा, कि इस व्यवस्था के कारण शांतुंग प्रान्त में चीन का प्रभुत्व पुनः स्थापित हुआ और महायुद्ध के अवसर पर इस क्षेत्र में जापान ने जो अनेक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे, उनका उसने बहुत अंशों में परित्याग कर दिया।
- (४) १९०२ में ब्रिटन और जापान में जो सन्धि हुई थी, उसके स्थान पर अब चार राज्यों की एक नई सन्धि हुई, जिस पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फांस ने हस्ताक्षर किये। इस सन्धि द्वारा इन चारों राज्यों ने यह निश्चय किया कि पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जो प्रदेश व द्वीप जिस किसी राज्य के हाथ में इस समय हैं, उन पर उन्हीं राज्यों का अधिकार स्वीकृत किया जायगा और यदि इन चारों राज्यों द्वारा अधिकृत प्रदेशों के सम्बन्ध में कोई विद्विद्ध किन्हीं दो राज्यों में उठ खड़ा हो, तो वे उसका फैसला राजनय (डिप्लोमेशी) द्वारा करने का प्रयत्न करेंगे। यदि राजनय द्वारा फैसला कर सकने में वे समर्थ न हों, तो वे चारों राज्यों की कान्फरेन्स बुलाकर उसमें इस विवाद का फैसला

करेगे । यह भी व्यवस्था की गई, कि यह मन्धि दस साल तक स्थिर रहेगी, और इस अवधि के समाप्त होने से पहले चारों राज्यों को हक होगा, कि वे बारह महीने की नोटिस देकर इस सन्धि का अन्त कर दें। किसी एक राज्य द्वारा दिया गया नोटिस भी सन्धि के अन्त के लिये पर्याप्त समझा जायेगा।

(५) पनडुब्बियों की संख्या को नियंत्रित करने और जहरीली गैसों के इस्तेमाल को रोकने के सम्बन्ध में भी वाशिगंटन कान्फरेन्स द्वारा अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई।

इसमें सन्देह नहीं, कि वाशिगटन कान्फरेन्स पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित रखने में बहुत अधिक सहायक हुई। इस क्षेत्र में अमेरिका और जापान के हित एक दूसरे के साथ टकराते थे। प्रशान्त महासागर के पूर्व में अमेरिका निथत है और पश्चिम में जापान। वीसवीं सदी के पूर्वाई में अमेरिका और जापान दोनों ही अत्यन्त प्रबल व शक्तिशाली राज्य वन गये थे। इस दशा में प्रशान्त महासागर के सम्बन्ध में इन दो शक्तिशाली राज्यों में परस्पर हित विरोध की उत्पत्ति अस्वाभाविक नहीं थी। पेरिसकी शान्ति परिषद् में अमेरिका और जापान का विरोध अनेक बार प्रकट हुआ था। इस दशा में वाशिगटन कान्फरेन्स के किंगेयों द्वारा इन राज्यों के विरोध के दूर होने में बहुत सहायता मिली।

(६) १९२२ से १९३१ तक जापान की विदेशी राजनीति

एशिया के आधुनिक इतिहास में सन् १९३१ से एक नये युग का प्रारम्भ होता है। इस साल जापान ने अपने साम्राज्य विस्तार की उस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया था, जिसके कारण सन् १९४२ तक उसने सम्पूर्ण पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। १८९४-९५ के चीन-जापान युद्ध के समय से जापान ने अपने साम्राज्य को विस्तृत करना शुरू किया था। १९२२ में वाशिगटन कान्फरेन्स के समय तक जापान अपने उद्देश्य में किस हद्द तक सफल हुआ था, इस विषय पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। अब हमें यह प्रदर्शित करना है, कि १९२२ में १९३१ तक साम्राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में जापान की क्या नीति रही।

्र १९१४-१८ के महायुद्ध द्वारा संसार में आधुनिक युग की नवीन प्रवृत्तियों क्यी बहुत बल मिला था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में जर्मनी के होहन्द्-सोलन, आस्ट्रिया-हंगरी के हास्सवुर्ग और रूस के रोमनोफ राजवंशों का अन्त हुआ। फांस के बूवों राजवंश के समान ये तीन भी यूरोप के अत्यन्त प्राचीन व प्रभावशाली राजवंश थे। साथ ही, इस समय यूरोप में अनेक नगे राज्यों

की स्थापना हुई, जिनका आधार राष्ट्रीयता का सिद्धान्त था । चेकोस्लोवाकिया, पाँठण्ड, युगोस्लाविया आदि के रूप में जो अनेक नये राज्य इस समय बने थे, वे राष्ट्रीयता की विजय के स्पष्ट प्रमाण थे। साथ ही जहां इन नये राज्यों में लोकतन्त्री रिपहिलकों की स्थापना हुई थी, बहां जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, हुम आदि प्राचीन राज्यों में भी लोकतन्त्र शासन का सुत्रपात हुआ था। राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र-बाद की यह लहर केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रही थी। भारत में इस समय असहयोग आन्दोलन ने ब्रिटिश शामन की स्थिति को वहत कुछ डांबाडोल कर दिया था। टकी में मुस्तफा कमालपाशा के नेतृत्व में मुलतान के शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना की गई थीं। चीन में विद्यार्थी आन्दोलन ने इतना प्रचण्ड रूप धारण कर लिया था, कि शंघाई आदि नगरों में विदेशी लोगों का जीवन मरक्षित नहीं रह गया था। महायुद्ध के बाद का काल साम्राज्य विस्तार के किये अनकुछ नहीं था । राष्ट्रपति विल्मन के नेतृत्व में राष्ट्रसंघ द्वारा जो नये आदर्श प्रतिपादित किये जा रहे थे, वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद को यहन महत्त्व देने थे। इस दशा में जापान जैसे माम्राज्यवादी देश के लिये भी यह सम्भव नहीं था, कि वह समय की प्रवृत्ति के विपरीत चीन में अपने प्रभूत का विस्तार करने के लिये प्रयत्नशील हो सके। वाशिगटन कान्फरेन्स में जापाध-ने जो शांतुंग प्रान्त में अपने विशेषाविकारों के परित्याग की वात को स्वीकार कर लिया था, उसमें समय का प्रभाव प्रधान कारण था। उसी कारण जापान ने १९२२ में बलादीबोस्तोक से अपनी सेनाओं की बापस हटाने की बात स्वीकार कर ली थी और उत्तरी मञ्चिरिया के मामले में भी उसने अमेरिका के साथ समझौता कर लिया था। चीन में विद्यार्थी आन्दोलन जिस प्रकार उग्र रूप घारण कर पहा था, जमें दृष्टि में रखते हुए जापान ने यह भलीभांति समझ लिया था, कि यह समय साम्राज्य-विस्तार के लिये अन्कूल नहीं है। जब कुओमिलांग दल की शक्ति चीन में बढ़नी शुरू हुई, तो जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का बड़ी प्रबलता के साथ सब्चार हुआ। चीन की यह राष्ट्रीयता विदेशियों के प्रति विद्वंप की भावना ने परिपूर्ण थी। इसीलिये जब कुओमिन्नांग दल की सेनाओं ने कैन्टन से उत्तर की तरफ बढ़ना शरू किया, तो उन्होंने विदेशी लोगों पर कई स्थानों पर आक्रमण किये । मार्च, १९२७ में अब चियांग काई जेक की सेनाएं नानिकंग 📐 प्रविष्ट हुई. नो उन्होंने जापानी दुताबास पर हमला किया और अनेक जापान नागरिक उनके कोध के शिकार बने । हैको आदि अन्य नगरों में भी जापानी व , अन्य विदेशियों पर इसी तरह के आक्रमण हुए । इस समय जो जापानी, ब्रिटिश, फीट्च बादि सरकारें चीन की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को कूचलने के लिये अपनी प्रबल

जस्त्र शक्ति का उपयोग नहीं कर सकीं, उमका मुख्य कारण यही था, कि इस भ्रम्य सर्वेत्र राष्ट्रीयना और लोकतन्त्रवाद का जोर था। बिदेशी लोग अनुसय क्रिते थे, कि चीनी राष्ट्रवादियों के बिलाफ उग्र उपायों के अवलम्बन का जह परिणाम होगा, कि संसार का लोकनन उनके बिलाफ हो जायगा। इसी बात का यह परिणाम था, कि कुओमिन्तांग सरकार अपने देश से विदेशियों के प्रभुत्व को दूर कर सकने में बहुत अंशों तक सफलता प्राप्त करने में समर्थ हुई थी।

पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि चीन से विदेशी प्रभाव व प्रभन्व का पूर्णतया अन्त हो गया था । विदेशी नागरिकों को एक्स्टा-टैरिटोरिएलिटी के अबि-कार अब भी प्राप्त थे। जापानी भी ब्रिटेन, फांस, अमेरिका आदि के समान इनका उपभोग करता था। कोरिया तो पूर्ण रूप से जापान के प्रभुत्व में या ही, मञ्चुरिया में भी वह अपने आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार करने में नत्पर था। मञ्जूरिया के सिपहसालार चांग त्सो-लिन के साथ जापानी सरकार का समझौता हुआ था । यह शक्तिशाली सिपहसालार जापानियों के आर्थिक प्रभत्व का विरोध नहीं करता था। साथ ही उसे इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं थी, कि नेलवे के क्षेत्र में जापानी लोग अपने राजनीतिक व सैनिक प्रभूत्व को भी कायम रखें। चौंग त्सो-लिन पेकिंग की केन्द्रीय सरकार के झगड़ों में इतना व्यग्र था, कि अपने प्रदेश में विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव की तरफ ध्यान देने की उसे फुरसत ही नहीं थी । पर जापानी लोग भलीभांति समझते थे, कि चांग त्सो-लिन जैसे शब्तिमाली सिपहसालार के रहते हुए मञ्जूरिया में उनका मार्ग सर्वया सुरक्षित नहीं रह सकता । जुन, १९२८ में जिस प्रकार बॉम्ब द्वारा अकस्मात् चांग त्सो-लिन का देहावसान हुआ था, उसे दृष्टि में रखकर अनेक ऐतिहासिकों का विचार है, कि उसकी मृत्य में जापानी लोगों का हाथ था । कुछ समय बाद ही (१९३१ में) जापानी लोगों ने मंच्रिया में अपने प्रभुत्व को पूर्ण रूप से स्थापित करने के प्रयत्न को प्रारम्भ कर दिया और उस प्रदेश में मञ्चकुओ नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की । मञ्चकुओ राज्य जापान की संरक्षा में कायम हुआ था, और चीन के साथ उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था।

पर इस प्रसंग में यह व्यान में रखना चाहिये, कि १९२२ से १९३१ तम जापान ने अपने साम्राज्य के प्रसार के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं, किया। इस समय जापान के आन्तरिक शासन में भी लोकतन्त्रधाद की प्रयूचि प्रवल हो रही थी और जनता पालियामें करी शायत की स्थापना में नन्पर थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि जापान साम्राज्य विस्तार के कार्य पर दिलेप स्थान न देसके।

जापान की प्रगति

(१) राजनीतिक इतिहास

१८९५ मे१९३० तक जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लियें जो प्रयत्न किये, उनका विवरण हम पिछले अध्यायों में दे चुके हैं। पर इस काल में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में जो उन्नति जापान ने की, उसका उल्लेख हमने अभी तक नहीं किया है। इस अध्याय में हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे।

जापान के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में जिस बात पर हमें विशेष ल्य से प्रकाश डालना है, वह यह है कि इस काल में जापान के शासन में लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का किस प्रकार प्रयोग किया गया, जिस प्रकार वहां राजनीतिक वर्ली का विकास हुआ और जापानी सरकार ने अपने देश की उन्नति के लिये किन उपायों को प्रयुक्त किया । शोग्न शासन का अन्त होने के बाद किस प्रकार जापान वं सम्राट् की सना की पुनः स्थापना हुई थी और किस प्रकार वहां संविधान का निर्माण होकर पार्लियामेन्ट द्वारा शासन का सूत्रपाल किया गया था, इस विषय पर पहले विचार किया जा चुका है। १८९५ से १९३० तक जहां जापान एक तरफ पाश्चात्य देशों के अनुसरण में पालियामेन्टरी शासन के विकास में नत्पर ,था, वहां उसने अपनी प्राचीन परम्पराओं का भी त्याग नहीं कर दिया था। सम्राट के प्रति देवी भावना व उसका असाबारण सम्मान अब भी जापानी जनता में विद्यमान था। पाश्चात्य देशों के सुधारवादी व क्रान्तिकारी विचारक जिस प्रकार अपने देशों के प्राचीन राजवंशों का मूलोच्छेद करके रिपब्लिक की स्थापना के लियं प्रयत्नशील थे, वैसा कोई यत्न जापान में नहीं हुआ । जापान ने पाश्चात्य देशों के ज्ञानिवज्ञान को पूर्ण रूप से अपनाया, अपनी सैनिक शक्ति की भी पार्नाहर राज्यों के समकक्ष कर लिया, पर उसने अपनी परम्परागत विशेषताओं का कार्यस् रखा। सम्राट् के प्रति भिक्त भी उसकी इन विशेषताओं में से एक थी। सम्राट् के प्रति भिवत की भावना के कारण जापानी लोगों ने शासनसूत्र का संचालन भी उसके हाथों में रखा हो, यह बात नहीं थी। यद्यपि शासन का सब

काम सम्राट् के नाम पर होता था, पर वहा स्वयं राज्य का मञ्चालन नहीं करता था। ज्यों ज्यों जापान में पालियामेन्ट की सक्ति बढ़ती गई, क्षिरकार पर राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रभाव बढ़ता गया। पर पालियामेन्ट की सक्ति के विकास में जापान में कम समय नहीं लगा। संविधान की स्थापना के साथ ही ऐसे मन्त्रिमण्डलों का निर्माण नहीं हो गया, जो कि पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी हों। क्योंकि संविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी हों। क्योंकि संविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी न होकर सम्राट् के प्रति उत्तरदायी होता था, अतः स्थापाविक रूप से राजदरवार में जिन लोगों का असर हो, वे मन्त्रिमण्डल के निर्माण में महत्त्वपूर्ण सिक्त रखते थे। यद्यपि शोगुन जासन के अन्त के बाद जापान में सामन्तपद्धित की भी समाप्ति कर दी गई थी, पर बड़े बड़े सामन्त राज्यों की स्थित अभी सर्वथा लुन्त नहीं हुई थी। सत्सुमा और चोत् जैमे सिक्तशाली कुलों के नेता राजदरवार में बहुत अधिक प्रभाव रखते थे और वे मन्त्रिमण्डल के निर्माण स्थित और पनन के मामलों में खुले रूप से हस्तक्षेप करते थे।

शक्तिशाली कुलों के अतिरिक्त स्थल और जल सेना के सेनापितयों का भी शासन में अतूल प्रभाव था। इसके दो कारण थे। १८८९ की एक राजाज्ञा के - अंकनसार युद्ध मन्त्री और जलसेनामन्त्री को यह अधिकार दिया गया था, कि वे सम्राट् से सीये मिल सकें। उनके लिये यह आवश्यक नही था, कि वे युद्ध व सेना सम्बन्धी मामलों पर पहले प्रधानमन्त्री के साथ परामर्श करें और फिर प्रधान-मन्त्री की मार्फत ही सम्राट से मिलकर राजकीय आदेश को प्राप्त करे। इस व्यवस्था के कारण युद्धमन्त्री और जलसेनामन्त्री को मन्त्रिमण्डल में ऐसी स्थिति प्राप्त थी. जिसके कारण वे अपने को प्रधानमन्त्री के अधीन न समझकर उसका समकक्ष मानते थे । १८९८ में एक अन्य राजाज्ञा प्रकाशित हुई, जिसके अनुसारयह क्यवस्था की गई, कि यद्धमन्त्री के पद पर केवल ऐसा ही व्यक्ति नियत किया जा सके, जो स्वयं उच्च सैनिक पद पर रह चुका हो । इसी प्रकार जलसेना मन्त्री भी ऐसा ही व्यक्ति नियत हो सके, जो जलसेना में उच्च पदाधिकारी रह चुका हो। क्योंकि युद्ध सचिव व जलसेना सचिव को कमशः स्थल और जलसेनाओं पर शासन करना होता था, और इन पदों पर उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती थी, ज़ो कि स्वयं उच्च सैनिक अफसर रहे हों, अतः स्वाभाविक रूप से इन मन्त्रियों की नियुक्ति के समय स्थल और जलसेना के उच्च पदाधिकारियों की सम्मति को महत्त्व दिया जाता था । यद्ध मन्त्री और जलसेना मन्त्री के पदों पर केवल ऐसे ही व्यक्ति नियत किये जाते थे, जिन्हें सैनिक अफसर चाहते हों और जिनसे सेना की उन्नति व हित का सम्पादन होने की आशा हो। १८९८ की इस राजाज्ञा का यह परिणाम हुआ, कि मन्त्रिमण्डल में सेना का प्रभाव बहुत बढ़ गया। ये मैंनिक मन्त्री सीचे सम्राट् से मिल सकते थे, अन्य मन्त्रियों की अपेक्षा किये बिन्तू सम्राट् की सहमिन से किसी भी निर्णय पर पहुंच सकते थे और इनके निर्णय गन्त्रिक सण्डल को स्त्रीकार करने पड़ते थे, चाहे वे उन्हें पसन्द न भी करते हों। इस दशा में जापान का मन्त्रिमण्डल उन अर्थों में लोकतन्त्र प्रभावों के अधीन नहीं था, जैसा कि आधीनक युग के लोकनन्त्र राज्यों में होता है।

पार्लियामेन्टरी शासन और राजनीतिक दलों का निर्माण-पुराने सामन्त कुल, सम्राट् की देवी सना और सैनिक नेताओं का महत्त्व--ये तीन तत्त्व ऐसे थे, जो जापान में लोकतन्त्र पालियामेन्टरी शासन के विकास में बाधक थे। पर इन तत्त्वों के बावजद भी जापान में ऐसे राजनीतिक दलों का विकास हो रहा था, जो पालियामेन्ट के जासन के पक्षपाती थे। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम इन राजनीतिक दलों, इनके द्वारा निर्मित मन्त्रिमण्डलों व लोकतन्त्र शासन के लिये किये गये प्रयत्नों पर संक्षिप्त रूप से भी प्रकाश डाल सकें। इस सम्बन्ध में जापान में जो प्रयत्न हुए, उनका निर्देश कर देना ही इस ग्रन्थ के लिये पर्याप्त होगा । जापान में राजनीतिक दलों का निर्माण १८८१ में ही प्रारम्भ हो गया था । जुरू में वहां जो दल मंगठित हुए, वे दो थे-जियुतो दल और कैशुन्तो दल । जियुनो दल का नेता काउण्ट इतागाकी था । यह दल उदार विचारों का पक्षपाती था। इसके विचार प्रायः वैसे ही थे, जैसे कि इस युग के पारचात्य दिशों के लिबरल दलों के थे। कैश्न्तो दल का नेता काउण्ट ओकुमा था। विचारों की दिष्टि से यह दल जिय्तो दल की अपेक्षा अधिक सनातनवादी (कन्जर्वेटिव) था । पर यह ध्यान में रजना चाहिये, कि इन दो दलों का संगठन विचारों व सिद्धान्तों के आधार पर उतना नहीं हुआ था, जितना कि प्रभायशाली व्यक्तियों के नेतृत्व के कारण। इतागाकी और ओकूमा जापान के अत्यन्त प्रभावशाली नेता थे, और इन्होंने अपने नेतरक में इन दो दलों का संगठन किया था। जियुतो और कैश्न्तो, दोनों दल ही यह चाहते थे, कि जापान में पूरानी सामन्तपद्धति का पूर्ण रूप से विनाश हो, जागीरदार कुलों की शक्ति का हास हो और प्रतिनिधिसत्तात्मक लोकतन्त्र शासन की स्थापना हो । विचार और कार्यक्रम में बहुत कम भेद होते हुए भी ये दोनों दल १८९८ तक पृथक रूप से कायम रहे । इसका कारण यही था, कि इतागाकी, और ओकुमा जैसे शक्तिशाली नेताओं के लिये एक साथ मिलकर कार्य कर सकन्ती स्गमं नहीं था।

संविधान की स्थापना—(१८८९) के बाद जापान में जो मन्त्रिमण्डल यामागाता (दिसम्बर, १८८९), मत्सुकाता (मई, १८९१) और इतो (अगस्त,

१८९२) के नेतृत्व में वने, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके है । जब १८९४ में चुक्त-जापान का युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो प्रिस इतो का मंत्रिमंडल विद्यमान था। इती ने यत्न किया, कि यद द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों को दिष्ट में रम्बकर विविध राज-नीतिक दल अपने मतभेदों की उपेक्षा कर दे और सब मिलकर युद्ध में महयोग दें। जापानी लोगों में देशभिक्त और राष्ट्रीयता के विचार कुट कर भरे हुए थे। परिणाम यह हुआ, कि चीन-जापान युद्ध (१८९४-९५) के अवसर पर सब राज-नीतिक दलों ने दिल खोलकर इतो की सहायता की । पर यद के ममाज हो जाने पर पालियामेन्ट में इतो का विरोध बहुत प्रबल हो गया। इस दशा में उने प्रधान-मन्त्री पद से त्यागपत्र देने के लिये विवश होना पड़ा । १८९६ के शरू में कैशिन्तों दल के नेता काउन्ट ओकुमा ने नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया। इस समय ओकुमा ने अपने दल के आकार को बहुत अधिक बढ़ा लिया था। कैशिलो दल के पूराने सदस्यों के अतिरिक्त कतिपय अन्य लोगों को अपने मार्थ मिलाकर उसने एक नये दल का संगठन किया था, जिसे शिम्पोतो दल (प्रगतिशील दल) कहते थे। इस नये दल का मुख्य कार्यक्रम यह था, कि मन्त्रिमण्डल पालियामेण्ट 🐧 प्रति उत्तरदायी हो। ओकुमा जापान में उसी ढंग का उत्तरदायी पालिया-र्यत्टरी शासन स्थापित करना चाहता था, जैमा कि ब्रिटेन में विद्यमान था । पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई । वह जिन लोगों के सहयोग से काम कर रहा था, उनमें वहत से व्यक्ति पूराने जागीरदार कुलों के साथ सम्बन्ध रखते थे । सत्युमा और चोश कुलों के सहयोग के विना ओकुमा के लिये सफल हो सकना सम्भव नहीं था और इन कुलों के लोग पालियामेन्टरी जासन के विकास में अपनी शक्ति का हास अनुभव करते थे। परिणाम यह हुआ, कि एक साल के बाद उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया ।

अय (१८९७) इतो एक बार फिर प्रधानमन्त्री पद पर अधिष्ठित हुआ। शिम्पोतो और जियुतो दोनों दल उसके विरोध में थे। इस समय जापान की पालियामेन्ट में एक नया दल संगठित हुआ, जिसे केन्सेईकाई (संविधानवादी) कहते थे। यह दल भी पालियामेन्टरी शासन का पक्षपाती था। केन्सेईकाई दल में जहां शिम्पोतो और जियुतो दल सम्मिलित थे, वहां अन्य भी अनेक व्यक्ति स्थिमिल हो गये थे, जो उत्तरदायी पालियामेन्टरी शासन के पक्षपाती थे। इतने लोगों के शामिल हो जाने के कारण केन्सेईकाई दल की शक्ति बहुत बढ़ गई थीं और प्रिन्स इतो के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह सरकार का संचालन कर सके। परिणान यह हुआ, कि विश्व होकर प्रिम इतो ने रहायान दे दिया। प्रिय इतो ने प्रधानमन्त्री पद से त्यानम्थ केत हए सम्भद को पर्यान के किया।

कि केन्सेईकाई दल के नेताओं को मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य सुपूर्व किया जाय। जापान के इतिहास में यह सर्वथा नई बात थी। संविधान के निर्माण में प्रिंड इतो का प्रमुख कर्त्रव था। जब उसने स्वयं केन्सईकाई दल के मन्त्रिमण्डल की सिफारिश की, तो इससे यही सूचित होता था, कि उसने उत्तरदायी पालियामेन्टरी शासन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि जापान की पालियामेन्ट में बहमत केन्मेईकाई दल का था, अतः यही उचित था, कि वही दल मन्त्रिमण्डल का भी निर्माण करे। १८९८ में इस दल ने अपना मन्त्रिमण्डल बनाया और उसमें ओकुमा और इतागाकी दोनों मन्त्री रूप से सम्मिलित हए। पर यह मन्त्रिमण्डल भी देर तक कायम नहीं रह सका । चार मास बाद ही इसे त्यागपत्र दे देने के लिये विवश होना पड़ा। इसका कारण यह था, कि केन्सेईकाई दल का निर्माण अनेक प्राने दलों (जियतो, शिम्पोतो आदि) के मिलने से हुआ था। मरकार के संचालन कार्य को हाथ में लेते हुए इन पुराने दलों के भेदभाव किर प्रकट होने लगे और उनके नेताओं के लिये माथ फिलकर कार्य कर सकना सम्भव नहीं रहा । काउन्ट ओकुमा ने इस दल से पृथक् होकर अपने पूराने शिम्पोती दल का पुनः संगठन किया । काउन्ट इतागाकी ने जियतो दल का पुनरुद्धार नहीं किया अपित् केल्मेईकाई दल में रहकर ही अपने अनुयायियों का संगठन कायम रखा। लांकतन्त्र मिद्धान्तों के अनुसार उत्तरदायी पार्लियामेन्टरी शासन की स्थापना का जो प्रथम प्रयत्न जापान में किया गया था, वह असफल हो गया।

अगला मन्त्रिमण्डल मार्किवस यामागाता के नेतृत्व में बना । इसे पुराने जागीरदार कुलों का सहयोग प्राप्त था, पर पालियामेन्ट का बहुमत इसके पक्ष में नहीं था । केन्सेईकाई दल इसका समर्थक था, पर पालियामेन्ट में इस दल का भी बहुमत नहीं था । १९०० में यामागाता को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पडा ।

अब प्रिस इतो ने एक बार फिर मिन्त्रमण्डल का निर्माण किया। इस बार उसने यह यत्न किया, कि पालियामेन्ट के बहुसंख्यक सदस्यों का सहयोग प्राप्त करें। उसने सैयुकाई नाम से एक नये दल का संगठन किया। केन्सईकाई दल (जो पुराने जियुतो दल का उत्तराधिकारी था) के लोग इसमें शामिल हो गये। प्रिस इतो के वैयिक्तक प्रभाव के कारण पालियामेन्ट के अन्य भी अनेक सद्ध्ये सैयुकाई दल में सम्मिलित हुए, और पालियामेन्ट के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर प्रिस इतो अपना मन्त्रिमण्डल बना सकने में समर्थ हुआ। पर इतो यह नहीं चाहता था, कि मन्त्रिमण्डल अपनी स्थिति के लिये पालियामेन्ट के बहुमत पर निर्मर करे। उसने घोषणा की, कि संविधान के अनुसार मन्त्रियों को नियुक्त

करना सम्राट् के हाथों में हैं, और मन्त्री लोग तब तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक कि सम्राट् उन्हें पदच्युन न करें। इस घोषणा का परिणाम यह हुआ, कि पार्कियामेन्ट में काउन्ट ओकुमा के किम्मोतों दल की क्षांकित बहुत वह गई। लोकतन्त्र शासन के पक्षपाती लोग सैयुकाई दल को छोड़कर शिम्मोतों दल में शामिल हो गये। इस स्थित में प्रिस इतो के लिये प्रधानमन्त्री पद पर कायम रह सकता सम्भव नहीं था। मई, १९०१ में उसने त्यागपत्र दे दिया।

अब बत्यूरा नामक सेनापित के नेतृत्व में नया मिन्त्रमण्डल वना। कत्यूरा मार्किस यामागाता का अनुयायी था और लोकतन्त्र जामन से उमे कोई प्रेम नहीं था। उसे स्वल ओर जलसेना की सहायता का पूरा भरोसा था, और इसीलिये उसने पार्लियामेन्ट के संगर्यन की विशेष चित्ता नहीं की। कत्यूरा न केवल एक योग्य सेनानी था, अपितु कुशल राजनीतिज्ञ भी था। १९०२ में जापान ने बिटेन के साथ जो सन्धि की थी, वह कत्यूरा के मन्त्रिमण्डल की ही इति थी। इसी के शासन काल में रूस-जापान युद्ध (१९०४-५) हुआ। युद्ध की आवश्यवता को दृष्टि में रखकर विविध राजनीतिक दलों ने मन्त्रिमण्डल की पूर्ण रूप से सहयोग दिया और यही कारण है, कि चत्यूरा मन्त्रिमण्डल अनेक वर्षों तक कायम रहा। रूस-जापान युद्ध में शुरू से ही जापानी सेनाओं को जो असाधारण सफलता प्राप्त हो रही थी, उसके कारण कत्यूरा मन्त्रिमण्डल जनता की दृष्टि में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य में तत्पर था। पालियामेन्ट के विविध दलों ने जो उसना विरोध नहीं किया, उसमें यह एक प्रधान कारण था।

रूस-जापान युद्ध की समाप्ति पर पोर्ट्समाउय में मन्धि परिपद् का अधि-वेशन हुआ था। पोर्ट्समाउय की मन्धि की शर्ते अनेक जापानी नेताओं की दृष्टि में सन्तोषजनक नहीं थी। विशेषतया रूस से हरजाना न लेकर कत्सूरा मन्त्रिमण्डल ने एक ऐसा कार्य किया था, जिससे जनता बहुत अमंतुष्ट थी। इस दशा में कत्सूरा मन्त्रिमण्डल का विरोध बहुत अविक बढ़ गया और दिसम्बर, १९०५ में उसने त्यागपत दे दिया।

अब नया मिश्रमण्डल बनाने का कार्य प्रिस सेओन्जी के मुपुर्द किया गया।
यह प्रिस इतो का अनुयायी था और इम समय सैयुकाई वल का नेतृत्व कर रहा
था। यद्यपि यह जापान के एक अत्यन्त उच्च कुछ (फूजीवारा) के साथ सम्बन्ध
रखता था, पर इसकी शिक्षा फांस में हुई थी और उस देश के लोकतंत्र विचारों के
साथ सम्पर्क में आने के कारण यह स्पर्ध भी लोकतन्त्रवात का पक्षपाती वन गया
था। कत्सूराका सम्बन्ध जापान के मेनिक कुलों के भाग था, और वह कोल नंत्रवात
का समर्थक नहीं था। इसके विपरीत प्रिस सेओन्जी का भीनिक कुलों के नाथ

कीई सम्बन्ध नहीं था और फांस के प्रभाव में रह चुकने के कारण वह लोकतन्त्र-बाद का प्रबल समर्थक था। दिसम्बर, १९०५ से १९१३ तक जापान का प्रधान के भून्यों पद कभी सिओन्जी के हाथों में रहा और कभी कत्सूरा के। आठ वर्ष के इस बाल में दो बार सिओन्जी प्रधानमन्त्री बना और दो बार कत्सूरा। इस काल के इन मन्त्रिमण्डली के सम्मुख मुख्य समस्या आर्थिक थी। रूस-जापान पृद्ध में जापान को बहुत अधिक रुपया खर्च करना पड़ा था। यदि पोर्ट् संमाज्य की मन्धिद्वारा रूस को हरजाना देन के लिये विवश किया जाता, तो आर्थिक समस्या हल हो सकनी थी। पर हरजाना न लेने के कारण जापानी सरकार के सम्मुख यही उपाय शेष था, कि टैक्मों को बढ़ाकर युद्ध की क्षति को पूरा किया जाय। खर्च में कभी इमलिये सम्भव नहीं थी. कि इस समय जापान अपनी जल और स्थल सेना पर अत्यधिक खर्च कर रहा था। वह साम्राज्यप्रसार के लिये तत्पर था, और इसमें सफलता नभी सम्भव थी, जब उसकी सैन्यशक्ति अजेय हो।

कत्सूरा के त्यागपत दे देने पर १९१३ में एड्मिरल यामामातो जापान का प्रधानसन्त्री बना । पर उसका मन्त्रिमण्डल भी देर तक स्थिर नहीं रह सका । अब नम्रा मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य काउन्ट ओकुमा के सुपूर्व किया गया । इस समय उसकी आयु ८० साल की थी । पर वह वैध शासन का प्रबल पक्षपाति था. ओर अपने मुदीर्व राजनीतिक जीवन में उसने कभी भी अपने राजनीतिक सिद्धान्तों में परिवर्तन नहीं किया था । सैयुकाई दल से उसे सहायता की आया नहीं थी । इस समय पालियामेन्ट में सैयुकाई दल का बहुमत था, अतः काउन्ट ओकुमा ने त्रिटिश पालियामेन्टरी शासन की पद्धति का अनुसरण कर पालियामेन्ट को भंग कर दिया और नये निविचन की व्यवस्था की । नई पालियामेन्ट में सैयुकाई दल का बहुमत शा । यह दल लोकतन्त्र पालियामेन्टरी शासन का पक्षपाती था, और ओकुमा को इसका पूर्ण सहयोग प्राप्त था ।

१९१४-१८ के महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय जापान में ओकुमा का मिन्त्रमण्डल विद्यमान था। उसी ने जर्मनों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और जर्मन मेनाओं की परास्त कर शांतुंग प्रान्त में अपने विशेषाधिकारों की स्थापना कर ली थी। जापान की जिन २१ मांगों का उल्लेख पहले किया जा चुका है, उन्हें भी चीनी सरकार के सम्मुख ओकुमा मिन्त्रमण्डल द्वारा ही पेश किया गया था। ओकुमा स्वयं साम्राज्यवादी नहीं था। महायुद्ध के सम्बन्ध में भी वह उदार नीवि का अनुसरण करना चाहता था। इसीलिये महायुद्ध में शामिल होने के समय उसने घोषणा की थी, कि जापान साम्राज्यवाद की नीवि का

अनुसरण न करके अन्य राज्यों के अधिकारों का सम्मान करेगा। पर जापान में ऐसे लोगों की कमी नहीं थीं, जो महायुद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में लान उठीकर साम्राज्य विस्तार के इच्छुक थे। १९१५ के अन्न तक ये लोग इनने अधिक प्रवल हो गये थे, कि ओकुमा को त्यागपत्र दे देने के लिये विवक्ष होना पड़ा।

अव नया मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य काउन्ट तेराउची के सुपूर्व किया गया।
यह यामागाता का अनुयायी था और कट्टर साम्राज्यवादी था। जापान के
सैनिक नेताओं का ममर्थन इसे प्राप्त था। महायुद्ध के अन्त तक तेराउची का
मन्त्रिमण्डल ही जापान में कायम रहा। क्योंकि पालियामेन्ट में केन्सईकाई दल
का बहुमत था और यह दल उदार विचारों व लोकतन्त्रवाद का समर्थक था, अतः
तेराउची ने इस पालियामेन्ट को भंग कर नये निर्वाचन की व्यवस्था की। युद्ध की परिस्थितियों के कारण जापान में सैनिक नेताओं का जोर था, अतः नयं
चुनाव में केन्सेईकाई दल को अधिक सफलता नहीं हो सकी। अब तेराउची के
लिये यह सर्वथा सुगम था, कि वह नव निर्वाचित पालियामेन्ट का सहयोग
भलीभांति प्राप्त कर सके।

महायुद्ध की समाप्ति के बाद संसार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति प्रवल हुँ । जापान भी इस नई लहर से अछूता नहीं वच सका । साथ ही इस समय सर्वत्र कीमतों बढ़ने लगीं । कीमतों में वृद्धि के कारण सर्वसाधारण जनता के लियं अपना निर्वाह कर सकना कठिन हो गया । मजदूरों में सर्वत्र असन्तोष बढ़ने लगा । जापान के व्यावसायिक केन्द्रों में भी मजदूरों द्वारा अनेक विद्रोह हुए । इस दगा में काउन्ट तेराउची का मन्त्रिमण्डल कायम नहीं रह सका । सितम्बर, १९१८ में उसने अपने पद का परित्याग कर दिया ।

काउन्ट तेराज्वी के बाद श्री हारा जापान के प्रधानमन्त्री बने । वे किसी जागीरदार कुल के व्यक्ति नहीं थे, न ही किसी सैनिक कुल के साथ उनका सम्बन्ध था । जापान में यह प्रथम अवसर था, जब कि मध्यश्रेणि का एक व्यक्ति प्रधानमन्त्री पद पर आधिष्ठित हुआ था । श्री हारा सैयुकाई दल के थे और प्रिस सिओन्जी के बाद इस दल के नेता बने थे । पुरानी परम्परा के अनुसार अब प्रिम सिओन्जी को प्रधानमन्त्री बनना चाहिये था, पर समय की गति को देखते हुए सिक्टिजी ने यही उचिन समझा था, कि नये मन्त्रिमण्डल को संगठित करने का कार्य श्री हारा के सुपुर्द किया जाय । हारा ने यह भार स्वीकृत करने हए उस उन को भलीभांति स्पष्ट कर दिया था, कि वे उत्तरदायी लोकतन्त्र जागन में विद्यास रखते हैं और मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हुए अपने राजनीतिक दल को पूर्ण रूप से महत्त्व देंगे । उन्होंने जो मन्त्रिमण्डल बनाया, उसमें दो के अति-

रिक्त अन्य सब मन्त्री सैयुवाई दल के ये और इन दो मन्त्रियों के विचार भी सैयुकाई दल के राजनीतिक सिद्धातों से मिलते जुलते थे। यह पहला अवसर जा,
जब ि जापान में ब्रिटेन के समान पार्टी गवर्नमेन्ट का निर्माण हुआ था। - कैंहें
बात समय की प्रवृत्ति के सर्वथा अनुकूल थी, क्योंकि इस समय संसार के सभी
देशों में लोकतन्त्रवाद जोर पकड़ रहा था। पालियामेन्ट में सैयुवाई दल का
बहुमत नहीं था, अतः हारा ने पालियामेन्ट को भंग कर नयं निर्वाचन की व्यवस्था
की। १९२० में जो नया नर्वाचन हुआ, उसमें सैयुवाई दल के उम्मीदिवार बहुसंख्या में निर्वाचित हुए। हारा के मन्त्रिमण्डल ने अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की,
जिनके कारण जापान में लोकतन्त्रवाद के विकास में सहायता मिली। उसने
मताधिकार को विस्तृत किया और कोरिया, फार्मूमा आदि अधिकृत प्रदेशों पर
शासन करने के लिये ऐसे व्यक्तियों को नियत किया, जो सैनिक कुलों के न होकर
लोकतन्त्रवाद के साथ सहानुभूति रखनेवाले थे। श्री० हारा इस समय जापान में
जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, उससे लोकतन्त्रवाद के विरोधी लोग उनसे
बहुन असंतुष्ट थे। परिणाम यह हुआ, कि नवम्बर, १९२१ में तोक्यों के रेलवे
स्टेशन पर उन पर हमला किया गया और वे कतल हो गये।

अब मैयुकाई दल का नेता काउन्ट ताकाहाशी को चुना गया। श्री० हर्षी हारा मंगित मिन्त्रमण्डल उनकी हत्या के बाद भी कायम रहा। अन्तर केवल इतना आया, कि प्रधानमन्त्री का पद ताकाहाशी ने ग्रहण कर लिया। इस समय वाशिंगटन में पूर्वी एशिया की विविध समस्याओं पर विचार करने के लिय कान्फरेन्स ही रही थी। उसमें जापान ने जिस उदार नीति का अनुसरण किया था, उसका प्रधान श्रेय श्री हारा और काउन्ट ताकाहाशी के मन्त्रिमण्डल को ही दिया जाना चाहिये। वाशिंगटन कान्फरेन्स में जापान ने किस प्रकार अपनी जलसेना को मर्यादित करने व शांतुंग प्रान्त में अपने विशेषाधिकारों को कम करने की बात को स्वीकार किया था, इस पर हम पहले विशव रूप से प्रकाश डाल चुके ही।

काउन्ट ताकाहाशी के नेतृत्व सैयुकाई दल की एकता कायम नहीं रह सकी। इसका परिणाम यह हुआ, कि सैयुहोन्तो नाम से एक नये दल का संगठन किया गया। इस दशा में काउन्ट ताकाहाशी ने त्यागपत्र दे दिया, और एडिकाल काली जापान के नये प्रधानमन्त्री बने। पर कालो का मन्त्रिमण्डल किसी विशिष्ट राजनीतिक दल की सहायता पर आश्रित नहीं था। यद्यपि सैयुहोन्तो दल का समर्थन उसे प्राप्त था, पर उसका निर्माण किसी एक दल के आधार पर नहीं किया गया था। २४ अगस्त, १९२३ को कालो की मृत्यु हो गई। अब एड्मिरल यामामोतो नये प्रवानम्न्त्री वने । इन्हीं के समय में जापान में वह भयंकर भू-चुक्क आया, जिसमें बहुत से समृद्ध नगर नष्ट हो गये और जापान का आधिक जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया।

मर्ड, १९२४ में पालियामेन्ट का नया निर्वाचन हुआ। इस निर्वाचन में कैन्सेईकाई दल के १५१, मैयुहोन्तो दलके ११६ और मैयुकाई दलके १०० उम्मी-दवार निर्वाचित हुए। १९२४ के इस निर्वाचन में उदार और लोकतन्त्र दलीं को असाधारण संकलता हुई थी। इसका कारण यह था, कि इस समय जापान में मताधिकार बहुत अधिक विस्तृत हो गया था और संसार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद का जोर था। अव नैन्सेईकाई दल के लिये यह सम्भव था, कि अन्य लोकतन्त्रवादी दलों के सहयोग से एक ऐसे मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सके, जो नई भावनाओं का पक्षपाती हो। अब काउन्ट कातो (एडिमरल कानो नहीं) के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डलका निर्माण हुआ,जिसे कैन्सेईकाई और सैयुकाई दलोंका समर्थन प्राप्त था। पर शीघ्र ही सैयुकाई दल काउन्ट कातो के मन्त्रिमण्डल का विरोधी हो गया और कातो ने कैन्सेईकाई दल व कतिपय स्वतन्त्र सदस्यों के समर्थन से एक ुत्वे मन्त्रिमण्डल (१९२५) का निर्माण किया । श्री कातो का यह मन्त्रिमण्डल १९२७ तक कायम रहा । इस समय कैन्सेईकाई दल के म्काबले में सैय्काई दल का जोर अधिक वढ गया और श्री कातो के त्यागपत्र दे देने पर वैरन तनका ने नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । बैरन तनका को सैयुकाई दल का समर्थन प्राप्त था। उसका मन्त्रिमण्डल १९२९ तक कायम रहा।

१९२७ में जापान में एक नये दल का संगठन हुआ, जिसका नाम मिन्सेइतो दल था। सैयुहोन्तो दल और कैन्सेईकाई दल ने साथ मिलकर इस नये मिन्सेइतो दल का संगठन किया था। १९३० के निर्वाचन में मिन्सेइतो दल के २७३ और सैयुकाई दल के १७४ उम्मीदवार पालियामेन्ट में निर्वाचित हुए। इसका परिणाम यह हुआ, कि बैरन तनका के मिन्समण्डल का पतन हो गया और श्री हामागृची के नेतृत्व में मिन्सेइतो दल के मिन्समण्डल का निर्माण हुआ। मिन्सेइतो दल का यह मिन्सिण हुआ। मिन्सेइतो दल का यह मिन्सिण हुआ। मिन्सेइतो दल का यह मिन्सिण हुआ। मिन्सेइतो दल का यह परिणाम वह समय मञ्चिरिया के क्षेत्र में जापान ने अपने साम्राज्यवाद का प्रसार प्रारम्भ कर दिया था। मिन्से की दल उदार और लोकतन्त्र विचारों का समर्थक था। वह साम्राज्यवाद की नीति के संचालन के लिये अधिक उपयुक्त नहीं था। परिणाम यह हुआ, कि जनता में उसके प्रति असन्तोप बढ़ गया और १९३१ का अन्त होने से पूर्व ही उसने त्यागपत्र दे दिया।

१९३२ में जापान की पालियामेन्ट का नया निर्वाचन हुआ । इसमें सैंगुकाई

दल के ३०४ और मिन्सेइतो दल के १८७ उम्मीदवार निर्वाचित हुए। निर्वाचन में पूर्व ही मिन्सेइतो दल के मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र दे देने पर श्री इनुकाई के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का मंगठन हो गया था। श्री० इनुकाई इस समय मैयुकाई दल के नेता थे। पालियामेन्ट में अपने दल का बहुमत होने के कारण ही इन्होंने १९३२ में नया निर्वाचन कराया था। कुछ समय बाद श्री इनुकाई की हत्या हो गई. और जनरल मैतो व जनरल अराकी के नेतृत्व में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ। जिस समय मञ्चूरिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये जापानी सरकार भगीरथ प्रयत्न में लगी थी, जनरल अराकी ही उसके कार्णश्रार थे।

१८९५ से १९३१ तक जापान का शासन किन किन मन्तिमण्डलों के हाय में रहा, इसका यहां हमने अत्यन्त संक्षिप्त क्प से उल्लेख किया है। जापान के इस काल के राजनीतिक इतिहास की ये ही उल्लेख योग्य घटनाएं है। इनसे निम्निलिन्त वातें भलीभांति स्पष्ट हो जाती हैं—(१) जापान धीरे धीरे लोकतन्त्र शासन के मार्ग पर अग्रसर हो रहा था। उसमें राजनीतिक दलों का भी संगठन जारी था। इन राजनीतिक दलों के सिद्धान्तों और आदर्शों में भेद था। शुरू में सेयुकाई दल उत्तर नीति और लोकतन्त्रवाद का समर्थक था, पर कैन्सेईकाई दल के मंगठन के कारण मैयुकाई दल आपेक्षिक दृष्टि से अनुदार व कज्ववेंटिव हो गया था। कैन्सेईकाई दल उपकी अपेक्षा लोकतन्त्रवाद में अधिक आगे बढ़ गया था। जापान के विविध राजनीतिक दलों का आधार जहां कितपय प्रभावशाली नेताओं को व्यक्तित्व था, वहां साथ ही उनके अपने सिद्धान्त व आदर्श भी थे, जिनको सम्मुख रनकर जापान में विविध उम्मीदवार अपने को पालियामेन्ट में निर्वाचित कराने का यत्न करते थे। (२) देशके शासन में पुराने जागीरदार कुलों व सैनिक नेताओं का बहुत महत्त्व था, पर वीसवीं सदी में इनकी अपेक्षा राजनीतिक नेताओं का महत्त्व अधिक बढ़ने लग गया था।

इन विविध मन्त्रिमण्डलों के शासन काल में जापान की जो आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति हुई, उस पर हम इसी अध्याय के अगले प्रकरणों में प्रकाश डालेंगे।

नये सम्राट्-जिस सम्राट् के समय में शोगुन शासन का अन्त होकर सम्राह्म की शक्ति की पुन: स्थापना हुई, उसका नाम मृत्सुहितो या मेइजी था। ४५ सार्छ के सुदीर्घ शासन के बाद १९१२ में सम्राट् मेइजी की मृत्यु हो गई। इसमें सन्देह नहीं, कि मेइजी के शासन काल में जापान ने असाधारण उन्नति की। १८६७ में जब मृत्सुहितो जापान के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, तो जापान की राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक दशा चीन के मुकाबले में किसी भी प्रकार अच्छी नहीं थी। पर उसकी मृत्यु से पूर्व जापान संसार के सबसे अधिक द्रावितशाली नेज्यों में गिना जाने लगा था। कोरिया और फोर्मूसा उसके अधीन हो चुके थे और मञ्चिरिया में उसका प्रभाव क्षेत्र कायम हो गया था। क्रम जैसे शिवनशाली पारचात्य राज्य को युद्ध में परास्त कर देने के कारण मारा संसार जापान का सिक्का मानने लग गया था। यही कारण है, कि १९१२ में जब सम्राट् मंदिजी की मृत्यु हुई, तो जापान में बहुत शोक मनाया गया। उसके स्मारक क्षप में नौक्यों के समीप एक विशाल मन्दिर का निर्माण किया गया।

सम्राट्मुत्सुहितो (मेइजी) के बादयोशीहितो जापान का सम्राट्वना। सम्राट्वना पर यह तैशो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्राट्तैशो की मानसिक देशा ठीक नहीं थी और इस कारण वह राज्य के भार को संभाल सकने में असमर्थ था। १९२६ में तैशो की मृत्यु हो गई और हिरोहितो सम्राट् शोवा के नाम में जापान के राज-सिहासन पर आरूढ़ हुआ। सम्राट्शोवा आधुनिक युग की प्रवृत्तियों में भर्ली-सुति परिचित था। वह पाश्चात्य देशों की यात्रा कर चुका था और यूरोप व अमेरिका की राजनीतिक देशा से भलीभांति परिचित था। इसीलिय उमके शासनकाल में सम्राट् और जनता में अधिक धनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुआ। उसकी साम्राज्ञी भी जनता के साथ सम्पर्क रखती थी और अनेक सावंजितक कार्यों में हाथ बटाती थी। यूरोप के अनेक राजाओं व राजनीतिक नेताओं के समान सम्राट्शोवा भी साम्राज्यवाद का कट्टर पक्षपाती था। यही कारण है, कि उसके शासनकाल में जापान अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील हुआ। शोवा के समय के युढ़ों का उल्लेख हम अगले अध्यायों में करेंगे।

(२) आर्थिक उन्नति

१८९५ से १९३१ तक का जापान का राजनीतिक इतिहास विशेष महत्त्व का नहीं हैं। इस काल में जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये जो प्रयत्न किया, एशिया व संसार के इतिहास में वही महत्त्व रखता है। पर इस सम्भूय आर्थिक क्षेत्र में जापान ने जो असाधारण जन्नति की, वह न केवल उसके अपने लिये अपितु सम्पूर्ण एशिया के लिये बहुत गौरव की बात थी। जापान की आर्थिक उन्नति का प्रारम्भ १८९५ से पहले ही हो चुका था। चीन जापान के युद्ध (१८९४-९५) से पहले ही जापान अपने व्यवसायों और व्यापार की उन्नति के लिये असाधारण रूप से प्रयत्नशील था। रेलवे लाइन और सड़कों का वहां पर्याप्त विस्तार हो गया था, नये ढंग के बैक भी वहां स्थापित हो गये थे, मुद्रापद्धित का आयुनिक ढंग से संगठन भी वहां कर लिया गया था, डाकघर टैलीग्राफ् व टैलीफोन का भी वहां विकास हो चुका था और विविध प्रकार के जहाज भी ख़िंही बनने शुरू हो गये थे। पर आर्थिक क्षेत्र में जापानने जो असावारण उपित वीसवी सदी में की, उसका वास्तिविक रूप से प्रारम्भ १८९५ के बाद में ही हुआ था। १९०३ के बाद जापान संभार के सबसे उसन व्यवसाय-प्रवान देशों में गिना जाने लगा और वहां ओसाका जैसे विशाल व्यावसायिक नगरों का विकास हुआ, जो बिटेन के विमंघम सद्श व्यावसायिक नगरों के समकक्ष थे।

विदेशी व्यापार—जापान की व्यावसायिक उन्नति का अनुमान उसके विदेशी व्यापार के विकास से भलीभांति किया जा सकता है। १८८५ में जापान के कुल विदेशी व्यापार का मूल्य ६,६५, ००,००० येन था। १९१८ तक यह बढ़ कर ४,००,००,००,००० येन तक पहुंच गया था। विदेशी व्यापार में प्रह असा-वारण उन्नति किस प्रकार हुई, यह निम्न तालिका द्वारा भलीभांति स्पष्ट की जा सकती है—

वर्ष	विदेशी व्यापार
१८८५	६,६५,००,००० येन
१८९४	२३,००,००,००० येन
१९०४	६९,०५,००,००० येन
6668	१,५८,७०,०००० येन
१९१८	४,००,००,००,००० येन

उपर जो अन दिये गये हैं, उन पर निसी टिप्पणी नी आवश्यकतान हीं है। १८८५ से १९१८ तन केवल ३४ साल के काल में जापान के विदेशी व्यापार में ६० गुना से भी अधिक वृद्धि हो गई थी। यह आश्चर्यजनक वृद्धि उस व्यावसायिक उन्नति का परिणाम थी, जो इस काल में जापान में बड़ी तेजी के साथ हो रही थी।

१८८५ से १८९४ तक जापान के विदेशी व्यापार में आयात माल की अपेक्षा निर्यात माल की मात्रा अधिक थी। इसका कारण यह था, कि इस समय जाजीत विदेशों से मर्शानरी, जहाज आदि अधिक परिमाण में नहीं खरीदता था। १८९५ से १९१३ तक जापान के निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मात्रा अधिक बढ़ गई, कारण यह कि इस समय जापान विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में मशीनरी

आदि के कय में तत्पर था । १९१४ में जब यूरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ, जापान में व्यावसायिक उन्नति यथेष्ठ परिमाण में हो चुकी थी । अब जापान की यह आव-्रीकता नहीं रही थी, कि वह अपनी मशीनरी, युद्ध सामग्री, जहाज आदि के लिये विदेशों पर निर्भर करें । ये सब वस्तुएं अब जापान में ही तैयार होने छग गई थी । महायुद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में जर्मनी, ब्रिटेन, फांस, आदि पाञ्चात्य देशों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे अपना नैयार माल एशिया के विभिन्न देशों में भेज सकें। इन देशों के वाजार जापानी माल का स्वागन करने के लिये तैयार थे। जापान ने इस दशा से पुरा पुरा लाभ उठाया। बहुत बड़े परिमाण में जापान का तैयार माल भारत, बरमा, इन्डोचायना आदि देशों में बिकने लगा आर इस कारण उसके निर्यात माल की मात्रा बहुत अधिक वढ़ गई। महायुद्ध के कारण जापान के व्यावसायिक उत्कर्प को बहुत सहायता मिली । यूरोपियन माल अब विदेशों में विकने के लिये नहीं जा सकता था, एशिया के बाजार कपड़ा, रेशम, मशीनरी आदि सब प्रकार के माल के लिये प्यासे हो रहे थे। जापान ने इस अवसर का अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिये उपयोग किया । महायुद्ध की समाप्ति तक एशिया के विविध बाजारों पर जापात अपना प्रभुत्व इतनी दृढ़ता से जमा चुका था, कि यूरोपियन देशों के लिये वहां उसका मुकाबला कर सकना सम्भव नहीं रहा था । १९२३ में जापान में भयंकर भूकाम आया। इस प्राकृतिक विपत्ति के कारण उसके व्यवसायों को भारी नुकसान पहुंचा । इसमे उसके विदेशी व्यापार को भी धक्का लगा और कुछ समय के लिये एक बार फिर जापान के निर्यात माल की मात्रा आयात माल की अपेक्षा कम हो गई, क्योंकि भूकम्प से हुई क्षति की पूर्ति के लिये उसे विदेशों से वहत बड़े परिमाण भें माल मंगाने की आवश्यकता हुई थी।

व्यावसायिक उन्निति के कारण धीरे घीरे जापान के विदेशी व्यापार के स्वरूप में भी अन्तर आना प्रारम्भ हुआ। उसके निर्यात माल में तैयार माल की और आयात माल में कच्चे माल की मात्रा निरन्तर बढ़ती गई।

व्यावसायिक उन्नित-१८९५ के बाद जापान की व्यावसायिक उन्नित कितनी तेजी के साथ हुई, इसे स्पष्ट करने के लिये उसके विदेशी व्यापार के अंक ही पर्याप्त के। पर इस सम्बन्ध में कितपय व्यवसायों का निदर्शन करना भी उन्योगी है। १९०५ में जापान के बस्त्र व्यावसायमें ७,१६,००० हाथ न नजनेवाली लाइगां और १९,०४० मशीन से जलने वाली खिंड्डयों की सना भी। १९१४ में मशीन की खड्डयों की संख्या १९,०४० से बढ़कर १,२३,००० हो गई और हाथ से चलनेवाली खिंडुडयों की संख्या ७,१६,००० से घटकर ४,००,००० रह गई। ९ साल के योड़े से समय में मजीन की खिड़्डियों की संख्या में छ: गुना की वृद्धि हो गई। १९१४ के बाद यह वृद्धि और भी तेजी से हुई। १९३१ तक यह दजा आ गई थीं, कि वस्त्र व्यवसाय के क्षेत्र में जापान का स्थान मंसार में तीसरे नक्षेत्र पर था। जापान में नैयार हुआ सूत और कपड़ा भारत और चीन के बाजारों में बहुत बड़े पिरमाण में विकता था। हाथ की खिड्डियों द्वारा भी जापान में जो कपड़ा तैयार होता था, विदेशों में उसकी बहुत मांग थीं, कारण यह कि कला की दृष्टि से यह कपड़ा अत्यन्त उत्कृष्ट होता था।

सूती बस्त्र के समान रेदामी कपड़े के व्यवसाय में भी जापान ने असाधारण उसित की थी। १९२८ में मंसार भर में जितना रेदाम तैयार होता था, उसका दो निहाई जापान में तैयार होता था। इस समय जो माल जापान में बाहर विदेशों में जाता था, रेदाम की मात्रा उसका ४० प्रतिशत थी। यह रेदाम प्रधानतया अमेरिका जाना था। रेदाम और सूती कपड़े के अतिरिक्त उनी बस्त्र भी अच्छी बड़ी मात्रा में जापान में तैयार होते थे। १९३१ के बाद जापान के उन के व्यवसाय में विशेष रूप में उन्नित हुई।

जापान की व्यावसायिक उन्नति का अन्दाज एक अन्यं प्रकार से भी किया जा सकता है। १९०५ में जापान में केवल ८३ जायन्ट स्टाक कम्पनियां विद्या मान थीं। इनमें कुल मिलाकर २०,००,००० येन पूंजी लगी हुई थी। १९१४ में जापान की जायन्ट कम्पनियों की संख्या बढ़कर १९८ पहुंच गई थी और उनमें लगी हुई पूंजी भी २०,००,००० से बढ़कर २,१०,००,००० तक पहुंच गई थी।

वस्त्र व्यवसाय के अतिरिक्त जहाज, दियासलाई, कागज, शराय, कृतिम लाद, लोहा आदि को तैयार करने के व्यवसाय भी इस काल में जापान में बहुत नेजी के साथ उन्नत हुए, और रेलवे के विस्तार से जापान की व्यावसायिक उन्नति में बहुत सहायता मिली। शुरू में रेलवे का व्यवसाय प्राइवेट कम्पिनयों के हाथ में था। १९०७ के बाद सरकार ने रेलवे को अपने स्वामित्व में लाना प्रारम्भ किया। गेलवे के समान जहाज का व्यवसाय भी जापान में बहुत उन्नति कर रहा था। १८९० तक समुद्र तट के साथ होने वाला सब व्यापार जापान के अपने जहाजों द्वारा होने लगा था। १८९० के बाद जापान में ऐसे जहाज भी बनने शुरू हुए, जो महासमुद्रों को पारकर विदेशों में माल को ले जाते थे। चीन और सम के साथ हुए युद्धों के समय से जापान के जहाज व्यवसाय ने और अधिक उन्निक्ति की। विशेषतया रूस के साथ हुए युद्ध के वाद (१९०५) जापान में अनेक ऐसी कम्पिनया स्थापित हुई, जिनके जहाज संसार के प्राय: सभी वन्दरगाहों में चक्कर लगाने लगे। अब तक पूर्वी एशिया का सब व्यापारी माल प्राय: अंग्रेजी जहाजों

द्वारा होया जाता था । १९०५ के बाद माल होने के व्यवसाय पर जायान का प्रभूत्व निरन्तर बढ़ता गया । १९१४-१८ के महायुद्ध द्वारा जागान की अपने र्जिंहाजों की उन्नति का सुवर्णीय अवसर हाथ लगा । इस समय यूरोप के जहाजो के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे एशिया में व्यापार के निमित्त आ जा सके जर्मनी की पनडुन्बियों द्वारा बिटेन और फांस के जहाज वड़ी संख्या में इदाये जा रहे थे। इस दशा में लाभ उठाकर जापान ने बड़ी तेजी के साथ नये जहाजी का निर्माण प्रारम्भ किया । मुसाफिरों को ले जानेवाले. माल ढोने वाले और यद्ध के काम आने वाले सब प्रकार के जहाज बहुत वड़ी संख्या में जापान में बनाय जाने ज्र हुए । १९२९ तक यह अवस्था आ गई थी, कि व्यापारिक जहाजों की दिटि से जापान का स्थान संसार में तीसरे नम्बर पर था। केवल मंगुवत राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ही ऐसे देश थे, जो इस क्षेत्र में उससे आगे वहें हुए थे । अब जापान के जहाज न केवल अपने देश के माल को ढोने के लिये प्रयुक्त होते थे, अपित अन्य देशों के माल को भी ढोते थे। जापानी जहाजों के अफसर, इन्जीनियर आदि भी अब पूर्ण रूप से जापानी लोग होने लगे थे। कोई ऐसा भी समय था, जब जापानी जहाजों के अफसर विदेशी लोग हुआ करते थे, यह वान भी अब लीग भेलने लग गये थे।

व्यावसायिक उन्नति के परिणाम-इसमें मन्देह नहीं, कि व्यावसायिक उन्नति द्वारा जापान के आधिक विकास में बहुत अधिक सहायता मिली। पर साथ ही इससे अनेक दुष्परिणाम भी उत्पन्न हुए । यूरोप में जब पहले पहल व्यावसायिक कास्ति हुई थी, तो वहां भी ये दुष्परिणाम उत्पन्न हुए थे। जापान में व्यावसायिक कान्ति के परिणामों का अत्यन्त संक्षिप्त रूप में इस प्रकार निदर्शन किया जा सकता है-(१) इससे आर्थिक उत्पत्ति में बहुत वृद्धि हुई। पहले के मुकाबले में माल अर्त्याधक परिमाण में तैयार होने लगा। इसी से उसके विदेशी व्यापार में जना-भारण रूप से वृद्धि हुई। (२) गृह व्यवसायों का अन्त होकर विशालकाय कारख़ानों का प्रारम्भ हुआ । पुराने समय का जापानी कारीगर अपने घर पर रह कर आधिक उत्पादन करता था। घर पर ही उसका छोटा सा कारवाना होता था, जिसमें वह अपनी स्त्री, बच्चों तथा अन्य अन्तेवासियों (शागिरों) के सुक मिलकर आर्थिक उत्पत्ति करता था। उसके काम करने के कोई घंटे नियत नहीं होते थे। वह जब चाहता और जितने समय तक चाहना काम करता था। पर व्यावसायिक क्रान्ति के कारण गृह व्यवसायों का स्थान वे फैक्टरियां व मिलें लेने लगीं, जिनमें श्रमी व कारीगर की अपेक्षा मगीनों का महत्व अधिक था। कारीगर अब स्वतन्त्र उत्पादक न रहकर मृति प्राप्त करनेवाला मजदूर बन गया।

(३) आधिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूंजीपितयों का महत्व वढ़ने लगा। (४) विशाल व्यावसायिक नगरों का विकास हुआ, जिनमें देहातों से हजारों पूरुप, स्की, व वच्चे मजदूरी प्राप्त करने के लिये एकत होने लगे। इन नगरों में मजदूरी के निवास की सम्चित व्यवस्था नहीं थी। जिन मकानों में मजदूर लोग निवास के लिये विवज होते थे, वे मन्ष्यों के रहने के लिये उपयुक्त नहीं थे। (५) पारिवारिक जीवन पर व्यायमायिक उन्नति ने बहुत बुरा असर डाला। मजदूरों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे शहर में परिवार के निवास योग्य स्थान को प्राप्त कर सकें। एक एक कोठरी में वहुत से मजदूर एक साथ निवास के लिये विवश होते थे । उनके लिये अपनी स्त्रियों व बच्चों को साथ रख सकता कठिन था। परिणाम यह हुआ, कि पारिवारिक जीवन का मुख व शान्ति नष्ट होने लंगी। साथ ही आजीविका की तलाश में बहुत सी स्त्रियों व बच्चों ने भी कारलानों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। मशीनों से चलने वाले कारलानों में काम करने के लिये शारीरिक बल व शिल्प नैपुण्य की विशेष आवश्यकता नहीं थीं । उनमें स्त्रिया व बच्चे भी सुगमता से काम कर सकते थे । पूंजीपतियों को इन्हें मजदूरी पर रजना लाभदाधक प्रतीत होता था, क्योंकि इनकी मजदूरी की दर कम होती थी। कारखानों में काम करने के कारण स्त्रियों और बच्चों की स्वास्थ्य पर ब्रा असर पड़ता था। (६) व्यावसायिक उन्नति के कारण जापान में एक नवे श्रेणीनेद का विकास शुरू हुआ। मजदूरों में अपनी प्यक सत्ता व अपने अधिकारों की भावना उत्पन्न हुई और वे प्ंजीपतियों से सैंघर्ष के लिये तत्पर होने लगे। (७) स्त्रियों की दशा पर व्यावसायिक कान्ति ने वहन बरा असर डाला। स्त्रियों की मजदूरी की दर कम थी, इसलिये पंजीपितयों ने कारलानों में काम करने के लिये स्वियों व लड़िक्यों को बहुत बढ़ी संख्या में भरती किया । जापान के कारखानों में कुछ मिलाकर जितने लोग मजदूरी करते थे, उनमें स्त्रियों की संख्या ६० प्रतिशत थी। वस्त्र व्यवसाय में तो स्त्री मजदूर और भी अधिक थे, उनकी संख्या ८० प्रतिशत के लग-भग थी। कारखानों में काम करने वाले वच्चों में भी लड़िकयां ८० प्रतिशत थीं। इन लडिक वों को देहातों से भरती किया जाता था। मां वाप परिवार की गरीबी को दृष्टि में रखकर खुशी से लड़कियों को शहरों के कारखानों में काम करते के लियें भेज देते थे। कारखानों की ओर से इन लड़िकयों के रहने के लिये लिया लम्बी बैरकों बनी होती थीं। इन्हें विश्वाम करने के लिये एक-एक चटाई दे दी जाती थी, जिन पर लड़िकयां अपना विस्तरा विछाकर सो जाती थीं। उनके रहने की परिस्थितियां इतनी दयनीय थीं, कि उनके लिये अपना किसी भी

प्रकार का विकास कर सकता सम्भव नहीं था। कारखानों में बारह बण्टे के लगभग मजदूरी करने के बाद ये उतना थक जातीं थीं, कि अपनी थकान को सिटान के लिये शराब, जूआ या लैंगिक मुख का आश्रय ठेती थीं। इसका गरिणाम यह होता था, कि जापान की मजदूर स्त्रियों में नैतिक पतन बड़ी तेजी से हो रहा था। ब्याबसायिक कान्ति ने जापान में जो अनेक दुष्परिणाम उत्पन्न थिये. उनमें स्त्रियों व सुकुमार बाल्ठिकाओं का नैतिक पतन सबसे अधिक बुरा था।

मजदूरों की दशा में सुधार का प्रयत्न-जापान में ज्यावसायिक उन्नित इतनी अधिक तेजी के साथ हुई, कि वहां के राजनीतिक नेता व विचारक मजदूरों की दुईशा पर तुरन्त ध्यान नहीं दे सके । इन्नुलैण्ड, फांस आदि पाश्चान्य देशों में भी व्यावसायिक कान्ति ने इसी प्रकार के दुध्परिणाम उत्पन्न किये थे । वहां भी तीन चौथाई सदी के लगभग समय तक सरकारों का ध्यान सजदूरों की दुईशा के प्रति आकृष्ट नहीं हुआ था । जब विविध सुधारकों के प्रयत्न से सरकारों ने एसे कानूनों का निर्माण शुरू किया, जिनका उद्देश्य काण्यानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा को सुधारना था, तो पूंजीपतियों की ओर से उनका घोर विरोध हुआ । बहुत से विचारकों ने भी उनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। है स दशा में यदि जापान में भी मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये कानून यनाने में समय लगा हो, तो इसमें आक्चर्य की कोई बात नहीं है।

इस सम्बन्ध में जापान में सबसे पहले १९११ में कानून बनाया गया।
यह कानून उन कारखानों के लिये बनाया गया था, जिनमें कम से कम १५ मजदूर
काम करते थे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि बारह साल से कम
आयु की बालिकाएं व बालक कारखानों में काम न कर सकें, और स्त्रियों व १५
साल से कम आयु के वालकों के लिये काम करने का अधिकनम समय १२
वण्टे प्रति दिन हो। पर इन नियमों के अनेक अपनाद भी रखे गये थे। १९२३
और १९२९ में इस कानून में महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये। इस समय तक
राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर महासभा संसार के सब देशों में
मजदूरों की अवस्था का सुधार करने के लिये प्रयत्न करने में तत्पर हो गई थी।
इस महासभा की स्थापना १९१९ में हुई थी। १९२३ और १९२९ के कानूनों द्वारा
ज्ञापानी सरकार ने यह प्रयत्न किया था, कि जापान के कारखानों में काम करने
वाले मजदूरों की दशा उन नियमों के अधीन हों, जिनका प्रतिपादन अन्तर्राष्ट्रीय
मजदूर महासभा द्वारा किया गया था।

जापान के कारखानों में मजदूरों की जो दुर्रशा थी, उनके कारण उनमें असन्तोंष का होना सर्वथा स्वामाविक था। इसीन्त्रिय वे अपने अधिकारों के

संघर्ष के लिये प्रयत्नशील थे। उन्नीसवी मदी का अन्त होने में पूर्व ही मजदूरों ने अपने संगठन बनाने शरू कर दिये थे। १९०० के एक कानून के अनुसार मजदूरीं ,, को अपने संगठन बना सकते का अधिकार भी राज्य द्वारा स्वीकृत कर लिया गर्या था । पर इस कानून ने मजदूरों को यह अधिकार नहीं दिया था, कि वे अपने संगठनों का उपयोग हडताल आदि के लिये कर सकें। १९०० के कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि यदि कोई मजदूर स्वयं हड़ताल में शामिल होगा या दूसरे मजदुरों को हड़ताल करने के लिये उकसायेगा, तो उसे एक मास मे छ: माम नक जेल की सजा दी जा सकेगी। इस व्यवस्था का परिणाम यह था, कि मजदूर लाग अपने मंगठनों का उपयोग अपने अधिकारों के मंघर्ष के लिये नहीं कर सकते थे। पर इससे जापान के मजदूरों में पंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रवित्त मकी नहीं। १९१२ में वहां मजदूर संघ (फिडरेशन आफ लेवर) का संगठन हुआ । १९२० तक इस संघ के सदस्यों की संख्या ५०,००० तक पहुंच गई थी। जापान के मजदूर आन्दोलन के प्रधान नेता थी। ब्न्जी स्जुकी थे। उनके प्रयत्न का यह परिणाम हुआ, कि १९१९ में मजदूरों के संगठनों के सम्बन्ध में जो ऐसे कान्न थे, जिनके कारण वे अपने अधिकारों के लिये स्वतंत्र रूप से संघर्ष नहीं कर सकते थे, उन्हें रह कर दिया गया । अब से जापान के मजदूर अपनी मजदूरी को वढवाने व कार्यानो में काम करने की परिस्थितियों को उन्नत कराने के उद्देश्य से हडताल के उपाय का आश्रय लेने लगे। १९१४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति के बाद संसार में सर्वेत्र कीमतों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई थी। कीमतों के वद जाने से मजदूरों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा था। वे अपना गुजारा तभी कर सकते थे, जब कि उनको अधिक मजदूरी मिल । इसी लिये उन्होंने हड़ताल के उपाय का आश्रय लेकर मंजदूरी में वृद्धि कराने के लिये संघर्ष शरू किया । १९३१ में जब एक बार फिर जापानी सरकार साम्राज्य विस्तार के लिये प्रवृत्तं हुई, तो देश में इससे बहुत सन्तीष हुआ। कारण यह था, कि जापान के पुंजीपति और मजदूर दोनों ही यह आशा करते थे, कि इससे उनकी आर्थिक ममस्या हल हो सकेगी।

कृषि की उन्नति—जिम प्रकार १८९५ के बाद जापान व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति के लिये तत्पर था, वैसे ही वहां कृषि में भी उन्नति हो रही थी। जापान कि सर्वप्रधान पैदाबार चावल है। गेहूं और जौ की पैदाबार वहां चावल की अपेक्षा वहुत कम होती है। १९१९ में ३१,०४,६११ चो (एक चों चहाई एकड़ के लगभग) जमीन चावल की खेती के लिये प्रयुक्त होती थीं। इसके मुकांबले में गेहूं और जौ की खेती के लिये केवल १७,२९,१४८ चो जमीन प्रयोग में लाई जाती थीं।

जापान के लोग अपने भोजन के लिये चावल का बहुत अधिक प्रयोग करते है। इसीलिये वहां चावल की गैदावार को बहन महत्त्व दिया जाता है। जापान की ्रीयादी में निरत्तर वृद्धि होने के कारण वहां के लोग इस बात के लिये प्रयत्त्रशील थ. कि वे अपने खेतों में अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न करें। माय ही उनका यह भी प्रयत्न था. कि जो जमीनें परती पड़ी हुई है, उन्हें भी खेती के योग्य बनाया जाय । १९०५ में जापान में कूल मिलाकर ५३, ८२, ३७८ चो जमीन खेती के काम में आती थीं। १९३४ में कृषि के काम में लाये जानेवाली भूमि का क्षेत्रफल बढकर ६०,३७, ६४५ चो कर दिया गया था । इस प्रकार २९ साल के अरसे में मात लाख चो (साढ़ सतरह लाख एकड़ के लगभग) नई जमीन खेती के लिये तैयार कर ली गई थी। नई जमीन को खेती के लिये प्रयुक्त करने के माथ माय जमीत की पैदावार को बढ़ाने पर जापानी लोग बहुत घ्यान दे रहे थे। १८८२ में जापान में कुल मिलाकर १,०६,९२,००० कोक् (एक कोक् = पांच व्शल के लगभग) चावल पैदा होता था। १९२८ में वहां चावल की पैदाबार १,०६, ९२,००० कोकु से वढकर ६,०३,०३,००० कोकु हो गई थी। आधी सदी में भी कम समय में जापानी लोगों ने अपनी चावल की पैदावार को छ: गुना के लगभग ैवढ़ा लिया था। इस वृद्धि का एक कारण यह था, कि इस काल में बहुत सी नई जमीन खेती के लिये प्रयोग में लाई गई थी। पर यदि प्रति एकड़ या प्रति चो पैदांबार को देखा जाय, तो यह जात होगा कि अब जापान में प्रति एकड ७५ फी-सदी पैदाबार बढ़ गई थी। यह ठीक है, कि इस काल में जापान की आबादी में भी बहुत वृद्धि हुई। पर आबादी की वृद्धि के साथ साथ चावल की पैदाबार में भी आश्चर्यजनक युद्धि करके जापान ने अपनी अनाज सम्बन्धी समस्या को हल करने में अच्छी सफलता प्राप्त की । अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिये जापान में नये किसम के कृतिम खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया गया, अच्छे बीज प्रयक्त किये गये, बाढ़ों से खेतों को नकमान न पहुंच सके, इसका इन्तजाम किया गया और किसानों को खेनी की नई पद्धति की शिक्षा दी गई। जापानी सरकार का खेती की उन्नति पर इतना अधिक ध्यान था, कि जहां एक तरफ उसने कृपि की उच्च शिक्षा के लिये पृथक कालिजों की स्थापना की, वहां साथ ही देहात के कुमूलों में कृषि की प्रारम्भिक शिक्षाको भी शामिल किया। सरकार ने किसानों को उस बात के लिये प्रोत्साहित किया, कि वे अपने खेतों में कृपि सम्बन्धी नये नये परीक्षण करें और सरकारी संस्थाओं द्वारा इस क्षेत्र में जो परीक्षण किये जा रहे हैं, उनसे लाभ उठावें। साथ ही सरकार ने विसानों को प्रेरित किया, कि वे खेती के साथ साथ व्यवसायों को भी अपनावें। रेशम तैयार करने का व्यवसाय जापान में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार ने यत्न किया, कि किसान शहतूत के पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में लगावें, उन पर रेशमी कीड़ों, को पार्ले और रेशम को बाजार में बेचने के लिये लावें। फल और शाक शब्जी की खेती पर भी सरकार ने विशेष रूप में ध्यान दिया । इन सब बातों का यह परिणाम हुआ, कि जापान के किसान पहले के मुकाबले में अधिक समृद्ध हो गये और खेतों के छोटे होने पर भी उनके लिये अपना निर्वाह कर सकना अधिक कठिन नहीं रहा। चायल, गेहं, जौ व अन्य अनाज के अतिरिक्त जापान में कुछ और चीजों की भी खेती की जाती थी। इनमें चाय की खेती पर विशेष रूप से ध्यान देने की आव-इयकता है। १९३१ में ३८,१०९ चो जमीन चाय के बगीचों के लिये प्रयोग में आ रही थी । १९१९ में जापान में चाय की कुल पैदावार ३,४०,००,००० येन की कीमत की थी। इसमें से १,८५,००,००० येन की कीमत की चाय अन्य देशों में विकने के लिये जाती थी। इसी प्रकार देहात के बहुत से किसान शहतूत के पेड़ों को बोने व रेशम के कीड़ों को पालने में लगे हुए थे। जापान में कुल मिला कर १७,००,००,००० येन की कीमत का रेगम तैयार होता था। बीस लाख के लगभग परिवारों की आजीविका का मख्य साधन रेशम का उत्पादन ही था। सर्वमाधारण किसान जो अनाज या चाय की खेती में लगे होते थे, उनकी स्त्रिया व लड़कियां रेशम के कीड़े पालने में अपना समय लगाती थीं। शुरू में विदेशी वाजारों में चीन के रेशम की मांग अधिक थी और इसीलिये चीन संसार में सबसे अधिक रेशम उत्पन्न करता था। पर १९१० तक यह दशा आ गई थी, कि जापान चीन की अपेक्षा अधिक रेशम तैयार करने लगा था। यरोप में फ्रांस और इटली रेशम की उत्पत्ति के प्रधान केन्द्र थे। पर इटली जितना रेशम तैयार करता था. जापान के रेशम की मात्रा उसके तिगने से भी अधिक थी। फांस की अपेक्षा भी जापान बहुत अधिक परिमाण में रेशम तैयार करता था। कच्चे रेशम की सूत व वस्त्र के रूप में परिणत करने के लिये बहुत से कारखानों का भी जापान में विकास हो रहा था।

मत्स्य व्यवसाय-जापान के आर्थिक जीवन में मत्स्य-व्यवसाय का भी महत्त्व-पूर्ण स्थान था। १५,००,००० के लगभग लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते थे। जापान के अन्तर्गत बहुत से छोटे बड़े द्वीप है, इनके चारों ओर के समुद्र में मछलियां बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। जापानी मिछ्यारे जहां अपने समुद्रतट से मछली पकड़ते थे, वहां साथ ही महासमुद्र में दूर-दूर तक जाकर भी वे मछली पकड़ने का उद्योग करते थे। सरकार का इस व्यवसाय के विकास पर भी समुचित ध्यान था। इसीलिये उसने माइवीरिया के समुद्रतट पर मछली पकड़ने का अधिकार रूम में प्राप्त किया था।

जनसंख्या में वृद्धि—जापान ने आधिक जीवन की समस्याओं की स्पष्ट करते हुए वहां की जनसंख्या की वृद्धि पर भी प्रकाश डाल्ना आवश्यक है। जापान में जनसंख्या किस प्रकार निरन्तर बढ़ रहीं थीं, इसे निम्नलिक्ति अंकों द्वारा भर्ला-भांति स्पष्ट किया जा सकता है—

 १८६७—
 २,६०,००,०००

 १८७२—
 ३,५०,००,०००

 १८९४—
 ४,१०,००,०००

 १९३०—
 ५,३०,००,०००

 १९३०—
 ६,९०,००,०००

१८६० से १९३० तक लगभग साठ मालों में जापान की जनसंख्या में ढाई गुना से भी अधिक बृद्धि हुई थी। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक, जब कि संसार में ज्ञान विज्ञान का भलीभांति विकास नहीं हुआ था, दिभक्ष, महामारियां व ैइसी प्रकार की अन्य प्राकृतिक विपत्तियां जनसंख्या को अधिक नहीं बढने देती थीं। पर स्वास्थ्यरक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी नये जान के कारण मनुष्य रोग पर बहुत कुछ विजय पा चुका था। इस कारण यह सर्वया स्वाभाविक था, कि विविध देशों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती जाय। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि सभी देशों में इस समय मनुष्य संख्या इसी ढंग से निरन्तर वढ़ रही थी। बढ़ती हुई आवादी के लिये यह आवश्यक था, कि देश में अधिक खाद्य सामग्री उत्पन्न हो और लोगों को आजीविका प्राप्त करने के लिये नये साधन उपलब्ध हों। विविध देश अपनी जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिये निम्नलिखित उपायों का अवलम्बन कर रहे थे-(१) नई जमीनों को खेती के लिये उपयोग में लाना और जमीन से अधिक पैदाबार का प्रयत्न करना। (२) व्यावसायिक जन्नति द्वारा अपने तैयार माल को दूसरे देशों में बेचना और वहां से कच्चे माल व अनाज को खरीदना ।(३) संसार के जिन प्रदेशों में आबादी कम थी, वहां जाकर ुअपने उपनिवेश बसाना। (४) पिछड़े हुए देशों को अपनी अधीनता में लाकर , इन्हें अपने साम्राज्य के अन्तर्गत करना, ताकि शासक, अव्यापक, इञ्जीनियर आदि के रूप में वहां कार्य प्राप्त किया जा सके और पिछड़े हुए देशों का आर्थिक विकास करके स्वयं घन उपार्जन कर सकता सम्भव हो । जापान ने भी अपनी जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिये इन सब उपायों का अवलम्बन किया।

लेनो और व्यवसाय की उन्नति के लिये जो प्रयत्न उसने किया. उसका उल्लेख हम अभी कर चके हैं। बहुत से जापानी लोग इस समय अन्य रेशों में जाकर आबाद होने श्रुह हुए। १९२० में विविध जापानी लोग जिस्हें प्रकार अन्य देशों में जाकर वसे हुए थे, उसे समझने के लिये निम्नलिखित अंक पर्याप्त होंगे-चीन में ३,५०,०००; सिगापुर, मलाया, जावा, सुमात्रा और फिलिपीन में १८,०००; हवाई द्वीप में १,००,०००; संयक्त राज्य अमेरिका में १,१०,०००; कनाडा में १४,०००; दक्षिणी अमेरिका में ४३,०००; और आस्टेलिया व ममीपवर्ती द्वीपों में १२०००। जापानी लोग जो इतनी संख्या में अन्य देशों में जाकर आबाद होने के लिये प्रवृत्त हुए, उसका प्रधान कारण आर्थिक ही था। अमेरिका और आस्ट्रेलिया के ज्वेता क्व लोग यह नहीं चाहते थे, कि एशिया के लोग उनके प्रदेशों में आकर वसें। इसलिये उन्होंने उनके खिलाफ अनेक कानुनों का निर्माण किया। जापानी लोगों के लिये भी इन कानूनों के कारण यह सम्भव नहीं रहा. कि वं अमेरिका आदि में जाकर वस सर्वे । इस दशा में जापान के सम्मूल केवल यह मार्ग जोप रह गया, कि वह ब्रिटेन, फ्रांस आदि के समान अपना साम्राज्य बनायं. ताकि वहां अपने तैयार माल को वेचकर अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या को हल कर सके।

(३) शिक्षा का प्रसार

जापान जिसं प्रकार अपनी मर्वतोमुखी उन्नति के लिये प्रयत्नद्द्यील था, उसके लियं यह आवश्यक था, कि वह शिक्षा के प्रसार पर भी विशेष रूप से ध्यान दे। १८९५ से पूर्व जापान ने शिक्षा प्रसार के लिये जो उद्योग किये, उन पर हम पहले प्रकाल डाल सुके हैं। जापान में बाधित प्रारम्भिक शिक्षा की पढ़ित पहले ही जारी की जा चुकी थी। १९०८ में यह कानून बना, कि प्रत्येक बालक व वालिका के लिये छः साल तक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो। इस कानून के कारण १९२२ तक यह दशा आ गई थी, कि जापान में एक भी बालक व बालिका ऐसी नहीं रह गई थी, जिसकी स्कूल जाने की आयु हो और जिसे स्कूल में शिक्षा न मिल रहीं हो। इस दिख्य से जापान यूरोप व अमेरिका के किसी भी प्रगतिशील देश के मुकाबले में पीछे नहीं रहा था। सरकार के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह देश के मन बच्चों की शिक्षा का समुचित रूप से प्रवत्य कर सके। इसके लिये वहुत से नये स्कूलों की स्थापना आवश्यक थी। साथ ही इन स्कूलों के लिये सुयोग्य अध्यापकों का भी प्रवन्ध किया जाना था। स्कूलों का खर्च चलाने के लिये स्प्यां भी कम नहीं चाहिए था। यद्यपि अस्यन्त गरीब लोगों के अतिरिक्त अन्य सबसे

यहाई की फीस ली जाती थी, पर यह फीस इतनी नही होती थी, कि इसमें स्कृत्यों का खर्च चल सके। यही कारण है, कि १९२९ में जापानी सरकार को जिल्ला प्रमार के कार्य पर १,५०,००,००,००० थेन खर्च करना पड़ रह था। इतनी भारी रकम प्रतिवर्ध शिक्षा प्रसार के लिये खर्च करना इस बात का पुष्ट प्रमाण है, कि जापान की सरकार शिक्षा को कितना अधिक महत्त्व देनी थी। प्रारम्भिक शिक्षा के छः वर्षों में जापानी भाषा के अतिरिक्त गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान और इाइंग की पढ़ाई होती थी। इनके अतिरिक्त कृषि, व्यापार और इञ्चलिक भाषा का भी प्रारम्भिक जान प्रत्येक विद्यार्थी को प्रारम्भिक शिक्षा के छः वर्षों में करा विद्या जाता था।

साक्षरता और विद्या के इस प्रचार के कारण जापान की उन्नति में बहुत अधिक महायता मिली। यह सम्भवं नहीं था, कि प्रारम्भिक शिक्षा को समाप्त कर चुकने पर प्रत्येक विद्यार्थी हाईस्कूल व कालिज में प्रविष्ट होकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसका कारण यह था, कि इस समय जापान में उच्च शिक्षा की संस्थाओं की बहुत कमी थी। सरकारप्रधानतया प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान देरहीं थी। पर सरकारी सहायता में बहुत से हाईस्कूल व कालिज भी इस समय जापान में म्यापित किये गये। इनमें ऐसी संस्थाएं अधिक थीं, जो व्यापार. व्यवसाय, जिल्प व कृषि की शिक्षा देती थीं। जापानी लोग भलीमांति अनुभव करते थे, कि देश का हित व कल्याण इस बात में है, कि विद्यार्थी लोग जीवन मंघर्ष में पड़कर आधिक इष्टि से सफल हों और देश की व्यावमायिक व आधिक उन्नति में सहायक हों।

जापान के शिक्षणालयों में पढ़ाई के साथ-साथ चरित्र निर्माण और देशभिक्त पर बहुत जोर दिया जाता था। प्रत्येक जापानी विद्यार्थी बड़ा होकर एक उत्तम नागरिक वर्न और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भलीभांति पालन करे, यह भावना विद्यार्थियों में कूट कूट कर मर दी जाती थी। सम्राट् के प्रति भिक्त, देश के प्रति प्रेम, अपने देश की परम्पराओं व रीति रिवाजों के प्रति निष्ठा और वड़ों की आज्ञाओं का पालन—ये बातें थीं, जिनकी शिक्षा साधारण पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक जापानी विद्यार्थी भलीभांति प्राप्त कर लेता था।

स्त्री शिक्षा—जापान की सरकार जहां शिक्षा के प्रसार पर ध्यान दे रहीं थी. बहु स्त्री शिक्षा के लिये भी उसने बहुत प्रयत्न किया। उन्नीसवीं सदी तक जापान में यह माना जाता था, कि स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर है, और उन्हें इस ढंग की शिक्षा दी जानी चाहिये, जिससे वे अपने गृहस्थ जीवन का सुचार रूप से संचालन कर सकें। पर बीसवीं सदी में इस विचार में परिवर्तन आना शुरू हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा जहां बालकों के लिये आवश्यक व बाधित थी, बहा वालिनाओं ने लिये भी यह जरूरी था, कि वे बाधित रूप से स्कूलों में भरती हों। प्रारम्भिक शिक्षणाल्यों में बालक बालिकाएं एक साथ शिक्षा प्राप्त करती थीं। मेइजी सम्राट् की शिक्ष की पुन: स्थापना के कुछ साल बाद ही १८७१ में पांच जापानी युवतियों को के उद्देश्य से विदेश भेजा गया था, कि वे वहां उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने देश में स्त्री शिक्षा के प्रसार में दिलचस्पी लें। ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित संस्थाओं में भी बालिकाओं की उच्च शिक्षा का समृचित प्रबन्ध था। बीसवीं सदी के शुरू होने के बाद सरकार की ओर से स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और बहुत से नये हाई स्कूल व कालिज स्त्रियों की शिक्षा के लिये स्थापित किये गये। अनेक ऐसे शिक्षणालय भी स्त्रियों के लिये खोले गये, जिनमें उन्हें अध्यापिका का कार्य करने के लिये तैयार किया जाता था। इन ट्रेनिंग कालिओं की आवश्यकता इसलिये अधिक थी. व कि प्रारम्भिक शिक्षणालयों में अध्यापन का कार्य मुख्यत्या अध्यापिकाओं के सुपुर्व किया गया था। १९०१ में जापानी महिला विद्वविद्यालय की भी स्थापना कर दी गई थी, जिसमें स्त्रियों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था।

स्त्री शिक्षा के प्रसार का यह परिणाम हुआ, कि बहुत सी स्त्रियों ने अध्यापिका, चिकित्सक, पत्रकार, वकील आदि के रूप में स्वतन्त्रता के साथ अपनी आजीविका की उपार्जन प्रारम्भ किया। अब उनका कार्यक्षेत्र केवल घर तक ही सीमित नहीं रह गया। जो बालिकाएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये हाईस्कृलों च कालिजों में प्रविद्द होती थीं, उनका विवाह किशोरावस्था में सम्भव नहीं होता था। शिक्षा के कारण स्त्रियों के गृहस्थाश्रम में प्रविद्द होने की आयु भी निरन्तर वड़ी होती जाती थीं, और इसमे जापानी स्त्रियों का साण जीवन केवल पत्नी बनकर पति व अन्य कुटुम्बियों की सेवा में ही व्यतीत नहीं हो जाता था। उनमें स्वतन्त्रता और आत्मिनर्भरता की भावना निरन्तर प्रवल होती जाती थीं।

पत्र पत्रिकाएं—शिक्षा के प्रसार का यह परिणाम अवश्यस्भावी था, कि जापान में पत्र पत्रिकाओं की असाधारण रूप से उन्नति हो। रिक्शा खींचने वाले कुली तक जापान में अपना अखबार खरीदते थे, और उसे पढ़कर देश थिदेश के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करते थे। जापान का पहला दैनिक पत्र १८७२ में प्रकाशित होना शृरू हुआ था। १९३० तक दैनिक पत्रों की लोकप्रियता इस हद्द तक वढ़ गई थी, कि प्रसिद्ध व्यावसायिक नगर ओमाका से प्रकाशित होनेवाले दो दैनिक अखकारों की दस लाख से भी अधिक प्रतियां प्रतिदिन प्रकाशित होती थीं। तोक्यों से निकलने वाले दो प्रमुख दैनिक पत्रों की साहे छः लाख से अधिक प्रतियां प्रतिदिन छपती थीं। इन चार अत्यन्त लोकप्रिय पत्रों के अतिरिक्त एक हजार से अधिक

अन्य दैनिक पत्र जापान के विविध नगरों से 'प्रकाशित होने छगे थे। साढ़े छः करीह के लगभग जनसंख्या के देश में एक हजार से भी अधिक दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशित होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि जापान में जनता को देश विदेश में होनेवाली घटनाओं में अत्यधिक दिलचस्पी थी। लोकमत के निर्माण में इन पत्रों का बड़ा हाथ था। जापान के समाचार पत्र स्वतन्त्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करते थे। प्रेस सम्बन्धी जो कानून वहां विद्यमान था, जब वे कोई ऐसा लेख प्रकाशित कारें, जो देश में शान्ति व व्यवस्था स्थापित रखने में बाधक हो। सम्राट् के प्रति भिक्त के विरोध में या समाजवाद (कम्युनिज्म) के प्रचार के लिये यदि कोई लेख समाचारपत्रों में छपते थे, तो सरकार उन्हें नहीं सह सकती थी। पर इन दो वातों के अतिरिक्त अन्य मामलों में समाचारपत्र के संचालकों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी।

दैनिक ममाचारपत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक, त्रैमासिक व मासिक पत्र भी जापान में बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशित होते थे। जापानी भाषा में प्रकाशित होनेवाली पत्रू पत्रिकाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में भी अनेक पत्र पत्रिकाएं जापान में प्रकाशित होती थीं। जापान के दैनिक पत्रों में सबसे प्रमुख स्थान अशाई शिम्बृन और मैनिशी शिम्बुन का है, जो ओसाका से प्रकाशित होते है, और जिनमें से प्रत्येक की दस लाख से भी अधिक प्रतियां १९३१ तक प्रतिदिन प्रकाशित होनी शुरू हो गई थीं।

साहित्य—यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि जापान के विशाल साहित्य के सम्बन्ध में अत्यन्त संक्षिप्त रूप से भी उल्लेख कर सकें। पर कुछ बातों का निर्देश करना इस इतिहास के लिये अवश्य उपयोगी होगा। आधुनिक युग के प्रारम्भ से पूर्व जापान के साहित्य पर चीन का प्रभाव बहुत अधिक था। बौद्ध धर्म का जापान में प्रवेश चीन द्वारा ही हुआ था, अतः यह स्वाभाविक था, कि जापान के धार्मिक साहित्य पर चीन का प्रभाव हो। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जब पाश्चात्य देशों के साथ जापान का सम्पर्क हुआ और उसने आधुनिक ज्ञान विज्ञान को अपनाना शुरू किया, तो जापानी लोगों ने पाश्चात्य साहित्य के अनुश्रीलन पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। अनेक पाश्चात्य ग्रन्थों का जापानी भाषा में अनुवाद हुआ और हजारों की संख्या में जापानी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका और यूरोप जाने लगे। इस दशा में यह सर्वधा स्वाभाविक था, कि जापानी साहित्य पर भी पाश्चात्य देशों का असर पड़े। यही कारण है, कि इस काल के जापानी साहित्य पर अंग्रेजी, फेड्च और रूसी लेखकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर

होता है। उक्षीसवीं सदी के अन्तिम भाग में शोयो, कोयो और रोहान नामक तीन प्रसिद्ध साहित्यिक जापान में हुए, जिनको संसार के सर्वोत्कृष्ट साहित्यिकों में िपून जा मकता है। इनमें से शोयो माहित्य के उस सम्प्रदाय का प्रतिनिधि था, निर्णं 'रोमान्टिक' कहते है। कोयो की कृतियों की विशेषता यह थी, कि वह प्रतिपाद्य विषय की 'वास्तविकता' (रीयल्जिंभ) को बहुत महत्त्व देता था। समाज के विभिन्न चरित्रों का यथार्थ क्य में चित्र निरूपण करने में उसने असाधारण मसलता प्राप्त की थी। रोहान साहित्य के उस सम्प्रदाय का प्रवर्तक था, जिसे आइ-डियल्स्ट (आदर्शवादी) कहा जाता है। उन्नीसवीं मदी के अन्त तक जापान के साहित्य में रोमान्टिक सम्प्रदाय का प्रभुत्व रहा। पर १९०० के बाद यथार्थवादका जोर बढ़ना शुरू हुआ और फांस आदि पास्चात्य देशों के यथार्थवादी साहित्यकों के समान जापान के साहित्यक भी यथार्थवाद का अनुसरण करने लगे। यथार्थवाद के नाम पर कित्यय जापानी लेखकों ने अपने प्रन्थों में अश्लिखता को ले अगने में भी संकोच नहीं किया।

उपन्यास, नाटक, काव्य सभी क्षेत्रों में इस समय जापान ने असाधारण उन्नित की । पुराने समय में जापान की कविता पर राजदरबार का प्रभाव बहुत अधिक था । सम्राट् व सामन्त राजाओं का आश्रय प्राप्त कर अनेक किव ऐसी किवतां की रचना में प्रवृत्त होते थे, जो राजदरबारों के सम्पन्न लोगों की रिच के अनुकूल होती थीं । पर आधुनिक युग में ऐसे काव्यों का विकास प्रारम्भ हुआ, जिनमें जनसाधारण की रिच को अधिक महत्त्व दिया जाता था । नाटक के क्षेत्र में भी इस समय बहुत उन्नित हुई । नृत्य और संगीत प्रधान नाटकों का स्थान ऐसे नाटक लेने लगे, जिनमें सब प्रकार के भावों व रसों की अभिव्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया जाता था । शेक्मिप्यर आदि पाञ्चात्य साहित्यकों के नाटकों का जापानी भाषा में अनुवाद होने के कारण जापान के अनेक साहित्यकों ने भी यूरोपियन ढंग के नाटक लिखने शुरू किये और जब रंग संच पर उनका अभिनय प्रारम्भ हुआ, तो नाटक की कला में परिवर्तन आता अवश्यमभावी था ।

साहित्यिक पुस्तकों के अतिरिक्त विज्ञान, दर्शन, कला आदि पर भी सब प्रकार के ग्रन्थ इस समय जापानी भाषा में प्रकाशित हुए। इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, सैनिक विद्या, रसायन, भोतिक विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्साशास्त्र अपूरि कोई भी विषय ऐसा नहीं रहा, जिस पर जापान में प्रामाणिक साहित्य की रचैना न हुई हो। विश्वविद्यालयों में उच्च से उच्च शिक्षा जापानी भाषा में दी जाने लगी, और बहुत से चीनी विद्यार्थी भी अपनी ज्ञान पिपासा को शान्त करने के लिये जापान आने लगे। पाश्चात्य देशों के समान जापान भी वैज्ञानिक खोज में तत्पर हुआ, और उसके वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अनुसंघान संसार में सर्वत्र भाग्य होने रुगे ।

(४) सामाजिक उन्नति

पारिवारिक दशा-चीन के समान जापान में भी सामाजिक सगटन का आधार परिवार होता था। परिवार या कुल के विविध व्यक्ति एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध अनुभव करते ये और अपने कुलवृद्ध के शासन में रहते थे। पित्-पुजा जापान में भी प्रचलित थी । प्रत्येक परिवार यह अपना पवित्र कर्तव्य समझता था. कि अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का अनुसरण कर अपने पितरों की पूजा करे। आधनिक यग के सूत्रपात के साथ यह स्वाभाविक था, कि परिवार के संगठन में शिथिलता आवे। व्यावसाधिक उन्नति के कारण शहरों में मजदूरों की मांग में वहत बद्धि हो रही थी। आजीविका प्राप्त करने की लालच मे जो बहत से लोग इस समय अपने कुल कमान्गत घर को छोड़कर शहरों में या सुदूर विदेशों में जाने के लिये विवश हो रहे थे, उनके लिये यह संभव नहीं था, कि वे अपने कुल के साथ सम्पर्क रख सकों या परिवार की प्राचीन समाधियों की पूजा कर सकें। जो लोग र्ह है छोड़कर नये प्रदेश में बस जाते थे, वे अपना नया घर बनाते थे और कुल-वद्ध का शासन उन पर नहीं रह पाता था । बीसवीं सदी में यह प्रवृत्ति बहुत जोर पकड़ गई थी और जापान की जनता कुछ या विरादरी की परम्परागत मर्यादा से बहुत कुछ स्वतन्त्र होने लग गई थी। निःसन्देह, जापान के सामाजिक जीवन में यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था।

पुराने समय में युवक व युवितयों के वैवाहिक सम्बन्ध का निक्चय उनके माता पिता या कुलबृद्ध लोग किया करते थे। पर शिक्षा के विस्तार के कारण अब युवक व युवितयों में यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही थी, कि वे म्बयं अपने जीवन साथी को जुनें। शिक्षित जागानियों में यह तो आवश्यक मा हो गया था, कि विवाह सम्बन्ध के तय होने से पूर्व वे एक बार अपने जीवन साथी से भेंट कर लें और उसके सम्बन्ध में अपना मत स्थिर कर लें। पर ऐसे लोगों की भी कभी नहीं थी, जो विवाह से पूर्व अपने होने वाले पित या परती से घनिष्ठ परिचय प्राप्त कर लेने की आवश्यकता समझते थे। वड़ी उमर में विवाह होने के कारण अब कुल वृद्धों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे विवाह के मामले में अपनी सन्तान की सम्भित की उपेक्षा कर सकें।

स्त्रियों की स्थिति—शिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रियां घर के कार्यक्षेत्र से निकलकर स्वयं आधिक उपार्जन के लिये प्रवृत्त होने छगी थीं, इस बात की महस्ते

स्पष्ट किया जा चुका है। जापान की सुशिक्षित महिलाएं पुरुषों के समान ही जीवन संघर्ष में तत्पर रहती थी और किसी भी प्रकार अपने को उनसे हीन नहीं समझती थीं। गरीब कुलों ी स्त्रियां भी आर्थिक आवश्यकताओं से विवश हो कि कारखानों में काम करने के लिये जाती थीं। हम ऊपर लिख चुके हैं, कि कारखानों में उनकी संख्या पुरुष मजदूरों के मुकावले में अधिक होनी थी। जापान में परदे का रिवाज नहीं था। स्त्रियां न केवल घर को संभालती थी, अपितु आर्थिक उत्पत्ति में भी पुरुषों का हाथ बटाती थीं।

इस प्रमंग में यह भी आवश्यक है, कि हम जापान की स्त्रियों के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करें, जिन्हें नैतिक दृष्टि से आदर्श नहीं माना जा सकता। कारखानों में कार्य करनेवाली गरीब स्त्रियां व वालिकाएं अपने चरित्र को ठीक नहीं रख पाती थीं, इसका निर्देश हम ऊपर कर चुके हैं। इसके साथ ही यह भी बता देना आवश्यक है, कि जापान में वेश्यावृत्ति का बहुत जोर था। गरीब घरों की बहुत सी स्त्रियां वेक्यावृत्ति द्वारा अपना व अपने परिवार का पालन करने के लिये विवेश होती थीं । वेश्यावृत्ति को अन्य अनेक पेशों के समान एक पेशा माना जाता था । सरकार इस पेगे को कानन से रोकने की आवश्यकता नहीं समझती थी। जापान में यह भी प्रथा थी, कि वेश्यावित करने वाली स्त्रियों को सरकार की ओर से कार्कि सेन्स दिया जाय, और उनके स्वास्थ्य का बाकायदा निरीक्षण होता रहे । १९२० के लगभग इस प्रकार लाइसेन्स प्राप्त करके वेश्यावृत्ति करने वाली स्वियों की संख्या पचास हजार से कम नहीं थी । ये स्त्रियां वेश्यावृत्ति को पसन्द करती हों, यह बात नहीं थीं। बहुसंख्यक स्त्रियां इस पेशे को घृणा की दृष्टि से देखती थीं। पर दिक्कत यह थी, कि वेश्यावत्ति करनेवाली स्त्रियां इस पेशे को करने के लिये रार्वथा विवश होती थीं। गरीबी से परेशान होकर बहुत से माता पिता अपनी लड़िकयों को चकलों में भेज देते थे । इसके लिये चकले का मालिक उन्हें कुछ सौ येन प्रदान कर देता था। यह रकम इनकें नाम लिख ली जाती थी। साथ ही यस्त्र, आभूपण व श्रुंगार का सामान आदि के लिये चकले का मालिक जो रकम वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री के लिये वर्च करता था, वह भी उसके नाम लिख लेता था। इस प्रकार प्रत्येक वेरया ऋण के बोझ से दबी रहती थी। जब तक वह अपनी कमाई से इस रकम को अदा न कर दे, वह छुटकारा नहीं पा सकती थी। इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि वेश्यावृत्ति करनेवाली स्त्रियां प्रायः समाज के संबंधे गरीब और सबसे हीन वर्ग की होती थीं। जापान में एक ऐसा वर्ग था, जिसे अछत समझा जाता था। इस वर्ग को वहां एता कहते थे। इनकी प्राय: वही स्थिति होती थी, जो भारत में अछूत जातियों की है। ये शहर या गांव से बाहर पूथक् बस्ती में

निवास करते थे और इनके लिये अपना निर्वाह करना भी कठिन होता था। इस दुआ में यदि ये अपनी लड़िकयों को चंकले में भेजकर अपनी आधिक समस्या को हुले अरने का प्रयत्न करें, तो इसे सर्वथा अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। यहां यह लिख देना भी आवश्यक है, कि उन्नीमवीं सदी में पाश्चात्य संसार के बहुमंख्यक देशों में भी वेश्यावृत्ति को कानून द्वारा अभिमत गाना जाना था और बहां के चकलों में भी वेश्यावृत्ति की वहीं दशा थीं, जो जापान में थी।

चकलों में काम करनेवाली वेश्याओं के अतिरिक्त जापान में स्त्रियों का एक अन्य वर्ग था, जो होटलों, नाचघरों व चाय की दूकानों में काम करके अपना निर्वाह करता था। इनकी स्थित वेश्याओं की अपेक्षा ऊंची होती थी। साथ ही अनेक युवतियां गैशा रूप से जनता का मनोरंजन करने का पेशा करती थीं। गैशा वृत्ति के लिये बालिकाओं को बाबायदा शिक्षा दी जाती थी। गैशा का कार्य वेश्या से बहुत भिन्न है। वे स्पये के लिये अपने शरीर को नहीं बेचतीं, वे लोगों का मनोरंजन करके थन पैदा करती हैं।

ज्यों ज्यों जापान में आधिक उन्नति होती गई, वेश्या वृत्ति भी वहां कम होती गई। इस पेशे का मुख्य आधार आधिक था। जब जापान की स्त्रियों के लिये जिंच उपायों से धनोपार्जन करना सुगम हो गया, तो इस पेशे की आवश्यकता निरन्तर कम होती गई।

श्रेण भेद-भारत के समाज में जिस प्रकार का वर्ण भेद व जाति भेद विद्यमान है, वैसा जापान में नहीं था। आधुनिक युग के प्रारम्भ से पूर्व जापान की जनता को सामाजिक दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं—(१) कुलीन श्रेणि, इसमें राजकुल व गामन्त राजाओं के कुलों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले लोग अन्तर्गत किये जा सकते हैं। (२) सर्वसाबारण जनता—इसमें खेती, शिल्प, व्यवसाय आदि से निर्वाह करनेवाले लोग सम्मिलित थे। (३) एता श्रेणि—इसमें वे लोग अन्तर्गत थे, जो अछूत समझे जाते थे और जो अत्यधिक गरीब थे। ये लोग नगर व ग्राम के बाहर पृथक् बस्तियों में निवास करते थे। अन्य जनता के साथ इनका सम्पर्क वहन कम था।

आधुनिक युग का प्रारम्भ होने पर इस श्रेणिभेद में अन्तर आना शुरू हो गया।
सामन्तपद्धति का अन्त हो जाने से पुरानी कुलीन श्रेणि का महत्त्व कम होने लगा
और व्यवसाय च व्यापार का अनुसरण कर सर्वसाधारण जनता में सभी बहुत से
लोग धनी होकर सम्मानास्पद स्थिति प्राप्त करने लगे। नये युग की भावनाओं से
प्रेरित होकर सरकार ने अनेक ऐने कानून वनाये, जिनसे एता लोगोंको अन्य जनता
के समान अधिकार दियं गये। उनके लिने भी निशा प्रान्त करना अनिवार्य कर

दिया गया । इस स्थिति में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि एता लोगों की सामाजिक स्थिति में भी उन्नति हो । पर अनेक सिदयों से एता लोगों में अपने को हीन व की क्ष समझने की भावना इतनी बद्धमूल थी और आधिक दृष्टि से वे इतने गरीब थे, कि उनके लिये यह सम्भव व कियात्मक नहीं था, कि कान्न की दृष्टि से अन्य लोगों के समझ हो जाने पर भी वे वस्तुतः अन्य जनता के समान स्थिति प्राप्ता कर लें । पर यह स्वष्ट है, कि आधुनिक युग की प्रवृत्तिया जापान में बड़ी नेजी के साथ कार्य कर रही थी, और श्रेणि व वर्ग का भेद निरन्तर कम हो रहा था ।

पर नये युग की परिस्थितियां जापान में भी उसी प्रकार का नया श्रीणभेद विकसित करने में तत्पर थीं, जैसा कि उन्नीसवीं सदी में यूरोप के व्यवसाय प्रधान देशों में विकसित हुआ था। पूजीपित और मजदूर के रूप में इस समय जापान में दो ऐसे वर्ग विकसित हो रहे थे, जो एक दूसरे में सबंधा पृथक् थे, जिनके हितों में स्वाभाविक विरोध था, और जिनमें समन्वय व सामंजस्य स्थापित कर सकता सुगम नहीं था। यही कारण है, कि पाश्चात्य देशों के समान जापान में भी मजदूर आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।

(५) धार्मिक दशा

जापान की बहुसंख्यक जनता बौद्ध धर्म का अनुसरण करती थी, पर चीनी लांगों के समान उन पर भी कत्प्युसियस की नैतिक शिक्षाओं का प्रभाव था। चीन के प्रसिद्ध आचार्य कत्म्यसियस ने चरित्र निर्माण और नैतिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में जो शिक्षाएं दी थीं, जापानी लोग उन्हें आदर्श मानते थे और यथाशिक्त उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करते थे । इसीलिये जापान के शिक्षित व उच्च वर्गों में कन्त्रयसियस के ग्रन्थों को बड़े आदर के साथ पढ़ा जाता था। इसके अतिरिक्त जापान में बौद्ध धर्म के प्रवेश से पूर्व जो धर्म विद्यमान था, उमका प्रभाव भी अभी तक जनता पर मौजूद था । इस धर्म को शिन्तो कहते थे । शोग्न शासन का अन्त होने पर जब सम्राट् की शक्ति का प्रकटार हुआ, तो इस शिन्तो धर्म की भी बल मिला। इस धर्म के अनुसार कुछ देवी देवता ऐसे थे, जिनकी पूजा जापान में सर्वश्र प्रचलित थी । इन देवताओं के विशाल मन्दिर जापान में अनेक म्थानों पर विद्यमान थें। शिन्तों धर्म के इन मन्दिरों में जिन देवताओं की पूजा होती थी, उनका सम्बन्ध जापान के प्राचीन इतिहास के साथ था। जिस प्रकार भारत में राम, सीता, राष्ट्री कृष्ण, शिव, पार्वती, अर्जुन, भीम आदि की देवता रूप से पूजा प्रचितन हैं, पर वस्तृतः इनका भारत के प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध है, और इनके जीवन की अनेक घटनाएं पौराणिक ग्रन्थों में प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार जापान के विन्तो धर्म के भी बहत से

देवी देवता ऐसे थे, जिनका सम्बन्ध उसकी प्राचीन पौराणिक गाथाओं के साथ में है। सम्पूर्ण जापान में सर्वमान्य देवी देवताओं के अतिरिक्त बहुत से देवी देवता ती भी थे, जिनकी पूजा केवल किसी विशिष्ट प्रदेश में या ग्राम में ही की जाती थी। इनका सम्बन्ध उस प्रदेश व ग्राम के किसी प्राचीन व्यक्ति से था, जिसकी स्मति वहां की जनता में अब तक विद्यमान थी । साथ ही, प्रत्येक कुल का अपना पथक मन्दिर भी होता था, जिसमें उस कुल के पितरों की पूजा की जाती थी। जापानी लोग यह मानते थे, कि मरने के साथ मन्ष्य की आत्मा का अन्त नहीं हो जाता । 'कामी' रूप से उनकी सत्ता मृत्यु के बाद भी कायम रहती है। इनकी दैव रूप से पूजा करने के लिये जापानी लोग अनेक विधि विधानों का अनुष्ठान किया करते थे । १९३३ में शिल्तो धर्म के सब प्रकार के मन्दिरों की संख्या १,११. ०३७ थी, जिनमें १५,५८९ पूजारी पूजा का कार्य करते थे। छोटे छोटे मन्दिरों में पथक् रूप से पुजारियों की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी, इसीलिये मन्दिरों की अपेक्षा पुजारियों की संख्या कम थी। जिन्ती धर्म द्वारा जापान की जनता में यह भावना जागृत रहती थी, कि उनका देश बहुत प्राचीन व गौरवशाली है, उनकी अपनी उत्पत्ति देवताओं द्वारा हुई है, और वे अन्य लोगों की अपेक्षा "अधिक ऊंचे व उत्कृष्ट हैं। शिन्तो धर्म द्वारा जापानी लोग यह भी समझने थे, कि गम्बाट् का प्राद्रभिवभी अत्यंत शिवतशाली देवता द्वारा हुआ है, और वह स्वयं देवता रूप है। सम्राट् के प्रति भिक्त और देश के प्रति प्रेम की भावना को विकसित करने में जिन्तो धर्म का भारी उपयोग था। यह नहीं समझना चाहिये, कि जिन्तो धर्म के अन्यायी और बौद्ध लोग उस प्रकार एक दूसरे के भिन्न थे, जैसे कि हिन्दू, म्सलिम, व ईसाई लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जापान की सर्वसाधारण जनता बौद्ध धर्म की अन्यायी थी, पर साथ ही शिन्तो धर्म के देवी देवताओं की भी पूजा करती थीं । जित्तो धर्म उन अर्थो में मत, धर्म व सम्प्रदाय नहीं था, जिन अर्थों में कि किञ्चिएनिटी या इस्लाम है। इसीलिये जापान की सरकार इसे एक पृथक धर्म व मत के रूप में नहीं मानती थी । बौद्ध लोग शिन्तो देवी देवताओं को मानते थे । वे कहते थे, कि शिन्तों देवी देवता भी बुढ़ के ही पूर्वावतार थे। बौढ़ों ने शिन्तों धर्म के साथ इस ढंग से समन्वय व सामञ्जल्य स्थापित कर लिया था, कि वे मिलकर एक ्हों गये थे, उनकी पृथक् सत्ता नहीं रह गयी थी । एशिया के बहुसंख्यक धार्मिक आन्दोलन धर्म के मामले में समन्वयवाद के अनुयायी रहे हैं। भारत में बौद्ध और सनातन हिन्दू धर्म में इस ढंग से समन्वय हो गया था, कि हिन्दू लोग बुद्ध को अपने दशाबतारों में मानने लगे थे । बौद्धों ने भी भारत के बहुत से प्राचीन देवी देवताओं को अपने में इस ढंग से समाविष्ट कर लिया था, कि वे बीड धर्म के हो अंग का क्य

थे । तिब्बत, चीन आदि जिन देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, सर्वत्र यही प्रिक्रिया हुई । जापान में भी शिन्तो धर्म और बौद्ध धर्म में एक प्रकार का समन्त्रथ व अभेद स्थापित हो गया था ।

जापान का बौद्ध धर्म बारह सम्प्रदायों में विभक्त था। इनमें तीन प्रमुख थे, जेन, निचिरिन और शिन । सब बौद्ध सम्प्रदायों के कूल मिलाकर ७१,००० से भी अधिक मन्दिर १९३१ में जापान में विद्यमान थे, जिनमें कार्य करनेवाले पूरी-हितों की संख्या ५५,००० से भी अधिक थी। बीद्ध धर्म के ये मन्दिर व विहार कला की दिष्ट से अनुपम थे। बौद्ध धर्म ने जापान में जाकर एक ऐसी उत्कृष्ट कला का विकास किया था, जो वस्तुतः अनुपम थी । क्रिविचयन गिशनरियों के सम्पर्क में आने से बीद्ध धर्म में भी नवजीवन का संचार हुआ था । बौद्ध धर्म के भिक्षुओं व अन्य नेताओं ने अनुभव किया था, कि ईसाई धर्म के प्रचार का मुकाबला वे तभी कर सकते हैं, जब बौद्ध लोगों द्वारा भी शिक्षणालय व चिकित्सालय खोले जावें, सर्व-साधारण जनता में कार्य किया जाय और नवयुवकों में बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण व उत्साह उत्पन्न किया जाय । इसीलिये ईसाइयों के यंगमेन्स किश्चियन एशोसि-यन ने अनुकरण में जापान के बौद्धों ने यंगमेन्स वृद्धिस्ट एसोशियेसन का संगठन किया और यह एसोशियेशन भी जापानी नवयुवकों में कार्य करने के लिये तत्पक्क हुआ । बौढ़ों की और से जापान में अनेक स्कूल व अस्पताल खोले गये । फार्मुसा, कोरिया, चीन आदि में भी जापानी बृद्धिस्ट मिशन ने कार्य प्रारम्भ किया। विदेशों में स्थापित ये बौद्ध मिशन जहां उन देशों के बौद्ध लोगों में अपने धर्म के प्रति उत्साह की उत्पन्न करते थे, वहां साथ ही जापान के साम्राज्य विस्तार में भी महायक होते थे । जापानी लोगों ने जिस प्रकार पारचात्य संसार के ज्ञान विज्ञान को अपनाया या, वैसे ही उन्होंने उनके साम्राज्य विस्तार के तरीकों का भी अनुसरण किया था।

ईसाई धर्म का जापान में प्रवेश सबसे पूर्व सोलहवीं सदी में हुआ था। पर जापानी सरकार ने पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क का अन्त करने के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार को भी कानुन द्वारा रोक दिया था। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में जब जापान और पाश्चीत्य देशों का सम्पर्क पुनः स्थापित हुआ, तो ईसाई मिशनरियों ने भी वहां अपने प्रचार कार्य को शुरू किया। फांस का रोमन कैथोलिक मिशन और रूस का ओथोंडोक्स चर्च वहां विशेष रूप से धर्म प्रचार के, कार्य में तत्पर हुए। बाद में प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायों ने भी जागान में कार्य वाद किशी को विशेष सफलता नहीं मिली। १९३३ तक जापान में ईसाई लोगों की कुल संख्या तीन लाख से अधिक नहीं थी। आधी सदी के निरन्तर प्रयत्न से १९१५ तक ईसाई लोग केवल डेढ़ लाख के लगभग जापानियों

को अपने धर्म में दीक्षित कर सके थे। १९१५ से १९३३ तक वे डेढ़ लाख अन्य जापानियों को अपने धर्म में ले आ सकने में समर्थ हुए। जापान में ईमाई प्रचारकों की अधिक सफलता नहीं हो सकी, इसका प्रधान कारण यह था, कि जापानी लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रम बहुत उत्कट था। वे लोग विदेशी धर्म को स्वीकार करने के लिये आकर्षण अनुभव नहीं करते थे। बौढ़ धर्म में नवजीवन का सचार हो जाने के कारण जापानी लोगों को इस बात की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती थी, कि वे किसी अन्य धर्म को अपनावें। जापान में ईसाई धर्म का जो प्रचार हुआ, उसमें भी उन जापानी मिशनरियों का विशेष कर्न रच था, जिन्होंने कि शुरू में ईसाई धर्म को अपनाकर जापानी भाषा और जापानी पुस्तकों ढारा उसका प्रचार गुरू किया था।

(६) १९३१ का जापान

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह उपयोगी होगा, कि हम संक्षेप से इस बात का फिर उल्लेख कर दें, कि १९३१ में जब कि जापान एक बार फिर साम्राज्य-विस्तार के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ प्रवृत्त हुआ, उसकी क्या दशा थी। फार्मसा और कोरिया इस समय जापान के अधीन ये। फोर्मुसा के समीपवर्ती श्रीत्करेदोरस द्वीप समृह और दक्षिणी संखालिन पर भी उसका आधिपत्य था। प्रशान्त महासागर में विद्यमान बहुत से छोटे छोटे द्वीप समृह उसके कब्जे में थे। मञ्चरिया में उसका आर्थिक प्रभाव क्षेत्र विद्यमान था । लिआओतुंग प्रायद्वीप पर उसका प्रभुत्व था और मञ्चूरिया में भी उसकी सेनाएं स्थापित थीं । पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागरके क्षेत्र में उसकी स्थिति इतनी सुदृढ़ थी, कि वह निश्चिन्त होकर साम्राज्य विस्तार के लिये प्रवृत्त हो सकता था। जलसेना और साम्द्रिक शक्ति की दुष्टि से वह संसार में तीसरा स्थान रखता था। उसकी स्थलसेना भी अत्यधिक शक्तिशाली थी। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में वह ब्रिटेन और अमेरिका सद्श उन्नत व समृद्ध देशों का समकक्ष था। उसकी राजधानी तोक्यो जनसंख्या की दृष्टि से संसार में तीसरा स्थान रखती थी। तीन चौथाई सदी के लगभग समय में पूर्वी एशिया का यह छोटा सा देश इतना अधिक शक्तिशाली और समद्ध हो गया था, कि वह उन्नत से उन्नत पाश्चात्य देश के साथ लोहा ले सकता था। जापान की यह उन्नति वस्तृतः आश्चर्यजनक है, और संसार के डातहास में इसका उदाहरण अन्यत्र पा सकता सुगम नहीं है।

चौदहवां अध्याय

द्क्षिणी-पूर्वी एशिया

(१) दक्षिणी-पूर्वी एशिया के विविध राज्य

विछित अध्यायों में हमनं चीन और जापान के आव्निक ईतिहास की १९३१ तक की मुख्य घटनाओं का मंक्षेप के साथ उल्लेख किया है। एशिया के आधुनिक इति-हास में सन् १९३१ का बहन अधिक महत्त्व है। इस माल में जापान ने मञ्जूरिया में अपने राजनीतिक प्रभन्व की स्थापना का उपक्रम किया । मञ्च्रिया की अपने अधीन कर जापान ने मंगोलिया और उत्तरी चीन में अपने साम्राज्य का विस्तार शरू किया। इसी कारण चीन और जापान के द्वितीय युद्ध का सूत्रपात हुआ। १९३९-४५ के दितीय विक्व संग्राम के अवसर पर जापान ने सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया को पाश्चात्य देशों की अधीनना से मुक्त किया और इस विशाल क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया । जापान के इस उत्कर्ष का यह महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ, कि एशिया के विविध देशों को पाञ्चात्य देशों के साम्राज्यवाद से मुक्त होकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्थापित करने का अवसर मिला। महायुख के अवसर पर चीन में कम्युनिस्ट लोगों की जनित बढ़ने लगी और घीरे धीरे सम्पूर्ण चीन कम्युनिस्ट व्यवस्था के अधीन हो गया । १९३१ में जापान ने साम्राज्य विस्तार के लिये जो संघर्ष क्र किया था, उसमें सफल होकर वह पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया की अपनी अधीनता में तो नहीं ला सका, पर उसके कारण इन क्षेत्रों के देशों को स्वातनत्र्य प्राप्ति का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ । सन् १९३१ से १९४९ तक की घटनाएं एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। क्योंकि इस काल में जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव को विस्तृत करने का असाधारण प्रयत्न किया, अतः यह उपयोगी होगा, कि हम चीन और जापान के समान दक्षिण-पूर्वी एशियः के विभिन्न देशों के १९३१ तक के इतिहास पर भी प्रकाश डालें। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश १९३१ तक किस स्थिति में थे, किस प्रकार वे विविध पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए थे, और किस प्रकार उनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद की भावनाएं बल पकड़ रही थीं--यह जान लेने के बाद ही

पाठकों के लिये यह सम्भव होगा, कि वे १९३९-४५ के महायुद्ध के अवसर पर इस देखों में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए , उन्हें भलीभांति अवगन कर सकें।

बिविध राज्य—दक्षिण-पूर्वी एजिया को चीन में नान यांग और जापान में नान यों कहते हैं। नीनी और जापानी भाषा में इस क्षेत्र के लिये एक नाम का होना इस बात को सूचिन करता है, कि पूर्वी एशिया के ये दो प्रमुख देश देर में यह अनुभव करते रहे है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में आधारभून एकता विद्यमान हैं। यदि हम उत्तर पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर जावें, तो इसक्षेत्र में निम्नलिखित देश मिलेंगे—िफिल्पीन दीप समूह, ब्रिटिश बॉनियो, इन्डोनीसिया, इन्डो-चायना, गलाया, सियाम ओर वरमा। दक्षिण-पूर्वी एशिया के ये ही प्रमुख राज्य है। १९३९-४५ के महायुद्ध तक ये सब किसी न किसी रूप में पश्चित्र देशों के प्रभुत्त्व में थे। इस समय इन सब में प्राय: स्वराज्य स्थापित हो गया है। पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव व प्रभुत्त्व उन देशों में अब तक विद्यमान है, उनका भी धीरे शीरे अन्त हो रहा है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों का क्षेत्रफल व जनसंख्या कितनी है, इसका र्फ़्रिज़ान इनके राजनीतिक इतिहास को अवगत करने में बहुत सहायक होगा।

वेश	क्षेत्रफल वर्गमील	.जनसंख्या (१९३६)	प्रतिवर्गमील आबादी
बरमा	२,६१,६१०	2,55,00,000	६३
सियाम	2,00,986	8,48,00,000	৩৩
इन्डो-चायना	7,75,000	2,39,00,000	ر ۶
मलाया	५२,२८६	44,198,000	१०७
इन्डोनीसिया	७,३५,२६८	8,96,34,000	९४
विदिश बोनिया	८१,७६१	8,42,000	१२
तिमोर (पोर्त्गाल			,
क्ते अधीन)	७,३३०	8,60,000	६६
फिलिप्पीन द्वीपसमूह	१,१५,६००	१,६३,००,०००	5.9.8
दक्षिण-पूर्वी एशिया	१७,४०,०००३	१४,८६,४५,०००	८५

क्य तारिका क्षारा नह भागिभाषि सान्य हो जाता है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विशिष देवों का क्षेत्रकार कियान कितना है, और १९३९ में उनमें कितनी कितनी आसारी की । इस देवों के भौगोलिक व राजनीतिक गहरव को सगलने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। यहां यह लिख देना भी आवश्यक है, कि इन प्रमुख देशों के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में अनेक ऐसे अनेक छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जिन पर ब्रिटेन आदि विदेशी राज्यों का प्रमुक्त्व हैं, और जिनका शासन कॉर्जन कोलोनी के रूप में पृथक् रूप से किया जाता है। इन विविध द्वीपों में तिमोर का उल्लेख हमने इस तालिका में किया है। यह द्वीप पोर्तुगाल के अधीन है। पर तिमोर के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से छोटे छोटे द्वीप समूह इस क्षेत्र में हैं, जिनका यहां उल्लेख विशेष उपयोगी नहीं हैं।

अब हम इन विविध राज्यों के १९३१ तक के इतिहास पर प्रकाश डालना प्रारम्भ करते हैं। इसके लिये हम उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की और चलेंगे, क्योंकि अब तक इस ग्रन्थ में हमने चीन और जापान के इतिहास का निदर्शन किया है। विवय को स्पष्ट करने के लिये यही उचित होगा, कि हम जो राज्य जापान और चीन के सबसे निकट हैं, उन्हीं के विषय में पहले लिखें।

(२) फिलीप्पीन द्वीप समूह

जापान के दक्षिण और इन्डोचायना के पूर्व में जो फिलिप्पीन द्वीप समूह हैं। जनमें कुल मिलाकर ३१४१ द्वीप अन्तर्गत है । इन द्वीनों में लूजोन और मिन्दानाओं आकार में अच्छे बड़े हैं, और ये ही फिलिप्पीन के प्रमुख द्वीप हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सब द्वीप छोटे छोटे हैं। फिलिय्पीन द्वीप सगृह के बहुसंख्यक निवासी जाति की दृष्टि से मलाया के लोगों से मिलते जुलते हैं। वहां अनेक भाषायें बोली जाती हैं, और पर्वत प्रधान प्रदेशों के निवासी नसल व जाति की दुष्टि से भी मैदान के रहने वालों से भिन्न हैं। फिलिप्पीन द्वीप समृह के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में हमें वहत ज्ञान नहीं है, और इस इतिहास का इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय से सम्बन्ध भी अविक नहीं है । पन्त्रहवीं सदी में इन द्वीपों में इस्लाम का प्रचार प्रारम्भ हुआ । दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों व प्रदेशों में इस समय तक इस्लाम की भली-भाति स्थापना हो चुकी थी । धीरे-धीरे फिलिप्पीन दीवों में भी इस्लाम का प्रवेश हुआ और दक्षिणी द्वीपों के बहुत से लोगों ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया । इस्लाम के प्रवेश से पूर्व फिलिप्पीन द्वीप समह के निवासी बाह्य प्रभाव से प्रायः वंचित थे। भारत के धर्म प्रचारक व विजेता बरमा, मलाया, सियाम, इण्डो-चायना आदि 🙀 में तो अपना प्रभाव स्थापित कर चुके थे, पर फिलिप्पीन उनके सम्पर्क से पूर्वक रहा था । चीन के लोगों ने कोरिया और जापान में तो अपना धार्मिक व सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया था, पर फिल्प्पीन द्वीपों की तरफ उनका भी ध्यान नहीं गया था । मुसलिम लोग भी इन दीपों के बहुत थोड़े से भाग को ही अपने प्रभाव में ला

सके थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि विदेशी प्रभाव से मुक्त रहते हुए भी इन द्वीपों के निवासियों ने सम्यता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर ली थी। वे मकानों में रहते थं, खेती द्वारा अपने खाद्य अन्न को उत्पन्न करते थे, खेतों की सिंचाई की व्यवस्था करते थे और धातुओं के उपयोग से भी परिचित थे। लिखने की कला को भी वे जानते थे, और इस कारण साहित्य की भी वहां सत्ता थी। हिन्दू और बौद्ध धर्मों के प्रचारक भी किसी प्राचीन काल में वहां पहुंचे थे, पर उनके धर्म का कोई विशेष प्रभाव पन्त्रहवीं सदी तक विद्यमान नहीं रहा था। फिल्प्यान द्वीप समूह के जिन निवासियों ने इस्लाम को स्वीकृत कर लिया था, उनके अतिरिक्त अन्य लोग अपने देवी देवताओं की पूजा में तत्पर थे। किसी केन्द्रीय राजनीतिक संगठन का इन दीपों में अभाव था।

स्पेत का प्रभुस्य--दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान फिलिप्पीन में भी सबसे पूर्व पोर्तुगीज लोग ज्यापार का विस्तार करने के सिलसिले में आये। पर इस प्रदेश में अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के कार्य में स्पेनिश लोगों को . सफलता हुई । १५२१ में प्रसिद्ध स्पेनिश याश्री फर्डिनन्ड मैगेल्लन पृथ्वी की परिक्रमा करता ्रहुआ फिलिय्पीन पहुंचा । गैंगेल्लन बस्तुतः मलक्का पहुंचना चाहता था, जो कि उस युग में मसालों के व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। फिलिप्पीन पहुंच जाने पर उसने वहां स्पेन का आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और वहां के निवासियों के साथ युद्ध करते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। पर मैगेल्लन ने जी नया प्रदेश ढूंढ़ निकाला था, स्पेनिश लोग उस सुगमता से छोड़नेवाले नहीं थे। अमेरिका महाद्वीप के अच्छे बड़े भाग पर उनका प्रभुत्व था और मैक्सिको में वे अपनी सता को भलीभांति स्थापित कर चुके थे। मैक्सिको के पश्चिमी समुद्रतट को अपना आधार बनाकर उन्होंने प्रशांत महासागर को पार करना शरू किया और १५२७ व १५४२ में वो वार फिलिप्पीन पर आक्रमण किया। पर पोर्त्गीज लोग इस प्रदेश को अपने क्षेत्र में समझते थे। पाप की व्यवस्था के अनुसार उनका यह विचार था, वि पूर्वी एशिया के सब प्रदेशों पर उनका अधिकार है । इसल्पिये स्पेन के आक्रमणों का उन्होंने मुकाबला किया और १५२७ व १५४२ के हमलों में स्पेनिश लोगों को सफलता नहीं मिल सकी। बाद में पोर्तुगीज ्र अंतिश लोगों ने आपस में समझौता कर लिया और १५६४ में एक शक्तिशाली स्पेनिश बेड़े ने मैिन्सिको से फिलिप्पीन के प्रति प्रस्थान किया । सबसे पहले केब् द्वीप पर स्पेन का अधिकार स्थापित किया गया, यहीं पर युद्ध करते हुए १५२१ में मैगेल्लन की मृत्यु हुई थी। १५७१ में मनीला को जीत लिया गया। यह एक अच्छा समृद्ध बन्दरगाह था और मुसलमानों के अधीन या । सोनिश विजेताओं ने मनीला को अपनी राजधानी बनाया और उसे केन्द्र बनाकर घीरे घीरे सम्पूर्ण फिलिप्पीन पर अपना शासन स्थापित कर लिया।

राजनीतिक दृष्टि से फिलिप्पीन द्वीप समह को अपने अधीन कर स्पेनिश लोकी नं वहां क्रिव्चिएनिटी का प्रचार प्रारम्भ किया । इस युग में स्पेन की साम्राज्य विस्तार सम्बन्धी नीति यह थी, कि अवीनस्थ देशों के धर्म, सभ्यता व संस्कृति की पूर्ण रूप में नष्ट कर उन्हें अविकल रूप से पाश्चात्य रंग में रंग लिया जाय । मैक्सिकां आदि अमेरिकन प्रदेशों में भी स्पेनिश लोगों ने बल का प्रयोग कर ईसाई धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया था । बहत से स्पेनिश पादरी इस समय फिल्पिन में आये और उन्होंने जबर्दस्ती जनता को ईसाई बनाना शुरू किया। जो कोई व्यक्ति उनका विरोध करता था, उसे सबक सिखाने के लिये स्पेनिश सिपाही पादरियों के साथ रहते थे। फिलिप्पीन की बहसंख्यक जनता बहुत भीर थी, अपने धर्म व संस्कृति के लिये उसके हृदय में विशेष निष्ठा नहीं थी । परिणाम यह हुआ, कि स्पेनिश पादरी अपने प्रयत्न में सफल हुए और शीघ्र ही उन्होंने फिलिपीन द्वीप मम्ह के वहसंख्यक लोगों को ईसाई बना लिया । दक्षिण फिलिप्पीन के मुसलिम लोग ही ऐसे थे, जिन्होने डटकर ईसाई पादरियों का मुकाबला किया और अपने धर्म को छोड़ देना स्वीकार नहीं किया। यही कारण है, कि स्पेनिश लोग फिलिल्पीन के म सलमानों को (जिन्हें स्पेन के लोग मोरो कहते थे) अपने धर्म में दीक्षित कर सकते में सफल नहीं हो सके। ईसाई पादिरयों के प्रयत्न से फिलिल्पीन में सर्वत्र गिरजों की स्थापना की गई। ऐसे स्कुल खोले गये, जिनमें ईसाई धर्म की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाता था और जनता को पश्चिमी ढंग से रहने सहने का प्रकार सिखाया गया । इसमें सन्देह नहीं, कि स्पेन के रोमन कैथोलिक पादरी अपने प्रयत्न में सफल हुए और बीछ ही उन्होंने फिलिप्पीन लोगों को अपने रंग में एंग लिया ।

व्यापार के क्षेत्र में फिलिप्पीन के स्पेनिश शासकों को विशेष सफलता नहीं रूई। इसका मुख्य कारण यह था, कि वहां से स्पेन जाने का सीधा मार्ग मिलाया आदि के उन क्षेत्रों से होकर गुजरता था, जिन पर पोर्तुगाल व अन्य यूरोपियन शों का कब्जा था। चीनी लोगों ने यह कोशिश की, कि वे फिलिप्पीन के साथ गपने व्यापार का विकास करें। पर इस उद्श्य से जो चीनी व्यापारी वहां अत्यू येनिश लोगों ने उनके साथ बहुत वुरा बरनाव किया। स्पेनिश लोग चीनी व्यापपूर्ण ने वृद्धि को रोकने का एक ही उपाय जानते थे, वह यह कि फिलिप्पीन में आनेवाल तिनी व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया जाय। उन्होंने अनेक बार चीनी नेगों का वातले आम किया। पर फिर भी चीनी व्यापारियों का बहां आना हका

नहीं और फिलिणीन द्वीप समूह का विदेशों के साथ जो भी व्यापार विकसित हुआ, जुझका प्रधान श्रेय चीनी लोगों को ही है।

अमेरिका का प्रभुत्व—१५७१ से १८९८ तक फिलिप्पीन द्वीप सगृह स्पेन के अधीन रहा । इसके बाद उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपन्य स्थापित हो गया । फरवरी, १८९८ में संयुक्तराज्य अमेरिका और स्पेन में यद्ध का प्रारम्भ हुआ था । यहां हमारे लिये यह संभव नहीं हैं, कि इस युद्ध के कारणों पर विशद रूप से प्रकाश डाल सके । केवल इतना निर्देश कर देना पर्याप्त होगा, कि उन्नीमवीं सदी के अन्त तक भी अमेरिकन महाद्वीप के कतिपय प्रदेशों पर स्पेन का प्रभुस्य विद्यमान था । इन प्रदेशो पर स्पेन का शासन अत्यन्त अत्याचारमय था । इससे तंग आकर १८९५ में क्यूबा के लोगों ने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । स्पेन ने क्यूबा के विद्रोह को शान्त करने के लिये अत्यन्त उग्र उपायों का प्रयोग किया। अपने महा-द्रीग के एक प्रदेश गर विदेशी राज्य द्वारा होने वाला यह अत्याचार अमेरिकत लोगों को असह्य था । अमेरिकन पुंजीपतियों ने न्युबा के ज्यवसायों में बहुत सा धन लगा रखा था । अतः वे नहीं चाहते थे, कि स्पेन के दूपित गासन के कारण वहां निरन्तर द्विद्रोह होते रहें। उन्होंने आन्दोलन किया, कि अमेरिका को चाहिये कि क्यबा को स्पेन के शासन से मुक्त करावे । इसी बीच में एक अमेरिकन जहाज क्यूबा के तट पर इबो दिया गया । अमेरिकन लोगों ने इसके लिये स्पेन को दोषी ठहराया और उसके विकड़ युद्ध की घोषणा कर दी। स्पेन के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका जैरो प्रबल राज्य का म्काबला कर सके । वह परास्त हो गैया, और अगस्त, १८९८ तक युद्ध की समाप्ति हो गई। इस युद्ध के परिणाम-स्वरूप जहां अमेरिकन महाद्वीप के प्रदेश स्पेन की अधीनता ने मुक्त हुए, वहां साथ ही फिलिप्पीन द्वीप समृह पर भी अमेरिका ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । कमोडोर डयुई हारा १ मई, १८९८ को मनीला की खाड़ी के समीप स्पेन का जहाजी बेड़ा ब्री तरह परास्त किया गया और फिलिप्पीन द्वीप समूह से स्पेन के आधिपत्य का अन्त हो गया । अन्य पाश्चात्य देशों के समान अमेरिका भी इस समय साम्राज्य-वाद के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा था । पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये वह प्रयत्नशील था। परिणाम यह हुआ, कि फिलिप्पीन द्वीप समृह पर अमेरिका ने अपना शासन कायम कर लिया।

स्वाधीनता के लिये संघर्ष—जिस मगय पिलिस्पीन रपेन के अधीन था, तभी वहाँ राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आखीलन आरम्भ हो। गया था। पश्चिमी देशों के सम्पर्क में आंकर जहां फिलिस्पीन लोगों ने उनके धर्म न रहन नजन को स्वीकृत कर लिया था, बहां उनके विचारों का भी उनगर प्रभाव पह रहा था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के विचारों से फिलिप्पीन जोग भी अछते नहीं रहे थे। फिलिप्पीन के अनेक नवयवकों ने पश्चिमी देशों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और ये देशभक्त अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिये प्रयति-शील थे। इन देशभक्त नेताओं में जोसे रिजाल मकिदो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मर्कादों के प्रयत्न से फिलिप्पीन में राष्ट्रीय आन्दोलन ने बहत उग्र रूप धारण किया । स्पेनिश सरकार ने इस आन्दोलन को क्चलने के लिये अत्यन्त उग्र उपायों का अवलम्बन किया। १८९६ में मकदि को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे प्राण दण्ड दिया गया । पर रिजाल मकदों की मृत्य के साथ फिलिब्पीन स्वतन्त्रता के आन्दोलन का अन्त नहीं हो गया । अगुइना दो नामक नेता के नेतृत्व में फिलिप्पीन लोगों ने अपने आन्दोलन को जारी रखा । जिस समय स्पेन और अमेरिका में युद्ध जारी था, फिलिप्पीन लोगों ने अपनी स्वतःत्रता की घोषणा कर दी और अगइनात्दों के नेत्त्व में रिपब्लिकन सरकार का संगठन कर लिया। अमेरिका ने स्पेन को तो युद्ध में परास्त कर दिया था, पर फिलिव्यीन देशभक्तों को परास्त कर सकता सूगम बात नहीं थी । उन्होंने डटकर अमेरिकन सेनाओं का मुकाबला किया। पर अमेरिका जैसे शक्तिशाली राज्य का देर तक मुकाबला कर सकना फिलिप्पीन लोगों के लिये सम्भव नहीं था । १९०१ में अग्रे इनाल्दो गिरफ्तार कर लिया गया और १९०२ में अमेरिकन लोग फिलिप्पीन द्वीप राम्ह में अपना शासन भलीभांति स्थापित कर सकने में समर्थ हो गये। पर इसमें सन्देह नही, कि इस समय फिलिप्पीन लोगों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना भलीभांति विकसित हो चुकी थी, और वे अमेरिकन शासकों का विरोध करने के लिये कटिबंब थे।

अमेरिका का शासन—िफिल्पीन द्वीप समूह पर अपने शासन को व्यवस्थित रूप से स्थापित कर अमेरिकन लोगों ने उसकी आन्तरिक उन्नति पर ध्यान विया। बहुत से नये स्कूलों की स्थापना की गई। इनमें अध्यापन का कार्य करने के लिये सैंकड़ों शिक्षकों की अमेरिका से बुलाया गया। अंग्रेजी भाषा को स्कूलों में मुख्य स्थान दिया गया और उसी को शिक्षा का माध्यम नियत किया गया। स्कूलों के अतिरिक्त बहुत से कालिजों और अनेक युनिर्वासिटियों की भी स्थापना की गई। अमेरिका के प्रयत्न से फिलिप्पीन में शिक्षा का इतनी तेजी के साथ दिस्तार हुआ, कि १९२० तक वस लाख से भी अधिक विद्यार्थ फिलिप्पीन द्वीप समृह के विद्विष्ट शिक्षणालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। डेढ़ करोड़ के लगभग की आबादी के देश में दस लाख विद्यार्थिं का शिक्षा प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि अमेरिकन सरकार वहां शिक्षा के विस्तार के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रही थी।

फिलिज्पीन के स्वास्थ्य की उन्नति के लिये भी अमेरिकन सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दिया। इन द्वीपों में हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया, तपेदिक आदि का बहुत जोर रहताथा। स्वास्थ्य रक्षा के साधनों की उन्नति के कारण फिल्पिन में अकाल मृत्यु की मंख्या बहुत कम हो गई।

अमेरिका के प्रयत्न से फिलिप्पीन द्वीप समूह के आर्थिक विकास में भी बहुत सहायता मिली । रेलवे लाइनों, सड़कों व पुलों के निर्माण पर सरकार ने बहुत -ध्यान दिया । फिलिप्पीन की बहुत सी उपजाऊ भूमि किश्चियन मिशनों की सम्पत्ति थी। सरकार ने इस जमीन को मिशनों से खरीद कर छोटे छोटे ट्कड़ों में विभक्त किया और उन्हें फिलिप्पीन किसानों को बेच दिया । १९०९ के बाद अमेरिका और फिलिप्पीन में व्यापार की भी बहुत उन्नति हुई। अमेरिकन पूंजी के उपयोग से बहुत से नये कारोबार वहां विकसित हुए। १९३१ तक फिलिप्पीन में लगी हुई अमेरिकन पूंजी ८०,००,००,००० रुपये के लगभग तक पहुंच गई थी। यह पूंजी प्रधानतया बैंकों, यातायात के साधनों और खेती में लगाई गई थी। व्यवसायों के विकास पर अमेरिका ने बहुत ध्यान नहीं दिया था। खेती के साथ सम्बन्ध रखने वाल कुछ व्यवसाय ही इस समय तक फिलिप्पीन में विकसित हुए थे। चीनी और चावल की मिलों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के कारखाने अभी वहां स्थापित नहीं हए थे। पर खेती और व्यापार द्वारा फिलिप्पीन की आधिक समृद्धि निरन्तर बढ़ रही थी। आर्थिक उन्नति के कारण वहां की जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जाती थी । १९०३ में फिलिप्पीन की कुल आबादी ७५,००,००० थी । १९१८ में वह १,०३,००,००० और १९३९ में १,६३,००,००० हो गई थी।

शिक्षा की उन्नति और आधिक समृद्धि के बावजूद भी फिल्फिपीन लोग अमेरिकन शासन से संतुष्ट नहीं थे। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना उनमें भलीभांति विवासित हो चुकी थी। इसलिये अमेरिकन आधिपत्य से मुक्त होकर स्वराज्य स्थापित करने की आकांक्षा उनमें तीन्न रूप से विद्यमान थी। इस दशा में अमेरिकन सरकार ने धीरे धीरे स्वराज्य स्थापित करने की नीति को अगना कर फिल्फिगीन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। स्वातन्त्र्य युद्ध में फिल्फिगीन लोगों का परारत कर १९०२ में अमेरिका ने वहां जिस शासन को स्थापित किया। उनमें राज्यार का प्रथान अधिकारी गवर्नर जनरल को बनाया गया, जिसकी नियुवित अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा वी जाती थी। फिल्फिगीन का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम हावर्ड टाफ्ट की नियत किया गया। ये गज्जन आगं चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति पर गर भी निविध्यत हुए थे। १९०७ में फिल्फिगीन में गहर पहल पालिकामेट की स्थापना की गई, जिसमें दी सभाएं होती थीं, अतिनिधि तथा और अमीका। प्रतिनिधि

सभा के सदस्यों को जनता निर्वाचित करती थी, और दूसरी सभा (कमीशन) के सदस्यों को अमेरिकन राष्ट्रपित मनोनीत करता था। कमीशन के सदस्यों की संस्थों की अमेरिकन राष्ट्रपित मनोनीत करता था। कमीशन के सदस्यों की संस्था ९ होती थी, जिनमें ५ अमेरिकन और ४ फिलिल्पीन होते थे। १९१३ के इस शासन विधान में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपित श्री. बुडरो विल्सन थे। वे लोकतन्त्रवाद के प्रवल समर्थक थे। उन्होंने यह व्यवस्था की, कि फिलिल्पीन की द्विताय सभा (कमीशन) में फिलिल्पीन लोगों का बहुमत रहे और सरकार के विविध गदों पर फिलिल्पीन लोगों को अधिक संख्या में नियत किया जाया करे। फिलिल्पीन हीप समृह में निवास करनेवाल अमेरिकन लोग इन सुधारों के विरोधी थे। पर यह प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) का समय था और संसार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तिया जोर पकड रही थीं। उस दशा में १९१६ में अमेरिका की कांग्रेस ने एक नया बिल पास किया, जिसके अनुसार फिलिल्पीन की दूसरी सभा (कभीशन) के सदस्यों को भी जनता हारा निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गई।

१९२१ में अमेरिका ने फिलिप्पीन के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया। वहां के गवर्नर जनरल के पद पर श्री. लिओनाई वह को नियत किया गया, जो फिलि-प्पीन के स्वराज्य आन्दोलन का विरोधी था । उसका विचार था, कि अभी फिलिन् णीन लोग अपना शासन स्वयं करने योग्य नहीं हुए है, और अमेरिका को वहां अपना जासन मृद्दं रूप से कायम रखना चाहिये। श्री. वड की नीति का यह परिणाम हुआ, कि फिलिप्पीन के शासन में और अधिक मुधार स्थगित कर दिये गये। यह बात फिलिप्पीन लोगों को बहुत नापसन्द थी। महायद्ध की समाप्ति पर संसार के प्रायः सभी देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के आन्दोलन प्रयल हो रहेथे। फिलिप्पीन द्वीप समृह भी ममय की इस लहर से अछ्ता नहीं बचा था। परिणाम यह हुआ, कि फिलिप्पीन देशभक्तों ने अपने देश की स्वतन्त्रता और अमेरिकन आधिपत्य के विरुद्ध प्रचण्ड आन्दोलन किया। अनेक स्थानों पर हड़तालें व विद्रोह भी हुए। फिलिप्पीन में स्वतन्त्रता का आन्दोलन इतना जोर पकड़ गया था, कि अमेरिकन सरकार के लिये उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं रहा था । अतः विवश होकर अमेरिका की कांग्रेस ने १९३४ में फिलि-प्पीत के सम्बन्ध में एक नये कानून को स्वीकृत किया। १९३४ के इस कानून (जो टाइडिग्स-मैकडफ कानून के नाम से प्रसिद्ध है) के अनुसार फिलिप्पीन क्री यह अधिकार दिया गया, कि वह अपने लिये नये संविधान का स्वयं निर्माण कर सके। पर उसे यह अवसर नहीं दिया गया, कि वह अमेरिका के प्रभत्त्व से मक्त होकर पूर्ण रूप से अपनी स्वाधीनता को कायम कर सके । अमेरिका और फिलिप्पीन में बगा

नम्बन्ध रहेगा, और फिलिप्पीन के शासन पर अमेरिकन सरकार का किस अश नक अभूत्व रहेगा, यह बान भी इस कानून द्वारा निश्चित कर दी गई थी। यद्यपि बहुत से फिलिप्पीन लोग इस कानून से संतुष्ट थे, तथापि ऐसे राष्ट्रवादी देशभक्तों की बहुं कभी नहीं थी, जो १९३४ के कानून को अपर्यान्त और असन्तोषजनक समझते थे। यही कारण है, कि आंशिक स्वराज्य की स्थापना हो जाने के बाद भी फिलिप्पीन में भलीभांति शान्ति स्थापित नहीं हो सकी थी।

(३) इन्डोनीसिया और बोर्नियो

फिलिज्पीन हींप समूह के दक्षिण और मलाया के दक्षिण-पूर्व में जो बहुत से हींप पूर्व से पिहन्स की ओर हजारों मील तक फैले हुए हैं, पहले उन्हें ईस्ट इन्डीज नाम से कहा जाता था। उनका बड़ा भाग, जो हालैण्ड की अधीनना में था और जो अब तक भी डन्च साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखता है, इन्डोनीसिया कहाता है। ईस्ट इण्डीज के कुछ हीप ब्रिटेन और पोर्तुगाल को भी अधीन हैं, परहालैण्ड के मुकाबल में इस क्षेत्र में ब्रिटेन और पोर्तुगाल का प्रभुत्त्व बहुत कम है। ईस्ट इण्डीज के इन द्वीप समूहों में सुमाना, जावा, बाली, सोएम्बावा, फ्लोरेस, तिमोर, बांगका, बोनियो, सेलेबस, मोलक्का, न्यू गाइनिआ और पापुआ प्रमुख हैं। इनमें से तिमोर हींप का बड़ा भाग पोर्तुगाल के अधीन हैं, और उत्तरी बोनियो पर ब्रिटेन का प्रभुत्त्व है। ईस्ट इन्डीज के प्रायः अन्य सब प्रदेश हालैण्ड के प्रभाव में हैं, और इस समय वहां इन्डोनीसियन रिपब्लिक स्थापित हैं, जो भारत के समान अपने भूतपूर्व शासकों के साथ अभी भी सम्बन्ध बनाये हुए हैं। ईस्ट इन्डीज के इन विविध प्रदेशों पर किम प्रकार जनमें अपनी स्वतन्त्रताका आन्दोलन प्रबल हुआ, इसी विषय पर हम एक प्रकार जनमें अपनी स्वतन्त्रताका आन्दोलन प्रबल हुआ, इसी विषय पर हम एक प्रकार जनमें अपनी स्वतन्त्रताका आन्दोलन प्रबल हुआ, इसी विषय पर हम एक प्रकार जनमें अपनी स्वतन्त्रताका आन्दोलन प्रबल हुआ, इसी विषय पर हम एक प्रकार जनमें अपनी स्वतन्त्रताका आन्दोलन प्रबल हुआ, इसी विषय पर हम एक प्रकार जनमें अपनी स्वतन्त्रताका आन्दोलन प्रवल हुआ, इसी विषय पर हम एक प्रकारण में प्रकाश डालेंगे।

प्राचीन इतिहास—इन्डोनीसिया के विविध द्वीपों में सबसे अधिक समृद्ध व आबाद जावा है। उसका प्राचीन नाम यबद्वीप था। उसके इतिहास का ज्ञान हमें तब शुरू होता है, जब वहां भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। दूसरी सदी इ० प० में वहां का राजा देववर्षन था, जिसने १३२ ई० में अपना राजदूत कान के सम्बाद के राजदरबार में भेजा था। पश्चिमी जावा में संस्कृत भाषा में लिखे हुए चार शिलालेख मिले हैं, जो छठी सदी के पहले के हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से लीटता हुआ ४१४ ई० के लगभग जावा पहुंचा था। जिस जहाज से वह जावा उतरा था, उसमें २०० भारतीय लापारी भी उसके साथ थे।

फाइयान ने लिखा है, कि जावा में शैव और वैष्णव वर्मी का बहुत प्रचार है। जावा के समीप बाली द्वीप में भी पांचवीं सदी तक भारतीयों का उपनिवेश स्थापित हो चुका था। ५१८ ई० में यहां के भारतीय राजा ने अपना एक दूत चीनी सर्फ्रींट् की सेवा में भेजा था।

चौथी सदी में सुमात्रा में भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी, जिसेका नाम श्रीविजय था । संस्कृत भाषा में लिखे हुए बहुत से शिलालेख यहां उपलब्ध हए हैं, जिनसे श्रीविजय के राजाओं की शक्ति और वैभव का परिचय गिलता है। श्रीविजय के कतिपय राजाओं ने प्रायः सम्पूर्ण इन्डोनीसिया व मलाया को जीतकर अपने अधीन कर लिया था । चौथी सदी में बोनियो में भी भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। ४०० ई० के लगभग केचार शिलालेख यहां मिले हैं, जिनमें राजा अञ्चवमंन के पुत्र राजा देववमंन के दानपुष्य और यज्ञोंका वर्णन है। संस्कृत के ये लेख जिन स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं, वे राजा मुलवर्मन के यज्ञों में स्तूप के रूप में प्रयुवत होने के लिये बनाये गये थे। इन युक्तों के अवसर पर वप्रकेश्वर तीर्थ में बीस हजार गीवें और बहुत सा धन दान दिया गया था। इन्डोनीसिया के ये सब प्राचीन उपनिवेश शुद्धरूप में भारतीय थे। यदि बीच में समुद्र का व्यवधान न होता, तो इन्हें भारत का ही प्रदेश माना जा सकता था। इनमें प्राप्त शिलालेखीं की भाषा विशद्ध संस्कृत है। इनके राजा भारतीय आदर्शों के अनुसार शासन करते थे। उनके आचार विचार, चरित्र, व्यवहार आदि सब भारतीय थे। जैव, वैष्णव और बौद्ध तीनों भारतीय धर्म इन उपनिवेशों में प्रचलित थे। इनमें प्राप्त शिलालेखों से ज्ञात होता है, कि भारत की पौराणिक गाथायें, देवी देवता, सामाजिक आचार विचार, सब इनमें उसी प्रकार प्रचलित थे, जैसे कि भारत में । विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, नन्दी, स्कन्द, महाकाल आदि की मूर्तियां बोर्नियो में प्राप्त हुई हैं। भारत के चक्र, गदा, शंख, पद्म, त्रिशुल आदि सब चिन्ह जावा में मिले हैं । इन उपनिवेशों में भारत का पौराणिक धर्म अविकल रूप से फैला हुआ था। गंगा की पवित्रता तक की भावना इनमें प्रचलित थी । पौराणिक धर्म के साथ साथ अष्टाङ्किक बौद्ध धर्म का भी इन दीपों में प्रचार था। इस क्षेत्र में बीद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय गुणवर्मन को है, जो काश्मीर का एक राजकुमार था। राजा बनने के स्थान पर इसने भिक्षु बनना अधिक पसन्द किया और जावा जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बाद में इन्डोनीसिया के विविध द्वीप जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए, उसमें गुणव्यान का कर्त त्व बहुत अधिक था। उसकी कीर्ति इतनी वढ़ गयी थी, कि चीन के सम्राट् ने उसे अपने यहां निमन्त्रित किया था।

इन्डोनीसिया के विविध द्वीपों में बौद्ध व पौराणिक धर्म की सत्ता पन्द्रहवीं सदी

तक कायम रही । पन्द्रहवी सदी में इस क्षेत्र में अरब के मुसलिम व्यापारियों ने बड़ी संख्या में आना शुरू किया। इस समय भारत में भी मुसलिम आकान्ता अपने क्रिप्यत्य को स्थापित करने में तत्पर थे। बौद्ध और पौराणिक धर्मों में बहुत हास हो गया था और इन्होनीसियन प्रदेशों के विविध भारतीय राजा निर्वल हो गये थे। इसके विपरीत इस्लाम में बहुत जीवन था। अरब व्यापारियों के साथ बहुत से मुसलिम प्रचारक भी उस समय जावा, सुमात्रा, बाली, बोनियो आदि जाने लगे, और उनके प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ, कि बहुसंख्यक जनता ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। केवल बाली हीप ही ऐसा रह गया, जहां के लोगों ने इस्लाम को स्वीकृत नहीं किया। वहां की जनता अब तक भी पौराणिक हिन्दू धर्म को मानती है। पर अन्य द्वीपों में जो लोग मुसलमान बने, उन्होंने अपने पुराने देवी देवताओं की उपासना का सर्वथा परित्याग नहीं कर दिया। उतपर अब तक भी पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रभाव अनेक अंशों में विद्यमात है।

पाइचात्य देशों से सम्पर्क-रालहवीं सदी के शुरू में पोर्त्गीज लोगों ने इन्डो-करोत पारे के के कि वे अल्व करना अक्ता अक्ता का शिक्ष । इस समय इन द्वीपों की राजनीतिक १८ १ वर्ष को को । का को एक एक ६ वेतशाली राजा नहीं था, जिसके शासन को सब लोग स्वीकार करते हों। सब जगह बहुत से छोटे छोटे राजा विद्यमान थे, जो इस्लाम को स्वीकृत कर चके थे। ये राजा प्रायः आपस में लड़ते रहते थे। इस दशा में पोर्तुगीज लोगों के लिये यह कठिन नहीं था, कि व्यापार की वृद्धि के साथ साथ अपने राजनीतिक प्रभत्त्व की स्थापना में भी सफल हों। १५११ में पोर्तुगीज लोगों ने मलक्का को जीत लिया। व्यापारिक दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व था। भारत से इन्डोनीसिया के द्वीपों में आने जाने वाले जहाजों के लिये मलक्का के जलडमरू मध्य से ग्जरना आवश्यक था। मलक्का पर कब्जा करके पोर्त्गीज लोगों ने उसे एक दर्ग के रूप में परिवर्तित किया और उसे अपने सामुद्रिक व्यापार का प्रधान केन्द्र बनाया । इन्डोनीसिया के अन्य द्वीपों में भी उन्होंने अनेक बन्दरगाहों पर अपना प्रमुत्त्व स्थापित किया । पर पोर्तुगीज लोगों की नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं थी । पूर्वी एशिया के व्यापार को अपने हाथों में करके समृद्ध होना ही उनका मुख्य उद्देश्य था । अदः गोठहवीं तदी में उन होत के द्वीपों की राजनीतिक स्वतन्त्रता के या रही। पोर्तुगीज व्यापारियों के साथ साथ रोमन कैयोलिक पादिरयों ने भी इन द्वीपों में आना जाना शुर किया । क्येक्टियर के नेत्रक में बहुत से पादिख्यों ने यह उसीम किया, कि इन ही में के नियारियों को ईसाई धर्म में बीक्षित करें। पर उन्हें अपने प्रयत्न में विद्याप उक्तलता नहीं हुई। लगभग एक सदी पहले इनके

निवासियों ने इस्लाम को स्वीकार किया था, और उनमें अपने नये धर्म के प्रति निष्ठा बहुत प्रबल थी।

हालैण्ड का प्रभुत्त-गतरहवीं मदी में हालैण्ड के डच लोगों ने दक्षिण ्यूजी एशिया के इन द्वीपों में आना गुरू किया । सबसे पहले १६०५ में उन्होंने अम्बोयना द्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । १६४१ में उन्होंने मलक्का को भी पोर्तगीज लोगों से जीत लिया । मलबका पर प्रभूत्व स्थापित हो जाने से दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में इच लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई। इच लोग केवल व्यापार से ही संतृष्ट नहीं थे । अंग्रेजों के समान वे भी इन प्रदेशों की राजनीतिक दुर्वलता से लाभ उठाकर इन्हें अपने प्रभन्त में लान के लिये उत्सुक थे। जिस प्रकार इङ्गलैण्ड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना भारत आदि प्राच्य देशों के साथ व्यापार का विस्तार करने के लिये की गई थी, वैसे ही हालैण्ड में भी एक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की गई। इङ्गलिश कम्पनी के समान इच कम्पनी ने भी व्यापार के साथ साथ राजनीतिक प्रभत्त्व की स्थापना का भी उद्योग किया। इस उद्योग में उसे सफलना भी मिली। जावा में बटेविया को अपना केन्द्र बनाकर उसने अपने राजनीतिक उत्कर्ष का प्रारम्भ किया और उस द्वीप में शासन करनेवाले विविध राजाओं व मूळतानों को अपना वगवतीं बना लिया। अपने व्यापारिक हिन्हीं की रक्षा के नाम पर इच लोगों ने इन द्वीपों में अपनी सेनाओं की स्थापना की और इनके शासकों की राजनीतिक दुवेलता तथा पारस्परिक झगड़ों का लाभ उठाकर अपने राजनीतिक प्रभत्त्व को कायम कर लिया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समान इन्डोनीसिया में हालैटका जो प्रभूत्वस्थापित हुआ, वह वहांकी ईस्ट इण्डिया सम्पनी के द्वारा ही हुआ था। अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में फांस में राज्यकान्ति हुई । फोञ्च कान्तिकारी सेनाओं ने हालैण्ड का भी विजय कर लिया और वहां एक नई कान्तिकारी सरकार की स्थापना की । इस सरकार ने १७९८ में इच ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त किया और इन्डोनीसिया के शासन को अपनी अवीनता में कर लिया। नैपोलियन के युद्धों के समय में फ्रांस व उसके अधीतस्य राज्यों के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि समूद्र पार के प्रदेशों गर अपना आधिपत्य कायम रख सकों, क्योंकि समुद्र में ब्रिटेन की शक्ति अजेय थी। क्योंकि हालैण्ड पर नैपोलियन का कब्जा था, अतः ब्रिटेन ने इन्डोनीसिया पर अपना अधिकार कायम कर लिया । १८११ से १८१९ तक इन द्वीपीं पर ब्रिटेन का प्रमुखि रहा । वीएना की कांग्रेस (१८१४-१५) द्वारा ये प्रदेश फिर से हालैण्ड के संपूर्व किये गये, और १८१९ में उसने इन पर अपने प्रमृत्व की पुनः स्थापना की ।

वीएना की कांग्रेस के निर्णय द्वारा जब १८१९ में इन्डोनीसिया के विविध

द्वीपों पर हालैण्ड ने अपना अधिकार वायम किया, तो अनेवा प्रदेश ऐसे थे, जहां उसकी राजनीतिक सत्ता को अविकार रूप से स्वीकृत नहीं किया जाता था। जो ौंदेश उसके अधिकार में थे, वहां की जनता भी उसके शासन से अमन्तीष अनुभव बारती थीं । इसीलिये १८२५ में जावा में विद्रोह हो गया । यह विद्रोह पांच साल तक जारी रहा । इसे शान्त करने और जावा के पूराने शासकों को पूर्ण रूप से अपना वशवर्ती बनाने में हालैण्ड को बहुत शक्ति लगानी पड़ी । पर १८२५-३० के विद्रोह का यह परिणाम हुआ, कि जावा का मुख्य भाग डच सरकार के सीधे कासन में आ गया और उस दीप में जो प्राने राजवंश कायम भी रहे, वे भारत के रियासती राजाओं के समान डच सरकार के पूर्णरूप से बजवर्ती हो गये। १९३० के बाद समात्रा द्वीप में भी अनेक पुराने राजवंशों का अन्त कर उन द्वारा शासित प्रदेशों का शासन डच सरकार ने अपने हाथों में ले लिया । पर सुमात्रा में कितपय प्रदेश ऐसे भी थे, जो उन्नीसनीं सदी में निरन्तर डच सरकार के साथ संघर्ष में व्यापत रहे। सुभावा की सुसलिम जनता यह नहीं सह सकती थी, कि उस पर विधर्मी डेच लोगों का शासन कायम हो। इसीलियं वे बहुत समय तक संघर्ष में तत्पर रहे। पर बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग तक सम्पूर्ण समात्रा पूर्णक्य से हालैण्ड के अधीन हो 💆 गया था । इसी प्रकार बोर्नियो को अपनी अधीनता में लाने में भी डच लोगों की पर्याप्त कठिनता वा सामना वारना पडा था । इस द्वीप के पश्चिमी तट पर चीनी लोगों की अनेक बस्तियां वसी हुई थीं । चीनी लोग डच सरकार की अधीनता को स्वीकृत भारते के लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने डटकर हालैण्ड का मुक्त बला किया । मुदीर्घ समय के संघर्ष के बाद १८८० में डच लोग बोर्नियों की चीनी बस्तियों को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुए । समद्र तट गए विद्यमान चीनी बस्तियों को अपने अधीन कर उच लोगों ने अन्दर के प्रदेशों की विजय प्रारम्भ की और १९३१ तक प्रायः सम्पूर्ण वोनियो पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

बाली द्वीप पर डच लोगों का तभी प्रभुक्त कायम हो गया था, जब कि जाना उनकी अधीनता में आया था। पर १९०८ में वहां की हिन्दू जनता ने डच शासन के विषय विद्रोह कर दिया, और इसे शान्त करने में डच लोगों को बहुत कठिनता का सामना करना पड़ा। रोलेवम द्वीप को अपनी अभीनता में लाने में भी इन लोगों की बहुत कठिनाई हुई। इन हींग में अनेक पुसल्या मुख्तानों का कारन था, ओ इच लोगों का मुकायला करने के लिये बादियल थे। १९१० तक हालैण्ड और एक मुख्तानों में अनेक बाद युख हुए। पर अन्त में इच लोगों की विजय हुई और सेलेवस के विविध शुख्तानों की परास्त कर उस हींग पर हालैण्ड ने अपना प्रभुक्त कारम कर लिया। इनसे यह समझने में कटिनाई नहीं होगी, कि इन्होतीरिया के

विविध द्वीभों के निवासियों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना प्रवल रूप से विद्यमान थी। उन्हें इच लोगों का जासन पसन्द नहीं था, और इसीलिय वीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में भी वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये तत्पर थे में पर हालैण्ड जैसे उन्नत व शक्तिशाली देश का मुकावला कर सकता उनके लिये सुगम नहीं था। यदि इस समय इन्डोनीसिया में किसी एक शक्तिशाली सुलतान का शासन होता, और यह देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त न होता, तो शायद वह डच सेनाओं से अपनी रक्षा करने में समर्थ होता। पर एशिया के अन्य देशों के समान इन्डोनीसिया की दशा भी इस समय अच्छी नहीं थी। यही कारण है, कि वह हालैण्ड का मुकावला नहीं कर सका और धीरे-धीरे उस पर डच सरकार का आध्यत्व स्थापित हो गया।

नैपोलियन के युद्धों की समाप्ति पर जब जावा, वाली आदि द्वीपों पर हालैण्ड का आविपत्य पुनः स्थापित हुआ, तो वहां के शासन को डच सरकार ने सीधा अपने हाथों में छे लिया। इन द्वीपों पर अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने में डच सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा था। विशेषतया जावा आदि में हए विद्रोहों को शान्त करने में हालैण्ड की धन व जन की बहुत अधिक हानि हुई थी। अत: डच लोग इस बात के लिये उत्सुक थे, कि अपने साम्राज्य के इन प्रदेशों को अपनी आर्थिक समद्धि का सावन बनावें। इसीलिये उन्होंने इन्डोनीसिया में एक नई आर्थिक पद्धति का प्रारम्भ किया, जो 'कल्चर सिस्टम' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक इन्डोनीसिया की प्रधान फसल चावल थी और नावल की पैदाबार का एक निश्चित हिस्सा सरकार मालगुजारी के रूप में किसानों से वसल किया करती थी। अब डच सरकार ने किसानों से वसूल होनेवाली मालग्जारी के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की, कि सब किसान अपनी जमीन के एक हिस्से में ऐसी फसलें बोवें, जिनको युरोप के बाजारों में सुगमता के साथ बेचा जा सके । ये फसलें प्रधानतया ईख और काफी की थीं । किसान लोग अपनी जमीन के एक भाग पर जो ईख या काफी बोते थे, उस सबको उन्हें मालगुजारी के रूप में डच सरकार के सुपूर्व कर देना पड़ता था। इसमें उनका जो समय लगता था या जो मेहनत उन्हें करनी पड़ती थी, उसकी कोई भी उजरत उन्हें नहीं मिलती थी। कल्चर सिस्टम के कारण इन्डोनीसियन किसानों की यह दशा हो गई थी. कि वे अपनी जमीन पर डच सरकार के लिये वेगार में खेती करते थे। ईख, काप्री जैसी फसलों के लिये किसानों को न केवल श्रम व समय का व्यय करना होता था. अपित रुपया भी पर्याप्त मात्रा में खर्च करना पड़ता था। इसका उन्हें कोई भी प्रति-फल प्राप्त नहीं होता था । डच सरकार को इससे बहुत अधिक लाभ था । गर्ने और

काफी सदृश महंगी वस्तुएं उसे इतने अधिक परिमाण में प्राप्त हो जाती थी, कि उनसे बुद्ध अगार सम्पत्ति संचित कर सकती थी। इनके लिये उसे कुछ भी कीमत नहीं देनी पड़ती थी। इन्डोनीसिया में अनेक स्थानों पर ईख से चीनी तैयार करने के लिये बड़ी बड़ी मिलें कायम की गई थीं, जो इच लोगों के प्रभुत्त्व में थीं। इन मिलों के लिये जो ईख चाहिये था, उसे इन्डोनीसियन किसान सरकार की वेगार में उत्पक्ष करते थे। इच सरकारी अफसर भी इस दशा से खूब लाभ उठाते थे। कौन किसान कितनी जमीन पर बेगार में खेती करे, क्या फसल बोवे और अपनी कितनी पैदावार सरकार को दे— इन बातों की व्यवस्था करते हुए वे दिल खोलकर रिश्वत लेते थे। कल्चर सिस्टम के कारण इन्डोनीसियन किसानों की दशा अर्थ दासों के समान हो गई थीं. जो अपनी ही जमीन पर दूसरे लोगों के लिये खेती करते थे और अपनी मेहनत का खुद प्रतिफल नहीं प्राप्त कर सकते थे।

आखिर हालैण्ड के विचारशील लोगों का ध्यान कल्चर सिस्टम की वराइयों की और आकृष्ट हुआ। उन्नीसवीं सदी में यूरोप में सर्वत्र दास प्रथा के विरुद्ध भावना प्रबल हो रही थी । १८१४ में वीएना की कांग्रेस द्वारा दास प्रथा को नध्ट कुरने के लिये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। १८६० में अमेरिका में भी दास प्रयाका अन्त कर दिया गयाथा । हालैण्ड के साम्राज्य में इन्डोनीसियन किसानों की दशा वासों के ही सदश थी। अतः १८४८ में डच लोगों का ध्यान अपने साम्राज्य के इस कलक की ओर आकृष्ट हुआ। अनेक पादरियों ने इस पद्धति के खिलाफ आवाज उठाई। इन्डोनीसिया के एक डच अफसर ने इस प्रथा के खिलाफ एक उपन्यास लिखा, जिसने हालैण्ड में इसके विरुद्ध भावना उत्पन्न करने में वैसा ही काम किया, जैसा कि 'टाम काका की कृटिया' नामक उपन्यास ने अमेरिका में दास प्रया के विरुद्ध भावना को उत्पन्न करने के लिये कियां था। इन्डोनीसियन देशभयत भी इस प्रथा का अन्त करने के लिये संघर्ष में तत्पर थे। इस दशा में उन्नीसवीं सदी के अन्त तक कल्चर सिस्टम की समाप्ति कर दी गई और इन्डो-नीसियन किसान अपनी जमीनों पर स्वेच्छापूर्वक खेती करने के लिये स्वतंत्र हो गये। अब वे बेगार में खेती नहीं करते थे और न ही डच पूंजीपति सरकारी सहायता द्वारा उनका शोषण ही कर सकते थे। इन्डोनीसियन लोगों की आर्थिक उन्नति में ्रक्तें बहुत सहायता मिली।

सादीय स्वतन्त्रता की भावना—देशी तगय इन्डोनीसिशा में राजनीतिक अधिकारों के छियं भी संघर्ष का प्रारम्भ हुआ। संसार के अन्य दशों के समान एन्डोनीसिया में भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन कल मनत् रहा था। पाश्यास्य पेतों में शिक्षा प्राप्त कर जो इन्डोनीसियन नवयुनक अपने देस को बागस आहे थे, वे नवयुग की प्रवृत्तियों से भलीभांति परिचित होते थे । हालैण्ड में भी एंसे राज-नीनिक दलों की सत्ता थी, जो अपने साम्राज्य के अन्तर्गत देशों के शासन में उद्धूर र्नाति का अनसरण करने के पक्षपाती थे । इसका यह परिणाम हुआ, कि बीसेवी सदी के प्रारम्भिक भाग में इन्होनीसियन स्वतन्त्रता के आन्दोलन ने अच्छा प्रवल रूप धारण कर लिया । १९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर इस आन्दोलन को और भी अधिक वल मिला। ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्रराष्ट्र इस समय डंके की चांट के साथ यह घोषित कर रहे थे, कि वे लोकतन्त्रवाद और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्तीं के लिये जर्मनी और आस्ट्रिया के खिलाफ यद्ध में तत्पर हुए हैं। १९१७ में जब अमेरिका महायुद्ध में शामिल हुआ, तो उसके राष्ट्रपति विल्मन ने भी इन्हीं सिद्धान्तों की दूहाई दी। यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि इन सिद्धान्तों का प्रभाव इन्डोनीसिया पर भी पड़े । महायद्ध की समाप्ति पर इन द्वीपों में अनेक स्थानों पर विद्रोह हए । १९२० में जावा और सुमात्रा में डच शासन के विरुद्ध वाकायदा विद्रोह हो गया। यह विद्रोह अनेक वर्षों तक जारी रहा, और इसका दमन करने में डच सरकार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। १९३० के बाद इन्डोनीसिया में बिद्रोह की प्रवित्त कुछ मन्द पड़ गई। इसका कारण यह था, कि इस समय जापान मञ्च-रिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने में तत्पर हो गया था, और इन्डोनीसियने नेता इस बात को अनुभव करते थे, कि उनके देश की अव्यवस्थित दशा का लाभ उठाकर जापान उसे भी अपने साम्राज्यवाद का शिकार बना सकता है। साथ ही १९२७ में डच सरकार ने इन्डोनीसिया में आंशिक स्वराज्य की स्थापना का भी उद्योग किया था।

डच सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह इन्डोनीसिया के स्वातन्त्रय आन्दोलन की सर्वथा उपेक्षा कर सके। इसीलिये महायुद्ध के काल में १९१६ में वहां फोल्वसराड नामक विधान सभा (पालियामेन्ट) की स्थापना की गई थी। जुरू में फोल्वसराड का कार्य कातृन व शासन के मामले में परामर्श देना ही था, उसे स्वयं कातृन वना सकने का अधिकार नहीं दिया गया था। १९२७ में उच सरकार ने इन्डोनीसिया के शासन में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये। इस समय वहां बाकायदा विधानसभा की स्थापना की गई, जिसके दो तिहाई सदस्य निर्वाचित होते थे। एक तिहाई सदस्यों को उच सरकार मनोनीत करती थी। विधानहास का अध्यक्ष भी उच सरकार द्वारा नियुक्त होता था। इन मनोनीत सदस्यों में ५० फीसदी इच होते थे, ५० फी सदी से कुछ कम इन्डोनीसिया लोग और शेष इन्डोनीसिया में बसे हुए अन्य विदेशी लोग होते थे। इन विदेशियों में प्रधान स्थान चीनी और अरब लोगों का था। इन्डोनीसिया का शासन करने के लिये एक बाका-

यदा सिविल सर्विस संगठित थी । शुरू में इसके प्रायः सभी सदस्य डच लोग होते र्थ । हालैण्ड में इन डच कर्मचारियों को शासनकार्य की मलीभांति शिक्षा दी जाती औं और इन्हें इन्डोनीसिया की भाषा, रीति-रिवाज आदि से भलीभांति परिचित करा दिया जाता था । बाद में इन्डोनीसियन लोगों को भी सिविल सर्विस में लिया जाने लगा । १९४१ तक यह दशा आ गई थी, कि इन्डोनीसियन सिविल सर्विम में ८४ फीमदी के लगभग वर्म चारी इन्डोनीसियन लोग हो गये थे। पर उच्च राजकीय पदों पर अब भी डच कर्मचारी विद्यमान थे। शासन की दिष्ट से इन्डोनीसिया की हालत प्रायः वैसी ही थीं, जैसी कि १९३५ के शासन सुधार से पूर्व भारत में ब्रिटिश शासन की थी। १९२७ के शासन स्धारो द्वारा उच सरकार ने यह प्रयत्न भी किया था. कि इन्डोनीसिया को अनेक प्रान्तों में विभक्त कर उनमें स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाय । पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये कि इन्डोनीसियन नता इन सुधारों से संतुष्ट नहीं थे । वे इन्हें अपर्याप्त समझते थे, और अपने देश की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये उत्सुक थे। डच शासन से और हानि चाहे कुछ भी क्यों न हुई हो, पर यह लाभ भी हुआ था, कि सम्पूर्ण इन्डोनीसिया में राष्टीय एकता की भावना उत्पन्न हो गई थी । इसं क्षेत्र के विविध द्वीप सदियों के बाद एक बार फिर एक शामन में आये भे और डच शामन के विरुद्ध एक होकर संघर्ष करने है कारण उनमें अपने एक होने की अनुभृति भलीभांति विकसित हो गई थी।

नीसिया में टीन भी बहुत बड़े परिमाण में उपलब्ध हुई। इस धातु के उत्पादम में केवल मलाया ही उससे आगे था। गन्ने की खेती के कारण चीनी की भी बहुत सी मिलें इन्डोनीसिया में स्थापित हुई। १९४० के लगभग संसार में कुल मिलाकर जितनी चीनी तैयार होती थी, उसका ५ प्रतिशत अकेले जावा में होती थी। चीनी, चाय, टीन और पेट्रोलियम द्वारा इन्डोनीसिया की आर्थिक समृद्धि में बहुत अधिक सहायता मिली।

उन्नीसवी सदी तक इन्डोनीसिया के विदेशी व्यापार पर हाल एक का एक पिर्यथा। अन्य देशों का उसके साथ व्यापारिक सम्बन्ध नाममात्र को था। पर वीसवीं सदी में अन्य देश भी इन्डोनीसिया के विदेशी व्यापार में हाथ बटाने के लिये तत्पर हुए। विदेशी राज्यों ने वहां के व्यवसायों में अपनी पूंजी भी अधिक बड़ी मात्रा में लगानी शुरू की। अभेरिका, बिटेन, चीन, बेल्जियम, फांस, जर्मनी और जापान के पूजीपति इस देश में पूंजी लगाकर वहां के व्यवसायों से नफा कमाने के लिये प्रवृत्त हुए। विशेषतया जापान ने इस बात का बहुत प्रयत्न किया, कि इन्डोनीसिया के साथ अपने व्यापार का विकास करे। इस समय तक जापान व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अधिक उन्नति कर चुका था। उसका माल पाश्चात्य देशों के माल के मुकाबले में बहुत सस्ता पड़ता था। अतः इन्डोनीसिया के बाजारों में जापानी मार्क की मांग वड़ी तेजी के साथ बढ़ने लग गई थी। व्यापार की वृद्धि के साथ साथ जापानी लोगों में यह विचार भी विकसित होने लगा था, कि इन्डोनीसिया भी उनके साम्राज्य-प्रसार का उपयुक्त क्षेत्र है।

जनसंख्या में बृद्धि—संसार के अन्य देशों के समान इन्डोनीसिया में भी इस समय जनसंख्या नड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। इस दृष्टि से जावा और मदुरा (जावा के उत्तर में एक छोटा सा द्वीप) सबसे आगे थे। १८१९ में इन दो द्वीपों की आबादी ४५,००,००० के लगभग थी। १८५० के लगभग तक वह बढ़ कर १,००,००,००० हो गई थी। तीन चौथाई सदी के बाद १९३० में जावा और मदुरा की जनसंख्या ४,१०,००,००० तक पहुंच गई थी। १८१९ से १९३० तक एक सदी से कुछ ही अधिक समय में इन द्वीपों की आबादी में दस गुना के लगभग की वृद्धि हुई थी। जावा और मदुरा के क्षेत्रफल को दृष्टि में रखते हुए यह आबादी बहुत ही अधिक थी। वहां ८०० व्यक्तियों का एक वर्गमील में निवासथा। इसे काल में भारत में एक वर्गमील में निवास करनेवाले लोगों की संख्या २३० कि लगभग थी। संसारका कोई भी देश ऐसा नहीं था, जहां आबादी इतनी अधिक समन हो, जितनी कि जावा और मदुरा में थी। इसमें सन्देह नहीं, कि इन द्वीपों की जमीन बहुत अधिक उपजाऊ है, पर इतनी अधिक आबादी का भरण-पोषण कर सकना

उसके लिये सम्भव गहीं था। इसीलिये डच सरकार ने यह प्रयत्न किया, कि इन दूषों के निवासियों को इन्डोनीसिया के अन्य प्रदेशों में बसने के लिये प्रेरित करे। कैं भाता, बोर्नियो आदि में जनसंख्या अधिक नहीं थी। पर डच सरकार के प्रयन्नों के बावजूद भी १९३० में केवल १३,००,००० जावानिवासी अन्य प्रदेशों में जाकर आबाद हुए थे। इस प्रसंग में यह भी निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा, कि १९३० में इन्डोनीसिया की कुल आबादी छः करोड़ के लगभग थी। इसमें से चार करोड़ से भी अधिक आदमी केवल जावा और मदुरा में निवास करते थे, जब कि इन दो हीपों का क्षेत्रफल केवल ५१,०३२ वर्गमील है, और इन्डोनीसिया के अन्य प्रदेश क्षेत्रफल में ६,८४,२३६ वर्गमील हैं। इन्डोनीसिया की जनसंख्या की समस्या का इससे भलीभांति अन्दाज किया जा सकता है।

ईसाई धर्म का प्रचार-इन्डोनीसिया के बहुसंख्यक निवासी इस्लाम के अनु-यायी हैं, यद्यपि वाली द्वीप में पौराणिक हिन्दू धर्म का प्रचार है। पर सुमात्रा बोर्नियो आदि के पर्वत प्रधान व जांगल प्रदेशों में ऐसी भी अनेक जातियों का निवास है, जो अपने पुराने देवी-देवताओं की पूजा करती हैं। जब डच लोगों ने इन्डोनी-सियन द्वीपों को अपने प्रभाव में लाना शुरू किया, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि 🧦 ह्माई मिजनरी भी वहां अपने घर्म का प्रचार करने में तत्पर हों । डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता इन मिशनरियों को प्राप्त थी। इच लोग प्रोटेस्टेन्ट धर्म के अनवायी थे, अतः शुरू में जो ईसाई पादरी इन्डोनीसिया में धर्म प्रचार के कार्य के लिये आये, वे भी प्रोटेस्टेन्ट ही थे। बीसवीं सदी में रोमन मैथोलिक पादरियों ने भी इन द्वीपों में कार्य शुरू किया। पर ईसाई लोगों को इन द्वीपों में विशेष सफलता नहीं हुई। १९४१ तक ये केवल बीस लाख आदिमयों ो ईसाई धर्म में दीक्षित कर सके थे। पर कुल जनसंख्या के तीन प्रतिशत भाग का ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेना भी साधारण बात नहीं थी। ईसाइयों की सफलता का मुख्य कारण यह था, कि उन्होंने विशेषतया उन लोगों में कार्य किया, जो मुसलिग व हिन्दू धर्मों के प्रभाव से वञ्चित थे और सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। जिस प्रकार भारत में गांड, भील आदि जातियां पिछड़ी हुई वंशा में हैं, और उनमें ईसाई लोग विशेष रूप में कार्य करते रहे हैं, वैसे ही इन्डोनीसिया के ईसाई पादरी वहां की पिछडी हई ुजानियों में कार्य करते थे, और उनमें अपने धर्म का प्रचार करने में उन्हें सफलता भी ग्राप्त हुई थी।

पोर्तुगाल द्वारा अधिकृत प्रदेश—सोलहवीं सदी के शुरू में पोर्तुगील लोगों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन द्वीपों में अपने व्यापार का विस्तार प्रारम्भ किया था, यह हम पहले लिख चुके हैं। पोर्तुगाल ने इस क्षेत्र में अपने सामान्य विस्तार पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, उसका ध्यान व्यापार पर अधिक था। फिर भी जी कितिय प्रदेश वाद में उसके प्रभुत्त्व में आ गये थे, वे भी अठारहवीं सदी में उसके हाथ से निकलकर हाल छ की अधीनता में आ गये थे। उन्नीसवीं सदी में तिर्मीर हीय का पूर्वी भाग व उसके समीप के कितपय छोटे-छोटे द्वीप ही पोर्तुगाल के प्रभुत्त्व में रह गये थे। पर इनके सम्बन्ध में भी हाल एड और पोर्तुगाल में प्रायः झगड़ा होता रहता था। १८५९ और १८९० में इन दोनों देशों ने परस्पर सिध करके दन झगड़ों का अन्त किया। इन सिध्यों हारा हाल एड ने अनेक छोटे-छोटे द्वीप पोर्तुगाल से वरीद लिये और तिमोर द्वीप में दोनों राज्यों की सीमा का ठीक प्रकार से निक्चय कर दिया गया। बीमबी सदी में दक्षिण-पूर्वी एशिया में पोर्तुगाल का प्रभुत्व अगण्य साथा। राजनीतिक व आधिक दृष्टि से पोर्तुगीज लोगों द्वारा अधिकृत प्रदेश का बोई महत्त्व नहीं था।

बिटेन द्वारा अधिकत प्रदेश-सत्तरहवी सदी में जब हालैण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध दीपों में अपने व्यापारिक व राजनीतिक प्रभुत्त्व की स्थापना में तत्पर थी, तभी ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कस्पनी भी इस क्षेत्र में अपना प्रमुक्त कायम करने के लिये प्रयत्नशील थी। सुमात्रा के कुछ प्रदेशों की उसने अपने अधिकार में कर लिया था। पर क्योंकि अठारहवीं सदी में ब्रिटिश ईस्टर्ड इण्डिया कम्पनी भारत में अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थी, अतः उसे दक्षिण-पूर्वी एशिया की ओर व्यान देने की अधिक फुरसत नहीं थी। नैपोलियन के युद्धों के अवसर पर जब हालैण्ड फ्रांस के अधीन ही गया, तो ब्रिटेन ने हालैण्ड के इन्डोनीसियन साम्राज्य को अपने अधिकार में कर लिया । १८११ से १८१९ तक इन द्वीपों पर त्रिटेन का प्रभुत्त्व कायम रहा । इनका शासन करने के लिये ब्रिटिश सरकार की ओर से सर टामस स्टैम्फोर्ड रैफल्स को नियत किया गया, जो एक अत्यन्त कुशल व शक्तिशाली शासक था। वीएना की कांग्रेस (१८१४) के निर्णय के अनुसार दक्षिण-पूर्वी एशिया के ये द्वीप हालैण्ड को वायस दे दियें गये । इससे सर रैफल्स को बहुत निराशा हुई। वह इन प्रदेशों को ब्रिटेन के प्रभुत्त्व में रखना चाहता था। विवश होकर उसने हालैण्ड के साथ यह समझौता विया, कि मलाया में ब्रिटिश लोगों के साम्राज्य विस्तार में हालैण्ड बाधा न डाले और बदले में ब्रिटेन इन दीपों में अपने अधिकारों का परित्याण कर दे। इस समझीत् के अनुसार सुमात्रा, जावा आदि द्वीप हालैण्ड को प्राप्त हुए और मलाया में अपनी शक्ति की स्थापना के लिये ब्रिटेन को खुली छुट्टी मिल गई। सर रैफल्स ने मलाया में किस प्रकार ब्रिटेन के प्रभुत्त्व को स्थापित किया, इस पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे ।

पर ब्रिटिश लोगों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों को अविकल हम से हालूँग्ड के लिये छोड़ दिया हो, यह बात नहीं थी । बोनियों के उत्तर पश्चिम में एक द्वीप है, जिसे छानुआन कहते हैं। अठारहवीं सदी में इसमें ब्रिटिश लोगों ने अपना व्यापारिक केन्द्र स्थापित किया था। ब्रिटिश लोग इसको विकसित करने में विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर सके थे। इसीलिये अठारहवीं सदी में उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी थी। पर १८४० में एक बार फिर उन्होंने इस पर किया कर लिया था और इसे अपना व्यापारिक केन्द्र बनाया था।

वोनियो द्वीप में एक राज्य था, जिसे बुनेई कहते थे। यहां एक मुसलिन सुल-तान का शासन था। किसी समय बुनेई की सल्तनत बहुत अवितशाली थी और न केवल बोनियों के बड़े भाग पर, अपितु लाबुआन आदि अनेक द्वीपों पर भी उसका शासन था। पर उन्नीसवी रादी के उत्तरार्थ में बुनेई राज्य की दशा बहुत खराब हो गई थी, और उसके मुलतान की निवंलता का लाभ उठाकर १८८० में बिटिश लोगों ने उसे अपने आधिपत्य में ले लिया था। यद्यपि बुनेई के सुलतान की राजगद्दी को कायम रखा गया था, पर ब्रिटेन की अधीनता में उसकी स्थिति प्रायः वहीं रह गई थी, जो भारत की देशी रियासतों के राजाओं की थी।

वीनियों के उत्तर पश्चिमी समुद्री तट पर सरावक नाम का एक राज्य था। उन्नीसवीं सबी में इसकी बक्षा भी बहुत खराब थी। सर जेम्स बृक (१८०३-१८६८) नामक एक अंग्रंज ने इसकी राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाकर इसे अपनी अधीनता में कर लिया था। सर जेम्स बृक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी में था और उसी की तरफ से दक्षिण-पूर्वी एशिया में भेजा गया था। सरावक के मुल्तान के विरुद्ध अनेक विद्रोह हो रहे थे, उन्हें शान्त करने में इसने सुलतान की सहायता की और बाद में अपनी सैनिक शक्ति का उपयोग कर सरावक राज्य पर ही अपना आधिपत्य कायम कर लिया। अब बृक सरावक पर एक स्वतन्त्र राजा के समान शासन करने लगा। १८६३ में उसने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने सरावक पर सर जेम्स बृक के अधिकार को स्वीकृत कर लिया। पर सरावक के इस अंग्रेज राजा की स्थिति भी ब्रिटेन के अधीनस्थ राजा के समान थी और इस प्रदेश पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्थानित हो गया था।

ै बुनेई और सरावक के अतिरिक्त बोनियो द्वीप के उत्तरी भाग पर भी बिटिश सरकार में अपना आनिएता स्वापित किया । यह प्रदेश (उत्तरी बोनियो) प्रायः भगओं से आज्ञादित था । उजीसती सदी के अन्तिन भाग में इस पर अपना आधि-पत्य स्थापित करने व प्रसास आशिक विकास करने के लिये नार्थ बोनियो कम्पनी की स्थापना की गई। यह प्रदेश रबड़ के लिये बहुत उषयुवत था। शिटिश नार्थ बोनियो कम्पनी ने यहां रबड़ के वृक्षों का जहां विकास किया, वहां साथ ही बिट्यू सरकार की संरक्षा में इसके शासन का भी संचालन किया। इस प्रकार बोनियो द्वीप के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी भाग पर ब्रिटेन का आधिपत्य स्थापित हुआ। दिक्षणी बोनियो हालैण्ड की अधीनता में था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक अन्य द्वीप हैं, जिसे न्यू गाइनिआ कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह इस क्षेत्र के अन्य सब द्वीपों की अपेक्षा अधिक बड़ा है। १८८० में इसके दक्षिण-पूर्वी भाग पर ब्रिटेन ने अपना प्रभुक्त कायम कर लिया। न्यू गाइनिआ के ब्रिटेन द्वारा अधिकृत प्रदेश को पापुआ कहते हैं। १८८० में ही न्यू गाइनिआ द्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर जर्मनी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। १९१४-१८ के महायुद्ध में जब जर्मनी की पराजय हुई, तो यह प्रदेश राष्ट्रसंघ की अधीनता में आस्ट्रेलिया के सुपुर्द कर दिया गया। न्यू गाइनिआ का पश्चिमी भाग हालैण्ड की अधीनता में था।

न्यू गाइनिआ और बोनियों के कतिपय प्रदेशों के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में अन्य भी अनेक द्वीपों पर ब्रिटेन का आधिपत्य कायम था। इनमें से कोकोम-कीलिंग द्वीपसमूह (सुमात्रा के दक्षिण में कई सौ मील की दूरी पर स्थित) सर्बें महत्त्वपूर्ण है।

(४) इन्डोचायना

प्राचीन इतिहास—दक्षिण-पूर्वी एशिया में फांस के अधीन इन्डोचायना का जो राज्य है, जसका क्षेत्रफल २,८६,००० वर्गमील हैं, और १९३९ में उसकी आवादी २,३७,००,००० थी। इस राज्य के पांच मुख्य भाग हैं, तोन्किन, अनाम, कोचीन चायना, कम्बोडिया और लाओस। फांस की अधीनता में रहने के कारण ये पांचों प्रदेश इस समय एक राज्य के अंग हैं, पर प्राचीन समय में ये राजनीतिक व सांस्कृतिक वृष्टि से एक नहीं थे। तोन्किन और अनाम पर चीनी सम्यता का प्रभाव था और दक्षिणी इन्डोचायना के प्रदेशों पर भारतीय सम्यता का। तोन्किन और अनाम चीन की दक्षिणी सीमा के बहुत समीप हैं। तोन्किन तो उसके साथ ही लगा हुआ हैं। इसी कारण चीन के अनेक शक्तिशाली सम्राट्डन प्रदेशों को अपनी अधीनता में समर्थ हुए थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक भी ये चीन के मुक्ति साम्राज्य के अधीन थे। दक्षिणी इन्डोचायना के विविध राज्यों की स्थिति भी इस समय चीनी साम्राज्य के करद राज्यों के सदृश थी। ये मञ्चू सम्राट्की अधीनता को स्वीकृत करते थे।

तीसरी सदी ई॰ पू अमें चिन वंश के शक्तिशाली सम्राट् शी हुआंग ती ने तोन्किन को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उसने अनाम पर भी आक्रमण किया था और उसके उत्तरी भाग को भी अपने विशाल साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया था। चिन वंश की शक्ति के क्षीण होने पर (२०६ ई० पू०) ये प्रदेश चीनी साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हो गये। चिन वंश की समाप्ति पर चीन में हान वंश का शासन कायम हुआ था। इसका सबसे अधिक शिक्तशाली सम्राट् ब्ती था। उसने चीन के साम्राज्य का फिर से विस्तार किया और तोन्किन व अनाम को जीतकर अपने अधीन कर लिया । ब्ती का शासन काल १४० ई० पू० से ८७ ई० पू० तक था। चीन के इतिहास में वह दिग्विजयी सम्राट् के रूप में प्रसिद्ध है। यद्यपि तोन्किन और अनाम उसके अधीन थे, पर उनके अपने पृथक् राजाओं की सत्ता विद्य-मान थी। भारतवर्ष के सम्राट् समुद्रगुप्त के अधीनस्थ विविध राजाओं के समान तोन्किन और अनाम के राजा भी सम्राट् बृती की अधीनता में अपने पृथक सत्ता रखते थे। हान वंश के क्षीण होने पर इन प्रदेशों के राजा फिर स्वतन्त्र हो गयें (२० ई० प० के लगभग)। तीसरी सदी ई० प० के प्रारम्भ में जब चीन की शक्ति का पुनरुद्धार हुआ, तो लोन्किन और अनाम फिर चीन के अधीन हो गये। इस कैंग्य इन राज्यों में चीन की सभ्यता और संस्कृति का विशेष रूप से प्रचार हुआ। तोन्किन और अनाम के उच्च श्रेणि के लोग चीनी भाषा बोलने और चीनी साहित्य के अध्ययन में गौरव अनुभव करने लगे। तीसरी सदी से नवीं सदी के अन्त तक ये राज्य चीन की अधीनता में रहे । इस काल में चीन में अनेक राजवंशों ने शासन किया, पर तोन्किन और अनाम अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए । दसवीं सदी के प्रारम्भ में जब तांग वंश का पतन हुआ, और चीन का विशाल साम्राज्य अनेक राज्यों में विभक्त हो गया, तो इन राज्यों को अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्थापित करने का अवसर मिला। पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी इन राज्यों में चीनी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव कायम रहा । तेरहवीं सदी में जब चीन पर मंगील लोगों के आक्रमण हुए, और चंगेज खां ने विशाल मंगोल साम्राज्य को स्थापित किया, तो तोन्किन और अनाम भी मंगोल आक्रमणों मे अपनी रक्षा नहीं कर सके । पर मंगोल विजेताओं के लिये यह सम्भव नहीं था, ुक्ति इतने सूदूरस्थ प्रदेशों पर वे अपने शासनको कायम रख सकें। जिस प्रकार भारत में मंगोल लोगों ने आक्रमण करने के बाद भी अपना स्थिर आधिपत्य स्थापित नहीं किया था, वैसे ही अनाम और तोलिश पर भी उन्होंने अपना स्थिर शासन कायम नहीं किया। पन्द्रहवीं सदी के शुरू में जीन के मिगवंशी सम्राट् युंगलों ने फिर तोन्किन और अनाम पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । इस समय के बाद ये प्रदेश चीन के सम्राटों को भेंट, उपहार, कर आदि हारा सन्तुष्ट करते रहे। तोन्किन और अनाम किस अंश तक चीन की अधीनता में रहे, यह बात चीनी सम्राट् की शक्ति पर आश्रित रहती थी। जो सम्राट् अधिक शक्तिशाली होते थें, इन प्रदेशों पर उनका प्रभुत्त्व अधिक दृढ़ होता था। पर तोन्किन और अनाम के राजाओं की पृथक् सत्ता कायम रहती थी, और वे चीनी साम्राज्य की अधीनता में रहते हुए अपने राज्यों का शासन स्वयं करते थे।

तोन्किन और अनाम के राज्यों में चीनी सभ्यता और संस्कृति का प्रभुत्त था।
पर इन प्रदेशों की कोई अपनी संस्कृति न हो, यह बात नहीं थी। चौदहवीं सदी में
अनाम के लोगों ने अपनी पृथक् लिपि का विकास किया, जिसके अक्षर चीनी लिपि
से भिन्न थे। इस लिपि में अनाम का अपना साहित्य लिखा जाने लगा, और घीरे
धीरे अनामी साहित्य का विकास हुआ। चित्रकला आदि में भी इन राज्यों की
अपनी पृथक् कौली थी। साथ ही इन प्रदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का
भी प्रभाव था। भारतीय ज्यापारी व धर्म प्रचारक बड़ी संख्या में अनाम के समुद्र
तट पर आते जाने थे और उनका प्रभाव वहां की जनता पर पड़ना सर्वथा स्वाभा-

प्राचीन समय में अनाम के दक्षिणी भाग में चम्पा नामक भारतीय राज्य की सत्ता थी। बुछ समय के लियं चम्पा के राज्य की उत्तरी सीमा तोन्किन से जा लगी थी और सम्पूर्ण अनाम चम्पा राज्य के अन्तर्गत हो गया था। नम्पा का पहला भारतीय राजा श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी ई० प० में है। श्रीमार और उसके उत्तराधिकारी चम्पा के राजा भारतीय थे, संस्कृत उनकी भाषा थी और उनके नाम भी भारतीय थे। इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए संस्कृत भाषा के अने कि बिलालेख दक्षिणी अनाम में उपलब्ध हुए हैं। चम्पा के राजाओं में श्री भद्रवर्मन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वह वेदों का विद्वान् था और उसने णिय के एक विशाल मन्दिर का निर्माण कराया था, जिसमें भद्रेश्वर स्वामी शिव की मूर्ति की प्रतिच्छा की थी। यह मन्दिर बाद में चम्पा के धर्म और संस्कृति का केन्द्र वन गया था, और इसकी कीर्ति सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में ज्याप्त थी। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि चम्पा के इन भारतीय राजाओं के सम्बन्ध में अधिक विरत्गर के साथ लिख सकों। चीन के जो शिवतशाली सम्प्राट् तोन्किन और अनाम के विविध राजाओं को अपनी अधानता में लाने में तत्पर थे, उन्होंने चम्पा के राजाओं को भी अपना वशवती व करद बनाने में सफलता प्राप्त की थी।

प्राचीन समय में चम्पा के पश्चिम में कम्बोडिया का राज्य था, जिसे भारतीय लोग कम्बुज कहते थे । चम्पा के समान कम्बुज भी भारत काही एक उपस्तिकाथा ।

चौथी सदी में कौन्डिन्य नामक एक भारतीय ब्राह्म ग ने यहां भारतीयों का एक न्तुज्य स्थापित किया था, जिसे चीनी ऐतिहासिकों ने फुनान नामसे लिखा है। फुनान कैंनिवासी शैव धर्म को मानते थे । फूनान के राजा चद्रवर्मन और उसकी माता कूळ-प्रभावती द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए अनेक शिलालेख इस प्रदेश से उपलब्ध हुए हैं। फनान के उत्तर में भारतीयों का एक अन्य उपनिवेश था, जिसे कम्बूज कहते थे। बाद में फुनान राज्य को भी कम्बुज के राजाओं ने विजय कर लिया और यह सारा प्रदेश ही कम्बुज व कम्बोडिया कहाने लगा। छठी सदी के अन्त तक कम्बुज और फनान के भारतीय राज्य परस्पर मिलकर एक हो गये थे। कम्बुज देश के राजा हौंब धर्म के अनुयायी थे और उनके शासनकाल में इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। न केवल राजा अपितु अन्य धनी मानी लोग भी वहां शैव मन्दिरों के निर्माण में तत्पर थे। कुछ ही सगय में कम्बुज शैव धर्म और भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया । शिव, विष्णु, दुर्गा आदि पौराणिक देवी देवताओं की वहां सर्वत्र पूजा होने लगी । वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि का वहां उसी प्रकार अध्ययन होने लगा, जैसा भारत में होता था। सातवीं सदी में महेन्द्र वर्मा, ईशान वर्मा और जयवर्मा कम्बुज देश के राजा थे। ईशान वर्मा ने कम्बुज में अनेक आश्रम 🎢 वाये। जैसे बौद्ध धर्म के मठ विहार कहाते थे, वैसे ही पौराणिक धर्म के मठों को आश्रम कहते थे। इनमें वहुत से सन्यासी निवास करते थे और बौद्ध भिक्षुओं की तरह धर्म-प्रचार, विद्याध्ययनं तथा शिक्षाकार्य में व्यापुत रहते थे। राजा ईशानवर्गा के समय में ही विष्णु और शिव की सम्मिलित मूर्ति बनाई गई। इससे सूचित होता है, कि कम्बुज़ देश के शैव और वैष्णव शिव व विष्णु में अविरोध मानते थे। नवीं सदी में कम्बूज देश का राजा यशीवमा था। उसने यशीघरपुर नाम से अपनी नई राजधानी बनाई थी । उसके भग्नाबशेष अब भी अङ्कोरधीम में उपलब्ध होते हैं। इसके चारों ओर ३३० फीट चौड़ी खाई है, जिसके भीतर की ओर एक विशाल प्राचीर बनी हुई है। नगर वगीकार है, जिसकी प्रत्येक भूजा लम्बाई में दो मील से भी अधिक है। नगर के द्वार विशाल व सुन्दर हैं। इनके दोनों ओर रक्षकों के लिये मकान बने हैं। तीन सिर वाले विशाल हाथी द्वारों की मीनारों को अपनी पीठ पर थामे हए हैं। सी फीट चौड़े और मील भर लुख़े पांच राजनार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये हैं । पक्की चिनाई के भिन्न भिन्न जीतित बाले क्रोक सरीवर अन तक भी अङ्कीर थोग के खण्डहरों में वि**द्यमान हैं।** नगण के ठीक बीच में शिक्ष का एक निवारण मन्दिर है । उसके दीन सण्ड हैं। प्रत्येक लण्ड पर एक एक ऊँची मीनार है। बीच के पीनार की उँचाई भन्न दका में भी १५० फीट के लगभग है। ऊंची मीनार के चारों तरफ बहुत भी छोटी छोटी

मीनारें हैं। इनके चारों ओर एक एक नर मूर्ति बनी हई है। ये समाधिस्थ शिव की मृतियां हैं। इस विशाल शिवमन्दिर में जगह जगह पर सुन्दर चित्रकारी की गई है। पौराणिक धर्म के किसी मन्दिर के इतने पुराने और विशाल अवशेष भारि में भी कहीं उपलब्ध नहीं होते । बारहवी सदी के पूर्वार्द्ध में कम्बुज देश का राजा सर्यवर्मा दिलीय था। उसने एक विशाल विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया, जो अङ्कोर वट के रूप में अब तक भी विद्यमान है। आजकल यह एक वीद्ध विहार है। पर शरू में इसका निर्माण वैष्णव मन्दिर के रूप में हुआ था। इसके चारों ओर की खाई की चौडाई ७०० फीट है। झील के समान चौड़ी इस खाई को पार करने के लिये पश्चिम की ओर एक पूल बना है। पूल पार करने पर एक विशाल द्वार आता है, जिसकी चौड़ाई १००० फीट से भी अधिक है। खाई और द्वार को पार करने के बाद जो मन्दिर आता है, वह भी बहुत विशाल है, उसकी चौड़ाई १८० फीट के लगभग है। समयान्तर में कम्बुज देश में पौराणिक धर्म का ह्यास हो गया और उसका स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया । कम्बोडिया व कम्बुज देश पूर्ण रूप से भारत का उपनिवेश था और इसी रूप में वह सोलहवीं सदी के लगभग तक विद्यमान रहा । पर कम्बज देश के भारतीय राजाओं की राजनीतिक शवित वहत संमय तक कायम नहीं रह सकी । सीलहवीं सदी में उस पर सियाम और अनाम (चम्पा) के राज्यों ने आक्रमण शुरू कर दिये और इनके हमलों के कारण उसकी शक्ति बहत क्षीण हो गई। सोलहवीं सदी में जब पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार आदि के लिये इस देश में आना शुरू किया, तब कम्बुज देश की राजनीतिक व सामरिक शक्ति बहत निर्वल दशा में थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं, कि वर्तमान समय में जिस राज्य को इन्डोचायना कहते हैं, प्राचीन समय में वह अनेक राज्यों में विभवत था। उसके उत्तरी राज्य चीनी सम्यता के प्रभाव में थे और दक्षिणी राज्यों में भारतीय सम्यता की सत्ता थी। राजनीतिक दृष्टि से यह देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभवत था, जो बहुधा आपस में संघर्ष करते रहते थे। प्राचीन समय में चम्पा और कम्बुज में अनेक एसे शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने इन्डोचायना के बहुत बड़े भाग पर चक्रवर्ती सम्राट् के रूप में शासन किया। उत्तरी इन्डोचायना पर चीन का प्रभुत्त्व बहुत समय तथ कायम रहा, यद्यपि वहां भी अनेक राजा चीन के करद रूप में शासन करते रहे

यूरोपियन जातियों से सम्पर्क—दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समाने इन्होचायना के समुद्र तट पर भी सोलहवीं सदी में पोर्तुगीज लोगों ने आना शुरू किया। पर पोर्तुगीज लोगों ने इस देश में अपने राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार का उद्योग नहीं किया। पोर्तुगाल के बाद हालैण्ड, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के ज्यापारी इस देश में व्यापार के लिये आये, पर उन्होंने भी इसमें अपने राजनीतिक प्रभुत्त्व को क्यापित करने की कोई कोशिश नहीं की । उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक इण्डोचायना की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रही ।

फ्रान्स का प्रभुत्त्व--इन्डोचायना पर अपना राजनीतिक प्रभुत्त्व कायम करने का उद्योग फ्रेंडच लोगों ने किया। फ्रेंडच पादरी इस क्षेत्र में देर से ईसाई धर्म के प्रचार का उद्योग कर रहे थे। सतरहवी सदी में पेरिस में एक मिशनरी सोसायटी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य विदेशों में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। इसने इन्डोचायना के दक्षिणी भाग कोचीनचायना में कार्य शरू किया। फ्रेडच पादरियों के साथ साथ फेडच व्यापारी भी इस प्रदेश में आने लगे। धीरे धीरे बहत से फे ज्च पादरी और ज्यापारी कोचीनचायना और अनाम में पहंच गये। ये लोग केवल धर्म प्रचार और न्यापार से ही संतुष्ट नहीं रहे, इन्होंने इन प्रदेशों के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया । अठारहवीं सदी में ब्रिटिश और फ्रेज्ब लोग भारत के विविध राजाओं व नवाबोंका पक्ष लेकर इस देश की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे। कोचीनचायना और अनाम में भी फेक्च लोगों ने इस नीति का अनुसरण करना शुरू किया। अनाम की राजगद्दी के एक सगड़ को लेकर १७८० में फांस के एक पादरी ने यह निक्चय किया, कि राजगद्दी के एक उमीदवार की भदद की जाय, ताकि जब फांस की मदद से यह व्यक्ति अनाम का राजा बन जाय, तो वह फांस के प्रभाव में रहे और ईसाई धर्म के प्रचार में भी उससे सहायता मिले। उस समय फांस में बूर्वी वंश के राजा लुई १६वें का शासन था। वह अनाम की राजगद्दी के इस उम्मीदवार की सहायता करने को तैयार हो गया। पर शीघ्र ही (१७७९) फ्रांस में राज्यकान्ति हो गई और लुई १६वें को अपनी राजगही का परित्याग करना पड़ा। फांस के सम्राट् की ओर से तो कीई फेञ्च सेनायें इस समय अनाम नहीं आ सकीं, पर पादिरयों और व्यापारियों की प्रेरणा पर बहुत से फेञ्च स्वयंसेवक इस समय अनाम पहुंच गये और उन की सहायता से गिआलोंग अनाम के राजसिंहासन को प्राप्त करने में समर्थ हुआ। अनाम की राजगद्दी के उस उम्मीदवार का नाम गिआलोंग था, जिसे फेंच पादरी सहायता दे रहे थे। आगे चलकर यह गिआलोंग अत्वता मितिशाली सम्राट् वना और यह न क्रेव्यू सम्पूर्ण अनाम को अपितु तोन्तिन, कोचीनवायना, छ।ओस और कम्बोडिया को भी अपने प्रभुत्त्व में लाने में समर्थ हुआ। क्योंकि सम्राट् गिआलोंग ने फेञ्च लोगों की सहायता से अपनी राजगद्दी प्राप्त की थी, अतः स्वामाविक रूप से इस नमय (अठारहवीं सदी के अना में) उनके राज्य में फ्रांस का प्रभाव वहना गुरू ही गया और फेंच पादरी बहुता निर्वित्तता के साय वर्ष प्रचार के कार्य में व्यापृत हो गये।

उन्नीसवीं सदी में फेञ्च पादरियों का प्रभाव इन प्रदेशों में जिस ढंग से बढ रहा था, अनाम की सरकार उसे पसन्द नहीं करती थी। धर्म प्रचार ओर व्यापार की आड़ मे पाइचान्य देशों के लोग चीन में जिस ढंग से अपना प्रभाव व प्रभाव स्थापित कर रहे थे, उससे अनाम के लोग बहत चिन्तित थे । इसका यह परिणाम हुआ, कि १८५८ में अनाम में कार्य करने वाले फेड्च पादरियों पर अनेक स्थानों पर हमले किये गये । इसी सभय ब्रिटेन और फ्रांस की सेनायें चीन में अपनी अक्ति का प्रयोग कर चीन के सम्राट् को इस बात के लिये विवश कर रही थीं, कि वह इस पारचात्य देशों को व्यापार आदि के सम्बन्ध में विशेष स्विधायें प्रदान करे। पूर्वी एशिया के लोगों में यरोपियंन जातियों के प्रति विरोध की भावना बहुत प्रबल हुए धारण कर रही थी। इस दणा में यदि अनाम के लोगों ने भी अपने देश में विद्यमान फ्रेंञ्च पादिरयों के प्रति अपने रोप को प्रकट किया हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। पर फोञ्च लोगों ने अपने देश के पादिरयों के प्रति किये गये व्यवहार की सहन नहीं किया। फांस की सेनाएं कोचीन वायनामें प्रविष्ट हो गई और उन्होंने उसके अनेक प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। अनाम का राजा उनका मुकावला नहीं कर सका और १८६३ में इस बात के लिये विवश हुआ, कि फ्रेड्च लोगों के साथ सन्धि कर ले। १८६३ की सन्धि के अनुसार कोचीनचायना फांस के अधीन हो गया और अली के राजा ने एक अच्छी बड़ी रकम हरजाने के रूप में फांस को प्रदान करती स्वीकार की।

इस प्रकार १८६३ में इन्डोचायना में फांस के प्रभुत्त्व का सूत्रपात हुआ। अगले पांच सालों में फांस ने साम्राज्य विस्तार की अपनी नीति को जारी रखा और कम्बोडिया पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। १८७० में प्रशिया और फांस का युद्ध हुआ, जिसमें फांस की बुरी तरह में पराजय हुई। इस दशा में फांस के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह इन्डोचायना में अपनी अक्त के विस्तार पर अधिक ध्यान दे सके। पर श्रीष्ट्र ही फांस साम्राज्यवाद के मार्ग पर फिर अग्रसर हुआ। १८७३ में एक फेल्च सेना ने तोन्किन में प्रवेश किया और उसके कुछ प्रदेश में अपनी सत्ता की स्थापना की। १८७४ में फेंच लोगों ने अनाम के राजा को इस बात के लिये विवश किया, कि वह तोन्किन में फ्रांस को व्यापार आदि के विशेष अधिकार प्रदान करे। साथ ही अनाम के राजा ने यह भी स्वीकार किया, कि अपनी विद्वेश नीति का संचालन वह फांस के परामर्श के अनुसार करेगा। राजनीतिक दृष्टि से यह एक अद्भुत स्थिति थी। अनाम चीनी साम्राज्य के अधीन था और प्रव्य सम्भव नहीं था, कि वे अनाम जैसे दूरवर्ती राज्य की प्रधीन था और प्रव्य सम्भव नहीं था, कि वे अनाम जैसे दूरवर्ती राज्य की प्रवार कोगों के प्रभाव

व प्रभत्त्व से रक्षा कर सकें। १८७४ की सन्धि से लाभ उठाकर फेञ्च व्यापारी बडी संस्या में तोत्किन जाने शुरू हुए । यदि ये केवल व्यापार से ही संतृष्ट रहते, नो ती किन के लोगों का कोई नुकसान नहीं था। पर फेल्च व्यापारी इस प्रदेश में अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने के लिये भी प्रयत्नशील थे। वे तोन्किन की जनता के साथ दृब्धवहार करते थे और वहां सब प्रकार से मनमानी करने को तत्पर रहते थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि तोन्किन के लोग उनका विरोध करें । १८७४ के बाद तोन्किन में अनेक स्थानों पर झगड़े शुरू हो गये और सर्वत्र अव्यवस्था सी छा गई। चीन की सरकार अपने माम्राज्य के अधीनवर्नी तोन्किन प्रदेश की इस अन्यवस्थित दशा की उपेक्षा नहीं कर सकती थी। उसने वहां अपनी सेनाएं भेज दीं, और तोन्किन के प्रश्न को लेकर चीन और फ्रांस में लड़ाई शुरू हो गई। यद्यपि उनमें बाकायदा युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी, पर इस समय चीन और फांस की सेनाएं आपरा में युद्ध में व्यापृत थी । चीन की सरकार के लिये यह सुगम नहीं था, कि अपनी राजधानी पेकिंग से इतनी दूर दक्षिण में स्थित तीन्त्रिन प्रदेश में फेञ्च सेनाओं का मुकाबला कर सके। आखिर उसे ब्बना पड़ा । १८८३ में अनाम का राजा फांस की अधीनता स्वीकृत कर हैंने को विवश हुआ। इस समय में अनाम पर (तोन्किन इस समय अनाम के राजा के ही अधीन था) फांस का आधिपत्य स्थापित हो गया। १८९३ में लाऔस प्रदेश पर भी फांस ने अपना अधिकार कायम कर लिया । इस प्रकार जन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही प्रायः सम्पूर्ण इन्डोचायना फांस की अधीनता में आ गया था।

के लिये अपने 'रेजिडेन्ट' नियत करती थी और इन राज्यों के राजा फ्रेड्च गर्वर्गर जनरल के हाथों में कठपुतली के समान थे। कोचीन चायना में किसी पुराने राजवंद की सत्ता नहीं थी। वह प्रदेश मीधा फ्रेडच गर्वर्गर जनरल के शासन में था। इसकी शासन करने के लिये एक सिविल सर्विस का संगठन किया गया था., जिसमें फ्रेडच लोगों का प्रमुख स्थान था। इन्डोचायना के सम्बन्ध में फ्रांस की यह नीति थी, कि वहां फ्रेंच भाषा का प्रचार किया जाय, शिक्षा फ्रेडच भाषा द्वारा दी जाय और सरकार का सब कार्य फ्रेडच भाषा में ही हो। इस नीति का परिणाम यह था, कि इन्डोचायना के लोग थीरे धीरे फ्रेडच रंग में रंगते जाते थे और उनगर फ्रांस का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जाता था।

१९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर हजारों अनामी सिपाही फ्रांस की सेना में भरती किये गये और उन्हें यूरोप के रणक्षेत्र में लड़ने के लिये ले जाया गया। इसी प्रकार हजारों अनामी मजदूर भी इस काल में यूरोप ले जाये गये । यह अवश्य-म्भावी था, कि यरोप के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आये हुए इन इन्डोचाइनीज लोगों पर म(रचात्य विचारों का असर हो। फ्रांस में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो इन्डोचाइनीज लांग अपने देश को लौटते थे, वे भी फांस के लोकतन्त्रवाद से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकते थे । १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद संसार में सर्वत्र राष्ट्रीय स्विती न्त्रता और लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियां बल पकड़ रही थीं। उनका प्रभाव इन्डो-चायना पर न पड़े, यह सम्भव नहीं था। अतः १९१९ में वहां भी राष्ट्रीय स्वत-न्त्रता का आन्दोलन प्रवल हो गया और फेट्च सरकार ने अनुभव किया, कि स्वराज्य के मार्ग पर अग्रसर हुए बिना इन्डोचायना के लोगों को कदापि संतोष नहीं होगा। इसीलिये वहां घीरे घीरे स्वशासन को स्थापित करने की नीति की अपनाया गया। को बीन चायना में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई, और उसमें प्रतिनिधि निर्वा-चित करने का अधिकार जनता को भी प्रदान किया गया। सिविल सर्विस में भी इन्होचायना के लोगों की संख्या बढाई जाने लगी। १९३० में अनाम के राजा ने भी पारचात्य देशों के ढंग पर अपने राज्य के शासन का पुनःसंगठन किया। अनाम के इस राजा की शिक्षा गेरिस में हुई थी, और वह आधुनिक विचारों व प्रवित्तयों से भलीभांति परिचित था। उसके प्रयत्न से अनाम के शासन में भी अनेक सुधार हुए। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि १९३० के बाद भी कम्बोड्यि, अनाम व कोचीन चायना का शासन ऐसा नहीं था, जिनसे वहां के राष्ट्रवादी/देश-भक्त लोग सन्तोष अनुभव कर सकते । कोचीनचायना में जी प्रतिनिधिसभा स्थापित हुई थी, उसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इस सभा के व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार भी पर्याप्त नहीं थे । इस दशा में वहां के देशभवत इससे कैसे संतुष्ट हो मकते थे। यद्यपि कहने को अनाम और कम्बोडिया में वहां के अपने राजवंशों का भासन था, पर वस्तुतः ये भी फांग के ही अधीन थे। हैन्होचायना का फेञ्च गवर्नर जनगळ इन राज्यों में नियुक्त रेजिङेन्टों द्वारा उन पर पूरा नियन्त्रण रखता था और इनके राजाओं की सत्ता नाममात्र को ही थी। इस दशा में इन्डोचायना में सर्वत्र विदेशी फेञ्च शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना निरन्तर प्रबळ होती जाती थी।

ईसाई धर्म का प्रचार—जब इन्डोचायना पर फांस का प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो वहां ईसाई धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली। १९३० तक इस देश में ईसाइयों की संख्या १३,००,००० से भी अधिक हो गई थी। इन्डोचायना में ईसाइयों की संख्या कुछ आबादी के ५ प्रतिशत के छगभग थी। इन्डोचायना के ये ईसाई प्रायः सब रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे और फेञ्च पादिरयों ने ही इन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित किया था।

आधिक दशा—तोन्किन का प्रदेश कोयले की खानों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। फ्रेंच्च लोगों ने इसका मलीमांति उपयोग किया और वहां बहुत सी कोयले की खानें खोदी गई। क्योंकि तोन्किन में कोयला प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होता हैं।, अतः वहां व्यवसायों को विकसित कर सकना भी सुगम था। फ्रेंच्च पूंजी द्वारा इस प्रदेश में व्यवसायों का खूब अच्छी तरह विकास हुआ। इन्डोचायना के खिनज द्वारों में टीन और जस्ता भी विशेष महत्त्व रखते हैं। ये वहां प्रचुर परिमाण में प्राप्तव्य हैं, और फ्रेंच्च लोगों ने इनके व्यवसाय को भी भलीमांति विकसित किया। रवड़ के वृक्षों की खेती पर भी वहां ध्यान दिया गया। इन्डोचायना से जो माल विदेशों में बिकी के लिये जाता था, उसमें टीन, जस्ता और रबड़ सबसे गुख्य थे। फ्रेंच्च लोगों ने इस देश की आधिक उन्नति के लिये रेलवे लाइनों और सड़कों का भी निर्माण किया और इसमें सन्देह नहीं, कि इनसे इन्डोचायना की आधिक उन्नति में अच्छी सहायता गिली। चीन के लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में वहां मजदूरी की खेती जोर वहां के व्यापार से आकृष्ट होकर बहुत से भारतीय भी वहां जाकर वसने शुरू हुए।

(५) सिआम या थाईलैण्ड

इन्होचायना के पश्चिम में सियाम देश हैं, जिसका वर्तमान नाम बाइलैण्ड है। क्षेत्रफल में यह २,००,१४८ वर्गमील है, और १९३९ में इसकी जनसंख्या १,५६, ००,००० थी। दक्षिण-पूर्वी एकिया में सियाम ही एक ऐसा देश हैं, जो किसी पाश्चात्य देश के सीधे शासन में नहीं रहा और जिसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रही, यद्यपि वहां भी अनेक विदेशी राज्यों ने व्यापार सम्बन्धी विशेषा-धिकार प्राप्त किये हुए थे और वहां निवास करने वाले विदेशी नागरिक सियाम के कानून व अदालतों के अधीन नहीं होने थे। एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धतिं भियाम में भी विद्यमान थी, और इस देश को भी यह अधिकार नहीं था, कि वह अपने बन्दरगाहों में माल के आयान व निर्यात पर स्वेच्छापूर्वक टैक्स लगा सके। इस प्रकार सियाम की राजनीतिक स्थिति प्रायः वही थी, जो मञ्चू शासन में चीन की थी।

प्राचीन इतिहास-सियाम के प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ भी उस समय से होता है, जब वहां भारतीय लोगों ने अपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ किये थे। कम्बोडिया व कम्बुज देश में फुनान नाम से जिस भारतीय ऑपनिवेशिक राज्य की स्थापना हुई थी, उसने सियाम के बड़े भाग को भी जीतकर अपने अधीन कर लिया था। फनान साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर सियाम का हिन्दू राज्य स्वतन्त्र हो गया। सियाम के इस हिन्दू राज्य को द्वारवती कहते थे। इसकी राजधानी का नाम अयोध्या था । अव तक भी यह 'अयदिआ' कहाती है । पर द्वारवती का हिन्दू राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं था । पहले उसे पुनान ने अपने अधीन किया था, बाद में कम्बज देश और सुमात्रा के हिन्दू राजा उसे अपनी अधीनता में लातें रहे। बारहवीं और तेरहवीं सदियों में थाई नाम की जानि ने उत्तर की ओर से मिआम में प्रवेश किया । ये थाई लोग दक्षिणी चीन के यनान प्रान्त में रहते थे और सिआम पर इनके आक्रमणों का प्रायः वही रूप था, जो कि रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत विविध प्रदेशों पर फांक, एंगल्स, लोम्बाई आदि जातियों का था । जिस अकार फांक लोगों के आक्रमण से पूराना गॉल फांस बन गया और वहां फांक लोगों की प्रभुता हो गई, वैसे ही थाई लोगों के प्रवेश से प्राचीन द्वारवती में थाई लोगों की प्रभुता हो गई और थाई लोगों की इस प्रधानता के कारण ही वर्तमान समय में वह थाईलैण्ड कहाने लगा। शुरू में इस देश में थाई लोगों ने बहत से छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की । पर बाद में ये विविध थाई राज्य एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की अधीनता में आ गये, जिसकी राजधानी अयोध्या ही रही । राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि थाई लोग विजेता थे, पर सिआम में आकर उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता व धर्म को स्वीकार कर लिया था।

निआम के थाई राज्य पर बरमा के राजा निरन्तर आक्रमण करने रहते थें पिन्द्रहवीं और शोलहवीं सिदयों में सिआम और बरमा का यह संघर्ष निरन्तर जारी रहा। दो बार बरमा की सेनाओं ने अयोध्या पर कब्जा किया और बुरी तरह से उसका विनाश किया। १७६७ में बरमा की सेनाओं ने अयोध्या का इतनी बुरी

तरह से विनाश किया था, कि वाद में जब सिआम ने पुनः अपनी स्वतन्त्रता की प्राप्त किया, तो नये सिआमी राज्य की राजधानी अयोध्या को न बनाकर वैंगकोक को बैनाया गया, जो अब तक भी उसकी राजधानी है। बरमा की अधीनता से अपने देश को स्वतन्त्र कराने वाले वीर का नाम चकी था और उससे सिआम में एक नये राजवंश का प्रारम्भ हुआ। आगे चलकर इस वंश के राजाओं ने बीसवी मदी में सिआम में वैध राजसत्ता की स्थापना का भी प्रयत्न किया।

पाश्चात्य देशों से सम्पर्क--दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान सिआम में भी सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार के लिये आना प्रारम्भ किया था। उसके समुद्रतट पर पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार के लिये अनेक केन्द्र कायम किये । पोर्तुगीज व्यापारियों के साथ साथ ईसाई पादरियों ने भी सिआम में प्रवेश किया । बाद में डच और इंगलिश व्यापारी भी सिआम में गये, पर एशिया के अन्य देशों के समान सिआम में इन्होंने अपने राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना का उद्योग नहीं किया । उन्नीमवीं सदी के प्रारम्भ तक पोर्तगीज, डच व इङ्गलिश लोगों ने अपने कार्यक्षेत्र को व्यापार ओर धर्म प्रचार तक ही सीमित रखा था। इसका कारण यह था, कि सिआम में इस समय एक मुसंगठित केन्द्रीय जामन की सत्ता 📆 और पारचात्य लोगों को वहां यह अवसर नहीं था, कि वे राज्य के विविध झगड़ों का लाभ उठाकर उनमें हस्तक्षेप कर सकें। साथ ही पाश्चात्य लोग एशिया के अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्यों के विस्तार में तत्पर थे और सिआम की ओर ध्यान देने की उन्हें अधिक फुरसत नहीं थी। पर चीन के समान सिआम में भी पारचात्य देशों ने ऐसी सन्त्रियां कीं, जिनके अनुसार विदेशी व्यापार के आयात और निर्यान माल पर टैवस की दर निश्चित की गई। सिआम की सरकार के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि मन्धियों में परिवर्तन किये बिना इन टैक्सों की दर में अदल बदल कर सके या अपनी इच्छानसार विदेशी व्यापार का संचालन कर सके। इसी प्रकार विदेशों के साथ की गई इन सन्धियों द्वारा विदेशी नागरिकों को एक्स्ट्रा-टैरिटोरि-एलिटी विषयक अधिकार प्रदान किये गये। विदेशी राज्यों के साथ में सन्धियां उन्नीसवी सदी के मध्य भाग में की गई थीं। इन सन्धियों के कारण सिआम की राजनीतिक स्वतन्त्रता बहुत कुछ मर्यादित हो गई थी।

सिआम के राजा—यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि वकी ढारा स्थापित राजवंश के राजाओं के शासन के सम्बन्ध में संक्षेप के साथ भी लिख सकें। पर कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना आवश्यक हैं। १८५१ में सिआम के राज-सिंहासन पर राजा मंगकूट (राम चतुर्थ) आरूढ़ हुआ। १८२४ से १८५१ तक यह एक बीद्ध विहार में का गा। इनने दीर्थ समगतक बौद्ध विहार में रहने के कारण उसे विद्या व ज्ञान प्राप्त करने का अच्छा अवसर हाथ लगा था। उसने न केवल पाली और संस्कृत का भलीभांति अध्ययन किया था, पर साथ ही ईसाई पादिरयों के सम्पर्क में आकर इङ्गिलिश और लैटिन से भी परिचय प्राप्त किया था $\widetilde{\ell}$ पाञ्चात्य संसार के ज्ञान य साहित्य से उसे परिचय था। इसीलिये जब वह १८५१ में सिआम का राजा बना, तो उसने अपनी स्थल व जल सेना का पनः संगठन करने के लिये युरोपियन अफसरों का सहयोग लिया। देश के शासन में परामर्श देने के लिये भी अनेक यूरोपियन लोग नियत किये गये। उसने सिआम की मद्रापद्धति में अनेक सुधार किये और एक नई टकसाल की स्थापना की। पारचात्य भाषाओं के अध्ययन को भी उसने उत्साहित किया और अपने देश के विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिये उसने यूरोपियन व्यापारियों से नई संधियां की । ये मन्धियां १८५५ में की गई थी और इन्हीं के द्वारा पाश्चात्य देशों को एकस्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी का अधिकार प्रदान किया गया था। इन्हीं सन्धियों से आयात और नियति माल पर टैक्स की दरों का भी निर्धारण किया गया था । राजा मंगकृट सिआम के विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिये उत्गुक था, पर उसके लिये उसने पारचात्य देशों के साथ ऐसी संधियां कीं, जिनसे उसके राज्य की राजनीतिक स्वतन्त्रता ही अनेक अंशों में मर्यादित व नियन्त्रित हो गई।

१८६८ में राजा मंगकूट की मृत्यु हुई और उसका लड़का चूललम्बकर्ण (राम पञ्चम) सिआम के राजसिंहासन पर आरू हुआ। उसने अपने पिता की नीति को जारी रखा। उसने सिआम से बाहर जाकर अनेक विदेशी राज्यों की यात्रा की और इससे उसका दृष्टिकोण अधिक विशाल व उदार हो गया। यही कारण है, कि उसने सिआम के बहुत से नवयुवकों को पाञ्चात्य देशों में शिक्षा के लिये भेजा और देश के शासन में सुधार के लिये अनेक यूरोपियन परामशंदाताओं को नियत किया। राजा चूललम्बकर्ण के शासनकाल में ही दासप्रथा का सिआम से अन्त किया गया। शासन के सम्बन्ध में जो सुधार उसने किये, उनमें न्याय व्यवस्था का पुनः संगठन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था । साथ ही उसने मन्त्रिमण्डल का बाकायदा निर्माण करना शुरू किया और सरकार के विविध विभागों के आय व्ययपर नियन्त्रण रखने के लिये नियमित रूप से बजट बनाने की भी व्यवस्था की। सिआम के विविध प्रदेशों को केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में लाने के लिये उसने बाबाय 🚉 सिविल सिवस का संगठन किया और विविध राजकीय कर्मचारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने लगी। इन सब सुधारों का यह परिणाम हुआ, कि िजाम का बासन मुचान एप के संगठित हो गया और शासन के संगठन के सम्बन्ध में उराकी स्थिति पायः वही हो गई, जो कि पाश्चात्य संसार के उन सुव्यवस्थित

देशों की थी, जिनमें अभी लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात नहीं हुआ था। राज्य की बिक्त के बढ़ने के साथ साथ सिआम के लोगों ने यह भी अनुभव करना शुरू किया, कि कै ५५ की सिक्यों द्वारा विदेशी लोगों को जो विशेषाधिकार शिआम में प्राप्त हैं, वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की दृष्टि से वाञ्छनीय नहीं हैं । इसलिये उनके बिलाफ आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और राजा चूललम्बकर्ण की सरकार इन सिक्यों में ऐसे संशोधन कराने में समर्थ हुई, जिनसे विदेशी राज्यों का प्रभुत्त्व व प्रभाव कम हो गया।

४२ साल वेः सुदीर्घ शासन के बाद १९१० में राजा चूललम्बकर्ण की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका लड़का बजायुष (राम पण्ठ) सिआम की राजगही पर आरूढ़ हुआ । उसकी शिक्षा पारचात्य देशों में हुई थी और वह आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से भरुीभांति परिचित था । उसने सिआम के शासन में अन्य अनेक सुधार किये और इस गात का भी प्रयत्न किया, कि एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी व तटकर के सम्बन्ध में पारचात्य देशों का जो प्रभाव सिआम में अभी शेष था, उसे दूर किया जावे। १९२५ में राजा वजायुध की मृत्यु हो गई और उसका छोटा भाई सिआम का राजा बना । १९१४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति के बाद संसार में सर्वत्र लोकतन्त्रवाद 🇌 प्रवृत्तियां जोर पकड़ रही थीं। सिआम भी इनसे अछूता नहीं रहा। राजा ब्ललम्बकर्ण के शासन काल में सिआम में मुज्यवस्थित शासन की स्थापना तो हो गई थी, पर इस शासन पर जनता का कोई भी नियन्त्रण नहीं था। सिआम के राजा एकतन्त्र व स्वेच्छाचारी शासकों के रूप में देश का शासन करते थे। इस दशा में जनता में असन्तोष का होना सर्वथा स्वामाविक था। राजा वजायुध के समय में ही जनता ने बैध राजसत्ता की स्थापना के लिये आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। अब १९३२ में यह आन्दोलन बाकायदा विद्रोह के रूप में परिणत हो गया । सिआम में अनेक स्थानों पर जनता ने विद्रोह किये । आधुनिक शिक्षा प्राप्त किये हए नव्यवक इस विद्रोह के नेता थे । राजा के लिये यह असम्भव था, कि शक्ति का प्रयोग करके इस विद्रोह को शान्त कर सके। उसे शासन सुधार करने के लिये विवश होना पड़ा । १९३२ का अन्त होने से पूर्व ही सिआम में नये शासन विधान की स्थापना की गई और उसके अनुसार जनता को बहुत से महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए । पर इन सुधारों से भी जनता को सन्तोष नहीं हुआ । उग्र राष्ट्रवादी दैशमक्तों ने अपने आन्दोलन को जारी रखा। आगे चलकर सिआम ने लोकतन्त्र-बाद की ओर किस प्रकार पंग बढ़ाया, इस पर हम अगले एक अध्यायमें यथास्थान प्रकाश हालेंगे।

सिआम की स्वतन्त्रता---लोकनन्त्रवादकी दृष्टि ने सिआम ने चाहे विशेष उस्रति

न की हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि वह अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को कायम रख सकते में समर्थ रहा । विदेशी राज्यों के साथ की गई विविध सन्वियों द्वारा तट-कर ारि एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी के सम्बन्ध में उसकी स्वतन्त्र सत्ता जिस ढंग से मर्थाविली हुई थी, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पर बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में गिआम इन मन्वियों में भी संशोधन करवा चुका था और उसकी स्थिति ्क सम्पूर्ण प्रभ्त्व सम्पन्न राज्य के समान हो गई थी। उन्नीसवीं और वीसवी म्पिटियों में भी सिआम जो पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का शिकार होने से बचा रदा, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था, कि उसके पश्चिम में बरमा पर ब्रिटेन का आधिपत्य था और पूर्व में इन्डोचायना पर फांस का । ब्रिटेन और फांस दोनों की ही यह हार्दिक इच्छा थी, कि वे सिआम को जीतकर अपने अधीन कर लें। पर यदि ब्रिटेन उसे अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करता, तो फ्रांस उसका विरोध करता और यदि फ्रांस उसे अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाना चाहता, तो विटेन इस बात की किसी भी दशा में सहन न कर सकता। उन्नीसवीं सदी में विटेन और फ्रांस एक दूसरे के कट्टर शत्र थे, साम्राज्यवाद के क्षेत्र में इन दोनों देशों ने प्रवल विरोध विद्यमान था। इसी विरोध का यह परिणाम हुआ, कि न फ्रांस सिआम को अपने कब्जे में ला सका और न ब्रिटेन ही वहां अपने प्रभत्त्व का विस्ताः 🐏 कर सका।

जनसंख्या की समस्या संसार के अन्य देशों के समान सिआम में भी इस समय आवादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी। पर सिआम की जनसंख्या की एक अन्य हमस्या यह थीं, कि वहां चीनी लोग बहुत बड़ी संख्या में आकर बसने लगे थे। १२४० में सिआम में यसने वाले चीनी लोगों की संख्या २५,००,००० के लगभग शि। १,५६,००,००० की कुल आबादी में २५,००,००० चीनियों की सत्ता (१६ प्रतिशत के लगभग) एक विकट समस्या को उत्पन्न कर रहीं थी। जाति, भाषा आदि की दृष्टि से चीनी लोग सिआग के निवासियों से सर्वथा भिन्न थे। जब सिआम में लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात हुआ, तो १६ प्रतिशत चीनी लोग एक महत्वपूर्ण समस्या बन गये। थाई जाति के राष्ट्रीय नेता यह नहीं चाहते थे, कि रीनी लोग सिआम में आकर वसे और वहां अल्पसंख्यक जाति की समस्या को उत्पन्न करें। इसीलिये सिआम की सरकार ने अनेक ऐसे कानूनों का निर्माण किया, जनका उद्देश्य चीनी लोगों के सिआम में आकर बसने को रोकना, था।

(६) मलाया

मलाया सिआम की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में हैं। उसका क्षेत्रफल ५२,२८६ वर्गमील

है। १९३९ में इसकी जनसंख्या '१५,७९,००० थी। गौगोलिक दृष्टि से मलायां का महत्त्व बहुत अधिक है। यूरोप,पिक्चिमी एशिया व भारत सेपूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया आने का सबसे छोटा रास्ता मलाया के जलडमक्ष्मच्य से होकर जाता है। इस समय पृथ्वी पर तीन जलमार्ग ऐसे हैं, जिन्होंने विविध देशों की आपस की दूरी को कम करने में बहुत सहायता दी है। पनामा की नहर के कारण प्रशान्त महासागर से अटलाण्टिक महासागर जाने के लिये दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रही हैं। इसी प्रकार स्वेज नहर के कारण भूमध्यसागर से हिन्द महासागर आने के लिये अफीका का चक्कर काटना अनावश्यक हो गया है। पर पनामा और स्वेज की ये नहरें मनुष्य की कृति है। इसके विपरीन मलाया का जलडमक्ष्मध्य प्राकृतिक हैं, और उसके कारण पश्चिमी तथा पूर्वी एशिया का जलमार्ग बहुत छोटा हो गया है। यही कारण है, कि सामरिक दृष्टि से मलाया का बहुत महत्त्व है। मलाया पर जिस राज्य का कब्जा होगा, उसके लिये पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्त्व कायम रखना बहुत सुगम होगा। इसीलिये मलाया के जलडमक्ष्मध्य में स्थित सिगापुर को ब्रिटिश लोगों ने अपनी जलसेना का प्रधान केन्द्र बनाया था।

🥍 प्राचीन इतिहास—दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य अनेक देशों के समान मलाया के प्राचीन इतिहास का प्रारम्भ वहां पर स्थापित हुए भारतीय उपनिवेशों के साथ में होता है। मलाया के इन प्राचीन भारतीय उपनिवेशों का प्रथम परिचय हमें चीनी साहित्य द्वारा मिलता है । चीनी लेखकों के अनुसार मलाया का एक प्राचीन राज्य 'लंग किया सू' था । इसकी स्थापना दूसरी सदी ई० प० में हुई थी । छठी सदी के प्रारम्भ में इगका राजा भगदत्त था और उसने आदित्य नाम का एक राजदूत चीन के सम्राट् की रोवा में भेजा था। इस प्राचीन काल में मलाया का कुछ भाग कम्बुज देश के भारतीय उपनिवंश फूनान के भी अधीन था। पुरातत्त्व सम्बन्धी अवरोपों द्वारा भी मलाया के प्राचीन भारतीय उपनिवेशों का परिचय मिलता है। मलाया में गुनांग जरई पर्वत की उपत्यका में एक विशाल हिन्दू मन्दिर के खण्डहर अब तक विद्यमान हैं। इसके समीप ही एक बौद्ध विहार के अवशेष भी पाये गये हैं। दोनों स्थानों पर संस्कृत के अनेक शिलालेख मिले हैं, जो पांचवीं सदी के हैं। श्री विष्णु वर्मन नाम के एक प्राचीन राजा की मुद्रा भी इस प्रदेश से मिली है। प्राचीन स्तूप, स्नम्भ व अन्य प्रकार की इमारतों के भी बहुत से अवशेष मलाया में मिलते हैं, जिनसे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा आदि के समान यह देश भी प्राचीन समय में भारत का उपनिवेश या और यहां भारतीय सभ्यता और संस्कृति मलीभांति स्थापित थी। बाद में मलाया के भारतीय उपनिवेश सुमात्रा के श्रीविजय साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये।

चौदहवीं सदी में अरव के मुसलमान व्यापारियों ने हम प्रदेश में व्यापार-हैं?
लिये आना शुरू किया। उस समय तक दक्षिण पूर्वी एशिया के हिन्दू व भारतीय राज्यों की शिवत बहुत निबंल हो गई थी। जिस प्रकार भारत के हिन्दू राज्य इस समय मुसलिम तुर्क व अफगान आकान्ताओं का मुकावला कर सकते में असमर्थ रहे, वैसे ही मलाया, जावा, सुमात्रा आदि के हिन्दू राजा भी अरवों की शिवत के सम्मुख नहीं ठहर मके। चौदहवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही अरवों ने भलक्का पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। मलाया में मलबका सबसे महत्वपूर्ण बन्दरगाह था। जो स्थान इस क्षेत्र में अब सिगापुर का है, वहीं प्राचीन समय में मलबका का था। मलक्का को अपने कब्जे में करके अरव लोगों ने पूर्वी एशिया के व्यापार पर अपना प्रभुत्त स्थापित कर लिया और साथ ही मलाया में अपने धार्मिक व राजनीतिक प्रभाव का विस्तार शुरू किया। मलाया में हिन्दू और बौद्ध धर्म इस समय बहुत क्षीण हो चुके थे। वहां के निवासियों ने अरवों के सम्पर्क में आकर इस्लाम को स्वीकार कर लिया।

पाडचात्य देशों में सम्पर्क—सोलहवीं सदी के शुरू में पोर्तुगीज लोगों ने व्याप्तिक के लिये इस प्रदेश में आना शुरू किया । उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी, कि दिक्षण-पूर्वी एशिया के व्यापार में मलक्का का कितना अधिक महत्त्व हैं । १५११ में अत्वुकर्क के नेतृत्त्व में पोर्तुगीज लोगों ने मलक्का पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । १५११ से १६४१ तक मलक्का पोर्तुगाल के आधिपत्य में रहा और इसे अपना केन्द्र बनाकर पोर्तुगीज लोग इन्डोनीसिया के विविध द्वीपों में अपने व्यापार का विस्तार करते रहे । सतरहवीं सदी में हालैण्ड के लोग इस क्षेत्र में अपने व्यापार का विस्तार करने के लिये प्रवृत्त हुए और १६४१ में उन्होंने मलक्का को पोर्तुगीओं से जीत लिया ।

बिटिश प्रभुत्त्व—अठरहवीं सदी के अन्त में जब फांस और ब्रिटेन का युद्ध शुरू हुआ और नैपोलियन की विजयों के कारण हालैण्ड पर फांस का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो ब्रिटेन ने हालैण्ड के समुद्र पार के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। इसी समय १७९५ में मलक्का भी ब्रिटिश लोगों के हाथों में चला गया। वीएना की कांग्रेस (१८१४) के निर्णयों के अनुसार जब इन्डोनीसिया के विश्व हींप फिर हालैण्ड को वापस मिले, तो १८१९ में मलक्का भी डच लोगों को दे दिया गया। पर इसी साल अंगरेजों ने मलक्का के अन्यतम राज्य जोहोर के सुलतान से उस प्रदेश को कय कर लिया, जिसमें आजकल सिंगापुर स्थित है। मलक्का को कुछ

माल तक अपने कब्जे में रखने के कारण अंगरेज लोग मलीभांति अनुभव करते थे, कि इस बन्दरगाह का व्यापारिक व सामरिक दृष्टि से कितना अधिक महत्त्व है। डम्मीलये वे मलनका के जलडमरूमध्य में अपना एक अड्डा बनाने की उत्सुक थे। मिगापुर को उन्होंने इसी दृष्टि से जोहोर के मुलतान से खरीदा था। १८२४ में अंगरेजों ने डच लोगोंसे एक समझौता किया, जिसके अनुसार मुमात्रा में अपने प्रभुत्त्व में विद्यमान प्रदेशों के बदले में उन्होंने मलक्का को प्राप्त कर लिया। १८२४ के इस समझौते के अनुसार ब्रिटेन और हालैण्ड में यह भी तय हुआ, कि मलाया में अपने प्रभत्त का विस्तार करने में अंग्रेज लोगों को खुली छट्टी रहेगी और ब्रिटिश लोग समात्रा, जावा आदि इन्डोनीसियन द्वीपों में डच लोगों को अपनी शक्ति का विस्तार करने देंगे। मलबका के जलडमरूमध्य पर अपना कब्जा कायम करके अंग्रेजों ने सिंगापूर की उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान दिया । इस समय दक्षिण-पूर्वी एशिया में अंग्रेजी प्रभुत्व में विद्यमान प्रदेशों का प्रधान शासक रार टामस स्टाम्फोर्ड रैफल्स था। नैपोलियन के युद्धों के अवसर पर जब इन्डोनीसिया के द्वीपों पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो गया था, तो उनका शासन रैफल्स के ही सुपुर्द था । रैफल्स बहुत ही चाणाक्ष और कुशल राजनीतिज्ञ था । वह समझता था, कि दक्षिण-पूर्वी और र्दुन एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का जो यह सुवर्णीय अवसर उपलब्ध हआ है, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। वह स्वप्न लेता था, कि भारत के समान इस क्षेत्र में भी शीध ही ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना हो जायगी। वीएना की कांग्रेस के निर्णय से उसे बहुत निराशा हुई थी। पर जोहोर के सुलतान से सिगापुर खरीदकर उसने यह प्रयत्न किया, कि उसे एक ऐसे बन्दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, जो न केवल पूर्वी एशिया के व्यापार का प्रधान केन्द्र बने, अपित् साथ ही ब्रिटेन की जलकावित का भी प्रधान अड्डा हो। इसीलिये उसने नियमय किया, कि सिंगापुर में सब देशों के व्यापारी खुले तौर पर व्यापार कर सकें, और वहां पर आनेवाले व्यापारिक माल पर किसी प्रकार का कर न लिया जावे । सर रैफल्स की नीति का कार कि एवं एक कि शी झ ही सिगापुर दक्षिण-पूर्वी एशिया का सबसे वडा 🐪 😘 🔆 🔆 😘 🙃 । कुछ समय बाद अंग्रेजों ने सिंगापुर की किलाबन्दी भी शरू की, और उसे अपनी जलशक्ति का प्रभूतन अङ्डा वना दिया।

यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम संक्षिप्त रूप से भी उस प्रक्रिया का उल्लेख कर नकों, जिनमें अंग्रेजों ने घीरे नीरे पम्पूर्ण मध्यया पर अपना आधि-। पत्य स्थापित कर लिया या । जनीतनी नदी के यान तक मत्याया में यह दशा थी, कि वहां बहुत में छोटे लोटे राज्य थे, जो आपस में निरात्य छन्ते रहते थे। इन

्राज्यों में भी राजगृही के झगड़े बहुधा होते रहते थे और विविध सरदार अपने राजा या मुळतान के विरुद्ध विद्रोह कर देने में तत्पर रहते थे। सिंगापूर व उसके समीप के कतिपथ द्वीप व प्रदेश ब्रिटिश सरकार के अधीन थे । इन्हें स्ट्रेट्स सेटलर्गिक्ट कहा जाता था । स्ट्रेट्स सेटलमैण्ट (अन्तरीप की बस्ती) के अन्तर्गत निम्नलिक्त द्वीप व प्रदेश थे--सिंगापुर, मलक्का, पेनांग, बेलेज्ली प्रोविन्स और डिन्डिंग्स। इनमें से पेनांग पर ब्रिटिश लोगों ने १७८६ में अपना अधिकार स्थापित किया था. सिंगापूर को १८१९ में जोहोर के सूलतान से कय किया गया था और मलवका को १८२४ में हालैण्ड के साथ की गई सन्य (लण्डन की सन्य) द्वारा स्मात्रा के कतिपय प्रदेशों के बदले में अधिगत किया गया था । वेलेज्ली प्रोविन्स मलक्का के उत्तर में और पेनांग के दक्षिण में स्थित है, और पेनांग के साथ ही इस प्रदेश की भी ब्रिटिश लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया था । डिन्डिंग्स की स्थिति पेनांग के समीप ही दक्षिण में हैं। स्ट्रेट्स मेटलमैण्ट के ये प्रदेश शामन की दिष्ट से १८६७ तक भारत के साथ सम्बद्ध थे । १८६७ में इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत एक काउन कोलोनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इनका शासन ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश विभाग (कोलोनियल डिपार्टमेन्ट) द्वारा किया जाने लगा। स्ट्रैट्स सेटलमैण्ट का कुल क्षेत्रफल १२६० वर्गमील है, और १९३९ में इसकी जैसी मंख्या १३.८०,००० थी।

मलाया में केवल स्ट्रेट्स सेटलमैण्ट का प्रदेश ही ऐसा था, जो ब्रिटेन के सीधे शासन में था। मलाया के अन्य प्रदेश दो भागों में विभक्त थे। फिडरेटेड मलाया स्टेट्स (संघ में संगठित मलाया राज्य) और अनिफडरेटेड मलाया स्टेट्स (संघ में संगठित मलाया राज्य)। दोनों प्रकार के राज्य ब्रिटेन की अधीनता स्वीकृत करते थे, और ब्रिटिश अधीनता में उनकी स्थिति प्रायः वैसी ही थी, जैसे कि भारत की देशी रियासतों की थी। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक मलाया के ये विविध राज्य स्वतन्त्र थे और इन पर विविध राजवंशों के मुसलिम सुलतानों का गासन था। पर इन राज्यों की दशा अच्छी नही थी। इनमें अनेक प्रकार के समझे जारी रहते थे। इनकी राजनीतिक दुदंशा से लाभ उठाकर ब्रिटेन ने इनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप किया और इनके साथ इस प्रकार की सन्धियों की, जिनमें कि ये राज्य ब्रिटेन की मंरक्षा व प्रमुत्व में आ गये। भारत में बड़ीद्रा, ग्वालियर, पटियालों, भूपाल आदि के राजाओं के साथ भी इसी प्रकार की सन्धियों कि विधिध राज्यों में ब्रिटिश रेजीडेन्ड नियुवत किये गये और उन्हें यह कार्य सुपुर्द किया गया कि वे इन राज्यों के शासन गर नियन्त्रण रखें। १८९६ में मलाया के चार राज्यों कि वारा राज्यों के शासन गर नियन्त्रण रखें। १८९६ में मलाया के चार राज्यों

का एक संघ (फिडरेशन) बनाया गया । ये चार राज्य निम्नलिखित थे-पेशक. सलागोंर, नेग्री सेम्बिळान और पेहांग। संघ में सम्मिलित इन चार राज्यों में उनके अपने मुलतानों की शक्ति निरंतर कम होती गई और संघ सरकार की शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती गई। फिडरेटेड मलाया स्टेट्स की सरकार के प्रवान को रेजिडेन्ड-जनरल कहते थे और उसकी निय्क्ति ब्रिटिश संस्कार द्वारा की जाती थी। संघ सरकार की राजधानी कुआला लुम्पूर को बनाया गया था, जो कि सेलागोंर राज्य की प्रमुख नगरी थी। कुजाला लुम्पूर में रहता हुआ क्रिटिश रेजिडेन्ड-जनरल अपने अधीन सिविल सर्विस की सहायता से इन चार मलाया राज्यों के शासन का संचालन करता था। इन राज्यों में सुलतानों के अधिकार नाम-मात्र को ही थे। उन्हें राजकीय आमदनी का अच्छा वडा भाग निज खर्च के लिये प्रदान कर दिया जाता था, और वे बड़े वैभव व सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते थे। पर शासन सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग वे नहीं कर मकते थे। शासन की दिष्ट से उनकी शक्ति उतनी भी नहीं थी, जितनी कि भारत की देसी रियासतों के राजाओं की थी। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद जब संसार में सर्वत्र राष्ट्रीय स्वतत्त्रता का आन्दोलन प्रबल हुआ, तो फिडरेटेड मलाया स्टेट्स में इस आन्दोलन नैंगह रूप धारण किया, कि ब्रिटिश रेजिडेन्ट जनरल (जो अब चीफ सेकेंटरी कहाने लगा था) की शक्ति का अन्त कर सुलतानों के प्रभुत्त्व की पूनः स्थापना की जाय। इन राज्यों के युरोपियन निवासी इस आन्दोलन के विरुद्ध थे। उन्होंने शक्तिभर यह प्रयत्न किया, कि मलाया के राज्यों पर ब्रिटिश जासन यथापूर्व कायम रहे। १९३५ में फिडरेटेंड मलाया स्टेट्स के शासन में कतिपक सुधार किये गये, जिन द्वारा चीफ सेकेटरी के पद को नष्ट कर दिया गया और स्टेट्स सैटलमेन्ट के गवर्नर को ही यह कार्य भी सुपूर्व किया गया, कि वह फिडरेटेड मलाया स्टेट्सके हाई किमस्तर के रूप में उनके शासन पर नियन्त्रण रखे। इस प्रकार १९३५ के सुधारों द्वारा मलाया के राज्यों के राष्ट्रीय नेताओं को आंश्रिक रूप से संतुष्ट किया गया । पर इन मुक्षारों से मलाया के लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए । इसीलिये उन्होंने अपने आन्दोलन को जारी रखा । बिटिश बासन के विषद असत्तोष मलाया में निरन्तर बढता गया ।

मलाया में पाच राज्य ऐसे थे, जो फिडरेटेड मलाया स्टेट्स के अन्तर्गत नहीं थे। इनके नाम निम्नलिखित हैं—जोहोर, केलान्तन, बेनाान्, केदाह और पेलिस। जोहोर मलाया के दक्षिण परेश में हैं, और थेप नारों राज्य गृहर उत्तर में। उनके बीच में फिडरेटेड मलाया स्टेट्स के चारों राज्यों की स्थिति है। नाम को ये पांचों राज्य स्वतन्त्र थें, पर वस्तुतः इनपर जिटेन या उसी देंग से प्रमुख्य का जैसे कि भारत में देसी रियासतों पर था। इनसे इस ढंग की सिन्धयां बिटिश सरकार ने की थीं, जिसके कारण इन राज्यों के शासनसूत्र का संचालन ब्रिटेन के हाथों में बर गया था। इन राज्यों में ब्रिटेन के प्रतिनिधि नियुक्त होते थे, और इनके सुल्किंग ब्रिटिश प्रतिनिधियों के परामर्थ के अनुसार शासनकार्य करने के लिये विध्य थे।

आर्थिक उन्नति-- पिछली एक सदी में मलाया ने आर्थिक क्षेत्र में अच्छी उन्नति की है। इसका मुख्य कारण वहां की खनिज सम्पत्ति है। मलाया की खानों में टीन प्रचर परिमाण में उपलब्ध होती है। संसार भर में जितनी टीन उत्पन्न होती है, उनका २९ प्रतिशत अकेले मलाया की खानों से प्राप्त किया जाता है। इन्हो-नीसिया और सियाम टीन की दिष्ट से मलाया से पीछे हैं। संसार की कुछ टीन का १४ प्रतिशत इन्डोनीसिया से और १० प्रतिशत सिआम से प्राप्त होता है। टीन सम्बन्धी ये अंक १९३८ की उत्पत्ति के आवार पर दिये गये है। मलाया की यह टीन विदेशों में प्रचुर परिमाण में बिकती थी, और इससे गलाया की आधिक समद्भि में बहुत 'सहायता मिलती' थी। इस देश की आर्थिक समृद्धि का दूसरा हेतू रबड़ थी। मोटरकारों के निर्माण के कारण अमेरिका, यूरोप आदि में रबड की मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि मोटरों के पहिने रबड़ द्वारा ही बनते थे। १९३८ में संसार में जितनी रबड़ उत्पन्न होती थी, उसका ९० प्रतिशत भाग विक्री पूर्वी एशिया में उत्पन्न होता था। दक्षिण-पूर्वी एशिया में उत्पन्न होनेवाली कुल रबंड का ४० प्रतिशत से भी अधिक भाग अकेले मलाया में पैदा होता था। इससे यह गलीभांति समझा जा सकता है, कि संसार के बाजारों के लिये मलाया की रबड़ का महत्त्व कितना अधिक था। टीन और रबड़ के अतिरिक्त नारियल और नावल के उत्पादन में भी मलाया का प्रमख स्थान था। इनकी भी संसार के बाजारों में अच्छी मांग थी । दक्षिण-पूर्वी एशिया का व्यापार सिंगापूर में केन्द्रित था, और संसार के प्रायः सभी देशों के व्यापारी सिगापुर के व्यापार में हाथ बंटाने के लिये वहां आकर बसने लग गये थे । यही कारण है, कि १९४० तक सिंगापुर की जनसंख्या ६,००,००० से भी ऊपर पहुंच गई थी।

आवादी की समस्या—संसार के अन्य देशों के समान मलाया की जनसंख्या भी इस समय निरन्तर बढ़ रही थी। वहां की खानों आदि में काम करने के लिये चीन और भारत से मजदूर लोग वड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे थे। टीन की लानों और रबड़ के बगीचों में मजदूरों की बहुत अधिक मांग थी। इसीलियें इनमें कि करने के लिये चीनी और भारतीय मजदूर बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे थे। इनके आने का यह परिणाम हुआ, कि मलाया में विदेशी लोगों की संख्या मलाया के लोगों की अपेक्षा अधिक बढ़ गई। १९३७ में मलाया की कुल जनसंख्या ५५,

उ९,००० थीं। इसमें १६ फीसदी के लगभग भारतीय थे, और ३४ प्रतिशत के लुगभग चीनी लोग थं। इतनी वड़ी संख्या में भारतीयों और चीनी लोगों की सत्ता मंलाया के लिये राष्ट्रीय दृष्टि से एक विकट समस्या थी। शुरू में ये विदेशी लोग अकेले मलाया में आते थे, इनके परिवार साथ में नहीं आते थे। पर ज्यों ज्यों समय बीतता गया, चीनी और भारतीय मलाया में स्थिर रूप से बस गये और उनके परिवार भी वहीं आ गये। इस स्थित में चीनी और भारतीय लोगों का एक ऐसा वर्ग मलाया में हो गया, मलाया ही जिसकी मातृभूमि थी। पर भाषा, जाति, सभ्यता आदि की दृष्टि रो ये मलाया के लोगों से सर्वथा भिन्न थे। भारत और चीन की सरकारें अपने मलाया प्रवासी देशबन्धुओं के हितों की उपेक्षा करें, यह सम्भव नहीं था। इसीलिये इन देशों ने मलाया के आन्तरिक मामलों में विलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी, और मलाया की राष्ट्रीय स्वतन्वता की दृष्टि से यह बात बहुत वाञ्छनीय नहीं थी।

धार्मिक दशा—मलाया के निवासी इस्लाम को स्वीकृत कर चुके थे । पर वहां जो चीनी और भारतीय लोग आकर बस रहे थे, वे मुसलिम नहीं थे । बहुसंस्थक चिनी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और भारतीय लोग हिन्दू धर्म को मानने वाले थे । बहुसंस्था गये थे, अपितु बहुत से व्यापारी, महाजन और पूंजीपित भी वहां जाकर आवाद हुए थे । इस प्रकार भलाया में बौद्ध, मुसलिम और हिन्दू तीन धर्मों की सत्ता थी । ईसाई पादरी भी वहां अपने धर्म का प्रचार करने के लिये तत्पर थे और पिछड़ी हुई जातियों के बहुत से लोग ईसाई धर्म को अपनाते जा रहे थे । इन चार धर्मों की सत्ता के कारण मलाया में धार्मिक समस्या भी अधिक अधिक जिटल होती जा रही थी।

सिगापुर का सामरिक अड्डा - जिटिश लोगों ने सिगापुर का केवल व्यापारिक केन्द्र के रूप में ही विकास नहीं किया था, अपितु साथ ही पूर्वी एशिया में उसे अपना प्रमुख सामरिक अड्डा भी बनाया था। हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर में जिटिश साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत था। भारत, लंका और बरमा उसके अधीन थे। मलाया, बोनियो, पूर्वी गाइनिया आदि पर भी उसका प्रभुत्त था और चीन में अनेक प्रकार के व्यापारिक व अन्य विशेषधिकार जिटेन ने प्राप्त किये हुए थे। इस तृतिस्तृत साम्राज्य भी रक्षा तभी सम्मव थी, जब हिन्द और प्रभान्त अहानागरों के बीन में बिटेन का कोई बिनियाली जमितक केन्द्र हो। इसके उसि मिगापुर सम्भ अधिक उन्युक्त स्थान था। बिटेन ने वहां अपनी जलसेना व अंगी जहानां को प्रभुर गावा में स्थापित किया था, और उसकी किलावची इतनी मजपून एर की भी, कि बिटेन को इस बात का पुरा मरोसा था, कि कोई विदेशी अलसेना

सिगापुर को विजय नहीं कर सकती । ब्रिटिश सरकार को यह खयाल नहीं था, बि स्थलमार्ग से भी सिगापुर पर आक्रमण किया जा सकता है । १९३९-४५ के महा-युद्ध के अवसर पर जापान ने किस प्रकार स्थलमार्ग द्वारा मलाया को अपने अधी किया और फिर ब्रिटिश सेनाओं को सिगापुर छोड़ने के लिये विवश किया, इसपर हम सथास्थान प्रकाश टालेगे ।

(७) बरमा

दक्षिण-पूर्वी एशिया के। सबसे अधिक पश्चिमी देश बरमा है, जो क्षेत्रफल में २,६१,६१० वर्गमील है, और १९३९ में जिसकी आबादी १,६६,००,००० थी। १९३७ तक बरमा भारत का ही एक प्रान्त था। बाद में उसे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत एक पृथक राज्य के रूप में परिवर्तित किया गया और अय वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र राज्य है। बरमा के सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पाठक उसके इतिहास से भलीभाति परिचित होंगे। भारत के आधुनिक इतिहास के सम्बन्ध में जो पुस्तकों हमारे देश में पढ़ाई जाती हैं, उनमें बरमा का आधुनिक इतिहास भी दिया जाता है। पर यहां यह ध्यान रखना चाहिये, कि एशिया के भूगोल व इतिहास में बरमा का सम्बन्ध भारत की अपेक्षा दक्षिण-पूर्ण रिशया के साथ अधिक है।

प्राचीन इतिहास—वरमा के प्राचीन इतिहासका प्रारम्भ भीवहां पर स्थापित हुए भारतीय उपनिवेशों हारा होता है। अराकान की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार वहां का पहला राजा वाराणसी से आया था और उसने पहले पहल रामावती द्वीप को बसाया था। यही प्रदेश अब राम्ब्यी कहाता है। अराकान के समान मध्य और उत्तरी वरमा में भी अनेक भारतीय राज्य स्थापित थे। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अग्नाद अशोक के समय बौद्ध धर्मका विदेशों में प्रसार करने के लिये आचार्य मौद्गिल व्रवास ने जो महान् आयोजन निया था, उसमें कतिपय बौद्ध भिक्षु बरमा में भी प्रमं प्रचार के लिये गये थे। तीसरी सदी ई० पू० से पहले ही बरमा में अनेक भारिय खपनिवेश स्थापित हो चुके थे। इनके निवासी श्रीव धर्म के अनुयायी थे। स्थोक के समय में (तीसरी सदी ई० पू०) में यहां बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ गिर धीरे घीरे वरमा के भारतीय उपनिवेश बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये।

मध्यकाल में बरमा का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य पागन का था। वहीं गर वर्तमान माण्डले के दक्षिण में इरावदी नदी के तट पर स्थित था। ग्यारहवीं विभें अनावत नामके वीर पुरुष ने एक नथे राजवंशका वहां प्रारंभ किया। वोसदी ह लगभग तक अनावत द्वारा स्थापित पागन का राज्य बरमा में बहुत प्रवल रहा। अराकान, तनासरिम और शान राज्यों के प्रदेश पागन के राज्यों के अधीन थे।
पूरान के राजाओं ने दक्षिणी चीन के यूनान प्रान्त पर भी आक्रमण किया था और
कुछ समय के लिये यह प्रदेश भी पागन के राज्य के अन्तर्गत रहा था। तेरहदी
सदी में जब मंगोल जानि का उत्कर्ष हुआ और चंगेज खां के नेतृत्व में विशाल
मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो पागन का राज्य भी मंगोल आक्रमणों से
अछूता नहीं रह मका। दक्षिणी चीन से मंगोल सेनाओं ने बरमा पर भी आक्रमण
किया और पागन राज्य की शक्ति का अन्त कर दिया। पागन राज्य के पतन में
सोलहदीं नदी तक बरमा अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, और वहां
कोई भी ऐसा राजा नहीं रहा, जो अन्य सब राज्यों को जीतकर अपने प्रभूत्य की
स्थापना में नमर्थ हो। इस समय बरमा में जो विविध राज्य थे, उनमें आदा,
वेगू, तुंगू और अराकान के राज्य प्रमुख थे।

बरमा के इन विविध राज्यों में अराकान का राज्य समुद्र के तट पर स्थित था। इसीलिये वहां पहले अरब और बाद में पोर्तुगीज व्यापारी व्यापार के लिये आने जाने लगे । अरब व्यापारियों के सम्पर्क में आकर बहुत से अगकानी लोगों ने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार किया। अराकान के मल्लाह बंगाल की खाड़ी को वारकर भारतवर्ष में आने जातेथे और इसीलिये मुगल बादशाहत के साथ भी अरा-कान का सम्बन्ध था । बरमा के बिविध राज्यों में तुंगू सबसे अधिक वाक्तिशाली था । मोलहवी सदी के उत्तरार्ध में तुंगू के राजा ने पोर्तुगीज लोगों की सहायता मे अपने सेना का नये सिरे से संगठन किया । पोर्त्गीज लोग बन्दुक और तीप का प्रयोग जानते थे। इस समय तक बरमा के लोग बारूद के प्रयोग से अपरिचित थे। अतः तुंगू के राजा के लिये यह सुगम था, कि वह बरमा के अन्य राज्यों को जीनकर अपने अधीन कर सके । धीरे धीरे तुंगु ने अराकान के अतिरिक्त सम्पूर्ण बरमा को जीतकर अपने अधीन कर लिया । बरमा की सेनाओं ने सिआस पर भी आक्रमण किये और सिआम की राजधानी अयोध्या पर अपना अधिकार कर लिया । सत्रहर्वी सदी के उत्तरार्ध में तुंगु के राज्य का हास हुआ और आवा का राजवंश बहुत प्रबन्त हो गया । १८८५ में जब बरमा पर ब्रिटिश लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो बरमा आवा के उसी राजवंश के शासन में था। आवा राज्य के जिस राजा ने बरमा के अन्य राज्यों को अपनी अधीनता में लाने में विशेष कर्त त्व प्रदर्शित किया था, उसका नाम अलोम्प्रा था । अठारहवीं सबी के मध्य माग में जब बलाइव भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाल रहा था, अलोम्प्रा ने पेगू, तनेसरीम आदि की जीतकर अपने अधीन कर लिया । १७८४ में उसने अराकान को भी जीत लिया। १७९३ तक प्रायः सम्पूर्ण बरमा आवा राज्य के अधीन हो गया था जीन

बरमा की सेनाएं पश्चिम की ओर चटगांच पर आक्रमण करने को तत्पर हो गईं थी।

विटिश आधिपत्य-उन्नीसवी सदी के प्रारम्भिक भाग में बरमा एक स्वतन्त्री राज्य था और आवा का राजवंश उसपर सुव्यवस्थित रूप से शासन कर रहा था। युरोपियन लोगों ने समुद्र तट के बन्दरगाहों पर अपने व्यापारिक अड्डे कायम किये हुए थे, पर देश के शासन पर उनका कोई प्रभाव न था। रंगन के बन्दरगाह में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी विद्यमान थी। पर इस समय तक भारत में ईस्ट उण्डिया कम्पनी की जिन्त भलीभांति स्थापित हो चुकी थी । पूर्वी भारत के अनेक अदेश उसके आधिपत्य में आ गये थे। उबर बरमा में एक ऐसे राजवंश का शासन था, जो प्राय: सम्पूर्ण देश को अपने अधीनता में ला चुका या, और जो आसाम व चटगांव की ओर भी अपनी शक्ति के विस्तार के लिये ततार था। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि अंग्रेजों और बरमी सरकार में संघर्ष हो । १८१७ में बरमा की सेनाओं ने आसाम पर आक्रमण किया। आसाम में बरमा की सैनाओं को अच्छी सफलता मिली। अंग्रेजों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे बरमा के इस शक्ति-प्रदर्शन को सह सकें। परिणाम यह हुआ, कि १८२४ में ब्रिटेन और बरमा का प्रथम युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों के जहाजी बेड़े ने रंगुन पर कब्जा 🖑 लिया, पर वे बरमा में अधिक आगे नहीं बढ़ सके । इसी बीच में बरमा के सेनापति बन्दला ने बंगाल पर आक्रमण किया और वहां अंग्रेजी सेनाओं को परास्त किया। दो साल के निरन्तर युद्ध के बाद ब्रिटेन और वरमा में सन्धि हो गई। इसके अनसार अराकान और तैनेसरीम के प्रदेश बरमा से अंग्रेजों ने प्राप्त किये । आसाम से बरमा की सेनायें वापम बुला ली गई। आवा में ब्रिटिश रेजीडेन्ट की नियुक्ति की गई ्और बरमा ने १५,००,००० रुपया हरजाने के रूप में ब्रिटिश सरकार को देना स्वीकार किया । १८२६ की इस सन्धि की शर्ती से यह रगण्ट है, कि बरमा के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह बिटिश सेनाओं का मुकाबला वर सके। उसने युद्ध में अच्छी बीरता प्रदर्शित की थी, पर अन्त में विवश होकर उसे ब्रिटेन के साम्राज्य-बाद के सम्मख सिए झकाना पड़ा था।

पर १८२६ की यह सब्धि देर तक कायम नहीं रह सभी । व्यापार के निमित्त से जो ब्रिटिश व्यापारी रंगून में वसे हुए थे, वे अपने की बरमा के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्क्रुब्द समझते थे । वे वरमा के लोगों से बहुत उद्दुष्टता के साथ पेश कि थे । इसका परिणाम यह हुआ, कि बरमा की सरकार ने उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया । ब्रिटेन के व्यापारिक हितों की रक्षा के नाम पर १८५२ में ब्रिटिश सरकार ने फिर बरमा के व्यापारिक हितों की रक्षा कर दी । रंगून, प्रोम, पेमू आदि

पर क्रिटिश सेनाओं का करणा हो गया। १८५२ के इस युद्ध के परिणामस्वल्य दक्षिणी बरमा ब्रिटेन के आधिपत्य में आ गया। उत्तरी बरमा पर अब भी आवा के राजवंश का शायन रहा। पर आवा के राजा भी इस समय पूर्णक्य से स्वाधीन नहीं रहे थे। उनकी स्थिति अधीनस्थ राजाओं के सदृश हो गई थी। आवा में ब्रिटिश रेजिडेन्ट नियुक्त था और बह देश के शासन में हस्तक्षेप करता रहता था।

१८२६ की सन्ति हारा अराकान और तैनेसरीम ब्रिटेन के आधिपत्य में आये थे, १८५२ के युद्ध की समाप्ति पर पंगुका प्रदेश ब्रिटेन की अधीनता में आ गया था । स्वतन्त्र वरमा के पास अन्न नस्द्र तट का सर्वथा अभाव था । समुद्रतट पर ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने व्यापारिक केन्द्रों को भलीभांति स्थापित कर रखा था. पर वे इतने से ही संतुष्ट नहीं थे । वे उत्तरी वरमा में भी अपना व्यापारिक प्रभूत्व स्थापित बारना चाहते थे और इस बात के लिये प्रयत्न कर रहे थे, कि आवा के राज्य में भी व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करें । १८७८ में आवा के राजिंमहासन पर थेवो आरूढ़ हुआ। यह एक शक्तिशाली और महत्त्वाकांक्षी राजा था। इसने अपने राज्य में ब्रिटिश लोगों के हस्तक्षेप को अनुचित समझा और स्वतन्त्र राजा के 🗝 क्यात आचरण प्रारम्भ कर दिया । ब्रिटिश लोग चाहते थे, कि बरमा के विदेशी व्यापार पर उनका एकाधिपत्य हो । पर थेबो ने फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि से व्यापारिक सन्धियां करने का प्रयत्न किया । थेवो के राज्य की पूर्वी सीमा इन्डो-चायना के साथ लगती थी, और इस देश पर फांस अपने प्रभ्तव की स्थापना में तत्पर था। अतः थेवो ने यह यत्न किया, कि ब्रिटेन के मुकाबले में फांस के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करे। १८८३ में बरमा के एक प्रतिनिधि मण्डल ने पेरिस की यात्रा की और १८८५ में एक फेञ्च प्रतिनिधि मण्डल ले आया । थेबो ने ब्रिटिश रेजिडेन्ट को अपनी राजवानी में रखने से इन्कार कर दिया था और वह ब्रिटिश क्यापरियों के मुकाबले में फेञ्च लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने का पक्षपाती था। इस समय फांस और ब्रिटेन साम्राज्यवाद के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रधान प्रतिस्पर्धी थे। इस दशा में यह सम्भव नहीं था, कि ब्रिटेन बरमा में फ्रांस के बढ़ते हुए प्रभाव की सहन कर सके। १८०५ में ही ब्रिटिश सेनाओं ने उत्तरी बरमा ं भर आक्रमण कर दिया । बरमी सरकार उनका मुकानला नहीं कर सकी । तीधा ्रित्रों आवा और गाण्डले (इस समय तक स्वतन्त्र वरमा की राजवानी काण्डले बन चुका था) पर बिटिश सेनाओं का कब्जा हो गया । १ जनवरी, १८८६ की बिटिश सरकार ने चोषणा की कि बरमा पर ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना की जाती हैं। बरभा के दाजा को भिनक्तार करके भारत भेज दिया गया और बरमा को ब्रिटिश

साम्राज्य में शामिल कर लिया गया । इस प्रकार बरमा की स्वतन्त्र सत्ता का अन्त हुआ ।

बिटिश लोगों ने बरमा को जीतकर उसे बिटिश भारत के एक प्रान्त के रूप के परिवर्तित कर दिया । ज्यों ज्यों ब्रिटिश भारत के शासन में स्वशासन की स्थापना हुई, त्यों त्यों बरमा के शासन में भी जनता का सहयोग बढ़ता गया। १९०९ के मिन्टो-मार्ले सुधार और १९१९ के मांटेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार बरमा पर भी लाग कियं गये । १९१९ के सुधारों के अनुसार भारत के केन्द्रीय शासन में जो विधानसभी स्थापित की गई थी, बरमा के प्रतिनिधि भी उसमें भामिल होते थे। पर भारत के समान बरमा में भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र शासन के आन्दोलन निरन्तर जोर पकड़ते जाते थे । इण्डियन नेशनल कांग्रेस में बरमा भी सम्मिलित था और वहां अनेवा क्यान्तिकारी दल भी ब्रिटिश शासन से अपने देश की स्वतन्त्र कराने के लिये प्रयत्नशील थे। बरमा के राष्ट्रीय नेता जहां अपने देश को ब्रिटेन के आविपत्य में स्वतन्त्र कराने को इच्छक थे, वहां भारत के साथ राजनीतिक सम्बन्ध भी उन्हें पसन्द नहीं था। माइमन कमीशन (१९२७-२८) के सम्म्ल बरमा के नेताओं ने अपनी पृथक सत्ता और भाग्त से सम्बन्ध विच्छेद की मांग पेश की। इसीलियं १९३१ में बरमा के शामन की समस्याओं को हल करने व वहां के राष्ट्रीय नेताओं से समझौता करने के लिये पुथक गौल मेज कान्फरेन्स का आयोजन किया गया । १९३७ में बरमा भारत सेपृथक् हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उसकी पृथक् मत्ता स्वीकृत कर की गई। इस समय बरमा के वासन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था हई, उसके अनुसार वहां आंशिक रूप से स्वराज्य की स्थापना हुई। पर बरमा के लोग इसमें मानुष्ट नहीं थे। वे पूर्ण स्थराज्य चाहते थे। इसीलिये वहां स्वतन्त्रता का आन्दोलन निरन्तर जोर पकड़ता जा रहा था।

अधिक क्षेत्र में आधुनिक युग में बरमा ने अच्छी उन्नति की। रैलवे और सड़कों के निर्माण के कारण बरमा में व्यापार का विकसित होना अधिक सुगम हो गया। बरमा की निर्माण का कारण बरमा में व्यापार का विकसित होना अधिक सुगम हो गया। बरमा की निर्मा नौकानयन के योग्य हैं, ग्रेट ब्रिटेन में बने हुए याण्पशित से चलने वाले जहाज उनमें दूर दूर तक आने जाने लगे। पेट्रोलियम बरमा का प्रमुख विनिज पदार्थ है। इसके लिये बहुत से तैलकूप वहां तैयार किये गये। बरमा का में होलियम प्रचुर परिमाण में विदेशों में जाने लगा। किती के पैवावार में चावल एक ऐसा अन्न था, जो बहुत बड़ी मात्रा में बरमा से भारत आदि देशों में विन्नय के लिये जाना था। पेट्रोलियम और चावल के निर्यात के कारण बरमा की आधिक समृद्धि में बहुत सहायता मिली। इसमें सन्देह नहीं, कि बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में आवृत्तिक युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव बरमा में निरन्तर बढ़ता जाता था। एक

तरफ जहां उसका आर्थिक विकास हो रहा था, वहां साथ ही उसमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना भी जोर पकड़ रही थी । घीरे धीरे वरमा में वे परिस्थितिया उत्पन्न हो रहो थीं, जिन्होने आगे चळकर उसे एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया ।

(८) दक्षिण-पूर्वी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

दक्षिण पूर्वी एशिया के इतिहास की इस अत्यन्त संक्षिप्त रूपरेखा को लिख चुकर्न के बाद अब यह उपयोगी होगा, कि हम उपसंहार के रूप में उन बातों का निर्देश कर दें, जो इस क्षेत्र की राजनीति में विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है—

- (१) दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी देश व द्वीप विदेशी राज्यों के प्रभुत्त्व य प्रभाव में थे। फिलिप्पीन द्वीप समूह पर अमेरिका का शासन था। इन्होनीसिया हालैण्ड के अधीन था और इन्डोनीसिया कें कांतपय द्वीप बिटेन के अधीन थे। तिमोर द्वीप का कुछ भाग व अन्य कतिपय द्वीप पोर्तु गाल के कब्जे में थे। सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में केवल सिआग ही एक ऐसा देश था, जो किसी विदेशी राज्य के शासन में नहीं था। पर वहां भी एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी व व्यापारिक विशेषाधिकारों के कारण ऐसी स्थिति उन्ति हो गई थी, जिसमे सिआम को पूर्ण प्रभुत्त्व सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य नहीं समझा जा सकता था।
- (२) उन्नीसवीं सदी में इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों व द्वीपों पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये पाश्चात्य देशों में परस्पर विरोध व संघर्ष जारी था। पर बीसवीं सदी में इस विरोध व संघर्ष का अन्त हो गया था। जो प्रदेश जिस राज्य के अधीन था, वहां उसकी सत्ता को अन्य राज्यों ने स्वीकार कर लिया था। इस स्थिति के कारण निम्नलिखित थे—(क)—बीसवीं सदी में बिटेन और फांस के साम्राज्यवाद सम्बन्धी संघर्ष का अन्त हो गया था। यूरोप में जर्मनी की शक्ति से दोनों देश समान रूप से चिन्तित व भयभीत थे। १८७० के फांको-प्रशियन युद्ध के बाद पूरोप में जर्मनी की शक्ति जितनी तेजी के साथ बढ़ रही थी, वह यूरोप के अन्य राज्यों के लिये अत्यन्त चिन्ताजनक थी। बीसवीं सदी में जर्मनी साम्राज्य प्रसार के लिये विशेषरूप से प्रयत्नशील हुआ। एशिया में अपने प्रभुत्त्व का प्रसार करने के लिये उसने आस्ट्रिया-हंगरी और टर्की के साथ मिलकर एक गुट का निर्माण किया और बिलन से बगदाद तक रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिये योजना नैयान की। जर्मनी के इस उत्कर्ष से बिटेन का चिन्तित होना सर्वथा स्वामाविक था, वर्षोंक ईरान से लेकर योजना निर्माण विदेत का प्रमुत्त्व व प्रमाद स्थापित था। फांस तो जर्मनी के उत्कर्ष में अपनी क्षति समझता ही था। इस दशा में बिटेन और

फांस ने १९०४ में एक मन्चि कर ली थी, जिसका उद्देश्य यह था कि ये दोनों राज्य अपनी विदेशी राजनीति का संचालन पारम्परिक सहयोग द्वारा करेंगे । १९०५ की इस सन्ति के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी फांग और ब्रिटेन के विरोध के संघर्ष का अन्त हो गया था। (स) यरोग की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हार्रेण्ड का विभी अन्य राज्य से विरोध नहीं था। इसीलिये ब्रिटेन और फ्रांस उसके इन्डोनी-नियन साम्राज्य के विरोधी नहीं थे। साथ ही, वे यह भी समझते थे, कि जर्गनी व जापान जंमे अविनवाली राज्यों के म्याबल में इन प्रदेशों का हालैण्ड की अधीनता में रहना कही अधिक अच्छा है। यदि ये प्रदेश हालैंग्ड के हाथ में निकल जावें. तो जर्मनी व जापान इन्हे अपने प्रभन्व मे लाने का प्रयत्न करने, यह निश्चित था। अतः फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका इन प्रदेशों पर हालैण्ड के अधिकार से सन्तृष्ट थे। वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा जापान की जलगक्ति को मर्यादिन कर दिया गया था, अतः ब्रिटेन और अमेरिका यह समझते थे, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में उनके साम्राज्यों को जापान से विशेष भय नहीं है। (घ) मिआम का स्वतन्त राज्य इन्डो-चायना और बरमा के बीच में बफर राज्य के समान था। फांम और बिटंन इस बात से संतुष्ट थे और वे समझते थे, कि सिआम के स्वतन्त्र रहने में ही उन दोनों का लाभ है। (इ) फिलिप्पीन दीप समूह अमेरिया के अधीन था, अतः यह समझता था, कि प्रवालन महासागर में एक ऐसाप्रदेश उनके हाथ में है, जिससे वह जागानकी बढ़ती हुई महत्त्वाकांक्षाओं का मफलतापूर्वक मुकावला व विरोध कर सकता है।

(३) यद्यपि दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रायः सभी देश माम्राज्यवादी देशों की साम्राज्य िल्सा के शिकार थे, पर मर्वत्र राष्ट्रीय स्वावीनता और लोकतन्यवाद के आन्दोलन जार पकड़ने जाने थे। शासक देशों ने इन राज्यों में जो सुधार किये थे, उनसे राष्ट्र प्रेमी देशमक्त लोगों को मन्तोप नहीं था। जापान के उदाहरण को मम्मुख रखकर इन सब देशों में यह आकांक्षा प्रवर्णकर में विश्वमान थी, कि वे न केवल स्वनन्त्रना प्राप्त करे, अपितु जापान के सद्धा ही उन्नत व समृद्ध देश बन जावें। इसीलिये १९३९-४५ के महायुद्ध के अवसर पर जब फांग, ब्रिटेन, हालैण्ड और अमेरियन साम्राज्यों का पत्तन हुआ, तो दक्षिण-पूर्वी एशिया के सब देशों ने प्रसन्नता अनुभव की।

(४) जापान की साम्राज्य प्रमार विषयक भूव अभी शान्त नहीं हुई श्री यद्यपि कोरिया, फार्मूसा और प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीप उसके अधीन थे और मीन के शांतूंग और मञ्चूरिया प्रदेशों में उसे अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, पर जापान इसको अपने लिये पर्याप्त नहीं समझता था। व्यावसायिक और सामरिक दृष्टि से जापान ब्रिटेन च फांस का समक्षक्ष था। पर साम्राज्य के क्षेत्र में वह इन

देशों के मुकाविले में वहुत पीछे था। जर्मनी के समान जापान भी अपने साम्राज्य दिस्तार के लिये उत्सुक था। यदि नाजी जर्मनी पूर्वी यूरोप को अपने साम्राज्य के। स्वामाविक क्षेत्र समझनाथा, तो जापान भी पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एणिया को अपने साम्राज्य का उपयुक्त क्षेत्र मानता था। इमीलिये १९३१ में उमने मञ्चूरिया में अपने प्रभुक्त को स्थापित करने का प्रयत्न विद्या और इमीलिये १९३९-४५ के महायुद्ध में उसने दिशा प्र्यूती एशिया में पश्चिमी देशों के माम्राज्यों का अन्त किया। ब्रिटिश राजनीतिज भलीभांति समझते थे, कि उनके प्रशियन साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु जापान है। इसीलिये उन्होंने सिगापुर को अपनी सामृद्रिक शक्ति का सबसे वड़ा केन्द्र बनाया था।

जापान का वशवर्ती मञ्चूकुओ राज्य

(१) जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति

पिछले अध्याओं में हमने इस विषय पर विशद रूप से प्रकाश डाला है, कि सन् १९३१ तक पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्यों की क्या स्थिति र्था। एशिया के आध्निक इतिहास में सन् १९३१ का बहत सहत्त्व है, क्योंकि इम साल जापान ने अपने साम्राज्य विस्तार की उस प्रक्रिया को शुरू किया, जिसने दम साल के लगभग समय में प्रायः सम्पूर्ण पूर्वी व दक्षिणी-पूर्वी एशिया को व्याप्त कर लिया। बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ १९३९ में हुआ था, पर जहां तक एशिया का सम्बन्ध हैं, वहां तक यस्तुत: इस महायुद्ध का श्रीगणेश १ १३१ में ही हो गया था। १९३१ में जापात ने मञ्चूरिया से चीन के शासन का अन्त किया और अपनी संरक्षा में उस प्रदेश में मञ्जूकुओ नागक नये राज्य की स्थापना की। यह राज्य नाम को स्वतन्त्र होते हुए भी वस्तुतः जागान का वशवर्ती था । इसके बाद जापान और चीन के द्वितीय युद्ध का प्रारम्भ हुआ और चीन के अनेक प्रदेशों में जापान ने अपनी शक्ति व प्रभुत्व का विस्तार किया । इसी बीच में जब १९३९ में यूरोप में द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, तरे जापान ने जर्मनी और इटली का पक्ष लेकर मित्रराष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई की कोषणा कर दी और महायुद्ध के इस अवसर का लाभ उठाकर सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । संसार के आधुनिक इतिहास में जापान का यह उत्कर्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम जापान के इसी उत्कर्ष का वत्तान्त लिखना प्रारम्भ करते है।

कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां थीं, जो जापान को साम्राज्य विस्तार के लिये प्रेरित कर रही थीं, इस पर पहले भी इस पुस्तक में प्रकाश डाला जा चुका है। पर इन मनुत्तियों में से कितपय पर इस प्रसंग में फिर विचार करना उपयोगी है—

(१) जनसंख्या की वृद्धि और व्यावसायिक उन्नति-१९३१ में जापान की अप्रवादी ७,००,००,००० के लगभगथी। १८५४ में जब कमोडोर पेरी हारा जापान का पास्वात्य देशों के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ था, जापान की जनसंख्या

तीन करोड से भी कम थी। तीन चौथाई सदी के लगभग समय में जापान की जनसंख्या में २५० प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई थी। इस बढ़ती हुई आबादी की आर्जा-किंक्का समुचित प्रबन्ध करने का यही उपाय था, कि जानानी लोग अन्य प्रदेशों में जाकर बसें, क्योंकि जागान की अपनी जमीन इतने लोगों का बोझ उठा सकने के लिये पर्याप्त नहीं थीं । अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों में जापानी लोग नहीं बस सकते थे, क्योंकि वहां की गौरा क्र सरकार एशियन लोगों को अपने देशों में प्रविष्ट नहीं होने देना चाहती थीं। फार्मुमा, कोरिया आदि जो प्रदेश जापान की अधीनता में थे, वहा जापानी लोग व्यापारी, इन्जीनियर, शिक्षक व शासक के रूप में अवस्य आबाद हो रहे थे, पर वहां कृषक, मजदूर आदि के रूप में जापानी लोगों के लिये बसने की विशेष गुंजाइश नहीं थी। चीन, फिलीप्पीन, मलाया आदि में कुछ जापानी लोग विविध प्रकार के कार्यों के लिये गये थे, पर १९३५ में इन प्रदेशों में प्रवास करनेवाले जापानियों की संख्या दस लाख मे अधिक नहीं थी। इस दशा में जापान की सरकार अपनी बढ़ती हुई जनमंख्या की आजी-विका का एक ही उपाय समझती थी, वह यह कि जापान को व्यावसायिक दृष्टि से अधिक में अधिक उन्नत किया जाय। १९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर सम्भाग को अपनी ज्यावसायिक उन्नति का सुवर्णीय अवसर हाथ लग गया था. क्योंकि उस समय एशिया के विविध बाजारों में युरोप का माल आना रुक गया था। महायुद्ध की समाप्ति पर १९२१ के लगभग यूरोपियन माल भारत आदि देशों में फिर प्रचुर परिमाण में आने लगा था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के अफीका और एशिया में अपने अपने साम्राज्य व प्रभाव क्षेत्र थे। इनमें जापान का तैयार माल उतनी निश्चिन्तता के साथ नहीं बिक सकता था, जितना कि पाश्चात्य साम्राज्यवादी देशों का। जापानी माल का, मुकाबला करने के लिये त्रिटेन, फाम, आदि उसके माल पर अधिक तट कर लगाने की नीति का अनुसरण कर रहे थे। ब्रिटेन ने साम्राज्यान्तर्गत रियायती कर की नीति का अवलम्बन कर जापान के विदेशी व्यापार में रुकावटें उत्पन्न कर दी थीं। इस दशा में जापान का यह अनुभव करना स्वाभाविक था, कि उसका भी अपना साम्राज्य होना चाहिये, जहां वह अपने तैयार माल को निश्चिन्तता के साथ बेच सके और जहां री वह कच्चा माल सस्ती कीमत पर खरीद सके । इसी मूलभूत कारण से जापान फेर्किंसा और कोरिया को अपने आधिपत्य में लाने के लिये प्रवृत्त हुआ था। पर १९३१ में व्यायसायिक दृष्टि से जापान ब्रिटेन का समकक्ष था। फार्मूसा और कोरिया से संतुष्ट रह सकता उसके लिये सम्भव नहीं था। वह चाहता था, कि फांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के समान उसका साम्राज्य भी विशाल हो। वह इ.स. समय संगार के प्रधान राज्यों में से एक था। पर साम्राज्य की दृष्टि से वह अन्य जितन्याली राज्यों के मुकाबले में बहुत पीछे था। १९३१ में वह जो साम्राज्य-वाद के मार्ग पर अग्रमर हुआ, उसमें यह प्रधान कारण था।

(२) पूंजीबाद का विकास-व्यावसायिक उन्नति के साथ गांग जापान में पंजीबाद की असाबारण कप से वृद्धि हुई थी। १८९४-९५ में जब चीन और जापान का प्रथम युद्ध हुआ, तो उसकी कम्पनियों में लगी हुई पूंजी की कुल मात्रा इ०,८०,००,००० येन थी। १९२५ में यह पूजी बहुकर १३,७९,०७,५८,००० येन तक पहुंच गई थी। ३० साल के थोड़ से अरस में जापान में व्यावसायिक व व्यापारिक कम्पनियों की पंजी में ५० गुना के लगभग वृद्धि हुई थी। अनेक कम्पनियां ऐसी थीं, जिनमें अधिक पुजी नहीं लगी हुई थी। पर यह बात ध्यान देने योग्य है, कि जापान की कुछ कम्पनियों की १.५ प्रतिशत कम्पनिया ऐसी थीं. जिनमें कुछ पूंजी का ६५ प्रतिशत विनिय्वत था। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है, कि जापान का सम्पूर्ण आधिक जीवित कुछ थोड़ी मी सम्पनियों में केन्द्रित था, जिनके मालिक जापान के व्यावसायिक व व्यापारिक जीवरा के असली स्वामी थे। इन विशालकाय कंपनियों में सुमीतोमी, भित्सूई और भित्सूविशी कंपनियां सर्वप्रधान थीं । मित्नुई कम्पनी की अपनी पूजी ३०,००,००,००० येन थी। पर उसके अर्थिक व उसमे सम्बद्ध कम्पनियों की पुजी ८०, ००,००,००० येन तक पहुंच जाती थी। सुमीतोमी कस्पनी की अपनी पंजी १५,००,००,००० थी, पर उसकी अवीतस्थ काम्पनियों की पूंजी १८,००,००,००० तक पहुंच जाती थी। मित्सुविशी काम्पनीके सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। सब प्रकार के व्यवसाय व कारीबार इन विद्यालकाय कम्पनियोंकी अवीन्ता में संचालित होते थे। वैविग, वीमा, मिलें, खानें, भवनं तिमाण आदि सब प्रकार के कारोबारों पर इन गम्पतियों का प्रभत्व था। इनके मालिक राजनीति से पृथक रहकर आधिक क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखते हों, यह बात नहीं थी । ये देश की राजनीति में खुले तौर पर भाग लेते थे, और थिविध राजनीतिक नेता इनके हाथों में कठपुतली के समान थे। सैयकाई, मिन्मेइता आदि राजनीतिक दलों पर इनका प्रभुत्व था। जापान के सैनिक नेता भी इन पुंजीपनियों के प्रभाव में थे। रुपये के जोर पर इन पुंजीपतियों के लिये यह बहुत सुगम था, कि ये देश के राजनीतिक व सैनिक नेताओं को अपनी मट्ठी में रख सकें । यही कारण है, कि इस समय जापान में अनेक ऐसी घटनाएं 🛣 जिनमें सरकार के प्रमुख कर्मचारियों और मन्त्रियों तक ने पूंजीपनियों के साथ मिलकर अनुचित रूप में लाभ उठाने का प्रयत्न किया। इस बात से यह भलीभांति समझा जा सकता है, कि जागान के राजनीतिक जीवन में बड़े पंजीपतियों का

कितना अधिक गहत्त्व था। ये पूंजीपित अपने व्यवसायों और कारोबार के लिये यहू आवश्यक रामझते थे, कि जापात माम्राज्य प्रसार के लिये तत्पर हो। माम्राज्य के अभाव में इनके लिये अपने तैयार माल को निश्चिन्ता के साथ वेच मकता व कच्ना माल काम कीमत पर प्राप्त कर मकता मुगम नहीं था। पूंजीबाद साम्राज्यवाद को जन्म देने का प्रधान कारण होता है, और जापान में इस समय पूजीबाद इस हद तक विकासित हो चुका था, कि वह वहा की भरकार को माम्राज्य विस्तार के लिये प्रेरित कर रहा था। इस समय जापान की राजनीति का निर्धारण करते हुए इन बड़े पूजीपितयों के हितों को विशेष कप में दृष्टि में रुवा जाता था, और इन पूंजीपितयों का हित इसी बात में था, कि जापान साम्राज्य विस्तार के लिये प्रवृत्त हो।

(३) मन्दी के युग का प्रभाव-१९२९ के लगभग मारे मंसार में मन्दी के युग का प्रारम्भ हुआ। बस्तुओं की कीमतें गिरने लगी और एक अर्थ संकट उपस्थित हो गया । यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि इस आर्थिक संकटं के कारणों पर प्रकाश डाल सकें। १९१४-१८ के महायद में जर्मनी आदि जो देश परास्त हुए थे, उन्हें भारी भारी रकमें हरजाने के रूप में अदा करनी थी। र्येंद्व में इन देशों का आर्थिक जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्तहोगयाथा। हरजाने के बोझ से इनकी मुद्रापद्धति बुरीतरह से अञ्यवस्थित हो गई थी। महायुद्ध के विजेता देशों के लिये यह सुगम नहीं था, कि वे अपने माल को अन्य देशों में ऊंची कीमतों पर बेच सकें, वयोंकि सर्वत्र वेरोजगारी फैल रही थी । कीमतें गिरने की जो प्रक्रिया १९२९ में शुरू हुई, वह १९३१ तक जारी रही। १९३१ तक कीमतें इस हद्द तक गिर गई थीं, कि कारमानों को भारी नुकसान होने लगा था। व्यापार, व्यवसाय और सब प्रकार के कारीबार में नकमान ही नकसान नजर आता था। जापान भी इस विश्वव्यापी अर्थसंकट मे नहीं बच सका । उसके माल की कीमनें निरन्तर गिरने लगीं। पर गिरी हुई कीमत पर भी उसका माल विदेशों में नहीं बिक पाता था । जापान के रेशम की अमेरिका में बहुत खपत थी । पर आर्थिक मंकट का जो असर अमेरिका पर पड रहा था, उसके कारण अमेरिकन जनना की क्रयशक्ति निरन्तर कम होती जाती थी। अब उसके लिये यह सम्भव नहीं हो, कि वह जापानी रेशम को खरीद सके। जापान का अन्य मारू भी विदेशी बाजारों में बिक सकता कठित हो गया था। इंस दक्षा में बहुत से जापानी कार-लाने बन्द हो रहे थे और लालों मजदूर बेसार होते जाते थे। जापान की कृषि-जन्य वस्तुओं की कीमतें भी निरन्तर गिर रही थीं। १९२६ और १९३० कें बीच में जापान के अनाज की कीमतें लगभग आधी हो गई भी । उस दर्भा का मर्च-

साधारण किसानों पर क्या प्रभाव हुआ, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। केवल किसान और मजदूर ही नहीं, अपितु दूकानदार और मध्य श्रेणु के ब्यवसायी भी मन्दी के अपेट में आ रहे थे। नफा न होने के कारण उन पर कैंज का बोझ निरन्तर बढ़ता जाता था। अनुमान किया गया है, कि १९३२ में जापान की मध्य श्रेणि के लोगों की कर्जदारी की मात्रा २,५०,००,००० येन से भी अधिक हो गई थी। जापान में आधिक संकट कितना उग्र था, इसका अनुमान इम बात में भलीभांनि किया जा सकता है। आधिक मंकट के इस काल में जापान के नेता व लोग यही समझते थे, कि इसमें छुटकारा पाने का सर्वोत्तम उपाय साझाज्य-प्रसार है।

(४) सेना का रख-पहले जापान की सेना में कतिपय कुलीन परिवारों का प्राचान्य था । चोश और मत्सुमा कुल जापान की स्थल व जलसेना में जो प्रमुख स्थिति रखते थे, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पर पारचात्य देशों के अनुसरण में जब जागान में भी बाधित सैनिक सेवा की गढ़ित का प्रारम्भ किया गया, ती जापान की सेना के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा। जल और स्थल सेना के आफिसर के पदों पर ऐमे व्यक्ति नियुक्त होने लगे, जो चौशु और सत्सुमा सद्भ कुलीन परिवारों के साथ सम्बन्ध नहीं रखते थे। अपनी सैनिक योग्यता व प्रतिभा के बल पर सर्वसाधारण लोग भी उच्च मैनिक पद प्राप्त करने लगे। १९२० और १९२७ के बीच में साबारण जनता के साथ सम्बन्ध रखनेवाले सैनिक अकपरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई, और उनकी संख्या ३० प्रतिशत तक पहुंच गई। इन अफसरों के कारण सेना के संगठन व द्धिकोण में परिवर्तन आता अवश्यम्भावी था । ये भलीभांति अनुभव करते थे, कि अर्थसंकट के बाल में, जापान की जनता को कैसी मसीबतों का सामना करना पड रहा है। ये यह भी समझते थे, कि जापान की सरकार पंजीपतियों के हितों को दिल्ट में एककर अपनी नीति का निर्धारण कर रही है, और यह बात सर्वथा अनचित है। कुछ सैनिक अ क्सरों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था, कि सरकार का मंचालन राज-नीतिक नेताओं के हाथ में न होकर सेना के हाथ में होना चाहिये, क्योंकि सेना राज्य व गासन के सम्बन्ध में सर्वथा निष्पक्ष नीति का अवलम्बन कर सकती है, और उसका जनता के किसी वर्ग के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं होता । जनता के बहुत से लागू भी सैनिक नेताओं के इन विचारों के साथ सहमति एक्ते थे। राजनीतिक नेति जिस ढंग से पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली बन रहे थे, उससे जनता में बहुत असं-तोष था। इस दशा में सेना का प्रभाव बढ़ जाना बिलकुल स्वाभाविक बात थी। जापानी सरकार की पुरानी परम्परा के अनुसार जलसेना और युद्ध के मन्त्रियों

को यह अधिकार था, कि वे सीधे सम्राट्से भेंट कर सकें और अपनी योजनाओं व नीति का उससे समर्थन प्राप्त कर सकें। इसल्पिये जिन बातों मे सैनिक नेता मन्त्रिमण्डल के राजनीतिज्ञों के साथ मतभेद रखते थे, उन्हें वे स्वयं सम्राट्के सम्मुख उपस्थित कर सकते थे, और उससे उन्हें स्वीकृत करा सकते थे। इस दशा का यह परिणाम था, कि सरकार में उनकी शिवत बहुत अधिक थी। क्योंकि इस समय बहुत से सैनिक अफसर मर्वसाधारण जनता में से लिये गये थे, अतः जनता की भावनाओं मे वे मलीभाति परिचित थे और उनका यह खयाल था, कि जापान को अर्थसंकट में बचाने का एकमात्र उपाय यह है, कि साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्न किया जाय। बाशिंगटन कान्फरेन्स के बाद जापान के राजनीतिज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति की जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, सैनिक नेता उसे नापसन्द करने थे। १९३१ में जापान साम्राज्यवाद के मार्ग पर जिस प्रकार तेजी के साथ अग्रसर हुआ, उसके लिये राजनीतिज्ञों की अपेक्षा सैनिक नेता उत्तरदायिता अधिक थी।

विश्वव्यापी अर्थसंकट के कारण जापान की सरकार को अपने वर्च चलाने में भी कठिनता अनुभव होने लगी थी। वह जरूरी समझती थी, कि सरकारी क्वें में कभी की जाय। बचत का सबसे सरल उपाय उसे यह समझ पड़ता था, कि सैनिक वर्च को घटाया जाय। पर सैनिक नेता इससे सहमन नहीं थे। सैनिक वर्च को घटान का यह परिणाम होता, कि सैनिकों व अफसरों के लिये उसित का मार्ग कक जाता। इसके मुकाबले में सेना का यह विचार था, कि मैनिक वर्च को कम करने के बजाय सेना का अपना कर्तृत्व प्रदक्षित करने के लिये मौका दिया जाना चाहिये। मना का यह कर्तृत्व साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में ही सम्भव था। सैनिक नेता कहते थे, कि जापान की आर्थिक समस्या को हल करने का सबसे उत्तम उपाय साम्राज्य का विस्तार है।

(५) राष्ट्रभिक्त की भावता—केवल जापान की सेना ही नहीं, अपितृ जनता भी साम्राज्य विस्तार के लिये उत्सुक थी। जापान में अनेक ऐसी समितियां स्थापित हो रही थीं, जो सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अत्यन्त निर्वल समझती थीं। देशभक्तों का कहना था, कि वाशिगटन कान्फरेन्स के निर्णयों की स्वीक्कार कर सरकार ने जापान को बिलकुल पंगु बना दिया है। उम्र राष्ट्रीय भावना साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। जापान में राष्ट्रीय मावना बहुन उम्र रूप धारण कर रही थीं। उम्र राष्ट्रीय भावना से आविष्ट जापानी नवयुक्त अपनी सरकार की विदेशी नीति के बहुत खिलाफ थे, और साम्राज्यविस्तार के लिये क्याकुल थे। नवयुक्त देशभक्तों की ये समितियां चितना प्रचण्ड

ह्य धारणकर रही थीं, इसको स्पष्ट करने के लिये एक यह बात ही पर्याप्त होगीकि १९३० में जापान के प्रधानमन्त्री हामागुचीको केवल इसलिये कातल किया गुण था,क्योंकि से राष्ट्रवादी देशभक्त उसकी अन्तर्राष्ट्रीय नीतिको निर्वल समझते हैं।

इसमें मन्देह नहीं, कि अनेक जापानी राजनीतिज्ञ अपने देश के उत्कर्ष के लिये साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करने के विरोधी थे। १९२७ में जापान के परराष्ट्रमन्त्री वैरन शिदेहारा ने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था— "हमारे लिये यह बात अत्यन्त महत्त्व की है, कि हम अपनी सम्पूर्ण शिवत व ध्यान को विदेशी व्यापार की वृद्धि में लगावें, पर इसके लिये हों किसी अन्य राष्ट्र के हितें में अन्याय्य रूप से बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। हमें बाजार चाहियें, अन्य राज्यों के प्रदेश नहीं चाहियें।" यह ठीक है, कि १९२२ के बाद जापान की सरकार का ध्यान अपने देश के विदेशी व्यापार की वृद्धि पर लगा हुआ था। जापानी माल के सबयें बड़े ग्राहक अमेरिका और चीन थे। इसीलिये जापानी सरकार इन देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध कायम रखने के लिये उत्सुक थी। पर १९२९-३१ के विदेशवायापा अर्थसंकट ने जापान के विदेशी व्यापार को मारी धक्का पहुंचाया था। यद्यपि इस समय भी जापान के राजनीतिक नेता साम्राज्य-प्रसार के लिये इच्छुक नहीं थे, पर जनता और सेना उनकी इस नीति से असहर्कें थी। देशभक्तों की समितियां और सैनिक नेता समझते थे, कि साम्राज्य विस्तार द्वारा ही जापान का कल्याण सम्भव है।

(२) मञ्चूरिया की स्थिति

जापान के लिये अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का सबसे उपयुक्त क्षेत्र मञ्जूरिया था। १९३१ में उसने इसी प्रदेश में अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को चरितार्थ करना प्रारम्भ निया। अनः यह आवश्यक है, कि हम पहले मञ्जूरिया की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करें। १९३१ के शुक्त में मञ्जूरिया की क्या स्थिति थी, इसे हम निम्नलिखित प्रयार से स्पष्ट कर सकते हैं—

(१) मञ्चूरिया चीन का अंग था। चीन के राजनीतिक नेता इसे अपना अधीनस्थ प्रदेश न समझकर अपने राष्ट्र का एक अंग मानते थे। वे इसे मञ्चूरिया न कहकर 'तीन पूर्वी प्रान्त' इस नाम से कहते थे। कुओमिन्तांग सरकार इस प्रदेश को चीनी रिपब्लिक का अखण्डनीय भाग समझती थी। चांग त्सो-लिक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चांग ह सुएह-लिओग मंचूरिया का सूबेदार व सिपहसालार बना था। उसके पिता चांग त्सो-लिन ने नानकिंग सरकार के साथ समझौता नहीं किया था। पर चांग ह सुएह-लिओग समय की गति को समझता था, और उसने

नानिका की कुओमिन्तांग सरकार को मञ्चूरिया का असली स्वामी मान लिया थर्मन कुओमिन्तांग सरकार के माथ जो समझीता ह्मुएह-लिआग ने किया था, उसके अनुसार मञ्चूरिया के वैदेशिक सम्बन्धों का संवालन नानिका की अखिल चीनी सरकार के मुपूर्व कर दिया गया था, यद्यि आन्तरिक शासन में चांग ह्मुएह-लिआंग को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। जापानी लोग इस बात से वहृत असतुष्ट थे। जब तक मञ्चूरिया का सिपहमालार केन्द्रीय चीनी सरकार के आधिपत्य से सर्वथा स्वतन्त्र था, वे उस पर जोर डालकर आपनी बात उससे मनवा सकते थे। नानिका की अपेका मुकदन (मञ्चूरिया की राजधानी) पर उनका जोर अधिक चल सकता था। इसीलिये जापानी लोगों ने चांग ह्मुएह-लिआंग को चेतावनी दी थी, कि वह नानिका की केन्द्रीय सरकार के साथ किसी भी प्रकार का समझीता न करे।

- (२) हम पिछले अध्यायों में बतला चुके हैं, कि उत्तरी मञ्जूरिया कस का प्रभावक्षेत्र था, और दक्षिणी मञ्जूरिया जापान के प्रभावक्षेत्र में था। विविध संधियों द्वारा रूस और जापान ने मञ्जूरिया के उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों में जो क्रिक्ष विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे, उन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं हैं। पर यह स्पष्ट है, कि एक प्रदेश में तीन राज्य एक साथ नहीं रह सकते थे। जब तक चीन की केन्द्रीय सरकार निर्वल थी, रूस और जापान के लिये मञ्जूरिया में मनमानी कर सकना सम्भव था। पर कुओमिन्तांग दल के शिवन प्राप्त कर रही थी। मार्शल चियांग काई शेक की सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील थी, कि चीन से विदेशी राज्यों के प्रभाव व प्रभुत्व का अन्त कर चीन में अधिकल रूप से राष्ट्रीय स्वृतन्त्रता की स्थापना की जाय। कुओमिन्तांग दल के कार्यकर्ता मञ्जूरिया में वृद्धी तत्परता के साथ कार्य कर रहे थे। अपने देश में विदेशियों के विशेषाधिकारों की सत्ता उन्हें सहा नहीं थी।
- (३) इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि चीन और जापान में मञ्चूरिया के मामले में विरोध के कारण उत्पन्न हों। ये विरोध के कारण निम्नलिखित थे—क. लिआओतुंग प्रायद्वीप का पट्टा २५ साल के लिये पहले इस ने प्राप्त
 क्षिण था। इस-जापान युद्ध (१९०४-५) के परिणामस्वरूप यह पट्टा
 जापान ने हस्तगत कर लिया था। १९१५ में चीन और जापान में जो सगझौता
 हुआ था, उसके अनुसार इस पट्टे की अवधि २५ साल से बढ़ाकर ९९ साल कर दी
 गई थी। पर चीन की नई राष्ट्रीत गरकार का कहना था. वि १९१५ का रामनौंगा
 जापान ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर चीन की निवसता ने लाग उत्कार विया

था, अत: वह चीनी सरकार को मान्य नहीं हो सकता । २५ साल के असली पड़े का काल १९२३ में समाप्त हो गया था । १९२३ के बाद लिआओतुंग पर जिल्ला के कब्जे को चीनी मरकार अन्याय्य समझती थी। पर जापान का कहना थी, कि १९१५ का समझौता न्याय्य और उचित है, तथा चीनी सरकार को उसे स्वीकृत करना चाहिये। ख. यही विवाद दक्षिणी मञ्ज्यितम रेलवे के सम्बन्ध में था। इस रेलवे का पड़ा भी शुरू में रूस ने २५ साल के लिये प्राप्त किया था, और १९०४-५ के रूम-जापान यह के बाद इस पर जापान ने अपना अधिकार कर लिया था। १९१५ में इसकी अवधि भी २५ साल से ९९ साल कर दी गई थी। चीनी सरकार का कहना था, कि १९२३ में २५ माल का काल समाप्त हो जाने से इस रेलवे पर जापान का स्वामित्व त्याय्य व उचित नहीं है। पर जापान १९१५ के समझौते के आधार पर इस रेलवे पर अपने आधिपत्य की अविव ९९ साल मानता था। ग. रेलवे के क्षेत्र पर जापानी पूलीस का अधिकार था । साथ ही मञ्चरिया में निवास करनेवाले जागानियों को एवसट्रा-टैरिटोरि. एलिटी सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थे। जापानी लोगों को मञ्चूरिया में जमीन व मकान किराये पर लेने के भी अधिकार मिल हुए थे। यह स्वाभाविक था, 😭 इन अधिकारों को फिया में परिणत करने के प्रक्रन पर चीन और जापान मैं अनेक प्रकार की समस्याएं व विवाद उत्पन्न होते रहें।

- (४) वाशिगटन कान्करेन्स में जापान ने चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्वीकृत किया था, और साथ ही यह भी माना था, कि वह उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर जापान मञ्चूरिया को चीन का अंग नहीं समझता था। वह कहता था, कि मञ्चूरिया चीन का अंधीनस्थ राज्य है, और उसमें विविध सन्धियों हारा जो विशेषाधिकार जापान को प्राप्त हैं, उन्हें वह नीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के नाम पर छोड़ देने को कदापि नैयार नहीं होगा। इसीन्छिये वह १९१५ के समझौत को आधार बनाकर लिआओत्ंग प्रदेश व दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे पर अपने आधिपत्य का दावा करता था, और उसे चांग ह गुएह लिआंग की यह बात भी पसन्द नहीं थी, कि उसने नानिकंग की केन्द्रीय चीनी सरकार के हाथों में मञ्चूरिया की परराष्ट्र नीति का संचालन दे दिया था। जापानी सरकार इस बान के लिये कटिबड़ थी, कि मञ्चूरिया में ९९ माल के लिये की विशेषाधिकार उसे प्राप्त हैं, वे अक्षुण्ण रहें।
- (५) चीनी सरकार का यह प्रयत्न था, कि मञ्जूरिया पर उसका आधिपत्य अविक अधिक दृढ़ होंता जाय । कुओमिन्तांग दल के राष्ट्रीय कार्यकर्ता वहां प्रचार कार्य में लगे थे । चीन के देशभनतों का यत्न था, कि मञ्जूरिया पूर्णत्या

चीन का एक अंग बन जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति में अन्य भी अनेक बाते महायक हो रही थीं । क. १९३० में मञ्चूरिया की कुल आबादी २,९०,००,००० थीं। इसमें मे २,६०,००० जापानी और ८,००,००० कोरियन थे। कसी लोगों ही संख्या १,००,००० थी। कुछ लोग मञ्च व मंगोल जाति के भी थे। पर मञ्चरिया की आबादी का बड़ा भाग चीनी लोगों का था। वहां बसे हुए चीनी लोगों की संस्था १९३० में २,००,००,००० के लगभग पहुंच गई थी। ज्यों ज्यों समक्ष बीतता जाता था, चीनी लोग अधिकाधिक संख्या में वहां बसते जाते थे। दक्षिणी मञ्जूरियन रेलवे के निर्माण के कारण जीनी लोगों के लिये मञ्जूरिया में जाकर बस सकता और अधिक सुगम हो गया था। जापानी लोग इस प्रदेश में लोहे. कोयले आदि की जिन खानों का विकास कर रहे थे, उनमें चीनी मजरूर बडी संख्या में काम करते थे। रेलवे के विस्तार के कारण मञ्चूरिया दे। कृषिजन्य पदार्थों की भाग भी बहुत बढ़ गई थी। इस दशा में बहुत से चीनी किसान वहां की उपजाऊ भूमिपर खेती करने के लिये पहुंच गये थे। इतनी बड़ी संख्या में चीनी लोगों के आबाद हो जाने के कारण मञ्जूरिया वास्तविक अर्थों में चीन का एक अंग बनता जाता था । ख. चीनी सरकार इस बात के लिये प्रयत्नकील न्त्री, कि दक्षिणी मञ्चिरिया में अपनी ओर से भी नई रेलवे लाइनों का निर्माण करे। जापान द्वारा अधिकृत दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे समुद्र तट पर दैरन के बन्दरगाह पर समाप्त होती थी। दैरन जापान के कब्जे में था, और यह उत्तर-पूर्वी चीन व मञ्चूरिया का सर्वप्रधान बन्दरगाह था। उत्तरी चीन, मञ्चूरिया और मंगोलिया के विदेशी व्यापार का यही सबसे बड़ा केन्द्र था । पर चीनी सरकार्य दैरन के मनाबले में हल्ताओं के बन्दरगाह को विकसित करने में तत्पर थी। वह दक्षिणी मञ्जूरिया और उसके समीपवर्ती प्रदेश में ऐसी रेलवे लाइनों को बना रही थीं, जो हलताओं में जाकर समाप्त होती थीं । जापान चीन की इस योजना से बहुत चिन्तित था। वह समझना था, कि चीनी सरकार उसकी अपनी रेलवे लाइन और दैरन के बन्दरगाह को नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील है। इससे मञ्चरिया के अंत्र में चीन और जापान का विरोध निरन्तर बढ़ता जाता था।

(६) मञ्चूरिया में अन्य भी अनेक बातें चीन और जापान में विरोध उत्पन्न क्षूर रही थीं। जापान ने मञ्चूरिया में अपनी ओर से एक दाक्तिशाली सेना म्बापित की हुई थी, जिसे क्वांतुंग सेना कहते थे। क्वांतुंग का अर्थ है, सीमा का पूर्ववर्ती। दक्षिणी मञ्चूरिया का अन्य नाम क्वांत्व था, क्वोंकि यह प्रदेश चीन की विशाल दीवार के पूर्व में स्थित था। ज्यांतुंग में विद्यमान जाणानी सेना अपना यह कर्तव्य समझनी थीं. कि मञ्जूरिया ये जाणान को जो विजतायकार

प्राप्त हैं, उनकी उत्साहपूर्वक रक्षा करे। वह न केवल लिआओं तुंग और दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे पर अपना अधिकार समझती थी, अपितृ मंचूरिया में जहां कहीं भी जापानी लोग व्यापार आदि के निमित्त से निवास करते थे, उनके हितों केंक्ष्रिता वरना अपना स्वयंगिद्ध अधिकार समझती थी। यह सर्वधा स्वाभाविक था, कि चीन की कुओमिन्नांग सरकार और क्वातुंग मेना में बहुधा विरोध होते। रहे। जापान की क्वातुंग सेना उग्र साम्राज्यवादी थी। इसके बहुत से आफिसर सर्वसाधारण जनना के साथ सम्बन्ध रखते थे। उन्हें मालूम था, कि १९२९-३१ के घोर आधिक संकट के कारण उनके परिवारों के लोगों को कैसे कब्टों का सामान करना पड़ रहा है। अपने बन्धुओं को आधिक कब्ट से बचाने का एकमात्र उपाय इन सैनिक आफिसरों को यही समझ पड़ता था, कि मञ्चूरिया में खायान के साम्राज्य का विस्तार किया जाय।

, (७) जापान समझता था, कि मञ्चुरिया उसका प्रभावक्षेत्र है, और वहा उसे जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है । उसका यह भी खयाल था, कि कच्चे माल को प्राप्त करने के लिये इस प्रदेश पर अपना अध-फार कायम रखना आवश्यक है। दूसरी तरफ चीन मञ्चूरिया को अपना अंग मानता था और वहां विदेशी राज्यों के विशेषाधिकारों को अपने राष्ट्रीय गोस्क के प्रतिकूल समझता था। इस दशा में वहां अनेक ऐसी घटनाएं होनी शुरू हुई, जिन्होंने चीन और जापान के विदेष को बहुत बढ़ा लिया। हमने दसी प्रकरण ' में लिखा है, कि मञ्ज्रिया में ८,००,००० के लगभग कोरियन लोग आबाद थे। वं मुख्यतया कृषि द्वारा अपना निर्वाह करते थे । क्योंकि कौरिया इस समय जागान के अधीन था, अतः कोरियन लोग जापान की प्रजा थे। मञ्चूरिया की उपजाऊ जमीन से आकृष्ट होकर बहुत में कोरियन लोग इस समय वहां आकर आबाद ही रहे थे। चीनी सरकार समझती थी, कि कोरियन लोगों का मञ्चूरिया में आबाद होना उस प्रदेश पर जापान के प्रभुत्व में वृद्धि करना है। अतः उन्होंने अनेक ऐसी व्यवस्थाएं कीं, जिनके कारण कोरियन लोगों के लिये मञ्चरिया में जमीन प्राप्त करना कठिन हो गया। साथ ही जो कोरियन लोग मञ्चूरिया में जमीनें प्राप्त कर चुके थे, उनके मार्ग में भी चीनी सरकार ने रुकावटें डालनी शुरू की । एक स्थान पर कोरियन लोग खेतों में सिचाई के लिये नहरें व नालियां वनाने में तत्पर थे। चीनियों ने वल का प्रयोग कर वहां से कोरियन लोगों 🎎 बाहर निकाल दिया। इस पर जापानी पुलीस ने अपनी कोरियन प्रजा की सहायताकी। यह मामला इतना उप रूप धारण कर गया, कि कोरिया और जापान के समाचार-ंपत्रों ने चीन के खिलाक आग उगलना शुरू कर दिया । कोरिया और जापान में

अनेक स्थानों पर चीनी लोगों के खिलाफ दंगे हुए। इसी तरह चीन में भी इस घटना से जापान के विरुद्ध विद्धेषानि वहत प्रचण्ड हो गई।

जून, १९३१ में नाकामुरा नामक जापानी मैनिक आफिसर की मञ्चूरिया में हत्या हो गई। यह हत्या किन कारणों से हुई और इसके लिये चीनी सरकार किम हह तक दोषी थी, इस पर विचार करने की यहां आवश्यकता नहीं है। पर इस प्रकार की घटनाएं चीन और जापान के विद्येषको और भी अधिक प्रचण्ड बना रहीं थी। कहा जाता है, कि अगस्त, १९३१ में ऐसे मामलों की संस्था ३०० के लगभग पहुंच गई थी, जिन पर मञ्चूरिया के क्षेत्र में चीन और जापान में झगड़ा था। इस बात में चाहे अतिश्योक्ति क्यों न हो, पर यह निश्चित है, कि इस समय मञ्चूरिया के प्रश्न पर चीन और जापान के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये थे। यह स्थिति आ गई थी, कि मञ्चूरिया पर या तो जापान का ही कब्जा रह सकता था और या चीन ही का। मञ्चूरिया सम्बन्धी झगड़ों को शान्ति व समझौते से निवटा सकता सम्भव नहीं रह गया था। अब इसका निर्णय केवल युद्ध द्वारा ही हो सकता था, और इसके लिये १८ सितम्बर, १९३१ को उपयुक्त अवसर उपस्थित हो

(३) मञ्चूकुओ की स्थापना

لدميكور

मञ्चूरिया के प्रश्न पर जो अग्नि चीन ओर जापान में धीरे धीरे मुलग रहीं थी, सितम्बर, १९३१ में वह प्रचण्डता के साथ धधक उठी। १८ सितम्बर को दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे की लाइन पर एक बम्ब फेंका गया, जिससे रेलवे लाइन का कुछ भाग नष्टहों गया। यह घटना बहुत साधारण थी, औरइससे जापान की रेलवे को बहुत अधिक क्षित नहीं पहुंची थी। पर इसके परिणाम बहुत सर्यकर हुए। जापान का कहना था, कि यह बम्ब चीनी सिपाहियों ने फेंका है। चीनी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। वास्तविक बात चाहे कुछ भी क्यों न हो, १८ सितम्बर, १९३१ की इस घटना से लाभ उठाकर जापान की वर्वान्तुंग सेना ने मञ्चूरिया की राजधानी मुकदन पर कब्जा कर लिया और १९३१ का अन्त होने से पूर्व ही प्राय: सम्पूर्ण मञ्चूरिया पर अपने आधिपत्य को स्थापित कर लिया। मञ्चूरिया के सुबेदार चांग ह सुएह-लिजांग किये यह सम्भव नहीं था, कि वह जापानी रेनाओं का मुकाबला कर सके। कुछ ही समय में क्वांतुंग सेना ने गञ्जूरिया के प्रभुत नगरों पर कब्जा कर लिया। चीनी सेनाए देहातों में कहीं कहीं जापान की सेनाओं का मुकाबला मरती रहीं। पर उन्हें परास्त कर सकता जापान के लिये कठिन बात नहीं थी।

१८ फरवरी, १९३२ को मञ्चूरिया में एक पृथक राज्य की स्थापना कर दी गई। इस तये राज्य का नाम मञ्चू कुओ रखा गया। मञ्चूरिया के तीनों पूर्वी प्रान्त और जहोल (मञ्चूरिया की दिखाणी सीमा पर स्थित अन्यतम प्रान्त के प्रदेश को इस नये राज्य में शामिल किया गया। यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि जहोल पर जापान ने अपना आधिपत्य १९३३ में स्थापित किया था। फरवरी १९३२ में मञ्चू कुओ के जिस पृथक राज्य का निर्माण किया गया था, जहोल प्रान्त उसके अन्तर्गत नहीं था। क्यों कि बाद में जहोल को भी मञ्चू कुओ में शामिल कर दिया गया, इसी लिये उसका भी यहां उल्लेख कर दिया गया है।

मञ्ज्युक्तओं के शासन के लिये जीन के पदच्युत सम्राट् को नियुक्त किया गया। १९११ में जीन की राज्यकान्ति के समय सञ्जूवंश का यह सम्राट् नावालिय था। इस समय यह बालिंग हो चुका था और जीन के जापानी दूतावास में जापानी सरकार की संरक्षा में निवास करता था। जापानी लोगों ने इसी सम्राट् पूर्यी को मञ्ज्युक्तओं का राजा नियत किया। एक दृष्टि से यह उजित भी था। जीन के मञ्ज्यू राजवंश के सम्राट् वस्तुतः मञ्ज्यूरिया के ही रहनेवाले थे और वहीं से बीन पर आक्रमण करके उन्होंने इस देश को अपने अधीन किया था। जापान का दाश था, कि मञ्ज्यूरिया जीन का अंग नहीं है, वह उसका विजित प्रदेश हैं के सञ्ज्युक्तों को एक पृथक व स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित करके उसकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना की जा रही है, यह जापानी लोगों का मन्तव्य था। ९ मार्च, १९३२ के दिन मञ्ज्युक्तओं के संविधान का निर्माण किया गया, जिनमों जनता के आधारभूत अधिकारों के प्रतिपादन के साथ साथ राज्य के शासन, व्यवस्थापन व न्याय विभागों की विश्वद रूप में व्यवस्था की गई। शासन विभाग का प्रधान सम्बाट् पूर्यी को बनाया गया।

१५ गितम्बर, १९३२ को जापान ने मञ्जूकुओ राज्य की पृथक् व स्वतन्य सत्ता को स्वीकृत कर लिया। पर चीन की सरकार मञ्जूकुओ की सत्ता को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थी, यद्यपि मञ्जूकुओ को फिर से अपने अधिकार में ले आने की शक्ति उसमें नहीं थी, पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि व समझौते हारा उसने इस राज्य की पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। कियात्मक दृष्टि से इस समय मञ्जूरिया चीन से पृथक् हो गया था, और यद्यपि नाम को वह एक स्वतन्त्र राज्य था, पर वस्तुनः वह पूर्णत्या जापान वे प्रभादक्ष प्रभादक्ष प्रभादक्ष प्रभादक्ष से था। जापान की क्यातुंग सेना वहां पर विद्यमान थी और मञ्जूकुषी राज्य की सत्ता इस जापानी सेना पर आधित थी। राज्य के विविध विभागों में जापानी लोगों को गलाहकार के रूप में नियत किया गया था और वस्तुतः मञ्जू

कुओं की राजनीति का संचालन इन्हीं जापानी सलाहकारों के हाथों में था। क्षण्डबुंकुओं की स्थापना के कारण रूस के सम्मुख भी एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्यों कि उत्तरी मञ्च्रिया में रूस को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे। पर रूस की कम्युनिस्ट सरकार इस समय जापान के माथ युद्ध में उलझने के लिये तैयार नहीं थी। मञ्च्रकुओं के मम्बन्ध में रूस का क्या रूख था, इस पर हम आगे चल कर यवास्थान प्रकाश डालेंगे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि १९३२ में सम्पूर्ण मञ्च्रिया। मञ्च्रकुओं राज्य के अन्तर्गत था, और इसकी स्वतन्त्र सरकार जापान के निरीक्षण व संरक्षण में अपने देश का शासन करने लगी थी।

यद्यपि चीन की सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं थी, कि मञ्चक्ओ में सैन्य वल मे जापान का प्रतिरोध कर सके, पर उसने जापान के साम्राज्यबाद के प्रति अपना विरोध प्रगट करने के लिये अन्य उपायों का आश्रय लिया। चीन में जापानी माल के बहिष्कार का आन्दोलन बहुत प्रबल हो गया। वहिष्कार का यह आन्दोलन किस अंश तक सफल हो रहा था, ुक्तका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि जहां सितम्बर, १९३१ में १,२७,०६,००० येन का जापानी माल चीन में आया था. वहां दिसम्बर, १९३१ में इस माल की मात्रा घट कर ४२,९९,००० येन की रह गई थी। चीन में सर्वत्र ऐसी समितियां कायम थीं, जो जनता को जापानी माल का वहिष्कार करने के के लिये प्रेरित करती थी। शंघाई इस आन्दोलन का प्रधान केन्द्र था, क्योंकि वह चीन के विदेशी व्यापार का प्रमुख बन्दरगाह था। जापानी लोग चीन के वहिष्कार आन्दोलन से इतने अधिक उद्विग्न हए, कि उन्होंने शंघाई के म्यनिसि-पल अधिकारियों से मांग की, कि उनके क्षेत्र में बहिष्कार का प्रचार करनेवाली जो समितियां विद्यमान हैं, उन्हें मंग कर दिया जाय । जापान की शवित के सम्मुख शंबाई के राजपदाधिकारी सर्वथा विवदा थे। उन्होंने जापान की मांग को स्वीकृत कर लिया । पर जापान इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ । जापान के जंगी जहाजों ने शंवाई पर आक्रमण कर दिया और एक जापानी सेना ने शंवाई नगरी के एक भाग पर अपना कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में बहुत से चीनी लोग मारे गये 🗝 है बहुत सी सम्पत्ति का विनाश हुआ । शंघाई पर यह जापानी आक्रमण जनवरी, १९३२ में हुआ था। १ फरवरी, १९३२ को चीन की राजधानी नान किंग पर भी जापानी सेना ने बम्ब वर्षा की । मई, १९३२ तक इसी ढंग से चीन और जापान का संवर्ष चलता रहां। इस समय इन दोनों देशों में बाकायदा युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, पर उनमें उसी ढंग से लड़ाई जारी थी, जैसे कि युद्ध के समय

में होती है। मई, १९३२ तक चीन में जापानी माल को बहिष्कृत करने का आन्दोलन बहुत कुछ शिथिल हो गया था, और उधर मञ्चूकुओ की सरकार क्ष्रिस्थाना भी व्यवस्थित रूप से हो गई थी।

(४) राष्ट्रसंघ और मञ्चूकुओ

१९१४-१८ के महायुद्ध की समाप्ति पर संसार में चिरशान्ति की स्थापना और राज्यों के पारस्परिक झगड़ों को शान्तिमय उपायों द्वारा निबटाने के उद्देश्य में राष्ट्रमंघ की स्थापना की गई थी। चीन और जापान दोनों ही राष्ट्रसंघ के सदस्य थे। जापान ने राष्ट्रमंघ की सदस्यता को स्वीकृत करते हुए यह बात भी मंजर की थी, कि वह अन्य किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय झगडों को निबटाने के लिये सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेगा। सितम्बर, १९३१ में जब जापान ने मञ्चिरिया की राजधानी मुकदन पर कब्जा किया, तो चीन ने उसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ से अपील की । राष्ट्रसंघ की कीसिक के अधिवेशन उस समय हो रहे थे। २१ सितम्बर को चीनी सरकार की अपील कौंसिल के सम्म्स पेश हुई। ३० सितम्बर को राष्ट्रसंघ की कौंसिल ने एक् प्रस्ताव स्वीकृत किया, कि ज्योंही परिस्थितियां अनुकुछ हों, मुकदन से जापानी सेनाओं को हटा लिया जाय । 'ज्योंही परिस्थितियां अनुकुल हों' ये शब्द प्रस्ताव में जान यहा कर इसलिये रखे गये थे, वाकि जापान भी इस प्रस्ताव की स्वीकृत कर सके। जापान ने काँसिल के प्रस्ताव को मान लिया और वह सर्वसम्मति सं स्वीकृत हुआ। अक्टूबर, १९३१ में जब कींसिल का फिर अधिवेशन हुआ, तो मञ्जूरिया की समस्या उसके सम्मुख पुनः उपस्थित की गई । अब तक जागान की सेनाएं मुकदन में मीजद थी। जापान का कहना था, कि मञ्चुरिया में चीन का शासन अत्यन्त निर्वल और विकृत है, वहां डाकुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, और शासनसूत्र अत्यन्त शिथिल हो गया है। इस दशा में जापानी लोगों के जान व मारह की रक्षा के लिये यह आवश्यवा है, जि मुनादन में व अन्यव जापानी मेनायें कायम रहें। पर राष्ट्रसंघ की कींसिल इस बात से सहमन नहीं थी । १० अक्टूबर को उसने एक अन्य प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसमें इस वात पर जोर दिया गया, कि क्वांतुंग सेना को केवल उस प्रदेश तक ही अपने को सी 🧱 रखना चाहिये, जहां जापान की रेलवे लाइन विद्यमान है, मुकदन व अन्य प्रदेशों से यह सेना शीघ्र ही हटा ली जानी चाहिये। जापान ने इस प्रस्ताय की स्वीकार नहीं किया, पर राज्दसंघ की कौंसिल में यह प्रस्ताव बहमत से स्वीकृत हो गया। नवस्वर, १९३१ में राष्ट्रसंघ की कौंसिल के सम्मुख मञ्चिरिया का मामला फिर पेश हुआ। इस बार भी जापान ने इस बात पर जोर दिया, कि मञ्चूरिया में चीनी शासन की शिथिलता के कारण उसके लिये यह सम्भव नहीं है, कि वह अपनी सेनाओं को वहां से हटा सके। अन्त में १० दिसम्बर, १९३१ को कौसिल ने यह निश्चय किया, कि मञ्चूरिया की समस्या पर विचार करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जाय, जो वहां जा कर वस्तुस्थित का अध्ययन करे और अपनी रिपोर्ट को कोसिल के सम्मुख उपस्थित करे। इस समय नक जापानी सेनाओं ने चिन्चों के अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण मञ्चूरिया पर करजा कर लिया था। जापान ने यह स्वीकृत कर लिया, कि वह इस बीच में चिन्चों पर करजा करने का प्रयत्न नहीं करेगा। पर मञ्चूरियन कमीशन की रिपोर्ट नैयार होने से पूर्व ही ३ जनवरी, १९३२ को जापानी सेनाओं ने चिन्चों पर भी अपना करजा कर लिया। राष्ट्र-संघ के निर्णयों का जापान की दृष्टि में उतना महत्व नहीं था, जितना कि मञ्चूरिया में अपने साम्राज्य-विस्तार में तत्पर था।

मञ्जूरिया के मामले का अनुसन्वान करने के लिये जो कमीशन राष्ट्रसंघ ्द्वारा नियुवत हुआ था, उसके प्रधान लाई लिटन थे। ब्रिटेन के इस प्रतिनिधि के अतिरिक्त मञ्चूरियन कमीशन में फ्रांस, अमेरिका, इटली और जर्मनी के प्रतिनिवियों को स्थान विया गया था । ४ सितस्वर, १९३२ को पेकिंग में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये । इस कमीशन ने यह प्रस्तावित किया कि मञ्जूरिया में चीन, जापान और रुस तीनों के विशेष हित विद्यमान हैं, और तीनों के हितों व विशेषाविकारों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये । मञ्जूरिया में एक ऐसी सरकार कायम की जानी चाहिये. जो अपने आल्तरिक मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र हो, पर साथ ही जसका मंगठन इस ढंग का हो, जिसने चीन की राष्ट्रीय प्रभुता अखण्डिल व अविभाजित रहे । मञ्चूरियन कमीशन एवा इस प्रकार के मध्य मार्ग का अनुसरण करने के पक्ष में था, जिसके कारण न तो मञ्जूरिया चीनका अंगमाध रह जाता था और र ही वह एक स्वतन्त्र व पृथक राज्य वन पाता था। पर जापान छिटन कमीयन की रिपोर्ट की स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं था। १५ सितम्बर, १९३२ को उसने मञ्जूकुओ राज्य की 🌙 खतन्त्र व पृथक् सत्ता की स्वीकार कर लिया था। इस दवा में उसके लिये यह सम्भव नहीं था, कि यह किसी केंग प्रमाव हो वहींकार कर सके, जिससे कि मञ्चुकुओ की स्थिति में अन्तर अस्ता हो । यहन चाद नियाद की याद फरदारि, १९३३ में २(प्ट्रमंभ ने रिटन कमोधन की रिपोर्ट को प्याञ्चन कर किया । उसने अपने सदस्य राज्यों को आदेश दिया, कि वे मध्यक्रको राज्य की राज्य व पूर्ण

रात्ता को स्वीकार न करें और उसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी स्थाणित न करें। जागान से भी उसने यह अनुरोध किया, कि वह चीन से अपनी सेनाएं हटा के जोर उसके खिलाफ अपनी सैन्यशिवत का उपयोग न करे। चीन के साथ झगड़ें की जो भी बातें हैं, उनका निब्रटारा करने के लिये जागान बानचीत व शान्तिमय प्राथ्यों का प्रयोग करे, शिवत का नहीं। पर जापान किसी भी दशा में इस बात कि लिये तैयार नहींथा, कि वह मञ्चूकुओ से अपने प्रभुत्वका परित्याग करे। मार्च, १५३ में उसने राष्ट्रमंघ को यह सूचना दे दी, कि वह भविष्य में उसवा सदस्य भन्न को तैयार नहीं है। वह राष्ट्रमंघ से पृथक हो गया और चीन में अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिये तत्पर हुआ। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद पृथ्वी के विश्वित देशोंको एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनकी अधीनतामें लाते का जो प्रयत्न राष्ट्रमंघ की शिक्त इससे बहुत निर्वल हो गई थी। बाद में अमंनी, और इटली भी साम्राज्य थाद के मार्ग को ग्रहण करके राष्ट्रसंघ से पृथक हो गये, और यह अन्तर्राष्ट्रीय एंगठन एकदम शिखल हो गया।

(५) मञ्चूकुओ पर जापान का प्रभुत्त्व

जागान की क्वांतुंग सेना के प्रयत्न से मञ्जूरिया में जो नया गृथन राज्य था त्रचुक्को नाम से स्थापित हुआ था, यह कहने को स्वतन्त्र था, पर वस्त्तः वह जापान का एक अधीनस्थ व संरक्षित राज्य था। १५ सितम्बर, १९३२ को जब पापानी सरकारने मञ्चकुओ की स्वतन्त्र सत्ता को बाकायदा स्वीकार किया था, तभी दोनों राज्यों की सरवारों ने एक शर्तनामा पर हस्ताक्षर कर विये थे, जिसमें उन एन विशेषाधिकारों का विशद रूप से उल्लेख किया गया था, जी कि जापान ने भाज्ज्रिया में चीन के साथ की गई विविध सन्धियों द्वारा प्राप्त कियं थे। १९१५ की सन्वि द्वारा लिआओतुंग प्रदेश और दक्षिणी मञ्चिरियन रेलवे के ९९ पाल के पट्टे की बात का भी इसमें स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया था। मञ्जुकुओ राज्य की सरकार ने यह बात स्वीकृत की थी, कि इस शर्तनामे में जागान के जिन विशेषाधिकारों का परिगणन किया गया है, उनको वह बिना किसी अनु नच के मानेगी और उनको अक्षुण्ण रखेगी। चीन की कुओ मिन्तांग सरकार् 🔏 री जापान के झगड़की जड़ये विशेषाधिकार ही थे, जिन्हों नष्ट पारने के लिये मार्शंल नियांग नाई शेन नी सरकार कटिबढ़ थी। पर अब मञ्चूकुओं के प्रथम राज्य के निर्णय के कारण जायान के ये विशेषाधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गये थे। इन विशेषाधिकारों के मञ्जूकुओं द्वारा स्वीकृत कर लेने के बदले में जापान की

सरकार ने यह जिम्मा लिया था, कि वह नवस्थापित मञ्जूकुओ राज्यों में ज्ञान्ति द्रिर व्यवस्था को कायम रखेगी और विदेशी आक्रमणों से उसकी रक्षा करेगी।

अपने इन विशंपाधिकारों की रक्षा के लिये जापान के पास मञ्चकुओं में शक्ति की कमी नहीं थी। वह निम्नलिखित साधनों द्वारा इनकी रक्षा करने में समर्थ था-(१) लिआओत्ंग का जो प्रदेश ९९ साल के पट्टे पर जापान के पास था, उसमें उसकी अपनी सरकार थी। इस प्रदेश में पूछीस, न्यायालय आदि सब जापान के अपने थे। (२) दक्षिणी मञ्चूरियन रेलवे के क्षेत्र में भी जापानी सैनिक पुलीस की सत्ता थी, और इस क्षेत्र के शासनप्रबन्ध में भी उसका हाथ था। (३) क्वांतुंग सेना मञ्चूकुओ में विद्यमान थी, और १९३१ के बाद इस सेना की संख्या और शक्ति दोनों में बहुत वृद्धि हो गई थी। (४) दक्षिणी मञ्चिरियन रेलवे के क्षेत्र में जिन अनेकविध व्यवसायों का संचालन रेलवे कम्पनी द्वारा किया जाता था, उसका उल्लेख हम पहले एक अध्याय में कर चुके है । इन व्यवसायों का संचालन जापानी लोगों द्वारा होने के कारण रेलवे क्षेत्र में जापान का प्रभुत्व बहुत व्यापक था। (५) जापानी लोगों के लियं एक्स्ट्रा-टैरिटोरिए-खिटी की पढ़ित को अब भी स्वीकृत किया जाता था, और इस पढ़ित को क्रिया में परिणत करने के लिये मञ्चूकुओं में उपयुक्त साधन विद्यमान थे। जापानी सरकार द्वारा मञ्चकुओ में सर्वत्र कान्सल नियुक्त किये गये थे, और जापानी लोग अपने को इन्हीं कान्सलों के शासन में मानते थे। (६) मञ्च-कुओ राज्य की नई राजधानी हि सन्किंग की बनाया गया था, और यहां जापान की ओर से एक राजदूत की नियनित की गई थी। लिआओत्ंग प्रदेश का गवर्नर, क्वांतुंग मेना का सेनापति और राजदूत के पद एक ही व्यक्ति के हाथ में रहते थे। इन तीन महत्त्वपूर्ण पदों के एक ही व्यक्ति के हाथों में रहने के कारण उसकी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती थी, कि वह मञ्जू-कुओ राज्य को भलीभांति अपने असर में रख सकता था। क्वांतुंग सेना के प्रधान सेनापति की हैसियत से मञ्चक्ओ में स्थित जापानी राजदूत वहां की सरकार को कठगुतली के समान नचा सकता था।

मञ्जूकुओं की सरकार पर जापान का कितना अधिक प्रभुत्व था, इसे इसी क्षालें में समझा जा सकता है, कि उसकी सिविल सीवस के उच्च कर्मचारियों में ६० फी सदी जापानी थे। मञ्जूकुओं की सिविल सीवस के निम्न श्रेणि के कर्मचारियों में भी जापानियों की संख्या (१९३६ में) ५० प्रतिशत के लगभग थी। यह ठीक है, कि वे जापानी नर्मचारी गञ्जूकुओं की नौकरी में थे। ये उसी से वेतन प्राप्त करते थे, जीर उसी वे आदेशों को किया में परिणत करते

थे। सरकार के विविध विभागों के प्रधान मञ्जूकुओ के ही लोग थे, अत: यह समझा जा सकता है, कि सरकारी नौकरी में जो जापानी लोग नियुक्त किये में हैं, उसका कारण शासन सम्बन्धी उनकी विशेष योग्यता थी। पर साथ ही यह भी स्पष्ट हैं, कि मरकार के कर्मचारियों में इतने अधिक जापानियों की सत्ता कि यातमक दृष्टि में मञ्जूकुओ में जापान के प्रभुत्व को स्थापित करने में सहायता पहुंचाती थी और ये जापानी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जापान के हितों को अपनी दृष्टि में रखते थे। मञ्जूकुओ राज्य में जो भी महत्त्वपूर्ण सरकारी पद थे, उन सब पर जापानी लोग नियुक्त थे। सेना, पुलीस आदि में तो जापानियों की प्रमुख स्थित थी ही, साथ ही शिल्प, व्यवसाय, न्याय विभाग आदि के विभागों में भी जापानी आफिसरों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। मञ्जूकुओ की आभ्यन्तर व बाह्य राजनीति के निर्धारण में जापानी लोगों का विशेष हाथ होता था।

मञ्जूकुओ राज्य की पथक व स्वतन्त्र रूप से स्थापना हो गई थी। पर इस राज्य के साथ जागान के अतिरिक्त अन्य राज्यों का भी सम्बन्ध था। इनके सम्बन्ध में सञ्चक्को की सरकार ने मार्च, १९३२ में जिस नीति का निर्धारण विया था, उसके प्रधान तत्त्व निम्नलिखित थे-(१) विदेशी राज्यों के साथ औ सम्बन्ध स्थापित किया जायगा, वह न्याय और शान्ति के सिद्धान्तों पर आश्रित होगा । इस सम्बन्धों को स्थापित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय कानन का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जायगा । (२) चीन की गरकार ने मञ्जूरिया में अत्य राज्यों के साथ जो विविध सन्धियां की थीं, उन्हें अविकल रूप से भाना जायगा और उन सन्धियों के कारण चीनी सरकार ने अपने ऊपर जो जिम्मेबारियां ली थी. मञ्जुक्त्रों की सरकार उन सबकों स्वीकृत करेगी। (३) भञ्जूरिया में विदेशी राज्यों ने जो अधिकार प्राप्त किये हुए थे, न केवल उन्हें माना जायगा, अपितु साथ ही भव्यकुओं की सरकार विदेशी राज्यों के नागरिकों के जान व माल की रक्षा के लिये मी पूरी तरह से जिस्मेवार होगी। (४) विदेशी लोगी की मञ्चूकुओं में आने व वसने की सुविधा दी जायगी व सब जातियों के लोगों के साथ एक समात व न्याययुक्त वरताव किया जायगा । (५) विदेशी राज्यों के साथ व्यापार की प्रोत्साहित किया जायगा । (६) जहां तक आधिक जीवन का सम्बन्ध है, किसी राज्यों के लोगों को मञ्जूलुओं में सब प्रकार की स्विधाएं दी आवेंगी।

इसमें सन्देह नहीं, कि यदि इस नीति को भलीभांति अनुसरण किया जाता, तो मञ्जूकुओं के सम्बन्ध में किसी भी विदेशी राज्य को शिकायत का मौका त होता। पर वस्तुतः मञ्जूकुओं जापान का संरक्षित व बगवर्ती राज्य था। यह

स्वाभाविक था, कि उसमें अन्य देशों के मुकाबले में जापान की विशेष मुविधाएं द्वान्त हों । फरवरी, १९३५ में मंचूरियन पेट्रोलियम कम्पनी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यह था, कि यह विदेशों से कुड आयल को मंगावे और उसे साफ करने के लिये व्यवस्था करे। इस कम्पनी की पूजी ५०,००,००० येन निश्चित की गई। इस पूंजी में से ३०,००,००० येन मञ्चूनुओं की सरकार और दक्षिणी मञ्च्रियन रेलवे कम्पनी ने लगाये और शेष २०,००,००० येन जापान की चार आयल कम्पनियों ने लगाये । इस दशा में पेट्रांलियम के महत्त्वपूर्ण व्यवसाय की संचालित करने का अधिकार मुख्यतया जापानी लोगों को प्राप्त हो गया। क्योंकि इस मम्पनी ना पेटोलियम के व्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित किया गया था. अतः अन्य देशों की इससे शिकायत होना सर्वथा स्वामाविक था, विशेषतया उस दशा में जब कि अनेक विदेशी कम्पनियां पहले से मञ्चूरिया में पेट्रोलियम के व्यवसाय में संलग्न थीं। अन्य देशों का कहना था, कि मञ्चिर्यन पेट्रोलियम कम्पनी के निर्माण के कारण उन्हें पेट्रोल के कारोबार में पहले के समान मुविधा नहीं रह गई है, और यह बात उस नीत के विरुद्ध है, जिसका प्रतिपादन मञ्चक्ञो सुरकार द्वारा किया गया था। पर मञ्चक्ञो और जापान की सरकारें इसका यह उतर देती थीं, कि जिन देशों ने मञ्चकुओं की पृथक व स्वतन्त्र राज्य के रूप में सत्ताको भी स्वीकृत नहीं किया है, उन्हें उससे आर्थिक मुविधाएं प्राप्त करने की आशा रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस युक्ति को सर्वथा गलत भी नहीं कहा जा सकता। मञ्चूकुओ की एक पृथक व स्वतन्त्र राज्य के रूप में सत्ता एक यथार्थ बात थी। इसलिये धीरे वीरे अन्य देश उसकी यथार्थ (द फैक्टो) सता को स्वीकृत करने के लिये विवन होते जाते थे। रूस के राज्य-प्रतिनिधि हि सिन्किंग (मञ्चकुओं की राजधानी)में रहने लगे थे और मञ्चकुओं का प्रतिनिधि भी साइबीरियन रिपब्लिक (रूमी सोवियत संघ के अन्तर्गत) में नियुक्त कर दिया गया था। अमेरिका के जो कान्सल मञ्चिरिया में १९३१ से पहले नियनत थे, उन्हें भी वहां से वापस नहीं बुलाया गया था । चीन, रूस, अमेरिका आदि जिन राज्यों का पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ट सम्बन्ध था, वे मञ्चूकुओ की उपेक्षा नहीं कर सकते थे । इसीलिये यद्यपि उन्होंने इस नये गज्य की वैधानिक कता को स्वीकार नहीं किया था, तथापि वे इसकी यथार्थ सत्ता को स्वीकृत करने के लिये विवश थे।

धीरे धीरे कुछ देशों ने मञ्चूकुओ की वैधानिक सना को भी स्वीद्धन दारण प्रारम्भ कर दिया था। सबसे पूर्व मई, १९३४ में व्यागारिक आवश्यकताओं से विवश होकर अल साल्बदोर रिपब्लिक ने मञ्चूकुओं की पृथक व स्वतन्त्र मत्ता को वैधानिक रूप से स्वीकृत कर लिया था। इसके बाद अन्य कई राज्यों ने भी उनका अनुसरण किया।

मञ्चकुओं पर जापान का प्रभाव व प्रभृत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान था इस दशा में यह समस्या उत्पन्न होनी अवश्यम्भावी थी, कि उनरी मञ्जूरिया में रूम को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे , उनके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जाय । उत्तरी मञ्चरिया की पूर्वी चाइनीज रेलवे रूस के प्रभुत्व में थी, उसके निर्माण के लिये कम ने बहुत अधिक चन का व्यय किया था। इस रेलवे लाइन के क्षेत्र में रूस को अनेक राजनीतिक विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। पर १९३२ तक सम्पूर्ण मञ्जुरिया मञ्जुकुओ राज्य की सरकार के अधिकार में आ चुका था। क्यों ंकि इस राज्य पर जातान का प्रभृत्य था, अतः रूस अपने विशेषाधिकारों की रक्षा ्तभी कर सकता था, जब कि वह जापान के साथ संघर्ष करने के लिये तैयार हो। पर इस यग में रूस किमी भी अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में उलझने की स्थिति में नहीं था। वह विविध योजनाओं द्वारा अपने सैनिक व आधिक उत्कर्ष के लिये प्रयत्न कर रहा था, और सब देशों के साथ मैत्री व सुलह की नीति का अनसरण करना चाहता था । इस दशा में रूसी सरकार ने यही उचित समक्षा, कि पूर्वी चाइनीजू रेलवे का विकय करके मञ्चरिया से अपने विशेषाधिकारों का अन्त कर दे। १२३४ में इस मामले का फैसला कर लिया गया। जिन शती पर रूस ने पूर्वी मञ्च्रियन रेलवेसे मञ्चकुओ सरकार को बंच देना मंज्रिकिया, वे निम्नलिखित थी-(१) मञ्जूकुओ सरकार १४,००,००,००० येन इस रेलवे की कीमत रूस को प्रदान करे। (२) जिन इसी रेलवे कर्मचारियों को पूर्वी मञ्चूरियन रेलवे की नौकरी से पृथक किया जायगा, उन्हें ३,५०,००,००० येन हरजाने के रूप में दिया जाय। (३) मञ्ज्कूओ सरकार इन रक्तमों को ठीक समय पर अदा करेगी, जापान इस बात की गारन्टी वे। १७,५०,००,००० येन की भारी रक्तम को अदा कर सकते का मञ्जूकुओ सरकार के सम्मुख केवल यही उपाय था, कि वह पूर्वी चाइनीज रेलवे को जमानत के तौर पर रख कर यह रकम जापान से कर्ज ले। उसने इसी उपाय का अनुसरण किया, और उत्तरी मंचूरिया की यह रेलवे लाइन रूस के बजाय जापान के हाथ में आ गई। चीन की सरकार इस सौदे के खिलाफ थी, उसने इसका विरोध भी किया। पर उसका विद्रास सर्वथा निरर्थंक था। २३ मार्च, १९३५ को पूर्वी चाइनीज रेलवे रूस के बर्जाय जापान के अधिकार में आ गई। मञ्चूकुओ राज्य के किसी प्रदेश पर भी जापान के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी राज्य का कोई विशेषाधिकार नहीं रहा। मञ्चू जुओ के पृथक राज्य के स्थापित हो जाने पर जापान ने उसमें किस

प्रकार अपने प्रभाव को स्थापित करना शुरू किया, इस सम्बन्ध में कुछ अन्य बातों का उन्लेख भी आवश्यक है—

- (१) जापान के पूंजीपितियों ने बहुत बड़ी मात्रा में मञ्जूकुओं के विविध व्यवसायों में पूंजी लगानी प्रारम्भ की । १९३२ में जो जापानी पूंजी इस राज्य में लगी हुई थी, उसकी मात्रा ९,७२,००,००० येन थी । इसके बाद मञ्जूकुओं में जापानी पूंजी निरन्तर बढ़ती गई। १९३८ में वहां ४३,१०,००,००० येन नई पूंजी लगाई गई। यह पूजी प्रधानतया रेलवे लाइनों और लोहे व कोयले के व्यवसायों में लगाई गई थी। १९३१ से पहले मञ्जूरिया कुषिप्रधान देश था, उसमें व्यवसायों का विकास अधिक नहीं हुआ था। पर १९३२ से दहां व्यवसायों की बड़ी शी घता से वृद्धि गुरू हुई।
- (२) जापान और मञ्चूकुओ में पारस्पिक व्यापार पहले भी विद्यमान था। पर १९३२ तक जापान मञ्चूरिया में जितना तैयार माल विकी के लिये भेजना था, उससे कहीं अधिक कच्चा माल उससे कय करता था। यही कारण है, कि १९३२ में मञ्चूरिया से जापान को निर्यात होनेवाले माल की मान्ना वहां से आयात होनेवाले माल की अपेक्षा २,६०,००,००० येन अधिक थी। पर मञ्चूरिया की चीनी शासन का अन्त कर अपनी संरक्षा में मञ्चूकुओ राज्य की स्थापना में जापान का प्रधान उद्देश्य आधिक था। वह इस प्रदेश पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करके उससे अपनी आधिक समस्या को हल करना चाहता था। इस उद्देश में जापान को सफलता हुई। १९३६ में जापान से मञ्चूकुओ जाने वाले माल की मान्ना यहां से आने वाले माल की अपेक्षा २७,००,००,००० येन अधिक हो गई।
- (३) जापान ने यह भी यत्न किया, कि अपनी निरन्तर बढ़ती हुई आवादी के एक भाग की मञ्ज्यूकुओं में आबाद करे। १९३१ में मञ्ज्यूरिया में जितने जापानी लोग आबाद थे, १९३७ में उसकी अपेक्षा दुगने के लगभग जापानी इस देश में बसे हुए थे। १९३५ की जनगणना के अनुसार मञ्ज्यूकुओं में बसे हुए जापानियों की संख्या ५,०१,१५१ थी। जापानी लोगों के अतिरिक्त कोरिया और फार्मूसा के भी बहुत से लोग इस राज्य में आकर आबाद होने लगे थे। कोरिया और फार्मूसा के भी बहुत से लोग इस राज्य में आकर आबाद होने लगे थे। कोरिया और फार्मूसा इस समय जापान के अभीनथे, अतः स्वामाविक रूप से मञ्ज्यूकुओं में बहुं के लोगों को बसने के लिये सब प्रकार की मुविधाएं दी जाती थीं। जापानी सरकार ने बाकायदा एक ऐसी योजना का निर्माण किया था, जिसके अनुसार मञ्ज्यूकुओं के विविध प्रदेशों में जापानी लोगों को आबाद किया जाना था। १९३६ के अन्त तक गर्यन्यूकुओं में जापानी लोगों को अबाद किया जाना था।

निवासियों की संख्या ४,२४५ थी। इन वस्तियों में बसे हुए जापानी कृषि द्वारा अपना निर्वाह करते थे। १९३६ में मञ्चूकुओं में जापानी वस्तियों का श्री-गणेश मात्र किया गया था। जापानी सरकार की योजना यह थी, कि अक्षेत्र वीस सालों में १०, ००,००० जापानी परिवारों को मञ्जूकुओं के विविध क्षेत्रों में बसा दिया जाय, नाकि जापान की बढ़ती हुई आबादी के कुछ अंश को इस संरक्षित राज्य में आबाद किया जा सके। यदि जापान १९४० में महायुद्ध के चक्कर में न फंम जाता, नो नि:मन्देह उगकी यह योजना अविकाल कप में सफल हो सकती।

जापानी गरकार यह भी अनुभव करती थी, कि मञ्चूकुओं को जापानी लोगों के आवाद होने के लिये उसी दशा में उपयुक्त बनाया जा सकता हैं, जब कि वहां चीनी लोगों के प्रविष्ट होने में स्कावटें उपस्थित की जावें। वह स्पष्ट हैं, कि यदि चीनी लोगों की मञ्चूकुओं में निर्वाध रूप से आवाद होते रहते, तो इस राज्य में जापानी लोगों की स्थित मुरक्षित नहीं समझी जा सकती थी, क्योंकि चीन की सरकार मञ्जूरिया को अपना अंग मानती थी और चीनी लोगों में जापान के प्रति विरोध का भाव बहुत अधिक था। अतः १९३५ में मञ्जूकों की सरकार ने अनेक इस प्रकार के कानून बनाये, जिनके कारण चीनी लोगों के लिये यह को सम्भव रहा, कि वे सामयिक रूप से मजदूरी आदि के लिये मञ्जूकुओं में आ जा सकें, पर उनके लिये इस देश में स्थिर रूप से आवाद हो सकना सम्भव नहीं रह

पर मञ्चूकुओ में चीनी लोगों की कमी नहीं थी। उसकी आयादी में चीनी लोगों की बहुसंख्या थी। इसलिये मञ्चूकुओ की सरकार ने यह प्रयत्न किया, कि इस नवस्थापित राज्य के सब निवासियों को सम्राट् के प्रति अनुस्त करके उनमें राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न किया जाय। मञ्चूकुओ के लोगों में यह प्रचार किया गया, कि सम्राट् के प्रति भिवत रखना और सरकारी आजाओं का पालन करना उनका परम कर्तव्य है। यह विचार जापान की अपनी परम्पर के अनुकूल था। जापान में सम्राट् को दैवी माना जाता था और जनता उसके प्रति असाधारण श्रद्धा रखती थी। मञ्चूकुओ में भी यह प्रयत्न किया गया, कि वहां निवास करनेवाले विविध जातियों के लोग सम्राट् को अपना अधीरवर समन्ने। चीनी लोगों के लिये यह नई वात नहीं थी। १९११ तक वे मञ्चू स्थार को अपना स्वामी मानते रहे थे। अतः उनके लिये यह कठिन नहीं था, कि अब भी वे मञ्चूवंश के सम्राट् को अपना अधिपति मानने लगें और उसकी आजापालक प्रजा बन सकें।

(६) मञ्चूकुओ राज्य की प्रगति

मञ्चक्ञा राज्य के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या देश में जान्ति और व्यवस्था को स्थापित करने के सम्बन्ध में थी। जिस समय मञ्चरिया चीन के अधीन था, यहां व्यवस्थित शासन का अभाव था। इस कारण वहां डाकुओ का बहत जोर था । डाकुओं के दल के दल देण में लूटमार करने फिरने थे । किसानों व गरीव लोगों की इतनी आमदनी नहीं थी, कि वे शान्ति के साथ अपना जीवन बिता सकें । अतः सर्वसाधारण किसान लोग भी मौका मिलने पर डकैती से बाज नहीं आने थे। विशेषतया जब फसल खराब हो जाती थी या बाढ आदि के कारण फसल नष्ट हो जाती थी, तो भूख से पीड़ित लोग डाकाजनी पर उतर आते थे और देद्रातों में अव्यवस्था उत्पन्न कर देते थे। जब मञ्चित्या चीन से पृथक् हो गया और जापान की संरक्षा में वहां नई सरकार की स्थापना हुई, तो अव्यवस्था और डाकाजनी की यह प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ गई। बहुत से चीनी लोग जो नई सरकार से असन्त्रष्ट थे, गुरीला पढ़ित का अनुसरण कर लुटमार पर उतर आये और देश में अध्यवस्था मचाने लगे। चांग ह सुएह-लियांग की सेना इस समय भग कर दी गई थी। उसके बहुत से सिपाही अब बेकार हो गये थे। ये किंगही सैनिक दृष्टि से सुशिक्षित थे, और अस्त्र शस्त्र भी इनके पास गीजुद थे। ये उन देशभक्तों के साथ मिल गये, जो मञ्चूकुओ सरकार के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थे। मञ्जूनुओं में प्रधानतया सोयाबीन की खेती होती थी। वहां की सोयाबीन न केवल जापान में अपित चीन और यूरोप में भी बिकती थी। पर इस समय विदेशों में मञ्चूकुओ की सोयावीन की मांग बहत कम हो गई थी। चीन मञ्चूकुओ के साथ व्यापारिक सम्बन्ध नहीं रखना चाहता था। विश्व-व्यापी अर्थसंकट के कारण जर्मनी आदि यूरोपियन देश भी इस समय इस स्थिति में नहीं थे, कि वे मञ्जूकुओ से सीयाबीन की अधिक परिमाण में खरीद सकें। इस दशा का यह परिणाम हुआ, कि मञ्चूकुओ में सोयाबीन की पैदावार में कमी होने लगी। १९३० में वहां ५३,००,००० टन सोयाबीन उत्पन्न हुई थी। १९३४में उसकी मात्रा घटकर ३३,५०,०००टन रह गई थी। मञ्चकुओं के किसानों पर इस दशा का क्याप्रभावपड़ा होगा, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। बहुत सी जमीन परती पड़ गई थी, और बहुत से किसान बेकार हो गये थे। इत दशा में यदि मञ्जूजुओ में डाकाजनी की प्रवृत्ति में और अधिक बृद्धि हो गई हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

मञ्जू को की सरकार ने जबती और अज्यवस्था की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिये बहुत सख्त उपायों का अयोग किया। दहानों में यह योजना बनाई गई,

कि गावों के चारों और मट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें बगाई जावें, ताकि डाक लोग गांवों पर आक्रमण न कर सकें। १९३६ तक २००० से भी अधिक गांवों के नारों ओर दीवार वनाकर उन्हें छोटे छोटे दुर्गों के एप में परिणत कर दिया गया था। इस प्रकार सरकार ६०,००,००० के लगभग मनुष्यों की डाकुओं से रक्षा करते में समर्थ हुई थी। साथ ही डाकुओं और देशभक्त गुरीला सैनिकों का दमन करेने के लिये क्वांतुंग सेना में बहुत अधिक वृद्धि की गई थी। इस जापानी सेना के दस्ते मञ्चकुओ में सर्वत्र नियक्त कर दिये गये थे । शहरों और देहातों में सब जगह पर क्वांतंग मेना की छावनियां डाल दी गई थीं, और इसमें सन्देह नहीं कि सैन्य-शक्ति का प्रयोग कर जापान की सरकार व उसकी संरक्षित मञ्चूकुओं सरकार देश में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना में बहुत अंश तक समर्थ हुई थी। पर इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि गञ्च्रिया में निवास करनेवाले बहुत से चीनी लोग देशभक्त गुरीला लोगों के साथ सहानुभूति रखते थे,और बहुधा वे उनकी सहायता के लिये भी तत्पर रहते थे। १९३६ के बाद संसार के प्राय: सभी देशों में कीमतें फिर ऊंची उठनी शुरू हो गई। मन्दी का वृग समाप्त होकर एक बार फिर तेजी का समय शुरू हुआ । मञ्चूकुओ भी इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं रहा। उसकी सोयाबीन व अन्य कृषिजन्य पदार्थों की संसार के बाजारो से मांग बढ़ने लगी और आधिक मंकट के दूर होने पर वहां शान्ति और व्यवस्था के स्थापित होने में बहुत सहायता मिली । १९३६ में अनेक राज्यों ने गञ्चकूओ के साथ व्यापार को फिर मे प्रारम्भ कर दिया। इस दशा में वहां डाकाजनी और अन्यवस्था बहुत कुछ कम हो गई।

मञ्जूकुओ की सरकार ने देश की उन्नति के लियं जिन विविध उपायों का अवलम्बन किया, उनमें से कतिपय का यहां उल्लेख करना आवश्यक हैं। उसने देश की मुद्रापढ़ित का पुनः संगठन किया। इसमें पूर्व मञ्जूकुओ में अनेन प्रकार के सिक्के प्रचल्ति का पुनः संगठन किया। इसमें पूर्व मञ्जूकुओ में अनेन प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। अब युआन नामक नये सिक्के को जारी किया गया, जिसका मूल्य जापान के येन के आधार पर निश्चित किया गया। युआन और येन के मूल्य को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के विविध देशों के निक्कों की कीमत ब्रिटिश पाँड के साथ सम्बद्ध थी, वैसे ही मञ्जूकुओ के युआन को जापानी येन के साथ सम्बद्ध कर दिया गया।

इस समय मञ्जूकुओ में अनेन नई रेलने लाइनों मा भी निर्माण किया गर्की १९३२ से १९३६ तन चार साल के अरसे में मञ्जूकुओ की रेलने लाइनों में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई। आधिक वृष्टि से जहां ये नई रेलने लाइनें अत्यन्त उपयोगी थीं, नहां साथ ही इनका मैनिक महत्त्व भी क्षम नहीं था। मञ्जूको सरकार भली-

भांति समझती थी, कि मिविष्य में इस और चीन के साथ उसका संघर्ष अवस्यस्भावी है। अतः इन रेलवे लाइनों का निर्माण इस ढंग से किया गया था, जिसमें युद्ध के र्चेमय में इनमें लाभ उठाया जा सके । इन लाइनों का निर्माण जापानी पंजी द्वारा किया गया था, अनः इनका प्रबन्ध दक्षिणी मञ्चिरियन रेलवे सम्पनी के मृपूर्व कर दिया गया था, जो कि एक जापानी कम्पनी थी। इस से जिस पूर्वी चाइनीज रेलवे लाइन को १४,००,००० येन में प्रय किया गया था, उसका प्रवन्य भी दक्षिणी मञ्ज्रियन रेल्वे कम्पनी के हाथों में दे दिया गया था । इस प्रकार यह विशाल जापानी रेलवे सम्पनी मञ्चूक्जो की सब रेलवे लाइनों का प्रबन्ध करती थी। मञ्चकुओ की सरकार ने देश में सड़कों के निर्माण पर भी बहुत ध्यान दिया था। देश के स्वासन और डकैती का दमन करने के लिये इन सडकों का बहुत उपयोग था । हवाई जहाजों की उन्नति के लिये भी मञ्जूक्ओ की सरकार ने प्रयतन किया था और मञ्च्रियन एविएशन कम्पनी नाम से एक नई कम्पनी की स्थापना की गई थी, जिसकी तरफसे देशके प्रायः सभी मुख्य नगरों में हवाई जहाजोंकी मिनस चलती थी। इसी प्रकार दैलीफोन व दैलीग्राफ के विस्तार के लिये भी सरकार द्वारा अनेक व्यवस्थाएं की गई थीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, 🎏 चीन से पथक होकर जापान जैसे उन्नत देशकी संरक्षा में मञ्चकुओकी सरकार ने देश की आधिक उन्नति के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये थे।

पर साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि मञ्चूकुओ की सरकार देश की उन्नति की अपेक्षा सैन्यगिवत को अधिक महत्य देती थी। सरकारी आमदनी का ४० प्रतिशत भाग मेना पर व्यय किया जाता था। इसके मुकावल में शिक्षा पर वर्च की मात्रा कुल मरकारी खर्च का केवल २.२ प्रतिशत थी। मञ्चूकुओं में उच्च शिक्षा की संस्थाओं की बहुत कभी थी। सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिये बहुत से नये शिक्षणालय लोले थे, पर उसने उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था। मञ्चूकुओं के जिन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती थी, वे जापान के विद्यविद्यालयों में जाकर भरती होते थे। इससे उनमें जापानकी सभ्यता व संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न होने में सहायता मिलती थी, और वे जापानी रंग में रंग जाते थे। जापानी सरकार की यह बात अभीष्ट की यी, क्योंकि मञ्चूकुओं के शिक्षतवर्ग को अपने प्रभाव में रखकर ही जापानी लीग मञ्चूकुओं पर अपना प्रभुत्व कायम रख सकते थे।

सोलहवां अध्याय

चीन में जापान के आधिपत्य का विस्तार

(१) मंगोलिया और जापान

जायान मञ्चरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुना था। पर उसकी साम्राज्य प्रसार की भूल मञ्चूरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करने ही संतृष्ट नहीं हो गई। उसने यत्न किया, कि उत्तर-पूर्वी चीन और मंगोलिया में भी अपने प्रभुत्व का प्रसार किया जाय । वस्तुनः जापान सम्पूर्ण चीन की अपने प्रभाव य प्रभुत्व में ले आना चाहता था । वह भलीमांति अन्भव करता था, कि चीन में जिस प्रवार राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा है, और कुओमिलांग दल जिस ढंग से चीन में एक गुरुयस्थित और मुपृढ़ शासन स्थापित करने के लिये प्रयतन-शील है, उसका यह परिणाम अवस्यमभावी है, कि वह मञ्चूरिया को फिर अपने अधीन करने का प्रयतन करे । नवस्थापित मञ्चकुओं राज्य की दक्षिणी मीमा चीन से लगती थी, ओर उसकी पश्चिमी सीमा मंगोलिया को छुनी थी। गंगोलिया चीन के अधीन था, अतः स्वाभाविक रूप से जापान यह समझता था, कि मञ्ज्कुओ राज्य पर अपने आधिपत्य को कायम रखने के लिये यह आबश्यक है, कि मंगोलिया और उत्तरी चीन को भी अपने प्रभाव में लाया जाय। १९३७ में चीन और जावान में बाकायदा युद्ध प्रारम्भ हो गया । पर १९३२ और १९३७ के बीच में भी जापान चीन में अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था। इस काल में चीन और जावान में युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी। उनके राजदूत व अत्य राजप्रतिनिधि भी एक दूसरे राज्य में विद्यमान थे। पर जापान धीरे धीरे चीन को अपने प्रभूत्व में लाने में तत्परथा । १९३२ से १९३७ तक चीन के जिन प्रदेशों में जापान ने अपने प्रभुत्व को विस्तृत विखा, ये आभ्यन्तर मंगोलिया और उत्सी चीन के होपेर्ड, शान्मी, ओर शान्तुंग प्रान्त थे । इन प्रदेशों में नीन ने किस प्रकार अपने प्रभत्व का प्रसार किया, इसी विषय पर हम इस अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

जहोल की विजय-१९३३ के प्रारम्भ में क्वांतुंग सेना ने शानहैशयान पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का उद्देश्य जहोल प्रान्त को अपने आधिपत्य में लाने का उपक्रम नरना था। मञ्चूरिया के भूतपूर्व सिपहसालार चांग-ह् सुएह-कियांग ने घोषणा की, कि जब तक उसकी सेना का एक भी सैनिक जीवित है शानहैनावान पर जापानी सेना का कब्जा नहीं होने दिया जायगा। पर चीनी सेनाओं के लिये यह सम्भव नहीं था, कि ये क्यांतुंग सेना के सम्मृत्व ठहर सकती। वे परास्त हो गई, और गानहैक्शन को जीनकर जापान की सेना ने जहोल पर आक्रमण किया। ३ मार्च, १९३३ को जहोल की राजधानी चेंग्नेह पर जापान का कब्जा हो गया। जहोल के प्रदेश को मञ्चूकुओ राज्य में सम्मिलिस कर लिया गया और मंजूरिया के समान उस पर भी जापान का प्रभुत्व स्थापित हो गया।

मंगोलिया में हस्तक्षेप-मंगोलिया किस प्रकार वाह्य और आभ्यन्तर वां भागों में विभवत था, इस पर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। बाह्य मंगोलिया में गंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक के नाम से एक समाजवादी राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जो रूस के प्रभाव में थी। पर आस्थान्तर मंगोलिया चीन के अधीन था, यद्यपि उसमें अनेना मंगोल सरदार कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र रूप से शारान भरते थे। पर चीनी लोग इम प्रदेश में तेजी के साथ आवाद ही रहे थे, और वे गंगोलिया की क्रिय पोप्य भूमि को अपने कको में लाते जाते थे। मंगोल लोगों का मुख्य पेशा पश्यालन था और खेती की तरफ उन्होंने विशेष ध्यान गहीं दिया था। पर मंगोलिया में बसनेवाल नीनी लोग प्रधानतया निसान थे और वे घीरे घीरे मंगोल लोगों की जमीन पर अपना अधिकार स्थापित भरने जाने थे। कुओमिन्तांग दल की अनेक शास्त्राएं आस्थन्तर मंगोलिया की विविध वस्तियों में गायम थीं, और यह राष्ट्रवादी चीनी पार्टी मंगोलियन लोगों को चीनी सम्यता व संस्कृति के रंग में रंगने में तत्पर थी।

यह स्थिति थी, जब जागानी लोगों ने आभ्यन्तर मंगोलिया में हस्तक्षेप प्रारम्भ किया। जहोल की बहुसंख्यक आबादी मंगोल जाति की थी। यस्तुतः जहोल भी मंगोलिया ता ही एक अंग था। जहोल के मञ्चूकुओ राज्य के अन्तर्गत हो जाने के बगरण जागान के बशवर्ती इस राज्य में मंगोल लोगों की संख्या बहुत नाफी ही गई थी। जहोल में निवास करने वाले मंगोलों की संख्या २०,००,००० के लगभग श्री। इतनी बड़ी संख्या में मंगोल लोग आभ्यन्तर मंगोलिया में यी नहीं थे, यद्यपि इस प्रदेश वा क्षेत्रफल जहोल की अपेक्षा कई गुना या। जागिनमां ने जहोल की मञ्चूकुओ बा एक पृथक प्रान्त का दिया जीर इस प्रान्त को जागे सामन में पूरी स्वतन्यता दे दी नह। २३ र स्वानिव धा, कि जहोल में वामने की सम्वीव स्वानिव स्

उन्हें चीनी सामन में भी प्राप्त नहीं थी। जापानी लोग समक्षते थे, कि जहांल में बसनेवाले अपने बन्वुओं को प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त करते देखकर आश्यन्तर मंगोलिया के मंगोल निवासियों में भी यह प्रवृत्ति होगी, कि वे चीन की अधीनता समुक्त होकर जापान के प्रभाव में आने की बात का स्वागत करें। पर आश्यन्तर मंगोलिया के विविध सरदारों ने शक्तिशाली व साम्राज्यवादी जापान की प्रभृता में आने की अपेक्षा चीन की निर्वेल सरकार के अधीन रहना अधिक हितवार समझा। इस समय चीन की कुओमिन्तांग सरकार ने भी मंगोल लोगों के सम्बन्ध में जापान की नीति का अनुसरण किया। आश्यन्तर मंगोलिया को प्रान्तीय स्वतन्त्रता दे दी गई और विविध मंगोल सरदारों ने इसमें मंतोष अनुभव किया। १९३४ में मंगोल लोग तीन पृथक राज्यों में विभवत थे—(१) बाह्य गंगोलिया की रिपब्लिक, जो क्य के प्रभाव में थी। (२) आश्यन्तर मंगोलिया, जो चीन के अधीन था, पर जिमे प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त थी। (३) हिसानगान, यह उस प्रान्त का नाम था, जो सञ्चूकुओं के अन्तर्गत था, और जिसे मञ्चूकुओं राज्य की सरकार हारा प्रान्तीय स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी।

पर जापानी लोग आभ्यत्तर मंगोलिया पर अपना प्रभूत्व स्थापित करने के लिये उत्सक थे। जब उन्होंने देखा कि विविध मंगील सरदार चीन की अधीनना में प्रान्तीय स्वतस्त्रता प्राप्त करके संतृष्ट हैं, तो उन्होंने धनित के प्रयोग का निश्चय किया । मञ्च्कुओं और गंगोलिया की सीमाएं आपस में गाथ लाती थीं। इस सीमा के सम्बन्ध में अगडों का उलाब होना कोई पाठिन वात नहीं थीं। हम पहले लिख चके हैं, कि आभ्यन्तर मंगोलिया के तीन प्रान्त थे, चहर, सूइयआत और निन्ध्सआ। इनमें से चहर का प्रान्त मञ्चक्कों की पश्चिमी सीमा पर स्थित था । १९३५ के शुरू में सीमा सम्बन्धी एक अगई का लाभ उठाकर क्वांत्ंग सेना ने नहर प्रान्त के एक प्रदेश पर कब्जा कर लिया। जुन, १९३५ में एक अन्य मीमा सम्बन्धी अगर्ड को निमित्त बनाकर क्वांतंग सेना ने चीनी सरकार को निम्नलिखित बातों को मानने के लिये विवश किया-- (१) चहर प्रान्त में कुओमिन्तांग दल की जो शासायें विद्यमान है, उन्हें भंग कर दिया जाय। (२) चहर प्रान्त के पूर्वी प्रदेशों में चीनी लाग भविष्य में न यस सकें। (३) पूर्वी चहर से चीनी सेनाओं को हटा लिया जाय । इन शतों को मान लेन ना यह परिणाम हुआ, कि चहर प्रान्त पर से चीन का प्रभत्व बहुत कुछ नष्ट हो गया 🛊 इसी समय चहर में क्वांत्य सेना की एक छावनी स्थापित कर दी गई और यह प्रान्त जापान के प्रभाव में आ गया ।

जापानी सरकार केवल जहर प्रान्त को ही अगरे प्रभाव ये प्रभुत्व में लाकर

मंतुष्ट नहीं हुई । उसने आभ्यातर मंगोलिया के सरदारों की कीशिल के सम्मुख यह मांग भी पेन की, कि वह अपने प्रदेश में जापान को हवाई जहाजों के अड्डें की निर्माण करने और एक वायरलेंस स्टेंशन स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। उसके अिश्वित आभ्यात पंगीलिया की सरकार में जापान ने यह भी मांग की, कि वह अपने प्रदेशों में सेना और शासन के रम्बन्य में परामर्थ देने के लिये आपनी राज्यहकारों को नियुक्त करें। मंगोलियन मरकार जापान के सम्मुख असहाय थी। परिणाग यह हुआ, कि उसने जापान की मांगों को स्वीकार कर लिया। यद्यपि आभ्यान्तर मंगोलिया में प्रान्तीय स्वराज्य स्थापित था और वह नाम की चीन की अधीनता में था, पर जुलाई, १९३५ के बाद इम प्रदेश पर जापान का प्रभाव भलीमांति स्थापित हो गया था और क्वांतुंग सेना की अनेक लावनियां उस प्रदेश में कायम कर दी गई थी।

बाह्य मंगोलिया और जापान-मञ्चकुओ राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में बाह्य मंगोल्टिया के साथ छुती थी । आभ्यत्तर मंगोल्टिया के चहर प्रान्त के क्वांत्ंग सेना के आधिपत्यमें आ जाने के बाद बाह्य मंगोलिया के साथ मञ्चकुओ व जापान का समार्क ओर भी अधिक व्यापक हो गया था । जापान की उच्छा थी, कि बाह्य 🌁 मंगोलिया में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया जावे। उसकी सीमा पर क्वांतुंग रोना के साथ बहुत संघर्ष लखते रहते थे, इस दशा में जापान ने मंगोलियन पीपत्स रिपब्लिक से यह मांग की, कि (१) बाह्य मंगोलिया में जापानी लोगों की व्यापार करने व जसने की अनुमति दी जाय। (२) बाह्य मंगोलिया की गीमा की नये सिरे से निर्धारित किया जाय, ताकि भविष्य में मीमा सम्बन्धी अगडों की संभावना न रहे। पर मंगीलिया पीपल्स रिपब्लिक जापान की इन मांगों की स्त्रीकार करने के लिये तैयार नहीं हुई । उसका कहना था, कि बाह्य मंगोलिया की सीमा पहले ही मुचार कृप से निर्वारित है, और उस पर पून: विचार निरर्थन है। साथ ही वह जापानी छोगों की व्यापार आदि के लिये अपने प्रदेश में बसने वेने की अन्-मित देने को जबान गहीं थी । परिणाम यह हुआ, कि बाह्य मंगोलिया की सीमा सम्बन्धी जगहीं ने बहुत उग्र कृप भारण कर लिया। ८ फरवरी, १९३६ की एक अच्छी वडी जापानी सेना मंगोलिया की गीमा में ६ मील अन्दर घुस आई। पह सेना अस्य शस्त्रों से भलीभांति सुगज्जित थी । पर बाह्य मंगोलिया की सेना ने इसका इटकर मुकावला किया और इसे अपने प्रदेश से बाहर निकालने में मफलता प्राप्त नी । जापान के साथ इस संघर्ष में रूस मंगोलियन पीपत्स रिप-ब्लिक की पीठ पर था। रूस और बाह्य मंगीनिया ने परस्पर सन्धि करके यह निश्चय किया, कि वे किसी अन्य भाग है नाव युद्ध होने की दशा में एक दूसरे

की सहायता करेंगे। मार्च, १९३६ में मार्शल स्टालिन ने स्पष्ट थव्दों में घोषणा की, कि यदि जापान की सहायता से मञ्चूकुओ राज्य ने मंगोलियन पीपत्स रिपिटल के खिलाफ युद्ध किया, तो कस उसे अपने खिलाफ युद्ध समजेगा और वाह्य मंगोलिया की पूर्ण रूप में सहायता तरेगा। इस दशा में जापान के लिये यह समभव नहीं था, कि वह आभ्यन्तर मंगोलिया के समान गंगोलियन पीपत्स रिपिटलिय में भी अपने प्रभाव का विस्तार कर सके। इस विषय में उसे अपने प्रयत्न में सफल्यता नहीं हो सकी।

(२) उत्तरी चीन और जापान

चीन के सम्बन्ध में जापान की नीति—आभ्यन्तर मंगोलिया में अपने प्रभाव व प्रभुत्व को स्थापित कर चुकते के बाद जापान ने उत्तरी नीन में अपने आधिपत्य को कायम करने का प्रयत्न बुद्ध किया। उसरी पूर्व कि हम जापान के इस प्रयत्न का उल्लेख करें, यह उपयोगी होगा कि चीन के सम्बन्ध में जापान की नीति पर प्रवाश डाला जाय। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका सम्पूर्ण अमेरिका महाद्वीप के सम्बन्ध में अपनी विशेष उत्तरदायिता समझता था और यूरोग के साम्राज्यवादी देश अमेरिकान महाद्वीप के किसी भी प्रदेश में अपने प्रभुत्य का विस्तार न कर सकें, इस उद्देश्य से उसने मुनरो सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था; इसी प्रकार जापान का विचार था, कि पूर्वी एशियामें उसका विशेष स्थान हैं और उसका यह कर्तन्य है, कि इस क्षेत्र में कोई पाश्चान्य राज्य अपने प्रभुत्व का प्रसार न कर सकें। इसी उद्देश्य से १८ एप्रिल, १९३४ को जापानी सरकार के परराष्ट्र विभाग ने एक घोषणा प्रकाशित की थी, जिसकी कित्यय महत्त्वपूर्ण वातें यहां उद्धृत करना बहुत उपयोगी है—

"यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं, कि जापान विदेशी राज्यों के साथ सबैव मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित व प्रोत्साहित करने के लिये प्रयत्नशील रहता है, पर साथ ही हम समझते हैं, कि यह सर्वथा स्वाभाविक हैं, कि पूर्वी एशिया में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिये हम अपनी उत्तरदायिता पर अकेले भी तत्पर रहें। यह करना हमारा कर्तव्य भी हैं। साथ ही, जापान के अतिरिक्त केवल चीन ही एक ऐसा देश हैं, जो पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित रखने में जापान का हाथ बटा सकता है।

"यही कारण है, कि जापान समय रूप से इस बात के लिये उच्छुन है, कि चीन में एकता कायम हो, उसकी राजकीय सीमग्र अक्षुण्ण रहें, और उसमें व्यवस्था स्थापित रहे। इतिहास से यह बात भलीभांति स्पष्ट है, कि ये बातं तब तक सम्भव नहीं हैं, जब तक कि चीन में जापृति न हो, और चीन स्वयं इनके लियें प्रयत्न करें।

"यदि चीन जापान का विरोध करने के लिये किसी अन्य राज्य के प्रभाव का जप-योगकरेगा या यदि चीन कोई ऐसा प्रयत्न बारेगा जिसका उद्देश्य एवा राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ प्रयुक्त करना होगा, तो इसी कारण जापान उसका विरोध करेगा। मंचूरिया और शंघाई में जो घटनायें पिछले समय में हुई हैं, उनवे बाद भी यदि विदेशी राज्य इस समय जिल्पाचिपयक व आर्थिक सहायता के नाम पर कोई कार्य संयुक्त रूप से करेंगे, तो यह सहायता राजनीतिक महत्त्व प्राप्त किये बिना नहीं रह सकेगी। इस प्रकार के कोई भी कार्य, यदि उन्हें सामूहित रूप से किया जायगा, ऐसी जिल्लिताओं को उत्पन्न किये विना नहीं रहेंगे, जिनके कारण चीन का विभाजन करने व इसी प्रकार की अन्य समस्यायें पैदा होंगी। इस प्रकार के कार्यों का प्रभाव जागान व पूर्वी एशिया पर भी बहत गम्भीर होगा।

"अतः जापान भिज्ञान्त रूप से इस प्रकार के कार्यो का विरोध करेगा। पर यदि बोई विसेशी राज्य आधिक व क्यापारिक विषयों पर वैयक्तिक रूप से जीन के साथ किसी प्रकार का समझीता करना चाहेगा, तो जापान को उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवस्यकता नहीं होगी।

'पर मिंद कोई चिदेशी राज्य चीन की जंगी हवाई जहाज देगा, चीन में हवाई अइड बनायेगा, चीन की रथल व जल सेना को शिक्षा देने व संगठित करने के थिये शिक्षक मेजंगा, या चीनको गैनिक सलाहकार देगा, या राजनीतिक प्रयोजनों को सम्मुख रखकर चीन को कर्ज देगा, तो इसमें चीन, जापान और अन्य गाज्यों के मैंश्री पूर्ण सम्बन्धों में बाधा उपस्थित होगी और इसका परिणाम पूर्वी एशिया में शान्ति और व्यवस्था की क्षति पहुंचाना होगा। जापान इस प्रकार की सब योजनाओं का विरोध करेगा।'

जापान के परराष्ट्र विभाग की इस विज्ञप्ति पर टिप्पणी करने की आवस्यकता नहीं हैं। इसके द्वारा जापान ने अपनी नीति को बिलकुल स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर विया था। वह इस बात के विसद्ध था, कि पाश्चात्य देश संयुक्त रूप से किसी भी प्रकार चीन की सहायना के लिये तत्पर हों। १९३४ तक जापान राष्ट्रसंघ में पथक हो नुका था। राष्ट्रसंघ में सम्मिलित विविध राज्य इस बात के लिये प्रयत्नशील थे, कि वे चीन की सहायना करें। राष्ट्रसंघ ने चीन को सहायता देने के प्रकार पर विचार करने के लिये एए कमीधन की निग्निन की थी, जिगके अध्यक्ष डाठ राख्यान थे। यह तथीन अधा कार्य नगाप्त गर नुका था, जोए इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने की थी। इस देशा में जापान अपनी इस नीति को

स्पट्ट कर देता नाहता था, कि वह राष्ट्रसंघ में सम्मिलित राज्यों द्वारा चीन को सिमिलित च्या से दी जानवाली सहायता का विरोध करेगा। इस युग में अनेक विदेशी राज्य चीन के सैनित उत्कर्ष में सहायता देने के लियं तत्पर थे। जनरल फीन सीक्ट नाम का जमेंनी सेनापित नानिक्य सरकार का प्रयान सैनिक सलाहकार था और चीन ने अमेरिका से बहुत बड़ी रांच्या में गंगी हवाई जहाजों का क्रय किया था। अमेरिका की एक कम्पनी चीन में हवाई जहाजों के निर्माण के लिये एक बिशाल कारवाना स्थापित करने में भी प्रयत्नवील थी। जमेंनी और अमेरिका के अतिश्वित इटली भी चीन के सैनिक उत्कर्ण में दिलचम्पी ले रहा था। स्थाभविक इप से जायान के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह चीन में इन विदेशी राज्यों के सैनिक प्रभाव को सहन कर सके। उसका व्याल था, कि चीन में किसी अन्य विदेशी राज्य का प्रभाव जापान के अपने हितों के लिये उसने स्पत्त है। इसीलिये उसने स्पष्ट बब्दों में यह घोषणा की थी, कि यिव चीन किसी अन्य राज्य की सहायता से अपने सैनिक उत्कर्ण का प्रयत्न करेगा, तो जापान उमें सहन नहीं कर सकेगा।

जागान के परराष्ट्रमन्त्री श्री हीरोता ने २८ अक्टूबर, १९३५ को बीग के सम्बन्ध में अपनी नीति को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए तीन बातों व मन्तव्यों का निरूपण किया था—(१) चीन और जागान को वाहिये, कि ने परस्पर मैंबी सम्बन्ध में रहें। इसके लिये आवश्यक है, कि चीन की गरकार अब तक जागान के विरुद्ध जिन कार्यों को करती रही है, व जिन उगयों का प्रयोग करती रही है, उन्हें बन्द कर दिया जाय। (२) चीन और जागानकी मैंबीके लिये यह अगिवार्य है, कि चीन की गरफार मञ्चूकुओं की पृथक् व स्वतन्त्र राज्य के कम में गला को स्वीकार करे, और उससे बाकायदा वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित करे। (३) चीन ने कम्युनिज्य को नष्ट करने के कार्य में जागान चीनी सरनार की राहायता वारने की पूर्ण रूप से उद्यन रहे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि जापान नीन के साथ मैत्री संबंध को स्थापित करने के लिये तो इच्छुक था, पर उसकी मैत्री वह अभिप्राय यह था, कि चीन जापान की इच्छा के अनुसार चले, मञ्चूकुओं के रूप में उसकी नवातूंग रोगा ने जो पृथक राज्य स्थापित किया था, चीन उसे स्वीकृत कर ले और चीन की सरकारको अपने आधिक व सैनिक उत्कर्ष के लिये जिस विदेशी सहायता की आवश्यकता हो. उसे वह जापान से प्राप्त करे। पर इस समय चीन में राष्ट्रीय भावना भलीभांति किकसित हो चुकी थीं। कुओमिन्तांग दल के नेता अनुभव करते थे, कि जापान चीन में अपने साम्राज्यवाद का प्रसार करने को इच्छुक है। इसलिये वे जापान की अवेधा

अमेरिका, जर्मनी य इटली की सहायना को अधिक महत्त्व देने थे और राष्ट्रसंघ के सुहयोग से अपन देश की उन्नति के पक्ष में थे। इसके विपरीत जावान की यह इन्हा भी, कि जिन अर्थों में मध्यमुखों उसका वशवर्ती राज्य है, उसी प्रकार भीरे भीरे सम्पूर्ण कीन को अपने प्रभाव व प्रभूत्व में के आया जाय।

उत्तरी चीन में हस्तक्षेप-आस्पनार मंगोलिया को अपने प्रभृत्व में ले आने के बाद १९३५ की समालि से पूर्व ही जापानन उत्तरी चीनपर भी अपने आधिपत्य को स्थापित अरने के लियं प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। इस समय जापान चीन के जिन प्रदेशों को अपने प्रभाव में लाने के लियं तत्पर हुआ, वे निम्नलिखित थे-होपेडें (इसी प्रान्त को हम पहले निहली नाम में लिखते रहे हैं। कुओमिन्तांग सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके होपेडें कर दिया था), बात्वी और शांतुंग। इन तीन प्रान्तों में से होपेडें प्रांत (जिसकी उत्तरी मीमा मञ्चूकुओ राज्य के साथ लगता थी) पर १९३३ में ही आपान अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयत्न अस कर चुका था। मञ्चूतिया को अपने प्रभुत्व के स्थापित करने का प्रयत्न अस कर चुका था। मञ्चूतिया को अपने प्रभुत्व में लाने के बाद क्यातुंग सेना ने होपेडें की नरफ प्रस्थान किया था और २५ मई, १९३३ को इस प्रान्त के प्रमुत्व में किन लिएके प्रस्थान किया था और २५ मई, १९३३ को इस प्रान्त के प्रमुत्व में निम्नलिखित गमजीना नारने के लिये चीनी सरकार को विवय किया था---

- (१) होंगई प्रान्त के उत्तरी भाग में चीन अपनी सेनायें न रख सके ।
- (२) जापान को यह अधिकार हो, कि वह अपने हवाई जहाजों द्वारा इस बात का निरीक्षण कर सके, कि चीन की सनायें उत्तरी होंपेई में विद्यमान तो नहीं हैं।
- (३) जब जापान की यह भरोगा हो जाय, कि उत्तरी होपेई की चीनी सेवाओं ने खाली कर दिया है, नो वह स्वेच्छापूर्वम अपनी सेनाओं की चीन की विचाल दीवार के दक्षिणी प्रदेश से हटा ले।
- (४) उत्तरी होंगर में शान्ति और व्यवस्था स्थागित रखने का कार्य चीन की पृतीस के हाथों में रहे, गर उस पुत्रीस में ऐसे व्यक्ति न हों, जो जावान के विरोधी हों।

चीत और जापान का यह समझीता उतिहास में तन्गकू समझीते के नाम से अप्तिह है। यह रामजीता बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों कि इसके द्वारा उत्तरी चीत में जर्मान के प्रभाव व प्रभृत्व का सूत्रमात हुआ था। इसके अनुसार चीन के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह तीन्तित और पैक्तिगके उत्तरमें अपनी रोनाओं को रख सके। वद्यपि जापान ने भी इस समझौते के अनुनार उत्तरी होगेर के एन प्रदेश से अपनी रोनाओं को वापस जीटा छने की जान को स्तिकार किया था। पर

बोक्सर युद्ध के बाद जापान और चीन की जो सन्धि हुई थी, उसके अनुसार जापान को यह अधिकार था, कि वह पेकिंग और तीन्तिम में अपनी सेनायें रख सके और तन्त्व समझौते द्वारा उसने अपने इस अधिकार का परित्याभ नहीं कर दिया थाउँ। इसीलिये तन्गक समझौते के बाद भी जापान की सेनायें पेकिंग और तीनिसन के क्षेत्र में कायम रहीं और इन सेनाओं की मत्ता के कारण उसके लिये यह सर्वथा सुगम था, कि इस क्षेत्र में बह अपने प्रभाव में निरन्तर बढ़ि करता रह सके। जुलाई, १९३३ में जापान ने चीन को इस बात के लिये विवश किया, कि उत्तरी होपेई में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये जो पूलीस संगठित है, उसमें उन लोगों को भरती किया जाय, जो कि जापान के समर्थंक हो। १९३३ में तन्त्कु समझौते से पूर्व जब क्वांत्म सेना ने होपेई पर आक्रमण किया था, तो कतिपय चीनी सैनिकों ने इस आक्रमण में जापान की महायता की थी। अब जापान ने चीन की सरकार को इस बात के लिये विवश किया, कि इन देशब्रोही सैनिकों को उत्तरी होपेई की पूलीस में जगह दी जाय । इसका परिणाम यह हुआ, कि इस प्रदेश की पूर्लीस में उन लोगों का प्राधान्य हो गया, जो नीनी सरकार के विरोधी और जापान के पक्षपाती थे। जुलाई, १९३५ में इस प्रदेश के सम्बन्ध में जापान ने चीनी सरकार के साथ एक अन्य समझौता किया, जो हो उमत्सू समझौते 🕏 नाम से प्रसिद्ध हैं । इस समझौते की मुख्य शर्ते निम्निकिखित थी-(१) जो राजकर्म-चारी जापान के विरोधी है, उन्हें अपने पदों से पृथक कर दिया जाय। (२) इस प्रदेश में कुओमिन्तांग दल की शाखाओं को भंग कर दिया जाय। (३) जापान विरोधी जो भी कार्यवाही व प्रचार आदि इस प्रयंश में हो रहे है,

उनको बन्द किया जाय।

हो-उमेत्सू समझौते का यह परिणाम हुआ, कि होपेई प्रान्त के उत्तर के पेकिंग और तीन्तिसन के प्रदेश में जापान का प्रभूत्व व प्रभाव मलीभांति स्थापित हो गया । यद्यपि यह प्रदेश अब भी चीन का एक अंग था, और नानकिंग सरकार का शासन भी वहां विद्यमान था, पर फियात्मक दृष्टि से यह प्रदेश पूर्ण रूप से जापान के आधिपत्य में आ गया था। दिसम्बर, १९३५ में जापान ने इस प्रदेश की चीन में पृथक् करने के लिये और कदम बढ़ाया। उसने आन्दोलन श्रुक किया, कि उत्तरी चीन के प्रदेश नानिभिग सरकार की अधीनता से मुक्त होबार अपना पृथक व स्वतन्त्र राजि स्थापित करने के लिये उत्सक है। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ, कि १९३५ का अन्त होने से पूर्व ही उत्तरी होपेई का शासन करने के लिये एक 'स्वतन्त्र कौंसिल' की स्थापना हो गई। यह कौंसिल पूर्ण कृप से पेकिंग और

तीन्त्सिन में स्थित जापानी रोना के प्रभाव में थी, और उसी के इज़ारे पर अपने प्रदेश का भागन कार्य संचालित करती थी । उत्तरी होपेई की स्वतन्त्र कार्तिल ने जापानी सरकार के आदेशानुसार यह व्यवस्था की, कि उसके क्षेत्र में आनेवाले जापानी माछ गर तट-कर की मात्रा कम कर दी जाय। उस व्यवस्था के अनसार होगेई में विदेशी माल पर जो कर लगना था, जापान के लिये उसकी दर को घटाकर २५ फी सदी कर दिया गया । तट कर के सम्बन्ध में यह नीति जहां जापान के लियं अत्मन्त हितकर थी, वहां अन्य विदेशी राज्यों की इससे भारी नकसान था। अब उनके लिये यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वे जापान के मकाबले में अपने माल की उत्तरी चीन के इस प्रदेश में बेच सकें। साथ ही चीनी संस्कार की आमदनी पर भी इसका असर बहुत बुरा होता था। इतना ही नहीं, जापान के व्यापारी रियायती-कर देकर अपने माल को होपेई में ले जाते थे और और वहां से उसे उत्तरी चीन के अन्य प्रदेशों में पहुंचा देते थे। क्योंकि होपेई की गीमा अन्य प्रान्तों के साथ मिली हुई थी, अतः जापानी व्यापारियों को उनमें अपने माल को पहुंचाने में कोई भी कठिनाई नहीं होती थी। इसका परिणाम यह हुआ, कि उत्तरी चीन के विविध प्रान्तों के बाजार सस्ते जापानी माल से भ्राकृते हम मधे । अन्य विदेशी राज्यों के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि ने जापान के मुकाबले में अपने माल को उत्तरी चीन में बेच नकों। इस दशा से न केवल चीन की हानि थी, अपित जिटेन और अमेरिका आदि को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था । अमेरिका ने जापान की सरकार से इस मामले में शिकायत की और कहा कि जापान के साथ होपेई में रियायती कर की नीति का अनुसरण करना अत्यन्त अनुचित है। चीन में व्यापार के लिये सब देशों को समान अवसर रहेगा, इस बात की जापान स्वीकृत कर चका था। रियायती कर के कारण इसमें एकावट उत्पन्न होती थी। पर जापान ने अमेरिका की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं किया । अब उसने यह मांग पेश की, कि होपेई के समान चीन में अन्यन भी जापानी माल पर २५ प्रतिशत तट-कर लगना चाहिये।

होपेई को अपने प्रभाव में ले आने से जापान को यह भी अवसर मिला, कि वह चीन में अफीम व उससे निर्मित्त अन्य नवीली वस्तुओं का प्रचार करे। चीनी लोगों को अफीम का सेवन करने की आदत थी, और इस आदत के लिये मुख्य उत्तरियायिता ब्रिटिश लोगों के ऊपर थी। ब्रिटिश लोगों ने अपनी आर्थिक सामस्ती की वृद्धि के उद्देश्य से चीन में अफीम का प्रचार विष्य का श्री पर देंग के अफीम युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था। इस वृद्ध पर हम न्य प्रभाव में पहले प्रयान हाल चुके हैं। चीन की सरकार इस बात के लिये प्रयत्न गीन थी, कि अपने देश में

अफीम के प्रचार को कम किया जाय । इस सम्बन्ध में उसे आशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हुई थी। पर मञ्चूरिया और जहांछ के प्रदेशों पर जानान का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद अफीम के उत्पादन ओर उपयोग^णी असामारण रूप से वृद्धि होनं छगी। अफीम के व्यापार में आर्थिक छाभ बहुत अधिक था । जागान ने इसे खूब प्रोत्साहित किया । जहील का प्रदेश अफीम की खेती का बहत बड़ा केन्द्र था। यहा उत्पन्न हुई अफीम न केवल उत्तरी चीत में अपितु अन्यत्र भी बहुत बड़ी मात्रा में भेजी जाती थी। यह त्यापार म्ख्य-तया कोरियन लोगों के हाथों में था । मञ्चूकुओं में उत्पन्न हुई अफीम की कोरियन लोंग चीन में सर्वत्र ले जाते थे और उसकी बिकी में ख्व धन कमातेथं। अफीम से बननेवाली विविध नशीली वस्तुओं को तैयार करने के कारखाने जापानी लोगों ंद्रारा स्थापित ये। चीन की सरकार यदि कोरियन व्यापारियों को अफीम बेचते हुए पकड़ती थी, तो वह स्वयं उन्हें दण्ड नहीं दे सकती थी । कंश्रियन लोग जापान की प्रजा थे और एवस्टा-टैंप्टिनेरिएलिटी की पढ़ित का अभी तक भी चीन में पूर्णतया अन्त नहीं हुआ था । अनः चीन के अफीम कातून की तोड़ने गर कीरियन व्यापारियों पर जापानी अदालतों में मुकदमा चलता था और वहां उन्हें इतनी कम तजा मिलती थी, कि वे उसकी जरा भी परवाह नहीं करने थे। जब उत्तरी होंगेई भी जापान के प्रभुत्व में आ गया, तब तो अफीम के उस व्यापार में और भी अधिक वृद्धि हुई। जापान की सरकार ने स्वयं अपने देश में तो अफीम व उससे निभिन्न नशीली वस्तुओं के प्रयोग को राजश्वित द्वारा वस्त्र कर विमा था, पर जापानी लोग चीन में इन वस्तुओं के प्रचार के लिये प्रयत्तर्थाल थे, क्योंकि इनसे उन्हें भारी आधिक लाभ था। अफीम के अतिरिक्त कोकीन का भी वे चीन में प्रचार कर रहेथे।

जापान की सरवार केवल उत्तरी होपेई को ही अपने प्रभाव व प्रभूत्व में लाकर संतुष्ट नहीं हुई। वह बाहती थी, कि सम्पूर्ण होपेई, जान्सी और यांत्म प्रान्तों को भी अपने आविपत्य में ले आये। पर १९३७ तक उसने उसके लिये विशेष प्रयत्न नहीं किया। इसके दो कारण थे—(१) उत्तरी चीन के उन प्रान्तों की जनता पूर्ण रूप से चीनी थी। मंचूरिया, जहोल और मंगोलिया के समान इन प्रदेशों की जनता ऐसी नहीं थी, जिमे चीनी लोगों से भिन्न कहा जा गके। उन प्रान्ति के निवासी चीनी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भलीभांति विकसिन हो चुकी भूगें कुओमिन्तांग दल का उनपर बहुत अविक प्रभाव था। इस दशा में जापान के लिय् यह सम्भव नहीं था, कि उन्हें सुगमता से अपने प्रभाव में ला सके। सैन्यशित के प्रयोग द्वारा उन्हें अपने वश में लाया जा सकता था, पर सैन्यशित के प्रयोग

का परिणाम जीन के साथ बाकायदा युद्ध होता, जिसके लिये अभी जापान तैयार नहीं था। (२) चीन के इन प्रदेशों में अन्य विदेशी राज्यों ने भी अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे। चीन के साथ विविध समयों में अमेरिका, जिटन, फांस आदि देशों ने जो सन्धियों की थी, उनका उल्लेख हम इस इतिहास में पहले कर चुके हैं। इस सन्धियों के कारण इन प्रदेशों में इन राज्यों की अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस दशा में यदि जापान इन प्रदेशों में अपने प्रमुख को विस्तृत करने ना प्रयन्त करना, तो उसे इन राज्यों के साथ भी संघर्ष में आना पड़ता। जापान के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह विविध पाठचारय देशों के आधिक हितों व विशेषाधिकारों की सर्वथा उपेक्षा कर सकता। अतः वह संभलकर कदम बढ़ाना चाहता था।

चीन के लोग अपने देश में जापान के बढ़ते हुए प्रभृत्व में बहुत चिन्तित थे। १९३५ में चीन के नवयवकों और विद्यार्थियों ने पेकिंग में एक सभा की स्थापना की, जिसका उटेश्य जीन पर बढ़ते हुए जापानी प्रभाव का विरोध करना था। इसी प्रकार की सभायं चीन में अन्यत्र भी स्थापित हुई । चीनी सरकार ने भी इस समय जापान की उम नीति का विरोध किया, कि पूर्वी एशिया में शान्ति और व्यवस्था को कायम रम्पने की उत्तरदायिता केवल उसकी है। है। चीनी सरकार राष्ट्रसंघ पर बहुन विश्वास स्वती थी और उसका ख्याल था, कि इस अन्तर्षिट्टीय संगठन की सहायता से वह जापान की शक्ति का मुकाबला कर सकती है। पर राष्ट्रसंघ इस समय निरन्तर अशतन होता जाता था। अमेरिका पहले ही उससे पुथक् हो चुका था। बाद में जापान, जर्मनी और इटली भी उसमे पुथक् हो गये थे । चीनी सरकार ने अपनी रक्षा के लिये एक ऐसी संस्था पर भरोसा किया था, जो रुवयं निरन्तर अशवत होती जाती थी। इस समय जापान, जर्मनी और इटली तीन देश ऐसे थे, जो राष्ट्रसंघ की सर्वथा उपेक्षा कर शनित प्रयोग हारा अपने उत्कर्ण में तत्पर थे। १९३७ में जापान ने चीन में अपने प्रभूत्व की स्थापना के लियं पन: प्रयत्न प्रारम्भ किया, जिसके नारण चीन-जापान के यद्भ का प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध पर हम अगले अध्याय में प्रवाश हालेंगे।

सतरहवां अध्याय

चीन और जापान का युद्ध

(१) १९३७ में चीन की दशा

जुलाई, १९३७ में चीन ओर जापान का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। जापान जिस ्हंग से चीन में अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिये प्रयत्नशील था, उसका यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि इन दोनों देशों में बाकायदा युद्ध प्रारम्भ हो। जापान मञ्जूरिया और जहाँल के प्रदेशों को जीतकर उनमें मञ्जूकुओं राज्य की स्थापना कर चुका था। यह राज्य पूर्णतया जापान का वक्षवर्ती था। होपेई प्रान्त के उत्तरी भागमें भी जापान का अधिपत्य स्थापित था और सम्पूर्ण होपेई, शान्सी और शांत्ंग प्रान्तों में जापान की साम्राज्यवादी नीति निरंतर जोर पनन्ती जाती थी । इस दशा में चीन और जापान के युद्ध को देर तक स्थिगित गहीं निर्धा जा सकता था । १९३९ में जब यूरोप में बीसवीं सदी के दूसरे महायुद्ध का श्रीगणेश हुआ,तोपूर्वी एशिया में चीन-जापान का यह युद्ध अभी जारीया। महायुद्ध में जापान ने जर्मनी और इटली की फासिस्ट शक्तियों का साथ दिया और चीन ने बिटेन, फ्रांस और अमेरिकाका। इस दशामें चीन जापान का यह युद्ध १९३९-४५ के महायुद्ध का ही एक अंग बन गया । पर इससे पूर्व कि हम १९३७ में प्रारम्भ हुए चीन-जापान युद्ध पर प्रकाश डालें, यह आवश्यक है कि इस युद्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व चीन की राजनीतिक दशा क्या थी, इसको स्पष्ट किया जाय । चीन में मञ्चू शासन का अन्त हीकर किस प्रकार रिपब्लिक की स्थापना हुई और बाद में कुओमिन्तांग दल ने विस प्रकार नानकिंग को राजधानी बनावार देश में एक शक्ति-शाली केन्द्रीय शासन की स्थापना का उद्योग किया, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। पर नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकार का शासन सम्पूर्ण चीन में विद्यमान नहीं था। यद्यपि वह चीन की सबसे प्रवल सरवार थी, अन्तरां 🚉 राजनीति में उसी को स्वीकार किया जाता था और राष्ट्रसंघ में उसी के प्रति-निधि चीन का प्रतिनिधित्व करते थे, पर चीन के विविध प्रान्तों में अन्य भी अनेक सरकारों की सत्ता थी, जो या तो नानिका के प्रभुत्व को स्वीकार ही नहीं करती

श्री, और या कुओ मिन्तांग सरकार के अधिपति चियांग काई शेक के एकाधिगत्य के विद्यांग काई शेक के एकाधिगत्य के विद्या शि । इस प्रकरण में हम नीन की इसी राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे ।

चीन की विविध राजनीतिक शक्तियां-१९३३ में चीन की प्रधान राजनीतिक शक्तिया निम्निलिमित थीं-(१) नानिकग की कुओमिन्तांग सरकार-इसका अधिपति महासेनापति (जनग्लीसमी) चियांग काई शेक था । यह चीन की प्रधान सरकार थी और चीन के बड़े भाग पर इसका आधिपत्य था। (२) कैन्टन की वामपक्षी सरकार-यह भी कुओमिन्तांग दल की थी, पर डा० सन यात सेन द्वारा स्थापित कुओमिन्तांग दल की कार्यगीति के सम्बन्ध में इसके नेताओं का चियांग काई शंका के साथ मतभेद था। इसके प्रमुख नेता बाग चिंग वेई और चेन कृंग-गो थे । (३) गम्युनिस्ट सरकार-नियांगसी, आन्हई और फुनिएन प्रान्तों के अनेक प्रदेशों पर इस सरकार का अधिकार था । कम्यनिस्ट लोग कुओमिन्तांग दल की सरकार की मानन के लिये तैयार नहीं थे, और सम्पूर्ण चीन में समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार जासन व समाज संबंधी व्यवस्था स्थापित करने के पक्षपाती थे। चीन की कम्यनिस्ट पार्टी का प्रधान नेता माओ त्मेतुंग था। (४) उत्तरी चीन में पहले अनेव एं से सिपहमालारों की सत्ता थी, जो नाम को चीन की केन्द्रीय सरकार की अधीनता को स्वीकृत करते हुए भी कियात्मक दिष्ट से अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से शासन करने थे। इस प्रकार के सिपहसालारों में चांग हु सुएह-लियांग सर्वप्रधान था । इसका उल्लेख हम गहले अनेवा बार इस इतिहास में कर चुके हैं। पर मंचुरिया और जहोल में जापान का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण इन उत्तरी सिगहसालारों की शक्ति कम हो गई थी और ये नानिका सरकार के बशवर्ती हो गये थे।

१९३३ में चीन में ये विविध राजनीतिक शक्तियां विद्यमान थीं। पर कुओमिन्तांग दल की सरकार नानिक्य में इतने सुव्यवस्थित रूप से स्थापित ही चुकी थी, कि उसके लिये चीन की अस्य राजनीतिक शिवताों को अपने वस में ला सकता बहुत विदेश नहीं रह गया था। वित्यांग काई के का मुजीमिन्तांग दल राष्ट्रीय एकता को बहुत महत्त्व देता था। उसकी दृष्टि में लोकतन्त्रवाद का उद्धा महत्त्व नहीं था, जितना की चीन की राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय उन्नति का था। इसीलिये कुओमिन्तांग सरकार चीन में राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय उन्नति का था। इसीलिये कुओमिन्तांग सरकार चीन में राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय उन्नति का था। इसीलिये कुओमिन्तांग सरकार चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिये विशेष रूप से प्रयत्नवील थी। वस स्थानना से १९६३ है १९३६ तक जो यत्न उसने किया, उसका उन्लेख करना आवश्यक है।

कैल्टन की दासवाती सरकार-चीन के दिलाणी भाग में क्यांतूंग और न्यांगरी

प्रान्तों में कुओमिन्तांग दल के वामपक्षी नेताओं ने एक पृथक् सरकार की स्थापना की हुई थी, जिसकी राजधानी कैन्टन थी। कैन्टन की यह सरकार कम्पिन्स्ट नहीं थी, पर इसके नेता चियांग कार्ड शेक की दक्षिणपक्षी प्रवित्तयों 况 बिरोधी थे । इन नेताओं का विचार था, कि चियांग काई शेक डा॰ सन यात सन ह्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का भलीभांति अनुसरण नहीं कर रहा है। कुओमिन्तांग दल की नीति में इस प्रकार के परिवर्तन आवश्यक हैं, जिनका उद्देश्य न वेषिल चीन की राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि हो, अपित् साथ ही देश में लोकतन्त्र शामन का विकास व सर्वसाधारण जनता की आधिक उन्नति भी हो। क्यांगतग और क्यांगमी प्रान्तों की सेनाओं या सहयोग फैन्टन गरकार को प्राप्त था । क्यांगतंग प्रान्त के सिपहसालार चेन ची तांग की गैन्यजनित इस सरकार के साथ थी। कैन्टन सरकार का संचालन करने के लिये एक पृथक राजनीतिक कौसिल की सत्ता थी, जिसके प्रधान नेता कुआंमिन्तांग दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के भी सदस्य थे । ये प्रायः कुओं भिन्तांग दल की इस केन्द्रीय समिति के अधिवेशनों में राम्मिलित भी होते थे और चियांग वार्ड गेक के साथ अपने बिरोब को प्रकट करने में संकोच नहीं करते थे। १९३१ में जब जापान ने संचरिया पर अपने प्रभूटव का प्रसार शुरू किया, तो नानविष और कैन्टन की गरकाँ 🔭 (जिनके नेता कुओमिन्तांग दल के सदस्य थे) ने परमार मिलकर समझीता कर लिया, और नानकिंग की मरवार का मंचालन तीन व्यक्तियों की एक समिति के मुपूर्व कर दिया गया, जिसके सदस्य चिथांग काई शंक, बांग निग पेई और ह हान मिन थे। इनमें ने बांग चिंग पेई कैन्टनकी बामपक्षी सरकारका प्रधान नेता था । पर कुओमिन्तांग दल के वाम और दक्षिण पक्षों का यह सहयोग देर तक कायग नहीं रहा। बीघ्र ही उनमें फूट पड़ गई और वामपक्षी लोगों ने वांग चिंग पेई के नेतृत्व में कैन्ट्रन में अपनी पृथक् सरकार का पून: रांगठन कर दिया। पर कैन्ट्रन की यह मरकार नार्नाकर की केन्द्रीय मरकार के आधिपत्यको स्थीकृत करती थी और इसके नेता कुओमिल्तांग दलकी बेन्द्रीय वार्यकारिणी समिति के अधिवेलन में सम्मि-िलत हो बार यह यत्न भी करते रहते थे, कि चियांग कार्ड जेक के प्रभत्य के विरुद्ध आवाज उठाते रहें। इस प्रकार कैन्टन की सरवार यद्यपि क्रियात्मक दिए से अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र थी. तथापि नार्नाकंग की केन्द्रीय सरकार के साथ उपका सम्बन्ध कायम था।

नानिका और कैन्ट्रन की कुओमिन्नांग सरकारें जो आपस में मिळकर एक नहीं हो पानी थीं, उसका प्रधान कारण चियांग काई जेक का ब्यक्तित्य था। कुओमिन्तांग दळ में इस महासेनापित की शक्ति नियन्तर बहती जाती थी। उसका न केवल नानिका सरकार पर एकािबात्य था, अपितु साथ ही कुओमिन्तांग दल में भी उसकी रिशत अहितीय थी। दल के अन्य नेताओं के लिये उसका रिवरीय वर सकना किन था, वह स्वयं उस एजेण्डा को तय करता था, जिस पर दल की कार्यकारिणी समिति ने विभार करना होता था, दल के विविध प्रस्ताय भी उसकी इच्छान्यार ही स्वीकृत होते थे। चियांग वाई शेक की कुओमिन्तांग दल में प्रायः वही स्थित थी, जो कि जर्मनी के नाजी दल में हिटलर की था इटली के फैसिस्ट दल में गुसोलिनी की थी। यही कारण है, कि कैन्टन के वामपक्षी नेताओं की कुओमिन्तांग दल की वेन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में व दल की राष्ट्रीय महासभा में वोई भी मुन्धाई नहीं होती थी। कैन्टन के बाग चिंग वाई आदि वामपक्षी नेताओं को यह निर्थन प्रतीत होती थी। कैन्टन के बाग चिंग वाई आदि वामपक्षी नेताओं को यह निर्थन प्रतीत होता था, कि वे दल की विविध सभा सिमितियों में उपस्थित हों। इसीलिये १९३३ के बाद कुओमिन्तांग दल की राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन निरन्तर स्थितित होते गये और दल पर चियांग काई शेक का एकाधिपत्य स्थापित हो गया।

कैन्द्रन रारकार के नंताओं को नियांग काई शैक से एक अन्य शिकायत यह थी. कि उसने उत्तरी चीन में जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व की नष्ट करने के लिये क्षमचित उपायों का प्रयोग नहीं किया था। जिस प्रकार जापान ने मंच्रिया, जहोल और होपेई में अपने आधिपत्य को कायम कर लिया था, उसे कैन्टन के वाम-पक्षी नेता अत्यन्त चिन्ता की दृष्टि से देखते थे । उनका स्याल था, कि यदि जापान के प्रभाव के विकृत जनता में आन्दोलन किया जाय, और नियांग काई शेक ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया हुआ है, उसका विरोध किया जाय. तो मुओभिन्तांग दळ पर गहारानापति का जो अतुल्य प्रभाव है, उसे आघात पहं-भाया जा सकता है। कैन्टन की सरकार ने बील में जापान के बढ़ते हुए प्रभत्व के विरुद्ध न बेवल जनता में आन्दोलन ही किया, अपित १९३६ के प्रारम्भ में अपनी सेनाओं को भी जापान का मुकाबला करने के लिये तैयार किया । ववांगतुंग और क्वांग्सी की भेनाओं ने जापान के विरुद्ध छड़ाई करने के छिये उत्तरकी तरफ प्रस्थान किया और नानकिंग सरकार की सेनाओं को भी अपने उस प्रयत्न में सहयोग देने के लिये निमन्त्रित किया। पर चियांग काई शेक चीन की राष्ट्रीय एकता को अधिक महत्त्व देला था । जनकी दृष्टि में जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को रोकने की अपेक्षा भी कैन्टन सरकार के इस स्वच्छन्द आचरण का प्रतिरोध करना अधिक आवस्यक था । परिणाम यह उथा, कि उसने क्यांग्तुंग और क्यांग्री की रोनाओं का मुकाबला किया । ये सेनाएं परतन हो गई । आपाद को गरिन को नप्त जरने के लिये इन सेनाओं ने उत्तर की ओर अध्यक्त करने का हो उद्योग निया था। बह

निष्फल हो गया। चियांगकाई शेक कैन्टन की सेनाओं को परास्त करके ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसकी सेनाओं ने नवांग्तुंग पर भी आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। चियांग काई शेक स्वर्ध कैन्टन अाया और उसने वहां की सरकार के पृत्तः संगठन किया। क्वांग्तुंग के शासन सूत्र का संचालन करने के लिये ऐसे सैनिक व अन्य राजकर्मचारियों को नियत किया गया, जो चियांग काई शेक के पक्षपाती थे। सितम्बर, १९३६ में चियांग काई शेक ने क्वांग्ती के सेनापितयों के साथ भी समझौता कर लिया। इस प्रान्त को शासन के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वतन्त्र रखा गया, पर इसमें सन्देह नहीं कि १९३६ के अन्त तक कैन्टन सरकार अविकल रूप से नानिकंग सरकार के अधीन हो गई थी। ववांग्तुंग प्रान्त (जिसकी राजधानी कैन्टन थी) में ऐसी सरकार की स्थापना कर दी गई थी, जो पूर्ण रूप से चियांग काई शेक की वशवर्ती थी और क्वांग्सी प्रान्त की सरकार भी नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकार की अधीनता को मानने लगी थी।

इस प्रकार १९३६ तक दक्षिणी चीन को अपना वशवर्ती बनाने में चियांग-काई शेक को असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हो गई थी। वह चीन की जिस राज्ट्रीय एकता के लिये प्रयत्नशील था, उसकी स्थापना में इससे बहुत अधिक सहायता मिली थी।

कम्यनिस्ट सरकार के साथ संघर्ष-कैन्टन की सरकार बुओभिन्तांग दल के वामपक्ष की थीं, अतः नानिकंग रारकार के साथ उसका सम्बन्ध विद्यमान था। पर चीन में चियांग काई शेक की सबसे प्रवल विरोधी कम्युनिस्ट सरकार थी, जो किसी भी प्रकार चियांग काई शेक के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थी। १९२७ में जब बम्यनिस्ट लोग कुओमिन्तांग दल से पृथवा हो गये थे, ती उन्होंने चीन के अनेक प्रदेशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिया था। १९३१ में जनकी गृक्ति का प्रवान केन्द्र कियांगसी प्रान्त था। यह प्रान्त क्वांगतंग प्रान्त के उतर में स्थित है। इसमें कम्युनिस्ट लोगों ने अपनी बाकायदा रास्कार बनाई हुई थी और फुकिएन (कियांग्सी के पूर्व में), हुनान (कियांग्सी के पश्चिम में) व आन्हई (कियांगसी के उत्तर में) प्रान्तों के अनेक भागों में भी उनकी शक्ति भ्यापित थी । कियांगुसी की कम्युनिस्ट सरकार नानिकेग की कुओंपिन्तांग सरकार की सत्ता को स्वीकृत नहीं करती थी। और उसके हाथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखती थी। १९३२ में चीन की इस कम्युनिस्ट सरकार के अधीन प्रदेशों 🌉 क्षेत्रफल ३,३०,००० वर्गमील के लगभग था, और उसमें निवास करनेवाले लोगी की संख्या ९,००,००,००० से कम नहीं थी। इससे यह भलीभांति समझा जा सकता है, कि कम्युनिस्टों का चीन में प्रभाव कितना अधिक था। तीन लाख वग-

मील से भी अधिक विशाल प्रदेश में कम्युनिस्ट लोग रूस के ढंग की समाजवादी व्यवस्था को बायम कम्ने में तत्पर थे।

🤻 नियांग काई शेक कम्मुनिस्टों का प्रवल विरोधी था। वह चीन की राष्ट्रीय एकता के लिये यह आवश्यक रामझता था, कि कियांग्सी की कम्युनिस्ट सरकार को यद्ध द्वारा परास्त कर उस द्वारा अधिकृत प्रदेशों को नानकिंग की कुओमिन्तांग सरकार की अधीनता में ले आया जाय । उसकी दिष्ट में जापान का उत्तरी चीन में निरन्तर बढ़ता हुआ प्रभुत्व चीन के लिये उतना हानिकर नहीं था, जितनी कि कम्यनिस्ट सरकार की सत्ता चीन की राष्ट्रीय एकता के लिये विघातक थी। यही कारण है, कि उसने अपनी सैनिस शक्ति का प्रयोग जापान के विरुद्ध न करके कम्युनिस्टों के विरुद्ध किया । जिन दिनों जापानी लोग मञ्चूरिया, जहोल और होपेई में अपने प्रभूतव की स्थापना में तत्पर थे, नियांग काई शेक की सेनाएं कम्युनिस्टों के साथ युद्ध में व्यापृत थीं। १९३३ में महासेनापति चियांग काई शेक ने चार बार कियांगसी की कम्युनिस्ट सरकार पर आक्रमण किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। इस समय में कम्युनिस्ट लोग निरन्तर शक्ति प्राप्त नारते जाते थे। १९३३ के अन्त में ऐसा प्रतीत होता था, कि सम्पूर्ण कैकिएन प्रान्त कम्यनिस्ट लोगों के हाथ में चला जायगा। पर १९३४ में चियांग गाई शेक ने अपनी सम्पूर्ण सैनिक शक्ति को कम्युनिस्ट लोगों का विनाश करने के लिये लगा दिया। उसने याम्युनिस्टों के विरुद्ध अत्यन्त कूर व भयंकर उपायों का अवलम्बन किया । अब कम्युनिस्टों के लिये यह सम्भव नहीं रह गया, कि वे नानकिंग सरकार की शक्ति का मुकावला कर सकें। जिन प्रदेशों पर चियांग काई शेम की सेनाएं अपना अधिकार स्थापित कर लेती। थीं, उनके निवासियों पर वे भयंकर अत्याचार करती थीं। जिस आदमी पर कम्यनिस्ट होने का जरा भी सन्देह होता था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। १९३४ में लाखों व्यक्ति कुओमिन्तांग सेनाओं की क्रोधाग्नि के शिकार हुए। कम्युनिस्टों के विनाश के लिये चियांग काई शेक ने केवल अपनी सैन्यशिक्त का ही जगयोग नहीं किया, अपित अन्य भी अनेक साधन प्रयुक्त किये । इनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखिन थे-(१) फैसिस्ट ढंग पुर 'नीली कुड़ती' नाम से एए आतंकवादी दल का संगठन किया गया, िंग्रना उद्देश्य कुओमिन्तांग दल के विरोधियों का विनाश करना था। यह नीली कुड़ली (बल शर्ट) दल, जिन लोगों पर कम्युनिज्म के प्रति सहानुभूति रखने का सन्देह भी होता था, उन्हें मौत के घाट उतार वेने व उनकी गम्मिन की नष्ट कर देने में जरा भी संबोध नहीं करता था। (२) तुवां मिन्तांग सरभार

ही सेना में राजनीतिया शिक्षा का प्रचार किया गया। उसमें उन विचारों हो प्रसारित किया गया, जिनका प्रतिपादन कुओमिन्तांग दल द्वारा किया जाता मा । इसका परिणाम यह हुआ, कि चियांग काई शेक की सेना कम्युनिस्टों कें। रंग का गत्र समझने लगी । उसमें उन्हें तष्ट करने के लिये अद्भुत उत्साह का महार हुआ । (३) जिन प्रदेशों को नानिका सरकार कम्युनिस्टों से दिजय करती जाती थी, उनके पुराने जमीदारों व पूंजीपतियों को संगठित किया जाता या. ताकि वे कुओमिन्तांग दल की सहायता कर सकें। इन लोगों को कम्युनिस्ट मरकार द्वारा भारी नुकसान उठाना पड़ाथा, अतः स्वाभाविक रूप से इनकी सहानुभृति कुओ मिन्तांग दल के साथ थी। ये लोग कम्यनिस्टों का विनाश करने में नानिकिय मरकार की उत्साहपूर्वक सहायता करते थे। (४) चीन में एक नये आन्दोलन का सुत्रपात किया गया, जिसे 'नव जीवन आन्दोलन' कहते थे । इस आन्दोलन का उद्देश्य यह था, कि चीन के नवयुवकों में चीन के प्राचीन आदर्शी, व्यवहार, रीतिरिवाज व संस्थाओं के प्रति निष्ठा की भायना को उत्पन्न करे। अम्यनिस्ट लोग चीन में जिस व्यवस्था को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे, यह कालं मावसं व लेनिन के सिद्धान्तों पर आश्वित थी । यह व्यवस्था चीन के शिक्षित नवय्वकों को बहरा आकर्षक प्रतीत होती थी । कुओमिन्तांग दल ने नेताओं क्रिक्र यह अनुभव होता था, कि नवयुवकों को कम्युनिज्म के प्रति जो आन्नर्थण है, उसे दूर करने का सबसे उत्तम उपाययह हैं, कि उन्हें कन्पय्रियसआदि प्राचीन चीनी आचार्यों के सिद्धान्तों के प्रति आकृष्ट किया जाय, ताकि वे वाम्युनिज्य की एवा विदेशी सिद्धान्त समझकर उसके विरुद्ध हो जायें। चीन के नवजीवन आन्दोलन का पहीं प्रयान उद्देश्य था । इस अन्दोलन के नेताओं का विश्वास था, कि यदि चीन के नवयुवकों में अपने देश की प्राचीन विचारसंग्णी और सामाजिक मर्यादा के प्रति आस्था उत्पन्न कर दी जाय, तो वे कम्युनिज्य के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे।

चियांग काई शेक जिस ढंग से कम्युनिस्ट लोगों के विनाश के लिये तत्पर या, उससे अब यह सम्भव नहीं रहा था, कि कियांगसी प्रान्त व उसके समीपणतीं प्रदेशों पर अपने प्रभूत्व को कायम रख सकें। १९३४ के अन्त में उन्होंने अनुभव क्या, कि अब वे कुओमिन्तांग सेनाओं का सफलतापूर्वक म्काबना नहीं कर उकेंगे। पर वे यह भी जानते थे, कि चियांगकाई शेक उनके साथ विशी भी कार का समझौता करने की तैयार नहीं होगा। अब उनके सम्मुल केंकिंगों मार्ग थे, या तो वे नानकिंग सरकार की सेनाओं का मुकाबला वरने हुए अपने नीवन का अन्त कर देते और या कियांगसी प्रान्त को अन्ति। अन्ति का पुन संगठन करते। उन्होंने दूसरे मार्ग का सम्मुल कें का सम्मुल

निस्ट सेनाओं और अन्य कम्युनिस्ट लोगों ने इस समय कियांगरी के उत्तर की अोर 'महाप्रस्थान' शरू किया । चीन के उत्तर पश्चिम में एक प्रान्त है, जिसका नाम शंन्यी है। यह आभ्यन्तर मंगोलिया के दक्षिण और सिन्कियांग के एवं में स्थित है। अंग्जी पाल मंभी कम्यनिस्ट लोगों का जोर था। इस दक्षा में कियागरी। के कम्यानिस्टी ने वहीं उचित समझा, कि वे नियाग काई शेक की सेताओं का मुकाबका करने का प्रयत्न न कर उत्तर की ओर जेन्सी प्रान्त की तरफ प्रस्थान कर दे, ओर नहीं जाकर अपनी शक्ति का पुन:संगठन करें। इसके लिये उन्होंन उम पार्वत्य मार्ग का अवलम्बन विधा, जो चीन के पश्चिमी प्रदेशों में दर्गम पहाड़ों में से होकर ग्जरता था । उसी मार्ग का अनुसरण करके वे नात किंग सुरकार की सेनाओं से अपनी रक्षा कर सकते थे। कियांगसी से कस्यनिस्ट सेनायें पहले पश्चिम की ओर क्वेड्चाउ में गई। यहां से दक्षिण-पश्चिम की ओर युनान प्रान्त में जाकर फिर वे उत्तर की और रजेच्यान प्रान्त में गई और फिर पूर्वी तिब्बत व कान्यू होती हुई बेन्सी पहुंच गई। यह मार्ग बहुत विकट था, और इसमें उन्हें ६,०००मील के लगभग यात्रा करनी पड़ी थी। कम्युनिस्ट सेनाओं को जिस दुर्गम मार्ग से गुजरना पड़ा था, यहां न कोई सड़कों थीं और न ही निद्यों पर पुछ ही थे। इस दुर्गम पथ पर यात्रा करते हुए हजारों कम्युनिस्ट मार्ग के कप्टों द्वारा गृत्यु की प्राप्त हुए। एक साल से भी अधिक समय तक यात्रा के घोर कट उठाने हुए जो अम्युनिस्ट शेन्सी पहुंचने में समर्थ हुए, उनकी संख्या २०,००० के लगभग भी । १९३६ के बुरू तक कम्युनिस्ट लोग शेन्सी पहुंच गये थे और वहां येनान नगरी की राजधीनी बनाकर उन्होंने अपनी सरकार का पुनः संगठन कर लिया था। शेन्सी प्रान्त का उत्तरी भाग और कान्सू प्रान्त का उत्तर-पूर्वी भाग उनकी अधीनना में था। अपने इस राज्य में कम्युनिस्ट लोगों ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया और नियांग काई शंक की कुओमिन्तांग सरकार से लाहा लेने के लिये तैयारी शुरू की 1

करना चाहिये। १९३६ में कम्युनिस्ट सरकार के नेता माओ त्सेत्ंग ने अपनी पार्टी के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से प्रकट किया था-(१) विदेशी आकान्ता का मिलकर नकावला करना, (२) जनता को शासन सम्बन्धी अधिकार प्रदान करन ह और (३) देश की वाधिक उन्नति करना । पर चियांग काई शेक कम्युनिस्टों के साथ किसी भी प्रकार समझौता करना नहीं चाहता था। यह शेन्सी प्रान्त में भी उन्हें परास्त करके सम्पूर्ण चीन पर कुओमिन्तांग सरकार का शासन स्थापित करने के लिये कटिवद्ध था। जिस समय कम्युनिस्ट सेनाएं कियांगसी प्रान्त से उत्तर की ओर महाप्रस्थान कर रहीं थीं, चियांग काई शंक ने चीन के अन्य अनेक प्रान्तों पर भी अपना अधिपत्य कायम कर लिया था । जब सम्युनिस्ट लोग कियांग-सी से गहाप्रस्थान करते हुए क्वेईचाउ, युनान और रुजेच्वान प्रान्तों में गए, तो यहां के सिपहसालारों ने कम्य निस्टों से अपने प्रदेशों की रक्षा करने के लिये नानिका सरकार से सहायता की अभ्यर्थना की। यह सहायता इन प्रान्तों के सिपहसालारों को सहर्ष दी गई, पर इसके बदले में चियांग काई शेक ने इन पर अपने अधिकार की वहत दृढ़ कर लिया। १९३५ के अन्त तक यह अवस्था हो गई थी, कि सम्पूर्ण दक्षिणी और पश्चिमी चीन पर नानिकंग सरकार का शासन स्थापित हो गया था। क्वांगत्ंग और क्वांग्सू की वामपक्षी सरकार पर भी १९३६ में वियांग काई शेकि का प्रभुत्व कायम हो गया था । चीन की राष्ट्रीय एकता अब सम्पन्न ही होने वाली है, यह बात सबको स्पष्टद्षिटगोचरहोतीथी। विशाल चीन में केवल दो प्रदेशऐसे रह गयेथे, जो नानिकंग की कुओमिन्तांग सरकारके अधीन नहीं थे। उत्तरी चीन के मञ्चू रिया, जहोल और होपेई प्रान्तों पर जापान का प्रभुत्व था और आभ्यन्तर मंगोलिया का अच्छा बड़ा भाग भी जापान के प्रभाव में था। शैन्सी और कान्स पर कम्युनिस्टों का अधिकार था। चियांग काई शेक का खयाल था, कि जापान का मुकाबला करने के लिये यह आवश्यक है, कि पहले कम्युनिस्टों को परास्त किया जाय, ताकि चीन की राष्ट्रीय एकता पूर्ण हो जाय । जब सम्पूर्ण स्वतन्त्र चीन नानिका सरकार के अधीन ही जायगा, तो देश की आन्तरिक उन्नति द्वारा चीन को इतना समृद्ध व शक्तिशाली बनाया जा सकेगा, जिससे जापान के लिये उसमें अपने साम्राज्य को विस्तृत कर सकना सम्भव नहीं रहेगा। इसके विषरीत कम्युनिस्ट लोग चाहते बे, कि जापान चीन का सबसे बड़ा शत्रु हैं। उसका सफ्यूक पूर्वम मुकाबला तभी किया जा सकता है, जब कि चीन के विविध दल परस्पर मिलकर एक हो जावें और देश में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो, जो लोकतंत्र-वाद के सिद्धान्तों पर आश्रित हो। चियांग काई शेक और माओं त्सेतुंग के विचारों में इतना अधिक मेद था, कि उनमें समझौता हो सकना कियात्मक नहीं था।

चियांग काई श्रेक की गिरफ्तारी-इस दशा में चियांग काई शेव ने अपनी -भेतायें कम्यितस्टों पर आक्रमण करने के लिये भेजीं। इन सेनाओं का प्रधान सेना-पति चांग ह सएह-लिआंग को गियत किया गया। पर कम्युनिस्ट लोग अपने देशबन्धओं से नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने नांग हु सुएह-लिआंग की सेनाओं से कहा, कि चीनियों को आगस में छड़ने से क्या लाभ हैं। उन्हें तो चाहिये, कि वे मिलकर जापान का मुकाबला करें और उत्तरी चीन से जापान के प्रभटन को . नष्ट करें। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट नेता देशभिवत की भावना से आविष्ट थे। उन्हें यह व्यर्थ प्रतीत होता था, कि चीन की सेनाओं की शक्ति गृह युद्ध में नष्ट की जाय । यह स्वाभाविक था, कि चांग ह सुएह-लियांग की सेनाओं पर कम्युनिस्टों के प्रचार का असर पड़े । परिणाम यह हुआ, कि इन सेनाओं ने यह में कोई विशेष दिलचरिंग नहीं दिखाई। जो सेनायें कम्यनिस्टों का विनाश करने के लिये भेजी गई थीं, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई करने के स्थान पर मेल करना शुरू कर दिया। चांग हु गुएह-लिआंग व अन्य सेनापति भी कम्युनिस्ट प्रचार के प्रभाव में आ गये। जब यह बात चियांग काई शेक की जात हुई, तो ुडमने स्वयं शेन्सी प्रान्त की ओर प्रस्थान निया । उसने चाहा, कि ह् सुएह-लिआग की सेनायें पूर्ण शक्ति के साथ कम्युनिस्टों से युद्ध करें। पर उसे असफलता हुई । उसके रुख को देखकर चांग हु मुएह-लियांग ने अत्यन्त साहस का वार्य किया ! उसने चियांग काई शेष को गिरफ्तार कर लिया। वस्तुतः इस समय नानकिंग सरकार की सेना कम्युनिस्टों ये साथ यद्ध को जारी रखना इतना निरर्थक समझती। थी. कि उसके सेनापति ने चियांग काई शेक की गिरफ्तार तक करने में संकोच नहीं किया । चांग ह सएह-िल्यांग और उसके सहकारियों की यह इच्छा थी, कि कि वे विकाग काई शेवा को अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिये विवश करें। उनकी मूल्य मांगें निम्निलिखित थीं-(१) चीन में लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जाय। चीन सैनिक एकाधिकार (डिक्टेटरिक्स) की ओर बढ़ रहा है, यह बात उचित नहीं है। एकाधिकार का अन्त करके लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जानी चाहिये। (२) कम्युनिस्टों की इस बात को स्वीकार किया जाय, कि आपस की लड़ाई को बन्द शरके सम्मिलित रूप से जापान के साम्राज्यवाद मा मुनावला किया जाय। (३) जापान के साथ शीघ्र ही युद्ध शुरू किया जाय ।

पर चियांग काई श्रेक किसी भी प्रकार से इन वर्ती को मानने के लिये तैयार नहीं था। इन क्तीं को मानने का तो सवाल ही पैरा नहीं होता था, अयोंकि चियांग काई श्रेक उन लोगों से किसी प्रकार की बातकीत करने को ही तैयार नहीं

था. जिन्होंने कि उसे गिरफ्तार किया था । उसका कहना था, कि उसे गिरफ्तार करनेवाले सेनापनि चांग ह गुएह-लियांग आंग याग-चेंग उसके अवीनस्था नेनापिक भें । उनका कर्तव्य उसकी आजाओं का पालन करना है, उसके गाय समझीतां किरने के लिये शतें पेश करने का उन्हें कोई अविकार गई। है। यदि वे नार्विका संस्कार के विकत विदोह भएके उसे अपना कैदी समजल है, तो उन्हें पूरा अधिकार ही, कि वे या तो उसे जान से भार दें या उसके साथ जैसा चाहे यरताय करें। वियाग काई झेक की १२ दिसम्बर, १९३६ के दिन गिरफ्तार जिया गया था। रोगह दिन बाद २५ दिसम्बर को उसे कैद या नजरबन्दी में गस्त कर दिया गया। इस बीच में गदाम नियांग काई शेक अपने भाई श्री० टी० वी० मुंग के साथ शैन्सी आन्त की राजवानी सिआन (जहां कि नानकिंग सेना का हेडक्वार्टर था) पहुंच गई थी । इनकी प्रेरणा से चियांग काई शंक इस बात के लिये तैयार हो गया, कि नांग ह् सुएह-लिआंग ओर कम्युनिस्ट सेनापति चोच एन-लाई के साथ वातचीत भरे । पर उसने इन सेनापतियों के साथ किसी प्रकार का समझीता नहीं किया । इस बीच में चांग हु सूएह-लियांग को चियांग बाई शेक की डायरी पढ़नेका अवसर मिला। इस डायरी को पढ़कर उसे यह भलीभांति समझ में आ गया था. ंकि चियांग काई शेक वस्तुतः देशभक्त हैं, और उसका उद्देश्य चीन का हिंस करना 🖰 है। वह बीन की राष्ट्रीय एकता पर क्यों इतना अधिक जोर देना है, यह बात भी उसने मुचार रूप से समझ ली थी। उसी प्रकार कम्युनिस्ट नेता भी यह समजत थं, कि जावान के साथ संघर्ष करने के लिये चियांग काई शेक की उपयोगिता निविवाद है। उनका यह भी खयाल था, कि यवि इस महामेनापित को जनल कर दिया जायगा,तो चीन में इससे बहुत अधिक रोप फैलगा और अस्पृतिस्ट पार्टी बदनास झां जायगी । इसमें सन्देह नहीं, कि चीन में नियाग काई बोग की स्थिति बहुत कंची थीं । लोग उसे अपना राष्ट्रीय नेता गातते थे । इस दश में नांग ह्सुएह-लियांग व कम्युनिस्ट नेताओं ने यही उचित समझा, कि उसे मुक्त कर दिया जाय । नियांग काई शेक नानिकिंग वायस लीट आया और चांग हु सुगृह-लियांग भी उसके साथ नानकिंग गया। वहां उस पर विद्रोह के छिवे मुकदमा चलाया गया और उसे दण्ड भी दिया गया। पर यह दण्ड केवल निगन्त्रण को कायम रखने के लिये दिया गया था, और बाद में चियांग काई शेक के आदेश से उसे माफ कर दिस् गया था । इसमें सन्देह नहीं, कि सिआन की इस घटना ने नांग ह गुएह-िआंगी को एक बार फिर चियांग काई शेक का अनुरक्त सेनापति वना दिया था।

२५ दिसम्बर, १९३६ की जब चियांग काई शेक की कैद से रिहा कर विया भया, तो कम्युनिस्टों और नानकिंग सरकार में युद्ध का अन्त हो गया । इस समय

चीन का छोवमत गृह कलह को बन्द वार जापान वे साथ संघर्ष को सुरू करने के एक्ष में था। नियां कार्ड येक जैसे स्वन्छन्द व स्वेन्छाचारी सहासेनापति के ्रिये भी यह सम्भव नहीं था, कि वह लोकमत भी सर्वथा उपेक्षा कर सके । बाम्य-निस्ट लीग इस बात का प्रवल आन्दोलन नरने में तत्पर थे, कि चीन के विविध दलों की आपस के मनभंदों की भ्ला कर जागान के प्रभृत्व की नगर करने के लिये सम्मिलित रूप से प्रयत्न करमा नाहिये । परिणाम यह हुआ, कि कम्यृतिस्ट और कुओं भिस्तांग दलों में समझोते की तात शुरू हुई। यह बातचीन अभी समाप्त नहीं हुई थी. कि जुलाई १९३६ में चीन और जावान में युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस यद्ध के कारण पर हम अगले प्रकारण मे-प्रकाश डालेंगे । इस युद्ध में कम्युनिस्ट और कुआंभिन्नांग दलों की सम्मिखित शक्ति जापान का मुकाबला करने के लिये सम्रज्ञांथी । २५ दिसम्बर, १९३६ के बाद शेन्सी की कम्युनिस्ट सरकार और नानकिंग की मुओरिंग्लांग सरकार में संघर्ष का अन्त ही गया था और इन दीनों सरकारों में एक प्रकार की मुळह हो गई थी। इस प्रकार १९३७ में चीन-जागान के पृष्ठ के प्रारम्भ होने के रामय में चीन में दो पृथक सरकारें विद्यमान थीं । दोनों की अपनी अपनी पथक मेनायें श्री और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपने विचारों के अनुसार बासन और सामाजिक न्यवस्था के विकास में तत्वर थीं।

यहां यह भी निविध्य करना आवश्यक है, कि १९३७ में चीन के बड़े भाग पर नानिनेग की गुओमिन्नांग रारकार का शासन विद्यमान था। यह बात ध्यान देनं योग्य है, कि महांगनागति चियांग काई शेक की गिरफ्तारी के अवसर पर भी क्यांगरी, क्यांग्राम, हनान, क्वेडेनात आदि सुदूरस्थ प्रान्तों की रानाओं ने नानिकंग रारकार के मिलाक कोई विद्रोह नहीं किया । यह इस बात का स्पब्ट प्रमाण है, कि इस समय चीन में राष्ट्रीय एकता पर्याप्त अंशों में स्थापित हो गई थी। राष्ट्रीयता और देशमितकी भावना चीनमें बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी, और लोग अनुभव वारते थे, कि चीन में एक मुख्यवरियत केन्द्रीय सरकार का संगठन होता चाहिये। एक शांक्तशाली गृत्यवस्थित सरकार के लिये ही यह सम्भव हो सकता है, कि वह चीन में जायान की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति का सफलतापूर्वक मुकावला वर राके । इस समय चीन की जनता यह भी अनुभव करती थी, कि केंद्र-की केन्द्रीय व प्राक्तीय सरकारों को अविनय दंग में गृद्यवस्थित हुए पें संगठित करना चाहिये। जनता लोकतन्त्र पार या अगुरारण परयो चीन भी 'सरकार के पुन: संगठन के पक्ष में थी, पर जिलांग कार्र गंक की प्रवृति अब राज-यागित की अपने हाओं में रखने की थीं । इस दृष्टि व नह किटकर ओर मसीलिनी का समनक्ष था।

आर्थिक समस्या-चीन की सरकार के सम्मुख जहां राष्ट्रीय एकता की स्थापना और जापान के निरन्तर बढ़ते हुए प्रभुत्व था मुनाबला करने की महत्त्वपूर्ण राजनीतिक समस्यायें विद्यमान थीं, वहां साथ ही उसकी आर्थिक समस्या भी केंग्र महत्त्व की नहीं थी । चीन की राजकीय आमदनी निरन्तर कम होती जाती थी। इसके मख्य कारण निम्नलिखित थे-(१) मञ्चूरिया और जहाल के प्रान्त उसकी अधीनता से निकल गये थे। इनसे अब उसे कोई आभदनी नहीं होती थी।(२) होपेई की कींसिल ने जापान के आयात माल पर तट-कर की मात्रा घटाकर २५ प्रतिशत कर दी थी। इससे होगेई के मार्ग से जापानी माल बहुत बड़ी मात्रा में चीन आने लगा था। आयात माल पर तट-कर द्वारा जो आमदनी चीनी सरकार को होती थी. उसे इससे भारी आघात पहुंचा था। (३) चीन में इस समय अनेक नदियों में भयंकर बाढ़ें आई, और उनसे बहुत बड़े क्षेत्र की फसलें नष्ट हो गई। फसलों के विनाश से जहां राजकीय आमदनी में कमी आई, वहां साथ ही बाढ पीडितों की सहायता के लिये सरकार को भारी रकम खर्च करनी पड़ी। (४) १९२९-३३ के विश्वव्यापी अर्थसंकट का, जिसका उल्लेख हम इस इतिहास में पहले बार चुके हों, चीन की आधिक दशा पर भी बहुत बुरा असर हुआ। (🙆 आधिक संकट के कारण १९३४ में ब्रिटेन ने अपने सिक्के पींड का, जो पहले सुबर्ण पर आश्वित था, सुवर्ण से सम्बन्ध हटा दिया था । जून, १९३४ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अपने सिक्के डालर की कीमत को गिरा दिया। उसका परिणाम यह हुआ, कि पींड और डालर के बदले में सोने और चांदी की कीमतें बढ़ने लगीं। इस समय चीन का सिक्का चांदी पर आश्रित था, अनः चीन में चांदी सस्ती थी। इस कारण अमेरिका भारी परिमाण में चीन से चांदी खरीदने लगा और चीन की बहत सी चांदी विदेशों में जाने लग गईं। इस दशा में चीन के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह अपनी गुदा पद्धति को चांदी पर आश्रित रख सके। ४ नवम्बर, १९३५ को चीन ने भी विवश होकर अपने सिक्के और चांदी का सम्बन्धविच्छेद कर दिया। चीन के चार बड़े बैंगों को यह अधिकार दिया गया, कि वे पश्मदा जारी कर सर्वें जिस समय चीन की मुद्रापद्धति चांदी पर आश्रित थी, पत्रमदा उसी परिमाण में जारी की जा सकती थी, जितनी कि चांदी कोप में विद्यमान 🚵 नगगजी नोट के बदले में जब चाहें, तब चांदी ली जा सकती थी। पर अब चीन के कागजी नोट चांवी पर आश्रित नहीं रह गये। मुद्रापद्धति के चांदी पर आश्रित न रहने का यह परिणाय हुआ, कि चीन में बस्तुओं की कीमतें निरन्तर बढ़ने लगीं। जनता को इससे बहुत अधिक चल्ट का सामना मरना पड़ा। विदेशी व्यापारपर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा, और सरकारी आमदनी में कुमी आने लगी। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि अपनी मुद्रापद्धति को स्मालने के लिये इस समय चीनी सरकार ने जिन उपायों का आध्य लिया, उनका यहां उल्लेख कर सकें। इतना निर्देश करना ही पर्याप्त होगा, कि इस समय चीन की सरकार के राम्मुख आधिक समस्या भी अत्यन्त विकट रूप से विद्यमान थी और इसी कारण देश की उन्नति की विविध योजनाओं को पूर्ण कर सकना उसके लिये सुगम नहीं था।

(२) युद्ध का सूत्रपात

चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई थी। नानविंग की कुओमिन्तांग सरकार का शासन प्रायः सम्पूर्ण चीन पर विद्यमान था। उत्तर-पश्चिमी चीन की कम्यनिस्ट सरकार ने भी नानिकंग सरकार के साथ समझौता कर लिया था। चीन में जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई थी, उसका मूल कारण यह था, कि वहां के सब राजनीतिक दलों के नेता, प्रान्तीय सूबेदार और सेनापित यह अनुभव करने लगे थे, कि चीन में जापान जिस ढंग से अपने प्रभाव व प्रभुत्व का विस्तार कर रहा है, उसका मकावला किया जाना चाहिये। जापान के प्रति विरोध व विद्वेष की भावना चीन में निरन्तर प्रबल होती जाती थी। यही कारण है, कि अनेक देशभवत जापानियों पर हमले करने में भी तत्पर रहते थे। हैन्को में एक जापानी पुलीसमैन (जो उस नगर में स्थापित जापानी कान्सलेट की सर्विस में था) की हत्या कर दी गई थी। स्वेतो नगर में एक जापानी रेस्तरां में एक बम्ब मिला था, जिसे सम्भवतः किसी चीनी देशभक्त ने वहां रख दिया था। पैकिंग से कुछ दुरीपर फेंगताई में एक जापानी आफिसरपर हमला कर दिया गया था। इसी प्रकार की अन्य अनेक घटनाएं चीन के विविध नगरों में होती रहती थीं, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रभाग है, विर चीनी लोगों में जापानियों के प्रति विद्रेष की गात्रा किस हर तक पहंच गई थी।

इस दशा में चीन और जागान में किसी भी छोटी सी घटना को लेकर कुशई शुरू हो सकती थी। दोनों देश लड़ाई के लिये तैयार थे। जागान चीन में अपने प्रभुत्व को और अधिक तिस्तृत करना चाहता था। दूसरी तरफ चीन की जनता में राष्ट्रीयता की भागता बहुत प्रवल थी जीर चीन की कुशोधिनांग प कम्युनिस्ट सरकार परस्पर मिलकर जागान का मधावला करने के लिये तत्पर थीं। आखिर, ७ जुलाई १९३० को वह पटना घटना हुई, जिसने नामदनाने में चिनगारी का काम किया और चीन तथा जापान की विद्वेपानि को युद्ध के रूप में प्रजवस्तित कर दिया।

लुक्जियाओं की घटना-जिस घटना द्वारा चीत और जागान के युद्ध की थींगणेश हुआ, वह लुक्तिआओं में घटित हुई थी । यह स्थान पेकिम क ममीप है, आर यहां जावार्या नेना छड़ाई का अभ्यास करने में तलार थी। अधिसर यह के बाद अन्य राज्यों के साथ चीन ने जी सन्धियों की थीं, उनके जनगार जापान की यह अधिकार प्राप्त था, कि वह वैकिंग और तीन्तिम में अपनी सेनायें रख सके। इसकिये जापान की एक मेना पेकिंग में विधनान थी और यह यह का अभ्यास करने के छिये लुकुचिआओं को प्रयुक्त कर रही थी । १९३५ में पेकिंग में म्थित जागानी राना की संख्या बहन बढ़ा दी गई थी । यह बात विवादगस्त है, कि क्या पूरानी सिन्धियों के आधार पर जापान को यह अधिकार था, कि वह सैनिक अभ्यास के लिये लुकुचिआओं को प्रयुक्त कर सके। ७ जुलाई, १९३७ को चीनी गिगाहियों और ल्क्चिआओ में विद्यमान जागानी सैनिकों में गोली चल गई। इसके लिये कीन उत्तरादायी था, यह निरिचत कर सकना 'बहुत कठिन हैं। जापानी लोगों का कथन हैं, कि गोलाबारी का प्रारम्भ नीती सैनिकों ने किया था और चीनी लोग इसके लिये जापानी सैनिकों की दोली ठहराते हैं। दोग चाहे किसी का हो, पर यह स्पष्ट है कि ल्क्निआओं की इस घटना ने बहुत गम्भीर रूप घारण कर लिया । इसके कारण चीन ओर जापान के सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये। तीन सप्ताह तथ दोनों देशों की रापकारों में समर्पात ंकी वातचीत जारी रही । जापान की मांग थी, कि पैकिंग तीन्टिसन के क्षंत्र से चीनी सेनायें हटा ली जावें । इससे पूर्व उत्तरी होपेई से चीनी सेनायें एटाली जा 'चकी थीं, अब जापान चाहता था कि दक्षिणी होपेई (पेकिंग और तील्सिन दक्षिणी होपेई के ही नगर हैं) को भी चीनी सेनाओं से खाली कर दिया जाय। ंचीन की सरकार जापान की उस मांगको स्वक्षित करने के लिये तैयार नहीं थी। परिणाम यह हआ, कि बोनों देशों में यह प्रारम्भ हो गया।

कम्युनिस्टों से समझौता—हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं, कि २५ दिसम्बर, १९३६ के बाद कुओिमनांग सरवार और कम्युनिस्टों में लड़ाई बन्द होंगई थी और उन्होंने समझौते की बात शुरू कर दी थी। कम्युनिस्ट लेक्ट्रिंग हकलह के विषद्ध थे और देश की सम्पूर्ण शक्ति को जापान के विषद्ध युद्ध में लगी देने के लिये उत्सुक थे। लुकुनिआओं की घटना के बाद जब चीन और जापान में युद्ध की सम्भावना विलकुल प्रत्यक्ष होंगई,तो चियांग काई शेंकने भी अनुभव किया कि कम्युनिस्टों के साथ सुलह कर लेने में ही चीन का लाभ है। इस स्थित में

दोनों वर्लों में परस्पर समझौता होने में देर नहीं लगी। इस समझौते की मुख्य शह निम्नलिखित थीं—(१) जलर पश्चिमी चीन के जिन प्रदेशों (शैन्सी और कृतिम्) पर कम्युनिस्टों का अधिकार है, वहां उनका शासन कायम रहे। (२) उन प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का अधिकार है, वहां उनका शासन कायम रहे। (२) उन प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का अपना स्वतन्त्र व पृथक राज्य रहे, जो चीन के अन्वर्गत रहता हुआ भी शासन की दृष्टि से कम्युनिस्टों के अधीन हो। (३) कम्युनिस्ट सेना को चीन की राष्ट्रीय सेना का ही एक अंग मान लिया जाय और कम्युनिस्ट सेनापित जापान के साथ युद्ध करते हुए महासेनापित चियांग काई शेक के आश्चेशों का पालन करे। चीन के आधुनिक इतिहास में कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारों का यह समझौता अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कारण जापान के साथ संघर्ष के बाल में कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में सिद्धानों और विचार घारा में गौलिक भेद होते हुए भी परस्पर समझौता हो गया था और ये एक साथ मिलकर जापान का मुकाबला कर सकते में तत्पर हो गई थी। कम्युनिस्ट सेना को चीन की राष्ट्रीय सेना में 'आठवीं सेना' नाम दें दिया गया था और यह भी महासेनापित चियांग काई शेक थी आझानुवर्तिनी वन गई थी।

(३) युद्ध का इतिवृत्त

बीच में बीसवीं सदी का द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) प्रारम्भ हो गया और जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया की विजय में प्रवृत्त हुआ। रूस, अमेरिका और ब्रिटेन चीन की सहायता में तत्पर रहे और इन शक्तिशाली देशों से सहायकी प्राप्त कर चीन की कम्युनिस्ट और कुओमिन्तांग सरकारें जापान के साथ संघर्ष में व्यापृत रहीं।

उत्तरी चीन और नानिकंग पर जापान का प्रभुत्व-युद्ध श्रक्ष होते ही २७ जुलाई, १९३७ को जापानी रोनाओं ने पेकिंग पर कब्जा कर लिया । पेकिंग होवेई प्रान्त की राजधानी था और उसे जीत लेने पर सम्पूर्ण होपेई प्रान्त जापान के अधीन हो गया। इसके बाद जापानी सेनाओंने चहर और सुईयुआन प्रान्तों पर आक्रमण किया और उन्हें जीत लिया। ये प्रान्त आभ्यन्तर मंगोलिया के अंग वे और ये पहले भी जापान के प्रभाव क्षेत्र में थे। पर अब उनमें जापानी रोतावें प्रविब्ट हो गईं, और वे पूरी तरह से जापान की अधीनता में आ गये। चहर और स्ईयुआन पर कब्जा करने के बाद जापानी सेनाओं ने शान्सी प्रान्त पर आक्रमण किया । यह प्रान्त होपेई के पश्चिम और शेन्सी प्रान्त के पूर्व में स्थित है । शेन्सी कम्युनिस्ट सरकार के अधीन था, अतः शान्सी पर आक्रमण वरनेवाली जापानी सेनाओं का कम्युनिस्ट सेनाओं ने डट कर मुकाबला किया । कम्युनिस्टी 📸 कारण जापानी लोग शान्सी के पश्चिमी प्रदेशों को अपने अधिकार में नहीं ली सके । इस प्रकार युद्ध के शुरू होने के कुछ बिन बाद तक जापान ने होपेई, चहर, स्ईयुआत और पूर्वी शान्सी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अपने नये जीते हुए प्रदेशों का शासन करने के लिये जापान ने दो गई संरकारों का संगठन किया। २९ अक्टूबर, १९३७ को 'मंगोलिया की स्वतन्त्र सरकार' संगठित की गई और चहर व सुईयुआन प्रान्तों का शासन इसके सुपूर्व कर विधा गया। इसी प्रकार १४ दिसम्बर, १९३७ को पेकिंग में एक पथक सरकार संगठित की गई और होपेई प्रान्त व शान्सी प्रान्त के पूर्वी प्रदेश इस पेकिंग सरकार के अधीन कर दिये गये । पेलिंग सरकार का प्रधान वांग केह-मिन को निग्वत किया गया, जो कि कुओमिन्तांग दल के उत्कर्ष से पूर्व पेकिंग सरकार का अर्थमन्त्री रह चुका था। इन विजित प्रदेशों के शासन के लिये जो नई सरकारें संगठित की गई थीं; उनके प्रमुख राजकर्मचारी चीनी लोग थे, जो कि जापानी सलाहकारों के परामर्श के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में शासन करते थे।

मंगोलिया, होपेर्ड और पूर्वी शान्सी प्रान्त को अपने अधीन करने के साथ-साथ जापानियों ने चीन के समुद्रतट पर भी आक्रमण किया । नवम्बर, १९३७ में एक शक्तिशाली जापानी सेना ने समुद्रमार्ग द्वारा शंघाई पर हमला किया । वियाग काई शंक की सेनाओं ने यहां डटकर जापानी आक्रमण का मुकावला किया। पर चीन के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह जापानी आक्रमण को रोक सके। नक्ष्मिय सास के समाप्त होने से पूर्व ही चीनी सेनाओं ने शंघाई खाली कर दिया और उस पर जापान का कब्जा हो गया। शंघाई को जीत लेने के बाद नानिका पर आक्रमण कर सकना अधिक किन नहीं था। नानिका के युद्ध में भी चीनी सेनायें परास्त हुई, और १५ दिसम्बर, १९३७ के दिन जापान ने नानिका पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नानिका चीन की कुओमिन्तांग सरकार की राजधानी था। जापानी सेनाओं के प्रवेश में पूर्व ही नियांग काई शंक ने वहां से अपनी सरकार को हटा लिया था और सरकार के सब कार्यालय हैन्को पहुंचा दिये गये थे। नानिका में जापानी सेनाओं ने जनता पर बहुत मयंकर अत्याचार किये। सेना द्वारा इस समृद्ध य वैभवशाली नगर को बुरी तरह से लूटा गया। इस लूट के विशव बृत्तान्त युरोप, और अमेरिका के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, और इनको पढ़ कर पारचात्य संसार का लोकमत जापान के बहुत अधिक विरुद्ध हो गया।

हैंग्को और कैन्टन की विजय-उत्तरी चीन, शंघाई और नानिकण पर कब्जा कर लेने के बाद जापानने चीन के एक अच्छे बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कुछ लिया था। जापान सम्भवतः चीन में इससे अधिक आगे नहीं बढ़ना चाहता था। जिस प्रकार १९३१ में उसने मञ्चूकुओ में अपने वशवर्ती एक नये राज्य की स्थापना कर ली थी, उसी प्रकार शायद वह इन प्रदेशों में भी ऐसे एक या अधिक राज्य स्थापित कर देना चाहता था, जो मञ्चूकुओ के समान ही उसके वशवर्ती हों और जिनका चीन के साथ कोई सम्बन्ध न रहे। इस समय वह चीन में इससे अधिक आगे बढ़ने के लिये इच्छुक नहीं था। पर चीन में राष्ट्रीयता की भावना इतनी अधिक प्रवल हो चुकी थी, कि चीन का लोकमत अपने 'मध्यदेश' में एक विदेशी शक्ति के प्रभुत्व को किसी भी रूप में सहने के लिये तैयार नहीं था। यही कारण है, जो नानिकण की विजय के साथ चीन-जापान के युद्ध की समाप्ति नहीं हो गई। अब जापान के सम्मुख केवल एक ही मार्ग था, वह यह कि वह सम्पूर्ण चीन को अपनी अधीनता में ले आने के लिये संघर्ष को जारी रखे, अन्यथा चीन में उसकी स्थित सुरक्षित नहीं रह सकती थी।

चीन की कुओमिन्तांग सरकार की नई राजधानी हैन्को थी। अतः जापानी किन्नुओं ने उसकी ओर आगे बढ़ना घुछ किया। हैन्को पर यह आक्रमण दो तरफ से किया गया। नानकिंग की अपनी केनाओं ने पूर्व की ओर से और पैकिंग की उत्तरी सेनाओं ने उत्तर की आर के हिन्छों की तरफ प्रस्थान किया। इस समय शांसुंग प्राप्त का सुबेदार हान कु-पूथा। असे नाहिये था, कि यह पैकिंग से दक्षिण

की ओर बढ़ती हुई जानानी बेनाओं का डटकर मुकावला करता । पर उसने अपने कार्य में शिथिलता प्रविधित की । परिणाम यह हुआ, कि पेकिंग की सेनाओं ने शांतुंग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हान चू-फू पर कर्तव्य पिक्तिन करने के लिये मुकदमा चलाया गया और उसे प्राणदण्य दिया गया। जिस समय पेकिंग की उत्तरी सेनायें और नार्नाक्रम की सेनायें हैन्कों की और आगे बढ़ने में तरपर थी, उसी समय समुद्री मार्ग से जापान की एक अन्य मेना केल्टन पर भी आक्रमण कर रही थी। १७ अक्टूबर, १९३८ को इसने केल्टन पर कब्जा कर लिया। २१ अक्टूबर, १९३८ को हैन्कों भी जीत लिया गया और चीन की सरकार अपनी इस राजधानी को छोड़कर चुंगिकंग चले जाने को विवश हुई। हैन्कों को जीतने में जापान को जो इसना अधिक समय लगा, उसमें चीनी सेनाओं का प्रतिरोध जहां महत्त्वपूर्ण कारण था, वहां साथ ही परिचमी चीन की दुर्गनता भी इसमें कारण थी।

नानिका की नई सरकार-जब हैको के समीप जापान की मेनायें पहुंच गई। तो अनेक चीनी नेता इस पक्ष में थे, कि जापान के साथ यह को जारी रखना व्यर्थ है। उनकी दृष्टि में अब वह समय आ गया था, जब कि जापान के साथ समझीता करने में ही देश का हित था। इस वल का नेना बांग चिंग वेर्ड की पर चियांग काई शेक व अन्य चीनी नेता जायान के साथ यह की जारी रखने के पक्ष में थे। परिणाम यह हुआ, विः वांग चिग वेई व उसके अनयायी कुओमिन्तांग सरकार से पथक हो गये। चियांग काई शेक व उसके पक्षपातियों ने उन्हें देशदोही घोजित किया । इस समय जापान की ओर से यह घोषणा लगट शब्दों में की जा रही थी, कि हैन्कों को जीत लेने के बाद उनकी सेनाओं का कार्य समाप्त ही जायगा और जापान यह प्रयत्न करेगा कि जिन प्रदेशों को कुओिमन्तांग सरकार की अधीनता से स्वतन्त्र वार दिया गया है, उनमें ऐसी चीनी सरकार की स्थापना की जाय, जी जापान की अपना शत्र न समझकर उसके साथ सहयोग करके देश की उक्सति में तत्पर हो । पूर्वी एशिया में जापान और चीन दो ही प्रमुख राज्य हैं, और जनमें विरोध भावता एकिया के जत्कर्ष के लिये हानिकारक है । अतः पूर्वी एशिया में चिरशान्ति की स्थापना के लिये यह आवश्यक है, कि चीन की सरकार जापान के साथ मैत्री सम्बन्ध रखे। जापान का उद्देश्य चीन में अपना प्रभूत्व स्थापित करना नहीं है, वह उसका सहयोगी व भित्र बनकर रहना चाहना है। वांग कि वेडी जापान की इस नीति से बहुत प्रभावित हुआ और उसने नावविंग में एक नई चीनी संरकार को संगठित करना स्वीकार वार लिया। वांग चिंग वेई द्वारा स्थापित इस नानविंग सरकार पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे ।

चीन के दो विभाग-हैन्कों के गतन के बाद चीन दो भागों में विभवत हो गया-(१) स्वतन्त्र चीन और (२) जापान द्वारा अधिकृत चीन । उत्तर में पेविधा र्केश रू भर मध्य में हैनको होती हुई दक्षिण में कैन्टन तक यदिएक रेखा खींची जाय, तो इस रेखा के पश्चिमी प्रदेश 'स्वतन्त्र चीन' थे और इस रेखा से पूर्व की ओर के प्रदेश जापान द्वारा अधिकृत थे। स्वतन्त्र चीन के भी दो विभाग थे। कुओमिन्तांग सरवार की राजधानी चुंकांकिंग थी और अम्युनिस्ट सरकार की येनान (उत्तरी क्षोन्सी प्रान्त में) । १९३९ के बाद इन दोनों स्वतन्त्र चीनी सरकारों में सहयोग की भावना निरन्तर सम होती गई। चीन के पूर्वी प्रदेशों पर जापान का आधि-पत्य स्थापित हो चवा था और स्वतन्त्र चीनकी इन दोनों सरकारों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे जापान को चीन से बाहर निकाल सकें। इस दशा में उनमें परस्पर विद्वेष पूनः जागत होने लगा था। इस विद्वेश का एक कारण यह भी था, कि इस समय स्वतन्त्र चीन का वाह्य संसार से राम्द्र मार्ग द्वारा कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। उत्तर पश्चिमी चीन में जो नाम्यनिस्ट सरकार स्थापित थी, उसके लिये स्थल मार्ग द्वारा रूस के साथ सम्बन्ध कायम रख सवाता अधिक सुगम था। वह रूस से अंस्त्र-शस्त्र आदि की सहायता अधिक सुगमता से प्राप्त कर सकती। ंजी। इसके विपरीत चुंगिकम में स्थापित कुओमिन्तांग सरकार के लिये पाश्चात्य देशों सेसहायता प्राप्त करने के केवल तीन मार्ग थे-(१) फेंड्च इंडोचायना से फेंच मुनान रेलवे द्वारा और फिर मोटर रोड से होकर चुंगिकिंग को युद्ध सामग्री पहुंचाई जा सकती थी, यह मार्ग सुगम था, पर इसकी सफलता इस बात पर निर्मर थी, कि फांस किस हद तक चुंगिका सरकार की सहायता करने की तैयार है। (२) बरमा के उत्तरी मार्गी द्वारा स्वतन्त्र चीन की सहायला पहुंचाई जा सकती थी। पर ये मार्ग अभी भली भांति विकसित नहीं हुए थे। महायुद्ध के दौरान में ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों ने उत्तरी बरगामें मोटर रोडका निर्माण इसी उद्देश्य से किया था, ताबि जापान के विरुद्ध कुओमिन्तांग सरकार की सहायता की जा सके। (३) हांगकांग से वायुयानों द्वारा भी नुंगिकम युद्ध सामग्री भेजी जा सकती थी। महायुद्ध के समय पर ब्रिटेन और अमेरिका आदि ने इसी मार्ग. का आश्रय लेकार चुंगिवाग सरकार की मदद करने का प्रयत्न किया था। पर बा्युयानों द्वारा प्रचुर परिमाण में स्वतन्त्र चीन को सहायता पहुंचा सकता सम्भव नहीं था। क्योंकि कुओमिन्तांग सरकार वा पाइवात्य देशों के साथ सम्पर्क बहुत सम रह गया था, अतः जापान का एकावलः गरने के लिये उसकी शितत निरन्तर क्षीण होती जाती थी । इसके विभन्नित ज्या से सहानता प्राप्त करने की सुविधा होते के कारण मेनान की कम्पुनिस्ट सरकार अपने को जतना असहाय

अनुभव नहीं करती थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था, शि चियांग गाई शेक की सरकार कम्युनिस्टों से ईषा करने लगे और उसे यह मय हो, कि कहीं अम्युनिस्ट लोग इतने प्रवल न हो जावें, कि वे सम्पूर्ण चीन में समाजवादी व्यवस्था की स्थापनि का स्वप्न लेने लगें।

ग्रीला युद्ध-चीन के जो प्रदेश जापान हारा अधिकृत थे, उनमें इस प्रकार की सरकारें स्थापित हो गई थीं, जो ऊपर से देखने में पूर्णतया चीन की अपनी मरकारें थीं । मंगोलिया की स्वतन्त्र सरकार का उल्लेख हग पहले कर चके हैं। मञ्जूकुओ के समान मंगोलिया के चहर और सुईयुआन प्रान्तों में भी एक पुथक व स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर दिया गया था। पेकिंग को राजधानी बनाकर उत्तरी चीन में और नानिकंग को राजधानी बना कर दक्षिणी चीन में दी पृथक् राज्य कायम हुए थे, जिनका शासन चीनी लोगों के ही हाथों में था । पर मञ्चूकों के समान पेकिंग और नानिकंग के राज्य भी जापान के वशवर्ती थे । इस दशा में यह सर्वधा स्वाभाविक था, कि इन राज्यों में निवास करनेवाले राज्द्रवादी देशभक्त लोग जापान की कठपूतली के समान आचरण करने वाली पेकिंग व नानिका , की सरकारों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये तत्तर हों। उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे सम्मुख युद्ध में जापान का मुकाबला कर सकें, अतः उन्होंने गुरीहा युद्ध नीति का आश्रय लिया । देशभवत चीनी लोगों के अनेवा गिरोह जापान की सेनाओं पर आक्रमण करने लगे और उन्होंने ऐसी परिस्थित उत्पन्न कर दीं, जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी चीन में जापानियों की स्थिति बहुत असक्षत सी हो गई।

युद्ध की प्रगति—हैन्कों के पतन के बाद जापानी छोग चीन में युद्ध को समाफ कर देना चाहते थे। उनका खयाछ था, कि अपनी निरन्तर पराजयों के कारण चीनी छोगों को यह अनुभव करने में कठिनाई नहीं होगी, कि युद्ध को जारी रखना क्यर्थ हैं, और वे सन्धि के लिये तैयार हो जायेंगे। पर उन्हें निराशा का सामा करना पड़ा। महासेनापित चियांग काई क्षेक ने यही निश्चय किया, कि जापान के साथ संघर्ष को जारी रखा जाय। परिणाम यह हुआ, कि जापान ने भी हैन्तों से आगे बढ़ना शुरू किया। नवम्बर, १९३८ में योचोपर जापानी सेनाओं का कब्ज हो गया और उसके कुछ मास बाद इचांग जापान की अधीनता में चला गया। मार्च, १९३९ में कियांगसी प्रान्त की राजधानी नानचांग जापानियों के कियां में चली गई और नवम्बर, १९३९ में जापानी सेनाओं ने पेखोई के बन्दरगाह की जीत लिया। यह बन्दरगाह कैन्टन के दक्षिण में स्थित है। पेखोई के बाद नानिंग पर आक्रमण किया गया। नानिंग क्वांग्सी प्रान्त में हैं, जो

चीन का सबसे दक्षिणी प्रान्त हैं. और जो इन्छोचायना की उत्तरी सीमा पर स्थित है। नानिम पर कब्जा करने में जापान का यह उद्देश्य था, कि फेंच इन्छोचायना की मार्ग से स्वतन्त्र चीन की युद्ध सामग्री भेज गकना सम्मव न रहे। वायुथानों की रृष्टि में चीन की अवित जापान के सम्मृष्य अगण्य थी। अतः जापान की बायु सेना स्वतन्त्र चीन के नगरों व व्यवसाय केन्द्रो पर स्वेच्छापूर्वक आक्रमण करती रह सकती थी। चुर्माकम सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह जापान के हवाई हमलों को किसी भी प्रकार रोक सके। १९३९ में यूरोप में बीसवीं सबी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया था। पाइचात्य देशों के लियं यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे पूर्वी एशिया के मामलों पर ध्यान दे सकें। यह सम्भव नहीं रहा था, कि वे पूर्वी एशिया के मामलों पर ध्यान दे सकें। यह स्थिति जापान के लिये बहुत अनुकूल थी। उसने इसका पूर्ण रूप से उपयोग किया और चीन में अपनी शक्ति को मलीभांति मुद्दु कर लिया। पर कुछ समय बाद ही जापान भी इस महायुद्ध में शामिल हो गया। महायुद्ध के अवसर पर चीन ने किस प्रकार जापान का मुकाबला किया और किस प्रकार कुओमिन्तांग व कम्यु-निस्ट सरकारों ने जापान के साथ संघर्ष किया, इस विषय पर हम प्रथास्थान प्रकार डालेंगें।

(४) स्वतनत्र चीन

-17/24

जनता का प्रवास-चीन और जापान के युद्ध की मुख्य घटनाओं पर हमने पिछले प्रकरण में संक्षेप के साथ प्रकाश डाला है। अब हम इस बात पर विचाप करेंगे, कि स्वतन्त्र चीन के जिन प्रदेशों पर चुंगकिंग की कुओमिन्तांग सरकार का शासन था, उनकी क्या दशा थी। जापानी सेनाओं के आक्रमण के कारण जब नार्नाक्ता की सरकार पिक्चम की और जाने के लिये विवश हुई, तो बहुत से देशभक्त लोगों ने भी अपने घरबार को छोड़बर पिक्चम की और प्रस्थान किया। पिक्चमी चीन में प्रवास करनेवाल इन लोगों की संख्या लाखों में थी। जो लोग इस समय अपने घर बार को छोड़बर कुओमिन्तांग सरकार का अनुसरण कर पिक्म की ओर गयं, उन्हें हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं।

(१) विद्यार्थी और अध्यापक लोग—चीन के ज्ञान और विद्या के सब महत्वपूर्ण केन्द्र पूर्वी तह के समीपवर्ती नगरों में स्थित थे। इन प्रदेशों के विद्वविद्यालयों में इंडिंगरों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और विज्ञान, शिल्प, कला आदि सब प्रकार की शिक्षा का इनमें प्रवन्ध था। चीन के इन विद्यार्थिमों और निधानों में राष्ट्रीयता की भावना अत्यन्त प्रवत्य थी। चीन में राष्ट्रीयता और प्रवतन्त आरान की स्थापना के लिख को भी जो नी जा निज्ञ हुए, चीनी विद्यार्थिमों ने उनमें प्रमुख भाग

ितया था। जापान के विरुद्ध भावना को उत्पन्न करने में भी उनका प्रमुख हाथ था। इस दशा में उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे जापान द्वारा अधिकृत प्रदेशों में रह सकें। कुओमिन्तांग सरकार के साथ साथ उन्होंने भी पिर्चम कें अं अने क वालिज व विरुविद्यालय पहले पूर्वी चीन में स्थापित थे, अब पिर्चमी चीन में कायम हुए। चीनी विद्यार्थी और शिक्षक अपने साथ में बहुत सी पुस्तकों व अन्य शिक्षा सामग्री भी ले गये। चीन में यातायात के साधनों की बहुत कमी थी। अतः बहुत से लोग पैदल यात्रा करने को विद्या थे। पर पैदल जाते हुए भी उन्होंने इस बात का यत्न किया था, कि वे पुस्तकों व प्रयोगशालाओं के उपकरणों को अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ में ले जावें। पिरचमी चीन के रजेच्यान, क्वेईचाउ और यूनान प्रान्तों के जिन नगरों व ग्रामों को जापानी आक्रमणों से सुरक्षित समझा गया, वहां इन कालिजों और विरविद्यालयों की पुनः स्थापना की गई।

- (२) चीनी लोगों की यह नीति थी, कि जिन प्रदेशों पर जापानी रोनाओं का प्रमुख स्थापित होने की सम्भावना हो, उनकी फसलों को उजाड़ वें और उनके कारखानों को नष्ट कर दें, ताकि जापानी लोग उनका उपयोग न कर राकें । अतः कारखानों के मालिकों ने यह यत्न किया, कि पूर्वी चीन के गारखानों की मशीन के उखाड़ कर उसे पिरुची चीन में ले जावें और वहां अपने कारखानों को नथे सिरे से स्थापित गरें। यह सम्भव नहीं था, कि युद्ध की परिस्थित में सब मधीनरी को पश्चिम की ओर ले जाया जा सकता । पर जिस अंश तक भी सम्भव हुआ, जीनी लोगों ने अपने कारखानों की मशीनरी को पिर्चमी चीन में पहुंचा दिया। रेल, मोटर, ठेला बादि जिस किसी साधन से भी सम्भव हुआ, उन्होंने अपनी मशीनों को पश्चिम पहुंचाया। इस नीति का यह परिणाम हुआ, कि परिचमी चीन में बहुत से कारखानों का विकास हुआ और बहुत से पूंजीपित व व्यवसायपित पूर्वी चीन को छोड़बार पश्चिम के विविध प्रान्तों में आ बसे।
- (३) विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूंजीपतियों के अतिरिक्त बहुत से सम्पन्न लोग भी इस समय अपने परम्परागत घरों का परित्याग कर पश्चिमी चीन में चले आये। सम्भवतः इन्हें अपने घर बार को छोड़ने की काई विशेष आयश्यकता गहीं थी। पर इनका कुओमिन्तांग सरकार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था और जिस ढंग से इस समय चीन के विविध लोग पश्चिम की तरफ प्रस्थान में तत्पर कि समें ये भी शामिल हो गये थे। ये समझते थे, कि जापानी सेनाओं के शासन में इनके जान और माल की रक्षा सम्भव नहीं होगी। इसीलिये अन्य लागों के समान बे भी पश्चिम में जा बसने के लिये तत्पर हो गये थे।

पश्चिमी चीत की उसति—लावों की संख्या में जो बहुत से विद्यार्थी, क्रिश्चक, पूंजीपति और सम्पन्न लीग इस समय पूर्वो चीन को छोड़कर पश्चिम के वितिय प्रान्तों में बसने के लिये आ गये, उसके अनेव महत्त्व-पूर्ण परिणाम हुए। उन परिणामों को हम संक्षेप में इस प्रकार निर्दिष्ट कर सकते हैं—

- (१) पश्चिमी चीन में अनेक नयं कालिज और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। अब तक पश्चिमी चीन शिक्षा की दृष्टि रो बहुत पिछड़ा हुआ था। पर अब वह चीन के ज्ञान ओर विज्ञान का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया।
- (२) पश्चिमी चीन में बहुत से नये कारखाने खोले गये। कुओंमिन्तांग सरकार के लिये यह आवश्यक था, कि जापान के साथ युद्ध को जारी रखने के लिये युद्ध सामग्री को अपने क्षेत्र में ही तैयार किया जाय । विदेशों से अस्त्र शस्त्र आदि को प्राप्त सर सकता सुगम नहीं था, क्योंकि पश्चिमी चीन का पश्चात्य संसार से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। इस दशा में चियांग काई शंक की सरकार तभी यह को जारी रक्ष सकती थी, जब कि वह अपनी आवश्यक वस्तुओं को स्वयं उतान जुरने का प्रयत्न करे । बंहुत से पूंजीपति अपने कारम्वानों की मशीनरी को पश्चिमी चीन में ले आये थे। पर ये कारलाने युद्ध की दृष्टि से पयप्ति नहीं थे। अतः बुओमिन्लांग रारकार ने प्रयत्न किया, कि पश्चिमी चीन का आर्थिक दृष्टि से अधिक से अधिक विकास करें। इसके लियं उसने तीन कमीशनों की निय्क्ति की -क-व्यावसायिक औरचनिजद्रव्यक्तमीशन,इसके लिये एक करोड़ चीनी डालर की पूंजी की व्यवस्था की गई। ख- कृपि कमीशन, इसके लिये तीन करोड़ चीनी डालर पुंजी दी गई। ग- व्यापार कमीशन, इसके लिये दो करोड़ चीनी डालर एंजी दी गई। इन कमीशनों का उद्देश्य यह था, कि व्यवसाय, खान, कृषि और व्यापार की उन्नति के लिये योजनाएं तैयार करें और उन योजनाओं को किया में परिणत करें। इन क्यीशनों ने अपने कार्य के लिये अनेक विदेशी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की और शीष्ट्र ही पश्चिमी चीन आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति कर गया। कृषि और व्यवसाय की उन्नति के बिना यह किसी भी प्रकार सम्भव नहीं था, कि पश्चिमी चीन अपनी विशाल सेनाओं व पूर्वी चीन से आये हाइ लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता। पर कृषि और व्यवसाय की उन्नति एकदम नहीं की जा सकती थी, इसके लिये समय की अपेक्षा थी। यही कारण है, कि इस काल में पश्चिमी चीन के लोगों को बहुत सी दिनकतों का सामना 'बारना पड़ा । वहां बस्तुओं ी मांग उहुए प्रियम थी, पर उनकी उपलब्ध बहुत कम थी। इसका प्रिणाम नह हवा. कि बरनुओं की कोकों बड़ी वैकी के साथ

बढने लगीं, और सर्वसाधारण जनता के लिये अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को प्राप्त कर सकता कठिन हो गया।

- (३) इस समय पश्चिमी चीन में बहुत सी नई सड़कों और रेलवं लाइनी का निर्माण किया गया । युद्ध के सुचार रूप से संचालन के लिये यातायात और आवागमन के साधनों का उन्नत होना बहुत आवश्यक था । कुओं मिल्तांग सरकार ने इस और विशेष रूप से ध्यान दिया ।
- (४) अब तक पूर्वी चीन सम्यता, संस्कृति और आधिक जीवन का केन्द्र था। परिचमी प्रान्त इन क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हुए थे। आधुनिक युग के विचारों, संस्थाओं और आदर्शी का उन पर प्रभाव नाममात्र को ही था। उस दशा में चुंगिकिंग के राजवानी बन जाने से उन प्रान्तों की सर्वतोम् वी उन्नति में बहुत अधिक सहायता मिली।

खुंगांकम सरकार का जासन-जिस समय जीन की बुआंमिन्ताम सरकार की राजधानी नानकिंग में थी, तब भी उसका स्वक्ष्य छोकतन्त्र नहीं था। मरूचू राजवंश का अंत कर चीन में रिपब्लिक की स्थापना अवक्य हो गई थी; पर चीन की रिपब्लिक सरकार का संगठन छोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं कि मुख्या था। सम्भवतः रिपब्लिक के नेताओं को उस बात या। अवकाश ही नहीं मिछा था, कि वे देश में छोकतन्त्रवाद का विकास कर सकें। शुरू में उनकी सम्पूर्ण शक्ति विविध्व सिपहसालारों को अपने वश में छाने में छगी रही। बाद में चीन में अनेक ऐसी स्वतन्त्र सरकारों को अपने वश में छाने में छगी रही। बाद में चीन में अनेक ऐसी स्वतन्त्र सरकारों को अपने वश में हार्कित इन सरकारों को अपने अधीन कर राष्ट्रीय एकता की स्थापना में छगी। चीन में राष्ट्रीय एकता अभी पूर्ण कप से स्थापित नहीं हो पाई थी, कि जापान के साथ युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस दशा में यदि चीन में छोकतन्त्र संस्थाओं ना विकास न हो सका हो, तो उस अरवाभाविक व अनुचित नहीं कहा जा सकता।

यही कारण है, कि जब चंगिंकंग को राजधानी बनाकर कुओमिन्तांग दल ने अपना कार्य प्रारम्भ किया, तो चीन की शासन-व्ययस्था में लोकतन्त्रवाद की और भी अविन्त कमी हो गई। युद्ध की आवश्यकताओं ने इस समय चीन की सम्पूर्ण राजधानित को महासेनापित चियांग काई शंक के हाथों में केन्द्रित कर विष्या । उसकी स्थित एक एकाधिकारी (डिक्टेटर) के समान हो गई थी और बह न नेवल सैनिक क्षेत्र में अपितु शासन कार्य में भी पूर्णतया स्वच्छन्द हो गया था। चियांग काई शेक के सम्पूष कुओमिन्तांग दल भी सर्वथा अशक्त हो गया था और वह इस शक्तिकाली महासेनापित के हाथों में कठपुतली के समान आचरण करने

लगा था । इस समय चीन में चियाग कार्ड शेक की शक्ति जो इस प्रकार असीम हो सकी, उसमें निम्नलिगिन परिस्थितियां सहायक थी---

- (१) युक्त की परिस्थितियों के कारण देश के शासन में रोना और सेनापतियों का महत्त्व बहुत बढ़ा हुआ था। चियांग काई शेक स्वतन्त्र चीन की सेनाओं का प्रधान सेनापति था और तीन की राष्ट्रीय सेना के बहुसंख्यक युवक सेनापति उसे अत्यधिक आदर की दृष्टि में देखते थें। हम पहले लिख चुके हैं, कि कूओ मिन्तांग दल के उत्कर्ष के समय नानिधिंग के पास एक सैनिक एकेडमी की स्थापना की गई थी. जिसका सर्थापक और संचालक चियांग काई शेक ही था । इस सैनिक एके-डमी में शिक्षा प्राप्त करनेवाले आफिसर अपने को चियांग काई शेक का शिष्य समझते ये और उसे अपना गार्गप्रदर्शक मानते थे। जब नानकिंग जापानियों के हाथों में चला गया, तो अन्य अनेक शिक्षणालयों के समान यह सैनिक एकेडमी भी पश्चिमी जीन में छे आई गई थी। इस समय चीन की राष्ट्रीय सेना के बहुमंख्यक उच्च आफिसर ऐंगे भी. जिन्होंने चियांग काई शेक द्वारा स्थातिन रौतिक एके उसी में शिक्षा प्राप्त की थी। यह स्वाभाविक था, कि वे पूर्णतया उसके बन्यायी हो और उसके भिद्धान्तों, आदशों और नीति के समर्थक हो। इस . सैनिक एकेडमी की स्थापना रें। पूर्व चीन के विविध सेनापतियों में। प्रायः प्रतिद्वनिद्वता का भाग रहता था और किसी एक सेनापित की स्थिति ऐसी नहीं होती थी, जो अन्य अब सेनापितयों को पूर्ण रूप से अपनी आज्ञा में रख सके। पर अब यह स्थिति बदल चुकी थी।
- (२) कुओमिन्तांग दल में बहुत से लोग एंगे थे, जो वैयक्तित रूप में नियांग काई रोय के प्रति अनुरक्त थे। इनमें चेन ली-फू और चेन कुओ-फू का नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है। ये दोनों चेन बन्धु कम्युनिज्म के कट्टर विरोधी थे और दिक्षणपक्षी प्रवृत्तियों के पक्षणाती थे। कुओमिन्तांग दल में इनका बहुत ऊंचा स्थान था। चेन कुओ-फू चीन के केन्द्रीय पोलिटिकल इन्स्टिट्यूट का अध्यक्ष था। यह मंस्था कुओमिन्तांग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रेन करती थी। इस संस्था में नययुवकों को यह सिखाया जाता था, कि अपने नेताओं के आदेशों को आंक मीनकर मानना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। चीन की प्राचीन क्रियारमरणी भी यही शिक्षा देती है। कन्पयूसियस की यह प्रधान शिक्षा थी, कि अपने गुरुजनों और पुरुवाओं के प्रति भिक्त रखी जाय और बिना किसी नेनु नच के उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किया जाय। चेन कुओ-फू द्वारा संचालित पोलिटिकल इन्स्टिट्यूट में जो नवयुवक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करते थे, वे कुओमिन्तांग दल के विचारों और सिद्धान्तों में आंख मीचकर विश्वास करते

थे और उन्हें किया में पिण्णत करना अपना कर्तव्य समझते थे। चैन ली-फू चुंगिक्स सरकार में शिक्षामन्त्री के पद पर अधिष्ठित था। उसकी भी यही नीति थी कि चीन के विविध शिक्षणालयों में विद्याधियों को अपने नेताओं व गुरुजनों की शाजाओं के पालन की शिक्षा दी जाय। इस नीति का यह परिणास था, कि चीन के नव्युवकों व विद्याधियों में स्वतन्त्र विचार और परम्परागत आदर्शों की सत्यता व उपयोगिता में सन्देह करने की प्रवृत्ति में कभी होती जाती थी और वे अपने नेताओं को असाधारण आदर व श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे थे। क्योंकि चियांग काई शेक चीन का सर्वप्रधान नेता था, अतः उसके प्रति भिनत व सम्मान की भावना निरन्तर बढ़ती जाती थी और जो नवयुवक चीन की सेना व सरकार में विविध पदों को प्राप्त करते थे, ये उसके आदेशों को मानना अपना परम कर्तव्य समझते थे।

(३) चियांग काई रोक के अपने विचार दक्षिण पक्षी थे, और वह स्वयं कम्युनिज्म का कट्टर विरोधी था। इसीलिये उसने कुऑमिन्तांग दल रो कम्यनिस्टों को बहिष्कृत कर दिया था आर अपनी शक्ति का आयार चीन के उन पूजीपतियों, जमीदारों व सम्पन्न श्रीण के लोगों को बनाया था, जिनकी सर्वराधारण जनता से जरा भी सहान्भति नहीं थी। यही कारण है, जि कुओं मिन्तांग सरकार देहात में निवास करनेवाले किमानों की दशा की उन्नत करने के लिये कोई कार्य नहीं कर रहा था। उसका सम्पूर्ण ध्यान इस यात पर था, कि फल कारावानों का विकास हो, शहरों की उन्नति हो और रेलवे लाइनों, गडकों आदि का इस ढंग से निर्माण किया जाय, ताकि शहरों के व्यवसायपति उनसे लाभ उठा सकें। चीन की देहाती जनता में इस समय तया अनिया जागति नहीं हुई थी, इसलिये यदि उनके हित के लिये चियांग काई शेक ने कीई महत्त्वपूर्ण बार्य नहीं किया, तो इससे उसकी शक्ति व प्रभाव में कोई विशेष अन्तर नहीं आया । पर गहरों की भव्यम श्रेणि, पूंजीपित व जमींदार आदि सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिये कूओमिन्तांग दल जिस नीतिका अनुसरणकर रहा था, उससे यह वर्ग उसका पक्षपाली बन गया था। चियांग काई शेंक के अतुल प्रभाव के लिये सम्पन्न वर्ग का समर्थन वहत सहायक था।

इन सब वातों का यह परिणाम हुआ, कि चीन में कुओमिन्तांग दल की रिश्री जर्मनी की नाजी पार्टी व इरली की फैसिस्ट पार्टी के समान अहिसीय हो गई। चीनी सरकार की नीति का निर्धारण जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि गहीं करते थे। यह कार्य कुओमिन्तांग दलके हायों में था, और इस दल पर चियांग बाई शंक का एकाविपत्य था। महासेनापति चियांग काई शेक जो कुछ सोचता था, जो

कुछ निर्धारित नारता था, कुओमिन्तांग दल की केन्द्रीय नार्यकारिणी समिति किसा किसी विवाद के उने स्वीकार कर लेती थी। जापान के साथ यद्ध की परिक्षियि में कुओमिन्तांग दल पर चियांग काई क्षेत्र का आधिपत्य और भी अधिक बढ़ गया था। यही कारण है, कि चुंगिकंग सरकार में चियांग काई क्षेत्र की स्थिति एकाविगति (डिकटेटर) के सदश थी।

पर यह नहीं रामजना नाहिये, कि चुंगिकंग सरकार में जनता को अपनी सम्मित को अभिकानन तरने के लिये कोई भी अवसर नहीं था। जब चीन की स्वतन्त्र सरकार जा प्रधान कार्यालय हैन्को में था, तभी जनता की राजनीतिक कींसिल (पीपल्स पीलिटिकल कींसिल) की वहां स्थापना की गई थी। शुरू में इसके २०० सदस्य थे, बाद में उनकी संख्या बढ़ाकर २४० कर दी गई थी। जब सरकार हैन्को से चुंगिकंग चली गई, तो इस कींसिल के अधिवेशन भी चुंगिकंग में होने लगे। राजनीतिया कोंसिल के सदस्यों की नियुक्त जनता निर्वाचन द्वारा नहीं करती थी, उन्हें गनोनीत किया जाता था। पर इन सदस्यों को मगोनीत करते हुए यह भी ध्यान में रचा जाताथा, कि कुंगोमिन्तांग दलके अतिरिक्त अन्य विचारों का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो सकें। कम्युनिस्ट दल तक के व्यक्ति इस कौंसिल में बनीतीत किये जाते थे। इस कौंसिल से संगठन का प्रधान उद्देश्य यह था, कि सब दलों और विचारों के लोग परस्पर मिलकर जागान के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग दे सकें। पर साथ ही इस कौंसिल से यह लाभ भी अवस्य था, कि इसमें कुंगोमिन्तांग दल के विदिशियों को भी अपनी नीति य विचारों को प्रकट करने का अवसर मिल जाताथा।

येनान की कम्युनिस्ट सरकार-स्वतन्त्र चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में कम्युनिस्ट लोगों की पृथक् सरकार स्थापित थी, जिसकी राजधानी येनान थी। कम्युनिस्ट सरकार जापान के विरुद्ध संघर्ष में चियांग काई शेक के आदेशों के अनुसार नलती थी और उसकी सेनायें चीन की राष्ट्रीय सेना का अंग मानी जाती थीं। चुंगिकंग की गोलिटिकल कौंसिल में भी कम्युनिस्ट दल को स्थान प्राप्त था। पर शासन की दृष्टि से कम्युनिस्ट सरकार अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थी और वह समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार अपने राज्य का संगठन करने में ततार थीं। बड़े व्यवसायों को राज्य के अधिकार में कर लिया गया था और देहातों में स्थानीय सोवियतों की स्थानना कर दी गई थी। सर्वसाधारण जनता इस नई व्यवस्था से बहुत संजुष्ट थी और कम्युनिस्ट सरकार अस्ता है। वियाग काई चुंगिकंग और येनान की दो सरकार में कर शिवा वार्य महन्त्र थी। चुंगिकंग और येनान की दो सरकार में वह शिवा वार्य महन्त्र थी। चुंगिकंग और येनान की दो सरकार में वह शिवा वार्य महन्त्र थी। वार्य महन्त्र थी निर्माण की दो सरकार में वह शिवा वार्य महन्त्र थी। स्थान की दो सरकार महन्त्र भी है। चियांग काई शेक की नीति व कार्यक्रम से जनता को वियोग सहारूपत वह शिवा वार्य भी, स्थोंकि इसमें

उसे अपना कोई लाभ प्रतीत नहीं होता था। इसके विपरीत कम्युनिस्ट शारान में जनता जहां एक तरफ राष्ट्रीय आदर्श को सम्मुख रखकर जापान के साथ राष्ट्रीय में तत्पर थी, वहां माथ ही वह यह भी अनुभव करती थी, कि इस वारान से उसके अपना भी हित और कल्याण है। इसीलिये वह जापान के साथ मधा में बड़े से बड़ा त्याग करने के लिये तैयार थी। यहीं कारण हे, कि कम्युनिस्ट लोग जापान के विश्व गुरीला युद्ध में जनता का सहयोग प्राप्त करने में ममथे थे। वियोग काई शेंक की कुओमिन्ताग सेनाए गुरीला युद्ध में कोई भी निपुणना नहीं प्राप्त कर सकी थी, क्योंकि जनता उनके साथ सहयोग करते हुए कोई उत्साह अनुभव नहीं करती थी। इसीलिये जापान द्वारा अधिकृत चीन के जिन प्रदेशों में गुरीला युद्ध की आवश्यकता अनुभव की गई, उनमें कम्युनिस्ट लोगों को आगे किया गया।

नयोंकि कम्युनिस्ट सरकार के लिये स्थल मार्ग द्वारा क्स में युद्ध सामग्री की सहायता प्राप्त कर सकता अधिक स्गम था, अतः उसकी स्थिति चुंगकिंग सरकार की अपेक्षा अधिक मजबूत थी। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहियं कि . रूस चीन को युढ सामग्री की जो भी सहत्यता देताथा, यह च्यांकिंग सरकारका दी जाती थी और चुर्गीवंश सरकार ही उसके एक अंश की येनान सरकार को प्रवाही करती थी। क्रमी लोग येनान की कम्यनिस्ट रारकार के प्रति पक्षपात प्रदर्शित नहीं करते थे । क्योंकि कुओभिन्तांग संक्कार चीन की प्रमुख सरकार थी, अत: रूस की और से दी जानेवाली युद्ध सामग्री उसी के मुपूर्व की जाती थी। बहुधा येनान मरकार को यह शिकायत भी रहती थी. कि चुंगविंग सरकार रूप से प्राप्त होने वाली युद्ध सामग्री को कम्युनिस्ट नेनाओं को नहीं देती है । जिस समय १९४० में बरमा के मार्ग से बिटेन और अमेरिका की युद्ध सामग्री प्रचुरपरिणाम में चुंगविम पहंचने लगी, तो चियांग वार्ड शंक की सरकार का वस्युनिस्टों के साथ विरोध अधिक प्रत्यक्ष हो गया। कई बार ऐसे अवसर भी उपस्थित हुए, जब कि कुओ-मिन्तांग सरकार कम्युनिस्ट रोनाओं का सहयोग प्राप्त करने के बजाय उनका विरोध करने के लिये उद्यत हुई। वस्तुत: नियांग काई शेक और उसके साथी हृदय से कम्युनिस्टों के विरोधी थे। जापान के प्रभूत्व से अपने देश की रक्षा के कार्य में भी उन्हें कम्युनिस्टों का सहयोग अभीष्ट प्रतीत नहीं होता था । इसी विश्वे जब बांग चिंग वेई के नेतृत्व में जापान की संरक्षा में नानकिंग सरकार का सुक्री रूप से संगठन हो गया, तो चुंगिकिंग सरकार कम्युनिस्टों की अपेक्षा उस सरकार के साथ अधिक सहयोग करने लगी । बाद में कुओमिन्त्रांग और कम्युनिस्टों दलों में जो घोर संघर्ष हुआ, उसके मुल कारण इस समय में भी विद्यमान थे और यही

कारण है कि चियांग गाई शेक ने कभी भी जापान के विरुद्ध कम्युनिस्ट दल के सहियोग का हृदय से स्वागत नहीं विका।

चियांग काई शेक ने कम्युनिस्ट सेनाओं का जो सहयोग लिया, उसका कारण उसकी सैनिक विवयता ही थी। १८३८ में जब है को पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो गया, तो कुओमिन्तांग सरकार की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। चीन के बहुत बहु भाग पर जापान का प्रभत्व कायम हो गया था और जापानी सेनाएं निरन्तर आगे बढ़ती जाती थीं। इस दशा में चियांग काई शेक ने विवश होकर कम्यनिस्टों को यह अनुमति प्रदान की, कि वे यांगरसे नदी के दक्षिण में ग्रीला युद्ध को प्रारम्भ कर सकें। यांगरसे नदी के दक्षिण में विद्यमान कियांग्सी और हुनान प्रान्तों में १९३४ तक कम्युनिस्टों का शासन विद्यमान था। यहां उन्होंने समाजवादी व्यवस्था भी कायम की हुई थी। यद्यपि चियांग काई शेक की कम्यनिस्ट विरोधी नीति के कारण ये लोग इन प्रदेशों का परित्याग कर उत्तर-परिचम के शंन्सी प्रान्त में चले जाने के लिये विवश हुए थें, पर कियांग्सी प्रान्त और उसके नमीपवर्ती प्रदेशों में अब तक कम्य्निस्ट व्यवस्था की स्मति विद्यमान थी। ्राह्म ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो कम्युनिस्टों के साथ सहानुभृति रखते थे। विशेषतया सर्वभाधारण किसान मजदूर जनता कम्युनिस्ट शासन के दिनों को अभिमानपूर्वक याद करती थी। इस दशा में कम्युनिस्ट लोगों के लिये यह अत्यन्त स्गम था, कि वे विष्यांगभी की जनता के सहयोग से इस प्रान्त में ग्रीला युद्ध को शुरू कर सबीं। 'इस प्रान्त में जापान के साथ संघर्ष को जारी रखने का कार्य कम्य-निस्टों के सुपूर्व किया गया और उन्होंने 'बीन की चतुर्थ रोना' के रूप में वहां अपने गरीला सैनिकों की जापान से यह जारी रखते के लिये नियक्त किया। इसमें सन्देह नहीं, कि नाम्य्निस्ट लोग गुरीला युद्ध में बहुत प्रवीण थे और उन्हें जापान के साथ संघर्ष में इस क्षेत्र में अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई। कियांग्सी प्रोन्त में कम्य्निस्ट रोनाओं के प्रविष्ट हो जाने से चीन में कम्युनिस्टों के दो क्षेत्र हो गये-(१) उत्तर पश्चिमी चीन और (२) कियांग्सी प्रान्त । चीन के अगले इतिहास की भलीभाति समझने के लिये इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में जब कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में संधर्ष का फिर प्रारम्भ हुआ, की कम्युनिस्टों की शक्ति के ये दी महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी और इन्हीं से उन्होंने अन्य प्रदेशों में अपनी शिवत का विस्तार किया था।

(५) जापान द्वारा अधिकृत चीन

चियांग काई शेक की ऐनाओं की परास्त कर जापान ने चीन में पेकिंग और

तानिका में जिन दो सरकारों की स्थापना की थी, उनका उल्लेख इस अध्याय में पहले किया जा चुका है। पेकिंग की सरकार की स्थापना १४ दिसम्बर, १९ के होई थी, और नानिका सरकार की २८ मार्च, १९३८ को। इन दो सरकारों के अधिरिक्त जापान की अधीनता में एक तीसरी सरकार भी थी, जिसका शासन आभ्यत्वर मंगोलिया पर विद्यमान था। जापान की इच्छा थी, कि इन तीनों सरकारों को मिलाकर एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना की जाय, जो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से चीन की वैध सरकार गानी जाय और जो चियांग काई शंक का स्थापना की संयुक्त की सिला कर सके। इसी उद्देश्य से २२ सितम्बर, १९३८ की चीन की संयुक्त की सिल के संगठन किया गया, जिसका केन्द्र नानिका को रखा गया। पर इस संयुक्त की सिल के निर्माण द्वारा अधिकृत चीन की विविध सरकारों की पृथक सता का अन्त नहीं कर दिया गया। ये सरकारों कायम रही, यद्यीप यह कौ सिल उन सब पर नियन्त्रण रखती थी और उनमें सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न करती थी।

हम पहले लिख चुके हैं, कि जब हैन्को पर जागान का अधिकार हुआ, तो बांग चिंग वेई इस पक्ष में था, कि चीन को जापान के साथ समझीता कर छेना वाहिये । युद्ध का और अधिक जारी रखना उसकी दुष्टि में निर्यक था । चियांगी हाई होक ने उसे देशद्रोही समझा और वह अपने अनेवा साथियों के साथ कुओमिन्तांग सरकार से पृथक हो गया । बांग चिंग वेई ईमानदारी के साथ यह समझता था, कि चियांग काई शेक डा० सन यात सेन की नीति व आदर्शों का पालन नहीं कर रहा है, और उसके नेतृत्व में चीन लोकतन्त्रवाद के मार्ग से हटकर फैसिज्म की तरफ चला जा रहा है। बांग चिंग वेई यह भी समजता था, कि चीन वा हित व करयाण इस बात में हैं , कि वह अपनी उन्नति के लिये जापान का सहयोग प्राप्त करें । उसे विश्वास था, कि जापानी सरकार से बातचीत करके ऐसी सन्धि की जा सकती है, जिससे चीन की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अध्सण रहे और चीन जापान का सहयोग प्राप्त नर लोकतन्त्र शासन की स्थापना में और अपनी राष्ट्रीय उसति में समर्थ हो। इसीलिये उसने चियांग काई शेक का साथ छोड़कर जापान के साथ सन्धि भरने का प्रयत्न प्रारम्भ किया । पर यह कार्य स्गम नहीं था, नारण यह कि वांग चिग वेई जापान से कोई ऐसा समझौता नहीं करना चाहता था, जिसमें चीन 🛸 राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अक्षुण्ण न रहती हो । दूसरी तरफ जागान इस बात के किये उत्सुक था, कि चीन की सरकार उसके प्रभाव में रहे और पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में उसकी नीति का अनुसरण करे। वस्तुतः जापान की यह इच्छा थी, कि पूर्वी एशिया में मञ्जूकुओ, चीन और जापान की मिलाकर एक ऐसा गुट बनाया जाय,

जोअन्तर्राष्ट्रीयक्षेत्र में एयानीतिवा अनुसरणकरे। इस नीति के निर्घारण में जापान का प्रमुख हाथ हो, और चीन व मञ्चूकुओं विदेशी राजनीति में जापान के अन्-क्यी रहें। केवल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ही नहीं, अपित आर्थिक जीवन में भी में दोनों राज्य जापान के सहयोगी बन कर रहें। इसी उद्देश्य से जापान यह चाहता था, कि चीन और मञ्चुनुओं की मुद्रापद्धति येन से सम्बद्ध रहे। जापान की यह इच्छा नहीं थी, भि वह चीन के साथ एक अधीनस्थ राज्य का सा व्यवहार करे। जिन अर्थी में ब्रिटेन ने भारत और बरमा पर या फ्रांस ने इन्डोचायना पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, उन अथों में जापान चीन को अपनी अधीनता में नहीं लाना चाहता था। उसकी यह आकांक्षा नहीं थी, कि चीन पर जापान का शासन कायम हो, पर वह यह अवस्य चाहता था, वि चीन में ऐसी सरकार कायम हो, जो जापान की संरक्षा और सहयोग को महत्त्व दे। चीन पहले भी सम्पर्ण-प्रभत्व-सम्पन्न देश नहीं था । ब्रिटेन, अमेरिका आदि पारुवात्य देशों ने न केवल उसमें अपने अनेस प्रकार के विशेषाधिकार कायम किये हुए थे, अपित वियाग काई बोक की सरकार अमेरिका और ब्रिटेन की संरक्षा तथा साहाय्यपर भी निर्भर थी। पारवात्य देशों ने जिस ढंग से एशिया के प्रायः सभी देशों पर अपना प्रभाव व क्रमत्त स्थापित निया हुआ था, जापान उसके विरुद्ध था। वह चाहता था, कि पूर्वी एशिया से पारुवात्य देशों के प्रभुत्व का अन्त हो और इस भुराण्ड की विविध सरकारें जापान को अपना संरक्षक, नेता व सहयोगी स्वीकार करें।

यांग चिंग वेई जापान की इस नीति से सहमत था। इसीलिये उसने जापान के साथ सहयोग की नीति को स्वांनार किया। मार्च, १९४० में नानिका में चीन की केन्द्रींग सरकार का संगठन थिया गया और वांग चिंग वेई की इस सरकार का प्रधान बनाया गया। नानिका सरकार के साथ जापान ने जो सगझीता किया, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—(१) जापान ने वांग चिंग वेई की सरकार को चीन की वैध सरकार के रूप में स्वीकृत किया और उसे यह बचन दिया, कि चियांग काई शेंक की चुंगनिंग सरकार को परास्त करके सम्पूर्ण चीन में अपना शासन स्थापित करने के कार्य में वह बांग चिंग वेई सरकार की सब प्रकार से सहायता बारेगा। (२) जिस समय चियांग नाई शेंक की पराजय के कारण चीन में गृह कलह का अन्त हो जायगा, जापान अपनी सेनाओं को चीन से हटा लेगा। उसकार को समय तक जो जापानी रोनाएं चीन में रहेगी, उनका उद्देश्य केवल बांग चिंग वेई की सरकार को नदायना पर्नाता ही रह जायगा। (३) चियांग काई शंक की सेनाओं के परास्त हो जाने के नाव अस्पानी देनारें तब तक उत्तर-पश्चिमी चीन में रह सकेंगी, जब तक कि उस प्रवेश में कम्युनिस्ट लोगीं को परास्त न कर दिया

जाय। (४) आर्थिक मामलो में बांग विग वेई की सरकार जापान के साथ महयोग करेगी और मुद्रापद्धति व आर्थिक नीति का संचालन जापान के परामर्श के अनुसार करेगी । इस समझौतें के अनुसार जागान की दृष्टि में बांग विश्व वेई की नानकिंग सरकार चीन की असली और वैध सरकार थी और चियान काई शेक के साथ उसका संघर्ष एक गृहयुद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई हीसियत नहीं रखता था। जापान की दृष्टि में नियांग काई शंक की गरकार व कम्युनिस्टों के विरुद्ध यद्ध का संचालन वाग चिंग वेर्ड की सरकार कर रही थी और जापान केवल उसकी सहायता कर रहा था । इस समय यूरोप में द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) का प्रारम्भ हो चुका था ओर जर्मनी, इटली आदि राज्यों की सहानुभृति जापान के साथ में थी। अतः १ जुलाई, १९४१ तक अनेक युरोपियन राज्यों ने, जो कि इस समय जर्मनी के साथ थे, बाग चिंग वेई की सरकार को स्वीकृत कर लिया था। इन राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं-जर्मनी, इटली, स्पेन, क्रमानिया, स्लोबाकिया और कोटिया। यहां वह लिखने की आवश्यकता नहीं, कि इस समय क्यानिया, स्लोवाकिया और कोटिया जर्मनी के अधिकार में थे और इनकी सरकारें पूर्णतया जर्मनी की बजबर्ती थी। इटली और स्पेन जर्मनी के मित्र थे और महायुद्ध के अवसर पर उन राव राज्यों की सहानुभृति जागान के साथ थी। 🛶

राजनीतिक दुष्टि से बांग चिंग बेई की सन्वार स्वतन्त्र थी, गुर जापान उसकी आर्थिक नीति का संचालन इस ढंग से कर रहा था, जिससे उसका अपना लाभ हो। चीन के आर्थिक विकास के लिये जापानी मन्त्रिमण्डल की अधीनता में एक बोर्ड स्थापित किया गया था, जिसकी अधीनता में अनेक जापानी कम्पिनयां चीन में व्यापार और व्यवसायों की उन्नति के लिये काम कर रही थीं। इत कम्पनियों को चीन में विशेष अधिकार प्रदान किये गये थे। चीन की मुद्रा-पद्धति को जापान के येन के साथ सम्बद्ध किया गया था और जापानी सरकाएं का यह प्रयत्न था, कि चीन के साथ उसके व्यापार में निरन्तर बृद्धि हो । इस प्रयत्न में उसे सफलता भी प्राप्त हुई थी। १९३७ में जापान से जो गाल चीन में गया था, उसका मृत्य १९,००,००,००० येन था। १९३८ में चीन में आये जापानी माल की मात्रा बढ़कर ३४,३०,००,००० येन तक पहुंच गई थीं। इसके बाद चीन में जापानी आयात माल की मात्रा में और भी अधिक वृद्धि हुई। जापान से आने वाले माल के मुकाबले में चीन से जापान जाने 🗱 माल की मात्रा में इतनी तेजी के साथ वृद्धि नहीं हुई थी । १९३७ में चीन री जापान जानैवाले माल का मूल्य १७,००,००,०००, येन था। १९३८ में वह बढ़कर १७,९०,००,००० येग हो गया था। इससे स्पष्ट है, कि चीन जापान से जो

माल मंगा रहा था, उनकी मात्रा उससे जापान जानेवाले भाल की अपेक्षा बहुत अधिक थी। जापान को गही बात अभीष्ट भी थी। जापान चीन में अपने आधि- किय को इसीलियं स्थापित करना चाहता था, ताकि वहां वह अपने तैथार माल के लिये सुरक्षित बाजार प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य में उसे अच्छी सफलता प्राप्त हो गई थी।

महायुद्ध और जापान

(१) महायुद्ध से पूर्व जापान की अन्तर्राष्ट्रीय नीति

चियांग काई शेक की शक्ति का अन्त करके और वांग चिंग वेई के नेत्त्वमें नई चीती सरकार की स्थापना करने में जापान का क्या उद्देश्य था, इसे पिछले अध्याय में भलीभांति स्पष्ट किया जा चुका है। जापान पूर्वी एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित यारना चाहता था। उसकी इच्छा थी, कि मञ्चुकुओ , मंगोलिया और चीन में ऐसी सरकारों का शासन कायम हो, जो जापान को अपना नेता माने और अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का निर्माण जापान की इच्छा के अनुसार करें। इस उद्देश में उसे आंशिक रूप से सफलता भी हो गई थी। पर जापान यह भलीभांति सम-अता या, वि पूर्वी एशिया में उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति में तीन तरफ से बाया उके स्थित हो सकती है। (१) उत्तरी एशिया पर रूस का आधिपत्य था। रूसी सोवियत संघ की सीमायें मञ्चकूओ और मंगोलिया के साथ मिलती थीं। उत्तरी पश्चिमी चीन में येनान को राजधानी बनाकर जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापितथी, भौगोलिक वृष्टि से उसका रूस के साथ सिन्नकट सम्बन्ध था। स्वामाधिक रूप से रूस गेनान की सम्युनिस्ट सरकार का समर्थंग था। इस दशा में जापान की यह आशंका थी, वि पूर्वी एशिया को अपने प्रभाव में लाने के प्रयत्न में रूस उसका थिरोध कर सकता है। (२) चीन के समुद्रतट पर अनेक स्थानों पर ब्रिटेन का अधिकार था। हांगकांग सीधा ब्रिटेन के शासन में था और पूर्वी एशिया में यह ब्रिटेन की शिवत का प्रधान केन्द्र था । शंघाई की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में ब्रिटेन का स्थान सर्वप्रधान था और तीन्तिसन , कैन्टन आदि बन्दरगाहों में भी बिटेन की अनेक बस्तियां कायम थीं । चीन के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि ब्रिटेन चीन में निरन्तर बढ़ती हुई जानानी प्रमृता कु विरोबी हो। (३) संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये यह बात बहुत अधिक महरू की थी, कि प्रज्ञान्त महासागर के क्षेत्र आर पूर्वी एशिया में किस राज्य की अक्ति प्रधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल प्रदेश में नियन्तर पिक्चम की

भीर बढ़ना जा रहा था और उसकी वस्तियां प्रशान्त महासागर के पूर्वी तट पर कैलिफोर्निया आदि में भलीभांनि विकसित हो गई थीं। साथ ही, फिलीप्पीन हीं पस्मूह उसकी अवीनता में था। यदि जापान मञ्जूकुओ, मंगोलिया और चीन को अपने प्रभाव य प्रमृत्वमें ले आने की योजना में सफल हो जाता, तो अमेरिका के लिये यह बात वहुन हानिकारक होती। इसमें फिलिप्पीन द्वीप समृह पर अपना कब्जा रख सकना उसके लिये कठिन हो जाता और प्रशान्त महासागर में भी उसकी स्थित मुरक्षित न रहने पानी। इस प्रकार कस, ब्रिटेन और अमेरिका—तीन ऐसे देश थे, जो जापान के साम्राज्य विस्तार में सबसे अधिक बाधक हो सकते थे। इसीलिये इन देशों के माथ जापान ने किस ढंग के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विकसित किये, यह बात विचार के योग्य हैं।

एण्ट-कोमिल्टर्न पंषट-कम के मुकाबल में अपनी स्थित को सुरक्षित करने के लिये जापान ने जर्मनी के साथ एक गुट बनाया, जो इतिहास में एण्टि-कोमिस्टर्न पैनट के नाम से प्रसिद्ध है। यह पैक्ट २५ नवस्वर, १९३६ को विध्या गया था। इसका उद्देश्यग्रह था, कि जर्मनी और जापान मिलकर युरोप और एशिया में कम्युनिजन के प्रसारका विरोधकारें। इस पैनट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान ने एक ऐसे वाक्ति-्रीही देश के साथ मैत्री स्थापित कर ली थी, जो इस समय में युरोप में बहुत अधिक प्रवल था । हिटलर द्वारा जर्मनी में जिस नाजी व्यवस्था की स्थापना की गई थी. वह कम्यिनिज्म के नवंशा विभरीत थी । अतः हिटलर को यह भय था, कि यदि कोई वल उसके निरुद्ध खड़ा हो सकता है, तो वह केवल कम्युनिस्ट वल ही है। माजी दल के नेता जमंगी में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए बहुधा कहा करते षे, कि "यदि राष्ट्रीय समाजवादी (नाजी) दल शिथिल हो जाता है, तो जर्मनी में एक करोड़ कम्युनिस्ट लोग गैदान में आ जावेंगे।" अतः व अनुभव करते थे. कि संसार में जो देश कम्युनिज्य के विरोधी हैं, उन्हें परस्पर मिलकर अपना पृथक गुट बनाना चाहिये, और इस गृट का उद्देश्य कम्युनिज्म के प्रचार का विरोध होना चाहिये। १९३७ में इटली भी इस गुट में शामिल हो गया, और जर्मनी, जापान और इटली की सम्मिलित गवित कम्युनिज्म के विरोध में प्रयुक्त होने लगी। इस एप्टि को भिन्टनं पैक्ट के कारण जापान रूस की तरफ से बहुत कुछ निरिचन्त हो गया था । यही कारण है, कि रूस चीन में निरन्तर बढ़ते हुए जापान के प्रभूत्व की सफ्ट रूप में विरोध नहीं धर सवता था। जलाद का विरोध करने दा उसके सम्मास केल्ल गही वार्व था, कि वह बीव को अधिक ने अधिक सहायता प्रदान करें। मुझ गाम्प्री हारा हो वह जीन की शहाबता करता ही था, शाय ही धम के भेग से अत्यान को अपनी अवटी बड़ी सेना मञ्चकुओं की उत्तरी सीमा पर रखनी पड़ती

थीं। यह बात भी चीन के लिये अत्यधिक सहायक थीं। मञ्चूकुओं की उत्तरी सीमा पर जो जापानी रोना विद्यमान थीं, उसकी संख्या चार लाखके लगभग थीं। इतनी बड़ी जापानी सेना क्या की दक्षिण-पूर्वी सीमा पर इसीलिये रखीं निश्चे थीं, कि कहीं क्या मंचूकुओं व मंगोलिया पर आक्रमण न कर दे। पर इस समय क्स जापान के सम्बन्ध में बहुत कुछ निष्पक्ष व उदासीन गीति का अनुसरण कर रहा था, नयोंकि एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट के कारण जापान की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई थीं।

बिटेंन और जापान-१९०२ में इङ्गलैण्ड और जापान में जो सन्धि हुई थी. छसका उल्लेख हम इस इतिहास में विशद रूप से कर चुके हैं । इस गन्धि के कारण ब्रिटेन और जापान एक दूसरे के धनिष्ठ मित्र बन गये थे, और यह के अवसर पर उन्होंने एक दूसरे की सहायता का यनन दिया था। १९१४-१८ के महायुद्ध में जापान ब्रिटेन के पक्ष में लड़ाई में शामिल हुआ था और उनकी यह मित्रता तीस साल से भी अधिक समय तक कायम रही थी। पर इस समय ब्रिटेन और जापान के राजनीतिना सम्बन्ध पहले के समान मैत्रीपूर्ण नहीं रहे थे, क्योंकि जापान चीन में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिये प्रयत्नशील था और ब्रिटेन इस बात की पसन्द नि करताथा। चीन के अनेक प्रदेश ब्रिटेन के अधिकार में थे और चीन में जापान की शक्ति के विस्तार से ब्रिटेन के इस प्रभुत्व में बाधा पड़ती थी। पर जापान को ब्रिटेन की शक्ति का विशेष भय नहीं था। युरोप की राजनीति में ब्रिटेन जिस प्रकार शक्तिहीन हो गया था, उसके कारण जापान उसको विशेष महत्त्व नहीं देता था । २९ सितम्बर, १९३८ को ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ एक समझौता किया था, जो इतिहास में 'म्युनिस का समझौता' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस समजीते द्वारा ब्रिटेन ने चेकोरलीवाकिया के सम्बन्ध में हिटलर की सब मांगों को अविकल रूप से स्वीकार कर लिया था। ब्रिटेन और फांस जैसे देशों की सर्व था उपेक्षा कर जर्मनी इस समय जिस प्रकार पुरोप में अपने प्रभूत के विस्तार में ततपर था, उससे जापानी लोगों का यह विचार पृत् हो गया था, कि मिटेन की शक्ति अब बिलकुल धीग हो गई है। इसीलिये पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान ब्रिटेन से किसी प्रकार के बिरोध की आशंका नहीं रखता था। २९ सितम्बर, १९३८ को यूरोप में म्यूनिख समझौता हुआ था, जिसमें ब्रिटेन 🐞 : जर्मनी के सामने नीचा देखना पड़ा था। इस घटना के केवल अठारह दिन बार १७ अक्टूबर को जापानी सेनाओं ने कैन्टन पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। कैन्द्रन हांगकांग के समीप है, और यह भी ब्रिटिश व्यापार का महत्त्व-

पूर्ण केन्द्र था । कैन्टन पर जापान का कटजा इस बात का प्रमाण था, कि जापान ब्रिटिश शक्ति की कोई विशेष परवाह नहीं करता । वस्तुतः इस समय जापान यह केलीभांति अनुभव करता था, कि जिटेन के साथ उसकी मैत्री का कायम रह सकना असम्भव हैं। यूरोप में जिटेन और जर्मनी एक दूसरे के प्रवल विरोधी थे। जापान जर्मनी और इटली का भित्र था। इस दशा में उसने ब्रिटेन के साथ अपनी मैत्री को कायम रखने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया।

जायान और अमेरिका--प्रशान्त महासागर और पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान और अमेरिका के हित आपस में टकराते थे, यह हमने अभी ऊपर लिखा है। यही कारण है, कि जुलाई, १९३७ में जब जापान चीन में अपनी शक्ति के विस्तार के लिये प्रवृत हुआ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति श्री रुजवेल्ट ने शिकागो में भाषण करते हुए उद्घोगित निया यि "ऐसा प्रतीत होता है, नि दुर्भाग्यवश यह बात सच है, यि संसार में अराजकता की महामारी फैलने लग गई है। युद्ध छुत की बीमारी के रामान होता है। जहां से युद्ध का प्रारम्भ होता है, उससे बहुत दूर के राज्य व लोग भी उसकी लगेट में आ जाते हैं। हमारा यह पक्का इरादा है, कि हम अपने को युद्ध रो बचाये रखें, पर हम इस बात का भरोसा नहीं रख सकते, ंकि हम युद्ध के बिताशकारी परिणामों से या युद्ध की लपेट में आ जाने से अपने की बचाये रख सकोंगे। अतः यह आवश्यम है, कि संसार में शान्ति स्थापित रखने के लिये पुरा-पुरा प्रयत्न विधा जाय।" इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि अमेरिका के राजनीतिज्ञ यह भलीभांति अनुभव करते थे, कि जापान ने चीन में जिस युद्ध का प्रारम्भ किया है, उसके प्रभाव से बच सकता उनके लिये सम्भव नहीं रहेगा । इस युद्ध में जनकी राहात्मिति चीन के साथ थी और वे युद्ध सामग्री और धन द्वारा चियांग माई शेक की सहायता के लिये तत्पर थे।

राष्ट्रसंघ और चीन-जापान युद्ध-जिस समय जुलाई, १९३७ में चीन और जापान का युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो चियांग काई क्षेत्र की कुओमिन्तांग सरकार ने जापान के विरुद्ध राष्ट्रसंघ से अपील की। यह अपील राष्ट्रसंघ की ईस्टर्न एडवाइ-जरी कोन्टी (पूर्वी सलाहकार समिति) के सुपुर्व कर वी गई। कमेटी ने चीन और जापान के युद्ध पर भलीमांति विचार किया, और इस युद्ध के लिये जापान को दोगी ठहरावा,। उपने यह भी सिफारिश की, कि इस युद्ध का अन्त करने के लिये यह उपयोगी होगा, कि वालियन काल्करेन्स (१९२२) के परिणामस्वरूप नी राज्यों (अमेरिका, विरुप्त मा, बिल्या साम्राज्य, चीन, फांस, इटली, हालैय्य, पुर्वगाल और जापान) ने मिलकर जो सन्धि की विद्यान को खीनल किया था, उन्होंने एक दूसरे के प्रदेशों की अक्षुण्णता के विद्यान को खीनल किया था,

उन नौ राज्यों की एक कान्फरेन्स बुलाई जाय और यह कान्फरेन्स चीन और जापान की समस्या पर विचार करे। ६ अक्टूबर, १९३७ के अधिवेशन में राष्ट्रसंघ की एसेम्बर्ली ने ईस्टर्न एड्वाइजरी कमेटी की रिपोर्ट व सिफारियों को स्वीकार कर लिया। बेल्जियम की राजधानी असला में नी राज्यों की कान्फरेन्स का आयोजन विध्या गया, और ३ नवम्बर, १९३७ को उसका अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। जापान इस मान्फरेन्स में शामिल नहीं हुआ। संसार के अन्य प्रधान राज्यों में से जर्मनी और कस को भी इस कान्फरेन्स में शामिल होने का निमन्त्रण दिया गया था। जर्मनी इसमें शागिल नहीं हजा, वह अपने को चीन और जापान दोनों का मित्र समझता था और इस प्रयत्न में रुगा था कि उनमें सुलह कराई जाय । रूस गुसल्स कान्फरेन्स में वामिल हुआ। जापान की अनुपस्थिति के कारण यह सम्भव नहीं था, कि बुसल्स कान्फरेन्स सफल हो सके । उसमें चीन और जापान की समस्या पर विचार विधा गया, उन सिद्धान्तों को वियोरित किया गया, जिनका अनुसरण करके पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित की जा सकती है, और इसके लिये क्या कार्यवाई वावश्यक है, इस सम्बन्ध में भी शिफारियों तैयार कर ली गईं। २४ नवम्बर, १९३७ को असल्स कान्फरेना ने अपना कार्य समाप्त कर दिया, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला और चीन तथा जापान का यद पूर्ववत् जारी रहा । वस्तुतः इस समय तक राष्ट्रसंघ सर्वथा जित्तिहीन हो चुका था । संयुक्तराज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली और जापान जैसे वान्तियाली राज्य उससे पृथक हो चुके थे और संसार में शान्ति स्थापित रख सकाते के कार्य में राष्ट्रसंघ का कोई प्रभाव नहीं रह गया था। विविध राज्य अपनी रक्षा के लिये अपनी सैनिक शक्ति की वृद्धि में तत्पर थे और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किर से अराजनता का प्रादुमिन हो गया था। मई १९३६ तक एटली अफीका में अपने अच्छे बड़े साम्राज्य की स्थापित कर चुका था और अबीसीनिया के स्वतन्त्र राज्य (जो कि राष्ट्रसंघ का सदस्य था) को जीतकर अपने अधीन कर चका था । जर्मनी आस्ट्रिया और चेकोस्लोबाकिया को जीतकर अपनी अधीनता में लाने में ततार था और राष्ट्रसंघ इन साम्राज्यवादी देशों को नियन्त्रिन व गर्या-दित करने में सर्वथा अशक्त था। इस दशा में ग्रदि चीन में जापान के साम्राज्य प्रसार को रोकने में भी वह असमर्थ रहा हो, तो इसमें आक्चर्य की कोई काल् नहीं है।

राजनीतिक गुटबिच्यां—राष्ट्रसंघ से निराश होकर संसार के विविध राज्य अपनी रक्षा के लिये अपनी शैनिक शक्ति को बढ़ाने और आपस में गुट बनाने में सत्पर ये । जर्मनी, इटली और जापान का गुट इसी प्रवृत्ति का परिणाम था।

अन्य पारचात्य राज्य भी इस समय गुटवन्दियों के निर्माण में तत्पर थे। १९३४ में इस राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया था। फ्रांस और इस ने यह कोशिश की. ीं वि वे आपसमें भिलकर एवं ऐसासमग्रीताकर लें,जिसके अनुसार उन दोनों में से किसी पर यदि जर्मनी हमला नारे, तो दूसरा उसका साथ दे। वे चाहते थे, कि ब्रिटेन भी इस समझीते में शामिल हो जाय। जर्मनी की बढती हुई शक्ति इस समय यूरोण के राज्यों के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या थी । फ्रांस और रूस को उससे यहत भय था। पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जर्मनी की शक्ति से बहत चिन्तित नहीं थे। उनका विचार था, कि यूरोप में विविध राज्यों के समुत्तुलन को कायम रखने के लिये जर्मनी का शक्तिशाली होना आवश्यक है। चेकोस्ली-वाकिया, पोरुण्ड आदि पूर्वी युरोपियन राज्यों पर इस समय फांस का जिस ढंग से प्रभाव विद्यमान था, उसे जिटेन के राजनीतिज्ञ युरोप के शक्ति संतुळन के लिये हानिकारक समझते थे। यही कारण है, कि मई, १९३५ में इस और फांस ने परम्पर मिलकर जो गृट बनाया, ब्रिटेन उसमें शामिल नहीं हुआ। पोलैण्ड, चेकोस्लोबाकिया, कमानिया और यगोस्लाविया के साथ फांस की पहले ही पार-स्परिक सहायता की सन्चि विद्यमान थी। अब फांस के इस गृट में . इस भी बामिल हो गया । १९३६ में जर्मनी, जापान और इटली ने मिलगर अपने जिस गृट का विमाण किया था, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुने हैं। इस समय संसार के प्रमुख राज्य दो गुटों में संगठित हो गये थे। एक गुट का नेता जर्मनी था और इसरे का फांस । इन गृटों का आधार दो बातें थीं, एक तो विचारों और आदशींकी समानता और दूसरी हितों की एकता । इटली जर्मनी और जापान फैसिज्म के अनुपायी थे। ये राज्य अपने-अपने साम्राज्यों के विस्तार के लिये उत्सूक थे। अनको वसीय की सन्धि से समान रूप से शियायत थी और उसका उल्लंघन करके अपनी शनित की बढ़ाने में उनका एक समान लाम था। इसके विमरीत फांस, चेकीस्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि राज्यों को पेरिस की सन्धि परिपद द्वारा किये गये निर्णयों से बहुत लाभ पहुंचा था। उन निर्णयों की फायम रलने में उन सबना फायदा था। साथ ही ये राज्य स्रोकतत्त्रवाद के पक्षणाती थे। रूस में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण उसकी सामाजिक व आधिक व्यवस्था लोकतन्त्र राज्यों से भिन्न थी। पर उसका हित इसी बीत में था, कि इटली, जर्मनी और जापान का उत्कर्ष न होने पावे। जर्मनी की नाजी शक्ति रूस के कम्युनिज्य की विरोधी थी। यही कारण है, कि रूस में फैशिएए थानि। बों के खिलाफ कांग न उनके साथियों के पश में होना स्वीकार विधा । १९२६ के जन्म तम ब्रिटेन बोर अमेरिका इन टोनी पूर्वों से अलग रहे

थे। पर ब्रिटेन के लिये देर नक यूरीप के राजनीतिक दांव पेंचीं से अलग रह सकता सम्भव नहीं रहा । १९३६-३७ में यूरोप में युद्ध के बादल चिर्तु शक्त हो गये थे। स्पेन में जनरल फांको के उत्कर्ष के आरण सम्पूर्ण युरोप में सनसनी छा गई थी। फ्रेंच लोगों की इच्छा थी, कि स्पेन के गह-भलह में फांको के विरुद्ध वहा की रिपब्लियन सरकार की महायता करें। जर्मनी और इटली खुले तीर पर फांको की मदद कर रहे थे। पर ब्रिटेन यही उचित समझता था, कि स्पेन के आन्तरिक झगड़े में तटस्थता की नीति का अनगरण किया जाय। १९३७ और १९३८ में ब्रिटेन की यही कोशिश रही, कि युरोप के किसी यह में शामिल न हुआ जाय। पर जर्मनी और इटली की साम्राज्य विस्तार की नीति जो रूप धारण करती जाती थी, उससे ब्रिटेन का कल धीरे धीरे फांस की तरफ होता जाता था । अबीकिनिया की विजय के बाद इटली की यह आकांका थी, कि पूर्वी मुमध्यसागर पर भी उसका प्रभूत्व हो जाय और स्वेज की नहर के प्रबन्ध में भी उसका हाय रहे। ब्रिटेन यह सहन नहीं बर सकता था। परिणाम यह हुआ, कि ब्रिटेन का रुख इटली के खिलाफ ही गया। इनी बीच में जर्भनी ने आस्तिया और चेकोस्लोबाकिया का विजय किया। १९१४-१८ के महायद के बाद यरोप में जो व्यवस्था कायम हुई थी, उसके अनुसार बिटेन और फांस की कर्तव्य था, कि चेकोस्लोकिया के जर्मनी हारा विजय करने में वाशा उपस्थित करें। पर इस समय ब्रिटेन की यह नीति थी, कि गध्य गुरोप के बगड़ों से उसे पथक रहना चाहिये। ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री चैम्बरलेन ने यतन किया, कि फीस भी चैकोस्लोबाकिया के मामले में हस्तक्षेप न बारे। परिणाम यह हुआ, कि मध्य यूरोप में जर्मनी अपने प्रभृत्व का विस्तार करता गया और फांस, ब्रिटेन व रूस ने उसके मार्ग में बाबा नहीं डाली। पर ब्रिटेन देर तक अपनी तटस्थता की नीति का अनुसरण नहीं कर सका। आस्ट्रिया और नेकोस्लोकिया को जीत कर भी हिटलर की साम्राज्य पिपासा शान्त नहीं हुई। उसने शीध्र ही लियु-एनिया और पोलैन्ड की तरफ कदम बढ़ाया। अब युरोप की स्थिति ऐसी हो गई थी, कि ब्रिटेन को तटस्थता की नीति का परित्याग कर जर्मनी के खिलाफ फांस के पक्ष में शामिल होने के लिये विवध होना पड़ा ।

इस प्रकार १९२९ के शुरू तक संसार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दो पूज व गुट स्पष्ट रूप से विकसित हो गये थे। एक गुट में फांस, ब्रिटेन और रूस धार्मिल ये और दूसरे गुट में जर्मनी इटली और जापान थे। पूर्वी एशिया की राजनीति में इन गुटों का बहुत महत्त्व हैं, इसीलिये हमने उनका मंजिल प्रवाग उन्हें स्व ग्राम्स आवश्यक समझाहै। जिसप्रकार ब्रिटेन, रूस और फांस यूरोप में जर्मनी और प्रवाशिक साम्राज्य विस्तार से चिन्तात थे, वैसे ही ये राज्य पूर्वी एशिया में जापान के विस्तार को चिन्ता की वृष्टि से देख रहेथे। पर अशी संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप की गृट-विन्यों से पृथक था। इसमें सन्देह नहीं, कि उसकी सहानुभूति ब्रिटेन और फांस के पक्ष में थी और यूरोप में फैसिजम और साम्राज्यवाद के उत्कर्ष को वह संसार की शान्ति के लिये हानिकारका समझता था। पर अभी अमेरिकाने यह स्पष्ट नहीं किया था, कि वह जर्मनी और इटली के खिलाफ फांस और ब्रिटेन की सहायता किस रूप में और किस हद तक करने को तैयार है। यूरोप की अपेक्षा पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अमेरिका की दिल्चस्पी कहीं अधिक थी। इस क्षेत्र की घटनाओं के साथ अमेरिका अपना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध अनुभव करता था। यही कारण है, कि अमेरिका ने महायुद्ध (१९३९-४५) में पूर्वी एशिया के प्रश्न पर ही प्रवेश किया। यूरोप के महायुद्ध से लाभ उठाकर जब जापान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभृत्व की स्थापना के लिये प्रवृत्त हुआ, तभी अमेरिका भी खुले तार पर फैसिस्ट राज्यों के विरुद्ध बिटेन और फांस का पक्ष लेकार सुद्ध में शानिल हो गया।

🗦 (२) चीन में पाइचात्य देशों के प्रभावक्षेत्र और जापान

जिस समय जागानी नेनायें चीन में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिये तत्पर थीं, उस समय इस वेश में विश्वमान पारचात्य देशों के प्रभाव क्षेत्रों की क्या दशा थी, इस विषय पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका जापान की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था । चीन के अनेक बन्दरगाहों में पारचात्य देशों को व्यापार आदि की विशेष गुविधाएं प्राप्त थीं। शंघाई और तीन्तिमन में पाश्चात्य लोगों की अत्यन्त समृद्ध बस्तियां विश्वमान थीं और अन्यन कैन्टम आदि में भी पाक्चात्य व्यापारी वड़ी संस्था में विद्यमान थे। चीन के साथ की गई पुरानी सन्धियों के अनुसार अनेन स्थानों पर इन विदेशी राज्यों की शक्तिशाली सेनायें भी स्थापित थीं और यह सर्वथा स्वामाविक था, कि चीन-जागान के युद्ध के अवसर पर विदेशी राज्यों के इन प्रभाव क्षेत्रों पर भी युद्ध का असर एहे । युद्ध के समय यह असम्भव था, कि ब्रिटेन, अमेरिया, फांस, आदि भी सम्पत्ति गोलाबारी से सर्वथा सुरक्षित रहे भा उनका कोई नागरिक छड़ाई की चपेट में न आ जाय । जापानी सेनायें यह यहने फरती शीं, कि नीनी नेनाडों ने युद्ध के समय उनद्वारा पास्चात्य देशों के नागरिकों के , जान और भारतको मुक्तवान व पहुँचनै गावै । यह बहुधा चनका यह प्रयत्न सफ्ट नहीं होने पाता था ! इसंड कारण निम्निकन्ति मं, (१) वहन से पारवात्म

व्यापारी उन नगरों व प्रदेशों में बसे हुए थे, जहां युद्ध जारी था। युद्ध के समय यह असम्भव था, कि ये व्यापारी व अन्य विदेशी लोग लड़ाई की चपेट में न आ जावें। (२) शंवाई, तीन्तिसन आदि नगरों में विदेशियों की अनेश बस्तियी ऐसी थीं, जिनका प्रवन्ध व शासन भी विदेशी लोगों के ही हाथों में था । चीन के बहुत से गुरीला सैनिक जापानी सेनाओं से अपनी रक्षा करने के उद्देश्य से इन विदेशी वस्तियों में आश्रय के किते थे और क्योंकि इन विदेशी लोगों की सहानभति चियान काई क्षेक की सरकार के पक्ष में थी, अत: ये उन्हें सहर्ष आश्रय दे देतेथे। इस दशा में अनेक बार जापानी सेनाये चीन की विदेशी वस्तियों में हस्तक्षेप करने के लिये विवश होती थीं। (३) चीन-जापान युद्ध के कारण पाश्चात्य देशों के क्यापार को बहत नुकसान पहुंच रहा था। बहुधा विदेशी व्यापारी यह प्रयतन करते थे, कि वे जापानी सेनाओं के आदेशों की उपेक्षा कर चीन में अपने माल को गहचार्वे । इस दशा में जापानी सेनाओं के साथ उनका संघर्ष आयश्यवः हो जाता था। (४) अमेरिका, ब्रिटेन, और फांस चियांग काई शेक की सरकार को युद्ध सामग्री और धन की सहायता देते थे। यह सहायता हांगवांग से वायु गार्ग हारा, इन्डो-चायना से या उत्तरी बरमा से रेल और मोटर द्वारा पहुंचाई जाती थी । जापान स्वाभाविक रूप से यह यत्न करता था, कि यह सहायता चियांग का है शोक की सरकार की न पहुंचने पाने। इस कारण भी निदेशियों के साथ जापान ने संघर्ष के अवसर उपस्थित हो जाते थे।

पर साथ ही जापानी सरकार इस बात के लिये भी उत्सुक थी, कि चीन के आमले को लेकर उसका ब्रिटेन, फांस, अभेरिका आदि पाश्चात्य देशों के साथ युद्ध न शुरू हो जाय। इसीलिये जब इन पाश्चात्य राज्यों के जान व माल को चीन में जापानी सेनाओं द्वारा कोई नुकसान पहुंचता था, तो जापानी सरकार उसकी क्षित्र्यति का प्रयत्न करती थी। ब्रिटेन को क्षित्र्यति द्वारा संतुष्ट रखने की जापानी मरकार को उतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी कि अमेरिका को संतुष्ट रखने की जापानी मरकार को उतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी कि अमेरिका को संतुष्ट रखने की थी। जापान अनुभव करता था, कि ब्रिटेन उसका प्रतिरोध करने के लिये पर्याप्त वाबित नहीं रखता है। यूरोप में जर्मनी और उटली अपने साम्राज्य विस्तार के लिये जिस प्रकार मनमानी कर रहे थे, और ब्रिटेन उनके मार्ग में बाधा उपस्थित करने के लिये कोई भी प्रयत्न जो नहीं करता था, उससे जापान को विष्याप हो गया था, कि ब्रिटेन चीन में भी उसके मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। जैसेरिका की शक्त के सम्यन्ध में जापान का विचार दूसरा था। वह अनुभव करता था, कि प्रशान्त महासागर और पूर्वी एशिया के क्षेत्र के साथ अमेरिका का चिन्त सम्यन्ध है, और उसकी उपेक्षा कर सकता सम्भव नहीं हो। इसीलिये

१९३७ में चीन जापान के युद्ध के प्रारम्भिक काल में जापान उन प्रदेशों के विषय में पहले ही अमेरिका को सूचित कर देता था, जहां कि सैनिक कार्यवाई प्रारम्भ की जानवाली होती थी। अमेरिका भी इन प्रदेशों से अपने नागरिकों को हटा लेने की न्यबस्था कर देना था। १९३७ में जुलाई से नवम्बर तक चार महीनों में ५,००० से अधिक अमेरिकन लोगों को चीनके युद्धक्षेत्र से हटा लिया गया था। १२ दिसम्बर, १९३७ को जब कतिएय अमेरिकन जहाज नानिकम से अमेरिकन भागरिकों को ले जाने में तत्पर थे, वे जापानी सेनाओं की गोलावारी के शिकार हो गये और उनमें से चार डूब गये। अमेरिका में इस दुर्घटना से बहुत अधिका असन्तोष फैला, पर जापानी सरकार का कहना था, कि पनाई आदि इन चार जहाजों का ड्रबना एक आवस्मिक दुर्वटना है, और जापानकी सेनाओं ने जान बुझकर इन जहाजों पर हमला नहीं निया था। जापान की सरवगर ने इस दुर्घटना के लिये अमेरिका से वाकायवा धमा मांग ली और उसके लिये समिवत रूप सं क्षातिपूर्ति यारना भी स्वीकार कर लिया। अनेषा जापानी नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में इस घटना के लिये खंद प्रकाशित किया और अमेरिका की इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाई करने की आवश्यकता नहीं हुई। इसी प्रकार की जिन्य भी अनेवा घटनाएं इस समय युद्ध के कारण हुई, पर उनके कारण जापान और अभेरिका के सम्बन्धों में विशेष अन्तर नहीं आने पाया।

१९३९ में जब यूरोप में युद्ध के प्रारंभ होने की संभावना बहुत स्पष्ट हो गई, तो जानान बिदेशी राज्यों की और अधिय उपेक्षा करने लगा। १० फरवरी, १९३९ को हैनान हीए पर जापान ने अपना अधियार कर लिया। यह विशालकाय हीए हागकांग के दक्षिण और इन्होनायना के पूर्व में स्थित है। हैनान हीए चीन का ही एवा अंग था और इसके सम्बन्ध में चीन और फांस में यह सन्धि हो चुकी थी, कि इस हीए पर वे बिसी अन्य विदेशी राज्य वा प्रभुत्व नहीं होने देंगें। हैनान पर जापानी सेनाओं का प्रमुत्व हो जाने के बारण इन्होन्यायना में फांस की स्थित बहुत अधिया अमुत्वित हो गई थी। साथ ही ब्रिटेन के लिये भी हैनान पर जापान का बाब्जा बहुत अधिया हानिचारकथा। सिगापुर से हांगकांग जानेवाला सामुहिन मार्ग हैनान के समीप से होनार गुजरता था और इस हीए पर जापान का कब्जा हो जाने से उसके लिये यह बहुत सुगम हो गया था, कि वह हांगकांग जानेवाल बिहिश जहाजों पर आक्रमण कर सके। फांस और ब्रिटेन ने हैनान पर कब्जा कर लेने की बात पर आक्रमण कर सके। फांस और ब्रिटेन ने हैनान पर कब्जा कर लेने की बात पर आक्रमण कर सके। फांस और ब्रिटेन ने हैनान पर कब्जा कर लेने की बात पर अक्रमण कर सके। फांस और ब्रिटेन ने हैनान पर कब्जा कर लेने की बात पर आक्रमण कर सके। प्रांस और ब्रिटेन ने हैनान पर कब्जा कर सके की वी बात पर ब्रिटेन ने हैनान पर कब्जा कर लेने की बात पर ब्रिटेन ने हैनान पर कब्जा कर सके। इसके कुल दिन बाद जानानी रोनाओं ने स्पारंली ही समुह पर अपना अधिकार कर लिया। इन होनों पर जानानी रोनाओं ने स्पारंली ही समुह पर अपना अधिकार कर लिया। इन होनों पर जानानी रोनाओं ने

प्रमुख भी फांस और ब्रिटेन के लिये हानिकारक था, पर अपना विरोध व रोष प्रकट कर देने के अतिरिवत उनके सम्मुख अन्य कोई मार्ग नहीं था।

१९३९ के फरवरी मास के अस्तिम दिनों में जापान ने यह यहन किया. शंघाईकी अन्तर्राष्ट्रीय वस्ती के शासन में अपने अधिकार को ओर अधिक बढ़ाया जाय। चीन के बहुत से ग्रीला सैनिक इस बस्ती में आवार आश्रय ग्रहण करते थे और बहां रहकर जापानी सेना से अपनी रक्षा करने में समर्थ होते थे। जापान की स्वाभाविक रूप से यह उच्छा थी, कि वह इस वस्ती में चियाग कार्ड शेक की सरकार व यंनान की कम्यनिस्ट सरकार के पक्षपाती लोगों को आश्रय ग्रहण न करने दे। इसके लिये उसने शंघाई की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती के अधिकारियों पर यह जोर देना शरू किया, कि वे इस बस्ती के शासन में जापान का सहयोग प्राप्त करें और उस की इच्छा के अनुसार अपने शासन का संचालन करें। पर अमेरिका के विरोध के कारण उसे अपने उद्देश्य में अविक सफलता नहीं हो सकी। इसी प्रकार गई, १९३९ में कुलांग्सु द्वीप की अन्तर्राष्ट्रीय यस्ती को अपने प्रभाव में लाने के लिये जापानी सेनाओं ने प्रयतन किया । कुलांग्स् द्वीप अमीय के जन्दरगाह से कुछ दूरी पर स्थित है, और इसकी अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती में अमेरिकन, फेंच और ब्रिटिक लोगों की प्रमुखता थी। यहां पर भी कुओमिन्तांग वल के लोग आध्य ग्रहकी करते थे और जापान का प्रतिरोध करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। पर जापान की कुलांग्स द्वीप पर अपना प्रभूतव स्थापित करने में भी सफलता नहीं हो सकी, कारण यह कि अमेरिका, फांस और ब्रिटेन ने भी वहां अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ा दी और जापान के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह इन पाश्चात्य सेनाओं के साथ युद्ध विगये विना कुलांग्नु द्वीप को अपनी अधीनता में ला सके। शंघाई और कुळांग्स द्वीप की अन्तर्राष्ट्रीय बस्तियों के सम्बन्ध में जापान जिस नीति का अनुसरण कार रहा था, उससे यह स्पष्ट है, कि वह अमेरिका का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं करना चाहता था और उसकी यह नीति थी, कि जहां तक हो सके, पाश्चात्य राज्यों के साथ संघर्ष में आने से बचा जाय।

पाश्चात्य राज्यों के साथ संघर्ष का एक अन्य अवसर तीन्त्सिन की विदेशी विस्तियों के सम्बन्ध में उपस्थित हुआ। तीन्त्सिन बंदरगाह उत्तरी चीनके समुद्र तट पर स्थित है, और उत्तरी चीन पर १९३७ में ही जापान के प्रमृत्व की स्थापना हो चुकी थी। तीन्त्सिन में श्रिटिश और फेंच लोगों की दो बस्तियां थी, जिन्ही निवासी उत्तरी चीन पर जापान के प्रमृत्व की उपेक्षा करने में संकोच नहीं करते थे। इन बस्तियों में श्रिटेन और फांस के अनेक बैंक विद्यमान थे, जो बिदेशी विनिमय के लिये जापान की सरसा में विद्यमान पेकिंग सरकार द्वारा प्रचारित

मुद्रापद्धति को स्वीकृत नहीं करते थे। पेकिंग में जापान द्वारा फिडरल रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और यह बैंक उत्तरी चीन की मुद्रापद्धति का संचालन करता था । तीन्तिसन पेकिंग सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत था, पर उसकी ये विदेशी बस्तियां फिडरल रिजर्व वैंक द्वारा प्रचारित सिक्कों व नौटों की स्वीकार करने के बजाय चियांग काई शेक की कृशोमिन्तांग सरकार द्वारा प्रचारित मद्रापद्धति को स्वीकृत करने का आग्रह बारती थीं। साथ ही, इन विदेशी बैंकों के पास कुओ-मिन्तांग सरकार की बहुत सी चांदी व अन्य धन जमा या । अब क्योंकि तीन्तिसन के क्षेत्र में चियांग काई रोक के शासन का अन्त हो चका था और वहां एक नई चीनी सरकार की स्थापना हो गई थी. अतः स्वामाविक रूप से पेकिंग सरकार इस धन पर अपना अधिकार समझती थी । पर तीन्तिसन के ये ब्रिटिश और फेंच वैंक इस धन को कुओभिन्तांग सरकार की सम्पत्ति समझते थे और इसका उपयोग चियांगकाई शेक को युद्ध सामग्री पहुंचाने के लिये करना अपना कर्तव्य मानते थे। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था. कि जापान तीन्त्सिन की इन विदेशी बस्तियों को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करें। ९ एप्रिल, १९३९ में तीन्तिसन के तट-बार के प्रधान अधियारी की हत्या हो गई। यह अधिकारी चीनी या, और र्वेकिंग सरकार की ओर से तीन्तितन में नियनत था। इस चीनी अधिकारी के हत्याकारियों ने तीन्त्सिन की बिटिश बस्ती में आश्रय प्रहण किया। इस दशा में जापानी सेना ने तीन्तिसन की ब्रिटिश बस्ती के अधिकारियों से यह मांग की, कि वे इन हत्याकारियों को (जिनकी संख्या चार थी) गिरफ्तार करके जापानियों के सुपूर्व कर हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया । इस पर जून, १९३९ में जापान ने तीन्तिसन के ब्रिटिश अधिकारियों को यह चुनीती दी, कि यदि वे जापान की इस मांग को स्वीकृत नहीं करेंगे, तो तीन्तिसन की बिटिश बस्ती के सब मार्गी को अवस्त्र कर दिया णायगा । ब्रिटिश अधिकारियों ने जापान की इस चुनीती की कोई परवाह नहीं की । परिणाम यह हुआ, कि जापान के जंगी जहाजों ने तीन्सिन आने जाने के सामविक मार्ग पर कब्जा कर लिया। अब बिटिश जहाजों के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वे अपने माल की तीन्तिसन का सर्के व वहां से कोई माल बाहर किया सबा । जो बिटिश लोग तीन्तिसन से बाहर आते जाते थे, उनकी भी त्लाशी ली जाने लगी और वहां की शिटिय वस्ती में भीजर का पहुंच्या मी कठिन ही गया।

इस दक्षा में ब्रिटिश अधिकारियों की जापान के गाय समझौता करने के लिये विवश होना पड़ा । तीक्सी में समझौते की बातचीत शुरू हुई । यह समझौता कैंगी-अरीता समझौते के नाम में प्रतिद्ध हैं। इसके अनुसार ब्रिटेन के प्रतिनिधि श्री कैंगी ने इस बात को स्वीवार निया, कि जापान के लिये यह आवश्यक है, कि चीन में अपने अधिकृत प्रदेशों में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये अगर अपनी सैनिक आवश्यक ताओं को पूर्ण करने के लिये एसे कदम उठाये, जिनसे चीन में विद्यमान ब्रिटिश नागरिकों की स्वतन्त्रता में बाधा उगस्थित हो सके। इसी समझौते के अनुसार तीन्तिसन के ब्रिटिश अधिकारियों ने उन लोगों को भी जापान के सुपुदं कर दिया, जिनपर तट-कर के चीनी अधिकारी की हत्या करने का सन्देह था। इन हत्याकारियों को जापान के मुपुदं करने के मामले में ब्रिटेन को बहुत नीचा देखना पड़ा था। उसने यह बहुकर सन्तीप कर लिया था, कि और अधिक खोज के बाद इस बात के प्रमाण मिल गये हैं, कि वस्तुतः इन अभियुक्तों का चीनी अधिकारी की हत्या में हाथ था।

चीन में विश्वमान पाइचात्य देशों के अधिकार क्षेत्रों के सम्बन्ध में जैसी समस्याएं शंघाई, तीन्तिसन और कुलांग्यू में उत्पन्न हुई थीं, वैसी ही स्वातो, वें छतो, फूचो आदि में भी प्रादुर्भृत हुई थीं। इन सब स्थानों पर पाइचात्य देशों की वस्तियां थीं और उनमें विदेशी लोग अच्छी बड़ी संख्या में नियास करते थे। चीन पर अपना प्रमुत्व स्थापित करते हुए जापान को इन चिदेशियों के प्रति बहुत सावधार्णे से बरतना पड़ रहा था। यह जानते हुए भी कि ये थिदेशी लोग नियांग काई शेष की सरकार के साथ पूर्ण रूप से सहानुभूति रखते हैं, और हर प्रकार से उसकी सहायता करने को ज्वान रहते हैं, वह खुले तीर पर उनके विरुद्ध वार्यवाई नहीं कर सकता था।

(३) अमेरिका और जापान

इस अध्याय में हमपहलेलिख चुने हैं कि, पूर्वी एशियाऔर प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के हित आपस में टकराते थे। पूर्वी एशिया में जापान जिस नीति का अनुसरण कर रहा था, उस पर भी हम पहले प्रकाश डाल चुने हैं। जापान की चीन सम्बन्धी नीति के मुख्य आधार निम्निलिखत थे-(१) चीन में चियाग काई शेक के नेतृत्व में विद्यमान कुओमितांग सरकार के स्थान पर ऐसी चीनी सरकार की स्थापना की जाय, जो जापान के साथ सहयोग करने को तैयार हो, और जो जापान को अपना शत्रुन समझकर खें अपना मित्र, संरक्षक व सहयोगी माने। (२) चीन में पाश्चात्य देशों ना जो प्रभाव व प्रभुत्व है, उसका अन्त किया जाय। न केवल चीन में अपितु पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों से भी पाश्चात्य देशों के साम्राज्यों का अन्त कर उन्हें स्वतन्त्र

षिया जाय और ये स्वतन्त्र हुए एशियन देश जापान के सहयोग और संरक्षण में अपनी शासन नीति व आर्थिक व्यवस्था का संचालन करें। (३) चीन और जाधान मिलकर पूर्वी व उत्तरी एशिया में वास्य निज्य का मुकावला करें। बैकाल की बील के पूर्व में रूस अपनी शक्ति का विस्तार न कर सके। जापान, जर्मनी और इटली के साथ मिलकर एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट बना चुका था, अतः स्वाभाविक हप से वह नाम्यनिज्य का विरोधी था और इस कार्य में वह चीन के सहयोग की आशा रखता था। (४) चीन में व्यापार व आर्थिक विकास के लिये पादचात्य देशों को जो ख्ली छ्टटी भिली हुई है, उसका अन्त किया जाय। मञ्चक्यो. आभ्यन्तर मंगोलिया, चीन और जापान मिलवार एवा आर्थिया गृट (इलाका) का निर्माण करें। यह गुट आधिक दृष्टि से अपने आप में आत्म-निर्भर रहे और किसी अन्य देश की सहायता पर निर्भर न करे। चीन, भञ्चूकुओं और मंगं लिया में किसी अन्य देश की अपनी पूंजी लगाने व इनका आधिक विकास करने का अधिकार न रहे, और यदि किसी देश को इस कार्य के लिये अनुमति दी जाय, तो वह जापान की सहमति से । इस आधिक नीति में चीन को भी लाभ होगा, क्योंकि जापान उसके आधिक विकास के लिये सब आवश्यक पंजी जटा सकेगा। राजनीतिक दिस्टि से भी यह बात चीन के लाम की होगी, क्योंकि जापान की सैनिक शक्ति सदा चीन की रक्षा व सहायता के लिये तत्वर रहेगी।

जापान चीन सम्बन्धी अपनी नीति की 'नई व्यवस्था' (न्यू आईर) के नाम से कहता था। यह यह भी कहता था, कि वार्यिगटन कान्फरेन्स द्वारा चीन के विषय में जिस नीति का प्रतिपादन किया गया था, वह अब क्रियात्मक नहीं रह गई हैं। १९२२ के बाद संसार की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बहुत अंतर आ चुझा है, और पूर्वी एशिया में अनेक ऐसी नई बातें उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण अब वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा निर्धारित नीति पुरानी पड़ गई है। पर संयुक्त राज्य अमेरिया इस बात से सहमत नहीं था। उसका कहना था, कि यह बात ठीका है, कि १९२२ के बाद से पूर्वी एशिया की स्थिति में बहुत अन्तर आ गया है, पर इस अन्तर लाने की प्रधान उत्तरदायिता जापान के ऊपर है। जापान ने पिछले वर्षों में चीन के सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया है, उसके कारण चीन की राजनीतिक दशा बहुत कुछ परिवर्तित हो गई है। पर अमेरिका इस बात'को स्वीकार नहीं के सम्बन्ध में, जो कि उसकी अधीनता में नहीं है, या जिन पर किसी भी अन्य स्वतन्त्र सरकार का शासन है, स्वयं विधायक बन जाय और उनके भाग्य का निर्णय अपनी इच्छा के अनुसार करने लगे। अमेरिका की इस

नीति का स्पष्ट अभिप्राय यह था, कि वह जापान की 'नई व्यवस्था' का प्रवल विरोधी था और चीन में उसे स्थापित नहीं होने देना चाहता था।

चीन में जानान द्वारा स्थापित नई व्यवस्था का विरोध करने के लिये अमेर्सिक केसम्मुखयही उपायथा, किवह चियांगकाई शेक की सरकारकी अधिक से अधिक सहायता करे। उसीलिये १५ दिसम्बर, १९३८ की उसने नियांग काई शेंक की सरकार की मदद के लिये २,५०,००,००० डालर अलग कर दिये। इसी समय ब्रिटेन ने कुओमिन्तांग सरकार की सहायता के लिये ६०,००,००० रुपये के लगभग रकम प्रदान की। बरमा रोड इस समय तक बन कर नैयार हो चुकी थी और विक्षणी चीन के युनान प्रान्त से मोटर मार्ग द्वारा चुंगिकंग सरकारको युद्ध सामग्री की सहायता पहुंचाई जा सकती थी। ब्रिटेन ने ये साठ लाख रुपये चीन को इसी उद्देश्य से दिये थे, कि वे इनसे मोटर गाड़ियां खरीदकर युद्ध सामग्री को हो सकते में समर्थ हो। १९३८ का अन्त होने से पूर्व ही अमेरिका और ब्रिटेन घन ब्राश चियांग काई शेक सरकार की स्पष्ट रूप से सहायता करने को तत्पर हो गये थे। अमेरिका और ब्रिटेन पहले भी कुओमिन्तांग सरकार की युद्ध सामग्री व धन द्वारा सहायता कर रहे थे, गर १९३८ के बाद इस सहायता में और भी अधिक विद्व हो गई। बरमा रोड के निर्माण के कारण अब इन देशों के लिये यह मुगम हो गया की वे चुंगिक ग को युद्ध सामग्री भेज सकें। पहले इस रारकार को मुख्य रूप से सहायता इस द्वारा प्राप्त होती थी, पर बरमा रोड के तैयार हो जाने पर अमेरिका और ब्रिटेन चंगिक्स की सहायता के लिये पूर्ण रूप से कटियदा हो गये और इन देशों से युद्ध सामग्री प्रचुर परिमाण में चियांग काई शेक की सेनाओं को पहुंचने लगी। १९३९ में जब युरोप में महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, तो उसना असर पूर्वी एशिया पर क्या पड़ा, इस पर हम अगले प्रकरण में विचार करेंगे, पर महायुद्ध में जर्मनी और इटली जिस ढंग से सफल हो रहे थे, उससे अमेरिका बहत निन्तित था। १९४१ तक वह स्वयं महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था, पर वह युरोप की फैसिस्ट शक्तियों के खिलाफ मित्रराष्ट्रों की युद्ध सामग्री व घन द्वारा सहायता करना रहा। इसके लिये उसने 'लीज-लैण्ड बिल' नाम रो एक बिल अपनी कांग्रेस (पालियागेन्ट) में स्त्रीकृत किया, जिसका उद्देश्य उन राज्यों की युद्ध सामग्री और धन से सहायता करना था, जिनकी रक्षा अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिये आवश्यक थी। इस बिलके अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया 🖏 वह इस प्रकार के राज्यों को कितनी सहायता दी जाय और यह सहायता किन शर्ती पर दी जाय, इसका निश्चय कर सके । यह बिल जनवरी, १९४१ में स्वीकृत हुआ था। इसके अनुसार जहां युरोप में ब्रिटेन, फ्रांस आदि को अमेरिका द्वारा

सहायता दी गई, यहा साथ ही चीन की चुंगिंग सरकार को भी प्रभूत परिमाण में युद्ध सामग्री और धन की सहायता देने की व्यवस्था की गई। जापान ने अमेरिका की इस सहायता को अपने लिये अत्यन्त हानिकारक समझा और इससे अमेरिका के साथ जसके सम्बन्ध बहुत अधिक विगड़ गये। पर जापान अब भी यही चाहता था, कि अमेरिका के साथ उनके सम्बन्ध अधिक न बिगड़ने पायें। उसका ख्याल था, कि पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान और अमेरिका के हितों में इतना अधिक विरोध नहीं है, कि उसके कारण इन दो देशों में युद्ध की आवश्यकता हो। इस बात को दृष्टि में रखकर जापान ने अमेरिका के साथ सन्धि की जो बातचीत बुक्ष की, उसका उन्लेख हम इसी अध्याय में आगे चलकर करेंगे।

(४) महायुद्ध और जापान

सितम्बर, १९३९ में पोलैण्ड के प्रश्न पर यूरोप में महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया। जर्मनी चाहता था, कि आस्ट्रिया और चेको-स्लोबाकिया के समान पोलैण्ड को भी अपने प्रभुत्तव में ले आवे । उसे भरोसा था, कि ब्रिटेन आदि अन्य यूरोपियन राज्य इस मामले में भी उसके विरुद्ध लड़ाई के लिये तत्पर नहीं होंगे। पर जर्मनी यरोप 躇 जिस ढंग से अपनी सक्ति का विस्तार कर रहा था, उसे अब ब्रिटेन अधिक सहन नहीं बार रामता था । परिणाम यह हुआ, कि पोलैण्ड के प्रका पर यूरोप के फैसिस्ट राज्यों और लोकतन्त्र राज्यों में युद्ध का प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध का वृत्तान्त यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि शी झ ही पोलैण्ड के बड़े भाग पर जर्मन सेनाओं का कब्जा हो गया / कुछ ही महीनों में नार्वे, डेन्मार्क, होलैण्ड, बंल्जियम और फांस जर्मनी के अधिकार में आ गये। फांस की सहायता के लिये जो जिटिश सेनाएं यूरोप आई हुई थीं, उन्हें बड़ी मठिनता से ब्रिटेन वापरा और जाने में सफलता हुई। कुछ समय ने लिये ऐसा प्रतीत होने लगा, कि जर्मनी की शक्ति अजय है, और यूरोगका कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यरोप के महायद्ध की इन घटनाओं का प्रभाव पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया पर पहना आवश्यक था'। इस क्षेत्र में हालैण्ड, फ्रांस और ब्रिटेन के जो सुविस्तृत साधाज्य विद्यमान थे, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। हालैण्ड और फांस पर जर्मनी का प्रभत्त्व स्थापित हो चुका था, अतः उनके लिये यह सम्भवनहीं था, कि वे एशिया के अपने साम्राज्यों की रक्षा कर सकें। फांस की इन्डोनायना में और हालैएड की इन्डोनीसिया में अपनी अपनी पृथक अराजरें थी, पर ३न सरकारों की धैकिस बनित इतनी अविक नहीं थी, कि वे जातान जैने सन्तिकाली देश का मुकावला धर सकतीं। ब्रिटेन पर अमंनी का कब्जा नहीं हुआ था, पर तस पर अमंनवानुसेना इतनी तीवता के साथ आक्रमण कर रही थी, कि ब्रिटेन के लिये अपनी रक्षा कर सकत सुगम कार्य नहीं रहा था। इस स्थिति में उसके लिये भी यह मुगम नहीं था, कि का सुदूरपूर्व में विद्यान अपने सुविस्तृत साम्राज्य की रक्षा पर विशेष ध्यान दे सके महायद्ध ने ऐसी पिरिस्थितियां उत्पन्न कर दी थीं, जो जापान के लिये एक सुदर्णीय अवसर के समान थीं। इनका उपयोग कर जापान पूर्वी व दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी नई व्यवस्था की स्थापना कर सकता था, जिसका उद्देश इन प्रदेशों में पाश्चात्य साम्राज्यवाद का अन्त कर उनमें ऐसी सरकारों की स्थापना करना था, जो जापान को अपना भित्र, सहयोगी और संरक्षक समझें और जो जापान की सहमति से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय य आर्थिक नीति का संचालन करें।

कस के साथ सन्धि-जापान की इस आकांक्षा के पूर्ण होने में गदि किसी शक्ति-शाशी राज्य से विशोध की सम्भावना हो सकती थी, तो वह रूस था। रूस भी कम्मिनस्ट व्यवस्थां से जापान का विद्वेष था। कृषी सरकार येनान की कम्प-भिस्ट सरकार की सहयाता के लिये तत्पर थी। जर्मनी और इटली के साग भिलकर जापान ने १९३६ में जिस एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट का निर्माण किया था, उसका उद्देश्य भी संस्पृतिज्य का विरोध करना था । इस स्थिति में यदि जागान दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी नई व्यवस्था की स्थापना के लिये उद्योग करता, तो उ कुस के विरोध की प्रवल आशंका थी । अतः उसने यह आवश्यक समझा, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभूत्व का विस्तार करने से पूर्व इस की ओर से निविचन्त हो लिया जाय । इससे पूर्व २३ अगस्त, १९३९ को महायुद्ध के प्रायम्भ से कुछ दिन पहले जर्मनी ने भी रूस के साथ एवा सनझौता कर लिया था, जिलका प्रयोजन यह था, कि जर्मनी और रूस एक दूसरे पर आक्रमण न करें। जर्मनी भध्य यूरोप में जिस ढंग से अपनी शनित का विस्तार कर रहा था. उससे उसे यह सर्वथा स्कट था. कि फांसऔर ब्रिटेन के साथ उसका युद्ध अवश्यम्मावी है। इस दशा में स्त्राभाविक रूप से उपकी इच्छा थी, कि वह रूंस के साथ युद्ध की सम्भावना को दूर करने की व्यवस्था कर दें। इसीलिये उसने अगस्त, १९३९ में रूस के साथ समझौता पर लिया था। यह समझौता १९३६ के एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट के सर्वया विगरीत था, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों ने इस समय रूस और जर्मनी को एक सूत्र में बांध दिया था । रूस और जर्मनी के इस समझौते के कारण पूर्वी एशिया में जालत की स्थित और भी अधिक अरक्षित हो गई थी, क्योंकि अब रूम की सेनाओं की युरोप से बहुत बुछ छट्टी मिल गई थी और उन्हें जर्मनी के आक्रमण का भय नहीं रह गया था । अब रूस अपनी सैन्यशनित की पूर्वी एशिया में केन्द्रित कर सकता था और वहां जापान की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतिरोध कर सकता था। अता

जापान के लिये यह और भी अधिक आवश्यक हो गया था, कि वह दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी शिक्त का विस्तार करने से पूर्व रूस की तरफ से निश्चिन्त होने का प्रयत्न करें? । इसी उद्देश्य से १९४१ के प्रारम्भ में जापान के परराष्ट्र मन्त्री श्री मत्सुओका ने यूरोप की यात्रा की । इस यात्रा के सिलिसिले में श्री मत्सुओका मास्को भी गये और वहां उन्होंने १३ एप्रिल, १९४१ के दिन रूस के साथ एक सिच्च की, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—(१) रूस और जापान दोनों एक दूसरे की सीमाओं को अनुलंघनीय मानते हैं, और इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, कि वे एक दूसरे की मीमाओं का व्यावात करने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे । (२) इस मञ्जूकुओ पर जापान के प्रभावक्षेत्र को मतिलता हैं। (३) यदि कोई अन्य राज्य रूस या जापान के साथ युद्ध में व्यापृत हो जाय, तो इस युद्ध में रूस और जापान उस राज्य की सहायता नहीं करेंगे और तटरथ नीति का अवलम्बन करेंगे।

जापान की दृष्टि ने यह सन्धि अल्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। इसके अनुसार उसे यह भरोसा हो गया था, कि यदि पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के मामले पर उसका अमेरिका के साथ युद्ध प्रारम्भ हो जाय, तो कम से काम रूस इस युद्ध में तटस्थ रहेगा और जापान का उन दो प्रवल अक्तियों का एक साथ मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे दक्षिण-पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था' स्थापित करने के उद्देश्य में जापान का मार्ग बहुत कुछ निष्कलक हो गया था। रूस के लिये भी यह सिन्ध बहुत लाभदायक थी। उसे अथ यह भरोसा हो गया था, कि यदि मविष्य में जर्मनी के साथ यूरोप में उसका संघर्ण शुरू हो, तो उसे दो मोरचों पर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एशिया में जापान इस स्थित से लाभ उटाकर उसके बिलाफ लड़ाई शुरू नहीं कर देगा, इस विषय में वह निश्चित्त हो गया था। इस प्रकार रूस की ओर से निश्चित्त होकर जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी नई व्यवस्था को नायम करने के लिये प्रवृत्त हुआ। जापान को दक्षिण-पूर्वी एशिया में जा असाधारण सफलता हुई, उसमें एप्रिल, १९४१ का यह समझीता (रूस और जापान की परस्पर अनाक्रमण विषयक सन्धि) एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

इन्हो चायना और जापान जून, १९४० में जर्मनी की सेनाओं ने पेरिस पर किना कर लिया था। जर्मनी के संरक्षण में मार्शल पेतां के नेतृत्व में फांस में ऐसी सरकार कायम कर दी गई थी, जो नाजी लोगों की नीति का अनुसरण कर देश था शासन करने की तैयार थी। इस दशा में इन्होचायना की फेब्च सरकार के सम्मुख एक विकट समस्या उपस्थित हुई, पर तहां के फेब्च शासनों ने यही उचित समझा, कि वे मार्शल पेतां का अनुसरण करें और उसकी नीति की अपनावें। जापान ने इन्होचायना की सरकार की निर्वेलता से लाभ जठाया और उसे निम्न-लिखित बातों को मानने के लिये विवश किया--(१) इन्होचायना से कोई युद्ध सामग्री चुर्गावाग सरकार को न पहुंचाई जा सके। जापानी सरकार को अधिकार हो, कि वह इस सम्बन्ध में निरीक्षण रख सके। (२) बरमा रोड द्वारा जो युद्ध सामग्री चुंगविल सरकार को पहुंचाई जा रही है, उसमे वासुमार्ग द्वारा वाधा उपस्थित करने के लिये जापान इन्डोचायना के हवाई अड्डां को प्रयुक्त कर सके। कुछ समय बाद जापान ने इन्डोचायना की सरकार से यह अधिकार भी प्राप्त कर लिया. कि वह इन्डोचायना के प्रदेश में अपनी सेनाएँ भेज सके और वहां से उन्हें चुंगिंका सरकार के विरुद्ध लड़ाई के लिये प्रयुक्त कर सके। साथ ही, इन्डोचायना की सरकार ने जापान को यह अनमति प्रधान कर दी, कि उसके हवाई अङ्डों को चियांग काई शेक की सेनाओं के साथ संघर्ष के लिये प्रयोग में ला सके। फांस इस समय हिटलर की सेनाओं द्वारा परास्त किया जा चुका था। उसकी सैन्य-शिनत छिन्न-भिन्न हो चकी थी। पेरिस पर जर्मनी का कब्जा था। मार्शल पेतां के नेतृत्व में विशी की राजधानी बनाकर जो स्वतन्त्र फेञ्च सरकार कायम हुई थी, वह पूर्ण-तया जमेंनी की बशवतीं थी। इन्डोचायना की फेञ्च सरकार विशी की सरकार के अधीन थी, अतः स्वाभाविक रूप से वह अर्धनी के मित्र जापान की मांगों की उपेक्षा नहीं कर सकती थी।

इन्डोनीसिया और जापान—दक्षिण-पूर्वी एशिया में हाळेण्ड का जो सुविस्तृत साम्राज्य विद्यमान था, उसे इन्डोनीसिया कहते हैं। पहले उसे 'डच ईस्ट
इन्डीज' कहा जाता था। आर्थिक और व्यापारिक वृष्टि से जापान का इसने साथ
घनिष्ट सम्बन्ध था। जापान का तैयार माल बहुत बड़ी मात्रा में इन्डोनीसिया के
विविध द्वीपों में बिकता था और जापान इन द्वीपों से पेट्रोलियम, रबड़, टीन आदि
प्रचुर मात्रा में क्रय करता था। अमेरिका के साथ जापान के राजनीतिक सम्बन्ध
निरन्तर विगड़ते जाते थे, और अब उसके लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि पेट्रोलियम आदि की अपनी आवश्यकताओं को अमेरिका से सुविधापूर्वक प्राप्त कर सके।
अतः जापान की स्वाभाविक रूप से यह इच्छा थी, कि इन्डोनीसिया के साथ अपने
जावसायिक सम्बन्धों को और अधिक वृद्ध करे। वस्तुतः जापान सम्पूर्ण दिक्षणपूर्वी एशिया को उसी प्रकार अपने प्रभाव में ले आना चाहता था, जैसे कि वह मर्क्युकुओ को अपने प्रभाव व संरक्षण में ले आने में समर्थ हुआ था। जापान इस प्रदेश
को 'वृहत्तर पूर्वी एशिया' के नाम से कहता था और उसकी यह इच्छा थी, कि मञ्चुकुओ, आम्यन्तर मंगोलिया, चीन, इन्डोनीसिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य

देशों को मिलाकर एक ऐसा गुट या ब्लाक वनाया जाय, जो जापान को अपना सहयोगी व संरक्षक माने । यही कारण है, कि जर्मनी द्वारा हालैण्ड पर अधिकार स्मापित करने के गृछ समय पहले जापान के परराष्ट्र मंत्री श्री अरीता (जो श्री मत्सओका से पूर्व इस पद पर विराजमान थे) ने इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में निम्न-लिखित नीति का प्रतिपादन किया था—"दक्षिणी समुद्र के क्षेत्र के साथ और विशेषतया नीदरलैण्ड्स ईस्ट इन्डीज के साथ जापान का बहुत अधिक घनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध है, और ये एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये परस्पर सम्बद्ध हैं। पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ भी इन प्रदेशों का धनिष्ठ आर्थिक सम्बन्ध निद्यमान है। इसका अभिप्राय यह है, कि जापान और ये सब देश व प्रदेश पारस्परिक सहायता और अन्योन्याश्रयिता द्वारा पूर्वी एशिया की समृद्धि में सहायक हैं।" इसी प्रसंग में श्री अरीता ने यह भी स्पष्ट किया, कि यदि यूरीप में यद्ध की प्रगति के कारण नीदरलैण्ड ईस्ट इन्डीज (इन्डोनीसिया) की स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर आयगा, तो जापान उसकी उपेक्षा नहीं कर सकेगा । श्री अरीता को भयथा, कि जब जर्मनी हालैण्ड पर कब्जा कर लेगा, तो नीदरलैण्ड की अधीनता में विद्यमान ईस्ट इन्डीज की राजनीति का संचालन मित्रराष्ट्र व अमेरिका इस ढंग से पारने वा। प्रयत्न वारंगे, जिससे कि जापान इस देश के पेट्रोल, रबड़, टीन आदि का उपयोग न कर सके, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जापान की जर्मनी और इटली के साथ सन्धि थी । इसी आशंका की दिष्ट में रखकर जापान पहले ही अपने इस द ब्टिकोण को स्पब्ट कर देना चाहता था।

अमेरिका का एक यूरोप के महायुद्ध द्वारा जो नई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित उत्पन्न हो रही थी, अमेरिका भी उससे चिन्तित था। वह मलीमांति अनुभव करता था, कि जापान इसका उपयोग अपने उत्कर्ष के लिये कर सकता है, और वह हालैण्ड, फांस व ब्रिटेन के संबाद का लाभ उठाकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को सुगमता से अपने प्रभाव में ला सकता है। इसीलिये उसने अपनी यह नीति सर्वथा स्पष्ट कर दी, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में जो प्रदेश जिस रूप में हैं, जो देश जिस किसी राज्य के अधीन हैं, उन्हें वैसे ही रहना चाहिये, उनकी राजनीतिक स्थितिमें कोई अन्तर नहीं आना चाहिये। अपनी इस नीति को क्रिया में परिणत करने के लिये अमेरिका ने निम्निलिखत उपायों का अवलम्बन किया—(१) जापान अमेरिका से जो युद्ध-सामग्री मंगाता था, उसे देना बन्द कर दिया गया। केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, अपितु पेट्रोल, लोहा आदि जो वस्तुएँ युद्ध के लिये सहायक ही सकती थीं, उन्हें जापान को बेचना व पहुंगाता रोग दिया गया। (२) चीन में महासेनापित चियाग काई श्रोब की सरकार को वी जानेवाली सहायन की मात्रा पहले की। अपेका

बहुत बढ़ा दी गर्ड, ताकि अब वह अधिक प्रबलता से जापान के साथ युद्ध को जारी रख़ सके और जागान की अच्छी बड़ी मैन्यशक्ति चीन में उलक्षी रहे। (३) ब्रिटनको युद्ध सानग्री और धन की सहायता बहुत बड़ी मात्रा में दी जाने लगी, ताकि यूरोपिक रणक्षेत्र में फैसिस्ट राज्य सफल न हो सकें और ब्रिटेन उनका सफलता के साथ मुकाबला कर सके।

अमेरिका की इस नीति का यह परिणाम हुआ, कि वह शक्तिशाली देश महा-युद्ध के मैदान में उतर आया । यद्यपि उसकी मेनाएं फैरिस्ट अवितयों के साथ युद्ध करने के लिये अभी लड़ाई में शामिल नहीं हुई थीं, पर कियात्मक दृष्टि में अमेरिका ब्रिटेन, फ्रान्स आदि लोकतन्त्रवादी देशों को सब प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिये तत्वर हो गया था । यद्यपि महायुद्ध में अभेरिका की सहानुभृति शुरू में ही भित्र राष्ट्रों के पक्ष में थी, पर १९४० के मध्यभाग में, जब कि फांस जर्मनी द्वारा बरी तरह से परास्त कर दिया गया था और जर्मन हवाई जहाज बडी तेजी के साथ ब्रिटेन पर गोलाबारी करने में तत्पर थे, अमेरिका ने अपनी शनित भर मित्रराष्ट्री की सहायता करनी प्रारम्भ कर दी थी। अमेरिका जो इस समय खुले तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं हो गया था, उसके दो कारण थे-(१) अमेरिका का लोकमत अभी तक यह में शामिल होने के लिये पूरीतिरह रेतियार नहीं था। यूरीप के अगूडि में हस्त क्षेप न करने की नीति के कारणही अमेरिका राष्ट्रसंघ से पृथक् हुआ था और इस समय भी वहां ऐसे राजनीतिक नेताओं की कमी नहीं थी, जो अपने देश को युद्ध रो पृथक् रखना ही राष्ट्रीय हित की दिष्ट से उपयोगी समझते थे । (२) अमेरिका के राजनीतिक व सैनिक नेता यह भी अनुभव करते थे, कि अभी अनकी सेना यह के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं है । जर्मनी, इटली और जापान की फैरिस्ट सरकारें विछले परा सालों से युद्ध की तैयारी में तत्पर थीं और इस सगय में संसार के अन्य मीमतः य राज्यों के समान अमेरिका ने भी अपने सैनिक उत्कर्ष पर विश्लेष ध्यान नहीं दिय स्था अतः इस समय अमेरिका युद्ध की तैयारी के लिये अपनी पूर्णशक्ति के साथ तत्पर था, और वह पूरी तैयारी किये बिना लड़ाई में दामिल होने में संकोच करता था।

इटली, जर्मनी और जापान की संनिक सन्धि अमेरिया जिस हंग से ब्रिटेन, फांम आदि भित्र राष्ट्रों की सहायता के लिये कटिबढ़ था, उससे फैसिस्ट राज्यों के लिये यह समझ सकता कठिन नहीं था, कि वह समय दूर नहीं है, जब कि अमेरिक खुले तौर पर लड़ाई में शामिल हो जायगा। इटली, जर्मनी और जापान का गुट १९३६ में ही बन चुका था। अब २७ सितम्बर, १९४० को इन राज्यों ने परस्पर मिलकर एक सैनिक सन्धि की, जिसके अनुसार उन्होंने निश्चय किया कि (१) यदि

अमेरिका पूर्वी एशिया व प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जापान के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर या उन्होंनीसिया पर जापान हारा कब्जा करने के रास्ते में बाधा डाले, तो जर्मनी ओर इटली अटलाण्टिक महासागर के क्षेत्र में उसके विरुद्ध लड़ाई शुरू कर देंगे। (२) इसी प्रकार यदि अमेरिका ब्रिटेन को स्पष्ट रूप से सैनिक सहायता देने लगे, तो जापान प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में उसके खिलाफ युद्ध प्रारम्भ कर देगा। इटली, जर्मनी और जापान की यह सैनिक सन्धि बहुत अधिक महत्त्व रखती है। इसके अनुसार जापान को यह भरोसा हो गया था, कि यदि वह दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व के विस्तार का उद्योग करेगा, तो अमेरिका अपनी सम्पूर्ण शविन को उसके खिलाफ प्रयुक्त नहीं कर सकेगा। अमेरिका को अपनी अच्छी बड़ी जलमेना अटलाण्टिक महासागर में भी रखनी होगी और वह अपनी जो जलसेना प्रशान्त महासागर में प्रयुक्त कर सकेगा, उसमे जापान को विशेष भय नहीं होगा।

सितम्बर, १९४० की इस सिन्ध के कारण पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापात की स्थिति बहुत अधिक सुरक्षित हो गई थी। इस क्षेत्र में जापात की अमे- क्षित के अतिरिक्त रूस से भी मयथा। उसके हस्तक्षेप से निश्चिन्त होने के लिये ही उसैंने एपिल, १९४१ में रूस के माथ तटस्थता की जो सिन्ध कर ली.थी, उसका उल्लेख हम इसी प्रकरण में गहले कर चुके हैं। अमेरिका और रूस दोनों के मुकाब लेमें अपनी स्थिति को मजबूत कर लेने के बाद जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी कितनी स्थित को मजबूत कर लेने के बाद जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी कितनी सावधानी व बुद्धिमानी के साथ कदम बढ़ा रहा था, इसे अवगत करने के लिये थे दोनों सन्धियां पर्याप्त हैं।

अमेरिका के साथ सन्धि का प्रयत्न १९४१ के गुरू तक अमेरिका यह अन्तिम कप से निश्चय कर नुका था, कि फैसिस्ट शिक्तयों के विरुद्ध मित्रराष्ट्रों की पूर्णरूप से सहायता की जाय। वह अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, पर उसने युद्ध में तटस्थता व उदासीनता की नीति का परित्याग कर विया था। वह समझता था, कि लोकतन्त्रवाद के अनुयायी मित्रराष्ट्रों के लिये अस्त्रागार का कार्य करके वह उन्हें अच्छी तरह से सहायता पहुंचा सकता है। इसीलिये उसने जनवरी, १९४१ में क्षिज-लैन्ड बिल स्त्रीकृत किया था, जिसके अनुसार राष्ट्रपति रूजवेल्ट को यह अधिकार दिया गया था, कि वह फैसिस्ट राज्यों के साथ संघर्ष करने वाले देशों का युद्ध सामग्री और धन की सहायता की व्यवस्था चर सके। चीन की चुंगिकंग सरकार को यह सहायता प्रचुर मात्रा में दी जा रही थी। इस दशा में यह स्वा-भाविक था, वि जापान और अमेरिका में विरोध उत्पन्न हो। पर जापान इस वात

के लिये उत्सुक था, कि वह जहां तक सम्भव हो, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के साथ युद्ध में व्यापन होने से बचा रहे । पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में क्री व्यवस्था' स्थापित करने की जापान की आकांक्षा तभी निर्वाध रूप से सफल हो सकेती थी, जब रूस और अमेरिका से उसके युद्ध की सम्भावना न रहे। दक्षिण-पुर्वी एशिया के क्षेत्र में जापान का अमेरिका के साथ कोई निशेष विरोध नहीं था। यदि फिलिंजीत द्वीपसमूह को अपनी अधीनता में लाने का जापान प्रयत्न न करे, तो इस क्षेत्र में अन्य कोई प्रदेश ऐसा नहीं था, जिसमें अमेरिका का आधिपत्य हो और जिसे जापान की नई व्यवस्था से हानि पहुंचने की सम्भावना हो । एप्रिल, १९४१ में जापान रूस के साथ सन्धि कर चका था। साथ ही उसने यह भी यत्न किया, कि इसी हंग की सन्धि अमेरिका के साथ भी कर ली जावे। अमेरिका में जापानी राजदूत के पद पर एड्मिरल नोम्रा विद्यमान थे। उन्होंने अमेरिका के साथ शन्धि की बातचीत शुरू की और पारस्परिक समझौते के लिये निग्नलिखित बात पेश की--(१) नानांका में बांग चिंग-वेई के नेतृत्व में जो चीनी सरकार स्थापित हुई है, वह जागान के साथ मैत्री सम्बन्ध पर निश्वास रखती है। जापान चीन का पहोंगी राज्यं है. और इन दोनों राज्योंका मैत्री मंबंध व सहयोग पूर्वी एशिया में शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिये अनिवार्य है। अतः अमेरिका को चाहिये, कि वह चियेंग काई शेंक की सरकार पर इस बात के लिये जोर दे, कि वह जापान के साथ समझौताकर ले। (२) जापान और अमेरिका दोनों देश यह स्वीकार करें, कि उन्हें जिन बस्तुओं की आवश्यकता है, और जो वेए क दूसरे को दें सकते हैं, वेए क दूसरे को देते रहेंगे। जापान अमेरिका से पेट्रोल, लोहा आदि पदार्थ प्रचुर परिमाण में प्राप्त करता था। इसी प्रकार रेशम आदि अनेक पदार्थ जापान में अमेरिका जाते थे। एडमिरल नोमुरा की इच्छा थी, कि अमेरिका और जागान का यह पारस्परिक व्यापार भविष्य में भी पूर्ववत् जारी रहे। (३) जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया ने देशों के साथ जो अपना सम्बन्ध स्थापित रखना चाहता है, उसका स्वरूप शान्तिमय है। जापान इन देशों को अपनी अधीनता में लाकर उनमें अपना शासन स्थापित नहीं करना चाहता । अतः अमेरिका को चाहिये, कि इन देशों से जापान तेल, रखड़, टीन, निकाल आदि जिन पदार्थी को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें प्राप्त करने में वह किसी प्रकार की बाधा न डाले। (४) फिलिप्पीन द्वीप समृह को स्यापन राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और अमेरिका व जापान दोनों हैत स्वतन्त्र राज्य की उदासीन व तटस्थ सत्ता को स्वीकार करें।

इस प्रसंग में विचारणीय बात यह हैं , कि पूर्वी व दक्षिण गृगी गृजिया में जापत के उद्देश्य क्या वस्तुतः शान्तिगय थे ? इस बात का उत्तर देने के किये यह स्थान में रखना आवश्यक हैं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश इस समय स्वतन्त्र नहीं थे। वे ब्रिटेन, फांस, पोर्तुगाल, हालैण्ड और अमेरिका के साम्राज्यवाद के ्रीकार थे, और इन सब देशों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन जारी थे। अतः यदि जापान महायुद्ध की परिस्थितियों का लाभ उठाकर इन देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयत्न करता, तो उसका परिणाम किन्हीं स्वाधीन राज्यों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को नष्ट करना नहीं हो सकता था। जापान के लिये यह भी समभव नहीं था, कि वह इन देशों को उसी प्रकार अपनी अधीनता में ला सकता, जैसे कि वे पाश्चात्य देशों की अधीनता में थे। इस क्षेत्र में जापानी शक्ति के विस्तार का यही परिणाम हो सकता था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्त हो जाते, और उनमें जो नई सरकारें कायम होतीं, ये जापान को अपना संरक्षक, मित्र व सहयोगी समझतीं। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के लिये यह बात कुछ अधिक ब्री न होती.। वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता व लोक-तन्त्रयाद के मार्ग पर अग्रसर होने में इससे कुछ सहायता ही प्राप्त करते । मञ्चू-कुओं और चीन में जिस ढंग की सरकारें जापान के संरक्षण में कायम हुई थीं, वे उन अर्थों में जापान की अधीनता में नहीं थीं, जिन अर्थों में कि इन्डोचायना, भारत, वैरमा, इन्डोनीरिया आदि की सरकारें विविध पाश्चात्य देशों के अधीन थीं। चियांग काई घोक की सरकार को भी चीन की पूर्णतया स्वतन्त्र सरकार कह सवाना सम्भव नहीं है । वह ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभाव में थी, और उसपर इन पारचात्य देशों भा आधिपत्य व प्रभाव उसी प्रवार विद्यान था, जिस प्रकार विः वांग चुंग-वेई की रारकार पर जापान का । इस स्थिति में पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में जापान की नीति व उद्देश्यों को सर्वथा बुरा कह सकना एवं निष्पक्ष ऐतिहासिक के लिये सम्भव नहीं है। वस्तुतः महायुद्ध की परिस्थितियों ने एशिया के विविध देशों को पारचात्य साम्राज्यबाद से छुटक्यरा पाने का एक सुवर्णीय अवसर प्रदान विषया था । पर पराधीन एशियन देशों के राष्ट्रीय नेताओं की अपनी सैन्य-शक्ति इतनी नहीं थी. कि वे अकेले अपने की पाइचात्य देशों की अधीनता से मुक्त कर सकते । इसके लिये उन्हें किसी शक्तिशाली देश की सहायता की आव-श्यकता थी । जापान इस स्थिति में था, कि वह इन देशों को सहायता प्रदान कर सुके। दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान के विस्तार का यही परिणाम हुआ, कि इन्डोनीसिया, बरमा,मलाया आदि देशों को घणनी राष्ट्रीय खादीनवा प्राप्त करने का अवसर मिला और बहां जो नई सरकारें ात्यम हुई, महायुद्ध की प्रिन्स्पितिया के वावजुद भी वे इतनी अधिक स्वाधीन थीं, जिनती कि पाज्यारण देशों की अधीलहा में इन देशों की सरकारें कभी स्वाधीन नहीं हुई थी। जापान की सहायता हारा इन देशों के राष्ट्रीय आन्दोलन को जो वल मिला था, इनमें जो राष्ट्रीय शक्ति विकसित हुई थी, वह इतनी अधिक थी, कि यदि जापान उन देशों को अपनी अधी-नता में रखने का प्रयत्न करना, तो इनकी राष्ट्रीय चेतना उने कभी सहन न कर्षे सकती।

युद्ध का सूत्रपात-पर अमेरिका की नीति यह थी, कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जिस देश के शासन का जो स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन न आये। इराका अभि-भाय यह था, कि इन्डोनीसिया पर हालैण्ड का, इन्डोनायना पर फांस का और बरमा मलाया आदि पर बिटेन का प्रभुत्त्व यथापूर्व कायम रहे। इन देशों की भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त वारने का अधिकार है, और इन देशों में विदेशी साम्राज्यवादके विच्छ प्रवल आन्दोलन विद्यमान है -- इस तथ्य का अमेरिका की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था । इसीलिये अमेरिका के साथ सन्धि करने के प्रयत्न में एड्मिरल नोम्रा को सफलता नहीहो सकी। अमेरिका इण्डोचायना के मार्ग से चुंगांकम सरकार को सहायता न दे सके, इस उद्देश्य ने जब जापान ने इन्डोचायना में अपनी नेनाएं भोजनी प्रारम्भ की, तो अमेरिका अपने को काबू में नहीं रख सवा। २६ जुलाई, १९४१ को अमेरिकन सरकार ने एक आजा प्रकाशित की, जिसके अनुसार जापान के साथ होने वाले सब अमेरिकन व्यापार पर गरकारी नियन्त्रण कायकी कार दिया गया । साथ ही यह भी व्यवस्था की गई, कि अमेरिका में जापान की जो धनसम्पत्ति है, उस सबको सरकार अपने अधिकार में कर ले और जापानी लीग स्वेच्छापूर्वं उसका उपयोग न कर सकें। ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों ने अमेरिका का अनुसरण किया और उन्होंने भी इसी प्रकार के आदेश जारी किये। हालैण्ड की सरकार ने भी अमेरिका के अनुसरण में जापान के सम्बन्ध में इसी नीति का आश्रय लिया । इसका परिणाम यह हुआ, कि जापान के लिये पेट्रोल जैसे आवश्यक पदार्थं को प्राप्त कर सकता कठिन हो गया । जापान पेट्रोल की अमेरिका, बिटन या इन्डोनीसिया से ही प्राप्त कर सकता था। इन देशों की नीति के कारण अब उसके लिये पेट्रोल ब इसी प्रकार के अन्य पदार्थों को कहीं से भी प्राप्त कर सकता सम्भव नहीं रहा।

यह स्थामानिक था, कि जापान अमेरिका, श्रिटेन ओर हार्लैण्ड भी उस नीति को अपने प्रति विद्वेष व निरोध का परिणाम समझे। पर अभी अमेरिका युद्ध के लिये तैयार नहीं था। वह समझता था, कि अभी उसकी सामरिक तैयारी नहीं पूरी हुई है। इसीलिये उसने जापान के साथ सन्धि की वातचीत को जारी रखा। पर जापान ने यह मलीमांति अनुभव कर लिया था, कि अमेरिका के माथ उसका युद्ध अवस्थमावी है। उसके लिये यह सम्भव नहीं है, कि इस के समान अमेरिका को

भी वह तटस्थाना की नीनि का अनुसरण वरने के लिये राजी कर सके । अतः उसने यही निश्चय किया, कि अमिरका को युद्ध की तैयारी का और अधिक समय न दे । उंदिसम्बर, १९४१ के दिन उसने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया । पर्ल हार्बर हवाई द्वीपसमूह में अमेरिकन जलक्षित का प्रधान केन्द्र था । इस आक्रमण के कारण जायान और अमेरिका की सन्धि विषयक बातचीन का स्वयमेव अन्त हो गया और ये दोनों देश महायुद्ध के मैदान में कूद पड़े ।

(५) जापान की आन्तरिक राजनीति

जिस समय जापान ने १९३१ में मञ्चूरिया में अपने प्रभुस्त की स्थापना का प्रयत्न प्रारम्भ निया, उस समय तक के जापान के राजनीतिक इतिहास पर हम पहले एक अध्याय में संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाल चुके हैं। इससे पूर्व कि हम १९४१ के बाद जापान ने दिक्षण-पूर्वी एशिया में किस प्रकार अपनी शक्ति व प्रभाव का विकास किया, इसका उत्तिवृत्त लिखें, यह उपयोगी होगा कि १९३१ से १९४१ के जापान के राजनीतिक इतिहास की प्रमुख घटनाओं का भी संक्षेप के साथ उन्लेख कर दिया जाय।

🌞 १९३२ में जापान की पार्कियामेन्ट में सैयुकाई दल का बहुमत था और उसके नेता श्री इनुकाई जापान के प्रधानमन्त्री थे। इस समय जापान में इस बात पर संघर्ष शुरू हो चुका था, कि रास्कार का संचालन राजनीतिक दलों व उनके नेताओं के हाथों में रहे या सेना के 🖡 इस संघर्ष का उल्लेख हम इस इतिहास में पहले भी कर चके हैं। १९१४-१८ के महायुद्ध के बाद संसार के प्रायः सभी देशों में लोकतंत्रवाद की प्रवास को बल मिला था। बहत से राज्यों में लोकतन्त्र रिपब्लिकों की स्थापना ह ई थी और जहां वंशक्रमानुगत राजा कायम रहे थे, वहां भी शासन कार्य में लोकमत के प्रभाव में युद्धि हुई थी । जापान भी इस प्रवृत्ति से अछ्ता नहीं बचा था । १९२० के बाद जागान में भिक्ष प्रकार निरन्तर राजनीतिक दलों का विकास हुआ और देश के शासन में इन दलों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुने हैं। १९३० के बाद यूरोप में लोकतन्त्रवाद का हास शुरू हुआ, फैसिज्म और नाजीज्म के रूप में ऐसी प्रवृत्तियों का प्रारम्भ हुआ, जिनका उद्देश्य सरकार के संचालन में जनता द्वारा निर्याचित प्रतिनिधियों के महत्त्व को कम करके एक नी और एक दल के प्रभूत्व की स्थापना था। यह फैसिस्ट प्रवृत्ति केवल इटली और जर्मनी तक ही सीमित नहीं रही, यूरोप के अन्य देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ा । जर्मनी और इटली में जिस प्रकार हिटलर और मुसोलिनी के रूप में ऐसे नेताओं का प्राद्भीय हुआ, जिन्होंने निनिध राजनीनिक दलों की पृथक् सत्ता

और विरोध का अन्त कर राज्य की सम्पूर्ण शक्ति अपने हाथों में कर ठी, वैसे किसी नेता का प्राद्रभवि जापान में नहीं हुआ। पर वहां के सैनिक नेता इस बात को भलीभांति अनभव करते थे. कि राजनीतिक दलों के हाथ में मरकार के संचार्ली कार्य की रहते देना देश के लिये अत्यन्त हानिकारक है। राजनीतिक दलों की प्रभृता के कारण सरकार का संचालन कतिपय ऐसे लोगों के हाथों में आ जाता है, जो राजनीति को अपना पेशा बना लेते हैं, और सबंसाधारण मतदाताओं को अपने पक्ष में करके राजशक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ के लिये करते हैं, और बड़े पुजीपतियों के साथ मिलकार अपना स्वार्थ साधन करते हैं। अतः उचित यह है, कि देश के शासन में राजनीतिक दलों और राजनीतिक्यों का प्रभत्त न रहे । सैनिक नेताओं का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता. अंत: वे जनता के हित के लिये अपनी शपित का प्रयोग कर सकते हैं। १९३० के बाद केवल सैनिक नेता ही यह बात अनुभव नहीं करते थे. अपित जनता में भी बहुत से ऐसे लोग उत्पन्न हो गये थे, जो इन्हीं विचारों के थे। ये लोग उम्र राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के कारण यह विश्वास रखते थे, कि जापान के सब संकटों की दूर करने का एकमाथ उपाय यह है, कि ब्रिटेन, फ्रांस. अमेरिका, हाल्लैण्ड आदि पाश्चात्य देशों के समान जापान भी साम्राज्य विस्तार 🛊 लिये प्रवृत्त हो । पर साम्राज्य विस्तार के कार्य में सफलता के लिये राजनीतिक दलीं व राजनीतिक नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिये देश का शासन उन सैनिक नेताओं के हाथों में होना चाहिये, जो तलवार के धनी हों भीर जो अपने देश के उत्कर्ण के लिये उग्र उपायों का अनुसरण कर सकते में समर्थ हों। १९३१ में जापान की क्वांतुंग सेना ने मञ्चूरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया था । मञ्चिरिया में जापान की शक्ति के बिस्तार का उत्तर-दायित्व क्वांतुंग सेना पर ही था। जब यह मामला जापान के मन्त्रिमण्डल के राम्मुल विचारार्थ उपस्थित किया गया, तो प्रधानमन्त्री इनकाई नेकहा, कि जापानकी आर्थिक दशा ऐसी नहीं है, कि मञ्चूरिया और चीन में किसी बड़े युद्ध का सूत्रपात निया जा सके । इनुकाई चीन और मञ्चिरिया में लड़ाई बढ़ाने का विराधी था। परिणाम यह हुआ, कि सैनिक नेताऔर उग्र राष्ट्रवादी लोग उसके विरोधी हो गये। कतिपय सैनिक आफिसरों के नेत्त्व में इन जग्न राष्ट्वादियों ने तीक्यों में चयशर लगाना शुरू किया । ये लोग अस्त्र-शस्त्रों से मुसज्जित थे और अपने विरोधिकी मा संहार करने के लिये कटिबढ़ थे। उन्होंने सैयनाई दल के प्रधान कार्यालय, कोतवाली और प्रधान मन्त्री के निवासस्थान आदि महत्त्वपूर्ण इमारतों पर हमला किया। श्री इनुकाई इन राष्ट्रवादी लोगों हारा मार वियेगये, और उनके समान अन्य

भी अनेक राजनीतिक नेता जग्र राष्ट्रवादी क्रान्तिकारियों के कीप के शिकार बने । इन हत्याकारियों पर मुक्यदमे चलाथे गये, उन्हें राजा भी दी गई, पर यह सजा इतनी कीम थी, कि उसका जनता पर कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता था। इन लोगों को हत्याकारी न रामझकर 'पथ अष्ट देशमक्त' माना गया। इस समय जापान में सेना का इतना अधिक जोर था और लोग साम्राज्य प्रसार के लिये इतने अधिक उतावले थे, कि इन हत्याकारियों को कठोर दण्ड दे सकता सम्भव नहीं था। इन हत्याकों में केवल सेना का ही हाथ नहीं था, इस समय जापान में फैसिस्ट ढंग की एक राजनीतिक संस्था भी स्थापित हो चुकी थी और उसकी अधीनता में 'रक्त बन्धुत्त्व संघ' (बल्ड बदरहुड लीग) अपना कार्य कर रही थी, जिसका प्रयोजन अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्त्रियों की हत्या करना था। इस संघ में सैनिक आफिसर, विद्यार्थी व उग्र विचारों के नवयुवक सम्मिल्ति थे और इन्होंने यह अपना ध्येय बनाया हुआ था, कि सरकार के संचालन का कार्य ऐसे लोगों के हाथों में ले आमा जाय, जो साम्राज्य प्रसार के कहुर पक्षपाती हों। बल्ड बदरहुड लीग की स्थापना सन १९३० में हुई थी और उसके संस्थापकों में लेफिटनेन्ट फूजिमा और निशो इनूये प्रमुख ये। फूजिमा सैनिक आफिसर था और इन्ये एक बौद्ध भिक्षुक था।

इनुवाई की हत्या के बाद जनरल सैतो के नेत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया गया । सैतो का मन्त्रिमण्डल किसी एक राजनीतिक दल पर आश्रित नहीं था, उसमें सैनिक नेताओं की प्रधानता थी और एड्मिरल अराकी उसका अत्यधिक प्रभावदाली सदस्य था । यह मन्त्रिमण्डल १९३४ तक कायम रहा । जिस समय जापान मञ्चिरिया और आभ्यन्तर मंगोलिया के पूर्वी प्रदेशों में अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था, यही मन्त्रिमण्डल जापान में विद्यमान था। १९३४ में इस मन्त्रिमण्डल के अन्यतम मंत्री पर आर्थिक गवन सम्बन्धी कुछ आक्षेप किये गये और उसके कारण नयं मन्त्रिमण्डल के निर्माण की आवश्यकता हुई। अब एड्मिरल ओकोदा के नंत रंव में नये मन्त्रिमण्डल का संगठन हुआ। यह मन्त्रिमण्डल भी किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन पर आश्रित नहीं था। पर फरवरी, १९३६ में जब जापान की पालियामेन्ट का नया निर्वाचन हुआ, तो उसमें पुराने राजनीतिक दलों की शवित फिर बढ़ गई। इस नई पार्टियामेन्ट में विविध दलों के सदस्यों की बुंख्या इरा प्रकार थी--मिन्सेइतो २०५, सैयुकाई १७४, शोवाकाई (फैसिस्ट प्रवृत्ति का नया दल) २०, अन्य दल ६७। पार्टियामेन्ट के निवचिन के परिणाम से वे लोग बहुत अधिक असंतुष्ट हुए, जो जापान में राजनीतिक दलों के प्रभूत्व का अन्त कर सैनिया नेताओं के आभिपत्य के पक्षपाती थे। प्रधानमन्त्री एउमिएए ओकोदा ने इस समय यही उचित समझा, कि ठोकाम के अनुसार देश द्वा सासन

किया जाय और पालियामेन्ट के निर्वाचन द्वारा जनता ने जिन राजनीतिक दलों के प्रति अपना विश्वास प्रगट विद्या है, उनको देश के बासन में अधिक महत्त्व दिया जाय । पर सेना के नंता और बलड ब्रदरहड़ की ग के सदस्य इस बात की सहके सरने के लिये उद्यत नहीं थे। वे खले तीर पर विद्रोह सरने को तैसार हो गये। २६ फरवरी, १९३६ के दिन १५०० सैनिकों ने अस्त्र-शस्त्रों के साथ तोत्यों में विद्रोह कर दिया । उन्होने प्रधान मन्त्री ओकोदा, एड्सिंग्ल मैतो, एड्सिंग्ल मुजकी, श्री ताकाहाशी, बाउण्ट मिवानो आदि सरकार के प्रधान अधिकारियों व मिनियों पर हमला बोल दिया और अनेक सरकारी नेता इन विद्रोहियों के कीप के शिकार हुए । प्रधान मन्त्री ओकोदा बड़ी कठिनता से अपनी प्राणरक्षा करने में समर्थ हुआ । विद्रोही सैनिको के एक अन्य गिरोह ने हाईकोर्ट, पालियामेन्ट, पूलीस हेड-क्यार्टर्स, जल और स्थल सेना के प्रधान कार्यालय, राजप्रासाद आदि सरकारी डमारतों पर आक्रमण किया । सैनिकों का यह विद्रोह २९ फरवरी तक जारी रहा। यद्मपि अनेक मन्त्री व अन्य उच्च राजपदाधिकारी इस विद्रोह में मारे गये, पर सम्राट् और उसकी सरकार ने इस बार विद्रोह को शान्त करने में बहुन अधिक तत्परता प्रदक्षित की । विद्रोही सैनिकों को गिरमतार किया गया, उन पर मुकदभ चलाये गये और १७ सैनिक आफिसरों की प्राणदण्ड दिया गया।

पर इस विद्रोह के कारण मेना ने एडमिरल ओकोदा के प्रति जो रोप प्रकट किया था, उसके कारण उसके गन्त्रिगण्डल को त्यागपत्र देना पटा। ९ मार्चः १९३६ को श्री हीरोला के नेतत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का संगठन किया गया। हीरोता का मन्त्रिमण्डल देर तक अपने पद पर कायम नहीं रह राका । उसके पतन के बाद दो अन्य मन्त्रिमण्डल बने, पर उनका यहां उल्लेख करने की आवस्यकता नहीं है । ३१ मई, १९३७ को जापान के प्रधान मन्त्री के पद पर प्रिस कोनोये की नियुक्ति हुई। प्रिस कोनोसे को जहां सैनिक नेता पसन्द करने थे, यहां राज-नीतिक नेताओं का समर्थन भी उसे प्राप्त था। प्रिस कोनीये वस्तुत: जापान का राष्ट्रीय नेता था और उसीने पूर्वी एशिया व वृहत्तर पूर्वी एशिया (दक्षिण-पूर्वी एशिया) के सम्बन्ध में उस नई नीतिक: सूत्रपात किया था, जिसका उल्लेख हम पहले 'नाई व्यवस्था' के नाम से कर चके हैं। प्रिम कोनोये ने इस नाई व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था--(१) चीन में विषाप् काई शोक के नेतृत्व में स्थापित सरकार ना अन्त कर एक ऐसी सरकार की स्थापनी की जाय, जो जापान के साथ सहयोग करने को तैयार हो और जो जापान को अपना मित्र, सहयोगी व संरक्षक स्वीकार करे। (२) चीन में पारचात्य देशों के प्रभूत्व का अन्त करने के साथ-साथ पूर्वी एशिया के सम्पूर्ण प्रदेशों से पाञ्चात्य देशों के

साम्राज्यवाद का अन्त किया जाय । (३) रूस अपने प्रभाव व प्रभुत्त्व का विस्तार बैकल झील से पूर्व के प्रदेशों में न कर सके । पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था' की नियाना के लिये जापान ने चीन में जिन युद्धों का प्रारम्भ किया था, उनका उल्लेख इस इतिहास में पहले किया जा चुका है । इन युद्धों का संचालन प्रिस कोनोमें के मन्त्रिमण्डल द्वारा ही किया जा रहा था । चीन में जापान की शक्ति के विस्तार का प्रधान श्रेय इसी मन्त्रिमण्डल को है ।

प्रिस कोनोये का मन्त्रिमण्डल ५ जनवरी, १९३८ तक कायम रहा । मन्त्रियों में आपस के मतभेद के कारण इस मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया और डा० हीरानमा के ने तत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ। यद्यपि डा० हीरा-नमा स्वयं सैनिक आफिसर नहीं था, पर वह उग्र राष्ट्रवादी था और जापान की गक्ति के विस्तार का प्रबल पक्षपाती था। उसने चीन-जापान युद्ध का बड़ी उग्रता के साथ संचालन विध्या, पर वह देर तक अपने पद पर कायम नहीं रह सका । अगस्त. १९३९ में जब जर्मनी ओर रूस ने परस्पर तटस्थता की सन्धि कर ली, (इस सन्धि का उल्लेख हम इसी अध्याय में गहले कर चुके हैं) तो जापान में उससे बहुत असन्तीप हुआ। जर्मनी, इटली और जापान ने परस्पर मिलकर जो एण्टि-कोमिन्टर्न · भैक्ट बनाया हुआ था, यह सन्धि स्पष्टतया उसके विरुद्ध थी। इस सन्धि के कारण जापान की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत निर्वल हो गई थी और इसीलिये डा० हीरानुमा के लिये यह सम्भव नहीं रहा था. कि वह अपने विरोधियों से अपने मन्त्रिमण्डल की रक्षा कर सके । परिणाम यह हुआ, कि २८ अगस्त, १९३९ को उसने त्यागपत्र दे दिया और जनरल नोब्युकी आबे के नेतृत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का संगठन हुआ । जनरल आबे के मन्त्रिमण्डल के सम्मूल सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या यह थी, कि जापान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने का प्रयत्न करे। इसके लिये उसने यह निर्धारित किया, कि जहां तक सम्भव ही यूरीप के अन्तर्राष्ट्रीय अगड़ों से पृथक रहा जाय और संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ समझीते का अयतन किया जाय, ताकि पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था' को कायम करने की योजना को जापान निदिचन्त रूप से पूरा कर सके । पर अमेरिका और जापान में विरोध इतना अधिक था, कि उनमें समझौता हो सकना सूगम नहीं था । १५ जनवरी, १९४० को जनरल आबे के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया और एड्मिरल मित्सुमासा यीनाई के नेतृत्त्व में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ।

इस समय यूरोप में महायुद्ध का प्रारम्भ हो चुका था और जर्मनी बड़ी तेजी के साथ यूरोप के विविध देशों को अपनी अधीनता में लाने में तत्पर था। जापान के उग्र राष्ट्रवादी नेता अनुभव करते थे, कि पूर्वी एशिया में 'नई व्यवस्था' स्थापित

सरने का यह मुवर्णीय अवसर है। ब्रिटेन, फांस और हालैण्ड की इस समय जो दुवंशा है, उसका लाभ उठाकर जापान को अब चीन व दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में अपनी शक्ति के विस्तार के लिये प्रयत्नशील होना चाहिय। इस उप राष्ट्रवादी नेताओं का विचार था, कि एड्गिरल योनाई का गन्तिमण्डल महा-युद्ध के अवसर का मुचान रूप से जापान के उत्कर्ष के लिये उपयोग करने में असमर्थ है। इन नेताओं के विरोध के बारण १८ जुलाई, १९४० को ओनाई के मिल-मण्डल ने त्यागपत्र दे दिया और प्रिस कोनोये ने एक बार फिर जापानी सरकार के शासनसूत्र को अपने हाथों में लिया।

प्रिस कोनोये जापान की 'नई व्यवस्था' सम्बन्धी नीति का प्रवर्त्तक था। उसके शासनकाल में जापान ने पूर्वी व बहत्तर पूर्वी एशिया में नई व्यवस्था की स्यापना के लिये जो उद्योग किया, उसके सम्बन्ध में इतना निर्देश कर देनाही पर्याप्त हैं. कि उसी के मन्त्रिमण्डल ने एप्रिल, १९४१ में रूस के साथ तटस्थता की सन्धि की और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझीता करने का अत्यधिक गम्भीरता के साथ उद्योग किया । इन सन्वियों का क्या उद्देश्य था, इस पर हम इसी अध्याय में पहले प्रकाश डाल चुके हैं। प्रिस कोनोये वस्तुतः अमेरिका के साथ सन्धि करना चाहता था । पर जब अमेरिका ने अपने प्रदेशों में विद्यमान सम्पूर्ण जावानी सम्पृत् व धन पर सरकारी अधिकार कायम कर लिया और ब्रिटेन व हालैण्ड ने उसका अनुसरण किया (इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं), तो प्रिस कोनोये के लिये यह सम्भव नहीं रह गया, कि वह अमेरिका के साथ रान्यि की बात को आगे बढ़ा सके। पर प्रिस कोनोये अब भी निराश नहीं हुआ। उसने यत्न किया कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मुलावात मरे और स्वयं सब वातों ना निर्णय वारे। पर टाप्ट्रपति रूजवेल्ट प्रिस कोनोये से मुलाकात के लिये तैयार नहीं हुआ । प्रिस कोनोये की अमेरिका सम्बन्धी नीति की यह भारी असफलता थी। विवश होकर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा और जनरल हिंदेसा तोजो के नेतृत्व में नये मंत्रिमण्डल का विमाण हुआ । जनरल तोजो उग्र राष्ट्रवादी व साम्राज्यवादी था । उसमा मन्त्रि-मण्डल १९४४ तक बायम रहा । दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान की शक्ति वा जो असाधारण रूप से विस्तार हुआ, उसका श्रंय जनरल तीजो के मन्त्रिमण्डल को ही हैं। पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर जनरल तीजो की शरयार ने ही महायद में प्रवेश किया था।

१९३१ से १९४१ तथा के काल में जापान के राजकीय व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसका कारण मञ्जूरिया और चीन के युद्धों में अत्यधिक खर्च का होना था। १९३१-३२ में जापान का कुल राजकीय व्यय १,४७,७०,००,००० येन था। १९३६-३७ में इस खर्च की मात्रा बढ़कार २,२८,२०,००,००० येन तक पहुंच गई थी। १९३६ के बाद जापान के राजकीय व्यय में और भी अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि इस समय जापानी सेनाएं चीन के साथ युद्ध में व्यापृत थीं। इतने बर्न की अकेले टैक्सों से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, अतः सरकार की राष्ट्रीय ऋण का आअय लेना पड़ा। जापान के राष्ट्रीय ऋण में कितनी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थीं, इसका अन्दाज निम्नलिखित तालिका द्वारा भली-भांति किया जा सकता है।

सर्व	राष्ट्रीय ऋण की मात्रा
6 £ 9 8	४,५२,३०,००,००० यंन
१९३७	९,२५,८०,००,००० येन
१९.४०	११,०३,३०,००,००० येस

इस राष्ट्रीय ऋण को प्रधानतया जापान के पूंजीपतियों द्वारा प्राप्त किया गया था। जर्मनी के समान जापान भी इस समय अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिये कियेष रूप से तत्पर था। सरकार मुख्यतया ऐसे व्यवसायों पर विशेष रूप से ध्यान दे रही थी, जो युद्ध के लिये उपयोगी हों।

उन्नीसवां अध्याय

द्क्षिण-पूर्वी एशिया में महायुद्ध का प्रसार

(१) जापान द्वारा पाञ्चात्य देशों के साम्राज्यों का अन्त

पर्ल हार्बर--७ दिसम्बर, १९४१ की जापान ने पर्ल हार्वर पर हमला किया। यह बन्दरगाह प्रशान्त महासागर में हवाई द्वीपसमह में स्थित है, और अमेरिका की सामद्रिक शक्ति का प्रधान केन्द्र है । अमेरिका को इस बात की आशंका नहीं थी, कि जापान इस प्रकार अवस्मात पूर्व हार्बर पर आक्रमण कर देगा । इसमें नन्देह नहीं, कि अमेरिका और जापान के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध निरन्तर विगत्ने जा रहे थे। जापान के राजदूत द्वारा अमेरिका के साथ गन्धि व गमजोता करने का जो प्रयत्न जारी था, वह असफल हो चुका था। प्रिस कीनीयेक गाथ मुलाकात करने मु भी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इत्यार कर दिया था। इस दशा में इस दोनों देशों में युद्ध होना अनिवार्य हो गया था । जापान पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाश्चान्य देशीं के प्रभ्रत्य का अन्त कर वहां ऐसी सरकारें स्थापित सरना चाहता था, जो जापान को अपना मित्र, सहयोगी व संरक्षक मानें। अमेरिका जापान की इस नीति को किमी भी प्रवार सहने के लिये तैयार नहीं था। अतः जापान ने यह निश्चय किया, कि प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अमेरिका की जो जलगायत विधामान है, उसे एकदम पंगु बना दिया जाय, ताकि अमेरिका के लिये जापान के मार्ग में बाधा उपस्थित कर सकना सम्भवन रहे। पर्ल हार्वर के इस हवाई हमले में अमेरिका के अनेक जंगी जहाज ड्ब गये और अनेक तहस-नहस हो गये। इस आक्रमण में २,११७ अमेरिकन आफिसर और सैनिक गारे गयं, ३७६ घायल हुए और ९६० लापता हो गये । जो जंगी जहाज इस हमले द्वारा ड्वे या नष्ट हुए, उनकी संख्या १४ थी । इसी प्रकार १२७ अमेरिकन हवाई जहाज इस आक्षमण के भारण नद्ध हुए। जापान के इस अवस्मात् हमले से अमेरिका की आधे के लगभग साम्हि शक्ति नष्ट हो गई।

इसमें सन्देह नहीं, कि जिस उद्देश्य से जापान ने अगस्मात् पर्ल हार्वर पर आक्रमण किया था, उसमें उसे सफलता हुई। जापान यही चाहता था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति के विस्तार में अमेरिका की जलकावित बाधक न हो:

सके । पर्ल हार्बर पर आक्रमण के कारण प्रशान्त महासागर में विद्यमान अमेरिकन जलशक्ति इतनी अधिक पंग् हो गई थी, कि उसके लिये जापान का प्रतिरोध कर 🏰 मा सम्भव नहीं रहा था। पर अन्ततोगस्या इससे जापान को नुकसान ही हआ । अमेरिका में बहुत से लोग ऐसे थे, जो महायुद्ध से पृथक् रहने में ही अपने देश का हित समझते थे। उनका विचार था, कि यूरीप के झगड़ों में अमेरिका की नहीं पड़ना चाहिये और उसके लिये यही पर्याप्त है, कि वह फैसिस्ट शक्तियों के खिलाफ मित्र राज्यों की युद्ध सामग्री और घन द्वारा सहायता करता रहे। यद्यपि चाट्टपति रूजवेल्ट लीज लेन्ड बिरु द्वारा सब प्रसार से भित्र राष्ट्रीं की सहायता करने की अञ्चल के, पर अमेरिका की जनता में युद्ध में शामिल होने के लिखे विजेष उत्साह नहीं था । पर पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण ने स्थिति को एकदम परिवालित कर दिया । अब सम्पूर्ण अमेरिकार जनता फैसिस्ट राज्यों के खिलाफ यद में शामिल होने के लिये तैयार हो गई और इस विशाल रिपब्लिक की सम्पूर्ण शक्ति भित्र राज्यों के पक्ष में प्रयुक्त होने लगी । धन, जन और यद्ध सामग्री की दृष्टि से अमेरिका का भण्डार वस्तुत: अक्षय था । आधुनिक युग में सफलता प्राप्त करने के लिये जहां सैनिकों की आवश्यकता होती है, वहां साथ ही अपार आधिक "तै। भन और अत्यपिक युद्ध सामग्री की उगल्य कि भी अनिवार्य होती है। महायुद्ध में जो फैसिस्ट राज्यों की पराजय और मित्र राज्यों की दिजय हुई, उसका प्रधान कारण अमेरिका की अनन्त धनशक्ति और जनशक्ति थी । यदि जापान इस प्रकार अवस्मात् पर्कं हार्बर पर आकंगण न वार देता, तो यह बात संदिग्ध है, वि अमेरिका की यह शनित किस अंश तक मित्रराज्यों को उपलब्ध हो सकती। यद्यपि राष्ट्र-पति रूजवेल्ट की सरकार मित्र राज्यों की सब प्रकार से सहायता करने के लिये कटिबद्ध थी, पर अमेरिका में ऐसे लोग भी विद्यमान थे, जो महायुद्ध में शामिल होने के लिये विशेष उत्साह नहीं रखते थे और अमेरिका जैसे लोकतन्त्र देश में इन लोगों के मत की रार्वशा उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

अन्यत्र जापानी आक्रमण—जापान केवल पर्ल हार्यर में विद्यमान अमेरिकान जंगी जहाजों को डुवा करही संतुष्ट नहीं हुआ। १० दिसम्बर, १९४१को उसके ह्याई जहाजों ने मलाया के समुद्रतट पर स्थित ब्रिटिश जंगी जहाजों पर भी हमला विद्या । कि क्रिका अंग जेल्स और रिपल्स नामक दो बड़े ब्रिटिश जंगी जहाज डुवा दिये गये । इन जहाजों के डूवने का यह परिणाम हुआ, कि चीन का दक्षिणी समुद्रतट सर्वथा अरक्षित दशा में हो गया और ब्रिटेन के लिये यह सम्भव नहीं रहा, कि वह जापान की बढ़ती हुई शक्ति का सफलतापूर्वक मुकावला कर तके। उ दिसमान की जब जापाम के हवाई जहाजों ने पर्ल हार्बर पर हमला कि या था, नशी नाश ही गुकाग (फिल्प्पिन

के पूर्व में स्थित एक द्वीप), शंघाई और सिगापुर पर भी वायुगार्ग द्वारा आक्रमण हुए थे। इनके अतिरिक्त फिलिज्यान द्वीप समूह पर भी अनेक स्थानों पर बम्ब वर्णा की गई थी। अंबाई की अन्तर्राष्ट्रीय बस्ती पर तो उसी समय जाणानी सेनाओं के कन्जा भी कर लिया था। हम यह पहले लिख नुके हैं, कि ८ दिसम्बर, १९४१ की ग्रंट जिटेन, अमेरिका और नीदर्र लैक्स बैस्ट इन्हींज की इन सरकार ने जापान के बिरुद्ध बाकायदा युद्ध की घोषणा कर दी थी।

पर्छ हार्बर की अमेरिकन सामुदिक शक्ति को पंगु बनाकर जापान के फिलिप्पीन द्वीगरागूह पर हमला करना प्रारम्भ किया। बहुत से जहाज बनीकाएं आदि एकत्र कर दो लाख से अधिक जापानी सैनिकों को फिलिप्पीन में उतार दिया गया। जनरल मैंक आर्थर के नेगृत्व में अमेरिकन सेनाओं ने बड़ी वीरता के साथ इनका मुकाबला किया। पर जापानी रोना के राम्मुख के टिक नहीं सकीं। १९४२ के शुरू के सप्ताहों में साथ फिलिप्पीन द्वीपसमूह जापान के हाथ में चला गया। जनरल मैंक आर्थर ने आरट्रेलिया जाकर आश्रय ग्रहण किया और बहां से जापान का प्रतिरोध करने के लिये तैगारी शुरू की।

इसी बीच में जापान की सेनाएँ होगकांग पर भी हमला कर ग्ही थीं। चीन के पूर्वी रामुद्रतट पर विद्यमान यह विशाल य समृद्ध नगर ब्रिटिक्क शिक्त का प्रमुख केन्द्र था। जापान की शिक्त के सम्मुख हांगकांग देर तक नहीं टिक सका। सन् १९४२ के जुरू में उस पर भी जापान का कब्जा हो गया। फिल्पिन और हांगकांग की विजय में जापान ने अद्भुत साहस और सैनिक दामता का परिचय दिया। जहाजों द्वारा रामुद्र के रास्ते मेनाएँ उतारक स्थल में शत्रु को कैस परास्त निया जा सकता है, इसका उत्तम उदाहरण एस महायुद्ध में पहले पहल जापान ने ही उपस्थित किया। शंकाई जोर होंगांग पर जापान का कब्जा हो जाने से चीन के ये दो प्रनान नगर पास्त्रात्य देशों के प्रभुत्व से मुक्त हो गये थे। फिल्पिन द्वीप रामूह अमेरिका के अवीन था। उसे जीतकर जापान ने प्रशान्त महासागर के इस विशाल दीप समूह पर पास्नात्य आविपत्य का अन्त किया।

सिमापुर—पर्छ हार्वर में अमेरिका की सामृद्धिक सिक्त को अरहव्यस्त नारके और फिलिक्यीन द्वीपरामूह तथा हांगकांग पर कथ्ना करके जापात के िन्ने दक्षिणु-पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार करने का मार्ग विक्कृत माफ हो गया थे हैं। इस क्षेत्र में ब्रिटिय अक्ति का प्रधान केन्द्र सिमापुर था। यह बन्दरमाह मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में एक छोटे से द्वीप पर स्थित हैं। गलाया प्रायद्वीप के साथ एक बांच द्वारा इसका सम्बन्ध भी है। ब्रिटिश लोगों ने यहां जबदंश्त किलाबन्दी सी

हुई थी। इसमें पचास करोड़ के लगभग रुपया खर्च हुआ था। ब्रिटिश लोगों को अभिमान था, कि कोई सब्देश सिंगापुर के इस अड्डे पर आक्रमण नहीं कर सकता । क्रश उनके जेंगी जहाज वड़ी संख्या में रहते थे। विशाल ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्व मं पश्चिम या पश्चिम में पूर्व की और जानेवाले जहाज यह भरोसा रखते थे, कि उनकी स्थिति सर्वथा सुरक्षित है। सिगापुर के किलानमा बन्दरगाह मे विद्यमान ब्रिटिश सामद्रिक शनित उनकी रक्षा के लिये सदा उद्यत रहती थी। इसमें सन्देह नहीं, कि समृद्र के रास्ते से हमला करके सिंगापूर को जीत सकना सूगम नहीं था। पर मलाया से होकर स्थल-मार्ग द्वारा भी सिंगापूर पर हमला किया जा सकता है, यह बात ब्रिटिश लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी। उनका खयाल था, कि मलाया सघन व दुर्गम जंगलों से परिपूर्ण है। ये जंगल मलेरिया व अन्य घातक बखारों से सदा आकान्त रहते हैं। इनमें से गुजरकर कोई शब्सेना कभी सिंगापुर पर हमला करने का साहस नहीं वार सकती । पर जापानियों ने सिंगापुर पर आक्रमण के लिये इसी मार्ग का अवलम्बन किया । इन्डोचायना में जापानी सेनायें उसी समय आ गई थीं, जब कि फ्रांस के पराजित होने पर वहां मार्शल पेतां के नेतृत्व में विदेशी सरकार की स्थापना हुई थी । पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के बाद बाद अभिपानी सेनाओं ने इन्डोचायना से थाईलैंग्ड में प्रवेश किया और ये सेनाएँ मलाया के जंगलों में से होती हुई ३१ जनवरी, १९४२ को सिगापूर पहुंच गई । १५ फरवरी को सिगापुर की बिटिश सेनाओं ने जापान के सम्मुख घुटने टेक विये।

इंस्ट इन्होज शिंगापुर की विजय के कारण इंस्ट इन्होज की स्थिति बहुत संकटमय हो गई। ईस्ट इन्होज के बड़े भाग (इन्होनीसिया) पर हालैण्ड का आधिपत्य था और हालैण्ड इस समय जर्मनी के कब्जे में आ चुका था। इन्होनीसिया में जो भी उच सेना विद्यमान थी, वह जापान का मुकाबला कर सकते में असमर्थ थी। हालैण्ड अपने विशाल एशियन साम्राज्य की रक्षा के लिये अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता पर ही निर्भर कर सकता था। पर्ल हावंद के ध्वंस के कारण अमेरिका की और सिंगापुर के पतन से ब्रिटेन की अपनी स्थिति ही अत्यन्त संकटमथ हो गई थी, अतः उनके लिये यह सम्भव नही रहा था, कि वे नीदरलैण्ड्स इंस्ट इन्हीज की रक्षा में इन्ह सरकार की सहायता कर सके। १४ फरवरी, १९४२ को जापानी सेनाओं ने सुमात्रा में पालेम्बांग पर आक्रमण किया। यहां पेट्रोलियम कियानी सेनाओं ने सुमात्रा में पालेम्बांग पर आक्रमण किया। यहां पेट्रोलियम कियानी सेनाओं में न पड़ जायें। तेल को साफ उनमें द उसे जमा करके रनने के लिये जो बहुत सी महावारी व टेकियां यहां विद्यमान में, वे सा उन्ह जमा करके रनने के लिये जो बहुत सी महावारी व टेकियां यहां विद्यमान में, वे सा उन्ह हो। व लिये की सोसत का अनुमान २५,००,००,००० एपा किया प्राप्त । पालेम्बांग इसकी कीमत का अनुमान २५,००,००,००० एपा किया प्राप्त । पालेम्बांग

पर जापानी रेनाओं का बब्बा हो जाने के कुछ ही दिनों में सम्पूर्ण सुमात्रा जापान के अधिकार में चला गया । इसी समय के लगभग अन्य जापानी सेनाओं ने बोनिया, जाता, बाली, अम्बोयना, तिमोर, गेलेक्स आदि अन्य दीपों पर आक्रमण किया है पर्वा, १९४२ तक ईस्ट इन्हीं ज के ये सब दीप जापान के प्रमुक्त में जा राये थे । इन्होंनीसिया में हालैण्ड का जो विशाल माम्राज्य स्थापित था, वह सब उसकी अधीनता से गुक्त हो गया था । मार्च, १९४२ में जापानी सेनाओं ने न्यू गार्डानआ दीप पर भी आक्रमण किया । इस दीप का एक भाग इन अवीनता में था और एक ब्रिटेन के साम्राज्य के अन्तर्गन था। दोनों भागों पर जापान का प्रमुक्त स्थापित हो गया और न्यू गार्डानिआ पर जापान का कब्जा हो जाने से आस्ट्रेलिया की स्थित भी सुरक्षित नहीं रह गई । आस्ट्रेलिया इस दीप से केवल ४०० भीन्य की दूरी पर स्थित है, और बहां से जापानी वायुरेना के लिये यह अत्यन्त सुगप था, कि वह आस्ट्रेलिया पर बगब वर्षा कर सके।

बरमा—मन्त्रया और सिंगापुर पर जापान अपना प्रभुत्त्व रथापित गर नृज्ञा था। जब उसकी सेनाएं बरमा की और अग्रसर हुई। यहां उपका भुकाबला कर मकने की शनित ब्रिटिश लोगों के पास नहीं थी। जापानी सेनाएं निरम्तर आगे बढ़ती गईं, और ८ मार्च, १९४२ को रंगून पर उनका कर्या हो गया। बरमा औई सिंगापुर से ब्रिटिश सैनिकों व नागरिकों को बचाकर लीटा लाने की समस्या अल्पन्त विकट थी। बहुत से अंग्रेजों को हवाई जहाजों हारा भारत लाया गया। अनेक साहसी मन्ष्य जंगल के रास्ते भी बरमा से आसाम आने में समर्थ हुए।

पाइवास्य साम्राज्यवाद का अन्त—७ दिसम्बर, १९४१ को जापान महायुद्ध में सामिल हुआ था। तीन मास के स्वल्पकाल में उसने सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया रे पास्चात्य देशों के प्रभुत्य का अन्त कर दिया था। जापान की सेनार्य जो उतनी भी द्वाता और सुगमता से इस विशाल भूखण्ड से पास्चात्य साम्राज्यबाद का अन्त कर सकीं, उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—(१) इन देशों के निवासियों की सहानुभूति अपने विदेशी शासकों के साथ नहीं थी। अमेरिया व स्रांप के पौराङ्ग लोग यह समझते थे, कि एशिया के निवासी उनकी अपेक्षा हीन हैं, और उनपर शासन करने का उन्हें देवी अधिकार प्राप्त हैं। इन देशों में पास्नात्य शासकों की इतनी शेनाएं तो थीं, जो अधीनस्य जातियों के विद्रोहों को शान्त करने उन्हें अपनी अवीनता में रख सकती थीं। पर जब जापान जैसा विद्रान-कला-सम्बद्ध अत्र उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ, तो उसका पराजय थे तभी कर सकती थीं, जब कि इन क्षेत्रों के निवासियों का भी पूरा पूरा सहयोग उन्हें प्राप्त हो। पर एशि-यन लोगों का सहयोगऔर सद्मावना प्राप्त करने का कोईभी प्रयत्न परिचर्ग देशों

के गौरा द्वा लोगों ने नहीं किया था । आधुनिक युग की लडाइयों मे कोई पक्ष तभी मुकल हो सकता है, जब जनता की सामुहिक सहायता उसे प्राप्त हो । आधितक युग की यह रावरें। प्रवरू भक्ति ब्रिटिश और इन लोगों को एशिया के क्षेत्र में प्राप्त नहीं थीं । दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रना का आन्दोलन अच्छे प्रवार रूप में विश्वमान था । यही कारण है, कि जापानी सेनाओं के आक्रमण का इन देशों ने स्थापन किया । इस समय जापान स्पष्ट रूप से यह घोषित कर एहा था, कि उसका उद्देश्य पारचात्य माम्राज्यवाद से एशिया को स्वतन्त्र कराना है। उसकी यह नीति थी, कि पारचात्य प्रभून्य का अन्त कर इन देशों में ऐसी राष्ट्रीय व स्वतन्त्र सरकारं कायम की जावें, जो जावान को अपना पथ प्रदर्शक और मित्र समक्षें और जो पाश्चात्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में जापान के माथ सहयोग कारने को उद्यत हों। इस दना में यह सर्वधा स्वाभाविक था, कि जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की पारचात्य लोगों की अधीनता से मुबत कराने में विशंप कठिनना का अनुभव न करे। (२) पारुवात्य देश इस समय यूरोप के महायुद्ध में ज्यापुत थें। हालैण्ड जर्मनी द्वारा अधिकृत हो चुका था और ब्रिटेन के ऊपर जर्मन आक्रमण बड़ी तेजी के शाब जारी नै । दक्षिण-पूर्वी एशिया में जिल पाञ्चात्य देशों का शासन था, उनकी अपनी स्थिति ही अत्यन्त प्यानीय और अरक्षित थी। इस दशा में उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे सुदूर एशिया में विद्यमान अपने साम्राज्य की रक्षा पर ध्यान दे सकें । (३) एममें सन्देह नहीं, कि दक्षिण-पूर्वी एकिया में पाक्वात्य देशों की गैन्यजनित प्रनुर परिमाण में विद्यमान थी। ब्रिटिश, डच व अमेरिशन लोग अपने इस साम्राज्य की एका के लिये बेखबर नहीं थे। वहां उन्होंने अपनी शक्ति को भलीगांति स्थापित किया हुआ था, पर इन अधीनस्थ देशों में जो पाश्वात्य लोग गामवा के रूप में नियनत थे, वे धीरे घीरे अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख होने लग गये थे। अधीनस्थ लोगों पर शासन करने के कारण उनमें स्वेच्छाचारिता और निरं-कुशता की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी, और उनकी शासननीति कुछ कुछ उसी ढंग की हो गई थी, जैसी कि मध्यकाल के स्वेच्छाचारी राजाओं व उनके अमीर उमराओं की हुआ वाराण भी। ने सीमिनियाम भीग उच्छू खल जीवन के अभ्यस्त हो गये थे ं 😬 🐪 ः । 🧢 कि। जापान जैसे प्रवल शशुका मुकावला और जनमें वह See La कर सवाते के :

दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाश्चात्य साम्राज्य का अन्त संसार के आयुनिक उतिहास की पत्नका महत्त्वपूर्ण बक्ता है। गौराङ्ग लोग उच्च हैं, और एशिया व अर्फका के लोग होना — का गनका का योथापन इससे मलीभांति स्पष्ट ही गया। महायुद्ध में यद्यपि अन्ततोगत्त्वा जापान पराजित हुआ, पर एक बार दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोगों को अपने बन्धन काटकर स्वतन्त्र होने का अवसर प्राप्त हो भूका और उन्होंने अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये अद्भुत कार्यक्षमंत्रा और शक्ति प्रदक्षित की । इन्डोनीसिया, बरमा आदि पर पास्चात्य देश फिर से पहले के समान अपना प्रभूत्व स्थापित नहीं कर गके।

(२) दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रति जापान की नीति

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों से पाश्चात्य लोगों के नामन का अन्त कर जापान ने उनमें पहले सैनिक जामन की स्थापना की । युद्ध की परिस्थित में यह आवश्यक था, कि इन देशों में जान्ति और ज्यवस्था कायग गयी जावे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सैनिक शासन की स्थापना के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग कियानक नहीं था। मलाया, बरमा, वोनियो, जावा, सुमात्रा, फिल्फिपीन आदि सर्थत्र उच्च सैनिक आफिसरों को शासन कार्य के लिये नियुक्त किया गया। ये सैनिक शासक इन देशों में व्यवस्था कायम रखने में सफल हुए। राज्य परियर्ता के कारण देश में जो अराजकता व अव्यवस्था की प्रयुत्तिमां बलवती होती हैं, उन्हें प्रवल होने का अवसर जापानी मैनिक अधिकारियों ने छिते दिया। इन देशों के बहुसंस्थक जनता की सहानुभूति जापानी लोगों के साथ थी। ब्रिटिश, इच, अमेरिकन व फेंच लोग इन देशों के निवासियों को अपने से हीन समझते थे, उन्हें 'नेटिश' व 'एशियाटिक' वाहकर उनसे घृणा करने थे। अतः यह स्थामाविक था, कि जनता को उनके शासन का अन्त होने से प्रसन्नता व सन्तिय अनुभव हो।

पर विक्षण-पूर्वी एशिया के उन देशों में जापानी लोगों ने सैनिन शासन को देर तक कायम नहीं रखा। श्री झ ही सर्वत्र 'स्वराज्य' की स्थापना फर दी गई। फिलिप्पीन द्वीन समूह और वरमा में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन अच्छे प्रवल हम में विद्यमान था। वहा ऐसे देशमक्त नेताओं की कभी नहीं थी, जो अपने देश के शासन की बागडोर की मलीभांति संभाल सर्क। अतः श्री झ ही एन दोनों देशों में स्वतन्त्र सरकारों की स्थापना कर दी गई। मलाया के विविध राज्यों की मिलाकर एक केन्द्रीय संघ में संगठित किया गया और उनके शासन के लियं विधानसभा का विद्वाल कया गया। इन्होंनीसिया के शासन का कार्य भी वहां के राष्ट्रीय नेताओं के सुष्ट कर दिया गया। इन्होंनीसिया के शासन का कार्य भी वहां के राष्ट्रीय नेताओं के सुष्ट कर दिया गया। इन्होंनीसिया के शासन का कार्य भी वहां के राष्ट्रीय नेताओं के लेक यह लिया कारान के सर्वथा अयोग्य हैं, और पाश्चात्य शासनों का मत था, विर इन देशों के लोग स्वशासन के सर्वथा अयोग्य हैं, और पाश्चात्य शासन के अन्त का केवल यह परिणाम होगा, कि सर्वत्र अराजकता छा जावगी। पर जापान ने एन देशों के

राष्ट्रीय नेताओं को यह अवसर दिया, कि वे सरकार के कार्य को अपने हाथों में हे हों। ये नेता अपने कार्य में पूर्णरूप से सफल हुए और एक बार 'स्वराज्य' प्राप्त कैर हेने से इन देशों में इतनी अधिक राष्ट्रीय शक्ति विकासित हुई, कि महायुद्ध में जापान के परास्त हो जाने पर भी पाइचात्य देशों के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि वे इन देशों को फिर से अपने साम्राज्यवाद का शिकार बना मकें। बरमा, मलाया, फिल्प्पिन, इन्डोनीसिया आदि देशों में जापान के प्रयत्न से जिन स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई, उनके सम्बन्ध में हम अगले एक अध्याय में विशद रूप से प्रकाश डालेंगे।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के लिये जापान का उत्कर्ष बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। जापान की सेनाओं ने ब्रिटेन, अमेरिका और हालैण्ड की सेनाओं को परास्त कर दक्षिण-पूर्वी एशिया को स्वाचीन होने का अवसर प्रदान किया था । यह ठीक है, कि जापान इस भुखण्ड को अपने संरक्षण में रखना चाहता था। उसकी यह नीति थी, कि इन देशों में जो राष्ट्रीय सरकारें कायम हों, वे जापान को अपना मित्र, सहयोगी व मंरक्षका मानें और आर्थिक क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग करें। पर जापान की यह आकांक्षा पारचात्य देशों के साम्राज्यवाद से अनेक अंशों में भिन्न थी। (१) जापान के लोग एशियन हैं, वे एशिया के अन्य निवासियों को अपनी अपेक्षा उस ढंग से हीन नहीं समझने थे, जिस ढंग से कि पाश्चात्य गीरा क्र लोग उन्हें हीन मानते थे। (२) जापान ने यह प्रयत्न नहीं किया, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में अपना आविपत्य व साम्राज्य स्थापित करे । जापान की सैनिक शक्ति के सम्मुख इन देशों की शक्ति सर्वथा अगण्य थी । यदि वह चाहता, तो अत्यन्त सुगमता से इन देशों को अपनी राजनीतिक प्रभुता में ला सकता था और इन पर उसी ढंग से अपने गर्धार जनगरी द्वारा शामन कर सकता था, जैसे कि वरमा, भारत आदि में ब्रिटिश लोग करते थे। पर महायुद्ध की विकट परिस्थिति में भी जापान ने इन देशों में स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना की और इनपर अपने राजनीतिक प्रभास्य की कायम वारने का उद्योग नहीं किया । (३) जापान ने यह यतन अवश्य किया, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन देशों के साथ आधिक सहयोग कायम करे। क्रुन्डोनीसिया मे पेट्रोलियम् प्राप्त करने व मलाया आदि से रज़ड़, टीन आदि युड़ी-वैयोगी पदार्थों को प्राप्त करने की उसने भरपूर कोशिश की । उसने इन देशों की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारों के साथ इस प्रकार के समझौते किये, जिनके अनुसार इन देशों की सरकारों ने पेट्रोलियम, टीन, रखड़ आदि पदार्थों को जापान को देना स्वीकार किया । पर यह बात सर्वथा स्वाभाविक थी । इन्डोनीसिया, मलाया

आदि में जो सरमारें मायम हुई थी, उनका लाग इसी में था, कि महायुद्ध में पाश्चात्य देशों को सफलता न होने पाये । पाश्चात्य देशों की सफलता न मही परिणाम है। समला था, कि दक्षिण-पूर्वी एजिया की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता फिर से खतरे में पर्कें जाती । अनः उन्होंने न केवल आधिक क्षेत्र में जानान के साथ महयोग किया, अपितु ऐसी राष्ट्रीय सेनाओं का भी संगठन किया, जो पाश्चात्य देशों के निरुद्ध संवर्ष करने में तत्पर थीं । इन्होंनीसिया आदि में जब पाश्चात्य देशों की मेनाएं एक बार फिर विजेता के कुप में प्रविद्ध हुई, तो वहां की राष्ट्रीय सेनाओं ने इन विदेशी आकान्ताओं का शिवनभर मकावला किया।

पर इस प्रसंग में यह निर्दिष्ट कर देना भी आवश्यक है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया को पारवात्य साम्राज्यकाद के चंगुल से मक्त कराने में जापान का अपना स्वाय भी कम नहीं था । आर्थिक आनश्यकताओं से जापान इस बात के छिये वियश था, कि यह अपने साम्राज्य या प्रभावक्षेत्र का विस्तार करें। मञ्चकुओं को एक पृथक व स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्शित करके जापान ने एक नये हंग के साम्राज्यवाद का श्रीनणेश किया था । मञ्चूकुओ एक स्वतन्त्र राज्य था, पर वह जानान के प्रशाद में था । यांग चिग-त्रेर्ड के नेत्तुस्व में नानकिंग में जो स्वतन्त्र चीनी सरकार कायग हुई थी, यह भी जापान के प्रभाव में थी । सञ्चुकुओ और चीन के जानीतिकाँ शासन की अपने हाथ में न छेने पर भी उन देशों के शासन पर जापान का प्रभाव स्पष्टरूप से विरामान था। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के सम्बन्ध में भी जापान की यही नीति श्री, कि उनमें जो स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरफारें गायम हों, वे भञ्चुकुओं और नानवित्र सरकार के समान जापान के प्रभाव में रहे। बस्तुतः जायान पूर्वी य दक्षिण-पूर्वी एशिया में एक ऐसे गुट की स्थापना करना बाहता था, जिसके देश राजनीतिक द्विट से स्वतन्त्र रहते हुए भी जापान को अपना पथप्रदर्शक, नेता व संरक्षक मानें। पर लाय ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि आपान की यह नीति यक्षिण-पूर्वी एशिया को गुलामी के बन्तनों से गुवन करके राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता। पहुंचानेवाली थी । पारवात्य साम्राज्यवाद की जंजीरों को तोड़कर इन वेशों के लोगों को जो राष्ट्रीय स्वतन्थता प्राप्त करने का सुवर्णीय अवसर हाथ छन। था, उसके कारण उनमें राष्ट्रीय गीरत, आत्मरामान और देश-प्रेम की भावना इस हद तक उत्पन्न हो गई थी, कि वे जापान की अबीनना को सुगमता के साथ स्वीकार नहीं कर सकते थे।

(३) जापान की पराजय

बरमा को जीतने के लगभग दो साल बाद मार्च, १९४४ में जावान ने भारत

पर आक्रमण करना शुरू किया । यह आक्रमण आजाद हिद सरकार के सहयोग से किया जा रहा था । भारत के प्रसिद्ध नेता थी सुभाषचन्द्र वीस ब्रिटिश सरकार की तजरबन्दी से छट बार जर्मनी पहुंच गये थे। उनका खयाल था, कि जिटन के चंगुरु से भारत को पुनत कराने का यह मुबर्णीय अवसर है । यदि महायह में ब्रिटेन की पराजय हो जाय, तो भारत के स्वतंत्र होने में कोई बाबा नहीं रह जावगी । इसल्यि उन्होंने यूरोप में विद्यमान भारतीयों का एक सङ्घठन बनाया, और युद्ध के नगर्य में जर्मनी के साथ सहयोग प्रारम्भ किया। जब जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया से ब्वेलाङ्क देशों के प्रभुत्त का अन्त कर दिया, तो श्रीयत् सुभाषचन्द्र बास जागान चले आये । सिगापूर, मलाया आदि में लाकों भारतीय यसते थे। जिटेन की जो फीजें इस क्षेत्र में जापानियों के हाथ पड़ गई थी, उनमें भी भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। श्रीयत बोस ने इन्हें देशभीवता और राष्ट्रीयता का सन्देश दिया। ब्रिटेन की सेना में ये भारतीय केवल वेतन व सांसापिक समुद्धि व गौरव की खातिर भरती हुए थे। देज-प्रेम और राष्ट्रीयता का इनमें सर्वथा जभाव था। श्रीयुन् बोस के तेजस्वी भागगां से इनकी आंखें खुल गर्ट । जापान की विजयों के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षैचिविध देशों ने जो राप्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, उसका उदाहरण इनके सम्म्ण विद्यमान था । ये स्वेन्छापूर्वक बहुत नड़ी संख्या में आजाद हिन्द फीज में शामिल हुए । वाकायदा आजाद हिन्द सरकार का संगठन किया गया । श्रीयत् बोस इस रारकार के 'नेनाजी' जने, और इस आजाद हिन्द सरकार ने भारत की ब्रिटेन के प्रभुत्व में मक्त कराते के कार्य को अपने हाथ में लिया । आसाम की पूर्वी सीना पर मणिपुर की रियासत पर वाकायदा हमला किया गया। कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा, कि ब्रिटिश सेना इस क्षेत्र में नही टिक सकेगी। पर अन्त में उनकी विजय हुई। आजाद हिन्द मेना और उसके जापानी सहायकों को पीछे हटना पड़ा और भारत में ब्रिटेन की सत्ता सुरक्षित हो गई। १९४२ से १९४४ तक दो साल जागान ने भारत पर आक्रमण करने या कोई प्रयत्न नहीं किया, यह उसकी भारी भूल थी । इस अरसे में बिटेन ने भारत के धन व जन की अपार शक्ति को भलीभांति मंगठित कर लिया था । भारत और आस्ट्रेलिया में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने संयुक्त मौरचे कायम कर लिये थे। इनको आधार बनाकर मित्रं राज्यों ने जापान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने की योजना तैयार कर ली थी।

१९४२ में जब जागान ने बरमा से बिटिश शासन का अन्त किया था, तो ब्रिटेन की सैनिक शक्ति बहुत अस्त-व्यस्त दशा में थी। सिगापुर, मलाया, बरमा आदि से भागकर जो ब्रिटिश लोग भारत पहुंच रहे थे, उन्हें संभाल सकना भी भारत की ब्रिटिश सरकार के लिये एक विकट सगस्या थी। १९४२ में भारत में स्वराज्य के आन्दोलन ने भी बहुत विकट रूप घारण वार लिया था। अगस्त, १९४२ में भारत की राष्ट्रीय महासभा ने विदेशी ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध करने के लिंदी अधिक उन्न उपायों का अनुसरण वारने का निश्चम कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जनता में तीन्न भावना उत्पन्न हो चुकी थी, ओर स्वराज्य प्राप्ति की यह उत्कण्ठा अनेक रूपों में प्रगट होने लगी थी। देशभक्त भारतीय युवक ब्रिटिश सत्ता को लिन्न-भिन्न करने के लिये बड़ी से बड़ी कुर्जानी करने को तैयार हो गये थे। सरकार के प्रतिरोध ने इतना उन्न स्पा धारण कर लिया था, कि रेल, तार और डाक तक में अनियमितता आ गई थी। कई स्थानों पर जनता खुले तौर पर चिद्रोह के लिये कटिबद्ध हो गई थी। पर जापान ने भारत पर आक्रमण कर इसे भी इन्डोनीसिया, बरगा आदि के समान पाश्चात्य साम्राज्यवाद से मुक्त कराने के इस सुक्रणीय अवसर का कोई उपयोग नहीं किया। बाद में मार्च, १९४४ में जब आजाद हिन्द फीज ने भारत को स्वतन्त्र कराने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया, तो भारत में ब्रिटिश व अमेरिकन सेनाओं ने अपनी अस्ति को भारत के स्वान्त व सुक्ववस्थित कर लिया था।

अगस्त, १९४४ तक जापान के भारत पर आक्रमण कर सकते का भय संकृष्ट हो गया था। इसके विपरीत, ब्रिटिश सेना ने बरमा की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। इस्फाल आसाम की सीमा का प्रमुख नगर है। यदि आजाद हिन्द सेना व जापान इसे जीत सकते, तो आसाम पर कब्जा करने का गार्व उनके लिये खुळ जाता। पर इसमें उन्हें असफळता हुई और ब्रिटिश व अमेरिकन सेनाओं ने बरमा की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जनवरी, १९४५ तक उनरी यरमा मित्रराज्यों के अधिकार में चला गया। इ मई, १९४५ को रंगून पर भी मित्रराज्यों का कब्जा हो गया। यद्यपि जापानी व बरमी सैनिकों की अनेव टोलिया इसके बाद भी बरमा में युद्ध करती रहीं, पर अब वरमा पर एक बार फिर ब्रिटेन का आविपत्य कायम हो गया था। बरमा की विजय से मित्रराज्यों के लिये न केवल माल्या की तरफ आगे बढ़ सकना सम्भय हो गया था, अपितु चीन की चूंगिकिंग सरकार को स्थलमार्ग हारा सहायता पहुंचा सकता भी सुगम हो गया था। उत्तरी बरमा से रेल व मोटर मार्ग हारा पहिचम-दक्षिणी चीन का सम्बन्ध था और चीन का यह प्रदेश इस समय भी नियांग काई बंक की नुंगिकंग सरकार के अधीन का स्था

जनवरी, १९४५ में अमेरिकन रोनाओं ने फिल्लिपीन द्वीप ममूह पर हमले शुरू किये । एक लाख से अधिक अमेरिकन सैनिक जहाजों द्वारा लूजों। द्वीप पर उतार दिये गये । शोध्र ही मनीला पर कब्जा कर लिया गया और धीरे-धीरे सम्पूर्ण

फिलिंगीन द्वीप समूह अमेरिया के प्रमुत्त्व में आ गया । अब अमेरिकन सेनाओं ने फ़ुलिप्पीन को आधार बनाकर जापान के अधिक समीप विविध टापुओं पर आक्रमण र्वारम्भ किये । इससे चीन में भी चियांग काई ज्ञेक की जापान-विरोधी सरकार को बल मिला । प्रशान्त महासागर के विविध द्वीपों से जापानी सेनाओं की बाहर निकालने ने लिये ब्रिटिश और अमेरिकन जल व वायुसेना अपूर्व कार्यशक्ति प्रदक्षित करने लगी । जिस वायुवेग से जापान का उत्कर्ष हुआ था, उसका पतन भी उसी गति से हआ। १९४५ के मध्य तक यह दशा आ गई थी, कि जापान को अपनी स्थिति बिलकुल डांवाडोल प्रतीत होने लग गई थी। वरमा को अपनी अधीनता में लाकर ब्रिटिश लोगों ने मलाया पर आक्रमण किया । इस समय मित्रराज्यों की रोनाओं के तीन मुख्य आधार थे, भारत, आरट्रेलिया और पश्चिमी चीन । इन तीनों क्षेत्रों को अपना आधार बनाकर मित्रराज्यों की जल व वाय शक्ति बड़ी तीमता के साथ जापान व उसके प्रभाव में विद्यमान दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों पर आक्रमण में तत्पर थीं। इन आक्रमणों का मुकाबला कर सकना जापान की सनाओं के छियं राम्भव नहीं था । मई, १९४५ में यूरोप के रणक्षेत्र में जर्मनी की ुपराजय हो गई थी और ७ मई, १९४५ को जर्मनी ने आत्म समर्पण कर दिया था। इस दशा में मित्रराज्यों की सम्पूर्ण शक्ति जापान को परास्त करने के लिये छग गई थी और अकेले जापान के लिये यह सम्भव नही रहा था, कि वह मित्रराज्यों की सम्मिलित शक्ति का विरोध कर सके।

जुलाई, १९४५ में जापान पर घोर बम्ब वर्षा शुरू की गई। हवाई जहाजों हारा न केवल जापान के वल कारखानों, रेलवे लाइनों और युद्ध सामग्री के भण्डारों पर नम्ब बरसायं जाने लगे, अपितु जापानी जहाजों का भी ड्वाया जाना शुरू किया गया। जुलाई, १९४५ के दो सप्ताहों में जापान के ४१६ जहाज समुद्र नल में पहुंचा दिये गये, और ५५६ हवाई जहाज नष्ट कर दिये गये। २० और २८ जुलाई को जापान की जलसेना पर जबदेस्त हमला विया गया और इन दो दिनों में जापान के ५०० जहाज ड्वा दिये गये। चीन और जापान के मध्यवर्गी समुद्र में बड़ी संख्या में बाहदी सुरु हो बिला दी गई,और जापान के बंदरगाहों पर हवाई हमलों का जोर बहुन बढ़ गया। चीन में महासेनापित चियांग काई शेक की सेनाओं ने आगे बढ़ना बहुन बढ़ गया। चीन में महासेनापित चियांग काई शेक की सेनाओं ने आगे बढ़ना कियां थी छे हटने लगीं। २६ जुलाई, १९४५ को श्री ट्रु मैन (राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद श्री-रू मैन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गये थे), श्री. चिंचल और चियांग वाई शेक की और से एक घोषणा जापान की जनता के नाम प्रकाशित की गई, जिसमें यह बाहा गया, कि जापान की साम्राज्य विस्तार का इरादा छोड़ देना

चाहिये, जापान के अपने प्रदेशों पर निजया ग्यों की सनाएं कठना पहीं करना चाहती, जापान की राष्ट्रीय स्वतन्त्रमा अअणारकी जायमी और वहा सक्ते अभी में लोकहाडू जामन की स्थापना की जायमी। अतः जापान को चाहिये, कि गुर को जारी ने रखकर वह मित्रराज्यों के सम्मुख आत्म गमर्पण कर दे। पर जापान के नेताओं व इस घोषणा को को और बोई ध्यान नहीं दिया। उनका खयाल था, कि अब भी वे जित्रराज्यों को परास्त करने में समर्थ हो सकते है । उन्होंने गृह को जारी रखने में ही अपने देश का हित सम्मा।

८ अगस्त, १९४५ को रूम ने भी जापान के लिखाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। मञ्ज्रिया (मञ्जुकाओं का पृथक् व स्वतन्त्र राज्य) पर रूसी सेनाओं ने अधिकार कर लिया और उत्तरी चीन का यह सम्पूर्ण प्रदेश कम्य निस्ट रूस के प्रभाप में आ गया गया । इन सब विषम परिस्थितियों में भी जापान छड़ाई को जारी रखने के लिये वैयार था। पर इस समय अमरिका ने एक नये अस्थ का प्रयोग किया, जिसके कारण जापान में आतंत्र छा गया । यह अस्त्र एटम तम्ब वा । वैज्ञानिक लोग यह मलीभांति जानते थे, कि सब पदार्थ परमाणुओं (एटम) के संयोग ने बने होते हैं। परमाण उस सुध्म तत्त्व का नाम है, जिसके दुवाहे नहीं हो सकरों। ये अत्यन्त मुक्या परमाणु एक शक्ति से आपस में जुड़े रहते हैं। यदि इनको एक दूसरे से पृथक किया जा सके, तो जो असित प्रादर्भत होगी, वह उत्तरी अवदेश्त होगी कि गंधार की कोई भी जात शक्ति उसका मुकाबङा नहीं वर सबेगी । अग्नि, याय, जल, वियुत्-ये सब प्राकृतिक वाक्तियां है, पर परमाण वाक्ति उनकी अवेशा बहुत अधिक बणवती हैं। इस शक्ति का प्रयोग मनुष्य कैसे कर राके, यह जानने के लिये यैशानिक लोग जी जान से जुटे हुए थे। जर्मन वैज्ञानिक भी इस म्योज में नत्पर थे, और हिटलरको आशा थी, कि वे एटम बम्ब का आविष्कार करते में समर्थ हो जातेंगे। अमेरिकन वैज्ञानिक भी इसी कोशिय में छवे थे। जर्मनी की इसमें देर ही गई और भिष्याज्यों की सेनाओं ने पहले ही उसे परास्त कर दिया । मुक्त समय धाद अमेरिका वैज्ञानिक अपने प्रयत्न में सफल हो गये और उन्होंने एटम बम्ब तैयार गर लिया । अमेरिका ने इस वस्य का प्रयोग जापान को परास्त करने के किये किया । ५ अगस्त, १९४५ की पहला एटम बम्ब हिरोशीमा नामक नगर पर गिराया गया । इससे चार वर्गमील का प्रदेश बिलकुल नष्ट हो गया । हिरोशीमा नगर का नाम व निशान भी 🚉 नहीं बचा। एटम बम्बना असर इस चार वर्गमील के प्रदेशके नारी ओरभी दूर-दूरी तक पड़ा। इसके प्रभाव से लामों आदमी बीमार पड़ नये, उनके शरीरपर फुन्सियां ंनिकल आई। कई प्रकार की बीमारियां सर्वत्र फैल गई। पर जापान के सैनिक नेताओं ने अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया । भित्रराज्यों की और से तीस लात

परचे हवाई जहाजों द्वारा जापान पर गिराये गये, जिनमें एटम बम्ब की भयंकरता का वर्णन करने यह कहा गया था, कि अब लड़ाई को जारी रखना बिलकुल व्यर्थ हैं। अब जापान का हित इसी में है, कि वह आन्मसमर्पण कर दे। पर जापान पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। रूस ने भी इसी बीच में उसके खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। ९ अगस्त, १९४५ को दूसरा एटम बम्ब नागासाकी पर गिराया गया। इसके कारण यह विशाल नगर एकदम तहस-नहस हो गया। अब जापान के समाद ने अनुभव वित्या, कि लड़ाई को जारी रखने से देश बिलकुल नष्ट हो जायगा। उचिन यही है, कि आत्मसमर्पण करके लड़ाई का अन्त कर दिया जाय। १५ अगस्त, १९४५ को जापान ने मित्रराज्यों के सम्मुख बिना किसी शर्त के आत्मन मगर्पण कर विथा और पूर्वी एशिया में यद्ध का अन्त हो गया।

१९४२ में जापान सर्वत्र विजयी था । चीन के बड़े भाग में ऐसी सरकारें बायस थीं, जो जापान के साथ सहयोग करने को उसत थीं । मञ्चकुओं का राज्य जापान को अपना संरक्षक व सहयोगी मानता था और नानकिंग सरकार राजनीतिक विष्ट से स्वतन्त्र होती हुई भी जापान के प्रभाव में थी । दक्षिण-पूर्वी एशिया से पापचात्य देशों के साम्राज्यवाद का अन्त हो गया था और इस क्षेत्र के विविध देशों हैं जो नहीं राष्ट्रीय सरकारें कायम हुई थीं, वे पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगल से अपनी रक्षा करने के लिये जापान की सहायता पर निर्भर करती थीं। पर १९४५ के मध्य तक जापान की शक्ति पूर्णतया क्षीण हो गई थी और सैनिक क्षेत्र में उसे सर्वत्र परास्त होना पड़ा था। जापान की इस पराजय का मुख्य वारण उसके विरोधियों की अपार शवित शी। अमेरिका के युद्ध में प्रविष्ट होने से मित्रराज्यों के धन व अन की जितत में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई थी । महायुद्ध में जापान जर्मनी और इटली का पक्ष लेकर शामिल हुआ था। जर्मनी ने युरोप के जिन देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित विधा था, उनकी जनता जर्मन शासन के विरुद्ध थी। फांस, पोलैण्ड, चेको-स्लोवाकिया, ग्रीस, युगोस्लाविया आदि सब देशों में सर्वसाधारण जनता यह अनभव भरती थी, कि जर्मनी का नासन उनके राष्ट्रीय गीरव की दरित से सर्वथा अनुचित है। उनमें ऐसे देशभवतों की कमी नहीं थी, जो अपना सर्वस्य कुर्वान करके भी विजेता जर्मनी के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिये उदान थे। जर्मनी के लिये यह तो सम्भव था, कि वह लड़ाई के मैदान में बर्जु सेना को परास्त कर सबे । पर यह बात सुगम नहीं थी, कि जर्मनी सर्व साधारण जनता की स्वातन्त्र्य भावना का पूरी तरह से दमन कर सके। इसमें सन्देह नहीं, कि जर्मनी ने अपने अधिकृत और विजित रेजों में नाजी नियानों को नावने वाले पहीं , के लोगों का बासन स्थापित किया । पर इस जान में कोई सन्देश नहीं, कि अर्मनी

ने जिम हंग से यूरोप के वड़े भाग पर अपना आधिपत्य गायग कर लिया था, वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के अनुकूल नहीं था । यही कारण है, कि युरोप के महायुद्ध में नाजी और फैसिस्ट शिलियों की पराजय हुई। जब एक कर्री ब्रिटन, रूम और अमेरिया की सम्मिलित शक्ति युरोप में जर्मनी और इटली को गरास्त करने में समर्थ हो गई, तो उसके लिये यह वहत कठिन नहीं रहा, कि वह पूर्वी ब दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान की भी परास्त कर सके। इस क्षेत्र में जापान ने जां कार्य किया था, वह राष्ट्रीय भावना के अनुकुल था । दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों को पाश्चात्य साम्राज्यवाद से स्वतन्त्र कराके जापान ने एक ऐसा कार्य किया था, जोकि मानव इतिहासकी प्रवृत्तियों के अनुरूप था। पर जापान को इतना समय नहीं मिला, कि वह इन देशों की नई राष्ट्रीयसरनारों के साथ गहयोगवार इनके आर्थिक जीवन का सुचार रूप से विकास तर सके और इनकी धन व जनसमित को पाश्चात्य देशों का मुनावला करने के लिये प्रयुक्त कर सके । यदि युरोप में जर्मनी कुछ साल तक भित्रराज्यों का मुकाबला कर सकते में समर्थ रहता, तो जापान को भी एकिया में अपनी क्षतित को सुदृढ़ बनाने का अवसर मिल जाता । पर युद्ध के रांचालन में जर्मनी ने अनेक भूलें की थीं। उनकर्क की दुर्घटना के बाद जर्मनी ब्रिटेन पर सुगमता के साथ आक्रमण कर सकता था । मई, १९४० में जब फांस 🏖 परास्त हो जाने के बाद ब्रिटिश सेनाएं बड़ी कठिनता से उन्नलैण्ड लीट सकते में समर्थ हुई, तो ब्रिटेनकी अबित इतनी अस्त-व्यस्त थी, भि जर्मनी गुगमता के साथ उमें अपना वशवर्ती बना सकता था। पर हिटकर ने इस अवसर नम पूर्ण इप से उपयोग नहीं भिया । ऋस के साथ लड़ाई में उलड़ा पड़ना जर्मनी की दूसरी भयंभर भुछ थी । १९३९ में जर्मनी और एस में तटस्थता की सन्धि हो चुकी थी । पर हिटलर के हृदय में वम्युनिज्म के प्रति घोर थिहेंग था। गदि वह इस थिहेंग की उपेक्षा बार यह अनुभव भारता, कि रूस के साथ तटस्थता की नीति का अनुसरण करने में ही जर्मनी का हित है, तो शायद नाजीज्य का अन्त इतना द्वंशापूर्ण न होता। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के साथ रांगुक्त रूप में लड़ सकता जर्मनी की शक्ति के बाहर था । १९१४-१८ के महायुद्ध के समान १९३९-४५ के महायुद्ध में भी जर्मनी और उसके साथियों के खिलाफ संगार के बहुत में देश (इनकी कुल संग्या ४४ थी) मिलवार युद्ध कर रहे थे। विश्व के उतने देशों की सम्मिक्ति गिक्त क् मुकायला कर सकता जर्मती व उसके फैलिस्ट गाथियों के लिये सम्भव नहीं था 🏗 जर्मनी के परास्त हो जाने के बाद यह असम्भव था, कि जापान अकेला संसार के ४४ राज्यों की संयुक्त जाकित के मुकानके में खड़ा हो सके। इसमें सन्देह नहीं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश यह अनुभव बरते थे, कि महायुद्ध में पाश्चात्य

देशों की विजय रें। उनकी नर्ड प्राप्त हुई राष्ट्रीय स्वतन्त्रता मुरक्षित नहीं रह सक्केगी। इसीलिये जागान के साथ उनकी सहानुभृति थी। पर नीन साल के थोड़े से समय में जागान व इन देशों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे अपने व्यवसायों को इतना अधिक उधन नार लें, कि अमेरिका जैंगे समृद्ध व व्यवसाय प्रधान देश की शिवत का राफलतापूर्वक मुकावला कर सकें। दक्षिण-पूर्वी एकिया के लोगों के लिये तीन साल के वाल में यह भी सम्भव नहीं था, कि वे अपनी सेनाओं को इम रूप में संगठित कर लें, जो कि ब्रिटन और अमेरिका की अपार जल व वायुशक्ति का सामना कर सकें। परिणाम यह हुआ, कि जर्मनी के समान जापान को भी मित्रराज्यों से परास्त होना पड़ा। पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में कुछ गमय के लिये राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के कारण जो असाधारण देश-प्रेम व स्वातन्त्र्य की भावना विकसित हो गई थी, उसे दवा सकता पाश्चात्य देशों के लिये सुगम नहीं था। इसीलिये ये देश जापान की पराजय के बाद भी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा करने में अनेक अंशों में सफल हुए। इन देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता किस अंश तक कायग रही, इस विषय पर हुए। इन देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता किस अंश तक कायग रही, इस विषय पर हुम अपले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना

(१) महायुद्ध और चीन

दिसम्बर, १९४१ में जब जापान ने महायुद्ध में प्रवेश किया, तव चीन की क्या स्थिति थी, इस विषय पर हम पहले प्रकार चाल चुके हैं। मञ्चिरिया में एक रुपतंत्र व पथक राज्य विद्यमान था, जिसे 'मञ्जूकुओ' कहते पं । यह राज्य जापान के प्रभाव में था । नानविस को राजनानी बनायर एस स्टांत नीनी सरकार की स्थापना हो चकी थी, जो जागान के साथ सहयोग करने में ही जगने देश का हित समामती थी। नानिकार की इस चीनी सरकार के नेता अपने को पार कत कत सन का अनुषाधी बाहते थे और यह समझते थे, वियांग काई शैक में बंगुटन में संगीक्त में जो सरकार विद्यान है, यह कुओभिनांग वल के आदओं व सिदान्तों का अनुसर्फ नहीं कर रही है। इस सरकार के नेताओं की दृष्टि में चीन की उर्धात के छिये यह उपयोगी था, कि वह जापाल के राह्योग को महत्व दे और अमेरिका आदि पाइनात्व देशों को अपना पथ प्रदर्शक व भित्र न समझ यह जापान के माथ मैधी सम्बन्ध स्थापित करे। चीन के पूर्वी समुद्र तट के साथ के सब प्रदेश जागीकम सरकार के अधीन थे। महासेनापति चियांग काई शंग के नेतृत्व में जो स्वतंत्र पारद्वीय सर-कार स्थापित थी, उसकी राजधानी धुंगविम थी । उत्तर-पश्चिमी धीव में कस्य-निस्ट सरकार स्थापित थी, जिसवा प्रधान नेता माओ हमे तंत था । इस सरकार की राजधानी येनान थी। वान्युनिस्ट लोगों की यह सरकार राजनीतिक व मैनिश दृष्टि से अपनी पृथक् मला रचते हुए भी चंग्रातिम की शब्दीय सरकार के साथ सहयोग नारने के लिये तैयार थी। उसाम यह मत था, कि एक्ते व नीव के सब क्लों के छोगों को आगस के मतभेयों को भूछावार आपान के शाय गंधर्म गरने में अपनी सारी शक्ति को लगा देना चाहिये और चंगकिंग की बेल्डीय मरमार का संबद्ध लीकतन्त्र सिद्धान्ती के अनुसार विधा जाना चाहिये। मन एनी के कीसों की यह अवसर होना चाहिये, नि वे लोकमत की अपने पक्ष में परकार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकें। कम्युनिस्ट लांग चुगविक सरकार की अधीनता में रहते हुए जापान के साथ युद्ध कार्य में पूर्ण एप के मह्योग देने को उद्यत थे। पर चियांग काई शेक जापान के साथ संघर्ष की अपेक्षा चीन की आन्त-रिक राजनीति को अधिक महत्व देता था और उसे इस बात का भय था, कि कहीं कैंग्युनिस्ट लोग चीन में अधिक प्रबल न हो जावें। इसलिये वह जापान के विरुद्ध संघर्ष में कम्युनिस्टों के सहयोग को बहुत महत्व नहीं देना चाहता था।

चीन के संपूर्ण समुद्र तट पर जापान का अधिकार हो जाने के कारण चियांग काई शेक की सरकार का अन्य देशों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था । इस कारण अमेरिका, ब्रिटेन आदि पारचात्य देश उसे केवल दो मार्गो से सहायता पहुंचा सकते थे-(१) इन्डोचायना से और (२) उत्तरी बरमा से। जब यूरांप में फ्रान्स पर जर्मनी का आधिपत्य स्थापित हो गया, और मार्शल पेता के नेतत्व में विशी को राजधानी बनागर एग ऐसी फेञ्च सरकार की स्थापना हुई, जो जर्मनी के साथ मैत्री सम्बन्ध कायम वारने को तैयार थी, तो श्री देकू को इन्डोचायना का गदर्नर जनरल नियत किया गया । श्री देक मार्शल पेता के पक्षपाती थे और इसी बात में अपने देश का हित समझते थे. कि जर्मनी व उसके साथियों के साथ मैत्री सम्बन्ध रखा जायं । इसीलिये उन्होंने जापान के विरुद्ध चियांग काई शेक की सहा-यता न नरने की नीति का अनुसरण किया । जापानी सेनाओं को इन्डोचायना में अनेक प्रकार की स्विधायें दी गईं और मित्रराज्यों के लिये यह सम्भव नहीं रहा. कि वे इन्होचायना के मार्ग से चुंगिक गंसरकार को युद्ध सामग्री आदि पहचा सकें। इस दशा में १९४१ में चियांग नाई शेक को सहायता पहुंचा सकते का केवल एक ही मार्ग ब्रिटेन और अमेरिका के लिये शेष रह गया था। यह मार्ग उत्तरी बरमा से होकर जाता था। पर जब १९४२ के प्रारम्भ में जानान ने बरमा को विजय कर लिया, तो चुंगिकिंग को सहायता पंहचा सकते का यह मार्ग भी अवरुद्ध हो गया । अमेरिकन और ब्रिटिश लोग यह मली-मांति अनुभव करते थे कि जापान की परास्त करने के लिये चियांग काई शेक की सहायता करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि चियांग बाई शेक की सरकार का पतन हो जायगा, तो जापान की दो बड़े लाभ होंगें--(१) जापान की जो सेनाएं चुंगिकंग सरकार का प्रतिरोध करने के लिये चीन में विद्यमान हैं, वे खाली हो जावेंगी और जापान उनका उप-योग यद के अन्य क्षेत्रों में कर सकेगा। (२) चीन की सम्पूर्ण जनता यदि नानिका सहकार के शासन में आ जावगी, तो जापान के लिये यह बहुत सुगम होगा, कि वह इसे विशाल देश की घन व जन-शक्ति का उपयोग मित्रराज्यों को परास्त करने में मर सके। इंसलिये ब्रिटेन और अमेरिका इस बात के लिये उत्सुक थे, कि वे चुंग-किंग सरकार को अधिक से अधिक सहायता करते रहें, ताकि वह जामान के मुकाबले में अपनी स्थिति को कायम रख सके। अतः अब इन राज्यों ने

थागुमांगं हारा चियांग काई शेनाकी सरकार को सहायता पहुंचाना प्रारम्भ किया। हिमालय की उच्च पर्वतमाला को पार कर अमेरिका और जिटेन के हवाई जहाज भारत में चुंगिंकेंग जाने लगे और उन्होंने वायुयानो हारा युद्ध सामग्री को चुंगिंकिंग पहुंचाना अ्क किया। जनवरी, १९४४ में १३,३९९ टन युद्ध सामग्री भारत से चीन पहुंचाई गई। एक साल बाद जनवरी, १९४५ में वायु मार्ग हारा चीन पहुंचाई जानेवाली युद्ध सामग्री की मात्रा ४३,८९६ टन तक पहुंच गई। हवाई जहाजों हारा इतनी अधिक युद्ध सामग्री प्रति मास चीन मेजना उम बात का प्रमाण है, कि अमेरिका और बिटेन चियांग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार की सत्ता को कितना अधिक महत्व देते थे। पर वायु मार्ग हारा भारी माल को हिमालय वे पार भेज सकता सुगम नहीं था। इसीलिये मोटर ट्रक, टैंक आदि भारी उपकरणों को पर्यान्त सात्रा में चीन नहीं भेजा जा सकता था।

१९४२ में चुंगिकिंग सरकार का पास्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध प्रायः नहीं के कराबर रह गया था। इस स्थिति में यह स्वाभाविक था, कि चियांग काई जेक की क्षंतीनता में विद्यमान चीन की जनता में निरन्तर असन्तीप बढ़ता जाये । चंगिका सदकार के लिये अपने मित्रराज्यों से युद्ध सामग्री की सहागता प्राप्त कर सकता सगम नहीं था । उसके अपने प्रदेश में कल कारखानों का प्रायः अभाव था, और 🚜 सम्भव नहीं था, कि चियांग काई शेक की सरकार अपनी युद्ध सामग्री को स्वयं उत्पन्न कर सके । जो थोड़े बहुत कारखाने पश्चिमी चीन में विद्यमान थे, उन पर भी जापानी हवाई जहाज बहुचा आक्रमण करते रहते थे। आधिक उत्पत्ति की दशा चीन के इस माम में अत्यन्त अस्त-व्यस्त थी । किसान लोग खंती भी इन प्रवेशों में निश्चिन्त रूप से नहीं कर राकते थे। जब फसल तैयार होने को होती थी, जापानी हवाई जहाज खेतों पर अग्निवर्षक बम्ब गिरा देते थे और तैयार फसल की भसा कर देते थे। सब प्रकार के पदार्थों की पश्चिमी चीन में निरंतर कमी होती जाती थी। इस दशा में यदि जियांग काई शेक की सरकार के कर्मचारी वेशभिवत, स्वार्थत्याग और राष्ट्रीय हिन की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते, तो वे रिशति को बहुत कुछ संभाल सकते थे। पर उनका ध्यान जागान के साथ संघर्ष करने की अपेक्षा स्वार्थ साधन की तरफ अधिक था। युद्ध की परिस्थिति से लाग उठाकर वे अपनी 'वैयमितक समृद्धि के लिये तत्पर थे। सेनाओं की सहायता के लिये जो युद्ध सामग्री मायु मार्ग द्वारा चुंगिकाग पहुंचाई जाती थी, उसका भी अन्छा बड़ा भाग चौर बाजिहा में पहुंच जाता था और चियांग काई शेक की सरकार के प्रमुख राजवर्मचारी पुजीपतियों के साथ मिलकर इस माल को चोर बाजार में वेच देते थे। आर्थिक उत्पत्ति की कभी के कारण पश्चिमी चीन के बाजारों में सब अकार के प्राची की गांव

सदा बनी रहती। थी और युद्धकार्य में सहायता पहुंचाने के लिये आया हुआ माल कुँची कीमत पर बड़ी सुगमता के साथ विक जाता था। इस प्रकार चोर वाजार में युद्ध सामग्री को बे चकर चीन के अनेक मेनापति व उच्च राजकर्मचारी अपनी वैयिक्तक समृद्धि के लिये प्रयत्नशील थे। युद्ध को चलाने के लिये जो स्पया अपेक्षित था, उसे टैनसों द्वारा वसूल कर सकना सुगम नहीं था। अतः चुंगिकग सरकार अपने खर्च को चलाने के लिये सबसे अधिक सुगम व क्रियातमक उपाय यह समझती थी, कि अधिक से अधिक मात्रा में पत्र मुद्राओं को जारी कर दिया जाय। इसका यह परिणाम होता था, कि चीन में मुद्रा की कीमत निरन्तर गिरती जाती थी और वस्तुओं की कीमत में निरन्तर विद्ध होती जाती थी।

इस विकट परिस्थिति में भी येनान की कम्युनिस्ट सरकार इस बात के लिये उत्मुक थी, कि जापान के विरुद्ध लड़ाई में चुंगिकग सरकार के साथ सहयोग करे। पर चियांग काई शेक और उसके कुओमिन्तांग दल के साथी कम्युनिस्टों के साथ सहयोग की अपेक्षा उनके विरुद्ध संघर्ष की अधिक महत्त्व देते थे। यही कारण हैं, कि वायुमार्ग द्वारा प्राप्त होने वाली गुद्ध सामग्री का उपयोग वे कम्युनिस्टों के विरुद्ध करने में संकोच नहीं करते थे। चुंगिकंग और येनान की सरकारों में सहयोग किरन्तर फम होता जाता था, और चियांग काई शेक की सर्वोत्कृष्ट सेनाएं जापान के विरुद्ध लड़ाई में न लगकर कम्युनिस्टों के विरुद्ध युद्ध करने में अपनी शक्ति का उपयोग करने में कोई अनीचित्य अनुभव नहीं कारती थीं। जिस समय बिटेन और अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान के साथ घनकोर युद्ध में व्यापृत थे, चीन में चियांग काई शेक और उसकी राष्ट्रीय सेना जापान के खिलाफ लड़ाई न करके येनान की कम्युनिस्ट सेनाओं के साथ युद्ध में संलग्न थी।

चुंगिक्तिंग सरकार जापान के साथ लड़ाई करने में चाहे कितनी ही शिथिलता प्रदिशत कर रही थी, पर बिटेन और अमेरिका की वृष्टि में उसका महत्त्व बहुत अधिकथा। चीन और जापान की लड़ाई दस साल में भी अधिक समय तक जारी थी। युद्ध में जापान हारा निरन्तर परास्त होते रहने पर भी चियांग काई शेंक ने उसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया था। पार्कात्य देशों के राजनीतिज्ञ यह भलीभांति अनुभव करतेथे, कि इतने सुदीर्घ काल तक जापान के साथ निरन्तर संघर्ष करके कुओमिन्तांग सरकार ने असाधारण शक्ति और धैर्य का परिचय दिया है। वे यह भी जानतेथे, कि यदि वांग चिग-वेई के समान चियांग काई शेंक भी जापान के साथ समझौता कर लेता, तो जापान के लिथे चीन की अपरि-मित जन और धनशक्ति का पूर्ण हम से उपयोग कर सबना बहुत नुगय हो जाता। जिस प्रकार भारत पर ब्रिटेन का प्रभुत्व उसकी से यश्चित की वृद्धि से अन्यधिक

सहायक रहा है, और तिटेन भारत के सैनिकों को अपने साम्राज्य प्रसार के लिये प्रयक्त करना रहा है, उसी प्रकार जावान भी चीन की शक्ति को अपने उत्वार्ष के ियं गुगमता के साथ प्रयुक्त कर सकता था । पर चियांग काई अंब के प्रतिरास के कारण यह बात जापान के लिये सम्भव नहीं हो सकी । अतः ब्रिटेन और अमेरिका के राजनीतिक ने ता उसकी सरनार की बहत अविक महत्त्व देते थे, और उमे मब प्रकार से महायाना देने की उद्यत थे। चुंगिकिय सरकार की अपने पक्ष में रखने के िख्यें ११ जनवरी, १९४३ की ब्रिटेन और अमेरिका ने चियांग काई शेक के माथ एक सन्धि की, जिसके अनगार 'एक्स्ट्रा-टैरिटोरिएलिटी की पद्धति' का अन्त किया गुधा । इसके अतिरिक्त, इन देशों को चीन में जो अन्य अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त था, इस मन्धि द्वारा उनकी भी सभाष्ति की गई । साथ ही, यह भी स्वीकार किया गया, कि चीन राजनीतिक वर्षिट से पाक्चात्य देशोंका समकक्ष है,और संसार का एक प्रमुख व बाक्तिशाली राज्य है । इनीलिये जब बाद में संयुक्त राज्य संप (युनाइटेड नेशन्स आर्गनिजेशन) का संगठन किया गया, तो उसकी सुरक्षा परिषद् (सिक्यो-रिटी कींसिल) में चीन को भी स्थिर रूप सं सदस्यता प्रदान की गई। मुरक्षा परिवद के अन्य स्थिर सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, बिटेन, करा और फांस थे। चीन को भी उनका समकक्ष बनाकर मित्रराज्यों ने यह प्रदक्षित किया, कि वे अन्हि राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन को कितना अधिक महत्त्व देते हैं। महायुद्ध के अवसर पर मियपाज्यों की जो अनेक कान्फरेन्सं हुई, उनमें चीन को भी किमन्त्रित किया गया। कैरो की कान्फरेन्स (नवम्बर, १९४३) भें मित्रराज्यों के प्रतिनिधियों ने यहां तक म्बीकार निया, कि महायद्ध की समाप्ति के बाद चीन को वे सब प्रदेश प्राप्त करा बिगं जार्नेमे, जो १८९४ में उसके अधीन थे। इसका अभिपाय यह था, कि प्रथम चीन-जापान गृद्ध के समय से जो विविध प्रदेश चीन के हाथ से विकल कर जापान के प्रभाव व अधीनता में आ गये थे, वे सब चीन की पून: प्राप्त हो जावेंगे । मित्र राज्य इस बात के लिये बहुत अधिक उत्सुक थे, कि चियांग काई शेवा की सरकार जापान के विक्त लड़ाई को जारी एवं और किसी भी प्रकार उसके साथ समझौता न कर ले । पारचात्य देशों में पर्याप्त सहायता प्राप्त न हो सकते के वसरण चुंगीका गरकार जितनी दुर्देशाग्रस्त थी, उसमें यह असम्भव नहीं था, वि वह जापान के साय समझीता करने का प्रयत्न करती । इसीलिये ब्रिटेन और अमेरिया जिल तरह भी सम्भव हो, उसे जापान के खिलाफ लड़ाई जागी रखने के लिये तैयार मरने में तहार थे।

चीन के रणक्षेत्र में युद्ध की जारी रखने के लिये अमेरिका की ओर से जी सेनाएं यहां विद्यमान थीं, या जी युद्ध प्रयत्न जारी था, उसका प्रधान अधिकारी जनरल

स्टिल्वेल था। वह इस बात के लिये उत्सुक था, कि चुंगिकंग सरकार की सम्पूर्ण शक्ति का जापान के खिलाफ लड़ाई के लिये प्रयुक्त किया जाप। अतः उसकी हैं का थी, कि (१) चियांग काई शेक की जो राष्ट्रीय सेनाएं येनान की कस्यनिस्ट सरकार के नाथ संघर्ष में व्यापत है, उनका प्रयोग जापान से लड़ाई के लिये किया जाय । (२) जापान के खिलाफ लड़ाई के कार्य में माओ तमे तुंग की कम्यनिस्ट मेनाओं का सहयोग प्राप्त किया जाय, और चीनी लोग यह के समय में आपस के मतभेदों को भुलाकार संयुक्तरूप से जापान से युद्ध करें। (३) चीन की सेनाओं को नये ढंग की सैनिय शिक्षा दी जाय, ताकि वे जापान से लड़ने में अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें। यह कार्य अमेरिकन सेनापति अपने हाथों में छे और जब चीन की मेना युद्धकार्य में भलीभांति निपुण हो जाय, तो चुंगकिंग सरकार और येनान सरकार की सेनाएं राम्मिलित रूप से जापान के खिलाफ आगे बढ़ना प्रारम्भ करें। जिस प्रकार भारत और आस्ट्रेलिया को आधार बनाकर मित्रराज्यों की सेनाएं जापान के विरुद्ध रुड़ाई की योजना बना रही थीं, वैसे ही जनरर स्टिल्वेल चाहता था, कि पविचमी चीन को भी जापान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिये आधार बनाया जाय । पर महासेनापति चियांग काई शेक स्टिल्वेस की इस नीति से सहमत नैंही था । यह इतनी बात के लिये तो तैयार था, कि जापान पर हवाई आक्रमणों के लिये पश्चिमी चीन को आबार के रूप में प्रयुक्त किया जाय, पर उसे यह बात स्वीकार्य नहीं थी, कि येनान की कम्युनिस्ट सेनाएं भी पूर्वी चीन पर आक्रमण करें और पूर्वी चीन के प्रदेशों पर कम्युनिस्ट लोगों को अपने प्रभूत्व की स्थापना का अवसर मिले । महायुद्ध की समाप्ति पर जापान की पराजय के बाद चीन की आन्तरिक राजनीति जो कल धारण करेगी, वियांग काई होन की दिष्ट में उसका महत्त्व बहुत अधिक था । वह किसी भी दशा में इस बात के लिये तैयार नहीं था, कि येनान के कम्युनिस्टों को चीन में अपने उत्सर्ष का मीका मिले। यही कारण है, कि उसने स्टिल्वेल का विरोध किया और अन्त में अमेरिकन सरकार को विवश होकर स्टिल्बेल को वापस बुलाना पड़ा । अमेरिकन लोग वियांग काई वोक को किसी भी दशा में नाराज करने के लिये तैयार नहीं थे। इसीलिये इस महा-सेनापति के साथ विरोध होने की दशा में जनरल स्टिल्वेल को नीचा देखना पड़ा। 🍡 जनरल स्टिल्वेल को वापस बुला लेने के बाद अमेरिका की ओर से श्री हलें को चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। उसे यह समझने में देर नहीं लगी, कि चुंगिकम सरकार की आन्तरिक दशा बहुत अस्तत्मस्त है, और उसके मणादले में येनान की कम्युनिस्ट सरकार बहुत जिल्हा मुख्य-स्थित । विवयसकी है । असः उसने इस बात का उद्योग किया, कि गुआंगिन्तांग और अम्मृनिस्ट दर्छों में परस्पर ममझौता हो जाये और ये दोनों दल आपम में मिलकर काम करें। पर उसे भी अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई। जनरल हलें भी चुंगिकिय और येनान सरकारों में समझौता नहीं करा सका। पर उसके प्रयत्न का यह लाभ अवस्य हुआ, कि कुर्कें मिन्तांग और अम्युनिस्ट सरकारों में गृहयुद्ध प्रारम्भ नहीं हुआ, यद्यपि चीन की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार जापान को परास्त वरने के लिये किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को करने में असमर्थ रही।

(२) अमेरिका द्वारा चीन में एकता की स्थापना का उद्योग

जनरक हर्ले को चीन में अमेरिकन राजदूत के पर पर विशेष रूप से इसिल्ये नियुक्त किया गया था, ताकि वह चुमकिंग सरकार ओर कम्युनिस्ट लोगों में समझौता कराके उनकी संयुक्त शक्ति को जापान के बिरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रयुक्त कर सके । जनरल हर्ले ने अपने इस प्रयत्न में जो सिद्धान्त सम्मुख रखे थे, वे निम्न-लिखित थे--(१) चुंगिकम की राष्ट्रीय मरकार की सत्ता अक्षुण्ण रहे, उसकी सर्वोच्च स्थिति में कोई अन्तर न आने पावे। (२) चियांग काई शेक्ष स्वतन्त्र चीनी रिपब्टिय के राष्ट्रपति पद पर काथम रहे और चीन की सब राष्ट्रीय गेनाओं का प्रधान सेनापति भी वही रहे । (३) येनान की कम्युविस्ट सरकार चुंगविग 🖏 केन्द्रीय सरकार के आधिपत्य को स्वीकार करे और कस्यनिस्ट गेनायें यह के कार्य में चियांग बाई दोन की राष्ट्रीय सेनाओं के साथ पूर्ण रूप से सहयांग वारें। ७ नव-म्बर, १९४४ को जनरल हर्ले स्वयं येनान गया, और वहां जाकर उसने कम्युनिस्ट नंताओं से बातचीत प्रारम्भ की । कम्यनिस्ट लोग जापान से लड़ाई करने के उद्देश्य से च्राकिंग सरकार के साथ समझीता करने को तैयार थे । उन्होंने समझीते के लिये एक मराविदा तैयार किया, जिसके अनसार यह प्रस्तावित किया गया, कि चुंगिक्या की सरकार विविध राजनीतिक दलों की मिली-जुली सरकार हो और देश के शासन पर कुओं मिन्तांग दरू का एकाधिषद्य न रहे । यस्यनिस्ट नेताओं बा कहना था, कि चीन की राष्ट्रीय गरकार और कुओमिन्तांग दछ दो पुशक् सत्ताएं हैं, और कम्युनिस्ट आदि अन्य राजनीतिक दलों की भी सरकार की दृष्टि में बही स्थिति होनी चाहियें, जो कुओमिन्तांग वहा की है। कुओमिन्तांग को अन्य राज-नीतिक दलों की अपेक्षा अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त नहीं होनी नाहिये । मीन में लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना के लिये यह आवश्यक है, कि शासन का संचार्क लोकमत के अनुसार हो, और विविध राजनीतिक दलों को यह अवसर हो, कि वे अपने विचारों व सिद्धान्तों का स्वतन्त्रता के साथ प्रचार कर सकें। पर चियांग काई शेक व उसके साथी इस वात की स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं थे।

उनका कथन था, कि पहले कम्युनिस्ट लोगों को यह स्पष्टरूप से मान लेना चाहिये, कि वे चुंगिकिंग सरकार के अभीन हैं और उन्हें अपनी सेनाएं पूर्णरूप से चियाग काई जैन की सेनाओं के साथ सिम्मिल्त कर देनी चाहिये। यह हो जाने के बाद ही कम्युनिस्ट दल की सत्ता को जन्य राजनीतिक दलों के समकक्ष रूप से स्वीकृत किया जा सकता है। पर कम्युनिस्ट लोग समझते थे, कि यदि वे विना किसी शर्त के अपनी सेनाओं को उम चुंगिकिंग सरकार के अधीन कर देगे, जिस पर कुंगिमिन्तांग दल का एकाधिपत्य है, तो उसका परिणाम केवल यह होगा, कि कम्युनिस्ट दल की सत्ता ही खतरे में पड़ जायगी। वे पहले चुंगिकंग में विविध राजनीतिक दलों की मिली जुली सरकार स्थापित कर लेना चाहते थे, तािक कुंगिमिन्तांग दल का एकाधिपत्य कायम न रहने पावे। जनरल हलें के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, कि वह चियांग काई शेक को अम्युनिस्टों की इस मांग को स्वीकृत कर लेनेके लिये प्रेरित कर सके। पर उसने समझौते की बातचीत को जारी रखा, और इसी कारण चीन के इन दो प्रधान दलों में परस्पर गृहयुद्ध प्रारम्भ नहीं होने पाया।

इसी बीच में अगस्त, १९४५ में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और महा-पुंड (१९३९-४५) का अन्त हो गया । पर महायुद्ध की समाप्ति के साथ चीन की समस्या का अन्त नहीं हो गया। जापान की पराजय के कारण नानिवंग की उस सरकार का स्वयमेव अन्त हो गया, जो वांग चिंग-वेई के नेतृत्व में कायम की गई थी। बांग चिंग-वेई की मृत्यु १९४४ में हो गई थी, पर नानिकंग की सरकार अभी कायम थी । महायुद्ध की समाप्ति पर यह समस्या उत्पन्न हुई, कि नानकिंग सरकार द्वारा अधिकृत प्रदेशों पर अब किसका आधिपत्य स्थापित हो, चुंगिकंग की कुओिम-न्तांग सरकार का या येनान की कम्युनिस्ट सरकार की । कम्युनिस्ट सरकार इस स्थिति में थी. कि यह बड़ी सुगमता के साथ उत्तरी चीन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती थी। पर नियांग काई शेक कभी इस बात की सहन नहीं कर सकता था। अतः नानिकंग रारकार द्वारा अधिकृत प्रदेशों पर कब्जा करने के प्रक्त पर कुओ-भिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारों में परस्पर संघर्ष का प्रारम्भ अवश्यम्भावी था। अमेरिका का हित इस बात में था, कि चीन में सूव्यवस्थित और सुदढ़ शासन स्थापित हो, और चीन पूर्वी एशिया का प्रमुख राज्य वने । महायुद्ध के समय में मित्रराज्यों ने चियांग काई शेक और उसकी सरकार को बहुत अधिक महत्त्व दिया हुआ था। अतः अमेरिका और ब्रिटेन इस बात के लिये उत्सुक थे, कि चीन में गृह-कलह न हो और जापान की पराजय के बाद सम्पूर्ण चीन में एक शनितशाली व केन्द्रीय शासन स्थापित करने का जो सुवर्णीय अवसर उपस्थित हुआ है, उसका

पूर्णे रूप में उपयोग किया जाय । अतः उन्होंने कुओमिन्तांग और वस्युनिस्ट सरकारों में समक्षीता कराने के अपने प्रथतन को जारी रखा ।

२६ तथम्बर, १९४५ को जनरल हुई नं अपने पद रें। त्यागप्त्र दे दिया और दिसम्बर, १९४५ में राष्ट्रपति ट्रुमैन ने जनरल गार्शल को विशेषक्य रें। चीन इस उद्देश्य से भेजा, कि वह चीन के दोनों प्रमुख दलों में समझौता कराने का उद्योग करें। उन्हें यह कार्य सुपुदं किया गया, कि वे चीन जाकर न केवल कुओमिन्तांग और कम्मुनिस्ट दलों में सैनिक सन्धि स्थापित करें, पर साथ ही यह भी उद्योग करें कि चीन में एक ऐसी लोकतन्त्र सरकार स्थापित हो जाय, जिसके शासन को सम्पूर्ण चीन स्वीकृत करता हो।

अमेरिका चीन में शासन सम्बन्धी एकता को कायम करने के लिये जिस प्रकार प्रयत्नशील था, उसकी उपेक्षा कर सकता चियांग काई शेवा व उसके साथियोंने हिसे सम्भव नहीं था । अतः उन्होंने चीन में 'पीपल्स कान्सल्टेटिव कान्फरेन्स' नाम से एक नई संस्था का निर्माण किया, जिसके सदस्यों की संख्या ३६ नियत की गई। यह व्यवस्था की गई, कि इस कात्फरेन्स में कुओमिन्तांग दल के ८, कम्युनिस्ट दल के ७ और अन्य दलों के २१ व्यक्ति सदस्य रूप से लिये जावें। नि:सन्देह यह लीकतन्त्र गासन के मार्ग पर एक महत्त्वपूर्ण कदम था । यद्यपि चीन में कुओमिन्सांहरू व कम्युनिस्ट दलों का प्राधान्य था, पर इस कान्फरेन्स में इन दोनों दलों के मुका-बले में अन्य अप्रसिद्ध दलों य स्वतन्त्र व्यक्तियों को अधिया स्थान दिये गये थे। यदि यह बान्फरेन्स सफल हो सकती, तो चीन राष्ट्रीय एकता और लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर अवश्य अग्रसर हो सकता । पर पीपल्स कान्सल्टेटिय बाल्परेन्स केवल २२ दिन तक कायम रही । अपने इतने छोटे से जीवनकाल में उस वात्नारेन्स ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न कर दिया । यह कार्य था, कुओफिन्सांभ और कम्युनिस्ट दलों में यह समझौता कराने का, कि उनकी सेनायें आपस के यह को बन्द कार दें और चीन का जी प्रदेश जिस सेना के कब्जे में है, वह उसी के कब्जे में रहे। १० जनवरी. १९४६ को इस कान्फरेन्स की ओर से तीन व्यक्तियों की एवा समिति नियल की गई, जिसे कुओं मिन्तांग और कम्युनिस्ट रोनाओं में युद्ध बन्द रखने का कार्य सुपूर्द किया गया। इन तीन व्यक्तियों में एक कुओ मिन्तांग दलका हो, एक सम्बनिस्ट दल का हो और एक अमेरिकन हो, यह व्यवस्था की गई। इस प्रकार अमेरिका के जोर देने से चीन में गृहवालह कुछ समय के लिये स्थमित हो गया और बहुत समें बाद चीन में सामयिक रूप से शान्ति की स्थापना हुई।

पर १० जनवरी, १९४६ के समझौते से चीन की नास्तविक समस्या का हल नहीं हुआ था। चीन में स्थिर शान्ति के लिये निम्निलिखित वार्ते आवश्यक्ष थीं— (१) अब तक चियांग कार्ड शेक की सरवार कुओमिन्तांग दल की सरकार थी। अप्रस्मकता उस बात की थी, कि एक राजनीतिक दल के शासन का अन्त होवार जीन में ऐसी सरकार स्थापित हो, जो लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों पर आश्रित हो। (२) चीन की मेनायें राष्ट्रीय न होकर राजनीतिक दलों की सेनायें थी। चियांग कार्ड शेक की सेनायें कुओमिन्तांग दल की थीं और माओ त्से तुग की सेनायें कम्पुनिस्ट दल की। चीन की राष्ट्रीय एकता के लिये यह आवश्यक था, कि उसकी सेनाओं का किसी दल विशेष से सम्बन्ध न हो; वे चीन की राष्ट्रीय सेनायें हों और राजनीतिक दलवन्दी से सर्वथा पृथक रहते हुए राष्ट्रीय सरकार की आज्ञानुवित्ती हों। यह सुगम नहीं था, कि इन बातों की किया में परिणत किया जा सके। जनरल मार्शल ने इस बात की भरसक कोशिश की, कि कुओमिन्तांग और कम्पुनिस्ट दलों में समझौता कराके एक केन्द्रीय चीनी सरकार की स्थापना करे। पर जनरल हलें के समान जनरल मार्शल को भी निराश होना पड़ा। जनवरी, १९४७ में वह चीन की राष्ट्रीय एकता से निराश होकर अमेरिका बापस लौट गया।

अमेरिका के योग्यतम राजनीतिज्ञ जो चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना में निरन्तर असफल हो रहे थे, उसके बारण निम्नलिखित थे—(१) कुओसिनांग और कम्युनिस्ट दलों के लोग एक दूसरे के प्रति घोर अविश्वास रखते थे। (२) वियांग कार्ड शेंक और उसके साथी कम्युनिस्म के विरोधी थे, वे किसी भी रूप में समाजवादी व्यवस्था को सहन करने के लिये उच्चत नहीं थे। इसके विपरीत कम्युनिस्ट लोग चीन में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये उत्सुक थे। समाज संगठन के प्रश्न पर इतना गहरा मतभेद होने की दशा में यह असम्भय था, कि इन दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में किसी भी प्रकार से समझौता हो सके।

(३) लोकतन्त्र शासन की स्थापना का प्रयत्न

यद्यपि कुओमिन्तांग और नम्युनिस्ट दलों में विसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका, पर नियांग काई गेक के लिये यह असम्भन्न था, कि वह चीन में लोकतन्त्र शासन की स्थापना के कार्य को कोई महत्त्व न वे। जापान के साथ युद्ध की परिस्थितियों के कारण चीन की राष्ट्रीय सरकार का शासनसूत्र पूर्ण रूप से नियांग काई शेक के हाथों में आ गया था। वह एका चिपति (डिक्टेटर) के रूप में देश का शासन करता था और सम्पूर्ण राज्यशनित उसी के पास थी। १९३६ के बाद चीन में न कोई निर्वाचन हुए थे और न निसी अन्य प्रकार से लोक मत के अनुसार शासन करने का उद्योग किया गया था। युद्ध के समय नियांग काई शेक की ओर से बहुधा यह घोषणा की जाती थीं, कि युद्ध की समाप्ति पर जब शान्ति स्थापित हो जायगी,

तो चीन में पूनः लोकतन्त्र शासन कायम किया जायमा और सरकार का संगठन लोकमत के अनुसार किया जायगा । इसीलिये अब युद्ध की समाप्ति के लगभग एक साल बाद नवम्बर, १९४६ में वियांग काई शेक के आदेश के अनुगार राष्ट्री महासभा (नेशनल एसेम्बली) का संगठन किया गया । इसके रादस्यों की संख्या २१५० थी । इनमें से ९५० रादस्य वे थे, जिनका निर्याचन अब से दस साल पूर्व १९३६ में हुआ था। उनके अतिरिक्त अन्य सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थे । इन्हें नियुक्त करने हुए सरकार की ओर में यह यत्न किया गया था, कि जहां राष्ट्रीय महासभा में विविध राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हो, वहां साथ ही चीन के प्रमुख व्यक्ति भी उसमें स्थान पा सकें । २५ दिसम्बर, १९४६ को राष्ट्रीय महासभा का अधियेशन प्रारम्भ हुआ । कम्युनिस्ट सदस्य इस अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए । पर उनकी अग्-पस्थिति की कोई परवाह न कर राष्ट्रीय महासभा ने चीन के लिये नये शासन-विधानका निर्माण किया और यह व्यवस्था की, कि यह नया विधान २५ दिसम्बर. १९४७ से लागु कर दिया जाय । चीन वो इस नये लोगतन्त्र शासनविधान पर यहां प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे किया में परिणत करने के लिये चियांग काई शेक और उसके साथियों को अवसर नहीं मिल सका है। नम्युनिस्ट लोग राष्ट्रीय महासभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, और शीघ ही उन्होंने चीन के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित वार लिया था । जुओमिन्तांग दल की सम्पूर्ण शक्ति कम्य्निस्ट लोगों का मुकाबला करने में ही लग गई और इन्हें इस बात का अवकाश नहीं मिला, कि वे राष्ट्रीय महाराभा द्वारातीयार किये गये शासक-थिवान के अनुसार चीन में लोकतन्त्र शासन का विकास कर सकें। यहां इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि इस शासन विधान का निर्माण डा० सन कात सेन के सिद्धान्तों व आदशों को दृष्टि में रखकर किया गया था, और राजशक्ति के उपयोग का अधिकार राज्य के पांच विभागों व युआनों को दिया गया था। ये गुआन निम्नलिखित थे, व्यवस्थापन युआन, जामन युआन, न्याय युआन, परीक्षा युआन और नियन्त्रण युआन । डा० सन यात मेन के शासन सम्बन्धी विभागों पर हम इस इतिहास में पहले प्रकाश डाल चुके हैं, अतः इन पांच युआनों के सम्बन्ध में यहां अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है।

जनवरी, १९४८ में नये शासनविधान के अनुसार व्यवस्थापन युक्तीने (पालियामेन्ट) का निर्वाचन हुआ। श्री चियांग काई शंक चीनी रिपब्लिक के राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये और उप राष्ट्रपति के पद पर जनरल की त्सुंग-जेन को चुना गया। जनरल ली कहर सुधारवादी थे और चियांग काई शेक के साथ उनका

प्रवल मतभेद था । चियांग काई शेंक के विरोध के बावजूद भी उनका उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना इस बात का प्रमाण है, कि चीन में इस समय भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो चियांग काई शेवा का अन्धानुसरण करने को उद्यत नहीं थे। यदि इस समय चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती और कुओमिन्तांग व कम्युनिस्ट दलों के लोग आपस में समझीता करके लोकतन्त्र शासन के विकास के लिये उद्योग करते, तो नि:सन्देह चीन लोगतन्यवादवे मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो सकता। पर यह सम्भव नहीं था, कि इन दो दलों में परस्पर समझौता हो सकता। जिस समय चीन की केन्द्रीय सरकार दिसम्बर, १९४६ के शासन विधान के अनुसार विविध युआतों के संगठन में तत्पर थीं, तभी कम्युनिस्ट सेनायें निरन्तर आगे बढ़ रही थीं, और चीन के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न थीं। ज्लाई, १९४९ तक चीन के बड़े भाग पर कम्युनिस्ट लोगों का शासन कायम हो गया था और डा॰ सन यात सेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार निर्मित नये शासन विधान को किया में परिणत होने का कोई अवसर नहीं रह गया था । यहां यह निर्दिष्ट कर देने की आवश्यकता नहीं है, कि चीन जो लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सका, उसमें महासेनापित नियांग काई शेक का दुराग्रह और "स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति एक बड़ा कारण थी।

(४) कम्युनिस्ट दल का उत्कर्ष

अमेरिका के प्रयत्न के बावजूद भी कुओमिन्तांग और कम्मुनिस्ट दलों में सम-झौता नहीं हो सका था। जब तक जापान के साथ युद्ध जारी रहा, इन दोनों दलों में गृहवालह ने उग्रहम धारण नहीं किया। पर जापान के आत्मसमर्पण थारते ही जब उत्तरी व पूर्वी चीन पर पुनः अधिकार स्थापित करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो चुंग-किंग और येनान रारवारों के पारस्परिवा विरोध ने बहुत उग्र हुप धारण कर लिया। कुछ ही समय बाद इन दोनों दलों की सेनाओं में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया, और अन्त में इस युद्ध में कम्युनिस्टों की विजय हुई।

हम पहले लिख चुके हैं, कि ८ अगस्त, १९४५ को रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध की चीवणा वर दी थी। १९३९-४५ के महायुद्ध में रूस भित्र राज्यों के पक्ष में था और जर्मनी की नाजी शक्ति को परास्त करने में उसका कर्त रव अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण था। जर्मनी के शिलाफ लड़ाई में रूस ने अपनी सम्पूर्ण सक्ति लगाई हुई थी, इसीलिये उसने जापान के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित करना उचित नहीं समझा था। एप्रिल, १९४१ में रूस और जापान ने एक सन्धि की थी, जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने तटस्थता की नीति का अनुसरण करना स्वीकार किया था। यह सन्धि पांच साल

के छिये ही की गई थी और दोनों राज्योंको यह अधिकार था, कि सन्धि की अद्धि के समाप्त होने से एक साल पूर्व इस मन्यि को समाप्त कर देने का नोटिस वे सकें 🏃 ब्रिटेन और अमेरिका चाहते थे, कि रूस जापान के माथ छड़ाई की घोषणा कर 🕏 ताकि जावान को परास्त कर सकना उनके लियं सुगम हो जाय। पर रूप यह भलीभांति समझता था, विः उत्तर-पूर्वी चीन में जापान की शनितशाली क्वान्त्रंग सेता अदाण्य रूप से विद्यमान है, और यदि रूस जानान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जायगा, तो यह मेना पूर्वी साइबीरिया पर सुगमता के साथ अपना आधिपाय स्थापित कर लेगी, और एशियन इस का पूर्वी समद्र तट जापान के कब्जे में चला जायमा; क्रा को अपनी अच्छी बड़ी सेना जापान के मुकाबले में साइबीरिया भेजनी पड़ेगी, और इसका केवल यह परिणाम होगा, कि वह जर्मनी के विषद अपनी सम्पूर्ण सैन्यशक्ति का उपयोग नहीं कर संकेगा । फरवरी, १९४५ में याल्टा नामक स्थान पर मित्र राज्यों के प्रमुख नेताओं की कान्फरेन्स हुई । इस में रूस ने यह स्वीकार किया, कि जब जर्मनी महायुद्ध में परास्त हो जायगा, तो उसके दो या तीन महीने बाद रूस जापान के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर देगा. ताकि जापान को परास्त करने में वह भी सहायक हो सके । रूस समझता था, कि जापान के साथ लड़ाई शुरू करने के लिये इतने समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि युरोप से हजांकी मील दूर पूर्वी साइबीरिया में अपनी सेनाओं व युद्ध सामग्री की प्रनुर परिमाण में पहुंचाने के लिये दो या तीन महीने का समय अवश्य लग जायगा । याल्टा कान्फरेन्म में ही ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के साथ एक समझोता किया, जिसके अनुगार उन्होंने यह स्वीकार किया, कि जापान की पराजय के बाद पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में नई व्यवस्था करते हुए रूस की निम्निक्षित मांगों को मजुर किया जायगा-(१) मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिया (जिसमें समाजवादी व्यवस्था कायम थी) की एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में स्वीकृत किया जाय। (२) १९०४-५ के रूस-जापान युद्ध के परिणामस्वरूप रूस से जो प्रदेश व प्रभावक्षेत्र जापान ने प्राप्त किये थे, वे रूरा को प्रदान कर दिये जावें। (३) सखालिन द्वीपना दक्षिणी भाग व उसके समीपवर्ती डीप रूस को पुनः प्राप्त हों। (४) पोर्ट आर्थर रूस को पट्टे पर दे दिया जाने, ताकि वह वहां अपनी जलशक्ति का अड्डा बना सके। (५) मञ्चरिया पर चीनी सरकार का अधिकार हो, पर उसकी दो प्रमुख रेलवे लाइनों का संचाल हु एक ऐसी कम्पनी द्वारा किया जाय, जिसपर चीन और रूस वोनों का गम्मिलि आधिपत्य हो।

याल्टा कान्फरेन्स में ब्रिटेन और अमेरिका के साथ उपर्युक्त समझीता करके रूस ने यह तय कर लिया, कि जर्मनी की पराजय के कुछ मास बाद कह भी जापान

के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर देगा । ७ मई, १९४५ को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और उसके ठीक तीन मास बाद ८ अगस्त, १९४५ को रूस ने जापान के खिलाफ हैंडाई की घोषणा कर दी। रूस की सेनाओं ने उत्तर की ओर से मञ्चरिया में प्रवेश किया । कुछ समय बाद १५ अगस्त, १९४५ को जागान ने विना किसी शर्त के आत्मसमपंण कर दिया और रूस को और अधिक युद्ध की आवश्यकता नहीं हुई। पर जानान के साथ सामियक सन्धि २ सितम्बर, १९४५ से पूर्व सम्पन्न नहीं की जा मकी । इसका परिणाग यह हआ, कि ८ अगस्त से २ सितम्बर तक लगभग तीन सन्ताह तक रूसी सेनायें जापान द्वारा अधिकृत प्रदेशों में निरन्तर आगे बढ़ती गई। इम अवसर का लाभ उठाकर रूस ने सम्पूर्ण मञ्चरिया पर अपना कब्जा कर लिया और उसकी एक अन्य सेना कोरिया में निरन्तर आगे बढ़ती गई। २ सितम्बर तक उसने सम्पूर्ण उत्तरी कोरिया (३५वीं पेरेलल तक) पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । तीन सप्ताह के थोड़े से काल में मञ्चरिया और उत्तरी कोरिया के सविस्तत प्रवेश कसी वाम्युनिस्टों के अधिकार में आ गये। यद्यपि कस के इस आधिपत्य का चीन के कम्यनिस्टों के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था, पर हमने इसका इतने विशवस्य में उल्लेख इसलिये किया है, क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट दल ैं के उत्वर्ष में इससे बहुत सहायता मिली थी।

१५ अगस्त, १९४५ को जापान ने आत्म समर्पण किया था । यद्यपि महायुद्ध में जापान परास्त हो गया था, पर मञ्चरिया और पूर्वी चीन पर उसका आधिपत्य अभी अविकल रूप से विद्यमान था। मञ्चरिया और कोरिया में रूसी सेनायें निरुत्तर आगे बढ़ रही थीं, पर मञ्चूकुओ और नानिकग की सरकारें अभी पूर्ववत् कायम थीं। जापान के आत्म समर्पण का यह परिणाम अवश्यम्भावी था, कि मञ्चरिया और पूर्वी चीन से उन सरकारों का अन्त हो जाय, जो कि जापान को अपना संरक्षक, मित्र व सहयोगी मानती थीं। साथ ही, यह भी आवश्यक था. कि इन प्रदेशों में जो जापानी सेनायें विद्यमान थीं, वे हथियार डाल दें और मित्र-राज्यों के सम्मूख आत्म समर्पण कर दें। मञ्चिरिया और उत्तरी कोरिया में कसी सेनायें प्रविष्ट हो गई थीं, और रूस ने वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। पर प्रक्त यह था, कि पूर्वी चीन पर अब किसका अधिकार हो और वहां की जापानी सेनायें किसके सम्मख आत्म समर्पण करें। मित्रराज्यों ने इस बात का नो फैसला कर लिया था, कि पूर्वी चीन पर चीन की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार का अधिकार कायम होगा। पर चीन की स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार की सेनायें दो प्रकार की थीं, कुओमिन्तांग और सम्युनिस्ट। इन दोनों रेनाओं में किसी वी प्रकार का समझौता अब तक नहीं ही सका था। इस दशा में यह स्वाशादिक था, कि ये दोनों नेनामें

पुर्वी चीन के अधिक से अधिक प्रदेश पर अपना कब्जा कायम करने का प्रयत्न करें। कम्यनिस्ट रोनायं अधिक व्यवस्थित व संगठित थीं । उत्तर-पश्चिमी चीन पर त्रे उनका अधिकार था ही, साथ ही जापान द्वारा अधिकृत चीन में भी अनेक स्थानों पर् कम्यनिस्ट रोनायें गरीला पढ़ित से यद में व्यापुत थीं । इस दशा में उनके लिये यह अधिक सुगम था, कि वे पूर्वी चीन के बड़े भाग पर अपना कब्जा कायम कर हैं। पर चियांग काई शेक इस बात की नहीं सह सकता था। अमेरिकन लोग भी यह महीं चाहते थे, कि जापान को परास्त कर पूर्वी चीन के जिन प्रदेशों को जापान की अधीनता से 'स्वतन्त्र' कराया गया है, उन पर अब सम्युनिस्टों का आधिपत्य स्थापित हो जाय । अतः उन्होंने इस समय चियांग काई शेव की दिल खोलकर सहायता की । बहत बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियां, टूक, हवाई जहाज आदि चुंगिकेंग सरकार को प्रदान किये गये, ताकि कुओमिन्तांग दल की सेनायें तेजी के साथ पूर्वी चीन पहुंच सकों और अम्य निस्टों से पहुले उनगर अपना कटजा नार लें। इस अवस्था में यह स्वाभाविक था, कि चुंगिकिंग सरकार और गेनान सरकार में फिर से गृहयुह का प्रारम्भ हो । क्योंकि कम्युनिस्ट लोग यह नहीं चाहते थे, कि चियांग गाई शेक सम्पूर्ण पूर्वी चीन पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर छे। परिणाम यह हआ, कि सितम्बर, १९४५ में कुओमिन्लांग और कम्यनिस्ट सरकारों में लड़ाई बुक हो गई 🗓 जापान की पराजय के बाद भी चीन में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी।

अमेरिका नहीं चाहता था, कि चीन में इस प्रकार गृहयुद्ध जारी रहें ! इसीलिये उसने दिसम्बर, १९४५ में जनरल मार्शल को इस उद्देश्य से चीन मेजा, कि वह चीन के इन दोनों दलों में समझौता कराके वहां लोकतन्त्र शासन की स्थापना का उद्योग करें । जनरल मार्शल को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हो सकी, यह हम इसी अध्याय में पहले लिख चुके हैं । जनवरी, १९४६ में चीन के दोनों दलों ने जो सामिक रूप से समझौता किया, उसका विवरण भी हम ऊपर वे चुके हैं । पर कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट दलों में रामझौता हो सकता सुगम बात नहीं थी । नवम्बर, १९४६ में चियांग काई शेक ने देश के लिये नये शारान विधान का निर्माण करते के लिये जिस राष्ट्रीय महासभाका आयोजन किया था, वाम्युनिस्ट दल ने उसका बहिल्लार किया था । इस बीच में कम्युनिस्ट सेनायें उत्तरी थ पूर्वी चीन के अनेक प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी थीं । कुछ मारा बाद १९४५ के शुरू में रूसी सेनाओं ने मञ्चूरिया और उत्तरी कोरिया थो खाली को विधा था, और इन प्रदेशों पर भी चीन के कम्युनिस्टों ने अपना बाब्जा कायम कर लिया था । इस प्रकार चीन के बच्छे बड़े भाग पर चीनी वाम्युनिस्टों का अधिकार था अब और चियांग काई शेक चीन में राष्ट्रीय एकता की

स्थापना के लिये केवल दो जपायों का ही अवलम्बन कर सकता था—(१) या तो वह सम्युनिस्टों के साथ समझौता करके इस बात के लिये तैयार हो, कि चीन में एक ऐसी लोकतन्त्र सरकार की स्थापना की जाय, जिसका निर्माण लोकमत के अनुसार हो आर जो कुओमिन्तांग, कम्युनिस्ट व अन्य राजनीतिक दलों को एक समान वृष्टि से देखे। (२) और या वह कम्युनिस्टों को युद्ध में परास्त करके उन द्वारा अधिकृत प्रदेशों को अपने कब्जे में ले जावे। १९४७ तक समझौते के लिये जो प्रयत्न चीन में हुए, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। १९४८ में भी ये प्रयत्न जारी रहे, पर ये सफल नहीं हो सके। इस बीच में कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सेनाओं में थोड़ा बहुत युद्ध भी होता रहा। इस समय चीन दो भागों में विभक्त था। कुछ प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का कब्जा था और कुछ पर कुओमिन्तांग दल का। १९४८ के शुरू में चीन में जिस लोकतन्त्र शासन की स्थापना का उद्योग हुआ था, उसका सम्बन्ध केवल कुओमिन्तांग दल द्वारा अधिकृत चीन के साथ था। शेष चीन में कम्यनिस्ट लोग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में तत्पर थे।

१९४९ के प्रारम्भ में एक बार फिर दोनों वलों में समझौते का उद्योग किया गया । १४ जनवरी, १९४९ को कम्यनिस्ट दल की ओर से समझीते की निम्न-, 'लिखित शर्तों पेश की गईं—(१) चियांग काई शेक ओर ली त्स्ंग-जेन को अपने. पदों से पृथक् कर दिया जावे । (२) कुओमिन्तांग और कम्युनिस्ट सरकारें एक साथ अपनी सेनाओं को लड़ाई बन्द कर देने का आदेश दें। (३) देश के लिये एक नया शासन विधान बनाया जाय, जिसे बनाने ना कार्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुपूर्व हो। (४) जब तक नया शासन विधान न तैयार हो, शासन कार्य का संचालन करने के लिये एक ऐसी सरकार का संगठन किया जाय, जिसमें सब प्रमुख राजनीतिक दलों को स्थान दिया जाय। (५) सेना का नये सिरे से संगठन किया जाय । (६) युद्ध के लिये जिन चीनी नेताओं को दोपी पाया जाय, उन्हें दण्ड देने की व्यवस्था की जाय । यह स्पष्ट है, कि महासेनापित चियांग काई शेन इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता था। पर इस समय चीन में चियांग काई शेवा की स्थिति वहुत हीन हो चुकी थी। कम्युनिस्टों के निरुद्ध छड़ाई के लिये वह अमेरिका से यथेष्ट सहायता प्राप्त कर सकने में समर्थ नहीं हुआ था। इस समय अमेरिका इस स्थिति में नहीं था, कि चीन के गृहयुद्ध में एक पक्ष की खुले रूप से सहा-र्यता कर सके । यदि अमेरिका कुओमिन्तांग दल की सहायता करता, तो वाम्युनिस्ट लोगों की रूस से सहायता पाने का पूरा भरोसा था । इस दशा में अमेरिका ने बहुत नुछ तटस्थता की नीति का अनुसरण किया और इस कारण चियांग काई रोक की राजनीतिक स्थिति बहुत कुछ डांवाडोल हो गई। २२ जनवरी, १९४९ को उसने

अपनी सरकार का सब कार्य भार उप राष्ट्रपति ली त्सुंग-जेन के सुपुर्व कर दिया।
यद्यपि राष्ट्रपति के पद पर अब भी नियांग काई शेक कायम रहा, पर नानकिम्
सरकार (जापान के आत्म समर्पण के कुछ रागय बाद कुओमिन्तांग सरकार नुंगिकिंग
भ नानकिंग चली आई थी) का संचालन जनरल ली के हाथों में आ गया। इस
समय नानकिंग सरकार का प्रधानमंत्री सन को था। उनने कम्युनिस्टों के साथ
समझौते की बातचीन को जारी रखा। पर उसे अपने उद्देश्य में मकलता नहीं हो
सकी। १९ एप्रिल, १९४९ को समझौते की बातचीन अन्तिम क्य सं समाप्त हो
भई, और कम्युनिस्टों और कुओमिन्तांग सरकार की सेनाओं में बाकायदा युद्ध
प्रारम्भ हो गया।

यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि चीन के उस गृहयुद्ध की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त रूप में भी उल्लेख कर सकें। उत्तरी चीन के सब प्रदेशों पर कम्युनिस्टों का पहले से ही कन्ना था। जनवरी, १९४९ में समझीते की बातचीत युक होने के पहले कम्युनिस्ट लोग तीन्तिमन और पेविगपर अपना आविपत्य कायम कर चुके थे। समझीते की बातचीत के अमफल हो जाने पर एप्रिल, १९४९ में वाम्युनिस्ट सनाओं ने यांक्से नदी को पार कर लिया। नानिक्य और अंबाई कम्युनिस्टों के अविकार में चले गये। कुछ समय बाद कम्युनिस्ट मैनाओं ने हैंन्को को जैति लिया और अक्टूबर, १९४९ में दक्षिणी चीन के प्रसिद्ध नगर कैन्टन पर भी उनका प्रभत्त स्थापित हो गया।

१७ सितम्बर, १९४९ को ब्रिटेन, फांस और अमेरिका के परराष्ट्र विभाग की ओर से यह बात स्वीकृत कर ली गई, कि चीन में कुओ मिन्तांग दल की शक्ति व सत्ता का पूर्ण इप से हांग हो गया है। इस दल का चीन में कुओ मिन्तांग दल की शक्ति व सत्ता का पूर्ण इप से हांग हो गया है। इस दल का चीन में कुओ प्रभाग नहीं है, और इसका कोई ऐसा व्ययस्थित संगठन नहीं है, जिसे ये पाश्चात्य राज्य सहायता दे सकें। वस्तुतः, महायुद्ध के समय में ही अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों के अनेक राजनीतिज्ञ इस बात की अनुभव करते थे, कि कुओ मिन्तांग दल के नेताओं में बहुत अबिक विकृति आ चुकी है, और वे अपनी राजश्वित का उनमोग देश के हित व कल्याण के लिये न करके स्वार्थ साधन के लिये करने में तत्पर है। चीन की जनता भी उनके पक्ष में नहीं थी। इसके विपरीत कम्यनिस्ट लोग जहां गृज्यवस्थित और सुसंगठित थे, वहां साथ ही देश के हित-साधन में भी तत्पर थे। इस दशा में एडि उन्हें कुओ मिन्तांग सरकार की परास्त वार सकने में असाधारण रूप से सफलती मिनी हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई वात नहीं है।

नवम्बर, १९४९ तक यह दशा आ गई थी, कि कुओमिन्तांग मरनार की अवी-नता में केवल निम्नलिखित प्रदेश रह गये ये—(१) दजेचुआन का प्रान्त, जिसकी राजधानी चुंगिकंग थीं, (२) दक्षिण-पूर्वी चीन के क्यांग्सी प्रान्त का कुछ भाग, (३) फार्मुसा द्वीप और (४) हैनान द्वीप । ये चार प्रदेश जहां कुओमिन्तांग हैरकार की अधीनता में थे, वहां पश्चिमी चीन के अनेक प्रदेशों पर एक बार फिर विविध सिपहसालारों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चीन के गृह-कलह की दशा में यह सर्वधा स्वाभाविक था, कि विविध शक्तिशाली सेनापति अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र शासकों के समान आचरण करने लगें। इस दशा में कम्यु-निस्ट सरकार के सम्मुख मुख्य कार्य यह था, कि इन सब प्रदेशों को जीतकर सम्पूर्ण चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करे। इस कार्य में उसे विशेष कठिनता का सामना नहीं करना पड़ा । १९४९ के अन्त से पूर्व ही वस्युनिस्ट सेनाओं ने आभ्यन्तर मंगोलिया के निन्तिसभा प्रदेश को जीत लिया और मार्च, १९५० तक उन्होंने सब स्वतन्त्र सिपहसालारों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार कम्यनिस्ट सेनाओं ने श्लेचुआन और क्वांग्सी में विद्यमान कुओमिन्तांग सेनाओं के साथ भी संघर्ष जारी रचा। मार्च, १९५० तक यह स्थिति आ गई थी, कि कुओ-मिन्तांग दल का प्रभुत्त्व केवल फार्मुसा और हैनान द्वीपों तक ही सीमित रह गया गया था। चीन के विशाल प्रदेशों में कोई भी ऐसा नहीं रहा था, जो चियांग काई चैक या उसके कुओमिन्तांग दल के अधिकार में हों। बाद में हैनान पर भी कम्यनिस्ट सेनाओं ने कब्जा कर लिया । इस समय केवल फार्म्सा द्वीप ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जो चियांग काई शेक या कुओमिन्तांग दल के अधिपत्य में है । चीन की राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में कम्यनिस्ट दल को असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हुई है।

सम्पूर्ण चीन को अपने अधिकार में लाकर कम्युनिस्ट लोगों ने वहां किस प्रकार का शासन स्थापित किया और देश में किस ढंग की आर्थिक,, सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की, इस महत्त्वपूर्ण विषय पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे। पर इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व यह उपयोगी होगा, कि हम कम्युनिस्ट दल की सफलता के कारणों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालें। जापान की पराजय के बाद जो चीन की राजशिक्त कम्युनिस्ट लोगों के हाथों में आगई, उसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे—(१) कम्युनिस्ट लोगों में उप देशभित और राष्ट्रीय मावना विद्यमान थी। चीन में जापान का प्रभाव जित ढंग से बढ़ रहा था, वे उसके प्रबल विरोधी थे। वे चाहते थे, कि चीन के सब राजनीतिक दल जापस के मतभेदों को मुलाकर सम्मिलत रूप से जापान का मुकावला वारें। इस कारण चीन की जनता उनके पक्ष में थी। चियांग काई शिक व उसके साथी जापान के विरुद्ध युद्ध के मुकाबले में चीन में अपनी स्थिति को मजबूत

रखने की अधिक चिन्ता करते थे। इसीलिये वे पाश्चात्य देशों री प्राप्त होनेवाली सहायता का उपयोग भी जागान के विरुद्ध न करके कम्युनिस्टों के स्विलाफ करते थे। चीन की जनता इस बात को पसन्द नहीं करती थी। (२) महायुद्ध के सकी जो प्रदेश येनान की कम्युनिस्ट सरकार के हाथों में थे, उनकी आधिक व राजनीतिक अवस्था बहुत सन्तोपजनक थी। कम्युनिस्ट लोग इन प्रदेशों का युद्ध के लिये शोषण न करके इनकी उन्नति में संलग्न थे। इसके विपरीत चुंगिकिंग की कुंशोमिन्तांव सरकार द्वारा शासित प्रदेशों में आधिक दशा बहुत ही अस्त-व्यस्त थी। कीमतें वहां इतनी अधिक बढ़ गई थीं, कि सर्व साधारण जनता के लिये अपना निर्वाह कर सकना असम्भव हो गया था। (३) कम्युनिस्ट सरकार का जनता के साथ घनिष्ठ सम्पर्क था। वह अपनी शक्ति के लिये जनता की सद्भावना व सहयोग पर निर्भर करती थी। इसके विपरीत कुंशोमिन्तांग दल के नेता सर्वसाधारण जनता की सर्वथा उपेक्षा कर अपने वैयन्तक उत्कर्ष के लिये तत्पर थे।

- MB

दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये संघर्ष

(१) इन्डो-चायना

विक्षण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के लिये गत महायुद्ध (१९३९-४५) एक बरदान के समान था। इन्हो-चायना, मलाया, इन्होनीसिया, बरमा, फिलिप्पीन आदि जो देश गुदीर्घ समय से पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकार थे, जापान की विजयों के कारण उन्हें स्वतन्त्र होने का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हुआ था। जापान ने इन देशों में बुख समय के लिये अपना सैनिक शासन स्थापित किया और बाद में ृतमें ऐसी स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकारें कायम हुईं, जो पाश्चात्य देशों के विरुद्ध जापान के साथ सहयोग करने को तैयार थीं। महायुद्ध की परिस्थितियों के कारण इन देशों में जापानी सेनायें स्थापित थीं, और इनके शासन पर जापान का पर्याप्त प्रभाव था। पर एक बार पास्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हो जाने के कारण इन देशों में राष्ट्रीय खाधीनता की जो भावना अत्यन्त उग्र रूप में विकसित हो गई थी, उसे कुचल सकता न जागान के लिये सम्भव था और न पाश्चात्य देशों के लिये 🕞 महायुद्ध के अवसर पर युद्ध की परिस्थितियों से विवश होकर जब जापान ने इन देशों में अपने प्रभाव को अधिक व्यापक करने का प्रयत्न किया, तो वहां ऐसे देशभक्तों की वामी नहीं थी, जिन्होंने जापान का विरोध करने के लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगा दिया और जब जापान की पराजय के बाद ये देश एक बार फिर पाश्चात्य ' देशों की सेनाओं के अधिवगर में आ गये, तो इन्हीं राष्ट्रवादी देशभवतों ने पारचात्य साम्राज्यवाद का मुकावला करने के लिये असाधारण तत्परता प्रदर्शित की। एशिया के आधुनिवा इतिहास में दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों का राष्ट्रीय -स्वीधीनता के लिये संघर्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रसता है। इस अध्याय में हम इसी संघर्ष के वत्तान्त का संक्षिप्तरूप से उल्लेख करेंगे।

महायुद्ध में इन्डो-चायना की स्थिति—फांस ने किस प्रकार इन्डो-चायना पर-अपना आधिपत्य स्थापित किया, इस पर हम पहले प्रकाश ढाल चुके हैं। इन्डो- चायना फांस के उसी प्रकार अधीन था, जैसे कि भारत और वरमा जिटेन के । जन, १९४० में फांस जर्मनी द्वारा परास्त कर दिया गया था और पेरिस नाजी सेनाओं के कब्जे में आगया था। फांस में कतिपय ऐसे राजनीतिक नेता विद्यमान थे. 🖏 दिल मे नाजी विचारधारा के साथ सहानुभूति रखते थें। उनकी दुव्दि में नाजीज्य की अपेक्षा कम्युनिज्य अधिक सत्तरनाक था और उन्हें कम्युनिज्य के बढते हुए प्रभाव का मुकाबला करने का सर्वोत्तम उपाय यही समझ पड़ता था, कि नाजी जर्मनी के साथ समझौता कर लिया जाय । मार्शेल पेतां और श्री लवाल इन लोगों के प्रधान नेता थं । इन्होंने फांस में एक नई सरकार का संगठन किया और विशी को अपनी राजधानी बनाया । फांस की इस नई सरकार ने २१ जन, १९४० को हिटलर के प्रतिनिधियों से सन्धि कर ली। इस सन्धि के अनुसार फ्रांग को दो भागों में विभक्त विया गया, जर्मनी द्वारा अधिकृत फांस और स्वाधीन (विशी सरकार के अधीन) फ्रांस । सम्पूर्ण उत्तरी फ्रांस, जिसमें पेरिस भी सम्मिलित था, जर्मनो के अधिकार में रहा । दक्षिणी फ्रांस पर मार्चल पेतां की सरकार स्वतन्त्र रूप से शासन करती रही । २१ जन, १९४० की सन्धि के अनुसार विश्वी सरकार ने यह भी स्वीकार किया, कि फांस के पास जो कुछ भी गुद्ध सामग्री भेप है, वह सब जर्मनी के स्पूर्व कर दी जाय । फांस जर्मनी के अधिकार में आ गया था, पर उसका विशाल साम्राध्य अभी जर्मनी की पहुंच से बहुत दूर था। जो फेंच लाग मार्शल पेतां की नीति न असन्तरूट थे, उनका नेता जनरल द गाँल था । ये लोग ब्रिटेन में एसत्र हुए और वहां इन्होंने आजाद फेडन सरकार का संगठन किया । द गाँल ने यत्न निया, कि फांस के विशाल साम्राज्य के विविध प्रदेश आजाद फेड्च सरकार का साथ दें। पर मार्शल पेलां की सरकार यह नहीं चाहली थी। उसका विचार था, कि अब फेल्च लोगों को महायुद्ध में पूर्णतया तटस्य रहना चाहिये और जर्मनी के साथ जी सिक हुई है, उसका अविभल रूप से पालन करना चाहिये। इन्डो-चायना के गवर्नर जनरल श्री कार्त ने जनरल द गाँछ का साथ देने का फैसला किया । इस पर विशी सरकार ने उसे पवच्यत कर दिया और श्री देख की इन्डो-चायना का नया गवर्न र जनरल नियल किया गया।

शी. वेकू को यह भय नहीं था, कि जर्मन जलरोता इन्हो-नायता पर आश्रमण कर उने अपने अधीत कर सकेगी। पर जापान महायुद्ध में जर्मनी और इटली के साथ सहानुभूति रखता था। यदापि अभी जापान महायुद्ध में तटस्थ था, पर हा इन्हो-चायना को अपने प्रभाव में लाने के लिये उत्सुक था। ब्रिटेन और अमेरिका इन्हो-नायना को अपने प्रभाव में लाने के लिये उत्सुक था। ब्रिटेन और अमेरिका में तत्पर थे बीर यह बाल जापान को किसी भी प्रकार सहा नहीं थी। जापान

चुंग िंग सरकार का अन्त कर सम्पूर्ण चीन को एक ऐसी सरकार की अधीनता में ले आना चाहना था, जो जापान को अपना रक्षक . मित्र व सहयोगी समझे । अतः फांस के पतन वा उसने चुंग िंग सरकार का प्रतिरोध करने के लिये उपयोग किया और ३० अगस्त, १९४० को श्री देकू के साथ एक समझाता किया, जिसके अनुसार (१) इन्डोचायना की फ्रेंच सरकार ने जापान को यह अनुमति प्रदान की, कि वह अपनी सेनायें तोन्किन के प्रदेश में रख सके, और (२) जापान इन्डोचायना को मैन्य सञ्चालन के लिये आधार के रूप में प्रयुक्त कर सके । इस समझौत का उद्देश्य यह था, कि ब्रिटेन और अमेरिका इन्डोचायना के मार्ग से चुंगिंग सरकार को सहायता न पहुंचा सकें और जापान इस देश का चीन के विषद युद्ध के लिये उपयोग कर सके।

३० अगस्त. १९४० के समझौते का लाभ उठाकर जापान ने अपनी सेनायें इन्डोचायना में भेजनी प्रारम्भ कर दी । दक्षिण-पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में जापान की जो नीति थी, उसके अनुसार वह इस भूखण्ड से पाश्चात्य देशों के साम्राज्यबाद का अन्त करना चाहता था और वहां ऐसी सरकारें कायम करना चाहता था, जो जापान के प्रभाव में हो । अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जापान यह आवश्यक समझता था, कि इन्डो-चायना में अपनी इतनी अधिक सेनायें भेज दी जावें, जो उपयुक्त अवसर उपस्थित होने पर सियाम (धाइलैंड), मलाया, बरमा आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें। इसी कारण १९४० का अन्तं होने से पूर्व ही बहुत सी जापानी रोनायें इन्डो चायना पहुंच गई और वहां की फ्रेंट्न सरकार जापान के सम्मुख सर्वथा असहाय हो गई। यद्यपि इस समय इन्डोचायना में फांस का राजनीतिक प्रभूत्व विद्यमान था, पर श्री देक् की सरकार जापान का किसी भी प्रकार विरोध कर सकने में सर्वथा असमर्थ थी। पर यह नहीं समझना चाहिये, कि इन्डोचायना में ऐसे फ्रेंट्च लोगों का सर्वथा अभाव था, जो इस समय जापान के सैनिक प्रभुत्व का प्रतिरोध करने में तत्पर हों। उसके फेट्च नागरिक श्री देकु की नीति से असन्तृष्ट थे और इस प्रकार के गुरीला युद्ध में संलग्न थे, जिसका प्रयोजन इन्डोचायना में विद्यमान जापानी सेनाओं को नुकसान पहुंचाना था।

राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास—महायुद्ध (१९३९-४५) के प्रारम्भ से पूर्व मी इन्डो-चायना में राष्ट्रीय स्वधीनता का आन्दोलन विद्यमान था। यद्यपि इन्डो-चायना के मत निलामी जाति, नसल, भाषा, संस्कृति आदि की दृष्टि से एक नहीं थे, पर उन स्वमा फान के विदेशी भागन का विरोध कर राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्थापना की भागनिका समान कराने विरामान थी। इन्डो-चायना में जो अनेन दल स्वतन्त्रता के लिये प्रयुक्त की से उन्हों हुन निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) फाम—पुद्दन्हों दल—यह इन्डो-चायना का नरम दल था, जो फांस के साथ सम्बन्ध बनाये रख़ कर शासन सुधार से सन्तुष्ट था। इस दल के लोड़ चाहते थे, कि इन्डो-चायना फांस के साम्राज्य के अन्तर्गत रहे, पर धीरे धीरे देश के शासन में इस प्रकार के सुधार कर दिये जावें, जिनस इन्डोनाइनीज लोगों को शासन में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त हो। (२) कान्तिकारी दल—इसमें अनाम के नथयुवक देशभवत सम्मिलित थे। ये अपने देश को फांम की अधीनता से मुक्त करके पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के पक्षपाती थे। १९२८ तक इस दल में फम्यूनिस्ट लोग भी शामिल थे। पर बाद में कम्यूनिस्टों का राष्ट्रीय कान्तिकारी दल से मतभेद हो गया और उन्होंने अपना पृथक् दल बना लिया। (३) आतंक वादी दल—इस दल के लोग फेप्न शासन का अन्त करने के लिये आतंकवादी उपायों का अवलम्बन करने के पक्षपाती थे और इन्डो-चायना से बाहर कैन्टन को अपना आश्रय स्थान बना कर अपने वार्य में तत्तर थे।

महायुद्ध के समय ये सब दल अपने अपने ढंग से इंन्डो-चायनाकी राष्ट्रीय स्वतः अता के लिये प्रयत्नशील रहे । क्रान्निकारी दल के लीग और विशेषतया मस्युनिस्ट लोग महायुद्ध को अपने देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये एक सुवर्णीय अवस्य समझते थे और इसीलिये उन्होंने गुप्तरूप से श्री देकृ की सरनार का प्रतिराध करना प्रारम्भ कर दिया था । इन लोगों ने अनेक गुप्त समितियां कायम कर ही थीं, जो फेल्च शासन और जापान के सैनिक प्रभुत्त का अनुसरण कर मांस और जापान के आफिसरों पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे और विदेशी सरकार के कार्य को कठिन बना दिया था । महायुद्ध के समय में इन लोगों के लिये यह तो सम्भव नहीं था, कि ये खुले मैदान में आकर स्पष्टरूप से फांस या जापान की शक्ति का मुनावला कर सकें, पर ये गुरीला पद्धति का अनुसरण कर अपने देश को स्थतन्त्र कराने में तत्पर थे ।

विएत मिन्ह सरकार की स्थापना—मार्च, १९४५ में महायुद्ध की परिस्थिति ऐसी हो गई थी, कि जापान के लिये अपने विभाल साम्राज्य व प्रभावक्षेत्र की संभाल सकता सम्भव नहीं रहा था। जर्मनी देर तक मित्रराज्यों का मुकाबला करता रह सकेगा, इसकी कोई आशा नहीं रह गई थी। अगस्त, १९४४ में फांस जर्मनिक्ष आधिपत्य से स्वतन्त्र हो गया था और जनरल द गॉल के नेतृत्व में फांस की सरकार का पता हो गया था। मार्शल पेतां की विशी सरकार का पता हो गया था और इन्डो-चायना में थी देकू की स्थित बहुत हांबाडील हो गई थी। इस दशा में जब १९४५ में जापान ने अपनी सेनाओं को धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्वी एशिया

से हटाना शुरू विया, तो मार्च मास में इन्डोचायना से भी उसने अपनी सेनाएं वापस पुला लीं। जापान की सेनाओं के वापस चले जाने पर श्री देकू के लिये यह सम्भव ाहीं रहा, कि वह इन्डो-चायना में फांस के प्रभुत्त्व को कायम रख सके। इस दशा में राष्ट्रवादी देशभक्तों ने इन्डो-चायना की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी, और विएत मिन्ह नाम से अपनी स्वतन्त्र सरकार का संगठन कर लिया। इस सरकार मा नेता हो ची मिन्ह था, जो कटूर राष्ट्रवादी होने के साथ साथ कम्युनिज्य का मानने वाला था। हो ची मिन्ह के क्रान्तिकारी अनुयायी देर से इन्डो-चायना की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थे और महायुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर गुरीला युद्ध पद्धति का अनुसरण कर फेट्च आधिपत्य का प्रतिरीध करने में तत्पर थे। अगस्त, १९४५ में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो हो ची मिन्ह और उसके क्रान्तिकारी अनुयायियों को अपनी मनोकामना की पूर्ति का मुअवसर मिला। उन्होंने अनाम के राजा या सम्राट् वाओ दाई की सत्ता की सर्वथा उपेक्षा कर इन्डो-चायना में 'विएत नाम' नाम से रिपिब्लिकन राज्य की घोषणा कर दी और अपने को फेञ्च आधिपत्य से पूर्णरूप से मुक्त कर लिया । हम इस पुस्तन में पहले लिख चुके हैं, कि इन्डो-चायना अनेक राज्यों व प्रदेशों में विभक्त था। इनमें से कम्बोडिया और अनाम में प्राचीन राजवंशों का शासन था। फ्रेडच आधिपत्य में कम्बोडिया और अनाम के राजाओं की वही स्थिति थी, जो भारत के ब्रिटिश शासकों की अधीनता में ग्वालियर, रामपूर आदि रियासतों के राजाओं की थी। अनाम के राजा को 'सम्राद' कहा जाता था, यद्यपि वह इन्डो-चायना के फेञ्च गवर्नर जनरल के हाथों में कठपुतली मात्र था। इस समय अनाम का सम्राट बाओ दाई था। पर जब हो ची मिन्ह के नेतृत्व में विएत नाम रिपब्लिक की स्थापना हो गई, तो सम्राट् बाओ दाई के लिये अपने पद को कायम रख सकना सम्भव नहीं रहा । २५ अगस्त, १९४५ को बाओ दाई ने सम्राट् पद का परित्याग कर दिया और २ सितम्बर, १९४५ को विएत नाम रिपब्लिक का शासन सम्पूर्ण अनाम पर नियमित व व्यवस्थित रूप में नायम हो गया।

इन्डो-चायना के सम्बन्ध में फांस की नीति—पर फांस के लिये यह सम्भव नहीं था, कि इन्डो-चायना के अपने साम्राज्य को इस ढंग से अपनी' अधीनता से मुक्त हो लेने दे । यद्यपि महायुद्ध के समय मित्रराज्य डंके की चोट के साथ यह उद्घोषित करते थे, कि वे गानव स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के लिये नाजी व फैसिस्ट प्रवृ-ित्तयों के साथ संघर्ष कार रहे हैं, पर महायुद्ध में विजयी होने के बाद उन्होंने अपने सिद्धान्तों और आदर्शों को ताक में रख दिया था । ब्रिटेन, फांस, हालैण्ड और अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने खीये हुए साम्राज्य की पुनः स्थापना के लिये

तलपर थे। फांस ने इन्डो-चायना के सम्बन्ध में जिस नीति का निर्धारण क्षिया था, जसके मुख्य तत्त्व निम्निल्कित थे-—(१) फांस के विशाल साम्राज्य को एक युनिक्ष यन के खप में परिवर्तित कर दिया जाय, जिसमें फांस के अतिरिक्त जसके अधीनस्कें देश भी अन्तर्गत हों। (२) इन्डो-चायना इस फेड्न यूनियन का एक अंग हो। (३) उन्डो-चायना के चार संरक्षित राज्यों और कोचीन चायना को मिलाकर एक संवर्ग (फिडरेशन) बनाया जाय और इस फिडरेशन में राजकीय पदों को प्राप्त करने का इन्डो-चायना के सब नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाय। (४) इन्डो-चाइनीज फिडरेशन की परराष्ट्रनीति और सेना का सञ्चालन फेड्न सरकार के हाथों में रहे। राज्य के आन्तरिक धासन के सम्बन्ध में इन्डो-चाइनीज फिडरेशन को स्वतन्त्रता प्राप्त रहे। (५) फेड्न यूनियन में सर्वत्र सरकारी नौकरी प्राप्त करने का यूनियन के सब नागरिकों को समान रूप से अवसर हो।

फे अच यूनियन की यह योजना त्रिटिश कामनवेल्य की योजना से अनेक अंशों में भिलती है। महायुद्ध के बाद फांस के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह इन्हों- नायना आदि साम्राज्यान्तर्गत देशों पर पहले के समान अपना आधिपत्य स्थापित रख सके। अतः उसने फे ब्ल्च यूनियन की योजना तथार की थी, जिसके द्वारक इन्हों-चायना आदि देशों को अपने आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वत- नत्रता प्राप्त हो जाती थी। पर विदेशी मामलों और सेना पर उनका निधन्त्रण नहीं होता था। यह सम्भव नहीं था, कि इन्हों-चायना के सम्बन्ध नेना फे ब्ल्च मृनियन की योजना को स्वीकृत कर सकते। वे पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे। उनमें राष्ट्रीय स्वावीनता और लोकतन्त्रवाद की भावना प्रस हह तक उत्पन्न हो निकी थी, कि वे फांस के आधिपत्य की आशिक रूप में भी स्वीकृत करने के लिये उत्पत्न नहीं थे।

फांस के आधिपस्य की पुनः स्थापना—मार्ग, १९४५ में जापानी रोनाएँ इन्डो-चायना को छोड़कर चली गई थीं। यदि इसके याद फोन्च सेनाएँ अच्छी बड़ी संख्या में तुरन्त इन्डो-चायना पहुंच जातीं, तब फांस के छिये गह सम्भव होता, कि बहु एक बार फिर इस देश पर पहले के समान अपने आधिपस्य को स्थापित कर सकता। पर अभी महायुद्ध की परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं, कि फोन्च सेनाएँ अच्छी बड़ी संख्या में गुदूर पूर्व में पहुंच सकतीं। अगस्त, १९४५ में जापान के आत्म समर्थण कर देने पर इन्डो-चायना पर अधिकार स्थापित करने का कार्य मित्रराज्यों की ओर से ब्रिटेन और चीन के सुपूर्व किया गया। यह व्यवस्था थीं गई, कि ब्रिटिश सेनाएँ दक्षिणी इन्डो-चायना पर और चीनी नेताएँ उत्तरी लोना पर कार्ज करें, ताकि सर्वत्र व्यवस्था स्थापित की जा सके। पर मार्च और अगस्त के बीच के

महीनों में इन्डो-चायता में कोई भी ऐसी राजशिक्त नहीं थी, जो हो ची मिन्ह की जिल्लानाम सरकार का मुकाबला कर राकती । परिणाम यह हुआ, कि इस काल में ही ची मिन्ह के दल ने अनाम में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया । अगस्त, १९४५ तक न केवल अनाम अपितृ तोन्किन और कोचीन चायना भी हो ची मिन्ह की अवीनता में आ गये थे।

त्रिटिश सेनाओं ने सबरे पूर्व सेगोन पर अपना बब्जा कायम किया। इसमे पूर्व सेगोन विएत नाम सरकार के अधीन था। ब्रिटिश सेनाओं ने सेगोन पर तो अपना अधिकार कायम कर लिया था, पर उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे इन्हों-चायना में और अधिक आगे वह सकें, क्योंकि विएत नाम सरकार की सेनाएँ उनका मुकाबला करने के लिये तत्पर थीं। ब्रिटिश सेनाओं ने इसके लिये विशेष प्रयत्न भी नहीं किया। मैंगोन को अपने कब्जे में करके उन्होंने उसे फांस के सुपूर्व कर विया और अब सम्पूर्ण इन्हों-चायना पर अपने प्रमुख की पुनः स्थापना का कार्य फांस की सेनाओं के हाथों में आ गया। १९४६ के शुरू तक फेल्च सेनायें अच्छी बड़ी संख्या में मैंगोन पहुंच गई थीं और फेल्च सरकार स्वाभाविक रूप से इस प्रयत्न में लगी थी, कि इन्हों-चायना पर फिर से अपने आधिपत्य को स्थापित कर ले। फेल्च हैं लगी थी, कि इन्हों-चायना पर फिर से अपने आधिपत्य को स्थापित कर ले। फेल्च की सीमत कर ले। केल्च की सीमत कर ले। केल्व की सीमत कर ले। सेना की सीमत कर ले के किया तैयार कर लें। पर अपने इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं हुई। अब फांस के सम्मूख केवल यही मार्ग अविधिष्ट था, कि वह विएत नाम सरकार को मुद्ध हारा परास्त करे।

विएत नाम बोर फांस—उत्तरी इन्डो-चायना में जापान के प्रभाव का अल कर व्यवस्था स्थापित करने गा कार्य चीनी सरकार के सुपुर्द किया गया था। चीनी लोगों गे यह यत्न नहीं किया, कि विएत नाम सरकार के खिलाफ संघर्ष करें या उमके शासन-कार्य में किसी प्रकार का हस्सक्षेप करें। अतः उत्तरी इन्डो-चायना में विएत नाम सरकार की सत्ता अक्षुण्ण रूप से कायम रही। पर फांस इस बात के लिये उत्तर्य था, कि जिस प्रकार गैंगोन में उसकी सेनाएँ प्रविच्ट हुई हैं, वैसे ही उत्तरी इन्डो-चायना में भी प्रविच्ट हो जावें और चीनी सेनाओं का स्थान फेल्च सेनाएँ ले लें। पर यह बात तभी सम्भव थी, जब कि या तो फांस विएत नाम सरकार के साथ युद्ध करें और या किसी प्रकार समझौते हारा विएत नाम सरकार को इसके लिये राजी कार ले। इ मार्च, १९४६ को फांस ने विएत नाम सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसकी मुख्य शत निम्नलिखित थीं—(१) फांस यह स्वीकार करता है, कि विएत नाम रिपव्लिक की स्थित एक स्वतन्त्र राज्य की है, और उसे यह अधिकार है, कि वह अपनी पृथक सरकार, पृथक पालियामेन्ट और पृथक रोना

रख सके। (२) विएत नाम रिपिक्किक इन्डो-चाइनीज फिडरेशन के अन्तर्गत रहेगी और इन्डो-चाइनीज फिडरेशन फेक्च यूनियन का अंग बनकर रहेगा। (३) विण्युत् नाम रिपिक्किक का शासन किन-किन प्रदेशों में हो, यह बात लोकमत (रिफरेन्डमर्थ द्वारा निश्चित की जायगी। (४) फेक्च सेनाएँ तोन्किन में प्रवेश कर सकेंगी। (५) इस समझौते के बाद जब फांस और विएत नाम रिपिक्किक के पारस्परिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हो जावें, तो परस्पर बातचीत द्वारा यह बात तय की जाय, कि विएत नाम का अन्य विदेशी राज्यों के साथ क्या और किस प्रकार का सम्बन्ध रहे।

६ मार्च, १९४६ का यह सामझौता हनोई समझौते के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इन्डो-चायना के आधुनिय इतिहास में इसका बहुत अधिय महत्त्व हैं। यद्यपि विएत नाम सरकार के नेता पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे और अपने देश पर किसी भी प्रकार के फेंच प्रमुत्त्व को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थे, पर समय की परिश्वितियों को दृष्टि में रखकर उन्होंने यही उचित समझा, कि वे फांस के साथ समझौता कर लें, और फेक्च यूनियन के अन्तर्गत रहते हुए अपने देश की उन्नति के लिये प्रयत्नशील हों। हनोई समझौते के परिणामस्वरूप फेक्च सेनाएँ तोन्विन में प्रविष्ट हों गई और हनोई नगर में उन्होंने अपनी छायनी डाल दी। अब विश्वण में सैगोन में और उत्तर में हनोई में फेक्च सेनाओं ने अपना कब्जा कर लिया था, पर इनके बीच की सब प्रदेश विएत नाम सरकार के शासन में था।

पर ६ मार्च, १९४६ का यह समझौता देर तक कायग नहीं रह सका। जिन प्रक्तों पर फेंक्च और विएत नाम सरकारों में परस्पर मतमेद उत्पन्न हुआ, वे निम्निलिखित थे—(१) सैगोन में फेंच सेनाओं की सत्ता के वारण फांस ने कोचीन चायना में एक पृथक सरकारकी स्थापना कर दी थी, जो विएत नाम रिपब्लिंग की अधीनता में नहीं थी। कोचीन चायना विएत नाम रिपब्लिंग के अन्तर्गत हो या नहीं, इस प्रक्रन का निर्णय रिफरेन्डम हारा किया जाना चाहिये था। पर फांस ने अपनी सैन्य शिवत के जोर पर इस प्रदेश में पृथक सरकार का निर्माण कर लिया था, जिसकी विएत नाम सरकार स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं थी। (२) फेंक्न लोग समझते थे, कि इन्डो-चायना में जिस फिडरेशन का निर्माण किया जाना है, उसका अध्यक्ष फांस हारा नियन्त्रण रखेगा। इसके विपरीत विएत नाम रिपब्लिंग स्व राज्यों पर अपना नियन्त्रण रखेगा। इसके विपरीत विएत नाम रिपब्लिंग के नेताओं का यह विचार था, कि इन्डो चाइनीज फिडरेशन के अन्तर्गत सब राज्यों का यह विचार था, कि इन्डो चोइनीज फिडरेशन के अन्तर्गत सब राज्यों के एवं विचार साह से साह सोग करने के उद्देश्य से ही फिडरेशन में सिम्मलित होंगे।

इन मतमेदों को दूर वारने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये । १९४६ में कई बार

फांस और विएत नाम रिपब्लिंक के प्रतिनिधियों की सम्मिलित कान्फरेन्सें हुई। फूर ये मतभेद दूर नहीं हो सके। परिणाग यह हुआ, कि हनोई समझौता भंग हो गया और फांस और विएत नाम रिपब्लिंक में युद्ध प्रारम्भ हो गया। विएत नाम सरकार के नेताओं की सैन्य शिक्त इतनी नहीं थी, कि वे फ्रेंक्च सेनाओं का सम्मुख-युद्ध में मुकावला कर सकते। १९४६ में बहुत सी फ्रेंच सेनाएँ सैंगोन और हनोई में पहुंच गई थीं। इन सेनाओं को परास्त कर सम्पूर्ण तोन्किन, अनाम और कोचीन चायता में अपने प्रमुत्त्व की स्थापना कर सकना विएत नाम सरकार के लिये सुगम नहीं था। पर विएत नाम में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना इतनी अधिक प्रवल थी, कि फांस के लिये भी उसको दबा सकना सम्भव नहीं था। परिणाम यह हुआ, कि हो ची मिन्ह और उसके साथियों ने गुरीला युद्धनीति का आश्रय लिया और फ्रेंच सेनाओं के कार्य को बहुत अधिक कठिन बना दिया। फ्रांस और विएत नाम रिप-व्लिंक का यह युद्ध दिसम्बर, १९४६ में शुरू हो गया था।

बाओ दाई की सरकार-हो नी मिन्ह के साथ युद्ध शुरू हो जाने पर फ्रेंट्च सरकार ने यह आवश्यक समझा, कि इन्डो-चायना में एक ऐसी सरकार कायम की जाय, जो उसके हाथ की कठपुतली हो । महायुद्ध के बाद संसार में सर्वत्र राष्ट्रीयता भीर लोगतन्त्रवाद की प्रवित्तयां जिस ढंग से प्रवल हो गई थीं, उसके कारण फ्रांस के लिये यह सम्भव नहीं रहा था, कि वह इन्डो-चायना पर पहले के समान अपना शासन स्यापित कर सके । अतः उसने यह निश्चय किया, कि इन्डो-चायना में एक ऐसी सरकार कायम कर दी जाय, जो कम्यनिज्म की विरोधी हो और जो फ्रांस के आदेशों का अनसरण करती हुई हो ची मिन्ह के विरुद्ध युद्ध जारी करने का कार्य कर सके। हम इसी प्रकरण में ऊपर लिख चुके हैं, कि २५ अगस्त, १९४५ को अनाम के सम्राट बाओ दाई ने अपने राजसिंहासन का परित्याग कर दिया था, क्योंकि विएत नाम रिपब्लिक की स्थापना हो जाने के कारण उसके लिये अपने पद पर रह सकना सम्भव नहीं रहा था । इन्ही-चायना छोड़कर यह बाओ दाई युरोप चला गया था, और लण्डन में अपना समय बिता रहा था। दिसम्बर, १९४७ में ब्रिटेन में स्थित फेञ्च राजदूत की बाओ वाई के साथ मुलाकात हुई। वहां उसके सम्मुख यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, कि वह अपने देश की वापस जाकर उसके शासन को किए से संभाल ले। इंडो-चायना में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो ही ची मिन्ह की समाजवादी प्रवृत्तियों के विरोधी थे। फांस को आजा थी, कि ये सब कम्यु-निस्ट विरोधी लोग बाओ दाई का समर्थन करेंगे और उनकी सहायता से बाओ दाई एक ऐसी सरवार का निर्माण कर सकने में समर्थ हो सकेगा, जो विएत मिन्ह दल की विरोधी होगी । फेञ्च सेनाओं की सहायता से बाओ दाई की सरकार विएत नाम

रिपब्लिन की परास्त कर सकेगी और इन्डो-चायना में एक ऐसा शासन स्थापित हो जायगा, जो न केवल कम्युनिज्य का विरोवी होगा, अपितु साथ ही फ्रांस का ब्र्युन वर्ती भी होगा।

भार्च, १९४९ में फास के राष्ट्रपति श्री ऑरगोल और वाओ वाई में इन्हो-चापना के सम्बन्ध में बाकायदा सन्धि हो गई । इस सन्धि के अनुसार दण्डो-चायना का जासन-अधिकार फांम ने वाओं दाई के गुपूर्व कर दिया । सद्यपि वाओं दाई फांस की तरफ से इन्डो-चायना का शासक बना विया गया था, पर इस देश के बड़े भाग पर हो ची मिन्ह की सरकार का कब्जा था। वाओ दाई इन्डो-चायना पर अपना प्रभुत्व तभी स्थापित कर सवता था, जब कि वह विएत नाम रिपब्लिक की सेनाओं की युद्ध में परास्त करें। पर इस कार्य में फांस उसकी सहायता करने के लिये जवत था। एक छाल से भी अधिक फोल्य रौनिक बाओ दाई की सहायता के लिये एन्डो-चायना भेज दिये गये। ये सैनिक सब प्रकार के आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से मुसज्जित थे ओर हो नी मिन्ह की सरकार के लिये यह सुगम नहीं था, कि यह उनका सफलतापूर्वक मुकायला कर सकती । परिणाम यह हुआ, कि हो ची मिल्ह और वाओ वार्ड की रोनाओं में बाका-यदा युद्ध प्रारम्भ हो गगा । रूस, कम्युनिस्ट चीन आदि अनेस देशों ने हो ची मिर्कें की सरकार को इन्डोचायना की वैच सरकार के रूप में स्वीकृत किया और अमेरिका फांस, ब्रिटेन आदि ने बाओ दाई की सरकार को । शुरू में ही ची मिन्ट की विएत नाम सरकार पूर्णरूप से कम्यनिस्ट नहीं थी। उसका उद्देश्य दन्डी-नायना में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्यापना करना था । पर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि के विरोध के कारण और वाओ दाई के नेतृत्व में एक विरोधी सम्भार की स्थापना हो जाने से इन्डो-चायना में जो लोग कम्युनिज्य के पक्षापाती थे, वे हो ची भिन्त भी सरकार का रामर्थन वारने छगे और वाम्युनिज्य के विरोधी इन्डो-चाइनीज छोग थाओ बाई की सरकार के पक्ष में हो गये। इस प्रकार इन्डो-लायना में कम्युनिज्य और पूंजीवादी प्रवृत्तियों में परसार संघर्ष का प्रारम्भ हुआ, जो इस समय संसार के बहुत से देशों में जारी है।

(२) थाइलेंड

महामुद्ध से पूर्व दिक्षण-पूर्वी एशिया में सियाम या थाइलैण्ड ही एक ऐसा तेलें या, जो राजनीतिक दृष्टि से किसी पारुपात्य देश के अभीन नहीं था । बरमा (ब्रिटेन के अवीन) और इन्डो-चायना (फांस के अधीन) के बीन में उसकी स्थिति प्रायः वैसी ही थी, जैसी कि भारत और रूस के बीन में अफगानिस्तान की थी। सियाम

के राजनीतिक इतिहास पर हम पहले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं । १९३० के बाद जापान जिस प्रकार पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति के विस्तार में लगा था, विधाम के लोग उससे मली-मांति परिचित थे। मञ्चिरिया से चीन के शासन का अन्तं कर जापान ने वहा मञ्जूकुओ नामक पृथक् व स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी । वाद में द्वितीय चीन-जागान युद्ध के परिणामस्वरूप जापान ने पूर्वी व दक्षिणी चीन पर अपना प्रभाव व प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया था। इन बातों को देखकर, सियाम के राजनीतिक नेताओं का यह विख्वास दढ़ हो गया था, कि जापान का भविष्य बहुत उज्ज्वल हैं, और वह समय दूर नहीं है, जब कि जापान सम्पूर्ण पूर्वी व वक्षिण-पूर्वी एशिया का नेतृत्व करेगा और पाश्चात्य देश उसकी शक्ति के सम्मक्ष ंगडे नहीं रह सकेंगे। इसीलिये सियाम की सरकार जापान के साथ मैंत्रीः सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उत्सुक थी । १९३२ में जब मञ्चूरिया के प्रका पर राष्ट्रसंघ में जापान के विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तो सियाम इस प्रस्ताव पर उदासीन रहा । गई, १९३८ में मियाम और जापान ने परस्पर मिलकर एक सन्धि की, जिसके अनुसार जापानी नागरिकों को नियाम में व्यापार करने. कारोबार खोलने, मनान व जमीन को किराये पर लेने, जायदाद खरीदने थ चाहे पर लेने और वसने के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई। जून, १९४४ में . सियाम ने जापान के साथ एक और सन्धि की । इस सन्धि का उद्देश्य यह था, कि इन्डो-चायना के वे पश्चिमी प्रदेश, जहां थाई लोग बहुसंख्या में निवास करते थे, अब सियाम को प्राप्त हो जावें । जन, १९४० में फांस का पतन हो गया था और इन्डो-चायना की फोञ्च सरकार के साथ जापान ने समझौता कर लिया था । इस समझौते के अन्सार जापानी सेनाएँ इन्डो-चायना में प्रवेश कर गईं थीं, और फांस द्वारा शासित यह देश जापान के प्रभाव में भा गया था। फांस की निर्वलता से लाभ उठाकर सियाम ने यह उपयुक्त समझा, कि इन्हो-चायना के जिन पश्चिमी प्रदेशों में थाई लोग वडी संख्या में निवास करते हैं, उन्हें अपने देश के साथ मिला लिया जाय । इसके लिये उसे सैन्यशक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं हुई। इन्डो-चायना की फेञ्च सरकार इस समय इस स्थिति में नहीं थी, कि वह जापान की उपेक्षा कर सके । क्योंकि जापान सियास का भित्र था, और यह चाहता था, कि याई लोगों द्वारा आबाद ये प्रदेश शियाम को प्राप्त हो जावें, अतः इन्डो-चायना की सरकार ने इस ें धेरेन में नोई नाधा नहीं डाली और सियाम को अपने विस्तार का अवसर हाय छम गया ।

जापान ने थाई लोगों द्वारा आबाद प्रदेशों को इन्डोचायना से सियाम को विलाने में सहायता की थी, अतः सियाम और जापान के पारस्परिक सम्बन्ध और भी अधिक सिश्रतापूर्ण हो गये। दिसम्बर, १९४१ में जब जागान ने महायुद्ध में प्रवेश किया, तो सियाम ने भी उसका साथ दिया। २१ दिसम्बर, १९४१ को जापान और सियाम में गरस्पर सन्धि हो गई, जिसके अनुसार सियाम ने भी ब्रिटेन अक्ष्रि अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा गर दी। महायुद्ध के समय में सियाम की सरकार पूर्ण रूप से जापान की वजवर्ती थी। जापान ने स्थलमार्ग द्वारा जो मलाया और बरमा पर आक्रमण किया था, उसके लिये उसकी सेनाओं ने सियाम के स्थलमार्ग का म्वन्छन्द रूप से उपयोग किया था। सियाम की सरकार ने जापान की सेनाओं को अपने प्रदेश से गुजरने की अनुमति ही नहीं दी थी, अपितु उनकी पूर्ण रूप से सहायता भी की थी। इस समय सियाम की सरकार का प्रधान नेता श्री लुआंग पिगुल संग्राम था, जो जापान का प्रवल समर्थ कथा। पर सियाम में एंग्रे लोगों का भी अभाव नहीं था, जो अपने देश में जापान के प्रभाव व प्रभुत्त्व के विरोधी थे। महायुद्ध के अन्तिम दिनों में इन लोगों ने जापान के विरुद्ध मित्रराज्यों की सहायता भी की थी।

महायुद्ध में जब जापान परास्त हो गया, तो सियाम पर मान्जा नारने का ना मित्रराज्यों की ओर से ब्रिटेन के सुपूर्व किया गया । ब्रिटिश सेनाओं ने सियाम पर अपना अधिवार स्थापित कर लिया और वहां की सरकार के सम्मुख निम्नलिखिङ्ग मांगें पेश कीं-(१) सियाम की सरकार पूर्णतया ब्रिटिश शासकों के नियन्त्रण में रहे । (२) सियाम का विदेशी व्यागार ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संचालित हो । (३) जब तक कि मित्रराज्य सियाम को संयुक्त राज्यसंघ (युनाइटेड नेशन्स आर्ग-निजेशन) या सदस्य बनाना स्वीकार न कर हैं, सियाम की स्थिति ब्रिटेन के संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टरेट) के सद्श रहे। पर सियाम के राष्ट्रवादी नेता ब्रिटेन की इन मांगों को स्वीकृत बारने के लिये तैयार नहीं थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान सियाम में भी महायुद्ध के समय राष्ट्रीयता की भावना अत्यन्त उप-रूप घारण कर चुकी थी। सियाम में भी राष्ट्रवादी देशभक्तों का एक ऐसा दल विद्यमान था, जो अपने देश पर जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को अत्यन्त अनुवित समझता था । इस दल के नेता थी लुआंग प्रदीत थे । श्री लुआंग प्रदीत और उनके अनुयायी जब अपने देश पर जापान के प्रभाव की सहने के लिये तैयार नहीं थे. तो उनके लिये यह कैरी सम्भव हो सकता था, वि वे सियाम को ब्रिटेन का संरक्षित राज्य बनने दें । उन्होंने ब्रिटेन का प्रचण्डरूप से विरोध किया । आखिर, १ ज वरी, १९४६ को ब्रिटेन और सियाम में सन्धि हो गई, जिसकी मुख्य शर्ते निम्नलिखित थीं--(१) ७ दिसम्बर, १९४१ को सियाम की जो सीमायें थीं, वे ही अब भी रहें। (२) सियाम में १९४१ तक ब्रिटिश लोगों को व्यापार आदि के सम्बन्ध में जो विशेष

अधिकार प्राप्त थे, उन्हें फिर से स्वीकृत किया जाय। (३) महायुद्ध के समय सियाम के कारण जिटेन की जो नुकसान उठाना पड़ा था, सियाम की सरकार उसकी क्षीतपूर्ति करने के लिये उपयुक्त हरजाना प्रदान करे।

श्री लुआंग प्रदीत और उनके साथियों ने ब्रिटेन की इन मांगों को स्वीकृत करके अपने देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को कायम रख लिया। २८ एप्रिल, १९४७ को सियाम या थाईलैण्ड संयुक्तराज्य संघ का सदस्य बना लिया गया और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी प्रायः वही स्थित कायम रही, जो महायुद्ध के पहले थी।

महायुद्ध की समाप्ति पर सियाम के शासन में भी अनेन सुधार किये गये। पिछले एक अध्याय में हम सियाम के शासन पर प्रकाश डाल चुके हैं। वहां राज-सत्ता कायम थी, यद्यपि राजा के शासन को मर्यादित करने के लिये पालियामेन्ट मी वहां विद्यमान थी। १९४६ में सियाम के लिये जो नया शासन विधान बना, उसमें पालियामेन्ट में दो समाएँ रखी गईं। यह व्यवस्था की गई, कि दोनों सभाओं के सम्पूर्ण सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचन हारा की जाय। मन्त्रिमण्डल को भी पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। राष्ट्रीय स्वाधीनता की वृद्धि से कीयाम पहले भी एन पृथक् व स्वतन्त्र राज्य था। १९४६ के शासन विधान के कारण वहां लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति भी बहुत कुछ सफल हो गई। पर महायुद्ध के बाद लोकतन्त्र शासन की स्थापना के कारण सियाम की समस्याओं का अन्त नहीं हो गया। महायुद्ध के कारण संसार के बहुसंख्यम देशों में जो आधिक संकट प्रादुर्भूत हुआ था, उसका असर सियाम पर भी पड़ा और वहां भी अनेक ऐसे दल उत्पन्न हुए, जो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिये प्रयत्नशील थे।

(३) मलाया

महायुद्ध से पूर्व जिटेन की अधीनता में मलाया की क्या दशा थी, इस विषय पर हम पहले एवा अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। विक्षण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया में भी राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकांक्षा विद्यमान थी और अनेक मलाया नेता अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थे। जब जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त क्यिया, तो मलाया में भी राष्ट्रीय आन्वोलन को बहुत बल मिला। मलाया से ब्रिटिश शासन का अन्त कर जब जापान ने वहां अपना सैनिक शासन स्थापित किया, तो राष्ट्रभवत मलाया लोग उसका विरोध कारने के लिये समानरूप से तत्पर हो गये। इस पहले लिख चुके हैं, कि मलाया में नी राज्य थे, जिनमें वहां के पुराने वंशकमा-

नुगत सुलतानों का शासन था। इन सुलतानों की ब्रिटेन की अधीनता में गही स्थित थी, जो भारत में देशी रियासतों के राजाओं की थी। इन नी राज्यों के अतिरिक्त स्ट्रेट सैटलमेन्ट का राज्य सीधा ब्रिटेन के शासन में था। ब्रिटिश आधिपत्य के युग की इन दस राज्यों के नियासियों में अपने एक होने की अनुभूति भलीभांति विकसित नहीं हुई थी। पर जब जापान ने उन सब राज्यों को ब्रिटिश आधिपत्य स मुक्त कराके अपने सैनिक शासन के अधीन किया, तो मलाया के लोगों में राष्ट्रीय एकता की अनुभृति उत्पन्न हुई और उन्होंने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय स्थायीनता के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया। दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समाप मलाया में भी जापानी लोगों ने बाद में स्वराज्य की स्थापना की और इस देश के शासन का कार्य मलाया के लोगों के हाथों में सुपूर्व कर दिया।

अगस्त, १९४५ में जापान के आतम समर्पण कर देने के बाद शितम्बर, १९४५ में जब ब्रिटिश सेनाओं ने मलाया में प्रयेश किया, तो उन्होंने देखा कि इस देश में एक ऐसी सरकार स्थापित है, जिस पर राष्ट्रवादी देशभवतों का प्रभत्य है। इस स्थिति में ब्रिटिश लोगों के लिये यह बहुत सुगम नहीं था, कि वे मलाया पर पहले के समान अपना आधिपत्य स्थापित कर सर्के । मलाया के देशभक्तों के लिये यह तो सम्भव नहीं था, कि वे शक्तिशाली ब्रिटिश सेनाओं का सम्मूख युद्ध में मुकाबला करू सकते । पर वे ग्रीका युद्धनीति का अध्यय लेकर अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये अवश्व प्रयता वार सकते थे । इस दशा में बिटिश सरकार के लिये यह अति-वार्य हो गया, कि वह मलाया के सम्बन्ध में एक ऐसी नीति का अनुसरण करे, जिसे मलाया के राष्ट्रीय नेता स्वीकृत करने के लिये तैयार हों। अक्टूबर, १९४५ में ब्रिटिश सरकार की ओर से मलाया के सम्बन्ध में यह योजना प्रकाशित की गई. कि (१) मलाया के विविध राज्यों की मिलाकर एक यनियन का निर्माण किया जाय, जिसमें मणाया के नी पूराने राज्य (जिनपर गुलतानों का जासन था) और स्ट्रेंट्स सैटलमीन्ट अन्तर्गत हों। (२) सिगापुर को इस यूनियन से बोहर एया जाय, और वहां पर पहले के सदश ब्रिटेन का शासन जारी रहे। (३) मलाया यूनियन का एक गवर्नर हो, जिसकी निय्क्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाय । युनियन के जासन पर नियन्त्रण रखना इस गवर्नर का कार्य हो । (४) मळाबा युनियन में व्यवस्थापिका सभा का निर्माण किया जाय और इस सभा को देश वे लिये जानर आदि बनाने के उपयक्त अधिकार प्राप्त हों।

पर गलाया के राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश सरकार की इस योजना को स्वीकृत करमें के लिये ज्यत नहीं थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश योजना का विरोध करने के लिये एक संगठन का निर्माण किया, जो 'युनाइटेड मलाया नेशनल आगीनजेशक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रिटिश सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह मलाया के जाव्दीय नेताओं के विरोध की उपेक्षा कर सके। अतः उसकी तरफ से मलाया के शम्बन्ध में एक अन्य योजना बनाई गई, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—(१) मलाया के दस राज्यों की पृथक् रूप से सत्ता कायम रहे, उनकी पृथक् सरकारें और पृथक् व्यवस्थापिका सभायें हों और उन्हें मिलाकर एक मलाया फिडरेशन (संवर्ग) का निर्माण किया जाय। फिडरेशन की पृथक् सरकार और पृथक् संघ सभा (फिडरल कौंसिल) बनाई जाय। (२) मलाया के शासन पर देखभाल रखने के लिये ब्रिटिश सरकार की ओर से एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाय। इस हाई कमिश्नर का कार्य राज्यकार्य में परामर्श देना हो, सरकार पर इसका सीधा नियन्त्रण न हो। शासनकार्य में मलाया के विविध राज्यों की सरकारों और संघ सरकार को अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता व पूर्ण अधिकार प्राप्त हों।

युनाइटेड मलाया नेशनल आर्गनिजेशन के नेताओं को बिटिश सरकार की यह नई योजना पसन्द थी, पर मलाया में ऐसे उग्र राज्यवादी लोगों की कमी नहीं थी, जो अपने देश की पूर्ण स्वाधीनता के लिये उत्सुक थे और जो निसी भी रूप में ब्रिटिश आधिपत्य को सहने के लिये तैयार नहीं थे। इन लोगों ने मलाया नेशनलिस्ट पार्टी हैं।म से एक तथे दल का संगठन किया और ब्रिटिश योजना का विरोध करना प्रारम्भ किया । मलाया नेशनलिस्ट पार्टी की मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं—(१) मलाया के संघराज्य में सिगापुर को भी सम्मिलित किया जाय, (२) राम्पूर्ण मलाया के लिये जिस केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्माण हो, उसके सब सदस्य निर्वाचित हों। संघ के अन्तर्गत विविध राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य भी निर्वाचन द्वारा नियुक्त हों, और (३) मलाया के सब स्थिर निवासियों को नागरिकता के अधिकार समान रूप से प्रदान किये जायें। मलाया की यह नेशनलिस्ट पार्टी न केवल बिटिश आधिपत्य की विरोधी थी, अपितु साथ ही मलाया से सुलतानों के शासन का अन्त कर लोकतन्त्र शासन भी स्थापित करना चाहती थी। युनाइटेड मलाया नेशनल आर्गनिजेशन के नेता नरम दल के थे, वे ब्रिटेन के आधिपत्य की भी स्वीवृत करने के लिये उचत थे और प्राचीन वंशकमानुगत मुलतानों की सत्ता को भी कायम रखना चाहते थे।

ब्रिटिश सरकार के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह उग्र राष्ट्रवादी नेताओं (मेलाया नेशनलिस्ट पार्टी) की मांगों को स्वीकृत कर सके। परिणाम यह हुआ, कि उसने १९४७ की योजना (जिसे युनाइटेड मलाया नेशनल आगेनिजेशन ने स्वीकृत कर लिया था) के अनुसार मलाया के शासन का पुनः संगठन कर दिया। पर इससे मलाया की राजनीतिक समस्याओं का अन्त नहीं हो गया। १९४७ की

योजना को किया में परिणत करने के बाद मलाया की नई सरकार को जित गर्य समस्याओं वर गराना गरना पटा, वे निम्निङ्गिता थीं--(१) मलाया के उप भाष्ट्रवादी नेता अपने देश पर ब्रिटिश आधिपत्य को विसी भी रूप में गहन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश सा माज्यनाद के विरुद्ध अपने संघर्ष को आरी रखा। (२) गलाया की जनता में चीनी और भारतीय छोगीं की संख्या बहुत अविवा है। मलाया के अपने लोगों के अतिरित्त इस देश में चीनी भोर भारतीय कितनी अविना संख्या में विवास करते हैं, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मलाया जाति के लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना प्रवल हो रही थी. उसके कारण उन्हें चीती। व भारतीय लोगों का अपने देश में बची संख्या में निवास करता परान्य गहीं था । मलाया देश मलाया के अपने लोगों के जिये है, यह भाव जनमें निरन्तर प्रवल होता जाता था। (३) जब चीन में समाजवादी व्यवस्था अगयन ही गई और कम्युनिस्ट लोगों का चीन पर आधिपत्य स्थापित हो गया, तो भलाया में भी वान्यनिस्ट वल प्रवल होने लगा । विवोधनया भलाया में निवास मारने वाले नीनी लोगों में कम्युनिज्म का प्रवार बड़ी तेजी के साथ बढ़ते लगा और मलाया का कम्युनिस्ट वल अपने देश में समाजवादी धारान नगयम वरने के लिये पयत्नशील हो गया। भजाया के इस कम्युनिस्ट दल के गाथ यहां के राष्ट्रवर्ष देशभवतों की भी सहानभत्ति थी, वयोंकि ब्रिटिश आधिपत्य का अन्त गरने के लियें वे भी वस्पनिस्टों के समान ही प्रयत्नशील थे। परिणाग यह हजा, कि उग्र राष्ट्र-बादी नेताओं ओर कम्युनिस्टों के सांगाणित प्रयस्त के कारण गळाया भी सरकार के लिये अपने देण में शास्ति व्यवस्थापित कर राक्ता बहुत कठित हो। गया ।

(४) वरमा

जिस समय दिसम्बर, १९४१में जापान ने महासुद्ध में प्रवेश किया, तब बरमा की क्या क्थित थी, इस विकय गर हम विक्रंड एम अध्याय में प्रवास लाग लुते हैं। बरमा में ब्रिटिश शालन के विक्रंड प्रवल माचना विश्वपास थी, बार अनम उप राष्ट्रीय दल बिटिश शासन का जल्त कर अपने देश की स्वाधीनता के लिये प्रयत्नशील थे। यही कारण है, कि जय आगान ने दक्षण-पुनी एशिया के विविध प्रयत्नशील थे। यही कारण है, कि जय आगान ने दक्षण-पुनी एशिया के विविध देशों से पाइचात्य शाम्राज्यवाद का अन्त करते हुए बरमा पर आक्रमण किया, तो अनेय बरमी देशभवत दलों ने प्रसन्नता और सन्तोप का अनुभव किया। उन्हें समझा, कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने का यह सुवर्णीय अवश्वर है, और इसीलिय किटेन के आधिपत्य का अन्त करने में उन्होंने जापान के साथ राह्योग करने में की संबोच नहीं किया। फरवरी, १९४२ तक जापान ने बरमा के बड़े भाग को

बिदेन की अधीनता से स्वतन्त्र करा विया था और प्रारम्भ में देश में शान्ति और व्यवस्था को नायम रखने के लिये गैनिक शासन का संगठन किया था। पर जापानी लीग बरमा को अपनी अधीनता में रखने के स्थान पर वहां एक ऐसी बरमी सरकार कायम करना चाउते थे, जो पाश्चात्य साम्राज्यवाद का अन्त करने में जापान के साथ सहयोग करने को तैयार हो। इसीलियं उन्होंने १ अगस्त, १९४२ को बरमा में एक स्वतन्त्र वरमी सरकार का सगठन किया, जिसका अधिपति डा० वा मो को बनाया गया। डा० वा मो बिटिश आधिपत्य के युग में बरमा के प्रधान मन्त्री रह खुके थे और राष्ट्रीय दल के प्रधान नेता थे। यही कारण है, कि बिटिश सरकार के साथ कार्य कर सकता उनके लिये सम्भव नहीं रहा था और इसीलिये ब्रिटिश शासकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। डा० वा मो का यह विचार था, कि जापान के साथ सहयोग करके वरमा न केवल अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है, अपितु साथ ही एशिया से पारचात्य साम्राज्यवाद का अन्त करने में भी सहायक हो सकता है।

जिनवरी, १९४५ में भित्र सभी की किकानों ने नवमा पर आक्रमण किया, और कुछ ही समय में इस देश पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पर ब्रिटेन के लिये अब यह सुगम नहीं था, कि वह बरमा पर पहले के समान अपना शासन स्थापित कर सके। बरमा के लोगों में राष्ट्रीय रत्ना गीनता की मानना बहुत

प्रबल हो गई थी, और वे किमी भी प्रकार ब्रिटिश लोगों के शासन को सहने के लिये तैयार नहीं थे। विशेषतया एण्टि-फीसिस्ट पीपन्स फीडम लीग के नेता अपने देव की स्वाधीनता के लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार थे और वे किसी श्री रूप में ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करने के लिये उदात नहीं हो समते थे।

पर ब्रिटिश लोग बरमा को फिर से अपनी अधीनता में लाने के लिये कटिक्ड थे। जापानी आक्रमण के कारण बरमा की ब्रिटिश सरकार भारत चली आईथी और गिमला में रहकर जुल दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, जब कि उने फिर से बरण पर शासन करने का अवसर मिलेगा। रंगन की विजय के बाद गई, १९४५ में इस ब्रिटिश 'बरमी सरकार' की ओर से एक योजना प्रकाशित की गई, जिसकी मध्य बातें निम्तिकिसित थीं--(१) बरमा की वही स्थिति रहेगी, जो कि जापान के आक्रमण से पूर्व १९४१ में थी। (२) अरू में बरमा पर बिटिश गवर्नर का सीधा शासन कायम किया जायगा, और सम्पूर्ण राजशनित उसी के हाथों में होगी। (३) १९३५ में बरमा के शासन के लिये जो विधान ब्रिटिश पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत विधा गया था, उसे फिर से लागु किया जायगा और जब वरमा में पूर्णरूप से शानि व व्यवस्था कायम हो जायगी, तब इस विधान के अनुसार व्यवस्थापिका सभा का नया निर्वाचन होगा और फिर से मन्त्रिमण्डल का निर्माण विधा जायगा। पह इस स्थिति को लाने में तीन वर्ष के लगभग समय लग जायगा। (४) बरमा के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की यह नीति है, कि अन्तर्तागरका वतां ओपनियेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाय । यदि बरमा के विविध राजनीतिक दल औपनिवे-शिक स्वराज्य के सम्बन्ध में परस्पर सहमत होकर किसी नये जासन विधान का लिमाण कर सकने में समर्थ हो जावें, तो बिटिश सरकार उसे स्वीकृत कर लेगी।

मई, १९४५ की इस बिटिश योजना से बरमा के देशभवत संतुष्ट नहीं थे। जापान की विजयों के कारण बरमा एक बार स्थाधीनता का आस्थाद के चुका था। वहां के जग्न राष्ट्रवादी नेता जापान द्वारा स्थापित बरमी मरकार से भी सन्तुष्ट नहीं थे। इस दशा में यह कैसे सम्भव था, कि ये लोग अब ब्रिटिश आधिपत्य व शास्त को सह सकें। परिणाम यह हुआ, कि आंग सान और तसके अन्यापियों ने बिटिश शासन का विरोध करना शुरू किया और ब्रिटिश लोगों के लिये वरमा पर पहले के समान अपना शासन स्थापित कर सफना असम्भव हो गया। इस दशा में अगन्त १९४६ में बरमा के नये ब्रिटिश गयर्नर सर हुबट रान्स ने यह आवष्यक समझा, कि बरमा के राष्ट्रवादी नेताओं के साथ समझीता कर लिया जाय। उसने बरमा के शासन समा (एक्जीक्यूटिव कीसिल) का मंगठन विया, जिसमें स्थारह सदस्य रखे गये। इनमें से छ: एफ्ट-फैसिस्ट पीपत्म फीडम लीग के थे भे और

पांच अन्य राजनीतिक दलों के। इस कौंसिल के निर्माण से बरमा के नेताओं ने सुंतोण अनुभव किया। पर यह ब्यवस्था सामयिक रूप से की गई थी, और यह निश्चय किया गया था, कि बरमा के शासन के सम्बन्ध में स्थिर रूप से व्यवस्था करने के लिये लण्डन में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया जाय, जिसमें बरमा के नेता अपने देश की भावी ब्यवस्था के बिषय में निर्णय करने के लिये स्वतन्त्र हीं। २० दिसम्बर, १९४६ को ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री द्वारा यह घोषणा की गई, कि बरमा को यह निर्णय करने की पूरी स्वतन्त्रता होगी, कि वह ब्रिटिश कामनवेल्थ का अग बनकर रहना चाहता है, या उसके साथ कोई भी सम्बन्ध न रखकर पूर्ण स्वाधीनता चाहता है। वस्तुतः, इस समय ब्रिटेन के चतुर राजनीतिज्ञों ने यह मलीभांति अनुभव कर लिया था, कि बरमा पर अपना आधिपत्य कायम रख सकना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। बरमा में राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना इतनी प्रबल हो चुकी थी, कि सैन्य शक्ति का उपयोग कर इस देश को अपने अधीन रख सकना असम्भव था।

लग्डन कान्फरेन्स में बरमा की ओर से जो प्रतिनिधिमण्डल सम्मिलित हुआ, उनके प्रधान नेता थी आंग सान थे। इस कान्फरेन्स ने जनवरी, १९४७ में जो ौंतेर्णय किया, उराकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं—(१) बरमा का शासन विधान तैयार करने के लिये एक संविधान परिषद् का निर्वाचन किया जावे । इस परिषद् को यह अधिकार हो, कि वह अपने देश के लिये शासन विधानका निर्माण कर सके। (२) जब तक बरमा की संविधान परिषद् अपना कार्य समाप्त न कर ले, तब तक के बाल के लिये एक सामयिक सरकार का संगठन किया जावे। (३) इस काल के लिये बरमा में एक व्यवस्थापिका सभा हो, जिसके सदस्यों की संख्या १८० हो। संविधान परिषद के जो सदस्य निर्वाचित हों, उन्हीं में से १८० को सरकार इस सामयिक व्यवस्थापिका सभा के सदस्य रूप से गनोनीत कर ले। (४) इस काल में बरमा को यह अधिकार हो, कि वह लण्डन में अपनी तरफ से एक हाई किमस्नर को नियत कर सके, जो बरमा के हितों का ध्यान रखे। (५) संयुक्त राज्य संघ में बरमा भी एक सबस्य के रूप में सम्मिलित हो, और ब्रिटिश सरकार इस बात का प्रयत्न वारे, कि बरमा को संयुक्त राज्यसंघ का सदस्य बना लिया जाय । (६) बुरमा को यह अधिकार हो, कि वह अन्य देशों के साथ अपना सीया राजनीतिक संबन्ध स्थापित कर सके ।

बरमा के सब राजनीतिक नेता लण्डन कान्फरेन्स के इन निर्णयों से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे, कि बरमा में तुरन्त पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो, और सामयिक रूप से भी बरमा का बिटन के साथ कोई सम्बन्ध न रहे। पर आग सान और उसके अनुयायी लण्डन कान्फरेन्स के इन निर्णयों से संतुष्ट थे और उनका स्याण था, कि बरमा की अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की अपन करने का यह सुवणीत अवसर है इसके अनुसार एप्रिल, १९४७ में बरमा की गंविकान परिषद् का विधीनन किया गया, जिसमें एण्टि-फैसिस्ट पीपत्स फीडम लीग के उन्मीदवार बहुत वही राज्या में निर्वाचित हुए। २४ सितम्बर, १९४७ को बरमा का नया जानन विधान बन कर नैयार हो गया और १७ अक्टूबर, १९४७ को बरमा और बिटेन में परस्पर मिल हो गई, जिसमें ब्रिटेन ने बरमा की संविधान परिषद् द्वारा नैयार किये गये भासन विधान को स्वीकृत कर लिया। बरमा की संविधान परिषद् ने यह निर्णय किया, कि बरमा का ब्रिटिश कामनवेल्थ के साथ कोई सम्बन्ध न रहे और बह पूर्ण- रूप स्वतन्त्र हो। जनवरी, १९४८ से यह नया सागन विधान वरमा में लागू हो गया और तब से बरमा की स्थित ब्रिटिश कामनवेल्थ के साथ कोई सम्बन्ध न एक स्वतन्त्र राज्य के सब्द्रा है।

बरमा के के नये शासन विधान की मुख्य यातें निष्नांशिक्त हैं—(१) राष्ट्र पति का निर्वाचन पांच सास्त्र के लिये किया जाय। पांख्यामेन्द्र की वीनों सभाओं के सदस्य एम स्थान पर एकत्र होगर बैलट हारा राष्ट्रपति का निर्वाचन करें। (२) पांख्यामेन्द्र में दो सभायें हों, प्रतिनिधिषणमा और राष्ट्रसभा । प्रतिनिधिं सभा के सब सबस्य जनता हारा निर्वाचित किये जायें। राष्ट्रसभा में बरगा की अल्य-संस्थान जातियों को प्रतिनिधित्व देने की विशेषस्पर्य विश्वस्था की जाये। इस सभा के सबस्यों की संख्या १२/५ हो, जिनमें से ७२ अल्यगंस्यव जातियों के प्रतिनिधि हों। (३) मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधित्मभा के प्रति उत्तरस्थाये हों।

संविधान परिषद् ने अपना कार्य अभी समाप्त नहीं किया था, कि १९ जुलाई, १९४७ को अंग सान और उसके साथी छ: मन्त्रियों (जो कि सामित्र रूप से स्थापित सासन समा के सदस्य थे) की हत्या कर दी गई। इस हत्या के नेता थी यू सो थे, जो कि आंग सान के दल के मुख्य विरोधी थे। पर उस हत्याओं से एण्डिफेसिस्ट पीपत्स फीडम लीग की बावित कम नहीं हुई। आंग सान के जाय थी थाकिन नू ने बरमा के प्रधान मन्त्री का कार्य संभाजा और मंदियान परिषट्ने कार्य नो जारी रखा।

जनवरी, १९४८ से बरमा पूर्णस्य में स्थतन्त्र राज्य है। पर उसे अनेक विक् समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है—(१) दक्षिण-पूर्वी एकिया के अन्य देखें के समान बरमा में भी कम्युनिस्ट दल विद्यमान है, जो बरमा के तथे भासनविधात से संतुष्ट नहीं है। यह दल बरमा में समाजवादी व्यवस्था स्थापित नारने के लिये प्रयत्नशील है। (२) बरमा में अनेक इस प्रकार की अल्पसंख्यक जातियां विद्य- मान हैं, जो बरमा से पृथक् होकार अपना पृथक् स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाहती हैं। इनमें करन लोग मुख्य हैं। इन अल्प संख्यक जातियों के लोग अपना पृथक् राज्य स्थापित करने के लिये बरमी सरकार के भाध संघर्ष में तत्पर है।

(५) इन्डोनीसिया

महायुद्ध (१९३९-४५) के प्रारम्भ तक के इन्डोमीनिया के इतिहास पर हम पिछले एना अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। यह देश हालैण्ड के अधीन था, पर जनता में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये उत्कट अभिलाणा विकसित हो रही थी । मई, १९४० में यूरोप के रणक्षेत्र में हालैण्ड जर्मनी द्वारा परास्त कर दिया गया था और वहां की रानी विल्हिल्मना अपनी सरकार के साथ हालैण्ड छोड़कर बिटेन चली आई यी । इस समय तक जापान महायुक्त में सम्मिखित नहीं हुआ था, फिर भी हालैण्ड की पराजय का उसके साम्राज्य पर प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता था। इन्डो-नीसिया में स्वाधीनता का आन्दोलन अब अधिक प्रबल हो गयाथा। इस समय चाहिये तो यह था, कि हालैण्ड इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी देशभक्तों के साथ सहानुभूति प्रगट करता और उसकी स्थाधीनता की आयांक्षा को पूर्ण कर उसकी सहायता मिन-"राज्यों के लिये प्राप्त करता । पर हालैण्ड की साम्राज्यवादी सरकार (इन्डोनी-सियन उच सरफार) ने स्वाधीनता के आन्दोलन की कुचलने के लिये उग्र उपायों का अवलम्बन किया । पुलीस की शक्ति वढ़ा दी गई, अनेक देशभक्त नेताओं की गिरफ्तार विध्या गया और अनेवा ऐसे कानुन जारी किये गये, जिनका उद्देश्य जनता को भाषण करने व अन्य प्रकार से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त वारने से रोयाना था। पर यह सम्भय नहीं था, नि इन्डोनीसिया की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की कुचला जा सकता। अन्ततोगत्वा, उच संग्कार ने यह आवश्यव समझा, कि इन्हों-नीरिया पी जनना को संतुष्ट रखने के लिये शासन में सुधार मिये जायें। इस उद्देश्य से एक यामीयन की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष श्री विस्मान थे। बिरमान समीशन ने जनता के प्रतिनिधियों की गवाही छेकर इस बात पर विचार करना प्रारम्भ किया, कि इन्डोनीसिया के कारान में कीन से ऐसे सुघार किये जा सकते हैं, जिनसे जनता की राष्ट्रीय आयांक्षाओं को संतुष्ट विया जा सके ।

पर इन्होनीसिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये आन्दोलन इतना प्रवल हो चुका था, कि विस्मान वागीशन की नियुक्ति द्वारा उसे संतुष्ट नहीं विया जा सकता था। इस बीच में यूरोप के रणकंत्र में जर्मनी और इटली निरन्तर विजयी हो रहे थे। फ्रांस, बेल्जियम आदि देशों पर जर्मनी का कब्जा हो गया था, और ब्रिटेन, पर हवाई आत्रमण बहुत उस रूप धारण कर रहे थे। इस स्थिति में इन्डोनीसिया के देशगवत यह अनुभव करते थे, कि अपने देश से उच साम्राज्यवाद का अन्त करने वा यह मुवर्णीय अवसर है, और उन्हें इसका पूरी तरह से उपयोग करना चाहिये। दिसम्बर, १९४१ में जापान भी भिनराज्यों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया है जापान का दावा था, कि महायुद्ध में वह इस उद्देश्य में जामिल हुआ है, ताकि पूर्वी य दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद का अन्त कर इस क्षेत्र के सब देशों में स्वाधीन मरका से की स्थापना की जाय। इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी देश भक्तों को जापान से बहुत आशा थी। वे अनुभव करने थे, कि इच अधिपत्य के अन्त करने का कियातमक उपाय यही है, कि जापान की सेनायें इन्डोनीसिया पर आक्रमण कारें और उच सेनाओं को परास्त कर उनके देश को स्वतन्य करें। यही खारण है, कि जब जापानी सेनाओं ने फिलिप्पीन आदि देशों को थिजय किया, तो इन्डोनीसियन लोगों ने अत्यधिक उल्लास का अनुभव किया।

जापानी सेनायें विद्युत्पति से दक्षिण-पूर्वी एशिया में आगे बढ़ रही थीं। इस समय प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जापान का मुकाबळा कर सकते की शिवत किसी देश में नहीं थी। इन लोगों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे जापानी आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा कर सकते। जाया, सुमात्रा, बोकियो, बाली आदि जो विविध द्वीप हालैण्ड के अधीन थे, उन पर एक एक करके हमला किया गया। जल कीर वायु के मागों से जापानी सेनायें इन द्वीपों में प्रविष्ट हो गई, और मार्च १९४२ तक सम्पूर्ण इन्डोनीसिया एच आधिपत्य से मुनत होकर जापानी सेनाओं के कब्जे में आ गया। दिक्षण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समाग इन्डोनीसिया में भी शुक्र में जापान ने अपना सैनिक शासन स्थापित किया, लाकि देश में शान्ति और क्यवस्था काथम रह सके।

पर जापान स्थिररूप से इन्डोनीरिया को अपनी अधीनता में नहीं रखना चाहता था। इस देश के सर्वप्रधान राष्ट्रपति नेता डा० सुकर्ण थे। बी झ ही उनके नेतृस्व में इन्डोनीसिया की स्वतन्त्र राष्ट्रीय रारकार की स्थापना की गई। जिस समय अगस्त, १९४५ में महायुद्ध में परास्त होवार जापान ने मित्रराज्यों के सम्मृत आत्म-समर्थण विया, तब डा० सुकर्ण के नेतृस्व में इन्डोनीसिया में एवं स्वतन्त्र रिपिक्लिकन राज्य की स्थापना हो नुकी थी।

महायुद्ध में परास्त होकर भी हालैण्ड के राजनीतिक नेताओं को यह सुबुद्धि नहीं आई थी, कि अब इन्डोनीसिया को अपनी अधीनता में रख राक्षना सम्भव नहीं हैं। ६ दिसम्बर, १९४२ को (जब कि इन्डोनीसिया हालैण्ड की अधीनता से मुक्त हो चुका था, और वहां स्वतन्त्र रिपब्लिय की स्थापना की जा रही थी) बिटेन में स्थित डच रारकार की और से एक उद्घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें उस नीति

का प्रतिपादन किया गया, जिसका अनुसरण हालैण्ड महायुद्ध की समाप्ति पर इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में करेगा। इस उद्घोषणा में यह कहा गया था, कि महायुद्ध की समाप्ति पर डच साम्राज्य की नई व्यवस्था करने के लिये एक कान्फरेन्स
का आयोजन किया जायगा। इस कान्फरेन्स में इस बात पर विचार होगा, कि
हालैण्ड और उसके साम्राज्य के देशों के शासन का क्या रूप हो। उच सरकार का
विचार यह था, कि डच साम्राज्य को एक कामनवेल्थ के रूप में परिवर्तित कर दिया
जावे, जिसके अन्तर्गत सब राज्य अपने आन्तरिक मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र हों।
इच कामनवेल्थ की इस कल्पना के अनुसार इन्डोनीसिया को अपने आन्तरिक शासन
में तो स्वतन्त्रता मिल जाती थी, पर अब इन्डोनीसिया को अपने बन्तरिक शासन
में तो स्वतन्त्रता मिल जाती थी, पर अब इन्डोनीसिया हो चुकी थी, उसके शासन
विचान का निर्माण हो गया था और नई रिपब्लिकन सरकार ने देश के शासनकार्य
को भलीभांति संभाल लिया था।

महायुद्ध में जापान की पराजय होने के बाद इन्डोनीसिया पर कब्जा करने का कार्य ब्रिटिश रोनाओं के सुपूर्व किया गया । मित्र राज्यों की ओर से दक्षिण-पूर्वी **'**शिया में जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिये 'दक्षिण-पूर्वी एशिया कमान्ड' का मंगठन हुआ था, और इसी कमाण्ड की ओर से ब्रिटिश सेनाओं को यह कार्य स्पूर्द किया गया था, कि वे इन्डोनीसिया से जापानी सेनाओं को परास्तकर इस देशपर अपना सैनिया आधिपत्य स्थापित करें। साथ ही, यह व्यवस्था भी की गई थी, कि इन्डोनीसिया के जो द्वीप मित्र सेनाओं के कब्जें में आते जावें, उन्हें पूनः इच सरकार के शारान में दे दिया जाय। इसके लिये हालैण्ड की ओर से 'नीदरलैण्ड्स इन्डीज सिविल एड्मिनिस्ट्रेशन' नामक संगठन का निर्माण किया गया था । इन्डोनीसिया के जो जो द्वीप मित्रराज्यों के आधिपत्य में आते जाते थे. उस पर इस डच संस्था का शासन स्थापित कर दिया जाता था । पर जावा, मदुरा और सुमात्रा द्वीपों पर इन्डो-नीसियन रिपब्लिक का शारान सुव्यवस्थित रूप से कायम था । यह हम पहले लिख चुके हैं, कि इन्डोनीसिया के कुल निवासियों का दो तिहाई के लगभग भाग जावा और मदूरा के द्वीपों में निवास करता है। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि जनसंख्या की दृष्टि से ६६ प्रतिशत से भी अधिक इन्डोनीसियन लोग डा० सुकर्ण की रिपब्लिकन सर्कार के शासन में थे। मित्रराज्यों की तरफ से इन्डोनीसिया पर सैनिक आधिपत्य स्थापित करने का कार्य ब्रिटिश सेनाओं के सुपूर्द था। जावा, मदुरा और सुमात्रा में जो बिटिश सेनायें आईं, उन्होंने जापानी अधिकारियों, सैनिकों और नागरिकों को तो अपने कब्जे में ले लिया, पर उन्होंने यह उचित

नहीं समाप्ता कि इन हीपों भें स्थापित एन्डोनीसियन रिपिटियन संस्कार का प्रतिरोध करें। जिटिश सेनाओं की यह नीति वस्तुतः बुद्धिमत्तापूर्ण थी। इन्डोनीसियन लोगों में राष्ट्रीय स्वापीनता की भाषता एतने प्रथल रूप में विकसित हो चुकी थी, कि वे किमी भी दशा में अपनी स्वतन्त्रता की लोगों ले लिये उदात नहीं थे। यदि बिटिश सेना डा॰ मुक्कण की रिपिटियन संस्कार का प्रतिरोध करने का प्रयत्न करती, तो उसे न केमल एन्डोनीसियन सेना का अपितु उस देश की जनता का भी कहा मुकावला करना पड़ता। इस प्रकार १९४६ के मध्य में इन्डोनीसिया की राजनीतिक स्थित यह थी, कि जादा, मनुरा और गुमात्रा हीं में स्वतन्त्र रिपिटिक की मना थी, शो किसी भी प्रकार इन लोगों थे आविपत्य को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं थी। अन्य हीपों पर नीवरलेण्ड एन्डीज विविष्ठ एडिमिनिस्ट्रं शन का शासन था, और इम संस्थान अपने अधिकृत प्रदेशोंगर १९४२ से पूर्व जिस लंग का इन शासन बिद्यमान था, उसी प्रकार का शासन फिर से स्थापित कर दिया था।

सम्पूर्ण इन्होंनीसिया पर हालैण्ड पा बासन दो ही प्रकार से स्थापित हो सकता था। इस सेनायें युद्ध में इन्होंनीसियन रिपब्लिक को परास्त करने उस तारा अधिकत प्रदेशों को अपनी अधीनना में लाने का प्रयत्न कर सकती थीं, या डा॰ सुम्हें आदि रिपब्लिक नेताओं से समझौता करके इस गरकार एक ऐसा मार्ग निकाल सकती थीं, जिसम इन्होंनीसिया की स्वतन्त्रता भी कामम रहे और इस देश पर हालैण्ड का आधिपत्य भी बना रहे। इस नेताओं ने इस दोनों उपायों का स्वयोग वियो । इस सेनायें बहुत बड़ी संख्या में इस्होंनीसिया भेज दी गई। महां जाकर उन्होंने रिपब्लिक नेनाओं के साथ यद्ध प्रारम्भ किया। पर इन्होंनीसिया की सेनायें भी इस समय निर्वल नहीं थीं। उनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भाषा कहि कहि थीं और जापान जो बहुन सी युद्ध सामग्री इस दीपों में छोड़ गया था, उसका उपयोग कर इन्होंनीसियन सेनाओं ने अपने को बहुत शिवस्ताली भी बना लिया था। उन्होंने इटकर इन सेनाओं का मुकाबला किया। पर युद्ध के साथ साथ हाउँण्ड की रारवार ने इन्होंनीसिया के रिपब्लिक नेवाओं के गाथ समझौते की बातचीन की भी जारी रखा।

डाव रारकार की डा० मुकर्ण और उनके साथियों से बहुत थिडेंग था । उस्कार खयाल था, कि इन नेताओं ने महायुद्ध के समय जापान के साथ सहयोग किया की अतः उनके विक्री भी प्रकार का समझीना करता उचित नहीं है। पर इन्डोनीसिया में डा० सुकर्ण का प्रभाव इनना अधिक था, कि डाव सरकार उनकी उनेका नहीं कर सकती थीं। कतः उसने समझौत की बातजीन का यह मार्ग निकाला, कि राष्ट्र- पति सुनर्ण (डा० सुनर्ण इन्डोनीसियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित थे) से बातचीत वार प्रधानमन्त्री सहरीर के साथ समझौत का प्रयत्न किया जाय । पर ऐसा वारना डच सरकार का दुराग्रह मात्र था, क्योंकि श्री सहरीर डा० सुनर्ण के ही अनुयायी थे। अन्त में डच सरकार को अपना हठ छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा। उसने यह स्वीकार किया, कि इन्डोनीसियन रिपब्लिक एक सुत्र्यवस्थित राज्य है, और उसके विविध राजपदाधिकारी एक सरकार के ही विविध अंग हैं। उनमें भेद बार सकता कियातमक दृष्टि से सम्भव नहीं है। नवम्बर, १९४६ में डच सरकार और इन्डोनीसियन रिपब्लिकन सरकार में सामयिक रूप से सन्धि हो गई। उन्होंने युद्ध को स्थित कर दिया और इस बात का प्रयत्न प्रारम्भ किया, कि परस्पर बातचीत द्वारा इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में एक ऐसी व्यवस्था का निर्धारण करें, ओ दोनों पक्षों को मान्य हो।

अब दोनों सरकारों में समझौते की बातचीत शरू हुई । २५ गार्च, १९४७ को वे एक समझौते पर पहुंचने में समर्थ हुईं। यह लिगजाति समझौते के नाम से इति हास में प्रसिद्ध है। इसके अनुसार यह निश्चय किया गया, कि (१) इन्डोनीसिया के जिन प्रदेशों पर डा॰ सुकार्ण की रिपब्लियन सरकार का कब्जा है, उन्हें स्वतन्त्र ैं इन्डोनीरिायन रिपब्लिक के रूप में स्वीकार किया जाय । जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, ये प्रदेश जाया, मदुरा और सुमात्रा के द्वीप थे। (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया में डच सरकार की अधीनता में जो अन्य प्रदेश हैं, उनको और स्वतन्त्र इन्डोनीसियन रिपव्लिय को साथ मिलाकर 'इन्डोनीसिया का स्वतन्त्र राज्यसंघ' बनाया जाय । इस संघराज्य के अन्तर्गत इन विविध राज्यों की अतने आन्तरिक मामलों में पूर्ण स्वाधीनता रहे । पर केन्द्रीय शासन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलों पर संघ सरकारका नियन्त्रण रहे। (३) इन्डोनीसियन संयुक्त राज्यसंघ और हालैण्ड को मिला कर एक 'युनियन' कायम किया जाय । विदेशी राजनीति, सेना आदि विषय इस युनियन के अधीन रहें। डा० सुकार्ण के नेतुस्व में विद्यमान रिपव्लिकन सरमार का शारान जावा, सुमात्रा और मदूरा पर वायम था । इन तीन द्वीपों के अतिरिक्त बोनियों का द्वीप ऐसा था, जिसे इस छिन्नजाति समझीते के अनुसार एक पृथक् रिपिन्लिक के रूप में परिणत करने का निश्चय किया गया था। जावा, मदुरा, मुमाना और वोनियों के अतिरिक्त जी अन्य बहत से छोटे बड़े द्वीप इन्डोनीसिया के अन्तर्गत थे, उन्हें गिलाकर एक तीसार निर्माण कर किर्माण करने भी व्यवस्था की गई थी, जिसे 'विशाल पूर्व' (ग्रेट :--:) नाम ें अस्तार । इस प्रकार इंग्डोनीसियन राज्यसंघ के कर्म की कि कि कि कि की गई थीं। यह स्पष्ट हैं, कि १०००। ि २५०। विकास के सम्बन्ध में

जो व्यवस्था की गई थी, उससे इस देश के राष्ट्रीय नेताओं को पूर्ण मन्तीप नहीं हो सकता था । इससे सम्पूर्ण इन्डोनीसिया डा० सुकर्ण की रिपब्लियन सरकार के अधीन नहीं होता था । बोनियो और ग्रेट ईस्ट में जो नई रिपब्लिकों कायम की गर्ही थीं, उन पर डच लोगों का प्रभाव व प्रभृत्व बहुत दुढ़ रहता था । इसके अतिरिक्त इन्डोनीसियन राज्यसंघ की परराष्ट्रनीति और रोना आदि पर हालैण्ड का प्रभाव पूर्ववत् कायम रहता था । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि अनेना राष्ट्रवादी देशभक्त लिङ्गजाति समझौते से असन्तोष अनुभव करें। परिणाम यह हुआ, कि मार्च, १९४७ में हालैण्ड और इन्डोनीसियन रिपब्लिक में पुनः संघर्ष प्रारम्भ हो गया ! डच सेनाओं ने अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा छा० स्कर्ण की सरकार को परास्त कर जावा, मद्रा ओर मुमाथा पर अवना आधिपत्य स्थापित करने का उद्योग प्रारम्भ कर दिया । भारत ने इसी समय संयुक्त राज्यसंघ (यनाइटेड नेंगन्स आर्गनिजेशन) के सम्मूल इन्डोनीसिया का मामला पेश विधा । उसका मध्यन था, कि जावा, मदूरा और सुमात्रा पर इच सेनाओं का आक्रमण सर्वणा अन-चित है, और डच सरकार इन्डोनीसियन लोगों पर भीर अत्याचार कर रही है। पर डच सरनार का कहना था, कि इन्डोनीसिया का मामला हालैण्ड के साम्राज्य की आन्तरिक समस्या है। वह जिस नीति का वहां अनुसरण कर रही है, उसके, उद्देश्य अपने साम्राज्य के अन्यतम देश में शान्ति और व्यवस्था गायम करना ही हैं। संयुक्त राज्य संघ की सूरक्षा परिषद् (सिक्योरिटी कींसिल) ने सारे प्रक्त पर विचार नारके यह आदेश जारी किया, कि दोनों तरफ से लड़ाई की तुरन्त बन्द नार दिया जाय । साथ ही, यह भी व्यवस्था की गई, कि इन्डोनीसिया की समस्या पर विचार करने के लिये एक कमेटी बनाई जाय, जिसके तीन सदस्य हों। इस कमेटीके एक सदस्य को हालैण्ड मनोनीत करे, दूसरेको इन्डोनीसियन रिपब्लिक मनोनीत करे और वे दोनों सदस्य मिलकर एक तीसरे सदस्य को नियक्त करें। इसके अनुसार हालैण्ड ने बेल्जियम को,इन्डोनीसियन रिपब्लिन ने आस्ट्रेलिया को और उन दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका को कमेटी का सदस्य चना। इस कमेटी ने सबरी पहले रुड़ाई को बन्द कराया और फिर यह व्यवस्था की, कि दोनों पक्ष यद को बन्द कर शान्ति स्थापित रखें। शान्ति स्थापित करके जनवरी, १९४८ में उस कोटी ने इन्डो-नीसिया की समस्या को स्थिर रूप से सुळझाने का उदांग शुरू किया । बेल्जियम् आस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने हालैण्ड और उन्डोनीशियन रिपब्लिक्ट्री मों जो समझौता कराया, उसका आधार निम्नलिखित बातें थीं--(१) इन्डो-नीसिया में एक राज्यसंघ कायम किया जाय। जावा, सुमात्रा और गदुरा (डा॰ सुकर्ण की सरकार द्वारा अधिकृत द्वीप) पृथक रूप से या संयुक्त रूप से इस राज्यसंघ

में सम्मिलित हों। (२') इन्डोनीसियन राज्यसंघ और हालैण्ड को मिलाकर एक यूनियन बनाया जाय, जो विदेशी राजनीति, सेना आदि पर नियन्त्रण रखे।

पर यह समझौता भी देर तक कायम नहीं रह सका। डच सरकार का प्रयत्न यह था, कि इन्डोनीसिया की विविध जातियों व प्रदेशों को डा० सूक्ण की रिपब्लि-कान सरकार के खिलाफ उभाड़ दे। वह इन्डोनीसियन लोगों में फट डालकर उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचल डालने के लिये प्रयत्नशील थी । इसी उद्देश्य से डच सरकार ने इन्डोनीसिया के अनेक प्रदेशों में ऐसी सरकारें कायम करने का उद्योग किया, जो हालैण्ड के पक्ष में और डा० सूकर्ण की रिपब्लिकन सरकार के विरोध में थीं । इससे इन्डोनीसिया की समस्या और भी अधिक जटिल हो गई । वहां न केवल डच सरकार के साथ युद्ध जारी रहा, अपितु विविध प्रदेशों में भी गह-कलह प्रारम्भ हो गया । इस स्थिति से लाभ उठाकर दिसम्बर, १९४८ में डच सेनाओं ने बाकायदा इन्डोनीसिया पर चढ़ाई कर दी। जोग जाकर्ता (इन्डोनीसिया की राजधानी) पर उन्होंने कब्जा कर लिया। रिपब्लिकन सरकार के अनेक नेता गिरफ्तार गर लिये गये। पर इससे भी इन्डोनीसिया के राष्ट्रवादी देशभक्तों ने अपने संघर्ष को बन्द नहीं किया। संसार के लोकमत की सहान्भृति इस समय ें इन्डोनीसिया के साथ थी । संयुक्त राज्यसंघ के सम्मुख यह मामला फिर उपस्थित हुआ । सूरक्षा परिषद् ने हालैण्ड को आदेश दिया, कि इन्डोनीसियन रिपब्लिक के नेताओं को रिहा कर दिया जाय और डच सरकार जो सैनिक कार्रवाई इन्डोनीसिया में कर रही है, उसे बन्द कर दे। पर हालैण्ड ने सुरक्षा परिषद् के इस आदेश की कोई परवाह नहीं की । इस पर संयक्त राज्यसंघ ने एक बार फिर इन्डोनीसिया की समस्या को हल गरने के लिये एक समझौता गमीशन की नियुक्ति की । हालैग्ड चाहता था, कि इस कमीशन की कोई परवाह न करे, और इन्डोनीसिया को अपनी अधीनता में लाने के लिये युद्ध को जारी रखें। पर उसके लिये यह सम्भव नहीं था, कि संसार के लोकमत की पूर्ण रूप से अवहेलना कर सके। अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अन्ततोगत्वा हालैण्ड इस बात के लिये विवश हुआ, कि गिरफ्तार हुए इन्डो-नीसियन नेताओं को रिहा कर दे और इस देश की समस्या का हल युद्ध द्वारा न कर समझौते द्वारा वार्ने का उद्योग करे । ३ अगस्त, १९४९ को डा० स्कर्ण की रिपब्लि-कृत सरकार और हालैण्ड में सामयिक रूप से समझौता हो गया, जिसके अनुसार ाह निश्चय किया गया कि (१) दोनों पक्ष पारस्परिक युद्ध को स्थगित कर दें, (२) इन्डोनीसियन नेताओं को रिहा कर दिया जाय, और (३) इन्डोनीसिया की समस्या को स्थिर रूप से हल करने के लिये हालैण्ड की राजधानी हेग में एक गोल-मेज परिषद् का आयोजन किया जाय।

इसी बीच में जनवरी, १९४९ में भारतीय सरकार ने दिल्ही में एक एजियन वास्फरेन्स का आयोजन किया, जिसमें एशिया के १७ देशों के प्रतिनिध एक इहुए । इन्डोनीसिया की समस्या पर इसमें विस्तार के साल विचार किया गया । इस वाल्फरेन्स ने जो सुधार पेश विध्ये, संयुक्त राज्यसंघ ने उन्हें कियात्मवा व उतित माना । इन्डोनीसिया की समस्या के हल होंगे में इस वात्फरेन्स ने बहुत महायता मिली।

इन्डोनीसिया के सम्बन्ध में जो गोलमेज परिषद् हेग में हुई, उसने २ नवम्बर, १९४९ को अपना कार्य समाप्त कर लिया । मोलमेज परिपद में जो निर्णय किये गयं , उनके अनुसार इन्डोनीक्षिया को एक राज्यसंघ के रूप में परिपालित किया गया, जिसमें सबसे प्रधान स्थान डा० सुवर्ण के नेतृत्त्व में स्थापित रिपाविल्या की पिया गया । इस रिपब्लिक की अधीनता में पूर्वी सुगात्रा और ग्रेट देस्ट के हीगों के अलि-रिक्त अन्य राव इन्डोनीसियन प्रदेशों को ये दिया गया । इस गुविरत्व इन्डोनीशियन रिपब्लिय को यह अधियगर दिया गया, कि वह अपने शासन विधान का स्वयं निर्माण कार सके और इसके ठिये एक संविधान परिषद का निर्माचन वास करे। पर हेश काल्फरेन्स में जिस प्रक्त पर विशेषरूप से निर्णय किया जाना था, यह उन्होंनीसियन संघ और हालैण्ड के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में था । इस महल्कुणं भागके के विषय में जो निर्णय हेंग लान्फरेन्स द्वारा वियो गये, वे विस्विधित्वत वे(१) हार्छण्ड और इन्डोनीकिया, दोनों राज्यों की स्थित सम्पूर्ण-प्रभूतक मध्यक राज्यो के सदश हो। (२) ये दोनों सम्पूर्ण-प्रमुच्य-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य रचेन्छापुर्वतः एक पुनियत का निर्माण करें, जिसमें बीकों राज्यों की स्थिति समान मानी जाय । (३) यह युनियन परराष्ट्र नीति और आधिक मामली के गम्बला में उपयान अति-कार रखें और युनियन में सम्मिलित योगों राज्य विदेशी राजगीति और अधिवत उसति के लिये परलार राहयोग में कार्य करें । (४) हालैण्ड और १०वंभी(नेवा बोनों राज्यों का जालन निवान छोकतन्त्रवाद पर आधिन हो 🖯 (५) इलोनीविहार तम जो राष्ट्रीय मध्य है, उसे अया करते की जिम्मेवारी इन्होनीसिवन सर्वाप पर रहे। (६) बोनों राज्यों में जिस प्रश्न पर विवाद हो, उसका निर्णय प्रज्नाविणेय गडति द्वारा भिया नाय । (७) यूनियन का अप्यक्ष सामाजी जुलियाना च उसके वंशज रहें।

हेग गोलमेज नान्फरेन्स के इन निर्णयों को दोनों पक्षों ने स्वीकार निष्या। उनके अनुसार जहां इन्डोनीसिया का हालैण्ड के साथ सम्बन्ध नायम रहा, वहां राष्ट्रीय स्वाधीनता की उसकी आवांका भी पूर्ण हो गई। पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान इन्डोनीसिया में भी अभी अनेक समस्यायें विद्यमान हैं, जिनमें सबसे

अमुरा कम्युनिस्टों की है। इन्छोनीसिया में भी कम्युनिस्ट दल निरन्तर जोर पकड़ बुहा है।

(६) फिलिप्पीन द्वीपसमूह

फिल्मिन की नम्मह पर निस प्रकार संयुक्त राज्य अंगरिका का प्रभुत्त्व स्थापित हुआ, और फिल्मिन लोगों की राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना से विवश होकर
निस प्रकार अमेरिका की सरकार इस दीप समूह में आंशिक स्वराज्य स्थापित करने
के लिये उसन हुई, इसना उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। १९४२ के प्रारम्भ में जब
जापान ने इस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो वहां वैध शासन विद्यमान था। मानुआल कोजोन फिल्मिन के राष्ट्रपत्ति थे और थी ओसमेना उपराष्ट्रपति। फिल्मिन की पालियामेन्ट (इसे अमेरिकान सैली के अ सार कांग्रेस
कहा जाता था) में यो सभायें थी, सीनेट और प्रतिनिधिसभा। फिल्मिन की यह
लोगनन्य संस्तार आधिन क्या स स्वतन्त्र होती हुई भी अमेरिका की अधीनता में
भी और फिल्मिन वंगभनत इससे सर्वोप अनुभव नहीं यरते थे। जापानी सेनाओं के
कियाम किल्मीन वंगभनत इससे सर्वोप अनुभव नहीं यरते थे। जापानी सेनाओं के
कियाम किल्मीन से चुले गये, अपितु राष्ट्रपति क्वेजोन और उपराष्ट्रपति ओसमेना
ने भी अभेरिका जावर आध्य लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रवासी फिल्मिन
संस्तार की सना की कायम रखा।

पर फिल्मिन में ऐसे देशभवतों भी समीनहीं थी, जो जापानी विजय को अपनी साम्हीय स्थापितता के लिये सुवर्णीय अवसर समझते थे। उनका खयाल था, कि अमिरिका की पराजय से उन्हें स्थापीन होंग का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका शिक्षाित उनकों करना साहिये। थी लिए इनके नेता थे। उनके पेतृत्य में स्थापीन फिल्मिन सरवार का संगठन किया गया। एक्विनों, ओसिआस्, बर्गाम्, बंगम्य वादि अनेक गेताओं ने इस सरवार का साथ दिया। पुराने समय की फिल्मिन वायेश के बर्ग्यक्त सारम इस सरवार का साथ दिया। पुराने समय की फिल्मिन वायेश के बर्ग्यक्त साथ सहयोग करने की उनत हुए। श्री लिए स्वापीन फिल्मिन रिपब्लिक के राष्ट्र-पित कियीनत हुए और श्री लिए की सरवार जापान के साथ सहयोग करने में श्री अपने वेश का दिव समझने लगी।

पर णिलिस्पीन में एक ऐसा वल भी विद्यमान था, जो जापान के साथ सहसीम को अन्तित समक्षताथा । यह वल 'हुक बली हव' (जनता की सेना) कहाताथा । इस बल के लोग जहां जापान के किरोनों थे, बटो साथ टी अने स्किन अविषय के भी विद्यह थे। श्री लॉरेल इस्तर सामित सन्तार की ये उन्त व समान तमें की सर- नगर समझते थे और फिलिप्पीन द्वीप समूह में एक ऐसे शासन की स्थापना के लिये उत्सुत थे, जो वस्तुतः जनता द्वारा संचालित हो, और जिसमें जनता को अपरी आधिय उन्नति का अवसर प्राप्त हो। इस सगय संसार के प्रायः सभी देशों में ऐसे दल विद्यमान थे, जिनका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ था, जो केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता को पर्याप्त नहीं समझते थे, अपितु ऐसी सामाजिक व्यवस्था के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण जनता को आधिय उन्नति के लिये उपयुक्त अवसर प्राप्त होता हो। इमलिये हुक बली हप दल को बाद में कम्युनिस्ट घोषित किया गया, और अमेरिकन लोगों ने उसका उग्रक्ष से विरोध किया। क्योंकि महायुद्ध (१९३४-४५) में जापान फैसिस्ट शक्तियों के पक्ष में था, और जर्मनी समाजवादी क्सकी शक्ति व सत्ताको नष्ट करनेके लिये जी जातमे कोशिश वर रहा था, अतः हुक बली हप दल के लोग फिलिप्पीन में श्री लॉरेल की रिपब्लिक सरकार के विरुद्ध संघर्ष में तत्वर थे, और उनका प्रयत्व यह था, कि अपने देश को जापान के प्रभाव व प्रभुत्व से मुक्त कर एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाय, जो न नेवल राज्ये अर्थों में पूर्णतया स्वाधीन हो, पर साथ ही देश में समाजवादी व्यवस्था को कायग करने के लिये भी प्रयत्व ही। प्रस्ता की लिये भी प्रयत्व ही। प्रसाय की की लिये भी प्रयत्व ही। हो की स्थापना की जाय, जो न नेवल राज्ये अर्थों में हिल्ये भी प्रयत्व ही। हो साथ ही देश में समाजवादी व्यवस्था को कायग करने के लिये भी प्रयत्व ही। हो साथ ही देश में समाजवादी व्यवस्था को कायग करने के लिये भी प्रयत्व ही। हो स्थापना की काय स्थापन का कायग

अक्टूबर, १९४४ में अभेरिक्षन सेनाओं ने फिलिप्पीन पर आक्रमण प्रारमभें कर दिया था, और जनवरी, १९४५ तक प्रायः सभी फिलिएपीन द्वीप अमेरिकन सेनाओं के कब्जे में आ गये थे । इस दशा में प्रवासी फिलिप्पीन गरकार अमेरिका से अपने देश की बापस आ गई। इस बीच में राष्ट्रपति क्वेंजीन की अंगरिया में मत्य हो गई थी, अतः श्री ओसमेना ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण तर लिया था। २७ फरवरी, १९४५ को राष्ट्रपति औरामेना अगने राजकर्मचारियों के साथ फिलि-प्यान चले आये और उन्होंने शासनसूत्र को अपने हाथों में ले लिया । पर श्री शीस-मेना की सरकार की सत्ता अमेरियान सेनाओं की शक्ति पर आशित थी और उन्होंने ही उसे फिलिज्पीन के शासन का कार्य सुपूर्व किया था । महायह के कारण फिलि-प्पीन द्वीपसमूह का आधिक जीवन बिलकुल अस्त-व्यस्त ही गया था। १९४२ के श्रूक में उसपर जापान ने आक्रमण किया था और केवल ढाई साल बाद अमेरिकन सेनाओं ने इस देश में घोर युद्ध करके इस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। जापान को फिलिप्पीन से कोई होप नहीं था । उसने इस देश पर केवल इसलिए आक्रमण किया था, क्योंकि इस पर अमेरिका का प्रभत्त्व विद्यमान था और जापाके पुर्वी एशिया से पारचात्य साम्राज्यवाद का अन्त करना चाहता था । फिल्पिन लोग अनुभव करते थे, कि उन्हें युद्ध के कारण जो क्षति उठानी पड़ी ही और उनका आर्थिक जीवन जिस बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है, उसके लिये अमे-

रिया ही उत्तरकायी है और उसीना यह कर्तव्य है, कि आधिक पुनिर्माणमें उनकी पहायता करें। जिस समय (१९४१ तक) फिल्पिन पर अमेरिका का शासन मा, उसका आधिक जीवन पूर्णतया अमेरिका पर आधिन था। फिल्पिन हीप राम्हरों जो माल विदेशों में विकने के लिये जाता था, उसका ९५ प्रतिशत अमेरिका जाता था। वस्तुतः अमेरिका ने फिल्पिन की आधिक उत्पत्ति को इस ढंग से नियनित किया हुआ था, कि वह वहां से कच्चे माल को खरीदकर उसके बदले में अपने तैयार व्यावसायिक गाल को वहां बेच सके। इसी कारण फिल्पिन में कल-कारकानों और व्यवसायिक गाल को वहां बेच सके। इसी कारण फिल्पिन अपनी आवश्यकता की राज वस्तुआं को स्वयं उत्पन्न नहीं करना था। सब प्रकार के तैयार गाल के लिये वह अमेरिका पर आधित था। यही कारण है, कि जापान की क्विय के बाद जब फिल्पिन का अमेरिका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध नष्ट हो गया, तब फिल्पिन लोगों को बहुत अधिक आधिक कह का सामना करना पड़ा। महायुद्ध के रामय फिल्पिन लोगों को बहुत अधिक आधिक कह प्रवर्ध से अनुभव करने लगे थे, कि उन्हें आधिक वृद्धि से बहुत कुछ आत्मिनभेर होना चाहिये।

राष्ट्रगति ओसमेना ने फिलिप्पीन के शासनसूत्र को संभाल कर यह प्रयत्न किया, कि वेश में शानित और ज्यवस्था को स्थापित करे और ओरिका के साथ उस प्रकार के सम्बन्ध को काथम करे, जिससे राष्ट्रवादी देशमक्तों को शिकायत का अवसर न मिले। ओसमेना के सम्मुख मुख्य समस्याय निम्नलिखित थीं—(१) श्री लाँरेल आदि जिन नेताओं ने महायुद्ध के समय प्रवासी फिलिप्पीन सरकार की खोशा कर स्वतन्त्र सरकार की स्थापना करके जापान के साथ सहयोग किया था, जनके साथ क्या बरताव किया जाय। यह समस्या बहुत विकट थी, क्योंकि पुरानी कांग्रेस के बहुसंख्यन सदस्य थी लाँरेल के साथ थे, और उन्होंने जापान के साथ पूर्णस्प में सहयोग करने में ही अपने देश का हित समझा था। (२) हुकवली-हण दल अब तक भी अपने प्रयत्न में संलग्न था। यह दल किसी भी रूप में अमेरिका के प्रमाद का स्वीवृत्त करने के लिये तैयार नहीं था, और समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों में आपहीं स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों में आपहीं स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों में आपहीं स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों में आपहीं स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों में आपहीं स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों में आपहीं स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों में आपहीं स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों में आपहीं स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों में स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था। (३) फिल्मिल लोगों से साथ ने साथ ने प्रयादी हो।

जब फिल्फिपित पर अमेरिकत सेनाओं ने जनवरी, १९४५ में बब्जा किया, तो श्री लोरेल और उनके साथी जापान चले गये थे। जापार है आत्य नगर्पण के बाद इन्हें गिरपतार गरके फिल्फिपीन लाया गया और यह १४०० किया गया, कि जापान के साथ सहयोग करने के अपराय में इन पर मुक्तदमा चलाया जाय। पर इनमें अनेक ऐसे प्रभावजाली व सम्पन्न व्यक्ति भी थे, जिन्हें दण्ड दे सकता सुगम नहीं था। १९४५ में जब राष्ट्रपति औरमेना ने फिलिप्पीन के शासनसूत्र को अपने हाथों में लिया, तो पुरानी कांग्रेस का भी पुन फड़ार किया गया। कांग्रेस के सपस्यों का नया निर्वाचन बीद्र नहीं िमया जा सकता था, अतः यही निज्यय हुआ, कि अभी पुरानी कांग्रेस को ही यायम रखा जाय। इस कांग्रेस के बहुसंख्यक मदस्य जागान के साथ सहयोंग कर चुके थे, अतः यह सम्भव नहीं था, कि इस दंग के कानून कांग्रेस द्वारा स्वीकृत करायें जा सकें, जिनके अनुमार श्री लॉरेल व उनके साथियों को दण्ड दिया जाय। साथ ही, जनता यह अनुभव करती थी, कि महायुद्ध की परिस्थितियों में श्री लॉरेल के स्वाधीन फिलिप्पीन सरकार काथम करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया था। इस दशा में राष्ट्रपति ओसमेना के लिये यह सम्भव नहीं हुआ, िम वह श्री लॉरेल व उसके साथियों के विरुद्ध मुक्तदमें नलाकर उन्हें दण्ड दे सकें।

१९४५ के बाद हुन बली हव दल फिलिप्पीन में निरुत्तर प्रमल होता गया। इस दल के प्रधान नेता लुई तार्ग और कास्तो अलेकान्द्रितो थे। फिलिप्पीन गरनगर ने यत्न धिया, कि इस समाजवादी दल को जित्त के प्रयोग द्वारा जुनल दिया जाय। पर इसमें सफलता न होने पर उसने यह यत्न विधा, कि इस दल ने साथ समजीता नर ले। गुल समय के लिये हुन बली हम दल और फिलिप्पीन नरणार में समजीता भी हो गया। पर यह सम्भव नहीं था, कि फिलिप्पीन की पृंजीवादी सरणार और कम्युनिस्टों में कोई समजीता देर तक कायम रह सके। १९४९ में उनमें फिर संघर्ष प्रारम्भ हो गया। विधाण-पूर्वी एजिया के अन्य देशों के समान फिलिप्पीन में भी हुन बली हम के कम में कम्युनिस्ट दल की सना है, जो अपने देश में वम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। फिलिप्पीन के कम्युनिस्ट क्वित से अन्ती शिवत का निरुत्तर विकास कर रहे हैं।

महायुद्ध की रामाप्ति पर अमेरिका ने फिल्मित को स्वाधीनता प्रयान कर दी है। पर इस स्वाधीनता से इस देश से अमेरिकन प्रभाव व प्रभुत्वका अन्त नहीं ही गया है। १९४६ में अमेरिकन कांग्रेस ने फिल्मिका मा व लिए एक ट्रेड एक्ट (ज्यापार कानून) स्वीकृत किया था, जिसके बारण इस देश पर अमेरिका का आधिक प्रभुद्ध पूर्ववत् वायम है। इस कानून के अनुसार अमेरिका नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है, कि वे फिल्मिन में जमीन जायदाद खरीद समें और वहां स्वेच्छापूर्वक व्यापा:, व्यवसाय आदि का संचालन कर समें। अमेरिका लोग फिल्मिन में मह अवसर व अधिकार रखते हैं, कि वे यहां काल-कारकान

खोल सकें और क्योंकि अमेरिकन लोगों के पास पूंजी की प्रचुरता है, अतः वे अ्भनी इस पूंजी के जोर पर फिलिप्पीन को अपने आर्थिक काळे में रखने में समर्थ हैं।

इतना ही नहीं, अमेरिया ने इस बात की भी जिम्मेवारी ली है, कि वह भविष्य में विदेशी आक्रमणों से फिलिप्पीन की रक्षा करेगा । इसके लिये उसने फिलिप्पीन में अनेक स्थानों पर अपने सैनिक केन्द्र कायम करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये सैनिक केन्द्र फिलिप्पीन में अमेरिकन सैनिक प्रभुत्त्व के आधार हैं। इनसे अमेरिका न केवल फिलिप्पीन द्वीप समूह को अपना वश्वति बनाये रख सकता है, अपितु साथ ही प्रशान्त महासागर के मुविस्तृत क्षेत्र में अपने प्रभुत्त्व व शक्ति को स्थिर रख सकता है।

बाईगवां अध्याय

जापान की नई व्यवस्था

(१) परास्त जापान के सम्बन्ध में मित्रराज्यों की नीति

महायुद्ध (१९३९-४५) में जापान के परास्त्र होने से पूर्व ही सिचराज्यों ने यह तय कर किया था, कि जापान के परास्त हो जान पर उसके सम्बन्ध में किस तीति का अनसरण किया जायमा । अनम उद्घीषणाओं द्वारा उस नीति की स्पष्ट कर देने का भी प्रकृत्व भी मित्र राज्यों की ओर से किया गया भा । फरवरी, १९४५ में बाल्या कात्फरेन्य के परिणामस्बम्ध्य यह घोषणा की गई थी, कि कोश्या को जापान की अधीतना में मक्त कराके स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जायगा आर दक्षिणी समालिन तथा उमके समीपवर्ती द्वाप रूम के मुपुदं कर विधे जावेंग; मञ्चरिया, पूर्वी चीन, हैनान और फाम्सा की जापान की अर्वातता से मनत करें दिया जायया: पीन में स्वतन्त्र लीनी गरकार की स्थापना होगी, ओरहीगान व फार्म हा द्वीपों को चीन के अन्तर्गत रखा जायगा । भज्यश्या भी चीन के अन्तर्गत होगा, पर जापान हारा मञ्ज बुओ राज्यकी स्थापना से पूर्व बहां स्थाको जो बिशेषा-विकार प्राप्त थे, वे उसे पूनः प्राप्त होंगं । महायुद्ध के दौरान में दक्षिण-पूर्वी एशिया के जिल विविध देशों को जापान ने अपने अधीन कर लिखा है, उस सबको उनके प्रभत्त्व से मृतत् कर जापान की सत्ता केवल उन हीपों एक सीमित कर धी जायगी, जो बस्तुनः उसके अंग हैं, और जो १८९४-९५ तक उसके अधिकार में थे। जलाई, १९४५ में पोट्सइम कान्फरेन्स द्वारा यह घोषित किया गया, कि जापान की मैनिया अभित की सदा के लिये नष्ट कर दिया जागा। और यह प्रमन्त किया जायगा, कि सभ्य मंसार के अन्य देशों के समान जागान में भी लोकतन्त्र आसन की रुयापना हो और वहां भी भाषण व विचार की रचनत्वना का विकास हो ध साथ ही, ऐसी व्यवस्था की जायपी, कि भविष्य में फिर कभी जापान सामा 🎎 विस्तार के लिये प्रयत्न न कर सके।

अगस्त, १९४५ में जब जापान ने जिना किसी धर्त के आत्मसमागण कर दिया, तो यह प्रश्त उत्पन्न हुआ, कि परास्त जापान के शामन की गमा व्यवस्था की जाय । यह प्रश्त अधिक विकट नहीं था, कारण कह कि जापान में गशाह की सरकार का सुव्यवस्थित जागत विद्यमान था । मित्रराज्यों ने जापान के विविध हीयों पर अभी सैनिक वृष्टि से कब्बा नहीं किया था और नहीं वहां कोई ऐसे दल थे, जो सम्राट् के शियन वा अन्त कर एक नई रास्कार की स्थापना के लिये प्रयत्नर्शाल हों । सित्र-राज्यों ने जापान में सम्राट् की शरकार की कायम उत्ता, पर जस पर नियन्त्रण राधने व सैनिक कुष्टि से जापान की सैन्यशिवत पर अनना कब्जा कायम करने की सारी जिल्लेकारी जनराज मैं कुआर्थर के हाथों में दे दी । जनराज मैंक आर्थर प्रशान्त महासागर व पूर्वी एशिया के क्षेत्र में पित्रराज्यों के प्रधान मैनापित थे और इस क्षेत्र की सब सैन्य जिन्त उन्हों के हाथों में केन्द्रित थी। अब जीपान के शासन को नियन्त्रित करने का कार्य भी उन्हों के सुपूर्व कर दिया गया।

जनरल मैक आर्थर का अपने कार्य में परामर्श देने के लिये मित्रराज्यों की एक को सिल नियत की गई, जिसे 'अलाइड कोंसिल ऑफ जापान' कहते थे। इस कोंसिल में निम्निलिखित राज्यों ने प्रतिनिधि सदम्बह्म में नियत किये गये—(१) अमेरिका, इसका प्रतिनिधि इस को सिल के प्रधान का कार्य भी करता था। (२) चीन (३) कस और (४) ब्रिटेन। यह समझा जाता था, कि ब्रिटेन का प्रतिनिधि अपने देश के अतिरिनत आर्ट्टेलिया, न्यूजीलैण्ड और भारत का भी प्रतिनिधित्त्व करता है। क्या था। इस प्रधान कार्यालय जापान की राजधानी तोकियों में स्थापित किया गया था। इस प्रमंग में यह ध्यान में रजना चाहिये, कि इस कोंसिल का बार्य केवल परामर्श देना था। सब बातों का अन्तिम निर्णय जनरल मैक आर्थर के ही हाथों में था। अलाइड कोंसिल ऑफ जापान का पहला अधिवेशन ५ एप्रिल, १९४६ को तोंकियों में हुआ था।

दम कोंसिल के अतिरियत एक अन्य समिति थी, जिसका निर्माण जापान सम्बन्धी विषयों पर विचार करने व नीति के निर्धारण के उद्देश में किया गया था। इसे फार ईस्टन कमीशन (सुदूर पूर्व कमीशन) कहते थे, और इसका प्रधान कार्या-लग्न संयुक्तराज्य अमेरिका की राजधानी वार्षिगटन में था। इसके सदस्य निम्न-लिलिल ग्यारह राज्यों के प्रतिनिधि होते थे—(१) अमेरिका, इसका प्रतिनिधि वामीशन के प्रधान का कार्य भी करता था। (२) चीन, (३) आस्ट्रेलिया, (४) कानाडा, (५) फारा, (६) भारत, (७) हालेंड, (८) न्यूजीलेंड, (९) फिलिप्पीन, (१०) कम, और (११) ब्रिटेन। प्रधानत कार्य के नाथ जिन राज्यों का सम्बन्ध करते हुए अधीनस्थ देशों (इन्डोनीसिया, बरमा, उन्डो-नायना आदि) की दृष्टिमें नहीं रखागया था। इस कमीशनका मुख्य वार्य यह था, वि इस बात का फैसला करे, कि जापान की अधीनता व प्रभाव से मुक्त

हुए देशों व द्वीपों के शासन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जाय और जापान में जो नई सरकार कायम हो, उसवा क्या स्वरूप हो और वह निस्त नीति का अनुसरण करें। यह निर्णय किया गया था, कि सुदूर पूर्व कमीशन अपने निर्णय बहुमत द्वाकी बारे, पर कोई निर्णय तब तक मान्य न हो, जब तक कि अमेरिका, नीन, रूस और ब्रिटेन उसके साथ सहमत न हों। इसका अभिप्राय यह था, कि इन राज्यों में से प्रत्येच को बमीशन के निर्णयों को बीटो कर देने वा अधिकार प्राप्त था। वर्षांकि जापान का शासन और व्यवस्था पूरी तरह जनरल मैं या आवेर के एकाधिकार में दे दी गई थी, अतः यह कमीशन पहले अपने निर्णयों को अमेरिकान सरकार के पास भेजता था और अमेरिकान सरकार उन्हें जनरल मैं या आवेर के पास पहुंचाती थी। कमीशन के निर्णयों के सम्बन्ध में भी अन्तिम अधिकार जनरल मैं या आवंर के पास पहुंचाती थी। कमीशन के निर्णयों के सम्बन्ध में भी अन्तिम अधिकार जनरल मैं या आवंर के हाथों में ही था। यद्यप जापान में सम्राट और उसकी सरकार की सना विद्यान थी, पर वे पूरी तरह से मैं का आवंर के नियन्त्रण में थे और मित्रराज्यों के इस प्रधान सेनापति ने यह मलीभांति स्पष्ट कर दिया था, वि अपनी किसी भी आजा को मनवान के लिये सैन्यशितत के प्रयोग में वह जरा भी संकोच नहीं करेगा।

जनरल मैंक आर्थर ने जापान में जिस नीति वा अनुसरण किया था, बह पंहस-इम कान्फरेन्स द्वारा निर्धारित की गई थीं । उसके मुख्य अंग निस्तिलिखित थे- क्रिं (१) जापान की सैन्यशक्ति को सर्वशा पंगु बना देना । (२) युद्ध के लिये जो जापानी लोग जिक्सेबार थे, और जिन्होंने युद्ध के अवसर पर बिबिय प्रकार के अपराध किये थे, उन्हें दण्ड देना । (३) जापान में लोकतन्त्र बासन स्थापित करना और (४) जापान के आर्थिक जीवन को इस प्रकार ने सञ्चालिन यहना, ताकि उसका उपयोग सैन्यशक्ति के लिये न किया जा सके ।

एन चारों बातों को पूर्ण करने के लिये जनरल मैं में आर्थर ने कोई भी कसर उठा नहीं रखी। जावान ने सुद्ध व सैनिक विभागों को अब यह कार्य सुपूर्व किया गया, नि वे अपनी सम्पूर्ण सैन्यवादित को नण्ड-भ्रष्ट कर में। इसी उद्देश में वाधित सैनिक सिवा की पद्धतियों को नण्ड किया गया। जो लाखों सैनिक जापान की सैना में थे, उन्हें बर्बास्त कर दिया गया। जापान के लाखों सैनिक प्रशान्त महासागर के विविध द्वीपों य विधिण-पूर्वी एणिया के विविध प्रदेशों में फैले हुए थे, उन सबको जापान वापस बुटा लिया गया और पहां उन्हें सैनिक नैया से पृथ्य कर दिया गया। जंगी जहाज, हवाई जहाज व युद्ध के अन्य सब भी की समान को या तो मित्रराज्यों को दे विया गया और या उन्हें नण्ड पर दिया गया। यह भी व्यवस्था की गई, िक जिस अधिकारों ने जापान की रोना को एनना उन्नत व सिन्दाराली बनाने का वार्य किया था, उन्हें विस्ती भी राजकीय पद पर न रहने

दिया जाय । जापानी लोग समझते थे, कि उनका सम्राट् दैवी अधिकार द्वारा देश पर शारान वारता है, वह साक्षात् देवता है, और जापानी लोग अन्य सब जातियों की अपेक्षा अधिमाऊंचे व उत्कृष्ट हैं। इन विचारों के खिलाफ जबर्दस्त प्रचार किया गया । स्वयं सम्राट् की ओर से एवा उद्घोपणा प्रकाशित कराई गई, जिसमें यह वाहा गया था, वि सम्राट् को दैवी मानना या देवता के रूप में उसकी पूजा करना मर्बथा अनुचित है । यह बात भी गलत है, कि जापानी लोग अन्य लोगों की अपेक्षा ऊँचे व उत्कृष्ट हैं। शिक्षणालयों में जो ऐसे अध्यापक थे, जो उग्र राष्ट्रीय विचार रखते थे, उन्हें अपने पदों से पृथक् कर दिया गया । ऐसी पाठ्य प्रस्तकों को कीसं से हटाया गया, जो जग राष्ट्रभवित का प्रतिपादन करती थीं। जन सब सभासमितियों को गैर-कान्नी घोषित किया गया, जिनका उद्देश्य जापान की राष्ट्रीय शक्ति को उन्नत करना था । इन सब बातों का उद्देश्य यही था, कि जापान सैनिक दिष्ट से भाक्तिहीन हो जाय और वहां के लोग फिर कभी पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर को अपने आधिपत्य में लाने का प्रयत्न न करें। जापान में कुछ लोग ऐसे भी थे, जिल्हें उनके उदार राजनीतिक विचारों के नारण पिछली सरकार ने कैद कर रका था। उन रावको अब रिहा कर विया गया। इन लोगों से जापान 'में लोक्सत्तावादी विचारों के प्रसार में बड़ी सहायता मिली।

मृद्ध के रागय जापान के जो प्रमुख राजनीतिक व सैनिक नेता थे, प्रायः उन सबको गिरातार किया गया और उन पर युद्ध के अपराधी (वार किथिनल) होने का आरोप लगाया गया। यद्यपि इस की यह मांग थी, कि सम्राह् को सर्वप्रधान आराधी करार कर उस पर भी मुकदमा चलाया जाय, पर जापान की जनता में अपने सम्राह् के प्रति जो असाधारण भिवत मावना थी, उसे दृष्टि में रखकर सम्राह् पर युद्ध के अपराध का अभियोग नहीं चलाया गया और उसकी सत्ता को अशुण्ण कप से कारम रखा गया। जनरल तोजो, माक्विस किदो, मत्सुओका, हीरानुमा आदि प्रमुख व्यक्तियों पर युद्ध के अपराध का मुकदमा चलाया गया और इसके लिये एक विशेष त्यायालय की रचना की गई। इन मुकदमों पर हम आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

(२) जापान की नई सरकार

पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एकिया में अपने प्रभाव व प्रभुत्व की स्थापना के लिये जापान प्रयत्नशील था। इसीलिये उसने मञ्जूरिया और चीन में युद्ध का प्रारम्भ किया था और इसीलिये दिसम्बर, १९४१ में उसने महायुद्ध में जर्मनी और इटली के पक्ष में और मित्रराज्यों के विषद्ध प्रवेश किया था। इस बाल में जापान में भी

जुनी प्रकार की फीलप्ट प्रवृत्ति प्रबन्ध हो रही थी, जैसी की मसोलिनी के नेतृत्व में इटली में और हिटलर के नेतत्व में अर्गर्ता में हुई थी। यद्यपि आपान में हिट रुप व गर्मान्डिमी के समान किसी एक जित्तवाली एकाविकारी (विकटेटर) कार प्राटमीय नहीं हुआथा, पर सम्राट्के प्रति की असाधारण श्रद्धां का भाव जापानी जनता में विद्यमान था, उनके कारण जापान के छोग अपने राजकीतिक भेद-भावी ब मनभेदों को भलावर सम्राट् के नेतृत्य में अवसी राष्ट्रीय असित की पृक्षि में तत्पर हो गये थे । उसी कारण जापान में 'इस्पीरियल रूल अक्षिम्डेन्स एसीशियेजन' (सम्राह के जासन के लिये सहायक भभा) नामक संस्था का निर्माण हुआ था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों के मनभेदों की उपेक्षा कर सम्राद् की शनित के विस्तार में यहायता पहुंचाना था। १९४१ में जापान के प्रधानमन्त्री के गद पर प्रिस कोनोये विद्यमान था । पर जापान के महायुद्ध में प्रवेश करने से कुछ रामय पूर्व ही उसका र क जनरल तोजों ने ले लिया था। तोजो जापान के सैक्कि यल का नेता था जार उसके प्रधानमन्त्री बन जाने के कारण जापात की सरकार में उन जोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, जो सैनिक शक्ति का उपयोग कर जापान के उत्कर्व के पक्षपानी थे। फैलिस्ट विवारधारा का अनुसरण कर जनरह तोजो व इर्ष्यारियल रूल अमिस्टेन्स एमीवियम इस तात के प्रयत्न में थे, कि जापान्? की जनता के विविध वर्ग राष्ट्रीय उन्नति व माझाज्य विस्तार में सहायक हो। इसीलियं कारणाणों में काम वारनेवाल गजदुरों का 'देशभवत भाववायिक सोसा-यदी' के रूप में संगठन निया गया था, ताकि मजदूर छोग अपनी शक्ति का उपयोग अपने बैतन यहबानेके लिये व अन्य स्विधाएं प्राप्त करने के लियं हड़तालें करने में न करके अधिकतम आधिक उत्पत्ति करने में करें। इसी प्रकार जापान के ध्यवसायों व गण-कारणानों का स्वामित्व जिन वह पंजीपनियों के हाथीं में था, ओर जिनको 'जैबल्तू' कहा जाता था. उनसे भी यह अधा की जाती थी, कि राष्ट्रीय उन्धर्न के कार्य में वे सरकार के साथ सहयोग करें।

जापान की पराजय के बाद यह स्वाभाविक था, कि मिनराज्य वहां में एम फैसिस्ट झासन गा अन्त करके छोकतंत्र सरकार की स्थापना का उद्योग भरे। इसके लिये उन्होंने जो कार्य किये, उन्हें संक्षिप्त रूप से उस प्रनार पर्णाणन किया जा सकता है——(१) १८८९ में सम्राट् में इजी ह्यारा जापान में जिस भागन व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, उसके अनुसार सब राजकीय हानित सम्रात् में केन्द्रित थी। सम्राट् न कैनेन्द्र झासन विधान का प्रधान अध्यक्ष था, अपितृ व्यवस्थापन और स्थाप विधान की प्रधान विधान की स्थाप वाद में जापान ने लोकतन्त्रयाद की और पर बढ़ाया था, पर अब तक भी सम्राट् को दवी द साक्षात्

येवता भारा जाता था । ३ मई, १९४७ से जापान में जिस नये शासन विवान का प्रारंभ किया गया, उसके अनुसार पालियामेन्ट को राजकीय गक्तिका प्रधान आधार त्रैतापा गया । अल्ल बनाने को सम्पूर्ण शक्ति पालियामेन्ट को दी गई ओर सम्राट् की स्थिति को 'ध्वजमान' बना दिया गया । नये शासन विवान में यह प्रतिपादित किया गया, कि यमाट् राज्य का व्यजमात्र है, और उसमें जनता की एकता सूचित होती है। राज्य की प्रभरवंशियत जनता में निहिन है, और सम्राट् अपने पद को 'जनतार्का इच्छा' द्वारा ही प्राप्त करता है। जापानका सम्राट जोपहलेदैवी अधि-कार द्वारा भारत करता था, अब उसकी सत्ता व स्थिति जनता की इच्छा पर आश्रित हो गई। (२) जापान में जिस पालियामेन्ट की न्यवस्था की गई, उसमें दो सभाएं रम्बी गर्ड, प्रतिनिधि समा आर परामर्श सभा। दोनों सभाओं के सम्पूर्ण सदस्य जनता द्वारा बोटों ने चने जावें, यह व्यवस्था की गई। पुराने जासन विधान के अनुमार पार्लियामेन्ट की दूसरी सभा में उच्च कूलों के कूलीन लोग या सम्राट् द्वारा मनोनीत लोग सदस्य हुआ वारते थे । पर १९४७ के नये वासन विधान द्वारा यह व्यवस्था की गई, कि पालियाभेन्ट की दूसरी सभा के सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित हों। (३) सम्राट् के राजप्रासाद के खर्च को भी पार्लियामेन्ट के ^कनियन्त्रण में लाया गया । राजकीय आब व्यव पर प्रतिनिधि सभा का नियन्त्रण पूर्ण रूप से स्थापित किया गया ओर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के हाउस ऑफ कामन्स के समान जापान की प्रतिनिधि सभा की शक्ति भी द्वितीय सभा की अपेक्षा अधिक रखी गई। (४) न्याम विभाग का स्वतंत्र रूप से संगठन किया गया और उसे शासक वर्ग के प्रभाव से मुक्त रखा गया । जापान में सुप्रीम कोर्ट का संगठन करके उसे यह अधिकार दिया गया, कि वह यह निर्णय कर सके, कि सरकार द्वारा प्रचारित कोई आदेश व आज्ञा और पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत कोई कानून संविधान (कोन्स्टि-ट्यूशन) के अनुकुछ है या नहीं। (५) शासन विधान में जनता के अधिकारों का विजय कृप से प्रतिपादन किया गया और यह व्यवस्था की गई, कि इन आघारमून अधिकारों का कोई भी राजकीय शक्ति उल्लंबन कर सके। (६) बोट के अधिकार को बहुत अधिक विस्तृत किया गया और स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया । इसमें सन्देह नहीं, कि ३ मई, १९४७ के इस नये शासन विवान द्वारा जापान लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गया । यद्यपि वहां ेरिसाट की सत्ता कायम रखी गई, पर इंगलैण्ड के राजा के रागान जागान का सम्राट् भी नये शासन विवान के कारण पूर्ण रूप से 'वैध' तान्त्र अभार' वन नया । पालिया-भेरत के नये स्वरूप के कारण जापान का न विन्यापन विभाग ब्रिटेन के व्यवस्थापन विभाग की अपेक्षा भी जांगल लोकतन्त्र हो गया और स्वतन्त्र न्याय विभाग के

कारण जापान में इस बात का अवसर जनता को प्राप्त हुआ, कि वह राजकीय स्वच्छन्दता से अपने आधारम्त अधिकारों की भलीगांति रक्षा पर सके।

जापान को लोकतन्त्रवाद के मार्ग पर अग्रसर करने के लिये एक और गहरूव-पुर्ण कदम इस समय बढ़ाया गया । यह था जापान के कासन को धर्म निर्पेक्ष (सिवयलर) बनाने के रूप में। हम पहले लिख चके हैं, कि जापान में पमाट की दैवी माना जाता था और पितरों की पूजा वहां के धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग थीं। पितपूजा के लिये वहां बहुत से मन्दिर विद्यमान थे और राज्य की ओर से जनता में पित्पूजा और परस्परागत प्रथाओं व धार्मिक विश्वासों के अनुसरण को प्रोत्साहित फिया जाता था । इसी उद्देश्य से पितृपूजा सम्बन्धी बहुत से मन्दिरों का खर्च राज्य की ओर से दिया जाता था। यद्यपि जापान के छोग बोज धर्म के अनयायी हैं, पर इस अत्यन्त प्राचीन धार्मिक मर्यादा का पालन धरां के तोब लोग भी करते थे। राज्य की ओर से धर्म के इस अक्ष को (जिसे 'जिन्ती' कहते थे) संरक्षण व प्रोत्साहन गिलता था, क्योंकि इसके कारण जनता में राधाह के प्रति भिक्त की भावना को दृढ़ वरने में सहायता मिळती थी। जब १९४७ के नये शासन विधान के अनुसार सम्राट् के 'वैती अधिकार' का विरोध किया गया और उसर्धान सत्ता व स्थिति को 'जनता की इच्छा' पर आश्रित प्रतिपादित गिया गया, तो शिली-बाद को वहत बड़ा आघात लगा । साथ ही, इस समय यह भी व्यवस्था की गई, कि शिन्तो को राजकीय आमदनी में से सहायता न दी जाय और पितपूजा सम्बन्धी मन्दिरों की रक्षा व पूजा के खर्च का राजकीय कोप के साथ कोई सम्बन्द न रहे । इसमें सन्देह नहीं, कि जापान के लिये यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व कान्ति-कारी परिवर्तन था।

अगस्त, १९४५ में जब जापान ने आत्मसमपंण किया, तो यहां की पालिया-मैन्ट का नमा चुनाव १९४६ की वसन्त ऋतु में कराया गया। अभी तम ज्या शासन विधान नहीं बना था। इस समय जापान के प्रधानमन्त्री के पद पर श्री शिदेहारा विराजमान थे, जो कि अत्यन्त उदार विधारों के व्यक्ति शे। वे जापान के सैनिक आधिपत्य के पक्षपाती नहीं थे और शान्तिया नीति का अनुसरण करने के पक्षपाती थे। जापान के आत्मसमपंण के बाद उन्हों को वहां कर प्रधानमन्त्री नियत किया गया था। १९४६ के प्रारम्भ में जब पुराने आत्म विधान के अनुसार पार्कियामेन्ट का नया चुनाव हो गया, तो श्री शिदेहारा ने त्याशपश्र दे दिया और श्री सोशीदा ने उनका स्थान ग्रहण किया। उन्हीं के समक्ष में नथे शासन विधान का निर्माण हुआ, और जापान में सच्चे अर्थी में लोकतन्त्र शासन का सूत्रपात किया गया । इस नये शासन विधान का निर्माण १९४६ के चुनाव द्वारा निर्वाचित पालियागेन्ट ने ही किया था ।

१९४७ की शरद्बह्तु में नये शासन विधान के अनुसार जापान की पालिया-मेन्ट का चुनाव किया गया। इस चुनाव के परिणामस्वरूप जहां जापान के पुराने राजनीतिक दलों (सैयुकाई और मिन्सेइतो) के बहुत से प्रतिनिधि पालियामेन्ट में निर्वाचित हुए, वहां साथ ही एक नई राजनीतिक पार्टी भी मैदान में आ गई, जिसे 'सामाजिक लोकतन्त्रवादी दल' (सोशल डेमोकेटिक पार्टी) कह सकते हैं। इस दल के प्रधान नेता श्री कातायामा थे, जो कि जापान के मजदूरों के एक लोक-प्रिय नेता थे। श्री कातायामा की सोशल डेमोकेटिक पार्टी में बहुत से ऐसे लोग भी शामिल थे, जो केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता व राजनीतिक अधिकारों को अपर्यान्त समझते थे। इनका विचार यह था, कि जहां सब लोगों को राजनीतिक दिन्द से समान होना चाहिये, वहां साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उन्हें समान होना चाहिये। ये लोग कम्युनिस्ट व समाजवादी विचारों के थे। इस प्रकार संसार के अन्य देशों के समान जापान में भी इस समय कम्युनिस्ट विचारधारा जोर पकड़ने लगी थी और इस विचारधारा के अनुयायी भी पालियामेन्ट में निर्वाचित रहुए थे।

१९४७ के चुनाव में पालियामेन्ट की प्रतिनिधिसभा में विविध वलों के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से थी—सोशल डेमोक्रेट पार्टी १४३, सैयुकाई (लियरल) वल १३३, मिन्सेइतो वल १२६ और ४६६ स्वतन्त्र व अन्य पार्टियों के उम्मीदवार । क्योंकि प्रतिनिधि सभा में सबसे अधिक सदस्य सोशल डेमोक्रेट पार्टी के थे, अतः उसके नेता श्री कातायामा ने प्रधान मन्त्री के पद को ग्रहण किया और उन्होंने निन्सेइतो वल व कतिपय अन्य छोटे दलों के सहयोग से अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया। पर क्योंकि उनके अपने दल के सदस्थों की संख्या प्रतिनिधिसभा में पर्याप्त नहीं थी, अतः उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे आर्थिक य सामाजिक क्षेत्र में अपने विचारों को किया में परिणत कर सकें। परिणाम यह कुता, कि फरवरी, १९४८ में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र वे दिया और मिन्सेइतो वल के नेता श्री अजीदा हितोशी ने प्रधान मन्त्री के पद की ग्रहण किया।

पर श्री अशीदा हितोशी के लिये भी मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सकता मुगग नहीं था। इस समय जापान के विविध राजनीतिक दल अपनी सत्ता के लिये पूजीपितियों व अन्य सम्पन्न लोगों की सहायता को बहुत अधिक महत्त्व देते थे। लोकतन्त्र शासन की गह निर्बलना होती हैं, कि पिथिय राजनीतिक दलों के नेवा अपनी अपनी शासन की गह निर्वलना होती हैं, कि पिथिय राजनीतिक दलों के नेवा अपनी अपनी शासन की लिये पूजीपितियों भी तहाबता के स्त्रीय पर निर्मार करने

.ळजल हो । महायक्ष से पहले जापान के अनेक राजनीतिक वल जागीरवारों आप पर्जाणीतयां के हाथों में गरण्तजामात्र थे आप उनकी भारत बैं तिला के जन्तकेत विविध सगढ़ परिवारों की सहायता पर आश्वित थी । महायुद्ध के दौरान में जापान की सरकार पर पर्जापनियों व जागीरदारी का प्रभाव कुछ कम ही गया था, वयोंकि इस काल के धन्तिमण्डल में सीचक चंताओं की प्रमुखता थी। जापान के आता-समपर्ण कर देने के बाद वहां बहु पूंजीपांत पांटवारों का महत्त्व आविक नहीं रह गया था, वर्षोंकि उनके अनय प्रमुख व्यक्तियों को युद्ध का अपराधा कताकर उनपर मुकदमे चलाये गये थे और जनरल मैक आर्थरकी यह नीति भी, कि जापाद में जैवित्सु की जिंकत को छिन्न-भिन्न कर दिया जाय। पर महायद के बाद जन जापान में आर्थिक जीवन का पूरः विकास प्रारम्भ हुआ, तो सन्पन्न लोगों की एक नई धोण विकासित होनी प्रारम्भ हुई, जिस्ती आगदती व समृद्धिका मन्य आधार सरकारी ठेके थे। अमेरिकन सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ण करने के क्टिये और जनरह गैक आर्थर के आदेशों के अनसार आधिक जीवन के विकास के लिये विभिन्न हेके सम्पन्न जापानी व्यक्तियों को प्रदान किये जाते थे और इस सरकारी ठेकों द्वारा इन ठेके शरों को असाबारण आगदनी थी। ये ठेकेवार उनित व अन-चित सब प्रकार के उपायों से अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करते थे। और इस्ट्रे प्रयत्न में राजगीतिक दलों के नेताओं को रिश्वल आदि द्वारा अपन साथ मिलागे रखते थे । इसी लिये अज़ीदा हिलोजी का मन्त्रिमण्डल देर लग फायम नहीं रह सका । उस पर रिज्यत आदि ग्रहण करने के अनेक अपराध लगाये गये और अवस्थर, १९४८ में उसने त्यागरत वे दिया । अब सैयुकाई दल के नेता श्री योगीया शिगेष्ट ने नथे मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । जनवरी, १९४९ में जापान की पालियामेल्ड का पुनः नियम्निन हुआ, इस में श्री योशीदा के दल के उत्मीदबार वर्ग तड़ी पंच्या में निर्वाचित हुए । प्रतिनिधि सभा में इस दल की बहुनंख्या प्राप्त हो गई जार उम कारण योशीदा के मन्त्रिमण्डल की स्थिति बहुत अधिक गुर्शक्षत है। गर्भ। असे श्री ्यांशीदा की अन्य दलों के सहयोग की विशेष आवश्यकता नहीं रही थी।

जापान के आत्मसमर्गण के बाद उसके शासत में भी महत्वपूर्ण पिष्वतंत इए और जिन विविध सरकारों ने उसका शासन किया, उनके उन्लेख के साथ साथ सह निर्दिष्ट कर देना भी आवश्यक हैं, कि यद्यपि इस समय जापान का भासन सम्राट् के नाम पर होना था और वहां जापानी मन्त्रिमण्डल विद्यमान थें, पर धारतम् क्रिक का वास्तविक सञ्चालन जनरल मैंक आर्थेर के हाशों में था। उसी के आदेश के अनुसार जापान में सब कार्य होने थे और जापानी सरकार में यह साहय नहीं था, कि वह उसके किसी आदेश की उपेक्षा कर सके।

(३) जापानी नेताओं पर मुकदमे

पोटसटम कान्फरेन्स में मित्रराज्यों के नेताओं ने यह भी निर्णय किया था, कि जर्मनी, इटली और जाणान के उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाय, जिन्होंने युद्ध के लिये प्रविषेपरूप से कार्य किया था। इस निर्णय के अनुसार परास्त राज्यों के ने ताओं पर जो अभियोग लगाये गये थे, उन्हें चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) यद्ध के लियं साजिश करना, (२) युद्ध के समय में ऐसे अपराध करना, जा अन्तराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हों, (३) शान्ति और व्यवस्था के खिलाफ अपराध करना ओर (४) मानव समाज और मनुष्यता के विरुद्ध अपराध करना । एन मुकदमों का निर्णय करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जापान के अभियुक्तों पर मकदमा चलाने के िय्ये जो न्यायालय संगठित हुआ था, उसका एक न्यायाबींग भारतीय भी था। उन सज्जन का नाम है, श्री राधा विनोद पाल। जापान के जिन नेताओं को इस नगायालय के सम्मूख अभियुक्त के रूप में पेश किया गया, उनमें जनरल तोजो (भृतपूर्व प्रधानमन्त्री), मृतसुओका (भृतपूर्व परशब्द मन्त्री), 🗂 जनरल की मुरा, श्री हीरोता, माक्किस किदो और श्री हीरानुमा जैसे प्रमुख व्यक्ति भी जागिल थे। इस अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिन जापानी नेताओं की फांसी के तक्ते पर छटकाया गया, उनकी संख्या सात थी। अन्य बहुत से बड़े जापानी सेनापतियों व राजनीतिज्ञों को आजन्म कारावास की सजा दी गई।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अन्यतम न्यायाधीश श्री राधा विनोद पाल ते अपने निर्णय में यह बात भलीभांति स्पष्ट करवी श्री, कि युद्ध के लिये केवल जापानी अभियुक्तों को उत्तरवाशी नहीं ठहराया जा सकता । उन्होंने जो कुछ भी किया, यह अपने देश के हित को दृष्टि में रखकर किया । उनका प्रधान अपराध यही हैं, कि वे एक परास्त देश के नेता हैं । श्री पाल अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अन्य न्यायाधीकों के निर्णय से सहमत नहीं थे । इसमें सन्देह नहीं, कि परास्त देशों के नेताओं पर मुकदमा चलाकर उन्हें दण्ड देना संसार के इतिहास में एक नई बात श्री । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नई परम्परा का प्रारम्भ हुआ । पराजित राज्यों के ववला लेने की भावना इस परम्परा में स्पष्टरूप से प्रकट होती हैं, और इसका अभिप्राय यही समझा आ का कार्या हैं. कि उपने सन् का मानदा गण्यों का प्रवत्त किया जाय । यदि महायुद्ध में विटेन और अमिरका पनारत होते, तो श्री विचल और राष्ट्रपति हजनेवट पर भी इति उनार के मुकद चलाव जा सकते ने । जिस

हंग के अभियोग जनरल तोजो व मत्युओका पर लगाये गये, ठीक उसी ढंग के अभियोग चिल्ल आदि ब्रिटिश राजनीतिजों पर भी लागू हो सकते थे। इस समय समार सार में असिहिल्णुता की प्रवृत्ति बहुत नढ़ गई है। विविध देशों में लोग अपने से विशेष रखने वाले राजनीतिक विचारों को सहन नहीं करना चाहते। अपनी विरोधी राजनीतिक पार्टी की सता को सहन न करना इस युग की राजनीति की एक विशेषता हो गई है। फ्रांस की सरकार ने मार्शल पेता पर इसीलिये मुकदमा चलाया था। पेता ने फ्रांस के सम्बन्ध में जिस नीतिको अपनाया था, उनकी सम्मितमें वह देश के हित के लिये ही थी। पर बाद में उन्हें देशहोही माना गया। यही प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पाई जाती है। तोजो, गोयरिंग आदि परास्त देशों के नेताओं पर मुकदमे चलाना इसी असहिल्णता का परिणाम था। संसार के लिये इस प्रवृत्ति को हितकार नहीं कहा जा सकता।

मित्रराज्य केवल जागान के बड़े नेताओं पर मुकदमे चलाकर व उन्हें दण्य देने की व्यवस्था करके ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि उन सब लोगों को रारकारी पदों व आधिक जीवन के महत्त्वपूर्ण पदों से पुथक कर दिया जाय, जिन्होंने महायुद्ध के समय मिश्रराज्यों के विषद्ध तत्परता प्रविधित की थी। १९४६ और १९४७ में अनेक ऐसे आर्डिनान्स जारी किये गये, जिनका उहेश्य इस प्रकार के राव व्यक्तियों को अपने पदों से पथक् कर देना था। जापान के व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र से जिन प्रमुख व्यक्तियों को छन आर्टिनान्सों हारा पवच्यत विया गया, उनकी संख्या २२०० से भी अधिम थी। उनका मुख्य अपराध मही था, कि महायद्ध के समय में इन्होंने अपने देश के लिये उत्साह के साथ कार्य किया था और अपने कल कारखानों व आर्थिक जीवन के सञ्चालन में अपने वर्तक्यों का समुचित रूप से पालन किया था । २२०० के लगभग इन बड़े आदिमयों के अति-रिक्त जिन साधारण लोगों को इन आर्डिनान्सों के अनुसार अपने अपने कार्य से पृथक् बार दिया गया था, उनकी संख्या १५,००,००० के लगभग थी। महायद्ध के समय में जो लोग विविध राजकीय पदों पर नियत थे, जो कल कारखानों में इन्जीतियर, शिल्पी व निशेषज्ञ आदि के रूप में कार्य कर रहे थे, या जो लोग जापान के आधिक जीवन को संभाले हुए थे, उनके वहुत बड़े भाग को इस अपराध पर अपने वार्य मे पृथक किया गया, कि उन्होंने युद्धकार्य में अपने 'अपराधी' नेताओं के साथ सहयोती किया था । मित्रराज्य और विशेषतया अमेरिका परास्त जागान के साथ बरताव बारते हुए कितनी अयुक्ति युक्त नीति का अनुसरण कर रहे थे, यह बात इसका स्पष्ट उदाहरण है।

(४) जापान के सम्बन्ध में नई नीति

अगस्त, १९४५ में जब जापान ने मित्रराज्यों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसके सम्बन्ध में मित्रराज्यों की यह नीति थी, कि उसे सैनिक और आधिक दृष्टि से इतना अधिक पंग् और निर्बल बना दिया जाय, कि वह भविष्य में फिर कभी अपने साम्राज्य विस्तार के लिये प्रयत्न न कर सके । इसीलिये जनरल मैक आर्थर ने यह व्यवस्था की थी, कि जापान के कल कारखानों में जो उत्कृष्टप्रकार की मशीनें हैं, उन्ह वहां से उखाड़ कर चीन, फिलिप्पीन आदि देशों को यद्ध के हरजाने के रूप में दे दिया जाय । पर मित्रराज्य देर तक इस नीति का अनुसरण नहीं कर सके । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे—(१) चीन में कम्युनिस्ट दल की शक्ति किस प्रकार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। चियांग काई शेक का कुओमिन्तांग दल कम्युनिस्टों द्वारा निरन्तर परास्त हो रहा था, और बाद में यह स्थिति आ गई थी, वि फार्म्सा के अतिरिक्त शेष सब चीन कम्युनिस्टों के अधिनार में आ गया था। मित्रराज्यों और विशेषतया अमेरिका को यह भय था, कि यदि जागान सैनिक और आर्थिक द ब्हि से निर्वेल हो जायगा, तो वहां भी कैम्युनिस्टों की शक्ति बढ़ने में सहायता मिलेगी। (२) महायुद्ध की समाप्ति के बाद संसार की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लोकतन्त्रवादी और समाजवादी (कन्यु-निस्ट) देशों का विरोध सबसे महत्त्वपूर्ण बात हो गई। यद्यपि महायुद्ध में रूस, अमेरिया और ब्रिटेन एक साथ गिलकर फैसिस्ट चिक्तयों की पराजय के लिये तत्पर थे, पर उनमें सीमनस्य देर तक कायम नहीं रह सका। समाज का आधिक संगठन जिल प्रकार का हो, इस विषय पर ब्रिटेन और अमेरिका सदुश लोकतन्त्र राज्यों और रूस सद्दा समाजवादी राज्यों में गहरा मतभेद था। यह मतभेद शीझ ही स्पष्ट विरोध व विद्येप के रूप में परिणत हो गया और संसार के प्रमुख राज्य दो गटों में विभवत हो गये। एक गुट का नेता रूस था और दूसरे का संयुक्त-राज्य अमेरिका । जय चीन पर कम्युनिस्ट सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो प्रशान्त महासागर और दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी एशिया में अमेरिका की स्थिति बहुत निर्वल व अरक्षित हो गई। इस क्षेत्र में रूस के समाजवादी गुट का प्रभाव व प्रभूत्व बहुत अधिक बढ़ गया। इस स्थिति में अमेरिका ने यह अनुभव किया, कि यदि जापान की आधिक व सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाया जाय, तो वह कम्युनिज्य की जिल्ला 🕾 भाग 🖫 🕫 वे के कार्य में अमेरिका का प्रधान सहायक हो सकता है । महायुद्ध के समय में भित्रराज्यों और विभेषतया अमेरिका का यह खयाल था, वि चीन पूर्वी एशियाका नेतृत्व कर शकता है, और उसकी छोकतंत्र राष्ट्रीय सरकारको

नाजी व फैसिस्ट प्रविच्यों के खिलाफ प्रमुक्त करने के साथ-साथ करण्यिक के विकत्त की प्रयोग में लावा जा सकता है। इसीलिये संयुक्त राज्यसंघ में चीन को बिटेक, अमेरिका, कस ओर फांस के समान ही महत्त्वपूर्ण स्थान दिसा गया था। पर जर्स चीन जैसे दिशाल देश में करण्यातरहों का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो प्रशान महासागर और पूर्वी एशिया के क्षेत्र में करण्यात्म की नहती हुई विक्त का स्थान बना करने का केवल यही उपाय अमेरिका के सम्यूच रह गया, कि यह जापात को शिवा को किया । दक्षिणी कोरिया अमेरिका के प्रभूच्य में था और उत्तरी कोरिया में करण्यात्म हो गया। दक्षिणी कोरिया अमेरिका के प्रभूच्य में था और उत्तरी कोरिया में करण्यात्म में करण्यात्म को साम थी। दक्षिणी कोरिया की साम थी। दक्षिणी कोरिया की साम थी। दक्षिणी कोरिया की करण्यात्म स्थान की साम थी। विक्षणी कोरिया की साम की साम थी। जापान की लिये जय अमेरिका की साम की लिये जापान की साम की सा

जिस प्रकार कर के कम्युनिस्टों से पृष्टिनमी यूरोप की रक्षा करने के लिये विटेन और अमेरिका ने परिसमी जर्मनी को फिर से शांताकाली बनाने का स्थीप कुरू किया, तैसे ही चीनी बध्युनिस्टों से पूर्वी व यक्षाण-पूर्वी पृथिया की रक्षा कहाँ के लिये उन्होंने जापान को फिर से सिनाजाली बनाने की नीति का अन्यरण प्रारम्भ किया। यही कारण है, कि इस समय अमेरिका और विटेन जैने लेक्सिय देश जापान को अपना शत्रु न रामझ कर उसे अपना मित्र सालों हैं, और उस बात के लिये प्रयत्नकील है, कि बह एक बार फिर पूर्ववन् अपिताजी सलकर रस और चित्र के प्रमूनिजम का मुकायला कर सकने में समर्थ हो। पर जापान में भी कम्युनिस्ट विचारों का जोर निरन्तर बढ़ रहा है, और यह बात विचारायद है, कि जापान कहां तक कम्युनिज्म के प्रतिरोध में अमेरिका का सहायक हो सकेगा।

तेईसवां अध्याय

कोरिया की समस्या

(१) कोरिया की नई व्यवस्था

१ दिसम्बर, १९४३ को कैरो कान्फरेन्स के परिणामस्वरूप अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की तरफ से एक उद्घोषणा प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह कहा गया था, कि महायुद्ध में जापान के परास्त हो जाने पर कोरिया को जापान की अधीनता से म्यत कर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिणत कर दिया जायना । याल्टा और पोट्सडम की उद्घोषणाओं में इस बात को फिर दोहराया गया था और कोरिया के सम्बन्ध में भित्र राज्यों की यह नीति सर्वथा स्पष्ट थी, कि जापान की पराजय के न्याद कोरिया की राष्ट्रीय स्वाधीनला को पूनः स्थापित किया जायगा । उन्नीसबीं सदी में कोरिया चीनी साम्राज्य के अन्तर्गत एक अधीनस्थ राज्य की स्थिति रखता था । जापान ने उसे किस प्रकार अपने अधीन किया, इस पर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। १९४५ तक कोरिया पूर्णतया जापान के अधीन या और जापानी लोग उसे अपनी आर्थिक समृद्धि के लिये प्रयुक्त करने में तत्पर थे। पर कोरियन लोगों में अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना विद्यमान थी और वे जापान की अधीनता से मुक्त होने के लिये प्रयत्नशील थे । जहां विदेशों में विद्यमान बहुत. से मुशिक्षित कोरियन देशभवत अपनी मातभूमि की स्वतन्त्रता के लिये उद्योग में लगे थे, वहां कोरिया के अन्दर भी ऐसे लोगों ी कमी नहीं थी, जो महायुद्ध में जापान की गिरती गला से लाभ उठाकर स्वराज्य के संघर्ष में तत्पर थे।

कैरो काल्फरेन्स में अमेरिका, किटन और चीन ने यह बात तो स्वीकार कर छी। भी, कि महायुद्ध के नाद कीरिका को न्यान्त राज्य के रूप में परिचर्तित कर विवा भाषामा, पर समका लगान था कि एस दिस में गानित नोट जावस्था स्थापित रखने कि लिये अमेक क्यो तक यहां विपानकों का अविकास कामम रखने की आवश्य-कता होगी । भीरे भीरे जब कीरियन लोग अपने देश का जासन स्वयं संभाल सकने के लिये समर्थ हो जावेंगे, तब बहा स्वराज्य स्थापित धर दिया जायगा। जब अगस्त, १९४५ में इस ने भी जायक के विश्व युद्ध की भीषणा कर दी, तो

1

यह आवश्यक हो गया; कि उसे भी कोरिया के सम्बन्ध में की जाने वाली नई व्यवस्था में हाथ बटाने का अधिकार हो। उत्तरी चीन में जापान की सबसे अधिक शिक्ता आली स्थल सेना क्वांतुंग सेना विद्यमान थी। इसे इसी रोनाओं ने ही परारत किया था। इस दशा में उसे ही राबसे पूर्व यह अवसर मिला, कि वह उत्तरी कोरिया में जापानी सेनाओं को परास्त कर उस प्रदेश ो अपने कब्जे में ले आये। इस स्थित में मित्रराज्यों ने कोरिया के सम्बन्ध में आपस में यह समझीता किया, कि ३८वीं भेरेलल के उत्तर में इसी रोनायों अपना कब्जा रम्यें और ३८वीं भेरेलल के दक्षिण में अमेरिकन सेनायों। पर यह सैनिक कब्जा केवल सामयिक इन से हो और इसी व अमेरिकन सेनाओं का यह कार्य हो, कि वे अपने अपने क्षेत्र में जापान के रीनिक व अन्य प्रभुत्व को नष्ट कर कोरिया को जापानी अधीनता से मुक्त नरें।

यह स्वाभाविक था, कि जापान की अधीनता से मुक्त होने के बाद कोरिया में सर्वत्र स्वाधीनता की भावना अत्यन्त प्रबल रूप घारण कर है। इसी कारण वहां सर्वत्र जनता ने बड़ी बड़ी सभायें की और उत्साहपूर्ण जलरा निकालकर अपनी प्रस-न्नता की प्रकट किया। जो अनेक कोरियन देशभक्त जागान की जेलों में बन्द थे. वें इस समय रिहा हो गये। उनमें प्रसिद्ध कान्तिकारी गम्युनिस्ट नेता पाक हैन एन भी थां। उसने जेल से मुनत होकर कीरियां में नम्युनिस्ट दल का पुनर् संगठन शुरू विधा। शब बड़ें नंगरों में कम्युनिस्ट नेतृत्व में जनगमितियां (पीपल्स कमेटी) संगठित की जानी प्रारम्भ हुई और ६ सितम्बर, १९४५ को सिछल नगर में जनता के प्रतिनिधियों की एक विशाल कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें १००० से अधिक प्रतिनिधि एकत्र हुए । इस कांग्रेस ने निश्नय किया, कि कीरिया को एक स्वंतन्य रिपब्लिकन राज्य के रूप में परिवर्तित किया जाय। इसके लिये एक केन्द्रीय जनसमिति का भी संगठन कर लिया गया। इस केन्द्रीय समिति में कम्युनिस्टों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। यदि निवराज्य इस समय कोरिया के मागले में हस्तक्षेप न करते, तो कोरियन देश-भक्त स्वयं अपने देश के बासनसूत्र को संभाल सकते थे और कोरिया एक स्वतन्त्र रिपब्लिक के रूप में परिणत हो जाता।

में एक स्वतन्त्र व लोकतन्त्र राज्य की स्थापना के प्रक्त पर विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में रूस और अमेरिका ने दो पृथक् योजनायें पेश की। वहुत वाद-किंवाद के बाद अन्त में यह निश्चय हुआ, कि रूस और अमेरिका का एक संयुक्त कमीशन बनाया जाय, जो कि सम्पूर्ण कोरिया के लिये एक सामयिक लोकतन्त्र सरकार को संगठित करने का कार्य करे। इस कोरियन सरकार के निर्माण के लिये देश की विविध लोकतन्त्र राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त किया जाय और उनके परामर्श के अनुसार सब कार्य हो। अधिक से अधिक पांच साल तक कोरिया पर रूस और अमेरिका की ट्रस्टीशिप कायग रहे, और इस अवधि में कोरिया की रारकार को शासनमूत्र के संचालन की सारी उत्तरदायिता दे दी जाय। कोरिया की जनता ने मोस्को कान्फरेन्स के इस निर्णय का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। इससे वे अनुभव करते थे, कि कोरिया में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के स्थापित होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है।

मार्च, १९४६ में संयुक्त सोविएत-अमेरिकन कमीशन ने सिऊल में अपना कार्य प्रारम्भ किया। पर शुरू से ही रूस और अमेरिका में मतभेद प्रकट होने लग गये। सामयिक कोरियन सरकार की स्थापना में किन राजनीतिक दलों का कहांगा लिया जाय, इस प्रक्त पर रूस और अमेरिका के लिये एकमत हो सकता सुगम नहीं था। रूसी प्रतिनिधि समझते थे, कि कोरिया में सबसे अधिक शक्तिशाली दल कम्युनिस्टों का है, और वही दल जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत अमेरिकन प्रतिनिधियों की दृष्टि में कोरिया के दक्षिणपदी (कम्युनिस्ट-विरोधी) दलों का अधिक महत्त्व था। इस समय कोरिया के लोग दो मुख्य दलों में विभक्त थे। एक दल कम्युनिस्ट व्यवस्था का पक्षपति था और दूसरा दल अमेरिका और बिटेन के ढंग की लोकतन्त्र रिपब्लिंग के पक्ष में था। यह सुगम नहीं था, कि इन दो दलों में समझौता हो सके। स्वाभाविक रूप से रूस के प्रतिनिधियों की यह इच्छा थी, ि निधिक जीरिया के पक्ष में था। यह सुगम नहीं था, कि इन दो दलों में समझौता हो सके। स्वाभाविक रूप से रूस के प्रतिनिधियों की यह इच्छा थी, ि निधिक जीरिया कारिकन प्रतिनिधि इसके विखद थे। इस दशा में संयुक्त सोविएत-अमेरियन क्यीयन अपने उद्देश में सफल नहीं हो सका।

क्स और अमेरिका दोनों ही कोरिया के अपने अपने क्षेत्र में अपने विचारों व क्षित्रों के अनुसार सागिक सरकार के संगठन में ततार थे। यदि संयुक्त सोविएत-अमेरिकन कमीशन एकमत होकर सम्पूर्ण कोरिया में एक सरकार की स्थापना में समयं हो जाता, तो कोशिया की एकता अश्रुणण रहती । पर जब यह कमीशन अपने कार्य में असपाल हो भया, तो रूस और अमेरिका के सम्युख एक ही मार्य शेष रह

गया । उन दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में ऐसी सरकारें संगठित करनी शरू कर दी. जो उनके अपने आदशों के अनुकृत थीं। उत्तरी कोरिया व्यवसायों और कल-कारमानों का केन्द्र था । वहां मजदूर श्रेणि की प्रचुरता थी, जो सम्मृनिस्ट विचार घारा की अनुयायी थी। दक्षिणी कोरिया की जनता मुख्यतया कृषि पर निर्भर थी। यद्यपि वहां भी कम्पनिज्य की सत्ता थी, पर इस क्षेत्र में कम्पनिस्टों का उतना जोर नहीं था, जितना कि उत्तरी कोरिया में था। अतः रूपी सेनाओं के संरक्षण में उत्तरी कोरिया में एक शबित शाली केन्द्रीय सरकार का सुगमता के साथ संगठन हो गया, जिसमें कम्युनिस्ट लोगों की प्रधानता थी। कम्युनिस्ट लोगों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ सहयोग कर एक नई पार्टी का संगठन किया, जिसे 'नवीन जनता दल' (न्यू पीपल्स पार्टी) का नाम दिया गया । इस नये दल ने एक सामधिक सरकार का संगठन किया, जिसका नेता श्री किम इर सेन था। ये श्री किम इर सेन कम्यनिस्ट दल के प्रभावकाली व त्योग्य नेता थे। इस सामयिक सरकार ने देश के बासनसूत्र को भलीभांति संभाल लिया और इस प्रकार के अनेक सुधारों का प्रारम्भ किया, जिनका उद्देश्य कोरिया की जनता का हित य कल्याण था। कोरिया की अधिकांश मूंमि जापानी जागीरवारों की सम्पत्ति थी। इस भूमि को जापानी मालिकों से छीनकर कोरियन किसानों में विभवस कर दिया गया । कोरिक यन लोगों के पास भी जो बड़ी बड़ी जागीरे थीं, उनकी भूमि भी किसानों में बांट दी गई। भूमि सम्बन्धी इस सुधार के कारण जो भूमि सर्वसाधारण किसानी (जिनके पास अब तब खेती के लिये कोई भी जमीन नहीं थी) में विभक्त की गई, उसका क्षेत्रफल १०,००,००० ची (एक ची: :: २,४५ एकड़) में भी अधिक थी और इसमें जिन किसानों को लाभ पहुंचा, जनकी संख्या ७,२५,००० के लग-भग थी। श्री किम इर सेन की सरकार केवल जमीन की किसानों में बांट कर ही संतुष्ट नहीं हुई, उसने यह भी प्रयत्न किया, कि किसानों की खेली के छिये आयश्यक उपकरण भी प्राप्त हों। जमीन के सम्बन्ध में व्यवस्था करके थी निस इर सेन की सरकार ने व्यवसायों की उन्नति पर ध्यान दिया । अब तक कीरिया के प्राय: सभी कल कारलाने जापानी लोगों के स्वत्व में थे। उन पर राज्य ने अपना स्वत्ता रथापित कर लिया। बात की बात में कोरिया के सब कल कारलाने, बैक और बीमा कम्पनियां आदि राज्य की सम्पत्ति वह गई। जो छोटे व्यवसाय कोरियन लोगों के हाथों में थे, उन पर उन्हीं का अधिकार कायम रखा गया । गाउथ के स्वस्व 🖏 विग्रमान बड़े कल कारजानी व अन्य आधिक संस्थाओं में कार्य करने वाले मजदूरी के लिये इस प्रकार के कानून बनाये गये, जी मजदूरों व कर्मचारियों के लिये बहुत अधिक हित्कर व स्विधाजनक थे।

सितम्बर, १९४६ में उत्तरी कोरिया की सामयिक सरकार ने अपने देश के लिये नये आसनविवान का निर्माण कर लिया। इसमें यह व्यवस्था की गई, कि सिन बालिंग पुरुषों व स्त्रियों को बोट का अधिकार प्राप्त हो और बोट देने के लिये गुन्त पींचयों (बैलट) का प्रयोग किया जाय। नया शासन विवान समाजन्वादी और लोकतन्त्र सिद्धान्तों के अनुसार बनाया गया था। देश को अनेक प्रान्तों में और प्रान्तों को अनेक जिलों में विभक्त करके यह व्यवस्था की गई थी, कि प्रान्तों, जिलों और नगरों का शासन-प्रवन्ध जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में रहे। इसी के अनुसार नवम्बर, १९४६ में उत्तरी कोरिया में निर्वाचन किये गये। इस चुनाव में नवीन जनता दल को असाधारण सफलता हुई।

इस प्रकार जापान की अवीनता से मुक्त होने के लगभग एक साल बाद तक उत्तरी कोरिया में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो गई थी, जो पूर्णनया राष्ट्रीय व स्वतन्त्र थी। यद्याप रूसी सेनायें अभी इस क्षेत्र में विद्यमान थीं, पर देश के शासन में वे कोई हस्तक्षेप नहीं करती थीं। सरकार का संचालन पूर्ण रूप से कोरियन लोगों के हाथों में था और इस कोरियन सरकार का निर्माण लोकमत के अनुसार हुआ था। इसमें सन्वेह नहीं, कि रूसी सेनाओं की सत्ता के कारण कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी को वल मिलता था, पर साथ ही यह बात भी निविवाद है, कि उत्तरी कोरिया के ध्यवसाय प्रधान क्षेत्रों में कम्युनिस्ट लोग अधिक शक्तिशाली थे और जापानी लोगों की जागीरों को भूमिबिहीन किसानों में विभक्त कर तथा जापानी लोगों के कल कारखानों व वैकों आदि को राज्य के स्वत्व में लाकर सरकार ने एक ऐसा कार्य किया था, जिसके कारण सर्वसाधारण जनता की सहानुभूति उसे अधिकल रूप से प्राप्त हो गई थीं।

(२ दक्षिणी कोरिया में रिपब्लिक की स्थापना

हम जगर लिख चुके हैं, कि ३८वें पेरेलल के दक्षिण में दक्षिणी कोरिया में जापानी प्रभुत्त्व का अन्त करने का कार्य अमेरिकन सेनाओं के सुपूर्व किया गया था। इस अमेरिकन सेना के सेनापित जनरल जॉन हॉज थे, जो जनरल मैंक आर्थर की अवीनता में अपना कार्य करते थे। जिस प्रकार जागान में आक्रन के सञ्चालन का कार्य जापानी सरकार के हाथों में रखा गया था, उसी प्रकार दक्षिणी कोरिया में भी शुक्त में वहां का शासन जापानी वर्मचारियों के हाथों में ही रखा गया। ये जापाने कोशारी जनरल हॉज के आदेशों हे अनुसार शायन का कार्य करते थे। जनवरी, १९४६ में दक्षिणी कोरिया के शायन के लिये अमेरिका संनित्त सरवार का सगठन किया गया, जिसमें

कोरियन लोगों का सहयोग भी प्राप्त किया गया । यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस समय तक उत्तरी कोरिया में सर्वत्र जनसमितियां संगठित हो चकी थीं और जनता इन समितियों द्वारा अपने शासन कार्य का स्वयं सञ्चालन करने लगी थी। अमेरिकन सैनिक सरकार शासनकार्य में जिन कोरियन छोगों ना सहयोग प्राप्त कर रही थी, वे प्राय: धनी व सम्पन्न लोग थे। इनके अतिरिक्त वे कोरियन लोग जो विदेशों में रहने के कारण अंग्रेजी माणा और अमेरिकन आचार विचार से भली-भांति परिचित थे, इस रौनिक सरंकार की सहयोग देने का कार्य कर रहे थे। अमे-रिकन लोगों ने यह प्रयत्न नहीं किया, कि रूसी लोगों के समान सर्वसाधारण कोरियन जनता का सहयोग देश के शासन में प्राप्त करे। फरवरी, १९४६ में जब उत्तरी कोरिया में बाकायदा सामयिक सरकार की स्थापना ही गई थी और यह सरकार पूर्ण रूप से जनता के हाथों में थी, दक्षिणी कोरिया में एक परापर्श समिति (एडवाइजरी कौंसिल) का निर्माण किया गया । पर इस कौंसिल में कैवल उन लोगों को स्थान दिया गया, जो चोर दक्षिणपक्षी विचारों के थे। कम्यिनिस्ट व बामपक्षी लोगों के इसमें सम्मिलित होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था. जब कि इसमें ज्वार लोकतन्त्र विचारों के राजनीतिक दलों तक की स्थान नहीं दिया गया था।

नवम्बर, १९४६ में जब उत्तरी कोरिया में तसे शासन विधान के अनसार नई निर्वाचित सरकार का संगठन हो गया. तब दक्षिणी कोरिया में अमेरिकन सैनिक सरकार ने एक सामयिक व्यवस्थापिका सभा का संगठन करने की व्यवस्था की। इस व्यवस्थापिया सभा के बिषय में यह नियमय किया गया, कि इसके आधे सदस्य अमेरिकन सैनिक सरकार ब्रास मनोनीस किये जावें, और आधे निर्वाचन द्वारा नियुक्त हों। पर इन निर्वाचित सदस्यों के लिये भी यह व्यवस्था की गई थी, कि उन्हें सम्पूर्ण बालिंग स्त्री पुरुष अपने बाँटों द्वारा न चनगर कविषय सम्पन्न य शिक्षित लोग परोक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा निर्वाचित करें। यह स्वाभाविक था, कि विधाणी कोरिया की सर्वसाधारण जनता इस व्यवस्थापिका सभा और उसके सदस्यों की नियुनित की योजना का विरोध करती। परिणाम यह हुआ, कि नथम्बर, १९४६ के निवासन से पूर्व सम्पूर्ण दक्षिणी कोरिया में अधानित और विद्रोह के चिह्न प्रकट होने लगे। अक्टबर, १९४६ में दक्षिणी कोरिया के भजदूरी है आम हड़ताल की घोषणा कर दी। कई स्थानों पर दंगे और विद्रांह हए 🕏 वामपक्षी दलों का कहना था, वि अमेरिकान सैनिका सरकार जान बूझकर इस यात या यत्न कर रही है, वि जनता के वास्तविक प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में नियम्बित न हो सकें और केवल ऐसे लोग ही व्यवस्थापिका सभा

में आवें, जो अमेरिकन प्रमुत्त्व को कोरिया में स्थापित रखने में सहायक हों। इसके विपरीत अमेरिकन सैनिक सरकार का कहना था, कि दक्षिणी कोरिया में जो हड़तालें, दंगे व विद्रोह हो रहे हैं, वे सब कम्युनिस्ट लोगों की कृति हैं। यह स्वाभाविक था, कि व्यवस्थापिका सभा में जो ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचन द्वारा नियुक्त होते थे, वे सब अनुदार व दक्षिण पक्षी विचारों के हों। ऐसा ही हुआ, केवल कम्युनिस्ट व वामपक्षी लोगों का ही नहीं, अपितु उदार लोक-तन्त्रवादी लोगों का भी यह कहना था, कि नवम्बर, १९४६ का यह चुनाव एक तमालामात्र था, और इसके कारण दक्षिणी कोरिया की वास्तविक जनता को व्यवस्थापिका सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था।

इस प्रकार १९४६ के अन्त तक कोरिया में दो सरकारों की स्थापना हो गई थीं। वोनों का रूप सामयिक था। उत्तरी कोरिया की सरकार लोकतन्त्रवाद पर आश्रित थी और उसमें कम्युनिस्टों व अन्य वामपक्षी दलों का प्रभुत्व था। दक्षिणी कोरिया की सरकार में कुलीन-श्रेणि के लोगों, जागीरदारों, पूजीपितयों व अन्य दक्षिण पक्षी लोगों का जोर था और वह अमेरिकन सरकार के संरक्षण व तत्त्वावधान में कायम की गई थी। एप्रिल, १९४७ में रूस के परराष्ट्र मन्त्री श्री मोलोतोव ने प्रस्ताव किया, कि संयुक्त सोविएत-अमेरिकन कमीश्रन फिर से अपना कार्य प्रारंभ करें और सम्पूर्ण कोरिया के लिये एक लोकतंत्र सरकार के संगठन का प्रयत्न करें। २१ मई, १९४७ को संयुक्त कमीश्रन ने अपने कार्य को फिर से शुरू किया, पर उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं हो सकी। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के वोनों भागों में पृथक् पृथक् सरकारें कायम रहीं, और उन्हें एक करने के कार्य में संयुक्त कभीशन असफल रहा।

 संगठन करे, जो जनता के वास्तविक लोकमत का प्रतिनिधित्व करती हो । रूम के विरोध के बावजूद संयुक्त राज्य संघ द्वारा नियुक्त सामियक वमीशन ने कंरिया, में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया ।

जतरी कोरिया में सामयिक कमीशन का बहुत विरोध हुआ, वहां के राजनी-तिक नेता इसके साथ किसी भी प्रकार का संहयोग करने को तैयार नहीं हुए । वे नहीं चाहते थे, कि लोकमत के अनुसार जनसमितियों के रूप में जो संगठन उत्तरी कोरिया में स्थापित हो चना है, उसमें किसी भी प्रकार में बाधा उपस्थित हो। तक्षिणी कोरिया में भी ऐसे लोगों की कभी नहीं थी, जो कम्युनिस्ट व वामपक्षी विचारधारा के अनुसार अपने क्षेत्र में जनसमितियों की स्थापना के पक्षपाती थे। अमेरिकन सैनिक सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके जेलीं में डाला हुआ था। इस प्रकार गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या ३०,००० के लगभग थी। जब संयुक्त राज्य संघ द्वारा नियुक्त सामयिक कमीशन ने देखा, कि उत्तरी कोरिया के लोग उसके साथ किसी भी प्रकार से सहयांग करने की तैयार नहीं हैं, तो उसने निश्चय किया, कि दक्षिणी कीरिया में ही संयक्त राज्य संघ के प्रस्ताव के अनुसार निर्याचन कराये जावें। अत: १० मई, १९४८ की दक्षिण कोरिया में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पर अमेरिकन सैनिक सरकार द्वारा अधिकृत एस प्रदेश में भी सामगिक कमीशनः के खिलाफ भावना इतनी प्रबल थी, कि निर्वाचन से पहले ७ मई से १० गई तक तीन दिनों में दक्षिणी कोरिया में अनेक स्थानों पर वंगे हुए । वंगे व बिद्रोह के अप-राध में सरफार ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी गंग्या इन वीन दिनों में ५,४२४ तक पहुंच गई। इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना नाहिये, कि विक्षणी फोरिया की कुछ आबादी २,००,००,००० के छमभग भी । दो करोड़ की जन-संख्या में ५४२४ व्यक्तियों का गिरफ्तार किया जाना इस बात का सफ्ट प्रमाण है, कि दक्षिणी कोरिया में भी संयुक्त राज्यसंघ के निर्णय के खिलाफ असलीप की गावना वहत अधिक प्रवल थी।

१० मई, १९४८ के निर्वाचन द्वारा दक्षिणी कोरिया में जिस राष्ट्रीय महासभा (नेशनल असेम्बली) का चुनाव हुआ, उसने देश के लिये नयं जासन विधान का निर्माण करने का कार्य अपने हाथों में लिया । १२ जुलाई, १९४८ तम राष्ट्रीय महासभा ने नया शासन विवान तैयार कर लिया । इसकी मुख्य वार्ते निम्नलिकित औ—(१) कोरिया में रिपब्लिकन शासन की स्थापना की जाय। (२) कोरियन रिपब्लिक का शासन एक राष्ट्रपति के अधीन हो, जिसका चुनाव नेशनल एसम्बली हारा विधा जाय। राष्ट्रपति की कार्य में सहायता देने के लिये एक उपराष्ट्रपति भी हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बोनों का चुनाव नेशनल एसम्बली द्वारा चार

वर्ष के लिये किया जाय। नेशनल एसेम्बली को यह अधिकार हो, कि महा अपराध कुरने पर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पर अभियोग चला सके और उन्हें अपने पर में पृथक् कर मके। (३) राज्य की व्यवस्थापन शक्ति नेशनल एसेम्बली में तिहित हो, जिसके सदस्यों की नियुक्ति जनता के नोटों द्वारा हो। (४) राष्ट्रपति को यह अधिकार हो, कि वह किसी एसे व्यक्ति को प्रधानमन्त्री के पद पर नियत करे, जिसे नेशनल एसेम्बली के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो। यह प्रधान मन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सके। (५) राष्ट्रपति को अधिकार हो, कि वह नेशनल एसेम्बली के किसी भी निर्णय को वीटो कर सके। (६) शासन विधान के एक पृथक् अध्याय में जनता के जन्मसिद्ध अधिकारों का विश्वस्थ से प्रतिपादन किया गया। (७) न्याय विभाग का पृथक् रूप से संगठन करने की व्यवस्था ी गई और न्यायालयों को शासन विभाग के प्रभाव से स्वतन्त्र रखा गया। सुप्रीम कोर्टकोयह अधिकार दिया गया, कि किसी कानून, आदेश व प्रस्ताव के संविधान के अनुकूल व प्रतिकूल होने के सम्बन्ध में निर्णय दे सके।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि १२ जुलाई, १९४८का यह शासनविधान लोकतन्त्र विचारधारा के अनुकूल था, और इसके अनुसार प्रायः उसी ढंग की शासन व्यवस्था ीं। कायम करने का प्रयत्न किया गया था, जैसा कि समाजवाद का अनुसरण न करने बाले अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों में कायम है। १० मई, १९४८ को निर्वाचित हुई नेशनल एरामबली ने डा० सिंगमन रही को कोरियां का प्रथम राष्ट्रपति निर्वा-चित किया । प्रधानमन्त्री के पद पर श्री ली बोम सोक को नियुक्त किया गया । इस प्रकार दक्षिणी कोरिया में संयुक्त राज्यसंघ द्वारा नियुक्त सामयिक कमीशन के निरीक्षण व तत्त्वावधान में एक वाकायदा रिपब्लिकन सरकार कायम हो गई। यद्यपि उत्तरी कोरिया ने नेशनल एसेम्बली के चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लिया था, पर डा० रही की इस सरकार का दावा था, कि वह सम्पूर्ण कोरिया की वैध सरकार है, और वैधानिक रूप से उसका सम्पूर्ण कोरिया पर अधिकार है। उसका यह भी दावा था, कि क्योंकि उसका निर्माण संयुक्त राज्यसंघ द्वारा तय की गई व्यवस्था के अनुसार तथा था, अनः अन्तर्राष्ट्रीय देखि से सभी को अन्य देशों द्वारा स्वीकृत किया जाना महिए । चीत की यरकार (विधान काई रोक की अओमि-ेक्कांग सरकार) ने उरका पाठ एकी की सरकार को कोरिया की बैच। सरकार के क्रिय में स्वीकार कर किया । फिक्सियान की गरकार ने भी इस विषय में चीन का अनुसरण किया । टा॰ १८१५० गरकार ने अब अमेरिका के सैनिक अधिकारियों के साथ इस बात के लिए बालगीन अरू की. कि ने कीरिया के बारानचूप की पूर्ण-रूप से रिपविलकन राउकार के मणुई कर दें, ताकि कंग्रिक अन्तर्राष्ट्रीय वृष्टि ते

पूर्ण रूप से स्वतन्त्र राज्य बन जाय और जापान के आधिपत्य मा अन्त करने के लिये जो अमेरिकन शासन यहां सामयिक रूप से स्थापित किया गया थर् उसकी आवश्यकता न रहे।

(३) उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार

उत्तरी कंरिया में कम्युनिस्ट व अन्य वामपन्यी दलों के नेतृत्व में जिस साम-यिक सरकार का संगठन हुआ था, उसका उल्लेख हम इसी अध्याय में पहले कर मुके हैं। इस सरकार का शासन ३८ वीं पैरेलल के उत्तर में विधमान था। जब संयुवत सोविएत-अमेरिकन कमीशन सम्पूर्ण कोरिया के लिये एक सरफार के संग-ठन में असफल हो गया, तो उत्तरी कोरिया के राजनीतिक नेताओं ने निश्वय किया, कि वे भी अपने देश के लिये स्थायी सरकार का निर्माण करें। उस उद्देश्य से विविध राजनीतिक दलों और अन्य सार्वजनिक संगठनों के नेता एक समा में एकत्र हुए, और उन्होंने यह निश्चय किया, कि एक 'सर्वोच्न जन महासभा' (सुप्रीम पीपल्स एसेम्बली) का निर्वाचन किया जाय, जो कि देश के लिये नये शासन विधान का निर्माण करे। इस निर्णय के अनुसार २५ अगस्त, १९४८ की कोरिया में महा-सभा के सदस्यों का निवचिन किया गया । इस महासभा में जिन विविध दलों 🕊 राजनीतिक संस्थाओं के उम्मीदवार निर्वाचित हुए, उनकी संस्था ३२ थी। पर यें सभी वामपक्ष के विवारों के थे और रामाजवादी व्यवस्था के रागर्थक थे। इस महासभा ने कोरिया के लिये एक नये शासन विधान को स्वीकृत किया । इस शासन विधान के अनुसार कोरिया के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई थी. कि वहां 'कोरियन जनता की लोकतन्त्र रिपब्लिक' (कोरियन पीपल्प डेमोकेटिक रिपब्लिक) की स्थापना की जाय । जासन विवास का रूप प्राय: उसी हंग का था, जैसा कि समाजवादी देशों में होता है। रूस के शासन विधान की छागा स्पष्ट रूप से इस कोरियन विद्यान पर विद्यमान थी। इस कोरियन पीपल्स रिपब्लिक के मन्त्रिमण्डल के प्रधान पद पर श्री किम इर सेन की नियुक्त किया गया था। डा० पृष्ठी की बक्षिणी कोरियन रिपब्लिक के समान अंतरी कंपिया की एस पीयल्स रिपब्लिक का भी यह दावा था, कि वह सम्पूर्ण कोरिया की वास्तिक और वैध सरकार है।

१० सितम्बर, १९४८ को कोरिया की सुप्रीम पीगला एतम्बर्जी ने कस और अमेरिका की सरकारों से एक समय में ही यह निवेदन किया, कि वे अपनी अपनी सेनायें कोरिया से वापस बुला लें। इसी सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया और दिसम्बर, १९४८ में सब कसी सेनायें कोरिया से वापस बुला की गईं। अमे-

रिकन लोग श्री किम ६र सेन की उत्तरी पीपल्स रिपब्लिक को स्वीकृत करने के लिये तैयार नहीं थे। वे दक्षिणी कोरिया में डा॰ रही के नेतत्त्व में एक पथक सरकार की स्यापना करा चुके थे और इसी को सम्पूर्ण कोरिया की वास्तविक व वैध सरकार समझते थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सरकारों में परस्पर संघर्ष का प्रारम्भ हो।

उत्तरी कोरिया में श्री किम इर रोन की सरकार ने समाजवादी व्यवस्था को रथापित करने के लिये जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये, वे निम्नलिखित थे-(१) जमीं-दारी प्रथा का उन्मुलन किया गया और २४,५१,०३७ एकडु कृषियोग्य भूमि बिना म्आवजे के जमींदारों से लेकर किसानों को वितरित कर दी गई। (२) बड़े कल कारखानों, यातायात के साधनों, बैंकों, बीमा कम्पनियों व अन्य वड़े व्यवसायों को राष्ट्रीय सम्पत्ति बना दिया गया। (३) व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये अनेक नये कानून बनाये गये। दफ्तरों व कारखानों में काम करने का समय आठ घण्टा प्रतिदिन निश्चित किया गया और खतरनाक कारखानों व खानों में कार्य करने का अधिकतम समय सात घण्टा प्रतिदिन नियत किया गया । यह व्यवस्था की गई, कि १४ साल से कम आयु नैक बालक मजदूरी न कर सकें।

इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त उत्तरी कोरिया की सरकार ने १९४८ में एक वर्षीय योजना और १९४९ में दो वर्षीय योजनायें तैयार की । इन योजनाओं का उद्देश्य कीरिया की आधिक उत्पत्ति में वृद्धि करना था । इन्हें अपने उद्देश्य में सफ-लता भी प्राप्त हुई। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप उत्तरी कोरिया के कार-सानों का उत्पादन १९४६ के मुकाबले में ३॥ गुना बढ़ गया है। कागज, शीशा, विजली का सामान, मशीनरी आदि को तैयार करने के अनेक नये कारलाने वहां खों ले गये हैं, और इनके लिये नवीनतम ढंग के उपकरणों को प्रयोग में लाया गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार को अपने देश की आधिक उन्नति में और जनता के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने में अच्छी सफलता

प्राप्त हुई है।

(४) कोरिया का गृह-युद्ध

कोरिया में किम पकार, दो विभिन्न सरकारों की, स्थापना हुई, इस विशय पर हम इस जन्याय में पहले प्रकाश बाल नके हैं। दक्षिणी कोरिया की सरकार संगाताराज्य अमेरिका के प्रभाव में भी ओर उसी की सहायता पर निर्वेर रहकर अपना कार्य कर रही थी । यह सरकार कम्युनिष्म के विरुद्ध भी और अपने क्षेत्र में

पंजीबाद य वैयक्तिक सम्पत्ति पर आश्रित छोकतन्त्र बासन स्थापित करने में तत्पर थी । इसके विपरीत उत्तरी कोरिया की सरकार समाजवादी (कम्युनिस्ट) व्यवस्थर को माननेवाली थी। और अपनी शक्ति के लिये रूस की सहायता व सहानुभृति गरेँ भरोसा रसती थी । दोनों सरकारों का यह दावा था, कि वे सम्पूर्ण कोरिया की न्याय्य सरकार है। इस दशा में उनमें परस्पर युद्ध का प्रारम्भ होना सर्वधा स्याभाविक और अवक्यम्भावी था । जुन, १९५० में कोरिया की दोनों मरकारों में युद्ध शुरू हो गया । इस युद्ध के लिये उत्तरी और विक्षणी कोरिया में कीन उत्तर-दायी था, इसका निश्चय कर सकता सूगम नहीं है। उत्तरी कोरिया की सरकार यद्ध के लियं दक्षिणी कोरिया को दोषी ठहराती है। उसका कहना है, कि राष्ट्र-पति रही ने अमेरिका के इशारे पर युद्ध की शुरू किया और दक्षिणी कोरिया की सेनाओं ने ३८वीं पेरेलल को पार कर अनेक स्थानों पर कब्जा कर लिया । उत्तरी कोरिया को अपने देश की रक्षा करने के उद्देश्य से ही ३८वीं पेरेलल को पारकर दक्षिणी कोरिया की सेनाओं पर आक्रमण करने के लिये विवस होना पड़ा । इसके विपरीत दक्षिणी कोरिया की सरकार उत्तरी कोरिया की कम्यनिस्ट सरकार को युद्ध के लिये दोषी ठहराती है। संयुक्त राज्य संघ की सुरक्षा परिषद ने कीरियन यह के लिये उत्तरी सरकारको उत्तरदायी माना और विजिब राज्यों में इस बातके जिल्ह अपील की, कि वे कोरियन युद्ध में शिंगमन रही की सरकार की सहायता करें। यह में पहल चाहे किसी की ओर से हुई हो, पर इस बात में कोई सत्वेह नहीं, कि बोरियन गृहकलह का आधारमृत कारण सोवियत इस और संयक्त राज्य अभेरिका की परस्पर विरोधी राजनीति है। अमेरिका यह चाहता है, कि कीरिया में समाज-वादी व्यवस्था कायम न होने पावे, वहां ऐसी सरकार कायम रहे, जो समाजवाद (कम्युनिज्म) की विरोधी हो, और जो अभेरिकन ढंग की पूंजीवादी छोवलन्य व्यवस्था की पक्षपाती हो । इसके विगरीत इस और कम्युनिस्ट चीन कोरिया को कम्युनिस्ट प्रभाव में ले आने के लिये उत्पुक है। कोरिया की जनता में भी उन लोगों का बहुत जोर है, जो अपने देश में कम्यनिस्ट व्यवस्था को स्थापित करने के पक्षपाती हैं।

कोरिया के गृह्युद्ध का अभी अन्त नहीं हुआ है। इस युद्ध में कोरिया की कम्युनिस्ट सरकार ने असाधारण अकित प्रदिश्वत की। रूस की अक्तिआठी नेनाओं ने प्रत्यक्ष रूप से उत्तरी कोरिया की सहायता नहीं की, यद्यपि कम्युनिस्ट चीन की सहायता के लिये खुळे तीर पर मैदान में आ गई। अमेरिका ने पूर्ण रूप से सिगमन रही की दक्षिणी कोरियन सर्वार की मदद की और संयुक्त राज्य सच की प्रेरणा से अन्य भी अनेक राज्यों ने इस सरकार

को सहायता पहुंचाई । अनेक बार ऐसा प्रतीत होने लगा, कि कोरिया का युढ़ विश्वव्यापी महायुद्ध में परिणत हुए बिना नहीं रहेगा । पर संसार के राजनीतिज्ञ अब तक दस बात में सफल रहे हैं, कि वे कोरिया के युद्ध को अधिक व्यापक रूप धारण न करने दें । दोनों पक्षों में सुलह कराने के प्रयत्न भी अभी जारी हैं । वस्तुतः कोरिया की समस्या उस विश्वव्यापी संघर्ष का एक अंग हैं, जो कम्युनिस्ट और लोकतन्त्रवाद के पक्षपाती देशों में सर्वत्र जारी हैं ।

पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का विस्तार

(१) चीन में कम्युनिस्ट शासन

वीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) की समाप्ति पर चीन में किस अकार गृहयुद्ध (१९४६-४९) हुआ, और इसमें महारोनापति चियांग काई शेक की कुओमिन्तांग दल की पराजय होकर किस प्रकार कम्युनिस्ट दल की विजय हुई, इस विषय पर हम इस पुस्तक के बीसवें अध्याय में प्रकाश टाल नृके हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना न केवल एशिया के आधुनिक इतिहास की अत्यत्त महत्त्वपूर्ण घटना है, अपितु संसार के इतिहास की दूष्टि से भी उसका अत्यविक महत्त्व है। इसलिये यह उपयोगी होगा, कि हम कम्युनिस्ट चीन के सम्बन्ध में कुल अधिक विशव कृप से विचार करें।

कम्युनिस्ट सरकार गृहयुद्ध में विजयी होकर चीन के याम्युनिस्ट वल ने समाजवादी आदशों के अनुसार देश में शासन को स्थापित फिया। इसके लियं जनता के प्रतिनिधियों की एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसे 'नीनी जनता की राजनीतिक परामशंदात्री महासभा के ६६२ सदस्य थे, जी विधिध राजनीतिक दलों और प्रान्तों का प्रतिनिधित्त्व करते थे। महासभा का अधिवेशन २१ सितम्बर, १९४९ को शुरू हुआ और दस विन तक होता रहा। इसमें न केवल चीन के लिये नये संविधान का निर्माण किया गया, अपितु साथ ही उन राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक आदशों का भी निश्चय किया गया, जिन्हें चीन की नई सरकार ने अपने सम्मुख रक्षना है। चीन का नया संविधान समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार बनाया गया और यह निश्चय किया गया, कि देश में समाजवादी व्यवस्था को कायम किया जाय।

चीनी जनता की राजनीतिक परामशंदात्री महासभा ने देश की कियीय सरकार का प्रधान (चेयरमैन) माओं त्से तुंग की निर्वाचित किया ! माओं तो नुंव की निर्वे कम्मुनिस्ट वरू के प्रधान नेता हैं, और कुओं मिन्तांग दल को प्रशास्त करने के कार्य में उनका मुख्य कर्तृत्व था । कम्युनिस्ट चीन में उनका वही स्थान है, जो कम्युनिस्ट रूस में लेनिन और स्टालिन का है। इसी महासभा ने केन्द्रीय सरकार के लिये छ: उपप्रधानों का भी निर्वाचन किया, जिनके नाम निम्नलिखित हैं—सदाम सन यात रान, श्री नांग लांग, जनरल चू तेह, श्री काओ कांग, श्री लिऊ वाओ ची और जनरल ली चिह-शेंग । मदाम सन यात सेन कुओमिन्तांग दल के संस्थापक डा॰ सन यात सेन की पत्नी हैं, और चियांग काई शेक के साथ उनका मतभेद था । उनका विचार था, कि चियांग वाई शेक के नेतृत्व में कुओमिन्तांग दल ने अपने संस्थापक की नीति व आदशों का परित्याग कर दिया है । श्री चांग लांग चीन की डेमोक्रेटिक लीग के अध्यक्ष थे । यह लीग वामपक्ष की अनुयायी होते हए भी कम्यनिस्ट दल से प्यम् स्थिति रखती थी । जनरल चू तेह कम्युनिस्ट सेनाओं के प्रधान सेनापति थे और कुओमिन्तांग सेनाओं को परास्तं करने के लिये कम्युनिस्ट दल की ओर से जिस जन स्वातन्त्र्य सेना का संगठन किया गया था, उसके प्रधान संचालक थे । श्री काओ कांग मञ्चिरिया की प्रावेशिक सरकार के प्रधान (चेयरमैन) थे। श्री लिक शाओ ची कम्यानिस्ट दल के थे और उसकी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। जनरल ली चिह-शेंग कान्तिकारी कुओमिन्तांग दल के अध्यक्ष थे। कुओमिन्तांग र्पेटल के सब लोग महारोनापति चियांग काई शेक के अनुयायी नहीं थे । उनमें अनेक लोग चियांग काई शेक की नीति से मबभेद रखते थे, और यह समझते थे, कि महा-सेनापति ने डा० सन यात सेन के आदंशीं का परित्याग कर दिया है। इन लोगों ने अपनी पथक पार्टी का संगठन कर लिया था और जनरल ली चिह-रोह इन्हीं के नेता थे।

एक प्रधान और छः उपप्रधानों के अतिरिक्त "चीनी जनता की राजनीतिक परामर्शवात्री महासभा" ने एक 'केन्द्रीय जन शासन कौंसिल' (सेन्द्रल पीपत्स गर्वमंग्नेन्द्र कौंसिल) का भी निर्वाचन किया, जिसके ५६ सदस्य थे। यह कौंसिल महासभा की उपसमिति की स्थित रखती थी, जिसका कार्य चीनी सरकार की नीति का निर्धारण करना था। ५६ साधारण सास्यों के अतिरिक्त नीनी रिपब्लिक के प्रधान और अपस्थान अपने एसाधकार से उस सौनिल के सरस्य होते थे। इस सम्बाद इस कौंसिल के संस्था हो सहस्य होते थे। इस सम्बाद इस कौंसिल के निर्धाय की सरकार की नीति का निर्धारण ही नहीं करती थी, अपनु इस यह भी अधिनात दिया गर्वा था। कि यह राज्य के लिये कानुनों का निर्धाय कर सके।

केन्द्रीय जनशासन कासिल के निर्माद्याण में कार्य करने के लिये पार कींसिलों का निर्माण किया एक । ये चार कौंगिलें निम्नालिंग्वत थीं—(१) ज्ञासन सभा (स्टेट एड्मिनिस्ट्रेटिय कींसिल)—इस सभा के सदरयों की रोड्या २१ नियत की गई। इसकी वही स्थित रही रखी गई, जो लोकतन्त्र राज्यों में मिन्शमण्डल की होती है। यह व्यवस्था की गई, कि चीन का प्रधान मन्त्री इस शासनसभा का अध्यक्ष हो, और उसे अपने कार्य में सहायता करने के लिये नार उप-प्रधानमन्त्री रहें। प्रधानमन्त्री और चार उप-प्रधानमन्त्री के अतिरित्त इस शासनसभा के १५ अन्य सदस्य नियत किये। साथ ही, इस सभा के सचिव के रूप में एक अन्य पदाधिकारी को नियत किया गया, जिसे सेकेटरी जनरल कहने हैं। यम्युनिस्ट जीनी सरकार के प्रधानमन्त्री के पद गर थी चोऊ एन-लाई को नियत किया गया। (२) जन कान्तिकारी मैनिक कींसिल (पीपल्स रेबोल्युशनरी मिलिटरी कौंसिल)—इस कींसिल को सैन्यसंचालन का कार्य मुपूर्व किया गया। (३) सर्वोच्या जन न्यायालय (सुप्रीम पीपल्स कोर्ट)—इस न्यायालय को चीन के न्याय विभाग के संचालन का कार्य दिया गया। (४) जन निरीक्षण विभाग—इस यह कार्य दिया गया, कि यह जामन के विविध अंभों का निरीक्षण करे। यहां यह लिखने की आव- क्ययाता नहीं है, कि चार कींसिलों व विभागों का निरीक्षण कर ने यहां यह लिखने की आव- क्या ता नहीं है, कि चार कींसिलों व विभागों का निरीक्षण कर में यह लिखने की आव- क्या ता नहीं है की चार कींसिलों व वावशों को वृध्य में रखा गया था। ये विभाग पाय: इसी ढंग से बनाये गये थे, जैसे कि डा० सन यात सेन ने प्रतिगादित किया था।

३० सितम्बर, १९४९ की 'जीनी जनता की राजनीतिक प्रशासकीयी महा- " सभा' ने अपना कार्य समाप्त कर दिया, और १ अक्टूबर, १९४९ की जीन में सभाज-बादी रिपब्लिक की बाकायदा स्थापना कर दी गई। जीन के कम्य्तिस्ट कल की दृष्टि में १ अक्टूबर, १९४९ का दिन बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रसता है। वर्तमान जीन में यह माना जाता है, कि इस दिन जीन के इनिहास में एक वर्तन युग का प्रारम्भ हुआ है।

गृहयुद्ध की परिस्थित के कारण यह सम्भव नहीं था, कि जीन में सर्वत्र शान्ति व व्ययस्था स्थापित हो सकती । यद्यपि कुओमिन्तांग दल व उरानी संन्यशिक्त को परास्त किया जा चुका था, पर चीन जैसे विशाल देण में शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर सकता सुगम बात नहीं थी । यही कारण है, कि कम्युनिस्ट चीन में सर्वसाधारण जनता के बोटों द्वारा किसी केन्द्रीय पालियामेन्ट का निर्वाचन नहीं किया जा सका । चीनी जनता को केन्द्रीय परामर्शदावी महासमा के सदस्यों की नियुक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होकर नहीं हुई थी । पर इसमें सन्देह गहीं, कि इस महासमा के सदस्य जन विविध दलों का प्रतिनिधित्त करते थे, जो समाजवादी व्यवस्था के पक्षपाती व वामपक्ष की थीं । महासमा ने नम्युनिस्ट चीन के शासन के सम्बन्ध में जिस नीति व जिन आद्यों को स्वीकार किया था, उन्नके अनुसार यह व्यवस्था की गई थी, कि चीन के जिन-जिन प्रान्ती व प्रदेशों में शान्ति व व्यवस्था

कायम होती जाय, उनमें जनता (प्रत्येक वालिंग स्त्री और पुरुष) के बोटों हारा स्थानीय व प्रान्तीय सभाओं का निर्वाचन किया जाय और इन सभाओं को कानून बनाने व शासन पर नियन्त्रण रखने के अधिकार प्रदान किये जावें। इस नीति के अनुसार अब तक नीन के आधे से अधिक प्रदेशों में जनता द्वारा निर्वाचित सभाओं की स्थापना की जा चुकी है, और चीन लोकतन्त्र शासन की ओर अग्रसर हो रहा है।

कस्युनिस्ट झासन में चीन की उन्नति—१ अक्टूबर, १९४९ की चीन में कस्यु-निस्ट व्यवस्था के अनुसार लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। इस समग से अगले दो वर्षों में चीन ने जो असाधारण उन्नति की है, वह वस्तुतः आश्चर्य-जनक है। चीन की इस प्रगति पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

(१) विशाल चीन में राजनीतिन एकता स्थापित करने में कम्युनिस्ट सरकार को असाचारण सफलता मिली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन बहुत बड़ा देश है। इसफी जनसंख्या ४७,००,००,००० से भी अधिक है। जनसंख्या की दिन्ट से संसार का अन्य कोई देश चीन का मुकाबला नहीं करता। इतने विशाल देश में राजनीतिक एकता कायम करना साधारण बात नहीं है। मञ्च सम्राटों के शासन-क्राप्य में नीन के विविध प्रदेश सम्राट् की अधीनता को स्वीकार करते थे, पर साम्राज्य के अन्तर्गरा अनेमा राज्य व प्रदेश कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र थे और मञ्ज् सम्राटों का उन पर प्रभुत्व केवल नाममात्र को था। १९११ में जब चीन में राज्यकान्ति हई, तो विवेल्द्रीभाव (धीसेन्ट्रलिजेशन) की प्रवृत्तियां बहुत प्रबल हो गई, और विविच शिगहगाछार अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हो गये। कुओमिन्तांग दल ने चीन में राष्ट्रीय व राजनीतिक एकता को स्थापित करने का बहुत प्रयतन किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। कम्युनिस्ट सरकार इस कार्य में वस्तुतः सफल हुई है। फार्मशा के अतिरिक्त चीन के सब प्रदेश इस समय कम्युनिस्ट शासन में हैं। १९५० के मार्च गास तक हैनान और फॉर्म्सा द्वीप के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण चीन पर कम्यनिस्ट सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया था। बाद में हैनान पर भी कम्युनिस्ट रेजाओं ने अपना कब्जा कर लिया । १९५१ के मध्य-भाग में तिब्बत में कम्युनिस्ट रानाओं ने प्रवेश किया और वहां की सरकार ने पेकिंग की केन्द्रीय कम्यु-निस्ट सरकार की अधीनता स्वीकृत कर ली। मञ्जू शासन के काल में व उससे पूर्व भी तिब्बत चीन का अधीनस्थ राज्य माना जाता था। १९१२ के बाद जब चीन में कोई शिवतशाली, व व्यवस्थित केन्द्रीय सरकार नहीं रह गई थी, तिब्बत की स्थिति कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र राज्यं के समान हो गई थी। पर अब तिब्बत फिर चीन का अंग बन गया है, और विशाल चीन में अविकल रूप से राजनीतिक एकता कायम हो गई है। कम्युनिस्ट सरकार इस प्रयत्न में है, कि फार्मुसा को भी

कुओिमन्तांग राएकार की अवीनता से गुवत कर उसे भी अपने अधीन कर है, और इस प्रकार सम्पूर्ण चीन की एक जामन में है अबि । इसमें गन्देह नहीं, कि चीन कील एक गासन में है जाने और उसके विविध धरेशों में व्यवस्थित शामन स्थापित करने में कम्युनिस्ट छोगों को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है।

(२) राष्ट्रीय दृष्टि से चीन के सब निवासी एक नहीं है। नीनी लोगों के अतिरिक्त इस देश में तिब्बती, मंगोल, मसलिम, मिजाओ, यिग आदि अनेक अन्य जातियों के छोग भी पर्याप्त संख्या में निवास करते हैं। उन विविध प्रकार के लोगों में राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर सकता सूगम कार्य नहीं है। न्यस्युनिस्ट सरकार ने अल्पसंख्यक- जातियों के सम्बन्ध में यह गीति निवारित की, ंकि उन्हें अपनी जातीय विशेषताओं (भाषा, धर्म, परम्परा, रीति-रिवाज आदि) को विकसित करने का पूरा अवगर दिया जायगा, और चीन के छोकतन्त्र गणराज्य में उतकी स्थिति बहसंख्यक चीनी लोगों के समान व समगदा मानी जावेगी। उस जीवि की किया में परिणत करने के लिये तम्युतिस्ट संस्कार ने प्रत्येक अल्पसंख्यक जाति के लोगों को पथक स्वतन्त्र राज्य के रूप में संगठित करने का प्रयदन किया, जो विज्ञाल चीनी लोकतन्त्र गणराज्य के अन्तर्गत रहते हुए भी अपनी पथना न स्वतन्त्र राता रमते हैं। अस्पसंख्यक जातियों के इन पृथक स्वतन्त्र राज्यों की स्थिति की स्वव्ह करने के लिये आभ्यन्तर मंगोलिया के उदाहरण को सम्मन रचना उपयोगी होगा। आभ्यन्तर मंगोलिया के निवासी मंगोल जाति के हैं और उनकी संख्या ८,००,००० से अभिक है। मंगोल लोगों के असिंग्यत उस प्रदेश में चीनी लोग भी पर्याप्त संख्या में निवास करते हैं, और आभ्यन्तर मंगीलिया में वसे हुए बीनी कींगीं की संख्या १५ लाल से कम नहीं है । इस प्रकार यह समय है, कि जास्यकार मंगीलिया में मंगील लीग बहसंख्या में न हीवर अल्परंख्या में है। पर चीन भी कम्यनिस्ट सरकार ने इस प्रदेश को एक स्वतंत्र पृथक् राज्य के रूप में परिणत पित्रा, वाकि मंगोल लोग वहां अपनी जातीय विशेषताओं का मुचार रूप से विकास कर सकें । मंगोल लोगों की उनकी अपनी भाषा में शिक्षा दी जाती है, और मंगोल भाषा में साहित्य का बहन तेजी के साथ विकास हो रहा है। मंगोल गापा में अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं, और आभ्यन्तर मंगोलिया के राज शिक्ष-णालयों में मंगील भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर विया गया है। इसी प्रकार 🎉 नीति तिब्बत, सिन्किआंग आदि अन्य प्रदेशों में भी अपनाई जा रही है, क्योंकि इन प्रदेशों के निवासी जातीय दृष्टि से चीनी छोगों से भिन्न है । कम्यनिस्ट छोगों की इस नीति के कारण विशाल चीन में रहने वाले अल्पसंख्यक जातियों के लोग सन्तोप अनुभव करते हैं।

- (३) माओ तमे तुंग की सरकार ने चीन में समाजवादी व्यवस्था के अनुसार आर्थिक नीति का अनुसरण किया । इसके लिये उसने जो महत्त्वपूर्ण कदम उठाये ो निम्नलिखित हैं—(क) जापानी लोगों के स्वामित्त्व में जो कारखाने, खानें, रेलने, जहाज, बैंक व अन्य व्यवसाय थे, उन सबको राज्य ने अपने स्वामित्त्व में ले लिया। (ख) इसी प्रकार कुओभिन्तांग दल के पूंजीपतियों व सम्पन्न लोगों के हाथों में विद्यमान कल-कारखानों व अन्य व्यवसायों को उनसे छीनकर राज्य के स्वामित्त्व में ले आया गया। इसका यह परिणाम हुआ, कि चीन के कुछ व्यवसायों का ५० प्रतिशत के लगभग भाग राज्य के स्वामित्त्व गें आ गया । (ग) कम्युनिस्ट सरकार ने यह प्रयत्न नहीं किया, कि व्यवसायों व न्यापार का संचालन व्यक्तियों के हाथ में सर्वथा न रहने दिया जाय। चीन के जो ज्यवसायपति व ज्यापारी जुओमिन्तांग दल के साथ सम्बन्ध नहीं रखते थे, उन्हें यह अवसर दिया गया, कि वे पहले के समान अपने व्यापार व व्यवसाय का संचालन करते रहें। पर उनके सम्बन्ध में भी यह व्यवस्था की गई, कि वे कल-कारखाने आदि के प्रबन्ध के मामले में उस नीति का अनुसरण ्र करें, जो कि राज्य द्वारा संचालित कल-कारखानों में प्रयुक्त की जाती है। राज्य द्वारा संचालित कारखानों, बेंकों, रेलवे आदि में मजदूरों का बहुत अधिक महत्त्व है। कारखानों के कर्मचारी उनके प्रबन्ध में भी हाथ बॅटाते हैं, व आधिक उत्पत्ति में वृद्धि करने के लिये स्वयं प्रयत्नशील रहते है ।
- (४) मूमि सम्बन्धी कानून में सुधार करने के लिये चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने विशेष रूप से उद्योग किया। चीन में जमीन सम्पन्न जमीदारों की वैयनितक सम्पन्ति थी। ये जमीदार भोग-विलास में जीवन व्यतीत करते थे, और कृषि की उन्नति पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। किसानों की दशा बहुत खराब थी। चीन की ८० प्रतिशत जनता अपनी आजीविका के लिये कृषि पर आश्वित थी, पर बहु- मंख्यक किसान खेती से इतनी आमदनी प्राप्त नहीं कर पाते थे, जिससे वे अपना निर्वाह भलीभांति कर सकें। कम्युनिस्ट सरकार ने यह व्यवस्था की, कि जमीन पर से जमीदारों के स्वस्व को नष्ट कर दिया जाय, और जमीदारों को अपनी भूमि के बदले में किसी भी प्रकार का मुआवजा न दिया जाय। वे केवल इतनी जमीन के अपने पास रख सकें, जिस पर वे स्वयं खेती कर सकें, और जो उनके गुजारे के लिये गर्यात्त हो। जमीदारों से जो जमीन ली गई, वह उन किसानों में बांट दी गई, जो स्वयं उस पर खेती करने के लिये तैयार थे। इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि करो ज़ारीव चीनी किसान खेती के लिये जमीन प्राप्त करने में समर्थ हुए। जमीन की व्यवस्था करने का कार्य स्थानीय ग्रामसमाओं के सुपुर्व किया गया। देहातों में व्यवस्था करने का कार्य स्थानीय ग्रामसमाओं के सुपुर्व किया गया। देहातों में

जो स्थित पहुछे श्वितशाली व सम्पन्न जमीदारों की थी, वह अब ग्रामसभाओं की प्राप्त हुई। इन ग्रामसभाओं के सदस्य ग्राम के किसान हों, यह व्यवस्था की गई 🔆 पर यहां यह ध्यान में रखना चाहिये, कि भूमि सम्बन्धी इन सुधारों को सारे देश में एकदम लागु कर सकता सुगम व कियात्मक नहीं था । चीन जैसे विकाल देश में इन कान्तिकारी सुधारों को एक साथ प्रारम्भ कर सकता किसी भी प्रकार सम्भव नहीं था । अतः कम्यनिस्ट सरकार ने यह व्यवस्था की, वि धीरे-धीरे उन सुधारों को चीन के विविध प्रदेशों में लागू किया जाय। कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के दो साल बाद १ अक्टूबर, १९५ १ तक गह स्थिति आ गई थी, कि चीन की (अल्प संख्यक जातियों के प्रदेशों को छोडकर) वो तिहाई से भी अधिक जमीन में जमींदारों के स्वत्व का अन्त कर उसे किसानों में विभक्त कर दिया गया था । जिस जनता की इन गुमि सम्बन्धी सुधारों से लाभ पहुंचा था, उसकी संख्या ३० करोड़ से भी अधिक थी। इसमें रान्देह नहीं, कि दो साल के थोड़े से समय में कृपि राम्बन्धी इतने महत्व-पूर्ण व क्रान्तिकारी सुघार करके कम्युनिस्ट सरकार ने चीन के देहातों की दशा में बड़ा भारी परिवर्तन ला दिया है। अब चीन का किसान अपने को जमींदार का अर्घवास अनुभव नहीं करता । वह अपनी उपज का स्वयं मालिक होता है, और इसी कारण वह अधिक से अधिक पैदाबार का प्रयत्न करता है। चीन में अनाज की समस्या के हुए होने में इससे बहुत अधिक राह्ययता मिली है। इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना आवष्यक है, कि चीन में सब किसान आगदनी की दृष्टि से एक समान स्थिति नहीं रखते । वहां ऐसे भी किसान मौजूद हैं, जो अधिक सम्पक्ष है, और जो यान्त्रिक शक्ति की सहायता से बहुत बड़े सेतों में सेती गरते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने इन किसानों से अिंगियत भूमि को छीनमर उसे भूमिबिहीन किसानों में विभक्त करने की नीति को नहीं अपनाया है, नयोंकि उसका खयाल है, कि देश की वर्तमान स्थिति में उन सम्पन्न किसानों से अनाज की पैदाबार में महायता प्राप्त होती है।

(५) चीन की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या यह थी, कि वहां नदियों में बहुधा बाढ़ें आती रहती थीं, और इन बाढ़ों के कारण जहां लाखों एकए जमीन से खेती नष्ट हो जाती थी, वहां लाखों आदमी भी बे घरवार के हो जाते थे। कम्युनिस्ट सरकार ने नदियों पर बांध बांधकर व अनेक अन्य उपायों का अपलम्बन्द्रि, कर इन बाढ़ों को रोकने का प्रयत्न किया। अपने शासन के वो वर्षों में कम्युनिस्ट सरकार ने नदियों पर जो बांध बंधवाये, उनका आकार बहुत विशाल है। यदि एक मीटर (एक मीटर चैंच के लगभग) ऊंचा और एक मीटर चौड़ा बांध नूमध्य रेखा के साथ-साथ बांधा जाय, तो उसके २४ चक्कर लगाने में जितने बांध

की आवस्यकता होगी, उतने बांच कम्युनिस्ट सरकार ने चीन की निदयों पर बंध-जये हैं। उन बांनों का परिणाम यह हुआ, कि चीन की निदयों में बाढ़ों की आशंका बहुत कम हो गई। फसलों का नष्ट होना रक गया और चीन में अनाज की पैदा-बार बहुत बढ़ गई। चीन जो अपनी खाद्य समस्या को बहुत कुछ हल कर रहा है, उसका एक मुख्य कारण यह है, कि अब बाढ़ों के कारण करोड़ों रुपये साल की फसलें अब बहां नष्ट नहीं हो जातीं। इन बांचों के लिये कम्युनिस्ट सरकार ने देहात की जनता का सहयोग लिया था, और इनका निर्माण करते हुए मुख्यतया मानव धम को ही प्रमुक्त किया था।

(६) कृषि और व्यवसाय की उन्नति के कारण चीन के विदेशी व्यापार में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जन्नी निर्वा सदी के मध्यभाग (१८७७) से चीन विदेशों में जो माल विजय के लिये भेजता था, उससे कहीं अधिक विदेशों से क्रय करता था। उसके आयात माल की मात्रा निर्यात माल की मात्रा से अधिक होती थी। इसका परिणाग यह था, कि चीन निरन्तर अधिक-अधिक गरीब होता जाता था। पर १९४९ के आय कम्युनिस्ट शासन में इस स्थिति में परिवर्तन आ गया है। जब चीन के निर्यात गाल की मात्रा आयात माल की अपेक्षा अधिक हो गई है। चीन का विदेशी व्यापार मुख्यतया इस व अन्य समाजवादी देशों के साथ है।

(७) शिक्षा के विस्तार पर भी कम्मुनिस्ट सरकार का विशेष ष्यान है। १९४९ तक चीन में शिक्षा का बहुत कम प्रसार था। शिक्षित व साक्षर लोगों की संख्या वहां १४ प्रतिशत से अधिक नहीं थी। कम्मुनिस्ट सरकार के प्रयत्न से वहां शिक्षा में जिस ढंग से उन्नति शुरू हुई है, उसका अनुमान इस वात से किया जाता है, कि अक्टूबर, १९५१ में चीन के प्रारम्भिक शिक्षणालयों में ३,७०,००,००० माध्यमिक स्कूलों में १५,७०,००० और कालेजों व विश्वविद्यालयों में १,२८,००० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इनके अतिरिक्त जो किसान व मजदूर अपने अतिरिक्त समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनकी संख्या ४,००,००,००० के लगभग थी। इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट सरकार चीन में निरक्षरता के विनाश और शिक्षा प्रसार के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

(८) जनता का बारान स्थापित हो जाने के कारण चीन में असाधारण शक्ति हा संचार हुआ है। विवेशी साम्राज्यबाद से तो चीन पूर्णतया मुक्त हो ही चुका है, नाथ ही वह संसार के प्रमुख शक्तिशाली राज्यों में भी गिना जाने लगा है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का संसार के राज्यों में प्रथम रथान है। इस विशाल जाता की साम्रहिक शक्ति के कारण चीन में जो आधिक उन्नित हो रही है, उन्हें अन यह देश भीतिक साधनों की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहा है। कारिया के

युद्ध में उत्तरी कीरिया की कम्युनिस्ट सरकार की सहायता करने में जो असाधारण सैन्यशक्ति चीन ने प्रवर्शित की है, उसके कारण अब संसार का कीर्ड भी राज्यु चीन की उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-नीन के लोकतन्त्र गणराज्य (चाइनीज पीपल्स रिपव्लिका) की स्थापना १ अक्टूबर, १९४९ को हुई थी । अगले दिन २ अक्टूबर को इस के सोवियत यनियन ने चीन की नई कम्युनिस्ट गरकार की स्वीकृत कर लिया और उसके साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया । बन्गारिया, क्यानिया, हंगरी, उत्तरी कोरिया, चेकोम्लोबाकिया, पोलैण्ड, मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक, पूर्वी जर्मनी (जर्मन डेमोकेटिक रिपब्लिक), अल्बानिया और विएत नाम की सरकारों ने एक का अनुसरण किया और गाओरसेत्ंगके नेतृत्व में स्थापित चीनी सरवार की सत्ता को स्वीकार किया। इन सब राज्यों में समाजवादी व्यवस्था विद्यमान है, और चीन की समाजवादी रारकार की सता की स्वीकृत करके इन्होंने किसी असाधारण मार्ग का अनरारण नहीं किया था। पर कई एंसे राज्यों ने भी चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्वीकृत विधा, जिनमें कम्यनिस्ट व समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं है। इनमें भारत, स्वीडन, उन्मार्क, बरमा, इन्डोनीसिया, स्विट्जरलैण्ड, फिनलेण्ड और पाकिस्तान के नाम विशेष रूप सेहैं जल्लेखनीय है । इनके अतिरिक्त बाद में जिटेन, सीलोन, नार्व, एजराईल, जफ-गानिस्तान और नीवरळेण्ड ने भी चीनकी तम्यनिस्ट सरकार को स्वीकृत कर उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किये। संसार के प्रमुख राज्यों में अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका चीन की कम्यानिस्ट सरकार को चीन की बैच व वास्तविक सरकार मानने के लिये उचल नहीं है। इसी कारण संयक्त राज्यसंघ में भी अब तक चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक की स्थान नहीं मिल सका है। इस अन्तर्राष्ट्रीय संघ में अब तक भी वियाग काई शेव की कुओमिन्तांग सरकार के प्रतिनिधियों को ही स्थान प्राप्त है, यद्यपि इस सरकार की सत्ता क्षेत्रक फार्म्सा द्वीप तक ही सीमित है, और वास्तविक चीन में कहीं भी उसका अधिकार नहीं रहा है । संयक्त राज्यसंघ में चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक को स्थान देने के लिये जो भी प्रस्ताव उपस्थित हुए, अमेरिका ने उनका विरोध किया, और इसी कारण अब तक कम्य-निस्ट चीन को अन्तरिष्ट्रीय क्षेत्र में अपना समुचित स्थान प्राप्त नहीं हो भजा 🛦 पर इसमें सन्देह नहीं, कि कम्युनिस्ट सनकार अपनी स्थिति की बहुत मजबूत वना चुकी हैं, और न केवल चीन के मामले में, अपित एशिया के सम्बन्ध में कीई ऐसी व्यवस्था सम्भव नहीं है, जिसमें कम्यनिस्ट चीन का सहयोग प्राप्त न हो।

(२) फार्म्सा की कुओमिन्तांग सरकार

१ अनद्वर, १९४९ को जब कम्युनिस्ट लोगों ने पेकिंग को राजधानी बनाकर नाइनीज पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना की थी, तब दक्षिण-पूर्वी चीन और पिक्सिंग चीन पर कुओमिन्तांग सरकार की आधिपत्य था। इस कुओमिन्तांग सरकार की राजधानी कैन्टन थी। अन्द्वर, १९४९ में कम्युनिस्ट सेनाओं ने कैन्टन को जीत लिया था और कुछ ही समय में दक्षिण-पूर्वी व पिक्सिंग चीन से भी कुओमिन्तांग जासन का अन्त कर दिया था। इस दशा में चीन में कोई भी ऐसा प्रदेश शेष नहीं रहा था, जो कुओमिन्तांग सरकार के हाथों में रहा हो। हैनान और फार्मूका—ये सी द्वीप ही ऐसे थे, जो अब इस नरकार की अधीनता में रह गये थे। इस दशा में ८ दिसम्बर, १९४९ को कुओमिन्तांग सरकार चीन से फार्म्स चली आई थी, और तैपेई को राजधानी बनाकर उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था।

हम पहले लिल चुके हैं, कि २२ जनवरी, १९४९ को महासेनापित चियांग पाई क्षेत ने मुओमिन्तांग सरकार का सब कार्यभार उपराष्ट्रपित ली त्युंग जेन के सुपूर्व पर दिया था। यद्यपि राष्ट्रपित के पद पर अब भी चियांग काई के के विराजमान थे, पर जुओमिन्तांग सरकार के संचालन का उत्तरदायित्व जनरल ली के हाथों में आ गया था। १ मार्च, १९५० को चियांग काई के ने कुओमिन्तांग सरकार का वार्यभार पुनः ग्रहण किया और फार्मूसा की राजधानी तैपेई को केन्द्र जनाकर अपना कार्य प्रारम्भ निया। बाद में जब कम्युनिस्ट सेनाओं ने हैंनान द्वीप को भी जीत लिया, तो चियांग काई के की कुओमिन्तांग सरकार का वासन केवल कार्युंसा तक ही गीमित रह गया। फार्म्सा द्वीप के समीपवर्ती १३ अन्य छोटे-छोट द्वीप और पेस्कार्वांस द्वीपसमूह के अन्तर्गत ६४ छोटे-छोट द्वीप भी कुओ- मिन्तांग रारपार के आसन में हैं।

पार्म्शा य उसके साथ के इन दीपों का कुल क्षेत्रफल ३२९६२ वर्गमील है, और इनकी जनसंख्या ९० लास के लगभग है। जहां माओ तसे तुंग की कम्युनिस्ट सरकार के जासन में ४७ करोड़ के लगभग मनुष्य हैं, वहां चियांग काई शेक की सरकार की अधीनता में विद्यमान मनुष्यों की संस्या एक करोड़ से भी कम है। पर सैनिक दृष्टि से इस कुओमिन्तांग सरकार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसकी रेना में गान लाख के लगभग सैनिक है, जो सब प्रकार के बाधुनिक अस्त्रशस्त्रों से भलीभांति सुमज्जित है। मंयुक्तराज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली व वैभवपूर्ण देश की सहायता तंगेई की इस कुओमिन्तांग सरकार को प्राप्त है। अमेरिका और संयुक्त राज्यरांघ की दृष्टि में तैयेई सरकार ही बीन की वैध व वास्तविक सरकार

है, और अमेरिका यह सर्वथा उचित समझता है, कि इस सम्कार को अपने देश से विद्वोही कम्युनिस्टों के शासन का अन्त करने के लिये खुळ तौर पर सहायता दे। यही कारण है, कि अमेरिका यद्ध सामग्री, जंगी जहाज, वायुयान व धन आदि से चियांग काई शेव की पूर्ण रूप से सहायता कर रहा है । चियांग काई शेक की भी यह विश्वास है, कि वह एक बार फिर राम्पुर्ण चीन को कुओमिन्तांग भासन की अधीनता में छाने में समर्थ हो सकेगा । चीन के इतिहास में अनेक बार कुओं भिन्तांग दल को नी वा देखना पड़ा है। कुछ वर्षों के लिये जापानी लोग चीन के बड़े भाग की अपने प्रभाव व प्रभुत्व में लाने में समर्थ हुए थे, और चियाग काई शेवः की सरकार की पश्चिमी बीत में चुंगिकेंग में आध्यम लेने के लिये विवश होता पड़ा था। इस समय कम्युनिस्ट दल के उत्कर्ष के कारण कुओमिन्तांग दल को फार्म्भा में आध्य लेना पड़ा है। पर चियांग काई शेक व उसके अनुगायियों का यह दृढ़ विश्वास है, कि वे पहले के समान एक बार फिर चीन को अपने शासन में ले आने में समर्थ होंगे। अमेरिका की सहायता के कारण उनके पास गैनिकों, युक्क गामग्री व धन की कमी नहीं है। कम्युनिस्टों को परास्त कर पारचात्य ढंग की लोकतन्त्र व्यवस्थां को स्थापित कर सकते के कार्य में कुओमिन्तांग दल को सफलता होगी या नहीं, इस बात का निर्णय भावी इतिहास ही कर सकेगा।

जिस समय में कुओमिन्तांग सरकार ने फार्मुगा को अपना आध्य स्थान बनाया है, उसकी नीति में भारी परिवर्तन हुआ है । १ शितम्बर, १९५० की कुओ-मिन्तांग सरकार ने अपनी नीति की जो घोषणा की थी, उसकी मुख्य वातें निम्न-लिखित हैं—(१) हमारा उद्देश्य कम्युनिस्ट यिद्रोह की कुचलता है। संयुक्त राज्यसंघ द्वारा जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है, हम उन्हें स्वीकृत गरते हैं, और उन्हीं के अनुसार चीन का पुनः निर्माण करना चाहते हैं। (२) हम नाहते हैं, कि सब लोगों को विचार करने और अपने विचारों को अभिलायत करने की पूरी स्वतन्त्रता हो । धर्म के मागले में भी सब लोग स्वतन्त्र हों । जनता में राष्ट्रीय अनुभूति और लोकतन्त्रवाद की भावना का विकास हो । (३) रामाच की ध्ययस्था इस ढंग की हो, जिससे कि सब लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो रागें। आधिक जीवन और विविध व्यवसायों को इस हंग से विकशित किया जाय, जिससे कि राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि हो। जमीन से वसुल किये जाने वाले लगान में कमी की जाय और भूमि सम्बन्धी कानुन के सुधार की विशेष व्या से महत्व विधा जाय। (४) जब हम चीत की कम्युनिस्ट लोगों के पंजे से मुक्त करने में क्षमर्थ होंगे, ती कम्युनिस्ट नेताओं और उनके सहयोगियों के साथ जरा भी दगा प्रचित्रत नहीं करेंगे । पर जिन लोगों ने विवश होकर कम्युनिस्टों का साथ दिया है, जनके प्रति हम

सहानुभूति रखेंगे और उन्हें पश्चात्ताप करके सन्मार्ग पर आने का अवसर देंगे।

फार्म्सा में दो अन्य दल है, जो कुओमिन्तांग सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। ये दल लोकतन्त्र सगाजवादी दल (डेमोक्रेटिक सोगलिस्ट पार्टी) और चीती युवक दल (चाइना यूथ पार्टी) हैं। लोकतन्त्र समाजवादी दल चाहता है, कि समाज-यादी व्यवस्था की स्थापना के लिये लोकतन्त्रवाद के उपायों का अनुसरण किया जाय। कम्युनिस्ट लोग जिस प्रकार के उग्र व कान्तिकारी उपायों से समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, यह दल उसका विरोधी है।

तैपेई में बाकायया कुओभिन्तांग सरकार विद्यमान है। इस सरकार के राजदूत न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका आदि विविध देशों में मौजूद हैं, अपितु संयुक्त राज्यसंघ में भी उसी सरकार के प्रतिनिधि लिये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से यह स्थिति बड़ी अद्भुत है। संसार के बहुत से देश जहां पेकिंग की कम्युनिस्ट सरकार को चीन की वैग व बास्तविक सरकार मानते हैं, वहां ऐसे देशों की भी कभी नहीं है, जो तैपेई की कम्युनिस्ट सरकार को समूर्ण चीन की वैध सरकार स्वीकृत करते हैं।

(३) दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म का विस्तार

बीसवीं सवी के दितीय महायुद्ध (१९३९-४५) में जापान के परास्त होने पर पूर्वी व दिशण-पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म को बहुत अधिक बल मिला है। इस महा-युद्ध के परिणामस्वरूप चीन न केवल जापान व अन्य साम्राज्यवादी देशों के प्रभाव व प्रभुत्व से मुगत हुआ, अपितु वहां कम्युनिस्ट व्यवस्था की भी स्थापना हुई। इसी प्रकार दिशण-पूर्वी एशिया के अनेक देश जहां महायुद्ध के कारण पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने में समर्थ हुए, वहां उनमें कम्युनिस्ट प्रवृत्तियां भी निरंतर बल पनड़ती गई। इसमें संदेह नहीं, िक इस क्षेत्र के अन्य किसी देश में अभी पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है, पर यह सर्वथा स्पष्ट है, िक इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट दल निरंतर शक्ति पकड़ रहे हैं। इस इतिहास में हमारे लिये यह संभय नहीं है, िय दिश्या-पूर्वी एशिया के विविध देशों में कम्युनिस्ट दलों के विकास पर संदिप्त रूप से भी प्रकाश डाल सकें। सम्भवतः, यह उचित भी नहीं है, क्योंकि अभी इन देशों की राजनीति ने कोई स्पष्ट रूप घारण नहीं किया है। पर यह बात तिवाद है, िय कम्युनिज़ का विकास व विस्तार एक ऐसी घटना है, जिसे एशिया के आधुनिय इतिहास को लिखते हुए उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देला जा सकता।

इन्डोचायना—डा० हो ची मिन्ह ने के नेतृत्व में इन्डोचायना में फांस के प्रभुत्त्व के विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष प्रारम्भ हुआ, इस पर हम इस इतिहास के इक्कीसर्वे अध्याय में प्रकाश टाल चुके हैं। जापान के परास्त होने पर १७ अगस्त, १९४५ की डा० हो नी मिन्ह और उसके क्रान्तिकारी अनुयायियों ने उन्होनायना में 'लिएत नाम' नाम से रिपब्लिकन राज्य की घोषणा कर दी और टा० हो को इस रिपब्लिक का राष्ट्रपति उद्घोषित किया गया। यह विएत नाम रिपब्लिक उन्होन्यया में फांस के प्रभुत्व को स्वीकृत नहीं करती थी। स्वभावतः, फांस उस रिपब्लिक की सत्ता को मानने के लिये तैयार नहीं हुआ, और उसने वाओ दाई के नेतृत्य में एक ऐसी इन्होचाइनीण सरकार की स्थापना का प्रथत किया, ओ फांस के प्रभन्व को स्वीकृत करने के लिये व उसके साथ समझीता करके देश का सामन करने के लिये उद्यत थी। फेल्च सेनाओं की सहायता से बाओ वाई की सरकार में छा० हो ची मिन्ह की रिपब्लिकन सरकार के साथ किस प्रकार शंधर्ष निया, इस विषय पर भी हम इस इतिहास में पहले प्रकाश डाल चुके हैं।

पर यहां उल्लेखनीय बात यह है, कि डा० ही भी मिन्ह की सम्कार में केल फांस के प्रमुख्य का अन्त कर इन्डोचायना की राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्वापना के लिये तत्पर है, पर साथ ही बह कम्यनिस्ट व्यवस्था की भी पक्षपाती है। बाद अपने देश के आर्थिक व सामाजिक जीवन को कम्युनिस्ट आदर्श के अनुगर परिवर्तित कर रही है, और इन्डोचायना में उसी ढंग की व्यवस्था स्थापि। करने के लियें अपन्तित कर रही है, जैसी कि माओ त्मे तुंग की सरकार ने चीन में स्थापि। करने के लियें के सम्बन्ध में उसने इस ढंग के सुधार किये हैं, जिनमें आप की भूमि पर में जमीवारों का स्थल समाप्त हो गया है, और लेत कियानों में निभवन कर दिसे गये हैं। बड़े कल-कारखानों और व्यवसायों को राज्य के स्थामित्व में खारा गया है, और आधिक जीवन पर राज्य का नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया है। चा० हो ची मिन्ह की सरवार को कम्युनिस्ट चीन की सहायता प्राप्त है, और एस्डोजायना में छा० ही की दिश्वीत है, जो चीन में माओ त्मे देग की की है।

फांस अभी इन्होनायना को अपनी अधीनता में रख समने के सम्बन्ध में सर्वधा निरास नहीं हुआ है। छः वर्षों के निरन्तर संघर्ष के वाधणूद भी फेल्न मैनाएं हा० हो की रिपब्लिकन सरकार को परास्त नहीं कर सकी है। कोई आक्सर्य नहीं, कि नियट भविष्य में सम्पूर्ण इन्होनायना डा० हो ची मिन्द्र की नम्युनिस्ट शरकार के अधिकार में आ जाय, और इन्होनायना में भी चीन के छंग की कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो जाय।

मलाया—महायुद्ध के बाद मलाया के सम्बन्ध में वहां के ब्रिटिश शासकों ने नया व्यवस्था की, इस प्रश्न पर हम पहले प्रकाश टाल पुर्व हैं। मलाया के राष्ट्र-बादी देशभवत इस व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं ही सकते थे। गहायुद्ध के समय में जब

मलाया ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हो गया था, तो वहा राष्ट्रीय स्वाधीनता और लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियों को बहुत बल मिला था । उस समय वहां अनेक ऐरो दलों का संगठन हो गया था, जो न केवल मलाया की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिये प्रयत्नशील थे, पर साथ ही इस बात के लिये भी उत्स्क थे, कि मलाया से विदेशी पंजीपतियों और मध्यकालीन सामन्तपद्धति का अन्त होकर ऐसा शासन स्थापित हो, जो समाजवादी प्रवृत्तियों के अनुकूल हो। कम्युनिस्ट दल का भी इस समय मलाया में विकास हो गया था । जापान के परास्त हो जाने पर जब ब्रिटिश सेनाओं ने मलाया पर अपने शासन को फिर से स्थापित किया, तो कम्युनिस्ट लोगों के सम्मुख तेवल यही मार्ग रह गया था, कि वे गुरीला युद्ध नीति का अनुसरण कर ब्रिटिश रेताओं का मुकाबला करें। कम्युनिस्ट लोगों ने अपने स्वयंसेवक सैनिकों का व्यवस्थित रूप से संगठन किया और ब्रिटिश शासकों के साथ संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। १६ जून, १९४८ को तीन अंग्रेज (जो रबड़ के बगीचों के मालिक थे) कम्युनिस्ट लोगों द्वारा कतल कर दिये गये। ब्रिटिश लोग इसे कब सहन कर सकते थे ? २० जून से २४ जून तक पांच दिनों में ८०० से भी अधिक कम्युनिस्ट लोग ू गिरफ्तार किये गये, ओर उन्हें कठोर दण्ड दिये गये । पर कम्युनिस्टों ने भी अपने रांघर्ष को जारी रखा। १९४८-४९ में मलाया में कम्युनिस्ट लोगों की शिक्त इतनी बढ़ गई, कि ब्रिटेन को उन्हें वश में लाने के लिये नई सेनाएं भेजने की आवश्यकता हुई। यद्यपि ब्रिटिश सैन्यशक्ति के मुकाबले में मलाया के कम्युनिस्ट अपनी पृथक् सरकार कायम करने में सफल नहीं हुए हैं, पर इसमें सन्देह नहीं, कि वहां कम्युनिस्ट लाग पर्याप्त शक्ति रख़ते हैं, और ब्रिटिश शासक उनके गुरीला युद्ध से वहन अधिक परेशानी अनुभव करते है । ब्रिटेन की सैन्यशक्ति अभी मलाया के कम्युनिस्टों को नष्ट नहीं कर सकी है।

अन्य देशों में कम्युनिस्ट वल—उन्डोबायना और मलाया के समान बरमा, इन्डोनीसिया और फिलिप्पीन में भी कम्युनिस्ट वल विद्यमान हैं। बरमा के कम्युनिस्ट भी गुरीला युद्ध का आश्रय देकर वरमी सरकार को परेशान करने मैं तत्पर हैं। इस देश में अनेक ऐसी अल्पसंख्यक जातियां विद्यमान है, जो बरमा के केन्द्रीय शासन के अवीन न रहकर अपना पृथक् व स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिये। प्रयत्नशील हैं। कम्युनिस्ट लोग इनके समर्थक हैं। इन्डोनीसिया में स्वतन्त्र य व्ययस्थित सरकार कायम हो जाने के कारण कम्युनिस्ट वल निर्वल पड़ गया है, पर उसकी सत्ता अब भी विद्यमान है। यही बात फिलिप्पीन हीपसमूह के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। थाईलैण्ड में कम्युनिस्ट वल अभी तक अपने पर नहीं जमा सका है। यहां के शासन कम्युनिस्ट वल सरी हैं, और किसी

भी प्रकार इस दल को सहन नारने के लिये उदात नही है । पर फिर भी वहां ऐसे लोग बिद्यमान हैं, जो कम्युनिज्म के पक्षपाती हैं ।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश—इन्डोनीसिया, थाईलैण्ड, मलाया, फिलि- "णीन और वरमा कब तक कम्युनिज्म से बचकर अपने-अपने क्षेत्र में लोकतन्त्रवाद के अनुसार अपना विकास करते रह सकेंगे, यह बात अभी निक्नित रूप से नहीं कही जा सकती। संयुक्तराज्य अमेरिका सदृश कम्युनिज्म-निरोधी देश इस आत के लिये उत्मुक्त हैं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध राज्य कम्युनिज्म के प्रभाव से बचे रहें, और रूस के कम्युनिस्ट प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत न होने पार्वे। इसीलिये अमेरिका इन देशों को अपनी आधिक उन्नति व विकास के लिये उत्पर्दा है। पर साथ ही यह वान भी स्पष्ट है, कि इस क्षेत्र में कम्युनिज्म निरन्तर उन्नति कर रहा है। पाइचात्य साम्राज्यवाद से मृत्त होने के बाद ये देश इस बात के लिये प्रयन्तर्शील है, कि लोकतन्त्रवाद के सिहान्तों के अनुसार अपनी उन्नति करें। पर पूंजीयाद और वैयक्तिक सम्पत्ति पर आधित लोकतन्त्रवाद इन देशों को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने में कहां तक सहायक हो सकेगा, इसी बात से इस प्रजन का निर्णय होगा, कि ये देश प्रमृत्तिज्म के प्रभाव से जच सकते हैं या नहीं।

(४) भविष्य

बीसवीं सदी का हितीय महायुद्ध (१९३९-४५) पूर्वी य दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों के लिये एक कान्तिकारी महना थी। इस महायुद्ध ने इन देशों की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारी परिवर्तन ला दिया है। ये परिवर्तन निम्नलिखित हैं—

- (१) महायुद्ध में जापान के परास्त हो जाने के कारण इस देश की शिवत बहुत धीण हो गई है। १९४४ तक जापान संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली और साम्राज्यवादी देशों में गिना जाता था। अब उसके विशाल साम्राज्य का अन्त हो गया है, और उसका क्षेत्र केवल उन द्वीपों तक सीमित रह गया है, जिनमें जापानी लोगों का निवास है। जापान की सैनिक शिवत भी बहुत क्षीण हो गई है।
- (२) चीन की राष्ट्रीय एकता और उसमें समाजवादी (कम्युनिस्ट) व्यवस्था की स्थापना महायुद्ध का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिणाभ हैं। ४७,००,००,००० जनता का यह विशाल देश अब न केवल राष्ट्रीय वृष्टि से एया संगठन में संगठित हो गया है, अपितु कम्युनिस्ट व्यवस्था को अपनाकर यह अपनी आधिक व

सैनिना सिवत की वृद्धि के लिये भी तत्पर है। चीन की सीमा कम्युनिस्ट रूस की सीमा के साथ लगी हुई है, अतः प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अब कम्युनिज्म े का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है।

(३) पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश अब पाश्चात्य साम्राज्यवाद के चंगुळ से प्राय: मुक्त हो गये हैं। इन्डोनीसिया, फिळिपीन, थाईळेण्ड और बरमा राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर अपनी उन्नति के लिये प्रयत्नशील हैं, और इन्डोन्गायना व मलाया में ऐसे आन्दोलन जारी हैं, जिनका यह परिणाम अवश्यमभावी है, कि ये भी शीध ही राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर लें।

इन देशों की वर्तमान राजनीति ने अभी ऐसा स्पष्ट रूप धारण नहीं किया है, कि उनके भविष्य के सम्बन्ध में कोई बात निश्चित रूप से यही जा सके। पर पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के सम्बन्ध में कुछ बातें ऐसी है, जिनका यहां उल्लेख करना उपयोगी होगा—

- (१) संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी अन्य लोकतन्त्रवादी देश इस बात के लिये उत्सुक हैं, कि जापान फिर से शिक्तशाली हो। प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में वम्युनिस्ट चीन और रूस का प्रभाव जिस ढंग से बढ़ गया हैं, उसे ये देश अत्यन्त चिन्ता की दृष्टि से देखते हैं और कम्युनिज्म की बाढ़ को रोकने का उन्हें यह उपाय फियात्मक प्रतीत होता है, कि जापान फिर से शिक्तशाली बने। अमेरिका का सहारा पाकर जहां जापान अपनी सामरिक शिक्त को वहाने के लिये प्रयत्नशील है, वहां वह अपनी आर्थिक व व्यावसायिक उन्नति पर भी विशोगरूप से ध्यान दे रहा है। वह समय दूर नहीं है, जब जापान एक वार फिर संसार के सम्पन्न व शक्तिशाली राज्यों में गिना जाने लगेगा।
- (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में कम्युनिज्य का प्रभाव निरन्तर वह रहा है। इन देशों की आबादी में चीनी लोगों की संख्या कम नहीं है। इन्होंचायना, थाईलैण्ड और मलाया में चीनी लोग पर्याप्त संख्या में बसे हुए हैं। फिलीप्पीन, इन्होंनीसिया और वरमा में भी चीनी लोग अच्छी संख्या में विद्यमान हैं। इन प्रयासी चीनी लोगों का अपने देश के साथ घनिष्ट सम्पर्क है। क्ष्म्युनिज्य इनम निरन्तर शक्ति पगड़ रहा है, और इनके द्वारा अन्य लोग भी कायुनिज्य के प्रभाव में आते जा रहे हैं। प्राचीन समय में दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देश चीन के सांस्कृतिक प्रभाव में रह चुके हैं। यदि आधुनिक समय में भी शक्तिशाली कम्युनिस्ट चीन के संस्कृतिक है। कि कायुनिक समय में भी शक्तिशाली कम्युनिस्ट चीन के सांस्कृतिक है। क्ष्मिया के क्षा क्ष्मियान के प्रभाव में स्वाप्त के क्ष्मियान के प्रभाव के क्ष्मियान के प्रभाव के प्रभाव के क्ष्मियान के प्रभाव के क्ष्मियान के स्वाप्त के प्रभाव के क्ष्मियान के क्ष्मियान के क्ष्मियान के क्षमियान के क्ष्मियान क्ष्मियान के क्ष्मियान के क्ष्मियान के क्ष्मियान के क्ष्मियान क्

है। संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश कम्युनिस्ट-विशेष वेश इस प्रयस्त में है, कि इन देशों को कम्युनिज्य के प्रभाव से बनाया जाय। इस उद्देश्य से वे इन देशों की दिल खोलकर सहायता कर रहे है। पर यह असम्भय नहीं है, कि निकट भविष्यें में दक्षिण-पूर्वी एशिया कम्युनिज्य और लोकतन्त्रवाद के संघर्ष का क्षेत्र बन जाय।

(३) दक्षिण-पूर्वी एजिया के विविध देश उन अशों में राष्ट्रीय द्रिप्ट ने एक नहीं है, जिनमें कि फांम, जर्मन, इङ्गलिण्ड आदि देश राष्ट्रीय राज्य (नंशनल संटट) हैं। इनमें अनेक अल्पसंख्यक जातियों की सत्ता है। बरमा, मलाया, भाईलिण्ड आदि में अनेक ऐसी जातियों का निवास है, जो अल्पसंख्यक हैं, और जो अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिय उत्सुल हैं। नेकोम्लोबाकिया, पोलिण्ड आदि सूरीपयन राज्यों में अल्पसंख्यक जातियों की जिस हंग की समस्याएं १९३९-४५ के महायुद्ध से पहले विद्यमान थीं, वैसी ही समस्याएं विधाण-पूर्वी एक्षिया के विविध देशों में भी बिद्यमान हैं। यह समय ही बतायगा, कि इन देशों में नये स्थापित हुए लोकतन्त्र राज्य इन समस्याओं को हल करने में कहां तक सफल ही समते हैं। यह असम्भव नहीं है, कि अल्पसंख्यक जातियों के प्रश्न को लेकर नम्मुनिस्ट लोग इन देशों में अपनी द्रित को बढ़ाने का प्रयक्त करें।

(५) उपसंहार

एशिया के इस आधानिय इनिहास का प्रारम्भ हमने उस समय से किया था, जब वि इस महाद्वीप के सब देश अज्ञान और अविद्या के अत्मनगर में इबे हुए थे। धामिय सुवारणा, विद्या की पुनः जागृति, व्यानगायिक आन्नि आदि के कारण यूरोप के देशों में जिस प्रकार नवयुग का श्रीमणेश हो गया था, एशिया में उसके चिह्न भी अभी प्रकट नहीं हुए थे। उसीसवीं गदी के महगभाग में जब पारनात्य यूरोप के विविध देशों में यान्त्रिय शावित में चलनेवालेबिशालकायकारणार्थ स्थापत होने शुरू हो गये थे, रेलवे लाइनों के निर्माण से विविध देश एक दूसरे के अत्मत्त समीप आने लगे थे और भाग की अवित से चलनेवाले जहाज महागमुद्रों में स्वच्छन्द स्प से विचरने लगे थे, उस समय एशिया के विविध देश मध्यवालीन परिस्थितियों से आमें नहीं बढ़े थे। सर्वश्र राजाओं का एकच्छन व निरंकुश शासन विस्थान था, लोकतन्त्रवाद व राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियों से लोग सर्वथा अपरिन्ति थे अञ्च आधुनिय ज्ञान विश्वानों का कहीं भी विकास व प्रवेण नहीं हुआ था। वस्तुक एशिया उन्नित की दौड़ में यूरोप से बहुत पीछे रहे गया था।

 इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि गास्वाल्य देश एशिया में अपने साम्राज्यवाद का सुगमता के साथ विस्तार कर गर्के। ग्रेट ब्रिटेन, फांस, स्पेन, हार्छण्ड, पोर्तुगाळ आदि यूरोपियन देशों ने इस स्थिति का पूर्णरूप से उपयोग किया और एशिया के बड़े भाग को अपने अबीन कर लिया । जिन देशों को वे राजनीतिक दृष्टि से अपनी अधीनता में लाने में समर्थ नहीं भी हुए, वहां भी उन्होंने अपने आधिक साम्राज्य का विकास किया और कुछ समय के लिये जापान, चीन आदि देश भी यूरोप के वशवर्ती हो गये । इस दशा में अनेक विचारकों ने यह प्रतिपादित करना प्रारम्भ किया, कि पाश्चात्य लोग नसल व जाति की वृष्टि से एशियन लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है, और ईश्वर ने उन्हें यह कार्य सुपुर्द किया है, कि वे एशिया व अफीका के लोगों पर शासन करें और इस महाद्वीप के लोग पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने में ही अपना हित व लाभ समर्बों ।

पर ये विचारण इस बात को भूल गये थे, कि यूरोप के लोगों का यह उत्कर्ष केवल सामित्रक था। इतिहास में अनेवा सिंदयों तक एशियन लोग ज्ञान, विज्ञान गर्म व सम्भात के क्षेत्र में यूरोप की अपेक्षा अधिक उन्नत रहे थे, और इसीलिये वे संसार के बहुत बड़े भाग में अपनी सम्यता का प्रसार करने में समर्थ हुए थे। राजनीतिक व सागरिक दृष्टि से भी अनेक बार एशियन लोगों ने यूरोप के अच्छे बड़े भाग को अपनी अधीनता में रजने में सफलता प्राप्त की थी। उन्नीसवीं सदी में जो यूरोपियन लोग एशिया में अपना प्रभूत्व स्थापित करने में समर्थ हुए थे, उसका कारण यह नहीं था, कि पारचात्म लोग एशियन लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। इसका वारण केवल यह था, कि आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान की जो असाधारण उन्नति हुई, उसका प्रारम्भ यूरोप में हुआ था।

गर ज्ञान, विज्ञान व विचार किसी देश विशेष की सम्पत्ति नहीं होते । प्राचीन काल में चीन, भारत और अरव ने जो नये आविष्कार किये थे, उनके कारण इन देशों को सामधिक रूप से यूरोप व अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने का अथसार प्राप्त हो गया था । इसी प्रकार आधुनिक युग में यूरोप में जो नये आविष्कार हुए, उन्होंने नामधिक रूप से यूरोप को उत्कर्ष का अवसर प्रदान कर दिया था।

एक सदी के लगभग समय में एशिया के विविध देशों ने पाश्चात्य व आधुनिक शान विज्ञान व विचारसरणी को अपना लिया। परिणाम यह हुआ, कि जापान, चीन, भारत आदि एशियन देश भी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुए, और अब बीसवीं अदी के मध्य भाग में पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद व उत्कर्ष का प्रायः अन्त हो लिया है। जापान और चीन संसार की प्रधान शक्तियों में गिने जाने लगे हैं, और अब वह समय दूर नहीं है, जब कि भारत, इन्डोनीसिया आदि अन्य एशियन देश भी पाश्चात्य देशों के समकक्ष होकर संसार की सम्यता और राजनीति में अपना समु-चित स्थान प्राप्त कर लें। अब एशिया जाग गया है, वह उन्नति के मार्ग पर बड़ी तिजी के साथ अग्रसर हो रहा है। व्यवसाय, न्यापार, ज्ञान, विज्ञान, सम्मता आदि सब क्षेत्रों में वह उन्नति कर रहा है, और यह असम्भव नहीं कि प्राचीन काल के रामान भिवास में भी संसार का नेतृत्व फिर नसके हाथों में आ जाय। पाइचाल जगत् ने भोतिक विज्ञानों के सम्बन्ध में जो उन्नति की है, उसके कारण वह अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सका है। गंसार में युद्ध का भय बहुत अधिक वढ़ गया है, और मनुष्य अपनी वैज्ञानिक खोजों को परम्पर संहार के लिये प्रयुवन करने में ततार है। एशिया के निवासी भौतिक उन्नति के साथ-साथ आध्यातिक और मानव गुणों को भी महत्व देते रहे हैं। आज जब एशिया भीतिक उन्नति में भी मृरोप और अमेरिका का समयक्ष होवर संसार की राजनीति में अपना समुवित स्थान प्राप्त कर रहा है, यह अवश्यमभावी है, कि वह मानव जीवन सम्बन्धी अपने उन्न आदर्शों के अनुसार संसार की रामस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर और इस प्रकार भानव समाज के हित व कल्याण में महायक हो।

राष्ट्रानुकर्माणका

अगृह्नात्यो ३३० अड.कोर वट ३५० अनाम ३२, ३८, ७८, ७९, १३१, १३४, ३४६-५५ अनावत ३६८ अस्द्रेन्द्रा २०४ अन्धः वलच १६३, १६४, १९० अफगानिस्तान २१, २२, २६, ३६, १९८, १९९, २०४, २१३, ४५२ अफ़ीका १८, २१, ५३, ७४, ८९, ८९, ९५, २६७, ३७७, ४८४, ४९१, अबीसीनिया ४५२, ४५४ अमते रसू-ओमीकमी ५३ अमेरिका १७, १८, २१, ४६, ६१-६४, ६९, ७२-७४, ७७-४१, ९६, ९=-१०१, १०=, ११०-११, ५१३-१८, १३०-३२, १४१, १ मन, १४९, १४८, १६४, १६४, १७४-७५, १८६, १९०, २३६-३७, २४२, २४७-४८, १ै५२, २५५, २५७-५व, २६०, २६३-६९, २७२-७३, २८२-८९, ३०१. ३०४, ३७३, ३७९, ३८२, ३९१, 3 4 K, 805, 809, 887, 885-प्र, ४५५-५६, ४६१-६३, ४६६-७४, ४७७-६२, ४५७, ४५९, ४९१-९८, ४००, ४०२, ४०७-१२, ४२६, ४४०, ४४३-४४, 🙀 ५४९, ४४७-६३, ४६९, ४७२, ५ तर्- वर, ५ तत, ५९० अमीय २४३, ४५८ अम्बोयना ४५४ अयोध्या ३५६, ३५७, ३६९

अरब १६, २१-२३, ४०, ५३, २१४, , ३६२, ३६९, ४९१ अराकान ३६८-७१ अराकी ३००, ४७५ अरीता ४६७ अलाइड कीसिल आफ जापान ५४९ अलेवजीण्डर प्रथम ४३ अलेक्जान्द्रिनो कास्तो ५४६ अलाम्प्रा ३६९ अल्लाई १९५ अल्वुकाकं ३६२ अल्युतियन २८५ अल्सालवदोर रिपटिलक ३९५ अशाई शिम्यून ३१५ अशीदा हिलोशी ५५५, ५५६ अशोक ३०, ३१, २१३, ३६८ आजाद हिन्द सरकार ४८९, ४९० आदित्य ३६१ आन्हर्र प्रान्त २२९, २३३, ४१५,४१८ आवे, जनरल नोव्यकी ४७७ आर्मीनिया १४५ आस्र नदी ६४, ७८ बाल्मा आता १९६, १९९ आवा राज्य ३६९-७१ आसाम ३७०, ४८९, ४९० आस्टिया १८८, १८९, २५७, २८७, २८८, ४४२, ४४४, ४६३ आस्ट्रिया-हंगरी ४८, ११०, १७७ आस्ट्रेलिया २६७, २८६, ३७७, ४८२ ४८४, ४८९, ४९१, ४०१, ४४०. 488 उचांग ४३४ इजानमी ५३

उजराईल ४६२ इटली ३६, १२१, १३१-३२, १६८, २३६, २४१, २४६, २६६, २६९, चन्दर, चन्दर, एत्रह, चन्दर, व्रर०-११, ३७६, ३९१-९२, ४०८-०९ 843-48, 860, 868, 888, ४५१-५६, ४६१-६२, ४६८-६९, ४७३, ४७७, ४९३, ४९४, ५३१, प्रच्य, प्रप्रद, प्रप्रद, प्रप्रु डण्हो-नायना १८, २२, २६९, ३०३, ३२४, ३४०, ३४२-४४, ३७३, ४३५, ४५६, ४५७, ४६३, ४६५-६६,४७१-७२,४=३,४९७,४१५-28, 488, 454-58 उपरोशीशिया १८, ३२४, ३३३-३४, ३३६, ३३५-४४, ३६२-६३. ३७१, ३७३, ३७४, ४४४, ४६३, ४६६, ४६६-६९, ४७१-७२, ४८३-८८, ४९०, ४१४, ५३४-४३, ४४९, ४८२, ४८७, ४८९ इती, प्रिस १०७, १०८, २७१, २७२, 285-88 इलागाकी, काउंट १०६, १०७, २९२, 288 युनाई ३००, ४७३-७४ इन्ये मिशी ४७१ इम्पीरियल रूछ असिस्टैण्ट ऐसोसि-येशन ५५२ इम्प्राज ४९० इयासू ६६, ९१ इली १९९ इवाक्रा १११, ११२ द्रंग्लैंग्ड ४३, ५८, ७२,९०,९२,९६, ९५, १०५, ११३, १३२, १४१, १४४, १६३, २०६-०८, ३०७, चेरह, ४४०, ४९४

ईजिन्ह २९, ४३, १३४ र्दणान १८, २१, २२, २४, २६, ५०, २०४, २०६, २१७, ३७३ र्टम्ट इंडिया कंपनी ५५, ५७, ५९, ३७७ चर्डभाग १९८, २१५ जनरी एशिया २२, २३, २५, ५४, ११९, १२३, १२८, २६७, ४६० चद्गरी मां ३५ उपरका हिन्द २१३, २१४ उराल १७, १४५ उम्मानी १९७ उलान नातोर २०० उगुरी ६४ मबस्दा देशित शिम्मान्तरी ६१, ६२, ६५, - इ.इ. ७५, ५७, १००, ११६, ११वं, १५०, २२४, २३९, २४२, २७७, २६९, ३१६-६०, ३७३. चिद्धार, इंद्य, रश्य, ध्रक एविवनी ५४३ एण्डि कोचिन्दर्भ पंतर ४४९, ४५०, 888, 888, 8190 एष्टि फासिस्ट पीपल्य फ़ीउम छोग 樊章名, 樊章至, 吴章水 एन, पाक हेन १६२ एशिया माडनर २१, ३४, ३६, ५३ ओकामा, कालण्ट ११३ ओकुमा २९२-९७ आकोदा ४७५, ४७६ ओरामेना, गाउपति ५४३-४६ ओगाना ६०२, ३१४, ३१४ अगकारथोम ३५० आंग सान ५३१-३४ नात्गुरा २९५, २९६ कनाडा ५७, २६७, ३१२, ५४९ मानिष्का २१३ .कत्पय्सियस २६, २९, ३७, ४७-५०,

९४, २४४, ३२०, ४२० ४३९ क्रमाल पाचा रदद भागता २४८-५०, ३४६, ३६१ कम्बोदिया ३२, ३४६, ३४६-५६, कराक्रम ३४, ३५, १९६, २१७ कल्पान २०० कशिंग ६१ काओं कांग ५७५ काओंत्सु ३२ कार्गाजिमा १०२ कातायामा ५५५ कालो २९६, २९९ काल्सू १९७, १९६, २१६, ४२१, 835, 856 कारस्टॅस्टिनोघल ३४, ४३ *सामनात्या २७० सामा सागर ३४-३६, २१७. काशगर १९६, २१४ क्तिआंगकी २२९, २३२, २३३, ४१४, ४१६-२२, ४३४, ४४३ जिली १०४, ५५१, ५५७ किन राज्य ३३, ३६ निगमनामा ३६ निम इस नेन ४६४, ४७०, ४७१ नियाक चाक १२९, १७७, १५४, १९०, २३७, २३८, २८०, २८१ कियांगम् २४८ कीफ ३४ कीम्या ४५७ ्रमुआला लुम्पूर ३६५ णुआंग ह्सू सम्बाट् ७४, १३४, १३४, १५३, १५६, क्ओमिन्तांग दल १७४, १७४, १८४, २१९, २२१-२४३, २६२, २६६, २५९, ३५४, ४०३, ४०८,

४१०, ४१५-२०, ४२९, ४३९-४३, ४५८, ४९६, ४९९, ५०१-१४, ४४९, ४७४-७९, कुओमिन्तांग सरकार १९३, २१९, २३०-२३४, २४१-४३, २४२, २४७, २८९, ३८२-८४, ३८६, ३९२, ४०९, ४१४-२२, ४२५, ४२७, ४२९-३१, ४३७, ४३९, ४७८, ४८२, ४८३-८४ कुनलुन पर्वतमाला १९६, १९७ कुबले खान ३५, ३६, २०२, २१७ कुरील द्वीप ९५, ११९, १२०, २७०, २५४ कुलांग्सू द्वीप ४५६, ४६० क्चू १९८ केदाह ३६५ नेन्सेईकाई दल २९३, २९४, २९६, 299, 299, 300 केब् हीप ३२७ केलान्तन ३६५ गौन्टन ४८, ४४, ४६, ४९, ६०-६४, ६८, १३३, १६३, १८४-८६, १९१, १९३, २२१, २२३, २२४-२७, २३२, २३४, २८८, ४१४-१८, ४२९, ४३२, ४४८, ४४०, ४५५, ५१२, ५५३ क्रीपृचिन फादर्स २०४ करो कान्फरेन्स ५६१ कैरोलिन द्वीप २७९ कैलिफोर्निया ७३, ९६, २६८ कैश्नलो दल २९२, २९३ कैस्पियन सागर २१, ३१, ३२, ३४, ३६, २१४, २१७ कोकस कीलिंग द्वीप समूह ३४६ कोड्. पो नदी १९७ कोड़, जो २०१

कोचीन चायला ३४६, ३५१-५४, ५२१ कोनोय, त्रिस ४७६-७८, ४८०, ४५२ कोम्सोमोल्स्क २० कोगा ३१६ कोरिया २२, ३०, ३१, इट, ८४, ८६, ११८, १२०-२७, १३९, १४२-४५, यह९-७४, २७९, २५९, २९६, चंतर, बेचर, बेचबे, २७७, वन्ध्र, इतह, ३९७, ४१२, ४०९, ४१०, प्रकृत-६२, ५७३, ५६१, ५८२ कालींग ५६, ५९, ६१ कांग हुनी, सझाट ३७, ४३, ५५, २०४, २१४, २१६ कांग व केट १३२-३५ नपना ५१, ७१ भयाग झीप ५३, ८४, ५९ नयोती ६२, ९४, १०६, ११६ भीभियन युद्ध १८४ भगी-अभीता का समझोना ४६० भौतिया । ४४६ बलाइय ३६९ नवांगचाळ की खाड़ी १३०, २६६ क्यांगत्म प्रान्त १३०, ४१६-१६. '४५२, '४२५ सर्वागणी प्रान्त ७६, ४१५-१८, ४२५, 838, 283 स्वान्त १३९, इत्य, इत्य, इत्या, 300, 390, 393, 600, 604-04, 605-90, 80% वर्षाज्याकः प्राचा ४२१, ४२२, ४२५, 138 नवेई ह्वा २०० वयेजोन, राष्ट्रपति मानुआछ १४३, 4.68 नसंवियर, फ्रांसिस ८९, ३३५ सम्बाजीम २०६, २०७

मोलाच १९६, २१५, २१४ क्रिन्मोड बंदे वचन, सुधार २०१ किन्। २०१ मलींचा २०७ - मनुबन् २१२ - भाइनिया ३६७ भारतार ६१३ गिभालम, समाट ३५१ ंगिहिंगल ५०१ मुआम द्वीप २०४, उन्ह ्गुण वर्धन १३८ ग्लाम अंगरी पर्वतमान्य ३७१ भूनकी न्यान २०३, ०००, ५१५ मोर्ला मध्यभल १५९, २००, ५१७ गोरमंत्रिम ४,५६ गोष्य हुए विहास २१४ ग्यांची १९७, २०७, २०७, २००, भीम यक, २५२, ४५३ भन्नी ३५७ चल, भड़ मनार १९७ सम्मा भाजन एउट चर्चना १९६ चिनिल ४९१, ४५७, ४४६ अहर १९९, ५१९, ४०४, ४०५, ४३४ लाइका मनंब्द्य स्टीम 'तेविमेशक यागनी दश वाद्यीव पीपत्म रिपन्तिका १६२, y 5 3 चाङ वंश २७ चित्राजी लंग पुनर्याम - निश्यविद्यालय निग्नु छग, सम्राट् ३७, ३६, ४ 🎉 प्रेस, प्रेप्स, ७४ चिंग कियांग २४३ चिन वंश ३०, ८५, ३४७ चिन्कियांग ६०

चिन्धा १९६, २११ चिन्धा उ९१ १नेमांग साई संस १८५, २२६-३४, २६२, २८६, १८३, ४१५-२५, ४२६-३२, ४३४, ४३७-४८, ४५१, ४५६, ४५८-४२, ४६६-६७ ४७०-७१, ४७६, ४९०, ४९५-५०७, ५१०-५१३, ५५९, ५७४, ५७५, ५६२-६४ चिन्छी भाग्य ६१, १३४, १६१,

नीनी वृक्तिस्तान २०१
न्तृन, प्रिम १४६
न्तृम्ती घाटी २०७, २०६
न् तेष्ठ, अनरल ४७५
न्ललस्त्रकर्ण, राजा ३४६, ३४९
नेकोस्लोबाफिया २६३, २६६, ४९०, ४९३,

तम्तेष्ठ ४०३ विकृकी संघि ७२ चेन कुओ कू ४३९ वेन बुंग पौ २३२, ४१५
वेन वी तांग ४१६
वेन वी तांग ४१६
वेन ली फ् ४३९, ४४०
वांऊ एन लाई ४२४, ५७६
वोश् १०१-०४, २९१, २९३, ३८०, वंगेज खान १७, २१, ३३-३६, १४९, २०२, २१४, २१७, ३४७, ३६९ वांग विह तुंग १३३, १३४ वांग त्यो लिन १९२, १९३, २२५, २२६, ३८९ वांग लांग ४७५
वांग हमुएह-लिआंग २२६, २३१, ३६२-६४, ३६७, ३९९, ४०३,

चाग ह्मुण्ह-ालआग २२८, २३१, ३८२-८४, ३८७, ३९९, ४०३, ४१४, ४०३, ४२४ चांग हसन १८३

चुगक्तिम १९९, ४३२, ४३३, ४३४, ४३८, ४४०-४२, ४४५, ४६२, ४६३, ४६६, ४६९, ४७२, ४९०, ४९६, ५०३, ५०७, ५१०, ५१२, ५१३, ५१४, ५८४

चुगुचक १९७, १९८

त्रमंती ३५, १२१, १२६-३२, १३७-३, वस्ती ३५, १२१, १२६-३२, १३७, ३, १८, १६६, १७४, १७७, २३७, २५९, २६६, २०६, २०६-६४, २६७, २६६, २७६, ३०३, ३०१, ३११, ३७३-७६, ३७९, ४१३, ४१४, ४१७, ४४०, ४४६, ४४९-५५, ४७५, ४४७, ४४६, ४७०, ४७६, ४०७-०९, ५१६, ५३१, ५३५, ५६०

नेन मुओ मू ४३९ जहील ३८८, ३९१, ४०२-०४, ४१२.

४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२२, तक्छा मनान मन्यक १९७, १९६ 798.

जापान १८, २१,-२६, ३१, ५२.१४१, वर्गका, वस्त २९९ १५७, १५९, १६४, १६६, १७४, - वचामस्मि ३६९ ७१ १७७, १७६, १८५-९१, २०४, तस्क सम्भीता ४१० २१४, २२०, २२७, २२६, २३२, तक्विमताई पर्वतमाला १९४ २३६-३६, २४०-४४, २५०, ताओ कुआंग, सम्रात ७५ २५५-५७, २६०, २६३, २६६ - लाई फिम बिद्रीह ७६-७व ५१०, ५१३ - १६, ५२६ - २७, ताचिएनल १९६ प्रवल-वव, प्रवह-वज, प्रवब-४५, तारिम नदी २१५ प्रद=प्रद, प्रप्रज=द्रच, प्रजल, 复古集, 其代名

जावा २२, ३१२, ३३३-३८, ३४२-४४, ३६१, ३६५, ४८४, ४८४, ४८६. **夏**岛岛-188

जिम्मू नेतो, सम्राट् द ३, ५४ जियुती कल २६२, २९३, २९४ जुलियाना, साम्राभी ५४२ जैसार मध्यवाय ६९, ५९, ५०,२०१ जीवन्स् ५४२, ५५६ जीग जाकना ५४१ जोहोर ३६२-६५ दर्नी २२, २४, २६, ११०, १७७,

२८८, ३७३

खेम्मार्क ४६३, ५८२

टर्गर, बीप्टन २०५ टाईलर ६१ टापट, जनरलं विलियल हाबर्ड २३१ टिगिसा १७, ३१, ३४ सूमीन ४९१, ५०४ डच-ईस्ट-इंडीज ४६४ डम्ई, कमोडोर ३२९ खनंककं ४९४ विन्डिंग्स ३६४

च्रुच्, २१५ ३२४,३६६, ३७४-४७९, ४८०- ताकाहासी, का उन्ह ४९६, ४७६ तामक, लुई प्रदेश नाहिया जाति २१६ तिएवधारा पर्वतमान्य १९५, १९६ 223

तिकात १८, २१/२६, ३४, ३४, ३५, प्रव, १००, १३९, १६४, १९४, 90, 208-84, 280, 2864 ३२२, ४२१, ५७७, ५७६

सिमोर ३२४, ३२४, ३२४, ४४४, ३७३, ३८४ विह्या १९७७९

सीन्सिन ४८, ६४, ७०, ७७, ८१, १००, १३४-३७, १८५, ४४०, स्थर, ४०९,-११, ४२०, ४४०, ४११, ४५६, ४५०-६०, ५१० -

तुआन ची जुई १७२, १८१-८८, १८७-९३, २२४,

स्वाम १५३ त्रेके १८, २६, ३४, ५३, १४५, २६०, 387

नुभिन्तान २६, ३५, १४४ नुफीन १९६, २१४ तेराउची, काउन्द २९७ नेल अवीव २० र्तिपेट प्रदार, प्रदार

तैवान २७० तेको, गग्राट ३०१ तीकियो ११५, ११६, १४९, २९५, इत्र, इर्ड, इर्इ, ४४९, ४७४, 808, 269 तीकुगावा कुल ८८, ८९, ९१-९४, 00 808-08 तोजा, जमग्ल ४७८, ५५१, ५६२, प्रयंत, प्रयंत तीन्त्रित इ४६-४८, ३४१-४४, ४२१, लोसा १०३, १०४ लांग यंश ३२, २१६, ३४७ तांग-बाओ-बी १६८, २७२ तंग चित १३% राम मेंग हुई १४९, १७४, २२१ संगद्यम ७९, २५% न्या ३६० तांचिंग ७६, ७९, ४२? लोग साक विद्यास १०४, १२५ त्माओं कुन १९२ हसाओं ज छिन रियान शी रूप, ३० हिंसम लाओं १२९, १३०, १७७, २३७, २७८, २७९ त्सिनान २३७, २७९ त्त्ह् सी ७४, ७६, १३४, १३४, १३७, आहिलेक ३५५, ३५६, ४८३, ५२४-70, X59-90 थाकिन नू ५३४ थेबी ३७१ है गाल, जनरल ४१८ वलाई लामा २०२-०५, २०७-१०, शिनिष्ता ५१२ २१%

दक्षिण पश्चिमी एशिया २२, २४, २६, र्द०, र्दर् दक्षिण पूर्वी एशिया २२, २५, २१३, २६६, २८७, ३२४-३७४, ३७६, ४३०, ४५४, ४६०, ४६४-७३, ४७=, ४=०-९५, ४९९, ५१५, प्रह, प्रव, प्रह, प्रव, प्रव, ५४८-५१, ५४९ दार्जिफ २०५ देवा ४९७, ५१६, ५१७, ५२८ दैम्यो ८७, ८८ दैग्न ३८५ द्वस् २०२ नाकाम्रा ३८७ नागासांकी ८९, ९२, ९४, ९७, ९५, नानिकंग ६०, ६१, ७७, १६३, १६४, १६६, १६८, १७१, १७२, १७६, १७९, १८१, २२६-३४, २४१, २४२, २४७, २८८, ३८३, ३८४, 344, ROC' RSO' RSR-5R' ४२७, ४२९, ४३१, ४३२, ४३४, ४३८, ४३९, ४४२, ४४४, ४४६, ४४७, ४७०, ४८८, ४९३, ४९६, 880' X03' X08' X85 . नानिका की संधि ६१, ३८२, ३८३ नानचांग ४३४ नानिंग ४३४, ४३५ नारफोक ९७ . नालन्दा ३२, २०१, २१२ नाव ४६३. ५५२ निकोलम दिनीय जार १२७, १४८ विविगी-नी-मिक्तिती हर, दे वीद्रुग्डिंग्ड ४६७, ५६२

नीदरलैण्ड उन्हीज निवित्र एडिमनि-म्द्रेशन ५३७ नीदण्लैण्ड ईस्ट इन्डीज '४६७ नेग्री सेम्बिलान ३६५ नेपाल ३६, ८८, २०१ नेपोलियन १६८, १६९, १७८, ३६२ नैपियर ५९ नाम्या, एड्सिंग्ल ४७०, ४७२ निगपो ६१ निग्हिसआ १९९, २१९ न्यू गाइनिआ ३४६, ४८४ न्युच्याग ६४ न्युजीलीण्ड २६७, २८६ पनामा ३६१ पर्छ हामबर ४७३, ४७८, ४८०-८३ पशिया १९, ३५, ३६, ४३ वाओंकी १९८ पाओंती २०० पाकिस्तान २२, ५८२ पागन ३६८, ३६९ पामीर पर्वतमाला १९५, २१३ पाल, राधा-विनोद ५५७ पिरेनीज १७ भीराज व सेत ३७ भीपनस कान्सन्टेटिब कान्पारेन्स ५०४ पु यी, सम्राट ३८८ पूर्वी एशिया २२, २४, २६, ५४, ५६, ६४, ९८, ११८, १४४-४७, १८६, १९६, २३६, २६६-५०, २९६, इरुइ, इर्७, इ४२, ३६२, ३६७, ३७६, ३९४, ४०६, ४०७, ४१३, 868' 835' 838' 884-80' ४५०-५६, ४६०-६४, ४६४. ४६९, ४७७, ४७८, ४९३, ४९४, प्रइ६, ५४४, ४४९, ४४१, ४४९,

450, X08-92

पेड्यांग युनिवसिटी २५४ मेकिंग १८, ३३, ३४, ३७, ३८, ४४, प्रश, ५१, ६४, ६४, ७१, ७२, ७२, १२०, १२७, १२९, १३६-३८, १४०, १४१, १५३, १५५,-५19, ११६०६२, १६६, १७६, १७६, १७५, १८१-८४, १८७, १८९-९३, २०४-०९, २२१, २२४, २२व-२९, २३२, २३व, २४४, ५४०, २४४-५८, २६४, २७७, २८९, २४३, ३६१, ३९१, ४१०, ४१३, ४५% इ४, ४४३, ४८४, ४५६, ४५९, ५१०, ५१२, १७७, १वर-वर नेम्बोर्ड ४३४ पेक् ३६९-७१ पैता, मार्जल ४६५, ४६६, ४६५, ४९७, ५१६, ५१८, ४१८ पेनांग ३६४ मेरी, कामोधेर हुन, एक, ५७-५५, 300 पेश ७५ पेक्टिस ३६४ पेरकादोण्स १०६, ५८३ गेहांग ३६५ पॅरिस १८, ९४, ३५१, ४५३, ४६५, 888, 488 पोट्सडम कान्करेन्स १४८, ११०, ११७ पोटंस्माउथ १४६-४६, २७५-७७, २९४, २९६ पोर्त्त्वाल ५३, ५४, ९०, ५२, २०४, २३६, ३२६, ३२६, ५४३, ३४७, ३६२, ३७३, ४७१, ५९१ पोलैण्ड ३५, ३६, २८८, ४५३, ४६३, ४७०, ४८३, ४८२, ४९० प्रदीत, लुआंग ५२६, ५२७

पशान्त महासागर २१, २२, २७, ३१, फ़ेडरिक द्वितीय ३५ १३२, १४०, १४१, १८६, २१४, २१७, २३६, २६६, २६७, २७०, २७९, २८४-८७, ३२३, ३२७, ३६१, ३६७, ३७४, ४४८, ४४९, ४५१, ४५५, ४५६, ४६०, ४६९, ४८०-५२, ४९१, ५३६, ५४७. ४ ४९-४१, ४४९, ५६० प्रशिया १०८, ११२, १६६, ३५२ प्रोग ३७० फर्भ प, आनार्य २०२ फाइयान ३२, २१४, २३३, २३४ फाम पुडन्हो दल ५१८ फार ऐस्टर्न कमीशच (सुदूर पूर्व कमी-गन) ५४९, ५५० ४७ किंगो अभिनालेण्य १४८, ५६२ ं फिल्किप द्वितीय ४३, ५१ फिलिंग्गीन १८, २२, २४, ८९, ९०, फ्रांसिस्केन ६९, ९० ९०, ९२, ९७, १३२, १५८, रद्द, २७२, २५४, ३१२, ३२४-३३, ३७३, ३७४, ४४९, ४७०, ४८१, ४८२, ४८६, ४८७, ४९०, ४९१, प्रथ, प्रदे, प्रव-४९, प्रप्रः, प्रदेश, प्रतरं, प्रतर फ् भिएन प्रान्त १३१, २२९, २३३, २७०, ४१५, ४१६ प् ची ६१, ४६० पुजिमा, लेफिटनेन्ट ४७५ फुजीबारा २९५ श्रुनान ३४९, ३४६, ३६१ क्या कुओ चंग १८३, १९१, १९२ बलोरिया ५८२ किंग यू हि संआंग १९२, १९३, २२४, बाओ दाई ४१९, ४२१, ५२४, ५८६ २३१, २३२ फांको ४५४

इ४, ३८, ६०, ६४, ६६, ११९, फ्रांस ३७, ४३, ६२-७, ७२, ७४, ७८, ७९, ६१, ६२, ९७, १००, १०२, १०८, ११०, ११२, १२०, १२३, १२७,१३०,१३२-३४,१३७,१४०, १६४, १६५-७१, १७४-७८, १८२, १८५, २०६, २२७, २३६, २३९, - २४०, २४१, २४६, २५५, ३५९, २६०, २६३, २६६, २६९, २८१-८८, २९४, २९६, ३०३, ३०४, ३०७, ३१०, ३४०,-५२, ३६०, ३६२, ३७१, ३७३, ३७४, ३७७, ३९१, ४१३, ४१४, ४३३, ४४४, ४५०, ४५३-५८, ४६२, ४६३, ४६६-६८, ४७१, ४७२, ४७४, . ४७८, ४८३, ४९३, ४९४, ४९७, ५००, ५१२, ५१५, ५१६, ५३५, ४४९, ४४८, ४६०, ४८४,-८६, 180 वगदाद ३५, ५३ बटेविया ३३६ बताग १९६ बरमा १८, २१, २२, ३८, ७१, ७८, ७९, ८१, ९३, १२०, १४९, २०५, २६७, २६८, ३०३, ३२४, ३४६, ४५६, ४६२, ४७१, ४७२, ४५४, ४८६-९१, ४९७, ४१४, ४१६, ४२६, ४३०-३४, ४४९, ४८२, 150-90, · बर्कुल १९७, १९५ बातू खा १७, ३५ बामो ५३१

वाली ३३३-३७, ३४३, ४५४, ५३६ बाल्कन १७, १६८ विस्मार्क १४६ ब्दा, महात्मा १७, २९, ३१ बङ्जी मुजुकी ३०८ बती, मम्राट ३४७ खुर्बो १६४, १६८, २८७, ३४० बेल्जियम १७७, २३६, २४०, ४५२, ४६३, १३५, १४०

विकाल की जील ४६१, ४७७ वंबिलोनियन सभ्यता २१ बोबसर १३४-३७, १४०, १४१, १४०-५४, १८२, १८७-८९, २३४, २३८, २४८, ४०९, ४१०, 824

बोगल ज्याजी २०४ बोनिन हीन ११९, २७०, २८५ बोरीडिल, माडकेल २२२, २२५ यांगियों ५२, ३३३-३४, ३३७, ३३८,

३४१, ३४३, ३४५, ३४६, ३७३, बोल्शेविक फान्ति २२५, २८३ बीस, गुभासचन्द्र ४६९ बौद्ध धर्म २०१-०३, २१४,-१९, ५५४ बीगमाना ३५७ क्रिटेन ५९-६६, ७१, ७२, ७८, ७८,

म् १, मर, ९६, ९७, १००, १०२, **१**१०, १२१, १३३, १२७, १३०-३४, १३७, १४४, १४७, १५१, १६६, १६८, १७४, १७७, १७८-१८२, १८४, १८६, १९६, २०४-०६, २०८, २०९, २२७, २३६, २३६, २४०,-४२, २४४, २४७, मत्मुओका ४६४, ४६७, ४४१, ४४% प्रप्र, २६०, २६३, २६६-७२, २७८-६६, २८९, २९३, २९४, मल्युकाला २९२ २९८, ३०२-०५, ३४६, ३५०-X२, ३६०, ३६२, ३६४-६६,

३७०-७४, ३७७, ४१३, ४१४. दर्भ, दर्भ, ६४५-मूच, ४५०, 842-44, 840, 844, 862-683 697, 620, 640, 640, 720, 69,6-4,00, 403, 406, 420, प्रदेश प्रदेश, प्रवेश-वर्ष, प्रदेश, ४५३, ४४७, ४५९,-६१, ४६९ यून्य, यून्छ ब्रक्त, जम्स ३४५ असंधि ३४५ न्त्रमहरम् ४५५ क्लाबी बोस्तावा १२६, १४०, २६३, 7 mm 50 क्ष्मध्य ५०५ ब्लो-ब्राध्ययं वसी, जामा २०३ वत्तरपूर्वी एशिया ४६६, ४७६, ४७६ भारत, भारतवर्ष १०-१९, २१-२३, ्रह, ३०, ३१, ५०-४, ५६, ५१३ ्षत, यह, हुई, २३४, १४४, १४४, ्रेड्य, र्द्रि, घत्र, घत्र, घत्र, घर्ष, २६७, २६५, २०६, ३०२, ३०४ ३४७, ३४१, ३६१-६४, ३६% . ७२, ४७७, ४४४, ४७१, ४६७-

९१, ४९६-५०१, ५१६, ५२६, प्र४०, ५४%, ५८२, ५९१ - भदान २०७

भगव्य सागर ५३, १६६, २७९, मन्दर, मन्दर, उद्र, ४५४ सकाओ ५४, ५५, ६१, ७४, ९६ मिकनी, काउस ४७६ मणिपुर ४५५

पू पू ज मध्य एजिया २१, २५, ३१, १४४,

१९८, २१३, २१७

मनीला ३२७-२९, ४९० मन्दारिन ४८ 'मकादी, जोसे रिजाल ३३० मलक्का ५३, ५४, १८९, ३२७, ३३५, 365-68 गलाया २१, २२, ४४, १४८, ३१२, वर्ध-२न, वर्ध, व्हर्व्हन, ३७३, ४७१, ४७२, ४८१-९१, ११५, १२६-३०, १८६-९० मलाया नेशनलिस्ट पार्टी ५२९ मलाया युनियन ५२८-२९ महायुद्ध १७६-८०, १८५-९१, २३४-३६, २४९, २६६, २७७-५७, २९६ २९७, ३०३, ३०४, ३०८, ३४०, ३५४, ३५९, (१९१४-१८) ३६५, ३७७, ३९०, ३९२ महायुद्ध (१९३९-४५) ३२४, ३२५, ३६८, ३७४-७६, ३९८, ४१४, ४३०, ४३३, ४३४, ४४६, ४४८-९४, ४६१, ५७४, ५५४, ५५६-९० महेन्द्र बर्मा ३४९ माओत्री-तंग ४१४,४२२,४९६,४०१, ४०४, ४७४, ४७८, ४७९, ४६२, 鼠哺草, 鼠螨属 मागॅरी ७१, ७२ माण्डल ३६८, ३७१ माण्टेग्यु चेम्सफोर्ड स्थार ३७२ मारिआना द्वीप २७९, २८४ मार्को पोली ३६, ८९, २०४ माक्सं, कार्ल २२०, ४२० मार्शल द्वीप २७९, २८४ भार्शल, जनरल ४०४, १०३, ११० मास्को २२७,४६४, ५६२,४६३,५९७ **श**निआओ जाति १७८ विकटी भार्छ नुवार चित्सुई ९४, ११६, ३७८

मित्सुबिशी ११६, ३७८ मिन्दानाओ ३२६ गिन्सेइतो २९९, ३००, ३७८, ४७४. **ኢ**ሂሂ मुकदन १४७, २२८, ३८७, ३९० मुगल १८, ४१, ६२, १६२, १८४ मुत्सुहितो, सम्राट १०१, १०३, ३००, 308 मनरो ४०६ मुसोलिनी ४१७, ४२५, ४७३, ४५२ मुहम्मद द्वितीय ५३ मेईजी, सम्बाट १०१, १०३, १०४, १०६, ३००, ३०१, ३१४, ४४२ मेकोङ्ग नदी १९६ मैकआर्थर, जनरल ४८२, ५४३, ५४९, ५५०, ५५६, ५५९, ५६८ मैगेल्लन, फर्डिनन्ड ३२७ मैनिशी शिम्बून ३१५ मोरिसन, राबर्ट ७० मोलक्का ३३३. ३४१ मोलोतोव ५६७ मगकूट, राजा ३५७, ३५८ मंगु खां ३९ मंगील १७, ३३-३६, ५१, ८९, १६५, १९८, २०२-०५, २१४-२०, ३६९, इन्प्र, ४०३, ४०४, ४७८ मंगोलिया २२-२४, २८, ३४, ३४, ३८, १९४, १९४, १९९, २००, २०२. २०३, २१२, २१६-२०, २३४, २८०, ३२४, ३८४, ४०२-०६, 865 856 R\$0 R\$0, 838 R88 ,४४८-४०, ४६१, ४६४, ४६६, ४७४, े ४०८, ४१२, ४७८, ४८२ मंचू ३६-३८, ४६-४८, ४१, ४२, ४४, इ४, ७४-७७, १२२, १३४, १४९-ं ७१, १७६, १८२, १८३, १९४, १९९, २०४, २०४, २०९, २१०, २१४, २१८-२१, २४४, २४३, २४६, २६१, २६२, ३४६, ३५२, ३५६, ३६४, ३८८, ३९६, ४३६, ४७७

मञ्च्कूओ २८५, ३७६, ३८७-४०९, ४१४, ४३१, ४३४, ४४४, ४४४, ४४६-५०, ४६१, ४६५, ४६६, ४७१, ४८६, ४९२, ४९३, ४९६, ५०५, ५२५, ५४८

म्यूनिय समझौता ४५० यातुंग २०५, २०७ यामागाता २९२, २९३, २९७ यामागोतो २९६, २९९ सारकन्द १९६, २१४ याळू नदी १२५ याळू नदी १२५ याख्टा ५०६, ५६१ यासुदा ११६ युआन वंश ३६, २१४, २१७. युआन शिकाई १२२, १३४, १३५, १५४, १५६, १५७, १६१-६६, २२१, २२९, २६३, २८०, २६१

यगोस्लाविया २८८, ४५३, ४९३

सुइदि २१३, २१६

्रमुनाइटेड नंजन्स टापोरेंरी कमीशन 4810. 7.8 to. ્યુનાદ્દે જ પછામાં વેગનજ બાર્યોનિએં બન प्रदान, प्रवाद यनान ७१, ७२, १३०, १७९, ५४६, ३४६, ३६९, ४२१, ४२२, ४३६, 885 गेदो ९२, ५४, ९९, १०२ , ११६ यंनहुसी शान २३१, ५३२ येनान ४२१, ४३३, ४४१, ४४२, प्रदा, ४५६, ४६४, ४९६, ४९९, X02-07, X06 यं ल यनिवर्शिदी ७९ योकोहामा ९७, ११७ योजी ४३४ योनाम मिल्युमासा ४७७, ४७५ यांशीतांगां दद मोबीबा ५५४, ५५६ योशी हिली ३०१ यंग हस्बेकण्ड २०६, २०७ यांग चींग ४२४ मांगन्से फियांग १७, २७, ३० गांगत्से नदी ४८, ६४, १३०, १६१, १९६, ४४३, ५१२ यम धिम ७९, ८० एही, सिंगभन ५६९-७५ राममान, चार ४०७ रामावली क्षीप ३६८ राम्ख्यी ३६६ फजबेल्ट १४६, ४५१, ४६९, ४७५, 850, 860, KXB चमानिया ४४६, ५५३, ५६२ ल्स २२-२४, ३४, ३६, ३७, ४३, ४४, ६३-४, ७२, ७८, ८२,९४,-१००, ११७, ११९-२३, १२६-३२, \$ 36-86 \$ X8-8X \$ 608 \$ 600;

१८४, १९४, १९७-२००, २०४-०%, २१४-१%, २२२, २२४-२८, २३४, २३६, २४७, २६२, २६७, २६५, २७१, २७४, २७७, २८१- लुई फिलिए १६० बर, २८७, २८६, २९४, २९६, लुई चौदह्वां ३७, ४३, ४१ २०१, २११, ३७७, ३६३, ३६४, लूई सीलहवां ३५१ ३५९, ३९१, ३९४, ३९६, ४०१, ल्कृचिआओ ४२८ ४०४, ४३३, ४४२, ४४८-४३, ४५१-६४, ४६९-७२, ४७७, ४९२- लुजोन ३२६, ४९० ९४, ५००, ५०७-११, ५३१,५४४, ४,४५-४१, ५,५९-६३, ६६५, ५७२, प्रतिरे, प्रवर्, प्रवय, प्रवर रूसो चाइसीज पंधर १२९ रीफल्स, हासरा रहेमपार्ट ३४४, ३६३ रोबलास् प्रहर रोगम सामाज्य ३१, ३३, ३४ शोमनोफ २८७ प्रमुख ३५०, ४६४, ४९०, ५३२ र्यन्य दीप सग्छ ११९ लगाम ९४, ४३३, ५३४ ल्याक प्रश्रेष लाओर्स २९, ४०, १२४ काओस इंडर, ३५१, ३५३ नगजागिस्ट ६९ लाबुआन ३४५ कासिंग इसी समझीता २५२ खिआओ तुंग १२६-२९, १४०, १४२, १४३, १४५-४७, १७७, १८६, विएत मिन्ह ५१८ क्षद्, ३९२, ३९३. कर, प्र लिक गाओं वी ४७४ , लिंगिन दैवस २३९ लिथुएनिया १४६, ४५४ विल्हिल्मना, रानी ५३५ निवीका भी १२३ वर्ग वर्ग वर्ग ची विक्र अंग १०४

र्ला युजान हुंग १६१, १६३, १८१-८४, 898 ली हुंग चाग ८१, १२४-२८, २५४ लू २८ लेटविया १४५ लेनिन २२५, ४२०, ५७५ लोम्बाई ३५६ लंका १८, २१, २२, ९३, २४६, २४८, २६७, ३६७, लंग कियासु ३६१ लारेल ५४३-४६ लिग जाति समझौता ५३०,५४०,५४१ ल्हासा १९७, २०२, २०४-१० वर्गास् ५४३ वारमा १४८ बाई, फ़ेडरिया ७७ वाशिगटन ५४९ वाशिगटन कान्फरेन्स २३६-४१, २५४, २८६-८८, २९८, ३७४, ३८१ वास्को डिगामा ५३ विएत नाम ५१९, ५२१, ५२२, ५५२, とこと २७५, २७७, २८०, ३२३, ३८३- विएसा १८, १९, ३३६, ३४४, ३६२ विक्रमशिला २०२, २१२, २१८ विल्सन, राप्ट्रपति १९०, २७४, २५४, .२८८, ३३२ विशी ४६६, ४९७, ५१६ विस्सांन ५३५ की त्रांग जैन ५०६. ५११, ५१२, ५६३ वीटे, काउण्ट १२७, १२५ 🐃

ब्द, लिओनोई ३३२ ज्ञांग १६१ व तिंग फांग १६१, १६३, १६४ य ती, समार ३० ब पेई फ १९२, १९३, २२४ बसग द० चेंडी हाडी बेर्ड १२६, १३०, २३९ बङ्गो ४६० बेड, शर थामग ७१ वेनिस ३६ वेकेन्की प्रीविन्स ३६४ बाग केह मिन ४३० बाग निग वेई २३२, ४१५-१७, ४३२, ४४२-४७,४७०,४७१,४८८,४८६ व्यावसायिक कान्ति १९, ४०, ४१, ४६, ४८, ११४-१७, १३४, २४६, 784, 784, 30x-00 व्हाम्लीआ २२६ गान गुज्य ३६९ बान हैबाबान ४०२, ४०३ शान्त रक्षित, आचार्य २०१, २०२ भानती २३१, ४०२, ४०९, ४१२, 828, 830 शिगात्रे १९७ शिदेष्ठमा ३८२, ५५४ शिन्तो धर्म ९३, ११७, ३२०, ३२१, ३२२, ४१४ विमळा १९६, २११, ५३२ शिमोनोसकी १०२ शिमोनोरोकी की सन्वि १२५-२९ शिम्पोलो २९३-९५ शी-हुआंग-ती, सम्राट २१६, ३४७ शेन्सी प्रान्त ४२१-२३, ४२४, ४२९, ४३३, ४४३ क्षोगुन ८७-९४, ९७, ९९, १०१-०६, १०८, १११, ११३, ११८, २७०, सहरीर ५३९

२९०, २९१, ३००, ५०० भोगा ३१६ जीवा, सम्राट २०१ जीवाकाई दल ४७५ शंधाई ६१, ६६, ६०, ८१, १६१, १६२, २२६, २४३, ३४५, २४०, २४७, २५०, २७६, २६५, देवर, ४०७, ४३०, ४३१, ४४६, रप्रयू, प्रयुच्न, ह्याल, रहार, प्रथ्य शांग यंग २७ भानंग १२९, १३०, १६१, १७७. १८४, १८६, १८५-५१, २३७, २३६, २७६-६६, २८८, २५६, 296, 809, 809, 824, 888, 828, 838 श्वादील बील ४२४ भेंग ह्यअस हवार्ड १५०, १६२ रकेल्यान प्रान्त ४२१, ४२२, ४५५, ४२६, ५१२, ५१३ श्रीमार ३४५ श्री विजय ३३४ थी विजय गाम्राज्य ३६२ मधालित द्वाप (४४, ११५, १४६, २७४, ५०६, ५४६ मत्गुमा १०१-०४, २९१, २९४, ३८० सनपात सेन १३३, १४९, १६४, १६४, १६८, १७२-१७४, १८४, १८५, २२१-२६, २२९, २३२, २४१, २५७, २६२, ४१५, ४१६, ४४४, 898, X08, X00 रान यात रोन , मशाम ५७१, ५७६, सन यात सेन युनिविधिटी २२७ समूद्र मृत्त १४९, ३४७ समुराई ९३, ९४, १०१, १०४ सरावनः ३४५

माउबीणिसा ६१, ३६, ५४, १२९, १३९, १४१, १४५-४७, १९८, संग्राम, लुआंग पिबुल ५२६ ४१६, २६७, २६९, २७०, २८२, र्वड, ३११, ५०८ सामा १०४ गामन्त पद्धति २७, ८६, ८७, १०४, १०४, ११६ गायान पर्वतमाला १९५ भालबीन नदी १९६ मिलान उठर सिकन्दर १७, ३१, १४९ ांसकांग १९६, २११ भितिकम २०५-०७ सीक्ट जनग्ल फान ४०८ मीजिमा ३५, ४६ गुर्द्धयान प्रान्त १९८,२१९,४३०,४३४ गुवाणे १३६-४२ गुज्जाती, एड्निरल ४७६ मुमाना २२, ३१२, ३३३-३७, ३४१-४६, ३५६, ३६१-६३, ४८३, दिवर, दिवह, प्रवृद्-४२ मुभिनीमी ११६ गुमीतामा कम्पनी ३७८ मुरक्षा परिषद् (सिक्योरिटी कौंसिल) राया, राष्ट्र राष्ट्र, राष्ट्र में ओन्जी, प्रिंस २९५-९७ रीडाल १२१, १२२, १४२, २७३, प्रदेश, प्रदेश भेण्ट गीटमं वुर्ग १२७, १४३, १४८ स रा २१२ मेलागींग ३६५ 4 संगोन ५२१ नैसेतो, एड्मिरल ३०० मैयुकाएँ वल २९४-३००, ३७८, हर्ष वर्धन ३२, २०१ ३७३-७४, ४४४, ४४६ सैयहोती वल २९८, २९९

सोएम्बाबा द्वीप ३३३ संयुक्त राज्य संघ (युनाइटेड नेशन्स आर्गीनिजेशन) ५००, ५२६, ४४०-४२, ४६८, ४६९, ४७२ संयुक्त सोवियत अमेरिकन कमीशन ४६३, ४६७, ४७० सिकियांग २२-२५, ३८, १९४-९९, २०३, २१२-१७, ४२१, ५७८ सिगापुर १८५, ३१२, ३६१-६८, ३७४, ४५७,४८२-८४,४८९, ४२६, ४२८, ४२९ मुंग २३४, २६२ सुंग वंश ३२, ३३, ३५ स्टालिन, मार्शल ४०६, ४७५ स्टिलवेल, जनरल ५०१ स्पटिली द्वीप समूह ५४७ स्पेन १७, ४३, ५३, ५४, ८९, ९०, ९२, ११०, १३२, २४१, २६९, ३२७-३०, ३४०, ४४६, ४४४, स्याम २१, २२, २०६, ३२५, ३५०, ३४४-६०, ३६६, ३६९, ३७३, ३७४, ४१७, ४२६, ४२७ खोड्.-गचन-गरा्म्-पो, संझाट २०१ स्वातो ६४, ४६० स्विट्जरलैण्ड ५६२ स्वीडन १८२ स्वेज १४६ हनयांग आयरन वर्क्स ६१ हर्ले, जनरल ५०१-०५ हवाई द्वीप १४८, २६९, २८४, ३१२, 803,850 हाई लुंग कियांग १३९ हार्ट, राबर्ट ६७, ७२

हान फ-च ५३१, ५३२ हान वंश २०-३२, ५५. ३४७ हाप्सवर्ग वंश २५७ हाबिन १२६, १४७ द्वाचिन ब्लादीवीरताक रेलवे १२९ हामाग्ची २८९, ३६२ हामी १९७-९९ हारा २९७, २९८ व्यक्त, व्यक्त, व्रुव, व्यव, व्यक्त, ४७१-७४, ४७६, ४६६-६७, प्रम्प-४२, ५४९, ५९१ ४५४, ४५६, ४७३, ४९२, ४५४, प्रश्रह, प्रप्रश हिसंग न २१६ हिरोहिनो, गम्राट ३०१ हीजन १०३, १०४ हीरानुमा ४७७, ४५१, ४५७ हीसीता ४०६, ४७६, ५५७ हीरोजीमा ४९२ हता यानी हप दल १४३-४६ हलग् यान ३६ हल्ताओं ३५४ हुकुआंग प्रान्त १८३, १९२ हुनान प्रान्त २२९, ४१६, ४४३

हु हान भिन २३२, ४१६ हेश कात्पारेच्या ५४१-४३ हंग्स, राष्ट्रावि ७४ हेरिहरस २०४ हैचान १२०, ४५७, ५५२, ५४०, y.00, y.53 हेरिस, टाउनगंणः १६ हो-उपेन्स् समझाता ४१० हाळेण्ड ९६, १००, १०२, ११०, २३६, - होचो(यन्त ५१९, ५२१, ५६५, ५६६ २४१, २४२, २६९, ३३६-४१, होंगेर्ड प्रान्त ४०२, ४०५.१४, ४१७. हरूप, हरूप, दर्द, हरूद, हरूद, हरू ३७३, ३७४, ३६३, ४६६, ४६७, शाम कांग ५१, ५४, ६६, १३०, एलप्र 832. 664, 640 648, 840. KHV हिटलर ४१७, ४२४, ४४९, - ४४०, - हमिकांग एका लोनाई नेविस कारपीट रेशान ७ ५, फल क्षांज, जनभन प्रदर्भ र्धगर्नहमञ्जान ७६, ७७ ह्यांगही वर्ती १७, २०, ३०, १९६ हवनवाम इस, स्थ्र हिर्ग अस्मिई इल् हियाल पंग, सम्बद्ध ७५ किशन निम ३९०, ४९५ हिसया राज्य ६३ त्याभाग मंग समाट १५६, १६५ इ.स्मह व्याम इत्ह उत्पानिह भग, मध्यांत १५३, १५१. .

793



